

[2015] 13 एस. सी. आर 1

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

समाज और एक और

वी.

भारत का संघ

(2015 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 13)

16 अक्टूबर, 2015

[जगदीश सिंह खेहर, जे. चेलामेश्वर,

मदन बी. लोकुर, कुरियन जोसेफ,

आदर्श कुमार गोएल, जे. जे.]

संविधान (99 वां संशोधन) अधिनियम, 2014 -

न्यायालय, और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश; और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों का स्थानांतरण

एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में-नई योजना पर विचार किया गया कॉलेजियम प्रणाली को बदलने के लिए-छह-सदस्य राष्ट्रीय

न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) का गठन संविधान (नब्बे-नौवां संशोधन) अधिनियम, 2014

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के साथ पढ़ें

अधिनियम, 2014-एन. जे. ए. सी. निम्नलिखित से बना है: (क) भारत के मुख्य न्यायाधीश,

अध्यक्ष, पदेन; (बी) सर्वोच्च न्यायालय के दो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश के बगल में

सदस्य, पदेन; (ग) केंद्रीय कानून मंत्री

और पदेन सदस्य के रूप में न्याय; (घ) दो प्रतिष्ठित व्यक्ति, सदस्यों के रूप में नामित किया जाना-संविधान (नब्बे-नौवां)

संशोधन) अधिनियम, 2014-की वैधता (के आदेश के अनुसार)

अदालत): यह असंवैधानिक और अमान्य राष्ट्रीय न्यायिक है।

नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014-न्यायपालिका-उच्चतर

न्यायपालिका-संवैधानिक न्यायालय-नियुक्ति और स्थानांतरण

न्यायाधीशों की-प्रक्रिया।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014

- उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली

न्यायालय, और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश; सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों का स्थानांतरण

एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में-कॉलेजियम प्रणाली को बदलने के लिए नई योजना पर विचार किया गया-छह सदस्यीय राष्ट्रीय

न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) का गठन

संविधान (नब्बे-नौवां संशोधन) अधिनियम, 2014

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के साथ पढ़ें

अधिनियम, 2014-एन. जे. ए. सी. निम्नलिखित से बना है: (क) भारत के मुख्य न्यायाधीश,

अध्यक्ष, पदेन; (बी) सर्वोच्च न्यायालय के दो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश के बगल में सदस्य, पदेन; (ग) पदेन सदस्य के रूप में कानून और न्याय के प्रभारी केंद्रीय मंत्री; (घ) दो प्रतिष्ठित व्यक्ति,

राष्ट्रीय न्यायिक सदस्यों के रूप में नामित किया जाना नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014-आयोजित की वैधता

(न्यायालय के आदेश के अनुसार): यह असंवैधानिक और अमान्य है -

संविधान (नब्बे-नौवां संशोधन) अधिनियम, 2014-न्यायपालिका

- उच्च न्यायपालिका-संवैधानिक न्यायालय-नियुक्ति

और न्यायाधीशों का स्थानांतरण-प्रक्रिया।

न्यायपालिका-उच्च न्यायपालिका-संवैधानिक न्यायालय

न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण-प्रक्रिया-कॉलेजियम

उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली, और

मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों का उच्च न्यायालयों में स्थानांतरण और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से स्थानांतरण।

न्यायालय, दूसरे के लिए-प्रतिस्थापन के लिए नई योजना पर विचार किया गया

कॉलेजियम प्रणाली-छह सदस्यीय राष्ट्रीय न्यायिक

नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) का गठन

संविधान (नब्बे-नौवां संशोधन) अधिनियम, 2014

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014

एन. जे. ए. सी. से बना है: (क) भारत के मुख्य न्यायाधीश,

अध्यक्ष, पदेन; (बी) के दो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश
के बगल में

उच्चतम न्यायालय, भारत के मुख्य न्यायाधीश

सदस्य, पदेन; (ग) पदेन सदस्य के रूप में कानून और न्याय के प्रभारी केंद्रीय मंत्री; (घ) दो प्रतिष्ठित व्यक्ति,

सदस्यों के रूप में नामित किया जाना-आयोजित (न्यायालय के आदेश के अनुसार):

कॉलेजियम प्रणाली, जैसा कि संविधान सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं से पहले मौजूद थी-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई.

(99 वां संशोधन) अधिनियम, 2014, घोषित किया गया
पर विचार करने के लिए

ऑपरेटिव-हालांकि, उपयुक्त की शुरूआत

कॉलेजियम के बेहतर कामकाज के लिए उपाय, यदि कोई हो

प्रणाली ", बाद की तारीख को सूचीबद्ध मामला-संविधान (नब्बे-नौवां संशोधन) अधिनियम, 2014-राष्ट्रीय
न्यायिक

नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014।

न्यायपालिका-उच्च न्यायपालिका-संवैधानिक न्यायालय -

न्यायाधीशों का चयन और नियुक्ति-संसद, यदि

एक वैकल्पिक प्रक्रिया प्रदान करने के लिए सशक्त-आयोजित

(प्रति खेहर, जे.): अभ्यास करते समय यह संसद के लिए खुला रहता है।
इसकी शक्ति, कुछ अन्य प्रावधान करने के लिए

अनुच्छेद 368 के तहत

चयन और नियुक्ति के लिए वैकल्पिक प्रक्रिया

उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीश, जब तक कि, के गुण

"शक्तियों का पृथक्करण और न्यायपालिका की स्वतंत्रता,

जो संविधान की "मूल संरचना" के "मूल" घटक हैं, उनका रखरखाव किया जाता है।

भारत का संविधान-क्षेत्र में संशोधन-आयोजित

अलंघनीय-संविधान में इस तरह से संशोधन नहीं किया जा सकता है कि "बुनियादी विशेषताओं" को नकारें-इसके अलावा, यदि कोई चुनौती है

इसकी किसी भी

बुनियादी कानूनों में से एक के आधार पर एक सामान्य कानून बनाया गया

संविधान की विशेषताओं के अनुसार, ऐसा करना वैध होगा।

भारत का संविधान-कला। 368 – संवैधानिक

संशोधन-लोगों की इच्छा और न्यायिक समीक्षा

-

संशोधन शक्ति पर सीमाएँ-नियुक्ति और

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों का स्थानांतरण-व्यापक आधार पर न्यायिक

सदस्यों से मिलकर बना नियुक्ति आयोग

न्यायपालिका, कार्यपालिका और प्रतिष्ठित/महत्वपूर्ण व्यक्ति

प्रचलित जीवन को बदलने के लिए सार्वजनिक जीवन के गठन का प्रस्ताव

अनुच्छेद 124 (2) और 217 (1) के तहत विचार की गई प्रक्रिया -

कथित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, अनुच्छेद 124 और 217 अंतर और अनुच्छेद 124 ए, 124 बी और 124 सी अंतःस्थापित किए गए

अन्य रूप से संशोधित,

संविधान में, संविधान के माध्यम से (99 वां

संशोधन) अधिनियम, विचाराधीन प्रक्रिया का पालन करते हुए सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

अधिनियम, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती-आयोजित (प्रति सीमाएँ हैं

खेहर, जे.): संशोधन पर घोषित

संसद को प्रदत्त शक्ति, जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है

- यदि कोई संवैधानिक संशोधन संविधान के "मूल" का उल्लंघन करता है

संविधान में इसकी "बुनियादी या आवश्यक विशेषताओं" को नष्ट कर देता है या

जिस तरह से यह स्पष्ट रूप से असंवैधानिक था

वर्जित क्षेत्र को पार करना-यह पहलू,

निस्संदेह न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है -

मामले के ऊपर के दृष्टिकोण से, विवादित संवैधानिक

संशोधन, साथ ही, एन. जे. ए. सी. अधिनियम, के अधीन होगा

“मूल संरचना” की कसौटी पर न्यायिक समीक्षा

संविधान, और द्वारा निर्धारित मापदंड

उस ओर से सर्वोच्च न्यायालय, भले ही विवादित
और

संवैधानिक संशोधन को मंजूरी दी जा सकती है

सर्वसम्मति से या भारी बहुमत से पारित किया गया, और

अटार्नईस राज्य विधानसभाओं के संविधान (नब्बे-नौवें) द्वारा इसके अनुसमर्थन के बावजूद

संशोधन) अधिनियम, 2014-राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियाँ

आयोग अधिनियम, 2014।

न्यायपालिका-उच्च न्यायपालिका-संवैधानिक न्यायालय--

न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण-की स्वतंत्रता

न्यायपालिका-भारत के मुख्य न्यायाधीश को प्रधानता प्रदान की जाती है।

और उनके न्यायाधीशों का कॉलेजियम-आयोजित (प्रति खेहर, जे.): में

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों के स्थानांतरण के
मामले में भी

अनुच्छेदों के तहत एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय में

124, 217 और 222, के मुख्य न्यायाधीश को प्रधानता प्रदान की गई

भारत और उनके न्यायाधीशों का कॉलेजियम, स्वीकार किए जाने के लिए उत्तरदायी है

उपरोक्त प्रावधानों के एक अभिन्न घटक के रूप में (जैसे -

मूल रूप से अधिनियमित)-इसलिए, जब एक प्रश्न के साथ

चयन और नियुक्ति के लिए रेफरी (साथ ही, स्थानांतरण)

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई.

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की संख्या को उठाया जाता है, यह आरोप लगाते हुए कि "न्यायपालिका की स्वतंत्रता" एक "बुनियादी विशेषता/संरचना" के रूप में है।

संविधान का उल्लंघन किया गया है, यह होना चाहिए

यह सुनिश्चित किया गया कि क्या न्यायपालिका की प्रधानता का प्रयोग किया जाता है

भारत के मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से (एक सामूहिक आधार पर)

न्यायाधीशों के एक कॉलेजियम के ज्ञान का उल्लंघन किया गया था-तब

अकेले, क्या यह निष्कर्ष निकालना संभव होगा कि "न्यायपालिका की स्वतंत्रता" एक आवश्यक "बुनियादी विशेषता" के रूप में है या नहीं।

संविधान का, संरक्षित किया गया था (-और नहीं किया गया था

उल्लंघन)-भारत का संविधान-अनुच्छेद 124, 217 और 222।

न्यायपालिका-उच्च न्यायपालिका-संवैधानिक न्यायालय -

न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण-प्रक्रिया-नई

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) का गठन संविधान के तत्वावधान में (नब्बे-नौवां संशोधन)

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियों के साथ पढ़ा गया अधिनियम, 2014

आयोग अधिनियम, 2014-एन. जे. ए. सी. में न्यायपालिका के सदस्य, कार्यपालिका और प्रतिष्ठित/महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल होंगे।

सार्वजनिक जीवन से-चाहे व्यावहारिकता की बात हो,

विवादित संवैधानिक संशोधन पर विचार किया जा सकता है - निर्णय लेने के मामले में निरंतरता, प्रधानता,

अनुच्छेद 124, 217 और 222 के संशोधित प्रावधानों के तहत, अनुच्छेद 124 ए के जोड़े गए प्रावधानों के संयोजन से

124 ग, न्यायपालिका के साथ-आयोजित (प्रति खेहर, जे।): की प्रधानता

न्यायपालिका को टिकाऊ नहीं माना जाएगा,

केवल यह सुनिश्चित करके कि न्यायिक घटक में एन. जे. ए. सी. की सदस्यता, अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम थी

एक अयोग्य उम्मीदवार की उम्मीदवारी-प्रधानता के मामले में, एन. जे. ए. सी. का न्यायिक घटक होना चाहिए

स्वयं सक्षम, एक योग्य की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए
के तहत, भले ही

नामित, साथ ही-प्रतिस्थापित योजना

भारत के मुख्य न्यायाधीश और दो अन्य सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश

उच्चतम न्यायालय का (भारत के मुख्य न्यायाधीश के बगल में), एक नामित व्यक्ति को उच्च सर्वोच्च न्यायालय
रिपोर्ट में नियुक्ति के लिए योग्य मानता है।

[2015] 13 एस सी आर।

न्यायपालिका, संबंधित व्यक्ति को अभी भी नियुक्त नहीं किया जा सकता है, अगर एन. जे. ए. सी. के कोई भी दो
सदस्य अन्यथा राय देते हैं-यह होगा

बाहर होना-न्यायिक घटक की प्रधानता के लिए सही मायने में अप्रिय-तत्काल मुद्दे का परिमाण स्पष्ट है

इस तथ्य से कि दो "प्रतिष्ठित व्यक्ति" (-iay व्यक्तियों,

महान्यायवादी के अनुसार), पराजित कर सकता है
सिफारिश

मुख्य न्यायाधीश द्वारा सर्वसम्मति से की गई

भारत और उच्चतम न्यायालय के दो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश, एक व्यक्ति की नियुक्ति के पक्ष में

बिना किसी संदेह के विचार, की प्रधानता को नीचा दिखाना

न्यायपालिका, के चयन और नियुक्ति के मामले में

उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीश-तत्काल मुद्दा है

स्पष्ट रूप से कहीं अधिक प्रतिगामी, जब केंद्रीय मंत्री

कानून और न्याय के प्रभारी भी सर्वसम्मति का समर्थन करते हैं

न्यायिक घटक का दृष्टिकोण, क्योंकि अभी भी असहमति

"प्रतिष्ठित व्यक्तियों" की आवाज प्रबल होगी-यह स्पष्ट है,

न्यायपालिका की प्रधानता को और बढ़ा दिया गया है

विनाशकारी झटका, इसे बेहद नाजुक बनाकर-लेख

124 ए (1) (ए) और (बी) पर्याप्त प्रावधान नहीं करते हैं

चयन के मामले में न्यायपालिका की प्रधानता सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक घटक को मामले में
प्रतिनिधित्व और

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति, और इसलिए,
 उसी को अलग रखा जा सकता है और होने के रूप में नीचे मारा जा सकता है
 भारत के संविधान की "मूल संरचना" का उल्लंघन -
 इस प्रकार देखा जाए तो संविधान की "मूल संरचना"
 स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया जाएगा, यदि न्यायाधीशों के चयन की प्रक्रिया
 उच्च न्यायपालिका का संचालन इस तरह से किया जाना था
 एन. जे. ए. सी. के माध्यम से विचार किया गया-विवादित
 संवैधानिक संशोधन, अधिकार से परे होने के कारण "बुनियादी" संविधान की संरचना को
 दरकिनार किया जा सकता है-भारत का संविधान-कला। 124 ए (1) (ए) और (बी)।

न्यायपालिका-उच्च न्यायपालिका-संवैधानिक न्यायालय -

न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया-नई योजना

प्रतिरूपित-राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग शीर्ष अदालत के अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई.

(एन. जे. ए. सी.) की स्थापना-एन. जे. ए. सी. में सदस्य शामिल होंगे
 न्यायपालिका, कार्यपालिका और प्रतिष्ठित/महत्वपूर्ण व्यक्ति
 सार्वजनिक जीवन-- राजनीतिक-कार्यपालिका की भागीदारी-- यदि उचित हो।
 -केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री की उपस्थिति,
 एन. जे. ए. सी. के पदेन सदस्य के रूप में-चुनौती-आयोजित
 (प्रति खेहर, जे.): राजनीतिक-कार्यपालिका, जहाँ तक संभव हो,
 अंतिम/अंतिम चयन में कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए और
 उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति-विशेष रूप से
 भागीदारी की विशालता को ध्यान में रखते हुए
 राजनीतिक-कार्यकारी, न्यायिक निर्णय के कार्यों में
 पारस्परिकता, और राजनीतिक भुगतान की भावनाएँ

कार्यपालिका की स्वतंत्रता के लिए विनाशकारी होगा
 न्यायपालिका "-चूँकि कार्यपालिका की एक प्रमुख हिस्सेदारी है,
 उच्च न्यायपालिका के समक्ष विचार के लिए उत्पन्न होने वाले अधिकांश मामलों में केंद्रीय मंत्री की भागीदारी
 एन. जे. ए. सी. के पदेन सदस्य के रूप में विधि और न्याय का प्रभार स्पष्ट रूप से संदिग्ध होगा-इसके
 परिणामस्वरूप
 कानून और न्याय के प्रभारी केंद्रीय मंत्री की भागीदारी, मंत्री के साथ नियुक्ति के लिए अनुमोदित एक
 न्यायाधीश
 समर्थन, संघर्ष के अनुरोध का विरोध या प्रतिकार करने में सक्षम नहीं हो सकता है
 एक वादी द्वारा उठाए गए हित का, एक मामले में जब कार्यपालिका
 एक प्रतिकूल भूमिका है-एन. जे. ए. सी. में केंद्रीय मंत्री
 कानून और न्याय का प्रभार सभी अंतिम मामलों में एक पक्ष होगा।
 उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों का चयन और नियुक्तियाँ
 - एन. जे. ए. सी. द्वारा अनुमोदित न्यायाधीशों के लिए यह मुश्किल हो सकता है कि
 हितों के टकराव की याचिका का विरोध करें (यदि ऐसी याचिका होनी थी) उठाया गया, और दबाया
 गया), जहाँ राजनीतिक-कार्यपालिका एक पार्टी है
 लिस के लिए-उपरोक्त, का अपरिहार्य प्रभाव होगा
 "न्यायपालिका की स्वतंत्रता" को कमजोर करना, यहां तक कि जहां भी इस तरह की याचिका
 को खारिज कर दिया जाता है-इसलिए, उसे सौंपी गई भूमिका
 राजनीतिक-कार्यकारी, सबसे अच्छा एक सहयोगी तक सीमित किया जा सकता है
 भागीदारी, अंतिम निर्धारण में किसी भी भूमिका को छोड़कर -
 केवल केंद्रीय कानून मंत्री की भागीदारी और
 न्याय, चयन की अंतिम प्रक्रिया में, पदेन [2015] 13 एस. सी. आर. के रूप में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एन. जे. ए. सी. के सदस्य, संशोधित प्रावधान प्रदान करेंगे
 अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि यह

अनुच्छेद 124 ए (1) (सी) संविधान के

"न्यायपालिका की स्वतंत्रता" के सिद्धांतों को बाधित करता है

और "शक्तियों का पृथक्करण"-के विकास की प्रक्रिया में

दुनिया भर के समाजों में न्यायपालिका को मुक्त करने की प्रवृत्ति है

कार्यकारी और राजनीतिक नियंत्रण से, और एक शामिल करने के लिए

विशुद्ध रूप से आधारित न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति की प्रणाली

योग्यता के आधार पर-क्योंकि तभी न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया होती है।

प्रभावी रूप से राष्ट्र निर्माण का समर्थन करेगा-राष्ट्र की प्रगति
"न्यायपालिका" की अवधारणाएँ

"न्यायपालिका की स्वतंत्रता" और

समीक्षा को अब दुनिया भर में मान्यता दी जा रही थी-द

कार्यकारी और राजनीतिक भागीदारी की घटती भूमिका

उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों का मामला है

स्पष्ट वास्तविकता-उपरोक्त प्रवृत्ति की मान्यता में, वहाँ

इससे बड़ी और आगे की भागीदारी नहीं हो सकती

कार्यकारी, उससे जो पहले मौजूद था-और
है, के माध्यम से

भारतीय परिदृश्य, जैसा कि वर्तमान में कल्पना की गई

द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों के मामलों में दिए गए निर्णय

- इसलिए यह निष्कर्ष निकालना अनिवार्य है कि भागीदारी

फाइनल में कानून और न्याय के प्रभारी केंद्रीय मंत्री

एन. जे. ए. सी. में निहित निर्धारक प्रक्रिया, साथ ही,

प्रधानमंत्री और नेता की भागीदारी

लोकसभा में विपक्ष (और कोई नहीं होने की स्थिति में)

- सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता

), "प्रतिष्ठित व्यक्तियों" के चयन में, यह एक प्रतिगामी कदम है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है-भारत का संविधान-कला। 124 ए (1) (सी)।

न्यायपालिका-उच्च न्यायपालिका-संवैधानिक न्यायालय -

न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण प्रक्रिया

एन. जे. ए. सी.-एन. जे. ए. सी. की संरचना और संरचना
और दो प्रतिष्ठित

न्यायपालिका के सदस्य, कार्यपालिका

व्यक्तियों का "गैर-विवरण से उत्पन्न होने वाला मुद्दा

"प्रतिष्ठित व्यक्तियों" की योग्यता और अयोग्यता -

एन. जे. ए. सी. के लिए दो "प्रतिष्ठित व्यक्तियों" को नामित किया जाएगा-सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई.

वीटो की शक्ति के साथ-स्वामित्व-आयोजित (प्रति खेहर, जे):

योग्यता के विवरण का मुद्दा (-शायद, भी)

"प्रतिष्ठित व्यक्तियों" की अयोग्यता) अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसे स्वतंत्र इच्छा और चयन पर नहीं छोड़ा जा सकता है। नामित करने वाले अधिकारी, चाहे वे उच्च हों

उनके द्वारा धारण किए गए संवैधानिक पद-विशेष रूप से, क्योंकि

दो "प्रतिष्ठित व्यक्तियों" में कुल संख्या का एक तिहाई हिस्सा शामिल है।

एन. जे. ए. सी., और राजनीतिक-कार्यकारी घटक से दोगुना,

और इस तरह, एक सर्वोच्च महत्वपूर्ण भूमिका होगी

अलग रखे जाने और नीचे गिराए जाने के लिए उत्तरदायी, नहीं रखे जाने के लिए "प्रतिष्ठित व्यक्तियों" के रूप में नामित होने के लिए पात्रता की योग्यता को कम करना, और उसी को अस्पष्ट छोड़ने के लिए और

अव्याख्यायित-अन्यथा इसकी सराहना करना भी मुश्किल है

छह में दो "प्रतिष्ठित व्यक्तियों" को शामिल करने का तर्क-सदस्य

एन. जे. ए. सी.-यह सराहना करना मुश्किल है कि "प्रतिष्ठित" क्या इनपुट देते हैं।

व्यक्ति ", वकील द्वारा दर्शाई गई योग्यता को संतुष्ट करते हुए

सामान्य, चयन के मामले में प्रस्तुत करेगा और

न्यायाधीशों का चयन बहुत बड़ा है, और इसके परिणाम खतरनाक है कि अगर

अनुचित नियुक्तियाँ करना इतना

चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल लोग

उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों का गलत चयन करना,

यह हो सकता है

अच्छी तरह से राष्ट्र को एक तरह की अराजकता में ले जाएं-यह भी है

संसद के विवेक की सराहना करना मुश्किल है,

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति, और
दूसरा

एक साथ उन्हें वीटो की शक्ति प्रदान करें-

एस के तहत परंतुक। 5 (2), और एस। 6 (6) एन. जे. ए. सी. अधिनियम, स्पष्ट रूप से

अधिदेश, कि एक व्यक्ति नामित के लिए विचार किया जाना है

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति, और व्यक्ति

मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जा रहा है और उच्च न्यायालयों के
न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं की जा सकती है, यदि एन. जे. ए. सी. के कोई भी दो सदस्य प्रस्ताव से सहमत
नहीं हैं-सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट में

[2015] 13 एस सी आर।

:

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की चयन प्रक्रिया की योजना, विवादित संवैधानिक के तहत विचार किया
गया

एन. जे. ए. सी. अधिनियम के साथ पढ़ा गया संशोधन, दोनों "प्रतिष्ठित व्यक्तियों" को सभी को अस्वीकार करने
का पर्याप्त अधिकार है।

सिफारिशें, केवल अपने आप से-इतना ही नहीं,

दो "प्रतिष्ठित व्यक्तियों" के पास भी पूर्ण अधिकार होगा।
नामों को अस्वीकार करना

शेष द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित सभी

एन. जे. ए. सी. का संपूर्ण न्यायिक घटक-ऐसा निहित करना न्यायपालिका की स्वतंत्रता की योजना
में "प्रतिष्ठित व्यक्तियों" में अधिकार स्पष्ट रूप से अस्थिर है-अनुच्छेद

124 ए (1) (डी) को अलग रखा जा सकता है और इसके रूप में नीचे गिराया जा सकता है

संविधान की "मूल संरचना"-भारत का संविधान-कला का उल्लंघन। 124 ए (1) (डी)-संविधान (नब्बे)
नौवां संशोधन) अधिनियम, 2014 राष्ट्रीय न्यायिक

नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014-दूसरा परन्तुक यू/एस।

5 (2) और एस। 6 (6).

न्यायपालिका-उच्च न्यायपालिका-संवैधानिक न्यायालय -

न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण-की भागीदारी

राजनीतिक-कार्यकारी प्रतिष्ठान-"नागरिक समाज" की भूमिका

भारत में-आयोजित (प्रति खेहर, जे.): संविधान में नहीं है "लूट प्रणाली" (जिसे "संरक्षण" के रूप में भी जाना जाता है) की परिकल्पना करें।

प्रणाली "], जिसमें राजनीतिक दल जो चुनाव जीतता है, अपने समर्थकों, मित्रों को सरकारी पद देता है और

पार्टी को सत्ता में बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन-यह अत्यधिक होगा न्यायिक नियुक्तियों को किसी भी राजनीतिक घटना से बचाने का महत्व

कार्यकारी हस्तक्षेप, की स्वतंत्रता को संरक्षित करने के लिए

न्यायपालिका ", लूट प्रणाली के शासन से-संरक्षण

न्यायपालिका में वरीयता, चयन के मामले में और

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति एक

ऐसा करने का सुरक्षित तरीका-यह मानना मुश्किल है कि ज्ञान

न्यायाधीशों की नियुक्ति, राजनीतिक सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं के साथ साझा की जा सकती है-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई.

कार्यपालिका-भारत में नागरिक समाज का जैविक विकास,

अभी तक पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हुआ है-से अपेक्षा

न्यायपालिका, इसके नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए

भारत में समाज, की भागीदारी को बढ़ावा नहीं देता है राजनीतिक-कार्यकारी प्रतिष्ठान, चयन में और

इस देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार, के आधार पर अनुच्छेदों के तहत इसे सौंपी गई संवैधानिक जिम्मेदारी

32 और 226, नागरिक के रक्षक के रूप में कार्य करना जारी रखना चाहिए

समाज-भारत का संविधान-कला। 32 और 226।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014

- राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए एन. जे. ए. सी.-कोरम का कार्यकरण

न्यायिक नियुक्ति आयोग (एन. जे. ए. सी.), जब वैध हो -

वैध निर्णय लेने के लिए आवश्यक शक्ति-आयोजित (प्रति

खेहर, जे.): यदि कोई वैधानिक प्रावधान एक निर्णय निहित करता है

व्यक्तियों के निकाय में बिना किसी शर्त के अधिकार बनाना
केवल तभी आयोजित की जा सकती है जब

न्यूनतम गणपूर्ति, तब एक वैध बैठक

शरीर के सभी सदस्यों का बहुमत, जानबूझकर

निर्णय लेने की प्रक्रिया-इसलिए उसी सादृश्य पर,

ऐसे निकाय द्वारा एक वैध निर्णय के लिए एक निर्णय की आवश्यकता होगी।

शरीर के सभी सदस्यों के साधारण बहुमत से-यदि

उपरोक्त सिद्धांतों को एन. जे. ए. सी. पर लागू किया जाता है,

स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि एन. जे. ए. सी. की एक वैध बैठक

छह में भाग लेने वाले कम से कम चार सदस्य होने चाहिए

सदस्य एन. जे. ए. सी.-इसी तरह एन. जे. ए. सी. का एक वैध निर्णय हो सकता है

केवल लिया जाए (किसी भी निर्धारित पूर्व शर्त के अभाव में),

एक साधारण बहुमत से, अर्थात्, कम से कम चार सदस्यों द्वारा

एन. जे. ए. सी. (दोनों तरफ से तीन सदस्य, नहीं करेंगे

साधारण बहुमत)-न्यायपालिका-उच्च न्यायपालिका -

1 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

संवैधानिक न्यायालय-न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण

- प्रक्रिया।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014

- एसएस। 5 (2) और 6 (6)-वैधता-न्यायपालिका-उच्च न्यायपालिका

संवैधानिक न्यायालय-न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण

- वीटो की शक्ति एन. जे. ए. सी. के किसी भी दो सदस्यों में निहित है -

आयोजित (प्रति खेहर, जे.): वीटो की शक्ति किसी भी दो में निहित है।

एन. जे. ए. सी. के सदस्य, की प्रधानता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे

न्यायपालिका, के चयन और नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीश (साथ ही उनका स्थानांतरण भी)-एस. एस. 5 (2)

और 6 (6) संविधान की "मूल संरचना" का उल्लंघन करते हैं,

"न्यायपालिका की स्वतंत्रता" का संदर्भ और

"शक्तियों का पृथक्करण" -s. 5 (2) और 6 (6), इसलिए, उत्तरदायी

संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित किया जाए।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014

एस. 5 (1) - भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

प्रक्रिया - धारा 5 (1) बशर्ते कि एन. जे. ए. सी. उच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश की सिफारिश करना,

भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए,

शर्त, कि उन्हें पद धारण करने के लिए "उपयुक्त" माना गया था

तर्क है कि "फिट" शब्द को विस्तृत रूप से नहीं दिया गया था

वर्णित है और यह हमेशा संसद के लिए खुला था

उद्देश्यपूर्ण रूप से स्वास्थ्य को इस तरह से परिभाषित करें कि यह सहायक हो। कार्यपालिका की इच्छा और यह गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है/करेगा

न्यायपालिका की स्वतंत्रता-हेल्ड (प्रति खेहर, जे.): प्रक्रिया के अधीन होना संसद के दायरे में नहीं था

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के चयन के साथ-साथ

भारत के मुख्य न्यायाधीश की स्थिति, अनिश्चित और

अस्पष्ट शब्द-व्यक्त करना अनिवार्य था, स्पष्ट

"फिट" शब्द के मापदंड, वरिष्ठतम के संदर्भ में एस के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। 5- "फिट" शब्द हो सकता है

बहुत नीचे के उम्मीदवार को चुनने के लिए तैयार किया गया

वरिष्ठता सूची-महान्यायवादी द्वारा अपनाया गया पद,

अर्थात्, "फिट" शब्द का उपयोग एस में किया जाता है।

5 (1) सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं को पढ़ा जाएगा-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई.

मतलब केवल "मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य" की पुष्टि की जाती है।

और क्रिस्टलीकृत-यदि ऐसा किया जाता है, तो यह कानूनी होगा और

संवैधानिक-हालाँकि, यदि अपनाई गई स्थिति का उल्लंघन होता है

"न्यायपालिका की स्वतंत्रता", सुझाए गए तरीके से

याचिकाकर्ताओं द्वारा, वही कानून में उपलब्ध होगा।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014

एस. 5 (2), पहला परंतुक-किसी उच्च अधिकारी की नियुक्ति की वैधता

न्यायालय न्यायाधीश-एस के लिए पहला परंतुक। 5 (2) उस समय प्रदान करते हुए

उच्च न्यायालय की नियुक्ति के लिए सिफारिश करना

न्यायाधीश, वरिष्ठता के अलावा, ऐसे न्यायाधीश की क्षमता और योग्यता

एन. जे. ए. सी. द्वारा विचार किया जाएगा (प्रति खेहर,

जे.): निस्संदेह, पहले परंतुक में "वरिष्ठता" को अभिनिर्धारित करना।

एस के तहत। 5 (2), एक प्रशंसनीय उद्देश्य है-और अगर वरिष्ठता है

"क्षमता और योग्यता" के साथ पूरक और संलग्न किया जाए,

सबसे आदर्श दृष्टिकोण, अपनाया गया देखा जा सकता है -

लेकिन जो कागज पर दिखाई देता है, वह कभी-कभी सही नहीं भी हो सकता है

व्यवहार में-अनुभव से पता चलता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

कोर्ट को बैचों में नियुक्त किया जाता है, प्रत्येक बैच के पास सिर्फ

दो या तीन नियुक्त, या कभी-कभी दस भी हो सकते हैं या
न्यायाधीशों का एक समूह

अधिक व्यक्ति-एक उच्च पद पर नियुक्त

न्यायालय, नियुक्त न्यायाधीशों के समूह से अलग किया जाएगा

एक और उच्च न्यायालय, कुछ ही दिनों में, या कुछ ही हफ्तों में,

और कभी-कभी कुछ ही महीनों में-अखिल भारतीय वरिष्ठता में न्यायाधीशों का पूरा बैच उसी दिन नियुक्त किया जाता है,

एक उच्च न्यायालय को, एक चल रहे क्रमिक आदेश में रखा जाएगा (में

अदालत, कुछ दिनों या हफ्तों या महीनों के बाद-न्यायाधीश बाद में नियुक्त, नीचे सामूहिक रूप से रखा जाना होगा

पूर्व बैच, वरिष्ठता में-यदि न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय, वरिष्ठता (प्राथमिक विचार के रूप में) के आधार पर बनाया जाना है, तो पहले के बैच के पास होगा

उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति के मामले में प्राथमिकता-और काल्पनिक रूप से, यदि बैच में दस न्यायाधीश थे (एक साथ नियुक्त)

किसी विशेष उच्च न्यायालय को), और यदि वे सभी सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर. साबित कर चुके हैं।

स्वयं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में सक्षम और मेधावी, वे

रिक्तियों पर एक के बाद एक नियुक्त करना होगा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों का उदय होता है-इस दृष्टिकोण से कि

मामले में, उसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया जाएगा, जब तक कि पूरा बैच समाप्त नहीं हो जाता -

उपरोक्त स्थिति में उसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

जहां दस न्यायाधीशों का बैच एक तिहाई पर कब्जा करेगा उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीश पदों में से-वह

स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य होना-इस पर न्यायाधीशों का विचार

उनकी वरिष्ठता का आधार, एक प्राथमिक के रूप में समान व्यवहार करके

विचार, वर्तमान सम्मेलन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा राज्य उच्च न्यायालयों से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए,

जितना संभव हो-प्रचलित परंपरा है, बनाए रखने के लिए

क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व-तदनुसार, पहला प्रावधान

एस। 5 (2) गिराए जाने और अलग रखे जाने की संभावना है।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014

-- धारा 6 (1)-किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की वैधता

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायालय - धारा 6 (1) में यह प्रावधान किया गया है कि

एन. जे. ए. सी. अंतर वरिष्ठता के आधार पर सिफारिश करेगा

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और योग्यता, योग्यता और कोई अन्य मानदंड

एस के तहत पहले परंतुक का संदर्भ। 5 (2) - वास्तव में इसके लिए पहले परंतुक के मामले में देखे गए समान कारण

एस। 5 (2), वरिष्ठता के आधार पर (प्राथमिक विचार के रूप में), दस

विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं।

एक मूल उच्च न्यायालय से लिया गया - एस. 6 (1) इसलिए उत्तरदायी है -

एस के तहत पहले परंतुक के रूप में एक ही भाग्य का सामना करें। 5 (2); और है।

गिराया जा सकता है और अलग रखा जा सकता है।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014

- एस. 7-भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की वैधता या

उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश

न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश - एस. 7 का प्रावधान है कि

राष्ट्रपति इस तरह की नियुक्तियां सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं-ऑन-रिकॉर्ड पर करेंगे।

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई.

एन. जे. ए. सी. द्वारा की गई सिफारिशें-एस. के लिए पहला प्रावधान। 7

बशर्ते कि राष्ट्रपति एन. जे. ए. सी. को पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो सकती है

इसके द्वारा की गई सिफारिश-आयोजित (प्रति खेहर, जे.): यह नहीं है।

इसे स्वीकार करना संभव है। 7 राष्ट्रपति को यह प्रदान करके कि

इसके द्वारा किया गया, किसी भी तरह से अनुच्छेद 124 (2) का उल्लंघन करेगा और 217 (1) (किस आदेश से न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी)

एन. जे. ए. सी. की सिफारिश पर राष्ट्रपति)-यह होगा

यह अनुमान लगाना अनुचित होगा कि राष्ट्रपति की कार्रवाई, जिसमें एन. जे. ए. सी. को अपने प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता होती है, अस्वीकार करने के बराबर है। एन. जे. ए. सी. द्वारा किया गया प्रस्ताव-यदि एन. जे. ए. सी.

पहले किए गए प्रस्ताव को दोहराएँ, राष्ट्रपति ने भी धारा 7 की शर्तें इसके अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य थीं। (जैसा कि एन. जे. ए. सी. अधिनियम की धारा 7 के तहत दूसरे परंतुक से स्पष्ट है)।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014

- एस. 8-संयोजक के कार्यों की वैधता, संदर्भ के साथ

एनजेएसी के लिए - एस. 8 सरकार के सचिव के लिए प्रावधान करता है

न्याय विभाग में भारत के संयोजक होने के लिए

एन. जे. ए. सी.-यह तर्क दिया गया कि ऐसी भारी जिम्मेदारी,

इसे अकेले कार्यपालिका पर नहीं छोड़ा जा सकता था यह अनिवार्य था कि

की कार्यवाही में सभी कार्यकारी भागीदारी को बाहर करना

एनजेएसी-आयोजित (प्रति खेहर, जे.): यह पहले ही निष्कर्ष निकाला जा चुका है,

कि कानून के प्रभारी केंद्रीय मंत्री की भागीदारी

और एन. जे. ए. सी. के सदस्य के रूप में न्याय, जैसा कि विचार किया गया है।
नियुक्ति के मामले में अनुच्छेद 124 ए (1) के तहत

न्यायाधीशों की

उच्च न्यायपालिका को, की अवधारणाओं का उल्लंघन होगा

"शक्तियों का पृथक्करण और स्वतंत्रता

न्यायपालिका ", जो दोनों निर्विवाद रूप से इसके घटक हैं

"भारत के संविधान की मूल संरचना-ठीक उसी के लिए

एक ही कारण से, एस. 8 कानून में टिकाऊ नहीं है-जैसे एक निकाय में

एन. जे. ए. सी., प्रशासनिक कार्यप्रणाली के अधीन नहीं हो सकता है।

कार्यकारी या विधायी नियंत्रण-केवल शेष

वैकल्पिक रूप से, इस तरह के निकाय, [2015] 13 एस. सी. आर. का प्रशासनिक नियंत्रण निहित करना है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायपालिका के साथ।

भारत का संविधान-न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया द्वारा अलग रखा गया संशोधन-परिणाम-विवादित

पाँच न्यायाधीशों द्वारा रद्द किया गया संविधान (99 वां संशोधन) अधिनियम

सुप्रीम कोर्ट की बेंच, "बुनियादी" का उल्लंघन करती है

संविधान की संरचना-अनुच्छेद 124 का प्रभाव,

127, 128, 217, 222, 224, 224 ए और 232, जैसा कि वे पहले से मौजूद थे

विवादित संशोधन के लिए, पुनर्जीवित होगा; और इस तरह के

पुनरुत्थान, दूसरे और तीसरे में दिए गए निर्णय

न्यायाधीशों के मामले, फिर से चयन को विनियमित करेंगे और

नियुक्तियाँ, साथ ही, उच्च न्यायाधीशों का स्थानांतरण

न्यायपालिका-आयोजित (प्रति खेहर, जे.): वर्तमान स्थिति एक है

जहाँ, एक प्रक्रिया द्वारा विवादित संवैधानिक संशोधन

न्यायिक समीक्षा को दरकिनार कर दिया गया है-जैसे कि

स्थिति, जो भी आक्षेप का कारण और प्रभाव हो

संवैधानिक संशोधन, वही माना जाएगा

एक तरफ रखा, और संशोधन से पहले की स्थिति होगी

पुनर्स्थापित-इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके चरण या चरण क्या हैं

संशोधन का कारण और प्रभाव, सभी चरण और

कदमों को उसी तरह नकार दिया जाएगा जैसे वे थे
संशोधित प्रावधान

संशोधन द्वारा प्रस्तुत किया गया, जब

अलग रखे जाते हैं-यदि न तो विवादित संवैधानिक

न ही संविधान के संशोधित प्रावधान

बच जाएगा, यह संवैधानिक के टूटने का कारण बनेगा
के तरीके का संबंध है, तंत्र में ऐसी कोई कमी या अंतराल होगा

जहां तक न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति

उच्च न्यायपालिका का संबंध है-ऐसी स्थिति व्याख्या की किसी भी ठोस प्रक्रिया का परिणाम नहीं हो सकती है

संविधान को अधिनियमित करते समय संसद का स्पष्ट इरादा

(99th संशोधन) अधिनियम, एक नई प्रक्रिया के लिए प्रदान करने के लिए था
में न्यायाधीशों का चयन और नियुक्ति

उच्च न्यायपालिका

मौजूदा प्रावधानों में संशोधन करके-स्वाभाविक रूप से इसलिए,
प्रक्रिया का प्रतिपादन करता है

जब संशोधित प्रावधान एक अलग

चयन और सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं की मूल प्रक्रिया को अलग रखा जाता है-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई.

अपरिवर्तित प्रावधानों के तहत नियुक्ति फिर से शुरू होगी

-जब कोई निर्णय रद्द कर दिया जाता है, तो कोई संशोधन या निरसन

विधायिका द्वारा, यह स्वाभाविक है कि पूर्व स्थिति बहाल हो जाएगी-विवादित को अलग करने के साथ

संविधान (99 वां संशोधन) अधिनियम, 2014

संविधान में संशोधन करने की मांग की गई,

स्वचालित रूप से पुनर्जीवित हो जाएगा और यथास्थिति बनी रहेगी

पुनर्स्थापित-संविधान (नब्बे-नौवां संशोधन) अधिनियम, 2014

न्यायपालिका-उच्च न्यायपालिका-संवैधानिक न्यायालय

न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण।

भारत का संविधान-कला। 124 ए-की वैधता

राष्ट्रीय न्यायपालिका का संविधान और संरचना

नियुक्ति आयोग (एनजेएसी)-आयोजित (प्रति खेहर, जे.): अनुच्छेद 124 ए संविधान की इमारत (99 वीं) है।

संशोधन) अधिनियम, 2014-अनुच्छेद 124 ए को निरस्त करना।
पूर्ववत करने की ओर ले जाएगा

स्वचालित रूप से संशोधनों को

अनुच्छेद 124, 124 ख, 124 सी, 127, 128, 217, 222, 224,
कि बाद वाला

224 ए और 232-यह, सरल कारण के लिए,

अनुच्छेद तभी टिकाऊ होते हैं जब अनुच्छेद 124 ए को बरकरार रखा जाता है-यदि

अपनी संपूर्णता में-अनुच्छेद 124 ए (1) के खंड (ए) और (बी) में ऐसा नहीं है न्यायपालिका को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करना

एन. जे. ए. सी. में घटक, अनुच्छेद 124 ए (1) के खंड (ए) और (बी) न्यायपालिका की प्रधानता को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त हैं,

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति का मामला (साथ ही मुख्य न्यायाधीशों का स्थानांतरण और न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में)-वही हैं

तदनुसार, "स्वतंत्रता" के सिद्धांत का उल्लंघन

न्यायपालिका "अनुच्छेद 124 ए (1) का खंड (सी) अधिकार से बाहर है

संविधान के प्रावधान, के समावेश के कारण कानून और न्याय के प्रभारी केंद्रीय मंत्री एक पूर्व मंत्री के रूप में

एन. जे. ए. सी. के अधिकारी सदस्य-अनुच्छेद 124 ए (1) का खंड (सी) सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर. की स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर प्रभाव डालता है।

न्यायपालिका ", साथ ही, "शक्तियों का पृथक्करण "इसके अलावा, खंड

(घ) अनुच्छेद 124 ए (1) जो दो को शामिल करने का प्रावधान करता है। "एन. जे. ए. सी. के सदस्यों के रूप में प्रतिष्ठित व्यक्ति अधिकार से बाहर हैं।

विभिन्न कारणों से संविधान के प्रावधान

यही संविधान के "मूल ढांचे" का उल्लंघन है।

मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में, के सभी खंड (ए) से (डी)

-

अनुच्छेद 124 ए (1) को दरकिनार किया जा सकता है।

तदनुसार निरस्त किया गया-अनुच्छेद के निरस्त होने को देखते हुए

124 ए (1), संपूर्ण संविधान (99 वां संशोधन) अधिनियम, 2014

अलग रखे जाने के लिए उत्तरदायी है-वही तदनुसार है

प्रावधानों के अधिकार से बाहर होने के कारण इसे पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया

संविधान-संविधान (99 वां संशोधन) अधिनियम, 2014 - न्यायपालिका-उच्च न्यायपालिका-संवैधानिक न्यायालय

- न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण-प्रक्रिया।

भारत का संविधान-Art.124C-की वैधता-आयोजित (प्रति
खेहर, जे.): राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियाँ
आयोग अधिनियम, 2014 अन्य बातों के साथ-साथ कला से निकलता है। 124 सी.
एन. जे. ए. सी. की अनुपस्थिति में इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है।
कला के तहत गठित। 124 ए (1)-कला के बाद से। 124 ए और 124 सी
एक प्राकृतिक परिणाम के रूप में अलग रखा गया है, राष्ट्रीय
न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014 भी उत्तरदायी है।
अलग रखा जाना है, और उसी के अनुसार एतद्वारा मारा जाता है
नीचे-उपरोक्त को देखते हुए, यह आवश्यक नहीं था कि के व्यक्तिगत प्रावधानों के संवैधानिक
अधिकारों की जाँच की गई
एन. जे. ए. सी. अधिनियम-फिर भी, धाराओं को चुनौती दी गई
5, 6, 7 और उनमें से 8 की जाँच की गई है। 5, 6 और 8 में से
एन. जे. ए. सी. अधिनियम के प्रावधानों को अधिकार से बाहर पाया गया
संविधान-राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग
अधिनियम, 2014-एसएस। 5, 6 और 8-न्यायपालिका-उच्च न्यायपालिका -
संवैधानिक न्यायालय-न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण
- प्रक्रिया।

न्यायपालिका-उच्च न्यायपालिका-संवैधानिक न्यायालय -

न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण-संवैधानिक इतिहास भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति
के संबंध में-चर्चा की गई-सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई.

आयोजित (प्रति लोकर, जे.): जिन निष्कर्षों से निकाला जा सकता है
पृष्ठभूमि के ऐतिहासिक तथ्य इस प्रकार हैं: (1) द.

न्यायपालिका की स्वतंत्रता को हमेशा मान्यता दी गई है
और सभी संबंधित लोगों द्वारा स्वीकार किया गया-(2) पहले
स्वतंत्रता, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति
पूरी तरह से क्राउन का विवेकाधिकार था-संविधान
विधानसभा ने महसूस किया कि इस तरह की 'सर्वोच्च और पूर्ण' शक्ति राष्ट्रपति या उस समय की सरकार में
निहित नहीं होनी चाहिए या
भारत के मुख्य न्यायाधीश (एक व्यक्ति के रूप में) और इसलिए एक बंधनकर्ता
राष्ट्रपति से माँग करके उस शक्ति पर रखा गया था
अनिवार्य रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करें (अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करने का
विवेकाधिकार)
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश-न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए
उच्च न्यायालय का भी, मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श
भारत अनिवार्य था-इसके अलावा, प्रमुख के साथ परामर्श
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल थे अनिवार्य-महत्वपूर्ण रूप से, परामर्श का
कोई उल्लेख नहीं है
(3) नियुक्ति की प्रक्रिया में राष्ट्रपति की व्यक्तिगत भूमिका के बारे में कोई संदेह
न्यायाधीशों की संख्या कम हो गई और यह स्पष्ट था कि राष्ट्रपति से केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य
करने की अपेक्षा की जाती थी
— (4) इसी तरह, भारत के मुख्य न्यायाधीश से यह उम्मीद नहीं की जाती है कि
व्यक्तिगत या व्यक्तिगत क्षमता में कार्य करें लेकिन उनसे परामर्श करना चाहिए
उसके वरिष्ठ न्यायाधीशों के लिए सिफारिश करने से पहले न्यायाधीश की नियुक्ति-(5) डॉ.
अम्बेडकर और
संविधान सभा ने 'निरंकुश विवेक' को स्वीकार नहीं किया
संविधान सभा की बहसों (सी. ए. डी.) में सिद्धांत लेकिन यह
विचार को बाद में प्रथम न्यायाधीशों के मामले में खारिज कर दिया गया था जो
न्याय द्वारा प्रस्तावित अंतिम शक्ति सिद्धांत को लाया गया
भगवती और न्यायमूर्ति देसाई-(6) कार्यपालिका में हस्तक्षेप

नियुक्ति प्रक्रिया (शायद एक अनौपचारिक तरीके से) 'अधिग्रहण' स्वतंत्रता के समय के आसपास शुरू हुआ था

और स्वतंत्रता के बाद उग्र हो गया, चरम पर पहुँच गया

1980 के दशक के अंत में-(7) एक भी उदाहरण नहीं दिया गया जहां सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

राष्ट्रपति ने न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए एक व्यक्ति की सिफारिश की

कोई उदाहरण नहीं दिया गया था) लेकिन इसे रूट करने की आवश्यकता थी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से, के अनुसार

प्रक्रिया ज्ञापन-(8) केवल एक उदाहरण था

दिए गए, प्रथम न्यायाधीशों के मामले से पहले जहां एक के रूप में नियुक्ति

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सहमति के बिना बनाया गया था

भारत के मुख्य न्यायाधीश का-प्रथम न्यायाधीशों के मामले के बाद इस तरह की सात नियुक्तियों की गई-यह एक

स्पष्ट संकेत है कि 'अंतिम शक्ति' सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया प्रथम न्यायाधीशों के मामले में 'पूर्ण कार्यकारी' में अनुवादित

प्रधानता 'डॉ. अम्बेडकर का सपना एक दुःस्वप्न बन गया,

राजनीतिक कार्यपालिका को धन्यवाद-(9) 'अंतिम शक्ति'

सिद्धांत या 'निरपेक्ष कार्यकारी प्रधानता' सिद्धांत अब कमजोर हो गया है।

और न्यायाधीश की नियुक्ति में अंतिम शब्द

सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश के बीच साझा किया जाता है।

द्वितीय न्यायाधीशों के मामले के संदर्भ में भारत का न्याय और

तीसरा न्यायाधीश मामला-ऐतिहासिक रूप से, कार्यपालिका को अंतिम शब्द देने की कम से कम वकील द्वारा आलोचना की गई है

कानून की अध्यक्षता करने वाले जनरल श्री एम. सी. सीतलवाड़ भारत आयोग जब 14 वीं रिपोर्ट दी गई थी-कि

प्रणाली ने ठीक से काम नहीं किया है जैसा कि समय-समय पर उल्लेख किया गया है

- (10) संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग के साथ-साथ एक जिम्मेदार न्यायाधीश

हाउस ऑफ लॉर्ड्स की राय थी कि प्रक्रिया के लिए

द्वितीय न्यायाधीशों के मामले और तृतीय न्यायाधीशों के मामले में निर्धारित न्यायाधीशों की नियुक्ति व्यापक रूप से उद्देश्य को पूरा करती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखना और

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक उपयुक्त विधि प्रदान करना।

न्यायपालिका-उच्च न्यायपालिका-संवैधानिक न्यायालय

न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण-प्रक्रिया-‘पूर्ण कार्यकारी प्रधानता’ प्रणाली या ‘अंतिम शक्ति’ सिद्धांत और सर्वोच्च न्यायालय अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई.

न्यायाधीशों की नियुक्ति की ‘कॉलेजियम प्रणाली’ का प्रतिपादन किया गया

द्वितीय न्यायाधीशों के मामले और तृतीय न्यायाधीशों के मामले द्वारा -

चर्चा-आयोजित (प्रति लोकुर, जे.): दोनों ‘पूर्ण कार्यकारी’

प्रधानता ‘प्रणाली या’ अंतिम शक्ति ‘सिद्धांत और

अपने समय में न्यायालय और उच्च न्यायालय स्वीकार्य प्रणालियाँ थीं-दुर्भाग्य से ‘कार्यकारी प्रधानता’ प्रणाली, कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा दुरुपयोग बहुमूल्य काम कर सकता है

इसके बारे में बहुत कम, क्योंकि न्यायाधीश कानून के शासन द्वारा बाध्य हैं-यह इस दुरुपयोग के कारण है कि संवैधानिक प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के बार के कहने पर पुनर्विचार किया गया था

यही अंतर्दृष्टि है जिसके परिणामस्वरूप द्वितीय न्यायाधीशों का मामला और संविधान की सार्थक और व्यावहारिक व्याख्या

यह कहना कि कॉलेजियम प्रणाली विफल हो गई है और इसकी आवश्यकता है

प्रतिस्थापन सही या उचित पोस्टमॉर्टम नहीं होगा।

न्यायपालिका-उच्च न्यायपालिका-संवैधानिक न्यायालय -

न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण-प्रक्रिया-प्रक्रिया

सिफारिश चरण और सिफारिश के बाद का चरण - द्वितीय न्यायाधीशों के मामले का प्रभाव और प्रभाव-संविधान के अनुच्छेद 124 (2) और अनुच्छेद 217 (1) में होने वाला ‘परामर्श’

संविधान-अर्थ-आयोजित (प्रति लोकुर, जे.): प्रक्रिया.

न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति का विचार

सिफारिश किए जाने से पहले एक स्तर पर दोनों महत्वपूर्ण हैं

भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उनके परामर्श से किया गया
का गठन करते हुए और उसके बाद भी

उसके सहयोगी, एक 'कॉलेजियम'

· भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा कार्यपालिका को सिफारिश भेजी जाती है-दोनों चरणों में, प्रक्रिया सहभागी होती है -

पूर्व-अनुशंसा चरण, यह एक सहभागी प्रक्रिया है

भारत के मुख्य न्यायाधीश और उनके सहयोगियों को शामिल करते हुए,

कॉलेजियम का गठन-इस स्तर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों की राय लेते हैं और

यदि आवश्यक समझा जाए तो कोई और-यह चरण भी

इसमें कार्यपालिका की भागीदारी शामिल है क्योंकि यह [2015] 13 एस. सी. आर. में है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस चरण में कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यपालिका से किसी व्यक्ति की कमजोरियों, यदि कोई हो, के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं जो

अंततः इस पद पर एक न्यायाधीश नियुक्त किया जाए

अनुशंसा चरण भी प्रक्रिया सहभागी है लेकिन

कार्यपालिका के पास होने की स्थिति में मुख्य रूप से कार्यपालिका के साथ

किसी विशेष व्यक्ति की नियुक्ति पर कुछ आपत्ति

लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले मजबूत और ठोस कारण -

इसलिए, जब किसी व्यक्ति को नियुक्ति के लिए माना जाता है

एक न्यायाधीश, वहाँ व्यापक और गहन भागीदारी है

मुख्य न्यायाधीश के समक्ष न्यायपालिका के भीतर परामर्श

भारत वास्तव में नियुक्ति के लिए एक व्यक्ति की सिफारिश करता है

न्यायाधीश; और सिफारिश किए जाने के बाद, वहाँ है

इससे पहले कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच परामर्श
प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है-विचार करने में कठिनाई और
एक सिफारिश को स्वीकार करना केवल तभी उत्पन्न होता है जब
विचार-विमर्श के दौरान मतभेद

कार्यपालिका और न्यायपालिका-दूसरे न्यायाधीशों का मामला
हल करता है-- पूर्व में

इस विवाद को प्रभावी ढंग से

किसी व्यक्तिगत विशेषता से संबंधित सामग्री के कब्जे में है या
चरित्र की कमजोरी जो ज्ञात नहीं है

एक वकील या एक न्यायाधीश के

भारत के मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को और जो संभावित रूप से उस व्यक्ति को
अयोग्य ठहरा सकता है

एक उपयुक्त उम्मीदवार की सिफारिश करने की जिम्मेदारी
दृष्टिकोण को प्रधानता दी जाती है

न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति, के

न्यायपालिका (मुख्य न्यायाधीश के दृष्टिकोण से प्रतीकित)

भारत) जो सामग्री का वजन और वस्तुनिष्ठ रूप से विचार करेगा या
वांछनीयता पर अंतिम निर्णय लें

जानकारी दें और

नियुक्ति-भारत के मुख्य न्यायाधीश, अच्छे के लिए

कारणवश, कार्यपालिका के दृष्टिकोण को स्वीकार करें या अच्छे कारण से भी कार्यपालिका के दृष्टिकोण को
स्वीकार न करें-यह इस सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं-ऑन-रिकॉर्ड में है।

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई.

217 (1) संविधान को समझना होगा-संविधान

भारत सरकार-अनुच्छेद 124 (2) और 217 (1)।

न्यायपालिका-उच्च न्यायपालिका-संवैधानिक न्यायालय -

न्यायाधीशों की नियुक्ति-99 वां संविधान संशोधन अधिनियम

अन्य बातों के साथ-साथ अनुच्छेद 124 (2) में संशोधन किया गया और अनुच्छेद 124 ए पेश किया गया।

- संविधान के अनुच्छेद 124 (2) में एन. जे. ए. सी. की आवश्यकता थी

अनुच्छेद 124 ए के तहत गठित करने के लिए सिफारिश करना

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति

न्यायालय या उच्च न्यायालय-एन. जे. ए. सी. और राष्ट्रपति की भूमिका

चर्चा-आयोजित (प्रति लोकुर, जे.): इस पर कोई स्पष्टता नहीं है

राष्ट्रपति की भूमिका-किसी भी स्थिति में, राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करने के लिए उपलब्ध विवेकाधिकार

न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला हटा लिया जाता है -

राष्ट्रपति का निर्णय दो लोगों की राय के अधीन है। प्रतिष्ठित व्यक्ति जिनमें से कोई भी संवैधानिक रूप से नहीं है

जवाबदेह-अच्छी तरह से स्थापित पर संदेह है

मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी का सिद्धांत-एक कानून-एनजेएसी अधिनियम,

संविधान राष्ट्रपति को इसके विपरीत बाध्य नहीं करता है

संवैधानिक ढांचा-99 वां संविधान संशोधन

अधिनियम अनुच्छेद में गंभीर और असंवैधानिक हस्तक्षेप करता है

124 (2) संविधान का, जैसा कि मूल रूप से बनाया गया था-संविधान

(99 वां संशोधन) अधिनियम, 2014।

न्यायपालिका-उच्च न्यायपालिका-संवैधानिक न्यायालय -

न्यायाधीशों की नियुक्ति-भारत के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका

और न्यायपालिका-99 वें संविधान संशोधन के संदर्भ में

अधिनियम और एन. जे. ए. सी. अधिनियम-चर्चा-आयोजित (प्रति लोकुर, जे.):

न्यायपालिका की सर्वसम्मत राय को खारिज किया जा सकता है

दो प्रतिष्ठित व्यक्ति या एक प्रतिष्ठित व्यक्ति और कानून

मंत्री (जिसकी राय मंत्रिपरिषद की राय के अधीन है, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है)

एक संस्था के रूप में न्यायपालिका की सर्वसम्मत राय, और

राय जिसका सम्मान किया गया था (और योग्य रूप से) के लिए मायने रखता है
के पारित होने के साथ वस्तुतः कुछ भी नहीं सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

99 वें संविधान

संशोधन अधिनियम और एन. जे. ए. सी. अधिनियम-मुख्य न्यायाधीश

भारत को 99 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया है

एक मात्र मतदान आँकड़ा और एन. जे. ए. सी. में छह में से एक

वस्तुतः उसे संवैधानिक जिम्मेदारी से वंचित करना।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करना और उनकी निंदा करना / उसे इतिहास द्वारा प्रदत्त अधिकार, संवैधानिक

सम्मेलन और संविधान-भारत के मुख्य न्यायाधीश

और न्यायपालिका की संस्था अब वीटो के अधीन है

अपने निर्णयों में नागरिक समाज की पूरी योजना संविधान द्वारा अभिनिर्धारित न्यायाधीशों की नियुक्ति

99 वें संविधान द्वारा विधानसभा को अस्थिर बना दिया गया है।

संशोधन अधिनियम और एनजेएसी अधिनियम-संविधान (नब्बे)

नौवां संशोधन) अधिनियम, 2014 राष्ट्रीय न्यायिक

नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014।

न्यायपालिका-उच्च न्यायपालिका-संवैधानिक न्यायालय

न्यायाधीशों की नियुक्ति-में प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति

एन. जे. ए. सी.-चुनौती-आयोजित (प्रति लोकुर, जे.): सिद्धांत रूप में, वहाँ

न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में जीवन के सभी क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ परामर्श करने पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती-लेकिन

कि ये प्रतिष्ठित व्यक्ति एक निर्णय को वीटो कर सकते हैं जो लिया जाता है

सर्वसम्मति से या अन्यथा भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा (

अन्य न्यायाधीशों और संभवतः अन्य प्रतिष्ठित न्यायाधीशों के साथ परामर्श

व्यक्ति) अकल्पनीय है-यह वस्तुतः एक राजतंत्र प्रदान करता है

एन. जे. ए. सी. में प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर शक्ति, बिना किसी शक्ति के

कोई भी जवाबदेही-प्रतिष्ठित व्यक्तियों की श्रेणियाँ होनी चाहिए जनजाति, अन्य तक सीमित नहीं होना

अनुसूचित जाति, अनुसूचित

पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक या महिलाएँ लेकिन यह एक मामला है नहीं कहा जा सकता है, इसके अलावा

नीति और इसके बारे में और कुछ

एक पुनर्विचार आवश्यक है-इसके लिए कोई दिशानिर्देश नहीं हो सकते हैं

यह तय करना कि उद्देश्यों के लिए कौन एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है या नहीं है
लिए नामांकन का, लेकिन यह कि विकल्प एक पर छोड़ दिया गया है

एन. जे. ए. सी. के

उच्चाधिकार प्राप्त समिति एक पर्याप्त जाँच है, बशर्ते

समिति का निर्णय सर्वसम्मत है।

न्यायपालिका-उच्च न्यायपालिका-संवैधानिक न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई.

न्यायाधीशों की नियुक्ति-कानून मंत्री की उपस्थिति

एन. जे. ए. सी.-इस आधार पर चुनौती है कि भारत संघ

अदालतों में सबसे बड़ा वादी और कानून मंत्री होना

एन. जे. ए. सी. के सदस्य के रूप में मेला के लिए हानिकारक साबित हो सकता है।
उत्पादक नहीं है-आयोजित (प्रति लोकुर, जे.): द.

चयन, यदि प्रति-

न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हमेशा रहा है

में कार्यपालिका के बहिष्कार के आसपास केंद्रित किया गया था

निर्णय लेना, लेकिन कानून मंत्री को शामिल करना

एन. जे. ए. सी. प्रति-उत्पादक, ऐतिहासिक रूप से प्रति-बहुसंख्यकवादी है।

और में व्यक्त विभिन्न विचारों के अनाज के खिलाफ जाता है

विभिन्न समितियाँ-अधिक, क्योंकि कानून मंत्री कर सकते हैं निर्णय लेने वाले निकाय में वीटो का
प्रयोग करें-एन. जे. ए. सी. में कानून मंत्री की उपस्थिति पूरी तरह से अनावश्यक और खराब है।

सलाह-एन. जे. ए. सी. में कानून मंत्री की उपस्थिति मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी के सिद्धांत पर संदेह पैदा करती
है।

न्यायपालिका-उच्च न्यायपालिका-संवैधानिक न्यायालय -

न्यायाधीशों की नियुक्ति-संविधान का अनुच्छेद 124 (2)

जैसा कि मूल रूप से तैयार किया गया था, राष्ट्रपति के लिए इसे अनिवार्य बना दिया गया था

न्यायाधीशों की नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करें

- एन. जे. ए. सी. और अनिवार्य परामर्श पर प्रभाव-आयोजित (प्रति

लोकुर, जे.): 99 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम और
 एन. जे. ए. सी. अधिनियम ने परामर्श प्रक्रिया को एक प्रहसन बना दिया है।
 - एक सार्थक सहभागी परामर्श प्रक्रिया अब नहीं है
 मौजूद है-न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश के बीच साझा जिम्मेदारी है
 के चिंतन से परे एक शरीर पर पारित किया गया
 संविधान सभा-प्रतिबद्ध होने की संभावना
 न्यायाधीश और एक प्रतिबद्ध होने के परिणाम
 न्यायपालिका, एक ऐसी न्यायपालिका जो स्वतंत्र नहीं हो सकती है
 अकल्पनीय।

न्यायपालिका-उच्च न्यायपालिका-संवैधानिक न्यायालय

—
 न्यायाधीशों की नियुक्ति-एन. जे. ए. सी. और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति-आयोजित (प्रति
 लोकुर, जे.): संयुक्त प्रभाव

99 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम और [2015] 13 एस. सी. आर. की धारा 6।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एन. जे. ए. सी. अधिनियम यह है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति पर पूरा नियंत्रण एन. जे. ए. सी.
 द्वारा लिया जाता है और

ए के मुख्य न्यायाधीश के साथ प्रतिमान पूरी तरह से बदल जाता है

उच्च न्यायालय ने एक अनिवार्य सलाहकार से डाउनग्रेड किया, और

नियुक्ति के लिए सिफारिश के प्रवर्तक संविधान के अनुच्छेद 217 (1) द्वारा अभिनिर्धारित

पारंपरिक रूप से समझा जाता है, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो केवल बनाता है

किए गए नामांकन के संबंध में एक या दूसरे तरीके से - नियुक्ति के लिए सिफारिश शुरू करने की
 प्रक्रिया

एक न्यायाधीश, जिसे आम तौर पर स्वतंत्रता के बाद से स्वीकार किया गया है,

मौलिक रूप से परिवर्तित किया गया, अच्छी तरह से स्थापित संवैधानिक के साथ

सम्मेलनों को छोटी छूट दी जा रही है-मुख्य न्यायाधीश
 उच्च न्यायालय को नामित करने की भूमिका में घटा दिया गया है
 अधिकारी, जिसकी राय केवल नामांकन उद्देश्यों के लिए ली जाती है
 लेकिन इतने महत्वपूर्ण मामले में सलाहकार के रूप में नहीं लिया गया
 न्यायाधीश की नियुक्ति-दिया गया संवैधानिक महत्व
 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पूरी तरह से
 लगभग एक गायब होने वाले बिंदु तक नीचे चला गया-का संविधान
 भारत-कला। 217 (1) - संविधान (नब्बे-नौवां) संशोधन
 अधिनियम, 2014-राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम
 2014 - एस. 6. -

न्यायपालिका-उच्च न्यायपालिका-संवैधानिक न्यायालय -
 न्यायाधीशों की नियुक्ति-एन. जे. ए. सी. के संयोजक
 विभाग में भारत सरकार के सचिव
 न्याय धारा 8 (3) के संदर्भ में एन. जे. ए. सी. का संयोजक है।
 एन. जे. ए. सी. अधिनियम-आयोजित (प्रति लोकुर, जे.): कर्तव्यों और
 संयोजक की जिम्मेदारियों का वर्णन नहीं किया गया है
 एन. जे. ए. सी. अधिनियम और अधिनियम के तहत नियम और विनियम तैयार नहीं किए गए हैं-इसलिए
 इसकी सलाहना करना मुश्किल है।
 वे कार्य जो संयोजक से करने की अपेक्षा की जाती है-कि
 इसके अलावा, सचिव सरकार का एक अधिकारी होता है और एन. जे. ए. सी. के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है-
 सचिव को वेतन दिया जाता है।
 और सरकारी खजाने से मिलने वाले भत्ते-यह काफी उत्कृष्ट अदालत के वकील हैं-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई.

सीधे अपने संबंधित मुख्य न्यायाधीश के प्रति जवाबदेह हैं - इसके अलावा, उनका वेतन और भत्ते इस
 पर लिए जाते हैं -

भारत की समेकित निधि-इनकी 'स्वतंत्रता'

सचिव के रहते हुए अधिकारियों का रखरखाव किया जाता है

न्याय विभाग में भारत सरकार नहीं है -

एन. जे. ए. सी. को निरंतरता से वंचित करके और एक अर्थ में इसे छोड़कर, कार्यपालिका की सनक और इच्छाओं पर बदला जा सकता है। उच्च और शुष्क जब भी यह कार्यपालिका को प्रसन्न करता है-यह है

स्पष्ट रूप से आपत्तिजनक-राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियाँ

आयोग अधिनियम, 2014-एस। 8(3)।

न्यायपालिका-- उच्च न्यायपालिका-- संवैधानिक न्यायालय

न्यायाधीशों की नियुक्ति-गोपनीयता की आवश्यकताएँ

एन. जे. ए. सी. का कार्य-संचालन (प्रति लोकुर, जे.): संतुलन

पारदर्शिता और गोपनीयता के बीच बहुत नाजुक है और यदि किसी विशेष व्यक्ति के बारे में कुछ संवेदनशील जानकारी है सार्वजनिक किया जाता है, इसका उस पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है

प्रतिष्ठा और गरिमा-99 वां संविधान संशोधन

अधिनियम और एन. जे. ए. सी. अधिनियम ने गोपनीयता पर ध्यान नहीं दिया है

एक व्यक्ति की चिंताएँ-यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह था

महान्यायवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया कि

एन. जे. ए. सी. पूरी तरह से पारदर्शी होगा और कोई भी कर सकता है।

एन. जे. ए. सी. के पास उपलब्ध जानकारी तक पहुंच हो -

यह एक व्यापक सामान्यीकरण है जो स्पष्ट रूप से करता है।

किसी ऐसे व्यक्ति की निजता को ध्यान में न रखें जो

नियुक्ति के लिए अनुशंसित, विशेष रूप से एक न्यायाधीश के रूप में उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में

न्यायालय-जानने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन

सबसे अच्छा यह एक अंतर्निहित मौलिक अधिकार है और इसके साथ हेज किया गया है

निजता का अंतर्निहित मौलिक अधिकार जिसका सभी लोग आनंद लेते हैं

दोनों निहित मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन

इसे बनाए रखना मुश्किल है, लेकिन 99 वें संविधान संशोधन अधिनियम और एन. जे. ए. सी. अधिनियम इस पर विचार करने का प्रयास भी नहीं करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.
केवल उस संतुलन को प्राप्त करें-संविधान (नब्बे-नौवां)
संशोधन) अधिनियम, 2014-राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियाँ
आयोग अधिनियम, 2014।

न्यायपालिका-उच्च न्यायपालिका-संवैधानिक न्यायालय
न्यायाधीशों की नियुक्ति-99 वां संविधान संशोधन अधिनियम
संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन के रूप में घोषित -
प्रभाव-आयोजित (प्रति लोकुर, जे.): संवैधानिक प्रावधान

99 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित 99 वें संविधान की घोषणा पर जीवन में
वापसी

संशोधन अधिनियम असंवैधानिक संविधान है (नब्बे
नौवां) संशोधन अधिनियम, 2014।

संविधान (नब्बे-नौवां संशोधन) अधिनियम, 2014

की वैधता-आयोजित (प्रति लोकुर, जे.): यह मूल संरचना को बदल देता है।

संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को लागू करके उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में
न्यायाधीशों की नियुक्ति

अदालतें और पुनर्लेखन कला। 124 (2) और Art.217 (1)

संविधान, जिससे गंभीर रूप से समझौता किया जाता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता-
परिणामस्वरूप, 99 वां

संविधान संशोधन अधिनियम असंवैधानिक है -

99 संविधान संशोधन अधिनियम पूरी तरह से बदल गया है

संवैधानिक स्थिति और भूमिका को बदल दिया

नियुक्ति प्रक्रिया में भी काफी हद तक राष्ट्रपति

भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ अनिवार्य परामर्श को संशोधित किया और पूरी प्रक्रिया को एक द्वारा
प्रतिस्थापित या प्रतिस्थापित किया एन. जे. ए. सी. की सिफारिश-99 वां संविधान

संशोधन अधिनियम और एन. जे. ए. सी. अधिनियम की एक श्रृंखला

अनुत्तरित प्रश्न-यह सच है कि संविधान ऐसा नहीं कर सकता।
निर्दिष्ट और शामिल करें।

विशेष रूप से प्रत्येक विवरण को

प्रक्रियात्मक विवरण-लेकिन एक ही समय में, मूल

एन. जे. ए. सी. योजना की आवश्यकताएँ स्पष्ट होनी चाहिए

एन. जे. ए. सी. के साथ पढ़ा गया 99 वां संविधान संशोधन अधिनियम
जब यह एक मौजूदा विधि को उखाड़ फेंकने का प्रयास करता है

अधिनियम, विशेष रूप से

न्यायाधीशों की नियुक्ति जो स्वतंत्रता बनाए रखती है

न्यायपालिका के-महत्वपूर्ण मुद्दों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं को हल करने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई.

पूरक विधान के माध्यम से बाद की तारीख में या

पूरक अधीनस्थ विधान, अन्यथा

अस्वास्थ्यकर अंतराल बनाया जाएगा, जिससे स्थिति और खराब हो जाएगी

- भारत का संविधान-कला। 124 (2) और 217 (1)।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014-आयोजित की वैधता (प्रति लोकुर, जे.): 99 वें संविधान के बाद से

संशोधन अधिनियम असंवैधानिक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014

99 वां संविधान संशोधन अधिनियम स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता है

कानून की पुस्तकों पर जीवित रहें-अन्यथा भी, यह उल्लंघन करता है

उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति में मूल मनमानेपन को सक्षम करके संविधान का अनुच्छेद 14

न्यायालय और उच्च न्यायालय-न्यायपालिका-उच्च न्यायपालिका - संवैधानिक न्यायालय-न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण

- भारत का संविधान-कला। 14.

न्यायपालिका-उच्च न्यायपालिका-संवैधानिक न्यायालय -

न्यायाधीशों की नियुक्ति-न्यायपालिका की स्वतंत्रता और
नियुक्ति प्रक्रिया-आयोजित (प्रति लोकुर, जे.): द.
न्यायपालिका की स्वतंत्रता नियुक्ति के साथ शुरू होती है
न्यायाधीश की नियुक्ति-इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायाधीश की नियुक्ति
उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का एक अभिन्न अंग है
न्यायपालिका की स्वतंत्रता-हालाँकि, यह संभव नहीं है
महान्यायवादी से सहमत होना जब वह कहता है कि हालाँकि
न्यायाधीश की नियुक्ति स्वतंत्रता का एक हिस्सा है न्यायपालिका, यह एक छोटा सा हिस्सा है और
निश्चित रूप से एक नहीं है
न्यायपालिका की स्वतंत्रता-नियुक्ति की प्रक्रिया और किसी उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में
न्यायाधीश की वास्तविक नियुक्ति
सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्रता का एक प्रमुख हिस्सा है।
न्यायपालिका का और इसलिए, बुनियादी का एक अभिन्न अंग
संविधान की संरचना। भारत का संविधान-चुनौती के आधारों में संशोधन-चुनौती देने के आधारों
में अंतर
संसदीय प्रतिमा-आयोजित (प्रति लोकुर, जे.):

एक संशोधन सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

संविधान को तभी चुनौती दी जा सकती है जब यह बुनियादी ढाँचे को बदल दे।

विधानमंडल; (2) यह संविधान के अनुच्छेद 13 का उल्लंघन करता है; संविधान में निषेध के विपरीत
अधिनियमित किया गया है; और

(4) यह निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना अधिनियमित किया जाता है संविधान-
सिद्धांत/सिद्धांत-बुनियादी संरचना

सिद्धांत।

न्यायपालिका-उच्च न्यायपालिका-संवैधानिक न्यायालय -

न्यायाधीशों की नियुक्ति-विचार किए जाने वाले कारक-आयोजित

(प्रति लोकुर, जे.): दो महत्वपूर्ण कारक हैं-(1) पेशेवर

कौशल, न्यायिक क्षमता, उपयुक्तता और स्वभाव

एक अच्छा न्यायाधीश होने के लिए व्यक्ति, और (2) व्यक्तिगत शक्तियाँ,

उस व्यक्ति की कमजोरियाँ, आदतें और लक्षण-जहाँ तक

व्यावसायिक कौशल, न्यायिक क्षमता, उपयुक्तता और

एक व्यक्ति के एक अच्छे न्यायाधीश होने के स्वभाव का संबंध है, उस मूल्यांकन को करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति

भारत के मुख्य न्यायाधीश बनें (दूसरे के परामर्श से)

न्यायाधीश) और कानूनी विरादरी के बाहर का कोई व्यक्ति नहीं

दूसरी ओर, जहाँ तक व्यक्तिगत ताकतों की बात है

किसी व्यक्ति की कमजोरियों, आदतों और लक्षणों से संबंधित हैं,

उचित जानकारी केवल कार्यपालिका से ही मिल सकती है, क्योंकि भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को इसकी जानकारी नहीं होगी।

उनमें से-भारत के मुख्य न्यायाधीश इस संबंध में 'विशेषज्ञ' हैं

संभावित जबकि कार्यकारी के संबंध में 'विशेषज्ञ' है

पूर्ववर्ती और व्यक्तिगत लक्षण-चूंकि इन दो पहलुओं

एक इच्छुक न्यायाधीश का व्यक्तित्व निस्संदेह अलग होता है,

न्यायपालिका के बीच मतभेद नहीं हो सकते।

और इस संबंध में कार्यपालिका क्योंकि वे दोनों एक व्यक्त करते हैं

व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर राय प्रमुख जस्टिस ऑफ इंडिया की 'विशेषज्ञ राय' पर टिप्पणी नहीं कर सकते।

कार्यपालिका और न ही कार्यपालिका विशेषज्ञ पर टिप्पणी कर सकती है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय।

न्यायपालिका-उच्च न्यायपालिका-संवैधानिक न्यायालय-सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई.

न्यायाधीशों की नियुक्ति-संविधान (99-9)

संशोधन) अधिनियम, 2014-राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियाँ

आयोग अधिनियम, 2014-आयोजित की वैधता (प्रति लोकुर, जे.):

द्वितीय न्यायाधीशों के मामले ने स्वीकार किया कि राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति द्वारा की गई सिफारिश को अस्वीकार करने का विवेकाधिकार है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश, लेकिन केवल कुछ शर्तों के तहत

परिस्थितियाँ-यह विवेक पर बंधन था राष्ट्रपति-हालाँकि, 99 वां संविधान संशोधन अधिनियम

और एन. जे. ए. सी. अधिनियम ने विवेक को पूरी तरह से छीन लिया है। राष्ट्रपति की एक सिफारिश को अस्वीकार करने के लिए

एक न्यायाधीश की नियुक्ति, संवैधानिक को कम करना

राष्ट्रपति का महत्व-99 वां संविधान

संशोधन अधिनियम और एनजेएसी अधिनियम ने इसे हटा दिया है।

लेकिन केवल एन. जे. ए. सी. की सिफारिश को ध्यान में रखना और उससे आगे की यात्रा न करें-एक बार फिर, संवैधानिक

राष्ट्रपति का महत्व और महत्व काफी है

कम किया गया, अगर नहीं लिया गया-99 वां संविधान संशोधन

अधिनियम और एन. जे. ए. सी. अधिनियम ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (दोनों व्यक्तिगत रूप से) के अधिकार को काफी सीमित और कम कर दिया है।

साथ ही संस्थागत रूप से) और भारत के मुख्य न्यायाधीश अब हैं

अन्य न्यायाधीशों या किसी की राय लेने से वर्जित एन. जे. ए. सी. के बाहर का व्यक्ति-भारत के मुख्य न्यायाधीश ने

एक संस्थागत प्रमुख से एक व्यक्तिगत व्यक्ति तक कम कर दिया गया

99 वां संविधान संशोधन अधिनियम और एनजेएसी अधिनियम

द्वितीय न्यायाधीशों के मामले और तृतीय न्यायाधीशों के मामले में सुविचारित प्रक्रिया को उलट दिया और भारत के मुख्य न्यायाधीश का संवैधानिक अधिकार और स्थापित

यह एन. जे. ए. सी. के लिए शोषण करने के लिए एक थाली पर है-हमारे संवैधानिक को देखते हुए

इतिहास, स्थापित सम्मेलन, विभिन्न लोगों के विचार पिछले सत्तर वर्षों में समितियाँ और उनके विचार

श्री मोतीलाल सीतलवाड़ के साथ शुरू होने वाले कई कानूनी दिग्गज, जिन दौर से न्यायपालिका गुजरी है

कई दशक और हमारे संविधान के प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

संविधान में अनुच्छेद 124 ए

संविधान (नब्बे-नौवां संशोधन) अधिनियम, 2014 न्यायपालिका की स्वतंत्रता और इन मामलों में बाधा डालता है -

न्यायाधीशों की नियुक्ति (जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का एक मूलभूत और अभिन्न अंग है) और बुनियादी नियमों को बदल देती है।

असंवैधानिक-संविधान के अन्य प्रावधान (99 वां संशोधन) अधिनियम, 2014 कायम नहीं रह सकता है।

स्वयं और इसलिए भी असंवैधानिक घोषित किए जाते हैं - इसी तरह, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग

अधिनियम, 2014 मनमाना और अपरिवर्तित शक्तियाँ प्रदान करता है

कानून के तहत विभिन्न प्राधिकरण और यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है संविधान का और असंवैधानिक घोषित किया गया है-यहां तक कि

अन्यथा, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग

अधिनियम, 2014 के अभाव में अकेले नहीं खड़ा हो सकता है

संविधान (नब्बे-नौवां संशोधन) अधिनियम, 2014-इस घोषणा का परिणाम यह है कि कॉलेजियम प्रणाली ' द्वितीय न्यायाधीश मामले और तृतीय न्यायाधीशों द्वारा अभिनिर्धारित

मामला फिर से शुरू हो जाता है-हालांकि, नियुक्ति की प्रक्रिया इन निर्णयों में निर्धारित न्यायाधीशों के साथ पढ़ा जाता है

(संशोधित) प्रक्रिया ज्ञापन पर निश्चित रूप से जुर्माना लगाने की आवश्यकता है

ट्रूनिंग-एक 'परिणाम सुनवाई' की आवश्यकता है

भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों के लिए मामले में सहायता करें

नियुक्ति की प्रक्रिया और प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करें

न्यायाधीश, इसे आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए

लोग, इसे अधिक पारदर्शी और सामाजिक के अनुरूप बनाने के लिए

आवश्यकताएँ, और विशेष रूप से, पाँचवें न्यायाधीश के मामले से बचने के लिए

संविधान (99 वां संशोधन) अधिनियम, 2014-राष्ट्रीय

न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014।

संविधान (99 वां संशोधन) अधिनियम, 2014 -

न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की वैधता
संरचना-पर चर्चा की गई

संवैधानिक न्यायालय-योजना और

- आयोजित (प्रति कुरियन, जे.): कार्य के पहले चरण में

संविधान के अनुसार, कार्यपालिका ने सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं-ऑन-रिकॉर्ड में ऊपरी हाथ होने का दावा किया

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई.

नियुक्ति और भारत के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश

संबंधित उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को केवल

'परामर्श' ; अभिव्यक्ति को अक्सर इसके शाब्दिक रूप में समझा जाता है

अर्थ-निर्णय कार्यकारी द्वारा लिया गया था

मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी-यह प्रक्रिया जांच के दायरे में आई
के फैसले में

समशेर सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट

जिसमें सात न्यायाधीशों की पीठ ने अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया कि

"न्यायपालिका की स्वतंत्रता" का एक प्रमुख सिद्धांत है
द्वारा संरक्षित है

संविधान जो "सुसंगत अनुच्छेद निर्माण

भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श अनिवार्य "और

कि "सभी संभावित मामलों में उस उच्चतम के साथ परामर्श करें

भारतीय न्याय के गणमान्य व्यक्ति द्वारा स्वीकार किया जाएगा और किया जाना चाहिए

भारत सरकार "-प्रथम से निपटने वाली पीठ

न्यायाधीशों का मामला, जिसमें केवल सात का कोरम था,
चार के बहुमत के साथ -

अन्यथा आयोजित, हालांकि तीन के खिलाफ

दूसरे न्यायाधीशों के मामले में नौ-न्यायाधीशों की पीठ

उस नियुक्ति को अभिनिर्धारित करते हुए प्रथम न्यायाधीशों के मामले को खारिज कर दिया
 उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के प्रपत्र
 न्यायपालिका की स्वतंत्रता का एक अभिन्न अंग, कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता न्यायपालिका की मूल
 संरचना का हिस्सा है।
 भारत का संविधान, और इसलिए, कार्यपालिका नहीं कर सकती है
 के मामले में न्यायपालिका की प्रधानता में हस्तक्षेप
 नियुक्तियाँ-तीसरा न्यायाधीश मामला, 1998 में, केवल एक
 में सिद्धांतों के काम करने का व्याख्यात्मक विस्तार
 प्रक्रिया को संस्थागत बनाकर दूसरा न्यायाधीश मामला
 संवैधानिक रूप से आवंटित न्यायपालिका की सर्वोच्चता क्षेत्र को दूसरे और तीसरे न्यायाधीशों के
 मामलों द्वारा बहाल किया गया था यह पीठ इस अनुपात से बाध्य है कि
 न्यायपालिका संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है और वह
 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और
 उच्चतम न्यायालय की अवधारणा का एक अभिन्न अंग है
 न्यायपालिका की स्वतंत्रता-और उस सरल कारण के लिए,
 संविधान 99 वें संशोधन को असंवैधानिक घोषित किया गया है-[2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट
 न्यायपालिका-उच्च न्यायपालिका-संवैधानिक न्यायालय।
 राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014
 - की वैधता-आयोजित (प्रति कुरियन, जे.): चूंकि यह आयोजित किया जा रहा है
 बहुमत कि स्वयं संशोधन अर्थात् संविधान 99 वां
 संशोधन खराब है, वैधता से निपटने का कोई मतलब नहीं है
 संशोधन के सृजन का, अर्थात्, राष्ट्रीय न्यायिक
 नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014-इसके तहत अस्तित्व में नहीं है।

कानून-न्यायपालिका-उच्च न्यायपालिका-संवैधानिक न्यायालय - न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण।

संवैधानिक कानून-संविधान की व्याख्या

संवैधानिक तर्कों की विशिष्टता-"ऐतिहासिक", "पाठ्य",

"संरचनात्मक", "विवेकपूर्ण", "सैद्धांतिक" और "नैतिक"-का प्रभाव

संविधान का 99 वां संशोधन-आयोजित (प्रति कुरियन, जे.): में।

संविधान की व्याख्या करते हुए, सभी उपकरणों को होना चाहिए उचित रूप से उपयोग किया जाता है, और अक्सर, संयोजन में भी -

वर्तमान मामले में, संविधान 99 वां संशोधन है

नियुक्ति के लिए एक नई संवैधानिक योजना शुरू की गई

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश -

तीन संवैधानिक शाखाएँ, उनकी शक्तियाँ और कार्य संविधान, और उनके अंतर संबंध महत्वपूर्ण हैं

वर्तमान मामले में विश्लेषण किए जाने वाले मुद्दे, 'संरचनात्मक उपकरण'

मुद्दों को हल करने के लिए प्रमुखता से लागू किया जाना है-वैधता

संविधान के 99 वें संशोधन का परीक्षण मूल संरचना के सिद्धांत की कसौटी पर किया जाना है-पृथक्करण

शक्तियों की संख्या भारत के संविधान की विवर्तनिक संरचना है

संवैधानिक योजना के तहत, एक शाखा नहीं है

संवैधानिक रूप से सौंपे गए कार्यों में अनुचित तरीके से हस्तक्षेप करना

एक अन्य शाखा की शक्तियाँ और कार्य-अनुमेय

हस्तक्षेप के क्षेत्र नियंत्रण और संतुलन हैं-लेकिन वहाँ प्रत्येक शाखा के लिए कुछ विशिष्ट क्षेत्र हैं जो हो सकते हैं

प्रत्येक शाखा की केंद्रीय शक्तियों पर-एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका बनाने के लिए मूल संरचना को कमजोर करने का कोई भी प्रयास। दूरस्थ संभावना है, इसे अंकुर में निपटा जाना है-सर्वोच्च न्यायालय विज्ञापन-चालू-रिकॉर्ड

संसद के पास संविधान को अस्थिर करने की कोई शक्ति नहीं है-संविधान का 99 वां संशोधन संरचनात्मक ढांचे को बाधित करता है। शक्तियों का वितरण, और इसलिए, यह अस्वीकार्य है -

संविधान (99 वां संशोधन) अधिनियम, 2014।

न्यायपालिका-उच्च न्यायपालिका-संवैधानिक न्यायालय -

न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण नई योजना

संविधान के संदर्भ में परिकल्पित (नब्बे-नौवें)

संशोधन) कॉलेजियम प्रणाली को बदलने के लिए अधिनियम, 2014

भले ही उक्त संवैधानिक संशोधन है

गिराया, कॉलेजियम पुनर्जीवित नहीं होता है-आयोजित (प्रति

कुरियन, जे.): यह तर्क आम लोगों को भी पसंद नहीं आता है

99 वें संशोधन ने कुछ को 'प्रतिस्थापित' करने की मांग की

संविधान में प्रावधान और कुछ नए प्रावधान शामिल करें।

एक बार एक के माध्यम से प्रतिस्थापन और सम्मिलन की प्रक्रिया

संवैधानिक संशोधन को ही खराब माना जाता है और अस्वीकार्य, पूर्व-संशोधित प्रावधान स्वचालित रूप से संविधान को पुनर्जीवित और पुनर्जीवित करते हैं (नब्बे-नौवें -

संशोधन) अधिनियम, 2014।

न्यायपालिका-उच्च न्यायपालिका-संवैधानिक न्यायालय -

उसमें सुधार की आवश्यकता-आयोजित (प्रति कुरियन, जे.): द. वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव है

और वस्तुनिष्ठता-विश्वास की कमी ने विश्वसनीयता को प्रभावित किया है कॉलेजियम प्रणाली, जैसा कि कभी-कभी नागरिक द्वारा देखा जाता है

समाज-अक्सर, बहुत गंभीर आरोप और कई ए

समय भी निराधार नहीं है, यह उठाया गया है कि इसका दृष्टिकोण

अत्यधिक व्यक्तिपरक रहा है-आरोप निश्चित रूप से एक गहरे आत्मनिरीक्षण की मांग करते हैं-यह अभी तक एक ठीक होने वाली स्थिति है-नहीं

संदेह है, गलती पूरी तरह से कॉलेजियम की नहीं है-दूसरा

और तीसरे न्यायाधीशों के मामले में प्रभावी उपकरण प्रदान किए गए थे

विचलन रोकने के लिए कार्यपालिका के हाथ-कार्यपालिका

शायद ही कभी उन उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है-इसलिए, कॉलेजियम प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है

'ग्लासनोस्ट' और 'एक' पेरिस्त्रोइका ; और इसलिए मामले को अदालत की रिपोर्ट को ऊपर रखने की आवश्यकता है

[2015] 13 एस सी आर।

इस संबंध में आगे सुना जाए।

भारत का संविधान Art.368-का संशोधन

संविधान-संसद की शक्ति पर सीमा

संविधान में संशोधन-मूल संरचना का परीक्षण-आयोजित (प्रति

गोयल, जे.): संविधान का अनुच्छेद 368 शक्ति प्रदान करता है -

संविधान और उसके लिए प्रक्रिया में संशोधन-ए

अंततः सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मामले से निर्धारित किया जाना है मामले में।

भारत का संविधान-बुनियादी संरचना/विशेषता-क्या

है-आयोजित (प्रति गोयल, जे.): क्या संविधान की कोई विशेषता है क्या मूल विशेषता है या मूल संरचना का हिस्सा संविधान की योजना में इसके स्थान को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना है

और के काम करने पर इसके इनकार का परिणाम संविधान।

न्यायपालिका-न्यायपालिका और लोकतंत्र-आयोजित (गोयल के अनुसार,

जे.): यह निष्पक्षता में लोगों का विश्वास है और

न्यायपालिका की क्षमता जो लोकतंत्र को बनाए रखती है -

न्यायपालिका को शक्ति को नियंत्रित करने की शक्ति सौंपी गई है

कार्यपालिका और विधानमंडल पर जब भी यह आरोप लगाया जाता है कि

कहा कि अंगों ने उनके संवैधानिक रूप से सौंपे गए अंगों को पार कर लिया है

अधिकार-यही लोकतंत्र का सार है।

न्यायपालिका-उच्च न्यायपालिका-संवैधानिक न्यायालय -

न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण-योजना और संरचना

- क्या न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायपालिका की प्रधानता है

मूल संरचना का हिस्सा-आयोजित (प्रति गोयल, जे.): के निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह स्वतंत्रता निर्धारित की है कि

न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा बुनियादी संरचना का हिस्सा हैं -

तीनों विभागों के बीच शक्तियों का व्यापक विभाजन राज्य का नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का एक हिस्सा है-यह है

लोकतंत्र का भी एक हिस्सा-न्यायपालिका की स्वतंत्रता है संविधान की पूरी योजना का अभिन्न अंग जिसके बिना सर्वोच्च न्यायालय अधिवक्ताओं को-चालू-रिकॉर्ड करता है

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई.

न तो संविधान की प्रधानता और न ही संघीय चरित्र, सामाजिक लोकतंत्र और न ही समानता और स्वतंत्रता के अधिकार हो सकते हैं

प्रभावी-दूसरे और तीसरे न्यायाधीशों में पहले के निर्णय '

मामले को बाध्यकारी उदाहरण के रूप में लिया जाना चाहिए-एक बार ऐसा हो जाने के बाद, यह माना जाना चाहिए कि नियुक्ति में न्यायपालिका की प्रधानता है

न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हिस्सा है-यह मूल संरचना का हिस्सा है

न्यायपालिका की निष्पक्षता और क्षमता में लोग

जो लोकतंत्र को बनाए रखता है-यदि न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो

न्यायपालिका के कामकाज का अभिन्न अंग प्रभावित या नियंत्रित है

कार्यपालिका द्वारा, यह निश्चित रूप से न्यायाधीशों की निष्पक्षता को प्रभावित करेगा

और उनकी कार्यप्रणाली-की स्वीकृत योजना संविधान और इसका कार्य प्रभुत्व की अनुमति देना नहीं है

न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका-संशोधन द्वारा भी

न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायपालिका की प्रधानता नहीं हो सकती

बहिष्कृत-संवैधानिकता के अनुमान की याचिका हो सकती है

कोई लाभ नहीं जहां की एक स्थापित बुनियादी विशेषता

संविधान को क्षतिग्रस्त करने की मांग की गई है-इसी तरह, याचिका

कि संसद की आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए सबसे अच्छी तरह से सुसज्जित है लोग
शक्ति का विस्तार करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं हैं

संसद संविधान की मूल विशेषता में संशोधन करेगी -

समय का परिवर्तन न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की बड़ी भूमिका को उचित नहीं ठहराता है -

न्यायपालिका के पूरे कामकाज में प्रमुख तत्व है

संविधान और ऐसी स्वतंत्रता पूरी तरह से कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़ी हुई है।

मौजूदा कार्य में कोई कथित कमी

न्यायाधीशों की नियुक्ति का तंत्र अपने आप में उचित नहीं हो सकता है।

एक बार आयोजित होने के बाद मौजूदा योजना में परिवर्तन या क्षति

बुनियादी विशेषता का हिस्सा बनना-न्यायपालिका की प्रधानता और सीमित न्यायाधीशों की
नियुक्ति में कार्यपालिका की भूमिका संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है-न्यायपालिका की प्रधानता

एक प्रस्ताव शुरू करने और उसे अंतिम रूप देने में है-सीजेआई इस मामले में अंतिम शब्द है-
कार्यपालिका को अदालत की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है

[2015] 13 एस सी आर।

प्रस्ताव की शुरुआत करने से पहले सुझाव दें और दें

प्रस्तावित उम्मीदवारों के चरित्र और पूर्ववृत्त पर प्रतिक्रिया और प्रकट की गई नियुक्ति पर आपत्ति

द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों के मामलों में दिए गए कारण।

न्यायपालिका-उच्च न्यायपालिका-संवैधानिक न्यायालय -

न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण-संविधान में संशोधन

योजना और संरचना-राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियाँ

संविधान के तत्वावधान में गठित आयोग (एनजेएसी) (नब्बे-नौवां संशोधन) अधिनियम, 2014 को
राष्ट्रीय संशोधन के साथ पढ़ा जाता है।

इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश, अध्यक्ष, पदेन शामिल हैं;
न्यायालय के दो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश

मुख्य न्यायाधीश के बगल में सर्वोच्च

सदस्यों के रूप में भारत का न्याय, पदेन; केंद्रीय मंत्री सदस्य के रूप में विधि और न्याय का
प्रभार, पदेन; और दो प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिन्हें एक समिति द्वारा नामित किया जाएगा

जिसमें प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं

परिवर्तित या क्षतिग्रस्त-आयोजित (प्रति गोयल, जे.): संयुक्त राष्ट्र के तहत न्यायाधीशों की
नियुक्ति की संशोधित योजना, जो एक बुनियादी योजना है

संविधान की विशेषता, राष्ट्रपति को बनाना है

नियुक्ति, सी. जे. आई. के साथ परामर्श के बाद

न्यायपालिका-सी. जे. आई. के विचारों को नजरअंदाज करने की अनुमति है।

दर्ज किए गए कारणों के लिए असाधारण स्थितियों में असर

उम्मीदवार के चरित्र और पूर्ववृत्त पर और यदि ऐसा है

कारण सीजेआई को स्वीकार्य पाए जाते हैं-के तहत संशोधित योजना, ऐसा कोई अंतिम
दृष्टिकोण नहीं लिया जा सकता है

सीजेआई-बिना कोई कारण बताए, मंत्री या

नामित सदस्य सर्वसम्मत दृष्टिकोण को अस्वीकार कर सकते हैं

न्यायाधीश-उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसके सदस्य नहीं हैं

आयोग की कोई संवैधानिक भूमिका नहीं है

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति/स्थानांतरण-मात्र तथ्य यह है कि न्यायाधीशों के
बिना, मंत्री और नामित सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई.

सदस्य एक नियुक्ति नहीं कर सकते हैं जो इसके बराबर नहीं है

ऐसी स्थिति जहाँ स्वयं सीजेआई द्वारा निर्णय लिया जाता है न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करना-
भले ही दो प्रतिष्ठित लोगों की नियुक्ति में हो

सदस्य सीजेआई भी समिति के सदस्य हैं, तथ्य यह है कि

कि प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता के पास है

ऐसे सदस्यों की नियुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका, जिनकी होगी

शक्ति न केवल सीजेआई और दो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों के बराबर है

न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में सर्वोच्च न्यायालय का

उच्चतम न्यायालय और न्यायाधीशों की नियुक्ति/स्थानांतरण
अस्वीकार करने का भी अधिकार

उच्च न्यायालय लेकिन सर्वसम्मत को

सीजेआई और दो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों का प्रस्ताव -

न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए अनुकूल-नियुक्ति
नियुक्ति/स्थानांतरण

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, निश्चित रूप से प्रभावित हो सकते हैं

कानून मंत्री और दो नामित सदस्यों द्वारा काफी हद तक,

जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित होती है -

संशोधन सर्वसम्मत होने की प्रधानता को भी समाप्त कर देता है

न्यायिक सदस्यों की राय इस प्रकार नहीं है
न्यायपालिका की प्रधानता

नियुक्ति को अंतिम रूप देने के लिए पर्याप्त-

जैसा कि हमेशा न्यायिक उदाहरणों को बाध्य करने में समझा जाता है
अंतिम कॉल लेना शामिल है-ये

इसमें नाम की शुरुआत और

न्यायपालिका की प्रधानता की पहचान दो मुख्य विशेषताओं से होती है।

प्रधानता की इस अवधारणा से समझौता किया जाता है यदि न्यायपालिका

- पहली बार में प्रस्ताव शुरू करने में असमर्थ या यदि ऐसा है

प्रस्ताव को प्रभावी रूप से अस्वीकार किया जा सकता है-इसका प्रभाव
की नियुक्ति की जा सकती है

जिसके तहत न्यायाधीशों

कानून मंत्री द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली कार्यपालिका का प्रभाव

प्रमुख आवाज न्यायपालिका की नहीं है-इसका प्रभाव
न्यायाधीशों को उनका ऋण चुकाना होगा

नियुक्तियाँ ऐसी होंगी कि नियुक्त किए गए

कार्यपालिका में नियुक्तियाँ जो विनाशकारी हो सकती हैं

न्यायपालिका का सार्वजनिक विश्वास और निष्पक्षता और

एक महत्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट के रूप में न्यायपालिका की भूमिका को प्रतिकूल रूप से प्रभावित
करता है

[2015] 13 एस सी आर।

निष्पक्ष संवैधानिक अंग-न्यायाधीशों की नियुक्ति में संवैधानिक रूप से प्रदत्त न्यायिक प्रधानता को कम नहीं किया जा सकता है।

नीचे या उन लोगों द्वारा नियंत्रित होने की मांग की जाती है जिन्हें नहीं दिया जाता है या इस तरह के कार्यों को संभालने की अनुमति-यहां तक कि प्रदान करना

सबसे अच्छा इरादा, संसद से परे कार्य नहीं कर सका

संविधान द्वारा इसे प्रदत्त अधिकार-इस प्रकार, न्यायपालिका की प्रधानता को दूर करना या किसी को ऐसी प्रधानता प्रदान करना

निकाय जो उक्त अवधारणा के बराबर नहीं है, निश्चित रूप से नहीं है

संसद के पास उपलब्ध एक विकल्प-का संविधान

भारत की अपनी पृष्ठभूमि और व्यक्तित्व है-भारत के मॉडल

नुकसान पहुंचाने के लिए अन्य देशों का आख मूंदकर पालन नहीं किया जा सकता था

भारतीय संविधान की पहचान और व्यक्तित्व - महान्यायवादी द्वारा निर्दिष्ट न्यायिक आयोग

की पूर्व-विद्यमान भूमिका को कम करने की प्रवृत्ति न दिखाएँ

न्यायपालिका-वास्तव में, प्रवृत्ति पूर्व-विद्यमान को कम करने की है।

कार्यपालिका की भूमिका-विवादित संशोधन में यह है - इस प्रकार विपरीत, अन्य लोगों के काम करने का विवाद

अन्य देशों में अलग-अलग रचनाएँ उचित नहीं ठहराती हैं विवादित संशोधन जो मूल संरचना के विपरीत है

भारतीय संविधान-विवाद में कोई योग्यता नहीं है

कि वर्तमान मामले में केवल एक संवैधानिक में परिवर्तन

प्रावधान किसी बुनियादी विशेषता को नुकसान नहीं पहुंचाता है-यह

क्रीज को इस्त्री करने के लिए सरल संशोधन का मामला नहीं है-इसका

प्रभाव स्पष्ट रूप से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है-पूर्व

इस योजना के तहत संविधान की मूल विशेषता को नुकसान पहुंचाता है न्यायाधीशों की नियुक्ति में कौन सी प्रधानता होनी चाहिए

न्यायपालिका-नई योजना के तहत इस तरह की प्रधानता दी गई है

अनुमति दिए जाने पर-इस प्रकार विवादित संशोधन को कायम नहीं रखा जा सकता-संविधान (नब्बे-नौवां संशोधन) अधिनियम,

2014.

न्यायपालिका-उच्च न्यायपालिका-संवैधानिक न्यायालय -

न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण-सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं में संशोधन-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई.

योजना और संरचना-राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियाँ
के तत्वावधान में स्थापित आयोग (एन. जे. ए. सी.)

संविधान (नब्बे-नौवां संशोधन) अधिनियम, 2014

न्यायाधीशों में कानून मंत्री और दो प्रतिष्ठित शामिल हैं।
जाने वाले व्यक्ति -

एक निर्दिष्ट समिति द्वारा नामित किए

प्रतिष्ठित व्यक्ति को अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों में से नामित किया जाना था, अनुसूचित

जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक या महिलाएँ
आरक्षण

नामित सदस्यों में से एक के लिए ऐसा

चुनौती-आयोजित (प्रति गोयल, जे.): संविधान के विचार
स्पष्ट रूप से उस भूमिका को दर्शाती हैं

निर्माता और प्रतिष्ठित विशेषज्ञ समितियाँ

न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए।

और मोटे तौर पर उम्मीदवारों के चरित्र और पूर्ववृत्त की जांच करने के लिए सीमित है और अंत में मूल्यांकन
करने के लिए नहीं

ऐसे उम्मीदवारों की योग्यता और उपयुक्तता-इस दृष्टिकोण से

मामला, भले ही यह तर्क कि किसी दिशानिर्देश की आवश्यकता नहीं थी

प्रतिष्ठित व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए मानदंड के लिए जब

समिति में उच्च गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे जिन्हें स्वीकार किया जाता है।

तथ्य यह है कि ऐसे व्यक्ति केवल नहीं खेलेंगे

सर्वोच्च की नियुक्ति में सहायक लेकिन पूर्व-प्रमुख भूमिका

न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो अनुकूल नहीं होंगे

न्यायपालिका की स्वतंत्रता-इसका कोई औचित्य नहीं है

नामित सदस्यों में से एक के लिए आरक्षण निर्दिष्ट श्रेणियाँ-ऐसा प्रावधान योजना के खिलाफ है।
 संविधान और विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर न्यायाधीशों का चयन करने के उद्देश्य के विपरीत-नियुक्ति की प्रकृति
 किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या उनके लिए किसी भी सकारात्मक कार्यवाई को उचित नहीं ठहराता है।
 अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या महिलाएँ
 उम्मीदवारों की उपयुक्तता-धर्म, जाति या लिंग मूल्यांकनकर्ता की कोई प्रासंगिकता नहीं है।
 न्यायपालिका-उच्च न्यायपालिका-संवैधानिक न्यायालय-[2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण-मूल्यांकन और

न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय-आयोजित (जे. गोयल के अनुसार): द.

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति आम तौर पर होती है उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों या वरिष्ठ न्यायाधीशों से बना

या प्रख्यात वकील या प्रख्यात न्यायविद जिनकी योग्यता बेहतर है।

वरिष्ठ न्यायाधीशों को पता है-उनका मूल्यांकन निष्पक्ष और किसी भी राजनीतिक या अन्य विचारों से मुक्त होना चाहिए-व्यक्ति चयन करने के लिए मूल्यांकन करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति की आवश्यकता होती है

उनकी योग्यता और उपयुक्तता-प्रमुख और निर्णायक भूमिका

न्यायपालिका की आवश्यकता न केवल स्वतंत्रता की है

न्यायपालिका और शक्तियों का पृथक्करण लेकिन प्रेरणा के लिए भी

ताकत के लिए बड़े पैमाने पर लोगों का विश्वास आवश्यक है

लोकतंत्र-उल्लंघन की शिकायत रखने वाले नागरिक

कार्यपालिका के खिलाफ उनके मौलिक और कानूनी अधिकारों का

या विधानमंडल उम्मीद करता है कि उनकी शिकायत पर विचार किया जाए

जिन व्यक्तियों की नियुक्तियाँ प्रभावित नहीं होती हैं

बाहरी प्रभाव, निष्पक्षता में विश्वास, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रतीक है, समाप्त हो जाएगा-योजना अन्य देशों में यांत्रिक रूप से पालन नहीं किया जा सकता है जब यह है

भारतीय संविधान की मूल योजना के विपरीत।

संवैधानिक कानून-संविधान का संशोधन -

'पहचान परीक्षण' और 'प्रभाव परीक्षण'-आयोजित (प्रति गोयल, जे.): द.

शब्द संशोधन का शाब्दिक अर्थ है बेहतर या सुधार।

और संशोधन का प्रायोजक हमेशा सुधार का दावा कर सकता है

- इस तरह के दावे का परीक्षण पहचान परीक्षण लागू करके किया जाना चाहिए '

और प्रभाव परीक्षण 'संशोधन को प्रभावित नहीं करना चाहिए

संविधान की योजना के काम करने पर संशोधन के प्रभाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए-इससे कुछ हद तक व्यक्तिपरक तत्व जो अपरिहार्य है

किसी भी कानून का परीक्षण करते समय जो कथित रूप से सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं का उल्लंघन करता है-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई.

मौलिक अधिकारों की अवधारणा पर न्यायसंगत

'उचित प्रतिबंध' -इस संबंध में, कार्यपालिका का प्रभाव

हस्तक्षेप जिसे विशेषज्ञ अध्ययनों द्वारा प्रलेखित किया गया है

इस आधार पर अप्रासंगिक या उपेक्षित नहीं माना जा सकता है कि

यह संसद के विवेक का विषय है-यह केवल नहीं है

संशोधन का पाठ लेकिन इसका प्रभाव और क्षमता भी जो

मूल योजना की 'पहचान' को ध्यान में रखना होगा और नई योजना के तहत शक्ति की 'चौड़ाई'-नई

योजना क्रीज को इस्त्री कर सकती है लेकिन तंत्र को चाहिए

प्रतिस्थापित योजना शब्दों के साथ तुलनीय होना और

वाक्यांश-- "संशोधन"-का अर्थ।

न्यायपालिका-उच्च न्यायपालिका-संवैधानिक न्यायालय -

न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण-प्रक्रिया-नई योजना और संरचना-छह-सदस्य राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एन. जे. ए. सी.) का गठन-एन. जे. ए. सी. केंद्रीय कानून मंत्री और दो न्यायाधीशों के अलावा एक निर्दिष्ट समिति द्वारा नामित किए जाने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति-कानून मंत्री और दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति-यदि उचित-आयोजित (प्रति गोयल, जे.): नई योजना के तहत, कानून मंत्री को सीजेआई के बराबर भूमिका दी गई है-सही से संविधान की शुरुआत, कानून की यह भूमिका प्रक्रिया शुरू करते समय मंत्री की परिकल्पना कभी नहीं की गई थी और इसे अंतिम रूप देना-कानून मंत्री, सहभागी योजना में, कर सकते हैं किसी नाम का सुझाव देना या नामों पर अपनी टिप्पणी देना सबसे अच्छा है। प्रस्तावित लेकिन प्रस्ताव हमेशा द्वारा शुरू किया जा सकता था और किया गया था सीजेआई-दीक्षा के चरण में, यदि समान अधिकार है प्रदत्त, यह न्यायपालिका की प्रधानता को नष्ट कर देगा-अन्य दो व्यक्तियों को एक समिति द्वारा नामित किया जाएगा जो भी है प्रमुख राजनीतिक आवाज को सीजेआई के बराबर रखा जाएगा अपनी पहचान से परे योजना-किसी नाम की शुरुआत से पहले कोई भी सुझाव या दीक्षा के बाद भी प्रतिक्रिया उपयोगी हो सकती है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित नहीं कर सकता है लेकिन समान रूप से अंतिम [2015] 13 एस. सी. आर. में कानून मंत्री और दो बाहरी लोगों की भागीदारी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दीक्षा या नियुक्ति के लिए निर्णय हानिकारक हो सकता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता-इसे दूर नहीं किया जा सकता है यह मानते हुए कि कानून मंत्री और दो वितरक करेंगे किसी भी बाहरी विचार से प्रभावित न हों-ऐसा अनुमान स्वीकृत तथ्यात्मक के विपरीत होगा।

अनुभव-यह अलगाव की अवधारणा के खिलाफ भी होगा।
कार्यपालिका से न्यायपालिका का-इस पर अधिक विपरीत होगा
संविधान निर्माताओं के मूल उद्देश्य के लिए।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014

- एसएस। 2, 3, 5 (2), एस के लिए दूसरा प्रावधान। 5 (2), 5 (3), 6 (1), 6 (2), 6 (3),

6 (6), 6 (8), 8 & 13- एन. जे. ए. सी. अधिनियम की वैधता-आयोजित (प्रति गोल, जे.):

संविधान के बारे में निष्कर्ष को देखते हुए (नब्बे

नौवां संशोधन) अधिनियम की क्षमता से परे होना

संसद, इसकी वैधता पर चर्चा करना आवश्यक नहीं है

उक्त अधिनियम के रूप में एन. जे. ए. सी. अधिनियम संशोधन के बाद जीवित नहीं रह सकता है।
खारिज किया जाता है-हालांकि, इस विचार के अनुरूप कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायपालिका की प्रधानता नहीं हो सकती है

समझौता किया, और उस आधार पर न केवल एस। 2 में से

न्यायपालिका के साथ अनिवार्य परामर्श के साथ संशोधन, जैसा कि अपरिवर्तित के तहत विचार किया गया है

प्रावधान, एस. 3 एन. जे. ए. सी. को शक्ति प्रदान करना (अनुच्छेद के तहत)

124 ख) और आयोग के गठन के लिए प्रावधान करना।

सिफारिश करने में सीजेआई के बराबर प्रतिष्ठित व्यक्ति
न्यायाधीशों, प्रमुख के रूप में नियुक्तियाँ

सीजेआई, उच्चतम न्यायालय के

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश और
स्थानांतरण की सिफारिश करना

मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों के

उच्च न्यायालय असंवैधानिक हैं लेकिन अनुच्छेद 124 सी भी देते हैं
और स्थापित करने के लिए संसद को शक्ति

प्रक्रिया को विनियमित करने

प्रक्रियात्मक पहलू-एस में। 5 (2) 'उपयुक्तता मानदंड' होना बाकी है
किया गया-एस के लिए दूसरा परंतु।

विनियमों द्वारा तैयार

5 (2) और सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई.

एस. 6 (6) आयोग के दो सदस्यों को वीटो दें जो है संशोधन द्वारा विचार नहीं किया गया - एस. 5
(3) और एस. 6 (8)

द्वारा निर्धारित चयन के लिए शर्तों का प्रावधान करें

विनियम जो केवल प्रक्रियात्मक मामले नहीं हैं - एस. 6

पहले प्रस्ताव शुरू किए बिना उच्च न्यायालयों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा - धारा
6 (1) के लिए प्रावधान करता है

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए सिफारिश

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अंतर वरिष्ठता के आधार पर न्यायालय

यह अधिक से अधिक उच्च अधिकारियों को प्रतिनिधित्व देने को प्रभावित कर सकता है।

— न्यायालयों के रूप में व्यवहार्य, अंतर से वरिष्ठता में, कई न्यायाधीश केवल

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से नामांकन की मांग करना, लेकिन एस। 6 (3) आयोग को स्वयं बनाने
का अधिकार देता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए सिफारिश

और संक्षिप्त सूची के बाद मुख्य न्यायाधीश से टिप्पणी मांगें उम्मीदवार स्वयं - एस. 8 केंद्र
सरकार को सक्षम बनाता है

आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करना और

उनकी सेवा की शर्तों को निर्धारित करने के लिए-सचिव

सरकार आयोग की संयोजक है - एस. 13

संसद द्वारा सभी विनियमों को अनुमोदित करने की आवश्यकता होती है -

अधिनियम के ये प्रावधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बाधित करते हैं-भले ही बुनियादी संरचना का
सिद्धांत नहीं है। संसदीय कानून की वैधता का न्याय करने में लागू किया गया,

न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कानून का शासन अनुच्छेदों के अंग हैं। 14, 19 और संविधान
की धारा 21 और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अभाव उक्त मौलिकता को प्रभावित करता है।

अधिकार-एन. जे. ए. सी. अधिनियम इस प्रकार निरस्त होने योग्य है।

भारत का संविधान-कला। 124 ए, 124 बी और 124 सी।

न्यायपालिका-उच्च न्यायपालिका-संवैधानिक न्यायालय

न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण-प्रक्रिया

संशोधन-संशोधन का प्रभाव निरस्त किया जा रहा है -

आयोजित (प्रति गोयल, जे.): तर्क है कि भले ही संशोधन

शून्य माना जाता है, पूर्व-मौजूदा प्रणाली को सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट को बहाल नहीं किया जा सकता है

[2015] 13 एस सी आर।

न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए, ए

कोई तर्क नहीं है

—

प्रावधान को शून्य घोषित किया जा सकता है जिस मामले में कानूनी स्थिति

चूंकि यह इस तरह के शून्य प्रावधान के बिना है, इसलिए इसे प्रबल माना जा सकता है।

- यह ऐसी स्थिति नहीं है जब स्थिति स्पष्ट नहीं की गई हो।

किसी मुद्दे का निर्णय करते समय-संशोधन को निरस्त किए जाने पर,

पूर्व-विद्यमान प्रणाली पुनर्जीवित हो गई है-संविधान (नब्बे)

नौवां संशोधन) अधिनियम, 2014।

न्यायपालिका-उच्च न्यायपालिका-संवैधानिक न्यायालय

-

न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण-प्रक्रिया-समीक्षा मौजूदा प्रणाली के संचालन-आयोजित (प्रति गोयल, जे.): चूंकि संशोधन से पहले मौजूद प्रणाली को पुनर्जीवित किया जाएगा

संशोधन को निरस्त किए जाने और शिकायतों पर

इसकी कार्यप्रणाली के बारे में व्यक्त की गई शिकायतों पर विचार किया जाना चाहिए-ऐसी शिकायतों पर गौर किया जाना चाहिए। जिसके लिए मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की आवश्यकता है

-

विवादित संविधान संशोधन और एन. जे. ए. सी. अधिनियम असंवैधानिक के रूप में निरस्त- न्यायाधीशों की नियुक्ति की पूर्व-मौजूदा योजना को पुनर्जीवित किया गया है-मामले को सूचीबद्ध किया जाए

शिकायतों के बचे हुए मुद्दे पर विचार करने के लिए

पूर्व-विद्यमान प्रणाली का कार्यकरण-संविधान (नब्बे-नौवां)

संशोधन) अधिनियम, 2014-राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियाँ

आयोग अधिनियम, 2014।

न्यायपालिका-उच्च न्यायपालिका-संवैधानिक न्यायालय -

न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण -

संविधान-संविधान में इतिहास और बहस

सभा-भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श -

संसद की भूमिका की व्याख्या-आयोजित (प्रति

चेलमेश्वर, जे.) (अल्पसंख्यक राय): विधायी इतिहास
संविधान के सदस्य

यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि

विधानसभा ने स्पष्ट रूप से एक पूर्ण और निरंकुश निहित करने से इनकार कर दिया

किसी भी संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति

संविधान की तीन शाखाओं में से एक

विधानसभा ने संसद को कोई भूमिका सौंपने से इनकार कर दिया-यह

कार्यपालिका में एक बेलगाम शक्ति निहित करने से इनकार कर दिया-सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं में-
चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई.

उसी समय सीजेआई के प्रस्ताव से सहमत नहीं थे
आवश्यकता होती है-शब्द

किसी भी नियुक्ति के लिए सहमति की

'सहमति' के बजाय 'परामर्श' का उपयोग किया गया था, लेकिन वह था

कार्यपालिका के लिए बहुत कम, जो पहले निरपेक्ष थी
विवेकाधिकार-न्यायालय

भारत सरकार अधिनियमों के तहत

यह कभी नहीं माना गया कि परामर्श का अर्थ है सहमति जैसा कि माँगा जाता है
यहां तक कि संशोधन के लिए बताए गए उद्देश्यों और कारणों में भी व्याख्या की जानी चाहिए।

भारत का संविधान-प्रभाव में संशोधन-आयोजित

(प्रति चेलमेश्वर, जे.) (अल्पसंख्यक राय): एक का संशोधन

या एक बुनियादी विशेषता का गठन करने वाले कुछ लेख हो सकते हैं या
विनाश में परिणाम नहीं हो सकता है

के मूल संरचना के

संविधान-यह सब संदर्भ पर निर्भर करता है-एक ही अनुच्छेद के संशोधन के परिणामस्वरूप बुनियादी ढांचे का विनाश हो सकता है।

की प्रकृति के आधार पर संविधान की संरचना

मूल विशेषता और उसे निरस्त करने का संदर्भ

लेख यदि अनुच्छेद द्वारा उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है की मूल संरचना के लिए सर्वोत्कृष्ट का गठन करता है

संविधान।

न्यायपालिका-उच्च न्यायपालिका-संवैधानिक न्यायालय -

न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण-आयोजित (प्रति

चेलमेश्वर, जे.) (अल्पसंख्यक राय): कोई भी नियुक्ति

संविधान के तहत स्थापित प्रक्रिया अनिवार्य रूप से न केवल एक स्वतंत्र संगठन की स्थापना के लिए अनुकूल होनी चाहिए।

न्यायपालिका लेकिन इसकी दक्षता भी सुनिश्चित करती है-दो गुण

स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए आवश्यक।

न्यायपालिका-उच्च न्यायपालिका-संवैधानिक न्यायालय -

न्यायाधीशों की नियुक्ति-क्या राय की प्रधानता न्यायिक नियुक्तियों के मामले में न्यायपालिका आवश्यक है।

आयोजित (चेलमेश्वर, जे. के अनुसार) (अल्पसंख्यक राय): वहाँ है।

राय की प्रचुरता (विवेकपूर्ण और जिम्मेदार तरीके से) कानूनी विरादरी में नागरिक समाज के क्वार्टर, न्यायविद, सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

राजनीतिक सिद्धांतकार और विद्वान) कि न्यायपालिका की राय के लिए प्रधानता एक मानक या संवैधानिक मौलिक नहीं है एक स्वतंत्र और कुशल न्यायपालिका की स्थापना के लिए -

संविधान की मूल विशेषता इसकी प्रधानता नहीं है -

सीजेआई (कॉलेजियम) की राय लेकिन गैर-निवेश में निहित है

राष्ट्रपति (कार्यपालिका) में चयन करने की पूर्ण शक्ति और

जो लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है-तदनुसार, प्रधानता
न्यायपालिका की राय

न्यायपालिका के मामले में

यह धारणा कि न्यायिक शाखा की प्रधानता
प्रकार एक

नियुक्ति प्रक्रिया एक आवश्यक तत्व है और इस

मूल विशेषता बिना किसी आधार के अनुभवजन्य रूप से त्रुटिपूर्ण है।

न्यायपालिका-उच्च न्यायपालिका-संवैधानिक न्यायालय

न्यायाधीशों का चयन-छह के संदर्भ में परिकल्पित योजना

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के सदस्य (एन. जे. ए. सी.)-चाहे एन. जे. ए. सी. में कानून मंत्री की
उपस्थिति हो, जो प्रति मतदान शक्ति का 1/6 प्रदान करता है।

चेलमेश्वर, जे.) (अल्पसंख्यक राय): नहीं-अपने नियंत्रण में एक विशाल प्रशासनिक तंत्र के साथ कार्यपालिका
सक्षम है। के लिए विशाल और मूल्यवान योगदान देना

चयन प्रक्रिया-आपत्ति कुछ हद तक उचित है।

में कार्यकारी शाखा में विश्वास की कमी पर

यही तर्क न्यायिक शाखा पर भी लागू होता है, इस विश्वास के बावजूद कि यह सबसे कम खतरनाक
शाखा है

- संविधान सभा ने आराम करने से इनकार कर दिया

सीजेआई में भी विशेष विश्वास-सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए-चालू-
रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई.

चयन प्रक्रिया से कार्यपालक असंगत होगा।

इस मूलभूत आधार के साथ कि सरकार में लोकतंत्र जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा होता है

इस तरह के बहिष्कार का किसी अन्य लोकतंत्र में कोई समानांतर नहीं है।

जिनके मॉडल की संविधान सभा द्वारा जांच की गई थी

संवैधानिक सरकार के स्थापित सिद्धांत

अन्य लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्थाओं में प्रथाएं और यह तथ्य कि संविधान सभा ने एक भूमिका प्रदान की
क्योंकि कार्यपालिका स्पष्ट रूप से इस निष्कर्ष को प्रतिबंधित करती है कि कार्यपालिका

चयन प्रक्रिया में भागीदारी एक बुनियादी को निरस्त करती है

विशेषता-कार्यकारी शाखा का बहिष्करण विनाशकारी है

नियंत्रण और संतुलन की मूल विशेषता-एक मौलिक

संवैधानिक सिद्धांत में सिद्धांत।

भारत का संविधान-कला। 124 ए (1) (डी)-में स्थिरीकरण

अनुच्छेद 124 ए (1) (डी) कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियाँ

आयोग (एन. जे. ए. सी.) में प्रधानमंत्री की समिति द्वारा नामित दो प्रतिष्ठित व्यक्ति भी शामिल होने चाहिए।

मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के नेता

विपक्ष-आयोजित की वैधता (चेलमेश्वर, जे. के अनुसार)

(अल्पसंख्यक राय): यह विश्वास करना कि न्यायपालिका के सदस्य

केवल नियुक्ति प्रक्रिया में मूल्यवान निवेश ला सकता है

नागरिक समाज के लिए बहुत घमंड और अनादर की आवश्यकता है - न्यायिक शक्ति सहित सभी
शक्तियों का दुरुपयोग किया जा सकता है -

उपाय शक्ति के अनुदान से इनकार करना नहीं है, बल्कि इसकी संरचना करना है ताकि

दुरुपयोग की संभावना को समाप्त करने के लिए-नामित करने की शक्ति

दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों को तीन उच्च पदों पर सम्मानित किया जाता है।

संवैधानिक पदाधिकारी-प्रधानमंत्री, नेता

विपक्ष और सीजेआई का-यह प्राथमिक राजनीतिक है यह जानते हुए कि प्रधानमंत्री और नेता

विपक्ष के हमेशा परस्पर विरोधी राजनीतिक हित होते हैं और फिर भी शायद ही कभी किसी
मुद्दे पर सहमत होंगे,

द्विदलीय समझौते की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है -

हालांकि, समिति में सीजेआई की उपस्थिति होनी चाहिए

आम तौर पर सीजेआई के विफल होने की संभावना [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

में एक राजनीतिक समझौता या असहायता को समझना

इस तरह के समझौते की घटना से इंकार नहीं किया जा सकता है-यह है

न्यायिक समीक्षा के लिए प्रतिरक्षा-इस प्रकार देरी की संभावना है एन. जे. ए. सी. के कार्यकरण में और अनिवार्य रूप से प्रक्रिया

संवैधानिक न्यायालयों में नियुक्तियाँ-इसलिए, यह आवश्यक है कि एक अंतर्निहित प्रक्रिया होनी चाहिए

प्रतिष्ठित व्यक्तियों का नामांकन जो जोखिम को समाप्त करता है

संभावित द्विदलीय समझौते-एकमात्र कल्पनीय

उपचारात्मक प्रक्रिया में जांच के एक अन्य स्तर को शामिल करना है। नामांकन-निम्नलिखित सुरक्षा इस प्रक्रिया को लाएगी

मूल विशेषता के अनुमेय रूप के भीतर

एक साथ 'विलंब कारक' को समाप्त करना -

अनुच्छेद 124-ए (1) (ए) के तहत विचार की गई समिति को दोनों में से प्रत्येक के लिए तीन सदस्यों का एक पैनल तैयार करना चाहिए।

नामांकित व्यक्तियों की श्रेणियाँ (प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिए)-सभी में

छह व्यक्तियों का पैनल-इस तरह के पैनल को पहले रखा जाना चाहिए

मतदान के लिए सर्वोच्च न्यायालय का पूरा सदन-नामांकित व्यक्ति

दोनों श्रेणियों में से प्रत्येक में सबसे अधिक वोट हासिल करना चाहिए अंततः एन. जे. ए. सी. के प्रतिष्ठित सदस्यों के रूप में नामित किया जाएगा

इस तरह की प्रक्रिया अभी भी प्रतिष्ठित लोगों के चयन को संरक्षित रखेगी।

पी.

मुख्य रूप से समिति के साथ व्यक्ति जिनके तहत विचार किया गया है

Art.124-A, इसके खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा को शामिल करते हुए

समिति द्वारा शक्ति का संभावित दुरुपयोग।

भारत का संविधान-Art.124B (c)-अनुच्छेद 124B ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियों के कर्तव्यों को निर्धारित किया है।

आयोग (एनजेएसी)-कला। 124 बी (सी) एन. जे. ए. सी. को बाध्य करना

यह सुनिश्चित करें कि अनुशंसित व्यक्ति योग्य है और

सत्यनिष्ठा-तर्क कि संशोधन निर्धारित नहीं करता है
 मूल्यांकन के लिए एन. जे. ए. सी. द्वारा पालन किए जाने वाले कोई भी दिशानिर्देश
 क्षमता और सत्यनिष्ठा-आयोजित (चेलमेश्वर, जे. के अनुसार) (अल्पसंख्यक)
 राय): किसी स्पष्ट घोषणा के अभाव में भी,
 ऐसा दायित्व अंतर्निहित और निहित है, जिसे ध्यान में रखते हुए
 एन. जे. ए. सी. को सौंपी गई कार्यात्मक जिम्मेदारियाँ-सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई.

परिशुद्धता केवल एक प्रचुरता है-दस्तावेज़ की प्रकृति (i) को ध्यान में रखते हुए जिसके द्वारा ऐसा दायित्व है
 बनाया गया; (ii) शरीर की संरचना (एन. जे. ए. सी.) जिस पर
 दायित्व डाला जाता है; और (iii) कार्य की प्रकृति,
 तर्क को अस्वीकार करने की आवश्यकता है एन. जे. ए. सी. एक है
 एक महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए बनाया गया संवैधानिक प्राधिकरण संवैधानिक कार्य-इसका
 चार्टर स्वयं संविधान है।

इसके बावजूद, हमारे संविधान की श्रेष्ठता, एक संविधान
 हर मिनट के विवरण की वर्तनी अपेक्षित या आवश्यक नहीं है
 राज्य के प्रशासन के संबंध में-तीन सदस्य

इस देश का सर्वोच्च न्यायिक निकाय, एक सदस्य

केंद्रीय मंत्रिमंडल और दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा चुने गए तीन उच्च पदस्थ पदधारकों से बनी
 समिति

संविधान एन. जे. ए. सी. का गठन करता है-यह सुझाव देने के लिए कि

एन. जे. ए. सी. को संविधान के पाठ में स्पष्ट रूप से वर्णित विस्तृत दिशानिर्देशों की आवश्यकता है जो न्यायिक
 रूप से अनिवार्य करने के बराबर है।

संवैधानिक प्रारूपण के लिए लचीले मानक-संविधान की व्याख्या करने का कार्य संविधान से महत्वपूर्ण रूप से
 अलग है।

और सीजेआई का पालन करना-संशोधन के बाद, दायित्व है संरचना में है

अपरिवर्तित-एकमात्र परिवर्तन की

खिलाड़ी जिन्हें कार्य सौंपा गया है और किस प्रकार का कार्य में परिवर्तन किया जाता है।

अधिक से अधिक कार्य प्राप्त करने के लिए

चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की डिग्री-प्रतिस्पर्धा करने के लिए विनाशकारी है क्योंकि

कि संशोधन मूल संरचना के लिए

यह किसी भी दिशानिर्देश को निर्धारित नहीं करता है जो धारण करने के बराबर है।

कि मूल रूप से अधिनियमित संविधान का प्रारूप है

दोषपूर्ण!

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014

— एस. 6 (6)-एस के तहत स्थिरीकरण। 6 (6) अधिनियम का कि यदि कोई दो

एन. जे. ए. सी. द्वारा प्रस्तावित सिफारिश, एन. जे. ए. सी. नहीं करेगी की वैधानिकता की सिफारिश करें (प्रति [2015] 13 एस. सी. आर.

इस तरह के उम्मीदवार एम

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

चेलमेश्वर, जे.) (अल्पसंख्यक राय): सवाल यह है कि क्या

एस की सामग्री। 6 (6) वीटो की शक्ति प्रदान करता है या एक विशेष बहुमत निर्धारित करता है जो केवल शब्दार्थिक प्रासंगिकता का है-जो भी हो

नाम एक इसे बुलाता है, परिणाम एक ही है-दो सदस्य पर हावी हो सकती है और

एन. जे. ए. सी. की राय अन्य चार की राय

सिफारिश को रोकें-कुछ भी स्वाभाविक रूप से अवैध नहीं है।

इस तरह के एक पक्ष के बारे में।

न्यायपालिका-उच्च न्यायपालिका-संवैधानिक न्यायालय -

न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण-कॉलेजियम प्रणाली-यदि

उम्मीदवारों की उपयुक्तता के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त

संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए -

आयोजित किया गया

(प्रति चेलमेश्वर, जे.) (अल्पसंख्यक राय): फसाद पैदा हुआ
मामले में न्यायसंगत होगा

दिनाकरन मामले और शांति भूषण

प्रक्रिया में नागरिक समाज के सदस्यों की भागीदारी

चयन प्रक्रिया से रोगों को दूर करने के लिए

प्रक्रिया में शामिल-उपर्युक्त दो हैं

न केवल ऐसे मामले जहां प्रणाली विफल हो गई-यह एक बात है

सार्वजनिक रिकॉर्ड है कि पिछले 20 वर्षों में, के आगमन के बाद

कॉलेजियम प्रणाली, की गई सिफारिशों की संख्या

उच्च न्यायालयों के कॉलेजिया द्वारा खारिज कर दिया गया

सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम-मामले भी हैं

जहाँ सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम जल्दी से वापस आ गया

इसके कदमों ने उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा की गई एक विशेष नाम की सिफारिशों को खारिज कर दिया है
उन कारकों के बारे में बहुत सारी अटकलें हैं जिनके पास होना चाहिए

इतनी जल्दी नरम चेहरा बनाने के लिए कॉलेजियम के साथ तौला गया

-इस तरह के निर्णय कुछ मामलों में उचित हो सकते हैं और हो सकते हैं

अन्य मामलों में नहीं-इस संबंध में कोई जवाबदेही नहीं है।

- अभिलेख किसी भी व्यक्ति की पहुंच से बिल्कुल बाहर हैं।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों सहित जो भाग्यशाली नहीं हैं

भारत का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए पर्याप्त-इस तरह की स्थिति संस्थान की विश्वसनीयता को नहीं बढ़ाती है

और यह इस देश के लोगों के लिए अच्छा नहीं है।

संविधान (नब्बे-नौवां संशोधन) अधिनियम, 2014-सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई.

की वैधता-आयोजित (प्रति चेलमेश्वर, जे.) (अल्पसंख्यक राय):

संशोधन को बरकरार रखा गया है।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014

- की वैधता-आयोजित (प्रति चेलमेश्वर, जे.) (अल्पसंख्यक राय):

शून्य, जांच करने में कोई उपयोगी उद्देश्य नहीं है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियों की संवैधानिकता

आयोग अधिनियम, 2014-संविधान (नब्बे-नौवां)

संशोधन) अधिनियम, 2014।

भारत का संविधान-"बुनियादी विशेषताएं" और "बुनियादी"

संरचना "-आयोजित (प्रति चेलमेश्वर, जे.) (अल्पसंख्यक राय): अभिव्यक्तियाँ 'मूल संरचना' और 'मूल विशेषताएं' व्यक्त करती हैं।

दो अलग-अलग विचार-संविधान की मूल संरचना

संविधान की बुनियादी विशेषताओं का कुल योग है

-

बुनियादी विशेषताएं बुनियादी संरचना के घटक हैं-या तो

एक विशेष अनुच्छेद या लेखों का समूह एक मूल रचना का गठन कर सकता है।

संविधान की विशेषता-एक या कुछ का संशोधन

एक बुनियादी विशेषता का गठन करने वाले लेखों का परिणाम हो भी सकता है और नहीं भी।

संविधान की मूल संरचना को नष्ट करना।

प्रेक्टिस एंड प्रोसीजर-सुप्रीम कोर्ट-रिक्सल

एक वादी पक्ष के पूछने पर न्यायाधीश का-यदि उचित हो-नया

संवैधानिक रूप से न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की कॉलेजियम प्रणाली को बदलने के लिए योजना पर विचार किया गया

न्यायालय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन

संविधान के तत्वावधान में (नब्बे-नौवां संशोधन)

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियों के साथ पढ़ा गया अधिनियम, 2014

आयोग अधिनियम, 2014-उक्त की संवैधानिक वैधता

के समक्ष दायर रिट याचिकाओं में चुनौती दिए गए दो अधिनियम

भारत का सर्वोच्च न्यायालय-मूल रूप से तीन के समक्ष सूचीबद्ध मामला

जज बेंच-जिसे बाद में पांच जजों की बेंच को भेजा गया,

इनमें अनिल आर. दवे, चेलमेश्वर, मदन बी. लोकर, कुरियन जोसेफ और आदर्श कुमार गोयल, जे. जे. शामिल हैं।
- इसके बाद,

माननीय सीजेआई ने जे. एस. खेहर, जे.

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

चेलमेश्वर, मदन बी. लोकर, कुरियन जोसेफ और आदर्श

कुमार गोयल, जे. - माननीय न्यायमूर्ति जे. एस. खेहर, अध्यक्षता करते हुए

पाँच माननीय न्यायाधीशों के कॉलेजियम का-जब पुनर्गठित पीठ ने सुनवाई शुरू की, इसके लिए प्रार्थना की गई

माननीय न्यायमूर्ति जे. एस. खेहर का पीठ से अलग होना -

इस आधार पर अलग होने की प्रार्थना कि माननीय श्री.

पीठ में पीठासीन न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति जे. एस. खेहर

उसके साथ सुसंगत नहीं था (और स्पष्ट रूप से इसके साथ संघर्ष में था)

'कॉलेजियम' के सदस्य के रूप में पद जो अभ्यास करता है

महत्वपूर्ण संवैधानिक शक्ति; और यह अनुचित था

यदि कॉलेजियम का कोई वर्तमान सदस्य एक पर निर्णय में बैठता है योजना जो इसे बदलने की मांग कर रही थी-आयोजित: टिकने योग्य नहीं-आयोजित

(प्रति खेहर, जे.): इस तथ्य में कोई संदेह नहीं है कि मेरे पास है

1 + 4 कॉलेजियम का सदस्य रहा हूँ, और यह संभावना है कि मैं

जल्द ही एनजेएसी का सदस्य भी बन जाएगा, यदि

याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई वर्तमान चुनौती नहीं थी

सफल-इसलिए मैं चयन का हिस्सा बना रहूंगा।

प्रक्रिया, चाहे जो भी प्रक्रिया प्रचलित हो-वह

हालाँकि पल के चार के संदर्भ में स्थिति है

पाँच-न्यायाधीश पीठ-मेरे अलावा, मेरे सहयोगी

बेंच-जे। चेलमेश्वर, मदन बी. लोकर और कुरियन जोसेफ,

जे जे। नियत समय में कॉलेजियम का हिस्सा होगा (यदि रिट याचिकाकर्ताओं को सफल होना था), या वैकल्पिक रूप से, एक हिस्सा होगा एन. जे. ए. सी. का (यदि रिट-याचिकाकर्ता विफल हो जाते हैं)-इस प्रकार संभाव्यता, हितों के टकराव का आरोप, न केवल मेरे खिलाफ, बल्कि मेरे तीनों के खिलाफ भी उठाया जाना चाहिए था

सहकर्मी-लेकिन, इस तरह से मुद्दा नहीं था।

प्रचार किया गया है-इस प्रकार मेरे अलग होने की प्रार्थना अच्छी तरह से स्थापित नहीं है-अगर मुझे अपने अलग होने की प्रार्थना को स्वीकार करना है,

मैं एक गलत अभ्यास शुरू कर रहा हूँ, और एक गलत अभ्यास कर रहा हूँ

मिसाल-एक न्यायाधीश अपने दम पर किसी मामले से अलग हो सकता है।

मुख्य न्यायाधीश द्वारा उन्हें सौंपा गया-यह एक सुपर कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड का मामला होगा।

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई.

अपनी पसंद का-लेकिन एक मुकदमेबाज पक्ष के पूछने पर अलग होना, जब तक कि उचित न हो, कभी भी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए-क्योंकि

इससे यह आभास होगा कि न्यायाधीश डर गया था

मामले से बाहर, केवल आपत्ति के बल पर-एक न्यायाधीश

भय या पक्षपात के बिना कर्तव्य-वह अपनी शपथ का उल्लंघन करेगा पद पर, यदि वह अलग होने की प्रार्थना स्वीकार करता है, जब तक कि उचित न हो-यह मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी जिम्मेदारी का पूर्ण रूप से निर्वहन करूँ

गंभीरता और ईमानदारी-यह मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी शपथ का पालन करूँ। पद का, संविधान और कानूनों को बनाए रखने के लिए-मेरा

पीठ का हिस्सा बने रहने का निर्णय, से प्रवाहित होता है

शपथ जो मैंने इस न्यायालय में अपनी पदोन्नति के समय ली थी

आयोजित (जे. चेलमेश्वर के अनुसार) (अपने और जे. गोयल के लिए): यह है। एक सभ्य कानूनी प्रणाली के स्थापित सिद्धांतों में से एक

न्यायाधीश को निष्पक्ष होना आवश्यक है-यह कहा जाता है कि पहचान

लोकतंत्र का अस्तित्व एक निष्पक्ष न्यायाधीश का अस्तित्व है-पहले के निर्णयों से निम्नलिखित सिद्धांत उभरते हैं; (1) यदि न्यायाधीश का किसी मामले के परिणाम में वित्तीय हित होता है, वह है

स्वतः ही मामले की सुनवाई से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है; (2) मामलों में जहाँ मामले में न्यायाधीश का हित इसके अलावा है

वित्तीय, तो अयोग्यता स्वचालित नहीं है लेकिन एक

जाँच की आवश्यकता है कि क्या इस तरह के हित का अस्तित्व है

दोनों में से किसी एक के आलोक में परीक्षण किए गए न्यायाधीश को अयोग्य घोषित करता है

"वास्तविक खतरे" या "उचित आशंका" का सिद्धांत

पक्षपात; और (3) पिनोशे मामले में एक नई श्रेणी जोड़ी गई अर्थात् कि न्यायाधीश स्वतः सुनवाई से अयोग्य हो जाता है

मामला जहाँ न्यायाधीश एक ऐसे कारण में रुचि रखता है जो किया जा रहा है

मामले में एक पक्ष द्वारा पदोन्नत किया गया-यह किसी का नहीं है

मामला कि, हाथ में मामले में, न्यायमूर्ति खेहर के पास कोई था

आर्थिक व्याज या इसके अंतर्गत आने वाला कोई अन्य व्याज

उपर्युक्त श्रेणियों में से दूसरा-बहुत

मामले की प्रकृति, ऐसा कोई हित उत्पन्न नहीं हो सकता है-जहाँ तक

जैसा कि पिनोशे मामले में निर्धारित कानून के सिद्धांत का संबंध है, इन कार्यवाही के सभी पक्ष [2015] 13 एस. सी. आर. को बढ़ावा देने का दावा करते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक निष्पक्ष और के अस्तित्व को सुनिश्चित करने का कारण

स्वतंत्र न्यायपालिका-एकमात्र मतभेद पक्षकारों के बीच उस प्रक्रिया के बारे में है जिसके द्वारा

परिणाम प्राप्त करना है-इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि न्यायमूर्ति खेहर किसी भी हित को साझा करते हैं जिसमें से कोई एक

कार्यवाही के पक्षकार बढ़ावा देना चाहते हैं -

न्यायमूर्ति खेहर निर्णय लेने के लिए पूर्व-निर्धारित होंगे विवादित कानून अमान्य होगा-कोई समझने में विफल रहता है

याचिकाकर्ताओं का रुख-यदि ऐसी आशंका याचिकाकर्ता सही होते हैं, लाभार्थी होंगे केवल याचिकाकर्ता-इस आधार पर शिकायत, यदि कोई हो, होनी चाहिए। उत्तरदाताओं की ओर से-केवल एक पक्ष जिसके पास है प्रतिकूल निर्णय का सामना करना पड़ा या पीड़ित होने की संभावना है क्योंकि न्यायनिर्णायक की ओर से पक्षपात की संभावना आपत्ति उठाएँ-द्वारा वर्णित महत्वपूर्ण शक्ति याचिकाकर्ता केवल सदस्यों के लिए नहीं है कॉलेजियम, लेकिन उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश में निहित है जिसे इस संबंध में अपनी राय व्यक्त करने के लिए बुलाया जा सकता है उच्च न्यायालय की विभिन्न नियुक्तियों के प्रस्ताव उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश-जबकि कॉलेजियम के सदस्यों को इस तरह का अभ्यास करना आवश्यक है "प्रत्येक के संबंध में महत्वपूर्ण शक्ति उपर्युक्त श्रेणियों की नियुक्ति, अन्य उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को इस तरह का प्रयोग करना आवश्यक है "महत्वपूर्ण शक्ति", कम से कम नियुक्तियों के संबंध में उच्च न्यायालय को या उससे, जिसके साथ वे पहले थे न्यायाधीशों या मुख्य न्यायाधीशों के रूप में संबद्ध - याचिकाकर्ताओं का तर्क, यदि स्वीकार किया जाता है तो सभी इस न्यायालय के न्यायाधीशों को वर्तमान सुनवाई से अयोग्य घोषित कर दिया गया विवाद-एक परिणाम जिसकी सिद्धांत द्वारा कानूनी रूप से अनुमति नहीं है। आवश्यकता की "-उपरोक्त कारणों से, यह निवेदन कि न्यायमूर्ति खेहर को इस पद से अलग होना चाहिए कार्यवाही अस्वीकार की जा सकती है-आयोजित (प्रति कुरियन, जे.):

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई.

न्यायमूर्ति खेहर के अलग होने की कोई स्थिति नहीं है।

यह मामला-हालाँकि, इससे निपटना भी उचित है

सिक्के का दूसरा पक्ष, क्या किसी न्यायाधीश को कारण बताना चाहिए

एक विशेष मामले में उनके अलग होने के लिए-एक ऐसी संस्था होने के नाते जिसका

पहचान पारदर्शिता है, यह केवल उचित है कि न्यायाधीश उच्च और महान कर्तव्यों का निर्वहन, कम से कम मोटे तौर पर इंगित करता है

मामले से अलग होने के कारण ताकि वादी या

सार्थक जनता किसी का मनोरंजन नहीं कर सकती है

अप्रासंगिक कारण जैसे कि मामले बहुत पुराने हैं, जिसमें शामिल हैं विस्तृत विचार, कानून के कई प्रश्नों पर निर्णय,

एक ऐसी स्थिति जहाँ न्यायाधीश रोस्टर से खुश नहीं है,

न्यायाधीश जनता की धारणा के बारे में अनुचित रूप से संवेदनशील हो रहे हैं

या विवादास्पद मुद्दे, आदि-एक बार अलग होने के कारण हैं इंगित किया गया है, किसी भी उद्देश्य को जिम्मेदार ठहराने के लिए कोई जगह नहीं होगी

अलग होने के लिए-यह प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने में मदद करेगा फोरम खरीदारी-एक न्यायाधीश की निष्पक्षता अनिवार्य है

अपने कर्तव्यों के संचालन और न्यायालय के कामकाज में न्यायाधीश के कार्यालय की अखंडता का गठन करने वाले प्रमुख कारकों में से - वादी हमेशा जानना चाहेंगे हालांकि वे कर सकते हैं

यह जानने का निर्धारित अधिकार नहीं है कि किसी न्यायाधीश के पास क्यों है

मामले की सुनवाई से या अनुरोध के बावजूद, अलग नहीं किया गया है अपने मामले की सुनवाई से अलग हो गया-कारणों की आवश्यकता है

मोटे तौर पर संकेत दिया गया है-बेशक, के प्रकटीकरण के मामले में

कारणों से किसी भी मामले या कारण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है या

किसी और के हित में, न्यायाधीश यह कहने के लिए स्वतंत्र है कि

व्यक्तिगत कारणों का लेखा जो न्यायाधीश नहीं चाहते हैं

खुलासा करने के लिए, उन्होंने सुनवाई से खुद को अलग करने का फैसला किया है

मामला-आयोजित (प्रति लोकुर, जे.): जब किसी न्यायाधीश को किसी मामले की सुनवाई से अलग करने के लिए आवेदन किया जाता है, तो आवेदन

[2015] 13 एस. सी. आर. के रूप में पीठ के बजाय संबंधित न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पूरा-इसलिए, न्यायमूर्ति खेहर बिल्कुल सही हैं।

यह कहते हुए कि निर्णय पूरी तरह से उसका है-जहाँ तक दृष्टिकोण है न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ द्वारा व्यक्त किया गया कि कारण होने चाहिए

अलग होने के लिए एक आवेदन तय करते समय दिया गया, मैं पसंद करूँगा

उस निर्णय में शामिल नहीं होना-सबसे पहले, देना या न देना। कारण यहाँ कोई मुद्दा नहीं था-वे कारण वर्तमान में हैं

दिया जाना पूरी तरह से एक अलग बात है-दूसरा,

कारण बताना कुछ कठिनाइयों से भरा है-मुद्दा

किसी मामले की सुनवाई से अलग होना उतना आसान नहीं है जितना प्रतीत होता है

सामने रखे गए प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हैं और क्योंकि यह

ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे अनुप्रयोग आवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं, यह है

कुछ प्रक्रियात्मक और मूल नियम बनाए जाने का समय

इस संबंध में-यदि उचित नियम बनाए जाते हैं, तो

मामले को देखते हुए, यह अन्य न्यायाधीशों को शर्मिंदा होने से बचाएगा

पीठ पर-न्यायपालिका-उच्च न्यायपालिका-संवैधानिक

न्यायालय-न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण।

न्यायपालिका-उच्च न्यायपालिका-संवैधानिक न्यायालय

न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण-प्रधानता

न्यायपालिका-प्रथम न्यायाधीशों में उच्चतम न्यायालय के पूर्व निर्णय

मामला, दूसरा न्यायाधीश मामला और तीसरा न्यायाधीश मामला -

प्रथम न्यायाधीश मामला (एस. पी. गुप्ता बनाम. भारत संघ), कार्य

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति,

सात-न्यायाधीश पीठ प्रति बहुमत, कि अंतिम शक्ति नियुक्ति, निर्विवाद रूप से राष्ट्रपति के साथ -

दूसरे न्यायाधीशों के मामले में निर्णय को खारिज कर दिया गया था

(सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन v. संघ

भारत की), जिसमें यह नौ-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था कि

नियुक्ति की अंतिम शक्ति के संदर्भ में प्रधानता

(या स्थानांतरण) न्यायपालिका के साथ निहित-कानून का प्रदर्शन
घोषित, एक द्वारा फिर से पुष्टि की गई थी

दूसरे न्यायाधीशों के मामले में

1998 का संदर्भ संख्या 1)-भारत संघ, तब बनाया गया था
लिए 30.6.1999 पर प्रक्रिया ज्ञापन-ऑन-रिकॉर्ड

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं के

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई.

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति

और सर्वोच्च न्यायालय, दूसरे के अनुरूप

प्रक्रिया ज्ञापन नई योजना अब - राष्ट्रीय न्यायिक के दायरे में विचार किया गया

के तत्वावधान में गठित नियुक्ति आयोग

संविधान (नब्बे-नौवां संशोधन) अधिनियम, 2014

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014-लेकिन

तत्काल कार्यवाही में चुनौती दी गई-याचिकाकर्ता अन्य बातों के साथ
मामले में निर्णय पर भरोसा किया, और

द्वितीय न्यायाधीशों के

तीसरे न्यायाधीशों के मामले में निर्णय जबकि प्रत्यर्थियों,

अन्य बातों के साथ-साथ प्रथम न्यायाधीशों में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया।

मामला, और दिए गए निर्णयों पर पुनर्विचार करने की मांग की

द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों के मामलों में-संदर्भ के लिए प्रार्थना
पुनर्विचार के लिए और

एक बड़ी पीठ को, और दूसरे के

तीसरे न्यायाधीशों के मामले (न्यायालय के आदेश के अनुसार): नहीं।

मान्य-आयोजित (प्रति खेहर, जे.): समीक्षा की शक्ति थी

प्रथम न्यायाधीशों के मामले में प्रयोग किया गया और खर्च किया गया

दूसरे न्यायाधीशों के मामले में एक बड़ी पीठ द्वारा समीक्षा की गई थी

— और निश्चित रूप से, यह भारत संघ के लिए पूरी तरह से अनुचित था,

जो तीसरे की सुनवाई के दौरान स्वीकार कर लिया था न्यायाधीशों का मामला, कि उन्होंने दूसरे न्यायाधीशों के मामले में दिए गए निर्णय को बाध्यकारी के रूप में स्वीकार किया था, प्रयास करने और फिर से आंदोलन करने के लिए

मामला फिर से-मामले पर फिर से विचार किया गया है,

और स्थिति भारत संघ द्वारा स्वीकार की गई है,

यह भारत संघ के मुँह में नहीं है, की तलाश करने के लिए

न्यायिक घोषणा पर पुनर्विचार, दूसरे और

तीसरे न्यायाधीशों के मामले-इसके अलावा, एक पूर्ण समूह है

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति के मामले में न्यायपालिका और राजनीतिक-कार्यपालिका के बीच उद्देश्य

- और उनके बीच स्पष्ट पारदर्शिता भी है - विचारों का आदान-प्रदान लिखित रूप में किया जाता है, विचार और विरोधी विचार, सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट हैं

[2015] 13 एस सी आर।

काले और सफेद में-यह स्वीकार करना संभव नहीं है, कि

द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों के अधीन विचार की गई प्रक्रिया

मामले, न्यायाधीश अपने स्वयं के चुनिंदा न्यायाधीशों से लेकर उच्च न्यायाधीशों तक

न्यायपालिका, या कि, साम्राज्य में साम्राज्य की प्रणाली रही है

न्यायाधीशों के मामलों को इस तरह से प्रस्तुत किया गया था जो डॉ. बी. आर. द्वारा की गई टिप्पणियों को पूरी तरह से प्रभावी बनाएगा। अनुच्छेद 124 के संदर्भ में अम्बेडकर (मूल रूप से)

निगमित)-यह उत्तरदाताओं के लिए स्पष्ट रूप से गलत है तर्क है कि परामर्श प्रक्रिया के बीच अभिनिर्धारित

राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के साथ या

राज्यों में उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति के विवेक पर,

दूसरे और तीसरे न्यायाधीशों द्वारा समाप्त कर दिया गया था

मामले-इस तरह का कुछ भी नहीं-यह रहा है, और अभी भी खुला है

राष्ट्रपति, अपने निरंकुश ज्ञान में, परामर्श के लिए

अनुच्छेद 124 में इंगित किया गया है-इसके अतिरिक्त, यह इसके लिए खुला है राष्ट्रपति, उसी पर भरोसा करने के लिए, के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ अनिवार्य "परामर्श" -

ऊपर, आगे में कार्यकारी भूमिका को दर्शाता है ऐतिहासिक रूप से भी, उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों का चयन- शासन के तीनों अंगों में समान रूप से अभिनिर्धारित किया कि न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ करते समय उच्च न्यायपालिका, "न्यायपालिका की स्वतंत्रता" को स्वीकार किया गया था संविधान की भावना के एक अभिन्न घटक के रूप में, और

इस प्रकार, निम्नलिखित प्रावधानों में "परामर्श" शब्द का उपयोग किया गया है। विचार, के साथ निहित प्रधानता के रूप में समझा जाना था न्यायपालिका, विचार किए गए विषयों के संदर्भ में अनुच्छेद 124, 217 और 222 के तहत-उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक व्याख्या, वास्तव में कोई वैध कारण नहीं है उत्तरदाताओं में निर्णयों की समीक्षा की मांग करने के लिए द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों के मामले-साथ ही न्यायपालिका के निर्माता संविधान के अनुच्छेद 50 का मसौदा तैयार करते समय, उनके विचार में स्पष्ट और सर्वसम्मत, कि एक सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं की आवश्यकता है-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई.

न्यायपालिका, कार्यपालिका के प्रभावों से अलग

—

एक सामंजस्यपूर्ण निर्माण पर सर्वोच्च न्यायालय

संविधान के प्रावधान, दूसरे और तीसरे में

न्यायाधीशों के मामले, जो उचित रूप से अभिनिर्धारित हैं, कि उपरोक्त मामले में प्रधानता,

न्यायपालिका के साथ निहित, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि संदर्भ के तहत प्रावधानों में "परामर्श" शब्द होना चाहिए द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण को प्रधानता देने के रूप में समझा जाए

न्यायपालिका, भारत के मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से-इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय, शिशिर कांता में पांच न्यायाधीशों की पीठ के माध्यम से

सतपति मामले में कहा गया है कि द्वारा की गई सिफारिशें उच्च न्यायालय के तहत परिकल्पित परामर्श प्रक्रिया में अनुच्छेद 233, राज्यपाल के लिए बाध्यकारी है -

एक वनबद्ध बाध्यकारी मिसाल, एक विवाद पर, जो है हाथ में एक के समान आश्चर्यजनक रूप से, और कभी नहीं किया गया है सवाल किया, यह काफी समझ में नहीं आता है कि संघ कैसे भारत, इस न्यायालय को अब जांच करने के लिए राजी करना चाहता है अनुच्छेद 124 के संदर्भ में अलग तरह से "परामर्श" शब्द और 217, उपरोक्त को दिए गए अर्थ पर जोर दिए बिना पद, न्यायपालिका को नियंत्रित करने वाले मामले के संदर्भ में भी

आयोजित (प्रति लोकुर, जे.): कम से कम 1935 से, यदि पहले नहीं, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति इस दृष्टिकोण के अनुसार की गई थी भारत के मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

न्यायालय जैसा भी मामला हो-लेकिन उन मामलों में भी जहां 1959 से पहले (के मुख्य न्यायाधीश के साथ) विचलन थे उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया है) की सहमति भारत के मुख्य न्यायाधीश को लिया गया-इसलिए कार्यपालिका, न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में कभी भी वास्तविक प्रधानता नहीं थी - संविधान में परामर्श और भागीदारी का प्रावधान किया गया है।

के लिए संवैधानिक कार्यकर्ताओं के बीच प्रक्रिया 'सर्वश्रेष्ठ' संभावित व्यक्ति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करना न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय-इस परामर्श प्रक्रिया में

अंतिम शब्द एक संवैधानिक सम्मेलन द्वारा दिया जाता है और
से विकसित अभ्यास

के मुख्य न्यायाधीश के लिए वर्षों

भारत उस संवैधानिक पदाधिकारी के बाद से सबसे अच्छी तरह से सुसज्जित है [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रभावी न्याय वितरण की आवश्यकताओं की सराहना करना,

न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए, दूर रखने के लिए

बाहरी प्रभाव, 'न्यायाधीश की प्रारंभिक नियुक्ति के चरण में भी राजनीतिक प्रभाव को समाप्त करना' और
इसके प्रमुख के रूप में

न्यायपालिका, उसके निर्णय पर इस मामले में भरोसा किया जाना चाहिए।

डॉ. अम्बेडकर इस बात की पुष्टि करते थे कि

न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए और यदि

तब इस मामले में भारत के न्यायाधीश का अंतिम निर्णय नहीं होता है।

न्यायपालिका, एक अर्थ में, किसी अन्य प्राधिकरण के अधीन है और
संवैधानिक

इसलिए उस हद तक स्वतंत्र नहीं-

सम्मेलन, संवैधानिक योजना और संवैधानिक

न्यायपालिका में न्यायपालिका की जिम्मेदारी को पहचानना

न्यायाधीशों की नियुक्ति और इसे केवल औपचारिक रूप दिया गया था

द्वितीय न्यायाधीश मामला-शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत

या शक्तियों का वितरण दूसरे द्वारा बनाए रखा गया था

न्यायाधीशों के मामले को ओवरबोर्ड फेंकने के बजाय-संविधान

अपनी शाखाओं को अलग करने का आदेश देता है लेकिन
पारस्परिकता 'और दूसरा

परस्पर निर्भरता, स्वायत्तता लेकिन

न्यायाधीशों के मामले ने इस संतुलन को प्रभावी ढंग से बनाए रखा है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति-इन सभी कारकों और सीएडी को ध्यान में रखते हुए
जिन सभी पर दूसरे में चर्चा की गई थी

ध्यान में रखते हुए,

न्यायाधीशों के मामले में इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल है कि

दूसरे न्यायाधीश के मामले में गुण-दोष पर पुनर्विचार की आवश्यकता है -

दूसरे न्यायाधीश के मामले को वकील ने स्वीकार कर लिया था जनरल जैसा कि तीसरे
न्यायाधीशों के मामले में उल्लेख किया गया है और

राष्ट्रपति जिन्होंने इस बारे में कोई सवाल नहीं उठाया

संविधान के अनुच्छेद 124 (2) और अनुच्छेद 217 (1) को दी गई व्याख्या इन संवैधानिक प्राधिकरणों के पास
द्वितीय न्यायाधीशों के मामले में निर्धारित कानून को स्वीकार किया, वहाँ

उस निर्णय पर पुनर्विचार करने का कोई कारण नहीं है-कोई कारण नहीं है

आकस्मिक परिस्थितियाँ, स्पष्ट और सम्मोहक कारण

पुनर्विचार के लिए, और न ही यह कहा जा सकता है कि द्वितीय न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-
ऑन-रिकॉर्ड करते हैं

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई.

मामला स्पष्ट रूप से गलत था या कि इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है

जनता-इसके विपरीत, निर्णय ने बहाल किया

न्यायपालिका की वास्तविक रूप से स्वतंत्रता और उन्मूलन

कार्यकारी नियंत्रणों का हानिकारक प्रभाव-इसके अलावा, यह था

समशेर सिंह मामले में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि अंतिम

न्यायपालिका से संबंधित मामलों में शब्द प्रमुख के पास होना चाहिए जस्टिस ऑफ इंडिया-समशेर
सिंह मामले का फैसला एक

पुनर्विचार की आवश्यकता है या यह निर्धारित नहीं करता है सही कानून-दूसरे न्यायाधीशों का
मामला केवल दोहराता है

'एक सीमित अर्थ में अंतिम शब्द 'दृष्टिकोण-द्वितीय न्यायाधीशों का मामला

सही ढंग से तय किया गया है और सम्मेलनों और

उसमें निर्धारित सिद्धांत हमारे संवैधानिक इतिहास से आते हैं और इन्हें किसी पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं
है

एकमात्र

अब सवाल यह है कि क्या 99 वां संविधान संशोधन
 अधिनियम संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है और
 तय करें कि इस प्रश्न पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है

द्वितीय न्यायाधीश का मामला या तृतीय न्यायाधीश का मामला-- यह इस तथ्य से अलग है कि कानून में
 पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है, यहां तक कि

योग्यता के आधार पर-आयोजित (कुरियन, जे.): एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कानून के एक महत्वपूर्ण
 प्रश्न पर एक मुद्दे को संबोधित किया

संविधान की संरचना और कानून निर्धारित किया है, ए

पुनरीक्षण के अनुरोध का तब तक स्वागत नहीं किया जाएगा जब तक कि इसे दिखाया न जाए।

कि संरचनात्मक व्याख्या स्पष्ट रूप से गलत है-कोई नहीं

इससे पहले कि यह बेंच ग्राफिक तस्वीर को धुंधला कर सके

न्यायाधीशों की नियुक्ति की योजना और इसकी ठोस संरचना

मामला-आयोजित (प्रति गोयल, जे.): तय सिद्धांत यह है कि अदालत को ऐसा नहीं करना चाहिए, सिवाय
 इसके कि जब इसे सभी से परे प्रदर्शित किया जाए। उचित संदेह है कि इसका पिछला निर्णय नियत
 समय के बाद दिया गया था

विचार-विमर्श और पूरी सुनवाई गलत थी, पहले के फैसलों पर फिर से विचार करें ताकि कानून निश्चित रहे-
 असाधारण रूप से

परिस्थितियों या परिस्थितियों के नए सेट के तहत नए विचार, पहले का दृष्टिकोण, अगर गलत
 माना जाए, तो [2015] 13 एस. सी. आर. हो सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उल्टा-जबकि कानून की प्रगति जारी है और नई प्रणालियाँ

जब भी आवश्यकता हो इसे विकसित किया जा सकता है, यह केवल तभी किया जा सकता है जब

पहले की प्रणालियों को अव्यवहारिक माना जाता है-ऐसा कोई नहीं है

स्थिति उत्पन्न हुई है-तय किए गए सिद्धांतों पर, कोई मामला नहीं है

इस तर्क के संबंध में कि पेटेंट में त्रुटि थी पहले के निर्णयों, दूसरे न्यायाधीशों के मामले से पता चलता है कि

संविधान सभा की बहसों को विस्तृत रूप से उद्धृत किया गया था और

विचार किया गया-न तो बहस और न ही संविधान द्वारा अपनाया गया पाठ यह दर्शाता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति

विधानमंडल-तब से अभ्यास और परंपरा संविधान के प्रारंभ ने दिखाया कि

नियुक्ति हमेशा न्यायपालिका द्वारा शुरू की गई थी और

इस विषय पर अंतिम शब्द सीजेआई का था-यह योजना

संविधान निर्माताओं के इरादे के अनुरूप था

अन्य देशों में न्यायिक आयोग और

कार्यपालिका पर न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भी आह्वान नहीं किया जा सकता है दूसरे न्यायाधीशों के मामले में ऐसे कई मामलों पर पुनर्विचार

और इसी तरह के प्रावधानों पर दूसरे में विधिवत विचार किया गया था

न्यायाधीशों का मामला-इस प्रकार द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों के मामलों में पहले के फैसलों पर पुनर्विचार करने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया-आयोजित

(चेलमेश्वर, जे.) (अल्पसंख्यक राय): इस देश ने न्यायपालिका से जुड़ी कई अप्रिय घटनाओं को देखा

नियुक्तियाँ-घटनाएँ जो लोगों को विश्वास दिलाती हैं

यह अनुमान कि द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों द्वारा स्थापित प्रणाली अपनी परिचालन वास्तविकता में मामले

एक स्वतंत्र और कुशल न्यायपालिका को सुरक्षित करने के लिए शायद सबसे अच्छी प्रणाली नहीं है-परस्पर विरोधी राय हैं।

के निर्णय की न्यायशास्त्रीय दृढ़ता के बारे में

द्वितीय न्यायाधीश मामला-इसकी जाँच करना आवश्यक नहीं है कि

वर्तमान निर्धारित करने के उद्देश्य से मामले का पहलू विवाद।

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई.

खेहर के निर्णय में, जे। :

एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ 1981 (सप) एस. सी. सी. 87; 1982 एस. सी. आर. 365; उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम। भारत संघ (1993) 4 एससीसी 441: 1993 (2) पूरक। एससीआर 659; पुनः 1998 (1998) का विशेष संदर्भ सं. 17 एस. सी. सी. 739 1998 (2) पूरक। एससीआर 400; सुभाष शर्मा बनाम। भारत संघ 1991 पूरक (1) एस. सी. सी. 574: 1990 (2) पूरक। एस. सी. आर. 433; सुप्रीम कोर्ट में

भारत संघ बनाम। संकलचंद हिमतलाल सेठ (1977) 4 एस. सी. सी. 193: 1978 (1) एससीआर 423; टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य (2002) 8

एससीसी 481: 2002 (3) पूरक। एससीआर 587; पुनः 2002 (2002) की विशेष संदर्भ संख्या 18 एस. सी. सी. 237: 2002 (3) पूरक। एससीआर 366; एस. आर. चौधरी बनाम की स्थिति

पंजाब (2001) 7 एससीसी 126: 2001 (1) पूरक। एस. सी. आर. 621; इंद्र साहनी बनाम। भारत संघ 1992

पूरक (3) एस. सी. सी. 217: 1992 (2) पूरक। एस. सी. आर. 454; केशवानंद भारती बनाम. केरल राज्य (1973) 4 एससीसी 225: 1973 (0) पूरक। एस. सी. आर. 1; समशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974) 2 एससीसी 831: 1975 (1) एस. सी. आर. 814; मनोज नरूला बनाम। भारत संघ

(2014) 9 एस. सी. सी. 1; भीम सिंह बनाम भारत संघ

(2010) 5 एससीसी 538 2010 (6) एस. सी. आर. 218; राज्य

यू. पी. वी. जीत एस. बिष्ट (2007) 6 एससीसी 586: 2007 (7) एस. सी. आर. 705; सुराज इंडिया ट्रस्ट बनाम। भारत संघ

(2012) 13 एससीसी 497: 2011 (4) एससीआर 224; जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड बनाम। हरियाणा राज्य (2010) 4 एससीसी 595: 2010 (4) एससीआर 743; पुनः कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण 1993 पूरक (1) एस. सी. सी. 96: 1991 (2) पूरक। एस. सी. आर. 497; केरल राज्य विज्ञान और

प्रौद्योगिकी संग्रहालय बनाम। रामबल कंपनी (2006) 6 एस. सी. सी. 258: 2006 (4) पूरक। एससीआर 243; बंगाल प्रतिरक्षा कंपनी लिमिटेड बनाम। बिहार राज्य (1955) 6 एससीआर

603; मगनलाल छगनियाल (पी) लिमिटेड बनाम। नगर निगम। ग्रेटर बॉम्बे (1974) 2 एस. सी. सी. 402:

[2015] 13 एस. सी.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1975 (1) एस. सी. आर. 1; भारत संघ बनाम। रघुबीर सिंह (1989) 2 एससीसी 754: 1989 (3) एससीआर 316; प्रदीप कुमार विश्वास बनाम। भारतीय रसायन संस्थान

जीव विज्ञान (2002) 5 एस. सी. सी. 111: 2002 (3) एससीआर 100; खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाम। भारतीय इस्पात प्राधिकरण (2011) 4 एस. सी. सी. 450: 2011 (4)

एस. सी. आर. 19; पश्चिम बंगाल राज्य बनाम। केसरम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (2004) 10 एस. सी. सी. 201: 2004 (1) एस. सी. आर. 564; इंडिया सीमेंट लिमिटेड बनाम तमिल राज्य नाडु (1990) 1 एस. सी. सी. 12: 1989 (1) पूरक। एस. सी. आर. 692; उप-न्यायिक जवाबदेही समिति v. भारत संघ (1992) 4 एस. सी. सी. 97; बॉम्बे राज्य बनाम। यूनाइटेड मोटर्स (इंडिया) लिमिटेड (1953) एससीआर 1069; केशव मिल्ल कंपनी लिमिटेड बनाम। आय-कर आयुक्त, बॉम्बे उत्तर (1965) 2 एस. सी. आर. 908; लेफ्टिनेंट कर्नल खजुर सिंह बनाम। भारत संघ (1961) 2 एस. सी. आर. 828; गंगा चीनी निगम लिमिटेड बनाम। राज्य

उत्तर प्रदेश का (1980) 1 एस. सी. सी. 223: 1980 (1) एस. सी. आर. 769; गैनन डंकरली एंड कं. बनाम। राजस्थान राज्य (1993) 1 एससीसी 364: 1992 (3) पूरक।

एससीआर 103; पंजीयक (प्रशासन), उड़ीसा उच्च न्यायालय,

कटक बनाम। शिशिर कांता सतपति (1999) 7 एस. सी. सी. 725 1999 (2) पूरक। एस. सी. आर. 473; मिनर्वा मिल्ल

लिमिटेड वी. भारत संघ (1980) 3 एससीसी 625: 1981 (1)

एस. सी. आर. 206; किहोतो होलोहन बनाम। ज़चिल्लू 1992

पूरक (2) एस. सी. सी. 651: 1992 (1) एस. सी. आर. 686; मद्रास बार एसोसिएशन बनाम। भारत संघ (2014) 10 एससीसी

1 : एम. नागराज बनाम भारत संघ (2006) 8 एससीसी 212: 2006 (7) पूरक। एस. सी. आर. 336; सरदार लाल बनाम। संघ

भारत का ए. आई. आर 1971 एस. सी. 1547: 1971 (3) एस. सी. आर. 461; भारत संघ बनाम। आर. गांधी (2010) 11 एससीसी 1: 2010 (6) एस. सी. आर. 857; श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) 4 स्केल 1; मद्रास राज्य बनाम। वी. जी. रो (1952) एससीआर 597; आई. सी. गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य ए. आई. आर (1967) एस. सी. 1643: 1967 एससीआर 762; सिंधिया बहादुर बनाम। भारत संघ (1971) 1 एससीसी

85 : 1971 (3) एस. सी. आर. 9; सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई.

(3) एस. सी. आर. 147; मनोहर लाल शर्मा बनाम प्रधान सचिव (2014) 2 एस. सी. सी. 532; शशांक लक्ष्मण काले वी। भारत संघ (1990) 4 एससीसी 366: 1990 (3) एससीआर 441; पुनः विशेष न्यायालय विधेयक, 1978 (1979) 1 एस. सी. सी. 380; सुब्रमण्यम स्वामी बनाम। निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो (2014) 8

एससीसी 682: 2014 (6) एस. सी. आर. 873; डॉ. काशीनाथ जी. जल्मी बनाम। अध्यक्ष ए. आई. आर. 1993 एस. सी. 1873; ए.

रॉय बनाम। भारत संघ (1982) 1 एससीसी 271: 1982

(2) एस. सी. आर. 272; चरणजीत लाल चौधरी बनाम। भारत संघ राम एयर (1951) एससी 41: 1950 एससीआर 869;

कृष्ण डालमिया बनाम। न्यायमूर्ति एस. आर. तेंदुलकर ए. आई. आर (1958) एस. सी. 538: 1959 एससीआर 279; बी. बनर्जी बनाम। अनीता पान (1975) 1 एस. सी. सी. 166: 1975 (2) एससीआर 774;

आंध्र प्रदेश सरकार बनाम। पी. लक्ष्मी देवी (2008) 4 एससीसी 720: 2008 (3) एस. सी. आर. 330; मो.

हनीफ कुरेशी बनाम। बिहार राज्य ए. आई. आर 1958 एस. सी. 731: 1959 एस. सी. आर. 629; पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार 1952 एससीआर 284; इंदिरा नेहरू गांधी बनाम। राज नारायण (1975) पूरक एस. सी. सी. 1: 1976 एससीआर 347;

वामन राव बनाम। भारत संघ (1981) 2 एससीसी 362: 1981 (2) एस. सी. आर. 1; आसिफ हमीद बनाम। जम्मू और कश्मीर राज्य 1989 पूरक (2) एस. सी. सी. 364: 1989 (3) एस. सी. आर. 19; बिहार राज्य बनाम। बिहार डिस्टिलरी लिमिटेड (1997) 2 एस. सी. सी. 453: 1996 (9) पूरक। एस. सी. आर. 479; बैंगलोर वूलन, कॉटन एंड सिल्क मिल्स कंपनी लिमिटेड।

बी. बैंगलोर शहर निगम (1961) 3 एस. सी. आर. 707; खादिम हुसैन बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1976) 1 एस. सी. सी. 843: 1976 (3) एससीआर 1; बी. के. श्रीनिवासन बनाम

महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम, 1937 ए. आई. आर. 1941 एफ. सी. 72; पंडित एम. एस. एम. शर्मा बनाम डॉ. श्री कृष्ण सिन्हा 1961 (1) एससीआर 96; आर. सी. पौड्याल बनाम

भारत संघ 1994 पूरक (1) एस. सी. सी. 324: 1993

1 [2015] 13 एस. सी

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(1) एस. सी. आर. 891; संपत्ति मालिक संघ बनाम।

प्रांत मैंगनीज अयस्क कंपनी लिमिटेड (1977) 1 एस. सी. सी. 643: 1977 (1) एससीआर 1002; इंडिया टोबैको कंपनी लिमिटेड बनाम। वाणिज्यिक कर अधिकारी, भवानीपुर (1975) 3 एससीसी 512: 1975 (2) एस. सी. आर. 612; कोल्हापुर

केनसुगर वर्क्स लिमिटेड बनाम। भारत संघ (2000) 2

एससीसी 536: 2000 (1) एससीआर 518; यू. पी. राज्य बनाम हिरेन्द्र पाल सिंह (2011) 5 एस. सी. सी. 305: 2010 (15) एस. सी. आर. 854; एयर लाइन की संयुक्त कार्रवाई समिति

पायलट एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम नागरिक उड्डयन महानिदेशक (2011) 5 एससीसी 435 2011 (5)

एस. सी. आर. 1019; तमिलनाडु राज्य बनाम। के. श्याम सुंदर (2011) 8 एससीसी 737: 2011 (11) एससीआर 1094; नगरपालिका समिति, अमृतसर बनाम। पंजाब राज्य (1969) 1 एससीसी 475: 1969 (3) एससीआर 447; के. ए.

अब्बास बनाम। भारत संघ (1970) 2 एससीसी 780: 1971 (2) एससीआर 446; टी. एन. शेषन बनाम भारत संघ (1995) 4 एससीसी 611: 1995 (2) पूरका एससीआर 106; आई. आर.

कोएल्हो वी। तमिलनाडु राज्य (2007) 2 एससीसी 1:

2007 (1) एससीआर 706; लिली थॉमस बनाम। भारत संघ;

(2013) 7 एससीसी 653: 2013 (10) एस. सी. आर. 1130; मुख्य चुनाव आयुक्त बनाम. जन चौकिदार (2013) 7 एस. सी. सी. 507; कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ (1977) 4 एससीसी 608: 1978 (2) एस. सी. आर. 1; कुलदिप नायर बनाम। भारत संघ (2006) 7 एससीसी 1: 2006 (5)

पूरका एस. सी. आर. 1; अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ (2008) 6 एससीसी 1: 2008 (4) एस. सी. आर. 1; लोक सेवा न्यायाधिकरण बार एसोसिएशन बनाम। यू. पी. राज्य

(2003) 4 एससीसी 104: 2003 (1) एस. सी. आर. 666; उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम। राजेश

कुमार (2012) 7 एससीसी 1: 2012 (4) एस. सी. आर. 118; बिहार राज्य बनाम बाल मुकुंद साह (2000) 4 एससीसी 640:

सर्वोच्च न्यायालय के वकील-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई.

2000 (2) एस. सी. आर. 299; नवल किशोर मिश्रा बनाम। इलाहाबाद उच्च न्यायालय (2015) 5 एससीसी

479: 2015 (3) एससीआर 107; वेस्ट यू. पी. शुगर मिल्स एसोसिएशन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2002) 2 एस. सी. सी. 645: 2002 (1) एससीआर 897; गैमन इंडिया लिमिटेड बनाम। विशेष मुख्य सचिव (2006) 3 एससीसी 354: 2006 (2)

एस. सी. आर. 304-संदर्भित।

अमीर-उन-निसा बेगम बनाम। महबूब बेगम ए. आई. आर 1955 एस. सी. 352; फर्म ए. टी. बी. मेहताव माजिद एंड कंपनी बनाम मद्रास राज्य ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 928: 1963 पूरका एससीआर 435; बी. एन. तिवारी बनाम भारत संघ ए. आई. आर. 1965

एससी 1430: 1965 एस. सी. आर. 421; कोटेश्वर विट्टल कामत बनाम। के. रंगप्पा बालिगा एंड कंपनी (1969) 1 एससीसी 255: 1969 (3) एस. सी. आर. 40; मूलचंद ओधवजी

वी. राजकोट नगर पालिका (1971) 3 एस. सी. सी. 53; मोहम्मद। शौकत हुसैन खान बनाम। आंध्र राज्य

प्रदेश (1974) 2 एससीसी 376; 1975 (1) एस. सी. आर. 429; इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (बॉम्बे) प्रा. लिमिटेड वी. भारत संघ (1985) 1 एससीसी 641; 1985 (2)

एससीआर 287; भगत राम शर्मा बनाम। भारत संघ 1988 (सप) एस. सी. सी. 30; 1988 एससीआर 1034; और राजस्थान राज्य बनाम। मंगिलाल पिंडवाल (1996) 5 एस. सी. सी. 60; 1996 (3) पूरक। एससीआर 98-आयोजित

अप्रयोज्य।

सरदार वल्लभभाई पटेल का भाषण

15.7.1947; "एच. एम. सीरवई द्वारा भारत का संवैधानिक कानून ", चौथा संस्करण; न्यायिक सुधार पर विधि आयोग की चौदहवीं रिपोर्ट

(1958); "न्यायपालिका की स्वतंत्रता" के सिद्धांतों का बीजिंग वक्तव्य; डॉ. बी. आर. अम्बेडकर का भाषण (संविधान सभा में)

पर 24.5.1949); "दिसंबर में गुलाब-एक आत्मकथा" एम. सी. चगला; "न तो गुलाब।

नॉर थोर्न्स एच. आर. खन्ना; एच. एम. सीरवई द्वारा "भारत का संवैधानिक कानून-एक आलोचनात्मक टिप्पणी"; "मेकिंग द एंजल्स [2015] शीर्षक वाले लेख 13 एस. सी.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

थोर्न्डन के लॉर्ड कुक द्वारा "रोएँ", और "जहाँ स्वर्गदूत चलने से डरते हैं"; "एक मुख्य न्यायाधीश की कहानी", यू. एल. भट्ट द्वारा; पाँचवाँ वी. एम. तारकुंडे

"एक स्वतंत्र न्यायपालिका" विषय पर रूमा पाल, जे. द्वारा स्मारक व्याख्यान; "न्यायपालिका का दूसरा पक्ष"

एस. एस. सोधी द्वारा "जस्टिस"; फली एस. नरीमन द्वारा "बिफोर मेमोरी फेड्स"; शीर्षक वाला लेख

"संरचना के मामले: भारतीय और अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय पर न्यायालय संरचना का प्रभाव कोर्ट ", निक राबिन्सन द्वारा; लेख-"द बेस "

बर्ट्राम रेवेन द्वारा "सामाजिक मुद्दों और सार्वजनिक नीति के विश्लेषण, वॉल्यूम।

8, सं. 1, 2008, पृ. 1-22; लेख-- डेनिस द्वारा "अनुपालन पर पक्षपात और पसंद के प्रभाव"

टी. रीगन, कॉर्नेल विश्वविद्यालय; "प्रभाव: द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन "-रॉबर्ट सियाल्डिनी, रीजेंट के प्रोफेसर एमेरिटस ऑफ साइकोलॉजी एंड

मार्केटिंग, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी; लॉरा ई. लिटिल, लॉ की एसोसिएट प्रोफेसर, टेम्पल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ द्वारा "वफादारी, कृतज्ञता और संघीय न्यायपालिका" शीर्षक वाला लेख; "संरक्षकों की रक्षा" पर पेपर: न्यायिक परिषदें

और न्यायिक स्वतंत्रता "नूनो गारोपा और टॉम गिन्सबर्ग द्वारा, लॉ स्कूल, विश्वविद्यालय
शिकागो, नवंबर 2008; और साउदर्नलैंड्स स्टैच्युटरी कंस्ट्रक्शन, तीसरा संस्करण, खंड I-संदर्भित।
चेलमेश्वर के क्रम में। जे. :

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य। वी. भारत संघ, (1993) 4 एस. सी. सी. 441;
और पी. डी. दिनाकरन (1) v. न्यायाधीश जांच समिति, (2011) 8 एस. सी. सी. 380-निर्दिष्ट।

डाइम्स वी। ग्रैंड जंक्शन कैनाल के मालिक,
(1852) 10 ई. आर. 301; रेजिना बनाम. गफ (1993) एसी 646; रेजिना बनाम। बो स्ट्रीट मेट्रोपोलिटन
उपदान मजिस्ट्रेट, पूर्व पक्ष पिनोचेट उगार्ते, सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. *

(1999) 1 सभी ई. आर. 577; वेकफील्ड स्थानीय बोर्ड

मजिस्ट्रेट कोर्ट एक्स पी। सिक्कोन [1973] वी. आर. 122; आर. वी. एंट्रिम जस्टिस [1895] 2 1. आर.
603; टोलपुट (एच.)

& कं. लिमिटेड बनाम। मोल [1911] 1 के. वी. 836; और कोरिगन

वी. आयरिश भूमि आयोग [1977] आई. आर. 317-निर्दिष्ट।

आर. ग्रांट हैमंड, न्यायिक बहिष्कार: सिद्धांत, प्रक्रिया और समस्याएं (हार्ट पब्लिशिंग, 2009)

- संदर्भित किया गया।

चेलमेश्वर के फैसले में। जे. :

परम पावन केशवानंद भारती श्रीपदगलवरु बनाम। केरल राज्य और एक अन्य

(1973) 4 एससीसी 225: 1973 (0) पूरक। एससीआर 1; एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ और अन्य। ए.
आई. आर 1982 एस. सी. 149: 1982 एससीआर 365; एल. सी. चंद्र कुमार और अन्य। वी. भारत संघ और
ओआरएस। (1997) 3 एससीसी 261: 1997 (2) एस. सी. आर. 1186; उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन
रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम। भारत संघ (1993) 4 एससीसी 441: 1993 (2) पूरक। एससीआर
659; भारत संघ। संकालचंद हिमाटियाल

शेठ और अन्न। (1977) 4 एससीसी 193: 1978 (1) एस. सी. आर. 423; चंद्रमौलेश्वर प्रसाद बनाम। पटना
हाई

न्यायालय और ओआरएस। (1969) 3 एससीसी 56: 1970 (2)

एससीआर 666; समशेर सिंह बनाम। पंजाब राज्य ए. आई. आर. 1974 एस. सी. 2192; 1975 (1) एससीआर 814; सुभाष शर्मा बनाम। भारत संघ (1991) सप. 1 एससीसी 574; 1990 (2) पूरक। एससीआर 433; 1998 (1998) का विशेष संदर्भ संख्या 1 7 एस. सी. सी. 739; 1998 (2) पूरक।

एससीआर 400; शांति भूषण और एक अन्य बनाम। भारत संघ और एक अन्य (2009) 1 एस. सी. सी. 657; 2008 (17) एससीआर 791; पी. डी. दिनाकरन (1) v.

न्यायाधीशों की जांच शीर्ष अदालत की रिपोर्ट

[2015] 13 एस. सी

समिति और एक अन्य (2011) 8 एससीसी 474; एल चंद्र कुमार बनाम। भारत संघ और अन्य। (1997) 3

एससीसी 261; 1997 (2) एससीआर 1186; आई. सी. गोलक नाथ और अन्य। वी. पंजाब और अन्न राज्या। (1967) 2 एस. सी. आर. 762; मिनर्वा मिल्स लिमिटेड और अन्य। वी. भारत संघ और

ओआरएस। (1980) 3 एस. सी. सी. 625; वामन राव और अन्य। आदि।

आदि वी। भारत संघ और अन्य। (1981) 2 एस. सी. सी. 362; इंदिरा नेहरू गांधी बनाम। राज नारायण (1975) पूरक एस. सी. सी. 1; एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) 3 एस. सी. सी. 1; एम. नागराज और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य (2006) 8 एस. सी. सी. 212; आई. आर. कोएल्हो (मृत) एल. आर. वी. टी. एन. राज्य (2007) 2 एस. सी. सी. 1; ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य ए. आई. आर. 1950 एस. सी. 27; ए. डी. एम. जबलपुर

वी. एस. एस. शुक्ला Etc.Etc ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 1207;

नरेश श्रीधर मिराजकर और अन्य। वी. की स्थिति

महाराष्ट्र और अन्न. ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1; बेरियम केमिकल्स लिमिटेड बनाम। कंपनी लॉ बोर्ड ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 295-निर्दिष्ट।

मार्बरी वी। मैडिसन 5 यू. एस. 137 (1803); वैलेंटे बनाम। क्वीन [कनाडा का सर्वोच्च न्यायालय] (1985) 2 एससीआर 673; रेजिना वी। बो स्ट्रीट मेट्रोपोलिटन

उपदान मजिस्ट्रेट, पूर्व पक्ष पिनोचेट उगार्ते (1999) 1 सभी ई. आर. 577-निर्दिष्ट।

सर विलियम ब्लैकस्टोन की, इंग्लैंड के कानूनों पर टिप्पणियां, (1765) खंड। 1 पी। 269; फाली एस.

मई 1949 (खंड। VIII); अभिनव चंद्रचूड, अनौपचारिक संविधान: में अलिखित मानदंड भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीशों का चयन, (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, यूनाइटेड किंगडम 2014) पृष्ठ 113 से 120 देखें; लायर, वी. आर. कृष्णा, न्यायपालिका: एक सुधार एजेंडा-II, द हिंदू (ऑनलाइन संस्करण) 15.08.2002; "एक स्वतंत्र न्यायपालिका" सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई.

- सुश्री न्यायमूर्ति रुमा पाल द्वारा दिया गया भाषण

10 तारीख को 5 वें वी. एम. तारकुंडे स्मारक व्याख्यान में

नवंबर 2011; मेहता, प्रताप भानू, 'आप किस पर भरोसा करते हैं', द इंडियन एक्सप्रेस, 14 मई 2015; राष्ट्रीय आयोग की समीक्षा के लिए

न्यायमूर्ति एम. एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में संविधान (एन. सी. आर. डब्ल्यू. सी.), 2002 का कार्यक्रम; फली एस. नरीमन, बिफोर मेमोरी फेड्स एन

आत्मकथा, पी। 389; लॉरेंस एच. जनजाति, भगवान

इस माननीय न्यायालय, प्रथम संस्करण को सहेजें, पी. 10

11; लॉरेंस एच. ट्राइब (अमेरिकी संवैधानिक कानून) दूसरा संस्करण-संदर्भित। लोकुर के आदेश और निर्णय में, जे। :

अपने स्वयं के प्रस्ताव पर न्यायालय v. राज्य और अन्य एम. ए. एन. यू./डी. ई./9073/2007; सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता

रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम। भारत संघ (1993) 4 एस. सी. सी. 441 1993 (2) पूरक। एससीआर 659; एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ 1981 (सप) एस. सी. सी. 87 1982

एस. सी. आर. 365; सुभाष शर्मा बनाम भारत संघ।

1991 पूरक (1) एस. सी. सी. 574; 1990 (2) पूरक। एससीआर 433; 1998 (1998) का विशेष संदर्भ संख्या 1 7 एस. सी. सी. 739; 1998 (2) पूरक। एस. सी. आर. 400; भारत संघ बनाम संकलचंद हिम्मतलाल सेठ (1977) 4

एस. सी. सी. 1993; आर. पुष्पम बनाम मद्रास राज्य ए. आई. आर. 1953 मद 392; सरदार लाल बनाम। भारत संघ (1971) 1 एससीसी 411; ज्योति प्रकाश मित्तर बनाम। मुख्य न्यायाधीश,

कलकत्ता [1965] 2 एससीआर 53; भारत संघ बनाम। ज्योति प्रकाश मित्तर (1971) 1 एससीसी 396; 1971 (3) एस. सी. आर. 483; राम जवाया कपूर बनाम। पंजाब राज्य [1955] 2 एससीआर 225; केशवानंद भारती बनाम। की स्थिति

केरल (1973) 4 एससीसी 225; 1973 (0) पूरक। एस. सी. आर. 1; इंदिरा नेहरू गांधी बनाम. राज नारायण 1975 सपोट

एससीसी 1: 1976 एस. सी. आर. 347; मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ (1980) 3 एससीसी 625 1981 (1) एससीआर 206; आई. आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) 2 एससीसी 1: 2007 (1) एससीआर 706; भीम सिंह [2015] 13 एससी

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बी. भारत संघ (2010) 5 एससीसी 538: 2010 (6) एस. सी. आर. 218; तमिलनाडु राज्य बनाम। केरल राज्य (2014) 12 एस. सी. सी. 696; मुल्लापेरियार पर्यावरण संरक्षण मंच बनाम। भारत संघ (2006) 3 एससीसी 643: 2006 (2) एस. सी. आर. 740; प्रशासक-बंगाल के जनरल बनाम। प्रेम लाल मलिक (1894-95) 22 आई. ए. 107; ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 एस. सी. आर.

88; त्रावणकोर राज्य-कोचीन बनाम। द बॉम्बे कंपनी लिमिटेड 1952 एससीआर 1112; गोलक नाथ बनाम। पंजाब राज्य (1967) 2 एससीआर 762; भारत संघ बनाम। एच. एस.

दिल्लों (1972) 2 एस. सी. आर. 331; इंद्र साहनी बनाम। भारत संघ 1992 पूरक (3) एस. सी. सी. 217: 1992 (2) पूरक। एससीआर 454; एस. आर. चौधरी बनाम की स्थिति

पंजाब (2001) 7 एससीसी 126: 2001 (1) पूरक। एससीआर 621; मनोज नरूला बनाम। भारत संघ (2014) 9 एससीसी 1: 2014 (9) एससीआर 965; टी. एम. ए. पाई

फाउंडेशन बी। कर्नाटक राज्य (2002) 8 एससीसी 481: 2002 (3) पूरक। एससीआर 587; बंगाल

प्रतिरक्षा कंपनी लिमिटेड बनाम। बिहार राज्य और अन्य। ए. आई. आर. 1955 एससी 661: 1955 एस. सी. आर. 603; बॉम्बे राज्य बनाम।

यूनाइटेड मोटर्स (इंडिया) लिमिटेड (1953) 4 एससीआर

1069; लेफ्टिनेंट कर्नल खजुर सिंह बनाम भारत संघ ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 532: 1961 एससीआर 828; केशव मिल्ल बनाम। सी. आई. टी. एयर 1965 एस. सी. 1636 1965 एस. सी. आर. 908; न्यू जहांगीर वकील मिल्ल लिमिटेड बनाम। सी. आई. टी. (1960) 1 एस. सी. आर. 249; मगनलाल छगनलाल बनाम। नगर निगम

ग्रेटर बॉम्बे (1974) 2 एस. सी. सी. 402: 1975 (1) एस. सी. आर. 1; उत्तर भारत कैटरर्स बनाम। पंजाब राज्य।

ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1581 1967 एस. सी. आर. 399; पेटलैड तुर्की रेड डाई वर्क्स कंपनी लिमिटेड, पेटलैड बनाम। सी. आई. टी. (1963) पूरक 1 एस. सी. आर. 871; गंगा चीनी

निगम बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1980) 1 एससीसी 223: 1980 (1) एस. सी. आर. 769; भारत संघ बनाम। रघुवीर सिंह (1989) 2 एससीसी 754: 1989 (3) एस. सी. आर. 316; गैनन डंकरली एंड कंपनी. बी. की स्थिति राजस्थान (1993) 1 एससीसी 364: 1992 (3) पूरक।

एससीआर 103; बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम।

संघ के सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई.

भारत से। (1989) 2 एससीसी 645: 1989 (2) एस. सी. आर. 320; खजुर सिंह, केशव मिल्स प्रदीप कुमार बिस्वास वी. भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान

(2002) 5 एससीसी 111: 2002 (3) एस. सी. आर. 100; सभाजीत तिवारी बनाम। भारत संघ (1975) 1 एस. सी. सी. 485; के. कमलाजम्मन्नियावार बनाम। विशेष भूमि

अधिग्रहण अधिकारी (1985) 1 एससीसी 582 1985 (2)

एससीआर 914; भाग सिंह बनाम। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ (1985) 3 एस. सी. सी. 737: 1985 (2) पूरक। एससीआर 949; आर. सी. पौड्याल बनाम भारत संघ 1994 पूरक (1) एस. सी. सी. 324 1993 (1) एस. सी. आर. 891; उप

न्यायिक जवाबदेही समिति v. भारत संघ (1991) 4 एस. सी. सी. 699; कर्तार सिंह बनाम। पंजाब राज्य (1994) 3 एससीसी 569: 1994 (2) एससीआर 375;

कृष्ण स्वामी बनाम। भारत संघ (1992) 4-एससीसी 605: 1992 (1) पूरक। एस. सी. आर. 53; भारत संघ बनाम। मद्रास बार एसोसिएशन (2010) 11 एस. सी. सी. 1: 2010 (6) एस. सी. आर. 857; राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ (1977) 3 एससीसी 592: 1978 (1) एस. सी. आर. 1; कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ (1977) 4 एससीसी 608: 1978 (2) एस. सी. आर. 1; कुलदिप नायर बनाम। भारत संघ

(1996) 7 एससीसी 1: 1995 (6) पूरक। एससीआर 17; अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत संघ (2008) 6 एससीसी 1: 2008 (4) एस. सी. आर. 1; मद्रास बार एसोसिएशन

वी. भारत संघ (2014) 10 एस. सी. सी. 1; मिनर्वा मिल्स बनाम। भारत संघ (1980) 3 एससीसी 625: 1981 (1) एस. सी. आर. 206; संजीव कोक में मिनर्वा मिल्स

विनिर्माण कं. वी. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

(1983) 1 एससीसी 1471 : 1983 (1) एस. सी. आर. 1000; एम.

नागराज बनाम। भारत संघ (2006) 8 एससीसी 212: 2006 (7) पूरक। एससीआर 336; भीम सिंहजी बनाम। भारत संघ (1981) 1 एस. सी. सी. 166; चरणजीत लाल चौधरी

वी. भारत संघ [1950] एससीआर 869; राम कृष्ण

डालमिया बनाम। न्यायमूर्ति एस. आर. तेंदुलकर [1959] एस. सी. आर. 279; आर. के. गर्ग बनाम भारत संघ (1981) 4 एससीसी 675: 1982 (1) एस. सी. आर. 947; श्री पृथ्वी काँटन मिल्स लिमिटेड बनाम। ब्रोच बरो नगरपालिका (1969) 2 एससीसी [2015] 13 एस. सी.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

283 : 1970 (1) एससीआर 388; के. शंकरन नायर बनाम। देवकी अम्मा मालथी अम्मा (1996) 11 एससीसी 428: 1996 (6) पूरक। एस. सी. आर. 839; भुवनेश्वर सिंह बनाम भारत संघ (1994) 6 एससीसी 77: 1994 (1) पूरक। एस. सी. आर. 639; कावेरी जल विवाद

न्यायाधिकरण (1993) सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 96: 1991 (2) पूरक। एस. सी. आर. 497; इंडियन एल्यूमीनियम कं. v. राज्य

केरल का (1996) 7 एस. सी. सी. 637 1996 (2) एस. सी. आर. 23; ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य [1950] 1 एस. सी. आर. 88; जालान ट्रेडिंग कंपनी (पी) लिमिटेड v. मिल मजदूर सभा संघ [1967] 1 एस. सी. आर. 15;

कर्नाटक बैंक लिमिटेड बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2008) 2 एससीसी 254: 2008 (1) एस. सी. आर. 986; मो. हनीफ कुरेशी बनाम। बिहार राज्य [1959] एससीआर 629;

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम। अनवर अली सरकार [1952] एससीआर 284; ए. पी. बनाम राज्य मैकडॉवेल एंड कंपनी (1996) 3 एससीसी 709: 1996 (3) एस. सी. आर. 721; लोक सेवा न्यायाधिकरण बार एसोसिएशन बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2003) 4 एससीसी

104 : 2003 (1) एससीआर 666; छोटाभाई जेठाभाई पटेल बनाम। भारत संघ। 1962 उदाहरण के लिए (2) एस. सी. आर. 1; किहोतो होलोहन बनाम। ज़किलहु 1992 सप (2) एस. सी. सी.

651 : 1992 (1) एससीआर 686; डी. के. त्रिवेदी एंड संस बनाम गुजरात राज्य 1986 पूरक एस. सी. सी. 20: 1986 एस. सी. आर. 479; मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ

(1997) 5 एससीसी 536: 1996 (10) पूरक। एस. सी. आर. 585; बाबूलाल पाराटे बनाम। बॉम्बे राज्य [1960] (1) एससीआर

605; राजा राम पाल बनाम। लोकसभा (2007) 3 एससीसी 184: 2007 (1) एससीआर 317; ए. के. राँय बनाम संघ का

भारत (1982) 1 एससीसी 271: 1982 (2) एस. सी. आर. 272; पी. आई. एल. के लिए केंद्र बनाम। भारत संघ (2011) 4 एससीसी 1:

2011 (4) एस. सी. आर. 445; महापंजीयक, मद्रास उच्च न्यायालय बनाम आर. गांधी (2014) 11 एससीसी 547: 2014 (4) एससीआर 77; इंदिरा नेहरू गांधी और मिनर्वा

मिल्स। (2007) 2 एस. सी. सी. 1; कुमार पद्म प्रसाद बनाम भारत संघ (1992) 2 एस. सी. सी. 428; रेणु बनाम। जिला

जज (2014) 14 एस. सी. सी. 50; इंडियन एक्सप्रेस

समाचार पत्र वी।

भारत संघ (1985) 1 एस. सी. सी. 641; सर्वोच्च न्यायालय-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई.

यू. पी. राज्य बनाम राज नारायण (1975) 4 एससीसी 428; 1975 (3) एससीआर 333; रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड।

बी. इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स बॉम्बे (पी) लिमिटेड (1988) 4 एससीसी 592 के स्वामी: 1988 (3)

पूरका एससीआर 212; वेस्ट यू. पी. शुगर मिल्स एसोसिएशन बी. उत्तर प्रदेश राज्य (2002) 2 एस. सी. सी. 645; 2002 (1) एससीआर 897; बी. एन. तिवारी बनाम भारत संघ ए. आई. आर. 1965 एस. सी.

1430 : 1965 एससीआर 421; फर्म ए. टी. बी. मेहताब माजिद एंड कंपनी बनाम मद्रास राज्य ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 928; 1963 पूरका एस. सी. आर. 435; इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र (बॉम्) (पी) लिमिटेड बनाम भारत संघ (1985) 1 एससीसी 641; 1985 (2) एससीआर 287; राज्य टी. एन. बी. के. श्याम

सुंदर (2011) 8 एससीसी 737; 2011 (11) एससीआर 1094

- संदर्भित किया गया।

यूनाइटेड माइन वर्कर्स ऑफ अमेरिका 325 यू. एस. 897 (1945); हनराहन बनाम। हैम्पटन 446 यूएस 1301 (1980); अल-जेहाद ट्रस्ट बनाम। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान

पी. एल. डी. 1996 एस. सी. 324; ब्लैक क्लॉसन इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम पेपियरवेर्क वाल्डोफ़-एशाफ़ेनबर्ग अक्टॉजिसेलशाफ्ट [1975] ए. सी. 591; द स्टेट बनाम।

टी. मकवान्याने 1995 (3) एसए 391 (सीसी); एन. एस. डब्ल्यू. बनाम के लिए महान्यायवादी द परपेचुअल ट्रस्टी कं. लिमिटेड 85 सी. एल. आर. 237; द क्वीन बनाम. ब्यूरगार्ड।

[1986] 2 एससीआर 56; मार्बरी बनाम। मेडिसन: 5 अमेरिका (1 शाखा) 137; पुनः शक्तियाँ, विशेषाधिकार और

राज्य विधानमंडलों की छूट [1965] 1 एस. सी. आर.

413; पॉकेट वीटो मामला 279 यू. एस. 655,689 (1929); मिसौरी पैक की तुलना करें। राइ। को. बी. कैनेसस 248 अमेरिका 276; मायर्स बनाम। संयुक्त राज्य अमेरिका 272

52; राज्य बी। साउथ नॉरवॉक 77 कॉन। 257; यंगस्टाउन शीट एंड ट्यूब कं. बी. सॉयर 343 यू. एस.

579, 635 (1952); एंडरसन बनाम। गोरी [1895] 1 क्यू. बी.

668; मैक (ए माइनर), री [1985] ए. सी. 528; लोच्चर बी. न्यूयॉर्क 198 यूएस 45; फर्ग्यूसन बनाम। स्कूपा 372 यू. एस. 726; मिडलटन बनाम। टेक्सास पावर एंड लाइट कं।

249 यूएस 152,157; अब्राम्स बनाम। संयुक्त राज्य अमेरिका 250 यू. एस. 616 (1919); द क्वीन बनाम। बेयुरेगार्ड [1986] [2015] 13 एस. सी.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2 एस. सी. आर. 56; महान्यायवादी बनाम टाइम्स न्यूजपेपर्स लिमिटेड 1973 3 सभी ई. आर. 54-संदर्भित।

सप्रू समिति रिपोर्ट, 1945, अध्याय 5, पैराग्राफ 259, 261 और 268, //

सेप्रुकमिटी 035520 एम. बी. पी./सेप्रुकमिटी 035520 एमबीपी दिवू। टीएक्सटी; बी. शिव राव: 'द.

भारत के संविधान 'सेलेक्ट' का निर्माण

दस्तावेज़, खंड II और खंड IV; भारतीय

पृष्ठ 126 पर ग्रैनविल ऑस्टिन, फुटनोट 39; // भारत की संसद। ठीक है। / है/बहुस में। एचटीएम; न्यायिक स्वतंत्रता पर व्याख्यान, लॉर्ड फिलिप्स; विधि आयोग की 14 वीं, 80 वीं और 121 वीं रिपोर्ट

भारत;

एचटीटीपी: //

में से

डब्ल्यू. डब्ल्यू. टी. एन. एस. ए. टी.एन। ठीक है। में/लेख/न्यायिक% 20 स्वतंत्रता% 20JSVJ.pdf; ग्रैनविल ऑस्टिन:

लोकतांत्रिक संविधान पृष्ठ 131 पर काम करना;

एचटीटीपी: //अभी करें। गव. / साइटों/डिफ़ॉल्ट/फाइलों में

1

स्मारक। पी. डी. एफ.; एच. टी. पी: //करते हैं। गव. इन/साइट/डिफ़ॉल्ट/फाइल/मेमोस्क। पी. डी. एफ.; प्रोफेसर एम. पी. द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति में "योग्यता" शीर्षक वाला लेख। सिंह, (1999) 8 एस. सी. सी. (जर्नल) 1; सर्वोच्च लेकिन अचूक नहीं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सम्मान में निबंध पृष्ठ 48,53; राजनीति का व्याकरण (हेरोल्ड जे. लास्की का कार्य), 297; संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान पर विलोबी, पृष्ठ 64;

"लर्निंग एंड साइंस ", हार्वर्ड लॉ स्कूल एसोसिएशन में भाषण (25 जून, 1895); ओलिवर वेंडेल होम्स द्वारा भाषण (1896)। पी। 67-68; न्यायिक जोनाथन के. वान पैटन द्वारा स्वतंत्रता और कानून का शासन, खंड 2 बेंचमार्क पृष्ठ 117,129

(1986); ली एपस्टीन, जैक नाइट और ओल्गा श्वेतसोवा, न्यायिक चयन की तुलना

सिस्टम, 10 डब्ल्यू. एम. और मैरी बिल आर. टी. एस. जे. 7, एन. 9 (2001); न्यायिक स्वतंत्रता, संक्रमणकालीन

डेविड सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स द्वारा न्याय और कानून का शासन-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई.

डायजेनहॉस, (2001-2004) 10 ओटागो एल रेव 345 पर 345-346; द फ्रंटलाइन, खंड 25 अंक 20

27 सितंबर, 2008 से 10 अक्टूबर, 2008 तक; //

डब्ल्यू. डब्ल्यू. न्यायपालिका। सीनेट। जीओबी/इमो/मीडिया/डॉक /

केनेडी _ गवाही _ 02 _ 14 _ 07। पीडीएफ;

रिपोर्ट करें।

न्यायिक स्वतंत्रता: कानून और

यूरोपीय लोगों के लिए नियुक्तियों का अभ्यास

मानवाधिकार न्यायालय , HTTP: // डब्ल्यू. डब्ल्यू. अंतर्विरोध। ओ. आर. जी./दस्तावेज/142/सूचकांक।
एचटीएमएल;

के सिद्धांतों का बीजिंग वक्तव्य लावासिया में न्यायपालिका की स्वतंत्रता

28 अगस्त, 1997 को मनीला में संशोधित क्षेत्र; 'न्यायिक नियुक्तियों' पर तीसरा व्याख्यान

4 दिसंबर, 2012 को 'कानून सुधार के पहलू' शीर्षक से हैमलिन व्याख्यानों की 64 वीं श्रृंखला का वितरण किया गया।

एक अंदरूनी व्यक्ति का दृष्टिकोण ; नियुक्ति

ऑस्ट्रेलियाई न्यायाधीश: साइमन इवांस और जॉन विलियम्स का एक नया मॉडल, [2008] सिडनी लॉ रिव्यू
वॉल्यूम 30 पेज 295; //

सिडनी। एड्यू। एयू/लॉ/एसएलआर/एसएलआर 30 _ 2/इवांस। पीडीएफ;

एचटीटीपी: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. सबरा। को. ज़ा/लॉ-जर्नल्स/2010/दिसंबर/2010-दिसंबर-वॉल्यूम 023-नंबर 3-
पीपी43 48. पीडीएफ; //डब्ल्यू. डब्ल्यू. विधि समाज। org. बीडब्ल्यू/समाचार /

स्थिति% 20 पेपर% 20 ऑन% 20 अपोइन्टमेंट% 2 0 ऑफ% 20 जज्स% 20 फ़ाइनल% 2014% 20 जून%
202012% 2

ओ 'फाइनल'। पी. डी. एफ.; कार्ली वान ऑर्मन, परिचर्चा का परिचय: न्यायिक प्रक्रिया

नियुक्ति प्रक्रिया, 10 डब्ल्यू. एम. & मैरी बिल आर. टी. जे. 1 (2001), एचटीटीपी: //छात्रवृत्ति। कानून।
डब्ल्यू. एम. ई. डी. यू./डब्ल्यू. एम. बी. आर. जे./वॉल्यूम 10/आई. एस. 1/2; नियुक्ति और

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सर एंथनी मेसन ए. सी. के. बी. ई. द्वारा न्यायाधीशों को हटाना; //

एफबीमेसन। एचटीएम: शिमोन शेट्टीट, मुकदमे पर न्यायाधीश (नॉर्थ-हॉलैंड पब्लिशिंग कंपनी,
एम्स्टर्डम, (1976), पृष्ठ 46; अक्कास, सरकार अली (2004)

[2015] 13 एस. सी

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

"न्यायाधीशों की नियुक्ति: एक प्रमुख मुद्दा

न्यायिक स्वतंत्रता, "बॉन्ड लॉ रिव्यू:

खण्ड. 16 : इश्यू। 2, अनुच्छेद 8; HTTP:// प्रकाशन। बंधन। एड्यू। ए. यू./बी. एल. आर./वॉल्यूम 16/आई. एस. एस. 2/8

संदर्भित किया गया।

कुरियन के क्रम में, जे। :

एस. पार्थसारथी बनाम। ए. पी. राज्य (1974) 3 एस. सी. सी. 459: 1974 (1) एस. सी. आर. 697-संदर्भित।

आर वी। ससेक्स जस्टिस एक्स पार्टे मैक-कार्थी (1923)

सभी ई. आर. प्रतिनिधि। 233 ; सार्वजनिक उपयोगिता आयोग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया एट अल।
वी. पोलक एट अल। 343 यू. एस. 451 (1952); गणराज्य के राष्ट्रपति

दक्षिण अफ्रीका आदि v. दक्षिण अफ्रीकी रग्बी फुटबॉल

संघ आदि। 1999 (4) एस. ए. 147-संदर्भित। कुरियन के फैसले में, जे। :

पवित्रता

केशवानंद भारती

उनके श्रीपदगलवरु बनाम। केरल राज्य और अन्य

(1973) 4 एससीसी 225: 1973 (0) पूरक। एस. सी. आर. 1; समशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य
(1974) 2 एससीसी 831: 1975 (1) एस. सी. आर. 814-संदर्भित।

राज्य वी। एरिजोना स्वतंत्र पुनर्निर्धारण

आयोग मनु/यूएसएससी/0060/2015-निर्दिष्ट

को। गोयल के निर्णय में, जे। :

1998 (1998) का विशेष संदर्भ संख्या 1 7 एस. सी. सी.

739 1998 (2) पूरक। एससीआर 400; एससीएओआरए बनाम।

भारत संघ (1993) 4 एससीसी 441: 1993 (2) पूरक।

एस. सी. आर. 659; संपत्ति मालिक संघ v. राज्य

महाराष्ट्र (1996) 4 एस. सी. सी. 49; 1996 (2)

पूरका. एस. सी. आर. 230; केशवानंद भारती बनाम. राज्य

केरल का 1973 (4) एस. सी. सी. 225; 1973 (0) पूरका।

एस. सी. आर. 1; इंदिरा नेहरू गांधी बनाम. राज नारायण (1975)

सप. एससीसी 1: 1976 एससीआर 347; मिनर्वा मिल्स लिमिटेड।

बनाम भारत संघ (1980) 3 एससीसी 625 1981 (1)

एस. सी. आर. 206; एल. चंद्र कुमार बनाम

भारत संघ, सर्वोच्च न्यायालय-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई.

(1997) 3 एससीसी 261: 1997 (2) एससीआर 1186; आई. आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) 2 एस. सी. सी. 1:

2006 (10) पूरका. एस. सी. आर. 197; एम. नागराज बनाम भारत संघ (2006) 8 एससीसी 212: 2007 (9) एससीआर 259; एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ 1981 सप. एससीसी 87: 1982 एस. सी. आर. 365; सुभाष शर्मा बनाम संघ का

भारत 1991 पूरक (1) एस. सी. सी. 574: 1990 (2) पूरका. एस. सी. आर. 433; भारत संघ बनाम। संकलचंद हिम्मतलाल सेठ 1977 (4) एस. सी. सी. 193: 1978 (1) एससीआर 423; शमशेर सिंह बनाम। पंजाब राज्य 1974 (2) एससीसी 831: 1975 (1) एससीआर 814; जनहित याचिका केंद्र v. यूओओ! (2012) 3 एससीसी 1: 2012 (3) एससीआर 147; मनोहर लाल शर्मा बनाम। यूओआई (2014) 2 एससीसी 532; एस. आर. बोम्मई बनाम यूओआई (1994) 3 एससीसी 1: 1994 (2) एस. सी. आर. 644; रामेश्वर प्रसाद बनाम यूओआई (2006) 2 एससीसी 1: 2006 (1) एससीआर 562; एम. सी मेहता बनाम कमल नाथ (1997) 1 एससीसी 388: 1996 (10) पूरका. एस. सी. आर. 12; किहोतो होलोहन बनाम। ज़चिल्लू (1992)

सप. (2) 651 : 1992 (1) एससीआर 686; सहारा इंडिया

रियल एस्टेट कार्पोरेशन। लिमिटेड बी. SEBI (2012) 10 SC 603: 2012 (12) एस. सी. आर. 256; चंद्र मौलीश्वर प्रसाद वी. पटना उच्च न्यायालय 1969 (3) एस. सी. सी. 56: 1970 (2) एससीआर 666; मनोज नरूला बनाम। भारत संघ 2014

(9) एससीसी 1: 2014 (9) एस. सी. आर. 965; श्री पृथ्वी कॉटन मिल्स लिमिटेड बनाम ब्रोच बरो नगरपालिका (1969) 2 एससीसी 283: 1970 (1) एससीआर 388; भीम सिंह जी बनाम भारत संघ (1981) 1 एससीसी 166; अशोक

कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ (2008) 6 एससीसी 1: 2008 (4) एस. सी. आर. 1; मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ (1997) 5 एससीसी 536 1996 (10) पूरक। एस. सी. आर. 585; इंदरप्रीत सिंह काहलों बनाम।

पंजाब राज्य (2006) 11 एससीसी 356: 2006 (1) पूरक। एससीआर 772; मेनका गांधी बनाम. यू. ओ. आई. (1978)

1 एससीसी 248: 1978 (2) एससीआर 621; वी. जी. रो बनाम मद्रास राज्य (1952) एस. सी. आर. 597; माधव राव

जीवाजी राव सिंधिया बनाम। यूओआई 1971 (1) एससीसी 85: 1971 (3) एस. सी. आर. 9; रुस्तम कावासजी कूपर बनाम।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्टों का संघ

[2015] 13 एस. पी.

1 : 1994 (2) एस. सी. आर. 644; पी. संबमूर्ति बनाम। ए. पी. राज्य (1994) 3 एस. सी. सी. 1: 1994 (2) एस. सी. आर. 644; अमरीक सिंह ल्यालपुरी बनाम। यूओआई (2011) 6 एससीसी 535: 2011 (5) एस. सी. आर. 560; भारत संघ बनाम। मद्रास बार एसन। (2010) 11 एससीसी 1: 2010 (6) एस. सी. आर. 857; मद्रास बार एसन। वी. यूओआई (2014) 10 एससीसी 1:

विशेष संदर्भ संख्या 1 (1965) 1 एस. सी. सी. 413; लिली

थॉमस वी। भारत संघ 2013 (7) एससीसी 653: 2013 (10) एस. सी. आर. 1130; मुख्य चुनाव आयुक्त बनाम

जन चौकीदार 2013 (7) एस. सी. सी. 507-संदर्भित।

सीरवाई, चौथा संस्करण, भारत का संवैधानिक कानून; विधि आयोग की 14 वीं और 121 वीं रिपोर्ट;

रिपोर्ट दिनांक 26.9.2001 जैसा कि खंड में शामिल है। एन. सी. आर. डब्ल्यू. सी., 2002 की रिपोर्ट का II, पैरा 9.6 और 9.7

- संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

खेहर के निर्णय में, जे। : (संदर्भ क्रम)

1982 एससीआर 365

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

1993 (2) पूरक। एससीआर 659

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

1998 (2) पूरक। एससीआर 400

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

1990 (2) पूरक। एससीआर 433

संदर्भित किया गया है

पैरा 11

संदर्भित किया गया है

पैरा 16 (i.

1978 (1) एससीआर 423

2002 (3) पूरक। एससीआर 587

संदर्भित किया गया है

पैरा 26

2002 (3) पूरक। एससीआर 366

पैरा 26

संदर्भित किया गया है

2001 (1) पूरक। एससीआर 621

संदर्भित किया गया है

पैरा 26

1992 (2) पूरक। एससीआर 454

संदर्भित किया गया है

पैरा 26

1973 (0) पूरक। एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 26

1975 (1) एससीआर 814

संदर्भित किया गया है

पैरा 26

(2014) 9 एससीसी 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 26

2010 (6) एससीआर 218

संदर्भित किया गया है

पैरा 33 सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई.

2007 (7) एससीआर 705

संदर्भित किया गया है

पैरा 33

2011 (4) एससीआर 224

संदर्भित किया गया है

पैरा 36

2010 (4) एससीआर 743

संदर्भित किया गया है

पैरा 38

1991 (2) पूरक। एससीआर 497

पैरा 45

संदर्भित किया गया है

2006 (4) पूरक। एससीआर 243

संदर्भित किया गया है

पैरा 47

(1955) 6 एससीआर 603

संदर्भित किया गया है

पैरा 49

1975 (1) एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 49

1989 (3) एससीआर 316

पैरा 49

संदर्भित किया गया है

2002 (3) एससीआर 100

संदर्भित किया गया है

पैरा 49

2011 (4) एस. सी. आर 19

संदर्भित किया गया है

पैरा 51

2004 (1) एससीआर 564

संदर्भित किया गया है

पैरा 51

1989 (1) पूरक। एससीआर 692

संदर्भित किया गया है

पैरा 51

(1992) 4 एससीसी 97

संदर्भित किया गया है

पैरा 51

(1953) एससीआर 1069

संदर्भित किया गया है

पैरा 52

(1965) 2 एससीआर 908

संदर्भित किया गया है

पैरा 52

(1961) 2 एससीआर 828

संदर्भित किया गया है

पैरा 58

1980 (1) एससीआर 769

संदर्भित किया गया है

पैरा 58

1992 (3) पूरक। एससीआर 103

संदर्भित किया गया है

पैरा 58

पैरा 100

संदर्भित किया गया है

1999 (2) पूरक। एससीआर 473

(योग्यता पर आदेश)

1981 (1) एससीआर 206

संदर्भित किया गया है

पैरा 5

1992 (1) एससीआर 686

संदर्भित किया गया है

पैरा 5

(2014) 10 एससीसी 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 11.

2006 (7) पूरका एससीआर 336

संदर्भित किया गया है

पैरा 15

1971 (3) एससीआर 461

संदर्भित किया गया है

पैरा 26

2010 (6) एससीआर 857

संदर्भित किया गया है

पैरा 37

(2015) 4 स्केल 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 40

(1952) एससीआर 597

संदर्भित किया गया है

पैरा 43

1967 एससीआर 762

संदर्भित किया गया है

पैरा 44

1971 (3) एस. सी. आर 9

संदर्भित किया गया है

पैरा 45

2012 (3) एससीआर 147

संदर्भित किया गया है

पैरा 46

(2014) 2 एस. सी. सी. 532

संदर्भित किया गया है

पैरा 46

1990 (3) एससीआर 441

संदर्भित किया गया है

पैरा 47 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015] 13 एस. सी.

(1979) 1 एससीसी 380

संदर्भित किया गया है

पैरा 47

2014 (6) एससीआर 873

संदर्भित किया गया है

पैरा 47

ए. आई. आर 1993 एस. सी 1873

पैरा 54

संदर्भित किया गया।

1982 (2) एससीआर 272

संदर्भित किया गया है

पैरा 58

1950 एससीआर 869

संदर्भित किया गया है

पैरा 71

1959 एससीआर 279

संदर्भित किया गया है

पैरा 71

1975 (2) एससीआर 774

संदर्भित किया गया है

पैरा 71

2008 (3) एससीआर 330

संदर्भित किया गया है

पैरा 71

1959 एससीआर 629

संदर्भित किया गया है

पैरा 72

1952 एससीआर 284

संदर्भित किया गया है

पैरा 72

1976 एससीआर 347

संदर्भित किया गया है

पैरा 78

1981 (2) एससीआर 1

पैरा 78

संदर्भित किया गया है

1989 (3) एस. सी. आर 19

संदर्भित किया गया है

पैरा 81

1996 (9) पूरक। एससीआर 479

संदर्भित किया गया है

पैरा 81

(1961) 3 एससीआर 707

संदर्भित किया गया है

पैरा 99

1976 (3) एससीआर 1.

संदर्भित किया गया है

पैरा 99

1987 (1) एससीआर 1054

संदर्भित किया गया है

पैरा 99

(2005) 5 एस. सी. सी. 363

संदर्भित किया गया है

पैरा 99

1961 (1) एससीआर 96

संदर्भित किया गया है

पैरा 102

1993 (1) एससीआर 891

संदर्भित किया गया है

पैरा 105

1996 (2) पूरक। एससीआर 230

संदर्भित किया गया है

पैरा 107

(2001) 4 एससीसी 455

संदर्भित किया गया है

पैरा 107

(2013) 7 एस. सी. सी. 522

संदर्भित किया गया है

पैरा 107

आकाशवाणी 1955 एससी 352

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा 108

1963 पूरक। एससीआर 435

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा 108

अप्रयोज्य रखा गया

1965 एससीआर 421

पैरा 108

1969 (3) एससीआर 40

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा 108

(1971) 3 एससीसी 53

अप्रयोज्य रखा गया।

पैरा 108

1975 (1) एससीआर 429

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा 108

1977 (1) एससीआर 1002

संदर्भित किया गया है

पैरा 108

1975 (2) एससीआर 612

संदर्भित किया गया है

पैरा 108 सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई.

2000 (1) एससीआर 518

संदर्भित किया गया है

पैरा 108

2010 (15) एससीआर 854

संदर्भित किया गया है

पैरा 108

पैरा 108

संदर्भित किया गया है

2011 (5) एससीआर 1019

2011 (11) एससीआर 1094

संदर्भित किया गया है

पैरा 108

1969 (3) एससीआर 447

संदर्भित किया गया है

पैरा 121

1971 (2) एससीआर 446

संदर्भित किया गया है

पैरा 121

1995 (2) पूरक। एससीआर 106

संदर्भित किया गया है

पैरा 122

संदर्भित किया गया है

पैरा 130

2007 (1) एससीआर 706

(2013) 7 एस. सी. सी. 507

संदर्भित किया गया है

पैरा 138

2013 (10) एससीआर 1130

पैरा 138

संदर्भित किया गया है

1978 (2) एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 215

2006 (5) पूरक। एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 215

पैरा 215

2008 (4) एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 216

संदर्भित किया गया है

2003 (1) एससीआर 666

2012 (4) एससीआर 118

संदर्भित किया गया है

पैरा 217

संदर्भित किया गया है

पैरा 218

2000 (2) एससीआर 299

2015 (3) एससीआर 107

पैरा 218 को संदर्भित किया गया

अप्रयोज्य पैरा 250 (vii)

1985 (2) एससीआर 287

अप्रयोज्य पैरा 250 (viii)

1988 एससीआर 1034

लागू नहीं होने वाला पैरा 250 (ix)

1996 (3) पूरक। एससीआर 98

पैरा 250 (xi)

संदर्भित किया गया है

2002 (1) एससीआर 897

पैरा 250 (xi)

संदर्भित किया गया है

2006 (2) एससीआर 304

चेलमेश्वर के क्रम में। जे. :

(1993) 4 एस. सी. सी. 441

पैरा 2

संदर्भित किया गया है

(2011) 8 एससीसी 380

संदर्भित किया गया है

पैरा 25

चेलमेश्वर के निर्णय में, जे। :

पैरा 11

1973 (0) पूरक। एस. सी. आर. 1 संदर्भित

1982 एससीआर 365

संदर्भित किया गया है

पैरा 14

संदर्भित किया गया है

1997 (2) एससीआर 1186

पैरा 28

1993 (2) पूरक। एस. सी. आर. 659 संदर्भित

पैरा 39

संदर्भित किया गया है

1978 (1) एससीआर 423

पैरा 40 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015] 13 एस. पी.

1970 (2) एससीआर 666

संदर्भित किया गया है

पैरा 42

1975 (1) एससीआर 814

संदर्भित किया गया है

पैरा 42

1990 (2) पूरक। एससीआर 433

संदर्भित किया गया है

पैरा 45

संदर्भित किया गया है

1998 (2) पूरक। एससीआर 400

पैरा 56

2008 (17) एससीआर 791

संदर्भित किया गया है

पैरा 59

2011 (10) एससीआर 1064

संदर्भित किया गया है

पैरा 59

(2011) 8 एस. सी. सी. 474

संदर्भित किया गया है

पैरा 59

संदर्भित किया गया है

1997 (2) एससीआर 1186

पैरा 64

(1980) 3 एस. सी. सी. 625

संदर्भित किया गया है

पैरा 72

(1981) 2 एस. सी. सी. 362

संदर्भित किया गया है

पैरा 73

(1975) पूरक एस. सी. सी. 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 73

(1994) 3 एससीसी 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 79

(2006) 8 एससीसी 212

संदर्भित किया गया है

पैरा 80

(2007) 2 एससीसी 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 81

संदर्भित

को

आकाशवाणी 1976 एससी 1207

पैरा 103

आकाशवाणी 1967 एससी 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 106

ए. आई. आर 1967 एस. सी. 295

संदर्भित किया गया है

पैरा 111

लोकुर के फैसले में। जे:

1996 एससी 324

संदर्भित किया गया है

पैरा 7

1993 (2) पूरक। एस. सी. आर. 659 संदर्भित

पैरा 51

1982 एससीआर 365

संदर्भित किया गया है

पैरा 55

1990 (2) पूरक। एससीआर 433

संदर्भित किया गया है

पैरा 55

1998 (2) पूरक। एससीआर 400

संदर्भित किया गया है

पैरा 103

(1977) 4 एससीसी 1993

संदर्भित किया गया है

पैरा 105

(1971) 1 एस. सी. सी. 411

संदर्भित किया गया है

पैरा 139

[1965] 2 एससीआर 53

संदर्भित किया गया है

पैरा 142

1971 (3) एससीआर 483

संदर्भित किया गया है

पैरा 142

[1955] 2 एससीआर 225

संदर्भित किया गया है

पैरा 195

1973 (0) पूरक। एस. सी. आर. 1. संदर्भित

पैरा 196

1976 एससीआर 347

संदर्भित किया गया है

पैरा 197

1981 (1) एससीआर 206

संदर्भित किया गया है

पैरा 200 अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

अभिकरण v. यू. ओ. आई.

संदर्भित किया गया है

पैरा 202

पैरा 203

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

पैरा 204

संदर्भित किया गया है

पैरा 204

संदर्भित किया गया है

पैरा 208

संदर्भित किया गया है

पैरा 213

संदर्भित किया गया है

पैरा 214

संदर्भित किया गया है

पैरा 220

संदर्भित किया गया है

पैरा 228

संदर्भित किया गया है

पैरा 229

संदर्भित किया गया है

पैरा 229

संदर्भित किया गया है

पैरा 230

संदर्भित किया गया है

पैरा 243

संदर्भित किया गया है

पैरा 243

पैरा 249

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

पैरा 250

संदर्भित किया गया है

पैरा 250

संदर्भित किया गया है

पैरा 250

संदर्भित किया गया है

पैरा 251

संदर्भित किया गया है

पैरा 251

संदर्भित किया गया है

पैरा 252

संदर्भित किया गया है

पैरा 253

पैरा 256

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

पैरा 256

संदर्भित किया गया है

पैरा 257

संदर्भित किया गया है

पैरा 257

संदर्भित किया गया है

पैरा 263

संदर्भित किया गया है

पैरा 263

संदर्भित किया गया है

पैरा 263

संदर्भित किया गया है

पैरा 264

संदर्भित किया गया है

पैरा 270 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

[2015] 13 एस. पी.

(1991) 4 एससीसी 699

संदर्भित किया गया है

पैरा 297

1994 (2) एससीआर 375

संदर्भित किया गया है

पैरा 298

1992 (1) पूरक। एस. सी. आर. 53 संदर्भित

पैरा 299

संदर्भित किया गया है

2010 (6) एससीआर 857

पैरा 300

संदर्भित किया गया है

1978 (1) एससीआर 1

पैरा 361

1978 (2) एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 386

1995 (6) पूरक। एस. सी. आर. 17 संदर्भित

पैरा 387

2008 (4) एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 388

(2014) 10 एससीसी 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 389

संदर्भित किया गया है

1981 (1) एससीआर 206

पैरा 397

1983 (1) एससीआर 1000

संदर्भित किया गया है

पैरा 398

2006 (7) पूरक। एस. सी. आर. 336 को संदर्भित किया गया

पैरा 399

(1981) 1 एससीसी 166

संदर्भित किया गया है

पैरा 401

[1950] एससीआर 869

संदर्भित किया गया है

पैरा 406

[1959] एससीआर 279

संदर्भित किया गया है

पैरा 407

पैरा 409

1982 (1) एससीआर 947

संदर्भित किया गया है

1970 (1) एससीआर 388

संदर्भित किया गया है

पैरा 412

1996 (6) पूरक। एससीआर 839

संदर्भित किया गया है

पैरा 414

1994 (1) पूरक। एस. सी. आर. 239

संदर्भित किया गया है

पैरा 415

संदर्भित किया गया है

1991 (2) पूरक। एससीआर 497

पैरा 416

1996 (2) एससीआर 23

संदर्भित किया गया है

पैरा 417

[1950] 1 एससीआर 88

संदर्भित किया गया है

पैरा 421

[1967] 1 एससीआर 15

संदर्भित किया गया है

पैरा 423

संदर्भित किया गया है

2008 (1) एससीआर 986

पैरा 432

[1959] एससीआर 629

संदर्भित किया गया है

पैरा 439

[1952] एससीआर 284

संदर्भित किया गया है

पैरा 443

[1986] 2 एससीआर 56

संदर्भित किया गया है

पैरा 449

संदर्भित किया गया है

1996 (3) एससीआर 721

पैरा 453

2003 (1) एससीआर 666

संदर्भित किया गया है

पैरा 454

1962 पूरक (2) एस. सी. आर. 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 455

1992 (1) एससीआर 686

संदर्भित किया गया है

पैरा 456 सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई.

पैरा 458

986 एससीआर 479

संदर्भित किया गया है

996 (10) पूरका एस. सी. आर. 585 को संदर्भित किया गया

पैरा 459

960 (1) एससीआर 605

संदर्भित किया गया है

पैरा 461

संदर्भित किया गया है

007 (1) एससीआर 317

पैरा 462

982 (2) एससीआर 272

संदर्भित किया गया है

पैरा 497

011 (4) एससीआर 445

संदर्भित किया गया है

पैरा 500

संदर्भित किया गया है

पैरा 502

014 (4) एससीआर 77

992 (2) एससीआर 109

संदर्भित किया गया है

	पैरा 544
संदर्भित किया गया है	
014 (2) एससीआर 537	
	पैरा 551
985 (2) एससीआर 287	
संदर्भित किया गया है	
	पैरा 552
975 (3) एससीआर 333	
संदर्भित किया गया है	
	पैरा 553
212 संदर्भित किया गया है	
988 (3) पूरक। एससीआर	
	पैरा 554
002 (1) एससीआर 897	
	पैरा 558
संदर्भित किया गया है	
संदर्भित किया गया है	
965 एससीआर 421	
	पैरा 558
963 पूरक। एससीआर 435	
संदर्भित किया गया है	
	पैरा 558
985 (2) एससीआर 287	
संदर्भित किया गया है	
	पैरा 558
011 (11) एससीआर 1094	

संदर्भित किया गया है

पैरा 560

कुरियन का आदेश, जे। :

974 (1) एससीआर 697

संदर्भित किया गया है

पैरा 8

कुरियन के फैसले में, जे। :

973 (0) पूरक। एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 1

पैरा 2

संदर्भित किया गया है

975 (1) एससीआर 814

गोयल का निर्णय, जे। :

998 (2) पूरक। एस. सी. आर. 400 संदर्भित

पैरा 3.4

993 (2) पूरक। एस. सी. आर. 659 संदर्भित

पैरा 3.4

996 (2) पूरक। एससीआर 230

संदर्भित किया गया है

पैरा 10

973 (0) पूरक। एस. सी. आर. 1 संदर्भित

पैरा 15

976 एससीआर 347

संदर्भित किया गया है

पैरा 15.4

981 (1) एससीआर 206

संदर्भित किया गया है

पैरा 15.5

997 (2) एससीआर 1186

संदर्भित किया गया है

पैरा 15.6

006 (10) पूरक। एस. सी. आर. 197 संदर्भित

पैरा 15.7 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015] 13 एस. सी. एफ.

2007 (9) एससीआर 259

संदर्भित किया गया है

पैरा 15.8

1982 एससीआर 365

संदर्भित किया गया है

पैरा 16.4

1990 (2) पूरक। एस. सी. आर. 433 को संदर्भित किया गया

पैरा 16.5

1978 (1) एससीआर 423

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

1975 (1) एससीआर 814

संदर्भित किया गया है

पैरा 17.2

2012 (3) एससीआर 147

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

(2014) 2 एस. सी. सी. 532

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

1994 (2) एससीआर 644

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

2006 (1) एससीआर 562

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

1996 (10) पूरक। एस. सी. आर. 12 संदर्भित

पैरा 18

1992 (1) एससीआर 686

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

2012 (12) एससीआर 256

पैरा 18.1

संदर्भित किया गया है

1970 (2) एससीआर 666

संदर्भित किया गया है

पैरा 18.5

1970 (1) एससीआर 388

संदर्भित किया गया है

पैरा 18.9

2014 (9) एससीआर 965

संदर्भित किया गया है

पैरा 18.1

(1981) 1 एससीसी 166

पैरा 19.1

संदर्भित किया गया है

2008 (4) एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 19.1

1996 (10) पूरक। एससीआर 585

संदर्भित किया गया है

पैरा 19.3

2006 (1) पूरक। एससीआर 772

संदर्भित किया गया है

पैरा 19.3

1978 (2) एससीआर 621

संदर्भित किया गया है

पैरा 19.7

(1952) एससीआर 597

संदर्भित किया गया है

पैरा 19.7

1971 (3) एस. सी. आर 9

संदर्भित किया गया है

पैरा 19.7

(1970) 1 एस. सी. सी. 248

संदर्भित किया गया है

· पैरा 19.7

1973 (2) एससीआर 757

संदर्भित किया गया है

पैरा 19.7

1994 (2) एससीआर 644

संदर्भित किया गया है

पैरा 19.1

2011 (5) एससीआर 560

संदर्भित किया गया है

पैरा 19.1

2010 (6) एससीआर 857

संदर्भित किया गया है

पैरा 19.1

(2014) 10 एससीसी 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 19.1

(1965) 1 एस. सी. सी. 413

संदर्भित किया गया है

पैरा 19.1

2013 (10) एससीआर 1130

संदर्भित किया गया है

पैरा 20.4

2013 (7) एस. सी. सी. 507

संदर्भित किया गया है

पैरा 20.4 सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं के विज्ञापन-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई.

नागरिक मूल न्यायनिर्णय: लेखन याचिका (सिविल)

2015 का सं. 13।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

के साथ

डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या। 23, 70, 83, 108, 124, 14, 18, 24, 209,

309, 310, 323 और 2015 का 341 और टी. पी. (सी) संख्या। 391 और

971 2015 से।

रंजीत कुमार, एस. जी., ए. जी., पी. एस. नरसिम्हा,

ए. एस. जी., फली एस. नरीमन, प्रो. भीम सिंह, अनिल बी. दीवान, आर. के.

पी. शंकर दास, के. एन. भट, वी. मोहना, राम जेठमलानी, के.

के. वेणुगोपाल, टी. आर. अंधारुजिना, अजीत सिन्हा, रवींद्र

इरशाद अहमद, गौरव भाटिया, सी. डी. सिंह, सौरभ अजय
सुभाष सी. कश्यप,

गुप्ता, सूर्यनारायण सिंह, एएजीएस,

प्रणव व्यास (सूर्यकांत के लिए), संतोष पॉल, जोसेफ अरस्तू

एस., अरविंद गुप्ता, एम. बी. इलाक्कुमानन, मलय स्वप्निल, प्रिया
प्रशांत कुमार, सैयद रेहान, रणवीर सिंह, अनिदिता पुजारी, जितेंद्र

अरस्तू, सविता सिंह, प्रशांत भूषण,

महापात्रा, ए. सी. फिलिप, राबिन मजूमदार, सुमन, वी. एन.

सुब्रमण्यम, सुभाशीष भौमिक, एस. के. सिन्हा, जॉयदीप

मुखर्जी (रवीन मजूमदार के लिए), श्रीराम परक्कट, विष्णु

शंकर जैन (अंकुर एस. कुलकर्णी), प्राची बाजपेयी, डी. एल.

चिदानंद, माधवी दीवान, अभिनव मुखर्जी, बीनू टम्टा, डॉ. अर्घ्य सेनगुप्ता, रंजीता रोहतगी, देवांशी सिंह, दीक्षा

गौतम नारायण, देवाशीष भारुका, संदीप सिंह, अमित
के नाइक (गौतम के लिए)

शर्मा (सुश्री रुचि कोहली के लिए), एच

तकुलदार), अंकुर तलवार, रोहित भट, प्रेरणा प्रियदर्शिनी,

सुहासिनी सेन, अंकित के. (मिश्रा सौरभ के लिए), निशांत
सचथे, साकार सरदाना,

कांतेश्वरकर, अर्पित राय, अनीप

के. एनाटोली सेमा, एडवर्ड बेल्हो, अमित कुमार सिंह, अभिषेक

कुमार, अभिषेक कुमार सिंह, विजय प्रताप यादव, सोम राज सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट "।

[2015] 13 एस सी आर।

सिंह, मो. वकास, अनुराग सिंह, ऐश्वर्या के. सिन्हा,

रचना श्रीवास्तव, शशि जुनेजा, ए. पी. मयी, रमेश

बाबू एम. आर., स्वाति सेतिया, सपम विश्वजीत मेइतेई, जेड. एच. इसाक
सिंह, हेमंतिका वाही, विनक्षी

हैडिंग, अशोक कुमार

कादन, जगजीत सिंह छावड़ा (कुलदिप सिंह के लिए), सिबो शंकर

मिश्रा, प्रगति नीखरा, इंद्र प्रताप सिंह, प्रकाश कुमार

सिंह, अरुण मोंगा, कुदरत संधो (तुषार बख्शी के लिए), एम।

योगीश कन्ना, जयंत पटेल, कृष्ण सरमा, अविजीत राँय, नवनीत

कुमार, बरनाली दास, दीपिका (मेसर्स के लिए। निगमित कानून

समूह), गुंटूर प्रभाकर, प्रेरणा सिंह, नूपुर सिंघल,

संजय विसेन, अनिल कुमार चोपड़ा, अशोक कुमार ठाकुर, इमरान

खान बर्नी, अधिवक्ता। , उपस्थित दलों के लिए।

मैथ्यूज जे. नेदुमपारा, मनोहर लाल शर्मा, आर. के.

कपूर, विश्वजीत भट्टाचार्य, राजीव दैया, पी. एम.

दुरईस्वामी (याचिकाकर्ता-व्यक्तिगत)।

आशीष दीक्षित (प्रतिवादी-व्यक्तिगत रूप से)

न्यायालय के निम्नलिखित निर्णय और आदेश दिए गए:

न्याय

जगदीश सिंह खेहर, जे।

सूचकांक *

सामग्री

	पृष्ठ
पैराग्राफ	
<i>St.No</i>	
रद्द करने का आदेश	
	1 - 18
1	
संदर्भ आदेश	
	16 169
2.	
	1-101
चुनौती	
	16 - 19
ना.	
	10 - 19
इसकी पृष्ठभूमि	
II.	
	19 - 61
चुनौती	
गति	
III.	
	20-53
	61 - 115
द्वारा	
उत्तरदाताओं के लिए	
द्वितीय की समीक्षा	
और तीसरे न्यायाधीश	
मामले।	

एड। ध्यान दें: उपरोक्त सूचकांक में उल्लिखित पृष्ठों की योजना देते हुए
निर्णय मूल निर्णय के पृष्ठ संख्या को दर्शाता है।

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड
एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

IV. / 54-59 द्वारा आपत्ति

115-124

याचिकाकर्ताओं,

द.

को

समीक्षा के लिए प्रस्ताव

60-100

विचारणीय

124 - 168

VI. / निष्कर्ष

168 - 169

101

द ऑर्डर ऑन मेरिट

1-258

3.

170-439

आई.

प्रस्तावना

1 - 4

170-171

VII. / स्वीकारोक्ति

438 439

राजस्व आदेश

1. इस न्यायालय में किसी को सामान्य आदेश लिखने की आदत हो जाती है,

क्योंकि आदेश या तो पीठ की ओर से या न्यायालय की ओर से लिखे जाते हैं। ज्यादातर, असहमति पहले व्यक्ति में लिखी जाती है।

हालाँकि, यह असहमति की प्रकृति का आदेश नहीं है, फिर भी

इसे पहले व्यक्ति में लिखा जाना चाहिए। इसका समर्थन करते हुए

जे. चेलमेश्वर, जे., द्वारा व्यक्त राय

हाथ में मामलों को सुनने से मेरे अलग होने की प्रार्थना,

पीठ पर मेरे बने रहने के कारण भी होने चाहिए मुझे व्यक्त किया। कानून के किसी भी सिद्धांत की वकालत करने के लिए नहीं, लेकिन

आचरण के कुछ सिद्धांतों को निर्धारित करने के लिए।

2. यह क्रम एक प्रस्तावना की प्रकृति में है-एक अग्रदूत,

मुख्य विवाद के निर्धारण के लिए। यह हो चुका है

एक आपत्ति तय करने के लिए, वर्तमान के बारे में आवश्यक

बेंच की संरचना। जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, जे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

चेलमेश्वर, जे. ने आपत्ति पर निर्णय दिया है। घटनाएँ

जे. चेलमेश्वर, जे. के आदेश का पालन करने वाली

इनका भी कुछ महत्व है। मेरे विचार में, वे भी

वर्णन करने की आवश्यकता है, केवल तभी, पूरा मामला हो सकता है

माना जाता है कि पूरी तरह से व्यक्त किया गया है, जैसा कि होना चाहिए। आई.

कारणों को भी दर्ज करने की आवश्यकता है, क्यों मेरी निरंतरता

पुनर्गठित बेंच, मेरे लिए खुला एकमात्र कोर्स था। और

इसलिए, इसकी समझ का मेरा पक्ष,

बेंच के दूसरी तरफ की धारणा।

3 (i) मूल रूप से तीन न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया गया था -

इन मामलों को सुनें। पीठ में शामिल थे -

अनिल आर. दवे, जे. चेलमेश्वर और मदन बी. लोकुर, जे.

उस समय, अनिल आर. डेव, जे. 1 + 2 कॉलेजियम का हिस्सा थे।

साथ ही, 1 + 4 कॉलेजियम। उपरोक्त संयोजन ने सुना

मामला, 11.3.2015 पर अपनी पहली सूची में। के लिए वापसी योग्य सूचना

17.3.2015 सुनवाई की पहली तारीख को जारी किया गया था।

साथ ही, वाई. कृष्णन बनाम में सुनवाई। भारत संघ और अन्य, 2015 की रिट याचिका (एम. डी.) No.69, के समक्ष लंबित

मद्रास उच्च न्यायालय (अपनी मदुरै पीठ में), जिसमें

मुद्दों को समूह में उठाए गए मुद्दों के रूप में माना जा रहा था हाथ में मामलों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई थी।

(ii) अगली तारीख को, अर्थात् 17.3.2015 श्री फली एस.

नरीमन, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम। भारत संघ (रिट याचिका (सी) No.13 2015), श्री अनिल बी. दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता, बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम। भारत संघ (रिट याचिका (सी) सं: 108 2015),

श्री प्रशांत भूषण, अधिवक्ता, सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट में

मुकदमेबाजी v. भारत संघ (2015 की रिट याचिका (सी) No.83)

और श्री संतोष पॉल, अधिवक्ता, चेंज इंडिया बनाम में। भारत संघ (2015 की रिट याचिका (सी) No.70),

याचिकाकर्ताओं को सुना गया। भारत के अटॉर्नी जनरल श्री मुकुल रोहतगी ने जवाब में अग्रिम दलीलें दीं। बात यह थी कि

आंशिक रूप से दिखाया गया-सुना गया, और आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया

18.3.2015.

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

(iii) इस न्यायालय द्वारा 18.3.2015 पर दर्ज की गई कार्यवाही।

पता चलता है कि श्री संतोष पॉल, (लिखित याचिका (सी) No.70 में

2015) 18.3.2015 पर फिर से सुना गया, जिसके बाद, श्री मुकुल

रोहतगी और भारत के सॉलिसिटर जनरल श्री रंजीत कुमार ने भी

अपनी दलीलें दीं। इसके बाद, श्री दुष्यंत ए. दवे,

वरिष्ठ अधिवक्ता-और सुप्रीम कोर्ट बार के अध्यक्ष

एसोसिएशन ने बेंच को एक मध्यस्थ के रूप में संबोधित किया।
लिए उठी। 18.3.2015 पर, मामला

इसके बाद, अदालत दिन भर के

सुनवाई के लिए अगले दिन, यानी, के लिए स्थगित कर दिया गया था

19.3.2015.

(iv) 19.3.2015 पर पारित आदेश से पता चलता है कि

श्री दुष्यंत ए द्वारा उस तारीख को प्रस्तुतियाँ आगे बढ़ा दी गई थीं।

श्री डेव, श्री मुकुल रोहतगी, श्री टी. आर. अंधारुजिना, वरिष्ठ

अधिवक्ता, और श्री मैथ्यूज जे. नेदुमपारा। जब श्री फली एस.

नरीमन तब भी पीठ को संबोधित कर रहे थे, अदालत दिन भर के लिए उठी, अन्य बातों के साथ रिकॉर्ड करते हुए, "मामले भाग बने रहे।

सुना है। "मामलों में आगे की सुनवाई को स्थगित कर दिया गया था

24.3.2015.

(v) 24.3.2015 पर, श्री फली एस. नरीमन और श्री अनिल बी.

दीवान, फिर से सुना गया। इसके अतिरिक्त, श्री मुकुल रोहतगी

अपनी दलीलें पूरी कीं। सुनवाई के समापन पर,

फैसला सुरक्षित रखा गया था। 24.3.2015 पर, एक अलग आदेश था

2015 की रिट याचिका (सी) संख्या 124 में भी पारित किया गया (जे. मैथ्यूज।

नेदुमपारा बनाम। सचिव के माध्यम से भारत का सर्वोच्च न्यायालय

जनरल और अन्य)। यह नीचे पढ़ा गया है:

"श्री मैथ्यूज जे. नेदुमपारा द्वारा दायर आवेदन

न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से बहस करना अस्वीकार कर दिया जाता है। का नाम श्री रॉबिन मजूमदार, एओआर, जो पहले पेश हो रहे थे

उसे, कारण सूची में दिखाया जाए "।

(vi) 7.4.2015 पर, निम्नलिखित आदेश पारित किया गया

तीन न्यायाधीशों की पीठ की अध्यक्षता अनिल आर. दवे, जे. :

"1. याचिकाओं के इस समूह में, संविधान (नब्बे-नौवां संशोधन) अधिनियम, 2014 और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014 [इसके बाद [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) को चुनौती दी गई है। चुनौती इस आधार पर है कि वनाच्छादित संशोधन के आधार पर और अधिनियम का अधिनियम, संविधान की मूल संरचना

भारत को बदल दिया गया है और इसलिए, उन्हें निर्धारित किया जाना चाहिए एक तरफ।

2. हमने विद्वान वकील को उनकी ओर से पेश होते हुए सुना है पार्टियाँ और पार्टियाँ व्यक्तिगत रूप से लंबे समय तक उपस्थित होती हैं।

3. यह मुख्य रूप से याचिकाकर्ताओं के लिए प्रस्तुत किया गया है कि सभी

इन याचिकाओं को पाँच न्यायाधीशों की पीठ को भेजा जाना चाहिए।

संविधान के अनुच्छेद 145 (3) के प्रावधानों के अनुसार

भारत इस कारण से कि कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न

भारत के संविधान की व्याख्या के संबंध में हैं -

इन याचिकाओं में शामिल। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि जब तक इन सभी याचिकाओं का अंत में निपटारा नहीं किया जाता है,

एक अंतरिम राहत यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि अधिनियम को

इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए और न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में वर्तमान प्रणाली को जारी रखा जाना चाहिए। 4. वकील की प्रस्तुतियों का योग और सार

याचिका का विरोध यह है कि ये सभी याचिकाएं समय से पहले की हैं

क्योंकि यह अधिनियम आज तक लागू नहीं हुआ है

और जब तक अधिनियम लागू नहीं होता, तब तक कार्रवाई का कारण नहीं कहा जा सकता है। परिस्थितियों के अनुसार,

विद्वान वकील, याचिकाओं को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

5. विद्वान सलाहकार के साथ-साथ व्यक्तिगत रूप से पक्षकारों के पास है

अपने मामलों को साबित करने के लिए कई निर्णयों पर भरोसा किया।

6. मामले के तथ्यों को देखते हुए, हमारा विचार है कि

इन याचिकाओं में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं -

भारत के संविधान की व्याख्या और इसलिए।

हम रजिस्ट्री को इस समूह के सभी मामलों को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश देते हैं ताकि वे कर सकें

इसे विचार के लिए एक बड़ी पीठ के समक्ष रखा जाए।

7. चूंकि हम गुण-दोष के आधार पर मामलों का फैसला नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम नहीं करते हैं

द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर चर्चा करना उचित समझते हैं

विद्वान वकील और पक्षकार व्यक्तिगत रूप से।

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

8. यह याचिकाकर्ताओं के लिए प्रार्थना करने के लिए खुला होगा बड़ी पीठ के समक्ष अंतरिम राहत क्योंकि हम ऐसा नहीं सोचते हैं

इस स्तर पर कोई भी अंतरिम राहत देने के लिए उपयुक्त है।

4. मुकदमों की सुनवाई के दौरान, अनिल आर. दवे, जे.

कॉलेजियम की किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं लेना।

5. तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पारित आदेश के आधार पर

7.4.2015 पर, भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने एक

पांच-न्यायाधीश पीठ, जिसमें अनिल आर. दवे, चेलमेश्वर,

मदन बी. लोकर, कुरियन जोसेफ और आदर्श कुमार गोयल, जेजे।

6. 13.4.2015 संविधान पर (नब्बे-नौवें)

संशोधन) अधिनियम, 2014 और राष्ट्रीय न्यायिक
किया गया था

नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014 को अधिसूचित

भारत का राजपत्र (असाधारण)। उपरोक्त दोनों अधिनियम,

इसे 13.4.2015 से लागू किया गया था। तदनुसार,

13.4.2015 पर अनिल आर. डेव, जे. पदेन सदस्य बने

मुख्य न्यायाधीश के बाद दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होने का
(1) (बी) के अधिदेश के तहत।

भारत सरकार, अनुच्छेद 124 ए

7. जब मामला पहली बार सुनवाई के लिए आया,

आई. डी. 1 पर पाँच न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष उसने निम्नलिखित आदेश पारित किया:

"हममें से एक पीठ (अनिल) के समक्ष मामलों को सूचीबद्ध करें।

आर. डेव, जे.) सदस्य नहीं हैं।

इसलिए, भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश,

पीठ का पुनर्गठन खुद, जे. चेलमेश्वर, मदन के साथ किया।
कुमार गोयल, जेजे।, सुनने के लिए

बी. लोकुर, कुरियन जोसेफ और आदर्श

मामलों का यह समूह।

8. जब पुनर्गठित पीठ ने 21.4.2015 पर सुनवाई शुरू की, तो श्री फली एस. नरीमन ने मेरे लिए प्रार्थना की।

पीठ से अलग होना, जिसका श्री मैथ्यूज ने समर्थन किया था
याचिकाकर्ता-व्यक्तिगत रूप से) No.124

जे. नेदुमपारा (रिट याचिका में

2015 का), बाद के उन्नत प्रस्तुतियाँ, भले ही वह सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

पहले के एक आदेश द्वारा ऐसा करने से रोक दिया गया था

24.3.2015 (ऊपर निकाला गया)। मेरे लिए, अध्यक्षता करने के लिए

अनिल आर. डेव, जे. के संदर्भ में बनाया गया था।
उन्होंने व्यायाम किया था

बाहर, कि उपरोक्त प्रार्थना के परिणामस्वरूप

अलग करने का विकल्प (-15.4.2015 पर)। कुछ लोगों ने सीखा

वकील ने इस बात पर जोर दिया कि अनिल आर. देवे, जे. का अलग होना न केवल अनुचित था, बल्कि प्रेरित
भी था। यह था। यह भी सुझाव दिया कि पीठ का पुनर्गठन किया जाना चाहिए,

न्यायाधीश अनिल आर. देवे से पीठ की अध्यक्षता करने का अनुरोध किया। तथ्यों के उपरोक्त अनुक्रम से पता चलता है कि अनिल आर.

डेव, जे. अपने आप में नहीं थे, लेकिन एक समान प्रार्थना के सम्मान में थे।

उसे बनाया। तार्किक रूप से, अगर उन्होंने इन मामलों को सुना होता जब उन्होंने

तीन न्यायाधीशों की पीठ के पीठासीन न्यायाधीश थे, वे

यह सुना है, जब बेंच की ताकत बढ़ाई गई थी, जिसमें, वह अभी भी पीठासीन न्यायाधीश थे।

9 (i) श्री फली एस. नरीमन ने इस धारणा का दृढ़ता से खंडन किया बनाने की कोशिश की, कि उन्हें कभी भी अनिल आर. डेव की आवश्यकता थी, जे. से। त्याग करें। अपने दावे का समर्थन करने के लिए, उन्होंने बताया, कि उन्होंने 15.4.2015 पर लिखित रूप में निम्नलिखित अनुरोध किया था:

"संविधान के प्रावधान (नब्बे-नौवें)

संशोधन) अधिनियम, 2014 और राष्ट्रीय न्यायिक

नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014 को 13 अप्रैल, 2015 से लागू किया गया है। इसके परिणामस्वरूप,

इस पीठ के पीठासीन न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति महोदय

अनिल आर. डेव, अब बन गए हैं (पसंद से बाहर नहीं बल्कि द्वारा)

कानून का बल) राष्ट्रीय परिषद का पदेन सदस्य

न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसका संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है।

यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि यह उचित होगा।

यदि यह शुरुआत में घोषित किया जाता है-इस माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश द्वारा

अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

राष्ट्रीय कार्यवाहियों में कोई भाग नहीं
न्यायिक नियुक्ति आयोग "।

ज्ञात वरिष्ठ वकील ने बताया कि उन्होंने केवल

तत्कालीन पीठासीन न्यायाधीश (अनिल आर. डेव, जे.) से अनुरोध किया कि राष्ट्रीय न्यायिक कार्यवाहियों में कोई भी भाग लेना नियुक्ति आयोग, इनकी सुनवाई के दौरान विषय हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्होंने कभी अनिल आर. दवे से नहीं पूछा था, जे. पीठ के समक्ष लंबित मामलों की सुनवाई नहीं करना।

((ii) श्री मैथ्यूज जे. द्वारा लिखित रूप में प्रस्तुत किया गया।

अनिल आर. डेव, जे. से अलग होने के लिए नेदुमपारा

निम्नलिखित शब्द:

..... VI. यद्यपि माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल आर. दवे, तत्काल मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ का नेतृत्व करता है कानूनी विरादरी द्वारा सम्मानित और सम्मानित न्यायाधीश और बड़े पैमाने पर जनता, उच्चतम सत्यनिष्ठा, क्षमता का न्यायाधीश और निष्पक्षता, अभी भी सुआ कौसा में निमो जुडेक्स का सिद्धांत या प्रोप्रिया कौसा में निमो डेबेट एसे जूडेक्स-कोई भी नहीं कर सकता है अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश होना-उनके प्रभुता की आवश्यकता होगी न्यायालय स्वयं की शक्ति से जुड़े मामले का निर्णय करता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति स्पष्ट नहीं होगी सार्वजनिक विश्वसनीयता। फिर सवाल यह उठता है कि कौन यह तय कर सकते हैं। आवश्यकता का सिद्धांत कोई दूसरा नहीं छोड़ता है विकल्प तब सर्वोच्च न्यायालय स्वयं प्रश्न का निर्णय करता है। लेकिन उस मामले में, यह उन न्यायाधीशों द्वारा हो सकता है जो इसका हिस्सा नहीं हैं आज तक कॉलेजियम या यदि एन. जे. ए. सी. का गठन किया जाना है आज, इसका सदस्य हो सकता है। अत्यंत सम्मान के साथ, माननीय श्री न्यायमूर्ति दवे कॉलेजियम के सदस्य हैं; [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उनका लॉर्डशिप एन. जे. ए. सी. का सदस्य होगा यदि

आज गठित किया गया। इसलिए, एक स्पष्ट संघर्ष है

रुचि का।

VII. जनमत संग्रह। ऑस्ट्रेलिया में, एक संवैधानिक संशोधन

न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु को 70 तक सीमित करते हुए लाया गया था वर्षों से।
न्यायाधीशों की शुद्धता तय करने के बजाय

उक्त निर्णय, संशोधन की वैधता को छोड़ दिया गया था

संशोधन का समर्थन किया। इसलिए, एकमात्र निकाय जो यह तय कर सकता है कि क्या परिकल्पना के
अनुसार एन. जे. ए. सी. स्वीकार्य है। या नहीं इस देश के लोग जनमत संग्रह पर हैं।

VIII. न्यायाधीश-2 में निर्णय, जिसने पुनर्लेखन किया

बड़े पैमाने पर सार्वजनिक को सूचना दिए बिना निर्णय लिया। केवल दृश्य सरकार और अभिलेख
पर अधिवक्ताओं और कुछ

दूसरों को सुना गया। तत्काल मामले में, बड़े पैमाने पर जनता सुनवाई का अवसर दिया जाना
चाहिए; कम से कम

प्रमुख राजनीतिक दलों, और मामले को भेजा जाना चाहिए

संवैधानिक पीठ के लिए। अधिनियमों की संवैधानिकता

निर्णय लिया जाना चाहिए, कमजोर को दरकिनार करते हुए, नहीं,

विद्वान महान्यायवादी की क्षमा याचना कि

अधिनियम लागू किए गए हैं और उनकी वैधता नहीं हो सकती है।

चुनौती दी जाए, और आगे आने और बताने में विफल रहे स्पष्ट शब्द कि अधिनियम लोगों की
इच्छा हैं, बोली जाती हैं

अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से और वह भी बिना

कोई भी विभाजन, सर्वसम्मति। अधिवक्ताओं की याचिका रिकॉर्ड एसोसिएशन कि अधिसूचना
लागू हो रही है

उक्त अधिनियमों को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाए; इसलिए भी

मांग करें कि कॉलेजियम प्रणाली, जो बंद हो गई है

अस्तित्व में रहें, जारी रखने की अनुमति दी जाए और

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के प्रतिष्ठित कार्यालय में नियुक्तियाँ और उच्चतम न्यायालय अपनी
सिफारिश पर, ऐसा करने के लिए

इसका मतलब यह होगा कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश जो हैं

वर्तमान में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी क्योंकि दूसरों की तुलना में कम उम्र को सर्वोच्च अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया जाएगा-ऑन-रिकॉर्ड

समाज v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और यदि इसकी अनुमति है
ऐसा होता है, इससे ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जहाँ सर्वोच्च न्यायालय
कल सचमुच बेटों और बेटों से भरा होगा -

पूर्व न्यायाधीशों का कानून। कम से कम तीन प्रमुख हैं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश जो पूर्व
न्यायाधीशों के पुत्र हैं

सर्वोच्च न्यायालय। याचिकाकर्ता को किसी की भी जानकारी नहीं है।

गोपनीय जानकारी, गपशप भी नहीं। फिर भी वह मानता है

कि अगर एन. जे. ए. सी. के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी जाती है, तो तीन बेटे

उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है उच्चतम न्यायालय के
न्यायाधीशों के रूप में। याचिकाकर्ता ने

उन न्यायाधीशों में से किसी के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं;

यह मुद्दा किसी भी व्यक्ति के बारे में नहीं है। याचिकाकर्ता

आसानी से स्वीकार करता है, और ऐसा करने में खुशी होती है, कि कुछ

वे अत्यधिक सक्षम और समृद्ध रूप से योग्य हैं

IX. कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण
न्यायाधीश का कार्यालय

सार्वजनिक रोजगार का मामला।

उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, हालांकि उच्च न्यायालय

संवैधानिक पद, अभी भी जनता के दायरे में है

रोजगार, जिसके लिए प्रत्येक पात्र व्यक्ति को होना चाहिए

कब्जा करने का अवसर दिया गया, वह एक पर चुना जा रहा है

पारदर्शी, न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और गैर-मनमाना प्रणाली। द.

याचिकाकर्ता दोहराता है कि वह कम से कम योग्य हो सकता है

नियुक्त किया जाता है जब अन्य लोगों के साथ विचार किया जाता है उससे भी योग्य, लेकिन
तथ्य यह है कि चूंकि वह सभी को संतुष्ट करता है

अनुच्छेद 124 ए के तहत निर्धारित बुनियादी पात्रता मानदंड,
संशोधित रूप में, और 217, वह एक घोषणा की मांग करने का हकदार है
रिक्तियों या ऐसे अन्य के विज्ञापन द्वारा किया जाए उपयुक्त तंत्र।

X. न्यायिक समीक्षा बनाम लोकतंत्र। न्यायिक समीक्षा है
केवल अन्यायपूर्ण कानूनों को लागू करने और उनके अधिकारों को रोकने के लिए
अल्पसंख्यक, चाहे वे किसी भी रंग के हों
धर्म, नस्ल, उनके विचार, एक कानून द्वारा जो प्राप्त करता है क्रूर बहुमत और एक कार्यपालिका
जो अत्याचारी है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

इसका उद्देश्य लोगों की आवाज को प्रतिस्थापित करना नहीं है
उच्च न्यायपालिका की आवाज़ से।

XI. अनुच्छेद 124 ए, जैसा कि संशोधित किया गया है, केवल एक मामले में कम है। इसके तहत
विचार किया गया कॉलेजियम अभी भी है

उच्च न्यायपालिका के पक्ष में पूरी तरह से भरा हुआ। तीन बाहर

छह सदस्य न्यायाधीश होते हैं। इस मायने में यह मिलने में विफल हो रहा है।

न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक होना। लेकिन संसद ने अपने
विवेक ने ऐसा अधिनियमित किया और यदि कोई शिकायत है, तो मंच

जनमत उत्पन्न करना और अधिक से अधिक लोकतंत्र की तलाश करना है।
याचिकाकर्ता को वर्तमान में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है; वह खुश है।

अधिनियमित अधिनियमों और प्रमुख राहत के साथ जो उसने

तत्काल याचिका में मांग तत्काल आ रही है

उचित अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियमों का बल और

इस माननीय न्यायालय के हाथों इस आशय का आदेश।

10. जब मैं पुनर्गठित पीठ से अलग हुआ था

21.4.2015 पर माँगा गया, मैंने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया था, कि मेरे पास था

मामलों को सुनने की कोई इच्छा नहीं। फिर भी, श्री फली एस. नरीमन द्वारा लिखित रूप में व्यक्त किए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए,

अनिल आर. डेव, जे. आई. ने खुली अदालत में खुलासा किया था कि मैं पहले ही भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक संदेश भेजा,

कि मैं 1 + 4 की कार्यवाही में भाग नहीं लूंगा

कॉलेजियम (जिसका मैं सदस्य था), जब तक कि इनका निपटारा नहीं हो जाता। विषय हैं। फिर भी, आपत्ति को दबाया गया। इसे दर्ज करने की आवश्यकता है।

कि अनिल आर. डेव, जे. 1 + 2 कॉलेजियम के सदस्य थे,

साथ ही, इन मामलों में सुनवाई के दिन से 1 + 4 कॉलेजियम

मामले शुरू हुए। आश्चर्य की बात यह है कि इस वजह से उनका अलग होना कभी नहीं माँगा गया था, और उन्होंने मामलों को सुनना जारी रखा था,

जब उन्हें इस तरह रखा गया था (11.3.2015 से 7.4.2015 तक)। लेकिन इसके लिए

1 + 4 कॉलेजियम का सदस्य होने के नाते, एक प्रार्थना की गई थी

मेरे त्याग के लिए बनाया गया।

11. यह मेरा व्यक्तिगत विचार था और अभी भी है, जो मैं नहीं मानता।

श्री फली एस. नरीमन या श्री मैथ्यूज पर दबाव डालना चाहते हैं।

जे. नेदुमपारा, कि अनिल आर. डेव, जे. सबसे अधिक थे।

उपयुक्त, पुनर्गठित पीठ की अध्यक्षता करने के लिए।

जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने देखा है

अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. 1. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

i

ऊपर, वह 1 + 2 कॉलेजियम का हिस्सा थे, साथ ही, 1 + 4

कॉलेजियम, 'कॉलेजियम प्रणाली' के तहत; वह जारी रखेंगे

एक पदेन सदस्य के रूप में समान जिम्मेदारियों का निर्वहन करना
में

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग,

* संवैधानिक संशोधन के तहत 'आयोग प्रणाली'

13.4.2015 से लागू किया गया। इसलिए, चाहे जो भी हो

ऐसी प्रणाली जो न्यायनिर्णायक प्रक्रिया से बच जाएगी,

अनिल आर. डेव, जे. चयन, नियुक्ति में भाग लेंगे।

और उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों का स्थानांतरण। वह करेगा,

इसलिए, वर्तमान के निर्धारण से प्रभावित न हों

विवाद, एक या दूसरे तरीके से।

12. पीठ से मेरे अलग होने की प्रार्थना को दबाया गया था

श्री फली एस. नरीमन, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा लिखित रूप में, निम्नानुसार:

" 8. वर्तमान मामले में पीठासीन न्यायाधीश, (माननीय

श्री न्यायमूर्ति जे. एस. खेहर) निर्णयों के कारण
उच्चतम न्यायालय के दूसरे न्यायाधीशों के मामले में रिपोर्ट किया गया

अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन। वी. भारत संघ, (1993) 4

एस. सी. सी. 441, (9 सदस्यीय पीठ द्वारा सर्वसम्मति से पुष्टि की गई)
तीसरे न्यायाधीशों के मामले में न्यायाधीश विशेष संदर्भ

1998 का सं. 1, री. (1998 7 एससीसी 739), वर्तमान में एक है

पाँच माननीय न्यायाधीशों के कॉलेजियम के सदस्य जो

उच्च अधिकारियों को न्यायिक नियुक्तियों की सिफारिश करता है

न्यायपालिका, जो अब के दायरे में आएगी
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन

संशोधन) अधिनियम, 2014 को राष्ट्रीय न्यायिक के साथ पढ़ा जाता है।
2014 का नियुक्ति आयोग अधिनियम No.40-यदि वैध है;

लेकिन इन अधिनियमों की संवैधानिक वैधता है

इन कार्यवाहियों में सीधे चुनौती दी गई थी।

इस पीठ पर पीठासीन न्यायाधीश का पद

संवैधानिक चुनौती के इन मामलों की सुनवाई नहीं है

उसके साथ सुसंगत (और स्पष्ट रूप से संघर्ष)

'कॉलेजियम' के सदस्य के रूप में पद; और [2015] 13 एस. सी. आर. होने की संभावना है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस तरह से देखा जाए; हमेशा ध्यान रखें कि यदि

संविधान संशोधन और संबंधित कानून

उन्हें संवैधानिक रूप से वैध माना जाता है और बरकरार रखा जाता है, वर्तमान पीठासीन न्यायाधीश अब इसका हिस्सा नहीं होगा

कॉलेजियम-कॉलेजियम जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए

महत्वपूर्ण संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करता है।

9. दूसरे शब्दों में यह अनुचित होगा

पीठ में बैठना जारी रखेंगे माननीय पीठासीन न्यायाधीश

जो यह निर्णय करता है कि क्या कॉलेजियम प्रणाली, (जैसा कि यह है)

पिछले दो दशकों से और कहा जाता है (में रिट याचिकाएँ) की मूल संरचना का एक हिस्सा होना

लोगों के मन में यह धारणा होगी कि अनुचित नहीं तो अनुचित अगर एक का एक बैठे सदस्य

कॉलेजियम एक योजना पर निर्णय में बैठता है जो चाहता है

इसे बदल दें। यह एक विचार के अलावा है कि

निर्णय अंततः है या नहीं (या नहीं)

अमान्य या शून्य घोषित किया गया: पहली बार में या याचिका में "।

समीक्षा द्वारा या एक उपचारात्मक

मेरे अलग होने के लिए उपरोक्त प्रार्थना का श्री ने समर्थन किया।

ई. डब्ल्यू. एस. जे. नेदुमपारा, याचिकाकर्ता-व्यक्तिगत रूप से, लिखित रूप में:

"..... पीठासीन न्यायाधीश, माननीय श्री न्यायमूर्ति जे. एस. खेहर, उच्च सम्मान देता है और

एक न्यायाधीश जिसे याचिकाकर्ता

सम्मान, एक न्यायाधीश जो अपनी ईमानदारी, निष्पक्षता के लिए जाना जाता है याचिकाकर्ता यह कहने से डरता है, नहीं करना चाहिए

और विद्वता,

निर्णय लेने वाली संविधान पीठ की अध्यक्षता करें

संविधान की संवैधानिक वैधता या अन्यथा (99 वां संशोधन) अधिनियम, 2014 और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014 (उक्त) अधिनियम ", संक्षेप में)। उनका प्रभुत्व एक सदस्य होगा

कॉलेजियम यदि यह माननीय न्यायालय यह अभिनिर्धारित करता है कि उक्त अधिनियम असंवैधानिक हैं या इसके संचालन को रोकने के लिए हैं

अधिनियमों ने कहा, क्योंकि, यदि अधिनियमों के संचालन पर रोक लगा दी जाती है, तो यह सर्वोच्च न्यायालय-चालू-रिकॉर्ड है

समाज v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

यह माना जा सकता है कि कॉलेजियम प्रणाली जारी है

इस तरह के स्थगन आदेश के आधार पर लागू होना। यद्यपि माननीय श्री न्यायमूर्ति जे. एस. खेहर राष्ट्रीय आयोग के सदस्य नहीं हैं।

न्यायिक नियुक्ति आयोग, यदि एन. जे. ए. सी.

आज इसका गठन किया जाएगा, जिसमें माननीय भारत के मुख्य न्यायाधीश और इसके दो वरिष्ठतम न्यायाधीश माननीय न्यायालय। माननीय श्री एच. एल.

दत्त, भारत के मुख्य न्यायाधीश, महामहिम श्री

कॉलेजियम। इसलिए, एक आम आदमी, नहीं, एक जानकार दर्शक, एक अभिव्यक्ति के हाथों में स्वीकृति मिली

यह माननीय न्यायालय न्यायिक पृथक्करण के प्रश्न पर,

इस बात पर विचार करें कि न्याय नहीं होता अगर एक पीठ होती

इस माननीय न्यायालय की अध्यक्षता माननीय श्री न्यायमूर्ति जे. एस. खेहर को उपरोक्त मामले की सुनवाई करनी थी। इतनी जानकारी नहीं रखने वाले के लिए

दर्शक, आम आदमी, आम आदमी, यह माननीय न्यायालय उपरोक्त अधिनियमों को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं की सुनवाई

हंस के मुकदमे में जूरी में एक लोमड़ी के अलावा और कुछ नहीं। द.

याचिकाकर्ता का मानना है कि उनके प्रभुओं का महान हृदय

न्यायमूर्ति खेहर अनजाने में इससे प्रभावित हो सकते हैं

अचेतन, अवचेतन, अचेतन पूर्वाग्रह, उसका लॉर्डशिप्स को खुद को एक स्थिति में रखा गया है
हितों का टकराव।

3. यह माननीय न्यायालय स्वयं इस मामले की सुनवाई कर रहा है जिसमें कॉलेजियम के बीच
न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति

और सरकार, नहीं, कार्यपालिका, स्पष्ट नहीं करेगी

नामित वरिष्ठ को छोड़कर कोई भी सार्वजनिक विश्वास

वकील जो कॉलेजियम प्रणाली का समर्थन करते प्रतीत होते हैं। कॉलेजियम प्रणाली में कोई
विश्वास नहीं है

सामान्य वकील जिनके साथ अक्सर अनुचित व्यवहार किया जाता है और न ही

साधारण वादियों, दरीद्र नारायणों, एक उधार लेने के लिए

माना जाता है कि उच्च न्यायपालिका, और सर्वोच्च न्यायालय विशेष रूप से, यह आम आदमी
की पहुंच से बाहर है।

एक [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

साधारण वकील को प्रवेश पाने में भी कठिनाई होती है

उच्चतम न्यायालय परिसर। यह एक कठोर वास्तविकता है, हालांकि

कई लोग इसे नोटिस नहीं करने का नाटक करना पसंद करते हैं। इसलिए,

अत्यंत सम्मान के साथ याचिकाकर्ता, शाब्दिक रूप से इस माननीय न्यायालय की महिमा की पूजा
करते हुए, इसलिए भी माननीय

क्षमा याचना, यदि याचिकाकर्ता ने यह याचिका दायर करने में गलती की है,
माननीय न्यायमूर्ति जे. एस. खेहर से अलग होने का अनुरोध

उपरोक्त मामले की सुनवाई। "

13. पुनर्गठित पीठ की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश के रूप में, I

मैंने खुद को एक अजीब स्थिति में पाया। मेरे पास कोई व्यक्तिगत नहीं था

इन मामलों की सुनवाई में भाग लेने की इच्छा। मैं एक था

पीठ का हिस्सा, इसके लिए मेरे नामांकन के कारण, माननीय द्वारा

भारत के मुख्य न्यायाधीश। पीठ से मेरा अलग होना

श्री फली एस. नरीमन, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, से पूछने पर दूसरे विचार की आवश्यकता नहीं थी।
ऐसा नहीं है कि प्रार्थना की गई है श्री मैथ्यूज जे. नेदुमपारा की रचना अप्रासंगिक थी।

14. लेकिन फिर, यह दूसरा मौका था जब

किसी मामले में कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता, बस

क्योंकि, भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश, सबसे पहले,

अनिल आर. डेव, जे. को पीठ में नामित किया था और उसके बाद,

मुझे पीठ के लिए नामित करके उनकी जगह ली थी। यह था।

इसलिए महसूस किया कि सुनवाई के बाद कारणों को दर्ज किया जाना चाहिए

भारत के न्यायाधीश, ताकि उनके स्वामी पीठ के लिए एक और नामांकन न कर सकें, जिस पर समान रूप से
आपत्ति की जा सकती है। यह, श्री मुकल द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों के साथ जोड़ा गया

रोहतगी, श्री हरीश एन. साल्वे और श्री के. के. वेणुगोपाल ने कहा कि इस मुद्दे पर मापदंड
निर्धारित किए जाने चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए

त्याग करने का।

15. द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों के आधार पर

विद्वान वकील, पीठ ने प्रार्थना की जांच की, कि क्या मुझे पुनर्गठित पीठ में रहना चाहिए, इसके बावजूद कि मैं
एक वकील हूँ।

1 + 4 कॉलेजियम के सदस्य।

बेंच, सर्वसम्मति से सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

निष्कर्ष निकाला कि हितों का कोई टकराव नहीं था, और कोई अन्य नहीं था

कानून में न्यायोचित कारण, मेरे लिए सुनवाई से अलग होना

इन बातों को। 22.4.2015 पर, पीठ ने निम्नलिखित पारित किया:

लघु क्रम, जिसका उच्चारण जे. चेलमेश्वर, जे. :

"एक प्रारंभिक आपत्ति, क्या न्यायमूर्ति जगदीश सिंह

खेहर को इस पीठ की अध्यक्षता करनी चाहिए, उनके कारण इस न्यायालय के चौथे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होने के नाते,

कॉलेजियम के सदस्य होने के नाते, द्वारा उठाया गया था

याचिकाकर्ताओं। द्वारा विस्तृत प्रस्तुतियाँ की गई

याचिकाकर्ताओं और उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील।

सभी विद्वान वकीलों को सुनने के बाद, हमारी सर्वसम्मत राय है कि हम कानून में कोई कारण नहीं देखते हैं

न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर। खुद को हटाने के लिए

मामले की सुनवाई से। कारण सामने आएंगे। "

16. आदेश घोषित होने के बाद, मैंने अपने

बेंच पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं इस विचार के साथ खेल रहा था
लिए एक प्रार्थना, में किया गया था

अस्वीकार, क्योंकि उस प्रभाव के

अदालत का चेहरा। बेंच पर मेरे सहयोगियों के पास होगा

कुछ भी नहीं। वे अपने विरोध में स्पष्ट थे।

17. ऊपर देखी गई तथ्यात्मक स्थिति के बावजूद, मैं चाहता हूँ

रिकॉर्ड करें, कि यह उनका अनुनय या उपदेश नहीं है, जिसने बनाया

पुनर्गठित पीठ का सदस्य मेरा था, और केवल मेरा था।
था, बल्कि दिल का था।

मैंने जो चुनाव किया, वह दिल का नहीं

सिर। यह चुनाव खुद से दो सवाल पूछकर किया गया था।

सबसे पहले, क्या किसी मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश को अलग होना चाहिए, यहां तक कि

यद्यपि अलग होने की प्रार्थना अनुचित पाई गई है और

अनुचित? दूसरा, क्या मैं शपथ के प्रति सच्चा रहूंगा

मेरे कार्यालय से, अगर मैं मामलों की सुनवाई से अलग हो गया?

18. कारण जो मेरे खिलाफ बताया गया था, के लिए

मुझसे अलग होने की मांग यह थी कि मैं 1 + 4 कॉलेजियम का हिस्सा था।

लेकिन यह अनिल आर. दवे, जे. के लिए अयोग्यता होनी चाहिए थी।

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

साथ ही। जब उन्होंने मामलों की सुनवाई शुरू की, और तब तक

7.4.2015, उन्हें उसी कथित अयोग्यता का सामना करना पड़ा। फिर भी,

मेरे खिलाफ जो आपत्ति उठाई गई, वह उनके खिलाफ नहीं उठाई गई।

जब श्री फली एस. नरीमन का सामना किया गया, तो उन्होंने जोरदार विरोध किया, कि उन्होंने अनिल आर. दवे, जे. से अलग होने की मांग नहीं की थी।

सबूत के साथ अपने दावे का समर्थन किया। किसी को आश्चर्य होता है कि उसने ऐसा क्यों किया?

इस तथ्य के बारे में कि मैं 1 + 4 कॉलेजियम का सदस्य रहा हूँ, और यह संभावना है कि मैं भी जल्द ही सदस्य बन जाऊंगा

एन. जे. ए. सी., यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत वर्तमान चुनौती

सफल नहीं होना था। इसलिए मैं इसका हिस्सा बना रहूंगा

चयन प्रक्रिया, चाहे जो भी प्रक्रिया प्रचलित हो।

हालाँकि हम चारों के संदर्भ में यही स्थिति है (तत्काल पाँच-न्यायाधीश पीठ पर)। मेरे अलावा, मेरे सहकर्मी

पीठ-जे. चेलमेश्वर, मदन बी. लोकुर और कुरियन

जोसेफ, जे जे। नियत समय में कॉलेजियम का हिस्सा होगा (यदि

इस न्यायालय के समक्ष रिट-याचिकाकर्ता सफल होने वाले थे), या

वैकल्पिक रूप से, एन. जे. ए. सी. का एक हिस्सा होगा (यदि रिट-याचिकाकर्ता

असफल होना था)। ऐसी स्थिति में, संघर्ष का अनुमान

ब्याज, न केवल मेरे खिलाफ उठाया जाना चाहिए था, बल्कि

मेरे तीन सहयोगियों के खिलाफ भी। लेकिन, इस मुद्दे का प्रचार करने का तरीका ऐसा नहीं था। मेरे विचार में,

मेरे अलग होने की प्रार्थना अच्छी तरह से स्थापित नहीं है। अगर मैं मान जाता हूँ मेरे अलग होने की प्रार्थना के लिए, मैं एक गलत शुरुआत कर रहा हूँ

अभ्यास करें, और एक गलत मिसाल कायम करें। एक न्यायाधीश हो सकता है

प्रमुख द्वारा उन्हें सौंपे गए मामले से खुद को अलग करें

न्याय। यह उनकी अपनी पसंद का मामला होगा। लेकिन त्यागपत्र मुकदमा लड़ने वाले पक्ष की माँग पर, जब तक कि उचित न हो, कभी भी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए न्यायाधीश का प्रभाव पड़ेगा।

मामले से डर गया था, बस के बल से

आपत्ति की। एक न्यायाधीश अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेता है

बिना किसी भय या पक्षपात के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। वह अपने पद की शपथ का उल्लंघन करेगा, अगर वह अलग होने की प्रार्थना स्वीकार करता है, जब तक कि

न्यायसंगत है। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊँ।

पूर्ण ईमानदारी और ईमानदारी। सर्वोच्च न्यायालय का पालन करना मेरा कर्तव्य है।

अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

मेरे पद की शपथ, संविधान और कानूनों को बनाए रखने की। मेरा। निर्णय, से प्रवाहित होता है

पीठ का हिस्सा बने रहने का

शपथ जो मैंने इस न्यायालय में अपनी पदोन्नति के समय ली थी।

संदर्भ आदेश

1. चुनौती:

1. जिस प्रश्न पर विचार किया जाना है,

संवैधानिक वैधता से संबंधित मामलों का वर्तमान समूह

संविधान (नब्बे-नौवां संशोधन) अधिनियम, 2014

(इसके बाद संविधान (99 वां संशोधन) के रूप में संदर्भित किया गया

अधिनियम), साथ ही राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियों का भी

आयोग अधिनियम, 2014 (इसके बाद एन. जे. ए. सी. के रूप में संदर्भित)

अधिनियम)।

2. के गुण-दोष पर सुनवाई के दौरान

चयन और नियुक्ति से संबंधित विवाद

उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों (अर्थात्, मुख्य न्यायाधीश और न्यायालय के न्यायाधीश), और

उच्च न्यायालयों और उच्चतम

एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों का स्थानांतरण।

दूसरा, यह सामने आया कि उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील,

अन्य बातों के साथ-साथ एस. पी. गुप्ता में दिए गए फैसले पर भरोसा कर रहे थे

वी. भारत संघ 1, (इसके बाद प्रथम न्यायाधीशों के रूप में संदर्भित)

मामला); जबकि, याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील थे न्यायालय के अधिवक्ताओं के फैसले पर भरोसा करना

अन्य बातों के साथ-साथ सर्वोच्च

ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम। भारत संघ 2 (इसके बाद संदर्भित)

द्वितीय न्यायाधीशों के मामले के रूप में), और पुनः निर्णय:

1998 का विशेष संदर्भ सं. 13, (इसके बाद के रूप में संदर्भित,

तीसरे न्यायाधीशों का मामला)।

3. पर्स, विद्वान सलाहकार द्वारा अपनाया गया रुख

प्रथम में निर्णय पर निर्भरता रखने में उत्तरदाता

न्यायाधीशों का मामला उनके लिए खुला नहीं था। यह, सरल कारण के लिए,

कि प्रथम न्यायाधीशों के मामले में दिया गया निर्णय था,

1 1981 (सप) एस. सी. सी. 87

2 (1993) 4 एस. सी. सी. 441

33 (1998) 7 एस. सी. सी. 739 [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

द्वितीय न्यायाधीशों के मामले में एक बड़ी पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया। और

इसके अलावा, दूसरे में घोषित कानून की व्याख्या

न्यायाधीशों के मामले की पुष्टि तीसरे न्यायाधीशों के मामले द्वारा की गई थी।

4. कल्पना करते हुए, कि द्वारा अपनाई गई स्थिति

प्रतिवादियों, कानूनी रूप से अनुमत नहीं था, अटॉर्नी जनरल,

महान्यायवादी, और प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य विद्वान वकील

उत्तरदाताओं ने, उनके लिए खुला एकमात्र मार्ग अपनाया, अर्थात्, इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर पुनर्विचार करने के लिए

द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों के मामलों में। उपरोक्त उद्देश्य के लिए यह दावा किया गया था कि मामले के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं

दूसरे न्यायाधीश के मामले में उठाया गया प्रचार किया गया था। यह था। तर्क दिया कि, विवाद दूसरे में उठाया गया था

न्यायाधीशों के मामले की जांच सही परिप्रेक्ष्य में की गई, यह न्यायालय ने व्यक्त किए गए निष्कर्षों को दर्ज नहीं किया होगा

उसमें, बहुमत से। यह प्रस्तुत किया गया था कि जब तक उत्तरदाताओं

उनके प्रस्तुतिकरणों को प्रसारित करने की अनुमति नहीं थी, के संदर्भ में

द्वितीय में दिए गए निर्णयों की अस्वीकार्यता

और तीसरे न्यायाधीशों के मामलों में, यह उपयुक्त नहीं होगा इस न्यायालय द्वारा वर्तमान विवाद का निपटारा करने के लिए,

उक्त निर्णयों पर भरोसा करके।

5. के महत्व और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए

जिस विवाद पर बहस की जा रही है, साथ ही, जिस उग्रता के साथ उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील ने दबाव डाला इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की पुनः जांच के लिए,

द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों के मामलों में, हमने उन्हें अनुमति दी, उनके दावों के आधार का विस्तार से वर्णन करें।

6. इस मुद्दे को शुरू करने से पहले, अर्थात्, क्या

इस न्यायालय द्वारा द्वितीय और तृतीय में दिए गए निर्णय

न्यायाधीशों के मामलों, जिन पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, हम सबसे पहले यह निर्धारित करने का प्रस्ताव करते हैं कि यह हमारे लिए उचित होगा या नहीं।

इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए

सर्वोच्च न्यायालय शुरू करने के लिए इस न्यायालय द्वारा निर्धारित तकनीकी मानदंड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

कार्य। यदि हम नकारात्मक निष्कर्ष निकालते हैं, और मानते हैं कि दोनों निर्णयों की समीक्षा की प्रार्थना उचित नहीं थी, यह मामले को शांत कर देगा। हालांकि, अगर संवेदनशीलता, समीक्षा के लिए प्रार्थना को अस्वीकार करना उचित नहीं हो सकता है, पर केवल तकनीकी। तब हम यह निर्धारित करने का प्रयास करेंगे, क्या प्रस्तुतियाँ के हाथों प्रचार किया गया है उत्तरदाता, स्पष्ट और सम्मोहक कारणों का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि द्वितीय और तृतीय में दर्ज निष्कर्षों की समीक्षा न्यायाधीशों के मामले। हम यह भी जांच करने का साहस करेंगे कि क्या उत्तरदाता प्रथम दृष्टया यह दिखाने में सक्षम हुए हैं कि पहले के निर्णयों को स्पष्ट रूप से गलत माना जा सकता है। के लिए इस तरह के प्रारंभिक निर्णय, हम संतुष्ट हैं, कि वर्तमान बेंच-ताकत अभिधारणा की आवश्यकता को संतुष्ट करती है, अनुच्छेद 145 (3) के तहत परंतुक में व्यक्त किया गया।

7. उपरोक्त परीक्षा के परिणामस्वरूप, यदि -

द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों के मामलों में दिए गए निर्णय, यह दिखाया गया है कि प्रथम दृष्टया फिर से देखने की आवश्यकता है, फिर हम अनुमति दिए बिना मुख्य विवाद के गुण-दोष पर विचार करेंगे। याचिकाकर्ताओं को उपरोक्त दो में से किसी एक पर निर्भरता रखने के लिए निर्णय।

8. यदि हम अग्रिम प्रस्तुतियों को स्वीकार नहीं करते हैं

गुणदोष पर याचिकाकर्ताओं के हाथों, के संदर्भ में मुख्य विवाद, वह भी एक अर्थ में समाप्त होगा मामला, जैसा कि पहले का शासन दूसरे और तीसरे द्वारा शासित था न्यायाधीशों के मामले, अतीत की एक ऐतिहासिक घटना बन जाएंगे, जैसा कि विवादित के तहत विचार की गई नई योजना एन. जे. ए. सी. अधिनियम के साथ संविधान (99 वां संशोधन) अधिनियम,

यह पहले की व्यवस्था को बदल देगा। उपरोक्त स्थिति में, द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों की पुनः परीक्षा का प्रश्न

मामले केवल अकादमिक होंगे, और इसलिए अनावश्यक होंगे।

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

9. हालांकि, अगर हम अग्रिम प्रस्तुतियों को स्वीकार करते हैं

याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील के हाथ, जिसके परिणामस्वरूप पिछली प्रक्रिया का पुनरुद्धार हुआ, और साथ ही साथ

उत्तरदाताओं के पक्ष में निष्कर्ष निकालते हुए, कि दूसरा और तीसरे न्यायाधीशों के मामलों को फिर से देखने की आवश्यकता है, हम बाध्य होंगे

इस मामले को नौ न्यायाधीशों की पीठ (या यहां तक कि, एक बड़ी पीठ) को भेजें, ताकि दूसरे में दिए गए निर्णयों की फिर से जांच की जा सके। और तीसरे न्यायाधीशों के मामले।

II. चुनौती की पृष्ठभूमि:

10. भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश

राज्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 124 और 217 के तहत की जाती है।

क्रमशः। उच्च न्यायालय के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश और कार्यवाहक न्यायाधीश न्यायालयों की नियुक्ति अनुच्छेद 224 और 224 ए के तहत की जाती है। द.

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का स्थानांतरण

अनुच्छेद 222 के तहत दूसरे को न्यायालय बनाया जाता है। विवाद के लिए

हाथ में, मूल अनुच्छेद 124 को निकालना आवश्यक है और 217, इसके नीचे:

"124. उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन।

(1) भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें

भारत के मुख्य न्यायाधीश का और, कानून द्वारा संसद तक

सात से अधिक अन्य न्यायाधीशों की एक बड़ी संख्या निर्धारित करता है।

(2) उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश होगा -

राष्ट्रपति द्वारा अपने हाथ के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया गया और ऐसे न्यायाधीशों के साथ परामर्श करने के बाद मुहर

उच्चतम न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय जो राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझें

और पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करेंगे।

वर्ष:

बशर्ते कि न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश के अलावा, भारत के मुख्य न्यायाधीश

हमेशा सलाह ली जाएगी:

बशर्ते कि सर्वोच्च अदालतें-चालू-रिकॉर्ड होंसमाज v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

(क) न्यायाधीश अपने हाथ के नीचे लिख कर संबोधित कर सकता है।

राष्ट्रपति को, अपने पद से इस्तीफा दें;

(ख) न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है।

खंड (4) में उपबंधित रीति।

(2(क) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु होगी -

ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से निर्धारित किया जाता है जो संसद विधि द्वारा प्रदान करे।

(3) एक व्यक्ति के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा

उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश जब तक कि वह एक नागरिक न हो

भारत और

(क) कम से कम पाँच वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो।

न्यायालय या उत्तराधिकार में दो या अधिक ऐसे न्यायालयों का; या

(ख) कम से कम दस वर्षों से एक अधिवक्ता रहा है

उच्च न्यायालय या एक के बाद एक दो या दो से अधिक ऐसे न्यायालय;

या

(ग) राष्ट्रपति की राय में, एक प्रतिष्ठित

न्यायविद।

स्पष्टीकरण I-इस खंड में "उच्च न्यायालय" का अर्थ है -

न्यायालय जो अभ्यास करता है, या जो किसी भी समय न्यायालय के समक्ष प्रारंभ में प्रयोग किया गया,

इस संविधान के

भारत के क्षेत्र के किसी भी भाग में अधिकारिता।

स्पष्टीकरण III - इस उद्देश्य के लिए गणना में

खंड वह अवधि जिसके दौरान कोई व्यक्ति एक

अधिवक्ता, कोई भी अवधि जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने आयोजित किया है

न्यायिक पद जिला न्यायाधीश से कम नहीं

वह अधिवक्ता बन गया है उसे शामिल किया जाएगा।

(4) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया नहीं जाएगा।
अपने कार्यालय से

राष्ट्रपति के आदेश को छोड़कर

संसद के प्रत्येक सदन द्वारा एक संबोधन के बाद पारित किया गया

उस की कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा समर्थित

सदन और सदन के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से उपस्थित और मतदान किया गया है

इसके लिए उसी सत्र में राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया गया

1 [2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

साबित दुर्व्यवहार के आधार पर निष्कासन या असमर्थता।

(5) संसद विधि द्वारा प्रक्रिया को विनियमित कर सकती है -

पता प्रस्तुत करना और जाँच के लिए

और न्यायाधीश के दुर्व्यवहार या अक्षमता का प्रमाण

खंड (4) के अधीन।

(6) न्यायाधीश के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति

उच्चतम न्यायालय, अपने पद पर आने से पहले,

राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस संबंध में नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लें और उस पर हस्ताक्षर करें।

उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार पुष्टि

तीसरी अनुसूची में।

(7) कोई भी व्यक्ति जिसने न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया हो

उच्चतम न्यायालय किसी भी न्यायालय में या उससे पहले अभिवचन या कार्य करेगा।

भारत के क्षेत्र के भीतर कोई भी प्राधिकरण।

"217. एक के कार्यालय की नियुक्ति और शर्तें

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। - (1) उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश

राष्ट्रपति द्वारा आदेश द्वारा नियुक्त किया जाएगा

मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद उनका हाथ और मुहर

भारत का, राज्य का राज्यपाल, और, के मामले में

मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति,

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और एक अतिरिक्त या कार्यवाहक न्यायाधीश के मामले में, जैसा कि प्रावधान किया गया है, पद धारण करेंगे।

अनुच्छेद 224 में, और किसी अन्य मामले में, जब तक कि वह

बासठ-दो वर्ष की आयु:

बशर्ते कि -

(क) न्यायाधीश अपने हाथ के नीचे लिख कर संबोधित कर सकता है।

राष्ट्रपति को, अपने पद से इस्तीफा दें;

(ख) न्यायाधीश को उसके पद से हटा दिया जा सकता है -

अनुच्छेद के खंड (4) में उपबंधित रीति से राष्ट्रपति हटाने के लिए;

124 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को

(ग) न्यायाधीश का पद उसके होने के कारण खाली हो जाएगा।

राष्ट्रपति द्वारा 1 का न्यायाधीश नियुक्त किया गया

सर्वोच्च अदालतें-चालू-रिकॉर्ड

समाज v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

के क्षेत्र के भीतर किसी अन्य उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति भारत।

(2) एक व्यक्ति के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो

और

(क) कम से कम दस वर्षों तक न्यायिक पद पर रहा हो। भारत का राज्यक्षेत्र; या

(ख) कम से कम दस वर्षों से उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो।

एक के बाद एक दो या दो से अधिक ऐसे न्यायालय; स्पष्टीकरण। - इस खंड के प्रयोजनों के लिए

(क) उस अवधि की गणना करने में जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने

भारत के राज्य क्षेत्र में न्यायिक पद धारण करने के बाद, उसके किसी भी न्यायिक पद धारण करने के बाद की कोई भी अवधि शामिल होगी, जिसके दौरान व्यक्ति एक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा है

न्यायालय या किसी न्यायाधिकरण के सदस्य का पद धारण किया है या संघ या किसी राज्य के अधीन कोई पद, जिसके लिए विशेष आवश्यकता हो

कानून का ज्ञान; (एए) उस अवधि की गणना करने में जिसके दौरान किसी व्यक्ति के पास है

उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा है, वहाँ होगा इसमें कोई भी अवधि शामिल है जिसके दौरान व्यक्ति ने आयोजित किया है

न्यायिक कार्यालय या किसी न्यायाधिकरण के सदस्य का कार्यालय या

संघ या किसी राज्य के अधीन कोई पद, जिसके लिए विशेष आवश्यकता हो

अधिवक्ता बनने के बाद कानून का ज्ञान;

(ख) उस अवधि की गणना करने में जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने भारत के क्षेत्र में न्यायिक पद धारण किया या उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा, इसमें कोई भी शामिल होगा -

इस संविधान के प्रारंभ से पहले की अवधि

जिसके दौरान उन्होंने किसी भी क्षेत्र में न्यायिक पद संभाला है जो

था। अगस्त, 1947 के पंद्रहवें दिन से पहले शामिल,

भारत सरकार अधिनियम द्वारा परिभाषित भारत के भीतर,

1935, या किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा है

ऐसा कोई भी क्षेत्र, जैसा भी मामला हो।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

(3) यदि किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है

उच्च न्यायालय, इस प्रश्न का निर्णय करेगा
भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद राष्ट्रपति

और राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा।

11. के प्रावधानों का वास्तविक प्रभाव और इरादा

संविधान, और द्वारा बनाए गए अन्य सभी विधायी अधिनियम

संसद और राज्य विधानमंडलों को इस में समझा जाता है

जिस तरह से उनकी व्याख्या और घोषणा सर्वोच्च द्वारा की जाती है

न्यायालय, अनुच्छेद 141 के तहत। जिस तरह से इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 124 और 217 की व्याख्या की गई थी, वह मुख्य रूप से सामने आता है।

तीन में से-इस न्यायालय के संविधान पीठ के निर्णय, जो अब स्पष्ट रूप से विचाराधीन हैं। पहला फैसला था

4 के बहुमत से सात न्यायाधीशों की पीठ द्वारा प्रस्तुत किया गया: 3, में

30.12.1981 पर प्रथम न्यायाधीशों का मामला। सुभाष में तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने प्रथम न्यायाधीशों के मामले की शुद्धता पर संदेह किया था

शर्मा बनाम। भारत संघ, जिसने राय दी कि बहुमत का विचार है,

बेंच, दो प्रश्नों की जांच करने के लिए। सबसे पहले, क्या नियुक्ति के संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भी

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों का स्थानांतरण प्रधानता का अधिकार है?
और दूसरी बात, क्या का निर्धारण

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या न्यायसंगत थी? बहुमत से

7 में से: 2, इस न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ, दूसरे न्यायाधीशों में मामले में, प्रथम न्यायाधीशों के मामले में फैसले को खारिज कर दिया। द.

तत्काल निर्णय 6.10.1993 पर दिया गया था। परिणाम

भारत संघ के साथ संदेह उत्पन्न होने पर, के बारे में

द्वितीय न्यायाधीशों के मामले की व्याख्या, के अध्यक्ष भारत ने अनुच्छेद 143 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए नौ का उल्लेख किया

उच्चतम न्यायालय से उसकी राय के लिए प्रश्न पूछें। नौ-न्यायाधीश

बेंच ने 28.10.1998 पर सर्वसम्मति से संदर्भ का जवाब दिया।

12. द्वितीय न्यायाधीशों में इस न्यायालय के निर्णय के बाद
मामला 1993 में प्रस्तुत किया गया था, और इसकी सलाहकार राय

4 1991 पूरक (1) एस. सी. सी. 574 सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

न्यायालय को 1998 में भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। "अनुच्छेद 124 (2) और 217 (1) में परामर्श

उच्चतर न्यायाधीशों की नियुक्ति (साथ ही स्थानांतरण)

न्यायपालिका, में निहित प्रधानता के रूप में व्याख्या की जाने लगी

न्यायपालिका के साथ मामला। उत्तरदाताओं के अनुसार,

इसके परिणामस्वरूप "परामर्श" शब्द को इस रूप में समझा गया था

"सहमति" (अनुच्छेद 124, 217 और द्वारा शासित मामलों में) 222). भारत संघ ने तब एक ज्ञापन तैयार किया

न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 30.6.1999 पर प्रक्रिया और

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश,

उपरोक्त दो निर्णयों के अनुरूप। और नियुक्तियाँ इसके बाद बनाया गया, इसके अनुरूप

प्रक्रिया ज्ञापन।

13. हमारे सामने व्यक्त स्थिति के अनुसार, एक भावना

इस पर विचार किया गया कि चयन के लिए एक आयोग और

उच्चतर न्यायाधीशों की नियुक्ति, साथ ही स्थानांतरण के लिए भी

न्यायपालिका का गठन किया जाना चाहिए, जो

न्यायाधीशों और प्रमुख की नियुक्ति के लिए प्रचलित प्रक्रिया न्यायालय के न्यायाधीश,

उच्च न्यायालयों और भारत के सर्वोच्च

अनुच्छेद 124 (2) और 217 (1) के तहत विचार किया गया। यह महसूस किया गया कि प्रस्तावित आयोग व्यापक होना चाहिए। में।

कि, आयोग में सदस्य शामिल होने चाहिए

न्यायपालिका, कार्यपालिका और प्रतिष्ठित/महत्वपूर्ण व्यक्ति
सार्वजनिक जीवन। उपरोक्त तरीके से इसे लागू करने का प्रस्ताव किया गया था
चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता।

14. कथित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, अनुच्छेद 124 और
217 अन्य बातों के साथ-साथ अनुच्छेद 124 ए, 124 बी और
124 सी को संविधान में संविधान के माध्यम से जोड़ा गया था
(99 संशोधन) अधिनियम, प्रक्रिया का पालन करते हुए अनुच्छेद 368 (2) के तहत विचार किया
गया, विशेष रूप से,
इसके तहत परंतु। संशोधन को मंजूरी मिल गई
13.4.2015 से प्रभावी (इसकी अधिसूचना के परिणामस्वरूप) भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग
II, धारा 1)।

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट
इसके साथ ही संसद ने एन. जे. ए. सी. को अधिनियमित किया
अधिनियम, जिसे राष्ट्रपति की सहमति भी मिली
31.12.2014. उसी को भी लागू किया गया था, प्रभाव के साथ
13.4.2015 से (भारत के राजपत्र में इसकी अधिसूचना द्वारा) (असाधारण) भाग II, खंड 1)। उपरोक्त
संवैधानिक
संशोधन और विधायी अधिनियम, विषय हैं।
याचिकाओं के एक समूह के माध्यम से चुनौती, जिनकी हम सामूहिक रूप से सुनवाई कर रहे हैं। सच को
प्रभावी ढंग से समझने के लिए
कानूनी और संवैधानिक मुद्दों की बारीकियां शामिल हैं, यह है प्रथम न्यायाधीशों के मामले में
पक्षियों का दृष्टिकोण होना अनिवार्य है,
जिस पर विद्वान वकील द्वारा निर्भरता रखी गई है
उत्तरदाताओं के लिए, दूसरे और तीसरे न्यायाधीशों के मामलों की समीक्षा करने के उनके प्रयास में।
प्रथम न्यायाधीशों का मामला-1981 पूरक एस. सी. सी. 87।

15. केंद्रीय कानून मंत्री ने दिनांकित एक पत्र को संबोधित किया

18.3.1981 पंजाब के राज्यपाल और पंजाब के मुख्यमंत्रियों को

अन्य सभी राज्य। पता लगाने वालों को अन्य बातों के साथ-साथ सूचित किया गया था,

कि "। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक तिहाई, जहाँ तक होना चाहिए

संभव है कि वह उस राज्य के बाहर से हो जिसमें उच्च न्यायालय है

(क) उच्च न्यायालयों में काम करने वाले सभी अतिरिक्त न्यायाधीशों से उनकी नियुक्ति के लिए सहमति प्राप्त करने का अनुरोध किया गया। देश के किसी भी अन्य उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश।

उपरोक्त उल्लिखित पत्र में अपेक्षित है कि संबंधित नियुक्तियां " तीन उच्च न्यायालयों को नामित करने की आवश्यकता होगी,

स्थायी न्यायाधीश; और (बी) उन व्यक्तियों से प्राप्त करते हैं जिनके पास है पहले से ही आपके द्वारा प्रस्तावित किया गया है या भविष्य में किया जा सकता है

किसी अन्य उच्च पद पर नियुक्त होने के लिए उनकी सहमति नियुक्त करें तीन के लिए समान वरीयता के साथ देश में न्यायालय

उच्च न्यायालय "। केंद्रीय कानून मंत्री ने उपरोक्त पत्र में

स्पष्ट किया गया है कि उनकी सहमति या संकेत प्रस्तुत करना वरीयता, सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं के कहने पर किसी भी प्रतिबद्धता का संकेत नहीं देगा-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

सरकार,

उन्हें समायोजित करने के लिए

उनकी प्राथमिकताएँ। इसके जवाब में, कुछ अतिरिक्त न्यायाधीशों,

अपने मूल राज्य के बाहर नियुक्त होने के लिए अपनी सहमति दी।

(i) इकबाल चागला (और अन्य याचिकाकर्ताओं) ने महसूस किया कि पत्र

न्यायपालिका ", और एक महत्वपूर्ण/बुनियादी विशेषता पर एक निर्बाध हमला संविधान से। बॉम्बे में अधिवक्ता संघों की एक श्रृंखला ने दिनांकित पत्र की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित किए

उन्होंने पत्र को वापस लेने की मांग की। तब से नहीं किया गया, उपरोक्त संघों द्वारा एक रिट याचिका दायर की गई थी

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिनांकित 18.3.1981 पत्र को चुनौती दी।

उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था केंद्रीय कानून मंत्री और सरकार को दिनांकित 18.3.1981 पत्र को लागू करने से। ए. एल. ई. टी. आर. की पेटेंट अपील को प्राथमिकता दी गई

उपरोक्त अंतरिम आदेश के खिलाफ, एक द्वारा खारिज किया गया

उच्च न्यायालय की खंड पीठ। उपरोक्त अंतरिम आदेश,

इस न्यायालय के समक्ष हमला किया गया था। जबकि मामला लंबित था

इस न्यायालय के समक्ष केंद्रीय कानून मंत्री और सरकार

भारत सरकार ने अनुच्छेद 139 ए के तहत स्थानांतरण याचिका दायर की। स्थानांतरण याचिका को अनुमति दी गई और बॉम्बे में रिट याचिका दायर की गई।

उच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया।

((ii) दूसरी याचिका उच्च न्यायालय में वी. एम. तारकुंडे द्वारा दायर की गई थी।

दिल्ली का न्यायालय। इसने संवैधानिक वैधता को चुनौती दी

दिनांकित 18.3.1981 पत्र का। एक अतिरिक्त मैदान था

दिल्ली के तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों के संदर्भ में उठाया गया

उच्च न्यायालय, अर्थात् ओ. एन. वोहरा, एस. एन. कुमार और एस. बी. वाड,

जे जे।, जिनका कार्यकाल 6.3.1981 पर समाप्त हो रहा था। होने के बजाय

दो साल की और अवधि के लिए नियुक्त, उनकी नियुक्ति

7.3.1981 से तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। ये संक्षिप्त

कार्यकाल नियुक्तियों पर अनुच्छेद 224 के तहत अन्यायपूर्ण होने के अलावा "स्वतंत्रता" के विध्वंसक होने के रूप में हमला किया गया था।

न्यायपालिका का "। इस रिट याचिका को भी स्थानांतरित कर दिया गया था

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अब तक परिपत्र पत्र [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दिनांक 18.3.1981 का संबंध है, उच्चतम न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा की गई एक मौखिक प्रार्थना पर निर्देश दिया कि कोई भी अतिरिक्त जो न्यायाधीश परिपत्र पत्र का जवाब नहीं देना चाहते थे, वे दे सकते हैं

ऐसा नहीं करना, और यह कि, उसे न तो विस्तार से इनकार किया जाएगा और न ही

दिनांकित 18.3.1981 पत्र का जवाब दें। इसके बाद, नियुक्ति एस. बी. वाड, जे. को एक वर्ष की अवधि के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में जारी रखा गया था, लेकिन ओ. एन. वोहरा और एस. एन.

कुमार, जे. जे।, 7.6.1981 से आगे जारी नहीं रखा गया था। (iii और iv)। जे. एल. कालरा और अन्य द्वारा एक तीसरी रिट याचिका दायर की गई थी।

जो दिल्ली उच्च न्यायालय में वकालत कर रहे थे। और

चौथी रिट याचिका एस. पी. गुप्ता द्वारा दायर की गई थी।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता। तीसरा और चौथा

रिट याचिकाएं काफी हद तक उन्हीं राहतों के लिए थीं, जैसे

इससे पहले की दो याचिकाएँ।

(v) पाँचवीं रिट याचिका, लिली थॉमस द्वारा दायर की गई थी। उन्होंने चुनौती दी

मद्रास उच्च न्यायालय का स्थानांतरण प्रमुख के रूप में किया गया था केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। उपरोक्त आदेश था

राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 222 (1) के तहत परामर्श के बाद पारित किया गया

भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ। इसी तरह, हस्तांतरण

पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से लेकर मद्रास उच्च न्यायालय तक

अदालत को यह कहते हुए चुनौती दी गई थी कि हस्तांतरण की शक्ति

अनुच्छेद 222 (1) के तहत उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों तक सीमित था,

और इसका विस्तार मुख्य न्यायाधीशों तक नहीं हुआ। वैकल्पिक रूप से यह था

तर्क दिया कि स्थानांतरण केवल सहमति से किया जा सकता है

संबंधित न्यायाधीश का, और केवल लोक हित में, और उसके बाद

भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ पूर्ण और प्रभावी परामर्श।

(vi & vii) छठी रिट याचिका मुख्य रूप से ए. राजप्पा द्वारा दायर की गई थी।

19.1.1981 दिनांकित आदेश को चुनौती देते हुए, जिसके तहत कुछ प्रमुख

न्यायाधीशों का स्थानांतरण किया गया था। एक अतिरिक्त प्रस्तुति थी

न्यायाधीश बिना पूर्व परामर्श के बनाए गए थे
सर्वोच्च न्यायालय अधिवक्ताओं को-चालू-रिकॉर्ड करता है

संबंधित राज्यों के राज्यपाल, और आगे, कि उक्त

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

स्थानांतरण लोक हित में नहीं थे और इसलिए इसका उल्लंघन किया गया था

अनुच्छेद 217 (1) में निहित प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ। द.

ए. राजप्पा द्वारा दायर याचिका के आधार पर।
याचिका दायर की गई थी।

(viii) डी. एन. पांडे और ठाकुर द्वारा आठवीं रिट

पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रमापति सिन्हा
न्यायमूर्ति के. बी. एन. सिंह ने कहा,

अदालत। इस याचिका में मुख्य न्यायाधीश

पटना उच्च न्यायालय के प्रत्यर्थी नं. 3.

याचिकाकर्ता नं. 3, याचिकाकर्ता नं. 3, न्यायमूर्ति के. बी. एन. सिंह ने दायर किया
हलफनामा जिसमें कहा गया है कि उनका स्थानांतरण किया गया था

एक विस्तृत

सजा के रूप में, और आगे, कि यह किया गया था

अप्रासंगिक और अपर्याप्त आधारों पर, और सार्वजनिक रूप से नहीं

ब्याज। और आगे कि, यह एक पूर्ण और से पहले नहीं था
प्रभावी परामर्श।

भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ

अतः यह स्पष्ट है कि उपर्युक्त

दो अलग-अलग मामलों से संबंधित याचिकाएँ। सबसे पहले, मुद्रा
नियुक्ति से संबंधित, और

न्यायाधीशों की प्रारंभिक

अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की अवधि का विस्तार

उनके मूल कार्यकाल की समाप्ति। और दूसरा, का स्थानांतरण

एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश।

16. प्रथम न्यायाधीशों के मामले में दर्ज राय,

जहाँ तक वे वर्तमान विवाद के लिए प्रासंगिक हैं,

यहाँ संक्षेपित:

पी. एन. भगवती, जे. (जैसा कि वे तब थे): __

(i) न्यायपालिका की स्वतंत्रता के विषय पर, यह था

राय दी, कि "। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा एक है

महान अवधारणा जो संवैधानिक योजना को प्रेरित करती है और
 यह उस नींव का गठन करता है जिस पर हमारी इमारत टिकी हुई है
 लोकतांत्रिक राजनीति। अगर एक सिद्धांत है जो चलता है
 पूरे संविधान का पूरा ताना-बाना, यह सिद्धांत है
 कानून के शासन और संविधान के तहत, यह न्यायपालिका है जिसे [2015] 13 एस. सी. आर. के प्रत्येक अंग को
 बनाए रखने का कार्य सौंपा गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कानून की सीमाओं के भीतर राज्य करें और इस प्रकार शासन करें
 कानून सार्थक और प्रभावी है। न्यायपालिका के बीच खड़ा है
 नागरिक और राज्य कार्यपालिका के खिलाफ एक गढ़ के रूप में
 कार्यपालिका द्वारा ज्यादतियाँ और शक्ति का दुरुपयोग या दुरुपयोग, और
 इसलिए यह नितांत आवश्यक है कि न्यायपालिका कार्यकारी दबाव या प्रभाव से मुक्त और यह किया
 गया है
 संविधान निर्माताओं द्वारा विस्तृत रूप से सुरक्षित किया गया
 संविधान में प्रावधान "1 यह महसूस किया गया कि अवधारणा
 "न्यायपालिका की स्वतंत्रता" केवल तक ही सीमित नहीं थी
 कार्यकारी दबाव या प्रभाव से स्वतंत्रता, लेकिन यह था एक बहुत व्यापक अवधारणा, जिसने
 अपने व्यापक दायरे में ले लिया,
 कई अन्य दबावों और पूर्वाग्रहों से स्वतंत्रता। यह,
 उनके कई आयाम थे, अर्थात्, अन्य शक्ति की निडरता।
 केंद्र, आर्थिक या राजनीतिक, और पूर्वाग्रहों से स्वतंत्रता
 जिस वर्ग के न्यायाधीशों द्वारा अर्जित और पोषित किया गया था शामिल हैं। यह माना गया था
 कि "स्वतंत्रता का सिद्धांत
 न्यायपालिका "को ध्यान में रखना था, व्याख्या करते समय

संविधान के प्रावधान (अनुच्छेद 27)। (ख)। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय पर, यह

राय दी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की तरह, जो हैं
और सार का अर्थ था केंद्र सरकार), इसी तरह, अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति,
केंद्र सरकार द्वारा प्रयोग किया जाना था। ऐसी शक्ति,
यह आयोजित किया गया था, केवल प्रयोग करने योग्य था "।
भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। "यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह स्पष्ट था
उपरोक्त दो अनुच्छेदों के एक सादे पठन पर, कि प्रमुख
भारत के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और ऐसे
उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश (जैसा कि केंद्र सरकार परामर्श करना आवश्यक समझे), थे
संवैधानिक पदाधिकारी, एक सलाहकार भूमिका रखने वाले, और
नियुक्तियों की शक्ति पूरी तरह से और विशेष रूप से केंद्र सरकार के निर्णय में निहित थी।

यह बताया गया था कि सर्वोच्च अदालतें-चालू-रिकॉर्ड करती हैं
एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]
उपरोक्त शक्ति एक निरंकुश शक्ति नहीं थी, इस अर्थ में,
कि केंद्र सरकार मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकती, इसके बिना
दोनों में निर्दिष्ट संवैधानिक अधिकारियों से परामर्श करना
लेख। केंद्र सरकार को कार्रवाई करनी थी, उसके बाद ही
संवैधानिक अधिकारियों से परामर्श करना, और वह, परामर्श पूर्ण और प्रभावी होना चाहिए (पैराग्राफ 29)।

(iii)। "परामर्श" शब्द के अर्थ के सवाल पर
अनुच्छेद 124 (2) और अनुच्छेद 217 (1) में व्यक्त, यह अभिनिर्धारित किया गया था,
कि यह सवाल अब एकीकृत नहीं था, जैसा कि मुद्दा खड़ा था

संघ में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा निष्कर्ष निकाला गया

भारत बनाम. संकलचंद हिमतलाल सेठ 5, जिसमें इसका अर्थ था निर्धारित किया गया। लेकिन जब से यह

अनुच्छेद 222 (1) के संदर्भ में

पार्टियों के बीच आम आधार, कि शब्द

"अनुच्छेद 222 (1) में प्रयुक्त "परामर्श" का वही अर्थ था,

जो अनुच्छेद 124 (2) और 217 (1) में था, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि,

"..... अतः राष्ट्रपति को संवाद करना चाहिए। पाठ्यक्रम है

मुख्य न्यायाधीश को उनके पास जो भी सामग्री और

प्रस्ताव करता है। मुख्य न्यायाधीश को, बदले में, आवश्यक संग्रह करना चाहिए

जिम्मेदार चैनलों के माध्यम से या सीधे, आवश्यक डेटा के साथ खुद को परिचित करें, जानकारी पर जानबूझकर उसके पास है और उसके हितों में आगे बढ़ता है

राष्ट्रपति को ऐसी सलाह देने के लिए न्याय प्रशासन

जैसा कि वे सोचते हैं कि कार्रवाई सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाएगी, विशेष रूप से

न्याय प्रणाली का कारण। "यह आगे निष्कर्ष निकाला गया, अवलोकन

कि संकल्पचंद हिमतलाल सेठ में उपरोक्त

दायरा निर्धारित करने के लिए मामले समान बल के साथ लागू होंगे।

और अर्थ के भीतर "परामर्श" शब्द का अर्थ

अनुच्छेद 124 (2) और 217 (1)। प्रत्येक संवैधानिक परामर्श करने की आवश्यकता है,

इन दो अनुच्छेदों के तहत अधिकारियों से

उसके विचार के लिए, पूर्ण और समान तथ्य होने चाहिए पर

व्यक्ति की नियुक्ति या गैर-नियुक्ति

संबंधित, और उनमें से प्रत्येक की राय समान रूप से ली गई

सामग्री, केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाना चाहिए,

5 (1977) 4 एस. सी. सी 193 [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इससे पहले कि वह कोई निर्णय ले, व्यक्ति को नियुक्त करना है या नहीं संबंधित। यह केंद्र सरकार के लिए खुला था।

एक न्यायाधीश के रूप में

नियुक्ति या गैर-नियुक्ति के संबंध में अपना निर्णय लेने के लिए

उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति, महत्व देने के बाद,

राय को ध्यान में रखने और उचित

व्यक्त किया। यह भी देखा गया कि एकमात्र जमीन जिस पर

इस तरह के निर्णय पर हमला किया जा सकता था, कि कार्रवाई थी

दुर्भावनापूर्ण या अप्रासंगिक विचारों पर आधारित। ए के मामले में

संवैधानिक कार्यकर्ताओं के बीच मतभेद,

यह महसूस किया गया कि किससे परामर्श किया जाना है, यह केंद्र सरकार को तय करना है कि किसकी राय को स्वीकार किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि परामर्श प्रक्रिया, प्रधानता भारत के मुख्य न्यायाधीश की होनी चाहिए, क्योंकि वे भारतीय न्यायपालिका के प्रमुख थे

और न्यायिक बिरादरी के पिता परिवार, के लिए खारिज कर दिया गया था

कारण, कि प्रत्येक संवैधानिक पदाधिकारी हकदार था

समान भार के लिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि

भारत से परामर्श करने की आवश्यकता थी, लेकिन केंद्र सरकार

भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं था, भले ही उनकी राय का अधिकार था

बड़ा वजन। इसलिए यह माना गया था कि अंतिम शक्ति

नियुक्ति, जो केंद्र सरकार के पास होती है

(अनुच्छेद 30)।

(iv)। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मुद्दे पर

न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श

भारत की एक अनिवार्य आवश्यकता थी। लेकिन एक बनाते समय

नियुक्ति, परामर्श ऐसे अन्य न्यायाधीशों को भी दिया जा सकता है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, जो केंद्र सरकार आवश्यक समझे। इसके जवाब में

प्रस्तुत करना, जहां केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया गया था (यानी, जब परामर्श का विस्तार भारत के अन्य न्यायाधीशों तक नहीं हुआ था) सर्वोच्च न्यायालय, या उच्च न्यायालयों की), चाहे राय

भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सर्वोच्च न्यायालय माना जाना चाहिए-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

बाध्यकारी, यह राय दी गई थी कि परामर्श होना तय था,

उच्चतम न्यायालय के एक या अधिक न्यायाधीशों के साथ और उच्च न्यायालय, नियुक्ति की शक्ति का प्रयोग करने से पहले

अनुच्छेद 124 (2) के तहत प्रदान किया गया। यह महसूस किया गया कि परामर्श

के संदर्भ में अकेले भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ

उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी। नियुक्ति का संतोषजनक तरीका, क्योंकि ज्ञान और

ईमानदार और सार्थक। यह सुझाव दिया गया था कि यह होगा अधिक उपयुक्त यदि एक कॉलेजियम बनाएगा

राष्ट्रपति को सिफारिशें, जिनके संबंध में

उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियाँ, और सिफारिश करना प्राधिकरण अधिक व्यापक होना चाहिए। अगर कॉलेजियम था

इनमें ऐसे व्यक्ति शामिल थे जिन्हें व्यक्तियों का ज्ञान था, जो

न्यायपीठ में नियुक्ति के लिए उपयुक्त हो सकता है, और उसके पास इस तरह की नियुक्ति के लिए आवश्यक गुण, यह एक लंबा रास्ता तय करेगा

सही प्रकार के न्यायाधीशों को सुरक्षित करने की दिशा में, जो वास्तव में होंगे

स्वतंत्र (अनुच्छेद 31)।

(v) यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति,

अनुच्छेद में अभिनिर्धारित प्रक्रिया का पालन करके किया जाना चाहिए

217 (1). तदनुसार, जब एक अतिरिक्त न्यायाधीश का कार्यकाल कार्यकाल समाप्त हो गया, और वह न्यायाधीश बनना बंद कर दिया, उनकी पुनर्नियुक्ति हो सकती थी

केवल एक बार फिर निर्धारित प्रक्रिया को अपनाकर किया जाए

स्वचालित रूप से और बिना किसी और विचार के
कार्यकाल के लिए नियुक्त, या

अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में अगले

स्थायी न्यायाधीश को अस्वीकार कर दिया गया (पैराग्राफ 38 से 44)।

(vi) संघ कानून के पत्र की वैधता के सवाल पर

मंत्री दिनांक 18.3.1981, यह राय दी गई थी कि वही किया गया था

किसी भी कानूनी या संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है। यह महसूस किया गया कि

पत्र के माध्यम से प्राप्त की जाने वाली अग्रिम सहमति

दिनांक 18.3.1981, इससे पहले अतिरिक्त न्यायाधीशों या न्यायाधीशों से

उनकी स्थायी नियुक्ति का कोई अर्थ नहीं होगा, अब तक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

जैसा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का संबंध था, क्योंकि तथ्य की परवाह किए बिना, क्या अतिरिक्त
न्यायाधीश ने दिया था

उसकी सहमति हो या न हो, भारत के मुख्य न्यायाधीश को

विचार करें कि क्या यह सार्वजनिक हित में अनुमति देने के लिए होगा

अतिरिक्त न्यायाधीश को किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा
(पैराग्राफ 54)।

(vii) व्यक्तिगत दावे के गुण-दोष निर्धारित करने के बाद

S.N.Kumar, जे. द्वारा उठाया गया (जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था)

न्यायाधीश), यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह उचित होगा यदि संघ
सकता है, दिनांकित 7.5.1981 पत्र को रखने के लिए

भारत का एक रास्ता मिल

दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कानून को संबोधित किया
न्यायाधीश के समक्ष, और उनकी राय प्राप्त करें

मंत्री, भारत के मुख्य

उस पत्र के संदर्भ में। और फिर विचार करें कि क्या

एस. एन. कुमार, जे. को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में फिर से नियुक्त किया जाना चाहिए।

(viii) के. बी. एन. सिंह, सी. जे. के संदर्भ में।, यह राय दी गई थी कि

केंद्र सरकार द्वारा इसका स्पष्ट त्याग किया गया था

संवैधानिक कार्य, और इसलिए, से उनका स्थानांतरण

पटना उच्च न्यायालय से मद्रास उच्च न्यायालय को इस रूप में अभिनिर्धारित किया गया था असंवैधानिक और अमान्य।

ए. सी. गुप्ता, जे. :

((i)) "न्यायपालिका की स्वतंत्रता" के विषय पर, यह था राय दी कि इसका मतलब न्यायाधीशों को कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है

मनमाने ढंग से। इसका मतलब केवल यह था कि न्यायाधीश स्वतंत्र होने चाहिए, जबकि

अपने न्यायिक कार्यों का निर्वहन करना। बनाए रखने के लिए "न्यायपालिका की स्वतंत्रता", यह महसूस किया गया कि न्यायाधीशों को

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप से संरक्षित किया जाए। यह था।

एक तरह से समझा जाता है, जो कमजोर करने की प्रवृत्ति रखता है "न्यायपालिका की स्वतंत्रता" की अवधारणा (अनुच्छेद 119)।

((ii)) इस प्रश्न पर कि क्या कार्यकाल समाप्त होने पर उच्च न्यायालय के किसी अतिरिक्त न्यायाधीश के लिए यह अनुज्ञेय था कि -

उसे एक और कार्यकाल नहीं देकर छोड़ दें, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं की संख्या-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

उच्च न्यायालय में लंबित कार्य के लिए सेवाओं की आवश्यकता होती है

एक और न्यायाधीश? यह राय दी गई थी कि एक अतिरिक्त का कार्यकाल

न्यायाधीश, केवल काम के बकाया पर निर्भर था, या

उच्च न्यायालय के कार्य में अस्थायी वृद्धि। और तब से

एक अतिरिक्त न्यायाधीश परीवीक्षा पर नहीं था, उसका प्रदर्शन

यह निर्धारित करने के लिए विचार नहीं किया जा सका कि क्या वह इसके लिए उपयुक्त था

स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति। इसलिए यह कहा गया

निष्कर्ष निकाला कि यदि उच्च न्यायालय में लंबित कार्य की मात्रा एक अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति को उचित ठहराती है, तो

कोई कारण नहीं होना चाहिए, संबंधित अतिरिक्त न्यायाधीश को क्यों नहीं होना चाहिए

किसी अन्य कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाए। निवेदन है कि दोनों वर्षों की अवधि, ऊपरी सीमा को दर्शाती है अनुच्छेद 224 में उल्लिखित

कार्यकाल का, और यह कि राष्ट्रपति नियुक्त करने के लिए सक्षम था

किसी भी छोटी अवधि के लिए एक अतिरिक्त न्यायाधीश को अस्वीकार कर दिया गया था। तब से

एक न्यायाधीश की योग्यता, उसके समय पर विचार किया गया था

प्रारंभिक नियुक्ति, इसलिए, यह निर्धारित करते हुए कि क्या वह

अनुच्छेद 217 (1) के तहत फिर से नियुक्त किया जाना चाहिए, यह राय दी गई थी कि जांच का दायरा सीमित था, क्या

उच्च न्यायालय में लंबित कार्य के कारण उन्हें जारी रखना आवश्यक हो गया।

(iii)। मुख्य न्यायाधीश द्वारा व्यक्त की गई राय का उल्लेख करते हुए

एस. एन. कुमार, जे. के संबंध में उच्च न्यायालय की राय थी,

कि जब एक न्यायाधीश के खिलाफ आरोप लगाए गए थे

अपने कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में, केवल उचित

खुला रास्ता, जो स्वतंत्रता को कमजोर नहीं करेगा

न्यायपालिका का "था, जांच के साथ आगे बढ़ने के लिए

आरोप लगे और आरोप पाए जाने पर न्यायाधीश को हटा दें

सत्य होना (नीचे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार)

अनुच्छेद 124 (4) और (5) को अनुच्छेद 218 के साथ पढ़ा जाता है। यह महसूस किया गया कि,

अपने प्रारंभिक कार्यकाल के अंत में एक अतिरिक्त न्यायाधीश को हटाना कार्यालय, इस आधार पर कि उनके खिलाफ आरोप थे,

आरोपों की सच्चाई का ठीक से पता लगाए बिना, "न्यायपालिका की स्वतंत्रता" (पैराग्राफ 123) के लिए विनाशकारी था।

(iv)। दिल्ली उच्च न्यायालय के एक अतिरिक्त न्यायाधीश, एस. एन. कुमार, जे. की गैर-निरंतरता के संदर्भ में, यह कहा गया था, [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पत्र दिनांकित है

7.5.1981, कानून मंत्री को संबोधित, खुलासा नहीं किया गया था
 भारत के मुख्य न्यायाधीश को। जैसा कि प्रासंगिक सामग्री थी
 भारत के मुख्य न्यायाधीश से रोके जाने पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि
 जैसा कि सोचा गया था, कोई पूर्ण और प्रभावी "परामर्श" नहीं था।
 अनुच्छेद 217 (1) द्वारा। और इसलिए, विस्तार नहीं करने का निर्णय
 अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में एस. एन. कुमार, जे. का कार्यकाल
 दिल्ली उच्च न्यायालय, हालांकि में लंबित कार्य की मात्रा
 उच्च न्यायालय को एक अतिरिक्त न्यायाधीश की सेवाओं की आवश्यकता थी,
 अमान्य है।

(वी)। इस सवाल पर कि क्या मुख्य न्यायाधीश की राय है

मतभेद की स्थिति में भारत की प्रधानता होगी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और मुख्य
 न्यायाधीश के बीच

भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय को स्वीकार करें, जब तक कि ऐसा न हो। राय किसी भी स्पष्ट
 दुर्बलता से पीड़ित थी। और यह कि

राष्ट्रपति एक अंपायर के रूप में कार्य नहीं कर सकते थे, और दोनों राय (पैराग्राफ 134) के बीच चयन कर
 सकते थे।

(vi)। संकलचंद हिमतलाल में निर्णय का उल्लेख करते हुए शेट मामले, जिसमें यह निष्कर्ष
 निकाला गया था, कि बड़े पैमाने पर स्थानांतरण

अनुच्छेद 222 (1) के तहत विचार नहीं किया गया था, यह राय दी गई थी,

कि राष्ट्रपति एक उच्च न्यायालय से एक न्यायाधीश का स्थानांतरण कर सकता है

और यह कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को प्रत्येक मामले में विचार करना चाहिए, क्या प्रस्तावित
 स्थानांतरण जनहित में था (अनुच्छेद)

138).

(vii)। के. बी. एन. सिंह, मुख्य न्यायाधीश के स्थानांतरण के संदर्भ में।, पटना उच्च न्यायालय से लेकर मद्रास
 उच्च न्यायालय तक, यह राय दी गई थी, कि भले ही उपरोक्त स्थानांतरण प्रशासनिक कारणों से और
 सार्वजनिक हित में किया गया था, इसकी संभावना थी

अंतरिती को कुछ चोट पहुँचाना, और यह केवल उचित होगा

उसे स्थानांतरित करने की संभावना पर विचार करें, जहां उसे कम से कम कठिनाइयों का सामना करना
 पड़ेगा, अर्थात्, जहां भाषा की कठिनाई हो। तीव्र नहीं होगा।

सर्वोच्च न्यायालय

अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

एस. मुर्तजा फजल अली, जे. :

(i) इस मुद्दे पर, क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण

अनुच्छेद 222 के तहत प्रस्तावित न्यायाधीश की सहमति की आवश्यकता होती है

स्थानांतरित किए जाने के लिए, यह राय दी गई थी कि एक गैर-सहमति हस्तांतरण, यह सजा के बराबर नहीं होगा, न ही इसमें कोई शामिल होगा

"न्यायपालिका की स्वतंत्रता" (अनुच्छेद 345)। (ख)। राज्य के बाहर से उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में, और प्रत्येक में एक तिहाई न्यायाधीश होने के लिए

राज्य के बाहर से उच्च न्यायालय ने यह व्यक्त किया कि

अनुच्छेद 222 राष्ट्रपति को व्यक्त करने की शक्ति प्रदान करता है,

एक राज्य से एक न्यायाधीश (जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं) का स्थानांतरण

किसी और के लिए। यह निर्धारित करने में कि यह शक्ति कैसे होनी चाहिए

प्रयोग किया गया, यह महसूस किया गया कि राष्ट्रपति निस्संदेह

मानदंडों को निर्धारित करने के लिए एक निहित शक्ति थी,

सिद्धांत, परिस्थितियाँ और परिस्थितियाँ, जिनके तहत उक्त शक्ति का प्रयोग किया जाना था। द्वारा एक घोषणा

नीति की प्रकृति और शर्तों के बारे में राष्ट्रपति (जो

वस्तुतः मंत्रिपरिषद द्वारा एक घोषणा का अर्थ था)

(अनुच्छेद 410)। (iii)। संघ कानून के पत्र की वैधता के विषय पर

मंत्री दिनांक 18.3.1981, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि इसमें ऐसा नहीं था

किसी भी तरह से न्यायाधीशों की छवि को धूमिल करना, या स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाना।

न्यायपालिका का "(अनुच्छेद 433)। (iv)। अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रश्न पर, और

अनुच्छेद 217 की व्याख्या, पी. एन. द्वारा व्यक्त राय।

भगवती और ई. एस. वेंकटरमैया, जे. जे. अपनाया गया

(अनुच्छेद 434)।

(वी)। जहाँ तक अनुच्छेद 224 की व्याख्या का संबंध है, पी. एन. भगवती और डी. ए. देसाई, जे. थे। स्वीकार किया गया, (पैराग्राफ 537)।

और तदनुसार, उनका निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति की अवधि समाप्त होने के बाद, समर्थन किया।

(vi)। संकालचंद में दिए गए निर्णय का विश्लेषण करने पर

हिम्मतलाल सेठ मामले, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित आवश्यक हैं:

और भारत के मुख्य न्यायाधीश को तैयार किया गया। कि परामर्श, पूर्ण और प्रभावी होना चाहिए, और वास्तविक हस्तांतरण से पहले होना चाहिए

न्यायाधीश का। यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श किया गया था

न्यायाधीश के स्थानांतरण से पहले यह अभिनिर्धारित किया गया था कि

स्थानांतरण असंवैधानिक होगा। सभी प्रासंगिक डेटा और

आवश्यक तथ्य, भारत के मुख्य न्यायाधीश को प्रदान किए जाने चाहिए,

उपरोक्त प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन किया गया था, परामर्श होगा पूर्ण और प्रभावी माना जाए। यह महसूस किया गया कि मुख्य न्यायाधीश

भारत का राष्ट्रपति और न्यायाधीश दोनों के प्रति कर्तव्य है

प्रत्येक प्रासंगिक तथ्य पर विचार करने के लिए स्थानांतरित करने का प्रस्ताव,

राष्ट्रपति को अपनी राय देने से पहले। देने से पहले उनकी राय भारत के मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश से अनौपचारिक रूप से पता लगा सकते थे कि क्या कोई व्यक्तिगत कठिनाई थी, या कोई अन्य समस्या थी।

मानवीय आधार, जिस पर उनका स्थानांतरण नहीं किया जाना चाहिए।

और ऐसा करने के बाद ही, भारत के मुख्य न्यायाधीश,

राष्ट्रपति को अपनी राय भेजें। की वैधता के संबंध में परामर्श प्रक्रिया के उपरोक्त पहलुओं को लागू करना

आदेश दिनांक 19.1.1981, जिसके द्वारा के. बी. एन. सिंह, सी. जे., था।

स्थानांतरित किया गया, यह अभिनिर्धारित किया गया कि परामर्श प्रक्रिया

अनुच्छेद 222 के तहत विचार किया गया था, जिसका उल्लंघन किया गया था

राष्ट्रपति द्वारा पारित आदेश अमान्य (पैराग्राफ 589)। वी. डी. तुलजापुरकर। जे. :

((i)) जहाँ तक "न्यायपालिका की स्वतंत्रता" का सवाल है

संबंधित है, यह दावा किया गया था कि सभी न्यायाधीशों, जिन्होंने

इस मामले में अपनी राय व्यक्त की थी, इस बात पर जोर दिया था कि संविधान निर्माताओं ने सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं-ऑन-रिकॉर्ड के लिए बहुत मेहनत की थी

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

उच्च न्यायपालिका की "न्यायाधीशों की स्वतंत्रता" को सुनिश्चित करना।

उपरोक्त विवाद का समर्थन करने के लिए, के कई प्रावधान

उपरोक्त प्रस्ताव पर विवाद करें (पैराग्राफ 239)। ((ख)) अनुच्छेद के तहत भर्ती किए गए अतिरिक्त न्यायाधीशों के संदर्भ में

224 (1), अधिवक्ताओं का अभ्यास करने वाली विरादरी से, यह बताया गया था कि उनसे एक वचन लिया गया था

उनकी प्रारंभिक नियुक्ति का समय, कि यदि और कब एक स्थायी

उस न्यायालय के न्यायाधीश पद की पेशकश उन्हें की गई थी, वे नहीं करेंगे

उसी तरह अस्वीकार करें। और इसके अतिरिक्त, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से उन्हें आगे की जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

वचन देते हुए कि यदि वे इस तरह के स्थायी न्यायाधीश को स्वीकार करने से इनकार करते हैं (हालांकि प्रस्तावित), या यदि उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया

अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में, वे बंबई उच्च न्यायालय या उसके अधीनस्थ किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष वकालत नहीं करेंगे।

उपरोक्त उपक्रमों के आधार पर, विवाद आगे बढ़ा

था, कि एक वैध अपेक्षा, और एक प्रवर्तनीय अधिकार

पद पर बने रहें, अतिरिक्त पर सम्मानित होने के लिए आए

बार से न्यायाधीशों की भर्ती की जाती है। यह महसूस किया गया कि अनुच्छेद 224 (1) का यह अर्थ लगाना असंभव था कि यह नियुक्ति को प्रदान करता है।

उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति (पैराग्राफ 622 और 624)। (iii)
उत्तरदाताओं की ओर से की गई सभी प्रस्तुतियाँ, कि

एक अतिरिक्त न्यायाधीश को विस्तार देना, या उसे एक अतिरिक्त न्यायाधीश बनाना

स्थायी न्यायाधीश एक नई नियुक्ति के समान था, थे अस्वीकार कर दिया। यह निष्कर्ष निकाला गया कि एक अतिरिक्त के लिए विस्तार

628)। (iv)। एक की निरंतरता के सवाल से निपटने के दौरान

अतिरिक्त न्यायाधीश, उन स्थितियों में जहां तथ्य सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर. थे।

संदिग्ध दुर्व्यवहार और/या रिपोर्ट की गई कमी का खुलासा करना

सत्यनिष्ठा, व्यक्त किया गया दृष्टिकोण था, कि विचार करते हुए एक बैठे अतिरिक्त न्यायाधीश की निरंतरता का सवाल, पर

उनके प्रारंभिक कार्यकाल की समाप्ति, उपयुक्तता की परीक्षा पर विचार किया गया अनुच्छेद 217 (1) के तहत परामर्श प्रक्रिया के भीतर नहीं होना चाहिए

कम से कम एक उचित तंत्र तक जागृत किया जाए, जिसमें एक कानूनी

मंजूरी, न्यायाधीश के खिलाफ जांच करने के लिए प्रदान की गई थी

संबंधित, किसी भी संदिग्ध दुर्व्यवहार के संदर्भ में और /

या सत्यनिष्ठा की कमी (अनुच्छेद 628)। (v) विचार के दायरे पर, एक बैठक के रूप में जारी रखने के लिए

अतिरिक्त न्यायाधीश (न्यायाधीश का प्रारंभिक कार्यकाल समाप्त होने पर), यह

राय दी गई थी कि परामर्श प्रक्रिया को सीमित किया जाना चाहिए

केवल यह देखने के लिए कि क्या अनुच्छेद में उल्लिखित पूर्व शर्तें

224 (1) अस्तित्व में था या नहीं, या क्या, काम का लंबित होना उचित है

जारी रखें या न रखें। यह माना गया था कि उपयुक्तता का परीक्षण

अनुच्छेद के तहत परामर्श प्रक्रिया के भीतर विचार किया गया

217 (1), (पैराग्राफ 629) का सहारा नहीं लिया जा सकता था और न ही लिया जाना चाहिए।

(vi)। अनुच्छेद 217 (1) के संदर्भ में भारत के मुख्य न्यायाधीश की प्रधानता के सवाल पर व्यक्त किया गया विचार था, कि

उसमें परिकल्पित योजना, निहितार्थ और इरादे से, स्पष्ट रूप से

मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी गई सलाह को प्रधानता दी गई
 भारत। हालाँकि यह स्पष्ट करने की कोशिश की गई कि प्राथमिकता दी जाए।
 भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, के मामले में
 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, नहीं होनी चाहिए
 किसी भी प्रस्ताव को वीटो करने की शक्ति के रूप में माना जाता है। और कि, यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश
 की सलाह आगे बढ़ी थी बाहरी या गैर-जर्मन विचार, वही होंगे
 राष्ट्रपति के अंतिम निर्णय की तरह न्यायिक समीक्षा के अधीन होना
 भारत का, लेकिन उचित और ठोस कारणों से। लेख की व्याख्या 217 (1) उपरोक्त तरीके से,
 यह महसूस किया गया था, एक लंबा रास्ता तय करेगा
 न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संरक्षित करना (पैराग्राफ 632)।
 (vii) 'परामर्श' के दायरे के संबंध में, विचार किए गए सर्वोच्च न्यायालय-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. 1. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]
 अनुच्छेद 222 (1) के तहत, बहुमत द्वारा निकाले गए निष्कर्ष
 संकल्प, संकलचंद हिमतलाल सेठ मामलों में, समर्थित किया गया था। (viii)। जहां तक निर्णय के
 आधार पर संबंधित न्यायाधीश की सहमति लेने के मुद्दे का संबंध है, उनके स्थानांतरण से पहले
 संकलचंद हिमतलाल सेठ मामले 5 में यह महसूस किया गया था,
 कि हस्तांतरण की सहमति प्राप्त किए बिना किया जा सकता है
 संबंधित। न्यायाधीश। और तदनुसार यह अभिनिर्धारित किया गया था कि गैर
 सहमति से किए गए स्थानांतरण अनुच्छेद 222 (1) के दायरे में थे। (पैराग्राफ 645 और 646)।
 (ix) केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा लिखे गए पत्र के संदर्भ में दिनांक 18.3.1981, यह दावा किया गया
 था कि एक पॉलिसी हस्तांतरण भी,
 प्रक्रिया की अपेक्षित प्रणाली या तौर-तरीके को तय किए बिना,
 कार्यकारी के खिलाफ पूर्ण इन्सुलेशन सुनिश्चित नहीं करेगा
 हस्तक्षेप। इसके विपरीत यह महसूस किया गया कि एक चयनात्मक स्थानांतरण
 एक उपयुक्त मामला, सख्ती से वस्तुनिष्ठ कारणों से, और सार्वजनिक रूप से

ब्याज गैर-दंडात्मक हो सकता है। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला गया कि हस्तांतरण का प्रत्येक मामला, चाहे वह नीति पर आधारित हो, या

व्यक्तिगत कारणों को अपने स्वयं के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लेना होगा, यह तय करने के लिए कि क्या यह दंडात्मक था (अनुच्छेद 649)।

(x) यह निष्कर्ष निकाला गया था कि एक बैठे अतिरिक्त न्यायाधीश की आवश्यकता से,

किसी अन्य उच्च न्यायालय में नियुक्त होने के लिए अपनी सहमति देना,

वस्तुतः उनके स्थानांतरण के लिए उनकी सहमति लेने के बराबर था

उसका अपना उच्च न्यायालय किसी अन्य उच्च न्यायालय में, जिसके अंतर्गत आता है (1) की परिधि। में दिए गए निर्णय का उल्लेख करते हुए अनुच्छेद 222

संकलचंद हिमतलाल सेठ के मामलों में यह महसूस किया गया कि

18.3.1981 दिनांकित परिपत्र पत्र दरकिनार करने का एक प्रयास था

में व्यक्त किए गए सुरक्षा उपाय और सख्त शर्तें

उपरोक्त निर्णय (पैराग्राफ 652)। और आगे, कि परिपत्र

पत्र ने स्पष्ट रूप से कार्यकारी प्रभुत्व और अहंकार की गंध को उजागर किया, जिसका उद्देश्य लोगों के दिमाग पर जबरदस्त प्रभाव डालना था।

अतिरिक्त न्यायाधीशों को, उनके लिए एक धमकी का संकेत देते हुए, कि यदि

उन्होंने कहीं और स्थानांतरित करने के लिए अपनी सहमति नहीं दी, वे

न तो इसे जारी रखा जाएगा और न ही इसे स्थायी बनाया जाएगा।

उपरोक्त सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

पत्र, के साथ कार्यकारी हस्तक्षेप के बराबर माना गया था "न्यायपालिका की स्वतंत्रता", और इस प्रकार अवैध,

असंवैधानिक और अमान्य। इसके तहत प्राप्त कोई भी सहमति,

इसे भी अमान्य माना गया था (अनुच्छेद 654)।

(xi) यह भी निष्कर्ष निकाला गया कि, मुख्य न्यायाधीश की सलाह प्रभावकारिता को लूटा जाएगा, इसके सामने

भारत की, इसकी वास्तविक

ऐसी पूर्व-प्राप्त सहमति, और इस पर विचार करना होगा

के रूप में दुर्भावनापूर्ण और एक संपार्श्विक उद्देश्य के लिए जारी किया गया है, अर्थात्, अनुच्छेद 222 (1) को दरकिनार करने और प्रमुख का सामना करने के लिए

भारत का न्याय, एक उचित परिपूर्ति के साथ, और इस तरह, एक ही

अवैध और असंवैधानिक घोषित किए जाने योग्य था

(पैरा 655)। (xii) उपरोक्त परिपत्र दिनांक 18.3.1981 भी आयोजित किया गया था।

अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के लिए, क्योंकि अभेद्य भेदभाव था

वृत्ताकार पत्र के चेहरे पर बड़ा लिखें। इसके लिए अतिरिक्त

660) . (xiii) एस. एन. कुमार, जे. की गैर-निरंतरता के विषय पर, यह

आयोजित किया गया था, कि यह पत्राचार से प्रचुर मात्रा में स्पष्ट था

और टिप्पणियाँ, जो आगे विवरण और ठोस तथ्य और

उनकी सत्यनिष्ठा से संबंधित सामग्री, हालांकि विशेष रूप से मांगी गई थी
न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था, और पत्र

भारत के मुख्य

दिनांक 7.5.1981, जिसमें इस तरह के विवरण और ठोस विवरण शामिल थे
सामग्रियों को उससे दूर रखा गया, जिससे

तथ्यों और

निष्कर्ष, वे तथ्य जिन्हें केंद्रीय कानून मंत्री और दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ध्यान में रखा
गया था

एस. एन. कुमार, जे.) की नियुक्ति का विस्तार नहीं किया गया था।
समक्ष रखा गया, और इसलिए, वहाँ

भारत के मुख्य न्यायाधीश के

अनुच्छेद द्वारा अपेक्षित राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश के बीच न तो पूर्ण और न ही प्रभावी
परामर्श था।

217 (1) . तदनुसार यह निष्कर्ष निकाला गया कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं के खिलाफ निर्णय-ऑन-
रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

एस. एन. कुमार, जे., कानूनी दुर्भावना से दूषित थे, और इस तरह,

शून्य और अवैध ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी था, और उसके मामले को होना था

आवश्यक परामर्श के बाद पुनर्विचार और उचित आदेश पारित करने के लिए राष्ट्रपति को वापस भेज दिया
गया।

नए सिरे से शुरू किया गया (पैराग्राफ 664 और 666 से 668)। (xiv) के. बी. एन. सिंह के स्थानांतरण की वैधता के संबंध में,

सीजे।, यह महसूस किया गया था कि किसी भी मिलीभगत के अभाव में या जटिलता, क्योंकि प्रक्रिया में कोई अनुचित खेल शामिल नहीं था

भारत के मुख्य न्यायाधीश के बाद, यह उत्तरदायी था

निष्कर्ष निकाला कि विवादित स्थानांतरण सार्वजनिक रूप से किया गया था

व्याज, और सजा के रूप में नहीं। उपरोक्त स्थानांतरण

तदनुसार वैध माना गया था (अनुच्छेद 680)।

डी. ए. देसाई, जे. :

(i) यह ध्यान में रखने के बाद कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 के तहत कार्य करता है

मंत्रिपरिषद की सलाह, और वह, कार्य करते समय

अनुच्छेद 217 (3) के तहत राष्ट्रपति गंभीर महत्व के कार्य करता है। यह महसूस किया गया कि यह नहीं कहा जा सकता है कि जबकि

उच्चतर न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति का प्रयोग करना

न्यायपालिका, राष्ट्रपति या तो न्यायिक या अर्ध कार्य कर रहे थे न्यायिक कार्य। न्यायाधीशों की नियुक्ति का कार्य था

एक कार्यकारी कार्य के रूप में घोषित किया गया, और इस तरह, यह आयोजित किया गया था, कि अनुच्छेद 74 लागू होगा। और इसलिए

निष्कर्ष निकाला कि राष्ट्रपति को सलाह पर कार्य करना होगा मंत्री परिषद की नियुक्ति के मामले में

अनुच्छेद 217 (अनुच्छेद 715) के तहत न्यायाधीश। और इसलिए यह

अभिनिर्धारित किया गया कि नियुक्ति की अंतिम शक्ति

अनुच्छेद 217, "निर्विवाद रूप से" राष्ट्रपति के पास था।

((ii) यह इंगित किया गया था कि शक्ति का प्रयोग करने से पहले

न्यायाधीश की नियुक्ति (उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा)

न्यायालय), राष्ट्रपति एक संवैधानिक दायित्व के तहत था,

अनुच्छेद 217 (अनुच्छेद 718 और 719) में उल्लिखित तीन संवैधानिक अधिकारियों से परामर्श करें। और यह कि

उपरोक्त तीन संवैधानिक पदाधिकारी [2015] 13 एस. सी. आर. के बराबर थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक-दूसरे के साथ। वे समन्वित अधिकारी थे, बिना

कोई भी सापेक्ष पदानुक्रम, और इस तरह, प्रमुख की राय

भारत के न्याय को इस मुद्दे पर प्रधानता नहीं दी जा सकी

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति (पैराग्राफ 724,726) और 728)।

(iii) यह भी निष्कर्ष निकाला गया था कि मूल की समाप्ति पर अनुच्छेद 224 के तहत एक अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति की अवधि,

संबंधित न्यायाधीश की निरंतरता, अनुच्छेद 217 में निहित प्रक्रिया को फिर से अपनाने की परिकल्पना करेगी।

(पैराग्राफ 736 और 745)। (iv) यह महसूस किया गया कि कोई लाभ नहीं है, कि एक अभ्यास

जिसका 25 वर्षों से अधिक समय से पालन किया जा रहा था, अर्थात्

अतिरिक्त न्यायाधीश पर हमेशा नए कार्यकाल के लिए विचार किया जाता था, यदि

कोई स्थायी रिक्ति नहीं थी, और यदि ऐसा था

रिक्ति, उन्हें स्थायी के रूप में नियुक्ति के लिए माना गया था

न्यायाधीश। यह अभिनिर्धारित किया गया कि एटोमी जनरल का तर्क है कि ऐसे अतिरिक्त न्यायाधीश की कोई प्राथमिकता, वरीयता नहीं है,

महत्व या विचार किए जाने का अधिकार, और वह बराबर था किसी अन्य व्यक्ति के साथ, जिसे बाजार से लाया जा सकता था,

संवैधानिक योजना की अवहेलना के बराबर होगा, और

अस्वीकार किया जाना चाहिए (अनुच्छेद 759)। यह माना गया था कि जब ए

न्यायाधीश को दो साल की अवधि के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।

न्यायाधीश, यह विचार करने के लिए पर्याप्त था, कि उनकी नियुक्ति

स्थायी न्यायाधीश के रूप में नहीं था। और इसलिए, यदि एक स्थायी रिक्ति उत्पन्न हुई, तो अतिरिक्त न्यायाधीश अपने पद को लागू नहीं कर सके।

तीन महीने या छह महीने के लिए बढ़ाया नहीं जा सका, क्योंकि ऐसी अल्पकालिक नियुक्तियाँ पूरी तरह से असंगत थीं और

अनुच्छेद 224 के स्पष्ट इरादे के विपरीत, और
अनुपयुक्त (अनुच्छेद 763 और 764)।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की गरिमा के

(vi) एक अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के कार्यकाल के विस्तार के विषय पर

अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

न्यायाधीश, यह महसूस किया गया कि यह संवैधानिक के लिए खुला नहीं था

पदाधिकारी, बिना व्यक्त किए, एक प्रस्ताव पर कसकर बैठने के लिए

प्रस्ताव के गुणों पर उनकी राय, और सरासर

निष्क्रियता, एक प्रस्ताव को मारना। तदनुसार यह राय दी गई थी कि जब

एक अतिरिक्त न्यायाधीश का कार्यकाल समाप्त होने वाला था, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए यह अनिवार्य था कि वे

परामर्श की प्रक्रिया को पूरा करने का प्रस्ताव, इससे पहले

प्रारंभिक नियुक्ति की अवधि समाप्त हो गई (पैराग्राफ 772)।

(vii) एस. एन. के कार्यकाल के गैर-विस्तार के संदर्भ में।

कुमार, जे., यह महसूस किया गया कि जब दो उच्च संवैधानिक

पदाधिकारी, अर्थात् दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

और भारत के मुख्य न्यायाधीश, एक विशिष्ट संदर्भ के साथ मिले थे

उनकी संदिग्ध ईमानदारी के लिए, दिनांकित पत्र नहीं दिखाने का कार्य

7.5.1981 भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए, से विचलित नहीं होगा

अनुच्छेद 217 द्वारा आवश्यकतानुसार परामर्श की पूर्णता। तदनुसार, यह माना गया था कि एक पूर्ण और प्रभावी था

सभी प्रासंगिक बिंदुओं पर परामर्श, जिसमें वे भी शामिल हैं

7.5.1981 दिनांकित पत्र। और संबंधित न्यायाधीश का दावा जाने योग्य था। हालांकि यह था

जारी रखने के लिए, अस्वीकार किए

सुझाव दिया, कि भारत सरकार अब भी, दिखा सकती है
7.5.1981 दिनांकित पत्र, और

भारत के मुख्य न्यायाधीश को

उनसे अपनी टिप्पणी देने का अनुरोध करें। उसे प्राप्त करने के बाद
नए सिरे से निर्णय ले सकती है,

टिप्पणियाँ, भारत सरकार

क्या एस. एन. कुमार, जे., को फिर से नियुक्त किया जाना चाहिए

दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश। हालांकि यह था

स्पष्ट किया कि प्रस्तावित पुनर्विचार नहीं किया जाना चाहिए

एक दिशा के रूप में माना जाता है, लेकिन केवल एक सुझाव के रूप में।

(viii) इस प्रश्न पर कि क्या संबंधित की सहमति है।

अनुच्छेद के तहत न्यायाधीश को उसके स्थानांतरण से पहले प्राप्त किया जाना चाहिए।

222 (1), यह निष्कर्ष निकाला गया था कि एक की मांग की आवश्यकता

की शक्ति का प्रयोग करने के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में पूर्व सहमति

अनुच्छेद 222 (1) के तहत स्थानांतरण, अस्वीकार किए जाने के योग्य
यह देखा गया कि उपरोक्त

(पैरा 813)। हालांकि

अनुच्छेद 222 (1) के तहत हस्तांतरण की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सका [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जनहित के अभाव में, केवल सनक के आधार पर,
मोड़ने की उसकी इच्छा

कार्यपालिका की सनक या कल्पना, या न्यायाधीश को

अपने सोचने के तरीके से। तीन सुरक्षा उपाय, अर्थात् पूर्ण और

भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ प्रभावी परामर्श,

केवल लोक हित और न्यायिक उद्देश्यों के लिए शक्ति का प्रयोग
इसके विपरीत किया गया था

समीक्षा-यदि शक्ति का प्रयोग

कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित करने के प्रयास के खिलाफ, "न्यायपालिका की स्वतंत्रता" को संरक्षित करने के
लिए कानून के जनादेश का सुझाव दिया गया था।

यह (पैराग्राफ 813 से 815)।
स्थानांतरण

(ix) यह भी निष्कर्ष निकाला गया था कि किसी व्यक्ति का

न्याय करो, उसके व्यवहार या आचरण में कुछ अनुचित के लिए, निश्चित रूप से एक अपशब्द डालेंगे या एक कलंक संलग्न करेंगे, और छोड़ देंगे

उनके चरित्र पर एक अमिट छाप। यहाँ तक कि उच्च न्यायालय ने भी

जिसे उनका स्थानांतरण किया गया था, वे उनसे दूर रहेंगे और उपभोक्ता

न्याय की अपनी न्यायिक अखंडता में बहुत कम या कोई विश्वास नहीं होगा। तदनुसार यह निष्कर्ष निकाला गया कि के कारण एक हस्तांतरण

किसी न्यायाधीश के खिलाफ कोई शिकायत या शिकायत, जो उसके लिए संदर्भित हो। आचरण या व्यवहार, अनुच्छेद 222 (1) के तहत अनुज्ञेय था।

(x) के. बी. एन. सिंह, सी. जे. के स्थानांतरण के प्रश्न पर।, महसूस किया था, कि उनके स्थानांतरण के आदेश को प्रभावी नहीं होने के कारण दूषित कर दिया गया था

परामर्श, और उसका चयनात्मक स्थानांतरण एक कलंक डाल देगा या उस पर कलंक। यह महसूस किया गया कि स्थानांतरण प्रतीत नहीं हुआ

जनहित में रहें। हस्तांतरण का आदेश दिनांक 20.12.1980

तदनुसार, दूषित माना जाता था, और इस तरह, था

शून्य घोषित किया गया।

आर. एस. पाठक, जे. (जैसा कि वे तब थे):

(i) "न्यायपालिका की स्वतंत्रता" के मुद्दे के संदर्भ में,

यह देखा गया कि जबकि न्याय का प्रशासन आकर्षित करता है संविधान से इसकी कानूनी मंजूरी, इसकी विश्वसनीयता में निहित थी

लोगों का विश्वास। इस तरह के विश्वास के लिए अपरिहार्य था

"न्यायपालिका की स्वतंत्रता"। स्वतंत्र और निष्पक्ष

न्यायपालिका, यह महसूस किया गया था, चरित्र और सामग्री देता है

संवैधानिक परिवेश (अनुच्छेद 874)।

सर्वोच्च न्यायालय

अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

(ii) उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय पर, यह

राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल से परामर्श करना आवश्यक था

प्रक्रिया, और प्रत्येक की एक अलग भूमिका थी (पैराग्राफ 887)।
के मुख्य न्यायाधीश और

ऐसे मामले में जहां उच्च न्यायालय

भारत के मुख्य न्यायाधीश, एक सिफारिश पर सहमत हुए, यह

यह अभिनिर्धारित करने के कारण था कि राष्ट्रपति सामान्य रूप से

सिफारिश को स्वीकार करें, जब तक कि मजबूत न हो और

ऐसा न करने के ठोस कारण (पैराग्राफ 889)। यह था।

हालाँकि, यह बताया गया कि राष्ट्रपति हमेशा एक सिफारिश के साथ सहमत होने के लिए बाध्य नहीं थे, जिसमें मुख्य न्यायाधीश

उच्च न्यायालय और भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सहमति व्यक्त की थी।

इस संबंध में यह देखा गया कि यद्यपि इस दौरान संविधान सभा बहस करती है, एक प्रस्ताव बनाया गया था, कि एक न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए "सहमति" की आवश्यकता होनी चाहिए

भारत के मुख्य न्यायाधीश और उपरोक्त प्रस्ताव था

संविधान के माध्यम से गिर गया था, और इस तरह, जैसा कि वर्तमान में "परामर्श" और "सहमति" नहीं

मौजूद है, विचारित

(पैरा 890)।

((iii) इस प्रश्न पर कि क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश

प्रमुख द्वारा की गई सिफारिश पर प्रधानता थी

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने यह महसूस किया कि

भारत ने दी गई सलाह पर अपीलीय निर्णय नहीं दिया

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। यह बताया गया था कि

भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी गई सलाह सामने आई

ध्यान में रखने के बाद, न केवल प्राथमिक सामग्री से पहले

उसे, लेकिन यह भी, मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया गया मूल्यांकन

उच्च न्यायालय। और इसलिए, जब उन्होंने अपनी सलाह दी,

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मूल्यांकन पर उनके द्वारा विचार किया गया माना जाना चाहिए। यह इंगित किया गया था

बाहर, कि संवैधानिक योजना से, यह प्रतीत होता है कि [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1

टी

उच्च न्यायालयों से संबंधित मामले, वहाँ एक बंद था

राष्ट्रपति और प्रमुख के बीच परामर्श संबंध भारत का न्याय। उस क्षमता में, भारत के मुख्य न्यायाधीश

के अभ्यास पर, एक संवैधानिक जाँच के रूप में कार्य किया

मनमानी शक्ति, और स्वतंत्रता का रक्षक था न्यायपालिका का "(अनुच्छेद 891)।

(iv) उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय पर, यह निष्कर्ष निकाला गया कि एक अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति,

स्थायी न्यायाधीश की नियुक्ति की तरह, में किया जाना चाहिए

अनुच्छेद 217 (1) में विहित तरीका। तदनुसार, यह था

महसूस किया, कि संदेह करने का कोई कारण नहीं था, कि एक व्यक्ति ने पाया

अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त, और पहले से ही था

प्रवीणता और अनुभव प्राप्त किया, नियुक्त नहीं किया जाएगा

एक और अवधि के लिए एक न्यायाधीश के रूप में, ताकि काम हो सकता है निपटाया गया (अनुच्छेद 893)।

(v) यह भी राय दी गई थी कि न्यायपालिका न्यायिक निर्णय द्वारा, कर सकती है

उच्च न्यायालय। और यदि कोई न्यायालय ऐसा करने के लिए सक्षम नहीं था, तो वह सरकार को कोई निर्देश जारी नहीं कर सका, कि अतिरिक्त

न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए (अनुच्छेद

895)। तदनुसार यह महसूस किया गया कि इसमें कोई संदेह नहीं था,

कि अनुच्छेद 217 (1) का प्रावधान लागू होगा, जब

एक अतिरिक्त न्यायाधीश पर आगे के लिए विचार किया जाना था

अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति, या विचार किया जाना था

स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए (अनुच्छेद 897)।

(vi) एस. एन. कुमार, जे. की गैर-निरंतरता के संदर्भ में, यह इंगित किया गया था कि आरोप पत्र में निहित हैं। दिनांक 7.5.1981 ने सरकार के निर्णय को दृढ़ता से प्रभावित किया। चूंकि उपरोक्त पत्र को नहीं लाया गया था

भारत के मुख्य न्यायाधीश की सूचना, यह निष्कर्ष निकालना अपरिहार्य था,

कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श की प्रक्रिया

पूर्ण और प्रभावी नहीं था, और महत्वपूर्ण को रोकना और

भारत के मुख्य न्यायाधीश की प्रासंगिक सामग्री ने सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं-ऑन-रिकॉर्ड को दूषित कर दिया

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

प्रक्रिया। तदनुसार यह अभिनिर्धारित किया गया कि गैर-निरंतरता

एस. एन. कुमार, जे., का कार्यकाल अनिवार्य का उल्लंघन था

अनुच्छेद 217 (1) में निहित संवैधानिक आवश्यकताएँ। यह था।

यह महसूस किया गया कि एस. एन. कुमार की निरंतरता से संबंधित मुद्दा,

जे., पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, और एक निर्णय की आवश्यकता है

पूर्ण और प्रभावी परामर्श के बाद ही लिया गया (पैराग्राफ 904)।

यह निष्कर्ष निकाला गया कि संबंधित न्यायाधीश की सहमति अनिवार्य आवश्यकताओं में से एक नहीं थी (पैराग्राफ 913)। यह इंगित किया गया था कि एक न्यायाधीश का स्थानांतरण किया जा सकता है

केवल जनहित में, और यह कि किसी भी न्यायाधीश का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है,

दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर। सवाल यह कि

न्यायाधीश को दंडित करने के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 222 (1) का उपयोग करना,

स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया था (पैराग्राफ 917 और 918)। यह स्पष्ट किया गया था,

कि न्यायाधीश ने स्थानांतरण का प्रस्ताव रखा था, उसे कोई अधिकार नहीं था

सुनने के लिए। और वह, द्वारा जांच का दायरा और डिग्री

स्थानांतरण प्रस्तावित किया गया था, ताकि वह परिचित हो सके भारत के मुख्य न्यायाधीश, उनका इस तरह से स्थानांतरण क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

यह आगे स्पष्ट किया गया कि परामर्श की प्रक्रिया

अनुच्छेद 222 (1) के तहत परिकल्पित, आवश्यक है कि सभी सामग्री

राष्ट्रपति के अधिकार में भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाना चाहिए (पैराग्राफ 919)।
(viii) यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यह न्यायाधीश के लिए खुला था, जो था

स्थानांतरण के अधीन, न्यायिक समीक्षा प्राप्त करने के लिए, इस आधार पर उनके स्थानांतरण का विरोध करते हुए कि यह अनुच्छेद 222 (1) (पैराग्राफ) का उल्लंघन करता है।

920)। (ix) यह भी महसूस किया गया कि किसी न्यायाधीश को किसी एक से स्थानांतरित करने की शक्ति

उच्च न्यायालय दूसरे के लिए, इस अर्थ में एक खतरा हो सकता है कि

न्यायाधीश की स्वतंत्रता और निष्पक्षता, और तदनुसार,

यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उक्त शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए, और केवल बहुत मजबूत कारणों से (पैराग्राफ 921)।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

(x) के. वी. एन. सिंह, मुख्य न्यायाधीश के स्थानांतरण की वैधता पर।, यह था

निष्कर्ष निकाला कि जिन विचारों पर हस्तांतरण किया गया था "सार्वजनिक हित" अभिव्यक्ति के अंतर्गत आने के रूप में माना जा सकता है, और इसलिए, हस्तांतरण का आदेश नहीं था

यह अनुच्छेद 222 (1) का उल्लंघन करता है।

(xi) जहां तक केंद्रीय कानून मंत्री के पत्र की वैधता का संबंध है

दिनांक 18.3.1981 का संबंध है, यह देखा गया कि न तो

प्रस्ताव और न ही उस पर दी गई सहमति का कोई कानूनी दर्जा था।

उपरोक्त दृष्टिकोण में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि परिपत्र पत्र ऐसा नहीं कर सकता था

उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसके अनुसार दी गई कोई भी सहमति, बाध्यकारी नहीं।

(i) "न्यायपालिका की स्वतंत्रता" के संदर्भ में, यह था राय दी, कि वही केंद्रीय मूल्यों में से एक था जिस पर

संविधान आधारित था। यह इंगित किया गया था कि कुल मिलाकर

देश, जहाँ कानून का शासन प्रबल था, और शक्ति

एक आदमी और एक आदमी के बीच विवादों पर निर्णय लेना, और एक व्यक्ति और राज्य, और एक राज्य और दूसरा राज्य, और एक राज्य

और केंद्र, एक न्यायिक निकाय को सौंपा गया था, यह स्वाभाविक था

कि ऐसे निकाय को मनमौजी से मुक्त दर्जा दिया जाना चाहिए

या बाहर से सनकी हस्तक्षेप, ताकि यह कार्य कर सके,

भय के बिना और न्यायिक विवेक के अनुरूप

(पैरा 1068)।

(ii) अनुच्छेद 217 (1) का उल्लेख करते हुए यह दावा किया गया था कि प्रत्येक

उसमें उल्लिखित तीन अधिकारियों से परामर्श करना पड़ा

इससे पहले कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सके। यह था।

इंगित किया कि प्रत्येक वाणिज्य दूत के पास एक अलग और खेलने के लिए अलग भूमिका। उन्हें सौंपी गई विशिष्ट भूमिकाओं को देखते हुए,

जो कुछ हद तक अतिव्यापी हो सकता है, यह नहीं कहा जा सकता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने प्रधानता का पद संभाला था,

तीन वाणिज्य दूतों के बीच (पैराग्राफ 1019)।

(iii) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की शक्ति को एक कार्यकारी शक्ति माना जाता था (पैराग्राफ 1023)।

सर्वोच्च अदालतें-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

तदनुसार, उच्च न्यायालय की नियुक्ति करते समय न्यायाधीश, राष्ट्रपति अपनी सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य था

मंत्रिपरिषद, और साथ ही, उचित सम्मान देना

उन लोगों द्वारा व्यक्त की गई राय के लिए जिन्हें होना आवश्यक था

अनुच्छेद 217 (1) के तहत परामर्श लिया गया। उपरोक्त के बावजूद, यह महसूस किया गया,

कि धारण करने की कोई गुंजाइश नहीं थी, कि या तो परिषद

मंत्री राष्ट्रपति को सलाह नहीं दे सकते थे, या उनकी राय नहीं ले सकते थे।

भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी थे। हालांकि,

यह महसूस किया गया कि इस तरह की राय को उचित सम्मान और सम्मान दिया जाना चाहिए (पैरा 1032)। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उपरोक्त विधि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में आंतरिक था, क्योंकि इस तरह न्यायाधीशों को लोगों का न्यायाधीश कहा जा सकता है। अगर

न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ इन आधार पर की जानी थीं - न्यायाधीशों की सिफारिशें, तभी वे न्यायाधीश होंगे '

न्यायाधीश, और ऐसी नियुक्तियाँ इस योजना में फिट नहीं हो सकती हैं -

लोकप्रिय लोकतंत्र (पैराग्राफ 1042)।

(iv) यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संविधान में अलग-अलग प्रावधान नहीं हैं।

स्थायी न्यायाधीशों के लिए नियुक्ति के तरीके, अतिरिक्त

अनुच्छेद 217 (1) (पैराग्राफ 1061) के तहत विचार किया गया। द. शुरू में लगभग सभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति

अनुच्छेद 224 (1) के तहत अतिरिक्त न्यायाधीश, और बाद में अनुच्छेद 217 (1) के तहत स्थायी न्यायाधीश, के लिए अनुकूल नहीं थे

न्यायपालिका की स्वतंत्रता (पैराग्राफ 1067)। आयोजित किया गया था,

कि संविधान ने किसी अतिरिक्त अधिकार को प्रदान नहीं किया है न्यायाधीश, अधिकार के रूप में दावा करने के लिए कि उसे फिर से नियुक्त किया जाना चाहिए,

या तो स्थायी न्यायाधीश के रूप में, या एक अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में।

सही (पैराग्राफ 1074)। (v) उपरोक्त के बावजूद, यह देखा गया कि

अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करने के ठोस कारण, उनके स्थान पर किसी और की नियुक्ति एक होगी

अनुचित और एक विकृत कार्य, जो [2015] 13 एस. सी. आर. का हकदार होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अतिरिक्त न्यायाधीश, उचित राहत के लिए न्यायालय का रुख करने के लिए,

ऐसी कोई नियुक्ति करने से पहले परामर्श किया गया था, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुप्रयोग को, अधिकार के रूप में, खारिज कर दिया गया था (पैराग्राफ 1087)।

(vi) अनुच्छेद 222 के संदर्भ में, यह राय दी गई थी कि सहमति

न्यायाधीश के स्थानांतरण की पूर्व शर्त नहीं थी

हस्तांतरण का आदेश पारित करना (पैराग्राफ 1097 और 1099)। यह.

अभिनिर्धारित किया गया था कि उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का दूसरे न्यायाधीश को स्थानांतरण

उच्च न्यायालय, में एक नई नियुक्ति के रूप में नहीं माना जा सका

उच्च न्यायालय जिसमें न्यायाधीश का स्थानांतरण किया गया था। एक आदेश

अनुच्छेद 222 के तहत किए गए हस्तांतरण का, यह अभिनिर्धारित किया गया था, जिसके लिए उत्तरदायी था न्यायालय द्वारा निरस्त किया जाए, यदि यह दिखाया जा सकता है कि यह एक बाहरी कारण से बनाया गया था, अर्थात् जमीन पर गिरने के कारण।

अनुच्छेद 222 के दायरे से बाहर। अनुच्छेद 222 के तहत, एक न्यायाधीश

हस्तांतरण तब किया जा सकता है जब हस्तांतरण सार्वजनिक हित में हो।

यह अभिनिर्धारित किया गया था कि राष्ट्रपति के पास उच्च पद का हस्तांतरण करने की कोई शक्ति नहीं थी।

न्यायालय के न्यायाधीश, जनहित से संबंधित कारणों से नहीं, या

कार्यपालिका की सनक, सनक या कल्पना से उत्पन्न होना, या एक न्यायाधीश को अपने पक्ष में मोड़ने की कार्यपालिका की इच्छा के कारण

सोचने का तरीका (पैराग्राफ 1,097,1099 और 1132)।

(vii) यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अनुच्छेद 222 का सहारा नहीं लिया जा सकता है

न्यायाधीश के कथित दुर्व्यवहार या अक्षमता का आधार

(पैरा 1139)।

(viii) कई विशेषज्ञ निकायों द्वारा व्यक्त राय के आधार पर,

यह राय दी गई थी कि नियुक्ति की नीति को लागू करने के लिए अनुच्छेद 222 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कोई भी स्थानांतरण।

संबंधित राज्य के बाहर से प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और प्रत्येक उच्च न्यायालय के कम से कम एक तिहाई न्यायाधीश होने के लिए

राज्य के बाहर का न्यायालय असंवैधानिक नहीं होगा

(पैरा 1164)।

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

(ix) केंद्रीय विधि मंत्री का दिनांकित 18.3.1981 का पत्र,

वैध पाया गया। वैधता के खिलाफ उठाए गए सभी तर्क

उन्हें अस्वीकार कर दिया गया (पैराग्राफ 1239)।

(x) राष्ट्रपति का नया आदेश जारी नहीं करने का निर्णय
की समाप्ति पर नियुक्ति

एस. एन. कुमार, जे. को उनके कार्यकाल

दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश को न्यायोचित ठहराया गया

(पैरा 1128)।

(xi) के. बी. एन. सिंह, सी. जे. का स्थानांतरण। , माना जाता है कि

संकलचंद हिमतलाल सेठ मामलों में दर्शाई गई प्रक्रिया के अनुरूप सख्ती से बनाया गया। यह तदनुसार था

निष्कर्ष निकाला, कि धारण करने के लिए कोई आधार नहीं था, कि उपरोक्त

स्थानांतरण पर भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा विचार नहीं किया गया था

उचित और उचित तरीके से। तथ्यों और परिस्थितियों पर

मामले में, यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह मानना संभव नहीं था कि उपरोक्त हस्तांतरण या तो अवैध था
या अमान्य था (पैराग्राफ 1252)

और 1257)।

दूसरा न्यायाधीश मामला-(1993) 4 एस. सी. सी. 441:

17. वर्तमान मुद्दे के निर्णय के उद्देश्य से,

अर्थात्, क्या इस न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय

दूसरे न्यायाधीश के मामले की फिर से जांच करने की आवश्यकता है, व्यक्ति द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को
चित्रित करना आवश्यक नहीं है

न्यायाधीश, जैसा कि उनके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष अपने आप में नहीं हैं

चुनौती का विषय। सीमित चुनौती यह है कि

मामले के महत्वपूर्ण पहलू, जिनकी आवश्यकता थी

माना जाता है कि प्रचार नहीं किया गया था, और इसलिए, निर्णय लेने की प्रक्रिया में ध्यान में नहीं रखा जा
सकता था। में। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, हम इसे निकालना उचित और उचित मानते हैं।

इसके तहत, केवल बहुमत के दृष्टिकोण से निकाले गए निष्कर्ष हैं:

"(1) न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय एक एकीकृत न्यायालय हैं।

'सर्वश्रेष्ठ चयन के लिए 'सहभागी परामर्श प्रक्रिया'

और नियुक्ति के लिए उपलब्ध सबसे उपयुक्त व्यक्ति;
और सभी संवैधानिक अधिकारियों को यह [2015] 13 एस. सी. आर. करना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मुख्य रूप से एक सहमत तक पहुंचने के लिए एक दृष्टिकोण के साथ सामूहिक रूप से कर्तव्य
निर्णय, संवैधानिक उद्देश्य के अधीन, ताकि
प्रधानता का अवसर उत्पन्न नहीं होता है।

(2) मामले में नियुक्ति के प्रस्ताव की शुरुआत उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश द्वारा होना चाहिए

भारत, और मुख्य न्यायाधीश द्वारा उच्च न्यायालय के मामले में
उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश; और किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए /
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रस्ताव होना चाहिए
भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शुरू किया गया। यह है तरीका

जिसमें सर्वोच्च पद पर नियुक्तियों के लिए प्रस्ताव न्यायालय और उच्च न्यायालयों के साथ-साथ
स्थानान्तरण के लिए

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों/मुख्य न्यायाधीशों को अनिवार्य रूप से
बनाया जाए।

(3) संवैधानिक द्वारा परस्पर विरोधी राय की स्थिति में

पदाधिकारी, न्यायपालिका की राय 'का प्रतीक है भारत के मुख्य न्यायाधीश के दृष्टिकोण से, और
इंगित तरीके से गठित, इसकी प्रधानता है।

(4) उच्चतम न्यायालय में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं या कोई उच्च न्यायालय बनाया जा
सकता है, जब तक कि यह अनुरूप न हो।

भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय के साथ।

(5) अकेले असाधारण मामलों में, बताए गए मजबूत ठोस के लिए

भारत के मुख्य न्यायाधीश को बताए गए कारणों से यह संकेत मिलता है कि सिफारिशकर्ता इसके लिए उपयुक्त नहीं है नियुक्ति, उस नियुक्ति की सिफारिश की गई

भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया जा सकता है। हालांकि, अगर

भारत के और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश जो इस मामले में परामर्श किया गया है, की पुनरावृत्ति पर

भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश,

नियुक्ति एक स्वस्थ परंपरा के रूप में की जानी चाहिए।

(6) भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय में नियुक्ति

उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश होने चाहिए पद धारण करने के लिए उपयुक्त माना जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्डसमाज v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

(7) भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय मात्र नहीं है

प्रधानता, लेकिन स्थानांतरण के मामले में निर्धारक है

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों/मुख्य न्यायाधीशों का।

(8) स्थानांतरित न्यायाधीश/मुख्य न्यायाधीश की सहमति है

बाद के किसी भी हस्तांतरण के पहले के लिए आवश्यक नहीं है

एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय।

(9) की सिफारिश पर किया गया कोई भी हस्तांतरण

भारत के मुख्य न्यायाधीश को दंडात्मक नहीं माना जाना चाहिए, और इस तरह का स्थानांतरण किसी भी आधार पर न्यायोचित नहीं है।

(10) सभी नियुक्तियाँ और स्थानांतरण करने में, मानदंड

इंगित का पालन किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है प्रदान करें।

किसी को भी न्यायसंगत अधिकार

(11) केवल निर्दिष्ट आधारों पर सीमित न्यायिक समीक्षा है और

पहले नियुक्तियों के मामलों में उपलब्ध

स्थानांतरण।

(12) न्यायाधीश की प्रारंभिक नियुक्ति की जा सकती है

उसके अलावा उच्च न्यायालय जिसके लिए प्रस्ताव था
प्रारम्भ किया।

(13) न्यायाधीशों का निर्धारण-उच्च न्यायालयों में संख्या है
न्यायसंगत, लेकिन केवल हद तक और तरीके से
इंगित किया।

(14) एस. पी. गुप्ता बनाम में बहुमत की राय। भारत संघ

(1982) 2 एससीआर 365: ए. आई. आर. 1982 एस. सी. 149, जहाँ तक यह

की भूमिका की प्रधानता से संबंधित विपरीत दृष्टिकोण लेता है न्यायिक न्यायिकों के मामलों में भारत के
मुख्य न्यायाधीश

और स्थानान्तरण, और इन मामलों की न्याय्यता के रूप में

साथ ही न्यायाधीश-शक्ति के संबंध में, प्रशंसा नहीं करता है

हमारे लिए सही दृष्टिकोण होने के रूप में। प्रासंगिक संविधान के प्रावधान, संवैधानिक सहित

योजना का अब अर्थ लगाया जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए और

हमारे द्वारा यहाँ बताए गए तरीके से लागू किया गया।

तीसरा न्यायाधीश मामला-(1998) 7 एस. सी. सी. 739:

18. ठीक उन्हीं कारणों से जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर. में देखा गया है।

द्वितीय न्यायाधीशों के मामले के संदर्भ में, यह आवश्यक नहीं है तीसरे न्यायाधीशों में व्यक्त
सर्वसम्मत दृष्टिकोण पर ध्यान देना

मामला। भारत के लिए महान्यायवादी की रियायत, जैसे '

तीसरे न्यायाधीशों के अनुच्छेद 11 में स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया था

मामला, इस तथ्य को उजागर करने के लिए निकाला जाना चाहिए, कि तब

महान्यायवादी ने स्वीकार किया था कि द्वारा दर्ज की गई राय

दूसरे न्यायाधीशों के मामले में बहुमत स्वीकार कर लिया गया था

भारत संघ द्वारा और इस प्रकार, उस पर बाध्यकारी होगा।

पैराग्राफ 11 को तदनुसार यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया है:

" 11. हम शुरुआत में ही वकील के बयान दर्ज करते हैं।

सामान्य तौर पर कि (1) भारत संघ समीक्षा की मांग नहीं कर रहा है या दूसरे न्यायाधीशों में निर्णय पर पुनर्विचार

मामला (1993) 4 एस. सी. सी. 441 और यह कि (2) भारत संघ इस न्यायालय के उत्तरों को स्वीकार करें और उन्हें बाध्यकारी समझें

संदर्भ में दिए गए प्रश्न "।

19. इसी तरह यहाँ निकालने के लिए आवश्यक है, केवल तीसरे न्यायाधीशों में व्यक्त किए गए निष्कर्षों का अंतिम सारांश मामला, जो नीचे दिया गया है:

" 1. अभिव्यक्ति "के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श

भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 (1) में कहा गया है कि

के गठन में न्यायाधीशों की बहुलता के साथ परामर्श

भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय। एकमात्र, व्यक्तिगत

"उक्त अनुच्छेदों के अर्थ के भीतर परामर्श।

2. कनिष्ठ न्यायाधीशों का स्थानांतरण न्यायिक रूप से समीक्षा योग्य है

केवल इस हद तक: कि सिफारिश की गई है कि

भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इस संबंध में चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से ऐसा नहीं किया गया है

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और/या उनके विचार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनका स्थानांतरण किया गया है

प्रभावी होना और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जिसे हस्तांतरण किया जाना है, वह प्राप्त नहीं हुआ है।

3. भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक सिफारिश करनी चाहिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करना और सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं का स्थानांतरण करना-ऑन-रिकॉर्ड

समाज v. यू. ओ. आई. /जगदीश सिंह खेहर, जे. जे.

परामर्श से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या कनिष्ठ न्यायाधीश

सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ
अदालत। जहाँ तक उच्च न्यायालय में नियुक्ति की बात है
संबंधित, सिफारिश की जानी चाहिए
दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ परामर्श
सुप्रीम कोर्ट।

4. भारत के मुख्य न्यायाधीश को केवल कार्य करने का अधिकार नहीं है। उच्चतम न्यायालय के अन्य
न्यायाधीशों के साथ परामर्श के बिना, सामग्री के संबंध में उसकी व्यक्तिगत क्षमता और

नियुक्ति के लिए अनुशंसित न्यायाधीश की गैर-नियुक्ति के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई जानकारी।
5. मुख्य न्यायाधीश द्वारा परामर्श की आवश्यकता

भारत अपने उन सहयोगियों के साथ, जिनसे बात करने की संभावना है
संबंधित उच्च न्यायालय के मामलों के साथ संदर्भित नहीं है
केवल उन न्यायाधीशों के लिए जिनके अभिभावक के रूप में वह उच्च न्यायालय है
उच्च न्यायालय। यह उन न्यायाधीशों को बाहर नहीं करता है जिन्होंने कब्जा कर लिया है।
उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय स्थानांतरण।

6. "ठोस कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है

वरिष्ठता के क्रम से प्रस्थान के लिए औचित्य, में

पारित किए गए प्रत्येक वरिष्ठ न्यायाधीश का सम्मान। जो दर्ज किया जाना है वह इसका सकारात्मक कारण
है

7. परामर्श लिए गए न्यायाधीशों के विचार लिखित रूप में होने चाहिए और भारत सरकार को
सूचित किया जाना चाहिए

भारत के मुख्य न्यायाधीश अपने विचारों के साथ निर्धारित सीमा तक
इस राय के मुख्य भाग में।

8. भारत का मुख्य न्यायाधीश इसका पालन करने के लिए बाध्य है -

भारत सरकार।

9. भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई सिफारिशें

[2015] 13 एस. सी. आर. के मानदंडों और आवश्यकताओं का पालन किए बिना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वनों के रूप में परामर्श प्रक्रिया बाध्यकारी नहीं है

भारत सरकार "।

III. समीक्षा के लिए उत्तरदाताओं द्वारा प्रेरणा

दूसरे और तीसरे न्यायाधीशों के मामले:

20. यह विद्वान महान्यायवादी का तर्क था,

कि विद्वानों के हाथों आगे की गई प्रस्तुतियों में

इस न्यायालय द्वारा द्वितीय और द्वितीय में दिए गए निर्णयों पर
यह विद्वानों का तर्क था

तीसरा। न्यायाधीशों के मामले।

महान्यायवादी ने कहा कि उपरोक्त में निकाले गए निष्कर्ष

निर्णय, एक नई जांच के माध्यम से पुनर्विचार की आवश्यकता है,

यह निर्धारित करने के लिए कि क्या उसमें दर्ज निष्कर्ष, कर सकते हैं

में देखे गए संविधान के मूल प्रावधानों का सामना करना

संविधान सभा में बहस की पृष्ठभूमि।

21. तथ्यों को सच्चाई से दर्ज करने के लिए, यह था

इस बात पर जोर दिया कि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियाँ, नहीं कर सके
प्रचार किया जाए जैसा कि तीसरे में किया गया है

भारत संघ की ओर से

न्यायाधीशों के मामले में, संघ ने जानबूझकर बाध्यकारी के रूप में स्वीकार किया था

द्वितीय न्यायाधीशों के मामले में दिया गया निर्णय।

उपरोक्त के बावजूद, महान्यायवादी ने जोर देकर कहा कि भारत संघ को मांग करने से रोका नहीं जा सकता है

इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार दूसरे न्यायाधीशों का मामला। विद्वान
महान्यायवादी को उस पाठ्यक्रम से रोकने के लिए जिसे उन्होंने आगे बढ़ाने पर जोर दिया था, यह था

सुझाव दिया कि इस न्यायालय द्वारा दूसरे में निर्धारण

न्यायाधीशों का मामला भारत संघ के दावे पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा,

यदि संघ यह स्थापित कर सकता है कि संविधान की "मूल संरचना", अर्थात् "न्यायपालिका की स्वतंत्रता",
संविधान (99 वां संशोधन) द्वारा समझौता नहीं किया गया है

एकट करें। तत्काल सुझाव के बावजूद, महान्यायवादी

निवेदन किया, कि उसे स्थापित करने की अनुमति दी जाए, कि दृढ संकल्प

दूसरे न्यायाधीशों के मामले में नौ-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा प्रस्तुत, सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

कानून में टिकाऊ नहीं था। उनके आग्रह पर, हमने उन्हें अनुमति दी

अपनी प्रस्तुतियों को आगे बढ़ाने के लिए। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि

महान्यायवादी हमें यह समझाने में सफल रहे कि

कहा गया निर्णय प्रथम दृष्टया सही कानूनी /

संवैधानिक स्थिति, मामले की जांच करनी होगी

नौ या अधिक न्यायाधीशों की संख्या वाली संविधान पीठ द्वारा

इस न्यायालय का, केवल तभी जब हम अतिरिक्त रूप से चुनौती को बरकरार रखेंगे

विवादित संवैधानिक संशोधन के लिए, और नीचे हड़ताल

वही, जिसमें विफल रहने पर नई व्यवस्था पूर्ववर्ती प्रणाली की जगह ले लेगी।

22. सबसे पहले हमारा ध्यान अनुच्छेद की ओर खींचा गया

124 संविधान का, जैसा कि यह वर्तमान से पहले मौजूद था

संशोधन। यह प्रस्तुत किया गया था कि अनुच्छेद 124 में विचार किया गया था,

कि उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे

भारत सरकार और सात से अधिक अन्य न्यायाधीश (जब तक कि संसद ने कानून द्वारा एक बड़ी संख्या निर्धारित नहीं की हो)। यह था। प्रस्तुत किया, कि अनुच्छेद 124 के खंड (2) ने की शक्ति निहित की

राष्ट्रपति के साथ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 124 (2) के तहत प्रावधान में कहा गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ अनिवार्य "परामर्श"।

अनुच्छेद 124 के तहत विचार की गई नियुक्तियां भी आवश्यक हैं।

ऐसे अन्य न्यायाधीशों के साथ गैर-अनिवार्य "परामर्श"

आवश्यक है। तदनुसार यह प्रस्तुत किया गया था कि परामर्श तहत विचार किया गया

के हाथों अनुच्छेद 124 (2) के

राष्ट्रपति न केवल कॉलेजियम को शामिल करने के लिए काफी व्यापक थे

न्यायाधीशों का, इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के संदर्भ में

दूसरे न्यायाधीशों का मामला, लेकिन प्रत्येक न्यायाधीश पर

उच्चतम न्यायालय की ताकत, और इसके न्यायाधीश भी

राज्यों के उच्च न्यायालय, जैसा कि राष्ट्रपति चुन सकते हैं

परामर्श लें। यह प्रस्तुत किया गया था कि केवल एक सीमित भूमिका सौंपी गई थी

भारत के मुख्य न्यायाधीश को फैसले द्वारा बदल दिया गया था दूसरे न्यायाधीशों के मामले में, एक व्यापक निर्णय लिया गया

भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर. के कॉलेजियम के परामर्श से।

मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में अनुच्छेद 124 में व्यक्त किया गया भारत की व्याख्या "सहमति" के रूप में की गई थी। और

तदनुसार, राष्ट्रपति को बाध्य माना गया है,

भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उन्हें की गई सिफारिश और उनके न्यायाधीशों का कॉलेजियम। यह तर्क दिया गया था कि उपरोक्त

दृढ़ संकल्प, के सादे पढ़ने के लिए पूरी तरह से बाहरी था

अनुच्छेद 124 (अपने मूल प्रारूप में) में संलग्न भाषा। यह.

इस बात पर जोर दिया गया कि "सहमति" का कोई सवाल ही नहीं था, जैसा कि अनुच्छेद 124 ने केवल विचार किया था

"परामर्श"। यह तर्क दिया गया था कि उपरोक्त "परामर्श"

राष्ट्रपति पर भी अनिवार्य और बाध्यकारी बना दिया गया था

अनुच्छेद 124 को तैयार करने में लगी भाषा। यह प्रस्तुत किया गया था, कि एक बार प्रधानता भारत के मुख्य न्यायाधीश को दी जाती है (अर्थात्,

न्यायाधीशों का कॉलेजियम, दूसरे के तहत विचार किया गया और

तीसरे न्यायाधीशों के मामले), तब एक निहित बहिष्करण था

"", उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के साथ परामर्श,

और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के साथ भी, हालांकि,
राष्ट्रपति को सशक्त बनाने के लिए एक स्पष्ट प्रावधान था
अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद अपना मन बनाएँ
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, जैसा कि वह चाहे।

23. महान्यायवादी ने आगे तर्क दिया कि

द्वितीय न्यायाधीशों में अनुच्छेद 124 पर दी गई व्याख्या
मामला, एक बिल्कुल अस्थिर व्याख्या थी, विशेष रूप से
जब जाँच की जाती है, तो निम्नलिखित चित्रण के संदर्भ में। कि
भले ही उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश, एक नाम, जिसके लिए अकेले भारत के मुख्य
न्यायाधीश नहीं थे
सहमत, उक्त सिफारिशकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सका
एक न्यायाधीश। यह चित्रण, प्रस्तुत किया गया था, निरपेक्ष रखा गया था
एक व्यक्ति के हाथों में शक्ति-भारत के मुख्य न्यायाधीश।

सर्वोच्च अदालतें-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

24. विद्वान महान्यायवादी ने तब न्यायालय को आमंत्रित किया
अनुच्छेद 125 पर ध्यान दें, ताकि यह तर्क दिया जा सके कि देय वेतन
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को निर्धारित करना होगा
कानून द्वारा संसद, और जब तक ऐसा निर्धारण नहीं किया जाता,
न्यायाधीश को देय परिलब्धि ऐसी होगी जो दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट। यह प्रस्तुत किया गया था
कि
संसद को भी निर्धारित करने के लिए एक स्पष्ट भूमिका दी गई थी
न्यायाधीशों का वेतन, जो न्यायाधीशों की सेवा की शर्त है
उच्चतम न्यायालय से। उन्होंने अनुच्छेद 126 की ओर भी इशारा किया, जो मुख्य न्यायाधीश के
कार्यों का निर्वहन करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से एक की नियुक्ति पर विचार करता है

भारत, उनकी अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा, या जब भारत के मुख्य न्यायाधीश, अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ थे

कार्यालय। न्यायालय का ध्यान अनुच्छेद 127 की ओर भी आकर्षित किया गया था,

इंगित करें कि ऐसी स्थिति में जहां के उपलब्ध न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय, पीठ के कोरम को संतुष्ट नहीं कर सका,

एक विवाद पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक, भारत के मुख्य न्यायाधीश मामले की कार्यवाही जारी रख सकते हैं, जिसमें शामिल हैं

उसमें, उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश (जो इसके लिए योग्य था)

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति), ताकि

राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से कोरम तैयार करें। भारत से। यह प्रस्तुत किया गया था कि भारत के राष्ट्रपति की भूमिका

स्पष्ट रूप से न्याय के प्रशासन के साथ जुड़ा हुआ था,

राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करने की अनुमति देना,

'तदर्थ' आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में। संदर्भ

इसके बाद अनुच्छेद 128 में बनाया गया, जिसके तहत मुख्य न्यायाधीश

भारत को, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के साथ, सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, या एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता हो सकती है जिसके पास है

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया, और विधिवत योग्य था

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए, बैठना और

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करें। यह बताया गया था कि

यह एक और उदाहरण था, जहाँ राष्ट्रपति ने ध्यान दिया

उच्च न्यायपालिका के कामकाज में भूमिका पर विचार किया गया था

स्वयं संविधान द्वारा। इसके बाद अदालत का ध्यान आकर्षित किया गया

अनुच्छेद 130 के तहत, भले ही सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट का स्थान

उच्चतम न्यायालय दिल्ली में होना था, इसे किसी भी स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता था भारत में अन्य स्थान, यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ऐसा चाहा जाता है,

राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ। फिर भी, का चित्रण करते हुए

उच्च न्यायपालिका के कामकाज में राष्ट्रपति को सौंपी गई सक्रिय भूमिका। इसी तरह, न्यायालय का ध्यान आमंत्रित किया गया था कि

अनुच्छेद 133 और 134, में एक अपीलीय उपचार का प्रावधान

उच्चतम न्यायालय को क्रमशः दीवानी और आपराधिक मामले,

न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता के दायरे को बदलने के लिए इसे संसद के लिए खुला छोड़ देना। जहाँ तक अनुच्छेद 137 का संबंध है, यह इंगित किया गया था कि निर्णयों की समीक्षा की शक्ति या

उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या किसी भी नियम के प्रावधानों के अधीन था।

यह अनुच्छेद 145 के तहत किया जा सकता है। लेख के संदर्भ में

138, यह तर्क दिया गया था कि सर्वोच्च की अधिकारिता

न्यायालय, संघ सूची में आने वाले मामलों तक विस्तारित किया जा सकता है, जैसा कि संसद प्रदान करने का विकल्प चुन सकती है। इसी तरह का संदर्भ

अनुच्छेद 138 के खंड (2) में बनाया गया था, जिसमें आगे

अधिकारिता उच्चतम न्यायालय को सौंपी जा सकती है, जब

भारत सरकार और किसी भी राज्य द्वारा सहमत

सरकार, यदि संसद विधि द्वारा ऐसा प्रावधान करती है। के आधार पर

उपरोक्त, यह तर्क दिया गया था कि अनुच्छेद 138 एक और था

प्रावधान, जो एक सहभागी भूमिका का संकेत देता है संसद, उच्चतम न्यायालय की गतिविधियों में। इसी तरह,

इस न्यायालय का ध्यान अनुच्छेद 139 की ओर आकर्षित किया गया था, जिसके तहत

संसद, कानून द्वारा, निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है,

सीमांकित ढांचे के अलावा आदेश या रिट

अनुच्छेद 32 (2) के माध्यम से यह, विद्वान वकील के अनुसार

जनरल ने संसद की एक और सहभागी भूमिका का संकेत दिया

उच्चतम न्यायालय की गतिविधियों में। अनुच्छेद 140 की ओर इशारा करते हुए,

यह प्रस्तुत किया गया था कि संसद कानून द्वारा प्रदान कर सकती है
 उच्चतम न्यायालय की पूरक शक्तियाँ, इसके अलावा
 संविधान द्वारा निहित शक्तियाँ, जो प्रतीत हो सकती हैं -
 संसद आवश्यक या वांछनीय होगी, ताकि
 उच्चतम न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का अधिक प्रभावी ढंग से प्रयोग करे। यह
 प्रस्तुत किया गया था कि एक के बाद एक अनुच्छेद, जिसमें अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता शामिल
 हैं-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]
 140, एक सामूहिक और सहभागी भूमिका का संकेत दिया
 राष्ट्रपति और संसद, सर्वोच्च की गतिविधियों में
 अदालत। अनुच्छेद 142 (2) को पढ़ने के बाद, यह दावा किया गया था कि
 यहाँ तक कि किसी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने के विषय पर भी,
 और किसी दस्तावेज की खोज या उत्पादन, या स्वयं की किसी भी अवमानना की जांच या सजा,
 सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बनाए गए कानून के अधीन था
 संसद द्वारा। विद्वान महान्यायवादी ने भी संदर्भित किया
 अनुच्छेद 145, जिसके तहत, यह संसद के लिए खुला था
 आम तौर पर विनियमित करने के लिए संसद द्वारा बनाई गई कानून बनाना।
 उच्चतम न्यायालय का अभ्यास और प्रक्रिया। में
 अभ्यास और प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाएँ न्यायालय, राष्ट्रपति की मंजूरी
 से। यह प्रस्तुत किया गया था,
 कि प्रक्रिया जैसे प्राथमिक मुद्दों पर भी, संसद
 और/या राष्ट्रपति को संविधान द्वारा एक भूमिका सौंपी गई थी, न्यायिक क्षेत्र में सख्ती से
 गतिविधियों में। के संदर्भ में
 उच्चतम न्यायालय की गतिविधियों पर न्यायालय का ध्यान था

अनुच्छेद 146 का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें इन नियुक्तियों की परिकल्पना की गई है उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को होना था

भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा बनाया गया। यह बताया गया कि

अनुच्छेद 146 के तहत प्रदत्त अधिकार, के अधीन था राष्ट्रपति का अधिकार, भविष्य की आवश्यकता वाले नियम बनाने का

उच्चतम न्यायालय से जुड़े किसी भी कार्यालय में नियुक्तियाँ,

केवल संघ लोक सेवा के परामर्श से किया जाना है

आयोग। अधिकारियों की नियुक्ति का उपरोक्त अधिकार और

उच्चतम न्यायालय के सेवक भी स्पष्ट रूप से अधीन हैं

कानून बनाकर प्रावधान करने का संसद का अधिकार

उपरोक्त विषय पर। कानून के अभाव में,

भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित। द. मुख्य न्यायाधीश द्वारा बनाए गए नियम, अनुमोदन के अधीन हैं

राष्ट्रपति द्वारा, वेतन, भत्ते, छुट्टी के संदर्भ में

और पेंशन।

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

25. उच्च को की गई नियुक्तियों के संदर्भ में

न्यायालयों, न्यायालय का ध्यान अनुच्छेद 217 पर आमंत्रित किया गया था,

जिसके तहत, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त करने का अधिकार

राष्ट्रपति के पास निहित था। अकेले राष्ट्रपति थे,

के साथ "परामर्श" के बाद ऐसी नियुक्तियाँ करने के लिए अधिकृत

भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल और

संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अदालत का आकर्षित किया गया, जिसके तहत, शक्ति अनुच्छेद 221 की ओर भी ध्यान

न्यायाधीश को देय वेतन निर्धारित करने के लिए, होना था

संसद द्वारा अधिनियमित किए जाने वाले कानून द्वारा निर्धारित। जब तक कोई ऐसा कानून संसद, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा बनाया गया था वे ऐसे वेतनों के हकदार होंगे जो दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए थे। न्यायाधीशों को देय भत्ते उच्च न्यायालय, साथ ही, अनुपस्थिति की छुट्टी के संबंध में अधिकार और पेंशन को भी संसद के विवेक पर छोड़ दिया गया था कानून द्वारा निर्धारित। और इस तरह के निर्धारण तक, के न्यायाधीशों उच्च न्यायालय भत्ते और अधिकारों के हकदार थे, जैसा कि थे दूसरी अनुसूची में दर्शाया गया है। अदालत का ध्यान था अनुच्छेद 222 का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से "परामर्श" करने के बाद, न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करना। आमंत्रित कर रहे हैं पूर्वगामी में निर्दिष्ट प्रावधानों पर न्यायालय का ध्यान भाग 5, अध्याय 4 में निहित दो अनुच्छेद-संघ न्यायपालिका, और भाग VI, अध्याय V-में उच्च न्यायालय राज्यों, यह दावा किया गया था कि राष्ट्रपति की भूमिका, और यह भी, उच्च न्यायपालिका से संबंधित मुख्य पहलू। कार्यपालिका और विधायिका का बहिष्करण, व्यक्त तरीके से द्वितीय न्यायाधीशों के मामले के माध्यम से, नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की संख्या, साथ ही, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों का दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण, स्पष्ट रूप से था संविधान की भावना के खिलाफ।

26. यह प्रस्तुत किया गया था कि नियुक्ति की विधि

उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीश, "सभी" या "अंतिम सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड" नहीं थे

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सवाल उठेगा, एक के संदर्भ में न्यायाधीश, उच्चतर के न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति के बाद ही

न्यायपालिका। यह प्रस्तुत किया गया था कि इस न्यायालय ने बार-बार कहा था संविधान सभा में बहसों पर निर्भरता, ताकि संविधान निर्माताओं के इरादे को सामने लाना, संवैधानिक प्रावधानों का संदर्भ। इस संबंध में उन्होंने टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन बनाम पर निर्भरता कर्नाटक राज्य, पुनः 20027 का विशेष संदर्भ सं. 1 और एस. आर. चौधरी पर भी वी. पंजाब राज्य। अंतिम उद्धृत टिप्पणियों में निम्नलिखित टिप्पणियां निर्णय पर प्रकाश डाला गया:

"33. संवैधानिक प्रावधानों की आवश्यकता है

एक वस्तु-उन्मुख के साथ समझा और व्याख्या की गई दृष्टिकोण। संविधान का अर्थ इस प्रकार नहीं लगाया जाना चाहिए -

संकीर्ण और पांडित्यपूर्ण भावना। उपयोग किए गए शब्द हो सकते हैं

सामान्य रूप से लेकिन, उनका पूर्ण महत्व और सही अर्थ,

सही संदर्भ को ध्यान में रखते हुए सराहना की जानी चाहिए

जिनका उपयोग किया जाता है और उनका उद्देश्य क्या है

हासिल करने की कोशिश करें। संविधान सभा में बहस

इस निर्णय के पूर्व भाग में स्पष्ट रूप से संदर्भित

इंगित करें कि मंत्रिमंडल में एक गैर-सदस्य का समावेश

एक "विशेषाधिकार" माना जाता था जो केवल के लिए फैला हुआ था

छह महीने, जिसके दौरान सदस्य को मिलना चाहिए

निर्वाचित हुए, अन्यथा उनका मंत्री बनना बंद हो जाएगा। यह है।

एक स्थिर स्थिति जो संविधान में बहस करती है

एक की व्याख्या करने के लिए एक सहायता के रूप में सभा पर भरोसा किया जा सकता है

संवैधानिक प्रावधान क्योंकि यह कार्य है

के निर्माताओं के इरादे का पता लगाने के लिए अदालत संविधान। हमें याद रखना चाहिए कि एक संविधान है

न केवल गंभीर रूप में एक दस्तावेज, बल्कि प्रदर्शन करने वाली जनता की सरकार के लिए एक जीवंत ढांचा

(2002) 8 एससीसी 481 7 (2002) 8 एससीसी 237 8 (2001) 7 एससीसी 126 [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

काम करना अंतर्निहित लोकतांत्रिक भावना पर निर्भर करता है

इसका अक्षर और आत्मा में सम्मान किया जा रहा है। बहसों

स्पष्ट रूप से छह के लिए "केवल" बढ़ाने के "विशेषाधिकार" को इंगित करें महीनों "।

उन्होंने इसी उद्देश्य के लिए इंद्र साहनी बनाम का उल्लेख किया। संघ

भारत, और राय की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया

उसमें लिखा है:

"217. इसके अलावा, यह उपरोक्त कारणों से स्पष्ट है।

कि कार्यपालिका विभाजन या उप बनाते समय

वर्गीकरण ने विभिन्न विषयों पर अपने दिमाग को ठीक से लागू नहीं किया है।

विभाजन या उप-वर्गीकरण का बहुत ही उद्देश्य। उस में
(i) न केवल संवैधानिक रूप से अमान्य हो जाता है

विचार, पैरा 2

लेकिन मन के गैर-अनुप्रयोग की बुराई से भी पीड़ित है

और मनमानी।

XXX

XXX

XXX

772. अब हम संविधान सभा की बहसों की ओर रुख कर सकते हैं
अंतर्निहित मूल इरादे का पता लगाने की दृष्टि से

"नागरिकों का पिछड़ा वर्ग" शब्दों का उपयोग। जिसमें

सबसे पहले हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि हम इन्हें नहीं ले रहे हैं।

बहस या यहाँ तक कि डॉ. अम्बेडकर के भाषण भी

"पिछड़े" अभिव्यक्ति के अर्थ पर निर्णायक

कक्षाएँ "। हम इन बहसों को इस रूप में संदर्भित कर रहे हैं

संदर्भ प्रस्तुत करना जिसमें और उद्देश्य

जिसे प्राप्त करने के लिए यह वाक्यांश खंड (4) में रखा गया था। हम.
से अवगत हैं कि इन बहसों के दौरान जो कहा जाता है वह नहीं है

इस बात

न्यायालय पर निर्णायक या बाध्यकारी क्योंकि कई
विचार व्यक्त किए होंगे, सभी

सदस्यों ने कई

जो अंत में प्रावधान में परिलक्षित नहीं हो सकता है

अधिनियमित किया। इस पहलू पर डॉ. अम्बेडकर का भाषण।
हालाँकि, यह एक अलग पायदान पर खड़ा है। वह केवल नहीं था

प्रारूपण समिति के अध्यक्ष जिन्होंने इसे शामिल किया

अनुच्छेद 10 (3) के मसौदे में "पिछड़े" शब्द का प्रयोग किया गया था

92 पूरक (3) एस. सी. सी. 217 सर्वोच्च अदालतें-चालू-रिकॉर्ड

159

समाज v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

मूल मसौदा अनुच्छेद 10 (3) में नहीं था], वह ए था

वस्तुतः मसौदा लेख का संचालन। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि

जिसके लिए प्रारूपण समिति ने जोड़ा खंड में अभिव्यक्ति "पीछे की ओर"। इस स्थिति में।

हम यह समझने में विफल हैं कि कोई उनके भाषण बी को कैसे अनदेखा कर सकता है

उक्त के अर्थ का पता लगाने की कोशिश करते हुए

अभिव्यक्ति। कि संविधान सभा में बहस एक की व्याख्या के लिए एक सहायता के रूप में भरोसा
किया जा सकता है

संवैधानिक प्रावधान की एक श्रृंखला द्वारा वहन किया जाता है

एस.

इस न्यायालय के निर्णय। [मधु लिमये को पुनः आकाशवाणी में देखें।

1969 एससी 1014, गोलक नाथ बनाम। पंजाब राज्य, ए. आई. आर 1967

एस. सी. 1643 (सुब्बा राव, सी. जे.); सी. जे. सीकरी की राय
भारत संघ बनाम। एच. एस. डिल्लन (1971) 2 एससीसी 779 और
केशवानंद भारती (1973) 4 एस. सी. सी. में कई राय

डी.

225, जहाँ इन बहसों की प्रासंगिकता इंगित की गई है

बाहर, एक ही समय में जोरदार, जिस हृद तक और वह उद्देश्य जिसके लिए उन्हें संदर्भित किया
जा सकता है।/ तब से

अभिव्यक्ति "पिछड़े" या "पिछड़े वर्ग का
संविधान में नागरिकों को परिभाषित नहीं किया गया है, संदर्भ

ई.

इस तरह की बहस किसी भी तरह से सुनिश्चित करने के लिए अनुमत है,
उनके पीछे का संदर्भ, पृष्ठभूमि और उद्देश्य।

विशेष रूप से, जहां न्यायालय यह सुनिश्चित करना चाहता है कि 'मूल आशय' ऐसा संदर्भ
अपरिहार्य हो सकता है।

एन. सी. ई. को केशवानंद भारती बनाम पर भी रखा गया था। एफ ए 10 की स्थिति, और इस न्यायालय का
ध्यान निम्नलिखित पर आमंत्रित किया गया था:

"1088. इससे पहले कि मैं कार्यवाही का उल्लेख करूं संविधान सभा, मुझे पहले इस प्रश्न पर
विचार करना चाहिए

क्या संविधान सभा की बहस हो सकती है

जी.

महाराष्ट्र के महाधिवक्ता कहते हैं कि जब तक एच. एच. महाराजाधिराज माधव में इस न्यायालय
का निर्णय

राव जीवाजी राव सिंधिया बहादुर और अन्य बनाम। संघ का
73) 4 एससीसी 225

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत, (1971) 1 एस. सी. सी. 85-आमतौर पर प्रिवी के रूप में जाना जाता है
 पर्स मामला-बहस और कार्यवाही आयोजित नहीं की गई
 स्वीकार्य होना। फिर भी दोनों तरफ से सलाह
 उनका भरपूर संदर्भ दिया। से निपटने में
 सामान्य विधान की व्याख्या, व्यापक रूप से आयोजित दृष्टिकोण
 यह है कि बहसों को संदर्भित करने की अनुमति नहीं है
 निर्माण के लिए एक सहायता के रूप में, विभिन्न चरणों के माध्यम से
 जिसे मसौदा पारित किया गया था, उसमें प्रस्तावित संशोधन
 या तो इसके किसी भी हिस्से को जोड़ना या हटाना, इसका उद्देश्य
 जिसका प्रयास किया गया था और इसकी अस्वीकृति का कारण निर्माताओं के इरादे पर प्रकाश डाल सकता है
 या ट्राफ्ट्समैन। विधान सभाओं में भाषणों के बारे में कहा जाता है
 कोई मार्गदर्शक खर्च करने के लिए नहीं क्योंकि सदस्य जो बोलते हैं किसी विशेष प्रावधान या
 संशोधन के पक्ष या विपक्ष में
 इसका अर्थ लगाने के लिए सहायता के रूप में स्वीकार्य नहीं होगा प्रावधान। सदस्य ऐसे विचार
 बोलते और व्यक्त करते हैं जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं, और इसका कोई तरीका नहीं है
 यह पता लगाना कि जो लोग नहीं मानते हैं, उनके क्या विचार हैं बोलो। इसलिए इसका
 परिणाम प्राप्त करना कठिन है।
 एक बहस में विचार अंतिम परिणाम को छोड़कर कि ए
 विशेष प्रावधान या इसके संशोधन को अपनाया गया है। या अस्वीकार कर दिया गया, और
 किसी भी मामले में इनमें से किसी को भी नहीं देखा जा सकता है
 निर्माण के लिए एक सहायता के रूप में, सिवाय इसके कि विधायी
 यह पता लगाने के लिए प्रावधान के इतिहास का उल्लेख किया जा सकता है।
 शरारत को ठीक करने की मांग की गई या उद्देश्य जिसे यह अधिनियमित किया जाता है, यदि
 वे प्रासंगिक हैं। लेकिन त्रावणकोर में
 कोचीन और अन्य बनाम। बॉम्बे कंपनी लिमिटेड, आकाशवाणी 1952
 एस. सी. 366, गोलकनाथ मामला (ऊपर), प्रिवी पर्स

मामला (ऊपर), और भारत संघ बनाम। एच. एस. डिल्लन, (1971) 2 एस. सी. सी. 779, को संदर्भित करने के खिलाफ निर्देश हैं

संविधान सभा में और अंतिम में भाषण उल्लिखित मामले में उन्हें समर्थन के रूप में संदर्भित किया गया था

निष्कर्ष पहले ही आ चुका है। गोलकनाथ मामले (ऊपर) में, साथ ही प्रिवी पर्स मामले (ऊपर), भाषण सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता थे-ऑन-रिकॉर्ड

16

समाज v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

संदर्भित किया गया हालांकि यह ए की व्याख्या के लिए नहीं कहा गया था

प्रावधान लेकिन दिव्य की जांच करने के लिए

मौलिक अधिकारों का चरित्र या

ऐसी परिस्थितियाँ जो देने के लिए आवश्यक थीं शासकों को गारंटी। किसी भी उद्देश्य के लिए

संविधान सभा में भाषणों को भी पर देखा गया था

हालाँकि यह हमेशा दावा किया जाता था कि ये नहीं हैं

स्वीकार्य सिवाय तब जब अर्थ अस्पष्ट था या जहाँ आगे के समर्थन के लिए अर्थ स्पष्ट था

निष्कर्ष निकला। किसी भी मामले में उन्हें देखा गया

में प्रवेश करें। अपने लिए बोलते हुए, हमें इस पर गौर क्यों नहीं करना चाहिए

साहसपूर्वक यह पता लगाने के लिए कि उनका इरादा क्या था

हमारे फ्रेमर्स और उन्होंने उस इरादे का अनुवाद कैसे किया? क्या? क्या उन्हें वर्जित मानने का तर्क है या

निषिद्ध सामग्री। एक संवैधानिक मामले में न्यायालय।

ओ

जहाँ संविधान निर्माताओं का आशय

कोई भी भाषण शामिल है जो प्रकाश डाल सकता है रूप में अस्वीकार कर सकता है, अगर वे

इसका पता लगाना। यह उन्हें असहयोगी के

ई.

कोई रोशनी न डालें या केवल मंद रोशनी डालें जिसमें कुछ भी न हो।

पहचाना जा सकता है। एक क़ानून के विपरीत, एक संविधान एक है

सरकार का कार्य साधन, इसका मसौदा तैयार किया गया है जो लोग चाहते थे कि यह एक राष्ट्रीय साधन बने

एक के बाद एक आने वाली पीढ़ियों को सहारा दें। सभा एफ उच्च क्षमता के योग्य व्यक्तियों की समितियों का गठन,

सीखना और व्यापक अनुभव, और इसमें एक सक्षम सलाहकार था,

श्री बी. एन. राउ इसकी सहायता करेंगे। एक ज्ञापन तैयार किया गया था

श्री बी. एन. राउ द्वारा जो जनता के लिए प्रसारित किया गया था पेशेवर निकायों के लिए, जी के लिए, राय के हर रंग

व्यापक प्रचार किया गया। जब आलोचना होती है, टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त हुए, एक मसौदा था

इनके आलोक में तैयार किया गया जो प्रस्तुत किया गया था

संविधान सभा, और एक भाषण एच [2015] 13 एस. सी. आर. के साथ पेश किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तीन समितियों का गठन: (1) संघ शक्तियाँ समिति; (2) प्रांतीय शक्तियाँ समिति; और (3)

मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों पर समिति

समिति। विचार-विमर्श और इन समितियों की सिफारिशें -

प्रारूपण समिति की कार्यवाही और भाषण

डॉ. अम्बेडकर द्वारा इस प्रकार तैयार किए गए मसौदे को प्रस्तुत करना

इन समितियों की रिपोर्ट के साथ सभी मूल्यवान हैं

सामग्री। सभा के उद्देश्य, जिस तरह से

जिनका उन्हें किसी भी आलोचना का सामना करना पड़ा, परिणामी निर्णय उस पर लिया गया, प्रस्तावित संशोधन, भाषण

उनके पक्ष में या उनके खिलाफ और उनका अंतिम दत्तक ग्रहण या

अस्वीकृति विशेष पर प्रकाश डालने में सहायक होगी

विषय में। एक विधानमंडल की कार्यवाही में सामान्य मसौदा विधेयक, जैसा कि मैंने पहले कहा था, हो सकता है

पक्षपातपूर्ण और गरमागरम बहस, जो अक्सर उन मुद्दों पर कोई प्रकाश नहीं डालती है जो पहले आते हैं

न्यायालय लेकिन एक संविधान सभा में कार्यवाही

इस तरह की कोई पक्षपातपूर्ण बारीकियां नहीं हैं और उनकी एकमात्र चिंता है

राष्ट्रीय को इसके मूल के साथ एक कार्य साधन देना है

संरचना और मानवीय मूल्य पर्याप्त रूप से संतुलित और

बलों की परस्पर क्रिया की अनुमति देने के लिए पर्याप्त स्थिर जो आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करना। सबसे ऊँचा

इसके तहत बनाया गया और इसके कर्तव्य के लिए आरोपित न्यायालय

इसे समझना और व्याख्या करना नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो

निर्माताओं के उद्देश्यों को पकड़ें, खुद को लाभ से वंचित करें अभिलेखों से व्युत्पन्न मार्गदर्शन का

विधानसभा की कार्यवाही और विचार-विमर्श। बनो।

ताकि जैसा भी हो, मैं वर्तमान के लिए बस इतना ही करना चाहता हूँ

उन चरणों की जांच करें जिनके माध्यम से मसौदा पारित हुआ और

क्या और क्या पेश करने के प्रयास किए गए थे

शब्द या अभिव्यक्तियाँ या जो पहले से ही वहाँ थे और किस उद्देश्य के लिए थे उन्हें हटा दें।

यदि ये कार्यवाहियाँ सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

इस दृष्टिकोण से जांच की गई, क्या वे कोई प्रकाश डालते हैं मेरे द्वारा लिए गए दृष्टिकोण पर या उसका समर्थन करें?

इसी प्रस्ताव के लिए, निर्भरता भी रखी गई थी

समशेर सिंह बनाम। पंजाब राज्य ", और मनोज नरूला बनाम।

भारत संघ 12.

27. इस बात पर जोर देते हुए कि संविधान सभा

बहसों को समझने के साधन के रूप में अपनाया गया था
 संविधान के प्रावधानों का वास्तविक इरादा और महत्व,
 संविधान सभा को विस्तार से संदर्भित किया गया था
 वाद-विवाद, प्रावधानों के संदर्भ में (विशेष रूप से, अनुच्छेद 124) जो वर्तमान की विषय वस्तु हैं।
 विचार करें। यह इंगित किया गया था कि के संविधान के बाद
 संविधान सभा, न्यायिक नियुक्तियों का मुद्दा

और वेतन एक तदर्थ समिति द्वारा लिया गया था सुप्रीम कोर्ट। समिति में एस. वरदाचारियार शामिल थे।

(संघीय न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश), बी. एल. मित्र (एक पूर्व न्यायाधीश) संघीय न्यायालय के महाधिवक्ता), कुछ के अलावा

प्रसिद्ध न्यायविद-अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, के. एम. मुंशी और
 बी. एन. राउ (संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार)
 भारत से)। तदर्थ समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की
 21.5.1947 पर संविधान सभा। न्यायपालिका के संदर्भ में
 स्वतंत्रता, इसने सुझाए गए परामर्श प्रस्ताव को संशोधित किया
 सप्रू समिति की रिपोर्ट में, राष्ट्रपति द्वारा नामित 11 व्यक्तियों के पैनल की सिफारिश करके,
 भारत के मुख्य न्यायाधीश। वैकल्पिक रूप से, यह सुझाव दिया गया था कि
 पैनल तीन उम्मीदवारों की सिफारिश करेगा, और
 राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से,
 तीन में से एक चुनें। यह सुझाव दिया गया था कि पैनल
 दो तिहाई बहुमत से अपना निर्णय लें। स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए,
 यह सिफारिश की गई थी कि पैनल का कार्यकाल होना चाहिए
 दस साल। उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर, यह प्रस्तुत किया गया था कि प्रस्ताव में कॉलेजियम की
 व्यापक भागीदारी का सुझाव दिया गया

1 (1974) 2 एस. सी. सी. 831

12 (2014) 9 एस. सी. सी. 1 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

न्यायाधीशों, राजनेताओं और विधि अधिकारियों के अलावा

राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश, के मामले में

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति। विद्वान वकील

30.5.1947, जिसमें उन्होंने अपने स्वयं के सुझाव दिए। उपरोक्त से संबंधित सुझाव, और साथ ही,

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों

उच्च न्यायालयों से। न्यायालय को यह भी सूचित किया गया कि संघ

संविधान समिति ने संविधान को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की

4.7.1947 पर सभा, नियुक्तियों से भी संबंधित

उच्च न्यायपालिका। सिद्धांतों पर एक और ज्ञापन

द्वारा एक मॉडल प्रांतीय संविधान तैयार किया गया था

नियुक्तियों से संबंधित 13.5.1947 पर संवैधानिक सलाहकार

उच्च न्यायपालिका के लिए, जिसे प्रांतीय द्वारा अपनाया गया था

संविधान समिति। रिलायंस को वकील द्वारा रखा गया था

जनरल, सरदार वल्लभभाई पटेल के भाषण पर विचार व्यक्त किए:

15.7.1947 पर, जिसमें उन्होंने निम्नलिखित

"समिति ने विशेष ध्यान दिया है कि

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। यह है।

समिति द्वारा बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और

क्योंकि न्यायपालिका को संदेह से ऊपर होना चाहिए और होना चाहिए

पार्टी के प्रभाव से ऊपर होने पर, यह सहमति हुई कि

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जानी चाहिए

संघ के अध्यक्ष ने प्रमुख के परामर्श से

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, के मुख्य न्यायाधीश प्रांतीय उच्च न्यायालय और राज्यपाल सलाह के साथ

संबंधित प्रांत के मंत्रालय का। तो वहाँ हैं

उचित नियुक्तियाँ सुनिश्चित करने के लिए कई चेक प्रदान किए गए

उच्च न्यायालय। ”

न्यायालय को सूचित किया गया कि नए संविधान का पहला मसौदा

बी. एन. राउ द्वारा तैयार किया गया संविधान को प्रस्तुत किया गया था

अक्टूबर 1947 में विधानसभा, जिसमें यह व्यक्त किया गया था कि उच्चतम न्यायालय के
न्यायाधीशों की नियुक्ति द्वारा की जाएगी

राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं-ऑन-रिकॉर्ड के वर्तमान न्यायाधीशों के परामर्श से

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश की
नियुक्ति के मामले को छोड़कर भारत के न्यायाधीश

स्वयं भारत का न्याया। यह सुझाव दिया गया था कि यह था

संविधान के अनुच्छेद 124 (2) के तत्काल अग्रदूत, जैसा कि इसे मूल रूप से बनाया गया था।

28. यह बताया गया था कि उपरोक्त तैयार की गई रिपोर्ट में

संवैधानिक सलाहकार द्वारा, निम्नलिखित परिच्छेद संबंधित है -

न्यायपालिका:

“न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में, वह (न्यायमूर्ति)

फ्रैंकफर्टर, न्यायाधीश, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय

अमेरिका का) ने एक प्रावधान की ओर ध्यान आकर्षित किया जो सिर्फ था

न्यूयॉर्क राज्य में प्रस्तावित किया गया है-प्रावधान है
तब से स्वीकृत किया गया था और जिसे अधिकांश का समर्थन प्राप्त था

इस देश के न्यायाधीशों और वकीलों से। प्रावधान

9 - क. (1) अपील न्यायालय का न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, दावा न्यायालय का
न्यायाधीश।

न्यायाधीशों के) को अदालत द्वारा भी हटाया या सेवानिवृत्त किया जा सकता है

न्यायपालिका। न्यायालय अपील न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वरिष्ठ सहयोगी से बना होगा।

अपील न्यायालय के न्यायाधीश और एक न्यायाधीश

द्वारा निर्दिष्ट प्रत्येक विभाग में अपीलीय प्रभाग

ऐसे न्यायाधीशों के बहुमत की सहमति

अपीलीय प्रभाग।

(2) इसके आधार पर किसी भी न्यायिक अधिकारी को हटाया नहीं जाएगा। कारण को छोड़कर या मानसिक कारणों को छोड़कर सेवानिवृत्त होने के लिए धारा

हटाने या उसकी सेवानिवृत्ति के लिए आधार, और होगा सुनने का मौका मिला।

(3) न्यायिक अधिकारी को हटाने के लिए आरोपों की सुनवाई

या उसकी सेवानिवृत्ति के लिए आधारों से पहले आयोजित किया जाएगा

न्यायपालिका पर एक अदालत।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

(4) अपील न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने स्वयं के प्रस्ताव पर न्यायपालिका पर न्यायालय को बुला सकता है और

राज्यपाल या किसी अपीलीय प्रभाग के पीठासीन न्यायाधीश द्वारा लिखित अनुरोध पर न्यायालय बुलाना।

यह प्रस्तुत किया गया था कि निहित करने का उपरोक्त सुझाव

स्वयं न्यायपालिका द्वारा सदन में महाभियोग की शक्ति,

न्यायमूर्ति फ्रैंकफर्टर द्वारा अनुशंसित, खारिज कर दिया गया था। यह था।

इंगित किया कि संविधान का दूसरा मसौदा रखा गया था

21.2.1948 पर संविधान सभा के समक्ष। अनुच्छेद 103

और उपरोक्त मसौदे के 193, की नियुक्तियों से संबंधित

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। यह था।

प्रस्तुत किया, कि कई सार्वजनिक टिप्पणियां प्राप्त हुईं, के साथ

दूसरे मसौदे का संदर्भ। इस संबंध में एक ज्ञापन

संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों से भी प्राप्त किया गया था और जो, अन्य बातों के साथ-साथ,

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश

निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया गया:

"इन अनुच्छेदों (मसौदा अनुच्छेद 103 (2) और 193 (2) में इस आशय का प्रावधान सम्मिलित करना वांछनीय प्रतीत होता है कि व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाना चाहिए

न्यायालय या उच्च न्यायालय जिसने किसी भी समय स्वीकार किया हो

भारत संघ या किसी राज्य में मंत्री का पद।

इसका उद्देश्य उस व्यक्ति को रोकना है जिसने स्वीकार किया है। एक मंत्री का पद अपने प्रभाव का प्रयोग करने से

किसी भी समय न्यायाधीश बनना। यह सर्वसम्मत है

न्यायाधीशों का दृष्टिकोण कि भारतीय सिविल का एक सदस्य

सेवा किसी के भी स्थायी मुख्य न्यायाधीश नहीं होनी चाहिए। उच्च न्यायालय में उपयुक्त प्रावधान किया जाना चाहिए

इसके लिए लेख "।

यह प्रस्तुत किया गया था कि उपरोक्त के जवाब में

ज्ञापन, बी. एन. राउ ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

"इन प्रतिबंधों को लागू करना अनावश्यक है।

संविधान। इंग्लैंड में महान्यायवादी है

हमेशा क्राउन के मंत्रियों में से एक और अक्सर एक कैबिनेट मंत्री भी; उन्हें अक्सर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड का न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है।

167

समाज v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

कैबिनेट मंत्री और न्यायपालिका के प्रमुख)। भारत में, थे।

संप्र और सरकार कानून सदस्य या कानून मंत्री

जैसा कि उन्हें भविष्य में बुलाया जाएगा; कोई भी सुझाव नहीं देगा

कि इस प्रकार के पुरुष नियुक्ति के लिए अयोग्य होने चाहिए

बी.

इन उच्च पदों के लिए योग्यता ही एकमात्र मानदंड होना चाहिए।
प्रतिबंध नहीं होना चाहिए

नियुक्तियाँ; कोई संवैधानिक

योग्यता के तरीके को मान्यता दी जा रही है "।

यह दावा किया गया था कि सी द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में

संघीय न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश न्यायालयों ने निम्नलिखित सुझाव दिए:

"इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि अनुच्छेद 193 (1)
शब्द:

निम्नलिखित या अन्य उपयुक्त तरीके से

डी.

उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति इसके द्वारा की जाएगी -

राष्ट्रपति अपने हाथ और मुहर के नीचे एक वारंट द्वारा
सिफारिश

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की

राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद न्यायालय

और भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से..

-ई.

हम नहीं समझते कि इसमें कोई प्रावधान करना आवश्यक है।

मुख्य न्यायाधीश की संभावना के लिए संविधान

प्रस्तावित नियुक्ति में सहमति देने से भारत का इनकार

राष्ट्रपति द्वारा। दोनों सर्वोच्च स्तर के अधिकारी हैं।

उत्पन्न हुआ हालांकि अब एक परंपरा मौजूद है कि इस तरह
की जानी चाहिए

मामला भेजने के बाद नियुक्तियां

भारत के मुख्य न्यायाधीश को और उनके

सहमति। अगर संयोग से ऐसी स्थिति कभी होती

यह उत्पन्न करने के लिए निश्चित रूप से राष्ट्रपति जी द्वारा मुलाकात की जा सकती है

हमें लगता है कि इस ओर से ऐसा करने की आवश्यकता है।
उत्परिवर्तन लागू होता है

पूर्वगामी में उत्परिवर्तन

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, और

एच. सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

अनुच्छेद 103 (2) को भी उपयुक्त रूप से संशोधित किया जा सकता है। इसमें

संबंध यह सराहना नहीं की जाती है कि क्यों एक संवैधानिक उच्चतम न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश या न्यायाधीश से परामर्श करने का दायित्व राष्ट्रपति पर डाला जाना चाहिए।

न्यायाधीश की नियुक्ति से पहले राज्यों में उच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय। रोकने के लिए कुछ भी नहीं है

राष्ट्रपति जब भी विचार करें उनसे परामर्श न करें ऐसा करना आवश्यक है। ".

यह बताया गया कि उपरोक्त प्रस्तावों में से कोई भी नहीं था

स्वीकार कर लिया। भारतीय के संपादक को भी संदर्भ दिया गया था।

विधि समीक्षा और कलकत्ता बार एसोसिएशन के सदस्य, जिन्होंने निम्नलिखित सुझाव दिए:

"कि अनुच्छेद 103 के खंड (4) में "और मतदान" शब्द हैं।

इस खंड में विचार किए गए मुद्दे के रूप में, अवसर को यथासंभव कम किया जाना चाहिए।

विधायकों के तटस्थ रहने के लिए "।

जिस पर बी. एन. राउ की प्रतिक्रिया इस प्रकार थी:

"कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका के संविधानों में और आयरलैंड, सदस्यों का एक नंगे बहुमत मौजूद है

और न्यायाधीश को हटाने के लिए संबोधन प्रस्तुत करने के लिए मतदान पर्याप्त है। अनुच्छेद 103 (4) में दो की आवश्यकता है।

उपस्थित और मतदान करने वालों का एक तिहाई बहुमत। यह शायद ही है

"और" शब्दों को हटाकर इसे और कड़ा करना आवश्यक है।

मतदान करें "।

गैर के संबंध में सुझावों के संदर्भ में

न्यायाधीशों के वेतन में कमी, संवैधानिक सलाहकार ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

" की कमी के खिलाफ संवैधानिक सुरक्षा

मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन
अनुच्छेद 197 में न्यूनतम से नीचे निर्धारित किया गया है

ताकि राज्यों के विधानमंडलों को

वेतन को उचित संख्या से कम करना।

यह सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड है।

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

की शक्ति पर इस तरह की जाँच करना शायद ही आवश्यक हो

न्यायाधीशों का वेतन तय करेगी संसद

सुप्रीम कोर्ट "।

पित्ताभि सीतारामय्या द्वारा दिए गए सुझाव और

अन्य, अधिकारियों और सेवकों के संदर्भ में और

उच्चतम न्यायालय के खर्चों पर भी प्रकाश डाला गया। वे.

इन्हें नीचे निकाला गया है:

" कि अनुच्छेद 122 में, "के मुख्य न्यायाधीश" शब्दों के लिए

भारत ने राष्ट्रपति के परामर्श से "शब्द"

भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति "
प्रतिस्थापित किया जाए "।

संवैधानिक सलाहकार की प्रतिक्रिया इस प्रकार थी

निम्नलिखित है:

" वेतन, भत्तों के निर्धारण का प्रावधान

और भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की पेंशन

अनुच्छेद 122 के खंड (1) में निहित राष्ट्रपति के साथ परामर्श मौजूदा प्रावधान पर आधारित है।

भारत सरकार की धारा 242 (4) में निहित

अधिनियम, 1935, जैसा कि अनुकूलित किया गया है। प्रारूपण समिति

ऐसा प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक माना जाता है

जिस पर संघीय न्यायालय ने इतना जोर दिया था और
उच्च न्यायालयों ने मसौदे पर अपनी टिप्पणियों में

संविधान। ”

29. यह इंगित किया गया था कि का दूसरा मसौदा

संविधान, संविधान सभा में पेश किया गया था

4.11.1948. न्यायालय का ध्यान चर्चाओं की ओर खींचा गया,

उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों के संदर्भ में, जिनमें शामिल हैं -

बी. पोकर साहिब का सुझाव, जिन्होंने एक प्रस्ताव रखा

अनुच्छेद 103 (2) का विकल्प। इसका भी उल्लेख किया गया था

महबूब अली बेग साहिब द्वारा किया गया प्रस्ताव, इसके खिलाफ गार्डिंग

पार्टी के प्रभाव, जिन्हें संदर्भ के साथ सामने लाया जा सकता है

न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। यह प्रस्तुत किया गया था कि उपरोक्त [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समिति, जिसने महसूस किया कि इसे सक्षम करना खतरनाक होगा
न्यायाधीश की नियुक्ति पर वीटो करेंगे

मुख्य न्यायाधीश उच्चतर

न्यायपालिका। टी. टी. कृष्णमाचारी की राय भी थी निम्नलिखित प्रभावः

”[टी] न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी चाहिए

और यह कि न्यायपालिका को यह महसूस नहीं करना चाहिए कि

वे उन अनुग्रहों के अधीन हैं जो कार्यपालिका दे सकती है

समय-समय पर उनके लिए और जो स्वाभाविक रूप से होगा

किसी भी मामले में उनके निर्णय को प्रभावित करें जो उन्हें लेना है

जहाँ उस समय की कार्यपालिका के हित

चिंतित हो जाता है। उसी समय, श्रीमान, मुझे लगता है
यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि यह इरादा नहीं है

सदन या इस संविधान के निर्माताओं का कि वे
विशेष रूप से पसंदीदा निकायों को बनाना चाहते हैं जो
खुद साम्राज्य में एक साम्राज्य बन जाता है,
कार्यपालिका से पूरी तरह स्वतंत्र और
विधायिका और एक प्रकार के श्रेष्ठ निकाय के रूप में कार्य करना
सामान्य निकाय राजनीतिक "।

30. प्रस्ताव और उस पर लिए गए निर्णय थे -

विशेष रूप से के. टी. द्वारा की गई टिप्पणियों को हमारे ध्यान में लाया गया।

शाह, के. एम. मुंशी, तजामुल हुसैन, अल्लादी कृष्णस्वामी

आयर, अनंतसायनम अय्यंगार और अंत में डॉ. बी. आर.

अम्बेडकर। डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने इस प्रकार कहा था:

"अंत में बी. आर. अम्बेडकर ने कहा:

अध्यक्ष महोदय, मैं बस कुछ करना चाहूंगा।

कार्यपालिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी चाहिए
जितना हम इसे बना सकते हैं उतना स्पष्ट और निश्चित किया जाए

कानून। साथ ही इस बात का भी डर है कि नाम में

न्यायपालिका की स्वतंत्रता से, हम हो सकते हैं

जो मेरे दोस्त श्री टी. टी. कृष्णमाचारी बहुत

उचित रूप से "साम्राज्य में साम्राज्य" कहा जाता है।

हम सर्वोच्च अदालतें नहीं चाहते हैं-रिकॉर्ड चालू

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

मित्रों, यदि वे ध्यान से प्रावधानों की जांच करेंगे
जो नया संशोधन मैंने मूल अनुच्छेद 122 के स्थान पर प्रस्तावित किया है, वह पाएगा कि नया अनुच्छेद बी

एक मध्य मार्ग को चलाने का प्रस्ताव है। यह बनाने से इनकार करता है
साम्राज्य में एक साम्राज्य, और मुझे लगता है कि यह न्यायपालिका देता है

उद्देश्य के लिए जितनी स्वतंत्रता आवश्यक है
बिना किसी भय या पक्षपात के न्याय का प्रशासन करना। ”

31. संविधान सभा के समक्ष बहस की प्रकृति को व्यापक रूप से हमारे ध्यान में लाने के बाद, और
उस पर लिए गए निर्णय, विद्वान महान्यायवादी ने साहस दिखाया
यह प्रदर्शित करने के लिए कि कार्यपालिका की भागीदारी
उच्च संवैधानिक अधिकारियों की नियुक्ति के मामले में, डी “नहीं कर सका-और नहीं किया”, उनकी स्वतंत्रता
पर प्रभाव डालता है,

अपने कर्तव्यों का निर्वहन। सचित्र रूप से, निर्भरता रखी गई थी

संविधान के भाग IV अध्याय V पर, जिसमें 4 शामिल हैं

संविधान के अनुच्छेद (अनुच्छेद 148 से 151),

भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। यह प्रस्तुत किया गया था, ई
परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ -

नियंत्रक और महालेखा

अनुच्छेद 149 में वर्णित भारत की स्थिति से पता चलता है कि

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भी इससे कम नहीं थे।

उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों के लिए महत्व। इशारा करते हुए
उनका तर्क था कि नियुक्ति एफ

अनुच्छेद 148 के अनुसार, यह

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा बनाया गया है

राष्ट्रपति। अनुच्छेद 148 के खंड (1) के तहत उन्हें हटाया जा सकता है।
एक के रूप में समान आधारों पर बनाया जाए

केवल, समान तरीके से,

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। एक न्यायाधीश की तरह

उच्चतम न्यायालय, उनका वेतन और सेवा की अन्य शर्तें जी थीं।

संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किया जाना है, और जब तक वे थे

निर्धारित किए जाने पर, वे दूसरी अनुसूची में व्यक्त किए गए अनुसार होने थे। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट के
एक न्यायाधीश की तरह

न्यायालय, न तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन, [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न ही अनुपस्थिति की छुट्टी, पेंशन या उम्र के संबंध में उसके अधिकार
 सेवानिवृत्ति, उसके नुकसान के लिए भिन्न हो सकता है, उसके बाद नियुक्ति। इसी तरह से, जैसा कि
 उच्चतम न्यायालय के मामले में, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा में सेवारत व्यक्ति
 विभाग, सेवा की ऐसी शर्तों के अधीन होना था,
 जैसा कि संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निर्धारित किया गया था, और जब तक कि
 विधायी अधिनियम बनाया गया था, उनकी सेवा की शर्तें
 राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए गए थे, नियमों को तैयार करके,
 उपरोक्त के आधार पर, यह तर्क दिया गया था कि भले ही भारत के नियंत्रक और महालेखा
 परीक्षक की नियुक्ति,
 विशेष रूप से कार्यपालिका के साथ निहित था, वहाँ कभी नहीं था
 उसके प्रभावित होने के संदर्भ में एक प्रतिकूल बड़बड़ाहट
 कार्यकारी। जो निष्कर्ष निकाला जाना था वह यह था कि
 "नियुक्ति" का तरीका इस सवाल के लिए अप्रासंगिक है कि
 स्वतंत्रता। किसी प्राधिकारी की स्वतंत्रता, के अनुसार
 विद्वान महान्यायवादी, नियुक्ति के बाद, पदधारी की सेवा की शर्तों के संरक्षण से उभरे
 बनाया गया था।

32. इसी तरह हमारा ध्यान भाग की ओर खींचा गया।

संविधान का XIV, चुनावों से संबंधित है। यह प्रस्तुत किया गया था, कि अनुच्छेद 324 ने संसद और
 राज्यों के विधानमंडलों के चुनावों का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित किया है।
 प्रत्येक राज्य, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के लिए चुनाव
 अनुच्छेद 324 (2) के अनुसार आयोग में शामिल थे - मुख्य चुनाव आयुक्त और इतनी संख्या में अन्य
 राष्ट्रपति के रूप में चुनाव आयुक्त समय-समय पर
 समय तय करें। यह प्रस्तुत किया गया था कि प्रमुख की नियुक्ति
 चुनाव आयुक्त, और अन्य चुनाव आयुक्त, राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने थे, और थे
 संसद द्वारा बनाए गए कानून के प्रावधानों के अधीन। यह था।
 आगे बताया कि अनुच्छेद 324 (5) के तहत, की शर्तें
 सेवा और चुनाव सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं के कार्यालय का कार्यकाल-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

आयुक्त

(और क्षेत्रीय आयुक्त) हैं

जिस तरह से राष्ट्रपति नियमों द्वारा विनियमित हो सकता है

तय करें। बेशक, द्वारा कानून के अधिनियमन के अधीन संसद। ताकि नीचे दिए गए मामले के साथ समानता को दर्शाया जा सके

विचार करते हुए, यह तर्क दिया गया कि अनुच्छेद 324 (5) के तहत परंतु इस प्रभाव के लिए स्पष्ट था, कि मुख्य चुनाव

आयुक्त को उनके कार्यालय से हटाया नहीं जा सका, सिवाय इसके कि

अदालत। और इसके अलावा, कि सेवा की शर्तें मुख्य चुनाव आयुक्त, उनके लिए भिन्न नहीं किया जा सका

नुकसान, उनकी नियुक्ति के बाद। यह तर्क दिया गया था कि

भारतीय अनुभव यह रहा है कि मुख्य चुनाव

आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों ने

पूर्ण स्वतंत्रता के साथ कार्य किया, और कि, उनके

कार्यप्रणाली अप्रभावित रही, इस तथ्य के बावजूद कि उनकी

कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति की गई थी। यह था।

प्रस्तुत किया गया कि निष्पक्षता/स्वतंत्रता पदधारी की सेवा की शर्तों के संरक्षण से उभरी है

उसकी नियुक्ति, और उसके तरीके या तरीके से नहीं

नियुक्ति।

33. यह विद्वान वकील का भी तर्क था

नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली, जिसमें विभिन्न भाग लेते हैं

संवैधानिक पदाधिकारी विभिन्न प्रक्रियाओं में

चयन, नियुक्ति आदि, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि

विवाद, केशवानंद भारती पर निर्भरता रखी गई थी
निम्नानुसार टिप्पणी की:

मामला 10, जिसमें इस न्यायालय ने

"577. हम यह देखने में असमर्थ हैं कि न्यायपालिका की शक्ति क्या है।
समीक्षा न्यायपालिका को किसी भी मायने में सर्वोच्च बनाती है

शब्द। इस शक्ति का सर्वोपरि महत्व है
संघीय संविधान। वास्तव में यह कहा गया है कि

लोकतंत्र का दिल और मूल न्यायिक [2015] 13 एस. सी. आर. में निहित है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रक्रिया: (प्रति बोस, जे., बिडी सप्लाइ कंपनी में। संघ का

भारत, ए. आई. आर 1956 एस. सी. 479)। पतंजलि की टिप्पणियाँ

शास्त्री, सी. जे., मद्रास राज्य बनाम। वी. जी. रो, आकाशवाणी 1952 एस. सी. 196, जो लोकस
क्लासिकस बन गए हैं, केवल इस संबंध में दोहराया जाना चाहिए। न्यायिक समीक्षा है

अदालतों द्वारा किया गया "झुकने की किसी भी इच्छा से नहीं एक योद्धा की भावना में विधायी
प्राधिकरण, लेकिन में

उनके द्वारा स्पष्ट रूप से निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन

संविधान "। उत्तरदाताओं ने यह भी तर्क दिया है कि

अदालत को संवैधानिक मामलों पर न्यायिक समीक्षा करने दें

संशोधनों का अर्थ होगा अदालत को राजनीतिक मामलों में शामिल करना।

सवाल करते हैं। इसका जवाब शब्दों में दिया जा सकता है।

ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल में लॉर्ड पोर्टर बनाम। बैंक ऑफ

न्यू साउथ वेल्स 1950 एसी 235 310:

"हल की जाने वाली समस्या अक्सर इतनी नहीं होगी

राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक रूप से कानूनी, फिर भी इसे अदालत द्वारा हल किया जाना चाहिए। जहाँ
विवाद है, के रूप में

यहाँ, न केवल राष्ट्रमंडल और नागरिकों के बीच बल्कि

राष्ट्रमंडल और मध्यवर्ती राज्यों के बीच

एक ओर नागरिक और दूसरी ओर राज्य, यह केवल

न्यायालय जो इस मुद्दे का फैसला कर सकता है, उसका आह्वान करना व्यर्थ है

संसद की आवाज "।

संविधान में ही इसके लिए पर्याप्त प्रमाण हैं -
प्रणाली बनाता है

इंगित करें कि यह नियंत्रण और संतुलन की एक

दूसरों को व्यायाम करने से अक्षम करने के लिए प्रमुख और
का निर्वहन करना।

उन्हें सौंपी गई शक्तियों और कार्यों

अपनी सभी कठोरता में शक्तियों के पृथक्करण का जैसा कि मामला है
संविधान में लेकिन यह ऐसी परिकल्पना करता है

संयुक्त राज्य अमेरिका के

एक हद तक अलगाव जैसा कि रणसिंघे के मामले में पाया गया था। न्यायिक समीक्षा में स्पष्ट रूप से प्रदान
किया गया है अनुच्छेद 226 और 32 के माध्यम से संविधान एक है -

वे विशेषताएँ जिन पर जाँच की प्रणाली निर्भर करती है-सर्वोच्च न्यायालय

अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

175

समाज v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

और संतुलन। इसके अलावा, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, ए

क्षमता पर न्यायिक निर्णय की आवश्यकता या
उत्पन्न होता है

अन्यथा एक अधिनियम बहुत ही संघीय प्रकृति से

एक संविधान का (प्रति हाल्डेन, एल. सी. अटॉर्नी-जनरल में)

ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल के लिए बनाम। औपनिवेशिक चीनी

रिफाइनिंग कं. 1914 एसी 237 और एक्स पार्टी वाल्थ एंड बी
सी. एल. आर. 36 पी. 58. द.

जॉनसन; इन रे येट्स, (1925) 37

संविधान की व्याख्या का कार्य इस प्रकार है

राज्य की न्यायिक शक्ति को सौंपा गया, प्रश्न

चाहे कानून का विषय किसी एक के दायरे में हो या

एस.

द्वारा प्रदत्त विधानमंडल की अधिक शक्तियाँ संविधान हमेशा व्याख्या का प्रश्न रहेगा।
 संविधान से। यह जोड़ा जा सकता है कि किसी भी स्तर पर
 उत्तरदाताओं ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है कि
 संवैधानिक संशोधन की वैधता विषय हो सकता है।

डी.

इस न्यायालय द्वारा समीक्षा। महाधिवक्ता
 संबंधित प्रावधानों के कारण संविधान न्यायाधीशों की नियुक्ति, विशिष्ट प्रतिबंध जिसके लिए

ई.

मौलिक अधिकारों को विषय बनाया जाता है, जानबूझकर
 अनुच्छेद 21 में नियत प्रक्रिया खंड का अपवर्जन और
 अनुच्छेद 141 में पुष्टि जो न्यायाधीश घोषित करते हैं लेकिन नहीं
 दो तिहाई बहुमत का साधन और अतिरिक्त आवश्यकता अनुसमर्थन। ”
 टिप्पणियों पर भी न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया गया था।
 भीम सिंह बनाम। भारत संघ 13:

जी.

” 77. याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाया गया एक अन्य तर्क यह है कि
 योजना पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करती है
 संविधान के तहत शक्तियाँ। की अवधारणा शक्तियों का पृथक्करण, भले ही किसी में नहीं
 पाया गया हो
 10) 5 एस. सी. सी. 538

एच सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

विशेष संवैधानिक प्रावधान, राजनीति में निहित है
 संविधान ने अपना लिया है। शक्तियों के पृथक्करण का उद्देश्य अधिकतम सीमा को प्राप्त करना है

सरकार की प्रत्येक शाखा की जवाबदेही।
को समझना चाहिए।

78. जबकि-इस अवधारणा को समझते हुए, दो पहलुओं

ध्यान में रखें। एक, कि शक्तियों का पृथक्करण एक है

संविधान की अनिवार्य विशेषता। दो, कि आधुनिक में
न ही

शासन, एक सख्त अलगाव न तो संभव है।

जवाबदेही संरक्षित है, कोई उल्लंघन नहीं है
पहुँचते हैं

शक्तियों का पृथक्करण। हम एक ही निष्कर्ष पर

जब हम संवैधानिक के भीतर स्थिति का आकलन करते हैं

पाठ। संविधान ओवरलैप को प्रतिबंधित नहीं करता है

दूसरी शाखा के कार्य का अभ्यास जिसके परिणामस्वरूप

संवैधानिक शासन से दूर भागना

जवाबदेही।

79. राम जवाया कपूर बनाम। पंजाब राज्य, ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 549, इस
न्यायालय ने निर्णय दिया कि: (एयर पी। 556, पैरा 12)

" 12. भारतीय संविधान में वास्तव में ऐसा नहीं है

शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को मान्यता दी

पूर्ण कठोरता लेकिन सरकार के विभिन्न भागों या शाखाओं के कार्य पर्याप्त रूप से किए गए हैं।

विभेदित और इसके परिणामस्वरूप यह बहुत अच्छी तरह से कहा जा सकता है

कि हमारा संविधान धारणा पर विचार नहीं करता है,

राज्य के एक अंग या भाग द्वारा, उन कार्यों का जो
कार्यपालिका वास्तव में कर सकती है

अनिवार्य रूप से दूसरे से संबंधित है।

विभागीय या अधीनस्थ शक्तियों का प्रयोग करना

विधान जब ऐसी शक्तियाँ उसे प्रत्यायोजित की जाती हैं

विधायिका।

यह, जब इतना सशक्त हो जाता है, न्यायिक अभ्यास भी कर सकता है।

सीमित तरीके से कार्य करता है। कार्यकारी सरकार,

हालाँकि, के प्रावधानों के खिलाफ कभी नहीं जा सकता है

संविधान या किसी भी कानून का। "

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्डसमाज v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

(1976) 3 एस. सी. सी. 321, इस न्यायालय ने अलग होने की घोषणा की मूल संरचना का हिस्सा बनने की शक्तियाँ

संविधान। केशवानंद भारती मामले में जे. जे. शेल्ट और ग्रोवर। एस. सी. सी. पैरा 577 में सटीक बी का अवलोकन किया गया

अवधारणा की प्रकृति इस प्रकार है: (एस. सी. सी. पी. 452)

"577. संविधान में पर्याप्त सबूत हैं।

स्वयं यह इंगित करने के लिए कि यह जाँच की एक प्रणाली बनाता है और

संतुलन जिसके कारण शक्तियाँ इस प्रकार वितरित की जाती हैं

सी.

कि इसके द्वारा स्थापित तीन अंगों में से कोई भी ऐसा नहीं बन सकता है

हालाँकि संविधान इस सिद्धांत को निर्धारित नहीं करता है अपनी सभी कठोरता में शक्तियों का पृथक्करण जैसा कि मामला है

डी.

संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में अभी तक यह परिकल्पना की गई है कि

एक हद तक अलगाव जैसा कि रणसिंघे में पाया गया था मामला। न्यायिक समीक्षा में स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है

अनुच्छेद 226 और 32 के माध्यम से संविधान एक है -

वे विशेषताएँ जिन पर चेक की प्रणाली निर्भर करती है

और संतुलन "।

(5) भारतीय संविधान सख्ती को मान्यता नहीं देता है। शक्तियों का पृथक्करण। एफ का संवैधानिक सिद्धांत

शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन केवल तभी किया जाएगा जब एक आवश्यक

एक शाखा का कार्य दूसरी शाखा द्वारा लिया जाता है,

जिससे नियंत्रण और संतुलन को हटाया जा सके "।

कुल मिलाकर, विद्वान महान्यायवादी ने इस पर भरोसा रखा

जी.

यू. पी. बी. जीत एस. बिष्ट 14, जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

" 78. एक अर्थ में शक्तियों का पृथक्करण एक सीमा है
 प्रत्येक अंग का सक्रिय अधिकार क्षेत्र। लेकिन एक और बात है।
 गहरा और अधिक प्रासंगिक उद्देश्य: चेक के रूप में कार्य करना और
 07) 6 एस. सी. सी. 586

एच सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

अन्य अंगों की गतिविधियों पर संतुलन। इस प्रकार
 अंग के सक्रिय अधिकार क्षेत्र को चुनौती नहीं दी गई है;
 राजनीति के अंगों के बीच संचार। इसलिए,
 यह सुझाव दिया जाता है कि शक्तियों के पृथक्करण को न समझें
 जैसे कि वैक्यूम में काम करना। शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत
 आधुनिक समय में इसका पुनः आविष्कार किया गया है।

34. विद्वान महान्यायवादी ने जोर देकर कहा कि वहाँ

इस पर राय का एक बहुत ही गंभीर और तीखा विभाजन था

विषय, जिसका इस न्यायालय के समक्ष प्रचार किया जा रहा है। संकलचंद हिमतलाल में दिए गए निर्णय पर
 भरोसा करते हुए

शेठ मामला 5, उन्होंने बताया कि उपरोक्त निर्णय में,

यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा था कि अवधि

" "परामर्श" को "सहमति" नहीं माना जा सकता है, जिसके साथ

अनुच्छेद 222 का संदर्भ। उपरोक्त के संयोजन में, वह

समशेर सिंह के फैसले की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया

मामला 11, जिसमें एक सात-न्यायाधीश पीठ, जो इस मामले पर विचार कर रही थी

अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों से संबंधित विवाद, और

अनुच्छेद 311 के प्रभाव ने इस प्रश्न की जांच की थी कि क्या

राष्ट्रपति को अपनी व्यक्तिगत क्षमता में कार्य करना था, अर्थात् स्वयं का विवेक; या वह सहायता और सलाह पर कार्य करने के लिए उत्तरदायी था मंत्रिपरिषद्, जैसा कि अनुच्छेद 74 के तहत अनिवार्य है।
रिलायंस को निम्नलिखित टिप्पणियों पर रखा गया था
उपरोक्त निर्णय:

"149. संविधान की योजना के आलोक में हम
पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, यह संदेहपूर्ण है कि क्या ऐसा
राष्ट्रपति सही हैं। हमारा मानना है कि
राष्ट्रपति का अर्थ है, सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, मंत्री
या मंत्री परिषद्, जैसा भी मामला हो, और उसका
राय, संतुष्टि या निर्णय संवैधानिक है।
जब उनके मंत्री इस तरह की राय पर पहुंचते हैं तो यह सुनिश्चित किया जाता है-सर्वोच्च न्यायालय के
अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

संतोष या निर्णय। ए की स्वतंत्रता
न्यायपालिका, जो संविधान का एक प्रमुख सिद्धांत है
और विचलन को सही ठहराने के लिए भरोसा किया गया है, संरक्षित है
संबंधित लेख द्वारा प्रमुख के साथ परामर्श करते हुए
भारत का न्याय अनिवार्य है। सभी संभावित मामलों में
भारतीय न्याय की उस सर्वोच्च गरिमा के साथ परामर्श
भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया जाएगा और किया जाना चाहिए
और न्यायालय के पास जाँच करने का अवसर होगा यदि कोई हो
अन्य बाहरी परिस्थितियों में प्रवेश किया है
मंत्री का निर्णय, यदि वह वकील से अलग हो जाता है
भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिया गया। व्यवहार में अंतिम _

इस तरह के एक संवेदनशील उपखंड में शब्द का होना चाहिए

आम तौर पर प्रेरित _ द्वारा _ तिरछा माना जाता है
आदेश को दूषित करने वाले विचार। इस दृष्टि से यह

कोई फर्क नहीं पड़ता कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री

या न्याय मंत्री औपचारिक रूप से इस मुद्दे का फैसला करते हैं। ” .

35. यह प्रस्तुत किया गया था कि उपरोक्त टिप्पणियाँ

समशेर सिंह मामले में दर्ज किए गए थे, जिन पर भरोसा किया गया था

दूसरे न्यायाधीशों के मामले में। यह न्यायालय, यह इंगित किया गया था, ई

स्पष्ट किया था कि पैराग्राफ 149 में दर्ज टिप्पणियाँ

समशेर सिंह मामले में 11, केवल एक की प्रकृति में थे

समशेर सिंह मामला 11, पैराग्राफ 383 में भी देखा गया था। (पृष्ठ 665 पर), जिसमें यह निष्कर्ष
निकालने की मांग की गई थी कि एफ

राष्ट्रपति, सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, के रूप में माना जाना चाहिए

संबंधित मंत्री या मंत्रिपरिषद् होने के नाते

“परामर्श” के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों पर ध्यान दिया

न्यायपालिका के साथ, इस न्यायालय ने व्यक्त किया था कि सरकार ऐसे वकील से बाध्य है। संदर्भ तब जी था

प्रथम न्यायाधीशों के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के लिए किया गया,

जिसमें यह आयोजित किया गया था कि “परामर्श” में शामिल नहीं था

“सहमति”, और आगे, कि नियुक्ति की शक्ति

अनुच्छेद 124 के तहत न्यायाधीश राष्ट्रपति के पास निहित थे, और सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस.
सी. आर.

यह भी कि राष्ट्रपति के विचारों को ओवरराइड किया जा सकता है

सलाहकारों। सबसे अंत में, अपने समर्पण को प्रमाणित करने के लिए

राय के विभाजन के संबंध में, निर्भरता रखी गई थी

केशवानंद भारती मामला 10, जिसमें एक तेरह-न्यायाधीश

इस न्यायालय की पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया था कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन, कि "बुनियादी" की अवधारणा

संरचना ", एक सीमा थी, अन्यथा पूर्ण शक्ति के लिए

संविधान में संशोधन।

36. हमें मनाने के अपने प्रयास में, तत्काल मामले को संदर्भित करने के लिए,

नौ न्यायाधीशों की पीठ (या, एक और भी बड़ी पीठ) के लिए, विद्वान अटॉर्नी जनरल ने सुराज इंडिया ट्रस्ट बनाम पर भरोसा रखा। संघ

भारत का 15, और निम्नलिखित पर हमारा ध्यान आकर्षित किया:

"3. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ए. के. गांगुली ने कहा है कि

प्रस्तुत किया कि एक सर्वोच्च की नियुक्ति की विधि

न्यायालय न्यायाधीश का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 124 (2) में किया गया है।

भारत का संविधान जो कहता है:

राष्ट्रपति द्वारा अपने हाथ के तहत वारंट द्वारा नियुक्त और ऐसे न्यायाधीशों के साथ परामर्श के बाद मुहर

राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझ सकते हैं और साठ-पाँच वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर बने रहेंगे।

बशर्ते कि किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में

मुख्य न्यायाधीश की तुलना में, भारत के मुख्य न्यायाधीश हमेशा

सलाह लीजिए "।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि कोई उल्लेख नहीं है:

(i) अनुच्छेद 124 (2) में किसी भी कॉलेजियम का।

(ii) अनुच्छेद 124 (2) में प्रयुक्त शब्द "परामर्श" है, और "सहमति" नहीं।

(iii) उच्चतम न्यायालय की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति

न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय या यहाँ तक कि उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश से परामर्श कर सकता है क्योंकि वह इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझता है।

15 (2012) 13 एस. सी. सी. 497 सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्डसमाज v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

और केवल पाँच वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करने के लिए बाध्य नहीं है

उच्चतम न्यायालय से।

4. कि उपरोक्त दो मामलों में न्यायिक निर्णयों द्वारा, अनुच्छेद 124 (2) को व्यावहारिक रूप से संशोधित किया गया है, हालांकि

संविधान में संशोधन केवल इसके द्वारा किया जा सकता है में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संसद

भारत के संविधान का अनुच्छेद 368।

5. कि अनुच्छेद 124 (2) के तहत सर्वोच्च न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना होता है, लेकिन वह किसी अन्य सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से भी परामर्श कर सकते हैं।

न्यायालय के न्यायाधीश, न कि केवल चार वरिष्ठतम न्यायाधीश।

इसके अलावा, भारत के राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से भी परामर्श कर सकते हैं, जबकि उपरोक्त दो निर्णयों के अनुसार

भारत के राष्ट्रपति किसी भी सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श नहीं कर सकते हैं।

के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के अलावा अन्य न्यायाधीश

उच्चतम न्यायालय, और वह किसी भी उच्च न्यायालय से परामर्श नहीं कर सकता है

बिल्कुल भी न्याय करें।

6. श्री गंगुली प्रस्तुत करते हैं कि मामला होना आवश्यक है याचिका के रूप में एक बड़ी पीठ द्वारा विचार किया गया

संवैधानिक महत्व के निम्नलिखित मुद्दे:

(1) क्या उपरोक्त दो निर्णय अर्थात् सात-न्यायाधीश

इस न्यायालय की पीठ और नौ-न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय

ऊपर उल्लिखित वास्तव में अनुच्छेद 124 (2) में संशोधन करने के बराबर है।

संविधान का?

(2) क्या नियुक्ति के लिए कोई "कॉलेजियम" प्रणाली है

में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

संविधान?

(3) क्या संविधान में न्यायिक संशोधन किया जा सकता है

निर्णय या इसे केवल संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है

अनुच्छेद 368 के अनुसार?

(4) क्या संवैधानिक योजना यह थी कि

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है।

आपसी चर्चा और आपसी सहमति से

न्यायपालिका और कार्यपालिका; या क्या न्यायपालिका कर सकती है [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

केवल उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति

अदालतें?

(5) क्या अनुच्छेद 224 में "परामर्श" शब्द का अर्थ है

"सहमति"?

(6) चाहे न्यायिक व्याख्या के शब्दों में

संविधान को अनावश्यक बनाया जा सकता है, जैसा कि प्रतीत होता है
किया गया है जो किए गए हैं

उपरोक्त दो निर्णयों में

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ परामर्श
अनावश्यक है, इस तथ्य के बावजूद कि

क्या अनुच्छेद 124 (2) की स्पष्ट भाषा पर अनुमति है?

(7) क्या अनुच्छेद 124 (2) की स्पष्ट भाषा हो सकती है

न्यायाधीश) केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश और चार वरिष्ठतम
से अकेले परामर्श किया जा सकता है जबकि

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों

(8) क्या कोई परंपरा थी कि राष्ट्रपति

भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से बाध्य है, और

क्या ऐसा कोई कन्वेंशन है (यह मानते हुए कि एक था)

क्या यह अनुच्छेद 124 (2) की स्पष्ट भाषा पर हावी हो सकता है?

(9) क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय है

उपरोक्त नियुक्तियों में कोई प्रधानता?

(10) क्या उपरोक्त दो निर्णय होने चाहिए

एक बड़ी पीठ द्वारा खारिज किया गया?

7. श्री जी. ई. वाहनवती, भारत के विद्वान महान्यायवादी,

याचिकाकर्ता का यह तर्क देते हुए समर्थन करता है कि उपरोक्त

निर्णयों पर पुनर्विचार की आवश्यकता होती है। लेकिन वह भी

प्रस्तुत करता है:

न्यास के रूप में न्यास का आदेश किसी के उल्लंघन का दावा नहीं कर सकता है अपने मौलिक अधिकारों का;

(ख) याचिकाकर्ता के पास समीक्षा की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है।

इस न्यायालय के निर्णय। वास्तव में, अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय के तहत एक याचिका-ऑन-रिकॉर्ड

समाज v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

संविधान की शुद्धता को चुनौती देने के लिए झूठ नहीं है

नौ न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय। (घ) दो न्यायाधीशों की पीठ मामले को सीधे नौ या उससे अधिक न्यायाधीशों की बड़ी पीठ को नहीं भेज सकती है।

XXXX

XXXX

XXXX 11. हालांकि, श्री गांगुली लोकस के मुद्दे से निपट रहे हैं

न्यास ने प्रस्तुत किया है कि याचिका नहीं हो सकती है रखरखाव योग्य हो लेकिन इसका मनोरंजन किया जाना चाहिए क्योंकि यह

यह कानून पर बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। में।

अपने समर्पण को मजबूत करने के लिए वह एक पर भरोसा करता है

बी. पी. में इस न्यायालय के हाल के संविधान पीठ के फैसले सिंघल बनाम। भारत संघ (2010) 6 एस. सी. सी. 331 जिसमें

राज्यपालों को हटाने के मुद्दे पर विचार करते हुए, यह न्यायालय

निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया: (एस. सी. सी. पी. 346, पैरा 15)

"15. याचिकाकर्ता के पास राहत का दावा करने वाली प्रार्थनाओं के संबंध में याचिका को बनाए रखने का कोई अधिकार नहीं है व्यक्तिगत राज्यपाल। सभी आयोजनों में, ऐसी प्रार्थनाएँ अब नहीं की जाती हैं

समय बीतने के कारण जीवित रहें। लेकिन इसके साथ
 संविधान पीठ को निर्दिष्ट सार्वजनिक महत्व के सामान्य प्रश्न के संबंध में,
 अनुच्छेद 156 (1) और के सिद्धांत पर सीमाएँ
 अन्यथा, याचिकाकर्ता के पास आवश्यक अधिकार हैं। ”
 इस प्रकार, श्री गांगुली प्रस्तुत करते हैं कि की गंभीरता को देखते हुए
 इसमें शामिल मुद्दों पर विचार किया जाना चाहिए।

12. बड़े के संदर्भ के मुद्दे से निपटने के दौरान

बेंच, श्री गांगुली ने बहुत अधिक निर्भरता रखी है

क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाम। सेल (2011) 4 एससीसी 450, जिसमें व्याख्या के मुद्दे पर विचार
 किया जाता है

संवैधानिक प्रावधान और इसमें शामिल अधिनियम की वैधता

इसमें, माननीय की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की पीठ

मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले को नौ-न्यायाधीशों की पीठ को भेज दिया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

13. इस समय श्री गांगुली और श्री वाहनवती

प्रस्तुत किया है कि प्रारंभिक सुनवाई के चरण में भी

याचिका को स्वीकार करने के लिए, मामले की सुनवाई की आवश्यकता है

एक बड़ी पीठ द्वारा क्योंकि इस मामले पर पहले विचार किया जा चुका है

तीन-न्यायाधीशों की पीठ के साथ और इसमें बहुत जटिल शामिल है

कानूनी मुद्दे।

14. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम मामले को सामने रखते हैं
 माननीय मुख्य न्यायाधीश उचित निर्देशों के लिए ”।

यह इंगित किया गया था कि जब उपरोक्त विषय रखा गया था

इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष, वही था
 किया गया। फिर भी, जब से उपरोक्त

लोकस स्टैंडी की जमीन पर बर्खास्त

याचिकाकर्ता ट्रस्ट की अनुपस्थिति में आदेश पारित किया गया था, और

उपरोक्त आदेश को वापस लेने के लिए आवेदन भेजा गया था। यह.
 उनका दावा था कि वापस बुलाने का आदेश पारित किया गया था या नहीं
 उठाए गए प्रश्नों के संदर्भ में, यह स्पष्ट था कि
 इस न्यायालय की पीठ पहले ही यह विचार व्यक्त कर चुकी है कि
 द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों के मामलों में निकाले गए निष्कर्ष,
 इसे फिर से देखने की जरूरत है।

37. अंत में, उपरोक्त सुझावों का समर्थन करने के लिए, न्यायालय का

एच. एम. द्वारा अभिलिखित टिप्पणियों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। सीरवई ने अपनी
 पुस्तक "कॉन्स्टीट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया" के चौथे संस्करण में, जिसमें दूसरे न्यायाधीशों के मामले के संदर्भ में,
 मजबूत और प्रतिकूल विचार व्यक्त किए गए। उपरोक्त
 विचार अनुच्छेद 25.448 से 25.497 में निहित हैं। के लिए
 संक्षिप्तता के कारण, हमारे लिए इसे निकालना संभव नहीं है यहाँ। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि
 प्रस्तुतियाँ आगे बढ़ीं

विद्वान महान्यायवादी, जैसा कि में विस्तृत किया गया है

पूर्वगामी अनुच्छेद, कमोवेश, के अनुसार थे एच. एम. सेरवई द्वारा व्यक्त किए गए विचारा।

38. यह तर्क देने के लिए कि यह इस न्यायालय के लिए खुला था,

पहले से ही मामलों पर पुनर्विचार के लिए एक संदर्भ बनाएँ

विद्वान महान्यायवादी ने फैसला सुनाते हुए जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड बनाम की ओर हमारा ध्यान आकर्षित
 किया। हरियाणा राज्य 16.

16 (2010) 4 एस. सी. सी. 595 सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्डसमाज v. यू. ओ. आई. [जगदीश
 सिंह खेहर, जे।]

"6. केशव मिल्स कं. लिमिटेड बनाम। सी. आई. टी. ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1636. (ए. आई. आर. पीपी.
 1643-44, पैरा 23) इस न्यायालय की एक संविधान पीठ

उन परिस्थितियों को अधिनियमित किया जिनमें एक संदर्भ बड़ी बेंच होगी। यह अभिनिर्धारित
 किया गया था कि पुनरीक्षण में और

अपने पहले के फैसले को संशोधित करते हुए, इस न्यायालय को खुद से पूछना चाहिए

चाहे वह जनता के हित में हो या किसी अन्य के लिए। वैध और बाध्यकारी कारण, यह आवश्यक है कि

पहले के निर्णय को संशोधित किया जाना चाहिए? चाहे पहले

किसी का ध्यान नहीं गया, या न्यायालय का ध्यान आकर्षित नहीं किया गया था कोई सुसंगत और भौतिक वैधानिक प्रावधान, या कोई था

जिस बिंदु पर ध्यान नहीं दिया गया था, उस पर आधारित पिछला निर्णय? क्या?

पर पिछले निर्णय में त्रुटि का प्रभाव था

सार्वजनिक भलाई? क्या पहले के निर्णय का पालन किया गया है?

बाद के अवसर या तो इस न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा

अदालतें? और, क्या पहले के निर्णय को उलट दिया जाएगा?

सार्वजनिक असुविधा, कठिनाई या शरारत के लिए?

7. केशव मिल्स मामले के फैसले के अनुसार ये

और अन्य प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

जब भी इस न्यायालय को इसका प्रयोग करने के लिए कहा जाता है

अपने पहले के निर्णयों की समीक्षा और समीक्षा करने का अधिकार क्षेत्र। में से

बेशक, केशव मिल्स मामले में एक चेतावनी दी गई थी

प्रभाव जो इस न्यायालय की अपनी शक्ति का बार-बार प्रयोग करता है

अपने पहले के निर्णयों पर फिर से विचार करने की प्रवृत्ति संयोग से हो सकती है कानून अनिश्चित है और भ्रम पैदा करता है जो होना चाहिए

इस अवसर पर, न्यायालय संतुष्ट है कि उसका पूर्व निर्णय था स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण, इसे त्रुटि को सुधारने में संकोच करना चाहिए।

8. अंत में, केशव मिल्स मामले में, इस न्यायालय ने टिप्पणी की कि किसी भी सिद्धांत को निर्धारित करना संभव नहीं है जो न्यायालय के दृष्टिकोण को नियंत्रित करता है

अपने पहले के निर्णय पर पुनर्विचार करने का सवाल। यह अंततः कई प्रासंगिक विचारों पर निर्भर करेगा।

9. दाउदी बोहरा समुदाय के केंद्रीय बोर्ड बनाम। राज्य महाराष्ट्र (2005) 2 एस. सी. सी. 673., एक संविधान पीठ [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस न्यायालय ने कहा कि संदेह के मामले में, एक छोटा

पीठ मुख्य न्यायाधीश का ध्यान आकर्षित कर सकती है और अनुरोध कर सकती है

मामले को सुनवाई के लिए एक बड़ी पीठ के समक्ष रखा जा रहा है

उस व्यक्ति की तुलना में जिसके फैसले पर संदेह किया जा रहा है।

39. उपरोक्त उल्लिखित प्रस्तुतियों के साथ, विद्वान वकील

भारत के लिए जनरल ने समीक्षा के लिए अपना संबोधन समाप्त किया

द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों के मामलों में निर्णय।

40. श्री के. के. वेणुगोपाल, विद्वान वरिष्ठ वकील,

हमारा ध्यान, अनुच्छेद 124 के प्रस्तावित संशोधनों पर, 217, 222 और 233, और विशेष रूप से, के
समावेश के लिए

"राष्ट्रीय न्यायिक आयोग" शीर्षक के तहत संविधान में भाग XIII। अनुच्छेद 307 ए को प्रस्तावित किया गया
था -

भाग XIII में एकल लेख। संविधान के आधार पर

फैसले के प्रभाव को नकारने के लिए विधेयक पेश किया गया था प्रथम न्यायाधीशों के मामले में
इस न्यायालय का। यह प्रस्तुत किया गया था कि

जब उपरोक्त विधेयक संसद में पेश किया गया था,

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जिसमें से श्री वेणुगोपाल स्वयं तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उन्होंने
एक संगोष्ठी का आयोजन किया

1.9.1990, के पक्ष और विपक्ष पर बहस करने के उद्देश्य से

संविधान (67 वां संशोधन) विधेयक, 1990। यह प्रस्तुत किया गया था,

कि बहस में बड़ी संख्या में वक्ताओं ने भाग लिया था

और महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। उपरोक्त

सदन के समक्ष रखा गया, और या तो सर्वसम्मति से पारित किया गया या भारी बहुमत के
साथ। यह प्रस्तुत किया गया था कि

भारत, 5.10.1990 दिनांकित एक आवरण पत्र के माध्यम से। यह इंगित किया गया था बाहर,
कि प्रस्ताव भी पारित किए गए थे, के समापन पर

मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन, 31.8.1990 और के बीच आयोजित किया गया

2.9.1990, जिसमें संविधान के प्रावधान (67 वां) भी हैं।

संशोधन) विधेयक, 1990 पर विचार-विमर्श किया गया।

यह सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड था।

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

प्रस्तुत किया, कि उन्होंने प्रस्तावों का संकलन किया था
और निष्कर्ष

मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में पारित,

दूसरे न्यायाधीशों के मामले में तैयार किया गया, जो एक पक्षी का पक्ष देगा
विचारों का दृश्य। जिसके लिए संकलन

व्यक्त किए गए

विद्वान सलाह ने हमारा ध्यान आकर्षित किया, निकाली जा रही है

इसके नीचे:

" (1) न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय एक एकीकृत न्यायालय हैं।

'सर्वश्रेष्ठ चयन के लिए 'सहभागी परामर्श प्रक्रिया'
और नियुक्ति के लिए उपलब्ध सबसे उपयुक्त व्यक्ति; और

सभी संवैधानिक अधिकारियों को यह कर्तव्य निभाना चाहिए।

सामूहिक रूप से एक दृष्टिकोण के साथ मुख्य रूप से एक सहमत तक पहुंचने के लिए

निर्णय, संवैधानिक उद्देश्य के अधीन, ताकि

प्रधानता का अवसर उत्पन्न नहीं होता है।

(2) के मामले में नियुक्ति के प्रस्ताव की शुरुआत

सर्वोच्च न्यायालय भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा होना चाहिए,

और उच्च न्यायालय के मामले में उसके मुख्य न्यायाधीश द्वारा

उच्च न्यायालय; और किसी राज्य के न्यायाधीश/मुख्य न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए

उच्च न्यायालय, प्रस्ताव भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शुरू किया जाना है। यह वह तरीका है
जिसमें प्रस्ताव

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में नियुक्तियाँ

साथ ही न्यायाधीशों/मुख्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए

उच्च न्यायालय हमेशा बनाए जाने चाहिए।

(3) संवैधानिक द्वारा परस्पर विरोधी राय की स्थिति में

पदाधिकारी, न्यायपालिका की राय 'द्वारा प्रतीकित

भारत के मुख्य न्यायाधीश का दृष्टिकोण', और में गठित

जिस तरह से संकेत दिया गया है, उसमें प्रधानता है।

(4) उच्चतम न्यायालय में किसी न्यायाधीश की कोई नियुक्ति नहीं या

कोई भी उच्च न्यायालय बनाया जा सकता है, जब तक कि यह अनुरूप न हो।

भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय के साथ।

(5) अकेले असाधारण मामलों में, बताए गए मजबूत ठोस के लिए

भारत के मुख्य न्यायाधीश को बताए गए कारणों से यह संकेत मिलता है कि सिफारिशकर्ता नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है, कि

भारत के मुख्य न्यायाधीश [2015] 13 एस. सी. आर. द्वारा अनुशंसित नियुक्ति।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, यदि बताए गए कारण नहीं हैं

भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों द्वारा स्वीकार किए गए, जिनसे इस मामले में परामर्श किया गया है -

मामला, प्रमुख द्वारा सिफारिश की पुनरावृत्ति पर

भारत के न्यायाधीश, नियुक्ति एक के रूप में की जानी चाहिए स्वस्थ सम्मेलन। "

उपरोक्त संकलन के आधार पर, यह तर्क दिया गया था,

कि दूसरे न्यायाधीशों के मामले में दिया गया निर्णय,

अनुच्छेद 124 की तीन प्रमुख विशेषताओं को पूरी तरह से मिटा दिया गया। अनुच्छेद 124 के तहत, मुख्य आवाज यह थी कि

सबसे पहले, मूल

राष्ट्रपति से। यह प्रस्तुत किया गया था कि की आवाज

राष्ट्रपति का दूसरे न्यायाधीशों के मामले में पूरी तरह से दम घुट गया था।

दूसरा, अनुच्छेद 124, जैसा कि इसे मूल रूप से बनाया गया था, निहित था नियुक्तियों के संबंध में प्रधानता के साथ कार्यपालक उच्च न्यायपालिका, जबकि स्थिति द्वारा उलट दिया गया था द्वितीय न्यायाधीशों का मामला, न्यायपालिका को प्रधानता देकर। तीसरा, भारत के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका, जो मूल रूप से थी, दूसरे न्यायाधीशों के मामले में निर्णय द्वारा केवल एक प्रतिनिधि दल को "उसके प्रमुख को सौंप दिया गया"। अब, कॉलेजियम

भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायाधीशों को नियुक्तियां करने के लिए अंतिम निर्धारक अधिकार दिया गया है

उच्च न्यायपालिका के लिए। और राष्ट्रपति "सहमत" होने के लिए उत्तरदायी है, की गई सिफारिशों के साथ। उपरोक्त के आधार पर

दावा करते हुए, यह विद्वान वकील की प्रस्तुति थी, कि उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 124 का पूरी तरह से गलत अर्थ निकाल कर नियुक्ति की पूरी शक्ति ग्रहण की। और आवाज़ कार्यपालिका को पूरी तरह से दबा दिया गया था। यह प्रस्तुत किया गया था, कि न्यायपालिका ने एक विधायी कार्य किया था, जबकि अनुच्छेद 124 की व्याख्या करना। यह दावा किया गया था कि मूल रूप से संस्थापक पिताओं के पास प्रावधानों को तैयार करने की शक्ति थी प्रस्तुत किया कि संविधान सभा को सौंपी गई भूमिका, संसद के लिए भी, इस न्यायालय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं-ऑन-रिकॉर्ड में प्रदर्शन किया गया है

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

द्वितीय न्यायाधीशों का मामला। यह प्रस्तुत किया गया था कि यह सब था

"न्यायिक स्वतंत्रता" के नाम पर किया गया। उपरोक्त तर्क का इस बात पर जोर देकर गंभीरता से विरोध करने की कोशिश की गई कि

न्यायिक स्वतंत्रता अपने आप नहीं टिक सकती थी, वहाँ था

कुछ न्यायिक जवाबदेही की तरह भी, जिसे बनाए रखना था
दिमाग में।

41. यह भी तर्क दिया गया था कि न्यायपालिका ने लिया था
स्वयं पर, नियुक्तियाँ करने की अनन्य भूमिका
हितधारक। यह प्रस्तुत किया जाता है कि न्यायपालिका इसके लिए है
इसलिए, वादकारी समुदाय
के मामले में कुछ भूमिका के साथ निहित होने के लिए उत्तरदायी था
उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियाँ। इसी तरह, यह इंगित किया गया था
कि इस देश में लगभग दस लाख वकील थे। वे।
इस मामले में भी कुछ नहीं कहा गया था। यहाँ तक कि बार भी
संघ, जिनके पास वकीलों का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता है ' बंधुत्व, की प्रक्रिया में किसी भी भूमिका
से बाहर रखा गया था
नियुक्तियाँ। यह रेखांकित किया गया कि पुरानी प्रणाली के तहत,
उपरोक्त सभी हितधारकों को ऐसा करने का अवसर मिला
नियुक्तियों के मामले में कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व
उच्च न्यायपालिका के लिए। लेकिन, वह भूमिका अब पूरी तरह से हो गई है
अनुच्छेद 124 पर दी गई व्याख्या द्वारा,
दूसरा न्यायाधीश का मामला। न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया गया था कि
निष्कर्ष सं। 14 निष्कर्ष के सारांश में तैयार किया गया (दूसरे न्यायाधीशों के मामले में अनुच्छेद
486 में अभिलिखित) कि
प्रथम न्यायाधीशों के मामले में बहुमत की राय, जहाँ तक, यह थी
प्रमुख की भूमिका की प्रधानता के संबंध में एक विपरीत दृष्टिकोण लिया गया
नियुक्तियों और स्थानान्तरण के मामलों में भारत का न्याय, और
इन मामलों की न्यायसंगतता, साथ ही, न्यायाधीश के संबंध में
शक्ति, सही दृष्टिकोण होने के रूप में खुद की सराहना नहीं की।
तदनुसार यह निष्कर्ष निकाला गया कि संबंधित प्रावधान
संवैधानिक योजना सहित संविधान को अब

दूसरे न्यायाधीशों के मामले में निकाले गए निष्कर्षों में बताए गए तरीके से समझा, समझा और लागू किया जाए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

पूरी तरह से गलत धारणा, क्योंकि उसी ने प्रभाव को पूरी तरह से नकार दिया अनुच्छेद 74, जिसमें राष्ट्रपति को केवल इस पर कार्य करने की आवश्यकता थी

मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह। विद्वानों के अनुसार

अधिवक्ता, राष्ट्रपति को अब भारत के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों के कॉलेजियम के आदेश के अनुसार कार्य करना होगा। यह.

प्रस्तुत किया गया था, कि यह कानून में अस्वीकार्य था, एक पक्ष के लिए

अपने पक्ष में निर्णय लें। यह, विद्वानों के अनुसार

वकील, ठीक वही है जो सर्वोच्च न्यायालय ने किया था दूसरे न्यायाधीशों का मामला। यह संतुष्ट था, कि विवादित

संवैधानिक संशोधन के आदेश पर एक प्रयास था

संसद, उपरोक्त ऐतिहासिक विचलन को ठीक करने के लिए। सीखा है। वकील ने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि दो सदन थे

संविधान के तहत संसद की, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय

दूसरे न्यायाधीशों के मामले में, के तीसरे सदन के रूप में कार्य किया था

संसद, अर्थात्, सुधार सदन के रूप में। में

उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति की पृष्ठभूमि में, यह प्रस्तुत किया गया था,

कि जब भारत संघ और राज्य जिन्होंने अनुसमर्थन किया

संविधान (99 वां संशोधन) अधिनियम पर पुनर्विचार की मांग

द्वितीय न्यायाधीशों का मामला, क्या यह बहुत अधिक था कि संघ और राज्य क्या मांग रहे थे?

42. ऊपर देखी गई दलीलों के बाद, हमने श्री के. परासरन, वरिष्ठ अधिवक्ता को सुना, जिन्होंने भी समर्थन किया

विद्वान महान्यायवादी द्वारा की गई प्रार्थना। यह था।

प्रस्तुत किया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति का कोई लेना-देना नहीं था

संबंधित "न्यायाधीश की स्वतंत्रता", या समग्र रूप से न्यायिक संस्था के साथ। यह प्रस्तुत किया गया था कि इसके बाद

उच्च न्यायपालिका में उनकी नियुक्ति, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा की शर्तें उन्हें सुरक्षित रखा गया था। इसके बाद, की स्वतंत्रता

न्यायाधीश अपने न्यायिक विवेक पर निर्भर थे, और

इसमें कार्यपालिका की कोई भूमिका नहीं है।

43. यह दावा किया गया था कि जिन न्यायाधीशों ने व्यक्त किया

द्वितीय न्यायाधीशों के मामले में, बहुमत ने एक सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं-ऑन-रिकॉर्ड पर विचार किया

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

"बुनियादी संरचना" के बारे में पूर्वकल्पित धारणा, इससे पहले भी

(अनुच्छेद 124 के पाठ के संदर्भ में)। यह प्रस्तुत किया गया था कि अनुच्छेद 124 पर दी गई व्याख्या को स्पष्ट रूप से नजरअंदाज कर दिया गया,

न्यायाधीशों की नियुक्ति, लेकिन आसपास के संवैधानिक भी प्रावधान। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, न्यायपालिका ने नियुक्ति की कार्यकारी शक्ति का अतिक्रमण किया था

न्यायाधीश। यह एक संवैधानिक में अतिक्रमण करने के बराबर था

जोर देकर कहा कि संविधान के संशोधन की शक्ति, अनुच्छेद 368 के तहत संसद में निहित, केवल उद्देश्य था

कि संसद के पास निहित उपरोक्त शक्ति का उपयोग सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित करके नहीं किया जा सकता था न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया, जिस तरह से

सुप्रीम कोर्ट ने महसूस किया। यह प्रस्तुत किया गया था कि दूसरे न्यायाधीशों में

मामले के साथ-साथ, तीसरे न्यायाधीशों के मामले में भी, सर्वोच्च न्यायालय ने विधायी व्यवस्था को बाधित करके "बुनियादी ढांचे" का उल्लंघन किया था

शक्ति। यह तर्क दिया गया था कि यह इस न्यायालय के लिए अनिवार्य था

दोनों निर्णयों को फिर से देखने के लिए, ताकि यह निर्धारित किया जा सके,

क्या न्यायपालिका द्वारा कोई अतिक्रमण किया गया था

विधायी क्षेत्र। और, यदि यह न्यायालय निष्कर्ष पर पहुँचता है, कि ऐसा मामला था, उसे अपने पहले के मामले को रद्द कर देना चाहिए

दृढ़ संकल्प। यह आगे प्रस्तुत किया गया था कि की महिमा

संविधान को हर कीमत पर बनाए रखा जाना चाहिए और संरक्षित किया जाना चाहिए। और पहले की समीक्षा करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए।

निर्णय, ताकि एक गलत निर्णय को सही किया जा सके। के साथ

उपरोक्त टिप्पणियों, विद्वान वकील ने सराहना की

पीठ, विद्वान वकील [2015] 13 एस. सी. आर. द्वारा की गई प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सामान्य, और पुनर्विचार के लिए एक संदर्भ बनाने के लिए

इस न्यायालय द्वारा दूसरे और तीसरे में दिए गए निर्णय

न्यायाधीशों के मामले, एक उचित शक्ति के साथ एक पीठ के लिए।

44. श्री रवीन्द्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता भी

एक बड़ी पीठ के संदर्भ के लिए प्रस्तुतियों का समर्थन किया। यह

प्रस्तुत किया गया था कि इस न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष

द्वितीय न्यायाधीश का मामला और तृतीय न्यायाधीश का मामला उत्तरदायी था।

संदिग्ध के रूप में वर्णित किया जाना, क्योंकि बड़ी संख्या में मुख्य

तय किया गया। यह विद्वान वकील का तर्क था, कि याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुतियाँ, पर

गुण, संविधान के पाठ द्वारा समर्थित नहीं किया जा सका

प्रावधान, और वह, याचिकाकर्ताओं की निर्भरता पूरी तरह से आधारित है

द्वितीय न्यायाधीशों के मामले में बहुमत निर्णय पर, जैसा कि था

तीसरे न्यायाधीशों के मामले में आगे समझाया गया, गंभीरता से था वृद्धिपूर्ण। यह प्रस्तुत किया गया था कि प्रस्तुतियों का जोर

याचिकाकर्ताओं की ओर से योग्यता के आधार पर अग्रिम किया गया था, नहीं केवल यह कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श था

अनिवार्य, लेकिन न्यायाधीशों के कॉलेजियम की राय थी
कार्यपालिका पर बाध्यकारी। यह दावा किया गया था कि दोनों में से कोई भी
उपरोक्त आवश्यकताएँ लेख के सादे पठन से उभरीं।

124. यह दावा किया गया था कि विद्वान वकील का आधार याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व
करते हुए, आरोपित पर हमला करने के लिए

संवैधानिक संशोधन, साथ ही एन. जे. ए. सी. अधिनियम भी, पूरी तरह से था उपरोक्त संकल्प
पर आधारित। यह दावा किया गया था कि

न्यायपालिका की प्रधानता का निष्कर्ष, के मामले में
उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं हो सकी
मूल संवैधानिक प्रावधानों के किसी भी पाठ द्वारा समर्थित।
तदनुसार, यह सुझाव दिया गया था कि यह बिल्कुल अनिवार्य था
द्वितीय न्यायाधीशों में व्यक्त किए गए बहुमत के दृष्टिकोण को सही करना।
मामला।

45. विद्वान वकील के अनुसार, प्राथमिक
याचिकाकर्ताओं के कहने पर आपत्ति उठाई गई, जिसका विरोध किया गया
द्वितीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं-ऑन-रिकॉर्ड में दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]
न्यायाधीशों का मामला, में दर्ज टिप्पणियों पर आधारित था
तीसरे न्यायाधीशों के मामले का अनुच्छेद 10, जिसमें कथन
भारत के तत्कालीन महान्यायवादी के बारे में दर्ज किया गया था कि
भारत संघ समीक्षा या पुनर्विचार नहीं चाहता था
द्वितीय न्यायाधीशों के मामले में निर्णय। यह प्रस्तुत किया गया था,
कि उपरोक्त कथन, की याचिका पर रोक नहीं लगा सका
आने वाले सभी समय के लिए पुनर्विचार। यह आगे प्रस्तुत किया गया था,

कि उपरोक्त कथन संसद को बाध्य नहीं करेगा। यह था।

दूसरे न्यायाधीश के मामले का अर्थ यह नहीं समझा जाना चाहिए कि यह निहित रूप से स्वीकार किया गया था कि दूसरे न्यायाधीशों के मामले में था

सही निर्णय लिया गया। यह इंगित किया गया था कि परामर्श

अनुच्छेद 143 के तहत अधिकार क्षेत्र, जिसे द्वारा लागू किया गया था

तीसरे न्यायाधीश के मामले को प्रस्तुत करने वाला न्यायालय, न तो अपील्य था न ही प्रकृति में संशोधनकारी। इस पक्ष में, विद्वान वकील ने रखा

री पर निर्भरता कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण ", जिसमें यह

अभिनिर्धारित किया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश, कर सकता है

इसकी समीक्षा तभी की जाएगी जब अनुच्छेद के तहत इसका अधिकार क्षेत्र लागू किया गया हो।

137 संविधान का (आदेश 40 के नियम 1 के साथ पढ़ा गया)

उच्चतम न्यायालय नियम, 1946)। और वह, की एक समीक्षा

उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय, दूसरे में

न्यायाधीशों का मामला, राष्ट्रपति के माध्यम से नहीं मांगा जा सका

अनुच्छेद 143 के तहत दिया गया संदर्भ। वास्तव में, इस न्यायालय में उपरोक्त निर्णय ने यह निष्कर्ष निकाला था कि यदि की शक्ति

समीक्षा को अनुच्छेद 143 में पढ़ा जाना था, यह एक गंभीर बात होगी

"न्यायपालिका की स्वतंत्रता" में प्रवेश। इसलिए यह

प्रस्तुत किया कि तत्कालीन महान्यायवादी का बयान, तीसरे न्यायाधीशों के मामले की सुनवाई के दौरान,

आने वाले सभी समय के लिए बाध्यकारी नहीं माना जाएगा, ताकि वंचित किया जा सके

कार्यपालिका और विधायिका को समीक्षा की मांग करने से भी

दिए गए निर्णयों से। इसलिए यह तर्क दिया गया कि

17 1993 पूरक (1) एस. सी. सी. 96 (11)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

अपने कर्तव्य का निर्वहन करते समय निहित था कि यह न्यायालय था

अतीत में किया गया। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि सुभाष शर्मा मामले में इस न्यायालय के फैसले का अवलोकन मामला 4, स्पष्ट रूप से सामने लाया गया कि कोई औपचारिक अनुरोध नहीं किया गया था

द्वारा घोषित कानूनी स्थिति पर पुनर्विचार के लिए यह न्यायालय प्रथम न्यायाधीशों के मामले में यह न्यायालय। फिर भी, यह न्यायालय अपने आप में

प्रस्ताव, प्रथम न्यायाधीशों के मामले की शुद्धता की जांच की,

और स्वतः संज्ञान लेते हुए, नौ न्यायाधीश को मामले का संदर्भ दिया। पीठ, प्रथम न्यायाधीशों के मामले में घोषित कानून पर पुनर्विचार करने के लिए।

46. द्वितीय न्यायाधीशों के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर पुनर्विचार करने के कारणों की ओर इशारा करते हुए

बहुमत के दृष्टिकोण से नजरअंदाज किया गया। विद्वान वरिष्ठ वकील, तदनुसार, अनुच्छेद 124 (2) की योजना की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया।

और निम्नलिखित मुख्य विशेषताओं का प्रचार और सारांश किया

वहाँ से उभर रहा है:

"आई. उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार

ii. राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की उपरोक्त शक्ति थी, केवल एक शर्त के अधीन, अर्थात् 'परामर्श'।

iii. उपरोक्त परामर्श दो प्रकार का था-एक जिसे राष्ट्रपति की राय में आवश्यक माना जा सकता है,

और दूसरा जो अनिवार्य था।

iv. अनिवार्य परामर्श मुख्य न्यायाधीश के साथ था।

भारत से। राष्ट्रपति द्वारा किया जाने वाला परामर्श 'यदि इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझा जाता है, तो न्यायाधीशों के साथ था

उच्चतम न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालयों का भी,

जैसा उचित महसूस किया जा सकता है।

वी. शक्ति, दायरा और दायरे की कोई सीमा नहीं थी।

राष्ट्रपति के परामर्श में शामिल होने के लिए, वह केवल नहीं हो सकता है

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं से भी परामर्श कर सकते हैं-ऑन-रिकॉर्ड

समाज v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, जो वे इसके लिए आवश्यक समझें,

vi. कोई सीमा भी नहीं थी

उद्देश्य। राष्ट्रपति की परामर्श की शक्ति। वे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जितने न्यायाधीश हों, उनसे परामर्श कर सकते थे।

उन्होंने इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझा।

vii. उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए

इस तरह की नियुक्ति उच्चतम न्यायिक कार्यालय में थी गणतंत्र, स्पष्ट रूप से व्यापक होने का इरादा था,

संवादात्मक, सूचनात्मक और सार्थक, ताकि सबसे उपयुक्त उम्मीदवार की नियुक्ति की जा सके।

viii. परामर्श की शक्ति का यह पहलू

राष्ट्रपति, जैसा कि पूरी तरह से प्रदान किया गया था द्वितीय न्यायाधीशों के मामले में बहुमत के फैसले में अनदेखी की गई।

और ध्यान केवल परामर्श तक ही सीमित रहा है,

भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ। ix. परामर्श प्रक्रिया की व्याख्या, और

में बहुमत निर्णय में निर्धारित प्रक्रिया

द्वितीय न्यायाधीशों का मामला, कि राष्ट्रपति की शक्ति परामर्श, सर्वव्यापी था 'सीमित' किया गया था,

अनुच्छेद 458 में इस प्रकार स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है (न्याय द्वारा)

जे. एस. वर्मा) द्वितीय न्यायाधीशों के मामले में।

x. बहुमत का निर्णय केवल इस पर केंद्रित है कि

राष्ट्रपति द्वारा प्रमुख के साथ परामर्श की आवश्यकता भारत का न्याय जो परंतुक की आवश्यकता है, अनदेखा करना

मूल भाग।

xi. परामर्श के लिए कॉलेजियम प्रणाली विकसित की गई थी

भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के उद्देश्य, अकेले सी. जे. आई. एक व्यक्ति के रूप में मायने नहीं रखेगा, लेकिन

इसका अर्थ बहुलता में अर्थात् उसका कॉलेजियम है। लेकिन यह एक

केवल परंतुक की व्याख्या और मूल की नहीं

अनुच्छेद 124 (2) का भाग।

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शी कॉलेजियम प्रणाली के साथ परामर्श के लिए विकसित किया गया था

सीजेआई और उनके सहयोगी विशेष रूप से निश्चित संख्या में

जैसा कि निर्णय में निर्धारित किया गया है।

xiii. राष्ट्रपति द्वारा परामर्श के लिए पूरा प्रावधान

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ भारत का

अदालत, इस प्रकार की अज्ञानता में, स्तब्ध कर दिया गया था

अनुच्छेद 124 (2) का मूल भाग, और इस तरह, एक था

बहुमत के फैसले पर सवाल उठाने के लिए विवश प्रति

इनक्यूरियम "।

47. विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार,

सुभाष शर्मा मामले के फैसले से पता चलेगा कि

प्रथम न्यायाधीशों के मामले में निर्णयों पर पुनर्विचार किया गया था
पहले, स्थिति और महत्व

केवल दो मुद्दों पर। सबसे

परामर्श, और मुख्य न्यायाधीश के पद की प्रधानता
निर्धारण की न्याय्यता।

भारत से। और दूसरी बात, न्यायाधीश के

न्यायालय की शक्ति। यह दावा किया गया था कि कोई अन्य मुद्दा नहीं था

पुनर्विचार के लिए संदर्भित। इस दावे की मांग की गई थी

निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ समर्थित, में देखा गया

सुभाष शर्मा मामला 1:

" 49. इसी तरह सुभाष द्वारा दायर रिट आवेदन

ऊपर बताए गए कारणों के लिए शर्मा भी हो सकते हैं
आगे के निर्देशों के बिना निपटाया गया। कब और कैसे

आवश्यक मामला अदालत के समक्ष लाया जा सकता है। के रूप में हमारी राय में एस. पी. में बहुमत के दृष्टिकोण की शुद्धता। गुप्ता मामला [(1981) सप. एस. सी. सी. 871 पर विचार किया जाना चाहिए एक बड़ी पीठ द्वारा हम डब्ल्यू. पी. संख्या 1303 के कागजात का निर्देश देते हैं 1987 विद्वान मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखे जाने के लिए दोनों की जांच करने के लिए नौ न्यायाधीशों की एक पीठ का गठन जिन प्रश्नों का हमने ऊपर उल्लेख किया है, अर्थात् स्थिति प्रधानता के संदर्भ में भारत के मुख्य न्यायाधीश और, दूसरा, न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने की न्याय्यता। यह दावा किया गया था कि इसके लिए कोई गुंजाइश या अवसर नहीं था दूसरे न्यायाधीशों के मामले की सुनवाई करने वाली पीठ ने फिर से लिखा संविधान, सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय पर-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।] उच्च न्यायपालिका। यह प्रस्तुत किया गया था कि टिप्पणियाँ विद्वान वकील के अनुसार, घोषणा तक सीमित था कानूनी स्थिति की, केवल दो मुद्दों पर, संदर्भित विचार के लिए बड़ी बेंच। इस प्रकार देखा गया, यह दावा किया गया था, कि दूसरे न्यायाधीशों के मामले में दर्ज अन्य सभी निष्कर्ष, पुनर्विचार, वैध रूप से बाध्यकारी के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता अनुच्छेद 141 के तहत कानून। उपरोक्त विवाद का समर्थन करने के लिए, निर्भरता केरल राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संग्रहालय में रखा गया था वी. रामबल Co. 18 18, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"8. यह काफी अच्छी तरह से तय किया गया है कि जब एक पर संदर्भ दिया जाता है किसी विद्वान एकल न्यायाधीश या प्रभाग द्वारा विशिष्ट मुद्दा

किसी वृहत न्यायपीठ की न्यायपीठ, अर्थात् खंड न्यायपीठ या पूर्ण न्यायपीठ या संविधान न्यायपीठ, जो भी मामला हो,

पीठ किसी ऐसे मुद्दे पर निर्णय नहीं ले सकती है जो

भारत [(1981) पूरका एस. सी. सी. 38], समरेश चंद्र बोस बनाम।
जिला मजिस्ट्रेट, बर्दवान [(1972) 2 एस. सी. सी. 476] और के. सी. पी.

लिमिटेड वी. स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। भारत का [(1995) सपा (3) एससीसी
466]। "

48. विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि दूसरे में

न्यायाधीशों का मामला, इस न्यायालय ने एक अभिनव अर्थ सौंपा

"भारत के मुख्य न्यायाधीश" शब्द, यह अभिनिर्धारित करते हुए कि अनुच्छेद 124 में "भारत के मुख्य
न्यायाधीश" शब्द में न्यायाधीशों की बहुलता शामिल है,

और भारत के व्यक्तिगत मुख्य न्यायाधीश नहीं। इसके अनुसार

विद्वान परामर्श के लिए, के सादे अर्थ और पाठ के खिलाफ था
आगे कहा कि यह न्यायालय

अनुच्छेद 124। विद्वान वकील ने

वरिष्ठता, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए। यह भी।
के लिए निर्धारित नियम और मानदंड और

न्यायाधीशों के स्थानांतरण

18 (2006) 6 एस. सी. सी. 258 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

निष्कर्ष निकाला कि किसी न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश का कोई स्थानांतरण
मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर बनाया गया

उच्च न्यायालय,

भारत का, गैर-दंडात्मक माना जाएगा। कुल मिलाकर और

विद्वान वकील ने तर्क दिया कि दूसरा

न्यायाधीशों के मामले में, एक नई संरचना निर्धारित की गई,

वकील, जिसे केवल न्यायिक के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है
गया था कि यह कुछ भी कम नहीं था

व्याख्या। यह दावा किया

न्यायिक सक्रियता (या, न्यायिक विधान)।

49. विद्वान वरिष्ठ वकील ने तब न्यायालय को आमंत्रित किया

पुनर्विचार के लिए निर्धारित सिद्धांतों पर ध्यान देना, या

पिछले निर्णय की समीक्षा। इसके लिए उन्होंने स्पष्ट रूप से आमंत्रित किया
बंगाल प्रतिरक्षा कंपनी लिमिटेड बनाम पर न्यायालय का ध्यान। की स्थिति

बिहार 19, मगनलाल छगनलाल (पी) लिमिटेड बनाम। नगर निगम। में से ग्रेटर बॉम्बे 20, और
भारत संघ बनाम। रघुवीर सिंह 21.

विद्वान वकील ने प्रदीप कुमार विश्वास बनाम का भी उल्लेख किया।

भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान 22, जिसमें यह देखा गया:

" 61. क्या सभाजीत तिवारी (1975) 1 एस. सी. सी. 485. अभी भी खड़ा होना चाहिए?

तथ्यों पर भी एक प्राधिकरण के रूप में केवल इसलिए कि यह है

25 साल तक खड़े रहे? हम नहीं सोचते हैं। समानताएँ खींची जा सकती हैं

यहां तक कि उन तथ्यों पर भी जो एक असमर्थनीय व्याख्या की ओर ले जाते हैं

अनुच्छेद 12 और इसके लाभों का परिणामी इनकार
उन व्यक्तियों के लिए मौलिक अधिकार जो अन्यथा

उनका अधिकार है और

" [टी] यहाँ हमारे संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें रोकता है

यदि हम आश्वस्त हैं तो पिछले निर्णय से हटने से

इसकी त्रुटि और सामान्य हितों पर इसके हानिकारक प्रभाव का

जनता "। [बंगाल इम्युनिटी कं. लिमिटेड बनाम बिहार राज्य, आकाशवाणी

1955 एससी 661,672) (एआईआर पी। 672, पैरा 15)

19 (1955) 6 एससीआर 603

20 (1974) 2 एस. सी. सी. 402

21 (1989) 2 एस. सी. सी. 754 सर्वोच्च अदालतें-चालू-रिकॉर्डसमाज v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

चूंकि प्रश्न की पुनः जांच करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि निर्णय स्पष्ट रूप से गलत था।

यह हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसा कहें और अपनी गलती को कायम न रखें।

यह इंगित किया गया था कि द्वितीय न्यायाधीशों के मामले में एस.एवल पांडियन, जे. ने निम्नलिखित टिप्पणी
की थी:

" 17. इसलिए यह बड़े पैमाने पर उच्च न्यायालयों पर पड़ता है।

क्षमता और क्षमता का पता लगाने की जिम्मेदारी

बिना इस महान राष्ट्र के लोगों की जरूरतों की सेवा करें अपनी आवश्यक विशेषताओं और बुनियादी सिद्धांतों का त्याग करना जो भारतीय लोकतंत्र की जड़ में निहित हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में,

हमारा मुख्य उद्देश्य संविधान को सशक्त बनाना होना चाहिए।

रहस्य और रहस्य को दूर करके समझा जा सकता है

जो इसके चारों ओर फैलता है और स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित करता है

संवैधानिक प्रणाली और योजना के काम करने की वास्तविकता पर ताकि न्याय वितरण प्रणाली बनाई जा सके

अप्रत्याशित और यह न्यायालय आम तौर पर नहीं चाहेगा उन मुद्दों को फिर से खोलें जो समाप्त हो गए हैं, यह अब तक ठीक है

न्यायिक घोषणाओं की एक पंक्ति द्वारा तय किया गया है कि यह है

जोरदार रूप से प्रांत और वरिष्ठ का आवश्यक कर्तव्य अदालतें अपने पहले के फैसलों की समीक्षा या पुनर्विचार करें, यदि ऐसा है तो

बाध्यकारी परिस्थितियों में और यहाँ तक कि

किसी भी संदिग्ध निर्णय को पूरी तरह या आंशिक रूप से रद्द कर दें, यदि

यह गलत तरीके से अभिनिर्धारित किया गया था और किसी भी निर्णय का आनंद नहीं लिया गया था

संवैधानिक या कानूनी व्याख्या के नए दृष्टिकोण पर न्यायिक समीक्षा या पुनर्विचार से पूर्ण प्रतिरक्षा।

और नवीन विचारों के विकास के आलोक में,

के पारित होने के साथ-साथ सिद्धांत और धारणा बड़ी

समय। यह शक्ति चौकोर और सीधे रूब्रिक के भीतर आती है।

न्यायिक समीक्षा या पुनर्विचार "।

1 2) 5 एस. सी. सी. 111 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

यह प्रस्तुत किया गया था कि कुलदिप सिंह, जे., दूसरे में

न्यायाधीशों का मामला इस प्रकार दर्ज किया गया था:

" 320. इसमें कोई संदेह नहीं है कि टकटकी लगाने का नियम सही है। स्थिरता और एकरूपता लाता है लेकिन साथ ही

समय यह अनम्य नहीं है। क्या इसका पालन किया जाना है

मामला दिया गया है या नहीं, यह पूरी तरह से विवेकाधिकार के भीतर एक सवाल है

पहले से तय किए गए प्रश्न पर पुनर्विचार करने के लिए कहा गया है। न्यायालय ने उचित मामलों में अपने पहले के फैसले को रद्द कर दिया है।

निर्णय लेते हैं। परीक्षण और त्रुटि की प्रक्रिया, सबक

अनुभव और बेहतर तर्क की शक्ति इस न्यायालय को बनाती है

अपने न्यायिक कामकाज में बुद्धिमान। महत्वपूर्ण मामलों में

बुद्धिमान जीवन की सामान्य प्रक्रियाओं के बीच। हमारे पास है। पूर्व निर्माण पर पुनर्विचार करने से परहेज नहीं किया

संविधान का जो "सिद्धांत रूप में अनुचित" साबित हुआ है

और व्यवहार में अव्यवहारिक "।

74. क्योंकि दूसरे न्यायाधीशों के मामले ने गंभीर बना दिया था राष्ट्रपति की शक्ति में प्रवेश जो अनुच्छेद 74 के अनुरूप प्रयोग करने के लिए बाध्य था। यह तर्क दिया गया था,

कि राष्ट्रपति का कार्य, मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अभाव में, केवल नहीं हो सकता है

संविधान की योजना के तहत कल्पना की गई। और इसलिए,

परिषद की सहभागी भूमिका का प्रतिस्थापन

मंत्री (या, संबंधित मंत्री), मुख्यमंत्री के साथ

सर्वोच्च न्यायालय

अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

उनके कॉलेजियम के साथ मिलकर जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। और दूसरा, कि प्रथम न्यायाधीशों का मामला था,

गलत तरीके से खारिज किया गया, और नियुक्ति के लिए सही कानून

कार्यपालिका की भूमिका के संबंध में न्यायाधीशों को सही ढंग से रखा गया था।

प्रथम न्यायाधीशों के मामले में, विधिवत संरक्षित करके "न्यायपालिका की स्वतंत्रता"। यह प्रस्तुत किया गया था, कि संदर्भ

एक बड़ी बेंच के लिए अपरिहार्य था, क्योंकि यह खुला नहीं था उत्तरदाताओं, उपरोक्त प्रस्तुति का प्रचार करने के लिए, एक

पाँच-न्यायाधीश पीठ "।

50. श्री हरीश एन. साल्वे और श्री टी. आर. अंधारुजिना, विद्वान वरिष्ठ वकील ने अदालत को अलग से संबोधित किया। उनके हालाँकि प्रस्तुतियाँ समान थीं। यह उनका तर्क था, कि एक संवैधानिक न्यायालय संवैधानिक मुद्दों पर पुनर्विचार करता है, से समय-समय पर। विद्वान वकील के अनुसार, यह होना चाहिए किया क्योंकि संविधान एक जीवित दस्तावेज है, और परिवर्तन के साथ तालमेल रखने के लिए इसे फिर से स्थापित करने की आवश्यकता है समय. यह प्रस्तुत किया गया था कि यह अन्य लोगों के लिए सच नहीं हो सकता है कानून की शाखाएँ, जिनमें निर्णयों पर पुनर्विचार नहीं किया जाता है, क्योंकि न्यायालयों से स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से पालन करने की अपेक्षा की जाती थी से निपटने वाले कानूनों के संदर्भ में टकटकी निर्णय का सिद्धांत निजी अधिकारों के साथ। जहाँ तक हाथ में विवाद है संबंधित, यह प्रस्तुत किया गया था कि द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष इस न्यायालय ने दूसरे और तीसरे न्यायाधीशों के मामलों में संकेत दिया, संदिग्ध निष्कर्ष, क्योंकि बड़ी संख्या में मुख्य तथ्य (जैसा कि ऊपर दर्ज किया गया है), में नहीं लिया गया था विचार करें। यह प्रस्तुत किया गया था, कि एक में समीचीनता हाथ में विवाद की तरह, पक्ष में होना चाहिए कानून का विकास। यह प्रस्तुत किया गया था कि उनके विचार में यह एक था ऐसा मामला, जिसमें इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मुद्दा द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों के मामलों की फिर से जांच करने की आवश्यकता है एक बड़ी पीठ का संदर्भ देकर। सीखा हुआ परामर्श इंगित किया कि विभिन्न याचिकाओं में की गई प्रस्तुतियाँ

इस न्यायालय के समक्ष दायर किया गया, किसी भी पाठ द्वारा समर्थित नहीं था।
संवैधानिक प्रावधान, लेकिन केवल कानूनी स्थिति [2015] 13 एस. सी. आर. पर निर्भर था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उपरोक्त दो मामलों में इस न्यायालय द्वारा घोषित। इस तरह के एक महत्वपूर्ण विवाद में, विद्वान वकील के अनुसार, यह न्यायालय

अपने पिछले निर्णयों पर पुनर्विचार करने में संकोच नहीं करना चाहिए। श्री.

अंधारुजिना ने एक सवाल पूछा, अर्थात्, क्या हम तय कर सकते हैं

वर्तमान मामले में उठाया गया विवाद, बिना द्वितीय और तृतीय के निर्णयों पर पुनर्विचार

न्यायाधीशों के मामले? उन्होंने एक अन्य प्रश्न के माध्यम से इसका उत्तर दिया, न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीशों द्वारा कैसे की जा सकती है? उपरोक्त

स्थिति को फिर से अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया था, एक और आगे रखते हुए

प्रश्न, कार्ट प्रधानता में भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ आराम

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला?

51. श्री अजीत कुमार सिन्हा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता,

उनके तर्क का समर्थन, कि मामले की सुनवाई की आवश्यकता है

एक बड़ी पीठ द्वारा, खनिज क्षेत्र पर निर्भरता रखी गई

विकास प्राधिकरण बनाम। भारतीय इस्पात प्राधिकरण 23, और आमंत्रित

प्रश्न संख्या पर हमारा ध्यान। 5 इसके द्वारा दिए गए संदर्भ का

न्यायालय:

"5. क्या राज्य में बहुमत का निर्णय डब्ल्यू. बी. बनाम. केसोरम इंडस्ट्रीज लिमिटेड [(2004) 10 एस. सी. सी. 201] हो सकता है

सात में निर्धारित कानून से प्रस्थान के रूप में पढ़ें

इंडिया सीमेंट लिमिटेड बनाम में न्यायाधीश पीठ का निर्णय। की स्थिति

टी. एन. [(1990) 1 एस. सी. सी. 12]?

यह इंगित किया गया था कि उपरोक्त प्रश्न इस प्रकार था

फ्रेम किया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल राज्य बनाम। केसोरम इंडस्ट्रीज

Ltd. 24, यह न्यायालय 4 के बहुमत से: 1 फैसले को स्पष्ट किया था इंडिया सीमेंट लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ द्वारा प्रस्तुत। तमिलनाडु राज्य 2 5. इस न्यायालय को उपरोक्त रूपरेखा तैयार करनी थी

प्रश्न करें, और मामले को नौ-न्यायाधीशों की पीठ को भेजें। लीम्ड। वकील, फिर न्यायिक उप-समिति पर भरोसा रखा

उत्तरदायित्व v. भारत संघ 26, जिसमें इस न्यायालय ने

निम्नलिखित रूप में देखा गया:

23 (2011) 4 एससीसी 450

24 (2004) 10 एस. सी. सी. 201

25 (1990) 1 एससीसी 12

26 (1992) 4 एस. सी. सी. 97 सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. 1. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

"5. भले ही प्रार्थना की जाँच की जाती है जैसे कि यह एक था

स्वतंत्र मूल कार्यवाही, जिसके लिए उपयुक्त परीक्षण ऐसी स्थिति से यह अनुदान भी नहीं मिलेगा।

अनुमेय राहत। इसके अनुदान के विरुद्ध विचार

प्रार्थना स्पष्ट और सम्मोहक होती है। वास्तव में, कोई समन्वय नहीं

इस न्यायालय की पीठ इस पर टिप्पणी भी कर सकती है। अकेले बैठने दें।

निर्णय में, विवेक का प्रयोग या निर्णय

किसी अन्य समन्वय के समक्ष किसी कारण या पदार्थ में प्रस्तुत किया गया बेंच।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह तर्क दिया गया था कि यह न्यायालय

हाथ में विवाद के गुणों की जांच करते हुए, था

ऊपर वर्णित स्थिति, यह प्रस्तुत की गई थी कि यह न्यायालय मुद्दों पर प्रभावी ढंग से निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होना

प्रचार किया गया, जब तक कि मामला नौ न्यायाधीशों की पीठ को नहीं भेजा गया

(या यहाँ तक कि, एक और भी बड़ी बेंच)।

52. श्री रंजीत कुमार, भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल

प्रस्तुत किया, कि वह एक के संदर्भ के लिए दावे का समर्थन करेगा वृहद न्यायपीठ, दो निर्णयों पर भरोसा करके, और अधिक नहीं कहें। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने बंगाल इम्युनिटी पर निर्भरता रखी

कं. लिमिटेड मामला 1919, जिसे इंगित किया गया था, ने विचार किया था

बॉम्बे राज्य बनाम में निर्णय। यूनाइटेड मोटर्स (भारत) Ltd.²⁷

यह मामला, प्रस्तुत किया गया था, जिसे सात के पास भेजा गया था

न्यायाधीश पीठ, यह तय करने के लिए कि क्या निर्णय की आवश्यकता है

पुनर्विचार किया गया। विद्वान वकील के अनुसार यह प्रक्रिया सामान्य तौर पर, वर्तमान विवाद में इसे अपनाने की आवश्यकता है

ठीक है, ताकि पिछले निर्णयों पर एक नया निर्णय लिया जा सके।

विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने फिर केशव पर भरोसा रखा

मिल्स कं. लिमिटेड बनाम आय-कर आयुक्त, बॉम्बे उत्तर 28,

जिसमें सात न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"इस सवाल से निपटने में कि क्या पहले

27 (1953) एससीआर 1069

28 (1965) 2 एससीआर 908 [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यू जहांगीर मिल्स मामले में इस न्यायालय के निर्णय,

(1960) 1 एस. सी. आर. 249 और पेटलैड कंपनी लिमिटेड मामला, (1963)

सप. एस. सी. आर. 871 पर पुनर्विचार और संशोधन किया जाना चाहिए

हम, हमें उस दृष्टिकोण के बारे में स्पष्ट होना चाहिए जो होना चाहिए

ऐसे मामलों में अपनाया जाना चाहिए। श्री पालखीवाला ने विवाद नहीं किया है

तथ्य यह है कि, एक उचित मामले में, इस न्यायालय में अंतर्निहित है

अपने पहले के निर्णयों पर पुनर्विचार और संशोधन करने का अधिकार क्षेत्र,

और इसलिए, अमूर्त प्रश्न है कि क्या ऐसी शक्ति है इस न्यायालय में निहित है या हमें हिरासत में लेने की आवश्यकता नहीं है। व्यायाम में

यह अंतर्निहित शक्ति, हालांकि, यह स्वाभाविक रूप से पसंद करेगी

कुछ उचित सीमाएँ अधिरोपित करें और

पुनर्विचार के लिए याचिकाओं पर विचार करने के लिए अनिच्छुक और

अपने पहले के निर्णयों का संशोधन, जब तक कि यह संतुष्ट न हो कि

ऐसा करने के लिए सम्मोहक और ठोस कारण हैं। यह है।

सामान्य न्यायिक अनुभव जो कानून के मामलों में शामिल है

जब न्यायिक दृष्टिकोण को दोनों के बीच चुनाव करना होता है दो उचित रूप से संभव विचार, निर्णय की प्रक्रिया

बनाना अक्सर बहुत कठिन और नाजुक होता है। जब यह न्यायालय

उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई करता है और है

दृष्टिकोण की औचित्य या शुद्धता पर विचार करने की आवश्यकता है

कानून के किसी भी बिंदु पर उच्च न्यायालयों द्वारा लिया गया, यह होगा इस न्यायालय के लिए यह अभिनिर्धारित करने के लिए खुला है कि हालांकि द्वारा लिया गया दृष्टिकोण

उच्च न्यायालय उचित रूप से संभव है, वैकल्पिक दृष्टिकोण

जो उचित रूप से भी संभव है वह बेहतर है और होना चाहिए

पसंद किया जाता है। ऐसे मामले में, विकल्प दृश्य के बीच है।

उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया जिसका निर्णय अपील के अधीन है,

और वैकल्पिक दृष्टिकोण जो इस न्यायालय को प्रतीत होता है

अधिक उचित: और अपने स्वयं के दृष्टिकोण को स्वीकार करने में

उच्च न्यायालय की वरीयता, यह न्यायालय होगा अपील न्यायालय के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करना। लेकिन अलग-अलग विचार अनिवार्य रूप से उत्पन्न होने चाहिए जहां एक पूर्ववर्ती

इस न्यायालय के निर्णय ने एक विशेष दृष्टिकोण लिया है कि

उदाहरण के लिए, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड के रूप में एक वैधानिक प्रावधान का निर्माण

समाज v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

एस. 66 (4) अधिनियम से। जब यह आग्रह किया जाता है कि दृश्य पहले से ही इस न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय की समीक्षा और संशोधन किया जाना चाहिए, यह और यह मानने के लिए संशोधन कि हालांकि पहले का दृष्टिकोण एक है उचित रूप से संभव दृष्टिकोण, वैकल्पिक दृष्टिकोण जो है

बाद के अवसर पर दबाया जाना अधिक उचित है।

अपने पहले के फैसले की समीक्षा और संशोधन करते हुए, यह न्यायालय स्वयं से पूछना चाहिए कि क्या यह सार्वजनिक हित में है या नहीं।

किसी भी अन्य वैध और बाध्यकारी कारणों के लिए, यह आवश्यक है कि पहले के निर्णय को संशोधित किया जाना चाहिए। जब यह न्यायालय

भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी, और इसलिए, यह इस न्यायालय का निरंतर प्रयास और चिंता होनी चाहिए।

निश्चितता के एक तत्व को प्रस्तुत करना और बनाए रखना और देश में कानून की व्याख्या में निरंतरता। अक्सर इस न्यायालय द्वारा अपनी पूर्व की समीक्षा करने की अपनी शक्ति का प्रयोग

इस आधार पर निर्णय कि विचार उसके सामने दबाया गया था

बाद में न्यायालय को अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है, हो सकता है

संयोग से कानून को अनिश्चित बना देता है और लागू करता है भ्रम जिसे लगातार टाला जाना चाहिए। ऐसा नहीं है।

यह कहने के लिए कि यदि बाद के अवसर पर, न्यायालय है

इस बात से संतुष्ट है कि इसका पहले का निर्णय स्पष्ट रूप से गलत था त्रुटि को सुधारने में संकोच करना चाहिए: लेकिन इससे पहले

निर्णय को स्पष्ट रूप से गलत घोषित किया जाता है, न्यायालय

के बीच उचित मात्रा में सर्वसम्मति से संतुष्ट होना चाहिए

इसके सदस्य यह मानते हैं कि उक्त दृष्टिकोण का संशोधन पूरी तरह से उचित है।

यह संभव या वांछनीय नहीं है, और किसी भी मामले में यह होगा

शासन करने वाले किसी भी सिद्धांत को निर्धारित करने के लिए अक्षम

के प्रश्न से निपटने में न्यायालय का दृष्टिकोण

अपने पहले के निर्णयों की समीक्षा और संशोधन करना। यह हमेशा होगा।
विचारों पर निर्भर करता है: क्या है?

यह कई प्रासंगिक

दुर्बलता या त्रुटि की प्रकृति जिस पर एक याचिका

पहले के दृष्टिकोण की समीक्षा और संशोधन आधारित है? इससे पहले के अवसर पर, क्या प्रश्न के कुछ पेटेंट
पहलू थे किसी का ध्यान नहीं गया, या अदालत का ध्यान नहीं गया

+ [2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

किसी भी प्रासंगिक और भौतिक वैधानिक प्रावधान के लिए, या कोई था

इस न्यायालय का पिछला निर्णय इस बिंदु पर नहीं ध्यान दिया? क्या इस तरह की याचिका पर
सुनवाई करने वाला न्यायालय काफी सर्वसम्मत है?

कि पहले के दृश्य में ऐसी त्रुटि है? क्या होगा?

कानून के सामान्य प्रशासन पर या सार्वजनिक भलाई पर त्रुटि का प्रभाव हो? क्या पहले का निर्णय लिया
गया है

बाद के अवसरों पर या तो इस न्यायालय द्वारा या

महत्वपूर्ण तब होता है जब पहले का निर्णय सर्वसम्मत होता है इस न्यायालय के पाँच विद्वान
न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय।

टकटकी निर्णय का सिद्धांत, निस्संदेह, नहीं हो सकता है

न्यायालय अपने पहले के फैसलों पर पुनर्विचार और संशोधन करेगा
फिर भी, सामान्य सिद्धांत कि

आह्वान किया गया; लेकिन

इस न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय अंतिम होंगे, नहीं हो सकते

उपेक्षा की जाए, और जब तक कि एक महत्वपूर्ण और

सम्मोहक चरित्र ऐसा करना आवश्यक बनाता है, यह न्यायालय

इसकी समीक्षा और संशोधन करने के लिए अनिच्छुक होना चाहिए और होगा

निर्णय लेते हैं। यह, मोटे तौर पर कहा गया है, वह दृष्टिकोण है जो हम

विद्वान महान्यायवादी ने कहा कि इसके पहले के निर्णय
(1960) 1 एस. सी. आर. 249

न्यू जहांगीर मिल्स गैस में न्यायालय,

और पेटलैड कंपनी लिमिटेड मामला, (1963) सप. 1 एससीआर 871,

इस पर पुनर्विचार और संशोधन किया जाना चाहिए। आइए फिर हम एस को समझने के सवाल पर विचार करें। 66 (4) में से

अधिनियम। ऐसा करने से पहले, उप-खंड को पढ़ना आवश्यक है

(1), (2) और (4) एस। 66. धारा 66 (1) इस प्रकार है: —

"जिस तारीख को उसे सेवा दी जाती है, उसके साठ दिनों के भीतर

धारा 33 की उप-धारा (4) के तहत किसी आदेश की सूचना,

निर्धारिती या आयुक्त, सर्वोच्च न्यायालय-चालू-रिकॉर्ड संगठन v में आवेदन द्वारा आवेदन कर सकते हैं।

यू. ओ. आई. /जगदीश सिंह खेहर, जे. जे.

निर्धारित प्रपत्र, जिसके साथ आवेदन किया जाता है

निर्धारिती को एक सौ रुपये के शुल्क से,

अपीलीय न्यायाधिकरण किसी भी प्रश्न को उच्च न्यायालय को भेजेगा

ऐसे आदेश से उत्पन्न होने वाली विधि की, और अपीलीय न्यायाधिकरण ऐसे आवेदन की प्राप्ति के नब्बे दिनों के भीतर

मामले का एक बयान तैयार करें और इसे उच्च न्यायालय को भेजें
अदालत "।

उपरोक्त के आधार पर, विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक और कानूनी स्थिति के आधार पर यह दावा किया गया था

जनरल, कि इस न्यायालय द्वारा द्वितीय में घोषित स्थिति

न्यायाधीशों का मामला, और तीसरे न्यायाधीशों के मामले में भी, स्पष्ट रूप से था

गलत है। यह प्रस्तुत किया गया था कि उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए इस न्यायालय द्वारा विकसित प्रक्रिया

बुरी तरह से विफल, किसी भी दोष के कारण नहीं

निर्धारित प्रक्रिया की स्वतंत्रता, लेकिन क्योंकि

"न्यायाधीशों की अंतर-निर्भरता", जिन्होंने भाग लिया

न्यायाधीशों के कॉलेजियम में निहित जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए निश्चित रूप से एक पुनः परीक्षा की आवश्यकता थी।

53. यह अग्रिम प्रस्तुतियों से स्पष्ट है

भारत संघ और विभिन्न राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकीलों के हाथ, जो चुनने के बजाय

संविधान (99 वां संशोधन) अधिनियम की संवैधानिक वैधता के संदर्भ में किए गए दावों का जवाब देने के लिए, 2014 और एन. जे. ए. सी. अधिनियम ने सामूहिक रूप से प्रचार किया था कि

वर्तमान पाँच-न्यायाधीश पीठ को वर्तमान विवाद को संदर्भित करना चाहिए

नौ या अधिक न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय के लिए, जो

उपरोक्त पर विचार करते हुए, हमारा विचार है कि इस न्यायालय द्वारा सुराज इंडिया ट्रस्ट में दर्ज की गई टिप्पणियाँ

मामला 15, साथ ही यह तथ्य कि यह इस न्यायालय के समक्ष लंबित है, महत्वहीन है। पल भर में परिणाम

हमारे द्वारा निर्धारित, उपरोक्त मामले के लिए उत्तरदायी होगा

तत्काल निर्णय के संदर्भ में निपटाया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

IV. याचिकाकर्ताओं द्वारा, आंदोलन के लिए उद्देश्य

समीक्षा के लिए:

54. श्री फली एस. नरीमन ने इस सुझाव से असहमति जताई।

कि हाथ में विवाद, एक बड़े द्वारा तय किया जाना चाहिए

बेंच। यह उनका स्पष्ट निवेदन था कि इस मुद्दे का प्रचार किया गया

कुछ मुख्य बातों को नजरअंदाज करके अनुचित तरीके से दबाया गया था

विशेषताएँ, जिन्हें अनिवार्य रूप से ध्यान में रखा जाना था, इससे पहले कि एक बड़ी पीठ के संदर्भ के लिए अनुरोध किया जा सके

उत्तेजित हो जाते हैं। यह प्रस्तुत किया गया था कि सभी विद्वान वकील

उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए इस तथ्य की अनदेखी की गई थी कि

संविधान के अनुच्छेद 124 की व्याख्या की गई थी

पहले मामले में, पहले मामले में सात न्यायाधीशों की पीठ द्वारा

जिसने द्वितीय न्यायाधीशों के मामले में निर्णय दिया। यह इंगित किया गया था कि पुनर्विचार के लिए प्रार्थना, जो कि विद्वान वकील के कहने पर की जा रही है

भारत संघ और विभिन्न भाग लेने वाले राज्यों ने स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य, क्योंकि इसके द्वारा घोषित कानूनी स्थिति

प्रथम न्यायाधीशों के मामले में न्यायालय पर पहले ही पुनर्विचार किया जा चुका था

एक बड़ी संविधान पीठ द्वारा द्वितीय न्यायाधीशों का मामला नहीं।

केवल यह दावा किया गया था कि जब कुछ संदेह उत्पन्न हुए

द्वितीय न्यायाधीशों के मामले में निर्णय के कार्यान्वयन के लिए अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति का संदर्भ दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप

मामले की पुनः जांच में, एक और के हाथों में

नौ-न्यायाधीश पीठ, जहाँ भारत संघ ने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया

पैराग्राफ 11 में इसका रुख इस प्रकार है:

"11. हम शुरुआत में बयान दर्ज करते हैं

महान्यायवादी कि (1) भारत संघ मांग नहीं कर रहा है

निर्णय की समीक्षा या पुनर्विचार

द्वितीय न्यायाधीशों का मामला और यह कि (2) भारत संघ

इस न्यायालय के उत्तरों को स्वीकार करें और उन्हें बाध्यकारी समझें

संदर्भ में दिए गए प्रश्न "। सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

यह प्रस्तुत किया गया कि इसके बाद, मामला फिर से था

जांच की गई और दूसरे में घोषित कानूनी स्थिति

न्यायाधीशों के मामले को फैसले द्वारा दोहराया और पुष्टि की गई

तीसरे न्यायाधीशों के मामले में प्रस्तुत। उपरोक्त पर आधारित

तथ्यात्मक स्थिति, विद्वान वकील ने एक स्थिति उठाई, अर्थात्, कैसे

दावा किया, कि सिर्फ इसलिए कि ऐसी प्रार्थना प्रतीत होती है एकमात्र रास्ता, उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वालों के लिए, वही

स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है।

55. विद्वान वरिष्ठ वकील ने बताया कि कानूनी

उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों के संबंध में स्थिति जांच की गई और घोषित किया गया, पहली बार, में

1981 में पहला न्यायाधीशों का मामला। यह प्रस्तुत किया गया था कि उपरोक्त

यदि इस न्यायालय का ध्यान समशेर सिंह मामले 11 की ओर आकर्षित किया जाता, तो निर्णय नहीं दिया जाता।

सुनवाई का क्रम, प्रथम न्यायाधीशों के मामले में। यह प्रस्तुत किया गया था,

कि प्रथम न्यायाधीशों के मामले में इस न्यायालय द्वारा घोषित स्थिति

पुनर्विचार करने की आवश्यकता थी, सुनवाई के दौरान महसूस किया गया था सुभाष शर्मा
मामले में। जाँच करते हुए

इस न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों का औचित्य, प्रथम में

न्यायाधीशों का मामला, मामले को विचार के लिए रखा गया था, इससे पहले

नौ न्यायाधीशों की पीठ। यह प्रस्तुत किया गया था कि सभी मुद्दे, जो अब उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील के हाथों उठाए गए हैं, इससे पहले प्रचार किया गया था

द्वितीय न्यायाधीशों के मामले की सुनवाई करने वाली पीठ। यह न्यायालय, दूसरे में न्यायाधीशों का मामला, स्पष्ट रूप से इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि पहले

प्रथम न्यायाधीशों के मामले में दिया गया निर्णय निर्धारित नहीं था

सही कानून। यह प्रस्तुत किया गया था कि कानूनी स्थिति थी

दूसरे न्यायाधीशों के मामले में 7 के बहुमत से घोषित किया गया: 2.

56. यह प्रस्तुत किया गया था कि दूसरे न्यायाधीशों के मामले में अल्पमत का विचार ए. एम. अहमदी और एम. एम. ने व्यक्त किया था।

पुंछी, जे. जे., (जैसे वे तब थे)। विद्वान वरिष्ठ वकील,

द्वितीय न्यायाधीशों में दर्ज टिप्पणियों को संदर्भित किया गया

एम. एम. पुंछी, जे. :

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 500. इस प्रकार एस. पी. गुप्ता का मामला, जैसा कि मैं इसे देखता हूँ, जहाँ तक जाता है

कार्यपालिका को व्यक्त विचारों को दरकिनार करने की अनुमति देना

प्रमुख द्वारा अस्वीकृति या गैर-सिफारिश भारत के न्यायाधीश, और उस मामले के लिए जब एक उच्च न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है

न्यायालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विचारों का न्याय करता है, अस्वीकार्य अवमूल्यन का कार्य है, जो भावना का उल्लंघन करता है

संविधान, जिसे वह अनुमोदित नहीं कर सकता है, क्योंकि यह एक

कार्यपालिका को अन्यायपूर्ण और अनुचित अतिरिक्त शक्ति।

मूल रूप से कल्पना नहीं की गई। इस तरह की शक्ति का विश्राम कार्यपालिका पूरी तरह से अनुचित और प्रकृति में होगी।

मनमानी शक्ति। संवैधानिक प्रावधानों की कल्पना है, जैसा कि यह करता है, बहुलता और पारस्परिकता, लेकिन केवल के बीच

संवैधानिक पदाधिकारी और अतिरिक्त में बिल्कुल नहीं वैध लोगों के प्रतिस्थापन में संवैधानिक।

इन दोनों कार्यकर्ताओं की तुलना उनके बच्चों से की जा सकती है।

पालना, अपनी आम माँ से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ -

संविधान। वे इसके माध्यम से एक-दूसरे को पहचानते हैं

जुड़ावा। इस प्रकार के प्रति अधिक दायित्व है

वह पेड़ जो सीधे फल देने के बजाय फल देता है।

फलों की जड़ों को नजरअंदाज करना व्यर्थ है।

पेड़ को। यह विचार कि दोनों कार्यकर्ताओं को एक-दूसरे से दूरी बनाए रखनी चाहिए, उल्टा है। द.

दोनों के बीच संबंध बनाए रखने की आवश्यकता है

अधिक विचार करें। XXX

XXX

XXX

503. एक सदियों पुराना बेकोनियन उदाहरण वर्णन करने के लिए दिया गया है

एक वादी के अदालत में आने की दुर्दशा मेरे सामने आती है

दिमाग। यह वर्णन किया गया था कि जब भेड़ें आश्रय के लिए दौड़ती थीं
से खुद को बचाने के लिए झाड़ी में, उसने खुद को पाया

बारिश और ओलावृष्टि

बाहर आने पर अपने ऊन से वंचित। के लिए एक ही भाग्य
भारत के मुख्य न्यायाधीश की संस्था। यहाँ यह बस परिणाम देता है
और विशुद्ध रूप से प्रभुत्व के परिवर्तन में। पोस्ट में-एस. पी. गुप्ता
इस अवधि में, केंद्र सरकार यानी कानून मंत्री और प्रधानमंत्री को एक प्रमुख स्थिति में पाया गया
और यहां तक कि उच्च न्यायपालिका में एक न्यायाधीश की नियुक्ति भी कर सकते थे-सर्वोच्च न्यायालय
अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन v.

यू. ओ. आई. /जगदीश सिंह खेहर, जे. जे.

द्वारा अस्वीकृत या अनुशंसित नहीं होने के बावजूद
भारत के मुख्य न्यायाधीश और इसी तरह भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा
राज्य उच्च न्यायालय। शायद केवल अपवाद ही किया जा सकता है
जब मुख्य न्यायाधीश अपनी अस्वीकृति पर जोर नहीं दे रहे थे
और गैर-प्रतिबद्ध था। उनका रुख निश्चित हो सकता है।
तब परिस्थिति को निहित सहमति के रूप में माना जाएगा। ये
निश्चित रूप से दुर्लभ मामले होंगे। अब उपरोक्त के स्थान पर
दो कार्यकारी प्रमुख प्रमुख पद पर आते हैं, पहला
संविधान के तहत परेशान होने में सक्षम नहीं है। यह.
एस. पी. गुप्ता मामले से बच गया, हालांकि एक कटे हुए रूप में, और
पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुआ है, जैसा कि अब किया जा रहा है।
एस. पी. गुप्ता में इस संबंध में सुधार की आवश्यकता थी, लेकिन
अपसरण नहीं। ”

ऊपर निकाली गई राय की ओर इशारा करते हुए, यह कहा गया था,
कि कार्यपालिका की सिफारिश को स्थगित करने की कार्रवाई
भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा बनाया गया (अस्वीकार करते हुए
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति)

अवमूल्यन के कार्य के लिए राशि ", के स्पिट का उल्लंघन संविधान "। उपरोक्त व्यवहार/अभिव्यक्ति के अनुसार,

कार्यपालिका को अन्यायपूर्ण और अनुचित शक्ति देगा, जो संविधान निर्माताओं द्वारा अभिप्रेत नहीं था। द.

न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि इस तरह की शक्ति का निहित होना

कार्यकारी, पूरी तरह से अनुचित होगा, और की प्रकृति में

मनमानी शक्ति। यह भी नोट किया गया कि इसके बाद न्यायालय ने कहा कि

प्रथम न्यायाधीशों के मामले में अपना निर्णय, विधि मंत्री और

प्रधानमंत्री को इस तरह की प्रमुख स्थिति में पाया गया,

कि वे उच्च न्यायपालिका में एक न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं, इसके बावजूद

उसका अस्वीकृत होना (या, तब भी जब वह नहीं था) भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा (और इसी तरह, [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रथम न्यायाधीशों के मामले के लेखकों और उक्त निर्णय में उस संबंध में सुधार की आवश्यकता थी। तदनुसार, यह विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क था कि

अल्पसंख्यक न्यायाधीशों ने भी यही भावना व्यक्त की थी

जैसा कि बहुमत द्वारा दर्ज किया गया था, प्रधानता के विषय पर अनुच्छेद 124, 217 के तहत विनियमित मामलों में न्यायपालिका

और 222।

57. यह प्रस्तुत किया गया था कि हाथ में मुद्दे की जांच की गई थी

प्रथम में दिए गए निर्णय पर फिर से विचार करें।

न्यायाधीशों का मामला, जब इस न्यायालय ने मामले की समीक्षा की दूसरे न्यायाधीशों का मामला। यह प्रस्तुत किया गया था कि तीसरे न्यायाधीश के मामले के निर्धारण के दौरान, तत्कालीन वकील

भारत के लिए जनरल ने पीठ को एक बयान दिया था कि भारत संघ, समीक्षा या पुनर्विचार की मांग नहीं कर रहा था

द्वितीय न्यायाधीशों के मामले में निर्णय। हालांकि,

इस न्यायालय द्वारा दी गई राय, एक संदर्भ के परिणामस्वरूप न्यायालय में प्रस्तुत किया गया

भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च

अनुच्छेद 143 बाध्यकारी नहीं है, फिर भी एक बयान दिया गया था कि भारत संघ ने स्वीकार किया था

भारत के लिए महान्यायवादी,

बाध्यकारी के रूप में, इस न्यायालय के प्रश्नों के उत्तर निर्धारित किए गए हैं

तीसरे में दिए गए निर्णय के अनुच्छेद 11 में अभिलिखित वकील के अनुसार, यह था

न्यायाधीशों का मामला। विद्वान वरिष्ठ

स्पष्ट रूप से भारत संघ के दायरे से परे, दूसरे और तीसरे न्यायाधीशों के मामलों पर फिर से विचार करने की मांग करना।

58. पूर्वगामी में व्यक्त स्थिति के अलावा

पैराग्राफ, यहां तक कि द्वारा घोषित कानूनी स्थिति के अनुसार

यह न्यायालय, यह भारत संघ और राज्य के लिए खुला नहीं था

सरकारें, इस न्यायालय से शुद्धता की जांच करने की मांग करती हैं

द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों में दिए गए निर्णय का पाठ्यक्रम केवल हो सकता है

मामले। यह प्रस्तुत किया गया था कि इस तरह

अपनाया गया, जब इसे सभी उचित संदेह से परे स्थापित किया गया था, तो सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

समाजीकरण। वी. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

कि पिछले निर्णय गलत थे। जहाँ तक

लेफ्टिनेंट कर्नल खजुर सिंह बनाम पर निर्भरता रखी गई। भारत संघ 29 जिन पर विद्वान वकील ने प्रकाश डाला

(7 न्यायाधीशों की पीठ),

निम्नलिखित:

“हमने भाषा पर गंभीरता से विचार किया है। कला की। 226 और इस न्यायालय के दो निर्णयों को संदर्भित किया गया है

ऊपर। हमारी राय है कि जब तक वहाँ स्पष्ट और नहीं हैं बाध्यकारी कारण, जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता है, हमें करना चाहिए

इन दोनों मामलों में दी गई व्याख्या से अलग नहीं

और वास्तव में पहले दी गई किसी भी व्याख्या से

इस न्यायालय का निर्णय, जब तक कि उचित राशि न हो

सर्वसम्मति कि पहले के निर्णय स्पष्ट रूप से गलत हैं।

यह न्यायालय तब तक नहीं होना चाहिए जब तक कि यह प्रदर्शित नहीं किया जाता है।

सभी उचित संदेह से परे कि उचित विचार-विमर्श और पूर्ण सुनवाई के बाद दिया गया इसका पिछला निर्णय गलत था

अपने पिछले फैसले पर वापस, विशेष रूप से एक संवैधानिक पर

मुद्दा "।

केशव मिल्स कंपनी लिमिटेड का भी उल्लेख किया गया।

मामला 28, जिसमें इस न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया

इसके अंतर्गत:

"यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि जिस दृष्टिकोण के लिए विद्वान

महान्यायवादी तर्क देते हैं कि यह एक उचित रूप से संभव दृष्टिकोण है।

हालांकि हमें यह जोड़ने के लिए जल्दबाजी करनी चाहिए कि जो दृश्य है

इस न्यायालय द्वारा अपने पहले के फैसलों में भी लिया गया है

उचित रूप से संभव है। उक्त पूर्व दृष्टिकोण यह रहा है कि

इस न्यायालय द्वारा कई अवसरों पर पालन किया गया है और

में संदर्भ कार्यवाहियों में प्रक्रिया को विनियमित किया

इस देश के उच्च न्यायालय इस निर्णय के बाद से

न्यू जहांगीर मिल्स, (1960) 1 एस. सी. आर. 249 में न्यायालय था

12 मई, 1959 को घोषित किया गया। इसके अलावा, यह कुछ हद तक उल्लेखनीय है कि पहले किसी निर्णय का उल्लेख नहीं किया गया है

हम जहाँ निर्माण के बारे में सवाल है

एस. 66 (4) विचार किया गया और पक्ष में निर्णय लिया गया
तौला गया

अटॉर्नी-जनरल का तर्क। ध्यान से

विवाद के पक्ष और विपक्ष जो रहे हैं

वर्तमान अवसर पर हमारे सामने दबाया गया, हम नहीं हैं
लिए बनाया गया है और

संतुष्ट है कि एक मामला समीक्षा के

नए जहांगीर के मामले में हमारे निर्णयों को संशोधित करें
कंपनी लिमिटेड (1963) सप.

मिल्स एंड द केस ऑफ द पेटलैड

1 एससीआर 871। यही कारण है कि हम सोचते हैं कि विवाद

श्री पालखीवाला द्वारा उठाए गए मुद्दे को बरकरार रखा जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप,

उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को खारिज कर दिया जाता है और

एक निर्देश के साथ मामला उच्च न्यायालय को वापस भेजा जाता है

न्यू जहांगीर मिल्स में दो प्रासंगिक निर्णय और पेटलैड कंपनी लिमिटेड "।

गंगा शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का उल्लेख करते हुए v. राज्य

आर प्रदेश 30, हमारा ध्यान निम्नलिखित की ओर आकर्षित किया गया था

पाँच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा अभिलिखित अभिदान:

" 28. हम कुछ आश्चर्यचकित हैं कि तर्क के बारे में

अधिनियम की अयोग्यता इस आधार पर कि वह इसके संबंध में है

एक नियंत्रित उद्योग 'घातक निर्णय के बावजूद बुरी तरह मर जाता है

इस न्यायालय के च। टीका रामजी मामला [1956] एस. सी. आर. 393।

देश में प्रबुद्ध मुकदमेबाजी नीति को स्वीकार करना चाहिए

संविधान द्वारा इस न्यायालय की घोषणाओं को अंतिम रूप देना।

न्यायपीठ जब तक कि विषय इस तरह के मौलिक का न हो

राष्ट्रीय जीवन या तर्क के लिए महत्व इतना स्पष्ट है

बाद के विचार के प्रकाश में गलत है कि यह बुद्धिमानी है

लगातार गलत होने के बजाय अंततः सही। टकटकी लगाएँ।

निर्णय लेना सुविधा का अनुष्ठान नहीं है, बल्कि एक सीमित नियम है।

अपवाद, संविधान पीठों द्वारा घोषणाएँ

इसे इतना बेपरवाह नहीं माना जाना चाहिए कि इसे संशोधित किया जाए
 अक्सर। हम इस अदालत के फैसलों का अवमूल्यन नहीं कर सकते।
 संक्षिप्त अल्पकालिकता जो व्यक्त की गई राय को याद करती है
 स्मिथ बनाम में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रॉबर्ट्स द्वारा।

0) 1 एस. सी. सी. 223 सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड
 एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]
 ऑलराइट 321 यू. एस. 649 669 पर (1944) "
 न्यायालय तेजी से उसी वर्ग में जा रहा था
 एक प्रतिबंधित रेल टिकट, इस दिन के लिए अच्छा है और केवल "ट्रेन"
 गैरन डंकरली पर भरोसा करते हुए सीखी गई सलाह
 और को. वी. राजस्थान राज्य 31 (5 न्यायाधीशों की पीठ), निर्दिष्ट
 निम्नलिखित के लिए:

" 28. हम सहमत होने के लिए इच्छुक नहीं हैं। ये सिद्धांत
 पहले के निर्णय पर प्रशासनिक पुनर्विचार का निपटारा किया जाता है।
 नीचे: " इस न्यायालय को यह स्वीकार नहीं करना चाहिए कि कब
 सभी उचित संदेह से परे प्रदर्शित किया कि यह पिछले
 निर्णय, उचित विचार-विमर्श और पूर्ण सुनवाई के बाद दिया गया था
 गलत है, विशेष रूप से अपने पिछले फैसले पर वापस जाएँ
 एक संवैधानिक मुद्दे पर "। (देखिए: लेफ्टिनेंट कर्नल खजुर सिंह
 बनाम। भारत संघ, (1961) 2 एससीआर 828)। केशव मिल्स में
 कं. लिमिटेड बनाम। सी. आई. टी. (1965) 2 एस. सी. आर. 908 में यह देखा गया है:

(एससीआर पीपी। 921-22)
 लेकिन इससे पहले कि कोई पिछला निर्णय लिया जाए

इसके सदस्यों के बीच सर्वसम्मति की मात्रा कि एक संशोधन
 उक्त दृष्टिकोण पूरी तरह से उचित है।

के. यू.

XXX

XXX

XXX

30. ऊपर उल्लिखित टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए

और तर्क के दौरान पक्षों का रुख

हमारे सामने, हम इसे फिर से खोलना उचित नहीं मानते हैं

बिल्डर्स में निर्णय द्वारा कवर किए गए मुद्दे

एसोसिएशन का मामला "।

उपरोक्त निर्णयों को संदर्भित करने के बाद, यह प्रस्तुत किया गया था,

कि यह स्पष्ट रूप से उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील के लिए गलत धारणा थी, विवाद का संदर्भ लेने के लिए, एक बड़े

इसके द्वारा दिए गए निर्णयों की पुनः जांच के लिए पीठ
मामलों में न्यायालय।

द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों के

31 (1993) 1 एससीसी 364 [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

59. दावा करने के लिए एक और आधार, कि प्रार्थना की गई

इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रतिवादी
न्यायाधीशों के मामलों में, प्रचार किया गया था

दूसरे और तीसरे

इस आधार पर कि इस न्यायालय द्वारा अभिलिखित टिप्पणियाँ

आवारा टिप्पणियों के रूप में समझा जाता है, और न ही आज्ञाकारी के रूप में माना जाता है
डिक्टा। विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा व्यक्त किए गए कारण

उपरोक्त मुद्दे इस प्रकार थे:

" (i) स्वतंत्रता से संबंधित अन्य मामले में

न्यायपालिका (उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पुनः स्थानांतरण)-यू. ओ. आई. बनाम संकल

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है।
अदालत ने उनकी सहमति के बिना, बहुमत से यह निर्णय लिया कि

वह हो सकता है: बहुमत में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ शामिल थे।

न्यायमूर्ति कृष्णा लायर और न्यायमूर्ति मुर्तजा फजल अली।

((ii) न्यायमूर्ति कृष्ण लायर का निर्णय (की ओर से)

स्वयं और न्यायमूर्ति मुर्तजा फजल अली ने संकल चंद सेठ में-/[जिसके साथ न्यायमूर्ति भगवती ने कहा कि वह "पूरी तरह से सहमत" थे] इस प्रकार लिखा है (पैरा 115-116): " 115. इस अपील में विचार के लिए अगला बिंदु इस प्रकार है -

परामर्श की प्रकृति, दायरे और दायरे के लिए, जैसा कि दिखाई दे रहा है

संविधान के अनुच्छेद 222 (1) में, मुख्य न्यायाधीश के साथ

भारत से। परामर्श, अपने मानक को पूरा करने के लिए
अनुच्छेद 222 (1) में कार्य एक वास्तविक, सारवान और महत्वपूर्ण होना चाहिए।

पूर्ण और उचित सामग्री के आधार पर प्रभावी परामर्श
सरकार द्वारा मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इससे पहले

स्वाभाविक रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश अपनी राय देंगे

सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए

संबंधित न्यायाधीश से अनौपचारिक रूप से पता लगाएँ कि क्या उसके पास है

कोई वास्तविक व्यक्तिगत कठिनाई या कोई मानवीय आधार जिस पर उसका स्थानांतरण निर्देशित नहीं किया जा सकता है। ऐसे आधार हो सकते हैं

उसका स्वास्थ्य या चरम परिवार सहित एक विस्तृत श्रेणी का हो

कारक। मुख्य न्यायाधीश के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं को जारी करना आवश्यक नहीं है-ऑन-रिकॉर्ड

समाज v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

संबंधित न्यायाधीश को औपचारिक सूचना लेकिन यह पर्याप्त है -

■ ■ ■

यद्यपि यह अनिवार्य नहीं है-यदि वह इन तथ्यों का पता लगाता है

या तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से या उनके

अपने सहयोगियों या किसी अन्य माध्यम से जो मुख्य न्यायाधीश सुरक्षित, निष्पक्ष और तर्कसंगत सोचते हैं। जहाँ किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण का प्रस्ताव किया जाता है, वहाँ सरकार

मुख्य न्यायाधीश को हर संभव सामग्री भेजनी चाहिए

ताकि वह एक प्रभावी राय देने की स्थिति में हो। दूसरा, हालांकि भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय

हो सकता है कि यह सरकार के लिए बाध्यकारी न हो, यह महान अधिकार का हकदार है।

वजन और आम तौर पर सरकार द्वारा स्वीकार किया जाना है

क्योंकि अनुच्छेद 222 के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है

मनमाने ढंग से या मनमाने ढंग से। चन्द्रमौलेश्वर प्रसाद बनाम के मामले में। पटना उच्च न्यायालय, (1969)

3 एस. सी. सी. 36, "परामर्श" शब्द की व्याख्या करते हुए

संविधान के अनुच्छेद 233 में उपस्थित इस न्यायालय

निम्नलिखित रूप में देखा गया: "अनुच्छेद 233 के तहत उच्च न्यायालय के साथ परामर्श एक खाली औपचारिकता नहीं है। जहाँ तक अधिकारियों की पदोन्नति की बात है

जिला न्यायाधीशों के कैडर का संबंध उच्च न्यायालय से है

पदोन्नति के लिए विचार किया जा सकता है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। परामर्श या विचार-विमर्श पूर्ण या प्रभावी नहीं होता है।

दूसरे या दूसरों को ज्ञात दृष्टिकोण और चर्चा और जांच करें उनके विचारों के सापेक्ष गुण। यदि एक पक्ष एक

मन जो समृद्धि के लिए संप्रेषित नहीं है बिना प्रति-प्रस्ताव को प्रभावी बनाने का निर्देश

इसके बाद कुछ भी जारी नहीं किया जा सकता है

परामर्श लें।

समशेर सिंह के मामले में, ए. आई. आर. 1974 एस. सी. 2192, हम में से एक उसी तार को मारा है। इसे भी ध्यान में रखना चाहिए।

कि यदि सरकार प्रमुख की राय से अलग हो जाती है

भारत का न्याय उसे ठोस सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर. देकर अपनी कार्रवाई को सही ठहराना होगा।

और उसी के लिए विश्वसनीय कारण और, यदि चुनौती दी जाती है,

न्यायालय के संतोष के लिए यह साबित करने के लिए कि एक मामला था मुख्य न्यायाधीश की सलाह को स्वीकार नहीं करने के लिए बनाया गया भारत से। हमें ऐसा लगता है कि 'परामर्श' शब्द है अनुच्छेद 222 में संवैधानिक मामले के रूप में उपयोग किया गया था इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दो बहुत उच्च गणमान्य व्यक्ति मामले में संबंधित हैं, अर्थात्, राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश। बेशक, मुख्य न्यायाधीश ने

((iii) न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ (अपने निर्णय के दौरान) सहमत हुए-संकल्पचंद सेठ के अनुच्छेद 41 में इसका अनुसरण किया गया।
शमशेर सिंह (पैरा 149) "।

उपरोक्त के आधार पर, यह दावा था कि विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा कि भले ही विवाद आगे बढ़े प्रत्यर्थियों के वकील द्वारा स्वीकार किया जाना था, अर्थात्, उपरोक्त दो मामलों में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पुनः जाँच किए जाने की आवश्यकता थी, एक बड़े संदर्भ द्वारा पीठ, अभी भी पैराग्राफ 149 में दर्ज टिप्पणियाँ समशेर सिंह मामला 1 1 मैदान पर बना रहेगा, क्योंकि उसी की समीक्षा नहीं मांगी गई थी।

V. विचार:

एल.

60. संविधान की योजना में, संघ न्यायपालिका भाग 5 के अध्याय 4 में और उच्च न्यायालयों में राज्यों के साथ-साथ अधीनस्थ अदालतों को भी निपटाया गया है। भाग VI के क्रमशः अध्याय V और VI के साथ। द. संविधान के भाग 5 और 6 के प्रावधान, संदर्भ के साथ अधीनस्थ सहित संघ और राज्यों की न्यायपालिकाओं के लिए न्यायालय, इसके द्वारा व्याख्यात्मक निर्धारण के लिए उत्पन्न हुए हैं अदालत, कई मौकों पर। हम कालानुक्रमिक रूप से नोटिस कर सकते हैं

इस न्यायालय द्वारा दिया गया निर्धारण, के संदर्भ में
उपरोक्त भाग, विशेष रूप से वे जो कार्यकारी सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं के साथ काम करते हैं-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

संघ न्यायपालिका से संबंधित मामलों में भागीदारी, राज्यों में उच्च न्यायालय और अधीनस्थ-न्यायालय। इस दौरान

सुनवाई के दौरान, हमारा ध्यान निम्नलिखित पर आमंत्रित किया गया था: (i) समशेर सिंह बनाम। पंजाब राज्य, (1974) 2 एससीसी 831 -

पाँच-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा प्रस्तुत, (ii) भारत संघ बनाम। संकलचंद हिमतलाल सेठ (1977) 4 एस. सी. सी.

193 - पाँच-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा प्रस्तुत,

(iii) एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ, 1981 पूरक एस. सी. सी. 87-प्रस्तुत सात न्यायाधीशों की पीठ द्वारा,

भारत सरकार, (1993) 4 एस. सी. सी. 441-नौ न्यायाधीशों की पीठ द्वारा प्रस्तुत, और

(v) पुनः 1998 का विशेष संदर्भ संख्या 1, (1998) 7 एस. सी. सी. 739

नौ न्यायाधीशों की पीठ द्वारा प्रस्तुत।

इस न्यायालय ने कम से कम पाँच मौकों पर जांच की है।

जिस विवाद से हम वर्तमान में निपट रहे हैं,

संविधान पीठ। समशेर सिंह मामले 11 में, यह था

निष्कर्ष निकाला कि सभी संभावित मामलों में, भारतीय न्यायपालिका में सर्वोच्च गणमान्य व्यक्ति-के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श

भारत, भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया जाएगा और किया जाना चाहिए, ऊपर निर्दिष्ट संविधान के अध्यायों और भागों से संबंधित मामलों में। यदि इसे स्वीकार नहीं किया गया था,

न्यायालय के पास जाँच करने का अवसर होगा कि क्या कोई

अन्य बाहरी परिस्थितियाँ फैसले में प्रवेश कर चुकी थीं।

संबंधित मंत्री या मंत्रिपरिषद (अध्यक्षता में) प्रधान मंत्री द्वारा), जिनके विचार उपेक्षा करने में प्रबल थे

भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी गई सलाह। यह न्यायालय
तदनुसार यह निष्कर्ष निकाला गया कि व्यवहार में, अंतिम शब्द होना चाहिए
वे भारत के मुख्य न्यायाधीश के हैं। उपरोक्त स्थिति थी
यह भी स्पष्ट किया कि द्वारा दी गई सलाह की अस्वीकृति
भारत के मुख्य न्यायाधीश को आम तौर पर माना जाएगा
तिरछे विचारों द्वारा प्रेरित, आदेश को दूषित करना। ए में समशेर सिंह मामले में यह
न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

में व्यक्त "परामर्श" शब्द को पढ़ा हुआ देखा जाता है
राय को प्रधानता प्रदान करते हुए अनुच्छेद 124 और 217
मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत। जब बात आई संकलचंद हिमतलाल सेठ मामले में जांच, के साथ
अनुच्छेद 222 के संदर्भ में, इसकी एक अन्य संविधान पीठ न्यायालय ने समशेर सिंह में निकाले गए
निष्कर्ष को दोहराया
मामला 1 1, यह अभिनिर्धारित करके कि सभी कल्पनीय मामलों में, "परामर्श"
भारत के मुख्य न्यायाधीश को स्वीकार किया जाना चाहिए,
भारत सरकार। और आगे, कि किसी भी घटना में
अन्य परिस्थितियों ने निर्णय में प्रवेश किया था कार्यकारी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस
न्यायालय ने स्पष्ट रूप से एक
प्रबल आशा, कि प्रदर्शनी समशेर में दर्ज की गई है सिंह मामला 1 1, बहरे कानों पर नहीं पड़ेगा।
हो सकता है इसमें कोई शक नहीं
गौर हो कि एक बार फिर, इस न्यायालय ने इस शब्द को पढ़ा "एक अभिव्यक्ति के रूप में
"परामर्श", में प्रधानता व्यक्त करना
प्रधान द्वारा व्यक्त किए गए विचार के अनुसार विचाराधीन मामला
न्याय। उपरोक्त व्याख्या से एकान्त विचलन,
इस न्यायालय द्वारा प्रथम न्यायाधीशों के मामले में दर्ज किया गया था, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला
गया कि शब्द का अर्थ
" "परामर्श" को "सहमति" के रूप में नहीं समझा जा सका। में।

दूसरे शब्दों में, यह माना गया था कि प्रमुख द्वारा दी गई राय

भारत का न्याय, कार्यपालिका पर बाध्यकारी नहीं होगा। उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति का कार्य था,

एक कार्यकारी कार्य के रूप में वर्णित, और यह द्वारा आयोजित किया गया था

बहुमत, कि नियुक्ति की अंतिम शक्ति, निर्विवाद रूप से

राष्ट्रपति के साथ आराम किया। इस न्यायालय द्वारा व्यक्त राय

प्रथम न्यायाधीशों के मामले में सुभाष शर्मा पर संदेह था।

मामला 1, जिसके कारण मामले की दूसरे में फिर से जांच की गई

न्यायाधीशों का मामला, नौ-न्यायाधीशों की पीठ के हाथों, जो तब तक प्रथम न्यायाधीशों के
मामले में दिए गए निर्णय को रद्द करते हुए,

निर्णयों के अनुरूप अपनी राय व्यक्त की

समशेर सिंह मामले 1 11 और संकलचंद हिम्मतलाल सेठ मामलों में प्रस्तुत किया गया। इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला कि

दूसरा न्यायाधीशों का मामला, कि "परामर्श" शब्द ने सर्वोच्च न्यायालयों को व्यक्त किया-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

अनुच्छेद 124, 217 और 222 में निहित प्रधानता के रूप में पढ़ा जाना था

भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा व्यक्त की गई राय के आधार पर

एक सहभागी परामर्श प्रक्रिया पर। दूसरे शब्दों में, में

अनुच्छेद 124, 217 और 222 से संबंधित मामले, नियुक्ति (या स्थानांतरण) की अंतिम शक्ति का संदर्भ

न्यायपालिका के साथ निहित होने के लिए आयोजित किया गया था। उपरोक्त स्थिति

नौ न्यायाधीशों द्वारा तीसरे न्यायाधीशों के मामले में पुनर्विचार किया गया न्यायाधीश पीठ,
जिसके लिए तत्कालीन विद्वान महान्यायवादी

भारत ने एक बयान दिया कि भारत संघ की मांग नहीं थी

दूसरे में निर्णय की समीक्षा या पुनर्विचार

न्यायाधीशों का मामला, और आगे, कि भारत संघ ने उक्त निर्णय को स्वीकार कर लिया था, और इस न्यायालय के निर्णय पर विचार करेगा

दूसरे न्यायाधीशों का मामला बाध्यकारी है। इसलिए यह स्पष्ट है, कि न्यायपालिका द्वारा विनियमित मामलों में प्रधानता होगी

संघ द्वारा अनुच्छेद 124, 217 और 222 को स्वीकार किया गया था।

भारत, तीसरे न्यायाधीशों के मामले में।

61. हम ऊपर भी इन विचारों को चित्रित कर चुके हैं -

प्रथम न्यायाधीशों के मामले में अभिलिखित न्यायाधीश, जो था

4 के बहुमत से प्रस्तुत: 3. इतना ही नहीं, कि मार्जिन था

अत्यंत संकीर्ण, लेकिन न्यायाधीशों द्वारा व्यक्त किए गए विचार भी

प्रचार किए गए सभी मुद्दों पर काफी भिन्नता थी

न्यायालय के समक्ष। दृश्य को दर्ज करने का प्राथमिक कारण
मामले में प्रत्येक न्यायाधीश था,

इसके पहले प्रथम न्यायाधीशों के

कटौती, निष्कर्षों में अंतर प्रदर्शित करना और

अंतिम परिणाम। उपरोक्त के विपरीत, ए पर

द्वितीय खंड में एक बड़ी पीठ द्वारा मामलों पर पुनर्विचार
बहुमत से दिया गया था: 2.

न्यायाधीशों के मामले में, निर्णय 7 के

न केवल स्थिति स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई थी, बल्कि शायद ही थी
कोई भी भिन्नता। ऐसी थी स्थिति

प्रचार किए गए मुद्दों पर

तीसरे न्यायाधीशों के मामले के साथ, जो सर्वसम्मत था और

विवाद की स्पष्ट व्याख्या। इसलिए हम पाते हैं
के लिए इच्छुक नहीं हैं

स्वयं समीक्षा के लिए प्रार्थना को स्वीकार करने

द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों के मामले।

62. शीर्ष अदालत की रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर. पर स्पष्ट और विचारशील विचार करने के बाद।

विद्वानों के हाथों प्रचार किए गए प्रस्ताव के लिए

उत्तरदाताओं के लिए वकील, हम निष्कर्ष निकालने के लिए विवश हैं,

न्यायपालिका की प्रधानता का मुद्दा, के मामले में

उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण, बार-बार जाँच किए जाने के बाद, पुनः देखने के लिए प्रार्थना /

उसी पर पुनर्विचार नहीं किया जाता है। यह न्यायालय

आम तौर पर मामले की फिर से जांच करने के लिए सहमत नहीं होते हैं, और किसी मुद्दे के लिए अधिक समय बिताएँ, जो पहले से ही ठीक हो चुका है। लेकिन

वर्तमान को सुनने के दौरान समय बाधा नहीं रहा है

मामले, क्योंकि हमने एक स्वतंत्र बहस की अनुमति दी है, और लिया है

जिन मुद्दों पर चर्चा की गई है, उनकी जांच करने का काम खुद पर है।

फिर भी, समीक्षा के उपाय की कुछ सीमाएँ होनी चाहिए। श्री फाली

एस. नरीमन, विद्वान वरिष्ठ वकील, अपने निवेदन में सही हैं,

कि समीक्षा की शक्ति का प्रयोग किया गया था और खर्च किया गया था

जब प्रथम न्यायाधीशों के मामले की समीक्षा एक बड़ी पीठ द्वारा की गई थी

दूसरे न्यायाधीशों के मामले में। और निश्चित रूप से, यह पूरी तरह से था भारत संघ के लिए अनुचित, जिसने इस दौरान स्वीकार किया था

तीसरे न्यायाधीशों के मामले की सुनवाई का क्रम, कि उसने

बाध्यकारी के रूप में स्वीकार किया गया, दूसरे में दिया गया निर्णय

न्यायाधीशों का मामला, मामले को फिर से शुरू करने का प्रयास करना।

मामले पर पुनर्विचार किया गया है, और स्थिति की गई है

भारत संघ द्वारा स्वीकार किया गया, यह मुँह में नहीं है

भारत संघ, न्यायिक पर पुनर्विचार की मांग करने के लिए

द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों के मामलों में घोषणा। इसलिए,

कानून के एक प्रस्ताव के रूप में, हम भारत संघ और अन्य उत्तरदाताओं की पुनः विचार के लिए प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। या दूसरे और तीसरे में दिए गए निर्णयों की समीक्षा

न्यायाधीशों के मामले। सभी समान, जैसा कि हमने संकेत दिया है

इस आदेश की शुरुआत, क्योंकि मामला चरम का है

महत्व और संवेदनशीलता, हम अभी भी गुणों की जांच करेंगे

विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियाँ।

II.

63. सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं द्वारा सबसे सशक्त समर्पण-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

विद्वान महान्यायवादी, संविधान पर आधारित थे

विधानसभा की बहस। इस संबंध में हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए आमंत्रित किया गया था

के. टी. शाह, के. एम. मुंशी, तजामुल द्वारा व्यक्त किए गए विचार

विद्वान महान्यायवादी, कि संविधान के सदस्य विधानसभा को डर था कि चयन की प्रक्रिया और

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए

विशेष रूप से न्यायपालिका के साथ निहित। की प्रक्रिया

यह तर्क दिया गया था कि न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के दौरान
साम्राज्य में साम्राज्य के रूप में वर्णित

विधानसभा की बहस। उपरोक्त टिप्पणियों के जवाब में,

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर अनुच्छेद की सामग्री का उल्लेख करते हुए

122 (जिसे संविधान में अनुच्छेद 124 के रूप में पुनर्नामित किया गया था),

संविधान सभा के सदस्यों को आश्वासन दिया था कि

मसौदा अनुच्छेद ने मध्य मार्ग को अपनाया था, जबकि

साम्राज्य में एक साम्राज्य बनाने से इनकार करना, इस तरह से,

कि "न्यायपालिका की स्वतंत्रता" पूरी तरह से होगी

संरक्षित किया गया। डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की प्रतिक्रिया का सटीक पाठ,

ऊपर पैराग्राफ 30 में निकाला गया है।

64. यह विद्वान महान्यायवादी का तर्क था,

कि संविधान के दौरान व्यक्त किए गए स्पष्ट इरादे के बावजूद

विधानसभा बहस, साम्राज्य में एक साम्राज्य बनाने के लिए नहीं,

दूसरे और तीसरे न्यायाधीशों के मामलों ने ऐसा ही किया था। यह था।

प्रस्तुत किया गया कि चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया में

उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीश, जिनका 1993 से पालन किया जा रहा है, न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहे थे। यह भी था

केवल न्यायाधीश ही

तर्क दिया कि संविधान एक प्रणाली पर विचार करता है

नियंत्रण और संतुलन, जहाँ शासन का प्रत्येक स्तंभ है

स्तंभ। बार-बार इस बात पर जोर दिया गया कि वर्तमान प्रणाली में न्यायाधीशों का चयन और नियुक्ति,

उच्च न्यायपालिका में

कार्यपालिका की कोई भूमिका नहीं है। तदनुसार यह था

उत्तरदाताओं का तर्क है कि जिस तरीके से अनुच्छेद [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

124, 217 और 222 की व्याख्या दूसरे में की गई थी और

तीसरे न्यायाधीशों के मामले, संविधान के इरादे से गलत साबित हुए

सभा। यह, विद्वान वकील के अनुसार

उत्तरदाता, काफी कारण था, फिर से देखने और सही करने के लिए,

द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों के मामलों में व्यक्त विचार।

65. हमारे लिए इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है।

के लिए विद्वान वकील के हाथों में उन्नत

उत्तरदाताओं की घोषणा पर परिणाम

द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों के मामलों में निर्णय, ए

न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया ज्ञापन और

उच्च न्यायपालिका के लिए मुख्य न्यायाधीशों को मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया था

30.6.1999 पर कानून, न्याय और कंपनी मामलों का। द.

उपर्युक्त प्रक्रिया ज्ञापन पर उपलब्ध है

उपरोक्त मंत्रालय की वेबसाइट। उपरोक्त ज्ञापन

हमारे द्वारा प्रक्रिया की जांच की गई है। हमारे सुविचारित विचार में, प्रक्रिया ज्ञापन एक सहभागी का प्रावधान करता है।

न्यायपालिका के साथ-साथ राजनीतिक-कार्यपालिका की भी भूमिका। उपरोक्त में से प्रत्येक घटक योगदान के लिए जिम्मेदार हैं।

व्यक्ति के संदर्भ में जानकारी, सामग्री और डेटा

विचाराधीन है। जबकि न्यायिक योगदान है

व्यक्ति की व्यावसायिक क्षमता के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार,

राजनीतिक-कार्यपालिका को प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है

व्यक्ति के चरित्र और पूर्वजों के बारे में विवरण। हमारा

प्रक्रिया ज्ञापन के विश्लेषण से पता चलता है कि
निम्नलिखित चरणों पर विचार करता है।

यही अन्य बातों के साथ-साथ चयन के लिए

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का:

चरण 1: संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने

मुख्यमंत्री को संवाद करने की जिम्मेदारी

संबंधित राज्य के लिए चुने जाने वाले व्यक्तियों के नाम

नियुक्ति। मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी जाती है।

ज्ञापन में संलग्न प्रारूप की शर्तें।

इसके अलावा, अगर मुख्यमंत्री सिफारिश करना चाहते हैं

इस तरह की नियुक्ति के लिए व्यक्ति (ओं) का नाम, उसे आगे भेजना होगा

मुख्य न्यायाधीश को भी उनके विचार के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

चरण 2: प्रमुख को अपनी सिफारिशें भेजने से पहले
सहयोगियों से परामर्श करना चाहिए

मंत्री, मुख्य न्यायाधीश को अपने वरिष्ठ

उपयुक्तता के संबंध में उच्च न्यायालय कॉलेजियम में शामिल

प्रस्तावित नाम। पूरा परामर्श इसमें होना चाहिए

लेखन, और इन रायों को मुख्यमंत्री को भेजा जाना चाहिए

मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश के साथ।

चरण 3: प्रमुख द्वारा की गई सिफारिशों की प्रतियाँ संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री को उच्च न्यायालय के न्याय का केंद्रीय विधि मंत्री को अनुमोदन करने की आवश्यकता होती है।

और संबंधित राज्य के राज्यपाल को न्याय, और

भारत के मुख्य न्यायाधीश।

पत्रों के पूरे सेट के साथ सिफारिश केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री।

चरण 5: केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री अपने कार्यकाल में

स्वयं, उसके सामने रखी गई सिफारिशों पर विचार करें, रिपोर्टों के आलोक में, जो सरकार को उपलब्ध हो सकते हैं,

विचाराधीन नामों का सम्मान। प्रस्तावित नाम, के हाथों जांच के अधीन होंगे केंद्रीय गृह मंत्रालय के माध्यम से खुफिया ब्यूरो।

खुफिया ब्यूरो की अखंडता पर राय होगी

विचाराधीन व्यक्ति।

चरण 6: पूरी सामग्री, जैसा कि संघ के पास उपलब्ध है कानून और न्याय मंत्री को तब भेजा जाएगा

भारत के मुख्य न्यायाधीश उनकी सलाह के लिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश

उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम, के संबंध में अपनी राय बनाता है नियुक्ति के लिए अनुशंसित व्यक्ति।

चरण 7: उपलब्ध कराई गई सामग्री के आधार पर, और

इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विचार (जो

संबंधित उच्च न्यायालय के मामलों से परिचित थे), [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने अपने कॉलेजियम के परामर्श से

न्यायाधीश, संघ को अपनी सिफारिश भेजेंगे

कानून और न्याय मंत्री। न्यायाधीशों के उपरोक्त उल्लेखनीय विचार
 सिफारिश को शामिल करते हुए संकलन। चरण 8: केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री तब
 भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई सिफारिश को प्रस्तुत करें,
 प्रधानमंत्री को, जो पूरे मामले की जांच करेंगे
 प्रस्तावित मामले में राष्ट्रपति को सलाह दें नियुक्तियाँ।

66. हम वास्तविक विचार को चित्रित करने का साहस करेंगे।

कार्यपालिका के हाथों, चयन की प्रक्रिया में और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति,
 प्रक्रिया ज्ञापन, साथ ही, वास्तविक प्रचलित
 अभ्यास करें।

67. प्रक्रिया ज्ञापन के चरण 1 से 3 से पता चलता है,
 कि नियुक्ति के लिए चुने जाने वाले व्यक्तियों के नाम हैं
 मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भेजा गया
 संबंधित राज्य। नामों की प्राप्ति पर मुख्यमंत्री
 निर्धारित करने के लिए भारी जिम्मेदारी का निर्वहन करता है
 अनुशंसित उम्मीदवार (ओं) की उपयुक्तता। विशेष रूप से
 ईमानदारी से संबंधित उम्मीदवार (ओं) की उपयुक्तता, सामाजिक
 व्यवहार, राजनीतिक भागीदारी और इसी तरह। अनावश्यक है।
 उल्लेख करें कि संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री ने इस तरह के निवेश प्रदान करने के लिए पर्याप्त
 मशीनरी। यह भी होगा
 यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि संबंधित राज्य के राज्यपाल के हाथ में विचार भी खाली नहीं है।
 औपचारिकता। क्योंकि यह राज्यपाल है, जिसके माध्यम से फाइल
 मुख्यमंत्री द्वारा संसाधित, संघ को भेजा जाता है
 कानून और न्याय मंत्री। ऐसे अवसर आए हैं जब
 संबंधित राज्य के राज्यपालों ने अपने स्वयं के सर्वोच्च प्रमाणपत्र-चालू-रिकॉर्ड दर्ज किए हैं

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

अनुशंसित उम्मीदवार की उपयुक्तता पर प्रभाव,
प्रमुख द्वारा व्यक्त की गई राय के बिल्कुल विपरीत

अभिलिखित है कि ऐसे उदाहरण हैं जहाँ राज्यपालों ने न्यायाधीशों के चयन की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लिया

उच्च न्यायालय, आवश्यक जानकारी प्रदान करके। रिकॉर्ड भी अच्छा लगता है
इस तथ्य की गवाही, कि द्वारा व्यक्त की गई राय
राज्यपाल, अंततः कुछ मौकों पर विजयी हुए थे।

68. कार्यपालिका की भागीदारी, के संदर्भ में

प्रमुख द्वारा अनुशंसित उम्मीदवार का विचार

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत सरकार के स्तर पर आगे भी बने हुए हैं। उम्मीदवार की उपयुक्तता का मामला,

संघ के हाथों स्वतंत्र रूप से भी जांच की जाती है कानून और न्याय मंत्री। विधि और न्याय मंत्रालय

संघ के माध्यम से निवेश प्राप्त करने की एक मानक प्रक्रिया है

गृह मंत्रालय। इस तरह के निवेश उपलब्ध कराए जाते हैं

केंद्रीय गृह मंत्रालय, ईमानदारी रखते हुए,

सामाजिक व्यवहार, राजनीतिक भागीदारी और इसी तरह की जांच की गई

खुफिया ब्यूरो के माध्यम से। इस तरह के इनपुट की प्राप्ति के बाद,

और संघ के हाथों प्रस्ताव की जांच

कानून और न्याय मंत्री, फाइल मुख्यमंत्री के पास जाती है

भारत के न्यायाधीश, ऊपर उल्लिखित क्वार्टरों से प्राप्त विवरणों के साथ।

69. भारत के मुख्य न्यायाधीश के बाद, के परामर्श से

उनका न्यायाधीशों का कॉलेजियम संबंधित उम्मीदवार की सिफारिश करता है

उच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए, फाइल को तीसरे के लिए संसाधित किया जाता है

समय, कार्यपालिका द्वारा। इस अवसर पर, के स्तर पर

भारत के प्रधानमंत्री। पल भर के दौरान

यह भी ध्यान में रखते हुए, कार्यपालिका की भागीदारी एक नहीं है खाली औपचारिकता। प्रधानमंत्री को उपलब्ध जानकारी के आधार पर मंत्री महोदय, यह कार्यपालिका के लिए खुला है कि वह फाइल को फिर से वापस कर दे भारत के मुख्य न्यायाधीश को, के पुनर्विचार के लिए प्रस्ताव, ऐसी सामग्री को संलग्न करके जो सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट से बच गई हो

[2015] 13 एस सी आर।

भारत के मुख्य न्यायाधीश और उनके न्यायाधीशों के कॉलेजियम का नोटिस।
ऐसे भी अवसर आए हैं जब फाइल प्रमुख को वापस कर दी गई हो
पुनर्विचार के लिए भारत के न्याय के परिणामस्वरूप एक संशोधन हुआ है
न्यायपालिका और राजनीति के बीच उद्देश्य की एकता उच्च अधिकारी के चयन और नियुक्ति के मामले में कार्यपालक
न्यायालय के न्यायाधीश। और उनके बीच स्पष्ट पारदर्शिता है
भी। जैसा कि विचारों का आदान-प्रदान लिखित, विचारों और प्रतिवाद में किया जाता है
दृश्य काले और सफेद रंग में हैं। कुछ भी गुप्त रूप से नहीं होता है, बिना
भाग लेने वाले संवैधानिक अधिकारियों का ज्ञान।

70. हमारे लिए भागीदारी को चित्रित करना आवश्यक नहीं है।

चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया में न्यायपालिका का उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। उसी से स्पष्ट है
प्रक्रिया ज्ञापन में जिन कदमों पर विचार किया गया है ऊपर लिखा गया है। यह कहने के लिए पर्याप्त है, कि यह निहित नहीं है
उत्तरदाताओं का मुँह तर्क देने के लिए, कि कोई नहीं है
चयन प्रक्रिया में कार्यकारी भागीदारी और
उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति।

71. चयन के लिए प्रक्रिया ज्ञापन

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने एक समान भागीदारी का प्रावधान किया है न्यायपालिका और राजनीतिक-कार्यपालिका की भूमिका। वैसा ही है।

संक्षिप्तता के कारणों से यहाँ विश्लेषण नहीं किया जा रहा है। इसके लिए पर्याप्त है।
भी एक समान अभ्यास के साथ एक संयुक्त अभ्यास है।

बता दें कि यह

दृष्टिकोण।

72. ऊपर हमारे द्वारा दर्ज किए गए कारणों के लिए, यह है
प्रक्रिया में इसे स्वीकार करना हमारे लिए संभव नहीं है।
द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों के मामलों के तहत विचार किया गया,
उच्च न्यायपालिका के लिए अपने स्वयं के चुनिंदा न्यायाधीश, या
कि, साम्राज्य में साम्राज्य की प्रणाली के लिए बनाया गया है
हमारे लिए यह स्वीकार करना संभव है कि दूसरे में निर्णय न्यायाधीशों के मामले ने चयन और
सर्वोच्च न्यायालयों की प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया है-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

संवैधानिक योजना में कार्यपालिका की सहभागी भूमिका को कम करके उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की
नियुक्ति कार्यपालिका की भूमिका को ध्यान में रखते हुए नियंत्रण और संतुलन

ऊपर पूरी तरह से वर्णित। हम तत्काल विवाद में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

उत्तरदाताओं के हाथों में उन्नत।

III.

73. विद्वान महान्यायवादी ने जोर देकर कहा

संविधान सभा की बहसों पर निर्भरता। इसकी तलाश की गई।

दावा किया जा सकता है कि की एक उपयुक्त समझ के लिए

संविधान के प्रावधानों का उल्लेख करना अनिवार्य था

संविधान सभा की बहस, जिसके परिणामस्वरूप गठन हुआ था और संबंधित अनुच्छेद (ओं) की
रचना। रिलायंस था

तदनुसार बहसों पर रखा गया, जिसके कारण मसौदा तैयार किया गया था

अनुच्छेद 124। यह प्रस्तुत किया गया था कि द्वारा निकाले गए निष्कर्ष

इस न्यायालय ने, दूसरे न्यायाधीशों के मामले में, इस तथ्य की अनदेखी की,

जिसे स्पष्ट रूप से प्रचार किया गया था और विभिन्न द्वारा उठाया गया था
 संविधान सभा के सदस्य, और नियत समय पर अस्वीकार कर दिए गए
 दूसरे न्यायाधीशों का मामला। इसलिए यह विवाद था कि विद्वान महान्यायवादी, कि में दिए
 गए निर्णय
 द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों के मामलों में तिरछे तरीके से एक दृष्टिकोण दर्ज किया गया
 संविधान सभा के इरादे और संकल्प के विपरीत।

74. संक्षिप्तता के कारणों से, हमारे लिए यह आवश्यक नहीं है कि
 संविधान सभा के कुछ प्रतिष्ठित सदस्यों द्वारा मसौदा प्रावधान में किए गए संशोधनों का उद्धरण इसमें दिया
 गया है।
 (जिस पर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था)। इस समय हमें इसकी आवश्यकता है।
 केवल अनुच्छेद 772 (पहले से ही ऊपर निकाला गया) का उल्लेख करने के लिए, से
 इंद्र साहनी मामला, दर्ज करने के लिए, कि यह नहीं है
 सदस्यों के व्यक्तिगत विचारों को संदर्भित करना आवश्यक है, और यह कि,
 बहस के अंत में डॉ. बी. आर.
 अम्बेडकर, यह समझने के लिए पर्याप्त होगा कि क्या था प्रबल हुआ, और क्यों। यह कहने के लिए
 पर्याप्त है कि संविधान सभा की बहसों के दौरान, इसे स्पष्ट रूप से सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस.
 सी. आर. प्रस्तावित किया गया था।

कि "परामर्श" शब्द अनुच्छेद 124 और 217 में निहित है,
 "सहमति" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए। प्रस्तावित
 हालाँकि डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने संशोधन को अस्वीकार कर दिया था।
 उपरोक्त के बावजूद, यह न्यायालय दूसरे और तीसरे न्यायाधीशों में
 मामलों ने के खंड (2) में "परामर्श" शब्द की व्याख्या की थी
 अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 217 के खंड (1) को प्रधानता प्रदान करने के रूप में
 न्यायपालिका में, कुछ ऐसा जिसे स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया था,
 संविधान सभा में बहस। और इसलिए, विवाद

प्रत्यर्थियों की ओर से आगे कहा गया था कि यह न्यायालय संविधान को बदलकर उपरोक्त प्रावधानों की व्याख्या की थी

सभा का इरादा और संकल्प, उसके शीर्ष पर है। यह प्रस्तुत किया गया था, कि द्वितीय में दर्ज गलत व्याख्या

न्यायाधीशों का मामला, बड़े पैमाने पर लिखा गया था, यहां तक कि एक सरसरी जांच पर भी बहसों से।

75. हमारा विचार है कि जाँच के लिए यह पर्याप्त होगा।

उपरोक्त विवाद, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की प्रतिक्रिया के एक प्रासंगिक हिस्से को यहाँ निकालने के लिए, उपरोक्त उल्लिखित

ऊपर उल्लिखित प्रावधानों में संशोधन:

"अब, महोदय, कई संशोधनों के संबंध में कि इस लेख में स्थानांतरित कर दिया गया है, वास्तव में तीन हैं

जिन मुद्दों को उठाया गया है। पहला है, कैसे हैं? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी? अब,

विभिन्न संशोधनों को समूहीकृत करना जो संबंधित हैं -

इस विशेष मामले में, मुझे तीन अलग-अलग प्रस्ताव मिलते हैं। द.

पहला प्रस्ताव यह है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश

प्रमुख की सहमति से नियुक्त किया जाना चाहिए

न्याय। यह एक दृष्टिकोण है। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियाँ निम्नलिखित के अधीन होनी चाहिए -

संसद द्वारा दो-तिहाई मतों की पुष्टि; और

राज्य परिषद के साथ परामर्श।

इस मामले के संबंध में, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि मुद्दा उठाया गया है

इसका सबसे अधिक महत्व है। कोई अंतर नहीं हो सकता सदन में यह राय कि हमारी न्यायपालिका दोनों को सर्वोच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए-ऑन-रिकॉर्ड

समाज v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

कार्यपालिका का होना चाहिए और अपने आप में भी सक्षम होना चाहिए। और सवाल यह है कि ये दोनों वस्तुएँ कैसे हो सकती हैं? सुरक्षित रहें। अन्य देशों में इस मामले को दो अलग-अलग तरीकों से नियंत्रित किया जाता है। ग्रेट ब्रिटेन में

सीमा जो भी हो, जिसका अर्थ है कार्यपालिका द्वारा एक दिन। संयुक्त राज्य अमेरिका में विपरीत प्रणाली है

जहाँ, उदाहरण के लिए, उच्चतम न्यायालय के कार्यालय भी

राज्य के अन्य कार्यालय केवल के साथ बनाए जाएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में सीनेट की सहमति। ऐसा लगता है।

जिम्मेदारी की भावना उतनी नहीं बढ़ी है जिसके लिए हम इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में पाते हैं, यह होगा

नियुक्तियों को छोड़ने के लिए खतरनाक

राष्ट्रपति, बिना किसी प्रकार के आरक्षण या सीमा के, कि

कहने का मतलब है, केवल उस दिन की कार्यपालिका की सलाह पर।

इसी तरह, मुझे लगता है कि हर मुलाकात करने के लिए

जिसे कार्यपालिका इसके अधीन बनाना चाहती है विधानमंडल की सहमति भी एक बहुत उपयुक्त प्रावधान नहीं है। इसके भारी होने के अलावा, इसमें शामिल हैं

नियुक्ति के प्रभावित होने की संभावना

राजनीतिक दबाव और राजनीतिक विचार। मसौदा इसलिए, लेख एक मध्य मार्ग का मार्गदर्शन करता है। यह नहीं करता है

राष्ट्रपति सर्वोच्च और पूर्ण अधिकार में

नियुक्तियाँ करने का मामला। यह आयात भी नहीं करता है। विधानमंडल का प्रभाव। लेख में प्रावधान

परिकल्पना, के मामलों में उचित सलाह देने के लिए अच्छी तरह से योग्य इस प्रकार, और मेरा न्याय यह है कि इस प्रकार का प्रावधान

इस समय के लिए पर्याप्त माना जा सकता है।

प्रमुख की सहमति के प्रश्न के संबंध में

न्याय, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग इसकी वकालत करते हैं

ऐसा लगता है कि प्रस्ताव निहित रूप से निष्पक्षता दोनों पर निर्भर करता है। मुख्य न्यायाधीश और उनके निर्णय की दृढ़ता।

मैं अदालत की रिपोर्टों का समर्थन करता हूँ

[2015] 13 एस सी आर।

व्यक्तिगत रूप से इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश बहुत अच्छे हैं।

प्रतिष्ठित, व्यक्ति। लेकिन आखिरकार मुख्य न्यायाधीश एक आदमी है।

सभी विफलताओं, सभी भावनाओं और सभी पूर्वाग्रहों के साथ जो आम लोगों के रूप में हमारे पास हैं; और मुझे लगता है, अनुमति देने के लिए

मुख्य न्यायाधीश ने नियुक्ति पर व्यावहारिक रूप से वीटो कर दिया

न्यायाधीशों का अधिकार वास्तव में प्रमुख को हस्तांतरित करना है।

न्याय जो हम राष्ट्रपति को सौंपने के लिए तैयार नहीं हैं
या उस समय की सरकार। इसलिए मुझे लगता है कि

यह भी एक खतरनाक प्रस्ताव है।

ऊपर निकाले गए पहले पैराग्राफ से पता चलता है कि

नियुक्ति के मुद्दे पर तीन प्रस्ताव थे

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। पहला प्रस्ताव यह था कि
नियुक्ति द्वारा नहीं की जानी चाहिए

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की

राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ "परामर्श" में, लेकिन

मुख्य न्यायाधीश की "सहमति" से नियुक्त किया जाना चाहिए
संयुक्त राष्ट्र में था

भारत से। दूसरा प्रस्ताव था, जैसे

राज्यों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी चाहिए।
जाना, द्वारा पुष्टि के अधीन

राष्ट्रपति द्वारा किया

संसद, दो तिहाई बहुमत के माध्यम से। तीसरा प्रस्ताव

यह था कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के साथ "परामर्श" करके
की जानी चाहिए।

76. डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की सभी को प्रतिक्रिया

सुझावों की बहुत बारीकी से जाँच करने की आवश्यकता है, क्योंकि,

यद्यपि महान्यायवादी द्वारा उचित रूप से इंगित किया गया है, और

उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील, सभी

वर्तमान विवाद में विचार के लिए उत्पन्न होने वाले मुद्दे,

उपरोक्त प्रतिक्रिया में स्पर्श किया गया था। रहने से पहले

इस मुद्दे पर, जो सख्ती से नियुक्ति से संबंधित था

न्यायाधीश डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि संविधान सभा की सर्वसम्मति राय थी - कि "हमारी न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र होना चाहिए"। द.

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने भी यही भावना व्यक्त की थी।

के. टी. शाह, के. एम. मुंशी, तजामुल हुसैन, अल्लादी कृष्णस्वामी आयर और अनाथसायनम अय्यंगार (निकाले गए सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड) को जवाब देते हुए

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

ऊपर पैराग्राफ 30 में) जिसमें उन्होंने जोर दिया, कि "।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि आम तौर पर सदन इस बात पर सहमत हो गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी चाहिए

जितना हम इसे कानून द्वारा बना सकते थे उतना स्पष्ट और निश्चित किया गया।

नियुक्ति के मुद्दे पर बहस करते समय किया गया उपरोक्त दावा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, प्रभावी रूप से स्वीकार करते हैं,

कि उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में एक

"न्यायपालिका की स्वतंत्रता" के मुद्दे के साथ सीधा संबंध। यह.

इसलिए, उत्तरदाताओं के मुंह में यह दावा करना नहीं है कि "नियुक्ति" का विषय अधिकार क्षेत्र के भीतर नहीं आएगा /

"न्यायपालिका की स्वतंत्रता" का क्षेत्र।

77. दूसरे और तीसरे प्रस्तावों का जवाब देते हुए

ऊपर उल्लिखित डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने इस तरीके का हवाला दिया ग्रेट ब्रिटेन में न्यायाधीशों की नियुक्ति, और इंगित किया कि

यूनाइटेड किंगडम में नियुक्तियाँ क्राउन द्वारा की गई थीं,

बिना किसी सीमा के, और इस तरह, कार्यपालिका के अनन्य क्षेत्र के भीतर आता है। प्रणाली का उल्लेख करते हुए

संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाया गया, उन्होंने नोट किया, कि न्यायाधीशों अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय, केवल नियुक्त किया जा सकता था

संयुक्त राज्य

सीनेट की "सहमति" के साथ। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि प्रक्रिया के लिए था जो गिर गई

बाद वाला संदर्भ नियुक्ति की एक

विधायिका के क्षेत्र के भीतर (क्योंकि सीनेट एक है

अमेरिकी कांग्रेस बनाएँ)। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वह कर दिया, जहां उच्च पदों पर नियुक्तियां होती थीं

दोनों प्रणालियों को अस्वीकार

न्यायपालिका कार्यपालिका द्वारा बनाई गई थी, साथ ही, द्वारा

विधायिका। डॉ. बी. आर. अम्बेडकर इसलिए बहुत स्पष्ट रूप से

इस मुद्दे को यह व्यक्त करते हुए समाप्त किया कि यह अनुचित होगा

न्यायाधीशों की नियुक्तियों को उच्चतम न्यायालय पर छोड़ने के लिए,

राष्ट्रपति द्वारा किया जाना-कार्यपालिका (अर्थात्, सहायता पर और

मंत्री)। डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के शब्दों में, यह होगा एस. सी. आर. के हाथों में छोड़ना खतरनाक है।

इस तरह की नियुक्तियों को [2015] 13

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दिन का कार्यपालक, बिना किसी आरक्षण के और

सीमा। इसलिए हम संतुष्ट हैं, कि शब्द

"संविधान सभा द्वारा अनुच्छेद 124 और 217 में व्यक्त परामर्श पर विचार किया गया था, ताकि स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जा सके।

कार्यपालिका की इच्छा। अगर यही सच्चा इरादा था, तो शब्द

" "परामर्श" को कभी भी इसका सामान्य शब्दकोश नहीं सौंपा जा सका

अर्थ। और अनुच्छेद 124 (या अनुच्छेद 217) का मतलब कभी नहीं हो सकता था।

अनुच्छेद 74 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। इसलिए हमारे लिए यह संभव नहीं है कि

स्वीकार करें कि चयन के मामले में मुख्य आवाज और नियुक्ति की गई थी

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की

74)। न ही इस क्षण में उस प्रधानता को स्वीकार करना संभव है था। न ही न्यायपालिका ने

मामला कार्यपालिका के पास

मामले में एक भूमिका सौंपी गई थी, जिस पर विचार नहीं किया गया था संविधान के प्रावधानों के अनुसार। इसके लिए गलत धारणा है

प्रत्यर्थियों को यह दावा करने के लिए कि इस न्यायालय का निर्धारण

द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों के मामले व्याख्यात्मक नहीं थे

प्रकृति, लेकिन वास्तव में विधायी था। डॉ. बी. आर. अम्बेडकर,

इसलिए, उन्हीं कारणों से, इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि

उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जानी चाहिए। विधायिका द्वारा। लेकिन इस ओर से उन्होंने जो कारण व्यक्त किया

न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया सबसे उपयुक्त थी,

एक या दूसरे (या दोनों) द्वारा अनुमोदन का मत मांगकर संसद का सदन बोझिल होगा। अधिक

नियुक्तियों को निर्देशित किए जाने की संभावना और "राजनीतिक दबाव" और "राजनीतिक विचार" से प्रभावित,

यदि विधायिका शामिल थी। इसलिए हम संतुष्ट हैं कि जब संविधान सभा ने "परामर्श" शब्द का उपयोग किया,

नियुक्तियों के मामले में राजनीतिक-कार्यपालिका की भूमिका उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीश।

78. डॉ. बी. आर. अम्बेडकर का विचार था कि मसौदा

लेख ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड नहीं बनाकर एक मध्य मार्ग अपनाया था।

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

राष्ट्रपति-कार्यपालिका "सर्वोच्च और पूर्ण प्राधिकारी"

न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ करने के मामले में। और साथ ही, अपने स्पष्ट राजनीतिक कारणों से विधायकों को बाहर करके झुकाव और पूर्वाग्रह, जो उन्हें जिम्मेदारी संभालने के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं। इसलिए हमारा विचार है,

कि दूसरे और तीसरे न्यायाधीशों के मामलों में निर्णय

"परामर्श" शब्द के लिए एक शब्दकोश का अर्थ निर्धारित नहीं करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। अगर वास्तविक उद्देश्य होना चाहा गया

और उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति, से कार्यकारी और राजनीतिक भागीदारी, निश्चित रूप से शब्द

"परामर्श" का अर्थ कुछ और के रूप में समझा जाना था

केवल एक "परामर्श" के बजाय।

79. डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की टिप्पणियों से यह स्पष्ट है,

कि राष्ट्रपति द्वारा कार्यपालिका की आवश्यकता थी

मसौदा अनुच्छेद के प्रावधान, परामर्श के लिए "। व्यक्ति, जो थे

पूर्व परिकल्पना, मामले पर उचित सलाह देने के लिए अच्छी तरह से योग्य न्यायाधीशों की नियुक्ति "। द.

उच्चतम न्यायालय में

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की प्रतिक्रिया एक एकल पैराग्राफ में

(ऊपर निकाला गया), इस बात में कोई संदेह नहीं है कि लेख

124, जिस तरह से इस पर बहस की गई थी, उसका स्पष्ट रूप से मतलब था

प्रस्ताव, कि "न्यायाधीशों की नियुक्तियों का मामला एक था अभिन्न अंग। इसलिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए विचार की गई प्रक्रिया

न्यायपालिका की स्वतंत्रता का

समझने के लिए, ऐसा होने के लिए, जिसे संरक्षित/संरक्षित किया जाएगा राजनीतिक विचारों से।

राजनीतिक दबाव और

80. एक के बाद का अनुच्छेद, जो किया गया है

पूर्वगामी अनुच्छेदों में व्याख्या भी कोई जगह नहीं छोड़ती है

किसी भी संदेह के लिए, कि संविधान सभा नहीं चाहती थी

भारत के मुख्य न्यायाधीश को वीटो करने की शक्ति प्रदान करें

न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ। इसलिए यह एक परामर्शी है

प्रक्रिया पर अनुच्छेद 124 के तहत विचार किया गया था, क्योंकि यह था किया गया। वही अनिवार्य परामर्श न केवल

मूल रूप से तैयार

भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ, लेकिन [2015] 13 एस. सी. आर के अन्य न्यायाधीशों के साथ।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। बारीकी से देखने पर,

द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों के मामलों में निर्णय, थे

इस तरह से प्रस्तुत किया गया है जो पूर्ण प्रभाव देगा डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा की गई टिप्पणियाँ

अनुच्छेद 124 (जैसा मूल रूप से शामिल किया गया है)। यह स्पष्ट रूप से गलत है

उत्तरदाताओं को तर्क देने के लिए, कि परामर्श प्रक्रिया

द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों के मामले। ऐसा कुछ भी नहीं। इसमें है। राष्ट्रपति के लिए खुला है और अभी भी खुला है

विवेक, अनुच्छेद 124 में इंगित परामर्श के लिए।

इसके अतिरिक्त, यह राष्ट्रपति के लिए खुला है कि वह प्रमुख के साथ अनिवार्य "परामर्श" के दौरान उसी पर भरोसा करे।

भारत का न्याय। उपरोक्त, उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों के चयन में कार्यकारी भूमिका को दर्शाता है।

की ओर से अग्रिम प्रस्तुतिकरण के विपरीत

उत्तरदाताओं। हम संतुष्ट हैं कि पूरी चर्चा और

विधानसभा, को प्रभाव दिया जा सकता है, शब्द को पढ़कर "न्यायपालिका को प्रधानता देने के लिए "परामर्श"

चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारा यह भी विचार है कि उपरोक्त

वाद-विवाद निर्णयों में निकाले गए निष्कर्षों का समर्थन करते हैं

किसकी समीक्षा की जा रही है। दर्ज किए गए कारणों के लिए

ऊपर, हम अग्रिम प्रस्तुतियों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा

संविधान सभा बहस करती है।

IV.

81. हाथ में विचार भी एक ऐतिहासिक है

दृष्टिकोण। हम उसी की जांच करने का साहस करेंगे,

संविधान के लागू होने के बाद प्राप्त अनुभव, यानी इस देश के लोगों के खुद पर शासन करने के लिए आने के बाद,

परिभाषित रेखाओं के संदर्भ में, और की विशिष्टता

कार्यकरण, सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं की व्यवस्था और आवंटन द्वारा निर्धारित-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

संविधान में व्यक्त जिम्मेदारियाँ। इस संबंध में,

यह हुई चर्चा को उजागर करने के लिए प्रासंगिक होगा संसद में, जब कानून की चौदहवीं रिपोर्ट

न्यायिक सुधार आयोग (1958) के लिए प्रस्तुत किया गया था

राज्यसभा में 24-25.11.1959 पर चर्चा। जवाब देते हुए

24.11.1959 पर बहस के लिए, तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत की टिप्पणी, जैसा कि आधिकारिक रूप से दर्ज किया गया है, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार थे:

"महोदय, जहाँ तक उच्चतम न्यायालय में नियुक्तियों की बात है, तब से

1950 जब संविधान लागू किया गया था, उन्नीस

उच्चतम न्यायालय से। मुझे नहीं पता कि कोई अन्य विकल्प है या नहीं। इसके लिए योजना बनाई जा सकती है। के मुख्य न्यायाधीश

सर्वोच्च न्यायालय, मुझे लगता है, सही माना जाता है और माना जाता है अपने सहयोगियों की खूबियों से परिचित रहें और

न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं में से जो प्रमुख पदों पर हैं

अलग-अलग राज्य। इसलिए हमने सलाह का पालन किया है

सबसे सक्षम, भरोसेमंद और प्रतिष्ठित व्यक्ति जो

हम इस मामले में सवाल उठा सकते हैं।

उसी तरह। महोदय, जहाँ तक उच्च न्यायालयों का संबंध है, क्योंकि

1950. 211 नियुक्तियाँ की गई हैं और इनमें से एक को छोड़कर, यानी 211 में से 210 सलाह पर की गई थीं।

मुख्य न्यायाधीश की सहमति और सहमति से

भारत। और 211 में से 196 प्रस्ताव जो थे

सरकार द्वारा स्वीकार किए गए सभी व्यक्तियों का समर्थन था

जो इस मामले से जुड़े थे। माननीय के रूप में। सदस्यगण

जानते हैं, नीचे। मुझे लगता है, अनुच्छेद 217, के मुख्य न्यायाधीश

उच्च न्यायालय: संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री

और राज्यपाल पहले इन मामलों से निपटता है। फिर वे गृह मंत्रालय में आते हैं और मंत्रालय द्वारा संदर्भित किए जाते हैं

भारत के मुख्य न्यायाधीश को और जो भी सुझाव या

उनकी टिप्पणियों को ध्यान में रखा जाता है और यदि

आवश्यक है, मुख्यमंत्री सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर. को फिर से एक संदर्भ दिया जाता है।

और उच्च न्यायालय। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये 196 नियुक्तियाँ

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री राज्य, राज्यपाल और भारत के मुख्य न्यायाधीश।

अशोक कुमार सेन द्वारा की गई टिप्पणी, तत्कालीन संघ

विधि आयोग की रिपोर्ट से संबंधित भी एक आवश्यकता है संदर्भ:

.....यह मेरा कर्तव्य है कि मैं फिर से माननीय सदन की ओर इशारा करूँ।

जैसा कि मैंने लोकसभा में किया था जब विधि आयोग पहली बार आया था

अंतिम से पहले रिपोर्ट करें-यह इंगित करते हुए कि न्यायाधीशों के पास है असाधारण विचारों पर नियुक्त किया गया, हमने दिया

सभी नियुक्तियों से संबंधित तथ्य और आंकड़े

1950 से बनाया गया। हमने उनका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि, जैसा कि गृह मंत्री ने कल बताया था,

176 विषम न्यायाधीशों में से एक न्यायाधीश के मामले को छोड़कर

1950 से नियुक्त, सभी की सलाह पर नियुक्त किया गया था

मुख्य न्यायाधीश। जिसके बारे में वहाँ था

स्थानीय मुख्य न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश और सरकार के बीच मतभेद को स्वीकार किया गया

मुख्य न्यायाधीश के बजाय स्थानीय मुख्य न्यायाधीश की सलाह

भारत का न्याया। लेकिन यह उनका उम्मीदवार नहीं था। हमें उम्मीद करनी चाहिए थी कि विधि आयोग, पूरी निष्पक्षता में,

सरकार से दिए गए संचार से निपटा गया

न केवल उच्च न्यायालयों की सभी नियुक्तियों के तथ्य

लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से। मैं यह नहीं कहता कि वे थे

ऐसा करने के लिए बाध्य, लेकिन ऐसा करना केवल एक उचित काम है, अर्थात्,

जब आप किसी गंभीर दस्तावेज़ में कुछ आरोप लगाते हैं
विधि आयोग की रिपोर्ट की तरह, आपको इससे निपटना चाहिए

सभी निष्पक्षता में उम्मीद की जाती है कि इन तथ्यों को होना चाहिए था
निपटा लिया। दुर्भाग्य से, कोई तथ्य निर्धारित नहीं किए गए हैं ताकि यह हो

संभालना असंभव है।

अगर यह कहा गया था कि यह सुपर कोर्टवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड था

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

ए के मामले में, यह बी या सी के मामले में हुआ था, यह

हमारे लिए उनसे निपटना आसान होता। विशेष रूप से

जब हमने इस बारे में सभी तथ्य दिए थे

1950 से प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति।

82. यदि कोई निष्कर्ष निकालता है, तो तथ्यात्मक से

गृह मंत्री के बयानों में दर्शाई गई संख्याएँ और

कानून मंत्री, और उससे निकाले गए निष्कर्ष, यह अधिक है

स्पष्ट रूप से, कि प्रभारी लोगों की समझ

संविधान के प्रावधानों को लागू करना,

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति यह थी कि

भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह होनी थी, और वास्तव में थी
प्रयोग करता है) द्वारा हमेशा स्वीकार किया जाता है।

राष्ट्रपति (या जो कोई भी,

नियुक्ति की शक्ति)।

83. ऐतिहासिक रूप से फिर से, न्यायिक दृष्टिकोण से

घोषणाएँ, हाथ में मुद्दे पर अपनाई गई प्रथा, आई

इस प्रकार समझने के लिए, समशेर सिंह मामले 11 में, जिसमें

इस न्यायालय ने सात न्यायाधीशों की पीठ के माध्यम से निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"संविधान की योजना के आलोक में हमारे पास है

राष्ट्रपति की व्यक्तिगत संतुष्टि के रूप में व्याख्या
सही है। हमारा विचार है कि राष्ट्रपति का अर्थ है -

सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, मंत्री या परिषद

संविधान का और न्यायसंगत ठहराने के लिए भरोसा किया गया है
विचलन, प्रासंगिक लेख निर्माण द्वारा संरक्षित है

भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श अनिवार्य है। कुल मिलाकर

संभावित मामलों में उस सर्वोच्च गणमान्य व्यक्ति के साथ परामर्श

भारतीय न्याय द्वारा स्वीकार किया जाएगा और किया जाना चाहिए
भारत सरकार और न्यायालय के पास एक अवसर होगा

यह जांचने के लिए कि क्या किसी अन्य बाहरी परिस्थिति में [2015] 13 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मंत्री के फैसले में प्रवेश किया, अगर वह छोड़ देता है

भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी गई सलाह। व्यवहार में

ऐसे संवेदनशील विषय में अंतिम शब्द होना चाहिए
भारत के मुख्य न्यायाधीश, उनकी सलाह की अस्वीकृति को आम तौर पर तिरछे विचारों द्वारा प्रेरित माना
जाता है

आदेश को दूषित करना। इस दृष्टिकोण से यह मायने नहीं रखता कि क्या

राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या न्याय मंत्री

औपचारिक रूप से इस मुद्दे का फैसला करता है। "

84. 1974 से, जब उपरोक्त निर्णय दिया गया था

प्रस्तुत, उपरोक्त घोषणा, क्षेत्र को धारण किया है, के रूप में

उपरोक्त निर्णय की न तो समीक्षा की गई है और न ही उसे दरकिनार किया गया है। यह इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, कि टिप्पणियों से निकाला गया है

समशेर सिंह मामले की पुष्टि पांच अन्य लोगों ने की।

संकलचंद हिम्मतलाल सेठ मामले में न्यायाधीश पीठ 5, के रूप में नीचे।

"तब यह, मेरे विचार में, सही अर्थ और सामग्री है।

अनुच्छेद 222 (1) द्वारा परिकल्पित परामर्श

संविधान। प्रमुख के साथ प्रभावी परामर्श के बाद

भारत के न्यायाधीश, यह राष्ट्रपति के लिए एक पर पहुंचने के लिए खुला है इस सवाल का उचित निर्णय कि क्या एक न्यायाधीश को करना चाहिए

दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए क्योंकि, क्या

प्रस्तावित स्थानांतरण के साथ उनकी सहमति नहीं। लेकिन यह है। भगवती और कृष्ण अय्यर, जे. जे. को दोहराना आवश्यक है।

शमशेर सिंह (ऊपर) में कहा गया है कि सभी में कल्पना की जा सकती है

मामले, भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करना चाहिए भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया जाए और कि न्यायालय

यह जांचने का अवसर मिलेगा कि क्या कोई अन्य बाहरी है

कार्यपालिका के फैसले में परिस्थितियाँ आ गई हैं

भारत: "व्यवहार में ऐसे संवेदनशील विषय में अंतिम शब्द भारत के मुख्य न्यायाधीश से संबंधित होना चाहिए, उनकी सलाह की अस्वीकृति को आम तौर पर तिरछा माना जाता है

आदेश को दूषित करने वाले विचार "। (पृष्ठ 873)।

यह उम्मीद की जाती है कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

कि ये शब्द बहरे कानों पर नहीं गिरेंगे और तब से

अब सामान्य स्थिति बहाल हो गई है, मतभेद हैं। यदि कोई हो। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच हल किया जाएगा

आपसी विचार-विमर्श, प्रत्येक पक्ष के विचारों पर विचार करना
अन्य सम्मान और विचार के साथ।

85. यहां तक कि प्रथम न्यायाधीशों के मामले में भी पी. एन. भगवती, जे.
एक शुद्धिपत्र के माध्यम से अपने स्वयं के आदेश को सही किया, जिसके द्वारा उसका
आदेश, अन्य बातों के साथ, निम्नानुसार दर्ज किया गया:

"भले ही सभी संवैधानिक द्वारा दी गई राय
इसके द्वारा परामर्श किए गए पदाधिकारी समान हैं, केंद्रीय
राय, हालांकि तीनों की सर्वसम्मत राय है
संवैधानिक पदाधिकारी, इसका बहुत महत्व होगा और
यदि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है
इस तरह की सर्वसम्मत राय की अवज्ञा, यह प्रथम दृष्टया हो सकता है
इस आधार पर हमला करने की संभावना है कि यह दुर्भावनापूर्ण है या
अप्रासंगिक आधारों पर आधारित। वही स्थिति होगी
यदि केंद्र द्वारा नियुक्ति की जाती है तो प्राप्त करें
प्रमुख की सर्वसम्मत राय के विपरीत सरकार
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश "।

उपरोक्त उद्धरण से यह स्पष्ट है कि

इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 149 में अभिलिखित टिप्पणियाँ समशेर सिंह मामला 11, का
संकालचंद में समर्थन किया गया था।

हिमतलाल सेठ मामले, और पहले में भी अपनाए गए थे
न्यायाधीशों का मामला। स्थिति व्यक्त की गई दूसरे और तीसरे न्यायाधीशों के मामलों में जोर
देकर, पढ़कर
न्यायपालिका को प्रधानता देने के रूप में "परामर्श" शब्द,
उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्तियों का मामला।

इस बार, दो अलग-अलग नौ-न्यायाधीशों के हाथों पीठों ने समशेर सिंह मामले में व्यक्त स्थिति को
दोहराया।

86. उपरोक्त अनुक्रम से पता चलता है कि कार्यकारी जबकि

प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए (और मुख्य सर्वोच्च
न्यायालय रिपोर्ट के स्थानांतरण के मामले में भी)

[2015] 13 एस सी आर।

एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश और न्यायाधीश), दूसरे संवैधानिक की भागीदारी को स्वीकार करते हुए पदाधिकारी (अनुच्छेद 124, 217 और 222 में संदर्भित), अपनाए गए

एक प्रक्रिया, जिसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रधानता,

शुरू से ही, की घोषणा के बाद संविधान, कार्यपालिका द्वारा, अपने आप में। जहाँ तक

विधायिका चिंतित है, यह स्पष्ट है कि यह मुद्दा सामने आया

चर्चा के लिए, प्रतिक्रियाशील तरीके से जब चौदहवाँ

न्यायिक सुधारों पर विधि आयोग की रिपोर्ट (1958),

संसद द्वारा 1959 में चर्चा की गई थी, बस

देश द्वारा शासित होने के कुछ वर्षों बाद

संविधान। यह स्पष्ट है कि जब दोनों सदन संसद ने अन्य बातों के साथ-साथ अनुच्छेद 124, 217 और 222 पर विचार किया।

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में,

सर्वसम्मत भावना जो उभरी, वह थी "। सलाह सबसे सक्षम आश्रित और प्रतिष्ठित व्यक्ति। ":-भारत के मुख्य न्यायाधीश का उचित रूप से पालन किया गया था। दो।

संसदीय चर्चा के पहलू, जिन्हें रखा गया था ध्यान रखें कि जब इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया था, तो इसे उजागर करने की आवश्यकता है।

पहला, कि राष्ट्रपति का अर्थ (सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए),

संबंधित मंत्री, या प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद। और दूसरा, कि विचाराधीन प्रावधान

अन्य संवैधानिक की केवल एक सहभागी भूमिका की परिकल्पना की गई अधिकारीगण। इसलिए, उपरोक्त पुष्टि, की प्रधानता के लिए

न्यायपालिका, उच्चतर न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में

न्यायपालिका, जानबूझकर दर्ज की गई थी, सराहना करने के बाद

अन्य भाग लेने वाले संवैधानिक अधिकारियों का सरगम।

न्यायिक निर्धारण के मामले में, इस मुद्दे की जांच की गई थी

उच्चतम न्यायालय की एक संविधान पीठ द्वारा, जहाँ तक कि
में, जिसमें ध्यान में रखते हुए

1974 में समशेर सिंह मामले 1 1

मुख्य सिद्धांत-"न्यायपालिका की स्वतंत्रता", यह

न्यायपालिका-भारत के मुख्य न्यायाधीश, व्यवहार में मतलब था,
न्यायाधीश यानी सर्वोच्च न्यायालय का होना चाहिए

कि अंतिम शब्द भारत के मुख्य

अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

उच्चतर न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में प्रधानता

न्यायपालिका को न्यायपालिका के साथ रहना चाहिए। उपरोक्त स्थिति थी

1977 में संकलचंद हिमतलाल सेठ मामले 5 में बनाए रखा गया,

पाँच-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा, केवल प्रथम न्यायाधीशों में बदला जाना

1981 में सात न्यायाधीशों की पीठ द्वारा मामला, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था,

कि "परामर्श" शब्द को "सहमति" के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है।

इस मामले में भी पी. एन. भगवती ने स्थिति स्पष्ट की,

जे. (जैसा कि वे तब थे), ऊपर निकाले गए, अनिवार्य रूप से भी होना चाहिए

ध्यान में रखें। पहले की स्थिति को 1993 में बहाल किया गया था

द्वितीय न्यायाधीशों के मामले में नौ न्यायाधीशों की पीठ (जिसने प्रथम न्यायाधीशों के मामले को खारिज
कर दिया)। स्थिति फिर से थी

नौ न्यायाधीशों की पीठ ने तीसरे न्यायाधीशों के माध्यम से इसकी पुष्टि की

मामला। ऐतिहासिक रूप से, इसलिए, शासन के तीनों अंग,

समान रूप से बनाए रखा है, कि नियुक्तियाँ करते समय

न्यायाधीशों से लेकर उच्च न्यायपालिका तक, "न्यायपालिका की स्वतंत्रता"

की भावना के एक अभिन्न घटक के रूप में स्वीकार किया गया था

संविधान, और इस प्रकार, में उपयोग किया जाने वाला शब्द "परामर्श"

विचाराधीन प्रावधानों को इस रूप में समझना था

विषयों के संदर्भ में न्यायपालिका को प्रधानता देना

अनुच्छेद 124, 217 और 222 के तहत विचार किया गया। इसे ध्यान में रखते हुए

ऐतिहासिक व्याख्या के ऊपर, वास्तव में कोई वैध कारण नहीं है

उत्तरदाताओं के लिए द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों के मामलों में निर्णयों की समीक्षा की मांग करना।

वी.

87. इरादे के विषय पर ध्यान देते हुए

संविधान सभा के सदस्यों द्वारा व्यक्त किया गया है कि

न्यायसंगत और समीचीन माना जाता है, जिसे भी ध्यान में रखा जाना चाहिए

अलगाव को अपनाने के संबंध में व्यक्त किए गए विचार

संविधान में शक्तियों का। जब द्वारा तैयार किया गया मसौदा

संविधान सभा बहस के लिए आई. डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

अनुच्छेद 39 ए में संशोधन का प्रस्ताव। यह प्रासंगिक होगा।

यह उल्लेख करने के लिए कि उपरोक्त संशोधन को स्वीकार किए जाने पर,

संविधान में अनुच्छेद 50 के रूप में शामिल किया गया था (मूल रूप से

अधिनियमित)। यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि सरकार [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान सभा के समक्ष बहस की जा रही है। बिनि।

संविधान सभा की बहसों में भागीदारी,

इसलिए, न केवल एक सदस्य के रूप में उनकी क्षमता में था

संविधान सभा, लेकिन इसके प्रतिनिधि के रूप में भी

भारत सरकार। इसके नीचे निष्कर्ष निकालना आवश्यक है,

जवाहरलाल नेहरू, बख्शी टेक चंद और

लोकनाथ मिश्रा, उपरोक्त बहसों में, "अलगाव" से संबंधित
नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

शक्तियों का "। प्रासंगिक उद्धरणों को

"माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू (संयुक्त)

प्रांत: जनरल):

..... इस विशेष मामले पर आते हुए, माननीय

अध्यक्ष, पंडित कुंजरू, जिन्होंने अभी-अभी बात की है और विरोध किया है

डॉ. अम्बेडकर का संशोधन मुझे लगता है; यदि मैं कर सकता हूँ

पूरी तरह से, और की ओर से एक भयावह उद्देश्य पर संदेह करने के लिए
इस व्यवसाय के बारे में सरकार। सरकार ऐसी है

इस व्यवसाय से संबंधित नहीं है, लेकिन यह सच है कि कुछ
सरकार के सदस्य इसके बारे में दृढ़ता से महसूस करते हैं और चाहते हैं कि यह सदन विशेष रूप से इस पर
विचार करे

डॉ. अम्बेडकर ने आज सदन के समक्ष जो दृष्टिकोण रखा है, हम सीधे कह सकते हैं कि जहाँ तक
सरकार की बात है

संबंधित है, यह पूरी तरह से अलगाव के पक्ष में है

न्यायिक और कार्यकारी कार्य (चीयर्स)। मैं आगे कह सकता हूँ

इसे जितनी जल्दी लाया जाए उतना ही अच्छा है (सुनो, सुनो)

वास्तव में अब उस लक्ष्य के लिए कदम उठा रहे हैं। अगर कोई मुझसे पूछे,
यदि किसी ने तीन साल या किसी अन्य अवधि का सुझाव दिया है

इस अवधि में, मेरी पहली प्रतिक्रिया यह रही होगी कि

बहुत लंबा है। हम इसके लिए इतना लंबा इंतजार क्यों करें? यह पूरे भारत में नहीं तो बड़े हिस्से में
लाया जा सकता है।

भारत, उससे बहुत जल्दी। साथ ही, यह स्पष्ट है कि भारत वर्तमान समय में, विशेष रूप से इस दौरान
संक्रमण काल, राजनीतिक रूप से एक बहुत ही मिश्रित देश है, सर्वोच्च न्यायालय

अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

समाज v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

न्यायिक, आर्थिक और कई तरीकों से, और प्रत्येक क्षेत्र में लागू होने वाला कोई भी निश्चित नियम हो सकता है

-

कुछ क्षेत्रों के संबंध में नुकसानदेह और कठिन। एक तरफ, यह नियम वास्तव में प्रगति को रोकेंगा।

एक क्षेत्र, और दूसरी ओर, यह सेब को परेशान कर सकता है
 किसी अन्य क्षेत्र में गाड़ी। इसलिए, एक निश्चित लचीलापन है
 वांछनीय। आम तौर पर, मैंने कहा होगा कि किसी भी
 नीति का ऐसा निर्देश, यह कानूनी नहीं हो सकता है, लेकिन कोई निर्देश
 संविधान में नीति का एक शक्तिशाली प्रभाव होना चाहिए। मैं। इस तरह के किसी भी निर्देश में
 कोई विवरण या समय सीमा आदि नहीं होनी चाहिए। यह एक निर्देश है कि राज्य क्या चाहता है, और आपका
 किसी भी प्रकार की समय-सीमा लगाने से इसे कम किया जा सकता है।
 राज्य नीति की उस उच्च स्थिति से और इसे नीचे लाता है
 एक विधायी उपाय का स्तर, जो इसमें नहीं है
 भावना। मैं वहाँ होने के लिए कोई समय-सीमा पसंद नहीं करता, लेकिन
 अधिक व्यावहारिक रूप से बोलते हुए, इसमें किसी भी समय-सीमा के रूप में डॉ।
 अम्बेडकर ने बताया कि एक तरफ देश के बड़े हिस्सों में इस प्रक्रिया में देरी करना उचित है, शायद
 देश का बड़ा हिस्सा; दूसरी ओर, कुछ हिस्सों में
 जहाँ व्यावहारिक रूप से इसे लाना बहुत मुश्किल हो सकता है
 के बारे में, यह भारी भ्रम पैदा कर सकता है। मुझे लगता है,
 इसलिए, कि डॉ. अम्बेडकर का संशोधन, इससे बहुत दूर है
 इसके महत्व या महत्व को कम करना
 वांछनीय परिवर्तन जो हम लाना चाहते हैं, उसे लागू करें
 देश के सामने एक उच्च स्तर। और मैं खुद को नहीं देखता
 कोई भी प्रांतीय या अन्य सरकार इसे कैसे भूल सकती है।
 भविष्य में किया जाना काफी हद तक भावना पर निर्भर करेगा। जनता और भविष्य की
 विधानसभाओं और संसदों का
 यह मुलाकात होगी। लेकिन जहाँ तक इस संविधान का संबंध है,
 यह एक तरह से ताकि इसे संभव बनाया जा सके जिन क्षेत्रों में इसे लाया जा सकता है-प्रांत,
 आदि।
 और किसी विशेष राज्य आदि में कठिनाई के मामले में, यह करता है उन्हें न बांधें।

इसलिए प्रस्तुत करें कि यह सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

(जय हो) "। "डॉ. बख्शी टेक चंद (पूर्वी पंजाब: सामान्य): श्री वाइस

अध्यक्ष महोदय, मैं अपना पूरा समर्थन देने के लिए उठती हूँ।

डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत किया गया संशोधन

आज। कार्यपालिका के पृथक्करण का प्रश्न और न्यायिक कार्य न केवल कांग्रेस के रूप में पुराने हैं,

लेकिन वास्तव में यह बहुत पुराना है। यह वर्ष 1852 में था जब

बंगाल में जनमत ने खुद को व्यक्त करना शुरू कर दिया संगठित रूप में कि मामला पहली बार उठाया गया था। वह यह था कि

कांग्रेस के आने से तीस साल पहले

अस्तित्व। विद्रोह के बाद, आंदोलन को लाभ हुआ

और सत्तर के दशक की शुरुआत में, बंगाल में, किस्टो दास पाल और राम गोपाल घोष के नेतृत्व में, उन दिनों जनमत के नेता कौन थे, निश्चित रूप से

न्यायपालिका के पृथक्करण के संबंध में प्रस्ताव और

कार्यकारी कार्यों को आगे रखा गया। इसके बाद,

स्वर्गीय मान मोहन घोष ने इस मामले को उठाया और उन्होंने और बाबू ने

सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने साल-दर-साल इसे उठाया।

सभी सार्वजनिक बैठकों में प्रश्न।

जब कांग्रेस पहली बार बॉम्बे में सत्र में मिली थी

1885, प्रशासन में इस सुधार को रखा गया था

अपने कार्यक्रम में सबसे आगे। बाद में, न केवल राजनेताओं के

सभी विचारधाराएँ, लेकिन यहाँ तक कि सेवानिवृत्त अधिकारी भी जिन्होंने वास्तव में प्रशासन में अपना जीवन बिताया,

उन्होंने इसे महत्व दिया और अपना समर्थन दिया। मुझे अच्छी तरह से याद है

1899 की लखनऊ कांग्रेस जब रोमेश चंदर दत्त,

जो अभी-अभी भारतीय सिविल सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे, उन्होंने अध्यक्षता की।

उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण का एक बड़ा हिस्सा इसी के लिए समर्पित किया।

विषय और इसके लिए एक अच्छा उत्साह पैदा किया। नहीं।

केवल इतना कि: यहाँ तक कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और सर आर्थर हॉबहाउस और सर आर्थर विल्सन जैसे अंग्रेज, दोनों

जो बाद में प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति के सदस्य बने, उन्होंने इसका समर्थन किया

और उन्होंने कई प्रतिष्ठित भारतीयों के साथ संयुक्त रूप से एक सर्वोच्च न्यायालय-ऑन-रिकॉर्ड प्रस्तुत किया

समाज v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

भारत के राज्य सचिव को देने के लिए प्रतिनिधित्व

इस सुधार का तत्काल प्रभाव। वर्ष 1912 में, जब लोक सेवा आयोग

श्री अब्दुर रहीम को नियुक्त किया गया था, जो एक न्यायाधीश थे

मद्रास उच्च न्यायालय और कई वर्षों तक राष्ट्रपति रहे। केंद्रीय विधानमंडल का, एक लंबा मिनट जोड़ा गया

असहमति और उसमें उन्होंने इसके लिए कई पृष्ठ समर्पित किए।

सवाल करते हैं। इसलिए, महोदय, यह मामला देश के समक्ष रहा है।

लगभग एक शताब्दी और यह समय है कि इसे प्रभाव दिया जाए

तुरंत। बोलने वाले माननीय सदस्यों में से एक

कल देखा कि यह मामला बहुत बड़ा था

महत्व तब था जब हमारे पास एक विदेशी सरकार थी लेकिन अब

इसे प्रभाव दें। खैर, इसका एक प्रभावी जवाब दिया गया है आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया। उसके पास है

स्पष्ट रूप से कहा कि यह सरकार की नीति है,

और यह देखना उनका इरादा है कि यह सुधार किया जाए

तत्काल प्रभाव।

XXXX

XXXX

XXXX

मुझे यह सुनकर खुशी हो रही है कि वह इसकी पुष्टि करते हैं। यह शांति देता है।

इन दो आपत्तियों के लिए जो उठाई गई हैं, कि

बदली हुई परिस्थितियों के कारण, क्योंकि हमारे पास है
स्वतंत्रता प्राप्त की, यह अब आवश्यक नहीं है और कि
वित्तीय बोझ इतना भारी होगा कि यह कुचल सकता है।
प्रांतीय सरकारें। ये दोनों आपत्तियाँ खोखली हैं। इस संबंध में मुझे एक शब्द और कहना है और
वह है,
कि लोकतंत्र और स्वतंत्रता के आगमन के साथ,
नौकरशाही सरकार के सदस्य जिनसे न्यायपालिका में हस्तक्षेप को पकड़ा गया था, लेकिन अब।
मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि कुछ मंत्रियों को भी
प्रांतों और राजनीतिक दलों के सदस्यों ने शुरू कर दिया है
न्याय के स्वतंत्र प्रशासन में हस्तक्षेप करना।

[2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आप, जो समाचार पत्रों में न्यायिक रिपोर्ट पढ़ रहे होंगे

हाल ही में लिए गए निर्णय इस प्रकार के रहे होंगे हस्तक्षेप जिसकी विभिन्न मामलों में समीक्षा की
जा रही है

हाल ही में उच्च न्यायालय। एक प्रांत में हमने पाया कि एक मामले में

और मुकदमा चलाने वाले मजिस्ट्रेट को रुकने का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित किया मामले में
कार्यवाही। यह बिल्कुल कुछ था

अनसुना। मामला अंततः उच्च न्यायालय तक गया।

और विद्वान मुख्य न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीश को

ऐसी कार्यपालिका के खिलाफ बहुत कड़ी टिप्पणी करें

एक अन्य प्रांत में एक के खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा था विधान सभा के सदस्य और एक
निर्देश चला गया

जिला मजिस्ट्रेट से लेकर मामले की सुनवाई करने वाले मजिस्ट्रेट तक

इसे आगे न बढ़ाने और आदमी को रिहा करने के लिए। द.

मजिस्ट्रेट जो न्यायिक सेवा का सदस्य था और

मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य कर रहा था जिसका विरोध करने की ताकत थी
यह माँग। उन्होंने उन सभी पत्रों को रिकॉर्ड में रखा था और
अंततः मामला उच्च न्यायालय तक चला गया और कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने इसे बहुत
मजबूत बना दिया।
इस विषय पर टिप्पणी करें।
पंजाब में फिर से हाल ही में एक मामला सामने आया है जिसमें
उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश, श्री न्यायमूर्ति अच्यु राम ने सुना कि
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की और 164 का निर्णय दिया जिन पृष्ठों के समापन पर
उन्होंने देखा कि
एक सदस्य के खिलाफ पुलिस अधीक्षक कांग्रेस पार्टी दुर्भावनापूर्ण थी और इसका परिणाम था
लोकतंत्र की शुरुआत, यह और भी अधिक हो गया है न्यायपालिका को अलग करने के लिए
आवश्यक
कार्यपालिका से जल्द से जल्द संभव अवसर पर "। सर्वोच्च अदालतें-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

88. इससे पहले दिए गए बयानों का अवलोकन

संविधान सभा, जिसके परिणामस्वरूप अनुच्छेद को अपनाया गया

50 संविधान से पता चलता है कि प्रथम प्रधानमंत्री

यह देश, पूरी तरह से न्यायिक विभाजन के पक्ष में था

और कार्यकारी "कार्य"। अलगाव के विषय पर, यह था इंगित किया कि यह एक निर्देश था जिसे
सरकार ने स्वयं दिया था

चाहते थे। डॉ. बख्शी टेक चंद का बयान

संविधान सभा इस स्थिति को प्रस्तुत करती है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का विचार
इस उद्देश्य के लिए रखा गया था कि

पहली बार 1852 में, और उसके बाद,

राजनीतिक नेतृत्व और जनमत भी निर्देशित किए गए थे

न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच अलगाव सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि "साल-दर-साल", देर से मान मोहन घोष और बापू सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने उठाया था तत्काल प्रश्न, सभी सार्वजनिक बैठकों में। और जब कांग्रेस की पहली बैठक 1885 में बॉम्बे में हुई थी, जिसमें अलग होने का मुद्दा था। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अन्य सभी से ऊपर रखा गया था विचाराधीन मुद्दे। इसके बाद, न केवल राजनेताओं ने

सभी विचारधाराओं के, लेकिन यहां तक कि सेवानिवृत्त अधिकारियों, जिनके पास था प्रशासन में अपना जीवन बिताया था, समर्थन किया था वास्तव में

"शक्तियों के पृथक्करण" का मुद्दा। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि

1899, रोमेश चंद्र दत्त ने अपना एक बड़ा हिस्सा समर्पित किया था।

इस मुद्दे पर राष्ट्रपति का संबोधन। और वह, सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय

सर आर्थर हॉबहाउस और सर आर्थर जैसे न्यायाधीश और अंग्रेज

विल्सन (दोनों, जो बाद में प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति के सदस्य बने) ने भी इसका समर्थन किया।

सुधार से ऊपर। यह बताया गया था कि बहस चल रही थी

जाना, "शक्तियों के पृथक्करण" के सिद्धांत को स्वीकार करना, जिससे न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा जाएगा।

उन्होंने उदाहरणों की ओर भी इशारा किया, जो हस्तक्षेप का संकेत देते हैं

मंत्री और प्रशासन के सदस्य, जो

के बीच शक्तियों के पूर्ण पृथक्करण की आवश्यकता थी

न्यायपालिका और कार्यपालिका। लोकनाथ मिश्रा ने पूरा समर्थन किया

सिद्धांत के रूप में उपरोक्त संशोधन। अतः यह है कि यह निष्कर्ष निकालना अनिवार्य है कि संविधान के निर्माता जबकि [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान के अनुच्छेद 50 का मसौदा तैयार करना स्पष्ट था और

उनके विचार में सर्वसम्मत्, कि न्यायपालिका की आवश्यकता है,
कार्यपालिका के प्रभावों से अलग।

89. में दर्ज विचार के आधार पर

पैराग्राफ के तुरंत पहले भी, हमें ऐसा लगता है कि
संविधान का विस्तृत संदर्भ देने की आवश्यकता
दूसरे न्यायाधीशों के मामले में विधानसभा की बहस हो सकती है
माना गया, क्योंकि इसका कोई गंभीर परिणाम नहीं था, क्या यह था
उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय पर,
कार्यपालिका की नियुक्ति में अंतिम शब्द होना उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों को स्पष्ट रूप से
खारिज कर दिया गया था। और

इसलिए, इस न्यायालय ने एक सामंजस्यपूर्ण निर्माण पर

द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों में संविधान के प्रावधान उचित रूप से अभिनिर्धारित मामले,
कि उपरोक्त मामले में प्रधानता, निहित

न्यायपालिका के साथ, निष्कर्ष की ओर ले जाते हुए, कि शब्द

"परामर्श" "संदर्भ के तहत प्रावधानों में, होना चाहिए

द्वारा व्यक्त विचार को प्रधानता देने के रूप में समझा गया

न्यायपालिका, भारत के मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से।

VI.

90. विद्वान महान्यायवादी द्वारा प्रस्तुत एक अन्य महत्वपूर्ण निवेदन से निपटना अनिवार्य है, अर्थात् -

कि "न्यायपालिका की स्वतंत्रता" के मुद्दे में कुछ भी नहीं है

उच्च पदों पर न्यायाधीशों की "नियुक्ति" की प्रक्रिया

न्यायपालिका। यह प्रस्तुत किया गया था कि स्वतंत्रता का सवाल

न्यायाधीश की नियुक्ति के बाद ही न्यायाधीश की नियुक्ति होती है।

उच्च न्यायपालिका), क्योंकि केवल तभी उसे संरक्षित किया जाना है

कार्यकारी/राजनीतिक दबावों और प्रभावों से।

यह सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड था।

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. /जगदीश सिंह खेहर, जे. जे.

यह विस्तार से बताने की मांग की गई कि उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति के तुरंत बाद इतनी अच्छी तरह से संरक्षित किया गया था कि स्वतंत्रता का कोई अवसर नहीं हो सकता था न्यायपालिका से किसी भी तरह से या तो समझौता किया जा रहा है कार्यपालिका या विधायिका के हाथ।

91. तत्काल विवाद को आगे बढ़ाते हुए, यह था

विद्वान महान्यायवादी का स्पष्ट दावा, कि न तो

द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों के मामलों में दिए गए निर्णयों में कहा गया था कि न्यायाधीशों का "चयन और नियुक्ति", उच्च न्यायपालिका के लिए, के दायरे में आएगा

"न्यायपालिका की स्वतंत्रता"। इसलिए यह उनका तर्क था,

कि उपरोक्त दो के आधार पर यह मान लेना गलत था

निर्णय, कि न्यायाधीशों की "नियुक्ति" का प्रश्न

उच्च न्यायपालिका "बुनियादी" का एक घटक होगी।

संविधान की संरचना। यह था विवाद

विद्वान महान्यायवादी, कि संसद ने अपने विवेक से अब संविधान में संशोधन किया था, स्वीकार किया कि

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों के "चयन और नियुक्ति" की प्रक्रिया (उनके स्थानांतरण सहित)। यह आगे तर्क दिया गया कि

संविधान के माध्यम से विचार की गई प्रक्रिया (99 वीं)

संशोधन) अधिनियम, एन. जे. ए. सी. अधिनियम के साथ, ऐसा था कि इसमें हस्तक्षेप या बाधा डालने वाला नहीं माना जा सकता था।

"न्यायपालिका की स्वतंत्रता", और इस प्रकार देखा गया, यह होगा

यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि विवादित संवैधानिक

संशोधन, साथ ही एन. जे. ए. सी. अधिनियम भी, अपने आप में उल्लंघनकारी थे

"मूल संरचना"।

92. हम यह ध्यान में रखते हुए अपने विचार की शुरुआत कर सकते हैं कि

1985 से हर दो साल में सुप्रीम कोर्ट का एक सम्मेलन

एशिया प्रशांत क्षेत्र के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा आयोजित किया गया है

लॉ एसोसिएशन फॉर एशिया का न्यायिक अनुभाग और
 प्रशांत। अपनी स्थापना के बाद से, सम्मेलन ने एक के रूप में कार्य किया है
 जानकारी साझा करने और मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उपयोगी मंच क्षेत्र के मुख्य न्यायाधीशों
 के बीच पारस्परिक चिंता। छठे स्थान पर
 1997 में बीजिंग में आयोजित सम्मेलन में 20 मुख्य न्यायाधीशों ने सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट को अपनाया

[2015] 13 एस सी आर।

स्वतंत्रता के सिद्धांतों का एक संयुक्त वक्तव्य
 न्यायपालिका "। इस कथन को 7 वीं के दौरान और परिष्कृत किया गया था।
 मनीला में मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें
 एशिया प्रशांत क्षेत्र के 32 मुख्य न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित। द.
 उपरोक्त कथन में व्यक्त की गई स्थिति "न्यायाधीशों की नियुक्ति का ब्यौरा नीचे दिया गया है:
 "न्यायाधीशों की नियुक्ति
 11. न्यायपालिका को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाना और
 अपने कार्यों का पालन करते हुए, यह आवश्यक है कि न्यायाधीशों का चयन किया जाए
 सिद्ध क्षमता, सत्यनिष्ठा और
 स्वतंत्रता।
 12. न्यायाधीशों की नियुक्ति का तरीका इस प्रकार होना चाहिए -
 उन व्यक्तियों की नियुक्ति सुनिश्चित करेंगे जो सबसे अच्छे हैं
 न्यायिक पद के लिए योग्य। इसे सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए।
 अनुचित के खिलाफ। प्रभावों को ध्यान में रखा जा रहा है
 कि केवल सक्षम, सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति और
 स्वतंत्रता नियुक्त की जाती है।
 13. न्यायाधीशों के चयन में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।
 नस्ल, रंग, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ,
 धर्म, राजनीतिक या अन्य राय, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल,

वैवाहिक स्थिति, यौन अभिविन्यास, संपत्ति, जन्म या स्थिति।
उम्मीद है कि एक आवश्यकता है कि न्यायिक पद के लिए एक उम्मीदवार

संबंधित देश का नागरिक नहीं होना चाहिए

भेदभावपूर्ण माना जाता है।

14. कानूनी पेशे की संरचना और स्रोत

जिन न्यायाधीशों को कानूनी पेशे के भीतर लिया जाता है, वे विभिन्न समाजों में भिन्न होते हैं। कुछ समाजों में न्यायपालिका

एक कैरियर सेवा है; अन्य में, न्यायाधीशों को चुना जाता है

पेशे का अभ्यास करना। अतः यह स्वीकार किया जाता है कि विभिन्न समाज, विभिन्न प्रक्रियाएँ और सुरक्षा उपाय

उचित नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए अपनाया जा सकता है

न्यायाधीशों।

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

15. कुछ समाजों में, न्यायाधीशों की नियुक्ति,

किसी न्यायिक सेवा की सहमति या उसके साथ परामर्श के बाद

आयोग को यह सुनिश्चित करने के एक साधन के रूप में देखा गया है कि

वे चुने गए न्यायाधीश इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त हैं।

जहां न्यायिक सेवा आयोग को अपनाया जाता है, वह उच्च न्यायपालिका के प्रतिनिधियों को शामिल करना चाहिए और

यह सुनिश्चित करने के साधन के रूप में स्वतंत्र कानूनी पेशा

न्यायिक क्षमता, अखंडता और स्वतंत्रता

बनाए रखा।

16. न्यायिक सेवा आयोग के अभाव में,

न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रियाएँ स्पष्ट होनी चाहिए परिभाषित और औपचारिक और उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए

जनता के लिए उपलब्ध हो।

17. न्यायाधीशों की पदोन्नति एक उद्देश्य पर आधारित होनी चाहिए।

क्षमता, सत्यनिष्ठा जैसे कारकों का मूल्यांकन,
स्वतंत्रता और अनुभव "।

इसलिए यह तर्क देने के लिए कि "नियुक्ति" का विषय
की स्वतंत्रता के सवाल के लिए अप्रासंगिक है
न्यायपालिका ", एक कुँ की गलतफहमी के रूप में माना जाना चाहिए
मान्यता प्राप्त स्थिति।

93. तत्काल विवाद से निपटने के दौरान, हम भी करेंगे

उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीश आवश्यक थे (या नहीं थे)। "न्यायपालिका की स्वतंत्रता" के
सिद्धांत का घटक?

जहाँ तक मामले के तत्काल पहलू का संबंध है,
पहली बार में संदर्भ, दूसरे को दिया जा सकता है

न्यायाधीशों का मामला, जिसमें एस. रत्नवेल पांडियन, जे., रिकॉर्डिंग करते हुए उनकी सहमति वाली
राय, बहुमत के दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए, देखी गई

निम्नानुसार:

" 47. उपरोक्त तर्क, कि की स्वतंत्रता

न्यायपालिका संवैधानिक रूप से संतोषजनक रूप से सुरक्षित है

उस पद की सुरक्षा जो एक न्यायाधीश रखता है और गारंटी देता है
केवल सेवा शर्तों में से और उससे आगे नहीं, [2015] 13 एस. सी. आर. में हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हमारी सुविचारित राय असमर्थनीय है। वास्तव में हम असमर्थ हैं
यहाँ तक कि इस तरह के तर्क की कल्पना करने के लिए भी

वर्तमान में कहा गया है "।

उपरोक्त उद्धरण के अलावा, इसका उल्लेख करना आवश्यक है

कुलदिप सिंह, जे. की निम्नलिखित टिप्पणियां। :

एक और बात, क्या चयन का तरीका और न्यायाधीशों की नियुक्ति, संविधान सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से शुरू की गई

अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. /जगदीश सिंह खेहर, जे. जे.

(99) अधिनियम को एन. जे. ए. सी. अधिनियम के साथ जोड़ा जा सकता है।
स्वतंत्रता" का उल्लंघन माना जाएगा।

"न्यायपालिका की

इस पहलू की स्वतंत्र रूप से जांच और निर्धारण किया जाएगा,
द्वारा उठाई गई चुनौती के गुणों की जांच करते हुए
याचिकाकर्ता।

VII.

94. संविधान के प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है,
कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के अलावा
और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, अनुच्छेद 124 के तहत,
राष्ट्रपति को भी नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है।
अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश।
उपरोक्त दोनों प्रावधानों में, राष्ट्रपति के लिए जनादेश,
अन्य बातों के साथ-साथ यह भी है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश हमेशा
परामर्श ", (पहला परंतुक, अनुच्छेद 124 (2) के तहत, मूल रूप से
अधिनियमित), और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में, अनुच्छेद 217 में निहित भाषा यह थी कि
राष्ट्रपति
मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति
भारत का न्याय "(अनुच्छेद 217 के उप-अनुच्छेद (1) के अनुसार)।

95. "परामर्श" शब्द को समझने के लिए
अनुच्छेद 124 और 217 में उपरोक्त दोनों की तुलना करना आवश्यक है।
संविधान के अन्य अनुच्छेदों के साथ, जिसके तहत

इसके अलावा, राष्ट्रपति को अलग-अलग नियुक्त करने के लिए अनिवार्य किया गया है
प्राधिकारी। इस संबंध में संदर्भ हो सकता है

संवैधानिक

नियंत्रक और लेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई
प्रावधान निहित है

भारत के जनरल, अनुच्छेद 148 के तहत। उक्त

राष्ट्रपति के साथ उपरोक्त नियुक्ति का अधिकार,

बिना किसी परामर्श प्रक्रिया के। स्थिति बिल्कुल समान है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यों के
राज्यपालों की नियुक्ति के संदर्भ में। उक्त प्रावधान में यह भी विचार किया गया है

बिना किसी परामर्श प्रक्रिया के नियुक्तियाँ। राष्ट्रपति

अध्यक्ष की नियुक्ति करने का अधिकार भी निहित है और

अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के चार सदस्य।

इसमें भी, शक्ति विशेष रूप से राष्ट्रपति के पास निहित है,

बिना किसी परामर्श प्रक्रिया के। नियुक्ति की शक्ति [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संघ लोक सेवा के अध्यक्ष और अन्य सदस्य

आयोग, अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास भी निहित है

316. उपरोक्त नियुक्ति में किसी अन्य प्राधिकारी के साथ किसी भी विचार-विमर्श पर विचार नहीं किया गया
है। अनुच्छेद 324 के तहत,

मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की शक्ति और

चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के पास निहित हैं। विशेष रूप से। इसी तरह, राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष,
उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का मामला है।

अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जाति आयोग और इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य
अनुच्छेद 338 ए के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग।

उपर्युक्त प्रावधानों के तहत, राष्ट्रपति के पास है -

नियुक्तियाँ करने का अनन्य अधिकार, बिना किसी के

किसी अन्य प्राधिकारी के साथ विचार-विमर्श। अनुच्छेद 344 के तहत,

राष्ट्रपति के पास अध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार भी निहित है।

और संसद आयोग के अन्य सदस्य

आधिकारिक भाषाएँ। तत्काल प्रावधान भी नहीं है
प्रक्रिया का प्रावधान करें।

ऐसी नियुक्ति से पहले किसी भी परामर्श

यही स्थिति अनुच्छेद 350 बी से भी सामने आती है, जिसके तहत

राष्ट्रपति को भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करना है। इसमें भी किसी पूर्व विचार का उल्लेख नहीं है।

परामर्श लें।

96. यह स्पष्ट है कि मंत्रिपरिषद, के साथ

इसके प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को अपने कार्यों के अभ्यास में "सहायता और सलाह" देते हैं। यह स्थिति विवादित नहीं है। उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील द्वारा।

विद्वानों के अनुसार, उपरोक्त तरीके से व्याख्या की गई

महान्यायवादी, अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए अनुच्छेद
124,217,148,155,180,316,324,338,338 ए, 344

और 350 बी, राष्ट्रपति केवल एक आलंकारिक प्राधिकारी है, जबकि

सच में, अधिकार वास्तव में मंत्रिपरिषद में निहित है

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। और इस तरह, सभी इरादों के लिए और

उद्देश्यों के लिए, नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति में निहित अधिकार विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों,
वास्तव में इसका मतलब है कि शक्ति

ऐसी नियुक्ति कार्यपालिका में निहित है।

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

97. अगर किसी को शब्दों को समझना था, जैसे वे थे

अनुच्छेद 74 में व्यक्त, हमारे सुविचारित विचार में, यह होगा

यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल है कि "सहायता और सलाह" को एक बाध्यकारी "दिशा" का पर्याय माना जा सकता है, जो एक अपरिवर्तनीय है।

"आदेश "या एक निर्णायक" जनादेश "। निश्चित रूप से, "सहायता" शब्द

और "सलाह" को व्यक्तिगत रूप से अनिवार्य नहीं माना जा सकता है।

हुकुम देना, जिसका सभी परिस्थितियों में पालन करना पड़ता था। में।

सामान्य भाषा में, "परामर्श" की एक प्रक्रिया वास्तव में है "सहायता और सलाह" की प्रक्रिया।
एकमात्र अंतर यह है कि

" "परामर्श" प्राप्त किया जाता है, जबकि "सहायता और सलाह" हो सकती है
टेंडर किया गया। इसलिए एक सादे पठन पर, दोनों में से कोई भी ("सहायता") नहीं है।
और सलाह "और" परामर्श ") को व्यक्त करने के लिए समझा जा सकता है,
कि वे बाध्यकारी प्रकृति के हो सकते हैं। हमारा मानना है कि
उपरोक्त अभिव्यक्तियों का उपयोग किया गया था, उच्च को ध्यान में रखते हुए
राष्ट्रपति का पद (प्रथम नागरिक के रूप में)
देश)। प्रथम नागरिक के रूप में, यह अपमानजनक होता
प्रदान करने के लिए, कि वह अपने कार्यों को अनुरूप रूप से निर्वहन करेगा
कार्यपालिका के निर्देशों, आदेश या अधिदेश के साथ।
चूंकि, दोनों अभिव्यक्तियाँ ("सहायता और सलाह" और
"परामर्श "), एक ही व्याख्या के योग्य है, यदि कोई एक
उन्हें अनिवार्य और बाध्यकारी माना जाता है, वही
दूसरे के संदर्भ में आयात का पालन करना चाहिए। के माध्यम से
संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976, अनुच्छेद 74
संशोधन किया गया, और शब्दों के सम्मिलन के साथ "होगा
..... ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करें "; राष्ट्रपति ने कहा
बाध्य होना, अपने कार्यों का प्रयोग करना, के अनुरूप
"मंत्री परिषद द्वारा उन्हें दी गई सहायता और सलाह
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। तत्काल संशोधन, हमारे
दृष्टिकोण, चरित्र में स्पष्टीकरण के रूप में माना जाना चाहिए, केवल
मूल प्रावधान के तरीके को दोहराते हुए
समझा गया है।

98. यदि "सहायता और सलाह" बाध्यकारी और अनिवार्य हो सकती है,

निश्चित रूप से "परामर्श" शब्द भी, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 124 में किया गया है
एक ही प्रदर्शनी का कारण बन सकता है।

और 217,

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के अध्यक्ष [2015] 13 एस. सी. आर.
 भारत, देश का पहला नागरिक होने के नाते, इसका हकदार है
 सम्माननीयता। अनुच्छेद 124 और 217, निस्संदेह थे।
 संवैधानिक मामले के रूप में विनम्र भाषा में
 यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 124 (2) के तहत पहला परंतुक स्पष्ट रूप से यह आदेश
 दिया गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश "हमेशा करेंगे"
 सलाह ली जाए। यह एक विपरीत दायित्व था, जिससे अलग किया जा सकता था
 अनुच्छेद 74। इसमें, राष्ट्रपति परामर्श करने के लिए बाध्य था
 न्यायाधीशों की नियुक्ति के सभी मामलों में भारत के मुख्य न्यायाधीश
 सुप्रीम कोर्ट तक। "परामर्श" की प्रक्रिया
 उसमें विचार किए जाने को सार्थक रूप से समझना होगा। अगर ऐसा है।
 ऐसा नहीं होना था, उपरोक्त प्रावधान इसी तरह का हो सकता था
 नियंत्रक की नियुक्ति से संबंधित शब्द
 और महालेखा परीक्षक-भारत के, राज्यों के राज्यपाल, अध्यक्ष
 और वित्त आयोग के सदस्य, अध्यक्ष और
 चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सदस्य
 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, और साथ ही, वे
 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। यह विरोधाभास
 किसी भी "परामर्श" की अनुपस्थिति, के संदर्भ में अनुच्छेद 148, 155, 180, 316 के तहत अनुध्यात
 नियुक्तियां,
 324, 338, 338 ए, 344 और 350 बी, किसी भी संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते हैं, कि उपरोक्त
 "परामर्श" एक सरलीकरण नहीं था।
 "परामर्श"। और तब से, न्यायपालिका में सर्वोच्च पदाधिकारी
 पदानुक्रम से परामर्श करने के लिए बाध्य था, एक समान सम्मान
 उसे देने की जरूरत थी। इसका क्या मूल्य होगा
 भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ अनिवार्य "परामर्श", यदि

उनकी सलाह को बिना किसी औचित्य के अस्वीकार किया जा सकता था? यह था।

इसलिए, इस न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि सभी कल्पनीय मामलों में,

न्यायपालिका में सर्वोच्च गणमान्य व्यक्ति के साथ परामर्श-प्रमुख भारत के न्याय को स्वीकार किया जाएगा और किया जाना चाहिए। और, इस मामले में

यदि इस तरह से स्वीकार नहीं किया गया था, तो यह जांच करने की अनुमति होगी कि क्या इस तरह की अस्वीकृति किसी तिरछे सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं-ऑन-रिकॉर्ड द्वारा प्रेरित थी

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

विचार करें। इसलिए उचित रूप से "परामर्श" शब्द का उपयोग किया गया है।

अनुच्छेद 124 और 217 में, जैसा कि वे मूल रूप से अधिनियमित किए गए थे,

कि द्वारा प्रस्तुत राय को प्रधानता दी जानी थी

भारत के मुख्य न्यायाधीश, उन मुद्दों पर जिनके लिए राष्ट्रपति

इस तरह के "परामर्श" की मांग करने के लिए बाध्य था। प्रस्तुतिकरण

उत्तरदाताओं की ओर से अग्रिम, स्वीकार नहीं किया जा सकता है, इस कारण से भी, कि उनके द्वारा दी गई व्याख्या

"परामर्श" शब्द के परिणामस्वरूप एक व्याख्या होगी

अनुच्छेद 124 और 217, अनुच्छेद 148, 155 और 280 के बराबर,

"परामर्श" का उपयोग नहीं किया गया था। ऐसी व्याख्या, स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य होना। नियुक्ति के तरीके के बाद से

उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीश, इसके विपरीत हैं

विद्वान वकील द्वारा संदर्भित संवैधानिक प्राधिकारी

जनरल, की ओर से प्रस्तुत किया गया अन्य संवैधानिक के संदर्भ में उत्तरदाता

वर्तमान विवाद पर अधिकारियों का कोई प्रभाव नहीं हो सकता है।

99. हम बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार करेंगे और स्वीकार करेंगे

विद्वान महान्यायवादी द्वारा की गई प्रस्तुति, जैसा कि है

ऊपर ध्यान दिया गया है, लेकिन केवल विभिन्न अनुच्छेदों के तहत विचार की गई नियुक्ति की स्थितियों तक सीमित है

संविधान, जहाँ नियुक्ति की शक्ति विशेष रूप से राष्ट्रपति के पास निहित है। इस तरह, किसी के लिए कोई जगह नहीं है

संदेह है कि संविधान के प्रावधान, के संदर्भ में

उच्च न्यायापालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति पर विचार किया गया कि "सहायता और सलाह"
(- "परामर्श") द्वारा दी गई

भारत के मुख्य न्यायाधीश, मामलों पर प्रधानता के हकदार थे अनुच्छेद 124 और 217 (साथ ही,
अनुच्छेद 222 के तहत भी) के तहत विनियमित।

VIII.

100. में निकाले गए निष्कर्षों की निरंतरता में

पूर्वगामी विश्लेषण, मामले की जांच दूसरे से की जा सकती है

दृष्टिकोण भी। "परामर्श" शब्द (संबंध में)

उच्च न्यायापालिका में न्यायाधीशों की नियुक्तियों के साथ)

[2015] 13 एस. सी. आर. की नियुक्ति के विषय पर अनुच्छेद 233 में अपनाया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जिला न्यायाधीश। अनुच्छेद 233 के तहत नियुक्ति की शक्ति

संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास निहित है, जो है

नियुक्तियाँ (पदोन्नति सहित) करने के लिए सशक्त

जिला न्यायाधीश। यह न्यायालय, पाँच न्यायाधीशों की पीठ के माध्यम से, पंजीयक (प्रशासन), उड़ीसा उच्च न्यायालय, कटक बनाम। शिशिर कांता सतपति 32, ने माना है कि उच्च द्वारा की गई सिफारिशें

अनुच्छेद 233 के तहत परिकल्पित परामर्श प्रक्रिया में न्यायालय,

राज्यपाल के लिए बाध्यकारी है। वनों के सामने

बाध्यकारी मिसाल, एक विवाद पर, जो आश्चर्यजनक रूप से समान है

हाथ में एक के लिए, और कभी पूछताछ नहीं की गई है, यह काफी है

यह समझ में नहीं आता कि भारत संघ कैसे राजी करना चाहता है

यह न्यायालय अब "परामर्श" शब्द की अलग तरह से जांच करेगा
में,

अनुच्छेद 124 और 217 के संदर्भ

किसी मामले के संदर्भ में उपरोक्त शब्द को दिया गया अर्थ

न्यायपालिका को भी नियंत्रित करता है।

VI. निष्कर्ष:

101. ऊपर दिए गए निष्कर्षों के आधार पर, जबकि

विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर विचार करना

प्रतिद्वंद्वी दलों के लिए, जैसा कि "वी-द

या इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की समीक्षा करते हुए,
मामलों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। द.

द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों के

तदनुसार, प्रार्थना अस्वीकार कर दी जाती है।

मेरिट पर आदेश

I. वरीयता

1. तत्काल आदेश को प्रस्तावना से शुरू करना आवश्यक है,

एक स्पष्टीकरण की प्रकृति में। के लिए, यह थोक को कम कर देगा

तत्काल आदेश, और उन मुद्दों से निपटने की आवश्यकता को दूर करता है जिन पर विचार किया गया है और
जिनसे निपटा गया है, सुनवाई करते समय

मामलों का वर्तमान समूह।

32 (1999) 7 एस. सी. सी. 725 सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

2. जिस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए

मामलों का वर्तमान समूह की संवैधानिक वैधता से संबंधित है

संविधान (नब्बे-नौवां संशोधन) अधिनियम, 2014

[इसके बाद संविधान (99 वां संशोधन) के रूप में संदर्भित किया गया

अधिनियम], और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियों का भी

आयोग अधिनियम, 2014 (इसके बाद एन. जे. ए. सी. के रूप में संदर्भित)

अधिनियम)। विचार के लिए उत्पन्न होने वाला मुख्य मुद्दा संबंधित है -

चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया की वैधता

उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीश (अर्थात् मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश)

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय का), और

एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश, दूसरे को।

3. पारित आदेशों की श्रृंखला में यह तीसरा आदेश है।

हमारे द्वारा, वर्तमान विवाद पर निर्णय लेते हुए। पहला आदेश, बार में की गई प्रार्थना से संबंधित था, "अलग होने" के लिए।

हममें से एक (जे. एस. खेहर, जे.) ने वर्तमान मामलों की सुनवाई की। जैसे ही और जब पहले उपरोक्त का संदर्भ दिया जाता है

आदेश के अनुसार, इसे "निष्कासन आदेश" के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। द. दूसरा क्रम, विद्वानों द्वारा की गई प्रार्थना माना जाता है

महान्यायवादी और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ विद्वान वकील उत्तरदाता, वर्तमान विवाद का "संदर्भ" मांगते हुए,

उच्चतम न्यायालय में दिए गए निर्णय की पुनः जांच करने के लिए नौ न्यायाधीशों की पीठ (या उससे भी बड़ी पीठ) को

अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम। भारत संघ 2

(इसके बाद द्वितीय न्यायाधीशों के मामले के रूप में संदर्भित), और री में सलाहकार राय: 1998 का विशेष संदर्भ संख्या 1 3

(इसके बाद, तीसरे न्यायाधीशों के मामले के रूप में संदर्भित),

पुनर्स्थापित करने और पुनर्स्थापित करने का कथित उद्देश्य, घोषणा

एस. पी. गुप्ता बनाम में इस न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई कानूनी स्थिति। भारत संघ 1 (इसके बाद प्रथम न्यायाधीशों के रूप में संदर्भित)

मामला)। जैसे ही और जब उपरोक्त सेकंड का संदर्भ दिया जाता है आदेश में, इसका उल्लेख "संदर्भ आदेश" के रूप में किया जाएगा।

4. इसलिए हम उन मुद्दों की जांच नहीं करेंगे जिनसे निपटा गया है।

निरस्तीकरण आदेश और/या संदर्भ आदेश में, यहां तक कि

यद्यपि वे फिर से विचार के लिए उठ सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर. में।

गुण-दोष के आधार पर वर्तमान विवाद के निपटारे की प्रक्रिया के रूप में आदेश का संदर्भ दिया जाता है,

और जब तत्काल तीसरे

विवाद के "गुणों" की जांच करते हुए, यह विज्ञापित किया जाएगा "गुणों पर आदेश" के रूप में।

II. मेरिट पर याचिकाकर्ताओं की सामग्री:

5. के आधार पर संविधान में संशोधन के विषय पर

अनुच्छेद 368 में प्रदान की गई प्रक्रिया, इसे प्रस्तुत किया गया था

श्री फली एस. नरीमन, वरिष्ठ अधिवक्ता, की शक्ति था।

संविधान में संशोधन एक पूर्ण शक्ति नहीं है। यह

इंगित किया कि उपरोक्त शक्ति सीमित थी, क्योंकि,

संशोधन की शक्ति में संशोधन की शक्ति शामिल नहीं थी

संविधान की "मूल" या "मूल संरचना"। इसमें

पक्ष से, विद्वान वकील ने मिनर्वा मिल्स लिमिटेड पर निर्भरता रखी।

वी. भारत संघ 33, जिसमें बहुमत का विचार व्यक्त किया गया था

वाई. वी. चंद्रचूड़, सीजे के माध्यम से।, निम्नानुसार:

"17. चूंकि संविधान ने एक सीमित

संसद की शक्ति में संशोधन, संसद नहीं कर सकती

उस सीमित शक्ति के प्रयोग के तहत बहुत बड़ा हो जाता है

एक पूर्ण शक्ति में शक्ति। वास्तव में, एक सीमित संशोधन शक्ति हमारे संविधान की बुनियादी विशेषताओं में से एक है और

इसलिए, उस शक्ति पर सीमाएं नहीं हो सकती हैं

नष्ट कर दिया। दूसरे शब्दों में कहें तो। संसद इसके तहत नहीं कर सकती है।

अनुच्छेद 368 अपनी संशोधन शक्ति का विस्तार करता है ताकि इसे प्राप्त किया जा सके।

अपने लिए संविधान को निरस्त करने या निरस्त करने का अधिकार या

इसकी बुनियादी और आवश्यक विशेषताओं को नष्ट करना। द डोने ऑफ़ ए

सीमित शक्ति उस शक्ति के प्रयोग से परिवर्तित नहीं हो सकती है।

एक असीमित शक्ति में सीमित शक्ति "।

उपरोक्त निर्णय में अल्पमत का दृष्टिकोण दर्ज किया गया था

पी. एन. भगवती, जे. द्वारा (जैसा कि वे तब थे), निम्नानुसार:

"88. यह हमें अनुच्छेद 368 के खंड (5) पर ले जाता है। यह खंड

"संदेह दूर करने के लिए" शब्दों के साथ खुलता है और यह घोषणा करने के लिए आगे बढ़ता है कि कोई सीमा नहीं होगी

अनुच्छेद के तहत संसद की संशोधन शक्ति पर जो कुछ भी हो

33 (1980) 3 एस. सी. सी. 625 सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्डसमाज v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

368. उद्घाटन के अर्थ को समझना मुश्किल है। "संदेह दूर करने के लिए" शब्द क्योंकि बहुमत

केशवानंद भारती मामले में निर्णय: ए. आई. आर 1973 एस. सी 1461

स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि मूल संरचना संविधान की धारा संसद और इंदिरा गांधी की संशोधनकारी शक्ति की क्षमता से बाहर थी।

मामला [1976] 2 एससीआर 341, सभी न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से

मूल संरचना के सिद्धांत को एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया जिसके द्वारा

उनके समक्ष आक्षेपित संशोधन की वैधता,

अर्थात् अनुच्छेद 329-ए (4) पर निर्णय लिया जाना था। इसलिए इसके बाद

केशवानंद भारती मामले में निर्णय और इंदिरा

गाँधी के मामले में, इसमें कोई संदेह नहीं था कि संशोधन

संसद की शक्ति सीमित थी और यह सक्षम नहीं थी।

संविधान की मूल संरचना को बदलने के लिए संसद को

और खंड (5) उस संदेह को दूर नहीं कर सका जो नहीं था करने की कोशिश की गई थी कि उसे हटा दिया जाए।

मौजूद है। खंड (5) में वास्तव में क्या

संसद की संशोधन शक्ति पर सीमा और

इसे सीमित शक्ति से असीमित शक्ति में परिवर्तित करें। यह स्पष्ट रूप से और निर्विवाद रूप से एक व्यर्थ अभ्यास था संशोधन ताकि स्वयं को निरसन की शक्ति प्रदान की जा सके या संविधान को निरस्त करना या उसे नुकसान पहुंचाना या नष्ट करना। बुनियादी संरचना। यह स्पष्ट रूप से अधिक होगा संसद के पास संशोधन करने की सीमित शक्ति है। संविधान ने केवल एक सीमित संशोधन शक्ति प्रदान की है संसद पर ताकि वह संविधान के मूल ढांचे को नुकसान या नष्ट न कर सके और संसद द्वारा उस सीमित संशोधन शक्ति का प्रयोग उसे परिवर्तित कर देता है एक पूर्ण और असीमित शक्ति में शक्ति। अगर ऐसा होता। इसे एक पूर्ण शक्ति में प्रदान की गई शक्ति संशोधन, तब एक सीमा रखना अर्थहीन था संशोधन की मूल शक्ति पर।

अदालत की रिपोर्टों का समर्थन करना मुश्किल है

[2015] 13 एस सी आर।

इस बात की सराहना करें कि कैसे संसद के पास सीमित शक्ति है संशोधन का प्रयोग करके सीमा से छुटकारा पाया जा सकता है बहुत शक्ति और इसे एक पूर्ण शक्ति में परिवर्तित करें। खंड (5) अनुच्छेद 368 जो पर सीमा को हटाने की मांग की संसद को पूर्ण बनाकर उसकी संशोधन करने की शक्ति इसलिए इसे संशोधन शक्ति से बाहर माना जाना चाहिए। संसद से। एक और आधार भी है जिस पर इस खंड की वैधता पर सफलतापूर्वक हमला किया जा सकता है। यह खंड एक नियंत्रित संविधान को एक में बदलने का प्रयास करता है संशोधन पर सीमा को हटाकर अनियंत्रित संसद की शक्ति जो, जैसा कि ऊपर बताया गया है, स्वयं है संविधान की एक अनिवार्य विशेषता है और इसलिए यह है

मूल संरचना का उल्लंघन। परिस्थितियों में मैं

अनुच्छेद 368 के खंड (5) को असंवैधानिक और अमान्य ठहराएँ।

उसी प्रस्ताव के संदर्भ में, विद्वान वकील

किहोतो होलोहन बनाम पर निर्भरता रखी गई। ज़किलू 3 4. यह था।

संविधान की संरचना, जिसके परिणामस्वरूप संशोधन को सीमित किया गया
अभिनिर्धारित शक्ति।

अनुच्छेद 368 में

6. विद्वान वकील के अनुसार, अब यह स्वीकार किया जाता है,

"संविधान की मूल संरचना। उपरोक्त दृश्य में विषय, न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान

उच्च न्यायपालिका को ऐसा होना चाहिए कि उपरोक्त सिद्धांत अक्षुण्ण और अक्षुण्ण रहें। यह प्रस्तुत किया गया
था कि किसी भी

ऐसी कार्रवाई जो नियुक्ति करने का परिणाम होगी

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, जो स्वयं न्यायपालिका के अलावा किसी अन्य एजेंसी
के अधीन हैं, अर्थात् - कार्यपालिका या विधायिका को भाग लेने की अनुमति देकर

उनका चयन और नियुक्ति, न्यायपालिका को प्रदान करेगी

इस तरह के अधिकार के अधीन, और इस प्रकार,

"न्यायपालिका की स्वतंत्रता "।

34 1992 पूरक (2) एस. सी. सी. 651 सर्वोच्च अदालतें-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे. जे.

7. विद्वान वकील ने न्यायालय का ध्यान आकर्षित करने के लिए आमंत्रित किया

1 "न्यायिक सुधार" पर प्रथम विधि आयोग की रिपोर्ट

प्रशासन "(भारत के विधि आयोग की 14 वीं रिपोर्ट,

एम. सी. सीतलवाड़ की अध्यक्षता में), जिस पर बहस की गई थी, कि

संविधान के निर्माताओं, अनुच्छेद 124 और 217 को लागू करना
को नियुक्त करने का प्रयास किया था

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों

"कार्यकारी नियंत्रण से ऊपर "। उक्त रिपोर्ट के पैराग्राफ 4 को नीचे निकाला जा रहा है:

"(न्यायाधीशों की नियुक्ति और निष्कासन)

4. रक्षा के महत्व को समझना

न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान ने प्रदान की है

कि उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा
भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति

और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे अन्य न्यायाधीशों के साथ परामर्श करने के बाद
जो वह समझे

आवश्यक है। वे 65 वर्ष की आयु तक इस पद पर बने रहते हैं।

वर्ष और एक द्वारा पारित संसद के प्रत्येक सदन द्वारा एक संबोधन की प्रस्तुति को छोड़कर
अपरिवर्तनीय है

सिद्ध दुर्व्यवहार के आधार पर निर्दिष्ट बहुमत

या असमर्थता। इस प्रकार संविधान ने प्रयास किया है कि
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यकारी नियंत्रण से ऊपर रखें। "

8. यह प्रस्तुत किया गया था कि "न्यायपालिका की स्वतंत्रता"

मान लिया गया था और शामिल किया गया था, उच्च के इन्सुलेशन
कार्यपालिका और विधायी नियंत्रण से न्यायपालिका। इस संबंध में,
भारत संघ बनाम का संदर्भ दिया गया था। संकलचंद हिमतलाल
सेठ 5, जिसमें इस न्यायालय ने टिप्पणी की थी:

"50. अब न्यायपालिका की स्वतंत्रता एक लड़ाई है
हमारे संविधान में विश्वास। निर्भीक न्याय एक प्रमुख पंथ है

हमारे संस्थापक दस्तावेज़। यह वास्तव में हमारे प्राचीन काल का एक हिस्सा है।

परंपरा जिसने अतीत में महान न्यायाधीश पैदा किए हैं। में।

इंग्लैंड भी, जहाँ से हमें अपना वर्तमान विरासत में मिला है

न्याय के प्रशासन की प्रणाली अपने व्यापक और आवश्यक रूप में

विशेषताएँ, न्यायिक स्वतंत्रता एक बुनियादी मूल्य के रूप में मूल्यवान है

और इसलिए स्वाभाविक और अपरिहार्य इसे [2015] 13 एस. सी. आर. माना जाने लगा है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और इस तरह से यह जीवन और विचार में अंतर्निहित हो गया है

वे लोग जिन्हें अब लगभग हल्के में लिया जाता है और यह किसी के भी सोचने के लिए पागलपन का कार्य माना जाएगा

अन्यथा। लेकिन यह लंबे समय के बाद पूरा किया गया है।

लड़ाई का समापन निपटान अधिनियम, 1688 में हुआ। इससे पहले

उस अधिनियम के अधिनियमन, इंग्लैंड में एक न्यायाधीश ने कार्यकाल आयोजित किया

क्राउन और संप्रभु की खुशी खारिज कर सकती थी

अपने विवेकाधिकार पर न्यायाधीश, यदि न्यायाधीश अपनी पसंद के अनुसार निर्णय नहीं देता है। एक न्यायाधीश से कम प्रसिद्ध नहीं

लॉर्ड कोक को चार्ल्स प्रथम ने राजा के आदेश का पालन करने से उनके शानदार और साहसी इनकार के लिए बर्खास्त कर दिया था।

प्रक्रिया उसे कदम उठाने का आदेश देने के लिए असंसदीय है या उसके न्यायालय में कार्यवाही में देरी करना। निपटान अधिनियम,

1688 एक को खारिज करने के लिए इसे संप्रभु की शक्ति से बाहर कर दें

अच्छे समय के दौरान 'कार्यकाल' को प्रतिस्थापित करके खुशी से न्याय करें

'आनंद में कार्यकाल' के लिए व्यवहार। न्यायाधीश तब कर सकते थे

ये ऐसे दिन नहीं हैं जब कोई भी अंग्रेजी न्यायाधीश ऐसा करने में विफल रहेगा। गर्वित चेतना में उठने के अपने अधिकार का दावा करें कि

न्याय महामहिम के क्षेत्र में प्रशासित किया जाता है

रानी, बेदाग, बेदाग, और असुरक्षित। वहाँ

हमारे संविधान निर्माता इन बातों से अवगत थे इंग्लैंड में संवैधानिक विकास और वे थे

न्यायिक स्वतंत्रता की हमारी महान परंपरा के प्रति जागरूक

और निष्पक्षता और उन्होंने महसूस किया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने की आवश्यकता और भी अधिक थी

संघीय या अर्ध-संघीय संविधान जो प्रदान करता है मौलिक अधिकार, अन्य संवैधानिक सीमाओं को लागू करता है-सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

समाज v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है और इसके परिणामस्वरूप भारत संघ

और राज्य सबसे बड़े एकल वादी बन जाएंगे

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के समक्ष। न्याय,

जैसा कि इस न्यायालय ने शमशेर सिंह बनाम में बताया है। की स्थिति

पंजाब। (1974) 2 एस. सी. सी. 831, "निडर और स्वतंत्र" बन सकता है।
संस्थागत प्रतिरक्षा और स्वायत्तता की गारंटी हो।

केवल तभी जब

इसलिए संविधान निर्माताओं ने कई अधिनियम बनाए।

की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए बनाए गए प्रावधान

उच्च न्यायपालिका को कार्यपालिका या विधायी से अलग करके

नियंत्रण करें। मैं संक्षेप में इन प्रावधानों का उल्लेख यह दिखाने के लिए करूंगा कि कैसे
सुनिश्चित करने के लिए संविधान निर्माताओं की बड़ी चिंता थी

यह

उच्चतर न्यायपालिका की स्वतंत्रता और किसके साथ

सावधानीपूर्वक देखभाल करते हुए उन्होंने इसके लिए प्रावधान किए।

तुरंत प्रस्तुत करने की निरंतरता में, सीखा

स्वयं दूसरे न्यायाधीशों के मामले पर भरोसा किया, और आकर्षित किया

एस द्वारा अभिलिखित निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख।

अवेल पांडियन, जे। :

"54. इस अवधारणा के महत्व को ध्यान में रखते हुए

हमारे संविधान के निर्माताओं के सामने विचार हैं

संघीय न्यायालय और उच्च न्यायालय ने कहा है कि

ज्ञापन:

"हमने मान लिया है कि यह सभी हाथों से मान्यता प्राप्त है कि

न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अखंडता

सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली सर्वोच्च है।
लिए भी महत्व और हित

न केवल न्यायाधीशों के लिए बल्कि न्यायाधीशों के

बड़े पैमाने पर नागरिक जिन्हें अंतिम समय में निवारण की मांग करनी पड़ सकती है
अवैध कार्य या उच्च न्यायालय के खिलाफ कानून की अदालतों का सहारा लें

किसी भी

कार्यपालिका द्वारा शक्ति का प्रयोग सौंपना, बनाने में

निम्नलिखित प्रस्ताव और सुझाव, सर्वोपरि

एक के निडर कामकाज को सुरक्षित करने का महत्व

स्वतंत्र और कुशल न्यायपालिका को लगातार बनाए रखा गया है
राव: द फ्रेमिंग ऑफ इंडिया

देखने में। (वीडियो बी. शिवा

संविधान, खंड 1-बी, पी। 196)

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

55. इस संदर्भ में, हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि

न्यायमूर्ति कृष्ण लायर के अद्वितीय शब्द, "स्वतंत्रता

न्यायपालिका छल नहीं है, न ही इसका विरोध है

"संवैधानिक धर्म" के रूप में अवधारणा।
अवधारणा

56. निर्विवाद रूप से न्यायपालिका की स्वतंत्रता की यह

जो अटूट रूप से जुड़ा हुआ है और इसके साथ जुड़ा हुआ है

न्यायपालिका के कामकाज से संबंधित संवैधानिक प्रक्रिया

इस अवधारणा का मूल अभिधारणा अधिक होना है
प्रभावी न्यायिक प्रणाली

अपनी पूरी ताकत और जीवंतता के साथ

अनिवार्य विश्वास को सुरक्षित और मजबूत करने के लिए

न्याय के प्रशासन में लोग। केवल इसके साथ

इस सिद्धांत को सफलतापूर्वक प्राप्त करने का उद्देश्य और

वर्तमान न्यायिक प्रणाली से संबंधित अधिकांश समस्याओं को दूर करते हुए, अन्य बातों के साथ, यह तर्क दिया
गया है कि मामले में

उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति अदालत की 'प्रधानता' जो केवल एक है

सीजेआई की राय के लिए

इस अवधारणा के पहलू को दिया जाना चाहिए ताकि

न्यायपालिका की स्वतंत्रता दृढ़ता से सुरक्षित और संरक्षित है
लिए अतिवादी कार्यकारी घुसपैठ

और अपने आप को लागू करने के

उच्च न्यायपालिका में चयनित व्यक्ति को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जाता है

और दबाया गया। "

और उसी फैसले से, संदर्भ दिया गया था

कुलदिप सिंह, जे. :

"335. फिर वह प्रश्न जो विचार के लिए आता है

क्या एक स्वतंत्र न्यायपालिका हो सकती है जब शक्ति

न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका में निहित है? कहने के लिए

हां, यह अतार्किक होगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता है

अटूट रूप से जुड़ा हुआ और संवैधानिक रूप से जुड़ा हुआ

उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया।

'न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमारे सर्वोच्च न्यायालय की मूल विशेषता है

अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

संविधान और यदि इसका मतलब है तो हमने ऊपर चर्चा की है।

तब संविधान निर्माता कभी नहीं कर सकते थे

यह शक्ति कार्यपालिका को देने का इरादा है। अन्यथा भी।

सरकारें-केंद्र या राज्य-पहले पक्ष हैं।

बड़ी संख्या में मामलों में न्यायालय। संघ कार्यकारी

आने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों में महत्वपूर्ण रुचि रखते हैं

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए। कार्यकारी-में

एक या दूसरा रूप सबसे बड़ा एकल वादी है

अदालतें। मामले के इस दृष्टिकोण में न्यायपालिका है

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार और कार्यपालिका के हाथों में उच्च न्यायालयों का। यह न्यायालय

एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ, 1981 पूरक एस. सी. सी. 87

इस धारणा पर आगे बढ़े कि की स्वतंत्रता

न्यायपालिका संविधान की मूल विशेषता है लेकिन विफल रही

यह समझने के लिए कि व्याख्या, इसने दी, में नहीं थी

दोनों अवधारणाओं के व्यापक पहलुओं के साथ अनुरूपता -

'न्यायपालिका की स्वतंत्रता 'और' न्यायिक समीक्षा 'जो हैं

आपस में जुड़े हुए "।

उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर, यह प्रस्तुत किया गया था कि

"न्यायपालिका की स्वतंत्रता को तभी बनाए रखा जा सकता है जब न्यायाधीशों की नियुक्ति, द्वारा की गई थी

उच्च न्यायपालिका में

मुख्य न्यायाधीश की राय की प्रधानता के अनुसार,

न्यायाधीशों के कॉलेजियम के निर्णय पर। तभी कार्यकारी और विधायी घुसपैठ प्रभावी ढंग से हो सकती है।

नियंत्रित और नियंत्रित।

9. विद्वान वकील, फिर एक संदर्भ बनाने का साहस किया

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के अक्सर उद्धृत भाषण में

24.5.1949) पर संविधान सभा। यह प्रस्तुत किया गया था कि

उपरोक्त भाषण पर द्वितीय न्यायाधीशों में विधिवत विचार किया गया था

मामला, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला:

"389. यह मानते हुए कि मामले में प्रधानता

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति [2015] 13 एस. सी. आर. के साथ निहित है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायपालिका, वह महत्वपूर्ण प्रश्न जो उत्पन्न होता है

विचार यह है कि क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश,

संविधान, एक "व्यक्ति पदनाम" के रूप में कार्य करता है या

नेता-न्यायपालिका के लिए प्रवक्ता।

390. संवैधानिक योजना को प्रधानता नहीं दी जाती है

कोई भी व्यक्ति। अनुच्छेद 124 (2) के साथ परामर्श प्रदान करता है

भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। इसी तरह अनुच्छेद 217 (1) की बात करता है

भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

अदालत। परामर्शों की बहुलता का स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया है

ऐसा आभास होता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों को इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया है

अनुच्छेद 217 (1) के तहत परामर्श लेकिन एक करीबी जांच पर

संवैधानिक योजना से पता चलता है कि यह नहीं था

संविधान निर्माताओं का इरादा। वहाँ है।

पुसिन को बाहर करने के लिए कोई औचित्य नहीं है

से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

संविधान के अनुच्छेद 217 (1) के तहत "वाणिज्य दूत क्षेत्र"।

391. श्री नरीमन के अनुसार यह तनावपूर्ण नहीं होगा। अभिव्यक्तियों का अर्थ लगाने के लिए निर्माण "के मुख्य न्यायाधीश

भारत "और" उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश "के अर्थ में

न्यायाधीशों की सामूहिकता, उच्चतम न्यायालय के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश और सभी उच्च न्यायाधीशों द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया

(संबंधित राज्यों के) न्यायालयों का प्रतिनिधित्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 124 (2) का अवर रीडिंग

और 217 (1) यह स्पष्ट करता है कि के निर्माता संविधान का अंतिम शब्द छोड़ने का इरादा नहीं था,

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला,
 किसी भी व्यक्ति के हाथ चाहे वह कितना भी ऊँचा हो
 संवैधानिक पदानुक्रम। वाणिज्य दूतों का सामूहिक ज्ञान
 ऐसी नियुक्तियों के लिए अनिवार्य है। डॉ. बी. आर.

अम्बेडकर 24 मई, 1949 को संविधान में अपने भाषण में
 व्याख्या करते हुए सभा

संबंधित मसौदा लेखों के दायरे की

उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए।

सर्वोच्च अदालतें-चालू-रिकॉर्डसमाज v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

XXX

XXX

XXX

392. डॉ. अम्बेडकर ने सुचारू रूप से काम करने में कोई कठिनाई नहीं देखी।
 प्रावधानों का संचालन

संबंधित संवैधानिक

संविधान निर्माताओं ने आश्वस्त महसूस किया कि
 यह है।

नियुक्तियाँ हमेशा सर्वसम्मति से की जाती थीं।

अतीत के दौरान संविधान का कार्यकरण अधिक

चार दशकों से अधिक जो आवश्यकता लेकर आया है

इस तरह के मामले में प्रधानता के सवाल पर विचार करना

नियुक्तियाँ। एक बार जब हम मानते हैं कि प्रधानता के साथ निहित है

न्यायपालिका, फिर यह सामूहिकता के रूप में न्यायपालिका है जो

प्राइमल कहते हैं और कोई भी व्यक्ति नहीं, यहां तक कि प्रमुख भी नहीं

भारत का न्याय। अगर हम "प्रमुख" अभिव्यक्ति की व्याख्या करते हैं

भारत का न्याय "एक" व्यक्ति पदनाम "के रूप में तब यह होगा
 व्यावहारिक रूप से वीटो करने की अनुमति देने के लिए

राशि "मुख्य न्यायाधीश को

न्यायाधीशों की नियुक्ति "जिसके निर्माता

डॉ. अम्बेडकर के शब्दों में संविधान का कभी इरादा नहीं था

करने के लिए। इसलिए, हमारा विचार है कि अभिव्यक्तियाँ
 "भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश
 उच्च न्यायालय "संविधान के अनुच्छेद 124 (2) और 217 (1) में के प्रतिनिधियों के रूप में उक्त
 न्यायिक अधिकारियों का मतलब है
 उनकी संबंधित अदालतें।

13

निकाले गए अवलोकनों के साथ संयोजन में
 इसके अलावा, अदालत का ध्यान भी आमंत्रित किया गया था
 आगे के निष्कर्ष निकालना:
 मनमानी जो नियम की एक आवश्यक विशेषता है कानून पूरे संविधान में सर्वव्यापी है; और
 मनमानी की घुसपैठ की संभावना को ध्यान में रखा जाना चाहिए, और संवैधानिक व्याख्या में छोड़
 दिया और,
 इसलिए, मुख्य न्यायाधीश [2015] 13 एस. सी. आर. की राय का अर्थ।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रधानता के संदर्भ में भारत का निर्धारण किया जाना चाहिए। एक सजातीय मिश्रण, जो संवैधानिक के
 अनुरूप है
 उद्देश्य और इसके लोकाचार, इंगित करते हैं कि यह राय है
 न्यायपालिका के मुख्य न्यायाधीश के दृष्टिकोण से प्रतीक
 भारत जिसे अधिक महत्व या प्रधानता दी जाती है
 नियुक्तियों का मामला। दूसरे शब्दों में, का दृष्टिकोण
 भारत के मुख्य न्यायाधीश को परामर्श प्रक्रिया में न्यायपालिका की राय को सही मायने में प्रतिबिंबित करने
 के रूप में व्यक्त किया जाना है।
 जिसका अर्थ है कि इसमें अनिवार्य रूप से तत्व होना चाहिए
 इसके गठन में बहुलता। वास्तविक व्यवहार में, यह है कि कैसे
 भारत के मुख्य न्यायाधीश ऐसा करते हैं और उनके ऐसा करने की उम्मीद है

कि उनके द्वारा व्यक्त अंतिम राय केवल उनकी नहीं है
व्यक्तिगत राय, लेकिन सामूहिक राय के बाद बनाई गई
कुछ अन्य न्यायाधीशों के विचारों को ध्यान में रखते हुए जो
पारंपरिक रूप से इस कार्य से जुड़े हैं।

467. इस प्रक्रिया में न्यायपालिका की प्रधानता को देखते हुए,

अगला सवाल इस उद्देश्य को प्राप्त करने के तौर-तरीकों का है। संवैधानिक प्रावधानों में संकेत
से पाया जाता है

भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय का संदर्भ, जो

इस उद्देश्य को व्यावहारिक रूप से प्राप्त करने के लिए नामित किया गया है तरीके से।
न्यायपालिका की राय द्वारा प्रतीकित

भारत के मुख्य न्यायाधीश का दृष्टिकोण द्वारा प्राप्त किया जाना है

भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श; और यह है राय जिसकी प्रधानता हो।

468. कानून का शासन विवेकाधिकार के क्षेत्र की परिकल्पना करता है

न्यूनतम, केवल ज्ञात के आवेदन की आवश्यकता है

गैर-मनमानेपन को सुनिश्चित करने के लिए सिद्धांत या दिशानिर्देश, लेकिन उस सीमित सीमा तक, विवेक एक
व्यावहारिक आवश्यकता है।

उच्च अधिकारियों को विवेकाधिकार प्रदान करना और,

जब भी संभव हो, बहुलता के तत्व को पेश करना

एक सामूहिक निर्णय की आवश्यकता, मनमानेपन के खिलाफ आगे की जाँच हैं। आदर्शवाद और व्यावहारिकता
इस प्रकार हैं। प्रणाली को व्यवहार्य बनाने के लिए सामंजस्यपूर्ण और एकीकृत

संतोषजनक तरीके से। के कार्य को सौंपना उच्च संवैधानिक सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं के
लिए वरिष्ठ न्यायाधीशों की नियुक्ति-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

कार्यकर्ता; दृष्टिकोण से जुड़ा सबसे बड़ा महत्व
भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो आकलन करने के लिए सबसे अच्छी तरह से सुसज्जित हैं

उनके निर्णय के लिए उम्मीदवारों का वास्तविक मूल्य

उपयुक्तता; भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय
 ध्यान में रखने के बाद गठित सामूहिक राय
 उनके कुछ सहयोगियों के विचार; और कार्यपालक
 माना जाने वाली नियुक्ति को रोकने की अनुमति
 मुख्य न्यायाधीश को बताए गए ठोस कारणों के लिए अनुपयुक्त
 भारत का, सबसे अच्छा तरीका प्रदान करता है, संवैधानिक में
 बिना संवैधानिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए योजना
 दोनों में से किसी एक को पूर्ण विवेकाधिकार या वीटो प्रदान करना
 न्यायपालिका या कार्यपालिका, किसी भी व्यक्ति में बहुत कम,
 भारत के मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री।

10. यह विद्वान वकील का जोरदार तर्क था,

कि दूसरे न्यायाधीशों के मामले में इस न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को कार्यपालिका और
 उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति, प्रधानता न्यायपालिका के साथ निहित, और आगे कि,
 की राय

न्यायपालिका में बहुलता का तत्व होगा। यह दावा

पर निर्भरता रखते हुए आगे स्थापित करने की मांग की गई थी तीसरे न्यायाधीशों का मामला। यह
 प्रस्तुत किया गया था कि निष्कर्ष

द्वितीय न्यायाधीशों के मामले में बहुमत के निर्णय में से, थे

तीसरे न्यायाधीशों के मामले के पैराग्राफ 9 में पुनः प्रस्तुत किया गया, और

इसके बाद, इस न्यायालय ने तत्कालीन का बयान दर्ज किया

महान्यायवादी, कि राष्ट्रपति के संदर्भ के माध्यम से,

भारत संघ समीक्षा या पुनर्विचार नहीं मांग रहा था,

द्वितीय न्यायाधीशों के मामले में निर्णय। और यह कि भारत संघ ने उपरोक्त बहुमत के फैसले को बाध्यकारी
 के रूप में स्वीकार कर लिया था।

इस संदर्भ में, तीसरे न्यायाधीशों के मामले के पैराग्राफ 10 से 12,

जिन पर भरोसा किया गया था, उन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

हस्तक्षेप करने वालों और कुछ उच्च न्यायालयों के लिए वकील
 और कुछ राज्यों के महा-अधिवक्ता।

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

11. हम शुरुआत में ही वकील के बयान दर्ज करते हैं।

मामला (1993) 4 एस. सी. सी. 441 और वह (2) भारत संघ
स्वीकार करेगा और बाध्यकारी मानेगा।

इस न्यायालय के उत्तरों को

संदर्भ में दिए गए प्रश्नों के लिए।

12. द्वितीय न्यायाधीश मामले (1993) में बहुमत का दृष्टिकोण 4

एस. सी. सी. 441 यह है कि नियुक्तियों के मामले में
की राय

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों

भारत के मुख्य न्यायाधीश को प्रधानता प्राप्त है। मुखिया की राय

भारत का न्याय "न्यायपालिका की राय को दर्शाता है।

जिसका अर्थ है कि इसमें अनिवार्य रूप से तत्व होना चाहिए

इसके गठन में बहुलता "। इसे लेने के बाद इसका गठन किया जाना है
के विचारों को ध्यान में रखें जो पारंपरिक रूप से

कुछ अन्य न्यायाधीशों

इस कार्य से संबंधित "। इस प्रकार दी गई भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय सभी के मामले में प्रमुखता
रखती है। नियुक्तियाँ "। भेंट करने के लिए, यह करना होगा

मुख्य न्यायाधीश की अंतिम राय के अनुरूप होना।

इंगित तरीके से गठित भारत का "। इसका पालन करना चाहिए।
द्वारा किसी भी मामले में बनाई गई राय

भारत के मुख्य न्यायाधीश

इंगित के अलावा अन्य तरीके में कोई प्रधानता नहीं है

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में नियुक्तियों का मामला
पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

अदालतें और सरकार उस

11. विद्वान वकील ने न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया,

मद्रास बार एसोसिएशन बनाम में निष्कर्ष निकाला गया। संघ का

35, जो नीचे दिया गया है:

" 136. (iii) संविधान की "मूल संरचना" बनी रहेगी।

यदि हस्तांतरण से संबंधित कानून बनाते समय उल्लंघन किया गया हो

न्यायिक शक्ति की, संसद यह सुनिश्चित नहीं करती है कि नए
 बनाया गया न्यायालय/न्यायाधिकरण मुख्य के अनुरूप है
 न्यायालय की विशेषताओं और मानकों की मांग की गई प्रतिस्थापित "।

14) 10 एस. सी. सी. 1 शीर्ष अदालतें-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

विद्वान वकील ने तब जोर देकर कहा कि "बुनियादी संरचना"

संविधान और/या कानून बनाने के लिए, संसद नहीं करती है यह सुनिश्चित करें कि नया बनाया
 गया शरीर मुख्य के अनुरूप है

शरीर की विशेषताओं और मानकों की मांग की गई

प्रतिस्थापित। इस बात पर जोर दिया गया कि उच्च पदों पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की मौजूदा प्रक्रिया की
 मुख्य विशेषताएं

न्यायपालिका, जो समय की कसौटी पर खरी उतरी थी, वैध रूप से और

संवैधानिक रूप से प्रतिस्थापित किया जाए, लेकिन प्रचलित को प्रतिस्थापित करते हुए

प्रक्रिया, मुख्य विशेषताएँ जो पहले मौजूद थीं,

संरक्षित करने के लिए। अनुच्छेद 124 और 217 पर निर्भरता रखते हुए,

यह दावा किया गया था कि उपरोक्त प्रावधान, मूल रूप से

अधिनियमित, इस न्यायालय के निर्णयों द्वारा समझाया गया था, शुरू

1974 से समशेर सिंह बनाम। पंजाब राज्य 1 1, इसके बाद

संकलचंद हिमतलाल सेठ मामले 1977 में, और दूसरा

न्यायाधीशों का मामला। यह प्रस्तुत किया गया था कि चार संविधान पीठ उच्चतम न्यायालय ने
 केवल इस बात की पुष्टि की थी कि इस प्रथा का पालन किया जाता है

1950 से कार्यपालिका द्वारा (जब इस देश के लोग,

संविधान द्वारा शासित होने के लिए सहमत)। यह इंगित किया गया था बाहर, कि उच्च
 न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया

न्यायपालिका, एक सहभागी सलाहकार बनी रही थी

प्रक्रिया, जिसमें नियुक्ति के लिए प्रस्ताव की शुरुआत सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का, मुख्य न्यायाधीश द्वारा भारत; और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। और इसके लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश/मुख्य न्यायाधीश का स्थानांतरण उच्च न्यायालय, प्रस्ताव मुख्य न्यायाधीश द्वारा शुरू किया गया था भारत। यह तर्क दिया गया था कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में उपरोक्त मामलों (नियुक्ति और स्थानांतरण) पर, राय न्यायपालिका का प्रतीक मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से किया गया था भारत, और वही कॉलेजियम के निर्णय पर आधारित था न्यायाधीशों की संख्या, 1993 से-जब दूसरे न्यायाधीशों का मामला था तय किया। उपरोक्त नियम का एकमात्र अपवाद, [2015] 13 एस. सी. आर. के अनुसार।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विद्वान वकील, जब कार्यकारी, के आधार पर कहा गया था ठोस कारण (भारत के मुख्य न्यायाधीश को बताए गए), अन्यथा महसूस किया। हालाँकि, यदि बताए गए कारण, जैसा कि थे भारत के मुख्य न्यायाधीश को खुलासा किया गया, स्वीकार नहीं किया गया, दोहराने पर न्यायाधीशों के कॉलेजियम के निर्णय का परिणाम होगा प्रस्तावित नियुक्ति/स्थानांतरण में। इसके अनुसार विद्वान वकील ने पहले की प्रक्रिया का गठन किया अनुच्छेद 124 और 217। उपरोक्त प्रक्रिया थी, पर्याप्त माना जाता है, "की स्वतंत्रता को संरक्षित करने के लिए न्यायपालिका "।

12. विद्वान वकील के अनुसार, इसकी आवश्यकता थी

यह निर्धारित किया गया कि क्या अब एन. जे. ए. सी. की स्थापना की गई थी या नहीं।

नियुक्तियों/स्थानान्तरण के मामले में समान विशेषताएं,

"न्यायपालिका की स्वतंत्रता" को कौन सुरक्षित रखेगा?

प्रश्न का उत्तर देते हुए, विद्वान वकील ने जोर देकर कहा कि

न्यायपालिका की प्रधानता, इसके माध्यम से पूरी तरह से समाप्त हो गई थी

विवादित संवैधानिक संशोधन। उपरोक्त के लिए, सीखा

वकील ने अनुच्छेद 124 ए की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया।

संविधान (99 वां संशोधन) अधिनियम। यह प्रस्तुत किया गया था कि
विचार किए गए एनजेएसी में छह शामिल होंगे।

अनुच्छेद 124 ए के तहत

सदस्य, अर्थात् भारत के मुख्य न्यायाधीश, दो वरिष्ठ न्यायाधीश

सर्वोच्च न्यायालय (मुख्य न्यायाधीश के बगल में), संघ

व्यक्तियों "। यह प्रस्तुत किया गया था कि न्यायाधीश घटक, जो
तरीके से -

प्रधानता थी (और समझ के

सर्वसम्मति), पूर्व प्रक्रिया के तहत, अब किया गया था
शक्ति तक कम हो जाता है। यह.

चयन निकाय-एन. जे. ए. सी. में आधा-

यह इंगित किया गया था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास अब एन. जे. ए. सी. के अन्य सदस्यों के समान
मतदान का अधिकार होगा।

यह प्रस्तुत किया गया था कि भले ही भारत के मुख्य न्यायाधीश

एन. जे. ए. सी. का अध्यक्ष होगा, उसके पास कोई निर्णायक मत नहीं है,

एक टाई की स्थिति में। यह प्रस्तुत किया गया था कि प्रतिस्थापित के तहत

प्रक्रिया, भले ही भारत के मुख्य न्यायाधीश, और दो अन्य
न्यायाधीश (मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं के बगल में-ऑन-रिकॉर्ड) उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

भारत सरकार), किसी व्यक्ति की नियुक्ति/स्थानान्तरण का समर्थन किया,

इसे किसी भी दो सदस्यों द्वारा नकार दिया जा सकता है

एनजेएसी। यहां तक कि दो "प्रतिष्ठित व्यक्तियों" द्वारा भी जिनके पास नहीं हो सकता है

प्रशासन की प्रक्रिया के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध

न्याया। इसलिए यह प्रस्तुत किया गया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास निहित प्रधानता पूरी तरह से और पूरी तरह से थी

नष्ट हो गया।

13. की प्रधानता के विषय के संदर्भ में

न्यायपालिका, यह दावा किया गया था कि प्रणाली के तहत होना चाहिए

न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, केवल हो सकते थे भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शुरू किया गया था। और इसी तरह,

उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रस्ताव, हो सकता है केवल संबंधित के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शुरू किया गया है

उच्च न्यायालय। परिवर्तित स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए,

विद्वान वकील ने अनुच्छेद 124 बी पर निर्भरता पेश की

संविधान (99 वां संशोधन) अधिनियम द्वारा, जिसके तहत, प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार अब

एनजेएसी। नई व्यवस्था के तहत, अकेले एनजेएसी

उच्च न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करना

न्यायपालिका। विद्वान वकील के अनुसार यह भी स्पष्ट था,

कि एनजेएसी को अब विशेष रूप से सम्मानित किया गया है

मुख्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश करने की जिम्मेदारी और

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। उपरोक्त का वर्णन करते हुए

प्रचलित प्रक्रिया के कुल विध्वंस के रूप में परिवर्तन,

जो समय की कसौटी पर खरा उतरा था, और नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रक्रिया की स्वतंत्रता को सुरक्षित किया था

उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों को यह बताया गया कि संसद ने कारणों का खुलासा नहीं किया था, क्यों

भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों को,

त्याग दिया जाए। या उस मामले के लिए, क्यों प्रचलित है

प्रक्रिया में बदलाव की आवश्यकता है। यह आगे विवाद सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट थी।

[2015] 13 एस सी आर।

अनिवार्य रूप से इस निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि ऐसा कोई नहीं था कारणों से।

14. डॉ. राजीव धवन, विद्वान वरिष्ठ वकील,

"बुनियादी संरचना" के संदर्भ में उन्नत प्रस्तुतियाँ,

और संविधान के प्रावधानों में संशोधन की गुंजाइश।

संशोधन करने की संसद की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करना

संविधान, यह प्रस्तुत किया गया था कि केशवानंद में यह न्यायालय

भारती बनाम. केरल राज्य ने घोषणा की थी कि "बुनियादी संविधान की "संरचना",
अतिसंवेदनशील या उपयुक्त नहीं थी

संशोधन के लिए। अनुच्छेद 368 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए, यह था

प्रस्तुत किया, कि संसद के पास संशोधन करने की शक्ति निहित है

संविधान, घटक के विस्तार पर विचार किया

शक्ति, जिसका प्रयोग संविधान सभा द्वारा किया गया था, जबकि

संविधान का निर्माण। यह इंगित किया गया था कि अभ्यास में

उपरोक्त शक्ति, संसद को अनुमति दी गई थी

संविधान सभा के समान भूमिका निभाएँ। द.

संविधान के प्रावधान, यह दावा किया गया था, हो सकता है

संशोधित, नागरिक समाज में विकास के साथ तालमेल रखने के लिए,

जब तक संशोधन "मूल" का उल्लंघन नहीं था

संविधान की संरचना। यह प्रस्तुत किया गया था कि यह नहीं था पर्याप्त, वर्तमान मामले के तथ्यों
और परिस्थितियों में,

में संवैधानिक संशोधन की वैधता निर्धारित करें प्रश्न, परीक्षा को एक निर्धारण तक सीमित करके,

"न्यायपालिका की स्वतंत्रता" थी या नहीं

उल्लंघन किया गया, प्रावधानों के एक सादे पढ़ने पर संशोधित किया गया। यह दावा किया गया
था कि इसे लेना अनिवार्य था

इस विषय पर इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर विचार करना।

प्रथम, द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों में कानून की घोषित स्थिति संबंध है, मामले।

जहां तक वर्तमान विवाद का

विद्वान वकील के अनुसार, यदि अधिनियमों के तहत

चुनौती, "बुनियादी संरचना" के उल्लंघन में पाए गए थे

संविधान के, जैसा कि उपरोक्त निर्णयों में घोषित किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

विवादित संवैधानिक संशोधन, साथ ही, कानून होगा।

संदर्भ के तहत, निस्संदेह संवैधानिक रूप से अमान्य

15. उपरोक्त संदर्भ में, विद्वान वकील ने बताया,

कि मौलिक अधिकारों में संशोधन के संदर्भ में,

संविधान के भाग III में निहित, दिशानिर्देश निर्धारित किए गए थे नागराज बनाम. भारत संघ 3 6, साथ ही, में

इस न्यायालय द्वारा एम.

किहोतो होल्लोहन मामला 3 4. यह प्रस्तुत किया गया था कि संविधान में विवादित संशोधन के माध्यम से परिवर्तन, (और

एन. जे. ए. सी. अधिनियम) एक परिधीय परिवर्तन नहीं था, लेकिन एक था

एक महत्वपूर्ण, जो अपरिवर्तनीय भी प्रतीत होता था। और

इसलिए, विद्वान वकील के अनुसार, इसकी वैधता होगी

चौड़ाई और पहचान के आधार पर निर्धारित किया जाना है

परीक्षण। यह प्रस्तुत किया गया था कि चौड़ाई और पहचान परीक्षण थे

वैधता निर्धारित करने के लिए लागू परीक्षणों से अलग संवैधानिक

सामान्य संसदीय विधान, या एक

मौलिक अधिकारों से संबंधित संशोधन। इसका तरीका

चौड़ाई और पहचान परीक्षणों पर काम करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया था,

एम. नागराज मामले 36 में निर्धारित किया गया था, जिसमें यह न्यायालय

आयोजित:

"9. उत्तरदाताओं की ओर से निम्नलिखित तर्क दिए गए:

उन्नत थे। अनुच्छेद के तहत संशोधन की शक्ति

368 एक "घटक" शक्ति है न कि एक "गठित शक्ति";

कि, कि घटक पर कोई निहित सीमाएँ नहीं हैं

बुनियादी संरचना। संशोधन की ऐसी प्रक्रिया में, यदि -
संविधान की मूल विशेषता को नष्ट करता है,

संशोधन असंवैधानिक होगा। संविधान,
उत्तरदाताओं के अनुसार, यह केवल वही नहीं है जो वह कहता है। यह.

प्रासंगिक प्रावधान की अंतिम व्याख्या क्या है

उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया संविधान जो प्रचलित है

कानून के रूप में। द्वारा संविधान पर रखी गई व्याख्या

36 (2006) 8 एस. सी. सी. 212 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

न्यायालय संविधान का हिस्सा बन जाता है और इसलिए।

यह अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन के लिए खुला है। एक व्याख्या

संविधान के किसी भी प्रावधान पर न्यायालय द्वारा रखा गया

व्याख्या किए गए प्रावधानों में अंतर्निहित हो जाता है। ऐसे लेख हैं -

अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करने में सक्षम। इस तरह के बदलाव

उच्चतम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित कानून मात्र नहीं होगा

केवल इसी कारण से मूल संरचना का उल्लंघन होता है

संविधान या न्यायिक शक्ति का दुरुपयोग। यह

इस तरह संविधान गतिशील हो जाता है। कानून को बदलना होगा। इसके लिए संविधान में संशोधन
की आवश्यकता है
समय की जरूरतों और समाज की जरूरतों के अनुसार। यह है।

न्यायिक और घटक शक्तियों की एक चल रही प्रक्रिया, दोनों में अंतिम कहने के साथ कानून के
परिवर्तन में योगदान

न्यायपालिका इस तरह के परिवर्तन की वैधता पर फैसला करेगी

इस बात की जाँच करके कि क्या घटक शक्ति द्वारा प्रभावी कानून इस तरह के संशोधन मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं

संविधान। हर अवसर पर जब एक संवैधानिक

मामला न्यायालय के समक्ष आता है, जिसका अर्थ है

संविधान के प्रावधानों की व्याख्या की आवश्यकता होगी, लेकिन लेख की हर व्याख्या बुनियादी नहीं होती है।

संविधान की विशेषता। कि, कोई निहित नहीं है

अनुच्छेद 368 के तहत संसद की शक्ति पर सीमाएं

जब यह संविधान में संशोधन करना चाहता है। हालांकि, एक

मूल संरचना। संशोधन की वैधता नहीं है अनुच्छेद 13 की कसौटी पर निर्णय लिया जाएगा लेकिन केवल

मूल विशेषताओं के उल्लंघन का आधार

संविधान "।

16. यह प्रस्तुत किया गया था कि जब संसद के पास था

संविधान में संशोधन करने की शक्ति; विधायिका (-या

कार्यपालिका), के पास संविधान की व्याख्या करने की कोई शक्ति नहीं थी,

या प्रावधानों में संशोधन की वैधता निर्धारित करने के लिए

संविधान से। एक की वैधता निर्धारित करने की शक्ति

विद्वान वकील के अनुसार, संवैधानिक संशोधन, सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

यह विशेष रूप से उच्च न्यायपालिका के पास है। प्रत्येक संशोधन

न्यायपालिका द्वारा घोषित "बुनियादी संरचना" की कसौटी पर इसका परीक्षण किया जाना था। यह प्रस्तुत किया गया था कि उपरोक्त

न्यायपालिका के पास निहित शक्ति को वापस नहीं लिया जा सका या विद्वान वकील के अनुसार, गठित किया

निरस्त कर दिया। यह,

मौलिक न्यायिक शक्ति, और कम महत्वपूर्ण/भारी नहीं थी
संसद की विधायी शक्ति से अधिक। न्यायिक समीक्षा की शक्ति का महत्व उच्च न्यायपालिका के पास निहित है
(

कार्यकारी और विधायी कार्यों की वैधता की जांच करें), न्यायपालिका को अन्य दो स्तंभों पर श्रेष्ठता
प्रदान की गई

शासन की। यह स्थिति, यह इंगित की गई थी, महत्वपूर्ण थी
नागरिक समाज द्वारा समर्पण की गई शक्ति को संतुलित करने के लिए,
राजनीतिक और कार्यकारी संप्रभुता।

17. प्रस्तुतियों की वैधता निर्धारित करने के लिए

याचिकाकर्ताओं की ओर से हमें सूचित किया गया कि
अनुच्छेद 124 पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या
और 217 (जैसा कि वे अस्तित्व में थे, विवादित संशोधन से पहले),

इसे ध्यान में रखना होगा। यह प्रस्तुत किया गया था कि अवधि

"अनुच्छेद 124 के संदर्भ में "परामर्श" किया गया था

न्यायपालिका को प्रधानता प्रदान करने के रूप में समझा जाता है। इसलिए,

विवादित संवैधानिक संशोधन की जांच करते हुए

अनुच्छेद 124, इस न्यायालय के लिए यह अनिवार्य था कि वह अनुच्छेद 124 में "परामर्श" शब्द को समझे
और इसे इस रूप में पढ़े कि,

न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में प्रधानता,

न्यायपालिका। अनुच्छेद 124 के तहत, विद्वान वकील के अनुसार,

राष्ट्रपति को केवल मुख्य न्यायाधीश से "परामर्श" करने की आवश्यकता नहीं थी

भारत का, लेकिन कार्यपालिका को व्यक्त किए गए विचार को स्वीकार करना था

भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। जहाँ तक "मुख्य न्यायाधीश" शब्द का संबंध है

भारत का "संबंधित है, यह प्रस्तुत किया गया था, कि वही था

इसका अर्थ भी समझा गया है, न कि व्यक्तिगत राय

भारत के मुख्य न्यायाधीश, लेकिन न्यायपालिका की राय

भारत के मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से प्रतीक। तदनुसार, यह

इस बात पर जोर दिया गया कि मुख्य न्यायाधीश की व्यक्तिगत राय
(अनुच्छेद 124 और 217) के संदर्भ में [2015] 13 एस. सी. आर. के रूप में समझा गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायपालिका की संस्थागत राय। तदनुसार, विवादित संवैधानिक संशोधन की जांच करते हुए,
चौड़ाई और पहचान परीक्षण (ओं), उपरोक्त घोषित कानूनी स्थिति,
यह निर्धारित करते समय ध्यान में रखना था कि क्या नहीं
विवादित संवैधानिक संशोधन और विवादित विधायी अधिनियम ने संविधान के "मूल ढांचे" का उल्लंघन
किया था।

संविधान।

18. यह तर्क दिया गया था कि दूसरे में निर्णय

न्यायाधीशों के मामले को कसौटी के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, जिसके द्वारा
विवादित संवैधानिक संशोधन की वैधता (और
एन. जे. ए. सी. अधिनियम) की जांच की जानी चाहिए। यह प्रस्तुत किया गया था कि

विवादित संवैधानिक संशोधन का प्रभाव (और एन. जे. ए. सी. अधिनियम को लागू करना), का
परीक्षण इस तरह से करना होगा,

जो बदलते समय के लिए एक जैविक अनुकूलन की अनुमति देगा, और साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि
इसकी "बुनियादी संरचना"

संविधान का उल्लंघन नहीं किया गया। एम. नागराज पर भरोसा

मामला 3 6, न्यायालय का ध्यान निम्नलिखित की ओर आकर्षित किया गया था:

टिप्पणियाँ:

मामला है-क्या विवादित संवैधानिक आधार पर
संशोधन, संसद की शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि

किसी भी या सभी संवैधानिक सीमाओं को मिटाने के लिए

और आवश्यकताएँ?

संवैधानिक

संशोधनों की न्यायिक समीक्षा के मानक

19. संविधान एक अल्पकालिक कानूनी दस्तावेज नहीं है

गुजरने वाले घंटे के लिए कानूनी नियमों का एक सेट शामिल करना। यह सेट करता है।
एक विस्तारित भविष्य के लिए सिद्धांत तैयार करना और इसका उद्देश्य है -

आने वाले युगों के लिए सहन करें और परिणामस्वरूप अनुकूलित किया जाए
मानव मामलों के विभिन्न संकटों के लिए। इसलिए, एक सख्त शाब्दिक दृष्टिकोण के बजाय एक उद्देश्यपूर्ण

व्याख्या को अपनाया जाना चाहिए। एक संवैधानिक प्रावधान

इसका अर्थ संकीर्ण और संकुचित अर्थों में नहीं लगाया जाना चाहिए
लेकिन एक व्यापक और उदार तरीके से ताकि अदालत के अधिवक्ताओं का पूर्वानुमान लगाया जा सके और
उनका समर्थन किया जा सके-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

बदलती स्थितियों और उद्देश्यों को ध्यान में रखें ताकि

एक संवैधानिक प्रावधान जीवाश्म नहीं हो जाता है लेकिन

नए उभरते हुए लोगों से मिलने के लिए पर्याप्त लचीला रहता है
समस्याएँ और कठिनाइयाँ "।

विद्वान वरिष्ठ वकील ने भी न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया

दूसरे न्यायाधीशों के मामले में दर्ज समान टिप्पणियों के लिए।

19. विद्वान सलाह जोरदार थी, कि विवादित

यदि अनुमोदित किया जाता है, तो यह दस, बीस, तीस या चालीस वर्षों तक बना रहेगा, और इसलिए, इसे
बारीकी से देखने की आवश्यकता है और निष्पक्ष रूप से। प्रावधानों की व्याख्या इस तरह से करनी
होगी कि "न्यायपालिका की स्वतंत्रता" नहीं होगी।

समझौता किया। यह प्रस्तुत किया गया था कि यदि आक्षेपित प्रावधान

संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया जाना था, वहाँ होगा

इसके बाद कोई साधन नहीं, स्वतंत्रता को बहाल करने के लिए

न्यायपालिका "।

20. विद्वान वकील के अनुसार, सवाल था

न्याय वितरण प्रणाली की शुद्धता। सवाल यह था कि

न्यायिक मानकों का रखरखाव। ये सभी सवाल

फव्वारे के सिर से उभरा, अर्थात्, का तरीका

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति। प्रावधान

अनुच्छेद 124 के अनुसार, यह इंगित किया गया था, जैसा कि यह पहले से मौजूद था

विवादित संशोधन, एक प्रणाली के लिए प्रदान किया गया था

ट्रस्टीशिप को उन लोगों द्वारा साझा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जिनके प्रतिद्वंद्वी दावे न्यायालयों के समक्ष विचार के लिए उत्पन्न हुए

विद्वान वकील के अनुसार, न्यायाधीश सबसे अधिक होते हैं महत्वपूर्ण ट्रस्टीशिप, जिसे साझा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी,

या तो कार्यपालिका या विधायिका के साथ।

21. स्वयं संशोधन का उल्लेख करते हुए, यह तर्क दिया गया था,

कि केवल कानून के आधार को बदलना, सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट नहीं होगी

[2015] 13 एस सी आर।

संसद के कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए सही परीक्षण,

वर्तमान विवाद। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि

तर्कसंगतता और आनुपातिकता भी लागू किए जाने वाले सही परीक्षण नहीं थे। विद्वान वकील के अनुसार, क्रम में

विवादित संवैधानिक की वैधता निर्धारित करने के लिए

संशोधन (और एन. जे. ए. सी. अधिनियम), भारत संघ और

अनुसमर्थन करने वाले राज्यों को संतोषजनक रूप से जिम्मेदारी उठानी होगी

यह स्थापित करना कि संशोधित प्रावधान, नहीं के तहत कर सकते हैं परिस्थितियों का उपयोग किया जाए (वास्तव में दुरुपयोग किया जाए)

"न्यायपालिका की स्वतंत्रता"। एम पर निर्भरता रखना।

नागराज मामला 3 6, न्यायालय का ध्यान निम्नलिखित पर आमंत्रित किया गया था:

टिप्पणियाँ:

" 22. हमारे सामने जो सवाल उठता है, वह है -

न्यायिक समीक्षा के मानकों की प्रकृति आवश्यक है

संवैधानिक की वैधता का न्याय करने में लागू किया गया

बुनियादी सिद्धांत के संदर्भ में संशोधन
संरचना। एक बुनियादी संरचना देने की अवधारणा

संविधान के प्रति सुसंगतता और स्थायित्व की एक निश्चित विशेषता है -

आंतरिक बल। यह सिद्धांत अनिवार्य रूप से विकसित हुआ है

जर्मन संविधान। यह विकास है

अपने आप में संवैधानिक सिद्धांतों का उदय।

यह शाब्दिक शब्दों पर आधारित नहीं है।

23. एस. आर. बोम्मई (1994) 3 एस. सी. सी. 1 में न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अपने निष्कर्ष के आधार पर विशेष के उल्लंघन पर इतना नहीं

संवैधानिक प्रावधान लेकिन इस सामान्यीकृत आधार पर अर्थात्

सिद्धांत के खिलाफ निर्देशित कार्रवाई के एक पैटर्न का सबूत

धर्मनिरपेक्षता। इसलिए, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि

के संदर्भ में एक बुनियादी संरचना की मान्यता

संशोधन एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि इससे परे हैं

विशेष प्रावधानों के शब्द, व्यवस्थित सिद्धांत

संविधान और इसे एक जैविक संपूर्ण बनाएँ। ये सिद्धांत वे संवैधानिक कानून का हिस्सा हैं, भले ही वे स्पष्ट रूप से सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड समाज व न हों।

यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

नियमों के रूप में बताया गया। एक उदाहरण सिद्धांत है

तर्कसंगतता जो अनुच्छेद 14, 19 और 21 को जोड़ती है।

इनमें से कुछ सिद्धांत इतने महत्वपूर्ण हो सकते हैं और

मौलिक, "आवश्यक विशेषताओं" या इसके हिस्से के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए संविधान की "मूल संरचना", अर्थात्, वे

संशोधन के लिए तैयार नहीं हैं। हालाँकि, यह केवल लिंक करके है जो

ऐसे व्यापक सिद्धांतों के प्रावधान

आवश्यक को कम आवश्यक से अलग करने में सक्षम होना
संविधान की विशेषताएँ।

XXX

XXX

XXX

25. एक संवैधानिक सिद्धांत के लिए एक आवश्यक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए विशेषता, यह स्थापित किया जाना चाहिए कि उक्त सिद्धांत एक है विधायिका पर बाध्यकारी संवैधानिक कानून का हिस्सा। केवल इसके बाद, दूसरा कदम उठाया जाना है। अर्थात्, क्या सिद्धांत इतना मौलिक है कि बांधने के लिए भी संसद की शक्ति में संशोधन करना अर्थात् इसका एक भाग बनाना बुनियादी संरचना। तदनुसार मूल संरचना अवधारणा संसद की संशोधन शक्ति को सीमित करना। संक्षेप में: मैं एक आवश्यक विशेषता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए, एक सिद्धांत होना चाहिए पहले संवैधानिक कानून के हिस्से के रूप में स्थापित और के रूप में विधायिका पर ऐसा बाध्यकारी। तभी ऐसा हो सकता है। जाँच की कि क्या यह इतना मौलिक है कि बांधने के लिए भी संसद की शक्ति में संशोधन करना अर्थात् मूल का हिस्सा बनाना संविधान की संरचना। यह न्यायिक मानक है के संदर्भ में संवैधानिक संशोधनों की समीक्षा बुनियादी संरचना का सिद्धांत।

XXX

XXX

XXX

30. संवैधानिक निर्णय लेना किसी अन्य निर्णय लेने की तरह नहीं है। प्रत्येक प्रमुख के लिए एक नैतिक आयाम है

न्यायाधीशों द्वारा इसकी व्याख्या करते समय। यह वह सूचित स्वतंत्रता है न्यायाधीशों की कार्रवाई जो संरक्षण और सुरक्षा में मदद करती है

शासन का हमारा मूल दस्तावेज।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट।

[2015] 13 एस सी आर।

XXX

XXX

XXX

35. मूल संरचना का सिद्धांत इस सिद्धांत पर आधारित है -

कि किसी वस्तु में परिवर्तन से उसका विनाश नहीं होता है
और किसी वस्तु का विनाश पदार्थ की बात है न कि

रूप में। इसलिए, किसी को व्यापक परीक्षण लागू करना पड़ता है।

योजना से एकत्र किया जाने वाला सिद्धांत और

संविधान में किसी अनुच्छेद का स्थान और संरचना।
उदाहरण के लिए, समानता में अनुच्छेद 14 का स्थान

कोड; स्वतंत्रता संहिता में अनुच्छेद 19 का स्थान;

कोड में अनुच्छेद 32 का स्थान, जो इस तक पहुंच प्रदान करता है
सुप्रीम कोर्ट। इसलिए, मूल संरचना का सिद्धांत है

एकमात्र सिद्धांत जिसके द्वारा आक्षेप की वैधता

संविधान में संशोधनों पर निर्णय लिया जाना है।

22. इस न्यायालय द्वारा व्यक्त स्थिति का उल्लेख करते हुए,

विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि के लिए व्यापक सिद्धांत

इस न्यायालय को, सबसे पहले अपने ध्यान में रखना था, की सटीक प्रकृति

संविधान के माध्यम से विचार किया गया संशोधन (99 वां

फिर से एम. नागराज मामले 3 6 पर रखा गया, और हमारा ध्यान था
पहुंचे:

निम्नलिखित निष्कर्षों पर

" 102. बुनियादी सिद्धांत के अनुप्रयोग के मामले में

संरचना। जुड़वां परीक्षणों को संतुष्ट करना होगा, अर्थात्, "चौड़ाई"

"परीक्षण" और "पहचान" का परीक्षण। जैसा कि ऊपर बताया गया है,

"पकड़" नियम और "परिणामी वरिष्ठता" की अवधारणा

संवैधानिक आवश्यकताएँ नहीं हैं। वे अंतर्निहित नहीं हैं।
अनुच्छेद 16 के खंड (1) और (4) में। वे नहीं हैं।

संवैधानिक सीमाएँ। वे अवधारणाएँ हैं जिनसे व्युत्पन्न
सेवा न्यायशास्त्र। वे संवैधानिक नहीं हैं।

सिद्धांत। वे धर्मनिरपेक्षता जैसे स्वयंसिद्ध नहीं हैं,

संघवाद, आदि। इन अवधारणाओं का विस्मरण या सम्मिलन
इन अवधारणाओं में से समानता संहिता को नहीं बदलता है।

संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 द्वारा इंगित।

अनुच्छेद 16 का खंड (1) राज्य को सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं को लेने से नहीं रोक सकता है।

समाज v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

पिछड़े लोगों के सम्मोहक हितों का संज्ञान

समाज में वर्ग। अनुच्छेद 16 के खंड (1) और (4)

अनुच्छेद के तहत समानता के सिद्धांत के पुनर्कथन हैं

14. अनुच्छेद 16 का खंड (4) सकारात्मक कार्रवाई को संदर्भित करता है -

आरक्षण का तरीका। हालांकि, अनुच्छेद 16 के खंड (4) में कहा गया है

कि उपयुक्त सरकार प्रदान करने के लिए स्वतंत्र है

उन मामलों में आरक्षण जहां इसे आधार पर संतुष्ट किया जाता है

मात्रात्मक आँकड़ा कि पिछड़ा वर्ग अपर्याप्त है

सेवाओं में प्रतिनिधित्व। इसलिए, हर मामले में जहाँ

राज्य ने आरक्षण का प्रावधान करने का फैसला किया है कि वहाँ मौजूद होना चाहिए

दो परिस्थितियाँ, अर्थात् "पिछड़ेपन" और

"प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता"। जैसा कि ऊपर बताया गया है, इक्विटी,

न्याय और दक्षता परिवर्तनशील कारक हैं। ये कारक हैं

और प्रत्येक मामले की परिस्थितियाँ। ये हैं सीमाएं
इनमें से कोई नहीं।

राज्य द्वारा शक्ति के प्रयोग के तरीके पर।

इन सीमाओं को विवादित द्वारा हटा दिया गया है

संशोधन। यदि संबंधित राज्य पहचान करने में विफल रहता है और
समग्रता को मापें

पिछड़ेपन, अपर्याप्तता और

प्रशासनिक दक्षता तब उस स्थिति में प्रावधान

आरक्षण अमान्य होगा। ये संशोधन करते हैं

अनुच्छेद 14, 15 और 16 (इक्विटी कोड) की संरचना को नहीं बदला जाएगा।

अनुच्छेद 16 (4) में उल्लिखित मापदंडों को बरकरार रखा गया है।

खंड (4-ए) अनुच्छेद 16 के खंड (4) से लिया गया है। खंड

(4 - ए) केवल एससी और एसटी तक ही सीमित है। इसलिए,
बदलती है

वर्तमान मामले की पहचान नहीं

संविधान। "संशोधन" शब्द का अर्थ परिवर्तन है।

और कारण इंगित करते हैं कि विवादित संशोधन
गया है

संसद द्वारा रद्द करने के लिए घोषित किया

इस न्यायालय के निर्णय। हम इसमें कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

तर्क। संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस न्यायालय की घोषणा देश का कानून है। द.

भारत संघ 'v' में इस न्यायालय के निर्णय। विरपाल सिंह

चौहान। (1995) 6 एस. सी. सी. 684. अजीत सिंह जानुजा बनाम। राज्य

पंजाब, (1996) 2 एस. सी. सी. 715. अजीत सिंह (II) बनाम। की स्थिति

पंजाब, (1999) 7 एस. सी. सी. 209. और इंद्र साहनी बनाम। संघ

भारत का 1992 का प्रावधान (3) एस. सी. सी. 217. निर्णय थे।
जिसने कानून का प्रतिपादन किया

इस न्यायालय द्वारा दिया गया

भूमि। यह वह कानून है जिसे बदलने की मांग की गई है

विवादित संवैधानिक संशोधन। द इम्पाग्ड

संवैधानिक संशोधन प्रकृति में सक्षम कर रहे हैं। वे.

आरक्षण प्रदान करने के लिए इसे राज्यों पर छोड़ दें। यह ठीक है।

यह तय किया कि संसद कोई कानून बनाते समय ऐसा नहीं करती है
प्रदान करें। सामग्री प्रदान की जाती है

"दाहिनी ओर" सामग्री

उच्चतम न्यायालय के निर्णय। यदि उचित हो।

अनुच्छेद 16 (4) और अनुच्छेद के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए
निश्चित रूप से अलग कर देगा और खारिज कर देगा

335 तब यह न्यायालय

ऐसा कानून। "चौड़ाई परीक्षण" को लागू करते हुए, हम नहीं पाते हैं

किसी भी संवैधानिक सीमा का उन्मूलन। आवेदन करना

"पहचान" के परीक्षण में, हम कोई परिवर्तन नहीं पाते हैं

समानता संहिता की मौजूदा संरचना। जैसा कि ऊपर बताया गया है,

धर्मनिरपेक्षता, संघवाद आदि जैसे स्वयंसिद्धों में से कोई भी नहीं जो
उल्लंघन किया गया है

व्यापक सिद्धांतों का

विवादित संवैधानिक संशोधन। समानता दो प्रकार की होती है

पहलू- "औपचारिक समानता" और "आनुपातिक समानता"।

आनुपातिक समानता "वास्तव में" समानता है जबकि औपचारिक

कानून का शासन। आनुपातिक समानताक मामले में राज्य अछि -
उठाने की उम्मीद है

के पक्ष में सकारात्मक कदम

ढांचे के भीतर समाज के वंचित वर्ग

उदार लोकतंत्र। समतावादी समानता आनुपातिक है।

समानता "।

फिर भी चौड़ाई और पहचान परीक्षणों का उल्लेख करते हुए,

एड काउंसल ने जोर देकर कहा कि यह इस सर्वोच्च न्यायालय के लिए अनिवार्य था

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

न्यायालय, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, जाँच करें कि क्या संशोधन की शक्ति का प्रयोग

संसद, इतनी चौड़ी थी कि इसे अत्यधिक बना देती थी। इसके लिए ऊपर, मद्रास बार एसोसिएशन को संदर्भ दिया गया था

मामला 35, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज किए:

" 134. (i) संसद के पास कानून बनाने की शक्ति है और पहले उच्च में निहित न्यायिक कार्यों को निहित करने के लिए एक वैकल्पिक न्यायालय/न्यायाधिकरण के साथ न्यायालय। इस तरह का अभ्यास संसद द्वारा शक्ति अपने आप में "बुनियादी" का उल्लंघन नहीं करेगी। संविधान की संरचना।

135. (ii) संबंधित मान्यता प्राप्त संवैधानिक सम्मेलन वेस्टमिंस्टर मॉडल कानून बनाने पर रोक नहीं लगाता है। कानून बनाने से लेकर न्यायनिर्णायक तक का अधिकार कार्य जो पहले एक उच्च न्यायालय में निहित थे वैकल्पिक न्यायालय/न्यायाधिकरण। इस तरह की शक्ति का प्रयोग संसद अपने आप में किसी भी संविधान का उल्लंघन नहीं करेगी। सम्मेलन।

136. (iii) संविधान की "मूल संरचना" बनी रहेगी। यदि हस्तांतरण से संबंधित कानून बनाते समय उल्लंघन किया गया हो न्यायिक शक्ति। संसद यह सुनिश्चित नहीं करती है कि नए बनाया गया न्यायालय/न्यायाधिकरण मुख्य के अनुरूप है न्यायालय की विशेषताओं और मानकों की मांग की गई प्रतिस्थापित।

137. (iv) से संबंधित संवैधानिक समझौते वेस्टमिंस्टर मॉडल पर शैलीबद्ध संविधानों का भी उल्लंघन किया जाएगा, यदि कानून बनाते समय, संबंधित न्यायिक शक्ति, परंपराओं और मुख्य का हस्तांतरण

प्रतिस्थापित किए जाने की मांग की गई अदालत की विशेषताएँ नहीं हैं न्यायालय/न्यायाधिकरण में निगमित किए जाने की मांग की गई।

138. (v) लिखित याचिका (सी) संख्या 621 में की गई प्रार्थना

2007 अस्वीकार कर दिया जाता है। कंपनी सचिवों को अयोग्य ठहराया जाता है

एन. टी. टी. के समक्ष अपील के लिए किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

139. (vi) निष्कर्षों की कसौटी पर जांच की गई (iii)

और (iv) (उपरोक्त पैरा 136 और 137 में निहित) धाराओं की सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

5. 6. 7. 8 और एन. टी. टी. अधिनियम की धारा 13 (इंगित सीमा तक)

ऊपर), को असंवैधानिक माना जाता है। तब से
उपरोक्त प्रावधान एन. टी. टी. अधिनियम की इमारत का गठन करते हैं।

और इन प्रावधानों के बिना शेष प्रावधान हैं -

अप्रभावी और अप्रासंगिक, पूरे

अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया जाता है। ”

उपरोक्त के आधार पर, यह दावा किया गया था कि इस न्यायालय ने

न्यायिक शक्ति की परंपराओं का उल्लंघन नहीं किया जा सका। यह था।
कि जिसका मूल्यांकन उपरोक्त मानकों द्वारा किया गया है, वह

यह भी प्रस्तुत किया गया

यह स्पष्ट रूप से सामने आएगा कि “न्यायपालिका की स्वतंत्रता”

गंभीर रूप से समझौता किया गया था, विवादित के माध्यम से

संवैधानिक संशोधन (और एनजेएसी अधिनियम)।

23. यह श्री राम जेठमलानी का समर्पण था, विद्वान

वरिष्ठ अधिवक्ता, कि द्वारा दिए गए निर्णय में दोष

प्रथम न्यायाधीशों के मामले में यह न्यायालय यह था कि संविधान के अनुच्छेद 50 को उचित रूप से उजागर
नहीं किया गया था, क्योंकि

विचार करें। यह प्रस्तुत किया गया था कि अनुच्छेद 50 का महत्व

अनुच्छेद 12 और 36 के साथ पढ़ा गया, जिसमें जांच की गई

द्वितीय न्यायाधीश का मामला, जिसमें बहुमत का विचार था, इस प्रकार था

निम्नलिखित है:

" 80. उपरोक्त विचार-विमर्श से यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 50

प्रतिष्ठित न्यायाधीशों द्वारा विभिन्न निर्णयों में संदर्भित किया गया था

इस न्यायालय ने स्वतंत्रता के सिद्धांत पर चर्चा करते हुए
न्यायपालिका से। हम अनुच्छेद 36 का हवाला दे सकते हैं जो इसके अंतर्गत आता है।

भाग IV (राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत) और जो

इस प्रकार पढ़ता है:

" 36. इस भाग में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो,

'राज्य' का वही अर्थ है जो भाग III में है। "

81. इस लेख के अनुसार, अभिव्यक्ति की परिभाषा

" अनुच्छेद 12 में राज्य पूरे भाग IV में लागू होगा,
जहाँ भी उस शब्द का उपयोग किया जाता है। अतः यह कहा जाता है कि

अनुच्छेद 50 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "राज्य" का अर्थ सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं-ऑन-रिकॉर्ड से
लगाया जाना चाहिए।

समाज v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

भारत की सरकार और संसद और सरकार और विधायिका सहित वितरणात्मक अर्थों में प्रत्येक
राज्य और सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरणों के भीतर

भारत का क्षेत्र या सरकार के नियंत्रण में

भारत। जब न्यायपालिका को अलग करने की अवधारणा

कार्यपालिका को आश्वस्त किया जाता है और मूल्यांकन किया जाता है कि अवधारणा केवल अधीनस्थ
न्यायपालिका तक ही सीमित नहीं हो सकती है

उच्च न्यायपालिका को त्यागना। अगर इतना संकीर्ण और

निर्माण दिया जाता है, यह एक विसंगति की ओर ले जाएगा स्थिति कि संविधान पर जोर नहीं देता
है

कार्यपालिका से उच्च न्यायपालिका का पृथक्करण। वास्तव में,

इससे पहले, विभिन्न निर्णयों में अनुच्छेद 50 का उल्लेख किया गया है जबकि उच्चतर की स्वतंत्रता
की अवधारणा पर चर्चा करना या

श्रेष्ठ न्यायपालिका और इस प्रकार प्रकाश डाला और जोर दिया

अनुच्छेद 50 में अंतर्निहित मूल सिद्धांत और मूल्यों पर

न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करना।

XXX

XXX

XXX

इसलिए यह अपरिहार्य हो गया है कि प्रभावी कदम उठाए जाएं।
करने के लिए लिया जाना चाहिए। इसके बाद

स्थिति को सुधारने या पुनः प्राप्त

इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और विनाशकारी परिणामों को महसूस करते हुए, कोई भी चुप नहीं रह सकता है।

दर्शक या एक पुराना उत्साही आशावादी, देख रहा है

अन्य संवैधानिक पदाधिकारी, विशेष रूप से कार्यपालिका,

न्याय वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी और लचीला बनाने के लिए उत्साहजनक समाधान प्राप्त करने की शौकीन आशा में

समाज की समकालीन जरूरतों को पूरा करना, जो आशा करता है, जैसा कि अनुभव से पता चलता है, कभी सफल नहीं हुआ है। इसलिए, ऐसी तीखी स्थिति का सामना करते हुए, यह

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्टों के भीतर इन समस्याओं को हल करना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है

[2015] 13 एस सी आर।

विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या करके संवैधानिक ताना-बाना

न्यायपालिका के कामकाज से संबंधित संविधान

संविधान के अक्षर और भावना के प्रकाश में।

XXX

XXX

XXX

141. श्री राम जेठमलानी, विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा

उनकी शिकायत है कि चंद्र मोहन में निर्धारित सिद्धांत

मामला (1967) 1 एस. सी. आर. 77,83.
न्यायाधीश। राज्य

समशेर सिंह बनाम के साथ व्यवहार करते हुए विद्वान

पंजाब का, (1974) 2 एस. सी. सी. 831 जिन्होंने अपनी प्रस्तुति में, सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत को नजरअंदाज कर दिया जो था

के. एम. नानावती बनाम में व्यक्ति। बम्बई राज्य (1961) 1

एससीआर 497। उनके अनुसार, गुप्ता मामले में फैसला

1981 मान लीजिए कि एस. सी. सी. 87 को इनक्यूरियम के अनुसार माना जा सकता है। वह.

यह स्पष्ट करता है कि 'परामर्श' अभिव्यक्ति अपने आप में लचीली है और एक निश्चित संदर्भ में जिसका अर्थ बहन करने में सक्षम है

'सहमति 'या' सहमति '।

XXX

XXX

XXX

154. से जांच के लिए उत्पन्न होने वाला विवाद

के संबंध में उकसाए गए तर्क

'परामर्श' शब्द का निर्माण।

XXX

XXX

XXX

170. इस प्रकार, यह देखा जाता है कि राय की सर्वसम्मति यह है कि

सीजेआई के साथ परामर्श एक अनिवार्य शर्त है।

ताकि सी. जे. आई. के साथ परामर्श न करने पर आदेश दिया जाए।

असंवैधानिक अर्थात् शून्य।

171. अनिवार्य चरित्र का उपरोक्त दृष्टिकोण रही है

संकालचंद में लिए गए परामर्श की आवश्यकता

गुप्त में कुछ न्यायाधीशों द्वारा अनुसरण किया गया और दोहराया गया
ने गुप्ता मामले में फैसला सुनाया है: (एस. सी. सी. पी. 483,

मामला। फजल अली, जे.

पैरा 569)

"(3) यदि सीजेआई के साथ परामर्श पहले नहीं किया गया है

एक न्यायाधीश का स्थानांतरण, स्थानांतरण बन जाता है

असंवैधानिक "। सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्डसमाज v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

गुप्ता मामले में जे. वेंकटरमैया ने भी व्यक्त किया है

एक ही दृश्य।

172. संघ में व्यक्त उपरोक्त दृष्टिकोण के आलोक में

भारत बनाम. संकलचंद हिमतलाल सेठ। (1977) एससीसी 4 193।
कुछ न्यायाधीश एस. सी. सी.

और 1981 के गुप्ता मामले में

87 यह सरलता से माना जा सकता है कि सीजेआई के साथ परामर्श

अनुच्छेद 124 (2) के पहले परंतुक के साथ-साथ इसके तहत

अनुच्छेद 217 एक अनिवार्य शर्त है, जिसका उल्लंघन

यह संवैधानिक जनादेश के विपरीत होगा।

XXX

XXX

XXX

181. यह नहीं कहा जा सकता है कि सीजेआई के प्रमुख होने के नाते

भारतीय न्यायपालिका और न्यायिक बिरादरी के माता-पिता

अखंडता की रक्षा में सतर्क निगरानी रखनी होती है और

न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करना और वह उस में

क्षमता संबंधित उम्मीदवार की योग्यता का मूल्यांकन करती है।

उसकी व्यावसायिक उपलब्धियों, कानूनी क्षमता आदि के लिए और

अपनी राय देते हैं। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है।

आवेदन करके सीजेआई की उस राय को स्कैन करने में औचित्य

ओवरगार्डिंग की आड़ में एक सुपरइम्पोजिशन परीक्षण

न्यायपालिका।

XXX

XXX

XXX

183. इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि की बराबरी नहीं की जा सकती है

न्यायिक कार्यालय में नियुक्ति

कार्यपालक या अन्य सेवाओं में नियुक्ति। ए में

अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम में हालिया निर्णय। संघ का

भारत (1993) 4 एस. सी. सी. 288. तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा प्रस्तुत

एम. एन. वेंकटचलैया, सी. जे. की अध्यक्षता में और

ए. एम. अहमदी और पी. बी. सावंत, जे., निम्नलिखित

राज्य से। वे उसी में सार्वजनिक पदों के धारक हैं।
[2015] 13 एस. सी. आर. के सदस्यों के रूप में।

मंत्रिपरिषद और सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

विधायिका के सदस्य। जब कहा जाता है कि ए

लोकतंत्र जैसे कि हमारा, कार्यपालिका, विधायिका और

न्यायपालिका राज्य के तीन स्तंभों का गठन करती है,

यह बताने का इरादा है कि तीन आवश्यक हैं

राज्य के कार्य तीन अंगों को सौंपे गए हैं - राज्य और उनमें से प्रत्येक बदले में प्रतिनिधित्व करता है

राज्य का अधिकार। हालांकि, जो व्यायाम करते हैं राज्य की शक्ति मंत्री, विधायक और

न्यायाधीश, न कि उनके कर्मचारियों के सदस्य जो

उनके निर्णयों को लागू करने या लागू करने में सहायता करें। द.

मंत्रिपरिषद या राजनीतिक कार्यपालिका अलग होती है।

सचिवीय कर्मचारी या प्रशासनिक कार्यपालक से

जो राजनीतिक कार्यपालिका के निर्णयों को पूरा करता है।

इसी तरह, विधायक विधायी से अलग हैं।
भी ऐसा ही है। समानता

कर्मचारी। न्यायिक कर्मचारियों के न्यायाधीशों के लिए

राजनीतिक कार्यपालिका, विधायिका और विधायिका के बीच है

न्यायाधीशों और न कि न्यायाधीशों और प्रशासनिक के बीच

कुछ राज्य न्यायपालिकाओं का चुनाव उतना ही किया जाता है जितना राज्य के प्रमुख। द.

विधायिका के सदस्य और

न्यायाधीश, चाहे वे किसी भी स्तर पर हों, राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रशासनिक कार्यपालिका के विपरीत इसका अधिकार या अन्य सेवाओं के सदस्य। दूसरे के सदस्य इसलिए, सेवाओं को इसके बराबर नहीं रखा जा सकता है न्यायपालिका के सदस्य, या तो संवैधानिक रूप से या कार्यात्मक रूप से "।

जिसके बाद, इस न्यायालय ने अपने निष्कर्ष दर्ज किए। द.

चींटी निष्कर्ष यहाँ नीचे निकाले गए हैं:

"(1) राष्ट्रपति द्वारा सीजेआई के साथ 'परामर्श' किया जाता है

न्यायपालिका से संबंधित और किसी अन्य सेवा से संबंधित नहीं।

(2) विभिन्न संवैधानिक नियुक्तियों की प्रक्रिया में,

'इसके विपरीत 'परामर्श' केवल न्यायिक कार्यालय के लिए आवश्यक है।

अन्य उच्च श्रेणी के संवैधानिक कार्यालयों में। इससे पहले

'अनुच्छेद 124 (2) के पहले प्रावधान में परिकल्पित 'परामर्श' अनुच्छेद 217 (1) एक सर्वोच्च न्यायालय-ऑन-रिकॉर्ड है।

और न्यायिक कार्यालयों के संबंध में

समाज v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

आरक्षण

या राष्ट्रपति की शक्ति पर सीमा

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करना।

XXX

XXX

XXX

(4) जिस संदर्भ में अभिव्यक्ति "हमेशा होगी

अनुच्छेद 124 (2) के पहले परंतुक में प्रयुक्त "परामर्श" और

"नियुक्त किया जाएगा. परामर्श के बाद" अभिव्यक्ति

अनुच्छेद 217 (1) में तैनात अनिवार्य चरित्र को दर्शाता है

'परामर्श' का, जो बाध्यकारी होना चाहिए और है

चरित्र।

(5) अनुच्छेद 124 और 217 विशिष्ट शब्दों में नहीं बोलते हैं।

राष्ट्रपति से कार्यपालिका से इस प्रकार परामर्श करने की अपेक्षा करना,

लेकिन कार्यकारी की प्रक्रिया में खेल में आता है न्यायपालिका के उच्च क्षेत्रों में न्यायाधीशों की नियुक्ति

के अनुच्छेद 74 और 163 के संचालन द्वारा सेवा संविधान। दूसरे शब्दों में, नियुक्ति के मामले में

न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में अकेले सीजेआई अनुच्छेद के अनिवार्य प्रावधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय

124 (2) और न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में

उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति सीजेआई से परामर्श करने के लिए बाध्य है और

राज्य के राज्यपाल और इसके अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश

संबंधित उच्च न्यायालय की, नियुक्ति के मामले में

यह उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश से संबंधित है। अदालत। इसलिए, सी. जे. आई. की राय को समान रूप से रखना।

अन्य संवैधानिक अधिकारियों के साथ नहीं है

संविधान की भावना के अनुरूप, लेकिन इसके खिलाफ

विषय की प्रकृति-संबंधित विषय न्यायपालिका और उस संदर्भ के विरोध में जिसमें

'परामर्श' आवश्यक है। भगवती के दर्शन के बाद,

जे. गुप्ता के मामले में कि 'परामर्श' पूर्ण होना चाहिए और प्रभावी यह मानने का कोई कल्पनीय कारण नहीं है कि

'परामर्श' पर प्राथमिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

XXX

XXX

XXX

196. उपरोक्त तथ्यात्मक और कानूनी पृष्ठभूमि में स्थिति, 'परामर्श' शब्द का अर्थ नहीं हो सकता है यह अपनी सामान्य शाब्दिक परिभाषा तक सीमित है। इसकी सामग्री बहुत अधिक है। परिस्थितियों और संदर्भ के अनुसार भिन्न होता है जिसमें इस शब्द का उपयोग हमारे संविधान में किया गया है।

XXX

XXX

XXX

207. इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वर्तमान में राज्य ने प्रमुख वादी और उच्च न्यायालय बनें विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय, के लिए केंद्र बन गए हैं अशांत विवाद, जिनमें से कुछ के स्वाद के साथ राजनीतिक नतीजों और अदालतों को तूफान का सामना करना पड़ता है और तूफान क्योंकि उनकी जीवन शक्ति एक राष्ट्रीय अनिवार्यता है। मैं। अतः ऐसी परिस्थितियों में सरकार, अर्थात्, प्रमुख वादी को पूर्ण आनंद लेने में न्यायसंगत ठहराया जाए। अपने मध्यस्थों को नामित करने और नियुक्त करने का अधिकार। द. इसका जवाब नकारात्मक होगा। अगर ऐसी प्रक्रिया है जारी रखने की अनुमति दी गई, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लंबी दौड़ बिना किसी निशान के डूब जाएगी। तरह-तरह से गुजरने से विधि आयोग की रिपोर्ट (विशेष रूप से चौदहवाँ, अस्सी और एक सौ बीस-एक) की रिपोर्टें

प्रतिष्ठित न्यायविदों आदि के सेमिनार और लेख, हम
 समझें कि विधि में एक क्रांतिकारी परिवर्तन
 उच्च न्यायपालिका में प्रतिबंध लगाकर न्यायाधीशों की नियुक्ति।
 कार्यपालिका की शक्ति को बढ़ा दिया गया है लेकिन
 अभी तक वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं
 स्वतंत्रता की प्राप्ति के लगभग 46 वर्ष और के गठन के आगमन के बाद से 42 से अधिक वर्षों
 हमारी संवैधानिक प्रणाली बीत चुकी है। लेकिन यह एक
 गौरवपूर्ण विशेषाधिकार है कि हमारे न्यायपालिका का मनाया गया जन्म
 प्रणाली, इसकी स्वतंत्रता, न्याय के वितरण का तरीका राष्ट्रवादी विचारों को मजबूत रखने वाले
 प्रतिष्ठित न्यायाधीशों द्वारा
 किसी भी अन्य राष्ट्रों में अन्य न्यायाधीशों की तुलना में, और परिणामी
 भारतीय न्यायपालिका की जीत अत्यधिक सराहनीय है।
 लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वर्तमान प्रणाली को अदालत की अध्यक्षता करनी चाहिए

अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

हमेशा के लिए जारी रखें, और कार्यपालक को आनंद लेने की अनुमति देकर
 नियुक्ति के मामले में पूर्ण प्रधानता
 न्यायाधीशों को इसका 'शाही विशेषाधिकार' माना जाता है।
 208. विद्वान महान्यायवादी और श्री की दलीलें
 उनके अनुपात की ताकत, स्वीकार्य नहीं पाई गई है और उपरोक्त
 सभी कारणों से गिर जाता है
 सिद्धांत की अंतर्निहित कमजोरी के कारण जो
 उन्होंने बचाव करने का प्रयास किया है।
 जहाँ तक ए. एम. द्वारा लिखित अल्पमत निर्णय का संबंध है।

मादी, जे., (जैसा कि वे तब थे) का संबंध है, यह केवल प्रासंगिक है पैराग्राफ 313 में दर्ज पहले निष्कर्ष पर प्रकाश डालें, जो

यहाँ नीचे प्रस्तुत किया गया है:

"313. हम निष्कर्ष निकालते हैं:

(1) न्यायिक स्वतंत्रता की अवधारणा गहराई से अंतर्निहित है

हमारी संवैधानिक योजना और अनुच्छेद 50 में इसे उजागर किया गया है। स्वतंत्रता की डिग्री एक व्यक्ति के होने के बाद कुल के करीब होती है

न्यायिक परिवार में नियुक्त और शामिल किया गया। "

24. जहाँ तक मामले का तात्कालिक पहलू है

सिद्ध, विद्वान सलाह ने हमारा ध्यान आकर्षित किया

एन. जे. ए. सी. अधिनियम का प्रतीक, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए एक अधिनियम

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग

प्रमुख के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करना

भारत के न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश

और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश और

उनके स्थानान्तरण के लिए और उससे संबंधित मामलों के लिए या

आनुषंगिक "।

वस्तुओं और कारणों का कथन। यह भी हो रहा है

यहाँ नीचे निकाला गया है:

"उद्देश्यों और कारणों का विवरण

XXX

XXX

XXX

2. उच्चतम न्यायालय की शीर्ष अदालत की रिपोर्ट के मामले में सर्वोच्च न्यायालय

[2015] 13 एस सी आर।

अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ
वर्ष 1993 में, और वर्ष 1998 में अपनी सलाहकार राय में
तीसरे न्यायाधीशों के मामले में अनुच्छेद के खंड (2) की व्याख्या की गई थी।
124 और संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) के साथ
"परामर्श" के अर्थ के संबंध में "सहमति" के रूप में। नतीजतन, एक प्रक्रिया ज्ञापन के लिए
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति
न्यायालयों को तैयार किया गया था और उनका पालन किया जा रहा है
नियुक्ति।

3. प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों की समीक्षा के बाद, उच्चतम न्यायालय की घोषणाएँ और परामर्श
प्रख्यात न्यायविदों के साथ, यह महसूस किया जाता है कि एक व्यापक राष्ट्रीय
न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की जानी चाहिए।
न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने के लिए
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। ने कहा कि
आयोग एक सार्थक भूमिका प्रदान करेगा
न्यायपालिका, कार्यपालिका और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को प्रस्तुत करना उनका दृष्टिकोण इंगित करता
है और प्रतिभागियों को जवाबदेह बनाता है,
चयन में पारदर्शिता भी लाते हुए

प्रक्रिया। 4. संविधान (एक सौ इकतीस)
संशोधन) विधेयक, 2014 एक सक्षमकारी संवैधानिक विधेयक है।
संबंधित प्रावधानों में संशोधन के लिए संशोधन
संविधान और एक राष्ट्रीय न्यायपालिका की स्थापना के लिए
नियुक्ति आयोग। प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य है -
अनुच्छेद 124 के बाद नए अनुच्छेद 124 ए, 124 बी और 124 सी सम्मिलित करें।
संविधान से। उक्त विधेयक में यह भी प्रावधान है कि
प्रस्तावित राष्ट्रीय संविधान की संरचना और कार्य

न्यायिक नियुक्ति आयोग। इसके अलावा, यह प्रदान करता है कि
 संसद, कानून द्वारा, प्रक्रिया को विनियमित कर सकती है
 न्यायाधीशों की नियुक्ति और राष्ट्रीय न्यायपालिका को सशक्त बनाना
 नियुक्ति आयोग द्वारा प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी
 अपने कार्यों के निर्वहन के लिए विनियमन, नियुक्ति के लिए व्यक्तियों का चयन और ऐसे अन्य
 जिन मामलों को आवश्यक माना जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

5. प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य इस पद्धति का आधार व्यापक बनाना है -
 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति

प्रतिष्ठित व्यक्ति और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करना,
 नियुक्ति में जवाबदेही और निष्पक्षता

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश।

6. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है।

रविशंकर प्रसाद

नई दिल्ली -

8 अगस्त, 2014 "।

कारणों के गैर-प्रकटीकरण के आधार पर, मौजूदा क्यों

प्रक्रिया को अनुपयुक्त माना गया था, यह तर्क दिया गया था कि
 एकमात्र उद्देश्य जो प्राप्त करने की मांग की गई थी, वह थी प्रधानता को कम करना,
 इससे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास निहित (एक के आधार पर)
 न्यायाधीशों के कॉलेजियम का निर्णय), अनुच्छेदों के तहत प्रदान किया गया

124 और 217, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित है। यह दूर कर दिया गया था, यह इंगित किया
 गया था, भारत के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिस्थापित करके,

एनजेएसी के साथ।

25. प्राथमिक प्रस्तुतिकरण के हाथों में आगे बढ़ा

श्री फली एस. नरीमन, वरिष्ठ अधिवक्ता, के संदर्भ में थे
 "बुनियादी संरचना" का उल्लंघन, न केवल इसके माध्यम से
 संविधान (99 वां संशोधन) अधिनियम, लेकिन यह भी कि
 एनजेएसी अधिनियम। यह बताया गया था कि शुरुआत से ही संविधान के, जब भी परिवर्तनों की
 सिफारिश की गई थी
 न्यायाधीशों की नियुक्ति का संबंध, वह मुद्दा जो ध्यान का केंद्र बना रहा, प्रमुख की प्रधानता
 भारत का न्याय। यह तर्क दिया गया था कि प्रधानता थी
 न्यायपालिका की निर्णायक आवाज के रूप में मान्यता प्राप्त, जिसके आधार पर
 न्यायाधीशों के कॉलेजियम का सामूहिक निर्णय, जो इसका प्रतिनिधित्व करता है
 महाविद्यालयी ज्ञान। यह प्रस्तुत किया गया था कि मुख्य न्यायाधीश भारत, एक व्यक्ति के रूप में,
 साथ ही, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में
 व्यक्तिगत रूप से न्यायालयों को व्यक्ति नहीं माना जा सकता था।
 नामित करें। यह इंगित किया गया था कि निर्णय में दिया गया था
 द्वितीय न्यायाधीशों का मामला अप्रासंगिक नहीं हो गया था। यह
 न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के संरक्षण का प्रावधान किया है।

[2015] 13 एस सी आर।

"न्यायपालिका की स्वतंत्रता"। उपरोक्त निर्णय,
 साथ ही, तीसरे न्यायाधीशों के मामले में बाद का निर्णय,
 स्थापित और पुनः पुष्टि की कि भारत के मुख्य न्यायाधीश,
 न्यायाधीशों के एक निकाय के माध्यम से प्रतिनिधित्व, प्रधानता थी।
 विद्वान वकील के अनुसार, व्यक्तिगत मुख्य न्यायाधीश
 भारत, सामूहिक राय का प्रतिनिधित्व नहीं कर सका और नहीं किया
 न्यायाधीशों। यह दावा किया गया था कि संविधान (99 वां)
 संशोधन) अधिनियम और एन. जे. ए. सी. अधिनियम ने,

भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास निहित जिम्मेदारी,
 न्यायाधीशों के कॉलेजियम के माध्यम से प्रतिनिधित्व (अनुच्छेद 124 के तहत) और 217-जैसा कि
 मूल रूप से अधिनियमित)। तदनुसार, यह प्रस्तुत किया गया था,
 कि चयन और नियुक्ति के लिए अपनाई गई प्रणाली तक
 न्यायाधीश, स्थापित और पुष्टि करते हैं, निर्विवाद प्रधानता
 न्यायपालिका की, "न्यायपालिका की स्वतंत्रता" नहीं हो सकती थी
 संरक्षित माना जाता है।

26. जहाँ तक हाथ में मुद्दे का संबंध है, यह था
 विद्वान वकील का स्पष्ट तर्क, कि निर्णय
 इस न्यायालय द्वारा सरदार लाल बनाम में प्रस्तुत किया गया। भारत संघ 37, आया
 समशेर सिंह मामले में खारिज किया जाना। इसका उल्लेख करते हुए
 समशेर सिंह मामले में फैसला 11, उन्होंने इस अदालत को आमंत्रित किया
 उसमें दर्ज निम्नलिखित टिप्पणियों पर ध्यान दें:

"147. जे. पी. मिस्त्र बनाम मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता आकाशवाणी 1965 एस. सी.

961 इस न्यायालय को निर्णय पर विचार करना था

कलकत्ता के न्यायाधीश की आयु पर भारत सरकार
 उच्च न्यायालय और, उस संदर्भ में, सच्चाई का पता लगाना था

अनुच्छेद 217 (3) का दायरा और प्रभाव

आयु निर्धारित करने के लिए विशेष अधिकार क्षेत्र वाले राष्ट्रपति

अंत में एक न्यायाधीश का। उस मामले में गृह मंत्रालय

अनुच्छेद 217 (3) में निर्धारित अभ्यास से गुजरे। द.

तब गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री, पश्चिम को पत्र लिखा

बंगाल, कि उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया था,

और वह प्रमुख द्वारा दी गई सलाह से सहमत हो गया

न्याय, और इसलिए उन्होंने तय किया था कि जन्म की तारीख

37 एयर 1971 एससी 1547 सर्वोच्च न्यायालय-ऑन-रिकॉर्डसमाज v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

अपीलार्थी था। यह वह निर्णय है जो नियत समय पर लिया गया था।

अपीलार्थी को सूचित किया गया "। जब उक्त निर्णय

केवल गृह मंत्री के पहुँचने पर हमला किया गया था

और राष्ट्रपति द्वारा व्यक्तिगत रूप से नहीं, न्यायालय ने कहा: "अपीलार्थी ने जो वैकल्पिक रुख अपनाया वह यह था कि

कार्यपालिका को अपनी आयु निर्धारित करने का अधिकार नहीं था, और यह

यह याद रखना चाहिए कि यह रुख पहले लिया गया था

संविधान में अनुच्छेद 217 (3) जोड़ा गया था; अपीलार्थी निसंशय यह तर्क देना उचित था कि कार्यपालिका

उसके बारे में प्रश्न निर्धारित करने के लिए सक्षम नहीं था

उम्र क्योंकि यह एक ऐसा मामला है जिस पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए

आम तौर पर, उच्च न्यायालय के समक्ष स्थापित न्यायिक कार्यवाही में सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय। वहाँ काफी है

याचिका में बल जिसे अपीलार्थी ने प्रारंभिक चरणों में लिया था

इस विवाद का कि यदि कार्यपालिका को अनुमति दी जाती है

न्यायपालिका की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा स्वयं "।

इस तर्क के आधार पर, न्यायालय ने आदेश को रद्द कर दिया,

मामले का अनुपात यह है कि राष्ट्रपति को स्वयं करना चाहिए

कार्यपालिका द्वारा अप्रभावित न्यायाधीश की आयु निर्धारित करें। अर्थात् पोर्टफोलियो के प्रभारी मंत्री द्वारा

न्याय।

148. इस निर्णय को भारत संघ बनाम में दोहराया गया था। ज्योति

प्रकाश मिस्त्र (1971) 1 एससीसी 396। हालांकि एक तर्क

यह बनाया गया था कि राष्ट्रपति को उस मामले में खारिज कर दिया गया था

गृह मंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा, यह

न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसने तथ्यों पर पाया कि

स्वयं राष्ट्रपति होने का निर्णय, न कि राष्ट्रपति का

प्रधानमंत्री या गृह मंत्री।

149. संविधान की योजना के आलोक में हमारे पास है

पहले से ही संदर्भित, यह संदेहपूर्ण है कि क्या ऐसा

राष्ट्रपति की व्यक्तिगत संतुष्टि के रूप में व्याख्या

सही है। हमारा विचार है कि राष्ट्रपति का अर्थ है, सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, मंत्री या [2015] 13 एस. सी. आर. की परिषद।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मंत्री, जैसा भी मामला हो, और उनकी राय, संतुष्टि

या निर्णय संवैधानिक रूप से तब सुरक्षित होता है जब उसके मंत्री

इस तरह की राय संतुष्टि या निर्णय पर पहुँचें। द.
न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो एक प्रमुख सिद्धांत है

संविधान का और न्यायसंगत ठहराने के लिए भरोसा किया गया है

विचलन। प्रासंगिक लेख-निर्माण द्वारा संरक्षित है

भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श अनिवार्य है। कुल मिलाकर

संभावित मामलों में उस सर्वोच्च गणमान्य व्यक्ति के साथ परामर्श

भारतीय न्याय के द्वारा स्वीकार किया जाएगा और किया जाना चाहिए

भारत सरकार और न्यायालय के पास एक अवसर होगा

यह जांचने के लिए कि क्या कोई अन्य बाहरी परिस्थितियाँ हैं

मंत्री के फैसले में प्रवेश किया, अगर वह छोड़ देता है

ऐसे संवेदनशील विषय में अंतिम शब्द होना चाहिए
भारत के मुख्य न्यायाधीश, उनकी सलाह की अस्वीकृति

आमतौर पर तिरछे विचारों द्वारा प्रेरित माना जाता है
आदेश को दूषित करना। इस दृष्टिकोण से यह मायने नहीं रखता कि क्या

राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या न्याय मंत्री

औपचारिक रूप से इस मुद्दे का फैसला करता है। ”

27. यह बताया गया था कि समशेर में निर्णय

सिंह मामला 11, में निर्णय से बहुत पहले प्रस्तुत किया गया था

प्रथम न्यायाधीशों का मामला, जिसमें इस न्यायालय ने महसूस किया कि न्यायाधीश कर सकते हैं

संस्थागत स्वायत्तता की गारंटी दी गई थी। व्यक्त विचार 1974 में समशेर सिंह मामले में अंतिम प्राधिकरण यह था कि

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में,

भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ आराम किया। यह इंगित किया गया था कि।

उपरोक्त स्थिति ने तब से मैदान पर कब्जा कर लिया था। यह था।

प्रस्तुत किया कि “न्यायपालिका की स्वतंत्रता” हमेशा रही है नियुक्ति के मामले में स्वतंत्रता का अर्थ और शामिल

न्यायाधीशों से लेकर उच्च न्यायपालिका तक।

28. श्री अरविंद पी. दातार, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता

तर्क दिया कि एन. जे. ए. सी. को एक संशोधन द्वारा बनाया गया था

संविधान के लिए।

इसलिए यह सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं-ऑन-रिकॉर्ड का एक प्राणी था।

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

संविधान। बनाने के लिए एन. जे. ए. सी. के पास शक्ति निहित थी। न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिशें

प्रमुख के स्थानांतरण की शक्ति सहित उच्च न्यायपालिका उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय से लेकर

एक और। उपरोक्त संवैधानिक प्राधिकरण, यह प्रस्तुत किया गया था,

एक संवैधानिक योजना द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए, जो प्रवाहित होनी चाहिए

स्वयं संविधान के प्रावधानों से। इसलिए यह कहा गया

जोर देकर कहा कि एन. जे. ए. सी. के काम करने का तरीका होना चाहिए स्वयं संविधान में निहित।
यह प्रस्तुत किया गया था कि

एन. जे. ए. सी. के काम करने की विधि, पर नहीं छोड़ा जा सका संसद, सामान्य कानून द्वारा
विनियमित की जाएगी। समर्थन करने के लिए

उनके विवादित तर्क, निर्भरता को प्रविष्टियों 77 पर रखा गया था।

और 78, जो सातवीं अनुसूची की संघ सूची में निहित है। यह प्रस्तुत किया गया था कि कानून
बनाने की शक्ति, के साथ

प्रविष्टियाँ 77 और 78 का संदर्भ निरपेक्ष नहीं था

के रूप में, अनुच्छेद 245 ने संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत किया इसके दायरे में आने
वाले विषय, मूल के अधीन

संविधान में निहित प्रावधान। उपरोक्त कारणों से,

यह दावा किया गया था कि एन. जे. ए. सी. की गतिविधियों को नहीं किया जा सकता है

में निहित शक्ति के अधीन या अधीन किया गया संसद, प्रविष्टियों 77 और 78 के तहत।

29. यह श्री राम जेठमलानी द्वारा तर्क दिया गया था, ज्ञात

वरिष्ठ अधिवक्ता, कि पर्याप्त परिस्थितिजन्य था

यह प्रदर्शित करने के लिए सबूत, कि वर्तमान राजनीतिक

प्रतिष्ठान ने महसूस किया कि न्यायपालिका के लिए एक बाधा थी

अपनी नीतियों का कार्यान्वयन। यह तर्क दिया गया था कि पूरे

प्रयास, चयन में शामिल करके न्यायपालिका को वश में करना था प्रक्रिया, जो राजनीतिक रूप
से प्रभावित हो सकते हैं। इसके लिए

परियोजना, राजनीतिक व्यवस्था का ठोस प्रयास, में

"न्यायपालिका की स्वतंत्रता" को नष्ट करते हुए, विद्वान वकील,

राष्ट्रीय न्यायिक आयोग [संविधान (67 वां) संशोधन) विधेयक, 1990] को लोकसभा में पेश किया
गया था

18.5.1990. इसके "उद्देश्यों और कारणों" का कथन, जो

जिस पर भरोसा किया गया था, उसे नीचे निकाला गया है:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

"भारत सरकार ने हाल के दिनों में

एक उच्च स्तरीय न्यायपालिका स्थापित करने के अपने इरादे की घोषणा की

आयोग, जिसे राष्ट्रीय न्यायिक आयोग कहा जाएगा

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए और

उच्च न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का स्थानांतरण

अदालतें ताकि मनमानेपन की आलोचनाओं को दूर किया जा सके

ऐसी नियुक्तियों और स्थानान्तरणों में कार्यपालिका का हिस्सा

और बिना किसी देरी के ऐसी नियुक्तियाँ करना भी।

भारत के विधि आयोग ने अपने एक सौ और

सिस्टम में।

2. राष्ट्रीय न्यायिक आयोग ने

नियुक्ति के संबंध में सिफारिशें

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे

भारत के मुख्य न्यायाधीश की वरिष्ठता में अगला। द.

आयोग के संबंध में सिफारिशें करने के लिए

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में शामिल होंगे

भारत के मुख्य न्यायाधीश का एक वरिष्ठतम न्यायाधीश

उच्चतम न्यायालय, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री,

उस उच्च न्यायालय के अधिकांश न्यायाधीश।

3. विधेयक उपरोक्त उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है।

नई दिल्ली;

11 मई, 1990; "

उपरोक्त में प्रस्तावित राष्ट्रीय न्यायिक आयोग

विधेयक को भाग XIII का एक घटक बनाया जाना था
शामिल करके। मुखिया।

संविधान, उसमें अनुच्छेद 307 ए को

भारत के न्यायाधीश, और अगले दो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश

उच्चतम न्यायालय को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया था

नियुक्तियाँ करने के लिए विचारित आयोग उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश

उच्च न्यायालयों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के एक से स्थानांतरण के लिए उच्च न्यायालय से दूसरे तक।

उपरोक्त आयोग ने किसी भी सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं को हटा दिया-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

उच्चतम न्यायालय के, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायालय, और उस न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश। उपरोक्त बिल

एक स्वतंत्र और अलग सचिवालय के लिए भी प्रावधान किया गया

विचार किए गए आयोग के लिए कर्मचारी। यह प्रस्तुत किया गया था कि संविधान में उपरोक्त संशोधन, के कारण था

कानूनी स्थिति के साथ मोहभंग और अविश्वास,

प्रथम न्यायाधीशों के मामले में इस न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई। यह था। प्रस्तुत किया गया कि प्रस्तावित को प्रभावी बनाने की आवश्यकता

संविधान (67 वां संशोधन) विधेयक, 1990 को तब निरस्त कर दिया गया जब

इस न्यायालय ने दूसरे न्यायाधीशों के मामले में अपना फैसला सुनाया।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के अनुसार, यह सब

भुला दिया गया और नजरअंदाज कर दिया गया।

30. ऐतिहासिक रूप से, अगला चरण तब था जब संविधान बनाया गया था

(98) विधेयक, 2003 को संसद के समक्ष रखा गया था। उसके विचार के लिए। उपरोक्त विधेयक में, कार्यपालिका

चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया में भागीदारी

न्यायाधीशों को उच्च न्यायपालिका में पेश किया गया था

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री, के पदेन सदस्य

आयोग ने। दो प्रतिष्ठित नागरिक (या तो प्रख्यात न्यायविद,

या प्रतिष्ठित वकील, या उच्च प्रतिष्ठा के कानूनी शिक्षाविद)

आयोग के सदस्य भी होंगे। उनमें से एक था

प्रमुख के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना
 भारत के न्यायाधीश, और दूसरा, प्रधानमंत्री के परामर्श से
 मंत्री। एक और प्रयास किया गया (पिछले यू. पी. ए. द्वारा)।
 सरकार), उसी दिशा में, संविधान के माध्यम से
 (120) विधेयक, 2013, 2003 की तर्ज पर
 बिला। यह इंगित करने की मांग की गई कि सभी पक्षों के बीच आम सहमति थी कि उपरोक्त विधेयक
 मंजूरी दे दी गई। और वह, एक सदस्य के रूप में व्यक्तिगत रूप से विद्वान सलाहकार
 राज्यसभा ने उपरोक्त कदम का पुरजोर विरोध किया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.
 विद्वान वकील ने आपत्तियों पर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया
 राज्य सभा के समक्ष बहस के दौरान उनके द्वारा उठाया गया मुद्दा सभा। उन्होंने जोर देकर कहा कि
 उन्होंने प्रस्तुत किया था
 संसद, कि संविधान संशोधन विधेयक की आवश्यकता थी संसद की प्रवर समिति को संदर्भित किया
 जाए, जैसा कि
 उनकी राय में यह असंवैधानिक था। का एक उद्धरण
 बहस को भी हमारे ध्यान में लाया गया था (प्रतिस्थापित करके
 इसका स्थानीय भाग, इसके अंग्रेजी अनुवाद के साथ), यह किया जा रहा है
 यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है: .

आयोग विधेयक स्थायी समिति के पास जाता है। बाकी सब।
 जिस व्यवसाय से हमें आज गुजरना चाहिए। थैंक यू।

श्री राम जेठमलाली: महोदया, धन्यवाद; देर से आना बेहतर है।
 कभी नहीं।

महोदय, मैं दो प्रारंभिक सुझाव देना चाहता हूँ। अगर ऐसा है तो
 एक आश्वासन कि संविधान (संशोधन) विधेयक के रूप में
 साथ ही सहायक विधेयक दोनों को एक चयन के लिए भेजा जाएगा
 संसद की समिति, मैं इसे संबोधित करने का प्रस्ताव नहीं करता।

घर बिल्कुल। लेकिन, मैं इसे उपयुक्त या उचित नहीं मानता।

कि केवल दूसरे विधेयक को किसी चयनकर्ता को भेजा जाना चाहिए।

समिति। दोनों को भेजा जाना चाहिए। और, मैं अपना दूँगा

कारणों से।

महोदय, दूसरा सुझाव जो मुझे देना है वह यह है। मेरा।

मुख्य तर्क, जो मैं करने जा रहा हूँ, वह यह है कि संविधान (संशोधन) विधेयक पूरी तरह से असंवैधानिक है

और, यदि पारित किया जाता है, तो यह निस्संदेह द्वारा अलग रखा जाएगा

सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि यह मूल विशेषता में हस्तक्षेप करता है संविधान से। संविधान के ऐसे संशोधन

संविधान द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के लिए दो तिहाई की आवश्यकता होती है बहुमत और इसी तरह आगे। यह केवल उन पर लागू होता है

संविधान के संशोधन जो क्या नहीं छूते हैं

केशवानंद भारती मामले में समझी गई संविधान की बुनियादी विशेषताएँ कहल जाती हैं।

यह सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्डसमाज v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

संवैधानिक संशोधन, निश्चित रूप से, एक बुनियादी व्यवस्था में हस्तक्षेप करता है।

भारतीय संविधान की विशेषता और इसे कायम नहीं रखा जाएगा

सर्वोच्च को एक संदर्भ दिए जाने तक लागू किया जाता है न्यायालय और उच्चतम न्यायालय इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि

सकारात्मक में इस संविधान संशोधन की वैधता।

अगर ऐसा किया जाता है। मुझे फिर से बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन, श्रीमान, क्योंकि मैं

इन दोनों उचित सुझावों की अपेक्षा न करें

स्वीकार किया, मैं बोलने और अपने मन की बात कहने का इरादा रखता हूँ।

XXX

XXX

XXX

कपिल मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और देश के मंत्रियों में से एक हैं।

सरकार जिसका काम मैं कानून मंत्री के रूप में करता हूँ

पर्यवेक्षण कर रहा हूँ और मैं खुश हूँ जिस तरह से वह

अपने मंत्रालय का संचालन करता है। लेकिन, साहब। मुझे आज घोषणा करनी चाहिए कि मेरी
अंतरात्मा, समझ और मेरे प्रति मेरा कर्तव्य

इस देश के लोग, जिन्हें मैं सर्वोपरि मानता हूँ। दायित्व, मुझे इस तरह के अधीन होने की अनुमति न
दें

कानून। दोनों बिल, मेरे अनुसार खराब हैं। द.

बुराई, सबसे पहले, के भ्रामक कथन में शामिल है

वस्तुएँ-और-कारण। आपको कहना चाहिए था पूरी ईमानदारी से कि आप जिसे ध्वस्त करने की
कोशिश कर रहे हैं

कॉलेजियम प्रणाली, जो वस्तु प्रतीत होती है, और जो किसी के लिए भी स्पष्ट है। कुछ लोग जो

बोले हैं इस धारणा पर बोले हैं कि आप हैं

कानून के इस विशेष टुकड़े का उद्देश्य।

महोदय, पहली बात जो मैं कहना चाहूंगा वह यह है कि 1993

नौ न्यायाधीशों का निर्णय इस पर आधारित एक निर्णय है -

संविधान की मूल विशेषता की खोज, और

क्या मैं स्वयं उस मुकदमे में उपस्थित हुआ हूँ और मैं दावा करता हूँ कि मैं की सफलता में
जबरदस्त योगदान दिया

उस फैसले को। एक अर्थ में, मैं इसके संस्थापक होने का दावा करता हूँ

कॉलेजियम प्रणाली। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं हूँ कॉलेजियम प्रणाली के असंबद्ध
प्रशंसक।

कॉलेजियम [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रणाली एक मुख्य आधार पर अस्तित्व में आई तर्क। वह एक मुख्य तर्क जिसे हम आगे बढ़ाते हैं, और

बड़े जोश और बल के साथ आगे बढ़ना, यह है कि एक है संविधान का अनुच्छेद, संविधान का
अनुच्छेद 50,

जो संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद है,
 केवल एक वाक्य। उस लेख में कहा गया है कि सरकार
 न्यायपालिका को इससे अलग रखने का प्रयास करेगा
 कार्यकारी। महोदय, हमने उच्चतम न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि यह लेख
 इसका मतलब यह नहीं है कि न्यायाधीशों और मंत्रियों को सामाजिक रूप से ऐसा नहीं करना चाहिए
 मिलते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें अलग रहना चाहिए।
 कस्बों, या कि उन्हें आस-पास भी नहीं रहना चाहिए
 बंगले। इस लेख का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि
 न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यपालिका की कोई भूमिका नहीं है
 सलाहकार की भूमिका को छोड़कर। दूसरे शब्दों में, सिद्धांत न्यायिक प्रक्रिया में कार्यपालक की
 प्रधानता
 यह हमारे लिए परेशान करने वाला था क्योंकि पूरे भारत ने
 पहले में नियुक्त न्यायाधीशों का शिकार हुआ प्रणाली। मैं अपने ही देश से शरणार्थी रहा हूँ
 आपातकाल। यह क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि चार सर्वोच्च
 अदालत के न्यायाधीश-मैं पाँचवें की बात नहीं कर रहा हूँ जिसने अर्जित किया
 न्यूयॉर्क टाइम्स ने प्रशंसा की कि भारतीय राष्ट्र को करना होगा
 उनकी स्मृति में एक स्मारक बनाएँ, मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ।
 चार जिन्होंने न्यायपालिका को अपमानित किया, सर्वोच्च को अपमानित किया
 अदालत और भारतीय के विनाश के पक्षकार थे लोकतंत्र और विध्वंस और पतन
 भारत का पूरा संविधान। महोदय, वे किस प्रणाली के थे? उत्पाद? वे उस प्रणाली के उत्पाद थे जो,
 1981 में, अंततः गुप्त निर्णय द्वारा समर्थित किया गया था
 लेकिन, कुछ समय बाद, ऐसे लोग थे, बुद्धिजीवी, जो
 बोले कि यह प्रणाली काम नहीं करेगी; प्रणाली बदलाव की जरूरत है। महोदय, भारतीय
 लोकतंत्र बच गया है।
 बुद्धिजीवियों द्वारा नहीं; भारतीय लोकतंत्र अपने सबसे महत्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं-ऑन-
 रिकॉर्ड

समाज v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

इस देश के गरीब अनपढ़ लोगों ने समय बचाया है।

संकट के समय, केवल बहादुर दिल वाले ही मायने रखते हैं।

जिन पर गर्व था, उनकी जीभ बंधी रहती थी (दो वाक्यों का अनुवाद)।
त्रासदी है। महोदय, बुद्धिजीवियों

यही हमारे देश की

यह देश लगातार विफल रहा है और मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है

कि वे आज भी असफल हो रहे हैं। कॉलेजियम हो सकता है

न्यायपालिका का निर्माण, यह न्यायपालिका का निर्माण है

व्याख्या, फिर से, संविधान की, लेकिन जो भी हो

कॉलेजियम के दोषों का आज कॉलेजियम प्रतिनिधित्व करता है

कुछ प्रणाली जो बुनियादी विशेषताओं के अनुरूप है

संविधान का, अर्थात्, न्यायपालिका की सर्वोच्चता

और कार्यपालिका के किसी भी प्रभाव से इसकी स्वतंत्रता

नियुक्ति प्रक्रिया।

XXX

XXX

महोदय, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो अपरिवर्तनीय नहीं हैं

इस संशोधन के लिए मतदान करने के लिए प्रतिबद्ध। कुछ हैं।

आज केवल उन्हीं दिमागों से अपील करें। जो हैं।

अपरिवर्तनीय रूप से विनाश के लिए प्रतिबद्ध हैं

भारतीय लोकतंत्र।

महोदय, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का प्रमुख अंश

मुख्य न्यायाधीश की राय को प्राथमिकता देने का सवाल
भारत और उनके

नियुक्ति और स्थानांतरण के मामलों में

न्यायसंगतता के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए

बुनियादी के एक भाग के रूप में न्यायपालिका की स्वतंत्रता
लिए संविधान की संरचना

कानून के शासन को सुरक्षित करने के

लोकतांत्रिक प्रणाली के संरक्षण के लिए आवश्यक है। मैं अपनाई गई शक्तियों के पृथक्करण की व्यापक योजना

के निदेशक सिद्धांतों के साथ संविधान

न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, यहां तक कि
सबसे निचला स्तर, सही अर्थ के लिए कुछ अंतर्दृष्टि प्रदान करता है
सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्टों से संबंधित संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों का

[2015] 13 एस सी आर।

न्यायपालिका की संरचना। इन का निर्माण

प्रावधानों को इन बुनियादी अवधारणाओं के अनुरूप होना चाहिए। जीवन शक्ति को संरक्षित करने
के लिए संवैधानिक योजना में और

बनाए रखने के लिए आवश्यक के विकास को बढ़ावा देना एक जीवंत जीव के रूप में संविधान "।

महोदय, संविधान जीवित नहीं रह सकता, मानव स्वतंत्रता नहीं रह सकती।

जीवित रहें, नागरिकों के मानवाधिकार जीवित नहीं रह सकते, नहीं विकास तब तक हो सकता है
जब तक, निश्चित रूप से, न्यायाधीश

पहले कार्यकारी शक्ति से स्वतंत्र हैं क्योंकि नहीं

यह भूल जाएँ कि हर नागरिक को भ्रष्ट लोगों के खिलाफ शिकायत है

कार्यपालिका के सदस्य, या, त्रुटिपूर्ण नौकरशाही, जनता अधिकारी सत्ता का दुरुपयोग करते हैं,
भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं

गलत और अवैध आदेश। नागरिक अदालत जाता है,

कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है और कहता है, "कृपया मुझे एक

इस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ, इस भ्रष्ट के खिलाफ जनादेश

मंत्री "। और, महोदय, न्यायाधीशों को निर्णय लेना है

उच्चतम न्यायालय में जाने वाले सबसे गरीब लोगों के दावे।

..... (व्यवधान)... और न्यायाधीशों के लिए। हो सकता है और मैं हूँ

होश में... (व्यवधान)। साहब, यह हँसी नहीं है। बात है। कृपया सुनें, और फिर अपने लिए निर्णय
लें।

XXX

XXX

XXX

महोदय, सबसे पहले तो अब मैं यह कहना चाहूंगा कि पूरा फैसला नौ न्यायाधीशों में से इस सिद्धांत पर आधारित है कि नियुक्ति प्रक्रिया, कार्यकारी के पास कभी नहीं हो सकता है। अब बन गया है प्रधानता। यह सिद्धांत नंबर एक है। अब बन गया है

भारत के संविधान की मूल विशेषता। आज मेरी शिकायत इस संविधान (संशोधन) विधेयक के विरुद्ध यह है कि आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अब एक नई विधि बना रहा है जिसके द्वारा अंततः आप उस प्रणाली पर लौट जाएंगे जो पहले से मौजूद थी।

1993 तक। दूसरे शब्दों में, वही प्रणाली उत्पादन करेगी वे चार न्यायाधीश जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को नष्ट कर दिया,

मानवाधिकार और स्वतंत्रता। महोदय, कृपया देखें, क्यों। द. संविधान संशोधन बहुत निर्दोष लगता है। वह सब जो वह कहता है यह है कि हमारे पास संविधान में एक नया अनुच्छेद 124 (ए) होगा और अनुच्छेद 124 (ए) केवल यह कहता है कि एक न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड होगा।

समाज v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

नियुक्ति आयोग। यह निर्धारित करता है कि न्यायिक

नियुक्ति आयोग के ये कार्य होंगे। यह. वहाँ छोड़ देते हैं। लेकिन, कृपया देखें कि पहले वाक्य के बाद,

सब कुछ संसदीय इच्छा पर छोड़ दिया जाता है। यह कहने के बाद

एक न्यायिक नियुक्ति आयोग होगा, हर बात छोड़ दी जाएगी, 124 (ए) के दूसरे भाग के अनुसार,

एक संसदीय कानून जो होने में सक्षम है

यदि सत्तारूढ़ दल के पास दोनों में एक सदस्य का बहुमत है तो उसे हटा दिया जाता है।

संसद के सदन। इतना ही नहीं, मैं समझता हूँ कि

संसद के ऐसा करने की संभावना नहीं है, लेकिन वह ऐसा कर सकती है और दोनों सदनों में एक का बहुमत, आप पूरे को ध्वस्त कर सकते हैं

और इसे एक न्यायिक आयोग के साथ प्रतिस्थापित करें जो
इसमें केवल कानून मंत्री शामिल होंगे।

XXX

XXX

XXX

तो। महोदय, मेरी पहली आपत्ति यह है कि यह विधेयक एक ऐसा विधेयक है जो संविधान की मूल
संरचना से निपटने का इरादा

और इसलिए यह विधेयक अमान्य है। (समय-घंटी) दूसरा, यदि ए
इसके लिए संवैधानिक संशोधन पर्याप्त नहीं है।

उद्देश्य, निश्चित रूप से, कानून का एक साधारण टुकड़ा नहीं कर सकता है

कानून के किस साधारण टुकड़े को केवल हटाया जा सकता है प्रत्येक सदन में एक के बहुमत से।
इसे इस तरह हटाया जा सकता है

30 जुलाई खाद्य सुरक्षा अध्यादेश और आप पारित कर सकते हैं

उस दिन एक अध्यादेश और कहें कि पूरा अधिनियम है निरस्त कर दिया गया और अब व्यवस्था
यह होगी कि न्यायाधीश होंगे

अगले छह महीनों के लिए केवल कानून मंत्री द्वारा नियुक्त किया गया

भारत से। अगर श्री कपिल सिब्बल थे, (व्यवधान)। अगर

श्री कपिल सिब्बल हमेशा के लिए कानून मंत्री बन जाते हैं, श्रीमान, मैं बनूंगा।

इस विधेयक को जाने दें। (समय-घंटी) लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ

महोदय, मुझे दो मिनट और लेने दें और उन सभी को बताने दें। सदस्यों का कहना है कि इस
विधेयक का उद्देश्य न्यायिक व्यवस्था सुनिश्चित करना नहीं है

मानव, कुछ न्यायाधीश होंगे जो गलत होंगे, जो गलत हो सकता है। लेकिन एक महान बार उन्हें
नियंत्रित कर सकता है। "

जिन सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

XXX

XXX

XXX

महोदय, मुझे आशा है कि लोग जीवन में इस तरह की त्रासदी से बचेंगे।

इस देश से। आज आप कब्र खोद रहे हैं।
भारत का संविधान और इस देश की स्वतंत्रता।

..... (रुकावटें)। मैं बस इतना ही कहना चाहता था।

..... (व्यवधान) "।

यह प्रस्तुत किया गया था कि राज्यसभा में 131 मत थे

एकल के विपरीत, प्रस्तावित विधेयक की पुष्टि में डाला गया

विद्वान वकील का वोट, उसी के खिलाफ 5.9.2013 पर। यह. हालाँकि, यह बताया गया था कि प्रयास का फल नहीं निकला,

चुनावों के लिए मध्यवर्ती घोषणा का लेखा-जोखा संसद।

31. इसके बाद विद्वान परामर्श ने हमारा ध्यान आकर्षित किया

उद्धोषणा के लिए "उद्देश्य और कारण" का कथन

संविधान (121 वां संशोधन) विधेयक, 2014। वह विधेयक जो

अंततः विवादित संविधान (99 वां) को जन्म दिया।

संशोधन) अधिनियम, लोक सभा द्वारा विचार के लिए लिया गया था

13.8.2014 पर सभा, और बिना अधिक बहस के पारित कर दिया गया।

यह प्रस्तुत किया गया था कि अगले दिन यानी 14.8.2014,

उसी को राज्यसभा के समक्ष रखा गया था, और फिर से था बिना ज्यादा चर्चा के पारित हो गया।
यह बताया गया था कि एक

मुद्दा, हाथ में एक के रूप में गंभीर, जो गंभीर हो सकता है

"न्यायपालिका की स्वतंत्रता" पर प्रभाव, था

जल्दबाजी करने की कोशिश की।

32. यह प्रस्तुत किया गया था कि के "उद्देश्य और कारण"

संविधान (99 वां संशोधन) अधिनियम की दर्दनाक कमी थी,

प्रस्तुत किया, कि यह ध्यान में लाना अनिवार्य था
किया था, कि

संसद की, जिसे उच्चतम न्यायालय ने घोषित

"कानून का शासन", "शक्तियों का पृथक्करण" और

"न्यायपालिका की स्वतंत्रता मुख्य और बुनियादी थी।

संविधान की विशेषताएँ। और वह, वही नहीं हो सकता था

एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से निरस्त किया गया।

और आगे सर्वोच्च न्यायालय

अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

कि, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से प्रधानता प्रदान की थी

कॉलेजियम के निर्णय के आधार पर भारत के मुख्य न्यायाधीश
स्थानान्तरण के संबंध में

न्यायाधीशों की नियुक्तियों और

उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीश।

33. श्री राम जेठमलानी ने कहा कि

विवादित संवैधानिक संशोधन, ताकि अनुच्छेद लागू किया जा सके

124 ए, को संविधान के साथ धोखाधड़ी के रूप में वर्णित किया जाना चाहिए

स्वयं। यह बताया गया था कि अनुच्छेद को लागू करने का पहला प्रयास

124 ए पिछली सरकार द्वारा बनाया गया था, जिसके माध्यम से

संविधान (120 वां संशोधन) विधेयक, 2013। उपरोक्त विधेयक में,

अकेले अनुच्छेद 124 ए (वर्तमान में अनुच्छेद 124 ए से 124 सी के विपरीत)

अधिनियमित किया गया)। यह प्रस्तुत किया गया था कि राज्य

सदन ने उपरोक्त विधेयक को 5.9.2013 पर पारित कर दिया, जब 131 सदस्य थे।

इसका विरोध करते हैं)। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि केवल उनके पास था
विरोध किया। यह दावा किया गया था कि उपरोक्त धोखाधड़ी थी

विधेयक का

लोकसभा द्वारा संविधान (121 वां संशोधन) विधेयक, 2014
राज्यसभा द्वारा। यह था।

13.8.2014 पर, और 14.8.2014 पर

इंगित किया कि विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद दलों ने हाथ मिलाया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि एक

सांसद, वह यह दावा करने की स्थिति में थे कि गुण और संविधान में आक्षेपित संशोधन के दोष, वहस नहीं की गई थी, जब विधेयक पारित किया गया था, क्योंकि विधायिका द्वारा मनोरंजन किया गया सार्वभौमिक पूर्वाग्रह, के खिलाफ न्यायपालिका। यह प्रस्तुत किया गया था कि पूर्वाग्रह और असहिष्णुता थी उत्पन्न हुआ, क्योंकि न्यायपालिका अक्सर हस्तक्षेप करती थी के साथ, और अक्सर विधायी कार्रवाई (ओं) को समाप्त कर दिया, साथ ही, कार्यपालिका निर्णय (ओं)

34. विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह भी कहा कि

संविधान (99 वां संशोधन) अधिनियम, पूरी तरह से अधिकार के बाहर था, क्योंकि इसने "मूल संरचना/विशेषता" का गंभीर रूप से उल्लंघन किया

संविधान अर्थात् "न्यायपालिका की स्वतंत्रता"। यह था।

प्रस्तुत किया कि उपरोक्त संवैधानिक [2015] 13 एस. सी. आर. की सत्यता।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संशोधन की, अनुच्छेद 50 के आलोक में जांच की जानी थी।

विद्वान वकील के अनुसार, प्रक्रिया का राजनीतिकरण

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों का चयन और नियुक्ति,

इससे "न्यायपालिका की स्वतंत्रता" कमजोर हो जाएगी। यह प्रस्तुत किया गया था कि केंद्रीय मंत्री को इसमें शामिल किया जाए।

विधि और न्याय का प्रभार, पदेन सदस्य के रूप में एन. जे. ए. सी. ने प्रक्रिया के राजनीतिकरण का प्रभाव डाला

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति। यह इंगित किया गया था

बाहर, कि कानून के प्रभारी केंद्रीय मंत्री को शामिल करना और एन. जे. ए. सी. के ढांचे के भीतर न्याय का अर्थ था

चयन में उस समय की सरकार का परिचय
समावेश,

प्रक्रिया। यह दावा किया गया कि केंद्रीय मंत्री का

इसका अर्थ था नियुक्ति की शक्ति का छठा हिस्सा समर्पण करना,
सरकार ने। यह प्रस्तुत किया गया था कि समझने के लिए
केंद्रीय मंत्री को शामिल करने का वास्तविक प्रभाव
न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया
न्यायपालिका, एक को ध्यान में रखना था कि भारी मात्रा में
संरक्षण, जिसे केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री
ले जाता है, और इस तरह, यह के अनुमान के भीतर होगा
कानून और न्याय के प्रभारी केंद्रीय मंत्री,
समर्थन करने के लिए संरक्षण की अपनी शक्ति का विस्तार करके, प्रक्रिया दोषपूर्ण है
या उन उम्मीदवारों का विरोध करें, जो उपयुक्त या अनुपयुक्त हो सकते हैं
दिन की सरकार। भले ही केंद्रीय मंत्री

केवल एक वोट सौंपा गया था, यह प्रस्तुत किया गया था, कि वह
प्रणाली को पंगु बना सकता है

प्राधिकरण के आधार पर पूरी

उन्होंने व्यायाम किया। उसके विवाद को घर पहुँचाने के लिए, विद्वान वकील
के परिचय का संदर्भ दिया

"चॉइजिंग" पुस्तक

हम्मुराबी-न्यायिक नियुक्तियों पर बहस ", द्वारा संपादित

संतोष पॉल। पुस्तक के परिचय में, के विचार

एच. एल. मेनकेन को निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया गया है:

"लेकिन जब राजनेता इस तरह से बात करते हैं, या बिना बोले इस तरह से काम करते हैं,

यह उन्हें ध्यान से देखने का सही समय है। उनके

सामान्य योजना संविधान पर चुपके से आक्रमण करना है, और फिर

इंतजार करें कि क्या होता है। अगर कुछ नहीं होता है तो वे चलते रहते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय

अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

अधिक साहसपूर्वक; यदि कोई विरोध होता है तो वे गर्मजोशी से जवाब देते हैं कि संविधान जीर्ण-शीर्ण और बेतुका है, और यह प्रगति है मृत हाथ के नीचे असंभव। यह देखने का समय है विशेष रूप से उन्हें। वे किसी के लिए भी अच्छे नहीं हैं स्वयं। वे आम लोगों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं हम में से बाकी के अधिकार। उनका एकमात्र उद्देश्य, अब और हमेशा, उनके हाथों में अधिक शक्ति प्राप्त करना है कि यह हो सकता है उनके लाभ के लिए स्वतंत्र रूप से उपयोग किया जाए, और नुकसान के लिए जब वे सुधार की बात करते हैं तो उनसे सबसे अधिक सावधान रहें और संविधान में सुधार "।

35. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि

छह सदस्यीय एन. जे. ए. सी. में दो "प्रतिष्ठित व्यक्तियों" को शामिल करना। संविधान (99 वें) के अनुच्छेद 124 ए (1) के तहत प्रावधान के अनुसार संशोधन) अधिनियम भी स्पष्ट रूप से असंवैधानिक था। यह था। तर्क दिया, कि वहाँ आवश्यक रूप से होना था, एक संकेत के पास होने के लिए आवश्यक सकारात्मक योग्यताएँ दो "प्रतिष्ठित व्यक्तियों" को एन. जे. ए. सी. के लिए नामित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अयोग्यता निर्धारित करना आवश्यक था। सचित्र रूप से, यह बताया गया था कि एक व्यक्ति के पास एक हितों के टकराव को अयोग्य ठहराया जाना चाहिए। और इस तरह के संघर्ष यह स्पष्ट होगा, जब व्यक्ति की राजनीतिक भूमिका थी। ए. राजनेता को अपने निर्वाचन क्षेत्र की सेवा करनी होती है, उसे पोषण करना होता है और बैंक को बनाए रखें, और सबसे बढ़कर, उन्हें इसके अनुरूप होना होगा अपने वोट उनके राजनीतिक दल का एजेंडा। इसी तरह, एक व्यक्ति के साथ चालू मुकदमेबाजी, इस तरह के मुकदमे की प्रकृति की परवाह किए बिना, स्वयं को एक "प्रतिष्ठित" के रूप में सेवा करने के लिए अयोग्य बना देगा व्यक्ति "एन. जे. ए. सी. के ढांचे के भीतर, क्योंकि उसके

हितों का टकराव।

36. दो प्रतिष्ठित लोगों को शामिल करने के संदर्भ में

एन. जे. ए. सी. में श्री अरविंद पी. दातार, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अनुच्छेद 124 ए की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, जिसके तहत,

उपरोक्त दो "प्रतिष्ठित व्यक्तियों" को नामित किया जाना है -

प्रधान मंत्री, मुख्य न्यायाधीश की सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट वाली समिति

[2015] 13 एस सी आर।

भारत सरकार और लोक सभा में विपक्ष के नेता,

या, जहां विपक्ष का ऐसा कोई नेता नहीं है, तो नेता

लोक सभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी।

विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि न तो अनुच्छेद 124 ए, और न ही कोई अन्य प्रावधान, और एन. जे. ए. सी. अधिनियम के प्रावधान भी नहीं,

दो "प्रतिष्ठित व्यक्तियों" की योग्यताओं को इंगित करें, जो छह-सदस्य एन. जे. ए. सी. में शामिल किए गए हैं। यह था।

यह दावा करने की कोशिश की गई कि लगभग 70 कानूनों में और

नियम, अभिव्यक्ति "प्रतिष्ठित व्यक्ति" का उपयोग किया गया है।

70 विधानों में से, 67 में, वह क्षेत्र जिसमें ऐसे व्यक्ति

प्रतिष्ठित होना चाहिए, स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। केवल तीन में

कानून, "प्रतिष्ठित व्यक्ति" शब्द का उपयोग बिना किसी आगे के किया गया था योग्यता. यह दावा किया गया था कि "प्रतिष्ठित व्यक्ति" शब्द

अनुच्छेद 124 ए में इसे अस्पष्ट और अनिर्धारित छोड़ दिया गया था। यह था। प्रस्तुत किया कि "प्रतिष्ठित व्यक्ति" शब्द की अस्पष्टता

अपने आप में, हड़ताल को सही ठहराने के लिए काफी अच्छा था

प्रावधान। इस बात पर जोर दिया गया कि निर्धारक भूमिका

दो "प्रतिष्ठित व्यक्तियों" को सौंपा गया, जिनमें शामिल हैं छह-सदस्य एन. जे. ए. सी., इतना महत्वपूर्ण था कि वे ऐसा नहीं कर सकते थे

नामित समिति की कल्पना पर छोड़ दिया जाए, जो

इसमें न्यायप्रिय पुरुष शामिल हैं "। सभी विफलताओं, सभी भावनाओं के साथ।

और सभी पूर्वाग्रह जो आम लोगों के रूप में हमारे पास हैं। (डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के शब्दों पर भरोसा करते हुए)।

37. धारा 5 (2) के तहत दूसरे परंतुक का उल्लेख करते हुए, साथ ही, एन. जे. ए. सी. अधिनियम की धारा 6 (6), यह प्रस्तुत की गई थी, कि एक न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए एक सिफारिश, नहीं कर सका यदि दो "प्रतिष्ठित व्यक्तियों" ने स्वीकार नहीं किया तो किया जाए एक ही। यदि वे दूसरे से असहमत होना चुनते हैं

एन. जे. ए. सी. के सदस्य, प्रस्तावित सिफारिश कर सकते हैं

प्रभाव नहीं दिया जाएगा, भले ही अन्य चार सदस्य

सुप्रीम कोर्ट के तीनों प्रतिनिधियों सहित एन. जे. ए. सी.

अदालत ने भी इसे मंजूरी दे दी। यह बताया गया था कि दोनों

"इसलिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों की निर्णायक राय होगी। यह था। न्यायालय के अधिवक्ताओं के निर्धारण का प्रभाव-चालू-रिकॉर्ड

आगे प्रस्तुत किया कि सर्वोच्च

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

दो "प्रतिष्ठित व्यक्ति" ऐसे होंगे, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित होने से पहले की प्रधानता को नकारेंगे। यह.

इंगित किया गया था कि प्रमुख द्वारा एक सकारात्मक सिफारिश

उच्चतम न्यायालय के दो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों (भारत के मुख्य न्यायाधीश के बगल में) द्वारा समर्थित भारत के न्यायाधीश, हो सकते हैं

दोनों प्रतिष्ठित लोगों के हाथों विरोध से निराश

व्यक्तियों "। उपरोक्त निहित वीटो शक्ति, के अनुसार

विद्वान परामर्श, संरचित सौदेबाजी का कारण बन सकता है, ताकि

एन. जे. ए. सी. के अन्य सदस्यों को शामिल होने के लिए राजी करना

अवांछनीय नामांकित व्यक्तियों के नाम (केवल गतिरोध से बचने के लिए)

प्रकार)। यह प्रस्तुत किया गया था कि इस तरह की रचना पर इस न्यायालय द्वारा भारत संघ बनाम में प्रतिकूल टिप्पणी की गई थी।

आर. गांधी 38. निर्णय में, प्रावधान, जो विषय था विचार का विषय धारा 10-एफएक्स थी।
उपरोक्त के तहत

प्रावधान, नियुक्ति के लिए चयन समिति

अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य, और न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को शामिल किया जाना था

भारत के मुख्य न्यायाधीश (या उनके नामित), चार के अलावा

केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के सचिव। इस न्यायालय ने अपने निष्कर्षों को दर्ज किया

पैराग्राफ 120 (viii) में उपरोक्त प्रावधान, जो किया जा रहा है

यहाँ नीचे निकाला गया है:

" 120 (viii) पाँच सदस्यीय चयन समिति के बजाय
भारत के मुख्य न्यायाधीश (या उनके नामित) के साथ

मंत्रालय के अध्यक्ष और दो सचिव

वित्त और कंपनी मामलों के सचिव

श्रम मंत्रालय और विधि मंत्रालय में सचिव

और धारा 10-एफएक्स में उल्लिखित सदस्यों के रूप में न्याय,
चयन समिति को मोटे तौर पर निम्नलिखित पर होना चाहिए:

पंक्तियाँ:

(क) भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके मनोनीत-अध्यक्ष

(एक निर्णायक वोट के साथ);

(ख) उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश

उच्च न्यायालय के-सदस्य;

38 (2010) 11 एससीसी 1 [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(ग) वित्त और कंपनी मामलों के मंत्रालय में सचिव

-सदस्य; और

(घ) विधि और न्याय मंत्रालय में सचिव-सदस्य।

यह प्रस्तुत किया गया था कि उद्देश्य को प्राप्त करने की मांग की गई थी, विशिष्टता नहीं थी, बल्कि प्रधानता थी। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि यदि चयन के लिए प्रधानता को महत्वपूर्ण माना जाता था न्यायाधिकरण में नियुक्त किए जाने वाले सदस्य, प्रधानता ने माना कि कहीं अधिक महत्व तब है जब यह मुद्दा विचाराधीन है उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण था।

तदनुसार यह तर्क दिया गया था कि जिस तरीके से

एन. जे. ए. सी. की संरचना अनुच्छेद 124 ए में तैयार की गई थी।
सी. को संदर्भ के साथ कार्य करना है

और जिस तरीके से एन. जे. ए.

एन. जे. ए. सी. अधिनियम के प्रावधानों के लिए, किसी भी संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी, कि यह इस द्वारा निर्धारित कानून का स्पष्ट उल्लंघन था

न्यायालय, और इसलिए, अलग रखे जाने योग्य है।

38. उपरोक्त तथ्यों पर विद्वान वकील ने विरोध नहीं किया

केवल अनुच्छेद के खंड (ग) और (घ) की संवैधानिक वैधता

124 ए (1), लेकिन इसके तहत पहले परंतुक पर भी जोरदार हमला किया

अनुच्छेद 124 ए (1) (डी), जो यह अभिनिर्धारित करता है कि

व्यक्तियों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति से संबंधित होना चाहिए

जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक या महिलाएँ। यह था।

प्रस्तुत किया, कि इस तरह के लोकलुभावन उपायों को नहीं करना चाहिए

एक महत्वपूर्ण मामले की जांच करते समय विचार किया जाए
किया गया था कि यह नहीं था

उच्च न्यायपालिका। यह प्रस्तुत

समझने योग्य है कि किसी व्यक्ति को शामिल करने का विकल्प क्या है

उपरोक्त श्रेणियों में से एक का उद्देश्य था। राय में

विद्वान वकील का, उपरोक्त परंतुक प्रहसन था, और

इसलिए, पूरी तरह से अस्वीकार्य है। जबकि एक विशेष के सदस्य
 समुदाय उनके हितों की रक्षा के लिए प्रासंगिक हो सकता है
 समुदाय, फिर भी इसकी कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसा उपाय क्यों
 संवैधानिक के लिए अपनाया जाना चाहिए इस तरह के एक महत्वपूर्ण
 जिम्मेदारी। विद्वान वकील की राय में, समावेशन
 एन. जे. ए. सी. में ऐसे सदस्य का नेतृत्व करने के लिए बाध्य था समझौता करते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय

अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

39. श्री अरविंद पी. दातार का यह भी तर्क था कि संविधान (99 वां संशोधन) द्वारा अनुच्छेद 124 सी को लागू किया गया था।

अधिनियम, पूरी तरह से अनावश्यक था। यह इंगित किया गया था कि

अनुच्छेद 124 सी की अनुपस्थिति में, एनजेएसी में अंतर्निहित होता अपने स्वयं के कार्य को विनियमित करने की शक्ति। यह प्रस्तुत किया गया था कि

अनुच्छेद 124 सी उपरोक्त अंतर्निहित में एक गंभीर घुसपैठ थी।

शक्ति। अब जब, संसद को अधिकृत किया गया था

कानून बनाकर नियुक्तियों की प्रक्रिया को विनियमित करता है, यह

नियुक्ति पर नियंत्रण के हस्तांतरण में भी परिणाम होगा

प्रक्रिया (उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की), संसद को।

यह प्रस्तुत किया गया था कि कोई विधायी नियंत्रण नहीं हो सकता है,

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में।

विद्वान वकील के अनुसार, इस तरह के विधायी नियंत्रण

"न्यायपालिका की स्वतंत्रता" का उल्लंघन। यह प्रस्तुत किया गया था कि

संसद ने उस ओर से अपने अधिकार का प्रयोग किया है,

एन. जे. ए. सी. अधिनियम तैयार करना और उसमें अंतिम प्रावधान करना

संसद के साथ नियंत्रण, यह माना जाना चाहिए कि पार किया गया है

रेखा, और निषिद्ध क्षेत्र में अतिक्रमण, विशेष रूप से

न्यायपालिका के लिए आरक्षित। सीखी हुई सलाह। दावा किया कि
में निहित कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ,

किसी संवैधानिक प्राधिकारी

केवल संविधान द्वारा सीमित किया जा सकता है, और द्वारा नहीं

विधान के माध्यम से संसद। यह प्रस्तुत किया गया था कि

अनुच्छेद 124 ए से बाहर। इसी तरह, संसद भी एक थी
गया था कि एक इकाई

संविधान की रचना। यह प्रस्तुत किया

जो संविधान का निर्माण था, विनियमित नहीं कर सका

दूसरा, संविधान के अस्तित्व के कारण।

40. यह श्री राम जेठमलानी द्वारा इंगित किया गया था

वरिष्ठ अधिवक्ता, कि "उद्देश्यों और कारणों" का कथन,

जैसा कि तत्काल विधान के लिए प्रस्तावित किया गया था, अंतर इंगित किया गया
से, कि एन. जे. ए. सी. "एक सार्थक भूमिका प्रदान करेगा

अन्य रूप

न्यायपालिका "। यह प्रस्तुत किया गया था कि इसका क्या अर्थ था

उपरोक्त पुष्टि, उन्हें समझ में नहीं आ रही थी। यह था।
इसने "ऑब्जेक्ट्स एंड नो" में भी जोर दिया

आगे इस बात पर प्रकाश डाला गया कि

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

कारण ", कि" कार्यपालिका और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को

अपने विचार प्रस्तुत करें और प्रतिभागियों को शामिल करें
समझ से बाहर था। यह था।

जवाबदेह ", उनके लिए भी इसी तरह

प्रस्तुत किया कि संविधान का अवलोकन (99 वां संशोधन)

अधिनियम (साथ ही, एन. जे. ए. सी. अधिनियम) यह नहीं बताएगा कि सदस्य कैसे

एन. जे. ए. सी. को जिम्मेदार बनाया जाना था। यह आगे था
का बयान भी

प्रस्तुत किया कि "उद्देश्यों और कारणों"

इंगित करें कि उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति का तरीका

न्यायपालिका, चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाएगी। यह तर्क दिया गया था कि अधिनियमों के तहत संदर्भ, संसद द्वारा धोखाधड़ी करने के बराबर, देश के लोगों के लिए। क्योंकि यह संभव नहीं था समझें, कैसे और किसे जवाबदेह बनाया जाना था - कार्यपालिका, - "प्रतिष्ठित व्यक्ति", - स्वयं न्यायपालिका। यह था। तदनुसार यह दावा करने की मांग की गई कि संसद ऐसा प्रतीत होती है एक बात पर जोर देना, जबकि वह कुछ और कर रहा था। विद्वान वकील ने श्रेया सिंघल बनाम पर भी भरोसा रखा।

भारत संघ 39, जहाँ से निम्नलिखित टिप्पणियाँ थीं

हमारे ध्यान में लाया गया:

"50. याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि भाषा

धारा 66 ए में उपयोग किया गया इतना अस्पष्ट है कि न तो

अपराध जो किया गया है और न ही किया जाएगा धारा का प्रशासन करने वाले अधिकारी इस बारे में स्पष्ट हों कि

स्पष्ट रूप से खींची गई रेखा का कौन सा पक्ष एक विशेष

संचार कम हो जाएगा। "

उपरोक्त प्रस्तुतियों के आधार पर, यह दावा किया गया था कि

"उद्देश्यों और कारणों" का कथन अधिक अस्पष्ट, अस्पष्ट और काल्पनिक नहीं हो सकता था।

हाथ में बात।

41. श्री अनिल बी. दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता, पेश होते हुए

बार एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका में याचिकाकर्ता के लिए

भारत (2015 की रिट याचिका (सी) No.108), सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण

39 2015 (4) स्केल 1 शीर्ष अदालत के वकील-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. (जगदीश सिंह खेहर, जे।)

इंगित किया कि बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व करता है उच्च न्यायालय बार
एसोसिएशन, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)

अवध बार एसोसिएशन, लखनऊ (उत्तर प्रदेश), मद्रास

बार एसोसिएशन, चेन्नई (तमिलनाडु), सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, नई दिल्ली, गुजरात उच्च
न्यायालय के अधिवक्ता '

एसोसिएशन, गांधीनगर (गुजरात), अधिवक्ता ' एसोसिएशन, चेन्नई (तमिलनाडु), आंध्र प्रदेश हाई
अदालत अधिवक्ता संघ, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश),

दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, नई दिल्ली, बार

एसोसिएशन मुंबई (महाराष्ट्र), गुवाहाटी उच्च न्यायालय

बार एसोसिएशन, गुवाहाटी (असम), पंजाब और हरियाणा

उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, चंडीगढ़ (पंजाब और हरियाणा),

बॉम्बे निगमित विधि सोसायटी, मुंबई (महाराष्ट्र), मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन,
जबलपुर

(मध्य प्रदेश), अधिवक्ता संघ बैंगलोर

(कर्नाटक), केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क (सोना) नियंत्रण बार

एसोसिएशन, नई दिल्ली, एडवोकेट्स एसोसिएशन, इलाहाबाद

(उत्तर प्रदेश), कर्नाटक अधिवक्ता संघ,

बैंगलोर (कर्नाटक), इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार

एसोसिएशन (उत्तर प्रदेश), गोवा उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, पणजी (गोवा), सोसाइटी ऑफ
इंडिया लॉ ऑफ फर्म्स,

एसोसिएशन, पणजी (गोवा), सोसाइटी ऑफ

नई दिल्ली, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, बिलासपुर (छत्तीसगढ़), नागपुर उच्च
न्यायालय बार

बिलासपुर (छत्तीसगढ़), नागपुर उच्च

एसोसिएशन, नागपुर (महाराष्ट्र), की मदुरै पीठ

मद्रास उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, मदुरै (तमिलनाडु),

झारखंड उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, रांची (झारखंड),

बार एसोसिएशन ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन, नई दिल्ली,

और गुलबर्गा उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, गुलबर्गा

(कर्नाटक)। यह प्रस्तुत किया गया था कि उपरोक्त सभी बार

संघ अपनी चुनौती में सर्वसम्मत थे,
 संविधान (99 वां संशोधन) अधिनियम और एन. जे. ए. सी. अधिनियम। यह था।
 प्रस्तुत किया कि पूर्व को चुनौती इस तथ्य पर आधारित थी कि यह संविधान की "मूल संरचना" का उल्लंघन करता है, और
 उत्तराद्ध के लिए चुनौती, इसके अल्ट्रा वायर्स होने पर आधारित थी संविधान के प्रावधान।

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

42. विद्वान वकील ने एक रुख अपनाया था, जो था
 दूसरों द्वारा अपनाए गए से अलग। प्रस्तुतियाँ
 विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा उन्नत, पर आधारित थे
 तथ्य यह है कि न्यायिक समीक्षा की संवैधानिक शक्ति के तहत, उच्च न्यायपालिका ने न केवल मौलिक
 अधिकारों को लागू किया, बल्कि
 विधायिका और कार्यपालिका को भी प्रतिबंधित कर दिया,
 उनके अधिकार क्षेत्र (ओं) की सीमाएँ। यह बताया गया था कि यह
 उपरोक्त शक्ति, जो तनाव और घर्षण का स्रोत थी
 एक ओर न्यायपालिका और दूसरी ओर दो स्तंभों के बीच
 अन्य। यह घर्षण, यह बताया गया था, इसके कारण हुआ था तथ्य यह है कि न्यायिक की अपनी
 जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए
 समीक्षा, विधायिका के कार्यकारी समर्थित कार्य, थे
 के अन्य दो स्तंभों को प्रभावित और हावी कर रहा था शासन। सचित्र रूप से, यह बताया गया था
 कि
 देश के स्वतंत्र शासन की शुरुआत, न्यायिक
 समीक्षा के कारण संबंधित कानूनों को अलग कर दिया गया भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन।
 इस वजह से
 नौवीं अनुसूची में शामिल किए गए विधानों को अपनाना
 संविधान, ताकि उन्हें न्यायिक दायरे से बाहर रखा जा सके

समीक्षा करें।

43. यह प्रस्तुत किया गया था कि एक की पहली अभिव्यक्ति न्यायपालिका और न्यायपालिका की अन्य दो शाखाओं के बीच टकराव शासन, में दर्ज टिप्पणियों में संकेत दिया गया था मद्रास राज्य बनाम। वी. जी. रो, जिसमें 1952 में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उसके निष्कर्ष थे अभिलिखित, विधायी प्राधिकरण पर झुकाव की किसी भी इच्छा से नहीं एक योद्धा की भावना में, लेकिन स्पष्ट रूप से निर्धारित कर्तव्य के निर्वहन में संविधान द्वारा। न्यायालयों पर,

44. यह प्रस्तुत किया गया था कि इसमें रखे गए विधान संविधान की नौवीं अनुसूची, मूल 13 मदों में से (भूमि सुधारों और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित), गुणा

40 (1952) एस. सी. आर. 597 सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।] एक तेज दर पर, और वर्तमान में इसकी संख्या लगभग 284 है। और कई उनमें से, भूमि सुधारों से शायद ही कुछ लेना-देना था। यह था। आई. सी. गोलक नाथ मामले 41 में अभिनिर्धारित किया जाए, कि संसद वैसे संवैधानिक संशोधन (ओं) को हटाया या कम नहीं किया जा सका मौलिक अधिकार।

45. तनाव से संबंधित अपने विवाद को पेश करने के लिए और न्यायपालिका और न्यायपालिका की अन्य दो शाखाओं के बीच टकराव शासन, यह प्रस्तुत किया गया था कि 1950 से 1973 तक, वहाँ वस्तुतः राजनीतिक-कार्यपालिका द्वारा इसे कमजोर करने का कोई प्रयास नहीं था या न्यायपालिका पर प्रभाव डालना या हावी होना। यह बताया गया था,

कि उपरोक्त अवधि के दौरान, जब जवाहरलाल नेहरू (27 मई, 1964 तक), गुलजारी लाल नंदा (9 जून, 1964 तक), लाल

बहादुर शास्त्री (11 जनवरी, 1966 तक), गुलजारी लाल नंदा (24 जनवरी, 1966 तक) और
इंदिरा गांधी (1972 तक)

भारत में कार्यकारी और राजनीतिक शासन चलाना, उनके

प्रधानमंत्री के रूप में क्षमता, कोई कदम नहीं उठाया था

न्यायपालिका पर हावी होना। इसके बाद, दो तथ्य नहीं हो सके

राजनीतिक-कार्यकारी नेतृत्व द्वारा पचाया गया। सबसे पहले,

एक कार्यकारी आदेश द्वारा प्रिवी पर्स का उन्मूलन, जो था

माधवराव सिंधिया मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित

बहादुर बनाम। भारत संघ 42. और दूसरा, मौलिक अधिकार मामला, अर्थात् केशवानंद भारती
मामला 10 10, जिसमें

सर्वोच्च न्यायालय 7 के बहुमत से: 6, प्रस्तावित किया था कि

संविधान की "बुनियादी संरचना" का सिद्धांत, जो सीमित था

अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संशोधन शक्ति। के रूप में

उपरोक्त निर्णयों की अगली कड़ी में, कार्यपालिका ने प्रयास किया कि

न्यायपालिका को डराना, सर्वोच्च न्यायालय में पहले अधिनिर्णय द्वारा

25.4.1973 पर अदालत। इसके बाद, आंतरिक आपातकाल था

41 ए. आई. आर 1967 एस. सी. 1643

42 (1971) 1 एस. सी. सी. 85 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

25.06.1975 पर घोषित किया गया, जो 21.03.1977 तक जारी रहा। यह था।

प्रस्तुत किया, कि आपातकाल के दौरान, संवैधानिक के माध्यम से

संशोधन (ओं), न्यायिक समीक्षा की शक्ति उच्चतर में निहित है

न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश की गई थी। यह प्रस्तुत किया गया था कि

आपातकाल के दौरान घुसपैठ को ठीक किया गया जब

जनता पार्टी 22.03.1977 पर सत्ता में आई,
43 पहला और 44 वां संविधान संशोधन, जो बहाल किया गया
द्वारा प्रदान की गई मूल स्थिति के लिए न्यायिक समीक्षा
संविधान सभा।

46. यह प्रस्तुत किया गया था कि हाल ही में भी,
न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग असुविधाजनक रहा था
राजनीतिक-कार्यपालिका के लिए, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप एक शृंखला उजागर हुई
घोटालों से। इस संबंध में दो निर्णयों का उल्लेख किया गया था।

इस न्यायालय, अर्थात्, जनहित याचिका केंद्र द्वारा प्रस्तुत
वी. भारत संघ 43, और मनोहर लाल शर्मा बनाम। प्रधानाचार्य
सचिव 44. यह प्रस्तुत किया गया था कि कार्यपालिका और
विधायिका कभी इस बात की सराहना नहीं कर सकती कि न्यायपालिका की शक्ति

समीक्षा का प्रयोग उच्च न्यायपालिका द्वारा एक मामले के रूप में किया गया है जनता का
विश्वास। उपरोक्त दो निर्णयों की अगली कड़ी के रूप में, यह था

बताया कि लगभग दो लाख रुपये की राशि करोड़ (रु। 20,00,00,00,00,000 / -) जनता ने
हासिल किया

में प्रकाशित एक लेख पर निर्भरता रखी गई थी इंडियन एक्सप्रेस दिनांक 10.3.2015)। और एक
अतिरिक्त राशि

एक लाख दस हजार करोड़ रुपये का (Rs.11,00,00,00,00,000/-) सरकारी खजाने द्वारा प्राप्त
किया गया था।

स्पेक्ट्रम नीलामी से (जिसके लिए निर्भरता रखी गई थी)

फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक लेख दिनांक 25.03.2015)। यह था।

प्रस्तुत किया, कि राजनीतिक द्वारा सामना की जाने वाली शर्मिंदगी

कार्यकारी, के लिए स्मारकीय लाभ को छुआ दिया है

राष्ट्र। यह तर्क दिया गया था कि संविधान (99 वां)

संशोधन) अधिनियम, और एन. जे. ए. सी. अधिनियम, सच में एक राजनीतिक थे।

43 43 (2012) 3 एससीसी 1

44 (2014) 2 एस. सी. सी. 532 सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

कार्यकारी उपकरण, न्यायिक समीक्षा की शक्ति पर लगाम लगाने के लिए, बचने के लिए इस तरह की निराशा।

47. यह भी तर्क दिया गया था कि निर्णय लेते समय

वर्तमान विवाद, इस न्यायालय के लिए यह लेना अनिवार्य था

मौजूदा सामाजिक-राजनीतिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए,

नागरिक समाज की जागरूकता से संबंधित जमीनी वास्तविकताएं,

और आसपास की प्रासंगिक परिस्थितियाँ। ये विद्वान वकील के अनुसार, घटकों का वर्णन किया गया था

प्रासंगिक विचारों के रूप में, एक सार्थक न्यायिक निर्णय के लिए

वी. जी. रो केस 40। शशांक लक्ष्मण काले बनाम का उल्लेख करते हुए।

भारत संघ 45, यह तर्क दिया गया था कि

प्रयोजन या विधान का उद्देश्य, इसके लिए अनुमेय था उन परिस्थितियों को देखने के लिए एक न्यायालय जो प्रचलित थी

वह समय जब कानून पारित किया गया था, और घटनाएँ जो थीं

कानून को पारित करने की आवश्यकता थी। इसका उल्लेख करते हुए

इस न्यायालय द्वारा पुनः दिया गया निर्णय: विशेष न्यायालय

बिल, 197846, विद्वान वकील ने इस पर जोरदार निर्भरता रखी

निम्नलिखित:

" 106. हमारे समय का सबसे बड़ा आघात, एक विकासशील के लिए

तत्काल लेकिन उत्तेजक अनिवार्यताओं का देश है

निराशाजनक, फिर भी मर जाता है-जनता की गरीबी और लोकतांत्रिक, फिर भी भ्रष्टाचार-ग्रस्त, सत्ता-धारकों का जीवन-शैली।

वे एक साथ मिलकर घोर दुर्व्यवहार पैदा करते हैं

व्यक्तिगत उन्नति, एक्सपोजर का दमन और

अन्य भयानक, फिर भी छिपे हुए, अपराधों का एक मेजबान
 शिखर सम्मेलन के अधिकारी, अस्थायी, परा-राजनीतिक
 जोड़-तोड़ करने वाले और नौकरशाहों को उकसाने वाले। और नियम
 कानून लंगड़ा या भौंकता है लेकिन कभी काटता नहीं है। अ.

अनाम कवि ने सामाजिक रूप से प्रस्तुत किया
 इस प्रणालीगत कमी का आयाम:

कानून पुरुष और महिला दोनों को बंद कर देता है।
 जो आम से हंस चुराता है,

?

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लेकिन बड़े अपराधी को छोड़ दें जो हंस से आम चोरी करता है।

107. तीसरी दुनिया में 'शिखर' अपराधों का प्रभाव

भ्रष्टाचार और दमन-ऐसी स्थितियों में चचेरे भाई विकासात्मक प्रक्रियाओं का अपहरण करें। और,
 लंबे समय में,

राष्ट्रीय प्रगति में कमी का मतलब है लोगों की प्रगति में कमी लाना।
 सामाजिक न्याय के लिए संवैधानिक साधनों में विश्वास। और
 तो, पता लगाने के लिए और इन भारी सामानों को छोटा करने के लिए
 वज़न वाले अपराधी जो अक्सर लोगों को गुमराह करते हैं
 सार्वजनिक नैतिक भारोत्तोलन और बहुआयामी घोषणापत्र
 एक तत्काल विधायी मिशन है जो आंशिक रूप से किया जाता है
 विधेयक चर्चा में है। ऐसे अति-अपराधियों को दंडित करना
 शीर्ष पदों पर, कानूनी भागने के मार्गों को बंद करना और
 विलम्बकारी रणनीतियाँ और उन्हें उच्च स्तर के साथ न्याय के दायरे में लाना
 गति और प्रारंभिक अंतिमता, एक इच्छा है जो व्यर्थ में आवाज उठाती है
 समितियों द्वारा

अतीत में आयोगों और

कानून के शासन की गतिशीलता का आयाम। यह विधेयक,
 उम्मीद है लेकिन आंशिक रूप से, इसके विपरीत नई जमीन तोड़ता है
 लोगों का इस्तीफा देने वाला सनकीपन कि सभी उच्च शक्ति वाले हैं
 जांच, रिपोर्ट और सिफारिशें समाप्त होती हैं
 विधायी और न्यायिक निरर्थकता, कि ये सभी बहादुर
 व्यायाम केवल ध्वनि और क्रोध हैं जो कुछ भी नहीं दर्शाते हैं, कि 'हमेशा की तरह व्यवसाय
 जनता की हस्ताक्षर धुन है
 व्यापार, यहाँ से पहले, यहाँ से और यहाँ से आगे। तो यह सामाजिक
 न्याय के उपाय को नैतिक सिद्धांत में मेरी व्यापक सहमति है।
 और संवैधानिक वर्गीकरण में, गंभीर के अधीन
 दुर्बलताएँ जिनसे यह विद्वान प्रमुख के रूप में पीड़ित है
 न्याय का संक्षिप्त चित्रण किया गया है। क्या यह उपाय होगा
 आपराधिक शिखर सम्मेलन की बीमारी का प्रभावी ढंग से इलाज करना है
 भविष्य बताने के लिए।

108. यह सब एक पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करता है। मुझे पूरी तरह से प्रकट होने दें।

90) 4 एस. सी. सी. 366

"9) 1 एस. सी. सी. 380 सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

327

समाज v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

जाता है, अब तक बुरा है क्योंकि यह नहीं जाता है-हालांकि एक द्वारा बचाया गया है व्यावहारिक
 अपवाद में वर्तमान में समझाऊंगा। कहाँ का

प्रस्तावित कानून में आपातकाल से पहले और बाद के हालात शामिल नहीं हैं।

अपराध-उच्च कोष्ठक में करने वाले और केवल 'आपातकालीन' अपराधियों को चुनते हैं, इसका सौम्य उद्देश्य
 शायद बी

पहले और उससे पहले अपराधियों की तरह एक गुप्त आवरण बन जाता है

इसके बाद। बारहमासी को पूरा करने के लिए एक 'अल्पकालिक' उपाय

खतरा न तो एक तार्किक कदम है और न ही राष्ट्रीय पूर्ति।
अनुमान लगा सकता हूं, तो यह है

वर्गीकरण, यदि मैं अपने निष्कर्ष का

सी.

संवैधानिक टूटने के कगार पर-उस समय

और के हमले के लिए लगभग असुरक्षित हो जाता है

अनुच्छेद 14.

XXX

XXX

XXX

114. महत्वपूर्ण परीक्षा है 'सभी शक्ति एक विश्वास है'। इसके धारक

'इसके अभ्यास के लिए जवाबदेह' हैं, 'लोगों से।
अस्तित्व होना चाहिए। के द्वारा

और लोगों के लिए, सभी स्रोत, और सभी का

इस उच्च और एकमात्र मानक विधेयक को नैतिक रूप से विफल होना चाहिए यदि यह

गैर-आपातकालीन अपराधियों को छूट दी गई है जिनके बारे में पहले बताया गया था
की रिपोर्ट, अब आधिकारिक कबूतर में सो रहा है

आयोग

ई.

छेद, गवाह और भविष्य के आयोग की रिपोर्ट

(कौन जानता है?) समय पर गवाही दे सकते हैं। इस बड़े में

दृष्टिकोण। आपातकाल एक महत्वपूर्ण अंतर नहीं है और विधेयक इसे लगभग मान्यता देता है।
27 फरवरी, 1975 तक संचालन जब कोई एफ नहीं था

'आपातकाल'। अगर 'आपातकाल' था तो पहले की तारीख क्यों?

महत्वपूर्ण मानदंड?

XXXXXX

XXX

XXX

117. आइए हम 'आपातकाल' पर करीब से नज़र डालते हैं,

वर्गीकरण। कार्यवाही से आने वाली जानकारी
की रिपोर्ट से पता चलता है कि उस शांत कार्यकाल के दौरान, कई

और उच्चाधिकार प्राप्त न्यायिक आयोगों के एक समूह

एच सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

चौंकाने वाला इलाज झेलना पड़ा। के शब्दों में
प्रस्तावना, नागरिक स्वतंत्रता को काफी हद तक वापस ले लिया गया था,
लोगों के महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार थे निलंबित किया गया, प्रेस पर सख्त सेंसरशिप लगाई गई
और न्यायिक शक्तियों में काफी हद तक कटौती की गई।

XXX

XXX

XXX

128. आइए हम समस्या को थोड़ा अलग तरीके से देखें। यहां तक कि
अगर स्वतंत्रता में कटौती नहीं की गई थी, तो प्रेस को बंद नहीं किया गया था या
रिट अधिकार क्षेत्र में कटौती नहीं की गई, आपराधिक मुकदमे और अपील
और संशोधनों ने अपना अंतहीन समय ले लिया होगा विलम्ब। यह फोरेंसिक देरी है जिसे समाप्त
करना होगा और
इसका आपातकाल की बुराइयों से कोई लेना-देना नहीं है। इस तरह
न्यायिक आयोगों द्वारा पहले अपराधों का खुलासा किया गया था,
दोनों में मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री शामिल हैं स्तरों का पालन किया गया और अब के अलावा
कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की गई और
एक चयनित समूह का। यह इच्छाशक्ति की कमी थी-आपातकाल की नहीं।
कि गैर अभियोजन में टुकड़े का खलनायक था
कई आयोगों द्वारा प्रकट किए गए मामले जैसे
1967 में उड़ीसा के (श्री न्यायमूर्ति खन्ना), आयोग 1965 में जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा नियुक्त
जांच
(श्री न्यायमूर्ति राजगोपाला अय्यंगार), मुधोलकर संयुक्त मोर्चा के 14 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ
आयोग
1968 में बिहार सरकार द्वारा नियुक्त और टी. एल. वेंकटरामा अय्यर जांच आयोग

बिहार सरकार द्वारा नियुक्त, 1970-उल्लेख करने के लिए

लेकिन कुछ। हमें शायद ही यह कहने की आवश्यकता है कि कोई कानून नहीं है

आपराधिक अभियोजन के लिए सीमा। किसी तरह, कुछ कानून से ऊपर रहने का प्रबंधन करें और कई नीचे रहते हैं

कानून। कैसे? -1 बताने में संकोच करें "।

अंत में, इस निर्णय पर निर्भरता रखी गई थी

टिन सुब्रमण्यम स्वामी बनाम। निदेशक, केंद्रीय ब्यूरो

अभियोग 47, जिसमें इस न्यायालय ने व्यापक रूप से

14) 8 एस. सी. सी. 682 सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

भ्रष्टाचार से संबंधित स्थितियाँ जो देश में प्रचलित थीं।

उपरोक्त उद्देश्य के लिए, इसने इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखा एन. एन. वोहरा समिति की रिपोर्ट द्वारा व्यक्त,

आपराधिक सिंडिकेट्स और माफिया के बीच सांठगांठ।

48. रिलायंस को तब किए गए प्रयासों पर रखा गया था

भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश की मृत्यु पर कार्यपालिका

(संविधान की घोषणा के बाद), जब पतंजलि

शास्त्री, जे., जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश थे, की मांग की गई थी अनदेखी की गई। इस संबंध में अभिलिखित ग्रंथों पर निर्भर करते हुए,

ग्रैनविल ऑस्टिन, जॉर्ज एच. गैडबोइस जूनियर और एम. सी. चगला, यह

प्रस्तुत किया गया था कि सभी छह न्यायाधीशों, उस समय, था

सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश की अनदेखी करने पर इस्तीफा देने की धमकी दी भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए।

49. पहले अवसर का उल्लेख करते हुए, जब सम्मेलन

ए. एन. रे, जे. को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करके तोड़ दिया गया था

भारत, यह प्रस्तुत किया गया था कि अतिक्रमण ने जनता को प्रेरित किया
 पूर्व न्यायाधीशों के भाषणों सहित विरोध, पूर्व
 महान्यायवादी, कानूनी दिग्गज और बार के सदस्य,
 पूरे देश में। एम. हिदायतुल्ला, सीजे।, एक सार्वजनिक भाषण में,
 उन तीन न्यायाधीशों की सराहना की, जिन्हें हटा दिया गया था
 अपने पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद ए. एन. रे की भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में
 नियुक्ति। भाषण में
 एम. हिदायतुल्ला, सीजे द्वारा वितरित।, उन्होंने एक संदर्भ दिया कि
 अफवाहें चल रही हैं, कि उनके बाद सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश, अर्थात्, जे. सी. शाह, जे., प्रमुख के रूप में
 उनका स्थान नहीं लेंगे।
 भारत का न्याया। और कि, एक बाहरी व्यक्ति को लाया जा रहा था
 उच्चतम न्यायालय, इसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में। उनके भाषण पर प्रकाश डाला गया
 तथ्य यह है कि उच्चतम न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश को छोड़कर सभी
 जे. सी. शाह के हटने की स्थिति में इस्तीफा देने के लिए सहमत हो गए थे,
 जे. उन्होंने अपने भाषण में यह भी बताया था कि यदि निर्णय
 उनकी सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले भी कार्यपालक द्वारा लिया गया था,
 वह भी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। भारत के मुख्य
 न्यायाधीश के रूप में। तदनुसार यह प्रस्तुत किया गया था कि
 संवैधानिक परिपाटी, कि सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा
 भारत के, वास्तव में और ईमानदारी से एक अभेद्य के रूप में मान्यता प्राप्त थी सम्मेलन। उपरोक्त
 विवाद का समर्थन करने के लिए, यह भी था
 इंगित किया, कि उन स्थितियों में भी जहां सबसे वरिष्ठ
 कनिष्ठ न्यायाधीश का कार्यकाल बहुत कम होगा, सम्मेलन

ऐसा करने की अक्षमता के बावजूद, अटूट रहा था
 नियुक्तियाँ। इस संबंध में न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया गया।
 इस तथ्य के लिए कि जे. सी. शाह, सीजे। (35 दिनों का कार्यकाल था), के. एन.
 सिंह, सीजे। (उनका कार्यकाल 18 दिनों का था) और एस. राजेंद्र बाबू,
 सी. जे. (उनका कार्यकाल 29 दिनों का था)।

50. यह विद्वान वरिष्ठ का भी तर्क था

वकील, कि कार्यपालिका एक महत्वपूर्ण वादी है और
 उच्च न्यायपालिका के समक्ष हितधारक, और इस प्रकार, कार्यपालिका की इस मामले में कोई भूमिका
 नहीं होनी चाहिए कि

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति/स्थानांतरण। में।

इस ओर से, विद्वान वकील ने कई पर भरोसा रखा

इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, जिसमें

उच्च न्यायपालिका में कार्यपालिका को माना गया था

न्यायाधीशों की नियुक्तियों के मामले में असंवैधानिक और

न्यायाधिकरणों के अन्य सदस्य, जो अर्ध न्यायिक कार्यों में निहित हैं।

यह प्रस्तुत किया गया था कि केंद्रीय मंत्री को इसमें शामिल किया जाए

एन. जे. ए. सी. में कानून और न्याय का आरोप, एक स्पष्ट उल्लंघन था

इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय। इसके अलावा, यह था

इंगित किया कि दो "प्रतिष्ठित व्यक्ति", जिन्हें होना था

एन. जे. ए. सी. के आवश्यक घटकों का चयन एक

समिति, जिसमें प्रमुख आवाज की थी राजनीतिक नेतृत्व। यह इंगित किया गया था कि
 तीनों में

"प्रतिष्ठित व्यक्तियों" को नामित करने के लिए अधिकृत सदस्य समिति

इसमें प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता शामिल थे भारत के मुख्य न्यायाधीश के अलावा,
 लोकसभा में। यह था।

इसलिए प्रस्तुत किया कि छह-सदस्य एन. जे. ए. सी. में, तीन

विद्वान वकील के अनुसार, मामले में एक होगा विनाशकारी प्रभाव। यह उच्च सर्वोच्च
 न्यायालय की प्रधानता को नकार देगा

अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. (जगदीश सिंह खेहर, जे।)

न्यायपालिका, और उसी के परिणामस्वरूप कमजोर होगा

"न्यायपालिका की स्वतंत्रता"। उपरोक्त के आधार पर फाउंडेशन, विद्वान वरिष्ठ वकील ने कई मुद्दे उठाए

विवाद। सबसे पहले, यह प्रस्तुत किया गया था कि

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा भारत के न्याय का उल्लंघन किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि

उपरोक्त कन्वेंशन ने एक संवैधानिक स्थिति प्राप्त की थी

स्वयंसिद्ध-एक संवैधानिक सिद्धांत। उपरोक्त की पुष्टि करने के लिए

तर्क, यह प्रस्तुत किया गया था, कि 26.01.1950 से,

सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश ने हमेशा

दो को छोड़कर भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया मौकों पर। सबसे पहले, उपरोक्त समझौते का उल्लंघन किया गया था, जब

ए. एन. रे, जे. को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था

25.4.1973, तीन सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों को हटा कर। यह था। प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त अधिनिर्णय पर किया गया था

जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था

केशवानंद भारती मामला 0. दूसरा, सुपरसेशन

प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आंतरिक आपातकाल के दौरान हुआ था

मंत्री, इंदिरा गांधी। उस समय एम. एच. बेग, जे.

द्वारा 29.1.1977 पर भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त

उनके वरिष्ठ एच. आर. खन्ना, जे. का स्थान लेते हुए, यह तर्क दिया गया था,

कि उपरोक्त दो उदाहरणों पर विचार किया जाना चाहिए

नियुक्ति से संबंधित कन्वेंशन में विचलन

भारत के मुख्य न्यायाधीश।

51. श्री अरविंद पी. दातार ने भी संविधान पर हमला किया संविधान द्वारा प्रस्तुत अनुच्छेद 124 सी की वैधता (99 वां) संशोधन) अधिनियम। यह प्रस्तुत किया गया था कि संसद थी के लिए प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए प्राधिकरण के साथ प्रत्यायोजित भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय, और मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश उच्च न्यायालयों का "। और एन. जे. ए. सी. को रखने का अधिकार था नीचे, विनियमन द्वारा, "अपनी खुद की सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर. के निर्वहन की प्रक्रिया।

कार्य, नियुक्ति के लिए व्यक्तियों के चयन का तरीका, यह "। यह विद्वान वकील का तर्क था कि अनुच्छेद 124 सी के तहत विचार की गई शक्ति का प्रत्यायोजन, एन. जे. ए. सी. को वह सौंपने के बराबर था जो पहले निहित था। भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ। इस संबंध में, संदर्भ था एन. जे. ए. सी. अधिनियम की धारा 11, 12 और 13 को भी लागू किया गया है। द. नियम बनाने की शक्ति केंद्र के पास निहित है धारा 11 के तहत सरकार, और बनाने की शक्ति धारा के तहत विनियम एनजेएसी को सौंपे गए हैं 12. उपरोक्त नियम और विनियम, जैसा कि द्वारा तैयार किया गया है केंद्र सरकार/एन. जे. ए. सी. को स्थापित करने की आवश्यकता है। धारा 13 के तहत संसद के समक्ष, और उसके बाद ही, नियम और विनियम प्रभावी होने थे (या नहीं होने थे) कोई प्रभाव, या संशोधित रूप में प्रभाव डालना)। यह प्रस्तुत किया गया था, कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को सौंपना उच्च न्यायपालिका को, और यह भी, नियुक्त करने की कार्यवाही

जिस तरह से एन. जे. ए. सी. अपने कार्यों का निर्वहन करेगा
 उच्च न्यायपालिका के लिए न्यायाधीशों का चयन), या तो
 कार्यपालिका या विधायिका के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था, अगर "स्वतंत्रता"
 न्यायपालिका को बनाए रखा जाना था। यह बताया गया था कि
 अनुच्छेद 124 सी के पीछे का इरादा, जिस तरह से यह किया गया था
 के उपरोक्त प्रावधानों द्वारा स्पष्ट रूप से उजागर किया गया था
 एनजेएसी अधिनियम।

52. एनजेएसी की धारा 12 का भी उल्लेख किया गया था।

अधिनियम, यह उजागर करने के लिए कि एन. जे. ए. सी. को अधिसूचित करने के लिए अधिकृत किया गया था
 आधिकारिक राजपत्र में, इसके द्वारा बनाए गए विनियमों के साथ अधिस्थापक शर्त, कि इस
 प्रकार बनाए गए विनियम
 एन. जे. ए. सी. को एन. जे. ए. सी. के प्रावधानों के अनुरूप होना था
 अधिनियम के साथ-साथ उसके तहत बनाए गए नियम (यानी धारा 11 के तहत)
 एनजेएसी अधिनियम)। एन. जे. ए. सी. को इस तरह से सशक्त बनाना (के तहत)
 ऊपर उल्लिखित धारा 11 और 12), और चित्रित किया गया है धारा 12 (2) में, किसके
 संदर्भ में व्यापक रूपरेखा दी गई है
 विनियमों को तैयार किया जा सकता था, यह प्रस्तुत किया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

विनियम बनाने के लिए प्राधिकरण को प्रत्यायोजित करने की शक्ति स्पष्ट रूप से समाप्त हो गई थी। इसमें
 संसद का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था

इसके बाद, विनियम बनाने के मामले में हस्तक्षेप करना। में।

वास्तव में, विद्वान वकील के अनुसार, इसके परिणामस्वरूप विनियम बनाने के लिए एन. जे. ए. सी.
 का सशक्तिकरण, संसद

फ्रेमिंग के मुद्दे पर आधिकारिक रूप से प्रस्तुत किया गया था नियम। विद्वान वकील के अनुसार,
 उपरोक्त भी

स्थापित, पूर्वगामी पैराग्राफ में तैयार किया गया निष्कर्ष।

53. विद्वान वकील का यह भी तर्क था कि संविधान के माध्यम से गठित एन. जे. ए. सी. (99 वीं) संशोधन) अधिनियम, टिकाऊ होगा, जब तक कि यह नहीं था संविधान की "मूल संरचना" का उल्लंघन करता है। यह था। इस बात पर जोर दिया कि "बुनियादी" की मान्यता प्राप्त विशेषताओं में से एक संविधान की संरचना थी, "स्वतंत्रता की न्यायपालिका"। वह प्रक्रिया जिसके लिए एन. जे. ए. सी. अपना सकती है। अपने कार्यों का निर्वहन, और प्रक्रिया जिसके लिए यह उत्तरदायी था इसकी बैठकें आयोजित करते समय इसका पालन करें, और इसका दायरा और दायरा जिसके संदर्भ में एन. जे. ए. सी. को इसकी रूपरेखा बनाने के लिए अधिकृत किया गया था। विनियमों को अनन्य स्वतंत्र इच्छा पर छोड़ दिया जाना था एक स्वतंत्र एन. जे. ए. सी.। कि, विद्वान वकील के अनुसार, "एन. जे. ए. सी. की स्वतंत्रता" सुनिश्चित की होगी। तदनुसार यह तर्क दिया गया कि अनुच्छेद 124 सी ने "न्यायपालिका की स्वतंत्रता", और यह भी, एनजेएसी की स्वतंत्रता।

54. अगला विवाद के हाथों में आगे बढ़ा विद्वान वकील, अनुच्छेद के खंड (2) के संदर्भ में था 124 ए, जिसके संदर्भ में न्यायिक समीक्षा पर रोक लगा दी गई थी एन. जे. ए. सी. की कार्रवाई या कार्यवाही, के आधार पर के संविधान में एक रिक्ति या दोष का अस्तित्व एनजेएसी। विद्वान वकील ने तब इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया न्यायिक समीक्षा की शक्ति का अपवर्जन, जिसके तहत विचार किया गया है अनुच्छेद 323 ए (2) (डी) और 323 बी (3) (डी), जिसमें न्यायिक समीक्षा को भी इसी तरह से बाहर रखा गया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि इस न्यायालय ने उपरोक्त सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट में इसी तरह के प्रावधान को रद्द कर दिया था

संविधान की संरचना। इस संबंध में, विद्वान वकील किहोतो में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा रखा गया

होलोहन मामला 34, और निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख किया गया

उसमें अभिलिखित है:

"129. बहुमत के अनुसार सर्वसम्मत राय साथ ही अल्पसंख्यक यह है कि दसवें का अनुच्छेद 7

अनुसूची पूर्ण अपवर्जन के लिए एक प्रावधान लागू करती है

अनुच्छेद 136 के तहत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र सहित न्यायिक समीक्षा

संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 और इसलिए, यह

और संविधान का 227 जो परंतुक को आकर्षित करता है संविधान के अनुच्छेद 368 का खंड (2) और, इसलिए।

राज्य विधानसभाओं की निर्दिष्ट संख्या द्वारा अनुसमर्थन

इससे पहले कि विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाए

उसके अनुसार आवश्यक था। बहुमत का दृष्टिकोण

कि राज्य द्वारा इस तरह के अनुसमर्थन के अभाव में

विधायिका, यह केवल दसवीं अनुसूची का अनुच्छेद 7 है

जो असंवैधानिक है और इससे अलग किया जा सकता है

दसवीं अनुसूची का शेष भाग, केवल अनुच्छेद 7 स्पीकर के निर्णय को रद्द करने के लिए उत्तरदायी है

पैराग्राफ 6 के तहत एक न्यायिक न्यायाधिकरण के लिए उत्तरदायी है

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायिक समीक्षा

अनुच्छेद 136, 226 और 227 के तहत। अल्पमत की राय है

कि दसवें के अनुच्छेद 7 की अयोग्यता का प्रभाव

बिना विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद से अनुसूची राज्य विधानसभाओं द्वारा पूर्व अनुसमर्थन नहीं किया जाता है। द.

अल्पमत का दृष्टिकोण यह भी है कि अनुच्छेद 7 से अलग नहीं किया जा सकता है

दसवीं अनुसूची का शेष भाग और अध्यक्ष

इसके लिए एक स्वतंत्र न्यायनिर्णायक प्राधिकरण नहीं होना
लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता के अनुसार विचार किया गया उद्देश्य, सर्वोच्च न्यायालय-चालू-
रिकॉर्ड

समाज v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

दसवीं अनुसूची का शेष भाग इससे अधिक है -
संशोधन करने की शक्तियाँ एक मूल विशेषता का उल्लंघन करती हैं
संविधान। अल्पमत की राय में, हमने माना है कि
संपूर्ण संविधान (बावनवा संशोधन) अधिनियम, 1985
असंवैधानिक है और ऐसा करने का एक असफल प्रयास है
इसमें संवैधानिक संशोधन का संकेत दिया गया है।

रिलायंस को निम्नलिखित निष्कर्षों पर भी रखा गया था:

इस न्यायालय द्वारा डॉ. काशीनाथ जी. जल्मी बनाम. द.
केर 48।

" 43. किहोतो होल्लोहन में कोई अंतर नहीं था

अंतिमता की प्रकृति पर बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक राय

अध्यक्ष के अयोग्यता के आदेश को संलग्न करना
कि पैरा 7

दसवीं अनुसूची के पैरा 6 के तहत, और यह भी

इसमें गैर-अनुपालन को देखते हुए असंवैधानिक था

संविधान के अनुच्छेद 368 के खंड 2 के परंतुक का,

जिसके द्वारा न्यायिक समीक्षा को बाहर रखने की मांग की गई थी। द.

दोनों विचारों में मुख्य अंतर यह था कि

बहुमत की राय है कि इस दोष के परिणामस्वरूप संविधान बना

प्रारंभ से ही सम्मिलित करने के साथ संशोधित स्थिति
जबकि

दसवीं अनुसूची में पैरा 7 को घटाकर,

अल्पसंख्यक संविधान संशोधन का पूरा अभ्यास
प्रयास था

व्यर्थ था और संशोधन करने का एक असफल

संविधान, क्योंकि पैरा 7 विच्छेद योग्य नहीं था। के अनुसार

अल्पसंख्यक दृष्टिकोण, कई लोगों द्वारा दिए गए सभी निर्णय

और उपेक्षा की जा सकती है। बहुमत के विचार के अनुसार,
असंवैधानिक है और

दसवीं अनुसूची का पैरा 7

पृथक्कृत, दसवीं अनुसूची माइनस पैरा 7 वैध था

अधिनियमित और, इसलिए, अध्यक्ष द्वारा दिए गए आदेश

दसवीं अनुसूची के तहत शून्य नहीं थे, लेकिन इसके अधीन थे

न्यायिक समीक्षा। बहुमत की राय के आधार पर, यह

न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग किया है
अयोग्यता के आदेश

वक्ताओं द्वारा किए गए

1993 एस. सी. 1873 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

दसवीं अनुसूची की शुरुआत और इसका अभ्यास

न्यायिक समीक्षा केवल आदेशों तक ही सीमित नहीं रही है

12 नवंबर, 1991 के बाद की गई अयोग्यता जब

किहोतो होलोहन (1992 (1) एस. सी. सी. 309) में निर्णय था

प्रस्तुत किया गया। वेंकटचलैया, जे. (जैसा कि वे तब थे) ने लिखा था
बहुमत की राय और उसके बाद, इस आधार पर, प्रयोग किया गया

अयोग्यता के आदेशों पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति

12.11.1991 से पहले बनाया गया। में बुनियादी भ्रान्ति

उत्तरदाताओं की ओर से प्रस्तुत किया गया कि पैरा 7

12 नवंबर, 1991 तक विद्यमान माना जाना चाहिए

उस दृष्टिकोण पर न्यायिक समीक्षा की कोई शक्ति नहीं होगी।

अध्यक्ष द्वारा अयोग्यता के आदेश के विरुद्ध

12 नवंबर, 1991 से पहले, स्पष्ट शब्दों में पैरा 7 से

न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह से बाहर करता है।

इसलिए यह विद्वानों का जोरदार विवाद था।

अधिवक्ता, कि अनुच्छेद 124 ए के खंड (2) को निरस्त कर दिया जाना चाहिए,

यह संविधान की "मूल संरचना" का उल्लंघन है।

55. श्री फली एस. नरीमन, विद्वान वरिष्ठ वकील,

विशुद्ध रूप से एक तकनीकी याचिका दायर की। यह उनका तर्क था कि 121 वां

संविधान संशोधन विधेयक, अब संविधान (99 वां)

संशोधन) अधिनियम, 11 तारीख को लोकसभा में पेश किया गया था।

13 अगस्त, 2014 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।
गया कि 121 वां

अगस्त, 2014। यह आगे प्रस्तुत किया

संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा की गई और पारित किया गया

14.8.2014 पर राज्यसभा। इसके बाद उक्त संशोधन

विधेयक, जिसमें एक संवैधानिक संशोधन की परिकल्पना की गई थी, को अनुसमर्थन के लिए राज्य
विधानसभाओं को भेजा गया था। इसके परिणाम

16 राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद, इसे रखा गया था
के लिए। यह बताया गया कि

राष्ट्रपति की सहमति

राष्ट्रपति ने 31.12.2014 पर अपनी सहमति प्रदान की, जिसके बाद

यह संविधान (99 वां संशोधन) अधिनियम बन गया। सीखा है।

वकील ने तब धारा 1 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया

संविधान (99 वां संशोधन) अधिनियम, जो इस प्रकार है:

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे. जे.

"1 (1) इस अधिनियम को संविधान कहा जा सकता है (नब्बे

नौवां संशोधन) अधिनियम, 2014।

(2) यह ऐसी तारीख को लागू होगा जब केंद्रीय सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,

नियुक्त करें "।

उपरोक्त प्रावधान के आधार पर यह तर्क दिया गया कि

31.12.2014, संविधान (99 वां संशोधन) अधिनियम, नहीं होगा और वही आएगा

स्वचालित रूप से लागू होता है।

धारा 1 (2) में निहित अधिदेश के संदर्भ में लागू -

" केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसी तारीख को

आधिकारिक राजपत्र में, नियुक्त करें "। यह प्रस्तुत किया गया था कि अधिसूचित किया (99 वां)

केंद्र सरकार ने संविधान को

संशोधन) अधिनियम, भारत के राजपत्र में असाधारण

13.4.2015. उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति के आधार पर, से लागू हुआ

संविधान (99 वां संशोधन) अधिनियम, प्रभाव

13.4.2015 से।

56. में देखी गई तथ्यात्मक स्थिति के संयोजन में

विद्वान वकील ने इंगित किया कि पूर्वगामी अनुच्छेद

एन. जे. ए. सी. विधेयक को भी लोकसभा में 11.8.2014 पर पेश किया गया था।

लोकसभा ने 13.8.2014 पर विधेयक पारित किया, जिसके बाद, यह

राज्यसभा द्वारा 14.8.2014 पर पारित किया गया था। इसके बाद, की मंजूरी मिली

एन. जे. ए. सी. विधेयक को राष्ट्रपति

31.12.2014, और एन. जे. ए. सी. अधिनियम बन गया। यह तर्क दिया गया था,

संविधान (99 वां संशोधन) अधिनियम। यह प्रस्तुत किया गया था कि जब से संविधान (99 वां संशोधन) अधिनियम लाया गया है 13.4.2015 पर बल, एन. जे. ए. सी. विधेयक पर विचार और

लागू होने से पहले एन. जे. ए. सी. अधिनियम का पारित होना

संविधान (99 वां संशोधन) अधिनियम, इसे मृत जन्म देगा

और इसलिए नपुंसक। न्यायालय का ध्यान भी आमंत्रित किया गया था।

इस तथ्य के लिए कि उपरोक्त कानूनी दुर्बलता, संसदीय बहस के दौरान देखी गई और उठाई गई थी

एन. जे. ए. सी. विधेयक, राज्यसभा के समक्ष।

विद्वान परामर्शदाता सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

राज्य सभा में 13.8.2014 पर और 14.8.2014 (खंड 232 No.26) पर पृष्ठ 229 से 375 पर बहस का संदर्भ और 27), निम्नानुसार:

"कि श्री सीताराम येचुरी, सांसद, (राज्य सभा सदस्य)

सभा) ने एक संवैधानिक आपत्ति उठाई (13 अगस्त को,

2014) एन. जे. ए. सी. विधेयक में कहा गया है:

... संविधान संशोधन (121 ए 1 विधेयक) आने तक

प्रभावी रूप से, विधानमंडल। मैं विनम्रता से प्रस्तुत करना चाहूंगा,

नियुक्तियों के लिए न्यायिक आयोग के निर्माण के लिए विधेयक बनाने का अधिकार नहीं है। (पृष्ठ 488)

..... मैं केवल आपसे गंभीरता से विचार करने के लिए कह रहा हूँ कि हम हैं

यह

एक ऐसी स्थिति पैदा करना जहाँ एक के निर्माण के लिए यह प्रस्ताव

न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिकार से बाहर हो जाएगा।

भारतीय संविधान का क्योंकि इसे लाने का हमारा अधिकार है

इस तरह के प्रावधान को लागू करने के लिए एक विधेयक संविधान संशोधन विधेयक के प्रभावी होने के बाद ही आता है। (पृष्ठ

489)

इसलिए, आप कृपया विचार करें कि मैं क्या कह रहा हूँ।

गंभीरता से। मैं चाहता हूँ कि कानून मंत्री भी विचार करें।

यह। इसे बाद में अल्ट्रा वायर्स के रूप में नहीं गिराया जाना चाहिए। तो, चलो इस पर उचित विचार करें। " (पृष्ठ-490)

- विपक्ष के नेता (श्री गुलाम नबी आजाद)

तब उन्होंने कहा:

"विपक्ष के नेता (श्री गुलाम नबी आजाद): साहब,

मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि श्री येचुरी ने पूरी बात को पूरी तरह से अलग आयाम दिया है। यह काफी आंखें खोलने वाला है।

हम सभी को लगता है कि पूरा कानून अधिकार से बाहर हो जाएगा।

इसलिए, मेरा सुझाव है कि मेरे सहयोगी श्री आनंद से पहले

शर्मा, बोलते हैं, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। बेशक,

हमारे यहाँ हर तरफ से महान वकील हैं लेकिन मुझे लगता है कि उनमें से एक

कानूनी पेशे में सबसे पुराने दिग्गज श्री हैं।

परासरन। इससे पहले कि हम सभी यह तय करें कि क्या करना है, क्या हम सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं से अनुरोध कर सकते हैं-ऑन-रिकॉर्ड

समाज v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

श्री येचुरी ने जो कहा है उस पर प्रकाश डालने के लिए? (पृष्ठ

490)

श्री के. परासरन (मनोनीत सदस्य) ने तब अपना

विचार कह रहे हैं:

श्री के. परासरन (निरंतर)। अनुसमर्थन से पहले, यदि आप
कर दें, आज यह असंवैधानिक होगा

विधेयक को आगे बढ़ाएँ और पारित

जैसा कि हम देखते हैं, केवल लेखों में है। अनुच्छेद 368 में कहा गया है - करने की शक्ति।

XXX

XXX

XXX

सभापति महोदय: यह मैं जानना चाहता हूँ। आप.

उल्लेख किया है कि दो प्रावधान हैं। नंबर एक, अगर इसे किसी विशेष तरीके से संशोधित किया जाता है, तो यह सीधे जा सकता है

राष्ट्रपति। यदि संशोधन में अध्याय IV शामिल है, तो भाग

5, या अध्याय V, आदि, आदि, इसे आधे में अनुमोदित किया जाना है

सभाएँ। ठीक है। मैं उन दोनों को स्वीकार करता हूँ। लेकिन कुछ भी करें।
विधेयक पर अब विचार करने से रोकती हैं?

ये आपत्तियाँ हमें इस

यही मेरा सवाल है। श्री के. परासरन: नहीं। हमारे पास कानून नहीं है

- कानून और न्याय मंत्री ने तब कहा: "..... यह विधेयक अनुसमर्थन के बाद प्रभावी हो जाएगा लेकिन

अलग विधेयक विधानमंडलों को मार्गदर्शन देने के लिए है कि कैसे

पूरा ढांचा अस्तित्व में आ गया है। इसलिए यह असंवैधानिक नहीं है। हमें इसके तहत संक्षिप्त शक्ति मिली है

अनुच्छेद 246 को प्रविष्टि 77 और 78 के साथ पढ़ा जाता है, जो एक अनुच्छेद नहीं है।

सीमित शक्ति। यह एक पूर्ण शक्ति है, संपूर्ण शक्ति है। यह

संसद रचना के संबंध में कोई भी कानून पारित कर सकती है।

50 प्रतिशत विधानसभाओं के समर्थन के बाद ही एक प्रस्ताव द्वारा क्या आपका विधेयक लागू हो सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर. के बाद।

राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। और फिर, आप कह रहे हैं कि

विधेयक को इसके साथ केवल एक दिशानिर्देश के रूप में पारित किया गया था, इसलिए

कि विधानसभाओं के सदस्यों को पता हो कि आप क्या करने जा रहे हैं

करने के लिए।

श्री रविशंकर प्रसाद: लेकिन यह प्रभावी होगा।

सहमति के बाद। बस इतना ही।

सभापति महोदय: यही मैं कह रहा हूँ। यह होगा।

छह महीने के बाद प्रभावी हो जाता है। अब, मैं श्री परासरन से एक बात जानना चाहूंगा।

अनुच्छेद 246, उनके अनुसार, (मंत्री) निरपेक्ष देता है।

संसद को विधान पारित करने की शक्तियाँ। क्या कोई है? संविधान में प्रावधान, जो पारित होने से रोकता है

संवैधानिक संशोधन से पहले ऐसा विधेयक है

राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित? क्या ऐसा कोई प्रावधान है?

..... (व्यवधान)। मैं आपके पास आता हूँ। हां, श्रीमान परासरन।

(पृष्ठ-495)-इसके जवाब में श्री के. परासरन ने कहा:

"श्री के. परासरन: महोदय, मैं यह समझाऊंगा। अब हम हैं

अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद के तहत एक कानून से संबंधित

246 सातवीं अनुसूची में प्रासंगिक प्रविष्टियों के साथ पढ़ें,

माननीय द्वारा इंगित किया गया। मंत्री। अब सुप्रीम कोर्ट
इसके विपरीत कोई अधिनियम पारित नहीं कर सकते।

अनुच्छेद 124 की व्याख्या की है। हम

संविधान के लिए। यदि संविधान में संशोधन नहीं किया जाता है, तो
की कमी है। कोई फायदा नहीं है

हमारे पास विधायी क्षमता

अनुच्छेद 246 पर जाएँ और प्रविष्टियों को पढ़ें। क्या हम अनुच्छेद 246 के तहत विधायी क्षमता के साथ पढ़ते
थे

प्रविष्टियाँ। (जोर दिया गया) पृष्ठ 495।

सभापति महोदय: फिर, आप लेख की व्याख्या कैसे करते हैं?

246 ?

श्री के. परासरन: मान लीजिए कि संविधान संशोधन

पारित हो जाता है, तो क्या इस विधेयक को पेश किया जा सकता है और चर्चा की जा सकती है
जैसा है वैसा? एक काल्पनिक मामले के रूप में, यदि यह संशोधन विधेयक है

पारित नहीं हुआ, क्या हम इस विधेयक को पेश कर सकते हैं और इसे पारित कर सकते हैं? हम ऐसा नहीं कर
पाएंगे। " (जोर दिया गया) (पृष्ठ-496) "। सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. /जगदीश सिंह खेहर, जे।/

57. दूसरे शब्दों में, यह विद्वानों का विवाद था

अधिवक्ता, कि एन. जे. ए. सी. विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था, जब संसद के पास
कोई शक्ति, अधिकार या अधिकार नहीं था।

अनुच्छेद 124 (2) के अनुसार ऐसे विधेयक पर विचार करने की अधिकारिता

और 217 (1), जैसा कि मूल संविधान में अधिनियमित किया गया है। यह था।

प्रस्तुत किया कि उक्त विधेयक का पारित होना अपने आप में था
शून्य, क्योंकि संशोधित

असंवैधानिक, अति अधिकार और

संविधान (99 वां संशोधन) अधिनियम में निहित प्रावधान,
गया था कि द्वारा पारित

खेल में नहीं आया था। यह प्रस्तुत किया

लोक सभा, साथ ही 121 वीं की राज्य सभा द्वारा

16 राज्य विधानमंडलों द्वारा इसके अनुसमर्थन के साथ-साथ स्वीकृति भी
31.12.2014 पर दिया गया, प्रदान नहीं करेगा

राष्ट्रपति द्वारा

एन. जे. ए. सी. अधिनियम पर वैधता। यह, सरल कारण से, कि
संविधान (99 वां संशोधन) अधिनियम, केवल लागू किया गया था
13.4.2015 पर। मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में, के अनुसार
विद्वान वकील, अनुच्छेद 124 (2) और 217 (1) तक
भारत के संविधान को पढ़ा जा सकता था, क्योंकि वे थे
मूल रूप से अधिनियमित। उपरोक्त संदर्भ में, यह प्रस्तुत किया गया था,
कि एन. जे. ए. सी. अधिनियम पारित नहीं किया जा सकता था, जब तक कि
संविधान के अपरिवर्तित प्रावधान लागू थे। और

कि, एन. जे. ए. सी. अधिनियम पर राष्ट्रपति की मात्र सहमति 31.12.2014, उस पर वैधता लागू
नहीं कर सके।

58. उपरोक्त विवाद की पुष्टि करने के लिए,

विद्वान वकील ने ए. के. रॉय बनाम पर भरोसा रखा। भारत संघ 49, और निम्नलिखित पर हमारा ध्यान
आकर्षित किया:

"45 के प्रावधानों से उत्पन्न तर्क

अनुच्छेद 368 (2) पर पहले विचार किया जा सकता है। यह बताता है कि जब

एक विधेयक जिसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है

अपेक्षित बहुमत, इसे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

जो विधेयक को अपनी सहमति देगा, और उसके बाद

संविधान के अनुसार संशोधन किया जाएगा

विधेयक की शर्तें "। यह प्रावधान दर्शाता है कि एक संवैधानिक

49 (1982) 1 एस. सी. सी. 271 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

संशोधन का कोई प्रभाव नहीं हो सकता है जब तक कि राष्ट्रपति

इसे अपनी सहमति देता है और दूसरा, कि राष्ट्रपति द्वारा विधिवत पारित संशोधन के लिए राष्ट्रपति की सहमति के अलावा और कुछ नहीं संसद की आवश्यकता है, ताकि संविधान

शर्तों के अनुसार संशोधित होना चाहिए

बिल। इसी से संविधान खड़ा हुआ।

44 वीं की शर्तों के अनुसार संशोधित

संशोधन अधिनियम जब राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दी

वह अधिनियम 30 अप्रैल, 1979 को। तब हमें उस अधिनियम की ओर रुख करना चाहिए, क्योंकि

यह देखते हुए कि संविधान इस प्रकार कैसे और किस तरीके से खड़ा था

संशोधित किया गया। 44 वाँ संशोधन अधिनियम स्वयं निर्धारित करता है -

धारा 1 (2) एक पूर्व शर्त जिसे पहले पूरा किया जाना चाहिए।

इसका कोई भी प्रावधान लागू हो सकता है। वह पूर्व शर्त

केंद्र सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है

आधिकारिक राजपत्र में, उस तारीख को नियुक्त करना जिससे

अधिनियम या उसका कोई विशेष प्रावधान लागू होगा,

विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग-अलग तिथियां निर्धारित करने की शक्ति के साथ।

इस प्रकार, 44 वें संशोधन की शर्तों के अनुसार।

इसका कोई भी प्रावधान तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक कि

केंद्र सरकार एक अधिसूचना जारी करती है

धारा 1 (2) द्वारा विचारित:

46. प्रावधानों के बीच कोई आंतरिक विरोधाभास नहीं है। अनुच्छेद 368 (2) और 44 वें संशोधन अधिनियम की धारा 1 (2)। अनुच्छेद 368 (2) एक सामान्य नियम निर्धारित करता है।

जिस तारीख से संविधान लागू होगा

द्वारा स्वीकृत विधेयक के अनुसार संशोधित स्थिति

राष्ट्रपति। संशोधन अधिनियम की धारा 1 (2) उस तरीके को निर्दिष्ट करती है जिसमें वह अधिनियम या इसके किसी भी प्रावधान

लागू किया जाए। के बीच अंतर है

संविधान के अनुसार संशोधित स्थिति

राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित विधेयक की शर्तें और तारीख
संविधान में। प्रभाव के साथ तिथि निर्धारित करने के लिए जिनसे संविधान में संशोधन किया
गया है

विधेयक की शर्तों के अनुसार, किसी को सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड की ओर रख करना होगा

समाज v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

तारीख जिस पर राष्ट्रपति ने दिया था, या करने के लिए बाध्य था

संशोधन के लिए उनकी सहमति दें। निर्धारित करने के लिए

जिस तारीख से संविधान, जैसा कि संशोधित किया गया है।

आया या लागू होगा, एक को बदलना होगा

केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना, यदि कोई हो, संशोधन अधिनियम की धारा 1 (2)।

47. संशोधन अधिनियम यह प्रावधान कर सकता है कि

इसके द्वारा लागू किया जाना तुरंत लागू हो जाएगा।

राष्ट्रपति विधेयक को अपनी सहमति दे रहा है या यह प्रदान कर सकता है

कि संशोधन भविष्य की तारीख से लागू होगा।

वास्तव में, स्वयं घटक निकाय द्वारा भविष्य की एक विशिष्ट तिथि निर्धारित करने पर कोई आपत्ति नहीं की
जा सकती है।

संशोधन अधिनियम लागू होगा और यदि ऐसा है, तो

इसे लागू करने के लिए अलग-अलग तिथियां निर्धारित की जा सकती हैं। संशोधन अधिनियम के
विभिन्न प्रावधान। बिन्दु का

बात यह है कि संविधान में संशोधन किया गया है विधेयक और संशोधन की शर्तों के अनुसार

इस प्रकार लागू होने वाले संविधान में शामिल किए गए हैं दो अलग-अलग चीजें। बस द्वारा
विधिवत पारित एक कानून के रूप में

विधायिका का कोई प्रभाव नहीं हो सकता है जब तक कि यह न आए या न लाया जाए। लागू,
इसी तरह, संविधान का एक संशोधन कर सकते हैं

तारीख या तारीखें जिनसे संशोधन अधिनियम प्रभावी हुआ या इसके किसी भी प्रावधान के लागू
होने से पता चलता है कि

अनुच्छेद 368 (2) के बीच कोई विरोधाभास नहीं है

संविधान और 44 वें संशोधन अधिनियम की धारा 1 (2)।
संबंध में

विधायी या घटक की अभिव्यक्ति के

प्रस्तुत करना कि, अभिव्यक्ति के विपरीत

घटक, 44 वें द्वारा पेश किए गए संशोधन

संशोधन अधिनियम 30 अप्रैल, 1979 को लागू हुआ जब
मंजूरी दे दी। सही स्थिति

राष्ट्रपति ने उस अधिनियम को अपनी

यह है कि 44 वें संशोधन [2015] 13 एस. सी. आर. द्वारा प्रस्तुत संशोधन।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिनियम 30 अप्रैल को संविधान का हिस्सा नहीं बना।

1979. वे उस स्थिति को तभी हासिल करेंगे जब केंद्र

सरकार एक अधिसूचना जारी करके उन्हें लागू करती है।

संशोधन अधिनियम की धारा 1 (2) के तहत। "

59. यह श्री फली एस. नरीमन का भी तर्क था।

कि एक संवैधानिक संशोधन के रूप में उत्तरदायी था अल्ट्रा वायर्स के रूप में घोषित, यदि यह
उल्लंघन करता है और/या निरस्त किया जाता है, तो "कोर"

या संविधान की "बुनियादी संरचना"; यहां तक कि एक साधारण विधायी अधिनियम, जिसने संविधान की
"बुनियादी संरचना" का उल्लंघन किया।

संविधान को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता था।

तत्काल प्रस्ताव के लिए, विद्वान वकील ने संदर्भित किया

मद्रास बार एसोसिएशन मामला 35, और इस पर भरोसा रखा

उसमें निम्नलिखित टिप्पणियाँ दर्ज की गई हैं:

"109. भले ही हमने स्वीकार करने से इनकार कर दिया है

याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत किया गया विवाद, पूर्वनिर्धारित

"बुनियादी संरचना" सिद्धांत पर, हम महसूस करते हैं कि यह अभी भी आवश्यक है

हमारे लिए, की ओर से अग्रिम प्रस्तुतिकरण से निपटने के लिए
उत्तरदाताओं ने जवाब दिया। हम पहले रिकॉर्ड कर सकते हैं

उत्तरदाताओं की ओर से प्रस्तुत किया गया विवाद। यह था।
 तर्क दिया कि एक कानून (एक संशोधन नहीं होने के नाते
 संविधान), प्रावधानों के अनुरूप अधिनियमित
 संविधान के दायरे में आने वाले किसी विषय पर
 संबंधित विधायिका पर जमीन पर हमला नहीं किया जा सकता है
 कि यह संविधान के "मूल ढांचे" का उल्लंघन करता है। के लिए
 वर्तमान विवाद, उत्तरदाताओं ने रखा था
 संविधान के अनुच्छेद 245 और 246 पर निर्भरता, और साथ ही,
 संघ सूची की 77 से 79, 82 से 84, 95 और 97 प्रविष्टियों पर
 सातवीं अनुसूची, और प्रविष्टियों पर 11-ए और 46
 सातम अनुसूचीक समवर्ती सूची। इसके आधार पर
 यह दावा किया गया था कि संसद अधिनियम बनाने के लिए सक्षम थी
 एनटीटी अधिनियम। तत्काल विवाद की जांच करने के लिए, आइए हम
 मान लीजिए कि ऐसा है। उपरोक्त को स्वीकार करने के बाद, हमारे
 विचार इस प्रकार है। संविधान विनियमित करता है कि
 शासन का तरीका काफी सूक्ष्म विवरण में। यह इस तरह के शासन के लिए शक्ति का वितरण करने
 वाला फव्वारा है।

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्डसमाज v. यू. ओ. आई. /जगदीश सिंह खेहर, जे. जे.

संविधान में कानून बनाने की शक्ति निहित है - केंद्र, लोकसभा और राज्यसभा के साथ, और
 राज्य विधानसभाओं वाले राज्य (और
 कुछ राज्य, राज्य विधान परिषदें भी)। द. तत्काल विधायी शक्ति को "भाग XI" द्वारा विनियमित
 किया जाता है

संविधान। प्रस्तुतिकरण के हाथों में आगे बढ़ाया गया
 उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील, जहाँ तक
 मामले के तत्काल पहलू का संबंध है, जिस पर आधारित है
 यह दावा कि एन. टी. टी. अधिनियम में सख्ती से अधिनियमित किया गया है

के "भाग XI" में दर्शाई गई प्रक्रिया के अनुरूप संविधान। यह विद्वान वकील का भी तर्क है।
 उत्तरदाताओं के लिए, कि उक्त शक्ति का प्रयोग किया गया है
 सख्ती से उस विषय के अनुरूप जिस पर संसद कानून बनाने के लिए अधिकृत है। निपटते समय
 तत्काल प्रस्तुतिकरण के हाथों में आगे बढ़ा
 उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील, वह सब जो होना चाहिए कहा गया है कि "भाग" के तहत
 प्रदत्त विधायी शक्ति
 संविधान के 11 में एक समग्र अपवाद है, जो
 निस्संदेह यह संविधान की "मूल संरचना" है।
 इस न्यायालय की पीठों का उल्लेख ऊपर किया गया है। यह हमें लगता है, कि क्या में एक अच्छा
 अंतर है
 याचिकाकर्ताओं का तर्क है, और उत्तरदाता क्या चाहते हैं
 याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील की कमी नहीं है अधिकारिता या अधिकारिता का
 अनुचित प्रयोग। द.
 विद्वान वकील के हाथों अग्रिम प्रस्तुतिकरण
 याचिकाकर्ताओं के लिए स्पष्ट रूप से यह है कि यह अस्वीकार्य है
 इस तरह से कानून बनाएँ जिससे "मूल संरचना" का उल्लंघन हो।
 संविधान से। इस न्यायालय ने बार-बार कहा है कि
 संविधान के प्रावधानों में संशोधन नहीं होगा
 यदि यह "मूल संरचना" का उल्लंघन करता है तो टिकाऊ होगा
 संविधान, भले ही संशोधन किया गया था
 "आंशिक सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट" के तहत विचार की गई प्रक्रिया का पालन करके

[2015] 13 एस सी आर।

संविधान का XI "। यह दृढ़ संकल्प की ओर ले जाता है कि
 "मूल संरचना" अलंघनीय है। हमारी नज़र में, एक ही

(संशोधनों को छोड़कर) अन्य सभी विधानों पर लागू होगा।
संविधान) के साथ-साथ, भले ही कानून था

निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके अधिनियमित किया गया था, और अधिनियमित करने वाले
विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र के भीतर था,

"मूल संरचना" का उल्लंघन होगा
अस्वीकार्य है। इस तरह के प्रस्तुतियाँ हाथों में आगे बढ़ीं

इसलिए उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील हैं।

अस्वीकृत किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं, और तदनुसार अस्वीकार किए जाते हैं।

60. श्री अरविंद पी. दातार, विद्वान वरिष्ठ वकील, ने हमला किया

एन. जे. ए. सी. के विभिन्न प्रावधानों की संवैधानिक वैधता अधिनियम, उन्हीं प्रस्तुतियों को आगे बढ़ाते
हुए, जिन पर भरोसा किया गया था

उनके द्वारा अनुच्छेदों की संवैधानिक वैधता पर हमला करते हुए

124 ए, 124 बी और 124 सी। संक्षिप्तता के कारणों से, वनाच्छादित

एन. जे. ए. सी. अधिनियम के अलग-अलग प्रावधानों के संदर्भ में देखी गई प्रस्तुतियों को फिर से नहीं दोहराया
जा रहा है।

61. अलग-अलग लोगों के लिए एक चुनौती भी उठाई गई थी

एनजेएसी अधिनियम के प्रावधान। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, एक चुनौती

भारत के मुख्य न्यायाधीश के चयन के तरीके के अनुसार उठाया गया था। एन. जे. ए. सी. अधिनियम की धारा
5 (1), जो प्रस्तुत की गई थी, प्रदान करती है

कि एन. जे. ए. सी. सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश की सिफारिश करेगा

सर्वोच्च न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए

भारत, इस शर्त के अधीन, कि उन्हें "फिट" माना गया था कार्यालय को संभालें। यह तर्क दिया गया
था कि विनियमन की प्रक्रिया

भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होनी थी

संसद द्वारा अनुच्छेद 124 सी के तहत कानून द्वारा निर्धारित। यह था।

तर्क दिया कि "उपयुक्त" शब्द, की धारा 5 में व्यक्त किया गया है

एन. जे. ए. सी. अधिनियम का विस्तृत वर्णन नहीं किया गया था। और इस तरह, फिटनेस को व्यक्तिपरक
आधार पर निर्धारित करना होगा

एन. जे. ए. सी. के सदस्यों का संतोष। यह प्रस्तुत किया गया था,

कि भले ही विद्वान महान्यायवादी ने व्यक्त किया था, सुनवाई के दौरान, उस फिटनेस का मतलब था "मानसिक और

केवल शारीरिक स्वस्थता।", यह हमेशा संसद के सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं-ऑन-रिकॉर्ड के लिए खुला था।

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

उद्देश्यपूर्ण रूप से स्वास्थ्य को इस तरह से परिभाषित करना जो सहायक हो।

कार्यपालिका की इच्छा। यह प्रस्तुत किया गया था कि एक अध्यादेश भी

प्रक्रिया का पालन करने, कानून बनाने की आवश्यकता के बिना जारी किया जा सकता है। यह दावा किया गया था कि मानदंड स्वास्थ्य को परिभाषित और पुनर्परिभाषित किया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया था,

कि यह एक संवैधानिक परंपरा थी, कि सबसे वरिष्ठ

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हमेशा के रूप में नियुक्त किया जाएगा

भारत के मुख्य न्यायाधीश। और कि, उपरोक्त कन्वेंशन था अटूट रहा, भले ही कुछ मामलों में का कार्यकाल

नियुक्त व्यक्ति, छोटा था, और इस तरह, नहीं हो सकता है

समग्र रूप से न्यायिक संगठन के लाभ के लिए। विद्वान वकील के अनुसार, अनुभव से पता चला था कि

सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रथा का पालन करना भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, इसके परिणामस्वरूप संस्थागत

न्यायाधीशों के बीच सामंजस्य, जो अत्यंत महत्वपूर्ण था

न्यायपालिका का स्वास्थ्य, और "की स्वतंत्रता" के लिए भी न्यायपालिका "। यह प्रस्तुत किया गया था कि यह न्यायसंगत होगा और

उपयुक्त, वर्तमान मोड़ पर, की चौड़ाई को समझने के लिए

शक्ति, ताकि भविष्य में इसके दुरुपयोग की किसी भी संभावना को रोका जा सके।

यह प्रस्तुत किया गया था कि विभिन्न तरीके और साधन हो सकते हैं

न्यायाधीशों को हटाने के लिए, और पसंदीदा को लाने के लिए भी तैयार किया गया।

पिछले अनुभव से पता चला था कि कार्यपालिका ने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया था, जब वह अप्रैल 1973 में उपरोक्त नियम से अलग हुई थी। जे. एम. शेलट, जे., सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश और

यहाँ तक कि उसके बाद वरिष्ठता के क्रम में अगले दो न्यायाधीश,
 अर्थात्, के. एस. हेगड़े और ए. एन. गोवर, और चौथे नियुक्त
 भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश ए. एन. रे। एक बार फिर
 अधिकांश न्यायाधीश एच. आर. खन्ना को नजरअंदाज कर दिया गया और अगले वरिष्ठ
 अधिकांश न्यायाधीश एम. एच. बेग को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था
 भारत। कार्यपालिका के हाथों में इस तरह का नियंत्रण कारण होगा निर्णय लेने की प्रक्रिया में
 अपार पैठ। और हो सकता है।
 परिणामस्वरूप, न्यायाधीश व्यक्तिगत लाभ और पुरस्कारों के लिए कार्यपालिका को शांत करने और खुश
 करने की कोशिश करते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

62. ऊपर उल्लिखित प्रस्तुति की मांग की गई थी

निम्नलिखित उदाहरण के माध्यम से चित्रित। यह बताया गया था,
 कि यह संसद के लिए वास्तविक और वैध होगा
 अधिनियम, कि एक व्यक्ति को नियुक्ति के लिए उपयुक्त माना जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश के
 रूप में, केवल तभी जब उनके पास न्यूनतम शेष था
 कम से कम दो साल का कार्यकाल। इस तरह के एक अधिनियम में एक होगा
 विनाशकारी प्रभाव, भले ही यह प्रतीत होता है
 निर्दोष रूप से वैध। यह तर्क दिया गया था कि 41 में से अब तक भारत के मुख्य न्यायाधीशों की
 नियुक्ति, केवल 12 मुख्य न्यायाधीश
 भारत का कार्यकाल दो साल से अधिक का था। इस तरह की कार्रवाई
 संसद के हाथ, कारण बनने के लिए बाध्य थे
 भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद धारण करें। यह प्रस्तुत किया गया था कि समान उदाहरणों को
 आयामी परिवर्तनों के साथ गुणा किया जा सकता है।
 विभिन्न मापदंड निर्धारित करके। यह प्रस्तुत किया गया था कि
 संसद को कभी भी निर्माण का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए।
 चयन और नियुक्ति के मामले में अनिश्चितता

भारत का महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह बेहद गंभीर था और प्राधिकारी का प्रयोग,

भारी जिम्मेदारियाँ। उपरोक्त

यह इंगित किया गया था, हो सकता है/गंभीर रूप से प्रभावित करेगा

"न्यायपालिका की स्वतंत्रता"। उपरोक्त संदर्भ में,

प्रसिद्ध द्वारा व्यक्त की गई राय के अनुसार भी बनाया गया था

न्यायिक संस्थान में विशाल अनुभव रखने वाले व्यक्ति,

आगे बड़े विवाद की सच्चाई को प्रभावी ढंग से सामने लाना।
का संदर्भ दिया गया था।

इस संबंध में एम. सी. की टिप्पणियों

चागला ने अपनी पुस्तक "रोज़ेज़ इन दिसंबर-एन ऑटोबायोग्राफी" में न्यायाधीशों पर अधिस्थगन के प्रभाव की जांच की है। जो मौजूदा परंपरा के आधार पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में थे, लेकिन एक को प्राथमिकता देकर उनकी अनदेखी की गई

जूनियर। द्वारा व्यक्त राय का भी संदर्भ दिया गया था

एच. आर. खन्ना, जे. (अपनी पुस्तक-"न तो गुलाब और न ही कांटे"में)।

अंत में, न्यायालय का ध्यान व्यक्त किए गए विचार की ओर आकर्षित किया गया

एच. एम. सीरवई द्वारा (भारत के संवैधानिक कानून-ए क्रिटिकल में)

टिप्पणी 7)। यह प्रस्तुत किया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं के मुद्दे को-चालू-रिकॉर्ड पर छोड़ दिया गया है

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

संसद के साथ योग्यता का निर्धारण, प्रशंसक के लिए उत्तरदायी था

न्यायाधीशों की महत्वाकांक्षाएँ, और उन्हें उन लोगों के प्रति वफादार बना देगा

जो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सके। इसलिए यह था

न्यायोचित वकील का तर्क, कि धारा 5, जिसने

मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में अस्पष्टता

भारत का, और इसकी स्वतंत्रता को खतरे में डालने के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है

न्यायपालिका को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता था।

63. यह विद्वान वकील का भी तर्क था

याचिकाकर्ताओं, कि चयन और नियुक्ति के मुद्दे पर

उच्च न्यायापालिका के न्यायाधीशों के लिए, एन. जे. ए. सी. क्षमता, योग्यता और उपयुक्तता (जो भी हो) को ध्यान में रखने के लिए उत्तरदायी था। नियमों द्वारा निर्दिष्ट)। यह प्रस्तुत किया गया था कि उपरोक्त

मानदंड के तहत बनाए गए नियमों के माध्यम से प्रदान किया जा सकता है धारा 12 (2) (ए), (बी) और (सी)। यह बताया गया कि

न्यायाधीश की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए बनाए गए विनियम

(क्षमता और योग्यता के संदर्भ में), का पर्याय होगा

पात्रता की शर्तें। इस प्रकार, एक उम्मीदवार जिसने किया

विनियमों में व्यक्त मानकों को पूरा नहीं करते हैं,

नियुक्ति की निर्धारित शर्तों को भी पूरा नहीं करता है। यह

दावा किया गया था, कि यह एक ही इलाज करने के लिए एक गलत नाम होगा

यह केवल प्रक्रिया की बात है। इस प्रकार देखा गया, यह तर्क दिया गया था,

कि एन. जे. ए. सी. अधिनियम के प्रावधान, जो निर्धारित (या निर्धारित करने के लिए प्रदान किए गए) मूल शर्तों के लिए

नियुक्ति स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 124 सी के दायरे से बाहर थी।

चूंकि, उपरोक्त प्रावधान के तहत, अकेले संसद को कानून द्वारा प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए अधिकृत किया गया था

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, या उन्हें सशक्त बनाना

एन. जे. ए. सी. विनियमों द्वारा इसे निर्धारित करने के लिए, अन्य बातों के साथ

न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों के चयन का तरीका

सर्वोच्च न्यायालय। यह प्रस्तुत किया गया था कि एनजेएसी अधिनियम,

विशेष रूप से धारा 5 (2) के संदर्भ में, बहुत आगे की यात्रा की थी

अनुच्छेद 124 सी के तहत विचार किए गए क्षेत्राधिकार मानदंड।

64. यह भी तर्क दिया गया था कि सिफारिश करते समय

उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए नाम, सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

योग्यता और योग्यता के अलावा विचार। यह प्रस्तुत किया गया था, कि तत्काल जनादेश के तहत पहले परंतुक में निहित है

एन. जे. ए. सी. अधिनियम की धारा 5 (2) ने स्पष्ट रूप से संघीय कानून का उल्लंघन किया है। शासन की संरचना, जिसके लिए निस्संदेह सर्वोच्च न्यायालय में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की आवश्यकता थी। चूंकि "संघीय

संविधान में परिकल्पित संरचना भी इनमें से एक थी

के निर्माताओं द्वारा परिकल्पित "बुनियादी संरचनाएँ"

संविधान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था।

65. उपरोक्त के अलावा, न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया गया था

एन. जे. ए. सी. अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत दूसरे परंतुक के लिए,

जो आदेश देता है कि एन. जे. ए. सी. अनुकूल नहीं होगा

सिफारिश, यदि उसके किसी भी दो सदस्यों ने इसका विरोध किया

किसी व्यक्ति की उम्मीदवारी। यह तर्क दिया गया था कि वीटो की शक्ति को किसी भी दो सदस्यों के हाथों में रखना

एन. जे. ए. सी., व्यक्त की गई सिफारिश करने की शक्ति का उल्लंघन करेगा

अनुच्छेद 124 ख में। इस पक्ष में, यह तर्क दिया गया था कि धारा 5 (2) के तहत दूसरा परंतुक दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों (-सामान्य व्यक्ति, यदि विद्वान द्वारा प्रस्तुत किया जाता है) को सक्षम बनाएगा। महान्यायवादी को स्वीकार किया जाना है) एक सर्वसम्मत को हराने के लिए

भारत के मुख्य न्यायाधीश और दो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों की राय

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। और इस प्रकार प्रधानता को नकारता है

न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में न्यायपालिका में निहित

उच्च न्यायपालिका के लिए।

66. यह प्रस्तुत किया गया था कि वीटो की उपरोक्त शक्ति

दो सामान्य व्यक्तियों, या वैकल्पिक रूप से एक सामान्य व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया जा सकता है,

कानून और न्याय के प्रभारी केंद्रीय मंत्री के साथ मिलकर, "स्वतंत्रता" में गंभीर उल्लंघन होगा।

न्यायपालिका का "। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह तर्क दिया गया था कि न तो

विवादित संवैधानिक संशोधन, और न ही एन. जे. ए. सी. अधिनियम के प्रावधान, बैठकों के आयोजन के लिए किसी भी कोरम का प्रावधान करते हैं।

एनजेएसी से। और इस तरह (विवादों के बिल्कुल विपरीत) विद्वान महान्यायवादी के हाथों अग्रिम), यह था

यह तर्क देते हुए कि एन. जे. ए. सी. की बैठक आयोजित नहीं की जा सकी, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

एनजेएसी के सभी सदस्यों की उपस्थिति के बिना। क्रम में

अपने उपरोक्त तर्क का समर्थन करने के लिए, उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्भरता रखी संविधान (122 वां संशोधन) विधेयक, 2014 पर [लाया गया]

संसद के समक्ष, उसी सत्तारूढ़ राजनीतिक दल द्वारा, जो

संविधान को प्रस्तुत करके सफलतापूर्वक संशोधन किया था संविधान (121 वां संशोधन) विधेयक, 2014)। उद्देश्य.

संविधान (122 वें) के माध्यम से प्राप्त करने की मांग की गई संशोधन) विधेयक, 2014 में अनुच्छेद 279 ए को शामिल किया जाना था। द.

प्रस्तावित अनुच्छेद 279 ए का उद्देश्य वस्तुओं का निर्माण करना और

सेवा कर परिषद। उप-अनुच्छेद 279 ए का अनुच्छेद (7)

अभिधारणा, कि ". एक-सदस्यों की कुल संख्या का आधा

वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन किया जाएगा।

इसकी बैठकों के लिए कोरम। और इसके अलावा, कि "... हर एक

वस्तु एवं सेवा कर परिषद का निर्णय लिया जाएगा।

एक बैठक में, कम से कम तीन चौथाई के बहुमत से

उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मत। " होने के नाते

विधेयक में उपरोक्त मापदंडों को निर्धारित किया गया, जिसके बाद विधेयक जिसके कारण संविधान (99 वां संशोधन) अधिनियम की घोषणा हुई, यह प्रस्तुत किया गया कि

एन. जे. ए. सी. के कार्यकरण के लिए गणपूर्ति का प्रावधान करना, और

वैध निर्णय के लिए आवश्यक शक्ति की मात्रा निर्धारित करने में चूक

बनाना, निर्दोष नहीं था। और यह कि, इसने प्रावधान को दूषित कर दिया

स्वयं।

III. उत्तरदाताओं का जवाब। मैरिट्स पर:

67. विद्वान महान्यायवादी ने गुण-दोष पर अपना जवाब देते हुए कहा कि कोई प्रावधान नहीं था

भारत के संविधान में, या तो जब इसे मूल रूप से तैयार किया गया था,

या उसके बाद किसी भी स्तर पर, जिस पर विचार किया गया था कि न्यायाधीश

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। यह तदनुसार था

दावा किया कि न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी

संविधान के प्रावधानों के लिए विदेशी। यह बताया गया था,

कि कुछ राजनीतिक उथल-पुथल थी, जो

"न्यायपालिका की स्वतंत्रता" को कमजोर किया, जिसमें शामिल हैं
मामले में कार्यकारी ओवररीच [2015] 13 एस. सी. आर.

नियुक्ति और स्थानांतरण के

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों के, के अधिनिर्णय से शुरू

1973 में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों ने

उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों का सामूहिक स्थानांतरण

1977 में सर्वोच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ न्यायाधीश। यह था।
हस्तक्षेप था

स्वीकार किया, कि द्वारा निरंतर

कार्यपालक, उच्चतर न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में

1980 के दशक के दौरान न्यायपालिका। इसके बावजूद, निर्णय लेते हुए

1981 में प्रथम न्यायाधीशों के मामले में हुए विवाद पर,

यह न्यायालय, यह इंगित किया गया था, अप्रभावित रहा था, और

कार्यपालिका की प्रधानता को दोहराया, के मामले में
नियुक्ति।

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की

68. यह इंगित किया गया था कि प्रथम न्यायाधीशों के मामले में दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार करने का
मुद्दा उत्पन्न हुआ

सुभाष शर्मा बनाम। भारत संघ 4, जिसमें प्रश्न

विचार किया गया था, क्या मुख्य न्यायाधीश की राय भारत, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में

न्यायालय और उच्च न्यायालयों के साथ-साथ उच्च न्यायालय का स्थानांतरण

न्यायाधीश, प्रधानता के हकदार थे, और यह भी कि क्या मामला

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करना न्यायसंगत था?

यह दावा किया गया कि उपरोक्त दो प्रश्न रखे गए थे

नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा निर्धारण के लिए

सात न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्णय लिया गया)। यह दावा किया गया था कि द्वितीय न्यायाधीशों के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय,

इस न्यायालय द्वारा अधिकारिता के स्वतः संज्ञान अभ्यास पर था, जिसमें इस न्यायालय ने इसके दायरे से परे मामलों की जांच की थी

संदर्भ आदेश। यह तर्क दिया गया था कि द्वितीय न्यायाधीश

मामला प्रस्तुत किया गया था, सभी की भागीदारी के बिना

अधिवक्ताओं और वकीलों के संघों का अभ्यास करने का आदेश, और इसकी सुनवाई के दौरान कोई अन्य हितधारक शामिल नहीं था।

69. यह दावा किया गया था कि न्यायपालिका का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है

सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की भूमिका को स्वयं ग्रहण करना।

अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. /जगदीश सिंह खेहर, जे।/

उच्च न्यायपालिका। यह बताया गया था कि यह संसद है

अकेले, जो नागरिकों और इस देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है देश, और उस पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार क्षेत्र है

विषय हैं। तदनुसार, यह दावा किया गया कि निर्णयों में

द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों के मामलों को इस रूप में देखा जाना चाहिए

बिना किसी अधिकारिता प्राधिकरण के कानून।

70. यह इंगित किया गया था कि संबंधित मुद्दा

विषय से संबंधित संविधान का संशोधन

न्यायिक प्रणाली के माध्यम से उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति

आयोग की शुरुआत संविधान (67 वें) के साथ हुई।

संशोधन) विधेयक, 1990। हालाँकि यह विधेयक व्यपगत हो गया। उसी पर (82 वां संशोधन) विधेयक, 1997

विषय, संविधान

परिचय कराया। हालाँकि, 1997 का विधेयक पारित नहीं हो सका। यह

इसके बाद संविधान (98 वां संशोधन) विधेयक, 2003 आया।

जिसे उस समय पेश किया गया था जब वर्तमान सरकार थी

शक्ति। 2003 में ही एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था समीक्षा, उसके बाद दूसरा

संविधान के कार्यकरण की

2007 में प्रशासनिक सुधार आयोग। अंतर्वर्धित

उपरोक्त घटनाओं के साथ, कई विधि आयोग थे

रिपोर्ट करते हैं। संसद की मंशा, 1990 में विधेयक पेश किए जाने के बाद से, एक

उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीश। यह इंगित किया गया था कि नहीं सकारात्मक उपलब्धि हासिल की गई, क्योंकि

उपरोक्त दिशा में

दो दशकों से अधिक। श्री न्यायमूर्ति एम. एन. वेंकटचलैया, जिन्होंने

के कामकाज की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग का नेतृत्व किया

संविधान ने पांच सदस्यीय राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की भी सिफारिश की थी, जिसके तहत एक व्यापक परामर्श प्रक्रिया शुरू की जाए। चयन और नियुक्ति में पेश करने की मांग की गई थी

न्यायाधीशों का। यह प्रस्तुत किया गया था कि सभी सिफारिशें

कार्यपालिका की सहभागी भागीदारी के लिए बनाया गया था,

साथ ही न्यायपालिका, न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में

उच्च न्यायपालिका के लिए। यह भी बताया गया कि संविधान (98 वां संशोधन) विधेयक, 2003 में सात प्रस्ताव रखे गए थे -

राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के सदस्य।

इसके बाद, [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रशासनिक सुधार आयोग ने आठ प्रस्ताव रखे

राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के सदस्य की अध्यक्षता करेंगे

उपराष्ट्रपति, और जिसमें प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, कानून मंत्री और दो सदस्य शामिल होते हैं।

विपक्ष के नेता। उपरोक्त सिफारिश,

फिर केंद्रीय कानून मंत्री। वर्तमान संविधान (99 वां संशोधन) अधिनियम, 2014, जिसके तहत अनुच्छेद 124 को लागू किया गया है। संविधान में संशोधन किया गया है और अनुच्छेद 124 ए से 124 सी को जोड़ा गया है, जिसमें छह सदस्यीय राष्ट्रीय न्यायिक समिति का विचार किया गया है।

आयोग। यह प्रस्तुत किया गया था कि एन. जे. ए. सी. की संरचना में कुछ भी गलत खोजने का कोई औचित्य नहीं था। को।

अवांछनीय व्यक्तियों के प्रवेश के खिलाफ सुरक्षा उपायों को इंगित करें

उच्च न्यायपालिका में, इस बात पर जोर दिया गया कि केवल तभी जब एन. जे. ए. सी. के छह में से पांच सदस्यों ने एक उम्मीदवार की सिफारिश की, वह

उच्च न्यायपालिका में नियुक्त किया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया था,

कि वनाच्छादित सुरक्षा उपाय, संशोधित में अभिनिर्धारित

प्रावधान, न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे, बल्कि व्यापक आधार पर विचार करें।

71. एक काउंटर के रूप में, अपनी ओर से आगे की गई प्रस्तुतियों के लिए

याचिकाकर्ताओं में से, यह दावा किया गया था कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पूर्ण थी, जो केवल एक के अधीन थी

प्रतिबंध, अर्थात्, कि संसद "मूल" में परिवर्तन नहीं कर सकती

संविधान की संरचना। और इस प्रकार, एक संवैधानिक संशोधन को संवैधानिक रूप से वैध माना जाना चाहिए।

(जब तक कि अन्यथा नहीं दिखाया गया हो)। तत्काल प्रस्ताव के लिए, निर्भरता चरणजीत लाल चौधरी बनाम पर रखा गया था। भारत संघ 50, राम कृष्ण डालमिया बनाम। न्यायमूर्ति एस. आर. तेंदुलकर 51,

केशवानंद भारती मामला 1 0 10, (विशेष रूप से व्यक्त किया गया विचार)

के. एस. हेगड़े और ए. के. मुखर्जी, जे. जे.), बी. बनर्जी बनाम अनीता

पैन 52, और आंध्र प्रदेश सरकार बनाम। पी. लक्ष्मी देवी 53.

52 (1975) 1 एससीसी 166

53 (2008) 4 एस. सी. सी. 720 सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

72. यह दावा किया गया था कि संसद सबसे अच्छी है

लोगों की जरूरतों का आकलन करने और उनसे निपटने के लिए सुसज्जित

बदलते समय। इसके लिए मोहम्मद पर निर्भरता रखी गई थी। हनीफ कुरेशी बनाम। बिहार राज्य 54, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम।

अनवर अली सरकार 55. यह तर्क दिया गया था कि अधिनियम बनाते समय

संविधान (99 वां संशोधन) अधिनियम और एन. जे. ए. सी. अधिनियम,

संसद ने एक जिम्मेदारी का निर्वहन किया था, जिसके लिए वह ऋणी थी

इस देश के नागरिक, एक सार्थक प्रदान करके

न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति के लिए प्रक्रिया

उच्च न्यायपालिका।

73. इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों का उल्लेख करते हुए

द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों के मामलों में यह दावा किया गया था कि

जिस तरह से उन्होंने इसे देखा, केवल एक ही समझ में आने वाला अंतर था

के माध्यम से विचार किए गए चयन की प्रक्रिया में पेश किया गया

एनजेएसी। शुरू की गई प्रणाली के तहत, न्यायपालिका कर सकती है

किसी व्यक्ति की नियुक्ति पर "आग्रह" न करें। लेकिन न्यायपालिका

की नियुक्ति को रोकने के लिए वीटो शक्ति को बनाए रखना जारी रखा
लिए अयोग्य माना जाता है। के अनुसार

एक व्यक्ति जिसे नियुक्ति के

उसे, एक उम्मीदवार का नामांकन, नियुक्ति के लिए

उपरोक्त निर्णयों के तहत उच्च न्यायपालिका भी ऐसा नहीं कर सकती।

फलदायी, यदि कॉलेजियम के किसी भी दो सदस्यों ने एक व्यक्ति किया

नामित उम्मीदवार के खिलाफ राय। यह बताया गया था,

कि उपरोक्त स्थिति को विवादित में बनाए रखा गया था
 प्रावधान। विद्वान महान्यायवादी के अनुसार, केवल विवादित प्रावधानों में अंतर यह था कि
 न्यायपालिका द्वारा नामित व्यक्ति की नियुक्ति पर "जोर" देना, नहीं था
 न्यायपालिका के लिए अधिक समय तक उपलब्ध। कॉलेजियम प्रणाली के तहत,
 उच्च पद पर नियुक्ति के लिए की गई सिफारिश
 न्यायपालिका, कार्यपालिका द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस की जा सकती है।
 हालाँकि, यदि सिफारिश को दोहराया जाता है, तो कार्यपालिका के पास अनुशंसित नामांकित व्यक्ति को
 नियुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह.
 इंगित किया गया था कि "आग्रह" करने का तत्काल अधिकार
 54 आकाशवाणी 1958 एससी 731

55 1952 एससीआर 284 [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक न्यायाधीश की नियुक्ति, अब एन. जे. ए. सी. में निहित थी। यह.
 जोरदार रूप से तर्क दिया गया था, कि "आग्रह" करने से इनकार, पर
 न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करता है। द. "न्यायपालिका की स्वतंत्रता", विद्वानों के अनुसार
 महान्यायवादी, अच्छी तरह से संरक्षित किया जाएगा, अगर एक नामित व्यक्ति को "अस्वीकार" करने का
 अधिकार न्यायपालिका के पास संरक्षित किया गया था, जो था
 किया।

74. उपरोक्त निवेदन के आधार पर, यह दावा किया गया था,
 कि 1990 में संसद द्वारा शुरू की गई प्रक्रिया (के लिए
 न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक आयोग की शुरूआत
 उच्च न्यायपालिका) को फलने-फूलने में चौबीस साल लग गए थे। द.
 संविधान के माध्यम से प्रस्तुत एन. जे. ए. सी. की संरचना
 (99 उनका संशोधन) अधिनियम, उनके अनुसार, सभी के साथ मिलता है

संवैधानिक आवश्यकताएँ, क्योंकि वे न तो उल्लंघन में हैं

"शक्तियों के पृथक्करण" के नियम का, न ही "का

न्यायपालिका की स्वतंत्रता"। यह तर्क दिया गया था कि संरक्षित करते हैं

विवादित प्रावधान "मूल संरचना" को

संविधान।

75. यह प्रस्तुत किया गया था कि हमला किए गए प्रावधानों में था

केवल सही नियंत्रण और संतुलन पेश किए गए, जो अंतर्निहित हैं

एक प्रभावी संवैधानिक व्यवस्था के घटका द. विद्वान महान्यायवादी ने भी इस न्यायालय को आगाह किया,

यह कहते हुए कि यह न तो याचिकाकर्ताओं के अधिकार क्षेत्र में था,

न ही इस न्यायालय का, एक वैकल्पिक संयोजन का सुझाव देने के लिए

एन. जे. ए. सी. के सदस्य, या एक वैकल्पिक प्रक्रिया, जो

इसके कामकाज को अधिक प्रभावी ढंग से विनियमित करेगा। जहाँ तक

वर्तमान याचिकाओं का संबंध है, यह दावा किया गया था कि

उसमें उठाई गई चुनौती को केवल तभी स्वीकार किया जा सकता था जब वह संसद अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग करते हुए

दिखाया कि

संविधान में संशोधन करने के लिए, "मूल संरचना" का उल्लंघन किया था

संविधान से।

76. यह प्रस्तुत किया गया था कि यह किसी का मामला नहीं था

इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता, या तो कि संसद सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता थे-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

अनुच्छेद 124 में संशोधन करने के लिए सक्षम नहीं है, या कि प्रक्रिया

अनुच्छेद 368 के तहत इसके लिए निर्धारित का पालन नहीं किया गया था।

मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में, यह प्रस्तुत किया गया था कि केवल

वर्तमान के संदर्भ में परीक्षा की गुंजाइश

संवैधानिक संशोधन था, चाहे बनाते समय

संविधान संशोधन, संसद ने किया था

संविधान की किसी भी "बुनियादी विशेषताओं" का उल्लंघन किया गया है।

77 (1). आक्षेपित की वैधता को प्रदर्शित करने के लिए

संवैधानिक संशोधन, पहली बार में निर्भरता थी

एस. एम. सीकरी, सी. जे. की टिप्पणियों पर किया गया।, विरोध करने के लिए, कि
के तहत संशोधन शक्ति की सीमा विधिवत थी

अनुच्छेद 368

के लिए विज्ञापित। संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हुए, यह था

इंगित किया कि मौलिक महत्व व्यक्त किया गया है

इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता और अविभाज्यता थी।

आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के साथ-साथ

निदेशक सिद्धांतों का महत्व (पैराग्राफ 282)। इसमें

पक्ष से, यह भी प्रस्तुत किया गया था कि "मौलिक विशेषताएं"

संविधान, उदाहरण के लिए, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और

राज्य (अनुच्छेद 283)। इस निष्कर्ष की ओर अग्रसर करते हुए कि मौलिक अधिकारों को भी जनहित में
संशोधित किया जा सकता है, विषय प्रबल स्थिति के लिए, कि वही नहीं हो सकता है

पूरी तरह से निरस्त (पैराग्राफ 287)। इस संबंध में यह यह भी बताया कि संशोधन करने के
लिए संसद का विवेक

संविधान न्यायिक समीक्षा का विषय नहीं हो सकता था

(पैराग्राफ 288), जिससे समग्र निष्कर्ष निकलता है, कि

संशोधन की प्रक्रिया, यह संसद के लिए मौलिक अधिकारों को समायोजित करने के लिए खुला था, ताकि
इसकी उपलब्धि को सुरक्षित किया जा सके

निर्देशक सिद्धांत, स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए और

प्रत्येक नागरिक की गरिमा (अनुच्छेद 289)। इस प्रकार देखा गया कि

महसूस किया, कि सही कानूनी व्याख्या होगी, कि भले ही

संविधान के प्रत्येक प्रावधान में संशोधन किया जा सकता है,

विचाराधीन संशोधन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि "बुनियादी सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट"

[2015] 13 एस सी आर।

संविधान की नींव और संरचना अक्षुण्ण रही।

इस संबंध में, विशेषताओं के लिए एक सचित्र संदर्भ दिया गया था, जो संविधान की "मूल संरचना" का गठन करता था।

विद्वान महान्यायवादी के अनुसार, उनमें संविधान, गणराज्य और लोकतांत्रिक की सर्वोच्चता शामिल थी

सरकार का रूप, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, विधायिका के बीच "शक्तियों का पृथक्करण",

संविधान (अनुच्छेद 292)। उपरोक्त के अलावा, यह था जोर देकर कहा कि भारत ने सार्वभौमिक घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं

मानवाधिकारों के, इस तरह के बनाए रखने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया था मौलिक अधिकार, जैसा कि उपरोक्त में शामिल किए गए थे

घोषणा (अनुच्छेद 299)। उपरोक्त दृष्टिकोण के अनुसार,

महान्यायवादी, अभिव्यक्ति "इसका संशोधन"

संविधान "संसद को निरस्त करने से रोकेगा

मौलिक अधिकार पूरी तरह से, या पूरी तरह से बदलते हुए संविधान की "मूलभूत विशेषताएँ", ताकि उन्हें नष्ट किया जा सके

उसकी पहचान। और यह कि, उपरोक्त सीमा के भीतर, संसद

संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद (पैराग्राफ 475) में संशोधन कर सकते हैं।

इस बात पर जोर दिया गया कि विवादित प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हुआ है

उपरोक्त सीमाओं में से कोई भी।

((ii) तब आम राय का संदर्भ दिया गया था।

जे. एम. शेल्ट और ए. एन. ग्रोवर, जे. जे. द्वारा व्यक्त किया गया। , (में

केशवानंद भारती मामले 1) यह दावा करने के लिए कि

संविधान में संशोधन के संबंध में सीमाएँ यह था कि इसे इस हद तक संशोधित नहीं किया जा सकता था, जो इसकी पहचान के संविधान को अस्वीकार कर दे (पैराग्राफ 537)। यह था।

प्रस्तुत किया, कि संशोधन करने की शक्ति, के परिणामस्वरूप नहीं हो सका

संविधान को निरस्त करना, या एक नए संविधान के निर्माण की ओर ले जाना
आवश्यक तत्वों को बदलना या बदलना

संविधान, या

संवैधानिक संरचना (अनुच्छेद 539)। यह इंगित किया गया था

बाहर, कि यह उचित नहीं था, एक संकीर्ण अर्थ देने के लिए

संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद में निहित है, और
देने के लिए, ताकि सर्वोच्च न्यायालयों-ऑन-रिकॉर्ड के लिए

उसी समय, इसे इतना व्यापक अर्थ

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

संरचना और पहचान को बदलने के लिए, संशोधन निकाय को सक्षम करें

संविधान (अनुच्छेद 546)। न्यायिक समीक्षा की शक्ति के संदर्भ में, यह तर्क दिया गया था कि पर्याप्त था

स्वयं संविधान में साक्ष्य, यह इंगित करने के लिए कि एक प्रणाली

"चेक और बैलेंस का प्रावधान किया गया था, ताकि कोई भी

शासन के स्तंभ इतने प्रबल हो जाएंगे कि

व्यायाम और निर्वहन से दूसरों को अक्षम करें उन्हें सौंपे गए कार्य। यह प्रस्तुत किया गया था कि
अनुच्छेद 32 और 226 के माध्यम से स्पष्ट रूप से प्रदान की गई न्यायिक समीक्षा

नियंत्रण और संतुलन की वन प्रणाली की एक घटना (अनुच्छेद 577)। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर
आधारित,

प्रस्तावना, संविधान की पूरी योजना, और अन्य अनुच्छेद 368 सहित इसके प्रासंगिक प्रावधानों में
यह प्रस्तुत किया गया था कि यह अनुमान लगाया जा सकता है कि

संविधान, गणराज्य और लोकतांत्रिक रूप

विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच, मौलिक अधिकारों के माध्यम से प्राप्त व्यक्ति की
गरिमा,

और एक कल्याणकारी राज्य के निर्माण का अधिदेश (भाग III में निहित)

और IV), और राष्ट्र की एकता और अखंडता, हो सकती है

संवैधानिक संरचना के "बुनियादी तत्वों" के रूप में माना जाता है

(पैरा 582)। यह भी कहा गया था कि जैसे-जैसे समाज बढ़ता है,

इसकी आवश्यकताएँ बदलती हैं, और तदनुसार, संविधान और

उभरती जरूरतों के अनुरूप कानूनों को बदलना होगा। और
तदनुसार, संविधान में संशोधन की आवश्यकता, अनुकूलन करने के लिए
बदलती जरूरतों के लिए, उत्पन्न होता है। इसी तरह, निदेशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए, कुछ को कम
करना आवश्यक हो सकता है।
नागरिकों में निहित मौलिक अधिकारों का। की शक्ति
उपरोक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक, एक व्यापक और उदार
अनुच्छेद 368 की व्याख्या। ऐसा अभिनिर्धारित करने के बाद, यह निष्कर्ष निकाला गया कि मौलिक
अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है (अनुच्छेद
634)। इस तथ्य का संदर्भ दिया गया था कि संस्थापक पिता
अगर आप जानते हैं कि बदलती दुनिया में कुछ भी नहीं होगा
स्थायी, और इसलिए; उन्होंने [2015] 13 एस. सी. आर. की शक्ति निहित की।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट
अनुच्छेद 368 के माध्यम से संसद में संशोधन, ताकि
संविधान को बदलती अवधारणाओं के अनुरूप रखें
राजनीति, अर्थशास्त्र और सामाजिक विचारों, और इस तरह के नए आकार देने के लिए
संविधान, जो उस समय की आवश्यकताओं को पूरा करेगा
(अनुच्छेद 637)। उपरोक्त के संदर्भ में, यह था
तर्क दिया कि संसद के पास शक्ति नहीं थी "बुनियादी तत्वों" या "मौलिक तत्वों" को निरस्त या
समाप्त करें।
संविधान की विशेषताएं, जैसे कि भारत की संप्रभुता,
हमारी राजनीति का लोकतांत्रिक चरित्र, देश की एकता,
और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं के आवश्यक तत्वों को सुरक्षित किया गया
नागरिकों के लिए। उपरोक्त सीमाओं के बावजूद, यह इंगित किया गया था
कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करने की शक्ति व्यापक थी

पर्याप्त, संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद में संशोधन करने के लिए, ताकि लागू हुए दायित्वों को पूरा करने के लिए संविधान को नया रूप दें

राज्य (अनुच्छेद 666)। और तदनुसार, यह इंगित किया गया था, कि निष्कर्ष अभिलिखित करते समय, इस न्यायालय ने कहा था कि

अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति थी

बहुत व्यापक, फिर भी नष्ट करने की शक्ति शामिल नहीं थी, या संविधान के "बुनियादी तत्वों" या "मौलिक विशेषताओं" को समाप्त करें (पैराग्राफ 744)।

(iii)। इसके बाद एच. आर. खन्ना, जे. (केशवानंद भारती मामले में) की टिप्पणियों का संदर्भ दिया गया। यह था।

इंगित किया कि 1950 से 1967 तक इस न्यायालय ने

आई. सी. गोलक नाथ मामले में निर्णय, स्वीकृत स्थिति

यह था कि संसद के पास इसके भाग III में संशोधन करने की शक्ति थी

संविधान, ताकि मौलिक को हटाया या संक्षिप्त किया जा सके

अधिकार। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि संसद द्वारा मौलिक अधिकारों को छीनने या कम करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था,

किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी स्वतंत्रता से संबंधित

अभिव्यक्ति, यह दर्ज किया गया था, कि भविष्य में भी ऐसा नहीं किया जा सकता था। तदनुसार, अनुच्छेद 368 के संदर्भ में, यह माँगा गया था यह निष्कर्ष निकालना कि संसद के पास संशोधन करने की शक्ति थी

संविधान का भाग III, जब तक की "मूल संरचना"

संविधान को बरकरार रखा गया (पैराग्राफ 1421)।

यदि "बुनियादी सर्वोच्च न्यायालय के वकील-चालू-रिकॉर्ड करते हैं"

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

मूल संविधान की संरचना को बरकरार रखा गया था

जैसा कि मूल संविधान बना रहा, यहाँ तक कि

हालांकि इसके कुछ प्रावधानों को बदल दिया गया था, की शक्ति

संशोधन को वैध रूप से माना जाएगा

प्रयोग किया गया (पैरा 1430)। और इसलिए, वास्तविक प्रभाव

अनुच्छेद 368 होगा, कि संविधान के साथ निहित नहीं था संसद, एक अलग संरचना के साथ एक नए और मौलिक रूप से परिवर्तित संविधान का मसौदा तैयार करने की शक्ति या प्राधिकरण और

रूपरेखा (पैराग्राफ 1433)। तदनुसार, के अधीन

"मूल संरचना या ढांचे" का प्रतिधारण

संविधान, संसद के पास संशोधन करने की शक्ति

संविधान को पूर्ण माना जाता था, और इसमें संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को जोड़ने, बदलने या निरस्त करने की शक्ति शामिल होगी।

मौलिक अधिकारों से संबंधित संविधान सहित। सभी

उपरोक्त उपायों को संसद की शक्ति में शामिल किया गया था।

संशोधन का, और इस तरह के एक व्यापक और इनकार व्यापक शक्ति, में कठोरता का परिचय देगा

संविधान, जैसा कि संविधान को ही तोड़ देगा (अनुच्छेद

1434)। इस प्रकार, यह अभिनिर्धारित किया गया कि संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई

अनुच्छेद 368 द्वारा, संशोधन करने की शक्ति शामिल होगी

संविधान के भाग III में निहित मौलिक अधिकार

(पैरा 1435)। इस संबंध में यह दावा किया गया कि इस मुद्दे पर, क्या प्रस्तुत किया गया संशोधन होगा (या नहीं)

प्रचलित स्थिति में सुधार, नहीं था

न्यायसंगत। यह दावा किया गया था कि क्या संशोधन होगा

सुधार हो या न हो, यह केवल संसद के लिए था

विधायिका, अपनी दूरदर्शिता, विवेक और समझ से (पैरा 1436)। इस बात पर जोर दिया गया कि संसद की संशोधन शक्ति में विधायी अधिनियम बनाने का अधिकार होना चाहिए

प्रयोग और परीक्षण के लिए प्रावधान, ताकि अंततः सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त किए जा सकें (पैराग्राफ 1437)। अंतिम विश्लेषण में, यह

यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संविधान के संशोधन में व्यापक

और व्यापक अर्थ, और अपने भीतर, सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट को गले लगाएंगे

[2015] 13 एस सी आर।

कुछ अनुच्छेदों का पूर्ण निरसन, या नए द्वारा उनके प्रतिस्थापन

लेख, जो सुसंगत नहीं हो सकते हैं, या अन्य के अनुरूप नहीं हो सकते हैं लेख। और एक न्यायालय एक की वैधता का निर्णय करते हुए

संशोधन, केवल इस प्रश्न से संबंधित हो सकता है, जैसे कि

क्या बनाने के लिए संवैधानिक आवश्यकताएँ

क्या संशोधन संतुष्ट था? और तदनुसार, एक प्रक्रिया के अनुरूप किया गया संशोधन

निर्धारित, नीचे मारा नहीं जा सका, इस आधार पर कि यह

सबसे खराब के लिए एक परिवर्तन था (पैराग्राफ 1442)। जाँच करते समय

सवाल यह है कि क्या संपत्ति के अधिकार को इसमें शामिल किया जा सकता है

संविधान की "मूल संरचना या ढांचा",

दिया गया जवाब नकारात्मक था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायालयों को

सरकार की व्यावहारिक आवश्यकताओं से अनजाना और कि, संशोधन की शक्ति का प्रयोग परीक्षण के लिए भी किया जा सकता है और

वृद्धि, क्योंकि न्याय साबित करने के लिए अवसर की अनुमति दी जानी थी

अनुभव द्वारा उचित विश्वास (पैराग्राफ 1535)। यह था।

तर्क दिया, कि किसी भी पीढ़ी का ज्ञान पर एकाधिकार नहीं था, न ही

आने वाली पीढ़ियों पर बंधन लगाने का अधिकार, न ही ढालने का अधिकार

शाश्वत भलाई को ध्यान में रखते हुए सरकारी तंत्र।

संभावना, कि संशोधन की शक्ति का दुरुपयोग किया जा सकता है,

इसके अस्तित्व से इनकार करने के लिए कोई आधार नहीं दिया गया। के अनुसार

महान्यायवादी, इसलिए यह मान लेना सही नहीं था,

कि यदि संसद को इसके भाग III में संशोधन करने का अधिकार दिया गया था

संविधान, यह स्वचालित रूप से और आवश्यक रूप से परिणाम देगा

मौलिक अधिकारों का उन्मूलन। समापन करते हुए, कि

संपत्ति का अधिकार संविधान की "मूल संरचना या ढांचे" से संबंधित नहीं था, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि

अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन में शक्ति शामिल नहीं थी

संविधान को निरस्त करना, या मूल संरचना में परिवर्तन करना या

संविधान का ढांचा। इस निष्कर्ष पर पहुँचने के बावजूद,

यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मौलिक अधिकारों का कोई भी हिस्सा दावा नहीं कर सकता है

संशोधन की शक्ति से प्रतिरक्षा (पैराग्राफ 1537)।

78. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड दिए गए निर्णयों का संदर्भ दिया गया।

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

इस न्यायालय द्वारा इंदिरा नेहरू गांधी बनाम. राज नारायण 56, वामन

राव वी. भारत संघ और एम. नागराज मामले 3 6, का प्रतिवाद करने के लिए,

कि संविधान की "मूल संरचना" का निर्धारण उन विशेषताओं के आधार पर किया जाना था जो संविधान में मौजूद थीं। संविधान के मूल अधिनियम का पाठ, उस तारीख को

इसे लागू करने के लिए। अतः यह इंगित किया गया कि संविधान में बाद के संशोधन, नहीं हो सके

"बुनियादी विशेषताओं" को निर्धारित करने के लिए, ध्यान में रखा गया

संविधान।

79. वनाच्छादित नींव रखने के बाद, विद्वान महान्यायवादी ने प्रस्तुत किया कि वह संदर्भ कर सकता है

केवल अनुच्छेद 124 और 217 में बनाया जाए, जैसा कि वे मूल रूप से करते हैं।

अस्तित्व में था, जब संविधान लागू किया गया था। अगर मूल

प्रावधानों को ध्यान में रखा जाना था, जिसके अनुसार

विद्वान महान्यायवादी, यह स्पष्ट होगा कि

"न्यायपालिका की सलाहकार भागीदारी, में थी कार्यपालिका का निर्धारक क्षेत्र। यह बताया गया था कि

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय पर,

कॉलेजियम प्रक्रिया के माध्यम से भारत के मुख्य न्यायाधीश की प्रधानता स्वयं न्यायपालिका का एक नवाचार था (द्वितीय सत्र में)।

न्यायाधीशों का मामला)। उपरोक्त प्रधानता, प्रावधानों के लिए विदेशी थी

संविधान, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था। और इस प्रकार, अनुच्छेद 124 में संशोधन और अनुच्छेद 124 ए को शामिल करना।

124 सी तक, के टचस्टोन पर जांच नहीं की जा सकी

सामग्री, जो अनुच्छेद 124 और 217 (जैसा कि वे मूल रूप से अधिनियमित किए गए थे) के सादे पठन के बिल्कुल विपरीत थी। यह था।

तदनुसार जोर देकर कहा कि वर्तमान चुनौती संविधान (99 वां संशोधन) अधिनियम, के अंतर्गत नहीं आएगा

उनके द्वारा व्यापक रूप से विस्तृत (जैसा कि हमारे द्वारा दर्ज किया गया है, 56 (1975) एस. सी. सी. 57 (1981) 2 एस. सी. सी. 362 [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ऊपर)। याचिकाकर्ताओं द्वारा तत्काल की गई प्रार्थनाएँ

इसलिए विद्वान वकील के अनुसार आधार थे जनरल, अस्वीकार किए जाने योग्य।

80. अब तक की यात्रा करने के बाद, यह बताया गया था कि यह

के वास्तविक उद्देश्य और प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण था

"न्यायपालिका की स्वतंत्रता" शब्द। इस संबंध में, प्रथम

उदाहरण के लिए, न्यायालय का ध्यान प्रथम न्यायाधीशों की ओर आकर्षित किया गया था

मामला, जिसमें व्यक्त राय का संदर्भ दिया गया था

ई. एस. वेंकटरमैया, जे. (जैसा कि वे तब थे), जिन्होंने लिया था

यह मत कि यह मानना कठिन था, कि केवल इसलिए कि नियुक्ति की शक्ति कार्यपालिका के पास थी,

ऐसा कहते हुए, इस बात पर जोर दिया गया कि सही सिद्धांत यह था कि ऐसी नियुक्ति के बाद, कार्यपालिका के पास कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए,

न्यायाधीश के कार्य में हस्तक्षेप करना (पैराग्राफ 1033)। आधारित

उस पर यह दावा किया गया कि एक न्यायाधीश की स्वतंत्रता

समझौता नहीं होगा, अगर उनकी नियुक्ति के बाद,
 भगवती, जे. (जैसा कि वे तब थे) (उसी निर्णय में), प्रभाव, कि "न्यायपालिका की स्वतंत्रता" की
 अवधारणा थी
 केवल कार्यकारी दबाव से स्वतंत्रता तक ही सीमित नहीं /
 प्रभाव, लेकिन कई अन्य दबावों से संबंधित था और
 पूर्वाग्रह। और इतनी रिकॉर्डिंग में, यह आयोजित किया गया था, कि
 "न्यायपालिका की स्वतंत्रता में निर्भीकता शामिल थी
 अन्य शक्ति केंद्र, आर्थिक या राजनीतिक, और सत्ता से स्वतंत्रता
 उस वर्ग द्वारा अर्जित और पोषित पूर्वाग्रह जिसके लिए
 न्यायाधीश संबंधित थे (पैराग्राफ 1037)। इसके आधार पर, यह था
 जोर देकर कहा कि "न्यायपालिका की स्वतंत्रता", शामिल है
 अन्य न्यायाधीशों के प्रभाव से भी स्वतंत्रता। और इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला गया कि एन.
 जे. ए. सी. की संरचना
 ऐसा था, जो न्यायाधीशों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगा
 उच्च न्यायपालिका में नियुक्त, जैसा कि प्रथम में विचार किया गया है न्यायाधीशों का मामला।

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. /जगदीश सिंह खेहर, जे।/

81. "स्वतंत्रता" के मुद्दे के साथ संयोजन में

न्यायपालिका ", जो "शक्तियों के पृथक्करण "की अवधारणा से बाहर निकलती है, यह बताया गया कि संविधान की योजना

नियंत्रण और संतुलन की एक प्रणाली की परिकल्पना की। जैसे-जैसे, शासन के प्रत्येक अंग को स्वतंत्रता दी जा रही है

उसे सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन, नियंत्रण के अधीन था, अन्य अंगों में से एक के हाथों में, या दोनों अन्य अंगों के हाथों में। सचित्र रूप से, यह तर्क देने की कोशिश की गई थी कि सभी

कार्यकारी प्राधिकारी, न्यायिक समीक्षा के माध्यम से जांच के अधीन है

(न्यायपालिका के हाथों में)। इसी तरह, कानून बनाया गया संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा भी

न्यायिक समीक्षा, (न्यायपालिका के हाथों में)। बावजूद इसके, करने की स्वतंत्रता है

कार्यपालिका और विधायिका को कार्य

और अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों का निर्वहन, बिना भी

शासन के अन्य अंगों द्वारा हस्तक्षेप, फिर

न्यायपालिका को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि

कार्यकारी और विधायी कार्यों का अभ्यास, में है

कानून के साथ सामंजस्य। इसी तरह, यह प्रस्तुत किया गया था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में, अनुच्छेद 124 और 217

और संतुलन। यह प्रस्तुत किया गया था कि तत्काल योजना कर दिया गया था

चेक और बैलेंस, दूसरे द्वारा समाप्त

और तीसरे न्यायाधीशों के मामले, की नियुक्ति के मामले में

उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीश। यह दावा किया गया था कि स्थिति

नियंत्रण और संतुलन को संविधान द्वारा बहाल किया गया है कार्यपालिका की भूमिका को कम करके,

(99 संशोधन) अधिनियम,

उस स्थिति से जो प्रारंभ में मौजूद थी

संविधान। केशवनंद में लिए गए निर्णयों का उल्लेख करते हुए गांधी मामला 56,

भारती मामला 10, इंदिरा नेहरू

संकलचंद हिम्मतलाल सेठ मामले, आसिफ हमीद बनाम। की स्थिति

जम्मू और कश्मीर 58, बिहार राज्य बनाम। बिहार डिस्टिलरी बनाम। भारत संघ 13, यह प्रस्तुत किया गया था,

सीमित 59, और भीम सिंह

कि इस न्यायालय ने मान्यता दी थी कि जाँच की अवधारणा और

58 1989 पूरक (2) एस. सी. सी. 364

59 (1997) 2 एससीसी 453 [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संतुलन, संविधान की योजना में निहित था। और

कि, भले ही विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका

सीमांकित अपने क्षेत्रों के भीतर कार्य करने की आवश्यकता थी
 संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से, फिर भी उनकी विशेषताएँ
 कभी भी पूर्ण रूप से नहीं हो सकता था। यह प्रस्तुत किया गया था कि प्रत्येक
 शासन की शाखा को जवाबदेह होना था, और सिद्धांत तक जवाबदेही को संरक्षित किया गया था,
 "अलगाव" का सिद्धांत
 शक्तियों की प्राप्ति संभव नहीं होगी। इसलिए यह
 तर्क दिया कि "न्यायपालिका की स्वतंत्रता" की अवधारणा,
 एक पूर्ण अंत के रूप में नहीं आंका जा सकता है,
 योजना में दिए गए चेक और बैलेंस संविधान।

82. इस प्रकार दावा करने के बाद, यह तर्क दिया गया था कि
 उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला,
 सबसे महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि कोई भी अयोग्य या संदिग्ध नियुक्ति नहीं होनी चाहिए,
 भले ही
 कई बार, एक अच्छे उम्मीदवार की उम्मीदवारी, हो सकता है
 स्वीकार नहीं किया जाता। यह दावा किया गया था कि एनजेएसी ने प्रदान किया था
 पूर्ण सुरक्षा के लिए, यहाँ ऊपर देखे गए अर्थ में,
 नियुक्ति की प्रक्रिया में यह प्रावधान करके कि एक नकारात्मक
 एन. जे. ए. सी. के दो सदस्यों में से किसी एक द्वारा व्यक्त किया गया विचार,
 जिसके परिणामस्वरूप संबंधित उम्मीदवार को अस्वीकार कर दिया जाता है। इसलिए,
 एन. जे. ए. सी. के केवल दो सदस्य, वीटो के लिए पर्याप्त होंगे।
 नियुक्ति का प्रस्ताव। यह प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि एन. जे. ए. सी. के तीन सदस्य सर्वोच्च न्यायालय के
 न्यायाधीश थे,
 एन. जे. ए. सी. में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेगी कि
 "न्यायपालिका की स्वतंत्रता पूरी तरह से बनी रही।
 सुरक्षित और सुरक्षित। इसलिए यह तर्क दिया गया कि न केवल संविधान (99 वां संशोधन)
 अधिनियम, बल्कि एन. जे. ए. सी. अधिनियम भी स्वतंत्रता मानदंड को पूरी तरह से संतुष्ट करता है।
 संविधान की "बुनियादी संरचना" के रूप में।

83. उपरोक्त स्थिति को दोहराने के लिए, यह था

जोर देकर कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में प्रधानता
उच्च न्यायपालिका के लिए, संविधान में विचार नहीं किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे. जे.

जैसा कि मूल रूप से बनाया गया था। इस संबंध में, संदर्भ दिया गया था कि

अनुच्छेद 124 और 217। और इसके साथ संयोजन में, विज्ञापन

संविधान के सदस्यों द्वारा इस विषय पर बहस करने के लिए

सभा। इसके बाद, यह दावा किया गया कि प्रधानता का मुद्दा

मुख्य न्यायाधीश के कॉलेजियम के निर्णय के आधार पर न्यायाधीश, एक न्यायिक नवाचार था,
जिसकी आवश्यकता थी

और तीसरे न्यायाधीशों के मामले, व्याख्या पर आधारित थे संविधान के अनुच्छेदों, जिन्हें तब से
संशोधित किया गया था,

याचिकाकर्ताओं के हाथों दलीलें आगे बढ़ीं। इसके अलावा, भले ही इस न्यायालय द्वारा दर्ज किया
गया अनुपात

दूसरे और तीसरे न्यायाधीशों के मामलों को अभी भी लिया जाना था

विचार, निष्कर्ष (5), (6) और (7) जे. एस. वर्मा, जे. (जिन्होंने बहुमत के विचार की प्रतिलिपि बनाई
थी), बताते हैं कि

न्यायपालिका की प्रधानता यह सुनिश्चित करना था कि कोई नियुक्ति न हो

उच्च न्यायपालिका को भेजा जा सकता था, जब तक कि इसकी मंजूरी न हो

कॉलेजियम से। यह प्रस्तुत किया गया था कि तत्काल पहलू, जो "स्वतंत्रता" सुनिश्चित करने के लिए कार्यात्मक
आधार का गठन करता है। न्यायपालिका को विवादित संवैधानिक संशोधन और एन. जे. ए. सी.
अधिनियम में संरक्षित किया गया था। यह तदनुसार था

प्रतिवाद किया कि यदि एक की नियुक्ति पर जोर देने का अधिकार

न्यायाधीशों के), उसी का परिणाम नहीं होगा, के नपुंसकता में संविधान की "मूल संरचना"। दूसरे
शब्दों में,

वही "आवश्यक और मौलिक" का उल्लंघन नहीं करेगा।

संविधान की विशेषताएँ, और न ही कम से कम, स्वतंत्रता

न्यायपालिका का "।

84. उपरोक्त प्रस्तुतियों के आधार पर, विद्वान

महान्यायवादी ने याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक तर्क की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया, अर्थात्, भले ही सभी [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीश जो अब पदेन हैं

एन. जे. ए. सी. के सदस्यों ने सामूहिक रूप से एक नामांकित व्यक्ति की सिफारिश की, ऐसी सिफारिश को गैर-न्यायाधीश द्वारा रद्द किया जा सकता है।

एनजेएसी के सदस्य। विद्वान महान्यायवादी ने प्रस्तुत किया,

कि उपरोक्त विवाद "आग्रह" करने के अधिकार तक सीमित था

एक नियुक्ति। और यह कि "आग्रह" करने का अधिकार यहाँ से नहीं आया

द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों में अभिलिखित निष्कर्ष

मामले। और इसके अलावा, कि उसी को अपने आप में नहीं लिया जा सकता है

की स्वतंत्रता के उल्लंघन को स्थापित करने के लिए एक घटना

न्यायपालिका "।

85. जहाँ तक दूसरे और तीसरे न्यायाधीशों के मामलों का संबंध है,

संबंधित, यह प्रस्तुत किया गया था, कि वही हो सकता है

समय की आवश्यकता, इस तथ्य के कारण कि 1976 में, सोलह

न्यायाधीशों का स्थानांतरण (उन उच्च न्यायालयों से जिनमें वे

काम कर रहे थे), अन्य उच्च न्यायालयों के लिए। सांकलचंद में

स्थानांतरित न्यायाधीशों में से एक, हिम्मतलाल सेठ के मामलों को चुनौती दी गई

उसका स्थानांतरण, अन्य बातों के साथ-साथ, इस आधार पर कि उसकी गैर-सहमति

स्थानांतरण अनुच्छेद 222 के दायरे से बाहर था, क्योंकि

"न्यायपालिका की स्वतंत्रता" पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

दिए गए दृढ़ संकल्प के बावजूद, चुनौती पर

यह संकेत दिया गया था कि यह मामला संकलचंद हिमतलाल सेठ के मामलों में उठाया गया था

बाहर, वही सवाल पहले में फिर से उत्तेजित होने लगा न्यायाधीशों का मामला। अनुच्छेद 222 की व्याख्या करते हुए बहुमत ने यह अभिनिर्धारित किया कि न्यायाधीश की सहमति को स्थानांतरित किया जा रहा है,

प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। यह भी बताया गया था कि तब से

संविधान की स्थापना, मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय

भारत के, सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा कब्जा कर लिया गया था सुप्रीम कोर्ट। उपरोक्त सिद्धांत को हटा दिया गया था

अप्रैल 1973 में, अगले सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में-जे. एम. शेलट थे।

भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत नहीं हुए, यहां तक कि उनके बाद अगले दो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश-के. एस. हेगड़े और

ए. एन. गोवर को भी नजरअंदाज कर दिया गया। द्वारा तत्काल अधिगमन

चौथे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश-ए. एन. रे की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं के लिए एक खतरे के रूप में देखा गया-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

"न्यायपालिका की स्वतंत्रता"। फिर से जनवरी 1977 में, ए. एन. रे, सी. जे. की सेवानिवृत्ति पर।, सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश तुरंत

उनके बगल में-H. R. खन्ना को नजरअंदाज कर दिया गया और दूसरे वरिष्ठ

अधिकांश न्यायाधीश-एम. एच. बेग को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।

न्यायपालिका का "। यह उपरोक्त पृष्ठभूमि में था कि इस न्यायालय ने दूसरे और तीसरे न्यायाधीशों के मामलों को प्रस्तुत किया, लेकिन न्यायाधीशों की नियुक्ति के तरीके का कार्यान्वयन

उच्च न्यायपालिका, उसके अनुरूप, विषय थी के लिए, भारी और चारों ओर आलोचना, होने सहित

जे. एस. वर्मा, सीजे द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी की गई।, के लेखक

द्वितीय न्यायाधीशों के मामले में बहुमत का दृष्टिकोण, उनके बाद

सेवानिवृत्ति। इस संबंध में न्यायालय का ध्यान आकर्षित करने के लिए आमंत्रित किया गया था -

उनकी टिप्पणियाँ, जो यहाँ निकाली गई हैं:

"मेरे 1993 के फैसले को बहुत गलत समझा गया और उसका दुरुपयोग किया गया। इस संदर्भ में, मैं

कहा कि निर्णय का कार्य, अब, कुछ समय के लिए,

गंभीर सवाल उठा रहा है, जिसे अनुचित नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, किसी प्रकार के पुनर्विचार की आवश्यकता है।

मेरा निर्णय कहता है कि उच्च न्यायालय की नियुक्ति प्रक्रिया और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश मूल रूप से एक संयुक्त या

कार्यपालिका और कार्यपालिका के बीच भागीदारी अभ्यास

न्यायपालिका, दोनों इसमें भाग ले रहे हैं।

इसलिए यह तर्क दिया गया कि बदले हुए परिदृश्य में,

इस न्यायालय को अपने दम पर ऐसे उपाय करने चाहिए थे -

प्रचलित प्रणाली के खिलाफ लगाए गए आरोपों को नकारें,

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति। चूंकि नहीं

इस तरह के उपचारात्मक उपायों को न्यायपालिका द्वारा अपनाया गया था

स्वयं, विधायिका ने संविधान लाया था (99 वां)

संशोधन) अधिनियम, एन. जे. ए. सी. अधिनियम द्वारा पूरक, व्यापक रूप से चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया को आधार बनाना

न्यायाधीशों के

उच्च न्यायपालिका, इसे पारदर्शी बनाने और प्रतिभागियों को जवाबदेह बनाने के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

86. मामले के संवैधानिक पहलू से निपटने के बाद, विद्वान महान्यायवादी ने न्यायालय के

जिस तरह से न्यायिक नियुक्तियों की गई थीं, उस पर ध्यान दें।

पंद्रह देशों में बनाया जा रहा है। यह प्रस्तुत किया गया था कि नौ में

देशों में न्यायाधीशों की नियुक्ति या तो न्यायिक नियुक्ति आयोग (केन्या, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और अन्य) के माध्यम से की जाती थी।

यू. के.), या समिति (इज़राइल), या परिषदें (फ्रांस, इटली, नाइजीरिया)

और श्रीलंका)। चार देशों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई

सीधे गवर्नर जनरल (ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यू यॉर्क) द्वारा जीलैंड), या राष्ट्रपति (बांग्लादेश)। यह प्रस्तुत किया गया था,

कि जर्मनी में न्यायाधीशों की नियुक्ति न्याय मंत्री द्वारा नामांकन की एक बहु-चरणीय प्रक्रिया के माध्यम से की गई थी,

और संसदीय समितियों द्वारा पुष्टि, जिसके बाद,

संबंधित व्यक्ति की नियुक्ति का अंतिम आदेश है -

राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में, न्यायाधीशों की नियुक्ति नामांकन की प्रक्रिया के माध्यम से की गई थी

राष्ट्रपति, और सीनेट द्वारा पुष्टि। यह था।

प्रस्तुत किया कि ऊपर निर्दिष्ट सभी पंद्रह देशों में, कार्यपालिका अंतिम निर्धारक/नियुक्ति प्राधिकरण थी।

जहाँ तक न्यायिक द्वारा की गई नियुक्तियों का संबंध है

नियुक्ति आयोग/समितियाँ/परिषदें (निर्दिष्ट)

ऊपर) संबंधित थे, नौ देशों में से

आयोग, दो देशों (दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका) में

चार देशों में कार्यपालिका का भारी बहुमत था।

कार्यपालिका सहित हितधारकों का प्रतिनिधित्व, तीन में देश (इटली, नाइजीरिया और पाकिस्तान) न्यायाधीशों की संख्या

बहुमत में थे। आयोगों/समितियों/परिषदों के बिना पांच देशों में (कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड,

बांग्लादेश और संयुक्त राज्य अमेरिका), निर्णय कार्यकारी द्वारा लिया गया था, बिना किसी औपचारिक प्रक्रिया के

न्यायपालिका के साथ परामर्श। यह बताया गया था कि जर्मनी, नियुक्ति प्रक्रिया द्वारा आयोजित की गई थी

संसद, और बाद में राष्ट्रपति द्वारा पुष्टि की गई। यह इंगित किया गया था

यह कि ऊपर उल्लिखित सभी देशों में न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड थी

तर्क दिया कि चयन और नियुक्ति का तरीका न्यायाधीशों को "स्वतंत्रता" की अवधारणा से जोड़ा नहीं जा सका

न्यायपालिका का "। यह प्रस्तुत किया गया था कि न्यायिक कार्यप्रणाली

ऊपर उल्लिखित देशों में, के रूप में स्वीकार किया गया है

संतोषजनक से अधिक, कोई कारण नहीं है, कि प्रणाली भारत में शुरू की गई नियुक्ति, एन. जे. ए. सी. में कार्यपालिका के एकल प्रतिनिधि द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। यह,

इसलिए यह दावा किया गया कि याचिकाकर्ताओं के हाथों दिए गए प्रस्तुतिकरण स्वीकार्य नहीं थे, यहां तक कि

शासित अन्य देशों के अनुभव का संदर्भ

एक संवैधानिक ढांचे के माध्यम से (उनमें से कुछ, वेस्टमिंस्टर मॉडल के)।

87. यह आगे दावा किया गया था कि की अनुपस्थिति

एन. जे. ए. सी. में न्यायाधीशों का पूर्ण बहुमत, का नेतृत्व नहीं कर सका

अनुमान, कि वही "मूल संरचना" का उल्लंघन था

संविधान का, ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि यह बाधित करेगा

"न्यायपालिका की स्वतंत्रता" पर। यह दावा किया गया था कि

एन. जे. ए. सी. में न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व, उससे बड़ा था शासन के अन्य दो अंगों, अर्थात्,

कार्यपालिका और विधायिका। किसी भी मामले में, दी गई

एनजेएसी में न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व, यह पूरी तरह से था

सक्षम, उच्च पद पर उम्मीदवार की नियुक्ति को रोकने के लिए

न्यायपालिका, जिस पर न्यायिक प्रतिनिधियों द्वारा विचार किया जाता था,

अनुचित के रूप में। तीन प्रतिनिधियों में से कोई भी दो

न्यायपालिका, दूसरों द्वारा समर्थित किसी भी नियुक्ति को वीटो करने के लिए पर्याप्त थी।

88. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि एन. जे. ए. सी. व्यापक था

न्यायपालिका के प्रतिनिधियों के आधार पर, कार्यपालिका

और "दो प्रतिष्ठित व्यक्ति", की श्रेणी में नहीं आएंगे

न्यायविद, प्रख्यात कानूनी शिक्षाविद, या प्रख्यात वकील। यह था।

तर्क दिया कि "प्रतिष्ठित व्यक्तियों" को शामिल करने का इरादा, जो

पेश करने के लिए कोई कानूनी पृष्ठभूमि नहीं थी, की प्रक्रिया में नियुक्ति, उसी [2015] 13 एस. सी. आर. में व्यक्तियों को नियुक्त करती है।

न्यायाधीशों का चयन और

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जिस तरह से न्यायिक नियुक्तियों में प्रावधान किया गया है

आयोग, यूनाइटेड किंगडम में।

89. यह विद्वान वकील का भी तर्क था

जनरल, कि यह पहला अवसर नहीं होगा, जब इस तरह की कवायद पर संसद द्वारा विचार किया गया है कानून। न्यायालय का ध्यान उपभोक्ता की ओर खींचा गया

संरक्षण अधिनियम, 1986, जिसमें सर्वोच्च न्यायनिर्णायक प्राधिकारी

न्यायिक पृष्ठभूमि के साथ और उसके बिना सदस्य शामिल हैं। अध्यक्ष

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण के

आयोग एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। सचित्र रूप से, यह तर्क दिया गया था, जहां एक मामला

तीन सदस्यीय पीठ द्वारा निर्णय लिया जा रहा है, जिनमें से दो

सदस्यों की कोई न्यायिक पृष्ठभूमि नहीं हो सकती है।

ये दो गैर-न्यायिक सदस्य, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा व्यक्त किए गए विचार को खारिज कर सकते हैं, जो इस मामले में पूर्व न्यायाधीश रहा हो।

उच्च न्यायपालिका। यह प्रस्तुत किया गया था कि उपरोक्त की स्थितियाँ है। फिर भी, ऐसी रचना के लिए

प्रकृति, कभी-कभी होती

न्यायनिर्णायक कार्यप्रणाली, जहाँ न्यायिक कार्य के साथ सदस्य

पृष्ठभूमि अल्पसंख्यक है, कानूनी और संवैधानिक रूप से मान्य है।

यदि न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया जा सकता है

उपरोक्त स्थिति, यह दावा किया गया था कि यह मुश्किल था

समझें कि इसे कैसे माना जा सकता है ऐसी स्थिति में समझौता किया गया, जिसमें एन. जे. ए. सी. के छह में से तीन सदस्य न्यायिक विरादरी से संबंधित हैं।

90. यह सुझाव देने की मांग की गई थी कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में न्यायपालिका की प्रधानता न्यायपालिका को संविधान की "बुनियादी संरचना" के हिस्से के रूप में नहीं माना जा सकता था। इसके अलावा, पूर्ण बहुमत की कमी

एन. जे. ए. सी. में न्यायाधीशों का भी समान नहीं होगा

संवैधानिक संशोधन का उल्लंघन किया जा रहा है

"बुनियादी संरचना"। मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में, यह था दावा किया, कि प्रस्तुतियाँ सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं के हाथों आगे बढ़ीं-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. /जगदीश सिंह खेहर, जे।/

याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील, के पहलू पर

संविधान की "मूल संरचना" का उल्लंघन, द्वारा

"न्यायपालिका की स्वतंत्रता" को कमजोर करना उत्तरदायी था

अस्वीकार करने के लिए।

91. दो प्रतिष्ठित लोगों को शामिल करने के संदर्भ में

छह सदस्यीय एन. जे. ए. सी. में यह प्रस्तुत किया गया था कि न्यायनिर्णायक में आम जनता प्रमुख हितधारक थी।

न्यायाधीशों के चयन/नियुक्ति में भागीदारी उच्च न्यायपालिका। उनकी भागीदारी, यह प्रस्तुत की गई थी,

पर्याप्त विविधता सुनिश्चित करें, जो सही निर्णय लेने के लिए आवश्यक है।

यह प्रस्तुत किया गया था कि आयोग के मॉडल में

एम. एन. वेंकटचलियाह, सी. जे. द्वारा सुझाए गए।, की भागीदारी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति प्रदान किया गया था। उन्हें नामित किया जाना था।

संसद के समक्ष रखे गए 2003 के विधेयक में, प्रस्तावित न्यायिक आयोग में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को शामिल किया जाना था।

कार्यपालिका द्वारा नामित किया जाने वाला व्यक्ति। 2013 का विधेयक, जो

इसका मसौदा पिछली राजनीतिक व्यवस्था-यू. पी. ए. द्वारा तैयार किया गया था।

सरकार, न्यायिक आयोग ने प्रस्तावित किया था कि

प्रधानमंत्री द्वारा चुने जाने वाले दो प्रतिष्ठित व्यक्ति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता लोकसभा। 2014 का विधेयक, जिसका मसौदा वर्तमान में तैयार किया गया था

राजनीतिक व्यवस्था-एन. डी. ए. सरकार, जिसमें दो शामिल थे प्रतिष्ठित व्यक्तियों का चयन लगभग उसी तरीके से किया जाएगा जिस तरह से 2013 के विधेयक के तहत विचार किया गया था। भिन्नता यह है कि,

कि प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक का अनुसूचित जाति, या अनुसूचित जनजाति, या अन्य से संबंधित होना आवश्यक था

पिछड़े वर्ग, या अल्पसंख्यक, या महिलाएँ, जिससे

स्पष्ट सामाजिक दायित्व। यह प्रस्तुत किया गया था कि न्यायाधीशों के चयन के लिए विचार-विमर्श में उनकी भागीदारी उच्च न्यायपालिका को प्रतिकूल नहीं बताया जा सकता था

न्यायिक समुदाय। उनकी भागीदारी से

नियुक्ति की प्रक्रिया, अधिक व्यापक आधारित।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015] 13 एस. सी. आर

92. प्रस्तुतियों का जवाब देते हुए,

याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील के हाथ, प्रभाव के लिए कि संविधान (99 वां संशोधन) अधिनियम, प्रदान नहीं करता था

कोई भी दिशा-निर्देश, जो "प्रतिष्ठित" की पात्रता को दर्शाता है व्यक्तियों को एन. जे. ए. सी. के लिए नामित किया जाना था, और इस तरह,

निरस्त किए जाने के लिए उत्तरदायी, यह प्रस्तुत किया गया था, कि अवधि

"प्रतिष्ठित व्यक्ति" किसी भी तरह से अस्पष्ट नहीं थे। इसका मतलब है-एक व्यक्ति जिन्होंने अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में विशिष्टता हासिल की थी।

संविधान की बहसों का भी उल्लेख किया गया था

सभा, "प्रतिष्ठित न्यायविद" शब्द से निपटते हुए,

अनुच्छेद 124 (3) में निहित, यह इंगित किया गया था कि

"प्रतिष्ठित व्यक्ति" अस्पष्ट नहीं था। वर्तमान स्थिति में, यह प्रस्तुत किया गया था कि के चयन और नामांकन के बाद से

"प्रतिष्ठित व्यक्ति", उच्च संवैधानिक के हाथों में होना था

पदाधिकारी (प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश से कम नहीं)

भारत सरकार और लोकसभा में विपक्ष के नेता), यह व्यक्ति,

यह मान लेना स्वाभाविक था कि नामित

दायित्व को ध्यान में रखते हुए चुना जाए और

जिम्मेदारी, जिसे निर्वहन की आवश्यकता थी। में रिलायंस

इस ओर से, सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट पर रखा गया था

मुकदमे का मामला 43, यह दावा करने के लिए कि यह मान लेना पर्याप्त था,

कि ऐसी उच्च स्तरीय समिति, जैसा कि विचाराधीन है,

अपनी शक्तियों का प्रयोग निष्पक्ष और उचित तरीके से करें।

तरीके से। उपरोक्त के आधार पर, यह तर्क दिया गया था कि यह अच्छी तरह से तय किया गया था, कि केवल व्यापक विवेकाधीन शक्तियों का प्रदान, यह प्रावधान को ही दूषित नहीं करेगा।

93. एक न्यायाधीश के आवश्यक गुणों का उल्लेख करते हुए

भारतीय संदर्भ में मान्यता प्राप्त, जैसा कि में गणना की गई थी

"बैंगलोर न्यायिक आचरण के सिद्धांत", और उसके बाद

गोलमेज बैठक में संशोधित के रूप में दुनिया भर में स्वीकार किया गया

नवंबर 2002 में हेग में आयोजित मुख्य न्यायाधीशों के लिए, यह "प्रतिष्ठित व्यक्ति" सबसे अधिक होंगे

प्रस्तुत किया गया था कि दो

विचाराधीन नामनिर्देशितों के संदर्भ में ऐसे मामलों का आकलन करने के लिए उपयुक्त। जबकि मुख्य जिम्मेदारी न्यायपालिका के सदस्य मुख्य रूप से सर्वोच्च न्यायालयों-ऑन-रिकॉर्ड से संबंधित होंगे।

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

संबंधित उम्मीदवारों के न्यायिक कौशल का पता लगाना,

कार्यपालिका की जिम्मेदारी होगी, यह निर्धारित करना कि

उम्मीदवार का चरित्र और अखंडता, और इनपुट, चाहे

उम्मीदवार के पास न्यायाधीश से अपेक्षित मूल्य थे होगी

उच्च न्यायपालिका, में "प्रतिष्ठित व्यक्तियों" की

एनजेएसी। इसलिए यह दावा किया गया कि दोनों "प्रतिष्ठित" हैं। व्यक्ति "सामान्य व्यक्ति" होंगे
जिनका कोई संबंध नहीं होगा

न्यायपालिका, या यहाँ तक कि वकालत के पेशे के लिए, शायद
ऐसे व्यक्ति जिनके पास कानून से संबंधित कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं हो सकती है

योग्यताएँ। यह प्रस्तुत किया गया था कि तत्काल व्यापक आधार एन. जे. ए. सी. की संरचना, अधिक
उपयुक्त होने के लिए बाध्य थी,

न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रचलित प्रणाली। इस पर भरोसा करें आर. गांधी मामला 38, यह
प्रस्तुत किया गया था कि यह नहीं होगा

नियुक्तियाँ करने के लिए उचित, की प्रक्रिया को निहित करके चयन, एक पृथक समूह या एक चयन
समिति के साथ

एक एकल समूह के प्रतिनिधियों का प्रभुत्व

न्यायपालिका। न्यायिक नियुक्तियों के मामले में, यह प्रस्तुत किया गया था,
उद्देश्य होना चाहिए, सर्वोत्तम कानूनी रूप से प्रशिक्षित दिमागों को चुनना,
एक गुणात्मक व्यक्तित्व के साथ। इसके अनुसार,
महान्यायवादी, एक सामूहिक परामर्श प्रक्रिया,

सबसे उपयुक्त बनें। यह इंगित किया गया था कि "प्रख्यात न्यायिक गतिविधियों से कोई संबंध
नहीं रखने वाले व्यक्ति

अलगाव का एक तत्व, और लाने में मदद करेगा

गैर-कानूनी दक्षताओं का मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञता,

एक साधारण नागरिक के दृष्टिकोण से, और इस प्रकार, न्याय वितरण प्रणाली के सभी हितधारकों का
प्रतिनिधित्व करता है। यह था।

तर्क दिया कि "प्रतिष्ठित व्यक्तियों" की उपस्थिति थी

प्रतिनिधि भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सामान्य जनता, न्यायाधीशों के चयन
और नियुक्ति में

उच्च न्यायपालिका। उनकी उपस्थिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि

चयन प्रक्रिया व्यापक आधार पर थी, और पर्याप्त रूप से परिलक्षित होती थी।

विविधता और जवाबदेही, और विकसित होने के साथ तालमेल में

दुनिया भर में न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया।

94. विद्वान महान्यायवादी ने तब संबोधित किया

कानून और सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट (2015) के प्रभारी केंद्रीय मंत्री को शामिल करने का मुद्दा 13 एस. सी. आर.

न्यायमूर्ति, एन. जे. ए. सी. में पदेन सदस्य के रूप में। संदर्भ था पहले अनुच्छेद 124 और 217 में बनाया गया, जैसा कि वे मूल रूप से थे संविधान में अधिनियमित। यह प्रस्तुत किया गया था कि मूल रूप से, उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति, विशेष रूप से राष्ट्रपति के पास निहित था। इस संबंध में निर्भरता अनुच्छेद 74 पर रखा गया था, जिसके तहत राष्ट्रपति था मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य, स्थिति, प्रथम न्यायाधीशों के मामले द्वारा घोषित की गई थी। और के रूप में इस प्रकार, संविधान के प्रारंभ की तारीख से, चयन में कार्यपालक की विशेष भूमिका थी और उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति। यह दावा किया गया था, कि स्थिति को पहली बार 1993 में बदल दिया गया था द्वितीय न्यायाधीशों का मामला, जिसमें "परामर्श" शब्द के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ की व्याख्या इस प्रकार की गई थी "सहमति"। इस तरह से व्याख्या की गई है, में प्रधानता उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला आया कार्यपालिका से मुख्य न्यायाधीश को स्थानांतरित किया जाना भारत (न्यायाधीशों के एक कॉलेजियम द्वारा एक सामूहिक निर्णय पर आधारित)। उपरोक्त के बावजूद, केंद्रीय कानून मंत्री और न्याय, कार्यपालिका का प्रतिनिधि होने के नाते, जारी रहा चयन प्रक्रिया में उनकी भूमिका है, हालांकि उनकी भागीदारी सौंपे गए दायित्व के विपरीत काफी सीमित था मूल रूप से अनुच्छेद 124 और 217 के तहत कार्यपालिका को

चयन के मामले में कार्यपालिका की सहभागी भूमिका की नियुक्ति, वास्तव में

और उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों

मूल स्थिति के विपरीत कम किया गया। इतना ही नहीं। को घटाकर एक कर दिया गया था

एन. जे. ए. सी. में कार्यकारी भूमिका

आयोग के छह सदस्यों में से। उपरोक्त दृश्य में

इस मामले में, यह दावा किया गया था कि यह अनुचित था

याचिकाकर्ताओं को नाराज़गी, केंद्रीय मंत्री की उपस्थिति

एन. जे. ए. सी. के सदस्य के रूप में विधि और न्याय का प्रभार।

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

95. जहां तक केंद्रीय मंत्री को शामिल करने की बात है

एन. जे. ए. सी. चिंतित है, यह प्रस्तुत किया गया था कि कोई नहीं हो सकता है

इस तथ्य से बचना, कि विचाराधीन मंत्री, होगा

न्यायपालिका और संसद के बीच संबंध। बिनि।

संसद, न्यायिक प्रतिष्ठान के मामलों के बारे में। यह प्रस्तुत किया गया था कि भागीदारी प्रक्रिया से उनका बहिष्कार, इसके परिणामस्वरूप शासन के दो महत्वपूर्ण स्तंभों के बीच समन्वय की कमी होगी। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया था कि

उम्मीदवार, जो एनजेएसी के शेष सदस्य हैं पहुँचने की संभावना नहीं है। यह, विद्वान के अनुसार

महान्यायवादी यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यक्ति सबसे उपयुक्त हों।

उच्च न्यायपालिका के लिए, चुना जाएगा। इसके अलावा, यह था

प्रस्तुत किया, कि कार्यकारी में एक प्रमुख हितधारक था

न्याय वितरण प्रणाली, और इस तरह, यह उनके लिए अनिवार्य था

चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया में एक भूमिका

न्यायाधीशों से लेकर उच्च न्यायपालिका तक।

96. विद्वान महान्यायवादी ने सभी आशंकाओं को दूर किया

यह कहते हुए कि वह राजनीतिकरण करने की स्थिति में नहीं होगा सदस्यों में से सिर्फ एक थे

नियुक्तियाँ, क्योंकि वे छह

एनजेएसी। और यह कि अन्य सदस्य एक

पर्याप्त जाँच, भले ही विचाराधीन मंत्री चाहते हों

राजनीतिक विचारों पर किसी विशेष उम्मीदवार का पक्ष लें। यह

विद्वान महान्यायवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया था,

याचिकाकर्ताओं के अनुमानित डर को ध्यान में रखते हुए

संघ के राजनीतिक झुकाव के कारण व्यक्त किया गया

तदनुसार जोर देकर कहा कि एक सदस्य की उपस्थिति प्रभावित नहीं करेगी

कार्यपालिका, छह सदस्यों के आयोग में,

"न्यायपालिका की स्वतंत्रता", जिससे स्पष्ट और सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

असंदिग्ध निष्कर्ष, कि संघ की उपस्थिति

एन. जे. ए. सी. में कानून और न्याय के प्रभारी मंत्री, नहीं

संविधान की "मूल संरचना" का उल्लंघन करता है।

97. इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लेख करते हुए,

मद्रास बार एसोसिएशन मामला 35, यह प्रस्तुत किया गया था कि, कार्यपालिका की भागीदारी

विचाराधीन न्यायाधिकरण, में

इसके सदस्यों का चयन अस्थिर माना गया था,

क्योंकि कार्यपालिका प्रत्येक मामले में एक हितधारक थी, कि

उपरोक्त स्थिति उच्च न्यायपालिका के रूप में प्रबल नहीं थी उच्च

चिंतित था, क्योंकि हितधारकों से पहले

न्यायपालिका विविध थी। अतः यह प्रस्तुत किया गया कि

एन. जे. ए. सी. की वैधता पर हमला नहीं किया जा सका, केवल केंद्रीय मंत्री की उपस्थिति के आधार पर, के एक पदेन सदस्य के रूप में

एनजेएसी।

98. उच्च पदों पर न्यायाधीशों की नियुक्ति का तरीका

न्यायपालिका, एन. जे. ए. सी. के माध्यम से, यह दावा किया गया था कि दो होंगे

प्रमुख लाभ। यह पारदर्शिता लाएगा

न्यायाधीशों के चयन और नियुक्तियों की प्रक्रिया, जो
रहा है

अब तक, नागरिक समाज के साथ बेहद गुप्त

अपनाए गए मानकों और मानदंडों के बारे में सोचने के लिए छोड़ दिया,
निर्धारित करने में। दूसरा, एनजेएसी

उम्मीदवारों की उपयुक्तता

चयन प्रक्रिया में विविधता लाएगी, जिससे आगे और प्रगति होगी।
जवाबदेही। यह था।

नियुक्तियों के मामले में

प्रस्तुत किया, कि न केवल मुकदमेबाजी करने वाली जनता, या अभ्यास करने वाले
को, लेकिन नागरिक समाज को भी, जानने का अधिकार था। यह.

अधिवक्ताओं

इंगित किया गया था कि जहाँ तक विधायी प्रक्रिया थी

चिंतित, संसद में बहस अब सार्वजनिक रूप से हो रही है
हाथों निर्धारित किए जाते हैं

डोमेन। व्यक्तियों के अधिकार, जिनके

कार्यपालिका, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत पारदर्शी रही है। यह प्रस्तुत किया गया था कि
इसी तरह,

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों का चयन और नियुक्ति,
ताकि न केवल परिचय दिया जा सके

नागरिक समाज को पता होना चाहिए,

निष्पक्षता, लेकिन आश्वासन की एक डिग्री भी, कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं में से सबसे अच्छा-चालू-
रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

इच्छुक लोगों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा रहा था।

99. अनुच्छेद 124 ए (2) का उल्लेख करते हुए

संविधान (99 वां संशोधन) अधिनियम, यह दावा किया गया था कि

संवैधानिक प्रक्रिया को रोका नहीं जा सका, क्योंकि

एक या अधिक सदस्यों की अनुपलब्धता (और/या अक्षमता)

एनजेएसी से। ताकि एन. जे. ए. सी. के गठन में कोई दोष, या उसमें कोई रिक्ति, की प्रक्रिया को प्रभावित न करे

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों का चयन और नियुक्ति।

अनुच्छेद 124 ए (2) में प्रावधान किया गया है कि एनजेएसी की कार्यवाही या अमान्य नहीं किया जाएगा

रिक्ति के कारण पूछताछ

या एन. जे. ए. सी. की संरचना में कोई दोष। यह तर्क दिया गया था,

कि याचिकाकर्ताओं के लिए अनुच्छेद पर गुस्सा करना गलत था

124 ए (2), क्योंकि कई वैधानिक अधिनियम थे जिनके साथ

समान प्रावधान। इस संबंध में न्यायालय का ध्यान था

केंद्रीय सतर्कता आयोग की धारा 4 (2) के बारे में

लोकपाल और लोकायुक्ता अधिनियम 2013 की धारा 4 (2),

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की धारा 7

अधिनियम 1993, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 29 ए,

अधिवक्ता कल्याण अधिनियम 2001 की धारा 7, की धारा 8

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 9

राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 7
राष्ट्रीय आयोग की धारा 8

अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1993,

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अधिनियम 2004,

विकलांग व्यक्तियों की धारा 24 (समान)

अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम

1995, और उसी के अन्य विधायी अधिनियमों का एक मेजबान

प्रकृति। बेंगलोर वूलन, कॉटन के फैसलों पर निर्भर

खादिम हुसैन बनाम। स्टेट ऑफ U.P. 61, बी. के. श्रीनिवासन बनाम। की स्थिति
पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम। संघ का

कर्नाटक 2, और

इंडिया 63, यह दावा किया गया था कि प्रावधानों की जांच पर

60 (1961) 3 एससीआर 707

61 (1976) 1 एस. सी. सी. 843

62 (1987) 1 एस. सी. सी. 658

63 (2005) 5 एससीसी 363 [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समान प्रकृति के इस न्यायालय ने बार-बार यह अभिनिर्धारित किया था कि ने सुनिश्चित किया कि प्रक्रिया के दोष,

विधायी अधिनियमों

जो किसी भी महत्वपूर्ण पूर्वाग्रह का कारण नहीं बनते हैं, वे वैधानिक रूप से हैं

चुनौती के दायरे से बाहर रखा गया। यह तदनुसार था

जोर देकर कहा कि तकनीकी अनियमितता के कारण अयोग्यता,

न्यायिक समीक्षा से बाहर होने के कारण, प्रस्तुतियाँ आगे बढ़ीं

याचिकाकर्ताओं की ओर से, की संवैधानिक वैधता पर

अनुच्छेद 124 ए का खंड (2) पूरी तरह से अस्वीकृत होने योग्य था।

100. यह सम्मानित महान्यायवादी का तर्क था,

कि एन. जे. ए. सी. अत्यधिक के दुष्प्रभाव से पीड़ित नहीं था

प्रतिनिधिमण्डल। यह दोहराया जाना चाहा गया था कि की शक्ति

"प्रतिष्ठित व्यक्तियों" का नामांकन सुरक्षित और सही था

संसद। यह प्रस्तुत किया गया था कि व्यक्त किए गए मापदंड 5 और 6 में मानदंड का वर्णन किया गया है।

एन. जे. ए. सी. अधिनियम की धारा

चयन के लिए, विशेष रूप से प्रदान करके, उस क्षमता, योग्यता और

उपयुक्तता स्पष्ट रूप से एन. जे. ए. सी. का ध्यान आकर्षित करेगी,

उच्च न्यायपालिका में नियुक्ति के लिए न्यायाधीशों का चयन करते समय,

इस चयन के लिए मापदंडों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया और

नियुक्ति प्रक्रिया। यह प्रस्तुत किया गया था कि तौर-तरीके

क्षमता, योग्यता और उपयुक्तता का निर्धारण आगे विस्तार से किया जाएगा।

नियमों और विनियमों के माध्यम से और वह, जैसे कारक,

बार में अभ्यास के वर्षों की न्यूनतम संख्या, संख्या

और तर्क दिए गए मामलों की प्रकृति, प्रतिष्ठित में अकादमिक प्रकाशन

पत्रिकाएँ, न्यूनतम और अधिकतम आयु, और इसी तरह,
 समान रूप से प्रदान किया जाए। ये सभी स्पष्ट रूप से परिभाषित मापदंड,
 यह तर्क दिया गया था, चयन की प्रक्रिया बनाएगा और
 उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति पारदर्शी, और
 यह भी सुनिश्चित करेगा कि जिन उम्मीदवारों पर विचार किया जाना है, वे थे
 न्यूनतम वांछित मानकों के अधिकारी। यह था।

प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए
 प्रक्रिया ज्ञापन, साथ ही, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की पदोन्नति के लिए, सर्वोच्च न्यायालय के
 अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड थे

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

ऐसे किसी भी विवरण का अभाव, और किसी का अभाव

यहाँ तक कि उच्चतम न्यायालय को भी, जो सामान्य रूप से होना चाहिए था टाल दिया। विद्वान
 महान्यायवादी ने एक संदर्भ दिया

तीन उदाहरण, जो उनके अनुसार, सार्वभौमिक थे

एक और सभी द्वारा निंदा की गई। नियुक्त न्यायाधीशों में से एक

उनके अनुसार, यह कोर्ट एक गैर-कलाकार था जैसा कि उन्होंने किया था

उन्होंने उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में कुछ ही निर्णय लिखे

दिल्ली और केरल के, और प्रमुख के रूप में बहुत कम निर्णय

उत्तराखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, और

न्यायाधीश के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान दस से कम निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय। दूसरे न्यायाधीश, उनके अनुसार,

अदालत की कार्यवाही शुरू करने में कुख्यात रूप से देर हो गई थी, एक आदत

जो उक्त न्यायाधीश के साथ एक न्यायाधीश के रूप में भी कायम रहा था

पटना और राजस्थान उच्च न्यायालय, और उसके बाद,

झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और एक न्यायाधीश के रूप में भी

उच्चतम न्यायालय से। तीसरे न्यायाधीश के अनुसार

विद्वान महान्यायवादी, को कुख्यात रूप से वर्णित किया गया था

न्यायाधीश को ट्वीट करना, अपने विचारों को ट्वीट करने की उनकी आदत के कारण, उनके सेवानिवृत्त होने के बाद। उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील,

न्यायाधीशों की पहचान को समझने की स्वीकृति

विद्वान महान्यायवादी द्वारा उनके उपरोक्त विवरण से, और इसके संबंध में व्यक्त की गई तथ्यात्मक स्थिति की भी पुष्टि की न्यायाधीशों ने उल्लेख किया। विद्वान महान्यायवादी भी

हमें एक संकलन (एक सीलबंद आवरण में) सौंपा

विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियां, इसके बावजूद

कार्यपालिका ने प्रतिकूल राय व्यक्त की है। द.

पाँच न्यायाधीशों की उच्च पद पर पदोन्नति के संदर्भ में किया गया संकलन न्यायालय (-जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीश,

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश, एक न्यायाधीश

पटना उच्च न्यायालय में, और कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश

स्पष्ट किया कि उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में आपत्ति न्यायाधीश अपनी उपयुक्तता से संबंधित नहीं थे, बल्कि कारण के लिए थे

कि कुछ उच्च न्यायालयों का सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट में प्रतिनिधित्व नहीं था

[2015] 13 एस सी आर।

अदालत। इसलिए हम उपरोक्त स्थिति को इस प्रकार समझेंगे 1993 से आज तक की अवधि को शामिल करते हुए। लेकिन यह उसका नहीं था।

निर्दिष्ट न्यायाधीशों को नियत समय पर उच्च पद पर पदोन्नत किया गया था भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय।

101. विद्वान एटोमी जनरल ने जोरदार विरोध किया

का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील द्वारा किया गया दावा

याचिकाकर्ताओं के लिए नियम और विनियम बनाने की शक्ति

एन. जे. ए. सी. की कार्यप्रणाली दिशाहीन थी, क्योंकि,

न तो संवैधानिक संशोधन और न ही विधायी

अधिनियम, नियम बनाने के लिए किसी भी मापदंड के लिए प्रदान किया गया और उपयुक्तता की कसौटी से संबंधित विनियम। इसमें

की ओर से, यह प्रस्तुत किया गया था कि पर्याप्त दिशानिर्देश थे

उपरोक्त, न्यायालय का ध्यान एन. जे. ए. सी. अधिनियम की धारा 5 (2), 6 (1) और 6 (3) की ओर आकर्षित किया गया था, जिसमें - न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उपयुक्तता निर्धारित की गई थी। में।

इस ओर से यह भी कहा गया कि अनुच्छेद 124, मूल रूप से

मानदंड व्यक्त किए गए थे। यह भी कहा गया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया और शर्तें थीं

यह भी निर्धारित नहीं है। उपरोक्त के विपरीत, यह इंगित किया गया था कि अनुच्छेद 124 बी और 124 सी और धारा 5 (2), 6 (1) और 6 (3)

एन. जे. ए. सी. अधिनियम, स्पष्ट रूप से निर्धारित शर्तें और दिशानिर्देश

नियुक्ति के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए

न्यायाधीश के रूप में। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, यह

प्रस्तुत किया गया था कि न तो संवैधानिक संशोधन "मूल संरचना" का उल्लंघन था, और न ही एन. जे. ए. सी. अधिनियम,

संवैधानिक रूप से अमान्य। उपरोक्त कारणों से, यह दावा किया गया था,

कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई चुनौती खारिज होने योग्य थी।

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

102. तकनीकी प्रस्तुति के जवाब में उन्नत

श्री फली एस. नरीमन द्वारा, अर्थात्, संविधान के बाद से (99 वां)

संशोधन) अधिनियम, इसके परिणामस्वरूप लागू किया गया था

केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से जारी अधिसूचना

13.4.2015 पर राजपत्र, एन. जे. ए. सी. विधेयक पर विचार और

एन. जे. ए. सी. अधिनियम का पारित होना, लागू होने से पहले इसे अमान्य कर देगा और

संविधान (99 वां संशोधन) अधिनियम,

शून्य, विद्वान अटॉर्नी जनरल ने लेख पर हमारा ध्यान आकर्षित किया
 118, जो संसद के प्रत्येक सदन को नियम बनाने के लिए अधिकृत करता है।
 उनकी प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए, उनके संचालन के मामले में
 लोकसभा के कामकाज का संचालन, विधिवत अधिनियमित किया गया था लोकसभा द्वारा।
 उपरोक्त नियमों का एक प्रासंगिक उद्धरण था
 हमें सौंप दिया। इसका नियम 66 निकाला जा रहा है। इसके नीचे:

सदन के समक्ष लंबित विधेयक, में पेश किया जा सकता है
 विधेयक के पारित होने की प्रत्याशा में सदन जिस पर यह

निर्भर है:

बशर्ते कि दूसरा विधेयक इसके लिए लिया जाएगा
 सदन में विचार और पारित होना पहले के बाद ही
 विधेयक सदनों द्वारा पारित किया गया है और इसके द्वारा सहमति दी गई है
 राष्ट्रपति "।

नियम 66 के तहत प्रावधान का उल्लेख करते हुए, यह था
 यह स्वीकार किया कि नियम स्वतंत्र रूप से पढ़ा जाता है, पूरी तरह से उचित है
 श्री फली एस. नरीमन की प्रस्तुतियाँ। हालांकि यह इंगित किया गया था
 बाहर, कि यह संसद के लिए निलंबन की मांग करने के लिए खुला था
 नियम 388 के तहत उपरोक्त नियम। नियम 388 भी निकाला गया है।
 इसके नीचे:

"388. कोई भी सदस्य, अध्यक्ष की सहमति से,
 कि इसके आवेदन में किसी भी नियम को निलंबित किया जा सकता है

सदन के समक्ष एक विशेष प्रस्ताव और यदि प्रस्ताव है

विचाराधीन नियम को समय के लिए निलंबित कर दिया जाएगा

होना "। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

अन्य बातों के साथ-साथ, दिनांक 12.8.2014 की लोकसभा की कार्यवाही, संविधान (121 वां संशोधन)
विधेयक और

एनजेएसी विधेयक। उन्होंने हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि चलते-फिरते
प्रस्ताव, कानून और न्याय के प्रभारी तत्कालीन केंद्रीय मंत्री
निलंबन के लिए अनुरोध किया गया था और मंजूरी दी गई थी
प्रक्रिया और आचरण के नियमों के नियम 66 के प्रावधान का
नियम 388 के निलंबन को दर्शाया जा रहा है इसके नीचे:

"नियम 388 के तहत प्रस्ताव

श्री रविशंकर प्रसाद ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:
"कि यह सदन नियम 66 के परंतुक को निलंबित करता है

लोक में प्रक्रिया और व्यवसाय के संचालन के नियम
सभा ने प्रस्तावों को लेने के लिए अपने आवेदन में
राष्ट्रीय न्यायिक पर विचार करना और पारित करना
नियुक्ति आयोग विधेयक, 2014 जितना हो सके उतना

संविधान पर निर्भर (एक सौ और
21 वां संशोधन) विधेयक, 2014. "

प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया।
विधेयकों पर विचार करने के लिए प्रस्ताव। ((i) द

संविधान (एक सौ बीस-प्रथम)
संशोधन) विधेयक, 2014 (नए अनुच्छेद 124 ए का समावेशन,
124 बी और 124 सी) और (ii) राष्ट्रीय न्यायिक
नियुक्ति आयोग विधेयक, 2014 पेश किया गया
श्री रविशंकर प्रसाद "।

के तहत बनाए गए नियमों के बल पर तैयार किया गया

अनुच्छेद 118, विद्वान महान्यायवादी ने भी इस पर निर्भरता रखी
पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

अनुच्छेद 122, जिसे नीचे

" 122. अदालतें कार्यवाही की जांच नहीं करेंगी

संसद। _ (1) में किसी भी कार्यवाही की वैधता
संसद को जमीन पर प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा।

प्रक्रिया की कोई भी कथित अनियमितता।

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

(2) संसद का कोई अधिकारी या सदस्य जिसमें शक्तियाँ हों

विनियमन के लिए इस संविधान द्वारा या उसके तहत निहित हैं

प्रक्रिया या व्यवसाय का संचालन, या बनाए रखने के लिए
संसद में आदेश, अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा

उनके द्वारा किए गए अभ्यास के संबंध में किसी भी न्यायालय का
शक्तियाँ "।

अनुच्छेद 122 के आधार पर, यह प्रस्तुत किया गया था कि

प्रक्रियात्मक दोषों के आधार पर चुनौती दी जा सकती है एन. जे. ए. सी. अधिनियम लागू करना।
इस संबंध में संदर्भ भी दिया गया था।

अनुच्छेद 246 के अनुसार, ताकि यह तर्क दिया जा सके कि

एन. जे. ए. सी. अधिनियम को लागू करने के लिए संसद स्पष्ट रूप से और

स्पष्ट रूप से संसद के साथ निहित। के समर्थन में

विवाद के ऊपर, निर्भरता को फिर से रखा गया था: हिंदू

महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम, 193764

संघीय न्यायालय, जिसमें उसने निम्नलिखित टिप्पणी की थी:

"शू में शामिल प्रावधानों में से एक। 9 कि एक बिल होगा

भारतीय द्वारा पारित नहीं माना गया है

विधानमंडल जब तक दोनों सदनों द्वारा सहमत न हो जाए

जिस पर दोनों सदनों की सहमति हो। यह आम है।

इस आधार पर कि हिंदू महिला संपत्ति अधिकार विधेयक पर दोनों सदनों द्वारा संशोधन किए बिना सहमति
व्यक्त की गई थी

भारतीय विधानमंडल, और जैसे ही यह राज्यपाल को प्राप्त करता है
जनरल की सहमति से यह एक अधिनियम बन गया। 9, पैरा। 68(2)).
तब तक यह या कोई अन्य न्यायालय अधिकार क्षेत्र नहीं था
यह निर्धारित करें कि क्या यह एक वैध कानून था या नहीं।

54 एयर 1941 एफ. सी. 72 [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विधान-मंडल की कार्यवाहियों में, के प्रयोजन के लिए यह निर्धारित करना कि कोई अधिनियम
वैध रूप से पारित किया गया था या नहीं;

उदाहरण के लिए, क्या यह वास्तव में पारित किया गया था, जैसा कि मामले में था

भारतीय विधानमंडल के लिए दोनों सदनों द्वारा कानून की आवश्यकता होती है राज्यपाल को
प्राप्त करने से पहले विधानमंडल का। जनरल का

सहमति दें। लेकिन न्यायालय को यह प्रतीत नहीं होता है कि प्रपत्र,

विधेयक की विषय-वस्तु या विषय-वस्तु, उसके प्रकाशन के समय

किसी भी सदन द्वारा इसका परिचय या उस पर विचार

विधानमंडल का एक ऐसा मामला है जिसके साथ एक न्यायालय है

चिंतित हैं। सवाल यह है कि क्या किसी भी चैंबर के पास है घरेलू मामले से पहले रखे गए
विधेयक पर चर्चा करने का अधिकार

चैंबर के नियमों द्वारा विनियमित, जैसा कि द्वारा व्याख्या की गई है

इसके अध्यक्ष, और एक ऐसा मामला नहीं है जिसके साथ एक न्यायालय कर सकता है

हस्तक्षेप, या वास्तव में जिस पर वह किसी भी अभिव्यक्ति का हकदार है राय दें। यह नहीं माना
जाना चाहिए कि एक विधायी निकाय करेगा

एक विधेयक पर चर्चा करके अपना समय बर्बाद करें, भले ही इसे गवर्नर-जनरल की सहमति मिल जाए, स्पष्ट
रूप से इससे परे होगा। विधानमंडल की अधिनियमित करने की क्षमता; लेकिन यदि वह चाहे

ऐसा करने के लिए, यह इसका अपना मामला है, और एक का एकमात्र कार्य है

न्यायालय विधेयक के पारित होने के बाद उस पर फैसला सुनाएगा।

एकट करें। अतः, इस न्यायालय की राय में, यह महत्वहीन है।

कि विधानमंडल की शक्तियाँ इस दौरान बदल गईं

विधान सभा से विधान सभा तक विधेयक का पारित होना
जिसके साथ न्यायालय है

राज्य परिषद। एकमात्र तिथि

संबंधित 14 अप्रैल 1937 है, जिस तारीख को गवर्नर जनरल की सहमति दी गई थी; और प्रश्न

क्या अधिनियम की क्षमता के भीतर था या नहीं

विधायिका का निर्धारण उस संदर्भ में किया जाना चाहिए

तारीख और किसी और के लिए नहीं। "

रिलायंस को पंडित एम. एस. एम. शर्मा बनाम पर भी रखा गया था।

श्री कृष्ण सिन्हा 55, जहाँ से निम्नलिखित

राशन को हमारे ध्यान में लाया गया था:

1 (1) एस. सी. आर. 96 सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्डसमाज v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

विधानमंडल के सदन के भीतर अपनाई गई प्रक्रिया थी
अनुसार नहीं। वहाँ

नियमित नहीं और सख्ती से कानून के

इस तर्क के दो उत्तर हैं, सबसे पहले, कि

इस न्यायालय के पिछले निर्णय के लिए, याचिकाकर्ता ने

उसके द्वारा दावा किया गया मौलिक अधिकार नहीं। इसलिए वह,

अदालत से बाहर। दूसरा, अंदर की कार्यवाही की वैधता
नहीं उठाया जा सकता है

किसी राज्य के विधानमंडल पर सवाल

आरोप है कि कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया थी

इसका सख्ती से पालन नहीं किया गया। संविधान का अनुच्छेद 212 है -
के इस हिस्से का पूरा जवाब

इस पर उठाए गए विवाद

याचिकाकर्ता की ओर से। कोई भी अदालत उन प्रश्नों में नहीं जा सकती है।

जो विधानमंडल के विशेष अधिकार क्षेत्र में हैं

स्वयं, जिसके पास अपना व्यवसाय करने की शक्ति है।

संभवतः, विवाद के इस हिस्से का तीसरा जवाब दिया गया याचिकाकर्ता की ओर से यह है कि यह अभी तक अपरिपक्व है

प्रक्रिया के प्रश्न पर विचार करें क्योंकि समिति है

अभी तक अपनी कार्यवाही को समाप्त करना बाकी है। इसका भी ध्यान रखना चाहिए।

कि एक बार यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विधानमंडल के पास है अपनी कार्यवाहियों के प्रकाशन को नियंत्रित करने की अधिकारिता और

इस सवाल पर कि क्या कोई उल्लंघन हुआ है अपने विशेषाधिकारों में से, विधानमंडल पूर्ण रूप से निहित है

के अनुसार अपनी कार्यवाहियों को जारी रखने की अधिकारिता

निर्धारित प्रक्रियात्मक कानून की आवश्यकताओं का अनुपालन अपने व्यवसाय के संचालन के लिए नीचे, जो एक आधार नहीं हो सकता है

कला के तहत इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के लिए। 32 में से

संविधान। न्यायालयों ने हमेशा अधिकार क्षेत्र की पूर्ण कमी और अधिकार क्षेत्र की पूर्ण कमी के बीच बुनियादी अंतर को मान्यता दी है।

अधिकारिता का अनुचित या अनियमित प्रयोग। बस नहीं। प्रक्रिया के नियमों का अनुपालन एक आधार नहीं हो सकता है।

कला के तहत एक रिट जारी करने के लिए। 32 संविधान के जनार्दन रेड्डी बनाम। हैदराबाद राज्य, (1951) एससीआर

344. " 1

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

उपरोक्त प्रस्तुतियों के आधार पर, यह था

विद्वान महान्यायवादी का जोरदार तर्क, कि वहाँ

द्वारा उठाई गई तकनीकी आपत्तियों में कोई योग्यता नहीं थी

याचिकाकर्ता एन. जे. ए. सी. अधिनियम के प्रावधानों पर हमला करते हुए।

103. श्री के. के. वेणुगोपाल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता,

मध्य प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थिति दर्ज की।

द्वारा प्रचार किए गए कुछ कानूनी प्रस्तुतियों को दोहराते हुए

विद्वान महान्यायवादी ने इस बात पर जोर दिया कि इस न्यायालय द्वारा दूसरे और तीसरे में दिए गए निर्णय

न्यायाधीशों के मामले, कानूनी स्थिति में बदल गए, जिनके तहत विचार किया गया

मूल अनुच्छेद 124 और 217, इसके शीर्ष पर। यह प्रस्तुत किया गया था,

कि इस न्यायालय को जनहित का ध्यान रखने की आवश्यकता है

मुकदमेबाजी, न्यायिक समीक्षा के एक अभूतपूर्व अभ्यास में,

जिसमें यह दावा करने की कोशिश की गई है कि "की स्वतंत्रता

न्यायपालिका का शासन के अन्य दो अंगों द्वारा अतिक्रमण किया गया था। विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया था कि

तत्काल दावा एक गलत धारणा पर आधारित था, प्रधानता के रूप में उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में,

न्यायपालिका के साथ कभी निहित नहीं था। यह बताया गया था कि

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में प्रधानता, अनुच्छेद 124 के तहत कार्यपालिका के पास निहित थी और

217, जैसा कि मूल रूप से लागू किया गया था। इसके अलावा, इस न्यायालय ने अपने माध्यम से

प्रथम न्यायाधीशों के मामले में अंतिम निर्णय, जबकि सही

संविधान के उपरोक्त प्रावधानों की व्याख्या करते हुए, ठीक ही निष्कर्ष निकाला गया कि कार्यपालिका और भारत के मुख्य न्यायाधीश (साथ ही, भारत के अन्य न्यायाधीशों) के बीच बातचीत

उच्च न्यायपालिका) केवल "परामर्शी" थी, और वह,

प्रमुख सहित न्यायाधीशों की नियुक्ति की जिम्मेदारी न्यायाधीशों से लेकर उच्च न्यायपालिका तक। यह प्रस्तुत किया गया था कि द्वितीय न्यायाधीशों का मामला, न्यायिक व्याख्या के माध्यम से,

न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में निहित प्रधानता

उच्च न्यायपालिका, भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ, और उनके न्यायाधीशों का कॉलेजियम। यह बताया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं को प्रस्तुत करने के बाद-ऑन-रिकॉर्ड

उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों का, जैसा कि द्वारा विचार किया गया है द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों के मामले। यह तर्क दिया गया था कि

चयन प्रक्रिया अब न्यायाधीशों के चयन करने वाले न्यायाधीशों तक सीमित थी।

बिना किसी बाहरी भागीदारी के। यह भी कहा गया कि न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति की भूमिका से कार्यपालिका का बहिष्कार इतना व्यापक था कि कार्यपालिका

नियुक्ति के लिए किसी भी उम्मीदवारी को शुरू करने का कोई अधिकार नहीं है

संविधान के प्रावधानों की व्याख्या, यह था इंगित किया, न केवल शब्द को पढ़ने में परिणाम दिया था

"अनुच्छेद 124 और 217 में 'सहमति' के रूप में परामर्श, लेकिन इससे बहुत आगे निकल गया है। यह दावा करने की मांग की गई थी कि

मूल अनुच्छेद 124 और 217 को बरकरार रखा गया है। द. यह इंगित किया गया था कि संशोधित प्रावधानों को झुका दिया गया है

न्यायपालिका का पक्ष, और सहभागी भूमिका, जो पहले निहित थी कार्यपालिका में, गंभीर रूप से कमजोर कर दिया गया है। यह प्रस्तुत किया गया था कि भले ही प्रधानता का कोई तत्व प्रदान नहीं किया गया था

अनुच्छेद 124 द्वारा न्यायपालिका पर, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, प्रधानता

अब न्यायपालिका में निहित किया गया है, क्योंकि एनजेएसी

न्यायिक से सदस्यता की सबसे बड़ी संख्या है

बंधुत्वा। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि केंद्रीय प्रभारी मंत्री

कानून और न्याय का, एकमात्र कार्यकारी प्रतिनिधि है,

संशोधित के तहत विचार की गई चयन प्रक्रिया

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति डाइल्यूटेड, इसकी स्वतंत्रता पर बाधा डाल रहा था।

104. यह तर्क दिया गया था कि बहुमत के लेखक का विचार

दूसरे न्यायाधीशों के मामले में (जे. एस. वर्मा, जे., जैसा कि वे उस समय थे), [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्वयं द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों के मामलों में निर्णयों के कार्यान्वयन के तरीके में त्रुटि पाई थी। यह था।

प्रस्तुत किया कि संसद, लोगों की आवाज होने के नाते,

जे. एस. वर्मा द्वारा की गई आलोचना को ध्यान में रखते हुए, जे.

(अन्य के अलावा), द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों के तहत विचार किए गए न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को संशोधित करना। मामला। इस प्रकार तर्क देते हुए, विद्वान वकील ने जोर देकर कहा कि

यदि इस न्यायालय ने महसूस किया कि किसी भी प्रावधान के संदर्भ में

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों का चयन और नियुक्ति,

मानकों और मानदंडों को पूरा नहीं करेगा, जो इस न्यायालय ने महसूस किया

पवित्र, यह इस न्यायालय को पढ़ने के लिए खुला था

उचित प्रावधान, इस तरह से कि उल्लंघन को पूरा किया जा सके

विवादित संवैधानिक प्रावधानों को रद्द करने के बजाय और पूरी तरह से विधायी प्रावधान।

105. श्री रंजीत कुमार, भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल

प्रस्तुत किया कि पूरे संविधान को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। इस संबंध में यह तर्क दिया गया था कि प्रत्येक प्रावधान संविधान का एक अभिन्न अंग था, और इस तरह, इसका

व्याख्या को समग्र रूप से प्रस्तुत किया जाना था। पल भर के लिए प्रस्ताव, किहोतो होलोहन पर निर्भरता रखी गई थी

मामला 34, टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन बनाम। कर्नाटक राज्य, आर. सी.

पौड्याल वी. भारत संघ, एम. नागराज मामला 36, और केशवानंद भारती मामला 01। उपरोक्त निर्णयों के आधार पर,

यह दावा किया गया था कि "राष्ट्रपति" शब्द, जैसा कि इसमें मौजूद था अनुच्छेद 124 और 217, यदि समग्र रूप से व्याख्या की जाती है, तो

स्पष्ट और स्पष्ट निष्कर्ष, कि राष्ट्रपति जबकि

नियुक्ति के संबंध में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना

उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों/मुख्य न्यायाधीशों की संख्या, मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बाध्य थी, जैसा कि विचार किया गया था।

अनुच्छेद 74 के तहत। यह तर्क दिया गया था कि उपरोक्त आयात

प्रथम न्यायाधीशों के मामले में अनुच्छेद 124 के संदर्भ में उचित रूप से जांच और व्याख्या की गई थी। लेकिन गलती हो गई

बाद के निर्णयों में अनदेखी की गई। तदनुसार, यह था

56 1994 पूरक (1) एस. सी. सी. 324 सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

जोर देकर कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है, जबकि विवादित संवैधानिक संशोधन की जांच करना, और साथ ही,

विवादित विधायी अधिनियम, कि संसद ने नहीं किया था

"मूल संरचना" के किसी भी घटक का उल्लंघन किया

संविधान।

106. यह भी तर्क दिया गया था कि चुनौती के मामले में

इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया, और इस द्वारा घोषित कानूनी स्थिति न्यायालय को प्रभावी किया जाना था, निरस्त प्रावधान होंगे

केवल इसलिए कि जिस संशोधन/विधान पर हमला किया जा रहा था, उसे असंवैधानिक माना गया था।

जहाँ तक मामले के तत्काल पहलू का संबंध है, सीखा गया सॉलिसिटर जनरल ने दो स्वतंत्र दलीलें उठाईं।

107. सबसे पहले, यह मुद्दा कि क्या एक संवैधानिक

उपरोक्त विवाद का समर्थन करें, और चित्र को प्रस्तुत करें पूरी तरह से, संपत्ति के मालिकों पर निर्भरता रखी गई थी

एसोसिएशन वी। महाराष्ट्र राज्य 67, संपत्ति के मालिक '

एसोसिएशन वी। महाराष्ट्र राज्य और संपत्ति मालिक संघ बनाम। महाराष्ट्र राज्य 9. यह प्रस्तुत किया गया था कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश, जिसमें नौ का संदर्भ

न्यायाधीश की संविधान पीठ बनाई गई थी, यह एक संबंधित मामला था

अनुच्छेद 31 सी की संवैधानिकता के लिए। यह बताया गया कि

अनुच्छेद 31 सी, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया है, प्रदान करता है कि

"..... अनुच्छेद 13 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई कानून नहीं

अनुच्छेद 39 के खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट सिद्धांतों को सुरक्षित करने की दिशा में राज्य की नीति को प्रभावी बनाना।

इस आधार पर शून्य माना जाएगा कि यह था

अनुच्छेद 14 और 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के साथ असंगत।

67 (1996) 4 एससीसी 49

08 8 (2001) 4 एससीसी 455

89 69 (2013) 7 एससीसी 522 [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बशर्ते "। और कोई कानून जिसमें यह घोषणा हो कि यह इसके लिए है पर किसी भी मामले में सवाल उठाया जाएगा।

ऐसी नीति को प्रभावी बनाने

न्यायालय इस आधार पर कि वह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं बनाता है। न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था

केशवानंद भारती में इस

मामला 1 0। यह तर्क दिया गया था कि जब संबंधित मामला

संवैधानिक संशोधन को निरस्त करने का प्रभाव,

नौ-न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया था, यह अनुचित होगा

इस न्यायालय के लिए, अपनी वर्तमान संरचना में बैठकर, निर्धारित करने के लिए

उपरोक्त मुद्दा।

108. दूसरा विवाद उनके हाथों आगे बढ़ा

विद्वान महान्यायवादी, धारा 6,7 पर आधारित था और

8 सामान्य खंड अधिनियम। यह तर्क दिया गया था कि एक हिस्से को हटा दिया था

संशोधन जिसने पूर्ववर्ती के कुछ

संविधान का अनुच्छेद 124, और इसके स्थान पर प्रतिस्थापित

कुछ अलग, जैसा कि अनुच्छेद 124 के मामले में,

संविधान (99 वां संशोधन) अधिनियम, के परिणामस्वरूप नहीं होगा

मूल अनुच्छेद का पुनरुद्धार जो इससे पहले था

संवैधानिक संशोधन, भले ही संशोधन स्वयं था

गिराने के लिए। यह प्रस्तुत किया गया था कि यदि एक प्रतिस्थापित

प्रावधान को असंवैधानिक घोषित किया गया था, चाहे जो भी आधार हो में स्वचालित रूप से परिणाम नहीं होगा

या कारण (ओं), उसी

निरस्त प्रावधान का पुनरुद्धार। समर्थन करने के लिए निर्भरता रखी गई थी

उपरोक्त विवाद, अमीर-उन-निसा पर

बेगम वी। महबूब बेगम, फर्म ए. टी. बी. मेहताब माजिद एंड कंपनी।

वी. मद्रास राज्य 71, बी. एन. तिवारी बनाम। भारत संघ 72, कोटेश्वर विट्टल कामथ बनाम।
के. रंगप्पा बालिगा और Co.7³, मूलचंद ओधवजी बनाम। राजकोट बरो म्युनिसिपैलिटी 74, मोहम्मद। शौकत
हुसैन खान

वी. आंध्र प्रदेश राज्य 75, महाराष्ट्र राज्य बनाम। केंद्रीय

70 आकाशवाणी 1955 एससी 352

71 ए. आई. आर 1963 एस. सी. 928

72 आकाशवाणी 1965 एससी 1430

73 (1969) 1 एससीसी 255

74 (1971) 3 एससीसी 53

75 (1974) 2 एस. सी. सी. 376 सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

प्रांत मैंगनीज अयस्क कंपनी Ltd. 76, इंडिया टोबैको कंपनी लिमिटेड।

वी. वाणिज्यिक कर अधिकारी, भवानीपुर और कोल्हापुर

केनसुगर वर्क्स लिमिटेड बनाम। भारत संघ 78. यह प्रस्तुत किया गया था,

कि निर्माण का सामान्य नियम था, कि इसके माध्यम से एक निरसन

एक निरस्तीकरण अधिनियम, जो किसी भी निरस्तीकरण को पुनर्जीवित नहीं करेगा

जिससे। रिलायंस को यू. पी. राज्य बनाम पर भी रखा गया था। हिरेन्द्र

पाल सिंह 79, एयर लाइन पायलटों की संयुक्त कार्रवाई समिति '

एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम नागरिक उड्डयन महानिदेशक, और

तमिलनाडु राज्य बनाम। के. श्याम सुंदर 31, यह तर्क देते हुए कि

जब भी कोई अधिनियम निरस्त किया जाता है, तो इसे इस तरह माना जाना चाहिए जैसे कि यह कभी
अस्तित्व में नहीं था। यह इंगित किया गया था

बाहर, जो पहले के तत्काल निरसन के परिणामस्वरूप

पूर्ववर्ती प्रावधानों को ऐसा माना जाना चाहिए कि

पूरी तरह से मिटा दिया गया/निरस्त कर दिया गया/मिटा दिया गया।

तत्काल विवाद को संक्षेप में प्रस्तुत करने की मांग की गई थी

इस बात पर जोर देते हुए कि यदि एक प्रतिस्थापित प्रावधान को निरस्त किया जाना था, मूल प्रावधान के पुनरुद्धार का प्रश्न (जो किया गया था) प्रतिस्थापित, निरस्त प्रावधान द्वारा) उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि जो प्रावधान प्रतिस्थापित किया गया था, उसे निरस्त कर दिया गया था, और इसलिए क़ानून में ही अस्तित्व समाप्त हो गया था। यह था। इसलिए प्रस्तुत किया कि भले ही चुनौती को उठाया गया हो विवादित संवैधानिक संशोधन को स्वीकार किया जाना था इस न्यायालय ने मूल रूप से अनुच्छेद 124 के अधिनियमित प्रावधानों और 217 पुनर्जीवित नहीं होगा।

109. विद्वान महान्यायवादी अतिरिक्त रूप से

तर्क दिया कि वर्तमान चुनौती के हाथों में याचिकाकर्ताओं पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह उठाया गया है समय से पहले। यह प्रस्तुत किया गया था कि द्वारा उठाई गई चुनौती याचिकाकर्ता धारणाओं और अनुमानों पर आधारित थे,

76 (1977) 1 एस. सी. सी. 643

7 (1975) 3 एस. सी. सी. 512

78 (2000) 2 एस. सी. सी. 536

79 (2011) 5 एससीसी 305

80 (2011) 5 एससीसी 435

81 (2011) 8 एस. सी. सी. 737 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

विवादित संशोधन के क्रिस्टलीकरण की अनुमति दिए बिना संविधान के लिए। यह दावा किया गया था कि स्थिति होगी नियमों और विनियमों के तहत बनाए जाने के बाद ही क्रिस्टलाइज़ करें

एनजेएसी अधिनियम। यह प्रस्तुत किया गया था कि "न्यायपालिका की स्वतंत्रता" का प्रश्न, के संदर्भ में किए गए संशोधन, एन. जे. ए. सी. के बाद ही निर्धारित किए जा सकते हैं अधिनियम को लागू किया गया था, इसके तरीके को निर्धारित करके कार्य कर रहा है। चूंकि वर्तमान मुकदमे की विचाराधीनता थी प्रावधानों के कार्यान्वयन में देरी संविधान में संशोधन, और एन. जे. ए. सी. अधिनियम में भी, यह इस न्यायालय के लिए किसी चुनौती को स्वीकार करना अनुचित होगा। अनुमानों और अनुमानों पर आधारित।

110. श्री के. परासरन, वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रवेश किया राजस्थान राज्य की ओर से उपस्थिति। उन्होंने प्रस्तुत किया, कि वह विवादित की वैधता का समर्थन करेगा संवैधानिक संशोधन, साथ ही, एन. जे. ए. सी. अधिनियम, और वह संघ की ओर से अग्रिम सभी प्रस्तुतियों का समर्थन किया भारत से। यह उनका तर्क था कि उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीश पहले से ही अपने न्यायिक कार्य के बोझ से दबे हुए थे, और इस तरह, उन्हें इस कार्य के बारे में गंभीरता से चिंतित नहीं होना चाहिए न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो विवादित संशोधन द्वारा, एन. जे. ए. सी. को सौंपा गया था। उनके विचार में, कार्यपालिका और संसद जनता के प्रति जवाबदेह थी, और इसलिए, उन्हें भारी बोझ उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए। उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जिम्मेदारी। यह, यह दावा किया गया था कि कार्यपालिका और विधायिका तब इस देश के लोगों के प्रति जवाबदेह बनें, क्योंकि नियुक्तियाँ जो वे करेंगे।

111. दो "प्रतिष्ठित व्यक्तियों" को शामिल करने के मुद्दे पर छह सदस्यीय एन. जे. ए. सी. में यह दावा किया गया था कि नामांकन "प्रतिष्ठित व्यक्तियों" को प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता द्वारा बनाया जाना था। लोकसभा। ये तीनों व्यक्ति, उच्च श्रेणी के हैं।

सर्वोच्च न्यायालयों का निर्वहन करने के लिए संवैधानिक कार्यकर्ताओं पर भरोसा किया जाना चाहिए-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

हित में उन्हें दी गई जिम्मेदारी

संवैधानिक पदाधिकारी और "प्रतिष्ठित व्यक्ति", कर सकते हैं भरोसा नहीं किया जाएगा, तो संवैधानिक तंत्र खुद होगा

असफल हो जाते हैं। यह इंगित किया गया था कि इस न्यायालय ने बार-बार वर्णन किया था,

कि संविधान चरित्र में जैविक था, और इसमें एक था

बदलते समय के साथ विकसित होने के लिए अंतर्निहित तंत्र। यह दावा किया गया था कि संसद के पास निहित शक्ति, के तहत

संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 एक था "घटक शक्ति", संसद को पुनः आकार देने के लिए अधिकृत करना

संविधान, बदलते वातावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए। यह था।

तर्क दिया कि उपरोक्त शक्ति संसद में निहित हो सकती है

एकमात्र अपवाद के साथ प्रयोग किया जाए, कि "मूल संरचना /

संविधान की विशेषताएँ, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है

केशवानंद भारती मामले में न्यायालय को बदला नहीं जा सका /

बदल गया। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार,

संविधान (99 वां संशोधन) अधिनियम एक अभ्यास था -

वनाच्छादित घटक शक्ति, और यह कि, इसके द्वारा प्रस्तुत संविधान में संशोधन, किसी भी तरह से बाधित नहीं था

"न्यायपालिका की स्वतंत्रता" पर।

112. अनुच्छेद 124 ए का उल्लेख करते हुए यह कहा गया कि एन. जे. ए. सी. पहचान, चयन के लिए छह सदस्यीय आयोग था।

और उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति। इसके तहत हो सकता है कोई परिस्थितियाँ नहीं, अभाव में पाया जाता है, संदर्भ के साथ

याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए दावे। यह बताया गया था कि
 उस पर एकमात्र कार्यकारी प्रतिनिधि संघ है
 कानून और न्याय के प्रभारी मंत्री, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सका,
 कि कार्यपालिका उसके माध्यम से ऐसा प्रभाव डालेगी, जैसे कि आयोग के पाँच अन्य सदस्यों की
 स्वतंत्रता को कमजोर करेगा। यह प्रस्तुत किया गया था कि सबसे बड़ा
 आयोग का प्रतिनिधित्व, न्यायाधीशों का था
 उच्चतम न्यायालय, भारत के मुख्य न्यायाधीश, और
 उच्चतम न्यायालय के दो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश पूर्व न्यायाधीश थे
 एन. जे. ए. सी. के सदस्य।

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

113. एन. जे. ए. सी. पर दो "प्रतिष्ठित व्यक्तियों" के संदर्भ में, यह उनका तर्क था कि उनकी पहचान नहीं की जा सकी।

या तो कार्यपालिका या विधायिका के साथ। नामांकन के लिए दो "प्रतिष्ठित व्यक्तियों" में से, चयन समिति

इसमें कार्यपालिका का एक सदस्य, एक सदस्य शामिल होता है

विधायिका, और न्यायपालिका का एक सदस्य। उपरोक्त में

मामले का दृष्टिकोण, यह दावा किया गया था कि तर्क, कि आयोग में दो "प्रतिष्ठित व्यक्ति" इसका समर्थन करेंगे

कार्यपालिका/विधायिका, बेतुकी थी। इसलिए यह

विद्वान वरिष्ठ वकील का निवेदन, कि "न्यायपालिका की स्वतंत्रता" को माना नहीं जा सकता है

की संरचना को ध्यान में रखते हुए अवमूल्यन किया गया

एनजेएसी।

114. यह भी तर्क दिया गया था कि इससे पहले की कार्यवाही

एन. जे. ए. सी. अधिक पारदर्शी और व्यापक होगा, और

तदनुसार, अधिक परिणाम उन्मुख, और यह सुनिश्चित करेगा कि लिए सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के

उच्च न्यायपालिका के लिए।

115. यह दावा किया गया था कि एन. जे. ए. सी. ने एक

उन व्यक्तियों के साथ परामर्श प्रक्रिया जो पूर्व-परिकल्पना थे, ठीक है

नियुक्ति के मामले में उचित सलाह देने के लिए योग्य तदनुसार दावा था

उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीश। यह

विद्वान अधिवक्ता का, कि इस न्यायालय द्वारा द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों के मामलों में दिया गया निर्धारण इसमें नहीं था उस आशय के अनुरूप, जिसके साथ अनुच्छेद 124 और 217

मूल रूप से लागू किए गए थे। अतः यह प्रस्तुत किया गया कि

"न्यायपालिका की स्वतंत्रता" का विषय, के संदर्भ में

विवादित संवैधानिक संशोधन, नहीं होना चाहिए

संविधान सभा के सदस्य इस पर बहस करते हुए कि जबकि संघ

उपरोक्त प्रावधान। यह प्रस्तुत किया गया था

कानून और न्याय के प्रभारी मंत्री, एक प्रभावी सर्वोच्च न्यायालय अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड में होंगे

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

आवश्यक निवेश प्रदान करने की स्थिति, के संदर्भ में पूर्ववृत्त

संबंधित उम्मीदवार (ओं) का चरित्र और

उस पर उपलब्ध सरकारी तंत्र का दृश्य

कमान), दो "प्रतिष्ठित व्यक्ति" एक पद पर होंगे

चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए,

आम जनता, और इस प्रकार, चयन प्रक्रिया होगी

चारों ओर तार्किक इनपुट के साथ भरा हुआ, एक स्वस्थ के लिए

विचार करें।

116. यह प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि के कोई भी दो सदस्य

एन. जे. ए. सी., एक नामांकित व्यक्ति की उम्मीदवारी को वीटो करने के लिए सक्षम थे,

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के तीन प्रतिनिधि होंगे

स्पष्ट रूप से अनुपयुक्त की नियुक्ति को रोकने की स्थिति में

उम्मीदवार। अतः यह तर्क दिया गया कि विधान

संसद द्वारा अधिनियमित, अनुच्छेद 368 के संदर्भ में विधिवत अनुसमर्थित, संविधान के साथ कार्यात्मक बनने की अनुमति दी जानी चाहिए

एन. जे. ए. सी. का, और आगे निर्वहन करने की अनुमति दी जानी चाहिए

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जिम्मेदारी। यह.

प्रस्तुत किया गया था कि निर्वहन में किसी भी कमी के मामले में

उक्त जिम्मेदारी में से, यह न्यायालय स्वतः चयन प्रक्रिया को अस्वीकार कर सकता है, या एक या दोनों को बाहर कर सकता है

चयन प्रक्रिया से व्यक्ति, यदि वे पाए गए

अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए अनुपयुक्त या अयोग्य। या भले ही वे अपनी उपयोगिता स्थापित नहीं कर सके। यह था।

प्रस्तुत किया, कि इस न्यायालय को विचारित को नहीं दबाना चाहिए

न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया

न्यायपालिका, एनजेएसी के माध्यम से, इसके बिना भी किया गया है

परीक्षण किया गया।

117. श्री टी. आर. अंधारुजिना, वरिष्ठ अधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य की ओर से उपस्थित हुए। यह उसका था।

तर्क, प्रस्तुतियों का समर्थन करते हुए आगे बढ़े भारत संघ की ओर से, कि विवादित संविधान

(99 संशोधन) अधिनियम, एक दुर्लभ घटना थी, क्योंकि

संसद ने सर्वसम्मति से सभी दलों के साथ इसे पारित कर दिया।

संशोधन का समर्थन करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई सर्वोच्च अदालत की रिपोर्ट नहीं थी

[2015] 13 एस सी आर।

यह स्वीकार किया कि एक संसद सदस्य था, जिसने दावा किया गया था,

मतदान से दूर रहे। उपरोक्त के अलावा, यह

कि यहां तक कि राज्य विधानसभाओं ने भी तत्काल संवैधानिक अनुमोदन किया

यह तर्क दिया गया था कि तत्काल संवैधानिक संशोधन, लोगों की सर्वसम्मत इच्छा के रूप में माना जाना चाहिए,

राष्ट्र की इच्छा के रूप में सभी द्वारा प्रयोग किया जा सकता है हितधारक।

118. यह प्रस्तुत किया गया था कि संदर्भ के तहत संशोधन को संदेह के साथ नहीं देखा जाना चाहिए। यह इंगित किया गया था

कि अनुच्छेद 124 और 217 ने एक प्रमुख भूमिका पर विचार किया कार्यपालक के लिए। यह तर्क दिया गया था कि निर्णय में

द्वितीय न्यायाधीशों का मामला, के मामले में निहित प्रधानता प्रमुख के साथ उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति

भारत के न्यायाधीश और उनके न्यायाधीशों का कॉलेजियम। इस तरीके से

विद्वान वकील के अनुसार, उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों का चयन और नियुक्ति बाकी लोगों के लिए अज्ञात थी।

दुनिया में, किसी अन्य देश की तरह, न्यायाधीशों की नियुक्ति है

स्वयं न्यायाधीशों द्वारा बनाया गया। के दोषों को इंगित करना

कॉलेजियम प्रणाली, यह दावा किया गया था कि इसका अभाव है

पारदर्शिता, और पर्याप्त रूप से व्यापक नहीं थी। जबकि

मुख्य न्यायाधीश जे. एस. वर्मा द्वारा व्यक्त विचार को स्वीकार करते हुए, कि

द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों के मामलों में न्यायाधीशों की नियुक्ति का तरीका बहुत अच्छा था।

प्रस्तुत किया कि जे. एस. वर्मा, सी. जे., खुद को निराश किया

उनके कार्यान्वयन, जैसा कि उन्होंने महसूस किया, कि एक पूर्ण था

उस मोर्चे पर विफलता। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि

जिन प्रश्नों के उत्तर दिए जाने की आवश्यकता थी, क्या वहाँ

क्या संविधान संशोधन में कोई मौलिक अवैधता थी? या, क्या न्यायाधीशों की नियुक्ति के माध्यम से विचार किया गया था

एन. जे. ए. सी. ने संविधान की "बुनियादी संरचना" का उल्लंघन किया?

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

और, क्या "न्यायपालिका की स्वतंत्रता" खड़ी थी

विवादित संवैधानिक संशोधन द्वारा विकृत? यह था।

दावा किया, कि यह मान लेना गलत था, कि तरीका

न्यायपालिका का "। इस संबंध में यह बताया गया कि न्यायाधीशों की स्वतंत्रता, इस बात पर निर्भर नहीं करती थी कि किसे नियुक्त किया गया है

उन्हें। यह भी बताया गया कि न्यायाधीशों की स्वतंत्रता उनके व्यक्तिगत चरित्र पर निर्भर करती है। सीखा हुआ परामर्श

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा व्यक्त की गई स्थिति को दोहराया।

संविधान सभा बहस करती है। उन्होंने कहा कि

"न्यायपालिका की स्वतंत्रता" की अवधारणा नहीं होनी चाहिए इसके द्वारा व्यक्त राय के संदर्भ में निर्धारित किया गया

द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों के मामलों में न्यायालय, लेकिन होना चाहिए

संविधान में बहस के संदर्भ में निर्धारित किया गया विधानसभा, जिसके कारण अनुच्छेद 124 का क्रिस्टलीकरण हुआ और

217, जैसा कि मूल रूप से लागू किया गया था।

119. विद्वान सलाहकार ने "एन्जिल्स को रोते हुए बनाना" शीर्षक वाले अपने लेख में थॉर्नडन के लॉर्ड कुक पर भरोसा रखा, जिसमें

उन्होंने दूसरे न्यायाधीशों के मामले की तीखी आलोचना की। संदर्भ

उनके लेख "जहाँ स्वर्गदूतों को चलने से डर लगता है" में भी बनाया गया था,

तीसरे न्यायाधीशों के मामले के संदर्भ में। अदालत का ध्यान

दूसरे और तीसरे न्यायाधीशों की आलोचना के लिए भी आकर्षित किया गया था

एच. एम. सीरवर्ड, फली एस. नरीमन और अन्य के हाथों मामले,

विशेष रूप से कृष्ण लायर और रुमा पाल, जे. जे. के हाथों आलोचना। , और बाद में यहां तक कि बहुमत के फैसले के लेखक

द्वितीय न्यायाधीशों का मामला-जे. एस. वर्मा, मुख्य न्यायाधीश।

तदनुसार, विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क, कि

"न्यायपालिका की स्वतंत्रता" के मुद्दे का निर्धारण करते हुए,

उपरोक्त दोनों में से किसी का भी उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए।
निर्णय, लेकिन अनुच्छेद 124 की सादे भाषा में किए जाने चाहिए
और 217। उपरोक्त तरीके से देखे जाने पर यह दावा किया गया कि
इस निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई सवाल ही नहीं होगा कि
विवादित संवैधानिक संशोधन ने बुनियादी अवधारणाओं का उल्लंघन किया
"शक्तियों का पृथक्करण" और "न्यायपालिका की स्वतंत्रता"।

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

120. भले ही, कोई दिशानिर्देश नहीं थे, क्योंकि
से उभरते हुए दो "प्रतिष्ठित व्यक्तियों" की नियुक्ति
संविधान (99 वां संशोधन) अधिनियम और/या एन. जे. ए. सी. अधिनियम, अभी तक
यह प्रस्तुत किया गया था कि यह स्पष्ट था कि "प्रतिष्ठित व्यक्ति"
चुने जाने के लिए, ऐसे व्यक्ति होंगे जो इसमें अच्छी तरह से पारंगत थे न्यायालयों का कार्य। अदालत
के पूछने पर, विद्वान वरिष्ठ वकील ने सुझाव दिया कि इस उद्देश्य के लिए "प्रतिष्ठित व्यक्ति"
केवल प्रख्यात वकीलों, प्रख्यात न्यायविदों में से ही चुना जा सकता था,
और यहाँ तक कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश, या इसी तरह के। तत्काल के रूप में
मामले के पहलू का संबंध है, यह स्पष्ट है कि विद्वान वरिष्ठ वकील ने एक स्थिति अपनाई थी, जो बिल्कुल
विपरीत थी
विद्वान महान्यायवादी द्वारा प्रचार किए गए व्यक्ति के लिए। एक अन्य
पहलू, जिस पर हमने प्रस्तुत करने में थोड़ा विचलन पाया
श्री टी. आर. अंधारुजिना का कहना था कि कई देशों में
न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में कार्यकारी भागीदारी
उच्च न्यायपालिका को नीचे लाया जा रहा था। और कुछ में
देशों में यह अब कार्यपालिका के हाथों में नहीं था। इसमें
इसके पक्ष में, विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा दिया गया स्पष्ट तर्क था कि दुनिया भर में, नियुक्ति की प्रक्रिया

उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों का विकास हो रहा था, ताकि एन. जे. ए. सी. की प्रकृति के आयोगों में निहित। और के रूप में "न्यायपालिका की स्वतंत्रता", जब दुनिया भर में आयोगों को निर्वहन करते हुए पाया गया था संतोषजनक रूप से जिम्मेदारी।

121. श्री तुषार मेहता, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भारत ने गुजरात राज्य की ओर से उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों को अपनाया। जनरल, साथ ही, श्री रंजीत कुमार, विद्वान सॉलिसिटर जनरल। यह उनकी प्रस्तुति थी, कि इस प्रणाली का नवाचार किया गया उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए यह न्यायालय, यह एक न्यायिक नवाचार था। यह बताया गया था कि 1993 से जब उपरोक्त प्रणाली अस्तित्व में आई, तो यह था

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।] उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, जब तक विवादित संवैधानिक संशोधन लागू हुआ। यह दावा किया गया था कि, अंतराल में, कुछ विशिष्ट घटनाएँ हुई थीं, जो परिवर्तन की आवश्यकता को दर्शाती हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति की विधि और रीति में उच्च न्यायपालिका। विद्वान सलाहकार ने हमारा ध्यान आकर्षित किया विभिन्न विधेयक जो संसद में पेश किए गए थे नियुक्तियों के लिए एक आयोग की स्थापना का उद्देश्य उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीश, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है यहाँ से पहले। यह बताया गया था कि कई अभ्यावेदन की वकालत करते हुए, उस समय की सरकार द्वारा प्राप्त किया गया था लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को पूरा करने के लिए एक व्यापक आधार वाले राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के साथ "कॉलेजियम प्रणाली" का प्रतिस्थापन

देश के नागरिकों की आकांक्षा। परिणामी प्रभाव
 संविधान (99 वां संशोधन) अधिनियम का पारित होना,
 और संसद द्वारा एन. जे. ए. सी. अधिनियम। यह प्रस्तुत किया गया था कि
 वही लगभग सर्वसम्मति से पारित किया गया, केवल
 राज्यसभा का एक सदस्य अनुपस्थित रहा। यह दावा किया गया था कि
 यह आजादी के बाद की एक दुर्लभ ऐतिहासिक घटना थी, जब सभी
 अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं वाले राजनीतिक दलों ने मतदान किया
 विवादित संवैधानिक संशोधन का समर्थन। इसके अलावा
 उपरोक्त के लिए, यह प्रस्तुत किया गया था कि अब तक 28 राज्य विधानसभाओं ने विधेयक की
 पुष्टि की थी। यह दावा किया गया था कि
 न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए संवैधानिक तंत्र
 उच्च न्यायपालिका ने पर्याप्त समय तक काम किया था, और इस तरह के अनुभव से सीखना
 यह महसूस किया गया कि एक व्यापक आयोग का गठन किया जाना चाहिए। यह तर्क दिया गया था कि
 आक्षेपित
 संवैधानिक संशोधन, सभी मापदंडों को संतुष्ट करता है
 एक संशोधन की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करना। ज्ञात अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने इसी तरह
 विरोध किया,
 याचिकाकर्ताओं के हाथों प्रस्तुतियाँ
 कानून और न्याय के प्रभारी केंद्रीय मंत्री को एन. जे. ए. सी. के सदस्य के रूप में शामिल करने को चुनौती देना।
 उन्हें योग्यता भी मिली।
 एन. जे. ए. सी. में दो "प्रतिष्ठित व्यक्तियों" को शामिल करना।

यह सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर. थी।

तर्क दिया कि "प्रतिष्ठित व्यक्ति" शब्द, के संदर्भ में

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति अपने आप में थी स्पष्ट और असंदिग्ध, और जैसे ही
 और कब, एक नामांकन होगा

यदि ऐसा किया जाता है तो इसकी प्रामाणिकता को समझा जाएगा। उसने दूरी बना ली। श्री टी.
 आर. द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतिकरण से स्वयं

अंधारुजिना, जिन्होंने महाराष्ट्र राज्य का प्रतिनिधित्व किया, जबकि

उन लोगों की पहचान के बारे में प्रस्तुत करना जो कर सकते थे

एन. जे. ए. सी. में "प्रतिष्ठित व्यक्तियों" के रूप में नामित किया जाए। यह था।

प्रस्तुत किया गया, नगरपालिका समिति पर भरोसा रखते हुए,

अमृतसर बनाम। पंजाब राज्य, के. ए. अब्बास बनाम भारत संघ, और ए. के. रॉय मामला 49, कि इसी तरह के प्रस्तुतियाँ आगे बढ़ीं

इस न्यायालय के समक्ष, अस्पष्टता और अनिश्चितता के संदर्भ में

इस न्यायालय द्वारा कानून को लगातार खारिज कर दिया गया था। विद्वान वकील के अनुसार, में कथित अस्पष्टता के संदर्भ में

"प्रतिष्ठित व्यक्ति" शब्द, एक के नामांकन के मामले में

व्यक्ति पर हमला किया गया था, सक्षम क्षेत्राधिकार का एक न्यायालय होगा

इसे, जहाँ तक हो सके, इरादे के अनुसार समझें।

विधायिका से। यह दावा किया गया था कि यह नहीं माना जा सकता है,

एन. जे. ए. सी. में "प्रतिष्ठित व्यक्तियों" के रूप में नामित किए गए थे, वे न्यायिक घटक के खिलाफ संतुलन को झुकाने में सक्षम होंगे एनजेएसी। यह प्रस्तुत किया गया था कि दोनों की नियुक्ति

"प्रतिष्ठित व्यक्ति" प्रधानमंत्री के सुरक्षित हाथों में थे,

भारत के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता

लोकसभा। मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने प्रार्थना के साथ निष्कर्ष निकाला, कि

विद्वान वकील के हाथों प्रस्तुतियाँ क्योंकि याचिकाकर्ता अस्वीकार किए जाने के योग्य थे।

122. श्री रवीन्द्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रवेश किया।

छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से उपस्थिति। उनके पास था

ग्यारह शीर्षों के तहत विभाजित प्रस्तुतियाँ करने के लिए चुना गया।

हालाँकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, कि विस्तृत प्रस्तुतियाँ

82 (1989) 1 एस. सी. सी. 475

83 (1970) 2 एस. सी. सी. 780 शीर्ष अदालतें-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

उनके सामने पेश होने वाले वकील द्वारा पहले ही पेश किया जा चुका था, उन्होंने इसे सीमित करने का फैसला किया। यह था कि विद्वान वरिष्ठ वकील का प्राथमिक तर्क, कि

विवादित संवैधानिक संशोधन, साथ ही एन. जे. ए. सी. अधिनियम, किसी भी तरह से संविधान के "मूल ढांचे" का उल्लंघन नहीं करता है।

संविधान। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार,

विवादित संवैधानिक संशोधन, आगे बढ़ाता है और मजबूत करता है

एक स्वतंत्र और स्वतंत्र न्यायपालिका का "मूल संरचना" सिद्धांत। यह उनका निवेदन था, कि किए गए दावे

याचिकाकर्ताओं के हाथ, इस प्रभाव के लिए कि विवादित

संवैधानिक संशोधन, "मूल संरचना" पर प्रभाव डालता है

संविधान और "न्यायपालिका की स्वतंत्रता",

पूरी तरह से गलत धारणा थी। यह प्रस्तुत किया गया था कि यह न्यायालय

कभी नहीं माना था कि न्यायपालिका की प्रधानता के माध्यम से

भारत के मुख्य न्यायाधीश, "न्यायपालिका की स्वतंत्रता" का एक अनिवार्य घटक थे। यह दावा किया गया था कि जबकि

याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई चुनौती पर विचार करते हुए

भारत के मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से न्यायपालिका की प्रधानता, केवल "शक्ति के पृथक्करण" के आवश्यक घटकों को संतुष्ट करना

और "न्यायपालिका की स्वतंत्रता"। यह प्रस्तुत किया गया था कि

न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में बहुलता की शुरुआत

उच्च न्यायपालिका के लिए, स्वतंत्रता का एक उदाहरण था, बल्कि

हस्तक्षेप के एक उदाहरण से अधिक। सदस्यों के संदर्भ में

एन. जे. ए. सी. की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि यह सुनिश्चित नहीं होगा कि

केवल पारदर्शिता, बल्कि एक व्यापक आधार वाली चयन प्रक्रिया भी,

बिना किसी गुप्त उद्देश्य के। इस बात पर जोर दिया गया कि उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों के चयन के लिए एन. जे. ए. सी. को अपनाया जाना,

इसके परिणामस्वरूप इच्छुक लोगों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन होगा

नियुक्त किया जाता है। संघ की भागीदारी के संदर्भ में
 विधि और न्याय के प्रभारी मंत्री, पदेन सदस्य के रूप में
 एन. जे. ए. सी. की, यह प्रस्तुत किया गया था कि केवल की भागीदारी
 एक कार्यकारी प्रतिनिधि, प्रक्रिया को "सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर. की स्वतंत्रता" की
 अवधारणा के साथ असंगत नहीं बनाएगा।

न्यायपालिका "। इस संबंध में, इस पर जोरदार निर्भरता रखी गई थी

ई. एस. वेंकटरमैया, जे. की दो पैराग्राफ से टिप्पणियाँ प्रथम न्यायाधीशों के मामले, जिन्हें यहाँ निकाला
 जा रहा है:

" 1033. इसी विवाद के हिस्से के रूप में यह आग्रह किया जाता है कि

भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में कार्यपालिका की कोई आवाज नहीं
 होनी चाहिए क्योंकि

न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो एक बुनियादी विशेषता है

न्यायपालिका की स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी। द.
 सही सिद्धांत यह है कि इस तरह की नियुक्ति के बाद कार्यपालिका

न्यायाधीश के कार्य में हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।

" 1038. पूर्वगामी काफी विश्वसनीय तस्वीर देता है

न्यायाधीशों की नियुक्ति की अंग्रेजी प्रणाली। इस प्रकार देखा जाता है

कि इंग्लैंड में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा की जाती है। फिर भी, न्यायपालिका काफी
 हद तक अछूती है

सख्त कानून के नियमों का गुण। संवैधानिक समझौते,

राजनीतिक अभ्यास और पेशेवर परंपरा, राजनीतिक से

प्रभाव "।

अंततः विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया कि एक बहु

सदस्य संवैधानिक निकाय से निष्पक्ष रूप से कार्य करने की अपेक्षा की जाती थी और स्वतंत्र रूप
 से, और संविधान के उल्लंघन में नहीं। यह था।

तर्क दिया कि बहुलता अपने आप में एक पर्याप्त सुरक्षा थी।

इस ओर से रिलायंस को टी. एन. शेषन बनाम पर रखा गया था। संघ का यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि संवैधानिक

भारत 34, ताकि अंततः

संशोधन ने "मूल संरचना" का उल्लंघन नहीं किया था संविधान, और वह, यह अवधारणा के अनुरूप

एक स्वतंत्र और स्वतंत्र न्यायपालिका को और मजबूत करके
संविधान की "मूल संरचना"।

123. श्री अजीत कुमार सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रवेश किया।

झारखंड राज्य की ओर से उपस्थिति। उन्होंने जोर देकर कहा,

84 (1995) 4 एस. सी. सी. 611 सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. 1. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

कि उसे सभी प्रस्तुतियों को अपनाने के रूप में लिया जाना चाहिए

भारत संघ की ओर से संबोधित। शुरू करते समय अपनी प्रस्तुतियों में, उन्होंने अनुच्छेद 124 (4)
पर निर्भरता रखी और

अनुच्छेद 217 (1) के तहत परंतुक (बी) यह तर्क देने के लिए कि

उच्च न्यायपालिका, एक आदेश के अलावा हटाया नहीं जा सका

प्रत्येक सदन द्वारा एक संबोधन के बाद राष्ट्रपति द्वारा पारित

संसद, कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा समर्थित

उस सदन के, और कम से कम दो तिहाई के बहुमत से

सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को प्रस्तुत किया गया था

राष्ट्रपति को, साबित दुर्व्यवहार के आधार पर या

असमर्थता। इस ओर से, विद्वान वरिष्ठ वकील को रखा गया सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की
धारा 16 पर निर्भरता, जो

यह प्रावधान करता है कि नियुक्त करने की शक्ति में यह शक्ति शामिल है कि

आदेश, कि जब तक संदर्भ अन्यथा आवश्यक नहीं है, सामान्य खंड अधिनियम 1897 के प्रावधान इन
पर लागू होंगे -

संविधान के प्रावधानों की व्याख्या, में
जिस तरह से वे एक अधिनियम की व्याख्या पर लागू होते हैं
विधायिका। उपरोक्त के आधार पर, यह चाहा गया था
जोर देकर कहा कि न्यायपालिका की किसी भी भूमिका के अभाव में
उच्च न्यायपालिका से संबंधित न्यायाधीश को हटाने का मामला,
न्यायपालिका मामले में प्रधानता की मांग नहीं कर सकी
अभिन्न अंग के रूप में उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति
"न्यायपालिका की स्वतंत्रता" का घटका। यह था।
प्रस्तुत किया गया, "न्यायपालिका की स्वतंत्रता" के मुद्दे पर,
नियुक्ति के तरीके का सवाल उससे कहीं कम महत्वपूर्ण था
न्यायाधीश के पद से हटाने का प्रश्न। विज्ञापन देना।
उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों को हटाने के तरीके में,
ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, यह था जोर देकर कहा कि न्यायाधीश को हटाने के
मामले में
उच्च न्यायपालिका में न्यायिक भागीदारी नहीं थी। यह केवल था
विधायिका का विशेषाधिकार। ऐसा होने पर, यह तर्क दिया गया था,
कि याचिकाकर्ताओं के कहने पर प्रस्तुतियाँ आगे बढ़ीं,
कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में प्रधानता होनी चाहिए,
न्यायपालिका में निहित होना एक भ्रान्ति के अलावा और कुछ नहीं था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

124. विद्वान वरिष्ठ द्वारा आगे बढ़ाया गया दूसरा विवाद

वकील ने कहा कि इसे एनजेएसी के रूप में नहीं माना जाना चाहिए,

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति न्यायपालिका से छीन ली जाएगी। यह प्रस्तुत किया गया था कि तीन

एन. जे. ए. सी. के छह सदस्यों में से न्यायपालिका से संबंधित थे, और

कि, उनमें से एक, अर्थात्, भारत के मुख्य न्यायाधीश को

एन. जे. ए. सी. की कार्यवाही की अध्यक्षता इसके अध्यक्ष के रूप में करते हैं।

इस प्रकार यह देखा गया कि यह पूरी तरह से गलत धारणा थी

याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क देने के लिए कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति, से छीन ली गई थी

न्यायपालिका, और कार्यपालिका के साथ निहित। यह प्रस्तुत किया गया था कि मौलिक रूप से कुछ भी अवैध या असंवैधानिक नहीं था

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति का तरीका,

जैसा कि विवादित संवैधानिक संशोधन द्वारा विचार किया गया है। यह भी तर्क दिया गया कि एन. जे. ए. सी. के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति के तरीके पर विचार नहीं किया जा सकता है।

संविधान, केवल इस तथ्य से कि एन. जे. ए. सी. के कोई भी दो सदस्य न्यायाधीश की नियुक्ति के प्रस्ताव को वीटो कर सकते हैं उच्च न्यायपालिका। और कि, उपरोक्त के परिणामस्वरूप होगा

"न्यायपालिका की स्वतंत्रता" का विध्वंस। समर्थन में वनाच्छादित प्रस्तुतियों में से, यह उजागर किया गया था, कि

न्यायाधीशों की नियुक्ति का तरीका, जिसमें अभिनिर्धारित किया गया था

द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों के मामलों में दिए गए निर्णयों से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि यदि नियुक्ति का तरीका

जैसा कि इसमें विचार किया गया था कि इसे बदल दिया गया था, यह "मूल" का उल्लंघन करेगा। संविधान की संरचना।

125. श्री यतींद्र सिंह, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता

एक मध्यस्थ के रूप में उपस्थिति में प्रवेश किया। उन्होंने तर्क दिया कि

भारत के संविधान की प्रस्तावना, अनुच्छेद 50 (जो प्रदान करता है)

न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए), शपथ

उच्च न्यायपालिका में नियुक्त न्यायाधीश का कार्यालय, सुरक्षा

सेवानिवृत्ति की निश्चित आयु सहित उनके कार्यकाल का संरक्षण

न्यायाधीशों को देय वेतन जिसमें वेतन और सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता शामिल हैं-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

छुट्टी, आदि, यह तथ्य कि न्यायाधीशों को उच्च पद पर नियुक्त किया गया था

न्यायपालिका ने अभिलेख न्यायालयों में कार्य किया, जिसके पास अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति थी, और न्यायिक अधिकारियों के प्रावधान

संरक्षण अधिनियम, 1850 और न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, 1985,

जो उन्हें नागरिक और आपराधिक दोनों से प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं

कार्यवाही, ऐसी घटनाएँ हैं, जिन्होंने "स्वतंत्रता" सुनिश्चित की

न्यायपालिका "। यह प्रस्तुत किया गया था कि नियुक्ति का तरीका

उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों का इससे कोई लेना-देना नहीं था

विवादित की वैधता के निर्धारण के रूप में संवैधानिक संशोधन का संबंध था, यह आवश्यक नहीं था

इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों का संदर्भ देना। द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों के मामलों में। यह प्रस्तुत किया गया था कि

एकमात्र प्रश्न जिसे निर्धारित करने की आवश्यकता थी

वर्तमान विवाद का संबंध यह है कि क्या एन. जे. ए. सी. के माध्यम से अभिनिर्धारित नियुक्ति का तरीका इसमें हस्तक्षेप करेगा। "न्यायाधीशों की स्वतंत्रता"। इस संबंध में सबसे पहले यह कहा गया था कि -

कि न तो दूसरे और न ही तीसरे न्यायाधीशों के मामले में

निष्कर्ष निकाला कि न्यायाधीशों की नियुक्ति का तरीका

संविधान की "मूल संरचना" का गठन करता है। न ही उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति का तरीका

जैसा कि द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों के मामलों में अभिनिर्धारित किया गया है, यदि

इसका उल्लंघन, संविधान के "मूल ढांचे" का उल्लंघन होगा।

यह प्रस्तुत किया गया था कि दूसरे में दिए गए निर्णय

और तीसरे न्यायाधीशों के मामलों ने केवल कानून की व्याख्या की, जैसा कि तब था

अस्तित्व में था। यह दावा किया गया था कि उपरोक्त निर्णय इस प्रश्न पर ध्यान नहीं देते हैं कि क्या कोई कारक या विशेषताएँ हैं।

माना जाता है, के "बुनियादी संरचना" के घटक थे

संविधान।

126. विद्वान वरिष्ठ वकील, जिन पर भी निर्भरता रखी गई

संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति का तरीका
 अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और जापान ने तर्क दिया कि इन सभी देशों में न्यायाधीशों की नियुक्ति
 उच्च न्यायपालिका, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही थी

} [2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्वतंत्र रूप से, और इस तरह, कोई कारण या औचित्य नहीं था
 इस न्यायालय के लिए यह अनुमान लगाने के लिए कि क्या न्यायाधीशों की नियुक्ति का तरीका
 दूसरे में विचार की गई स्थिति से बदल दिया गया था और
 तीसरे न्यायाधीश के मामले, विवादित द्वारा परिकल्पित मामले के लिए
 संवैधानिक संशोधन से "न्यायाधीशों की स्वतंत्रता" प्रभावित होगी। यह प्रस्तुत किया गया था कि विभिन्न देशों में
 दुनिया ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए चयन की विभिन्न प्रक्रियाओं को अपनाया था। प्रत्येक देश ने हासिल किया था
 "न्यायपालिका की स्वतंत्रता", और इस तरह, यह था यह सोचने के लिए अभिमानी है कि केवल न्यायाधीशों द्वारा नियुक्त न्यायाधीश,
 स्वतंत्र रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं।
 127. विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह भी बताया कि
 "कॉलेजियम प्रणाली "नियुक्ति की एकमात्र प्रक्रिया नहीं थी।
 न्यायाधीशों की, जो स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते थे
 न्यायपालिका "। अगर ऐसा होता, तो यह इस तरह से निष्कर्ष निकाला जाता
 द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों के मामलों में दिए गए निर्णय।
 यह विद्वान वरिष्ठ वकील का निवेदन था कि "न्यायपालिका की स्वतंत्रता" अन्य लोगों द्वारा प्राप्त की जा सकती है।
 यह दावा किया गया था कि नियुक्ति के तरीके पर विचार किया गया था विवादित संवैधानिक संशोधन में कोई कमजोरी नहीं थी,

न्यायाधीशों से लेकर उच्च न्यायपालिका तक। यह प्रस्तुत किया गया था कि

एन. जे. ए. सी. न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में पारदर्शिता के उद्देश्य को पूरा करेगा और साथ ही, चयन प्रक्रिया व्यापक आधार पर होती है। समापन करते हुए उन्होंने प्रस्तुतियाँ, यह विद्वान वकील द्वारा भी सुझाया गया था, कि एन. जे. ए. सी. को कुछ समय के लिए काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए, इसलिए इसकी शुरुआत में ही नष्ट किए जाने से पहले, परीक्षण किए जाने के लिए। और यह कि, प्रक्रिया को नकारना भी अनुचित होगा प्रयोग शुरू होने से पहले।

129. श्री दुष्यंत ए. दवे, वरिष्ठ अधिवक्ता और

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने प्रस्तुत किया कि एकमात्र प्रश्न जिस पर निर्णय लेने की आवश्यकता है,

वर्तमान विवाद का संदर्भ था, क्या तरीका

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के माध्यम से

एन. जे. ए. सी., संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत आएगा? सीखा है।

वरिष्ठ वकील ने सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्टों को उजागर करके अपनी दलीलें शुरू कीं।

[2015] 13 एस सी आर।

तथ्य यह है कि संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से विचार किया गया

संविधान के प्रावधान, एक बड़ी बुनियादी अवधारणा थी,

"न्यायपालिका की स्वतंत्रता" की तुलना में। यह था।

प्रस्तुत किया गया कि जिस तरीके से प्रस्तुतियाँ की गई थीं

याचिकाकर्ताओं के कहने पर, ऐसा प्रतीत होता है कि

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला है -

"बुनियादी संरचना सिद्धांत" में उच्चतम आधार पर रखा गया है।

विद्वान वरिष्ठ वकील ने इसकी सच्चाई का गंभीरता से विरोध किया

उपरोक्त विश्वास। यह प्रस्तुत किया गया था कि यदि वे प्रतिनिधित्व करते हैं

याचिकाकर्ता, दिए गए फैसले पर भरोसा कर रहे थे

द्वितीय न्यायाधीशों के मामले में, उपरोक्त सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए,

ऐसा करना कानूनी रूप से गलत था। कारण के अनुसार

विद्वान वरिष्ठ वकील थे, कि दूसरे में निर्णय न्यायाधीशों का मामला, किसी की व्याख्या पर आधारित नहीं था

संवैधानिक प्रावधान (ओं), और न ही यह एक विस्तृत पर आधारित था विचाराधीन विषय के संदर्भ में चर्चा,

न ही संविधान सभा की बहसों पर निर्भरता रखी गई थी।

यह इंगित किया गया था कि द्वितीय न्यायाधीशों में निर्णय विचार किए गए सिद्धांतों के आधार पर मामला प्रस्तुत किया गया था

निर्णय के लेखकों द्वारा, और किसी भी सिद्धांत पर नहीं

कानून। तदनुसार यह दावा किया गया कि याचिकाकर्ताओं '

विवाद, एकमुश्त अस्वीकृति के योग्य थे।

130. विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया

भारती मामला 0, मिनर्वा मिल्स लिमिटेड मामला 3 3, और आई. आर. कोएल्हो वी. तमिलनाडु राज्य-85, जिसमें संविधान की "बुनियादी संरचना" की अवधारणा तैयार की गई थी और उसे प्रभावी बनाया गया था, वे सभी मामले थे जिनमें विभिन्न पहलुओं पर न्यायपालिका की शक्ति थी।

समीक्षा को दबाया/अधीन किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया था,

कि उपरोक्त निर्णयों में से किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता था

यह निर्धारित करें कि क्या न्यायाधीशों की नियुक्ति का तरीका

उच्च न्यायपालिका के लिए, संविधान की "मूल संरचना" का एक हिस्सा था। इसलिए यह निर्भरता रखी गई थी

85 (2007) 2 एस. सी. सी. 1 सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

अनुच्छेद 368 पर तर्क देने के लिए, कि संशोधन करने की शक्ति

संविधान को एक "घटक शक्ति" के रूप में वर्णित किया गया था।

अर्थात्, उस शक्ति के समान एक शक्ति जो निहित होने लगी
संविधान सभा, संविधान का प्रारूपण करने के लिए। यह था।

"अनुच्छेद के तहत संसद के पास निहित घटक शक्ति करने के बाद, सीखा 368. उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति को उजागर

वरिष्ठ वकील ने भावुक प्रस्तुतियाँ दीं

के आधार पर की गई विभिन्न नियुक्तियों का संदर्भ

द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों के मामलों में अभिनिर्धारित प्रक्रिया।

एक की नियुक्ति के लिए स्पष्ट रूप से संदर्भ दिया गया था

इस न्यायालय के विशेष न्यायाधीश भी। यह बताया गया था कि

संबंधित न्यायाधीश ने सीज़िन लेकर एक मामले का फैसला किया था

उसी का, भले ही इसे पहले सुनवाई के लिए पोस्ट नहीं किया गया था

उसे। इसके बाद, भले ही एक समीक्षा याचिका दायर की गई थी

विसंगति को ठीक करें, उसी को संबंधित द्वारा खारिज कर दिया गया था

न्यायाधीश। के संदर्भ में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति

कॉलेजियम प्रणाली, विद्वान वरिष्ठ वकील ने जोर देकर बताया

बाहर, कि प्रक्रिया विवादित से पहले प्रचलन में है संवैधानिक संशोधन, एक बंद के रूप में वर्णित
किया जा सकता है

द्वार प्रक्रिया, जहाँ नियुक्तियाँ मौन में की जाती थीं

तरीके से। उन्होंने कहा कि प्रमुख हितधारकों सहित

निर्विवाद सत्यनिष्ठा वाले वकीलों से कभी परामर्श नहीं किया गया। यह.

प्रस्तुत किया गया था कि इनपुट कभी नहीं मांगे गए थे, उन लोगों से जो

सर्वश्रेष्ठ के चयन के लिए मूल्यवान सहायता प्रदान कर सकता है,

उपलब्ध लोगों में से। यह बताया गया कि

कॉलेजियम प्रणाली के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया,

कुछ मामलों में दुर्व्यवहार के लिए जाना जाता था, और वह, उसमें कुछ अंतर्निहित दोष थे। यह प्रस्तुत
किया गया था,

कि चयन की नीति और चयन की विधि थी
 न्यायसंगत नहीं होना, न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं होना, और
 इस तरह, गलत लोगों को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती थी
 "कॉलेजियम प्रणाली" के तहत नियुक्तियाँ की जाती हैं।

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

131. व्याख्या करने के तरीके के विषय पर

संविधान, उच्च पदों पर नियुक्तियों के संदर्भ में

न्यायपालिका, उच्च न्यायालय के पंजीयक (प्रशासन) पर निर्भरता रखी गई थी

दूसरे में दिए गए निर्णयों पर ध्यान देने के बावजूद न्यायाधीशों के मामले में, इस न्यायालय ने संदर्भ के साथ सावधानी बरती

अधीनस्थ न्यायपालिका पर उच्च न्यायालयों में निहित नियंत्रण। यह इंगित किया गया था, कि यह आयोजित किया गया था, कि नियंत्रण

निहित शक्ति को हड़पे बिना प्रयोग करना पड़ा

कार्यपालिका, विशेष रूप से अनुच्छेद 233, 234 के तहत शक्ति

और 235। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कार्यपालिका की शक्ति

बिना किसी औचित्य के दरकिनार नहीं किया जाएगा। यह था। तर्क दिया कि यह मान लेना अनुचित था कि केवल

न्यायपालिका सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकती थी, और कार्यपालिका या

विधायिका नहीं कर सकती।

132. विद्वान वरिष्ठ वकील ने भी भावुक कर दिया

यह भी कहा गया कि उन्हें न्याय से वंचित कर दिया गया था
 अर्थात्, इसके गरीब नागरिक

जो इसके सबसे अधिक हकदार थे,

देश। यह इंगित किया गया था कि नियुक्ति का तरीका

ऐसे न्यायाधीश जो गरीबों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील थे
 वकील का दावा था,

और जरूरतमंद। यह विद्वान वरिष्ठ

कि नई प्रणाली चयन और नियुक्ति के लिए लाई गई

उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और उनका परीक्षण किया जाना चाहिए,

और मामले में, कुछ मापदंडों के लिए प्रदान किया जाना था,

सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए इसके उचित कार्यकरण को सुनिश्चित करना,

इस तरह के दिशानिर्देश प्रदान करने के लिए इस न्यायालय के लिए हमेशा खुला था।

V. विभाजन और मुक्ति:

1.

133. संघ सरकार, साथ ही, भाग लेने वाली

सभी राज्य सरकारें अपने वेंटिलेशन में एकमत थीं कि सर्वोच्च न्यायालय अधिवक्ताओं को-चालू-रिकॉर्ड करता है

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

विवादित संवैधानिक संशोधन, पारित किया गया था

लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा सर्वसम्मति से,

जिसमें सभी राजनीतिक दलों के सांसदों ने बात की थी

एक स्वर में। लोकसभा ने 367 मतों के साथ इस विधेयक को पारित कर दिया था। सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया और कोई भी इसके खिलाफ नहीं था।

ए. आई. ए. डी. एम. के. के सदस्य-कुल 37, हालांकि अनुपस्थित रहे।

मतदान से)। राज्यसभा ने इस विधेयक को पारित करते हुए कुल संख्या-17 से पारित कर दिया।

विधेयक के पक्ष में मतदान करने वाले सदस्य और इसके सदस्यों में से एक - राम जेठमलानी, अनुपस्थित रहे। यह प्रस्तुत किया गया था, कि खाते पर

368 (2), आधे राज्य द्वारा कुछ ही समय में विधेयक की पुष्टि कर दी गई विधायिकाएँ। श्री तुषार मेहता, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर

भारत के जनरल ने न्यायालय को सूचित किया था कि जितने

अट्ठाईस राज्य विधानसभाओं ने अंततः विधेयक की पुष्टि की थी।

इसे राष्ट्रपति ने 31.12.2014 पर मंजूरी दी थी। इसलिए यह दावा किया गया कि संविधान (99 वां संशोधन) अधिनियम

प्रकट, लोगों की सर्वसम्मत इच्छा, और इसलिए,

उसी को इच्छा की अभिव्यक्ति माना जाना चाहिए

राष्ट्र को। इस तथ्य के आधार पर कि यह संवैधानिक है

संशोधन ने लोगों की इच्छा को प्रतिबिंबित किया, यह प्रस्तुत किया गया था कि एक प्रक्रिया के माध्यम से इसका परीक्षण करना उचित नहीं होगा

न्यायिक समीक्षा, यहां तक कि "बुनियादी" की अवधारणा की कसौटी पर भी

संरचना "।

134. याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील,

उपरोक्त कथन को गलत बताया। द.

विवाद को एक सवाल पूछकर खारिज कर दिया गया था, क्या वही है

क्या "संपन्न" राष्ट्र की इच्छा थी, या राष्ट्र की इच्छा थी

"हैव-नोट्स" में से? एक और सवाल पूछा गया कि क्या

विवादित संवैधानिक संशोधन ने इच्छा का प्रतिनिधित्व किया

अमीर, समृद्ध और प्रभावशाली, या गरीब और

जरूरतमंद, जिनकी परिस्थितियाँ, आशाएँ और अपेक्षाएँ थीं

विवादित संवैधानिक संशोधन से कोई लेना-देना नहीं है? यह.

प्रस्तुत किया गया था, कि राष्ट्र की इच्छा, केवल तय की जा सकती है

जनमत संग्रह या जनमत संग्रह द्वारा। यह प्रस्तुत किया गया था कि [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

याचिकाकर्ता स्वीकार करेंगे कि इसका निश्चित रूप से वर्णन किया जा सकता है

राजनीतिक-कार्यपालिका की भारी इच्छाशक्ति के रूप में। और नहीं।

संशोधन का एक अप्रत्यक्ष उद्देश्य था। याचिकाकर्ताओं की राय में, संशोधन सर्वसम्मति से पारित किया गया था सरल कारण, कि उच्च न्यायपालिका के कार्यों को सही करता है

कार्यपालिका और विधायिकाएँ। यह, यह बताया गया था,

राजनीतिक-कार्यपालिका को परेशान करता है।

135. लोगों की इच्छा के संदर्भ में, यह था

प्रस्तुत किया, कि उसी से आसानी से पता लगाया जा सकता है

एल. सी. गोलक नाथ मामले 4 1 में दिया गया निर्णय, जिसमें

ग्यारह-न्यायाधीश पीठ ने घोषणा की कि एक संवैधानिक संशोधन

संविधान के भाग III के संदर्भ में "कानून" था, और इसलिए, मौलिक की बाधा के अधीन था

अधिकार, उक्त भाग में। यह इंगित किया गया था कि संसद,

संविधान पारित करते समय अनुच्छेद 368 को लागू किया था (25 वां)

संशोधन) अधिनियम, 1971। उपरोक्त संशोधन द्वारा, एक कानून प्रदान करता है

शून्य घोषित नहीं किया जा सका, इस आधार पर कि यह था के माध्यम से व्यक्त मौलिक अधिकारों के साथ असंगत

अनुच्छेद 14, 19 और 31। अनुच्छेद 31 सी में यह भी प्रावधान किया गया है कि

ऐसी "घोषणा" वाला विधायी अधिनियम, अर्थात् -

कि यह राज्य की उपरोक्त नीति को प्रभावी बनाने के लिए था, इस आधार पर प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा कि यह नहीं था

वास्तव में इस तरह की नीति को प्रभावी बनाया। यह बताया गया था कि इस

केशवानंद भारती मामले में अदालत ने खारिज कर दिया था

आई. सी. गोलक नाथ मामले में निर्णय 4 1. यह न्यायालय, जबकि

अनुच्छेद 31 सी के हिस्से को असंवैधानिक मानते हुए, जिसने इनकार किया

न्यायिक समीक्षा, निर्दिष्ट "घोषणा" के आधार पर

ऊपर, यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायिक समीक्षा का अधिकार इसका एक हिस्सा था

संविधान की "बुनियादी संरचना", और इसका खंडन होगा

इसके परिणामस्वरूप संविधान की "मूल संरचना" का उल्लंघन होता है।

136. आगे बढ़ते हुए, यह प्रस्तुत किया गया कि

12.6.1975, लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी का चुनाव सर्वोच्च न्यायालय-ऑन-रिकॉर्ड था

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अपील लंबित है, संसद ने संविधान (39 वां संशोधन) अधिनियम पारित किया,

1975. उपरोक्त संशोधन द्वारा, संसद के लिए चुनाव,

प्रधानमंत्री और अध्यक्ष पर हमला नहीं किया जा सका, न ही

क्या चुनाव रद्द किया जा सकता है, या कभी किया गया माना जा सकता है

शून्य हो जाता है, किसी भी आधार पर जिसके आधार पर चुनाव हो सकता है

शून्य घोषित किया जाए। कुल मिलाकर और सार में, एक काल्पनिक कल्पना द्वारा कानून के अनुसार, प्रधानमंत्री और अध्यक्ष का चुनाव होगा

दोष (ओं) और अवैधताओं की परवाह किए बिना वैध बने रहें। उपरोक्त संशोधन द्वारा, यह प्रावधान किया गया था कि,

उच्चतम न्यायालय में लंबित अपील का निपटारा किया जाएगा संविधान के प्रावधानों के अनुरूप (39 वां)

संशोधन) अधिनियम, 1975। उपरोक्त संशोधन किया गया था इस न्यायालय द्वारा यह घोषणा करते हुए कि एक ही राशि एक

"कानून के शासन" का निषेध, और यह भी कि यह "विरोधी" था

लोकतांत्रिक ", और इस तरह, की" बुनियादी संरचना "का उल्लंघन किया

संविधान। यह प्रस्तुत किया गया था कि हड़ताल के जवाब के रूप में

संविधान के अनुच्छेद 39 ए के भौतिक भागों को हटाकर,

संसद ने अनुच्छेद 368 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए,

संविधान (42 वां संशोधन) अधिनियम, 1976 को पारित किया।

भारी बहुमत। उपरोक्त संशोधन के माध्यम से,

संसद ने अनुच्छेद 368 में खंड (4) और (5) जोड़े, जो नीचे पढ़ें:

"(4) इस संविधान का कोई संशोधन नहीं (जिसमें

भाग III के उपबंध) बनाए गए या किए जाने का तात्पर्य

इस अनुच्छेद के तहत चाहे पहले हो या बाद में

संविधान की धारा 55 का प्रारंभ (चालीस)
दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1976 पर सवाल उठाए जाएंगे।

किसी भी आधार पर किसी भी अदालत में।
(5) शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि

घटक पर कोई सीमा नहीं होगी

जोड़, परिवर्तन के माध्यम से संशोधन करने की संसद की शक्ति

या इस अनुच्छेद के तहत इस संविधान के प्रावधानों को निरस्त करें। "[2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उपरोक्त संशोधन को दरकिनार कर दिया गया था, क्योंकि

असंवैधानिक, एक सर्वसम्मति निर्णय द्वारा, मिनर्वा मिल्स में

लिमिटेड मामला 33। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि की संशोधन शक्ति

अनुच्छेद 368 के तहत संसद सीमित थी, क्योंकि उसने

संविधान को निरस्त करने या निरस्त करने या उसे नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है।

"बुनियादी या आवश्यक विशेषताएँ"।

137. विद्वान वरिष्ठ वकील ने बताया कि

वर्षों बाद, संसद द्वारा एक और रणनीति को अपनाया गया, कार्य में न्यायिक हस्तक्षेप से बचने के लिए

संसद। इस संबंध में, संदर्भ दिया गया था

संविधान (45 वां संशोधन) विधेयक, 1978, जिसमें बशर्ते कि संविधान की "बुनियादी संरचना" भी

जनमत संग्रह के माध्यम से इसके अनुमोदन पर संशोधन किया जा सकता है। द.

संशोधन ने अनुच्छेद 368 (2) में एक प्रावधान जोड़ा, जिसमें कहा गया है कि

"न्यायपालिका की स्वतंत्रता" के साथ समझौता करने वाला कानून

आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी, और

इसके बाद, अनुपलब्ध हो जाएगा, अगर एक साधारण द्वारा अपनाया जाता है

जनमत संग्रह में बहुमत से मतदान होता है। अपनी उपरोक्त कार्रवाई के माध्यम से,

उस समय की सरकार ने अपने इरादे का खुलासा किया

"न्यायपालिका की स्वतंत्रता" से भी समझौता करें। हालांकि

उपरोक्त विधेयक में भारी बहुमत से पारित किया गया था

लोकसभा, यह आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं जुटा सकी
कि के प्रस्तावक

राज्यसभा में। यह इंगित किया गया था

विधेयक तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार थी, न कि

कांग्रेस पार्टी सरकार (जो इसके लिए जिम्मेदार थी)

आपातकाल, और पहले के संवैधानिक संशोधन)। इसलिए इस बात पर जोर दिया गया कि इससे किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

राजनीतिक दलों ने एक स्वर में बात की थी, क्योंकि सभी राजनीतिक दल अपने संकल्प में एकजुट थे, डरने और वश में करने के लिए।

न्यायपालिका।

138. यह प्रस्तुत किया गया था कि विधायिका का इरादा

और कार्यपालिका, चाहे सत्ता में कोई भी दल हो,

"न्यायपालिका की स्वतंत्रता" पर आक्रमण करना। यह आगे था

प्रस्तुत किया, कि न्यायपालिका को नियंत्रित करने के प्रयास अधिक सर्वोच्च न्यायालय अधिवक्ता रहे हैं-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

हाल के दिनों में घोषित। इस संबंध में न्यायालय का ध्यान

लिली थॉमस बनाम में निर्णयों की ओर आकर्षित किया गया था। भारत संघ और मुख्य चुनाव आयुक्त बनाम. जान चौकीदार 87। यह था।

इंगित किया कि पूर्व निर्णय में, इस न्यायालय ने अभ्यावेदन की धारा 8 (4) को अमान्य और असंवैधानिक ठहराया।

लोक अधिनियम, 1951, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि

संसद सदस्य को एक अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई

कम से कम दो साल के लिए कारावास, पीड़ित नहीं होगा
 प्रावधान के तहत विचार की गई अयोग्यता, एक के लिए
 दोषसिद्धि की तारीख से तीन महीने की अवधि, या यदि
 दोषसिद्धि पर अपील या पुनरीक्षण के माध्यम से हमला किया गया था-जब तक कि ऐसा समय
 जब अपील या पुनरीक्षण का निपटारा किया गया हो। के द्वारा
 पूर्व निर्णय, दोषी सदस्य अयोग्य घोषित कर दिए गए,
 और उन्हें अपनी-अपनी सीटें खाली करनी पड़ीं, हालांकि,
 दोषसिद्धि चुनौती के तहत थी। बाद के फैसले में, यह न्यायालय
 पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए घोषणा की गई
 कि एक व्यक्ति जो जेल में बंद था, उसे वोट देने का कोई अधिकार नहीं था,
 धारा 62 (2) में निहित प्रावधानों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951। जब से वह
 निर्वाचक नहीं है, इसलिए यह माना गया कि वह नहीं हो सकता है
 किसी भी सदन के लिए चुनाव लड़ने के लिए योग्य माना जाता है
 संसद या किसी राज्य की विधान सभा के लिए।

139. यह इंगित किया गया था कि सरकार (तब द्वारा शासित)

यू. पी. ए.) ने जन चौकिदार मामले 87 में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को अमान्य करने के लिए
 विधेयकों की एक श्रृंखला पेश की। यह लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 2013
 को तीन चरणों में पारित करके करने की मांग की गई थी।

उपरोक्त निर्णय दिए जाने के महीनों। यह प्रस्तुत किया गया था कि विद्वान वकील के लिए यह पूरी तरह से
 गलत था

भारत संघ और संबंधित राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए

तर्क है कि संसद और राज्य द्वारा निर्धारण

संवैधानिक संशोधनों के संदर्भ में विधायिकाएँ,

86 (2013) 7 एससीसी 653 67 (2013) 7 एससीसी 507 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

उन कार्यों के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो पूरा राष्ट्र चाहता था,
या लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व किया। यह प्रस्तुत किया गया था कि
जो स्पष्ट रूप से असंवैधानिक था, दोनों का गठन नहीं कर सका राष्ट्र की इच्छा, या लोगों की इच्छा।

140. नियुक्ति की "कॉलेजियम प्रणाली" का उल्लेख करते हुए
उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों को यह बताया गया कि
नौ-न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय द्वारा स्थापित किया गया था
पीठ, दूसरे न्यायाधीशों के मामले में, जिसके माध्यम से
"न्यायपालिका की स्वतंत्रता को मजबूत किया गया और
मजबूत हुआ। इसे प्रधानता प्रदान करके प्राप्त किया जा सकता है
न्यायपालिका, के चयन और नियुक्ति के मामले में
उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीश। यह आगे बताया गया कि
कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना की गई है, जिसके कारण
पारदर्शिता का अभाव। यह प्रस्तुत किया गया था कि लाभ उठाते हुए
उपरोक्त आलोचनाओं में से सभी राजनीतिक दलों ने
स्पेक्ट्रम, निंदा और निंदा कर रहे हैं "कॉलेजियम प्रणाली"। एक बार फिर यह बताया गया कि
संसद न्यायिक प्रणाली में पैठ बनाने के अपने प्रयास में,
विवादित संवैधानिक संशोधन को अधिनियमित किया था, क्योंकि
न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना। यह तिरछा मकसद, यह था दावा किया, लोगों की इच्छा के
रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है, या
राष्ट्र की इच्छा।

141. तुलना में, का संदर्भ देते हुए
विवादित संवैधानिक संशोधन और एन. जे. ए. सी. अधिनियम, यह था
समान रूप से गंभीरता से तर्क दिया कि संवैधानिक संशोधन
नकार कर "न्यायपालिका की स्वतंत्रता" से समझौता किया
"न्यायपालिका की प्रधानता"। आक्षेपों के संदर्भ में
भारत संघ और संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित
सरकार, सुनवाई के दौरान, संदर्भ था

"संरचना के मामले:" शीर्षक वाले एक लेख पर लिखा गया द.

भारतीय और अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय पर न्यायालय संरचना का प्रभाव
द्वारा लिखित। संदर्भ दिया गया था

," निक रॉबिन्सन

उसमें निम्नलिखित व्याख्याएँ की गईं:

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

"उनके आभासी स्व-चयन को देखते हुए, भारतीय पर न्यायाधीश

उच्चतम न्यायालय की तुलना में कम राजनीतिकृत माना जाता है
संयुक्त राज्य अमेरिका। न्यायालय की पैनल संरचना भी

स्पष्ट वैचारिक अवरोधों को महसूस होने से रोकता है
(भले ही अधिक "कार्यकर्ता" या "रूढ़िवादी" न्यायाधीश हों)

इसका कोई मतलब नहीं है कि सभी न्यायाधीशों को इकट्ठा होना पड़ता है
की दृष्टि में वैध या निष्पक्ष होने के निर्णय के लिए एक साथ

जनता को। इसके बिल्कुल विपरीत, न्यायाधीशों को इस रूप में देखा जाता है
विभिन्न कौशल या पृष्ठभूमि लाना जो होना चाहिए

चुनिंदा रूप से उपयोग किया जाता है "।

142. यह प्रस्तुत किया गया था कि नियुक्ति की विधि,

द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों के मामलों के माध्यम से विकसित किया गया था

कई न्यायविदों द्वारा सराहा गया, जिन्होंने राय दी थी कि वही हो सकता है

संयुक्त राज्य द्वारा अनुकरण के योग्य एक मिसाल के रूप में माना जाए

साम्राज्य। इस संबंध में भी उल्लेख किया गया था,

हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य लॉर्ड टेम्पलमैन की राय

यूनाइटेड किंगडम में।

143. हमारे विचारशील विचार देने के बाद

प्रतिद्वंद्वी का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील द्वारा ग्रहण की गई स्थिति

दलों के लिए, यह मानना आवश्यक है कि प्रत्येक संवैधानिक
निम्नलिखित द्वारा

संसद द्वारा पारित संशोधन, या तो

368 (2), समझ की भावना में, व्यक्तियों द्वारा नहीं
के रूप में माना जाए

इस मुद्दे की कानूनी बारीकियों से परिचित,

लोगों की इच्छा, सरल कारण के लिए, कि

लोग। हमारे विचार में, जब तक निर्धारित बहुमत समर्थन करता है
एक के रूप में माना जाएगा

एक संवैधानिक संशोधन, इसे

संवैधानिक संशोधन वैध रूप से पारित किया गया। संतुष्ट करने के बाद
एक अभिव्यक्ति के रूप में समझा जा सकता है

बेंचमार्क से ऊपर, इसे

ऊपर देखे गए अर्थों में लोगों की इच्छा। ताकत है।

और एक संवैधानिक संशोधन की प्रवर्तनीयता होगी

बस वही, चाहे वह सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर. द्वारा पारित किया गया हो।

न्यूनतम बहुमत इसके लिए, या एक पर्याप्त द्वारा अभिनिर्धारित किया गया
सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई हो। क्या है?

बहुमत, या भले ही इसे

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि घोषित सीमाएँ हैं,

संसद को प्रदत्त संशोधन शक्ति पर, जो

उल्लंघन नहीं किया जा सकता है।

144. संसद द्वारा अधिनियमित एक साधारण विधान

संघ सूची में निहित विषयों के संदर्भ में या

समवर्ती सूची, और इसी तरह, राज्य सूची में निहित विषयों पर राज्य विधानमंडलों द्वारा अधिनियमित
सामान्य विधान और

समवर्ती सूची, ऊपर देखी गई समझ के अर्थ में,

के अनुरूप किए गए अधिनियमों के रूप में माना जा सकता है

लोगों की इच्छा, सामान्य व्यक्तियों द्वारा जो कानूनी से परिचित नहीं हैं

मुद्दे की खूबियाँ। इसमें भी, विधानों की शक्ति पर घोषित सीमाएँ हैं, जिनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता
है।

145. लगभग सभी चुनौतियों में, के आधार पर उठाया गया

संवैधानिक संशोधनों के "बुनियादी ढांचे" का उल्लंघन

अनुच्छेद 368 के तहत बनाया गया, और विशेष रूप से, जिनकी आवश्यकता है विशेष और अधिक कठोर प्रक्रिया का अनुपालन अनुच्छेद 368 (2) के तहत परंतुक में व्यक्त, दोहराया गया संघ के हाथों दिया गया दावा, एक ही। भारत संघ का यह तर्क रहा है कि संविधान में एक संशोधन, निम्नलिखित द्वारा पारित किया गया अनुच्छेद 368 (2) के परंतुक में व्यक्त प्रक्रिया, लोगों की इच्छा का गठन किया, और यह विषय नहीं था न्यायिक समीक्षा के लिए। एक ही तर्क बार-बार दिया गया था इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए खारिज कर दिया कि अनुच्छेद 368 अभिनिर्धारित करता है संविधान के संशोधन के लिए केवल एक "प्रक्रिया", और वह, उसी में निहित "शक्ति" के रूप में नहीं माना जा सकता था संसद संविधान में संशोधन करेगी, ताकि "मूल" को बदला जा सके संविधान, जिसे इस रूप में भी वर्णित किया गया है, "संविधान की बुनियादी विशेषताएं/बुनियादी संरचना। उपरोक्त पर उद्धृत निर्णयों के माध्यम से स्थिति का अनुमान लगाया गया है याचिकाकर्ताओं की ओर से, जिसका संदर्भ दिया गया है यहाँ ऊपर।

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

146. इसलिए, भले ही संसद हो सकती है

संविधान (121 वां संशोधन) विधेयक को भारी बहुमत के साथ पारित किया गया, क्योंकि इसमें केवल 37 सदस्य थे।

ए. आई. ए. डी. एम. के. ने जानबूझकर लोक सभा में मतदान से परहेज किया था।

राज्यसभा के केवल एक सदस्य-राम

जेठमलानी ने जानबूझकर पक्ष में मतदान करने से परहेज किया था

अतः यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि इसे न्यायिक समीक्षा से छूट दी गई है। न्यायिक पुनर्विलोकन का दायरा

एक संवैधानिक संशोधन और/या एक साधारण विधान,
चाहे वह संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित हो,
भिन्न नहीं हो सकता है, ताकि विभिन्न मानकों को अपनाया जा सके
संबंधित सदस्यों की संख्या पर विचार करें।
विधायिका, जिसने संबंधित को अनुमोदित और पारित किया था
वर्जित क्षेत्र को पार किया। यह पहलू निस्संदेह न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। उपरोक्त में
मामले के दृष्टिकोण से, यह मानना अनिवार्य है कि विवादित
संवैधानिक संशोधन के साथ-साथ एन. जे. ए. सी. अधिनियम भी न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा।
संविधान की संरचना और उस संबंध में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मानदंड, भले ही विवादित हों।
विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया विवाद उत्तरदाताओं, कि विवादित संवैधानिक संशोधन है
न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से उपलब्ध नहीं है।

II.

147. यह विद्वान वकील की प्रस्तुति थी

सामान्य तौर पर, कि "बुनियादी विशेषताएँ/बुनियादी संरचना"

संविधान, केवल सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्टों के एक सादे पठन से एकत्र किया जाना चाहिए

[2015] 13 एस सी आर।

संविधान के प्रावधान, जैसा कि वे मूल रूप से थे/थे

अधिनियमित किया। इस संबंध में विद्वानों द्वारा इसे स्वीकार किया गया

याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील, कि दायरा और विस्तार
"बुनियादी विशेषताओं/बुनियादी संरचना" में से,

संविधान की

केवल संविधान के प्रावधानों से पता लगाया जाए,

जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, और इसके अतिरिक्त, व्याख्या से

इस न्यायालय द्वारा संबंधित प्रावधानों पर रखा गया। उपरोक्त याचिकाकर्ताओं की ओर से किया गया योग्य दावा था, का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील के लिए अस्वीकार्य उत्तरदाताओं।

148. उपरोक्त असहमति, किसी की आवश्यकता नहीं है विस्तृत विश्लेषण। तत्काल पहलू में निर्धारित किया जाता है एम. नागराज मामला 3 6, जिसमें यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था:

" सवाल यह है कि क्या विवादित संशोधन

मूल संविधान को त्याग दें। इसका जोरदार आग्रह किया गया था

याचिकाकर्ताओं की ओर से कि उद्देश्यों का कथन

और कारण इंगित करते हैं कि विवादित संशोधन

संसद द्वारा रद्द करने के लिए घोषित किया गया है

इस न्यायालय के निर्णय। हम इसमें कोई योग्यता नहीं पाते हैं।
तर्क। संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत

इस न्यायालय की घोषणा देश का कानून है।

149. एक प्रावधान का कारण, प्रभाव और विस्तार, जो एक चुनौती का आधार है, कभी-कभी स्पष्ट नहीं हो सकता है।

उसके एक सादे पठन से। इसके द्वारा दी गई व्याख्या

एक विशेष प्रावधान पर न्यायालय, निश्चित रूप से एक

इसकी समग्र समझ, जिसमें सादा पठन होगा स्वाभाविक रूप से माना गया है, लेकिन इसके अलावा, एक सामंजस्यपूर्ण आधार पर उसमें छिपी महत्वपूर्ण मौन

प्रावधान का निर्माण, आसपास के संयोजन के साथ

प्रावधानों पर भी विचार किया गया होगा। अनुच्छेद 141 का अधिदेश, क्षेत्र के भीतर प्रत्येक न्यायालय को बाध्य करता है।

व्याख्या, निष्कर्ष या अर्थ का सम्मान करने के लिए भारत का

इस न्यायालय द्वारा किसी प्रावधान को सौंपा गया। इसलिए यह होगा कि अधिकारपूर्ण, संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं पर भरोसा किया गया-
ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

संबंधित प्रावधानों को अर्थ देते हुए,
 उन्हें सौंपी गई समझ और व्याख्या, उनके बारे में
 इस न्यायालय द्वारा व्याख्या। मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में, यह
 एक समझ पर बने रहना न तो कानूनी होगा और न ही न्यायसंगत होगा।
 संबंधित प्रावधानों का, केवल सादा पठन पर
 जैसा कि उत्तरदाताओं की ओर से सुझाव दिया गया था। यहाँ तक कि
 अनुच्छेद 141 के एक सादे पठन पर, हम बाध्य हैं,
 संविधान के प्रावधान, जिस तरह से इस न्यायालय द्वारा उनकी व्याख्या की गई है।

150. जिस तरीके से अनुच्छेद 124, 217 और 222 में उपयोग किए गए "परामर्श" शब्द की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की है।

न्यायालय, में बहुत विस्तार से विचार किया गया है "संदर्भ ऑर्डर ", और इसलिए, हमारे लिए
 फिर से रिकॉर्ड करने का कोई अवसर नहीं है।

एक बार फिर वही। यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है, कि शब्द
 "अनुच्छेद 124, 217 और 222 में निहित परामर्श
 द्वारा व्यक्त की गई राय को प्रधानता देने के रूप में पढ़ा जाना
 भारत के मुख्य न्यायाधीश (एक निर्णय के आधार पर, एक
 न्यायाधीशों का कॉलेजियम), जैसा कि "संदर्भ" में निष्कर्ष निकाला गया है

आदेश "। द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों के मामलों में, उपरोक्त इस न्यायालय द्वारा प्रावधानों
 की व्याख्या की गई थी, क्योंकि वे मौजूद थे

संविधान सभा द्वारा 26.11.1949 पर अपनाया गया था (जो 26.01.1950 पर प्रभावी हुआ)। इस प्रकार हम
 दोहराते हैं, कि उच्चतर न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में
 न्यायपालिका, और मुख्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण के मामले में भी
 और एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश,
 अनुच्छेद 124, 217 और 222, प्रमुख को प्रधानता प्रदान करता है।

भारत के न्यायाधीश और उनके न्यायाधीशों का कॉलेजियम, उत्तरदायी है उपरोक्त प्रावधानों के एक अभिन्न घटक के रूप में स्वीकार किया गया

(जैसा कि मूल रूप से लागू किया गया था)। इसलिए, जब चयन और नियुक्ति के संदर्भ में कोई प्रश्न (साथ ही, स्थानांतरण)

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की संख्या को उठाया जाता है, यह आरोप लगाते हुए कि "न्यायपालिका की स्वतंत्रता" एक "बुनियादी विशेषता/संरचना" के रूप में है।

संविधान का उल्लंघन किया गया है, यह सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट होनी चाहिए

[2015] 13 एस सी आर।

यह सुनिश्चित किया गया कि क्या न्यायपालिका की प्रधानता का प्रयोग किया जाता है

भारत के मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से (एक सामूहिक आधार पर)

न्यायाधीशों के कॉलेजियम के विवेक का उल्लंघन किया गया था)। फिर

अकेले, क्या यह निष्कर्ष निकालना संभव होगा कि "न्यायपालिका की स्वतंत्रता" एक आवश्यक "बुनियादी विशेषता" के रूप में है या नहीं। संविधान का, संरक्षित किया गया था (-और नहीं किया गया था

तोड़ दिया)।

III.

151. हम पहले ही "संदर्भ" में निष्कर्ष निकाल चुके हैं

आदेश ", कि अनुच्छेद 124, 217 में प्रयुक्त "परामर्श" शब्द

और 222 (जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया है) को निहित के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया के संदर्भ में न्यायपालिका में प्रधानता

उच्च न्यायपालिका को, और स्थानांतरण के संदर्भ में भी एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों से दूसरे उच्च न्यायालय में। उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, निम्नलिखित मापदंड

इन पर विचार किया गया:

(i) सबसे पहले, चार निर्णयों का संदर्भ दिया गया था, अर्थात्, समशेर सिंह मामला 1 1 1, जो 1974 में एक सात-न्यायाधीश द्वारा दिया गया था।

बेंच, जिसमें मुख्य सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए -

"न्यायपालिका की स्वतंत्रता ", यह निष्कर्ष निकाला गया कि

न्यायपालिका में सर्वोच्च गणमान्य व्यक्ति के साथ परामर्श-प्रमुख
 भारत के न्याय का, व्यवहार में, मतलब था कि अंतिम शब्द होना चाहिए
 भारत के मुख्य न्यायाधीश से संबंधित हैं, अर्थात्, में प्रधानता
 उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला आवश्यक है
 न्यायपालिका के साथ आराम करें। उपरोक्त स्थिति को 1977 में पांच न्यायाधीशों द्वारा संकलचंद हिम्मतलाल
 सेठ मामले 5 में बनाए रखा गया था।
 पीठ, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सभी संभावित मामलों में,
 भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी गई सलाह (के दौरान
 उसका "परामर्श"), मुख्य रूप से द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए भारत सरकार, और वह, यदि
 सरकार अलग हो जाती है
 भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी गई सलाह, न्यायालय करेंगे
 जाँचने का अवसर है, यदि कोई अन्य बाहरी सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड हैं

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]
 कार्यपालिका के निर्णय में परिस्थितियाँ आ गई थीं। में।
 तत्काल निर्णय, ताकि गंभीरता पर जोर दिया जा सके इस मामले में, इस न्यायालय ने यह भी व्यक्त
 किया कि उसे उम्मीद है कि
 उपरोक्त शब्द बहरे कानों पर नहीं पड़ेंगे। एक ही स्थिति इसे 1993 में नौ-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा
 7 के बहुमत से दूसरे न्यायाधीशों के मामले में अपनाया गया था: 2, जो भी आया
 निष्कर्ष, कि प्रथम न्यायाधीशों में दिया गया निर्णय
 मामला, सही कानून निर्धारित नहीं किया। एम. एम. पुंछी, जे. (के रूप में)
 वह तब) पीठ के न्यायाधीशों में से एक थे, जिन्होंने अल्पमत की राय का समर्थन किया, उन्होंने भी इस विचार
 का समर्थन किया कि
 कार्यपालिका द्वारा की गई सिफारिशों को स्थगित करने के लिए
 भारत के मुख्य न्यायाधीश, अवमूल्यन के कार्य के बराबर होंगे,
 "संविधान की भावना का उल्लंघन"। योग और सार में

इसलिए, दूसरे न्यायाधीशों का मामला, लगभग सर्वसम्मति से

निष्कर्ष निकाला कि चयन और नियुक्ति के मामले में

पीठ ने दूसरे न्यायाधीशों में दी गई स्थिति को दोहराया मामला।

((ii) दूसरा, संविधान से उभरने वाला अंतिम आशय।

अन्य बातों के साथ-साथ समापन टिप्पणियों पर आधारित विधानसभा की बहस

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने कहा कि न्यायपालिका

कार्यपालिका से स्वतंत्र होना चाहिए। उपरोक्त स्थिति

विषय पर विचार-विमर्श करते हुए व्यक्त किया गया था

"उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति। डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा व्यक्त भावनाओं का जवाब देते हुए

के. टी. शाह, के. एम. मुंशी, तजामुल हुसैन, अल्लादी कृष्णस्वामी

आयर और अनंतसायनम अय्यंगार ने इस दृष्टिकोण का उल्लेख किया

संविधान सभा, जिसमें सदस्य आम तौर पर होते थे

समझौता, कि "न्यायपालिका की स्वतंत्रता", से कार्यपालिका को "कानून द्वारा जितना स्पष्ट और निश्चित किया जा सकता है उतना स्पष्ट किया जाना चाहिए"। बहस के दौरान किया गया उपरोक्त दावा

सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति का मुद्दा, सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

प्रभावी रूप से स्वीकृति के परिणामस्वरूप, कि का मुद्दा

"उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति, एक प्रत्यक्ष थी

"न्यायपालिका की स्वतंत्रता" के साथ संबंध। डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

नियुक्ति के तरीके को अपनाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया

यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य में प्रचलित न्यायाधीशों की संख्या

अमेरिका के राज्य, और इस तरह, के अधीनता को खारिज कर दिया

न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया

कार्यपालिका और विधायिका के हाथों में उच्च न्यायपालिका

क्रमशः। बाद के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए डॉ. बी. आर.

अम्बेडकर को संदेह और अविश्वास था कि

संभवतः, उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियाँ, हो सकती हैं "राजनीतिक दबाव" और "राजनीतिक विचारों" से प्रभावित।

(iii) तीसरा, नियुक्ति का वास्तविक अभ्यास और तरीका उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीश, संसद से उभरते हुए

बहस, स्पष्ट रूप से दर्शाती है, कि बिल्कुल सभी न्यायाधीश (को छोड़कर)

एक मामले) 1950 से नियुक्त किया गया था, पर नियुक्त किया गया था

भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह। अतः यह स्पष्ट है कि राजनीतिक-कार्यपालिका इस तथ्य के प्रति सचेत रही है कि

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति का मुद्दा, न्यायपालिका की प्रधानता को अनिवार्य किया, जिसके माध्यम से व्यक्त किया गया

भारत के मुख्य न्यायाधीश। इस पक्ष में, विद्वान वकील भी जनरल ने स्वीकार किया था कि वरिष्ठ न्यायाधीशों को हटा दिया गया था

सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति के समय

1973 में भारत के मुख्य न्यायाधीश, के न्यायाधीशों का सामूहिक स्थानांतरण

1976 में आपातकाल के दौरान उच्च न्यायपालिका, और

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का दूसरा अधिनिर्णय, उस समय 1977 में भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में

कार्यकारी विचलन।

(iv) चौथा, नियुक्ति के लिए प्रक्रिया ज्ञापन उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति

1950, भारत के स्वतंत्र होने के तुरंत बाद, साथ ही,

न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया ज्ञापन और

1999 में उच्च न्यायपालिका के मुख्य न्यायाधीशों को फिर से नियुक्त किया गया।

द्वितीय न्यायाधीशों के मामले में निर्णय, यह प्रकट करता है कि सर्वोच्च न्यायालय अधिवक्ताओं को-चालू-रिकॉर्ड करता है

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

कार्यपालक ने समझा और स्वीकार किया था कि चयन और उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी से, और मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर बनाया जाएगा भारत।

(v) पाँचवाँ, के लिए जगह में प्रक्रिया के लिए विज्ञापन किया गया है उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों का चयन और नियुक्ति, उत्तरदाताओं की ओर से प्रस्तुत किया गया निवेदन, कि द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों के मामलों ने एक प्रक्रिया बनाई थी, जहाँ न्यायाधीश न्यायाधीशों का चयन और नियुक्ति करते हैं, या वह, प्रणाली साम्राज्य में साम्राज्य की नियुक्ति के लिए बनाया गया था न्यायाधीशों पर विचार किया गया और स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया (में "संदर्भ आदेश ")। इसके अलावा, निवेदन, कि चयन की प्रचलित प्रक्रिया में कार्यपालिका की कोई भूमिका नहीं थी। और उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति को भी इस मामले में कार्यपालिका की भूमिका को उजागर करके खारिज कर दिया गया था उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति। जबकि उपरोक्त निष्कर्षों को दर्ज करते हुए, इसे बनाए रखा गया था (में "संदर्भ आदेश "), नियुक्ति के मामले में वह प्रधानता उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की संख्या, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास थी, और यह कि, यह सामूहिक ज्ञान पर आधारित था न्यायाधीशों का एक कॉलेजियम।

(vi) छठा, विवाद के कहने पर आगे बढ़ा प्रत्यर्थियों, कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में भी उच्च न्यायपालिका को (और उनके स्थानांतरण के मामले में) अनुच्छेद 124, 217 (और 222), में निहित माना जाना चाहिए कार्यपालिका, क्योंकि राष्ट्रपति के आधार पर

अनुच्छेद 74 में निहित संवैधानिक जनादेश, में कार्य करना था
 उसके द्वारा दी गई सहायता और सलाह के अनुसार
 मंत्रिपरिषद को यह मानते हुए खारिज कर दिया गया था कि इसमें प्रधानता
 उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला,
 भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ बने रहे, और वह,
 यह एक कॉलेजियम के सामूहिक ज्ञान पर आधारित था
 न्यायाधीशों का। उपरोक्त निष्कर्ष को दर्ज करने में, निर्भरता थी
 अनुच्छेद 50 पर रखा गया। रिलायंस को अनुच्छेद 50, सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर. पर
 भी रखा गया था।

एक और निष्कर्ष दर्ज करने के लिए, कि अगर की शक्ति
 न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका पर छोड़ दी गई थी, वही
 "न्यायपालिका की स्वतंत्रता" के सिद्धांतों का उल्लंघन करेगा और "शक्तियों का पृथक्करण"।

152. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह निष्कर्ष निकालना होगा कि

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला, जैसे -

उनके स्थानांतरण के मामले में भी, निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रधानता अनिवार्य रूप से भारत के मुख्य
 न्यायाधीश के पास होती है।

और यही उम्मीद की जाती थी कि न्यायाधीशों के एक कॉलेजियम के सामूहिक ज्ञान के आधार पर इसे व्यक्त
 किया जाएगा। ऐसा होने पर

निष्कर्ष निकाला, हम उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील के हाथों दिए गए सभी प्रस्तुतियों को अस्वीकार
 करते हैं, प्रचार करते हुए

इसके विपरीत।

IV.

153. अगला प्रश्न जो विचार के लिए उत्पन्न होता है

क्या न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया है

उच्च न्यायपालिका (अर्थात्, मुख्य न्यायाधीशों और न्यायपालिका के न्यायाधीशों के लिए)

उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय), और मुख्य न्यायाधीश का स्थानांतरण

एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और न्यायाधीश,

विवादित संवैधानिक संशोधन के माध्यम से विचार किया गया,

निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रधानता बनाए रखता है और बनाए रखता है,

न्यायपालिका के साथ? यह विद्वानों का जोरदार तर्क था

महान्यायवादी, विद्वान महान्यायवादी, विद्वान
बड़ी संख्या

अतिरिक्त महान्यायवादी, और विद्वानों की एक

वरिष्ठ वकील जिन्होंने उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व किया, कि यहाँ तक कि
संवैधानिक संशोधन के बाद, में प्रधानता

विवादित

अनुच्छेद 124, 217 और 222 के तहत निर्णय लेने की प्रक्रिया,

मामले के पहलू का संबंध है, इसकी ओर से तर्क दिया गया था
के छह सदस्यों में से तीन

उत्तरदाताओं में से, कि एनजेएसी

न्यायपालिका से लिए गए पदेन सदस्य थे-प्रमुख

भारत के न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के दो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश

न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश के बगल में।

उपरोक्त सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं-ऑन-रिकॉर्ड के साथ संयोजन में

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे. जे.

तथ्यात्मक स्थिति, यह बताया गया था कि केवल एक ही था

राजनीतिक-कार्यपालिका से नामित-केंद्रीय मंत्री

छह में से दो सदस्य-सदस्य एन. जे. ए. सी., "प्रतिष्ठित" थे।
होने की उम्मीद की जाती थी। इसलिए,

जिन व्यक्तियों से राजनीतिक रूप से तटस्थ

उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील के अनुसार,
के मामले में प्रधानता

न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति

उच्च न्यायपालिका को, और स्थानांतरण के मामले में भी

एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश,

विवादित संवैधानिक संशोधन के तहत भी न्यायपालिका के हाथों में बना रहा।

154. उपरोक्त प्रस्तुतिकरण के साथ, यह था

जोर देकर कहा कि एनजेएसी अधिनियम के प्रावधान अभिधारणा, कि एन. जे. ए. सी. किसी व्यक्ति की सिफारिश नहीं करेगा

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति, यदि कोई दो

एन. जे. ए. सी. के सदस्य इस बात से सहमत नहीं थे

सिफारिश करें। इस तथ्य के आधार पर, कि मुख्य न्यायाधीश भारत और उच्चतम न्यायालय के दो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश,

एन. जे. ए. सी. के पदेन सदस्य थे, यह दावा किया गया कि

एक अनुपयुक्त सिफारिश को अस्वीकार करने के लिए वीटो शक्ति

एन. जे. ए. सी. के न्यायिक घटक को बनाए रखने में परिणाम होगा

चयन के मामले में न्यायपालिका के हाथों में प्रधानता

और उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति, और

एक से मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों के स्थानांतरण का मामला

उच्च न्यायालय से दूसरे तक। यह विद्वान वकील के अनुसार

उत्तरदाताओं, क्योंकि न्यायिक घटक होगा

एनजेएसी के अन्य सदस्यों को रोकने के लिए पर्याप्त होना,

अपने रास्ते से।

155. हमारे विचारशील ध्यान देने के बाद

विवाद से ऊपर, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है, कि तरीके से

विद्वान वकील द्वारा व्यक्त किया गया, सुझाए गए निष्कर्ष इसे कागज पर उचित ठहराया जा सकता है। विचार करने के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या व्यावहारिकता के मामले में, विवादित

संवैधानिक संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर. माना जा सकता है।

निर्णय लेने के मामले में निरंतर, प्रधानता, के तहत

अनुच्छेद 124, 217 और 222 के संशोधित प्रावधान,

अनुच्छेद 124 ए के अंतःस्थापित प्रावधानों के साथ संयोजन

124 सी, न्यायपालिका के साथ?

156. विद्वान वकील द्वारा की गई व्याख्या

जनरल और प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ अन्य विद्वान वकील

उत्तरदाता, एक अति सरलीकृत और संकीर्ण से उभरते हैं

एक समग्र दृष्टिकोण। हमारे लिए यह स्वीकार करना संभव नहीं है कि न्यायपालिका की प्रधानता को माना जाएगा केवल यह सुनिश्चित करके कि न्यायिक घटक में

एन. जे. ए. सी. की सदस्यता, अस्वीकार करने में पर्याप्त रूप से सक्षम थी एक अयोग्य उम्मीदवार की उम्मीदवारी। हम संतुष्ट हैं कि

प्रधानता के मामले में एन. जे. ए. सी. का न्यायिक घटक,

की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए स्वयं सक्षम होना चाहिए

योग्य नामांकित व्यक्ति भी। प्रतिस्थापित योजना के तहत, यहां तक कि

यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश और दो अन्य वरिष्ठतम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (भारत के मुख्य न्यायाधीश के बगल में),

किसी मनोनीत व्यक्ति को उच्च पद पर नियुक्ति के योग्य समझें।

न्यायपालिका, संबंधित व्यक्ति को अभी भी नियुक्त नहीं किया जा सकता है,

यदि एन. जे. ए. सी. के कोई दो सदस्य अन्यथा विचार रखते हैं। यह होगा बाहर होना- न्यायपालिका की प्रधानता के लिए उचित रूप से अप्रिय

घटक। तत्काल मुद्दे का परिमाण, इस तथ्य से स्पष्ट है कि दो "प्रतिष्ठित व्यक्ति" (-सामान्य व्यक्ति,

विद्वान महान्यायवादी के अनुसार), पराजित कर सकता है

भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के दो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा सर्वसम्मति से की गई सिफारिश,

विचाराधीन व्यक्ति की नियुक्ति का समर्थन करना। बिना किसी संदेह के, उच्च न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति के मामले में न्यायपालिका की प्रधानता को कम करना।

न्यायपालिका। इसे अप्रिय बताने का कारण यह है

- विद्वान महान्यायवादी के अनुसार, "प्रतिष्ठित व्यक्ति"

न्यायपालिका से कोई संबंध नहीं रखने वाले सामान्य व्यक्ति होने चाहिए थे, सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

या यहाँ तक कि वकालत के पेशे के लिए, शायद ऐसे व्यक्ति जो
हो सकता है कि उनके पास कानून से संबंधित कोई शैक्षणिक योग्यता न हो, ऐसे सामान्य व्यक्तियों के पास
सामूहिक अधिकार होगा कि वे
भारत के सर्वोच्च न्यायालय से। तात्कालिक मुद्दा यह है कि स्पष्ट रूप से कहीं अधिक प्रतिगामी, जब
केंद्रीय मंत्री
कानून और न्याय का प्रभार भी सर्वसम्मत दृष्टिकोण का समर्थन करता है
न्यायिक घटक की, क्योंकि अभी भी असहमति की आवाज
"प्रतिष्ठित व्यक्ति" प्रबल होंगे। यह स्पष्ट है कि प्रधानता
न्यायपालिका को एक और विनाशकारी झटका दिया गया है, इसे बेहद नाजुक बनाकर।

157. जब मुद्दा इतना महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि

उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की संवैधानिक स्थिति, यह व्यक्तियों की नैतिक शक्ति पर निर्भर
रहना घातक हो सकता है। द.

न्यायपालिका को निर्दोष लोगों द्वारा संचालित किया जाना चाहिए

सत्यनिष्ठा, जो बिना किसी भय के अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं या

अनुग्रह करें। विकल्प स्वीकार करने का कोई सवाल ही नहीं है। प्रक्रिया, जो न्यायपालिका की
प्रधानता सुनिश्चित नहीं करती है

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति का मामला (साथ ही मुख्य न्यायाधीशों के
स्थानांतरण के मामले में भी)

और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, अन्य उच्च न्यायालयों के)। उपरोक्त में

घोषित स्थिति, यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि

एन. जे. ए. सी. के गठन के लिए विचार किया गया संयोजन ऐसा है,

जो एक आसान उल्लंघन के लिए अतिसंवेदनशील नहीं होगा

"न्यायपालिका की स्वतंत्रता"

158. अनुच्छेद 124 ए (1) (ए) और (बी) में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

न्यायपालिका को मामले में पर्याप्त प्रतिनिधित्व

घटक, के मामले में न्यायपालिका की प्रधानता सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों का चयन और नियुक्ति,

और इसलिए, उन्हें अलग रखा जा सकता है और मारा जा सकता है

के "मूल संरचना" के उल्लंघन के रूप में नीचे

भारत का संविधान। इस प्रकार हम संतुष्ट हैं कि

"संविधान की मूल संरचना का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया जाएगा।

यदि उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों के चयन की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

के माध्यम से विचार किए गए तरीके से संचालित किया जाना था

संविधान की "बुनियादी संरचना" को अधिकार देता है, जिसके लिए उत्तरदायी है एक तरफ रख दें।

बी.

159. यह आश्चर्य की बात है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश

न्यायपालिका के पिता परिवार के रूप में उनके पद का लेखा-जोखा

बंधुत्व, और गंभीर मुद्दों के कारण, जो उनके सामने न्यायिक निर्णय के लिए आते हैं, जो अथाह हैं

दूर के मुद्दों के अलावा राजनीतिक और वित्तीय परिणाम जनहित तक पहुँचते हुए, किसी और द्वारा संदेह नहीं किया गया था

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर, संविधान के दौरान

विधानसभा में बहस, जब उन्होंने संविधान के कुछ सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया

विधानसभा, कि उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों का चयन और नियुक्ति की "सहमति" के साथ की जानी चाहिए

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने यह टिप्पणी करते हुए कि भले ही

भारत के मुख्य न्यायाधीश एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। सभी विफलताओं, सभी भावनाओं और सभी के साथ सिर्फ एक आदमी

पूर्वाग्रह, जो आम लोगों में होते हैं। और इसलिए,

संविधान सभा ने इसे व्यक्तिगत विवेक पर नहीं छोड़ा

भारत के मुख्य न्यायाधीश के, लेकिन एक के साथ परामर्श की आवश्यकता न्यायाधीशों की बहुलता, परामर्श प्रक्रिया में शामिल करके (भारत के राष्ट्रपति का विवेकाधिकार), न केवल भारत के न्यायाधीश भारत से)। आम तौर पर यह भी महसूस किया जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वहन में भारत और/या भारत के प्रधानमंत्री देश के मामलों को चलाने में उनकी भारी जिम्मेदारियां, व्यावहारिक रूप से हर समय दूरगामी निर्णय लेते हैं। परिणाम, न केवल आंतरिक मामलों के मामले में घरेलू मोर्चे पर देश, लेकिन के मामले में भी अन्य देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध। किसी को उम्मीद होगी, कि न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार उच्च सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं को सौंपना-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

उनमें से किसी एक के साथ न्यायपालिका को आम तौर पर किसी भी अनुचितता का संदेह नहीं होना चाहिए। फिर भी, संविधान सभा ने इसकी अनुमति नहीं दी

उनमें से कोई भी, कोई भी परिभाषित सहभागी भूमिका। वास्तव में बहस संविधान सभा में, की भागीदारी को हटा दिया

राजनीतिक-कार्यकारी घटक, "राजनीतिक-दबाव" और "राजनीतिक विचारों" से प्रभावित होने के डर के कारण। क्या संविधान सभा का दृष्टिकोण था, और उपरोक्त उल्लेख किया गया था

अविश्वास, वैध?

160. एक छोटे से व्यक्तिगत शोध के परिणामस्वरूप रहस्योद्घाटन हुआ

"पारस्परिकता की वैध शक्ति" की अवधारणा पर बहस की गई

बर्ट्राम रेवेन ने अपने लेख में लिखा है-"द बेस ऑफ पावर एंड पारस्परिक प्रभाव का शक्ति/अंतःक्रिया मॉडल "(यह

लेख सामाजिक मुद्दों और सार्वजनिक नीति के विश्लेषण में प्रकाशित हुआ,

खण्ड. 8, सं. 1, 2008, पृ. 1-22). निपटाने के अलावा व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले विभिन्न मनोवैज्ञानिक कारण

पारस्परिकता की शक्ति "। यह इंगित किया गया था कि पारस्परिकता मानक की परिकल्पना की गई है, कि अगर कोई कुछ फायदेमंद करता है

दूसरे के लिए, प्राप्तकर्ता पारस्परिक करने का दायित्व महसूस करेगा

("जब आपको इसकी आवश्यकता थी तो मैंने आपकी मदद की, इसलिए आपको बाध्य महसूस करना चाहिए

यह मेरे लिए करने के लिए। " - गोरान्सन और बर्कोविट्ज़, 1966; गोल्डनर, 1960)। लेखक द्वारा व्यक्त किए गए विचार में, शक्ति की अंतर्निहित आवश्यकता, अचेतन में सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध है

व्यक्तिगत। वांछित की संतुष्टि और उपलब्धि पर

शक्ति, वहाँ पारस्परिक करने के लिए एक समान अचेतन इच्छा है

अनुग्रह।

161. "वैध शक्ति" की मनोवैज्ञानिक अवधारणा

पारस्परिकता ", को डेनिस टी. रीगन द्वारा भी उजागर किया गया था

कॉर्नेल विश्वविद्यालय ने अपने लेख में कहा-"एक पक्ष और पसंद के प्रभाव"

अनुपालन पर "। यह इंगित किया गया था कि पर्याप्त था

स्थापित करने के लिए सबूत, कि पक्ष भावनाओं को उत्पन्न करते हैं

दायित्व, और प्रतिदान करने की इच्छा। इसके अनुसार

लेखक, उपलब्ध आंकड़ों ने सुझाव दिया कि एक पक्ष नेतृत्व करेगा

अपने प्राप्तकर्ता की ओर से दायित्व की भावनाओं की सूचना देना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

162. अपनी पुस्तक "प्रभाव: का मनोविज्ञान

अनुनय "-रॉबर्ट सियाल्लिनी, रीजेंट के प्रोफेसर एमेरिटस

एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान और विपणन के

"पारस्परिकता" शीर्षक वाले दूसरे अध्याय में यह विचार व्यक्त किया गया है कि शक्तिशाली अनुपालन तकनीकों में से एक थी

"संभवतः सबसे

पारस्परिकता का नियम, जो किसी को चुकाने के लिए प्रेरित करता है, क्या

किसी ने उसे दे दिया है। जब कोई उपहार दिया जाता है,

प्राप्तकर्ता दाता का ऋणी महसूस करता है, अक्सर असहज महसूस करता है

इस ऋण के साथ, और रद्द करने के लिए मजबूर महसूस करता है

ऋण. अक्सर उसके बेहतर निर्णय के खिलाफ "। यह इंगित किया गया था
का नियम, पूरे क्षेत्र में व्यापक था

बाहर, कि पारस्परिकता

किन समाजों, संस्कृतियों और संस्थाओं पर परस्पर निर्भरताएँ
दावा किया गया था कि वास्तव में नियम

सभ्यताओं का निर्माण हुआ। यह

पारस्परिकता का आश्वासन, कि कोई जिसने कुछ दिया था
यह प्रारंभिक उपहार होगा

पहले दूर, एक सापेक्ष आश्वासन है, कि

अंततः भुगतान किया जाता है। मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में, कुछ भी नहीं

खो जाएगी। मार्सेल नौस का उल्लेख करते हुए, जिन्होंने संचालन किया था

उपहार देने पर एक अध्ययन, इस बात पर जोर दिया गया था, कि "एक है

देने का दायित्व, प्राप्त करने का दायित्व, और एक दायित्व

चुकाने के लिए "। लेखक के अनुसार, यह उपरोक्त नेटवर्क में था

ऋण का, कि पहला दाता अनुग्रह का लाभ उठा सकता है, और उचित रूप से अनुपालन की भूमिका ग्रहण
करेगा

अभ्यासी। और तदनुसार यह निष्कर्ष निकाला गया कि हालांकि

चुकाने की बाध्यता का सार था

पारस्परिकता नियम, यह प्राप्त करने का दायित्व था, जिसने बनाया

नियम का उपयोग करना इतना आसान है। पारस्परिकता की शक्ति का वर्णन करते हुए, सियालदिनी ने अपने
लेख में व्यक्त किया कि वह व्यक्ति जो देता है

पहले नियंत्रण में रहता है; और वह व्यक्ति जो प्राप्तकर्ता था,

हमेशा कर्ज में डूबे रहे। यह बताया गया है कि उपरोक्त
थी, और मनोवैज्ञानिक रूप से

स्थिति अक्सर जानबूझकर बनाई गई

बनाए रखा। लेखक का यह भी विचार था कि जितना अधिक

मूल्यवान, सारवान और सहायक मूल अनुग्रह, उतना ही अधिक

प्राप्तकर्ता ऋणी महसूस करता रहेगा। उपरोक्त में

लेख में, एल्विन गोल्डनर का संदर्भ दिया गया था, जिनके सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड में

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

राय, पृथ्वी पर कोई मानव समाज नहीं था, जो नहीं है
पारस्परिकता के नियम का पालन करें। के विचारों का भी उल्लेख करते हुए
प्रसिद्ध सांस्कृतिक मानवविज्ञानी-लियोनेल टाइगर और रॉबिन
लोमडी, यह पुष्टि की गई थी कि मनुष्य एक "जाल" में रहते थे।
ऋण "। इसलिए यह महसूस किया गया कि पारस्परिकता एक थी
ऋण और एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक उपकरण, जिसका विरोध करना असंभव था।

163. संवैधानिक योजना के तहत

संयुक्त राज्य अमेरिका, संघीय न्यायाधीशों को नामित किया जाता है
राष्ट्रपति, और सीनेट द्वारा पुष्टि की गई। मुद्दा यह है कि
बहस, अर्थात्, "की वैध शक्ति" की अवधारणा पारस्परिकता ", इसलिए सीधे संयुक्त राज्य अमेरिका
में उत्पन्न होती है,

संघीय न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला। पहला अनुग्रह
संघीय न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा विस्तारित किया जाता है, जो
अपना नाम नामांकित करता है, और आगे एक द्वारा अनुग्रह बढ़ाया जाता है
सीनेट के या अधिक सदस्य, जिनके समर्थन से
न्यायाधीश का मानना है कि उन्होंने पुष्टि का वोट जीता। एक लेख
"वफादारी, कृतज्ञता और संघीय न्यायपालिका" शीर्षक से लिखा गया

लॉरा ई. लिटिल (कानून के एसोसिएट प्रोफेसर, मंदिर) यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ, जहाँ तक 1995 में
हैं)

हाथ में मुद्दा, स्पष्ट रूप से नियुक्ति के संदर्भ में
न्यायाधीश। लेख से पता चलता है कि पारस्परिकता का मुद्दा सचेत बहस का विषय रहा है।
काफी समय तक न्यायाधीशों की नियुक्ति। द. उपरोक्त लेख में निकाले गए निष्कर्ष प्रासंगिक हैं -
वर्तमान विवाद, और यहाँ नीचे निकाले जा रहे हैं:

"निष्पक्षता के मुद्दे पर, एक व्यक्ति एक उपक्रम

संघीय न्यायपालिका एक कठिन कार्य का सामना करती है।

समकालीन वकील आम तौर पर सहमत हैं कि कानून है पूरी तरह से तटस्थ सिद्धांतों का उत्पाद नहीं है और कि

न्यायाधीश को मूल्यों में से चुनना चाहिए क्योंकि वह कानून को आकार देती है। फिर भी, संघीय में निष्पक्षता को नियंत्रित करने वाले मानक

अदालतें काफी हद तक मानती हैं कि पूर्ण न्यायिक तटस्थता और निराशा संभव है। मानचित्रण की प्रक्रिया [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसलिए निर्णय लेने के लिए एक व्यक्तिगत ढांचा है

न्यायाधीश के लिए काफी विसंगति पैदा करने के लिए उपयुक्त।

इस बोझ के साथ कृतज्ञता के विशेष आकर्षण भी जुड़ जाते हैं।

और उन व्यक्तियों के प्रति वफादारी जिन्होंने संभव बनाया

न्यायाधीश का काम।

मैंने यह दिखाने की कोशिश की है कि कृतज्ञता और निष्ठा दोनों कर सकते हैं।

एक संघीय न्यायाधीश उपक्रम के लिए एक शक्तिशाली प्रभाव है एक मामला तय करने के लिए।
समस्या जटिल है क्योंकि

निष्ठा और कृतज्ञता एक बड़ी संभावित समस्या उत्पन्न करते हैं

दूसरों की तुलना में कुछ न्यायाधीशों के लिए। यह जटिलता

की प्रक्रिया से काफी हद तक उभरता है

नामांकन और पुष्टि, जो अक्सर उत्पन्न करता है, या

कम से कम एक न्यायाधीश की वफादारी की भावना को मजबूत करता है और उनके लाभार्थियों
के प्रति आभार।

पिछले कुछ वर्षों में, हमने एक लहर देखी है

संघीय चुनाव के लिए चयन प्रक्रिया से असंतोष

न्यायाधीशों। विशेष रूप से कानूनी छात्रवृत्ति की पेशकश की गई है

के लिए लगातार आलोचना और रचनात्मक सुझाव

परिवर्तन करें। जैसा कि यह आवश्यक है, यह छात्रवृत्ति मान्यता देती है कि कोई भी

साहसपूर्वक परिवर्तन नामांकन के प्रभाव को मापना चाहिए
जीवन, जिसमें शक्तियों का संवैधानिक संतुलन और न्यायपालिका की सार्वजनिक धारणा।
इन चिंताओं से हटने के लिए किसी भी परिवर्तन का प्रभाव
बेशक, एक गलती हो। इस प्रकार, किसी भी नए अध्ययन में चयन प्रक्रिया, हमें विचार करना चाहिए
एक बनाने और सशक्त करने के लिए प्रक्रिया की क्षमता
न्यायाधीश की उसके प्रति निष्ठा और कृतज्ञता की भावनाएँ
हितग्राही। इसलिए, पूर्वगामी को न केवल
संघीय अदालत की प्रक्रिया पर प्रकाश डालें सामान्य रूप से निर्णय लेना, लेकिन न्यायिक में
प्रस्तावित परिवर्तनों के मूल्यांकन के लिए बहुत आवश्यक मार्गदर्शन भी देना।

चयन "। सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. /जगदीश सिंह खेहर, जे।/

164. हालाँकि यह उल्लेख करना उचित है कि उनके लेख में,

लौरा ई. लिटिल ने व्यक्त किया है, जो अधिकांश नैतिक दार्शनिकों ने व्यक्त किया है। उनका मानना था कि कृतज्ञता के महत्वपूर्ण नैतिक घटक हैं। और

इसके अलावा, उस कृतज्ञता का उपयोगितावादी नैतिकता में एक तैयार स्थान है
प्रणाली, जो सबसे अच्छा सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई थी
व्यक्तियों की सबसे बड़ी संख्या के लिए। कृतज्ञता की अवधारणा

हालाँकि लौरा ई. लिटिल द्वारा निष्ठा के साथ जुड़ा हुआ था, क्योंकि उनके विचार में, कृतज्ञता और निष्ठा, निकटता से संबंधित थे। ए.

एक के माध्यम से लाभार्थी एक लाभार्थी के प्रति कृतज्ञता दिखा सकता है निष्ठा की अभिव्यक्ति।
जिस बात पर जोर देने की मांग की गई थी, वह यह थी कि

वफादारी को समझना जो कोई समझता है, हम अपने में कौन हैं
मित्रता, प्रेम, पारिवारिक बंधन, राष्ट्रीय संबंध और धार्मिक संबंध।
भक्ति। जहाँ तक भारतीय व्यवहार के प्रतिमानों का संबंध है।

सांस्कृतिक प्रणाली का संबंध है, एक बच्चा हमेशा अपने पालन-पोषण के लिए अपने माता-पिता के प्रति बाध्य रहता है, और यह बच्चे की अंतर्निहित नैतिकता है।

दायित्व, निर्विवाद निष्ठा और कृतज्ञता का विस्तार करके अपने माता-पिता के प्रति आदान-प्रदान करना। उपरोक्त स्थिति पता लगाती है

शिक्षक और पढ़ाए गए, मास्टर और शिक्षक के संबंधों में प्रतिकृति भारतीय सांस्कृतिक परिदृश्य में, सेवक, और इसी तरह। मौजूदा

एक लाभार्थी के प्रति पारस्परिकता न करने का कार्य, अधिक होगा

अक्सर, गंभीर नैतिक अभाव के कार्य के रूप में माना जाता है।

जब दिया गया पक्ष उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीश के पद जितना ही महत्वपूर्ण है, तो सबसे अच्छा होगा कि इसे इस पर छोड़ दिया जाए।

व्यक्तिगत कल्पना, की विशालता निर्धारित करने के लिए

पारस्परिक कृतज्ञता और निष्ठा।

165. यहाँ ऊपर दर्ज विचार, समर्थन करता है

यह विचार कि जहां तक संभव हो, राजनीतिक-कार्यपालिका की अंतिम/अंतिम चयन और नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए।

न्यायाधीशों से लेकर उच्च न्यायपालिका तक। विशेष रूप से ध्यान रखें

राजनीतिक-कार्यपालिका की भागीदारी की विशालता, में

न्यायिक निर्णय की कार्रवाई। पारस्परिकता और वेतन की भावनाएँ

राजनीतिक-कार्यपालिका पर वापस जाएँ, यह विनाशकारी होगा

"न्यायपालिका की स्वतंत्रता"। इसमें हम केवल दोहरा रहे हैं

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा अपनाई गई स्थिति।

उन्हें डर था कि [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राजनीतिक-कार्यपालिका की भागीदारी से, का चयन

न्यायाधीश, "राजनीतिक दबाव" और "राजनीतिक दबाव" से प्रभावित होंगे

प्रक्रिया के साथ कार्यकारी व्यवस्था का सबसे कम संबंध है।
नियुक्तियों को अंतिम रूप देना।

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की

VI.

ए.

166. उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों द्वारा जिन क्षेत्राधिकारों से निपटा जाना है, वे बड़े और व्यापक हैं। भीतर

उपरोक्त क्षेत्राधिकारों में, कई क्षेत्राधिकार हैं,

जिसे कार्यपालिका अनिवार्य रूप से एक मौलिक पक्ष है लीज़। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ कर लगाने से उत्पन्न मामले भी शामिल होंगे।

कानून जिनके गंभीर वित्तीय निहितार्थ हैं। द. कार्यपालिका प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में अकेले लगी हुई है।

संसाधन, अक्सर निजी उद्यमियों के माध्यम से। की बिक्री

प्राकृतिक संसाधन, जिनके पास भी भारी वित्तीय स्थिति है

की प्रकृति के न्यायाधिकरणों द्वारा पारित आदेशों से उत्पन्न दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण और

विद्युत के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण और इसी तरह के अन्य मामलों पर भी विचार किया जाता है

उच्च न्यायपालिका के साथ, जहाँ कार्यपालिका की भी भूमिका होती है। इसमें भी बड़े पैमाने पर वित्तीय निहितार्थ हो सकते हैं।

कार्यपालिका भी संबंधित सभी मामलों में एक आवश्यक पक्ष है।

राष्ट्रीय स्तर की अपीलों सहित पर्यावरणीय मुद्दों पर

हरित न्यायाधिकरण। न केवल सभी आपराधिक मामलों में, बल्कि

उच्च प्रोफाइल घोटाले, जो अब दुर्लभ नहीं हैं, कार्यकारी

पूर्व और निवर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री और मंत्री, और कभी-कभी

पूर्व और निवर्तमान मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के खिलाफ राज्य मंत्रिमंडलों से। यहाँ तक कि रोजगार के मुद्दों के क्षेत्र में भी,

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया निर्णय, सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

और सशस्त्र बल अपीलिय न्यायाधिकरण के समक्ष आता है
 उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीश। ये निर्णय भी
 कभी-कभी उच्च श्रेणी के प्रशासक और सशस्त्र भी शामिल होते हैं।
 बलों के कर्मी। इसमें भी कार्यपालिका अनिवार्य है।

राजनीतिक-कार्यपालिका की भागीदारी, मुकदमेबाजी में उच्च न्यायपालिका।

167. चूंकि कार्यपालिका की एक बड़ी हिस्सेदारी है, इसलिए बहुमत में
 उच्च न्यायपालिका के समक्ष विचार के लिए उत्पन्न होने वाले मामलों में केंद्रीय मंत्री की भागीदारी
 एन. जे. ए. सी. के पदेन सदस्य के रूप में विधि और न्याय
 स्पष्ट रूप से संदिग्ध होना। आज की दुनिया में लोग जागरूक हैं।
 और इस तथ्य के लिए जीवित, कि उनके अधिकारों में निर्णय लिया जाना चाहिए
 प्राकृतिक न्याय के नियमों का सामंजस्य। नियमों में से एक
 स्वाभाविक न्याय यह है कि न्यायनिर्णायक को पक्षपाती नहीं होना चाहिए।
 इसका मतलब यह होगा कि उसे न तो किसी भी पक्ष के खिलाफ पूर्वाग्रह रखना चाहिए और न ही उसका
 पक्ष लेना चाहिए।

कि न्यायनिर्णायक के हितों का टकराव नहीं होना चाहिए, जिस विवाद का उसे निपटारा करना है।
 जब मामलों का वर्तमान समूह

विचार के लिए आया, हितों के टकराव का एक अनुरोध था
 यहां तक कि पीठ के पीठासीन न्यायाधीशों में से एक के खिलाफ भी,
 जिसके परिणामस्वरूप 15.4.2015 पर अनिल आर. डेव, जे. को अलग कर दिया गया।
 हम में से एक के खिलाफ फिर से इसी तरह की प्रार्थना की गई (जे. एस.
 खेहर, जे.), 21.4.2015 पर, हितों के टकराव के आधार पर।
 जिस बात पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है, वह यह है कि पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह, पक्ष
 और हितों का टकराव ऐसे मुद्दे हैं जो बार-बार उभरते हैं।

न्यायाधीश ऐसे मामलों में निर्णय से बचने के लिए सावधान रहते हैं। न्यायाधीश न्यायनिर्णायक
 के एक या दूसरे पक्ष में नहीं होते हैं।

प्रक्रिया। इसके विपरीत राजनीतिक-कार्यपालिका, एक जबरदस्त तरीके से
 अधिकांश मामलों में, एक सहभागी भूमिका होती है। इस मायने में, वहाँ

एक या दूसरे तरीके से दिए गए निर्णय का प्रभाव/प्रभाव हो सकता है। सफलता या हार-जीत या हार। द. सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के खिलाफ हितों के टकराव की याचिका उपलब्ध होगी

[2015] 13 एस सी आर।

पार्टी। तत्काल मुद्दा मद्रास में विचार के लिए उठा। बार एसोसिएशन मामले 35. उपरोक्त मामले में पाँच-न्यायाधीशों की पीठ

चयन में केंद्र सरकार के विभागों के सचिवों की भागीदारी की वैधता पर विचार करना और राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर न्यायाधिकरण। उपरोक्त मामले पर, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 131. धारा 7 को अन्यथा भी नहीं माना जा सकता है

अध्यक्ष और सदस्यों का चयन और नियुक्ति एन. टी. टी. के, केंद्रीय विभागों के सचिव

सरकार। इस संबंध में यह भी उचित होगा कि - यह उल्लेख करते हुए कि केंद्र सरकार के हित

मुकदमे में किसी पक्ष को स्वीकार करना संभव नहीं है। चयन प्रक्रिया में भाग लें जिसके द्वारा

न्यायनिर्णायक निकाय के अध्यक्ष और सदस्य हैं -

चुना गया। "

यहां भी स्थिति अलग नहीं है। महान्यायवादी

उद्धृत मामले में यह कहते हुए विवाद का फैसला किया गया कि राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लिए गए मामलों में " एक तरफ केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व होगा।

प्रत्येक मुकदमा। "जो उच्च न्यायालय के समक्ष मामला नहीं है।

न्यायपालिका। खंडन, स्पष्ट रूप से प्रचार किए गए मुद्दे से बचाता है। प्रतिक्रिया से कोई यह मान लेगा कि स्थिति थी

मामलों की सीमा तक स्वीकार किया, जहां कार्यपालिका एक थी स्वयं चयनित न्यायाधीशों को बाहर कर देगा।

लिस के लिए पार्टी। लेकिन यह

अधिकांश मामलों की सुनवाई से। इसलिए एक

भारत संघ की प्रतिक्रिया को अस्वीकार करें।

168. हमारा विचार है कि इसके परिणामस्वरूप
कानून और न्याय के प्रभारी केंद्रीय मंत्री की भागीदारी, सर्वोच्च न्यायालय-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]
मंत्री के समर्थन से नियुक्ति के लिए अनुमोदित न्यायाधीश,
हितों के टकराव की याचिका का विरोध या प्रतिकार करने में सक्षम नहीं हो सकता है,
एक वादी द्वारा उठाया गया, एक मामले में जब कार्यपालिका के पास है
को कम करने का अपरिहार्य प्रभाव होगा "न्यायपालिका की स्वतंत्रता", यहां तक कि जहां ऐसी
याचिका है
तिरस्कृत किया। इसलिए, राजनीतिक-कार्यपालिका को सौंपी गई भूमिका,
सहयोगात्मक भागीदारी तक सीमित किया जा सकता है, सिवाय इसके कि अंतिम निर्धारण में
कोई भी भूमिका। अतः केवल
चयन की अंतिम प्रक्रिया में विधि और न्याय के प्रभारी केंद्रीय मंत्री की पदेन सदस्य के रूप में भागीदारी
एन. जे. ए. सी., अनुच्छेद के संशोधित प्रावधान को प्रस्तुत करेगा।
124 ए (1) (सी) संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि यह लागू होता है
"न्यायपालिका की स्वतंत्रता" और "अलगाव" के सिद्धांत
शक्तियों का "।

VII.

169. विद्वान महान्यायवादी ने हमें आमंत्रित किया था
न्यायिक नियुक्तियों के तरीके पर ध्यान देना
पंद्रह देशों में बनाया जा रहा है। यह प्रस्तुत किया गया था कि नौ में
देशों के न्यायाधीशों की नियुक्ति या तो न्यायिक प्रणाली के माध्यम से की जाती थी।
नियुक्ति आयोग, या न्यायिक आयोग के माध्यम से
नियुक्ति समिति, या न्यायिक नियुक्तियों के माध्यम से

कार्यपालिका द्वारा सीधे नियुक्त, अर्थात् राज्यपाल द्वारा जनरल या राष्ट्रपति। हमें सूचित किया गया था कि एक यूरोपीय देश में, न्यायाधीशों को मंत्री द्वारा नामित किया जाता था

न्याय और संसदीय समिति द्वारा पुष्टि की गई। संयुक्त राज्य अमेरिका में, न्यायाधीशों की नियुक्ति एक के माध्यम से की जाती थी

राष्ट्रपति द्वारा नामांकन की प्रक्रिया और सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर. द्वारा पुष्टि।

सीनेट। यह रेखांकित किया गया कि सभी पंद्रह देशों में, कार्यपालिका अंतिम निर्धारक/नियुक्ति प्राधिकारी थी।

और आगे यह कि, सभी देशों में, कार्यपालिका की भूमिका थी

न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति में भाग लेते हैं। पूर्वबताया गया

एकवचन के लिए तथ्यात्मक स्थिति हमारे ध्यान में लाई गई थी

प्रदर्शित करने का उद्देश्य, कि में कार्यकारी भागीदारी न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं की गई थी

पंद्रह देशों में से किसी में भी न्यायपालिका, जो राजनीतिक-कार्यपालिका के अधीन है। यह दावा किया गया था कि जिन देशों का उल्लेख किया गया है

उनके द्वारा दुनिया के विभिन्न महाद्वीपों में थे, और वहाँ की स्वतंत्रता के संदर्भ में कोई शिकायत नहीं थी

न्यायपालिका "। मुद्दा यह था कि चयन में कार्यपालिका की केवल भागीदारी और

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा "न्यायपालिका की स्वतंत्रता" पर।

170. वनाच्छादित समर्पण की आवश्यकता नहीं है

न्यायाधीशों का मामला, जिसमें एस. रत्नवेल पांडियन, जे. न्यायाधीश जिन्होंने एक अलग सहमति आदेश पारित किया, समर्थन किया

बहुमत का दृष्टिकोण। उन्होंने प्रकृति के समर्पण को अस्वीकार कर दिया था

विद्वान महान्यायवादी द्वारा निम्नलिखित के साथ प्रस्तुत किया गया

टिप्पणियाँ:

"194. फिर भी, हमें सबसे पहले रोगों का पता लगाना है

कानूनी बायोप्सी के तहत उन बीमारियों का मूल कारण,
तीसरा, व्यवस्था पर पीड़ा की प्रकृति का पता लगाना।

और अंत में उन बीमारियों के इलाज और इलाज के लिए एक नई विधि और रणनीति विकसित
करने के लिए
नई आविष्कार की गई दवा '(जिसका अर्थ है एक नई

विकसित विधि और रणनीति) भारतीय फार्माकोपिया के तहत सूत्र के संदर्भ में निर्मित (जिसका अर्थ
है

मिश्रित संस्कृति आदि में राष्ट्रीय समस्याओं के अनुसार) लेकिन
अमेरिकी या ब्रिटिश फार्माकोपिया के अनुसार नहीं जो अदालत के अधिवक्ताओं की वकालत करता है-चालू-
रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

ये हमारी भारतीय प्रणाली के लिए अलग हैं, हालांकि अन्य देशों में अपनाई गई प्रणाली विकास के
लिए कुछ प्रकाश डाल सकती है।
हमारी प्रणाली। कुछ आलोचकों का आक्रोश तब होता है जब

सभी लोकतांत्रिक क्षेत्रों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति

देश, दूर-दूर तक, केवल कार्यपालिका के साथ रहते हैं, वहाँ

इस बात पर जोर देने में कोई सार नहीं है कि प्रधानता दी जानी चाहिए

के चयन और नियुक्ति में सीजेआई की राय के अनुसार

न्यायाधीश पद के लिए उम्मीदवार। यह प्रस्ताव कि हमें करना चाहिए
विदेशी विधि की नकल करना और उसे अपनाना एक शुष्क कानूनी तर्क है, जो

इस संक्षिप्त आधार पर भी अस्वीकार किया जाना चाहिए कि

भारत के संविधान में ही अनिवार्य परामर्श की आवश्यकता है

बनाने से पहले राष्ट्रपति द्वारा सीजेआई के साथ

उच्चतर न्यायपालिका में नियुक्तियाँ। ऐसा नहीं हुआ है।

के लिए किसी भी वकील द्वारा हमारे ध्यान में लाया गया

उत्तरदाताओं ने कहा कि अन्य देशों में अकेले कार्यपालिका
के अस्तित्व के बावजूद नियुक्तियाँ करता है

उनके में कोई भी मौजूदा समान संवैधानिक प्रावधान

संविधान "।

171. हमारे प्रस्तुतिकरण से निपटने के बावजूद

लीम्ड अटॉर्नी जनरल के हाथों प्रचार किया गया

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली पर पंद्रह देशों में, हम आगे की खोज करना समीचीन समझते हैं

शिकागो विश्वविद्यालय के लॉ स्कूल के गिन्सबर्ग ने हाथ। अखबार का शीर्षक था- "संरक्षकों की रखवाली: न्यायिक परिषदें और न्यायिक स्वतंत्रता "। कागज संदर्भित करता है

को। के बारे में चल रही बहस के तुलनात्मक साक्ष्य

न्यायाधीशों का चयन और अनुशासन। लेख में कहा गया है कि

दो उद्देश्यों पर ध्यान दें। सबसे पहले, न्यायिक गठन का सिद्धांत

परिषदें, और वे आयाम जिन पर वे भिन्न हैं। और दूसरा, किस हद तक न्यायपालिका के विभिन्न अभिकल्पनाएँ

परिषद, न्यायिक गुणवत्ता को प्रभावित करती है। ये दो मुद्दे थे

अत्यधिक महत्व के रूप में माना जाता है, क्योंकि वे सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर. थे।

तथ्य का निर्धारक, क्या न्यायाधीश सक्षम होंगे व्यापक रूप से सामाजिक नीति को लागू करने में एक प्रभावी भूमिका है

कल्पना की गई। यह देखा गया कि न्यायिक परिषदें आ गई थीं नियुक्ति, पदोन्नति को सुरक्षित रखने के लिए और

पक्षपातपूर्ण राजनीतिक प्रभाव से न्यायाधीशों का अनुशासन, और उसी समय, न्यायिक जवाबदेही के कुछ स्तर को पूरा करने के लिए।

यह लेखकों का विचार था कि न्यायिक परिषदें झूठ बोलती हैं

अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करें, और पूर्ण के विकल्प राजनीतिक-नियुक्तियों का कार्यकारी नियंत्रण, पदोन्नति और

अनुशासन।

172. अखबार के अनुसार, फ्रांस ने पहली स्थापना की

1946 में न्यायपालिका की उच्च परिषद। इटली की न्यायिक परिषद

1958 में बनाया गया था। इटली पूरी तरह से इन्सुलेट करने वाला पहला देश था राजनीतिक नियंत्रण से पूरी न्यायपालिका। यह दावा किया गया था कि

इसके बाद अन्य देशों में इतालवी मॉडल का अनुसरण किया गया। द.

स्पेन और पुर्तगाल में स्थापित मॉडल में एक

सदस्यों का महत्वपूर्ण अनुपात जो न्यायाधीश थे। ये

इनमें तानाशाही के पतन के बाद मॉडल स्थापित किए गए थे।

देशों। इन देशों द्वारा बनाई गई परिषदों के बारे में कहा गया है - मामलों में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होना

न्यायिक पदोन्नति, कार्यकाल और निष्कासन से संबंधित। के अनुसार

कागज के लिए, फ्रांसीसी मॉडल अस्तित्व में आया

अत्यधिक राजनीतिकरण के बारे में चिंताओं का परिणाम।

स्वाभाविक रूप से, यह प्रक्रिया न्यायिक शक्ति की व्यापक स्वतंत्रता में विकसित हुई। फिर भी, न्यायिक चिंता कई गुना बढ़ गई यूरोपीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए न्यायपालिका का प्रयास

मानवाधिकारों का। और इस प्रक्रिया में न्यायपालिका की भागीदारी

राजनीतिक उठापटक की पृष्ठभूमि में न्यायिक समीक्षा

घोटालों। पेपर में इटली के पैटर्न को समान बताया गया है।

इटली में भी, प्रमुख घोटालों की जांच हुई व्यवसायी, राजनेता और नौकरशाह (इस अवधि के दौरान)

1992 से 1997 तक), जिसके परिणामस्वरूप व्यापक न्यायिक व्यवस्था बनी।

राजनीतिक गतिविधि में भागीदारी।

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं की संरचना-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

इटली में परिषद को तदनुसार 2002 में बढ़ाया गया था।

संसद का प्रभाव।

173. अखबार ने नोट किया कि फ्रांसीसी-इतालवी मॉडलों में था

लैटिन अमेरिका और अन्य विकासशील देशों में अपनाया गया

देशों। यह बताया गया था कि विश्व बैंक और अन्य समान बहुपक्षीय दाता एजेंसियां, न्यायिक पर जोर देती हैं

परिषदें, न्यायिक सुधार से जुड़ी होंगी, प्रवर्तन के लिए कानून के शासन से। यूरोपीय कानून के तत्व न्यायपालिका को न्यायपालिका का परिष्करण माना जाता था परिषद मॉडल। मजिस्ट्रेट की कथित सर्वोच्च परिषद, यह आवश्यक है कि कम से कम आधे सदस्य न्यायाधीश हों, यहाँ तक कि हालाँकि, सर्वोच्च परिषद के कुछ सदस्य हैं संसद से लिया गया। यह लेखकों का विश्वास था कि कागज, कि अपनाने के लिए प्रेरक चिंता फ्रांसीसी-इतालवी परंपरा में सर्वोच्च परिषदों का उद्देश्य था अवधि के बाद "न्यायपालिका की स्वतंत्रता" सुनिश्चित करने में संरचनात्मक समस्याओं के बारे में बताया गया कि बाहरी जवाबदेही इनके लिए दूसरे लक्ष्य के रूप में उभरी है। सर्वोच्च परिषदें। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड मॉडल, यह दावा किया गया था कि उनकी परिषदें थीं चयन में भूमिका निभाने तक सीमित (पदोन्नति के बजाय और न्यायाधीशों का अनुशासन)। डच मॉडल का उल्लेख करते हुए, यह बताया गया था कि हाल के सुधार अधिक सुनिश्चित करने के लिए पेश किए गए थे पारदर्शिता और जवाबदेही।

174. यह भी सामने लाया गया कि सिविल में न्यायिक परिषदें

उच्चतम न्यायालय का अधीनस्थ अंग। कुछ देशों में ब्राजील की तरह, न्यायिक परिषदें स्वतंत्र निकाय थीं जिनके साथ

संवैधानिक स्थिति, जबकि अन्य न्यायिक परिषदों में शासित

पूरी न्यायपालिका। और कुछ अन्य में, जैसे ग्वाटेमाला और अर्जेंटीना में, वे केवल निचली अदालतों को संचालित करते थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

175. न्यायपालिका में आम तौर पर भर्ती का उल्लेख

कानूनी देशों में, यह बताया गया कि यूनाइटेड किंगडम में, संवैधानिक सुधार अधिनियम, 2005 ने एक न्यायिक व्यवस्था का निर्माण किया।

नियुक्ति आयोग, जो इसके लिए जिम्मेदार था

केवल योग्यता के आधार पर नियुक्तियाँ, कोई कार्यकारी नहीं था भागीदारी। यह बताया गया था कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया

हम इस बात पर बहस कर रहे थे कि क्या इसका पालन किया जाए। उपरोक्त

कानून, यह तर्क दिया गया था, पर एक वैधानिक कर्तव्य अभिनिर्धारित

सरकारी सदस्य, न्यायिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए नहीं। और यह भी, सभी में लॉर्ड चांसलर की भागीदारी को बाहर रखा गया

ऐसी गतिविधियाँ, अपने कार्यों को राष्ट्रपति को हस्तांतरित करके

इंग्लैंड और वेल्स के न्यायालय, (पूर्व में इंग्लैंड और वेल्स के लॉर्ड मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित)।

176. अमेरिकी अनुभव का उल्लेख करते हुए यह उल्लेख किया गया था,

न्यायिक चयन के पारंपरिक तरीकों पर चिंता

(या तो राजनेताओं द्वारा या चुनाव द्वारा) ने "योग्यता" को रास्ता दिया था। आयोग "ताकि न्यायाधीशों का चयन योग्यता के आधार पर किया जा सके।

परिषदें। उसमें जिस प्रणाली पर विचार किया गया था, वह गैर-पक्षपातपूर्ण थी। न्यायिक चयन आयोग में न्यायाधीश शामिल थे,

वकीलों और राजनीतिक नियुक्तियों।

177. पर प्रसिद्ध न्यायविदों के कार्यों का उल्लेख करते हुए

विषय, यह निष्कर्ष निकालने की कोशिश की गई थी कि आज की दुनिया में,

एक मजबूत सर्वसम्मति थी कि सभी प्रक्रियाओं में से योग्यता योजना न्यायपालिका को राजनीतिक दबाव से बचाती थी। में।

उनकी टिप्पणियाँ, उनके द्वारा किए गए सर्वेक्षण से निकलकर, यह

यह निष्कर्ष निकाला गया था कि राजनीतिक को खत्म करना असंभव था

न्यायपालिका पर दबाव। न्यायिक आयोग/परिषदें विभिन्न देशों में बनाए गए उपाय, उनके विचार में, थे

न्यायिक स्वतंत्रता को बढ़ाना और राजनीतिक स्वतंत्रता को कम करना।

प्रभाव पड़ता है। यह उनका विचार था कि एक बार स्वतंत्रता दी गई थी, न्यायाधीशों अधिक महत्वपूर्ण की एक विस्तृत श्रृंखला को हल करने के लिए अधिक उपयोगी थे विवाद, जिन्हें आवश्यक माना जाता था, इस तथ्य को देखते हुए कि न्यायपालिका को अब अधिक से अधिक कार्य सौंपे जा रहे थे।

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. /जगदीश सिंह खेहर, जे. जे.

178. लेख में निकाले गए निष्कर्षों का विश्लेषण करते हुए, एक यह निष्कर्ष निकालने के लिए विवश है कि विकास की प्रक्रिया में दुनिया भर के समाजों में न्यायपालिका को मुक्त करने की प्रवृत्ति है कार्यकारी और राजनीतिक नियंत्रण से, और एक प्रणाली को शामिल करना विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर न्यायाधीशों का चयन और नियुक्ति। क्योंकि तभी न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया पूरी होगी। प्रभावी रूप से राष्ट्र निर्माण का समर्थन करें। विषय में, जो हमारे विचार के लिए गिरता है, यह हमारे लिए अनिवार्य होगा, रखने के लिए "की स्वतंत्रता" की अवधारणाओं की प्रगति को ध्यान में रखते हुए न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा को अब मान्यता दी जा रही थी। दुनिया भर में। उच्च पदों पर नियुक्तियों के मामले में कार्यकारी और राजनीतिक भागीदारी की घटती भूमिका न्यायपालिका, एक स्पष्ट वास्तविकता है। उपरोक्त प्रवृत्ति को मान्यता देते हुए, कोई अधिक और आगे की भागीदारी नहीं हो सकती है कार्यकारी, जो अब तक पहले से मौजूद था। और इसमें भारतीय परिदृश्य, जैसा कि वर्तमान में कल्पना की गई है, द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों के मामलों में दिए गए निर्णय। यह, इसलिए यह निष्कर्ष निकालना अनिवार्य है कि फाइनल में कानून और न्याय के प्रभारी केंद्रीय मंत्री एन. जे. ए. सी. में निहित निर्धारक प्रक्रिया, साथ ही, प्रधान मंत्री और एन. जे. ए. सी. के नेता की भागीदारी

लोकसभा में विपक्ष (और कोई नहीं होने की स्थिति में)

- सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता

लोगों का), "प्रतिष्ठित व्यक्तियों" के चयन में, होगा

एक प्रतिगामी कदम, और स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

VIII.

179. एन. जे. ए. सी. का एकमात्र घटक, जो बना हुआ है

जिनसे निपटा जाए, वे दो "प्रतिष्ठित व्यक्तियों" के संदर्भ में हैं

एन. जे. ए. सी. में नामित होने की आवश्यकता है। यह आवश्यक नहीं है कि

तत्काल पहलू पर प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों का विवरण दें, जैसा कि उनके पास है

यहाँ पहले से ही व्यापक रूप से देखा जा चुका है।

180. हम निर्विवाद रूप से स्वीकार करके आगे बढ़ सकते हैं

स्थिति, कि न तो विवादित संवैधानिक संशोधन, और न ही एन. जे. ए. सी. अधिनियम किसी भी सकारात्मक योग्यता को सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट होने के लिए अभिनिर्धारित करता है

[2015] 13 एस सी आर।

नामित किए जाने वाले दो "प्रतिष्ठित व्यक्तियों" के पास

एनजेएसी। ये संवैधानिक और विधायी अधिनियम किसी भी नकारात्मक अयोग्यता को निर्धारित नहीं करते हैं। इसलिए यह

स्पष्ट रूप से, कि दो "प्रतिष्ठित व्यक्तियों" का चुनाव होगा यह नामित करने वाले अधिकारियों की स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करता है। द.

विचार के लिए जो प्रश्न उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या यह न्यायसंगत है और

इस मुद्दे को स्वतंत्र इच्छा और पसंद पर छोड़ने के लिए उपयुक्त

नामित करने वाले अधिकारी?

181. विद्वान महान्यायवादी की प्रतिक्रिया थी

जोरदार। प्रधानमंत्री से बेहतर कौन जान सकता है,

भारत के मुख्य न्यायाधीश, या लोक सभा में विपक्ष के नेता

सभा (और जब विपक्ष का ऐसा कोई नेता नहीं है, तो

लोक सभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता

उच्च श्रेणी के संवैधानिक अधिकारियों के रूप में माना जा सकता है अनजान होने के कारण, इस देश में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता था,

सक्षम होना, मामले पर निर्णय लेने के लिए-न ही विधायिका, न ही कार्यपालिका, और न ही न्यायपालिका। द.

महान्यायवादी ने तब चुटकी ली-निश्चित रूप से यह न्यायालय ऐसा नहीं करेगा

विवादित संवैधानिक संशोधन, या एन. जे. ए. सी. को अलग कर दें।

ऐसे तुच्छ मुद्दे पर कार्रवाई करें। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि हमें

नामित करने वाले अधिकारियों के परिणाम की प्रतीक्षा करें, और यदि इस न्यायालय ने महसूस किया कि एक विशेष व्यक्ति को निर्वहन के लिए नामित किया गया है

एक "प्रतिष्ठित व्यक्ति" के रूप में उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी

एन. जे. ए. सी. अनुचित या अस्वीकार्य था या इसका कोई संबंध नहीं था

आवश्यक जिम्मेदारी के साथ, उनकी नियुक्ति को अलग रखा जा सकता है।

182. हमारे विचारशील विचार देने के बाद

हमारा मानना है कि यह मुद्दा निश्चित रूप से हाथ में है उतना तुच्छ नहीं है, जैसा कि बनाने की कोशिश की जाती है। दोनों "प्रतिष्ठित"

व्यक्तियों में एन. जे. ए. सी. की एक तिहाई ताकत और दोगुना शामिल है।

राजनीतिक-कार्यकारी घटक। हम समझ सकते हैं।

प्रस्तुतिकरण का महत्व, केवल विद्वान वकील को सुनने के बाद।

महान्यायवादी द्वारा दृढ़तापूर्वक व्यक्त किया गया विचार सर्वोच्च न्यायालय-चालू-रिकॉर्ड था।

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

कि "प्रतिष्ठित व्यक्तियों" को "सामान्य व्यक्ति" होना चाहिए जिनके पास कोई नहीं है

न्यायपालिका के साथ संबंध, या यहाँ तक कि पेशे से भी वकालत, शायद ऐसे व्यक्ति जिनके पास कोई कानून नहीं हो सकता है

संबंधित शैक्षणिक योग्यता। श्री T.R.Andhyarujina, सीखा

महाराष्ट्र राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील,

जिसने विवादित संवैधानिक संशोधन की पुष्टि की थी,

विवादित संवैधानिक संशोधन का समर्थन करते हुए दिखाई दिया,

साथ ही, एन. जे. ए. सी. अधिनियम, एक बिल्कुल विपरीत व्यक्त किया

देखें। उनके विचार में, "प्रतिष्ठित व्यक्तियों" के संदर्भ में एन. जे. ए. सी. को केवल प्रतिष्ठित वकीलों, प्रतिष्ठित वकीलों में से चुना जा सकता था।

न्यायविदों, और यहाँ तक कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, या जैसे, एक अंतर्दृष्टि रखने वाले

न्यायिक प्रणाली के काम करने और काम करने के लिए। यह है।

अतः यह स्पष्ट है कि विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता की दृष्टि में, नामित "प्रतिष्ठित व्यक्तियों" को व्यक्ति होना चाहिए,

कानूनी पृष्ठभूमि के साथ, और निश्चित रूप से सामान्य व्यक्तियों के साथ नहीं, जैसा कि सम्मानित अटॉर्नी जनरल द्वारा सुझाव दिया गया था। हमने रिकॉर्ड किया है।

श्री दुष्यंत ए. डेव द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियाँ, ज्ञात

वरिष्ठ वकील-सुप्रीम कोर्ट बार के अध्यक्ष

एसोसिएशन, जिसने बेंच को अपने सामान्य तरीके से संबोधित किया था

एनिमेटेड तरीके से, बिना किसी रोक के। हम उनके दृष्टिकोण का अनुरोध करते हैं,

क्या इसे शामिल करने पर विचार करना उचित होगा

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और/या

दो "प्रतिष्ठित व्यक्तियों" के स्थान पर एन. जे. ए. सी. उनकी प्रतिक्रिया सहज थी "कृपया ऐसा न करें!" " और फिर एक छोटे से विराम के बाद, ". यह विनाशकारी होगा!! ". होने के नाते

सबसे विद्वानों की सहायता से इस मुद्दे की जांच की और प्रख्यात वकील, यह निष्कर्ष निकालना अनिवार्य है कि मुद्दा

योग्यताओं का विवरण (-शायद, यह भी कि

और नामित करने वाले की स्वतंत्र इच्छा और पसंद पर नहीं छोड़ा जा सकता है पदों की परवाह किए बिना अधिकारी

उच्च संवैधानिक

एन. जे. ए. सी. में एन. जे. ए. सी. की एक तिहाई ताकत और उससे दोगुनी ताकत शामिल है। राजनीतिक-कार्यकारी घटक, और इस तरह, एक सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट होगी

[2015] 13 एस सी आर।

निर्णय लेने की प्रक्रिया में सर्वोच्च महत्वपूर्ण भूमिका

एनजेएसी। इसलिए हम इस अनुच्छेद को स्वीकार करने के लिए राजी हैं।

124 ए (1) (डी) को अलग रखा जा सकता है और नीचे गिराया जा सकता है, क्योंकि

नामांकित होने के लिए पात्रता की योग्यता निर्धारित नहीं की गई है "प्रतिष्ठित व्यक्तियों" के रूप में, और उसी अस्पष्ट को छोड़ने के लिए और

अनिर्धारित।

183. अन्यथा तर्क की सराहना करना भी मुश्किल है।

छह सदस्यीय एन. जे. ए. सी. में दो "प्रतिष्ठित व्यक्तियों" को शामिल करना।

यदि किसी को विद्वान वकील द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण के अनुसार चलना था जनरल, "प्रतिष्ठित व्यक्तियों" को एनजेएसी में शामिल किया गया था,

उन निवेशों को शामिल करने के लिए जो अब तक उपलब्ध नहीं थे

न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रचलित चयन प्रक्रिया

उच्च न्यायपालिका। वास्तव में सभी ढीले छोरों के साथ एक समर्पण, और

कोई स्पष्ट अर्थ नहीं। उन्होंने प्रचार किया था, कि वे "लेट" होंगे जिनका न्यायपालिका से या यहाँ तक कि न्यायपालिका से भी कोई संबंध नहीं है।

वकालत का पेशा, शायद ऐसे व्यक्ति जिन्होंने नहीं किया

यहां तक कि कानून से संबंधित कोई शैक्षणिक योग्यता भी हो। यह मुश्किल है।

"प्रतिष्ठित व्यक्तियों" के इनपुट की सराहना करने के लिए, संतुष्ट करना

विद्वान महान्यायवादी द्वारा दर्शाई गई योग्यता,

न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति के मामले में

उच्च न्यायपालिका के लिए। दो प्रतिष्ठित लोगों को शामिल करने की बेतुकी बात

एन. जे. ए. सी. पर व्यक्तियों की शायद सराहना की जा सकती है यदि एक

ऐसे "सामान्य व्यक्तियों" की भागीदारी की कल्पना करनी थी, जिसमें

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का चयन-अध्यक्ष

और वित्त आयोग के सदस्य, अध्यक्ष और

संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य, प्रमुख

निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त तथा

इस तरह के। स्थिति विनाशकारी होगी। हमारे विचार में

देखने के लिए, यह एक उन्नत में प्रचलित एक प्रणाली नकल करने के लिए अविवेकी है

एक विकसित नागरिक समाज के साथ देश।

184. न्यायाधीशों के चयन की संवेदनशीलता बहुत अधिक है,

और अनुचित नियुक्तियाँ करने के परिणाम

इतना खतरनाक, कि अगर वे चयन की प्रक्रिया में शामिल हैं और उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं को-चालू-रिकॉर्ड बनाएँ

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

गलत चयन, यह अच्छी तरह से राष्ट्र को अराजकता की ओर ले जा सकता है

प्रकार। "प्रतिष्ठित व्यक्तियों" की भूमिका की सराहना नहीं की जा सकती है

विवादित संविधान के माध्यम से व्यक्त किया गया तरीका

संशोधन और विधायी अधिनियम। सबसे अच्छा, शुरू करने के लिए,

एक या अधिक "प्रतिष्ठित व्यक्ति" (शायद एक समिति भी)

विचाराधीन उम्मीदवार। शायद, न्यायिक के तहत

चयन प्रक्रिया का घटक। और संभवतः, शामिल

प्रख्यात वकीलों, प्रख्यात न्यायविदों और यहाँ तक कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी,

या इस तरह के काम करने और कार्य करने के लिए एक अंतर्दृष्टि है

न्यायिक प्रणाली। और यह सुनिश्चित करके कि प्रतिभागियों के पास

हितों का टकराव नहीं। जाहिर है, अंतिम चयन निकाय होगा होगा, लेकिन बाध्य होगा

अनुभव की गई राय से बाध्य नहीं

नामों को अंतिम रूप देते समय दी गई राय को ध्यान में रखना।

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों का चयन और नियुक्ति, निहित करना। द.

और साथ ही उनके पास वीटो की शक्ति

धारा 5 (2) और धारा 6 (6) के तहत दूसरा परंतुक

एन. जे. ए. सी. अधिनियम, स्पष्ट रूप से आदेश देता है कि एक व्यक्ति को नामित किया जाए

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाता है, और व्यक्तियों को प्रमुख के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाता है

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं की जा सकती है, यदि

एन. जे. ए. सी. के कोई भी दो सदस्य प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं।

न्यायाधीशों की चयन प्रक्रिया की योजना में

न्यायपालिका, विवादित संवैधानिक के तहत विचार किया गया

एन. जे. ए. सी. अधिनियम के साथ पढ़ा गया संशोधन, दो "प्रतिष्ठित व्यक्ति" सभी सिफारिशों को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त हैं, बस

अपने आप में। इतना ही नहीं, ये दोनों "प्रतिष्ठित व्यक्ति"

सभी नामों को सर्वसम्मति से अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार भी है

एन. जे. ए. सी. के शेष चार सदस्यों द्वारा अनुमोदित। कि

स्पष्ट रूप से अस्वीकार करने की शक्ति, सर्वसम्मति [2015] 13 एस. सी. आर. शामिल होगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एन. जे. ए. सी. के पूरे न्यायिक घटक की सिफारिश। हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, इस तरह के अधिकार का निहित होना

"न्यायपालिका की स्वतंत्रता"। इस तरह के अधिकार का निहित होना जिन व्यक्तियों का प्रशासन प्रणाली से कोई संबंध नहीं है

न्याय स्पष्ट रूप से मनमाना है, और हम इसे ऐसा मानते हैं। समावेशन

"प्रतिष्ठित व्यक्तियों" का, जैसा कि पहले ही ऊपर निष्कर्ष निकाला जा चुका है (देखें

पैराग्राफ 156), की प्रधानता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा

न्यायपालिका, न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति के मामले में

उच्च न्यायपालिका को (साथ ही उनका स्थानांतरण भी)। कारणों से

यहाँ ऊपर अभिलिखित, यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 124 ए (1) (डी) एक तरफ रखा जा सकता है और उल्लंघन के रूप में मारा जा सकता है

संविधान की "मूल संरचना"।

IX.

186. सुनवाई के दौरान, विद्वान वकील

जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में पिछली नियुक्तियों के बारे में कुछ संदर्भ दिए, ताकि आरोप को तेज किया जा सके, कि

"कॉलेजियम प्रणाली ने कुशलता से काम नहीं किया था, क्योंकि,

उनके द्वारा संदर्भित प्रकृति के व्यक्तियों का चयन किया गया

किसी भी न्यायाधीश (न्यायाधीशों) को नाम से संदर्भित किया गया। उनका संदर्भ था कर्म।
न्यायालय कक्ष में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति,

संबंधित न्यायाधीश की पहचान से अवगत था, जिस तरह से

प्रस्तुतियाँ अग्रिम थीं। विद्वानों द्वारा प्रक्षेपण

महान्यायवादी को प्रिंट द्वारा खुशी-खुशी पेश किया गया और

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, व्यापक रूप से संकेतों को उजागर करता है

विद्वान महान्यायवादी द्वारा प्रचार किया गया। 187. यदि हमारी स्मृति हमारी सही सेवा
करती है, तो विद्वान महान्यायवादी ने अनुचित नियुक्ति का संदर्भ दिया था

उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीश। किसी ने महसूस किया होगा,

आरोप के गुण-दोष में गए बिना, कि दोष ढूँढना केवल तीन न्यायाधीशों के साथ, एक से अधिक
की नियुक्ति के बावजूद

सर्वोच्च न्यायालय के सौ न्यायाधीश, चूंकि सर्वोच्च न्यायालय-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

द्वितीय में दिए गए निर्णय का कार्यान्वयन

न्यायाधीशों का मामला (6.10.1993 पर सुनाया गया)-एम. के. मुखर्जी,

जे., "कॉलेजियम प्रणाली" के तहत नियुक्त पहले न्यायाधीश होने के नाते

14.12.1993 पर, और बी. एन. कृपाल, सी. जे.।, प्रथम मुख्य न्यायाधीश

इसके तहत, सर्वोच्च के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है

"कॉलेजियम प्रणाली" के तहत 11.9.1995 पर अदालत को होना चाहिए

इसे कोई मामूली उपलब्धि नहीं माना जाता है।

188. विद्वान महान्यायवादी की सूची में पहला

वह एक ऐसा न्यायाधीश था जिसने, उसके अनुसार, शायद ही कोई निर्णय दिया था, दोनों अवधि के दौरान वह एक न्यायाधीश बना रहा और

देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, साथ ही,

जिस अवधि के दौरान वे इस न्यायालय के न्यायाधीश बने रहे।

"कॉलेजियम प्रणाली" की विफलता के लिए इस तथ्य को जिम्मेदार ठहराया गया था,

कि ऐसे व्यक्ति को बाहर कर दिया गया होगा, अगर एक सार्थक

स्वभाव से, संबंधित न्यायाधीश को आगे बढ़ा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट। उनके द्वारा उद्धृत दूसरा उदाहरण था,

एक न्यायाधीश का सम्मान, जिसने किसी भी समय अनुसूची का पालन नहीं किया। यह.

यह दावा किया गया था कि न्यायाधीश को अनिवार्य रूप से देर हो चुकी थी

एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। यह खेद व्यक्त किया गया कि उपरोक्त व्यवहार अपनाई गई प्रक्रिया में पर्याप्त नहीं था। "कॉलेजियम प्रणाली" के तहत, न्यायाधीश को पदोन्नति से अस्वीकार करना

सुप्रीम कोर्ट तक। तीसरे न्यायाधीश के रूप में वर्णित किया गया था

व्यक्ति, जो आदतन अपने विचार ट्वीट कर रहा था, पर

इंटरनेट। उन्होंने उन्हें एक अयोग्य व्यक्ति के रूप में वर्णित किया

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का उच्च पद, और फिर भी,

"कॉलेजियम प्रणाली ने सर्वोच्च न्यायालय में उनकी नियुक्ति का समर्थन किया था।

189. जैसे किसी प्रस्तुति को नजरअंदाज करना असंभव था

महान्यायवादी द्वारा प्रस्तुत, इसलिए भी, किसी भी सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट द्वारा समान नोट पर प्रस्तुत प्रस्तुतियों को छोड़ना अनुचित होगा।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के अलावा।

जहाँ तक श्री दुष्यंत ए. दवे, वरिष्ठ अधिवक्ता की बात है,

चिंतित, गलत नियुक्तियों का उनका स्पष्ट दावा इसमें इस न्यायालय के एक न्यायाधीश का संदर्भ शामिल था, जिसने कथित रूप से

उनके बोर्ड पर एक मामला लिया गया, जो उनके रोजर को नहीं सौंपा गया था।

आरोप लगाया गया था कि उन्होंने मामले का गलत तरीके से निपटारा किया था। इससे पहले कि हम उपरोक्त विवाद पर ध्यान दें, यह आवश्यक है

नोटिस, कि आरोप लगाया गया है, कथित रूप से एक से संबंधित नहीं है अनुचित चयन और नियुक्ति। आरोप सीमित है।

“एक” मामले के गलत निर्धारण के लिए। तत्काल के रूप में

मामले के पहलू का संबंध है, हमारे लिए यह आवश्यक है कि नोटिस, कि एक समीक्षा याचिका दायर करने के लिए आया था

कथित अनुचित आदेश, उक्त न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया। वैसा ही।

बर्खास्त कर दिया गया। न्यायाधीश के पद छोड़ने के बाद, एक उपचारात्मक

याचिका दायर की गई थी, जिसमें कथित अनुचित आदेश पारित किया गया था संबंधित न्यायाधीश द्वारा हमला किया गया था। उसी को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद भी इसके खिलाफ याचिका दायर की गई थी

संबंधित न्यायाधीश, उसे एक पक्ष-प्रतिवादी के रूप में शामिल करके।

उक्त याचिका भी खारिज कर दी गई। हमें और कुछ नहीं कहना है,

यहाँ ऊपर जो देखा गया है, उसके संदर्भ में विशेष मामला, कथित रूप से संबंधित द्वारा गलत तरीके से तय किया गया

न्यायाधीश।

190. ध्यान में रखते हुए यह हमारे लिए अनिवार्य है।

विद्वान महान्यायवादी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियाँ, इस बात को उजागर करने के लिए कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की भूमिका

द्वितीय न्यायाधीशों में दिए गए निर्णय के अनुरूप

इस मामले में न्यायपालिका के सदस्यों के साथ-साथ कार्यपालिका के सदस्यों की दोहरी भागीदारी की परिकल्पना की गई है। विवरण में

यह पक्ष हमारे द्वारा “संदर्भ आदेश” में दर्ज किया गया है।

और इसलिए, किसी भी विफलता के मामले में, यह केवल न्यायिक नहीं है

घटक, लेकिन कार्यकारी घटक भी, जो संयुक्त रूप से हैं
और समान रूप से जिम्मेदार। इसलिए, न्यायपालिका को अलग करने के लिए
आलोचना के लिए, मामले का सही प्रतिबिंब नहीं हो सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

191. अपनी सहमति व्यक्त करना हमारे दायरे में नहीं है।

या हाथों में आगे बढ़े विवाद के साथ असहमति विद्वान महान्यायवादी का। वह अपने बारे में सही
हो सकता है।

अपनी धारणा, लेकिन उनके द्वारा बताए गए संदेह हो सकते हैं
दूसरों की धारणा में बहुत महत्व का नहीं होना, विशेष रूप से
जो न्यायिक प्रणाली के काम करने की पूरी तरह से सराहना करते हैं।

विद्वान महान्यायवादी द्वारा बताए गए संदेहों को निम्नलिखित की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए:
विचार:

सबसे पहले, न्यायाधीशों के खिलाफ लगाए गए आरोप,
न्यायिक कार्य के निर्वहन में क्षमता की कमी को न दर्शाएँ।

जिम्मेदारी। निश्चित रूप से यही मुख्य विचार है जिस पर विचार किया जाना चाहिए

ध्यान में रखते हुए, चयन और नियुक्ति के समय व्यक्ति, उच्च न्यायपालिका के स्तर पर एक
न्यायाधीश के रूप में।

दूसरा, की ओर से व्यक्त कोई भी संदेह नहीं
उत्तरदाता, सत्यनिष्ठा और दुराचार के लिए संदर्भित हैं।
एक अन्य पहलू, जिससे समझौता नहीं किया जा सकता है,

उच्च न्यायपालिका के स्तर पर न्यायाधीश के रूप में किसी व्यक्ति का चयन। इस मोर्चे पर भी कुछ गलत नहीं
है।

राजनीतिक-कार्यपालिका ने न्यायाधीशों की पदोन्नति पर आपत्ति जताई थी संदर्भित किया गया।
हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पूछने पर, हम थे

जिन्हें पदोन्नत किया गया था, उनके विवरण के साथ प्रस्तुत किया गया था,

संघ-कार्यपालिका के हाथों आपत्तियों के बावजूद। कोई नहीं।
 जिन न्यायाधीशों का उल्लेख किया गया है, वे उस सूची में शामिल हैं।
 चौथा, वकील द्वारा कोई आरोप नहीं लगाया गया था
 जनरल, न्यायाधीशों के संदर्भ में, जिनके खिलाफ आपत्तियाँ हैं
 राजनीतिक-कार्यपालिका द्वारा उठाया गया था, और फिर भी, वे थे
 मुख्य न्यायाधीश के आग्रह पर नियुक्त, के तहत
 "कॉलेजियम प्रणाली"।

पाँचवाँ, कि राजनीतिक-कार्यकारी स्वभाव, इसके बावजूद
 आरोप, [2015] 13 एस. सी. आर.

विद्वान महान्यायवादी द्वारा लगाए गए

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

चार में से तीन को सेवानिवृत्ति के बाद के कार्य प्रदान करें।
 पोस्ट

सुनवाई के दौरान संदर्भित मामले। एक

सेवानिवृत्ति कार्य को भी राजनीतिक द्वारा अनुमति दी गई थी

जनरल ने यह सब गलत समझा था। और अगर वह सही है, तो राजनीतिक
 गलत समझा, क्योंकि यह होने के बावजूद लड़खड़ा गया

कार्यकारी ने यह सब

उजागर की गई तथ्यात्मक स्थिति से अवगत।

अंत में, हमारे लिए यह समझना संभव नहीं हुआ है कि कैसे और क्यों, एक न्यायाधीश ने अपने विचारों को
 ट्वीट करना शुरू कर दिया।

सेवानिवृत्ति को पदोन्नति के योग्य नहीं माना जा सकता है। द.

तथ्य यह है कि संबंधित न्यायाधीश ने इसके बाद अपने विचार ट्वीट करना शुरू कर दिया

उनकी सेवानिवृत्ति विवाद में नहीं है। इस मामले को शामिल करना

यह अच्छी तरह से प्रदर्शित हो सकता है कि कुल मिलाकर, "कॉलेजियम प्रणाली" की कार्यप्रणाली उतनी
 खराब नहीं हो सकती जितनी दिखाई गई है।

192. श्री दुष्यंत ए. डेव द्वारा प्रस्तुतियाँ

केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के उदाहरण तक ही सीमित नहीं थे

अदालत। उन्होंने माया जैसे व्यक्तियों के बारे में मजबूत विचार व्यक्त किए।
 गुजरात के पूर्व मंत्री कोडनानी को दंगों के एक मामले में दोषी ठहराया गया है।
 राहत दिए जाने के लिए, जबकि एक कथित रूप से प्रसिद्ध
 कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को पाने के लिए एक खंभे से दूसरे खंभे तक भागना पड़ा अग्रिम
 जमानत। उन्होंने दोषी ठहराए जाने का भी हवाला दिया
 राजनेताओं और फिल्म सितारों, जिन्हें दो लोगों ने राहत दी थी
 विभिन्न उच्च न्यायालय, साथ ही इस न्यायालय द्वारा भी। यह उनका अफसोस था कि जब फिल्म सितारों और
 राजनेताओं को अनुमति दी जा रही थी
 उच्च न्यायपालिका द्वारा तत्काल राहत। आम लोगों को भुगतना पड़ा
 वर्षों से। उन्होंने इस सब के लिए दोषपूर्ण चयन को जिम्मेदार ठहराया
 प्रचलन में प्रक्रिया, जिसके परिणामस्वरूप नियुक्ति हुई थी
 "खराब न्यायाधीश"। उन्होंने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि पीड़ित
 1984 दिल्ली में सिख विरोधी दंगे और 2002 में मुस्लिम विरोधी दंगे
 गुजरात को कोई न्याय नहीं मिला था। यह उनका तर्क था कि न्यायाधीशों का चयन और नियुक्ति वर्तमान
 प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है
 प्रचलन में, दोष देना था। उन्होंने यह भी विचार व्यक्त किया कि
 नियुक्त न्यायाधीश मानवाधिकारों के उल्लंघन से अनजान थे।

सर्वोच्च न्यायालय

अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. /जगदीश सिंह खेहर, जे. जे.
 यह प्रस्तुत किया गया था कि यह शर्मनाक है कि कानून की अदालतें कर सकती हैं
 न्याय नहीं देते, उन लोगों को जिनके मौलिक और मानवीय अधिकारों का उल्लंघन किया गया
 था।

193. इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि प्रत्येक के तहत
 विधि प्रणाली में, प्रत्येक मुकदमे के दो पक्ष होते हैं। केवल एक।
 जिसमें वे सफल होते हैं। सवाल यह है कि मामला कैसा रहा है

निर्णय लेना हमेशा बहस का विषय रहेगा। पार्टी, जो सफल होता है, महसूस होता है कि न्याय किया गया था। जबकि पार्टी जो हारता है, वह शिकायत करेगा कि न्याय से इनकार कर दिया गया था। में। न्यायिक प्रक्रिया, उपचारों का एक समूह है, जो हैं

उच्चतम न्यायालय के स्तर पर कार्यवाही का समापन। एक बार जब प्रक्रिया पूरी तरह से चल जाती है, तो यह वास्तव में व्यर्थ है

पर्याप्त के आधार को छोड़कर किसी भी गलत काम का आरोप लगाएं।

अन्यथा दिखाने के लिए सामग्री। ऐसा नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय है ठीक है, लेकिन वहाँ एक बंद होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के राष्ट्रपति द्वारा सचित्र रूप से उल्लिखित अधिकांश मामले बार एसोसिएशन, आपराधिक अभियोजन से संबंधित है। द.

अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की पर्याप्तता। प्रकृति. आरोपों में से (सच, या अन्यथा), एक महत्वपूर्ण है

पक्षकारों द्वारा मांगी गई अंतरिम राहत (ओं) को ध्यान में रखते हुए। द.

वांछित आदेश पारित करने (या पारित नहीं करने) के लिए दोष देता है

इसलिए स्वयं निर्णय करने वाले न्यायाधीश की इच्छा पर निर्भर नहीं, लेकिन प्रस्तुत साक्ष्य की गुणवत्ता और प्रामाणिकता, और

आरोपों की प्रकृति। एक बार जब सभी उपचार उपलब्ध हो जाएँ

थक गया है, यह वादी के मुँह में नहीं है, या

उद्देश्यों को इंगित करने के लिए संबंधित वकील, बिना रखे

किसी भी अतिरिक्त सामग्री को दर्ज करें। यह भी दर्ज करने की आवश्यकता है कि संकेत देते समय, विद्वान वरिष्ठ वकील ने नहीं किया

किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नाम का एक स्पष्ट संदर्भ दें,

और न ही हमारे लिए ऐसे किसी न्यायाधीश की पहचान करना संभव था, केवल प्रस्तुतियों का आधार, उदाहरणों के विपरीत

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस मामले को देखते हुए, हमारे लिए यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि वहाँ प्रस्तुतियों के आधार पर प्रचलित "कॉलेजियम प्रणाली" हमारे सामने आगे बढ़े।

194. यह स्पष्ट है कि विद्वान वकील ने अपनी बात रखी थी, बिना किसी सीमा के। यह आवश्यक था, इसकी सराहना करने के लिए के संदर्भ में सभी प्रस्तुतियाँ (उम्मीद है) दर्ज की गईं समर्थन के अभाव में भी विवाद आगे बढ़े दलीलों। हम अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहेंगे, अगर हम श्री दुष्यंत ए. दवे के बिदाई के शब्दों का उल्लेख नहीं करते हैं - सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, जो अपने प्रकोप के बाद अपनी सांस वापस पाने के बाद, आखिरकार किया स्वीकार करें कि अभी भी न्यायाधीशों का बहुमत नियुक्त किया गया है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय उत्कृष्ट थे/हैं। और एक छोटा अल्पसंख्यक "खराब न्यायाधीश" थे। कुल मिलाकर, ए जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी, उससे काफी भावनात्मक भिन्नता है। कोई केवल यह देखकर निष्कर्ष निकाल सकता है कि व्यक्तिगत विफलताएँ ऐसे व्यक्ति जो कार्यपालिका के वास्तविक कार्य में शामिल हैं, विधायिका और न्यायपालिका, जरूरी नहीं कि अनुमान, कि वह प्रणाली जो उन्हें चुनती है, और उन्हें सौंपती है उनकी भूमिका दोषपूर्ण है।

एक्स.

नागरिक समाज के विकास के साथ परिवर्तन की आवश्यकता है। हमारे पास है। पहले से ही निष्कर्ष निकाला गया है कि एक से कहीं अधिक कारणों से,

द्वितीय न्यायाधीशों के मामले में अभिलिखित, "परामर्श" शब्द,

- उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों के चयन के लिए संदर्भित, वास्तव में मतलब, संविधान निर्माताओं के विवेक में भी,

इस मामले में प्रधानता भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास बनी रहना चाहिए (कई न्यायाधीशों के परामर्श से)।

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

निस्संदेह, यह संसद के लिए खुला है, जबकि इसका प्रयोग करते हुए

अनुच्छेद 368 के तहत कुछ अन्य विकल्प प्रदान करने की शक्ति

न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया

उच्च न्यायपालिका, जब तक, "के पृथक्करण" की विशेषताएँ

शक्तियाँ "और" न्यायपालिका की स्वतंत्रता ", जो "मूल "हैं संविधान की "मूल संरचना" के घटक हैं -

बनाए रखा।

196. हालाँकि, यह मानकों पर निर्भर करेगा

भारतीय राजनीति का नैतिक तंतु। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है,

कि विद्वान महान्यायवादी ने स्वीकार किया था कि वहाँ

कुछ राजनीतिक उथल-पुथल थे, जिन्होंने कमजोर कर दिया था

"कार्यपालिका सहित न्यायपालिका की स्वतंत्रता 1973 में भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय, न्यायाधीशों के सामूहिक स्थानांतरण के बाद

1976 में आपातकाल के दौरान और उसके बाद उच्च न्यायपालिका एक दूसरे की नियुक्ति के समय दूसरा अधिवेशन

1977 में भारत के मुख्य न्यायाधीश। और आगे, द्वारा हस्तक्षेप

1980 के दशक के दौरान उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में कार्यपालिका।

197. एक महत्वपूर्ण मुद्दा, जिसके लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होगी,

संविधान की जैविक संरचना में परिवर्तन से पहले,

विवादित संवैधानिक द्वारा विचार किया गया तरीका

संशोधन, यह होगा कि क्या नागरिक समाज सक्षम है

अपने नेताओं को राष्ट्रीय हित की ओर ले जाने के लिए? और

क्या, नागरिक समाज की ताकत, एक परिमाण की है, जैसे के किसी भी स्तंभ द्वारा किसी भी अतिक्रमण के लिए एक निवारक होगा

शासन? वर्तमान समय में, नागरिक समाज में विश्वास और विश्वास को फिर से स्थापित करना, किसी भी प्रभावी भूमिका को निभाना मुश्किल लगता है

उस दिशा में भूमिका। सरल कारण से, कि यह अभी तक नहीं है पर्याप्त रूप से प्रेरित, न ही पर्याप्त रूप से निर्धारित, एक में होने के लिए

राजनीतिक के लिए एक दिशात्मक निवारक के रूप में कार्य करने की स्थिति

कार्यकारी प्रतिष्ठान। इसलिए, उच्च न्यायपालिका,

जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है

यह देश, संवैधानिक जिम्मेदारी के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

अनुच्छेद 32 और 226 के तहत इसे सौंपा गया है, उसे कार्य करना जारी रखना चाहिए

नागरिक समाज के रक्षक के रूप में। यह जरूरी होगा।

"कानून के शासन" को संरक्षित करने के दायित्व पर विचार करें, राजनीतिक-कार्यपालिका को सीमाओं का उल्लंघन करने से रोकना

संविधान द्वारा परिकल्पित उनके अधिकार का।

198. ऐसा न हो कि किसी पर रिकॉर्ड करने का आरोप लगाया जाए

व्यापक निष्कर्षों के अनुसार, उपरोक्त निष्कर्ष के कारणों को दर्ज करना आवश्यक होगा। द इंडियन एक्सप्रेस, 18.6.2015 पर,

भाजपा के अनुभवी नेता एल. के. आडवाणी के साथ एक साक्षात्कार प्रकाशित किया लोकसभा में संसद सदस्य, शीर्षक के तहत

"अधिरोपण की 40 वीं वर्षगांठ से पहले

25.6.1975 "पर आपात स्थिति। उनके विचार भयानक रूप से प्रकट करने वाले थे। उनकी राय में, जो ताकतें लोकतंत्र को कुचल सकती थीं, वे अब पहले से कहीं अधिक मजबूत। उन्होंने जोर देकर कहा, "मैं कुछ नहीं सोचता।

ऐसा किया गया है जो मुझे यह आश्वासन देता है कि नागरिक स्वतंत्रता

इसे फिर से निलंबित या नष्ट नहीं किया जाएगा। बिल्कुल नहीं "!! यह था।

उनकी स्थिति भी, कि आपातकाल फिर से हो सकता है। जबकि यह स्वीकार करते हुए कि आज मीडिया अधिक सतर्क था और

स्वतंत्र, जो था उसकी तुलना में, जब आपातकाल था

चालीस साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसकी घोषणा की थी। उनकी धारणा में, मीडिया के पास कोई वास्तविक नहीं था

लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता। संदर्भ के साथ

नागरिक समाज के लिए, उन्होंने बताया, कि उम्मीदें बढ़ाई गई थीं

भ्रष्टाचार के खिलाफ अना हजारों आंदोलन के दौरान, जो उनके अनुसार, एक निराशा में समाप्त हुआ, यहां तक कि

भ्रष्टाचार के विषय का संदर्भ। यह तब है जब गरीब और इस देश का दलित बहुमत भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं कर सकता है।

उन्होंने कहा कि इस देश में लोकतंत्र के अच्छे कामकाज के लिए जिन विभिन्न संस्थानों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, उनमें से

कि न्यायपालिका दूसरे की तुलना में अधिक जिम्मेदार थी

संस्थाएं।

199. उपरोक्त साक्षात्कार में मणिशंकर अय्यर ने कहा,

राज्यसभा में कांग्रेस के अनुभवी सांसद,

अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि भारत सर्वोच्च न्यायालय का अधिवक्ता नहीं हो सकता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

"आपातकालीन प्रमाण", जब तक संविधान के लिए प्रदान किया गया है

निर्वाचित व्यक्ति के विवेक पर आपातकाल की घोषणा

सरकार। उन्होंने कहा कि यह नहीं भूलना चाहिए कि 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था।

संविधान की रूपरेखा। इसलिए यह सुझाव दिया गया था कि

आपातकाल की घोषणा से बचने के समाधानों में से एक हो सकता है

संविधान के भाग XVIII को हटाने या इसमें संशोधन करने के लिए,

और "केवल एक बाहरी आपातकाल प्रदान करने के लिए"। हालांकि उन्होंने

उन्होंने एक सवाल उठाया कि क्या ऐसा करना व्यावहारिक होगा? एक.

नकारात्मक में उसी का जवाब देने का साहस करेंगे। और ऐसे में

स्थिति, विश्वास करने के लिए, कि निर्वाचित सरकार में कार्य करेगा राष्ट्र का हित।

200. सीताराम ने एल. के. आडवाणी के रुख की पुष्टि की

येचुरी, एक अनुभवी सीपीआई (मार्क्सवादी) संसद सदस्य

राज्यसभा, जिसे एल. के. आडवाणी की तरह गिरफ्तार किया गया था

1975 में आपातकाल।

201. वर्तमान एन. डी. ए. सरकार ने शपथ ली,

26.5.2014. एक का मानना है कि उसके बाद तेरह राज्यपाल

विभिन्न राज्य और एक संघ का एक उपराज्यपाल क्षेत्र ने कुछ ही समय में अपने इस्तीफे दे दिए।
कुछ राज्यपालों ने पद छोड़ने के तुरंत बाद अपना पद छोड़ दिया।

इस तथ्य के बावजूद, कि संवैधानिक के तहत एक राज्यपाल अनुच्छेद 156 (3) के अधिदेश की
अवधि पाँच वर्ष है।

जिस दिन वह अपने कार्यालय में प्रवेश करता है। राज्यपाल का चयन पेशेवर उत्कृष्टता और/या व्यक्तिगत
योग्यता रखने वाले व्यक्तियों में से किया जाता है।

प्रशंसा करते हैं। उनमें से प्रत्येक नामित होने का पात्र होगा। अनुच्छेद 124 ए (1) (डी) के तहत
एक "प्रतिष्ठित व्यक्ति" के रूप में। आश्चर्य होता है,

क्या ये सभी इस्तीफे स्वैच्छिक थे। उपरोक्त

चित्रण किसी भी आक्षेप को डालने के लिए नहीं है। वास्तव में, इसका

पूर्ववर्ती-यू. पी. ए. सरकार ने 2004 में ऐसा ही किया था।

202. यह सराहना करना आवश्यक है कि संविधान

"लूट प्रणाली" (जिसे सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर. के रूप में भी जाना जाता है) की
परिकल्पना नहीं करता है।

"संरक्षण प्रणाली"), जिसमें राजनीतिक दल जो एक जीतता है चुनाव, अपने समर्थकों, दोस्तों को
सरकारी पद देता है

और रिश्तेदार, जीत की दिशा में काम करने के लिए एक पुरस्कार के रूप में, और के रूप में

पार्टी को सत्ता में रखने के लिए प्रोत्साहन।

203. यह इंगित करने के लिए भी प्रासंगिक है, की छवियाँ

"लूट प्रणाली" इस तथ्य से परिलक्षित होती है कि एक बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण संस्थानों में उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों का, इसी तरह वर्तमान के बाद अपने कार्यों से इस्तीफा दे दिया एन. डी. ए. सरकार ने शपथ ली। उनमें से कुछ सिर्फ एक था उनके कार्यकाल की समाप्ति से कुछ महीने पहले-और कुछ, यहाँ तक कि एक महीने से भी कम। जो लोग चले गए उनमें नौकरशाह भी शामिल थे उच्चतम स्तर पर प्रतिष्ठित पदों पर आसीन अखिल भारतीय सेवाएँ, के शैक्षणिक संस्थानों के निदेशक/अध्यक्ष राष्ट्रीय प्रशंसा, संवैधानिक प्राधिकरण (इसके अलावा)

राज्यपाल), निदेशक/राष्ट्रीय अनुसंधान के अध्यक्ष संस्थाएं, और इसी तरह। गंभीरता से, तत्काल कथन नहीं है

बदनाम करने के उद्देश्य से, लेकिन जमीनी हकीकत की सराहना के लिए,

सिस्टम वास्तव में कैसे काम करता है। 204. ऊपर से, यह समझने की बात है कि ये सभी व्यक्ति पसंदीदा श्रेणी के थे, जिन्हें पूर्ववर्ती द्वारा अनुमोदित किया गया था

राजनीतिक-कार्यकारी प्रतिष्ठान? या, सबसे अच्छा नहीं चुना गया था

पिछली व्यवस्था द्वारा स्थान भरने के लिए? हो सकता है कि जिन लोगों को सरकार की बागडोर संभालने का मौका मिलता है, वे अपने पसंदीदा लोगों का परिचय देते हैं? या, क्या मौजूदा पदाधिकारी न्याय के योग्य थे

कि? क्या यह हो सकता है, कि अपने पूर्ववर्ती की तरह, वर्तमान

जो उभरता है वह है, लूट प्रणाली का जाल, और कुछ भी नहीं और भी। उपरोक्त मापदंडों में से कोई भी नहीं अपनाया जा सकता है

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला। के लिए

न्यायपालिका, उपलब्ध लोगों में से सर्वश्रेष्ठ को चुनना होगा। परिवर्तन के साथ विचार अलग-अलग नहीं हो सकते हैं।

सरकार। जाहिर है, ठीक यही हुआ है।

(बार-बार?), गैर-न्यायिक नियुक्तियों के मामले में। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण होगा कि न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं की रक्षा की जाए-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे.]

नियुक्तियाँ, किसी भी राजनीतिक-कार्यकारी हस्तक्षेप से, शासन से "न्यायपालिका की स्वतंत्रता" को संरक्षित करें

लूट प्रणाली। न्यायपालिका में प्रधानता बनाए रखना,
न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति का मामला, उच्चतर
न्यायपालिका ऐसा करने का एक सुरक्षित तरीका होगा।

205. अंत में, इसे पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि

ऊपर व्यक्त की गई तथ्यात्मक स्थिति, कि ज्ञान

न्यायाधीशों की नियुक्ति, राजनीतिक दलों के साथ साझा की जा सकती है कार्यकारी। भारत में नागरिक समाज का जैविक विकास,

अभी तक पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हुआ है। से अपेक्षा

न्यायपालिका, इस देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए,

इसे पूरी तरह से अछूता रखकर ही सुनिश्चित किया जा सकता है और शासन के अन्य अंगों से स्वतंत्र। हमारे देश में

माना गया दृष्टिकोण, नागरिक के विकास की वर्तमान स्थिति

भारत में "समाज" राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा नहीं देता है कार्यकारी प्रतिष्ठान, के चयन और नियुक्ति में

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीश, या के स्थानांतरण के मामले में

एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश, दूसरे को।

XI.

206. यह ध्यान दिया जा सकता है कि विवादों में से एक

और राज्य सभा, इसे राज्य विधानमंडलों को भेजा गया था अनुमोदन। राज्य द्वारा अनुसमर्थन पर परिणाम

अनुच्छेद में निहित जनादेश के अनुपालन में विधान मंडल

368, राष्ट्रपति ने उसी पर अपनी सहमति प्रदान की

संविधान (99 वां संशोधन) अधिनियम। इसकी धारा 1 (2) प्रावधान आएंगे

यह प्रावधान करता है कि संशोधन के

केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से लागू। और इसके परिणामस्वरूप

उपरोक्त अधिसूचना जारी करने पर, संशोधन किया गया था

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट से प्रभावी एक अधिसूचना के माध्यम से लागू किया गया

[2015] 13 एस सी आर।

13.4.2015. यह याचिकाकर्ताओं का निवेदन था कि

एन. जे. ए. सी. अधिनियम को लागू करने का अधिकार क्षेत्र, द्वारा अधिग्रहित किया गया था

संसद 13.4.2015 पर, सरल कारण के लिए, कि वही

प्रचलित अनुच्छेदों के दौरान अधिनियमित नहीं किया जा सकता था

124 (2) और 217 (1) लागू थे, उसी के रूप में, प्रदान नहीं किया

एन. जे. ए. सी. जैसे निकाय द्वारा नियुक्तियों के लिए। यह,

प्रस्तुत किया गया था कि एन. जे. ए. सी. अधिनियम लागू किया गया था,

एन. जे. ए. सी. द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन करें।

न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्तियों की सिफारिश करना,

उच्च न्यायपालिका के लिए। यह तर्क दिया गया था कि प्रक्रिया

एन. जे. ए. सी. के बाद इसके द्वारा कानून नहीं बनाया जा सकता था संसद, जब तक संविधान में संशोधन नहीं किया गया, और

एन. जे. ए. सी. को चयन के लिए एक संवैधानिक इकाई के रूप में बनाया गया था। और के स्तर पर न्यायाधीशों की नियुक्ति (साथ ही, स्थानांतरण)

उच्च न्यायपालिका। एन. जे. ए. सी., यह दावा किया गया था, होना चाहिए

ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण तभी किया गया था जब संविधान (99 वां)

संशोधन) अधिनियम, से प्रभावी, लागू किया गया था

13.4.2015. यह प्रस्तुत किया गया था कि एनजेएसी अधिनियम ने प्राप्त किया

31.12.2014 पर राष्ट्रपति की सहमति, अर्थात् उस तारीख को जब एन. जे. ए. सी. अभी तक अस्तित्व में नहीं आया था। इसके लिए, सीखा वकील ने तर्क देने के लिए ए. के. रॉय मामले 49 पर भरोसा रखा था, कि तत्काल मामले में संवैधानिक संशोधन होगा 13.12.2014 पर नहीं, बल्कि 13.4.2015 पर लागू होता है।

207. एक पूरक अतिरिक्त प्रस्तुति थी

याचिकाकर्ताओं की ओर से उसी पर भरोसा करके आगे बढ़ाया गया तथ्यों का क्रम। यह तर्क दिया गया था कि वीटो की शक्ति

दूसरे के माध्यम से एन. जे. ए. सी. के दो सदस्यों में निहित

न्यायालय) और एन. जे. ए. सी. अधिनियम की धारा 6 (6) (के मामले में मुख्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति) को किसी भी प्रक्रिया को निर्धारित करने के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। यह था।

प्रस्तुत किया कि उपरोक्त प्रावधान स्पष्ट रूप से अधिनियमित किए गए हैं मूल कानून। इसी तरह, यह तर्क दिया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड का समर्थन करता है

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

"इन शब्दों के साथ परामर्श के बाद" शब्दों का संशोधन

राज्यों में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश

शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है "की सिफारिश पर में निर्दिष्ट राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग

अनुच्छेद 124 ए ", साथ ही, इसके तहत पहले परंतुक को हटाना

अनुच्छेद 124 (2) जो प्रमुख के साथ परामर्श को अनिवार्य करता है।

भारत का न्याय, और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियों की सिफारिश पर "शब्दों के साथ उसी का प्रतिस्थापन"

अनुच्छेद 124 ए के तहत निर्दिष्ट आयोग का परिणाम होगा -

एक बिल्कुल नए आहार की शुरुआत। यह प्रस्तुत किया गया था,

कि इस तरह का प्रतिस्थापन भी एक संशोधन के बराबर होगा

संविधान के विद्यमान प्रावधान, और इस प्रकार,

उसी के लिए प्रदान किए गए अभिधारणा अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होगी

एक संवैधानिक संशोधन के संबंध में, के प्रावधान के तहत अनुच्छेद 368 (2)। और जब से एनजेएसी अधिनियम, के रूप में अधिनियमित किया गया था

एक साधारण विधान, वही गैर के रूप में आयोजित किया जा करने के लिए उत्तरदायी था इस तथ्य के कारण, कि प्रक्रिया पर विचार किया गया था

अनुच्छेद 368 के तहत, संशोधन के लिए अभिनिर्धारित

संविधान का पालन नहीं किया गया था।

208. चूंकि यह विवादित नहीं था, कि संसद ने

नियम 66 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक विधेयक जो पूरी तरह से निर्भर था या आंशिक रूप से किसी अन्य विधेयक को इस प्रत्याशा में "पेश" किया जा सकता है कि

इस निष्कर्ष पर कि 121 वां संविधान संशोधन विधेयक, जिस पर एन. जे. ए. सी. विधेयक निर्भर था, उस पर विचार किया जा सकता था।

विचार (संसद में उसी को पेश करके), लेकिन

के गुजरने के बाद तक पारित नहीं किया जा सकता था

संविधान (99 वां संशोधन) अधिनियम, जिस पर यह निर्भर था।

209. जबकि इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है, जिसमें देखा गया है

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, हमने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार किया होगा

उपरोक्त प्रस्तुतिकरण, और वास्तव में इसे [2015] 13 एस. सी. आर. द्वारा स्वीकार किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रभाव के लिए अटॉर्नी जनरल, कि आश्रित विधेयक कर सकते हैं "

सदन में विचार और पारित करने के लिए लिया जाए, केवल सदन द्वारा पहला विधेयक पारित किए जाने के बाद। लेकिन हमारे

अध्यक्ष को किसी विशेष नियम (जिसमें नियम 66 शामिल होगा) के निलंबन की अनुमति देने के लिए अधिकृत करता है। यदि नियम 66 हो सकता है निलंबित, तो नियम 66 का प्रभाव नहीं होगा, जो

याचिकाकर्ता तत्काल प्रस्तुतिकरण के माध्यम से मांग करते हैं। यह एक नहीं है विवाद का विषय, जो तत्कालीन कानून और न्याय के प्रभारी केंद्रीय मंत्री ने मांगा था (नियमों के नियम 388 के तहत)

लोकसभा की कार्यप्रणाली और संचालन) नियम 66 के परंतुक का निलंबन। और उचित विचार पर, लोकसभा ने नियम 66 के प्रावधान को निलंबित कर दिया था, और

एन. जे. ए. सी. विधेयक पर विचार किया गया था। चूंकि वैधता

नियम 388 हमारे सामने चुनौती का विषय नहीं है, यह है

स्पष्ट है, कि यह अच्छी तरह से की क्षमता के भीतर था संसद, एन. जे. ए. सी. अधिनियम पर विचार करने के लिए,

जबकि संविधान (121 वां संशोधन) विधेयक, जिस पर

एन. जे. ए. सी. अधिनियम पूरी तरह से निर्भर था, अभी भी पारित नहीं किया गया था

संविधान के पारित होने की प्रत्याशा (121 वां)

संशोधन) विधेयक।

210. नियम 66 में निहित सिद्धांत, भले ही उक्त

नियम के लिए प्रावधान नहीं किया गया था, हमेशा माना जाएगा निहित रूप से वहाँ रहे हैं। नींव के अभाव में, नहीं

अधिरचना को ऊपर उठाया जा सकता है। तत्काल चित्रण है

नियम 66 से संबंधित, जिसमें लंबित विधेयक का गठन किया जाएगा।

नींव, और विधेयक की प्रत्याशा में पेश किया जा रहा है लंबित विधेयक का पारित होना, अधिरचना का गठन करेगा। इसलिए, आधारभूत के अभाव में

तत्काल मामले में, एनजेएसी अधिनियम)। हमारे सुविचारित दृष्टिकोण से, यह नियम 388 के संदर्भ में एक को लागू करना और पारित करना संभव था

संसद में विधेयक, सर्वोच्च न्यायालयों के पारित होने की प्रत्याशा में-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. /जगदीश सिंह खेहर, जे. जे.

यह अभी भी विचार करना संभव नहीं है कि एक विधेयक जो है किसी अन्य विधेयक पर पूरी तरह से (या, आंशिक रूप से) निर्भर, पारित किया जा सकता है।

और लागू किया गया, जब तक कि आश्रित विधेयक पारित नहीं हो जाता

और लागू किया गया।

211. हालाँकि यह दर्ज करना आवश्यक है कि भले ही

पूर्ववर्ती पैराग्राफ में अभिनिर्धारित स्थिति, जैसे

महान्यायवादी द्वारा प्रचार किया गया, अनुमेय था,

आश्रित अधिनियम अर्थात् एन. जे. ए. सी. विधेयक का पारित होना

आधारभूत अधिनियम तक प्रभावी नहीं किया गया है क्रियाशील हो गया था। तत्काल मामले में, एनजेएसी अधिनियम,

परीक्षण में विफल हो जाता, अगर इसे एक तारीख से प्रभावी किया जाता

उस तारीख से पहले, जिस पर अधिनियम के प्रावधान

जिस पर यह निर्भर था-संविधान (99 वां संशोधन)

अधिनियम, कार्यात्मक हो गया। दूसरे शब्दों में, एनजेएसी अधिनियम,

मृत जन्म होना, यदि आश्रित प्रावधान, के माध्यम से पेश किया गया है

उक्त नियम के निलंबन के बावजूद, और आश्रित अधिनियम लागू नहीं हो सका, इससे पहले कि आश्रित /

नियंत्रण प्रावधान चालू हो गया। का क्रम

ऊपर वर्णित तथ्यों से पता चलता है कि आश्रित और

प्रावधानों के आधार पर, एक साथ लागू किया गया था

उसी तारीख को, यानी 13.4.2015 पर। इसलिए यह स्पष्ट है कि आधार-संविधान (99 वां संशोधन) अधिनियम, जगह पर था, जब अधिरचना-एन. जे. ए. सी. अधिनियम था

उठाया गया। इस प्रकार देखा जाए तो हम संतुष्ट हैं कि प्रक्रिया

मतदान के समय संसद द्वारा अपनाया गया

एन. जे. ए. सी. विधेयक, या वह तिथि जिस पर एन. जे. ए. सी. अधिनियम प्राप्त हुआ राष्ट्रपति की सहमति, के अधिनियम को अमान्य नहीं कर सकती है

एन. जे. ए. सी. अधिनियम, जैसा कि विद्वान वकील द्वारा सुझाया गया है

याचिकाकर्ता।

212. एक को विवाद को स्वीकार करने के लिए भी राजी किया जाता है

विद्वान महान्यायवादी द्वारा प्रस्तावित, कि की वैधता संसद में किसी भी कार्यवाही पर हमला नहीं किया जा सकता है

सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया की अनियमितता का आधार

अनुच्छेद 122 के माध्यम से विचार किया गया। क्षण को स्वीकार करते हुए विद्वान महान्यायवादी का तर्क, इसके लिए आवश्यक है

हमें यह दर्ज करने के लिए कि हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, विद्वान वकील द्वारा इंगित की गई वनाच्छादित अनियमितता, होगी

पूरी तरह से चुनौती के दायरे से बाहर, विशेष रूप से क्योंकि यह याचिकाकर्ताओं का मामला नहीं था कि संसद ने किया

एन. जे. ए. सी. अधिनियम को लागू करने के लिए विधायी क्षमता नहीं है।

ऊपर दर्ज कारणों से, यह संभव नहीं है

हम स्वीकार करते हैं, कि एन. जे. ए. सी. अधिनियम मृत था, या कि यह था विद्वान द्वारा प्रचार किए गए कारणों के लिए अलग रखे जाने के लिए उत्तरदायी

याचिकाकर्ताओं के लिए वकील।

213. हमारे लिए यह स्वीकार करना भी संभव नहीं है कि

एन. जे. ए. सी. अधिनियम को लागू करना, संसद के लिए अनिवार्य था

अनुच्छेद 368 के तहत विचार की गई प्रक्रिया का पालन करें। यहाँ तक कि

जैसा कि मामले के तत्काल पहलू का संबंध है, संविधान

(99 संशोधन) अधिनियम, संशोधित अनुच्छेद 124 और 217 (के रूप में

साथ ही, अनुच्छेद 127, 128, 222, 224, 224 ए और 221), और अनुच्छेद

124 संविधान में ए से 124 सी जोड़ा गया था। जबकि

उपरोक्त संशोधनों को इंजीनियरिंग, प्रक्रियात्मक

अनुच्छेद 368 में निहित आवश्यकताएं स्वीकार्य थीं

अनुपालन किया। इसलिए यह स्पष्ट है कि कोई प्रक्रियात्मक चूक नहीं है।

संविधान को लागू करते समय किया गया था (99 वां) संशोधन) अधिनियम। अनुच्छेद 124 सी, संसद को अधिकृत करता है -

एन. जे. ए. सी. अधिनियम की प्रकृति में एक कानून बनाना। यह हो सकता है

के लिए विचार की गई प्रक्रिया का पालन करके वैध रूप से किया जाना चाहिए एक सामान्य कानून। यह विवादित नहीं है कि ऐसी प्रक्रिया, जैसा कि एक साधारण कानून बनाने के लिए विचार किया गया था, वास्तव में एन. जे. ए. सी. विधेयक के बाद संसद ने इसका पालन किया। संसद में पेश किया गया था, क्योंकि दोनों सदनों संसद ने एन. जे. ए. सी. विधेयक को अभिनिर्धारित बहुमत, सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं-ऑन-रिकॉर्ड द्वारा अनुमोदित किया।

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]
और उसके बाद, उसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई
31.12.2014 पर। उपरोक्त कारणों से, तत्काल अतिरिक्त
याचिकाकर्ताओं द्वारा अग्रिम प्रस्तुतिकरण भी नहीं किया जा सकता है
स्वीकार किया जाता है और तदनुसार अस्वीकार कर दिया जाता है।

बारहवीं।

214. भारत के विद्वान महान्यायवादी श्री मुकुल रोहतगी ने भारत सरकार द्वारा पेश की गई दलीलों को खारिज कर दिया।

याचिकाकर्ता, जो एन. जे. ए. सी. अधिनियम के प्रावधानों का अधिकार रखते हैं, कर सकते हैं
मूल का उल्लंघन करने के आधार पर चुनौती दी जाए संविधान की संरचना।

215. पहला और सबसे महत्वपूर्ण विवाद आगे बढ़ा, में
विद्वान महान्यायवादी के हाथ थे, कि
संविधान में संशोधन की संवैधानिक वैधता,
केवल उल्लंघनकारी होने के आधार पर हमला किया जा सकता है
"संविधान की मूल संरचना। इसके अतिरिक्त यह था कि

प्रस्तुत किया कि एक साधारण विधायी अधिनियम (एन. जे. ए. सी. की तरह)
अधिनियम), केवल विधायी क्षमता की कमी और/या संविधान के अनुच्छेद 13 के उल्लंघन के आधार पर
हमला किया जा सकता है।

संविधान। चूंकि, राज्य ऐसे कानून नहीं बना सकता है, जो संविधान के भाग III में प्रदत्त अधिकारों को छीन या कम कर देते हैं।

संविधान, या किसी अन्य संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं प्रावधान। यह स्वीकार किया गया कि कानून उल्लंघन में बनाया गया था

संविधान के भाग III में निहित प्रावधानों का, या

ऐसी सीमा तक कोई अन्य संवैधानिक प्रावधान

उल्लंघन, शून्य होगा। जहाँ तक मामले के तत्काल पहलू का संबंध है, विद्वान महान्यायवादी ने कहा

इंदिरा नेहरू गांधी मामले पर निर्भरता 56, कर्नाटक राज्य

वी. भारत संघ, और विशेष रूप से निम्नलिखित टिप्पणियों के लिए:

"238. श्री सिन्हा ने यह भी तर्क दिया कि एक साधारण कानून ऐसा नहीं कर सकता है

मूल योजना या मूल आधार के खिलाफ जाएँ

केंद्र-राज्य संबंध, जैसा कि इसमें निहित है

संविधान। उन्होंने इस संबंध में अपना तर्क बहुत ही

88 (1977) 4 एस. सी. सी. 608 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

सरल तरीके से क्योंकि उन्होंने इसे एक में रखने में कठिनाई महसूस की

सीधे तरीके से यह कहकर कि एक साधारण कानून का उल्लंघन नहीं हो सकता है

संविधान की मूल संरचना। श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी बनाम के मामले में। श्री राज नारायण ऐसा तर्क देते हैं

इस न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया था। हम आराम कर सकते हैं।

हमारे निर्णय से एक मार्ग का उल्लेख करके सामग्री

विद्वान भाई चंद्रचूड, जे., जो इस प्रकार हैं:

"संवैधानिक संशोधन, के अनुपात पर हो सकता है

संरचना। लेकिन इस सिद्धांत के अलावा कि एक मामला केवल है, वह तार्किक रूप से पालन नहीं करता है

एक प्राधिकरण जो यह तय करता

मौलिक अधिकारों के मामले में बहुमत के फैसले से

कि साधारण विधान को भी उसी परीक्षण का उत्तर देना चाहिए

संवैधानिक संशोधन के रूप में। सामान्य कानूनों को करना होगा उनकी वैधता के लिए दो परीक्षणों का उत्तर दें: (1) कानून होना चाहिए

विधानमंडल की विधायी क्षमता के भीतर अध्याय 1, भाग 11 में परिभाषित और निर्दिष्ट

संविधान और (2) इसके खिलाफ अपराध नहीं होना चाहिए

संविधान के अनुच्छेद 13 (1) और (2) के प्रावधान। 'बुनियादी संरचना' बहुमत के निर्णय से, इसका हिस्सा नहीं है

मौलिक अधिकार और न ही वास्तव में कोई प्रावधान

संविधान। बुनियादी संरचना का सिद्धांत इससे बुना गया है

संविधान का परिप्रेक्ष्य और संशोधन करने की शक्ति

इसके अधीन है क्योंकि यह एक घटक शक्ति है। द.

मौलिक साधन में संशोधन करने की शक्ति नहीं ले जा सकती है इसके साथ इसकी आवश्यक विशेषताओं को नष्ट करने की शक्ति '-यह,

संक्षेप में, मूल संरचना के सिद्धांत का कमान है। यह पूरी तरह से साधारण की वैधता से संबंधित मामलों में स्थान से बाहर

संविधान के तहत बनाए गए कानून "।

कुलदिप नायर की ओर भी अदालत का ध्यान आकर्षित किया गया।

भारत 89 पर, जिसमें यह दर्ज किया गया था:

"107. मूल संरचना सिद्धांत पर सीमा अधिरोपित करता है

संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति। अ.

06) 7 एस. सी. सी. 1 सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. /जगदीश सिंह खेहर, जे।]

अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है

मूल संरचना के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गई

संविधान से। एक सामान्य कानून ऐसा नहीं हो सकता है।

चुनौती दी। बनाए गए कानून के लिए चुनौती, इसके भीतर के आधार पर संसद द्वारा विधायी क्षमता

इस प्रकार संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन है

याचिकाकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है।

कुमार ठाकुर बनाम। भारत संघ, और निम्नलिखित के लिए संदर्भित

टिप्पणियाँ:

एक मौलिक साधन के रूप में संविधान की अखंडता
देश के शासन के लिए। यह देखा जा सकता है कि यह

आधार पर सामान्य कानूनों को चुनौती देने के लिए तैयार नहीं

मूल संरचना सिद्धांत। राज्य के कानून को इस सवाल पर चुनौती दी जा सकती है कि क्या यह कानून
का उल्लंघन करता है।

संविधान के प्रावधान। लेकिन संवैधानिक रूप से

संशोधन, यदि कोई चुनौती बुनियादी आधार पर दी जाती है

संरचना, इसकी बुनियादी विशेषताओं के आधार पर जांच की जानी चाहिए
संविधान "।

पूर्व-उद्धृत निर्णयों के आधार पर, यह था

विद्वान महान्यायवादी का दावा, कि एक की वैधता

इस आधार पर हमला किया गया कि वही "मूल" का उल्लंघन था
यह दावा किया गया कि

संविधान की संरचना। इसलिए

विद्वान वकील के हाथों में रखी गई निर्भरता, प्रकट हो रही है

याचिकाकर्ताओं के लिए, मद्रास बार एसोसिएशन मामले 35 पर, था

कानून में स्वीकार्य नहीं है।

216. उपरोक्त विवाद, विद्वान द्वारा आगे बढ़ाया गया

महान्यायवादी को खारिज कर दिया गया है। इसके लिए पहले चरण में

90 (2008) 6 एससीसी 1 [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उदाहरण के लिए, लोक सेवा न्यायाधिकरण बार पर निर्भरता रखी गई थी

एसोसिएशन बी। तत्काल निर्णय में U.P.91 की स्थिति देखी जाती है।

पैराग्राफ 26 में दर्ज टिप्पणियों से, कि यह न्यायालय

निष्कर्ष निकाला कि एक साधारण की संवैधानिक वैधता

विधान को केवल दो आधारों पर चुनौती दी जा सकती है, अर्थात् -

विधायी क्षमता की कमी के कारणों से, और

के भाग III में गारंटीकृत किसी भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन

संविधान, या किसी अन्य संवैधानिक प्रावधान का। द.

उपरोक्त निर्धारण द्वारा दिए गए विवाद का समर्थन करता है

विद्वान महान्यायवादी, जो उपरोक्त निष्कर्ष से संकेत देना चाहते हैं, कि एक सामान्य कानून पर हमला नहीं किया जा सकता है

इसका आधार "मूल संरचना" का उल्लंघन है

पैराग्राफ 44 में दर्ज निष्कर्ष के रूप में यह देखा गया था

इसके अंतर्गत:

"44. ऊपर बताए गए कारणों से, हम पाते हैं कि राज्य

विधानमंडल विवादित को अधिनियमित करने के लिए सक्षम था

प्रावधान। इसके अलावा, कि अधिनियमित प्रावधान नहीं हैं

मनमाना और इसलिए अनुच्छेद 14,16 या किसी का उल्लंघन नहीं करता है

संविधान के अन्य प्रावधान। वे इसके खिलाफ नहीं हैं।

भारत के संविधान की मूल संरचना भी।

तदनुसार, हम इन अपीलों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और उन्हें लागत के रूप में बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है।

यह बताया गया था, कि यह स्पष्ट था, कि तब भी जब

एक साधारण विधान की वैधता का निर्धारण, अर्थात्,

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (न्यायाधिकरण) अधिनियम, 1976, इस न्यायालय में

वनाच्छादित निर्णय ने जाँच की थी कि क्या प्रावधान

हमला किए गए विधान, संविधान के "मूल ढांचे" के खिलाफ थे, और ऐसा करने के बाद, इसने तर्क को खारिज कर दिया था। इसका तात्पर्य यह है कि यह पीड़ितों के लिए खुला था हमला करने वाला पक्ष, यहाँ तक कि एक सामान्य कानून के प्रावधान,

"बुनियादी संरचना" की अवधारणा पर आधारित। इसके अलावा

ऊपर, कुलदिप नायर मामले 89 (भी) पर निर्भरता रखी गई थी।

91 (2003) 4 एस. सी. सी. 104 सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

विद्वान महान्यायवादी द्वारा भरोसा किया गया), और जबकि

उपरोक्त निर्णय में दर्ज स्थिति को स्वीकार करते हुए,

कि एक साधारण विधान को चुनौती नहीं दी जा सकती थी

संविधान की "मूल संरचना" के उल्लंघन का आधार,

न्यायालय ने पैराग्राफ 108 में इस प्रकार टिप्पणी की थी:

" 108. जैसा कि ऊपर बताया गया है। निवास "संवैधानिक नहीं है

आवश्यकता और, इसलिए, बुनियादी के उल्लंघन का सवाल
संरचना उत्पन्न नहीं होती है।

यह प्रस्तुत किया गया था कि तत्काल निर्णय में भी, यह

न्यायालय ने स्वतंत्र रूप से जांच की थी कि क्या विधायी
अधिनियम 40, वास्तव में कानून का उल्लंघन करता है।

2003 का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन)

"संविधान की मूल संरचना। और इस तरह से निर्धारित करते हुए,

निष्कर्ष निकाला कि निवास का प्रश्न एक नहीं था

संवैधानिक आवश्यकता, और इसलिए,

"मूल संरचना" का उल्लंघन नहीं हुआ। सीखा हुआ परामर्श

फिर एम. नागराज मामले 36 पर भरोसा रखा गया, जिसमें यह था

निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला गया:

" 124. उपरोक्त के अधीन, हम संवैधानिक का समर्थन करते हैं

संविधान की वैधता (सत्तर-सातवां संशोधन)

अधिनियम, 1995; संविधान (अस्सी पहला संशोधन) अधिनियम,

2000; संविधान (अस्सी-दूसरा संशोधन) अधिनियम,
2000 और संविधान (85 वां संशोधन) अधिनियम,

2001.

125. हमने व्यक्ति की वैधता की जांच नहीं की है।

उपयुक्त राज्यों के अधिनियम और वह प्रश्न होगा -

उपयुक्त पीठ द्वारा व्यक्तिगत रिट याचिका पर विचार किया गया
वर्तमान मामले में हमारे द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार।

217. यह डॉ. राजीव धवन द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

वरिष्ठ अधिवक्ता, कि एम. नागराज मामले में यह न्यायालय 36, जबकि
संवैधानिक वैधता को बनाए रखना

अभियुक्तों की

संवैधानिक संशोधन, लागू करके उसी का परीक्षण करके

"चौड़ाई परीक्षण", ने उपरोक्त अवधारणा को राज्य तक विस्तारित किया
यह अनुमान लगाने की कोशिश की गई कि राज्य [2015] 13 एस. सी. आर.

कानून। तदनुसार

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कानूनों पर हमला किया जा सकता है, न कि केवल पत्र के आधार पर

और संवैधानिक प्रावधानों का पाठ, लेकिन इसके आधार पर भी

"चौड़ाई परीक्षण", जो "मूल संरचना" के आधार पर एक विधायी अधिनियम के लिए उठाई गई चुनौती के
समान था

संविधान।

218. रिलायंस को तब उत्तर प्रदेश पावर पर रखा गया था

निगम लिमिटेड बनाम। राजेश कुमार 92, जिसमें मुद्दा

संदर्भ के तहत उठाया गया था, जैसा कि स्पष्ट है

पैराग्राफ 61 में चर्चा, जो नीचे निकाली गई है:

"61. डॉ. राजीव धवन, विद्वान वरिष्ठ वकील, सहायक

डिवीजन बेंच का निर्णय जिसने घोषित किया है

अलट्रा वायर्स के रूप में नियम ने प्रस्तुत किया है कि यदि एम. नागराज हैं

संविधान पीठ द्वारा मूल के रूप में निर्धारित मापदंड
उद्देश्य संतुलन की स्थिति में लाना है लेकिन उक्त संतुलन

1994 के अधिनियम की धारा 3 (7) और नियम 8-ए द्वारा नष्ट किया गया है।

पहचान, अधिकार का सार, समानता संहिता और परिहार
विपरीत भेदभाव, के बीच सूक्ष्म अंतर

पर्याप्तता और आनुपातिकता, पिछड़े वर्ग और

पिछड़ेपन, प्रतियोगिता विशिष्टता की अवधारणा

समान न्याय और दक्षता, प्रावधानों की अनुमेय प्रकृति और निर्देशित शक्ति के वैचारिक सार के संबंध
में, ठोस शब्दों में कार्यान्वयन जो नहीं होगा

संवैधानिक जनादेश के लिए हिंसा का कारण बनता है; और प्रभाव
त्वरित वरिष्ठता और प्रचलित शर्तों के लिए

बसे हुए लोगों को आमंत्रित करने के लिए पूर्ववर्ती शर्तों की संतुष्टि

सिद्धांत "।

92 (2012) 7 एस. सी. सी. 1 सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

इस मामले का निर्णय निम्नानुसार किया गया था:

"86. हमारा दृढ़ विचार है कि एक नया अभ्यास

एम. नागराज में संविधान पीठ के फैसले का प्रकाश एक स्पष्ट अनिवार्यता है। यह स्थिति कि
संवैधानिक

संशोधनों ने पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा प्रदान की है

परिणामी वरिष्ठता के साथ और की मुहर दी है

अधिनियम और नियमों को मंजूरी देना बंद नहीं हो सकता है
संविधान पीठ ने स्पष्ट रूप से जांच की है

प्रावधान और राज्य इसके लिए प्रावधान कर सकता है।
निश्चित आधार या आधार पर। पूर्ववर्ती स्थितियाँ

संतुष्ट नहीं हुए। कोई अभ्यास नहीं किया गया है।

जिस बात का जोरदार तर्क दिया गया है वह यह है कि ऐसा नहीं है

पदोन्नति में आरक्षण की अवधारणा आवश्यक थी

पहले से ही प्रचलन में है। हम उक्त बात को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। प्रस्तुत करना, जब संविधान के प्रावधान हैं

कुछ शर्तों या सवारों के साथ वैध माना जाता है, यह बन जाता है

राज्य की ओर से सराहना करने और आवेदन करने का दायित्व

परीक्षण ताकि इसके संशोधनों का परीक्षण किया जा सके और सामना किया जा सके

उसमें निर्धारित मापदंडों की जांच "।

उपरोक्त निर्णय के अलावा, निर्भरता भी थी

बिहार राज्य बनाम। बाल मुकुंद साह 93, जिसमें ए

इस न्यायालय की संविधान पीठ, की शक्ति की जांच करते हुए

राज्य विधानमंडल, भर्ती के विषय पर कानून बनाने के लिए

जिला न्यायाधीशों और अन्य न्यायिक अधिकारियों की निर्भरता

केशवानंद में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भारतीय मामला 10, जिसमें से पाँच को ध्यान में रखा गया

संविधान की "बुनियादी विशेषताओं" की घोषणा की, और जांच की

विचाराधीन विषय वस्तु, की अवधारणा को लागू करके

"विधायिका, कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण

और न्यायपालिका, जिसे एक आवश्यक विशेषता के रूप में स्वीकार किया गया था संविधान की "मूल संरचना"। अंत में, निर्भरता

नवल किशोर मिश्रा बनाम पर रखा गया था। का उच्च न्यायालय

93 (2000) 4 एस. सी. सी. 640 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

इलाहाबाद का न्याय 4, जिस पर निर्भरता रखी गई थी

निष्कर्ष सं। 20.11, जिसे नीचे निकाला गया है:

" 20.11 विधायिका द्वारा ऐसा कोई भी प्रयास होगा

संवैधानिक योजना द्वारा निषिद्ध जैसा कि पाया गया था

के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित अवधारणा पर

विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ साथ
 एक स्वतंत्र न्यायपालिका की मौलिक अवधारणा
 दोनों अवधारणाओं को बुनियादी स्तर तक बढ़ा दिया गया है
 संविधान की संरचना और इसका दिल है
 संवैधानिक योजना "।

इसलिए यह विद्वान वरिष्ठ का तर्क था
 वकील, कि उत्तरदाताओं के लिए यह उठाना उचित नहीं था
 यह तर्क कि एन. जे. ए. सी. के प्रावधानों की वैधता
 अधिनियम की अवधारणा की कसौटी पर परीक्षण नहीं किया जा सका
 "संविधान की मूल संरचना।

219. इस बात पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है कि इस मुद्दे के तहत
 संदर्भ इस तथ्य के कारण उत्पन्न हुआ, कि विद्वान सलाह
 क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने इस फैसले पर भरोसा किया था
 अदालत, मद्रास बार एसोसिएशन मामले 3 5 में, जिसमें यह न्यायालय ने राष्ट्रीय कर
 न्यायाधिकरण के प्रावधानों की जांच की थी
 अधिनियम, 2005, और ऐसा करते समय, के प्रावधानों को अभिनिर्धारित किया था
 विधायी अधिनियम से ऊपर के प्रावधानों के रूप में अधिकार से परे हैं
 संविधान, उनके "मूल" का उल्लंघन करने के कारण
 संविधान की संरचना। इसलिए यह स्पष्ट है कि
 तुरंत विवाद उठाया गया था, विद्वानों को रोकने के लिए
 याचिकाकर्ताओं के लिए वकील, पर निर्भरता रखने से
 मद्रास बार एसोसिएशन मामले 3 5 में दर्ज निष्कर्ष।

220. हमने अपना विचारशील विचार दिया है
 विवादों के ऊपर। संविधान की "मूल संरचना",
 वर्तमान में अन्य बातों के साथ-साथ संविधान की सर्वोच्चता भी शामिल है,
 सरकार का गणराज्य और लोकतांत्रिक रूप, "संघीय
 "शक्तियों के वितरण, धर्मनिरपेक्षता", अलगाव का चरित्र

विधायिका, कार्यपालिका और के बीच शक्तियों का

94 (2015) 5 एस. सी. सी. 479 सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

न्यायपालिका, और "न्यायपालिका की स्वतंत्रता"। यह न्यायालय, जबकि

उपरोक्त "बुनियादी विशेषताओं" में से प्रत्येक को तराशते हुए, निर्भरता रखी गई

संविधान के एक या अधिक अनुच्छेदों पर (कभी-कभी, संविधान की प्रस्तावना के साथ संयोजन)। यह चला जाता है

बिना यह कहे कि प्रत्येक "मूल" या "मूल" को तराशने के लिए

संविधान की विशेषताएँ/बुनियादी संरचना, केवल प्रावधान

संविधान पर निर्भर है। इसलिए यह स्पष्ट है,

कि "बुनियादी विशेषताओं" या "बुनियादी विशेषताओं" का निर्धारण

संरचना ", विशेष रूप से के प्रावधानों से बनाई गई है

संविधान। सचित्र रूप से, हम "की स्वतंत्रता" का विज्ञापन कर सकते हैं।

न्यायपालिका "जिसका चयन वर्तमान प्रक्रिया के दौरान चर्चा और बहस के कारण किया गया है।

विचार करें। "स्वतंत्रता" की अवधारणा की कटौती न्यायपालिका का "लेखों के सामूहिक अध्ययन से उभरा

12, 36 और 50। कभी-कभी यह अनुमान लगाना संभव नहीं होता कि के एक सादे पढ़ने से संबंधित "बुनियादी संरचना"

संविधान के प्रावधान। और कभी-कभी, उनके भीतर छिपी सभी महत्वपूर्ण मौनताओं से इस तरह की कटौती की जाती है।

मामले और दूसरे न्यायाधीशों का मामला, जिसमें यह न्यायालय अनुच्छेद 124, 217 और 222 के साथ अनुच्छेद 74 की व्याख्या

संविधान निर्माताओं के इरादे के साथ संयोजन

संविधान सभा की बहसों से एकत्र हुए, और

राजनीतिक-कार्यकारी प्राधिकरण द्वारा पालन किए जाने वाले सम्मेलन

उच्चतर न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण का मामला

न्यायपालिका, इस निष्कर्ष पर पहुंची कि "न्यायपालिका की प्रधानता"

न्यायपालिका की स्वतंत्रता का एक घटक था जो

यह संविधान की एक "बुनियादी विशेषता" थी। अतः जब ए

याचिका के आधार पर एक चुनौती पेश की जाती है

के संदर्भ में "मूल संरचना" का उल्लंघन

"न्यायपालिका की स्वतंत्रता", इसकी सही समझ है, और यह होना चाहिए कि एक ओर अनुच्छेद 12,36 और 50 और दूसरी ओर अनुच्छेद 124,217 और 222, (सामूहिक रूप से पढ़ें)

और सामंजस्यपूर्ण रूप से) इसका आधार है।

स्पष्ट रूप से, सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

ये अपने आप में न्यायपालिका द्वारा बनाए गए काल्पनिक सिद्धांत नहीं हैं। इसलिए, यदि निष्कर्ष निकाला जाता है, कि "न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन किया गया है, यह है

समझा जाए, कि नियम/सिद्धांत सामूहिक रूप से उभर रहा है

उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन किया गया था, या कि उपरोक्त

एक साथ पढ़े गए लेखों का उल्लंघन किया गया था।

221. जहाँ तक संवैधानिक जांच का मुद्दा है

एक साधारण विधायी अधिनियम की वैधता का संबंध है, सभी पर

संवैधानिक प्रावधान, जिसके आधार

संबंधित "बुनियादी विशेषताएँ" उत्पन्न होती हैं, उपलब्ध हैं। संविधान के एकल प्रावधान का उल्लंघन, प्रदान करने के लिए पर्याप्त होगा

कानून, संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इस दृष्टि से

इस मामले में, संवैधानिक वैधता के आधार पर एक चुनौती को स्वीकार करना, विशेष अनुच्छेद (ओं) को संदर्भित करना उचित होगा, एकल या सामूहिक रूप से, जो विधायी अधिनियम

उल्लंघन करता है। और ऐसे मामलों में जहाँ एक संख्या का संचयी प्रभाव

संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन किया गया है, सभी संबंधित अनुच्छेदों का संदर्भ दिया जाना चाहिए,

यदि आवश्यक हो तो प्रस्तावना भी शामिल करें। मुद्दा विशुद्ध है तकनीकी, फिर भी, अगर एक आम विधायिका के लिए एक चुनौती उठाई जाती है "मूल संरचना" के सिद्धांत पर आधारित अधिनियम, वही कानूनी दुर्बलता से पीड़ित होने का इलाज नहीं किया जा सकता है। ऐसा होगा। यह केवल एक तकनीकी त्रुटि है। इस तरह, यह समझाना संभव होगा इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों में की गई टिप्पणियाँ के आधार पर एक विधायी अधिनियम के लिए एक चुनौती उठाई जाती है संविधान के कई अनुच्छेदों का संचयी प्रभाव, संबंधित में से प्रत्येक को संदर्भित करना हमेशा आवश्यक नहीं होता है लेख, जब उक्त लेखों का संचयी प्रभाव होता है पहले से ही निर्धारित किया गया है, "बुनियादी" में से एक के रूप में संविधान की विशेषताएँ। "बुनियादी संरचना" का संदर्भ, एक साधारण कानून के साथ काम करते समय, सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं-ऑन-रिकॉर्ड को हटा दिया जाएगा।

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

संदर्भ के तहत अनुच्छेद (ओं) की व्याख्या करते हुए लिखा गया था, सामंजस्यपूर्ण रूप से। इसलिए हम दोहराते हैं कि "बुनियादी

संविधान की संरचना अलंघनीय है, और इस प्रकार, संविधान को इस तरह से संशोधित नहीं किया जा सकता है कि किसी भी "बुनियादी" को नकार दिया जाए।

इसकी विशेषताएँ, और इसी तरह, यदि इसकी "बुनियादी विशेषताओं" में से किसी एक के आधार पर एक सामान्य कानून को चुनौती दी जाती है।

संविधान, ऐसा करना वैध होगा। अगर ऐसी चुनौती है

स्वीकार किया गया, "मूल संरचना" के उल्लंघन के आधार पर, यह

इसका मतलब यह होगा कि संविधान के अनुच्छेदों का समूह

(इसकी प्रस्तावना सहित, जहाँ भी प्रासंगिक हो), जो

विशेष "मूल विशेषता" का गठन करता है, जिसका उल्लंघन किया गया था। हम.

हालाँकि विद्वान वकील के तर्क को श्रेय देना चाहिए

सामान्य रूप से स्वीकार करते हुए, कि यह तकनीकी रूप से संदर्भित करने के लिए ध्वनि होगा
जिन अनुच्छेदों का उल्लंघन किया जाता है, जब एक सामान्य विधान
प्रावधानों के अधिकार से बाहर होने के कारण इसे निरस्त करने की मांग की जाती है संविधान से।
लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि एक साधारण विधायी अधिनियम को निरस्त कर दिया जाए।
"मूल संरचना" का उल्लंघन करना गलत होगा। इसलिए हम
विद्वान वकील द्वारा दिए गए विवाद में कोई योग्यता नहीं पाएँ
सामान्य, लेकिन ऊपर उल्लिखित तकनीकी पहलू के लिए।
तेरहवीं।

222. विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा

एनजेएसी अधिनियम के प्रावधान। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, एक चुनौती
चयन और नियुक्ति के तरीके के अनुसार उठाया गया था
भारत के मुख्य न्यायाधीश। एन. जे. ए. सी. अधिनियम की धारा 5 (1), यह थी
प्रस्तुत, प्रदान करता है कि एन. जे. ए. सी. की सिफारिश करेगा
भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, इस शर्त के अधीन, कि वह पद धारण करने के लिए
"उपयुक्त" माना जाता है। यह तर्क दिया गया था कि
संसद को कानून द्वारा विनियमित करने के लिए अधिकृत किया गया था
भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया,
अनुच्छेद 124 सी के तहत। यह प्रस्तुत किया गया था कि एनजेएसी को
सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के संदर्भ में विनियम बनाने की अनुमति दी गई है

[2015] 13 एस सी आर।

न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति का तरीका
भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायपालिका।

223. यह प्रस्तुत किया गया था कि शब्द "फिट", में व्यक्त किया गया था
एन. जे. ए. सी. अधिनियम की धारा 5 (1) को विस्तृत रूप से नहीं बताया गया था।

वर्णित है। और इस तरह, फिटनेस पर निर्धारित किया जाएगा
 एन. जे. ए. सी. के सदस्यों की व्यक्तिपरक संतुष्टि। यह था।
 स्वीकार किया, कि भले ही विद्वान अटॉर्नी जनरल
 सुनवाई के दौरान व्यक्त किया था कि केवल योग्यता
 मतलब "मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य", एक उत्तराधिकारी वकील
 जनरल इस मामले को अलग तरह से देख सकते हैं, जैसे कि पदधारी
 महान्यायवादी ने दर्ज की गई रियायत से असहमति जताई है
 अपने पूर्ववर्ती की ओर से (तीसरे न्यायाधीशों के मामले में), यहां तक कि
 हालाँकि वे दोनों एक ही सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं। और,
 संसद के लिए उद्देश्यपूर्ण रूप से परिभाषित करने के लिए हमेशा खुला था
 "उपयुक्त" शब्द, इस तरह से जो इच्छा की सेवा कर सकता है
 प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता के बिना जारी किया गया कानून बनाना, राजनीतिक
 पसंद के व्यक्ति को लाना
 गैर-न्यायिक की मीठी इच्छा के अनुसार परिभाषित या पुनर्परिभाषित किया जाए
 अधिकारीगण।

224. यह इंगित किया गया था कि एक संवैधानिक था

कन्वेंशन, जिसके तहत सुप्रीम के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायालय को हमेशा भारत के मुख्य
 न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है।

और यह कि, उपरोक्त परिपाटी अटूट रही थी,
 भले ही कुछ मामलों में नियुक्त व्यक्ति का कार्यकाल बेहद छोटा था, और हो सकता है कि उसने
 एक संस्था के रूप में न्यायपालिका का लाभ अनुभव था
 दिखाया, विद्वान वकील के अनुसार, कि पालन करने के लिए
 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को प्रमुख के रूप में नियुक्त करने की प्रथा
 भारत के न्याय के परिणामस्वरूप संस्थागत सद्भाव और
 न्यायाधीशों के बीच सामूहिकता, जो अत्यंत महत्वपूर्ण थी
 न्यायपालिका के स्वास्थ्य के लिए, और स्वतंत्रता के लिए भी

न्यायपालिका से। यह प्रस्तुत किया गया था कि यह न्यायसंगत और सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-
 रिकॉर्ड होंगे।

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]
 उपयुक्त, वर्तमान मोड़ पर, की चौड़ाई को समझने के लिए
 शक्ति, ताकि भविष्य में इसके दुरुपयोग की किसी भी संभावना को रोका जा सके।

225. यह सुझाव दिया गया था कि विभिन्न तरीके और साधन
 वरिष्ठ न्यायाधीशों को हटाने के लिए तैयार किया जा सकता है
 पसंदीदा। पिछले अनुभव से पता चला था कि कार्यपालिका ने
 अपने अधिकार का दुरुपयोग किया, जब यह उपरोक्त वरिष्ठता से अलग हो गया
 अप्रैल 1973 में शासन, जे. एम. शेल्ट को हटाकर, सबसे वरिष्ठ
 न्यायाधीश, और यहाँ तक कि वरिष्ठता के क्रम में अगले दो न्यायाधीश भी
 उनके बाद, के. एस. हेगडे और ए. एन. ग्रोवर, नियुक्ति करते हुए
 चौथे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश ए. एन. रे, के मुख्य न्यायाधीश के रूप में
 भारत। फिर से जनवरी 1977 में ए. एन. रे की सेवानिवृत्ति पर, सीजे।, सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश एच.
 आर. खन्ना की उपेक्षा की गई और
 अगले सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश एम. एच. बेग को नियुक्त किया गया था
 भारत के मुख्य न्यायाधीश। हाथों में इस तरह का नियंत्रण
 विद्वान वकील के अनुसार, कार्यपालिका बहुत बड़ा कारण बनेगी
 निर्णय लेने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप। और इसका परिणाम हो सकता है, न्यायाधीश व्यक्तिगत लाभ
 और पुरस्कार के उद्देश्य से राजनीतिक-कार्यकारी वर्ग को शांत करने और खुश करने की कोशिश करते हैं।

226. ऊपर उल्लिखित प्रस्तुतिकरण की मांग की गई थी
 निम्नलिखित उदाहरण के माध्यम से चित्रित। यह तर्क दिया गया था,
 कि यह संसद के लिए वास्तविक और वैध होगा
 कानून द्वारा अधिनियम, कि एक व्यक्ति के लिए "उपयुक्त" माना जाएगा
 भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति, केवल तभी जब उनके पास न्यूनतम
 दो साल के कार्यकाल के लिए छोड़ दिया गया। इस तरह के एक अधिनियम में एक होगा
 विनाशकारी प्रभाव, भले ही यह निर्दोष रूप से वैध प्रतीत हो। यह बताया गया कि 41 में से

[2015] 13 एस सी आर।

"न्यायपालिका की स्वतंत्रता "

न्यायाधीशों पर अधिस्थगन के प्रभाव का वर्णन किया, जो सद्गुण से

मौजूदा परंपरा के अनुसार, वे मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में थे
भारत के, लेकिन एक जूनियर को प्राथमिकता देकर उनकी अनदेखी की गई। पद की स्थिति
इसे इस प्रकार व्यक्त किया गया था:

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर जो कतार में थे
मुख्य न्यायाधीश का उत्तराधिकार। एक-दूसरे को देख रहे थे
संदेह के साथ और उसकी घोषणा करने में उसे पछाड़ने की कोशिश की
सरकार के प्रति वफादारी या तो उनके निर्णयों में या यहाँ तक कि
सार्वजनिक मंचों पर। यदि कोई न्यायाधीश अपनी पदोन्नति के लिए ऋणी है
सरकार के पक्ष में और न कि अपने आंतरिक गुण के लिए,
तब न्यायपालिका की स्वतंत्रता अनिवार्य रूप से खो जाती है।

एच. आर. खन्ना, जे. (अपनी पुस्तक 'नदर रोज़ेज़ नॉर' में)

कांटे) ने स्थिति को निम्नानुसार व्यक्त किया:

"फैसला सुनाने से कुछ दिन पहले
तनाव का माहौल और बढ़ गया क्योंकि हर तरह का
अफवाहें फैलने लगीं और सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं का नाम-ऑन-रिकॉर्ड रखा गया

समाज v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

मुख्य न्यायाधीश के उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की जा रही थी।
घोषणा की गई

फैसले के बाद रेडियो पर यह

का उच्चारण किया गया था और इसके परिणामस्वरूप

तीन वरिष्ठ न्यायाधीश।

मैं बहुत परेशान महसूस कर रहा था क्योंकि मेरी राय में यह था
पैदा करने के लिए बाध्य और

भय जटिल या इनाम की उम्मीद

इस प्रकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करता है।

न्यायमूर्ति हेगड़े। मैंने उसे किसी और की तरह थोड़ा तनावपूर्ण पाया।
लेकिन वह अन्यथा शांत थे। वह.

उस स्थिति में ऐसा होता,

गोवर जिन्हें हटा दिया गया था, वे अपनी पेशकश कर रहे थे

त्यागपत्र।

शेलट, हेगड़े और गोवर के इस्तीफे के बाद अदालत ने

एक नया रंग प्राप्त किया और मुझे बोधगम्य परिवर्तन मिला
वातावरण में। बहुत सी चीजें हुईं जिनसे
एक दुखी और मैंने सोचा कि सबसे अच्छा तरीका प्राप्त करना था
न्यायिक कार्य के निपटान में व्यस्त। न्यायपालिका
काम हमेशा मेरे लिए एक अपील था और मुझे यह विशेष लगा
इस पर ध्यान दिया जाता है कि यह फायदेमंद होने के साथ-साथ अवशोषित करने वाला भी हो।
नए रुझानों में से एक दृष्टिकोण में बदलाव था
सामाजिक न्याय जैसे शब्द अदालत ने आदेश पारित किए, प्रभाव जिनमें से तय किए गए सिद्धांतों
को अस्थिर करना और कमजोर करना था या
पहले के मामलों में निर्धारित आदेश को पूर्ववत करें।
इस संबंध में, संदर्भ भी दिया गया था
एच. एम. सीरवई (भारत के संवैधानिक कानून में -आइकल कमेंटरी), जो इस प्रकार हैं:
"संकलचंद सेठ के मामले में, जे. भगवती यह समझाते हुए कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को
क्यों होना पड़ा
इससे पहले कि किसी न्यायाधीश को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सके, उनसे परामर्श किया गया
एक अन्य राज्य की अदालत ने कहा: मुझे लगता है कि यह मिस्टर जस्टिस थे।
जैक्सन जिन्होंने कहा था कि 'न्यायाधीशों को अक्सर सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट द्वारा रिश्तत दी जाती है

[2015] 13 एस सी आर।

धन के बजाय उनकी महत्वाकांक्षा और वफादारी '। मुझमें
उपरोक्त परिच्छेद को उद्धृत करते हुए प्रस्तुत करना जे. भगवती।
यह महसूस करने में विफल रहा कि उसकी एकमात्र वफादारी अपने लिए थी।
जैसा कि बाद में दिखाई देगा, वह अन्य बातों के साथ-साथ अपने प्रति वफादार नहीं था।
मुखिया। चंद्रचूड़ सी. जे. अपना काम पूरा करने के लिए
जल्द से जल्द भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने की महत्वाकांक्षा
संभव है। कि जे. भगवती को उस महत्वाकांक्षा से रिश्तत दी गई थी

जब मैं न्यायाधीशों में उसके व्यवहार से निपटूंगा तो यह स्पष्ट हो जाएगा ' मामले में मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ का पक्ष न्यायमूर्ति कुमार और सिंह सी. जे. का लेख पाठकों के लिए दिलचस्प होगा। यह जानने के लिए कि "महत्वाकांक्षा" शब्द "महत्वाकांक्षा" से लिया गया है, वोट के लिए प्रचार करें "। , ... क्या जे. भगवती ने प्रचार किया था उसके एक या अधिक भाइयों के मतों से पता चलता है कि वे मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के हलफनामे पर विश्वास नहीं करना चाहिए सिंह सी. जे. के हलफनामे के जवाब में ज्ञात नहीं है; लेकिन क्या वह अपने एक या अधिक लोगों को मनाने में सफल रहा था भाई उस हलफनामे पर अविश्वास करने का फैसला करते हैं। चंद्रचूड़ सी. जे. ने इस्तीफा दे दिया होता और न्यायमूर्ति भगवती ने भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश बनने की महत्वाकांक्षा सभी संभावनाओं का एहसास हो गया है। हालांकि, उनकी कोशिश चंद्रचूड़ के चरित्र और आचरण को काला करने के लिए मुख्य न्यायाधीश के शपथ पत्र को स्वीकार किया और उस पर कार्रवाई की और अभिनिर्धारित किया कि सिंह सी. जे. का मद्रास में स्थानांतरण था वैध "।

229. यह प्रस्तुत किया गया था कि इस मुद्दे को छोड़ दिया गया संसद के साथ फिटनेस का निर्धारण, प्रशंसक के लिए उत्तरदायी था न्यायाधीशों की महत्वाकांक्षाएँ, और न्यायाधीशों को वफादार बनाने की संभावना थी, जो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। इसलिए यह इस बात पर जोर दिया कि धारा 5 (1), जिसने एक अस्पष्टता पैदा की, भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय में नियुक्ति का मामला, स्वतंत्रता को खतरे में डालने के लिए दुरुपयोग किए जाने का जाल था न्यायपालिका की ", और इसलिए, रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं के आश्वासन की परवाह किए बिना कानून-पुस्तक पर-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

महान्यायवादी, कि हाथ में उद्देश्य के लिए, शब्द "फिट"

इसका अर्थ है "... मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य"।

230. यह भी तर्क दिया गया था कि सिफारिश करते समय

उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए नाम, न्यायाधीशों के संवर्ग में संबंधित न्यायाधीशों की वरिष्ठता (उच्च न्यायालय के न्यायाधीश)

न्यायालय), प्राथमिक विचार के रूप में लिए जाने के लिए उत्तरदायी था,

अपनी क्षमता और योग्यता के साथ। यह प्रस्तुत किया गया था कि

धारा के तहत पहले परंतुक में निहित तत्काल अधिदेश 5 (2) एन. जे. ए. सी. अधिनियम ने स्पष्ट रूप से सर्वोच्च न्यायालय में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की परंपरा का उल्लंघन किया। तब से

"शक्तियों के वितरण का संघीय चरित्र भी इनमें से एक था

मान्यता प्राप्त "बुनियादी संरचना", यह प्रस्तुत किया गया था कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की अनदेखी नहीं की जा सकती थी।

231. उपरोक्त के अलावा, न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया गया था

धारा 5 (2) के तहत दूसरे परंतुक के लिए, जो निषेध करता है

एन. जे. ए. सी. एक अनुकूल सिफारिश करने से, यदि कोई दो इसके सदस्यों ने एक उम्मीदवार के नामांकन का विरोध किया। यह.

यह तर्क दिया गया था कि वीटो की शक्ति को एन. जे. ए. सी. के दो सदस्यों के हाथों में देने से सिफारिश का उल्लंघन होगा।

अनुच्छेद 124 बी में व्यक्त शक्ति। इस संबंध में यह

यह तर्क दिया गया कि उपरोक्त स्थिति दो "प्रतिष्ठित व्यक्तियों"-आम व्यक्तियों को हकदार बनाएगी (यदि प्रस्तुतिकरण द्वारा आगे बढ़ाया जाता है)

विद्वान महान्यायवादी को स्वीकार किया जाना है), एक को हराने के लिए न्यायाधीश की सर्वसम्मत सिफारिश और

भारत के मुख्य

सर्वोच्च न्यायालय के दो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश। और करेंगे भी।

साथ ही, मामले में न्यायपालिका में निहित प्रधानता को नकारें।

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति।

232. यह प्रस्तुत किया गया था कि दो सामान्य व्यक्तियों, या वैकल्पिक रूप से एक सामान्य व्यक्ति द्वारा प्रयोग की जाने वाली वीडियो की उपरोक्त शक्ति,

केंद्रीय कानून मंत्री के साथ मिलकर और न्याय, स्वतंत्रता में गंभीर पैठ का कारण बनेगा

न्यायपालिका का "। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह तर्क दिया गया था कि न तो

विवादित संवैधानिक संशोधन, और न ही [2015] 13 एस. सी. आर. के प्रावधान।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एन. जे. ए. सी. अधिनियम, बैठक आयोजित करने के लिए किसी भी कोरम के लिए प्रदान किया गया

एन. जे. ए. सी. की बैठक बिना उपस्थिति के नहीं हो सकती थी एन. जे. ए. सी. के सभी सदस्य। उसके ऊपर का समर्थन करने के लिए

विवाद, उन्होंने स्पष्ट रूप से संविधान पर निर्भरता रखी (122 दूसरा संशोधन) विधेयक, 2014 (संसद के समक्ष लाया गया,

उसी सत्तारूढ़ राजनीतिक दल द्वारा, जिसने संशोधन किया था

संविधान को प्रस्तुत करके (121 वां संशोधन)

बिल, 2014। उपरोक्त उद्देश्य को प्राप्त करने की मांग की गई

विधेयक एक नया अनुच्छेद 279 ए सम्मिलित करने के लिए था। नया अनुच्छेद 279 ए वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन किया। उप-अनुच्छेद (7)

वस्तु एवं सेवा कर परिषद के सदस्य। इसकी बैठकों के लिए गणपूर्ति का गठन करता है। और इसके अलावा, कि

" वस्तु एवं सेवा कर परिषद का प्रत्येक निर्णय

एक बैठक में लिया जाएगा, कम से कम बहुमत से नहीं उपस्थित सदस्यों के भारित मतों का तीन-चौथाई

और मतदान करें। " उपरोक्त मापदंडों को निर्धारित करने के बाद,

विधेयक जो विधेयक के बाद आया, जिसके कारण इसकी घोषणा की गई

विवादित संविधान (99 वां संशोधन) अधिनियम, प्रस्तुत किया गया था,

कि एन. जे. ए. सी. के कार्यकरण के लिए कोरम को छोड़ना,

और वैध के लिए आवश्यक शक्ति की मात्रा निर्धारित करने में चूक

निर्णय लेने से प्रावधान ही दूषित हो गया।

233. विद्वानों के हाथों आगे बढ़ा विवाद

याचिकाकर्ताओं के लिए वकील, जैसा कि पूर्वगामी में देखा गया है

पैराग्राफ, किसी भी विस्तृत परीक्षा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि

मौजूदा घोषित कानूनी स्थिति स्पष्ट और असंदिग्ध है। में।

इस निमित्त यह अभिलिखित किया जा सकता है कि यदि कोई वैधानिक

प्रावधान न्यूनतम कोरम निर्धारित किए बिना व्यक्तियों के एक निकाय में निर्णय लेने का अधिकार निहित करता है, फिर एक वैध बैठक

केवल तभी आयोजित किया जा सकता है जब शरीर के सभी सदस्यों का बहुमत, निर्णय लेने की प्रक्रिया में जानबूझकर। उसी पर

इसलिए सादृश्य, इस तरह के निकाय द्वारा एक वैध निर्णय अदालत के अधिवक्ताओं को प्राथमिकता देगा-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

सभी सदस्यों के साधारण बहुमत से निर्णय की आवश्यकता है

शरीर से। यदि उपरोक्त सिद्धांतों को लागू किया जाता है

एन. जे. ए. सी. का स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि एन. जे. ए. सी. की एक वैध बैठक में कम से कम चार सदस्य भाग ले रहे होंगे।

छह सदस्यीय एन. जे. ए. सी. इसी तरह, एन. जे. ए. सी. का एक वैध निर्णय केवल लिया जा सकता है (किसी भी निर्धारित की अनुपस्थिति में)

पूर्व शर्त), एक साधारण बहुमत से, अर्थात्, कम से कम चार से एन. जे. ए. सी. के सदस्य (दोनों तरफ तीन सदस्य)

साधारण बहुमत नहीं बनाते हैं)। हम संतुष्ट हैं कि

एन. जे. ए. सी. अधिनियम के प्रावधान जो आदेश देते हैं कि एन. जे. ए. सी. किसी व्यक्ति के पक्ष में सिफारिश नहीं करेगा

उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति

न्यायालय, यदि उसके दो सदस्य इस बात से सहमत नहीं थे

सिफारिश, का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है
 ऊपर व्यक्त नियम/सिद्धांत। वास्तव में,
 एन. जे. ए. सी. अधिनियम में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि यदि कोई दो सदस्य हैं
 किसी विशेष प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुआ, एन. जे. ए. सी. नहीं होगा
 एक सिफारिश करें। कानून में विचार करने के लिए कुछ भी नहीं है।
 या दूसरे परंतुक में उपरोक्त शर्तों का इलाज करें
 एनजेएसी अधिनियम की धारा 5 (2) और धारा 6 (6), के रूप में
 अस्वीकार्य है। तत्काल प्रस्तुतिकरण हाथों में आगे बढ़ा
 इसलिए याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील को अस्वीकार किया जा सकता है और तदनुसार खारिज कर दिया
 जाता है।

234. हमने अपना विचारशील विचार भी दिया है
 विद्वानों के हाथों आगे बढ़े अन्य विवाद
 याचिकाकर्ताओं के लिए वकील, धारा 5 के संदर्भ में
 एनजेएसी अधिनियम। हमारा विचार है कि यह क्षेत्र के भीतर नहीं था।
 न्यायाधीशों के चयन की प्रक्रिया के अधीन करने के लिए संसद
 उच्चतम न्यायालय के साथ-साथ मुख्य न्यायाधीश के पद पर
 भारत का, अनिश्चित और अस्पष्ट शब्दों में। संदर्भ के साथ "फिट" शब्द के स्पष्ट मापदंडों को व्यक्त करना
 अनिवार्य था।
 धारा के तहत उच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को
 5 एनजेएसी अधिनियम। हम संतुष्ट हैं कि "फिट" शब्द हो सकता है
 ताई ने वरिष्ठता सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर. में बहुत नीचे के उम्मीदवार का चयन
 किया।

सूची। यह विद्वानों द्वारा पर्याप्त रूप से प्रदर्शित किया गया है।
 याचिकाकर्ताओं के लिए वकील।

235. विद्वान वकील द्वारा अपनाया गया स्पष्ट रुख

सामान्य तौर पर, कि "उपयुक्त" शब्द की धारा 5 (1) में व्यक्त किया गया है एन. जे. ए. सी.
अधिनियम, सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था, जिसका अर्थ है

और केवल "मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य" को शामिल करना।

प्रमुख के कार्यालय की भारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना

भारत का न्याय, और कुछ नहीं। ऐसा कथन नहीं हो सकता है, और उत्तराधिकारी सरकारों या भावी पीढ़ी को बाध्य नहीं करता है।

हर आने वाले समय के लिए। वर्तमान ज्ञान भविष्य को बांध नहीं सकता है।

पीढ़ियाँ। और, ठीक इसी कारण से, कि उत्तरदाता उस समय दिए गए बयान से जवाब दे सकते हैं।

महान्यायवादी, तीसरे न्यायाधीशों की सुनवाई करने वाली पीठ के समक्ष

मामला, कि भारत संघ समीक्षा की मांग नहीं कर रहा था या

द्वितीय न्यायाधीशों के मामले में निर्णय पर पुनर्विचार (कि, यह बाध्यकारी के रूप में मानने के लिए स्वीकार किया था, में निर्णय

दूसरा न्यायाधीश मामला)। और फिर भी, सुनवाई के दौरान

वर्तमान मामले में, भारत संघ ने एक

द्वितीय न्यायाधीशों के मामले पर पुनर्विचार।

236. जहाँ तक एन. जे. ए. सी. की धारा 5 (1) को चुनौती का संबंध है

अधिनियम का संबंध है, हम पुष्टि करने और स्पष्ट करने के लिए संतुष्ट हैं महान्यायवादी द्वारा
अपनाई गई स्थिति, अर्थात्, कि पद

"धारा 5 (1) में प्रयुक्त "फिट" का अर्थ केवल "मानसिक" होगा।

और शारीरिक स्वास्थ्य "। यदि ऐसा किया जाता है, तो यह कानूनी होगा और

संवैधानिक। हालाँकि, यदि अपनाई गई स्थिति ने उल्लंघन किया है

"न्यायपालिका की स्वतंत्रता", द्वारा सुझाए गए तरीके से

याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील, वही होगा

कानून में उपलब्ध।

237. अब हम दूसरे को संबोधित करने का प्रयास करेंगे।

एन. जे. ए. सी. अधिनियम की धारा 5 (2) एक प्रशंसनीय उद्देश्य है। और अगर वरिष्ठता को
"क्षमता शीर्ष अदालत अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड संगठन v" के साथ पूरक और संलग्न किया जाना है।

यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

और योग्यता ", सबसे आदर्श दृष्टिकोण, देखा जा सकता है

अपनाया गया। लेकिन जो कागज पर दिखाई देता है, वह कभी-कभी नहीं भी हो सकता है।
व्यवहार में सही। अनुभव से पता चलता है कि हर किसी के लिए न्यायाधीश

उच्च न्यायालय को बैचों में नियुक्त किया जाता है, प्रत्येक बैच के पास हो सकता है

केवल दो या तीन नियुक्त, या कभी-कभी दस भी हो सकते हैं

एक उच्च न्यायालय, एक चल रहे क्रमिक आदेश में रखा जाएगा (में वरिष्ठता) किसी अन्य उच्च पद
पर नियुक्त अन्य न्यायाधीशों से ऊपर

अदालत, बस कुछ दिनों या हफ्तों या महीनों के बाद। न्यायाधीश बाद में नियुक्त, नीचे सामूहिक
रूप से रखा जाना होगा

पहले का बैच, वरिष्ठता में। यदि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर की
जानी है (

प्राथमिक विचार), तो पहले के बैच के पास होगा

सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति के मामले में प्राथमिकता। और

काल्पनिक रूप से, यदि बैच में दस न्यायाधीश थे (एक साथ नियुक्त)

स्वयं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में सक्षम और मेधावी, वे रक्तियों पर एक के बाद एक
नियुक्त करना होगा

उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों का उदय होता है। इस मामले को देखते हुए, उसी उच्च न्यायालय के
न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाएगा

सुप्रीम कोर्ट, जब तक पूरा बैच समाप्त नहीं हो जाता। न्यायाधीशों से

वही उच्च न्यायालय, उपरोक्त स्थिति में जहाँ बैच

दस न्यायाधीशों से मिलकर, कुल न्यायाधीश का एक तिहाई हिस्सा होगा

उच्चतम न्यायालय में पद। यह स्पष्ट होगा कि

विद्वान वकील द्वारा बताए गए कारणों के लिए अस्वीकार्य

याचिकाकर्ताओं के लिए। हम इस स्थिति को भी कानूनी रूप से अस्वीकार्य पाते हैं।

238. अतः एन. जे. ए. सी. अधिनियम की धारा 5 (2) के अनुसार

संबंधित है, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि

न्यायाधीश अपनी वरिष्ठता के आधार पर, समान व्यवहार करके

एक प्राथमिक विचार, वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर. पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

अधिक से अधिक राज्यों से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का सम्मेलन

अदालतें, जहाँ तक संभव हो। प्रचलन में परंपरा है, बनाए रखने के लिए

क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। ऊपर बताए गए कारणों से,

धारा 5 (2) के तहत पहला परंतुक निरस्त होने योग्य है और

एक तरफ रख दें।

धारा 6 (1) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति पर लागू होती है।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायालय। इसकी समान वरिष्ठता है।

अर्थ जैसा कि यहाँ ऊपर व्यक्त किया गया है, के साथ
सटीक रूप से

धारा 5 (2) के तहत पहले परंतुक का संदर्भ।

ऊपर जिन कारणों पर ध्यान दिया गया है, उनके आधार पर

वरिष्ठता (प्राथमिक विचार के रूप में), दस उच्च न्यायालयों में

मूल उच्च न्यायालय। इसलिए एनजेएसी अधिनियम की धारा 6 (1) थी
परंतुक के रूप में एक ही भाग्य का सामना करने के लिए उत्तरदायी

धारा के तहत पहले

5 (2).

239. हमारा यह भी विचार है कि शक्ति

एन. जे. ए. सी. के किसी भी दो सदस्यों में निहित वीटो का,

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति के मामले में न्यायपालिका की प्रधानता पर प्रतिकूल
प्रभाव (साथ ही उनका स्थानांतरण भी)। इस संबंध में विवरण पहले ही दिया जा चुका है

ऊपर भाग VIII में अभिलिखित है। एनजेएसी की धारा 6 (6)

अधिनियम, के तहत दूसरे परंतुक के समान अर्थ है

इसलिए एन. जे. ए. सी. अधिनियम की धारा 5 (2) और धारा 6 (6)

धारा 5 (2) के समान भाग्य का सामना करें। दर्ज किए गए कारणों के लिए

इसके अलावा, हम संतुष्ट हैं कि धारा 5 (2) और 6 (6)

एन. जे. ए. सी. अधिनियम भी इसकी "मूल संरचना" का उल्लंघन करता है।

संविधान, "स्वतंत्रता" के संदर्भ में

न्यायपालिका "और" शक्तियों का पृथक्करण "। धारा 5 (2) और

6 (6), हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, इसलिए, भी उत्तरदायी हैं

संविधान के अधिकार से बाहर घोषित किया गया।

240. विद्वान वकील द्वारा एक चुनौती भी उठाई गई थी

एन. जे. ए. सी. अधिनियम की धारा 7 के याचिकाकर्ताओं के लिए। यह था।

जोर देकर कहा कि एन. जे. ए. सी. द्वारा की गई सिफारिश पर, सर्वोच्च न्यायालय अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड करता है

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

राष्ट्रपति व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए बाध्य था

अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अनुशंसित 217 (1). यह प्रस्तुत किया गया था कि उपरोक्त स्थिति समान थी

अनुच्छेद 124 (2) के तहत विचार की गई स्थिति के लिए, जो

राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए अदालत। यह प्रस्तुत किया गया था कि न तो अनुच्छेद 124 (2) और न ही अनुच्छेद

217 (1) अभिधारणा, कि राष्ट्रपति को एन. जे. ए. सी. की आवश्यकता हो सकती है

एन. जे. ए. सी. द्वारा की गई सिफारिश पर पुनर्विचार करें, जैसा कि है

धारा 7 के पहले परंतुक के तहत प्रदान किया गया था

एनजेएसी अधिनियम। यह तदनुसार विद्वानों का तर्क था

याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि धारा 7 का पहला प्रावधान

क्या अनुच्छेद 124 (2) और 217 (1) के प्रावधान अधिकार से बाहर थे,

पुनर्विचार के लिए प्रावधान करके, और वह, वही था ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के दायरे और दायरे से परे।

241. द्वारा अग्रिम प्रस्तुतिकरण पर विचार करने के बाद

पूर्वगामी अनुच्छेद में याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील,

हमारे लिए यह स्वीकार करना संभव नहीं है कि एन. जे. ए. सी. की धारा 7

अधिनियम, यह प्रावधान करके कि राष्ट्रपति एन. जे. ए. सी. को उसके द्वारा की गई सिफारिश पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो सकती है, किसी भी तरह से होगा।

राष्ट्रपति द्वारा सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा (एनजेएसी)। यह अनुमान लगाना अनुचित होगा कि की कार्रवाई

राष्ट्रपति, एन. जे. ए. सी. से अपने प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा करते हुए,

एन. जे. ए. सी. द्वारा किए गए प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बराबर था। के लिए, यदि

एन. जे. ए. सी. को पहले किए गए प्रस्ताव को दोहराना था,

धारा 7 के संदर्भ में भी राष्ट्रपति कार्य करने के लिए बाध्य थे (जैसा कि दूसरे परंतुक से स्पष्ट है)

एन. जे. ए. सी. अधिनियम की धारा 7 के तहत)। हमारे विचार में, याचिकाकर्ताओं के हाथों त्वरित प्रस्तुतिकरण

अस्वीकार किए जाने के योग्य है, और तदनुसार अस्वीकार किया जाता है।

242. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने भी

एन. जे. ए. सी. अधिनियम की धारा 8 की वैधता पर हमला किया, जो

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट में भारत सरकार के सचिव के लिए प्रावधान

[2015] 13 एस सी आर।

न्याय विभाग एन. जे. ए. सी. का संयोजक होगा। यह था। तर्क दिया कि एक संयोजक का कार्य, के संदर्भ में

एन. जे. ए. सी. की बैठकों के लिए कार्यसूची, अर्थात्, निर्णय लेने के लिए अगली बैठक में विचार के लिए लिए जाने वाले व्यक्तियों के नाम। इसमें यह निर्णय भी शामिल होगा कि

अगले में विचार के लिए लिए जाने वाले नामों को नजरअंदाज करें बैठक होती है। वह नामों को विचार से शामिल या बहिष्कृत कर सकता है,

अपने वरिष्ठ के कहने पर। विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों को संकलित करना भी संयोजक की जिम्मेदारी होगी।

एन. जे. ए. सी. अधिनियम के तहत विचार किए गए क्वार्टर, और इसके अलावा

इसके लिए, जैसा कि प्रभारी केंद्रीय मंत्री द्वारा आवश्यक हो सकता है
 कानून और न्याय, और भारत के मुख्य न्यायाधीश। यह था।
 प्रस्तुत किया, कि ऐसी भारी जिम्मेदारी, नहीं हो सकती है
 केवल कार्यपालिका पर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि सामग्री को संयोजक द्वारा चुनिंदा रूप से एन. जे. ए. सी.
 के समक्ष रखा जा सकता है। अपने वरिष्ठ की इच्छा का सम्मान-केंद्रीय मंत्री
 अनुकूल सामग्री को छोड़कर विधि और न्याय का प्रभार,
 द्वारा अनुपयुक्त माने जाने वाले उम्मीदवार के संदर्भ में
 कार्यकारी, और प्रतिकूल सामग्री को छोड़कर, के साथ
 एक उम्मीदवार का संदर्भ जिसने कार्यपालिका का समर्थन किया।

243. यह भी प्रस्तुत किया गया था कि यह अनिवार्य था
 की कार्यवाही में सभी कार्यकारी भागीदारी को बाहर करने के लिए
 दो कारणों से एन. जे. ए. सी. सबसे पहले, कार्यपालिका सबसे बड़ी थी
 व्यक्तिगत वादी, उच्च न्यायपालिका के समक्ष लंबित मामलों में, और इसलिए, इस प्रक्रिया में कोई विवेकाधीन
 भूमिका नहीं निभा सकता है।
 उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों का चयन और नियुक्ति
 दूसरा, वही अवधारणाओं को कमजोर कर देगा "शक्तियों का पृथक्करण और न्यायपालिका की
 स्वतंत्रता,
 जिसके तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका या विधायिका के किसी भी संभावित हस्तक्षेप से बचाया जाना
 चाहिए।

244. हमने अपना विचारशील विचार दिया है
 उपरोक्त दो प्रस्तुतियाँ, पूर्ववर्ती दो सर्वोच्च न्यायालय अधिवक्ताओं-चालू-रिकॉर्ड में दी गई हैं।

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे.]
 परिच्छेद। हम पहले ही निष्कर्ष निकाल चुके हैं कि
 केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री की भागीदारी, एन. जे. ए. सी. के सदस्य के रूप में, जैसा कि अनुच्छेद के
 तहत विचार किया गया है

124 ए (1), उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में
 न्यायपालिका, "शक्तियों के पृथक्करण" की अवधारणाओं का उल्लंघन करेगी
 और "न्यायपालिका की स्वतंत्रता", जो दोनों निर्विवाद रूप से न्यायपालिका की "मूल संरचना" के घटक हैं।
 भारत का संविधान। ठीक उन्हीं कारणों से हम हैं
 एन. जे. ए. सी. अधिनियम की धारा 8 जो यह उपबंध करती है कि विभाग में भारत सरकार के सचिव
 कानून में। एन. जे. ए. सी. जैसे निकाय में प्रशासनिक कार्यप्रणाली कार्यकारी या विधायी नियंत्रण में
 नहीं हो सकता है। एकमात्र
 शेष वैकल्पिक, का प्रशासनिक नियंत्रण निहित करना है
 न्यायपालिका के साथ ऐसा निकाय। उपरोक्त कारणों से, अनुभाग
 8 एन. जे. ए. सी. अधिनियम भी इसी तरह कानून में अस्थिर होगा।

245. कानूनी दृष्टिकोण से जांच की गई, यह था
 हमारे लिए व्यक्तिगत प्रावधानों की जांच करना अनावश्यक है
 अस्थिर माना जाता है, विवादित संवैधानिक संशोधन के साथ-साथ एन. जे. ए. सी. अधिनियम
 को भी अमान्य कर दिया जाएगा। कुछ मुद्दों से निपटने की आवश्यकता थी
 विचार से प्रेरित, कि व्यापक मापदंडों को होना चाहिए
 व्यक्त किया जाए। V. प्रभावितों को नीचे गिराने का प्रभाव
 संवैधानिक संशोधन:

246. क्या संविधान के संशोधित प्रावधान
 पुनर्जीवित करें, यदि विवादित संवैधानिक संशोधन होना था
 के "मूल संरचना" के उल्लंघन के रूप में अलग रखा गया संविधान? यह उल्लेख करना
 प्रासंगिक होगा कि तत्काल
 याचिकाकर्ता, संभवतः इस धारणा पर कि यदि वर्तमान विवाद पर विचार करते हुए, यह
 न्यायालय [2015] 13 एस. सी. आर. पर हड़ताल करेगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट
 संविधान (99 वां संशोधन) अधिनियम, फिर अनुच्छेद 124,

127, 128, 217, 222, 224, 224 ए और 232, जैसा कि वे पहले से मौजूद थे

विवादित संशोधन को पुनर्जीवित किया जाएगा। और इस पर

न्यायाधीशों के मामले, फिर से चयन को विनियमित करेंगे और
न्यायपालिका के न्यायाधीशों का स्थानांतरण भी।

नियुक्तियाँ, साथ ही उच्च

247. उपरोक्त धारणा पर गंभीर आपत्ति,

सॉलिसिटर द्वारा उत्तरदाताओं की ओर से उठाया गया था

जनरल, जिन्होंने तर्क दिया कि विवादित लोगों को मार गिराया गया
पुनरुद्धार में परिणाम नहीं होगा

संवैधानिक संशोधन, के

उपरोक्त प्रस्ताव का प्रचार करने के लिए, निर्भरता थी
अभिनिर्धारित करता है कि

अनुच्छेद 367 पर रखा गया है, जो

सामान्य खंड अधिनियम, 1897 को लागू किया जाना था,

संविधान के अनुच्छेदों की व्याख्या, उसी तरह से, जैसे सामान्य खंड अधिनियम के प्रावधान करते हैं,

सामान्य विधान की व्याख्या के लिए लागू। यहाँ तक कि

जैसा कि तत्काल प्रस्तुत करने का संबंध है, हमें कोई संकोच नहीं है

यह पुष्टि करते हुए कि जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो,

सामान्य खंड अधिनियम के प्रावधान, एक के लिए लागू किया जा सकता है

के प्रावधानों की सही और प्रभावी समझ

संविधान।

248. पूर्वगामी में देखे गए प्रस्तुतिकरण पर आधारित

पैराग्राफ, सॉलिसिटर जनरल ने धाराओं पर निर्भरता रखी

6, 7 और सामान्य खंड अधिनियम के 8, जिन्हें निकाला जा रहा है

इसके नीचे:

"6. निरसन का प्रभाव। - जहां यह अधिनियम, या कोई केंद्रीय अधिनियम या

इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद बनाया गया विनियम,

अब तक या इसके बाद किए गए किसी भी अधिनियम को निरस्त करता है

किया गया, तब, जब तक कि कोई अलग इरादा प्रकट न हो, निरसन

(क) उस समय लागू या मौजूदा किसी भी चीज़ को पुनर्जीवित करें।

जिसे निरस्त करना प्रभावी होता है; या सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

समाज v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

(ग) इस प्रकार निरस्त किसी अधिनियम के तहत अर्जित, उपार्जित या उपार्जित किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या दायित्व को प्रभावित करता है; या (घ) में किए गए किसी भी दंड, ज़ब्त या सजा को प्रभावित करता है

जैसा कि ऊपर कहा गया है दंड, ज़ब्त या सजा; और ऐसी कोई जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय

7. निरस्त किए गए अधिनियमों का पुनरुद्धार। - (1) किसी भी केंद्रीय अधिनियम में या इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद बनाया गया विनियमन,

पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से यह आवश्यक होगा, या तो

पूर्ण या आंशिक रूप से, कोई भी अधिनियम पूर्ण या आंशिक रूप से

निरस्त किया गया, स्पष्ट रूप से उस उद्देश्य को बताने के लिए। (2) यह धारा बाद में बनाए गए सभी केंद्रीय अधिनियमों पर भी लागू होती है।

जनवरी, 1868 के तीसरे दिन और बनाए गए सभी विनियमों के लिए

जनवरी, 1887 के चौदहवें दिन या उसके बाद।

8. निरस्त किए गए अधिनियमों के संदर्भों का निर्माण। - (1) जहां यह अधिनियम, या कोई केंद्रीय अधिनियम या विनियमन इसके बाद बनाया गया है।

इस अधिनियम का प्रारंभ, निरसित करता है और पुनः अधिनियमित करता है,

या संशोधन के बिना, पूर्व का कोई प्रावधान

इस प्रकार निरसित प्रावधान का कोई भी लिखत, जब तक कि - अलग-अलग इरादे प्रकट होते हैं, जिन्हें संदर्भ के रूप में माना जाता है

इस प्रकार पुनः अधिनियमित प्रावधान।

(2) जहाँ अगस्त, 1947 के पंद्रहवें दिन से पहले कोई अधिनियम

यूनाइटेड किंगडम की संसद को निरस्त और पुनः के किसी भी प्रावधान को संशोधन के साथ या उसके बिना अधिनियमित किया गया

पूर्व अधिनियम, फिर किसी केंद्रीय अधिनियम या सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर. में संदर्भ।

इस प्रकार निरस्त किए गए प्रावधान का कोई विनियमन या साधन

जब तक कोई अलग इरादा प्रकट नहीं होता, तब तक इसका अर्थ लगाया जाएगा

इस प्रकार पुनः अधिनियमित प्रावधान के संदर्भ के रूप में।

249. धारा 6 के आधार पर, यह प्रस्तुत किया गया था कि

विवादित संवैधानिक संशोधन को अलग करते हुए,

निरस्तीकरण प्रावधान को अलग रखने के रूप में माना जाना चाहिए। और इस प्रकार,
याचिकाकर्ताओं के दावे की स्वीकृति,

वे संशोधन से पहले मौजूद थे। धारा 7 पर निर्भर करते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि यदि एक
निरस्त प्रावधान को पुनर्जीवित किया जाना है, तो यह

विधायिका के लिए इस तरह की मंशा व्यक्त करना अनिवार्य था,

और जब तक ऐसा स्पष्ट रूप से इंगित नहीं किया जाता है, तब तक अधिनियम पूरी तरह से या

आंशिक रूप से निरस्त, पुनर्जीवित नहीं होगा। अंत में सामान्य खंड अधिनियम की धारा 8 पर भरोसा करते
हुए, यह प्रस्तुत किया गया कि

जब एक मौजूदा प्रावधान को निरस्त कर दिया गया था और दूसरा प्रावधान इसके प्रतिस्थापन के
रूप में फिर से अधिनियमित किया गया था, आगे कोई संदर्भ नहीं हो सकता था

निरस्त किए गए अधिनियम के लिए, और सभी इरादों के लिए और

उद्देश्यों के लिए, संदर्भ अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए, केवल

पुनः अधिनियमित प्रावधान। अंतर्निहित सिद्धांतों पर भरोसा करना

धारा 6, 7 और 8, यह प्रस्तुत किया गया था कि भले ही प्रार्थनाएँ

याचिकाकर्ताओं द्वारा किया गया स्वीकार किया जाना था, और

विवादित संवैधानिक संशोधन को दरकिनार किया जाना था,

उसी के परिणामस्वरूप अपरिवर्तित का पुनरुद्धार नहीं होगा

प्रावधान।

250. विद्वान महान्यायवादी ने भी एक संख्या का उल्लेख किया

इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए

उसे खींचा। इसलिए हम सबसे पहले इसकी जांच करेंगे।

निर्णय इस पर निर्भर थे:

(i) रिलायंस को पहली बार में अमीर पर रखा गया था।

अन-निसा बेगम मामला। हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था

पैराग्राफ 24 में दर्ज टिप्पणियाँ, जो हैं -

यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"24 परिणाम एक ही होगा, भले ही हम आगे बढ़ें।

इस आधार पर कि निजाम द्वारा जारी किए गए विभिन्न फरमान सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता थे-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

निजी का निर्धारण करने वाले विधायी अधिनियमों की प्रकृति में

निजी अधिनियमों के सादृश्य पर कुछ अधिकार

संसद। हम मान सकते हैं कि 26-6-1947 का 'फरमान'

24-2-1949 के 'फरमान' द्वारा निरस्त किया गया था, और बाद वाला

' 'फरमान' को इसके बदले में 7-9-1949 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। के तहत

अंग्रेजी सामान्य कानून जब एक निरसन अधिनियम

1850 से पारित अधिनियमों को निरस्त करने के लिए लागू होता है और अब यदि एक पूर्व अधिनियम को निरस्त करने वाला अधिनियम स्वयं निरस्त हो जाता है, अंतिम निरसन

निरस्त होने से पहले अधिनियम को पुनर्जीवित नहीं करता है जब तक कि शब्द नहीं हैं इसे पुनर्जीवित करते हुए जोड़ा गया: मैक्सवेल की कानूनों की व्याख्या।

पी। 402 (10 संस्करण)।

यह वास्तव में कहा जा सकता है कि वर्तमान नियम का परिणाम है

व्याख्या अधिनियम द्वारा प्रस्तुत वैधानिक प्रावधान

1889 का और जैसा कि हम किसी के प्रावधानों से बाध्य नहीं हैं

अंग्रेजी कानून, हम अभी भी अंग्रेजी आम लागू कर सकते हैं

कानून नियम यदि यह हमें उचित और उचित लगता है।

लेकिन सामान्य कानून के सिद्धांत के अनुसार भी, निरसन

निरस्तीकरण अधिनियम मूल को पुनर्जीवित नहीं करेगा
अधिनियम यदि दूसरा निरस्तीकरण अधिनियम प्रकट करता है

इसके विपरीत इरादा। '

हमारे विचारशील विचार देने के बाद

उत्तरदाताओं, क्योंकि निर्णय में भरोसा किया गया था, यह था स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला कि
अंग्रेजी सामान्य कानून के तहत जब

एक निरसन अधिनियम को एक अन्य कानून द्वारा निरस्त कर दिया गया था, निरसन

दूसरा अधिनियम पूर्ववर्ती "अब इनिशियो" को पुनर्जीवित करेगा। में। मामले का उपरोक्त दृष्टिकोण,
विशेष रूप से अंग्रेजी पर आधारित है

विवादित को अलग रखने पर सामान्य कानून

संवैधानिक संशोधन, अपरिवर्तित प्रावधान, होगा पुनर्जीवित हो जाओ। यह भी ध्यान देने की
आवश्यकता है कि अंतिम स्थिति

इसके विपरीत, निर्णय में व्यक्त, सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

बाद के विधान के परिणामस्वरूप उभरा इंग्लैंड में बनाया गया अधिनियम, जो भारत पर लागू
नहीं होता है।

उपरोक्त बाद के संशोधनों को लेने के बाद

विचार करते हुए, यह निष्कर्ष निकाला गया कि निरस्तीकरण का निरसन

अधिनियम मूल अधिनियम को पुनर्जीवित नहीं करेगा, सिवाय इसके कि "।

यदि दूसरा निरस्तीकरण अधिनियम एक इरादा प्रकट करता है

इसके विपरीत। "दूसरे शब्दों में, निहितार्थ यह होगा कि मूल अधिनियम पुनर्जीवित होगा, लेकिन
निरसन अधिनियम में व्यक्त किए गए विपरीत इरादे के लिए। लेकिन यह आवश्यक है कि

यह ध्यान में रखा जाए कि उपरोक्त निर्णय एक

आवश्यकता जहां विधान द्वारा अधिनियमित प्रावधान था

एक अदालत के आदेश द्वारा रद्द कर दिया गया।

(ii) रिलायंस को तब फर्म ए. टी. बी. मेहताब माजिद पर रखा गया था।

पैराग्राफ 20। उपरोक्त निर्णय का अवलोकन होगा प्रकट करें, कि इस न्यायालय ने अपने निष्कर्षों को दर्ज किया था, बिना

या तो अंग्रेजी सामान्य कानून, या प्रावधानों पर भरोसा करना

सामान्य खंड अधिनियम, जो उत्तरदाताओं के हाथों दिए गए तर्कों की नींव का गठन करता है,

हमारे सामने। इसलिए हम संतुष्ट हैं कि निष्कर्ष तत्काल निर्णय में तैयार किया गया, आने के लिए लागू नहीं होगा

किसी निष्कर्ष पर एक या दूसरे तरीके से, जहाँ तक वर्तमान में विवाद की चिंता है।

(iii) इसके बाद बी. एन. तिवारी मामले का संदर्भ दिया गया।

और हमारा ध्यान निम्नलिखित टिप्पणियों की ओर आकर्षित किया गया:

"6. हम पहले इस सवाल पर विचार करेंगे कि क्या कैरी

1952 का अग्र शासन अभी भी मौजूद है। यह सच है कि

देवदासन का मामला, ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 17, का अंतिम आदेश

यह न्यायालय इन शर्तों में था:

"परिणामस्वरूप याचिका आंशिक रूप से सफल होती है और कैरी

1955 में संशोधित फॉरवर्ड नियम को अमान्य घोषित किया गया है।

हालाँकि इसका मतलब यह नहीं है कि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि

1952 के नियम को अस्तित्व में माना जाना चाहिए क्योंकि यह सर्वोच्च न्यायालय अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड है।

499

समाज v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे. जे.

न्यायालय ने कहा कि 1955 ए में संशोधित कैरी फॉरवर्ड नियम

अमान्य घोषित किया गया। 1952 का कैरी फॉरवर्ड नियम

1955 के कैरी फॉरवर्ड नियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। उस पर यह प्रतिस्थापन 1952 का कैरी फॉरवर्ड नियम स्पष्ट रूप से अस्तित्व में नहीं रहा क्योंकि इसका स्थान कैरी द्वारा लिया गया था।

बी.

1955 का अग्र शासन। इस प्रकार नई घोषणा करके

1955 में शासन को आगे बढ़ाते हुए, भारत सरकार ने स्वयं

1952 के कैरी फॉरवर्ड नियम को रद्द कर दिया गया। इसलिए जब

इस न्यायालय ने कैरी फॉरवर्ड नियम को संशोधित रूप में रद्द कर दिया

1955 में इसका मतलब यह नहीं था कि आगे ले जाने का नियम

ची.

1952 जिसका अस्तित्व पहले ही समाप्त हो चुका था, क्योंकि

भारत सरकार ने स्वयं इसे रद्द कर दिया था और

1955 में इसके स्थान पर एक संशोधित नियम को प्रतिस्थापित किया गया, पुनर्जीवित करें। इसलिए हमारी राय है कि इसके बाद

देवदासन के मामले में इस न्यायालय का निर्णय ए. आई. आर. 1964

डी.

1952 का कैरी फॉरवर्ड नियम तब समाप्त हो गया था जब भारत सरकार ने कैरी फॉरवर्ड को प्रतिस्थापित किया

इसके स्थान पर 1955 का शासन। लेकिन यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि

ई.

देवदासन के मामले में इस अदालत का फैसला

1964 एससी179, केवल उस भाग से संबंधित है

भारत सरकार के निर्देश जो इससे संबंधित हैं

कैरी फॉरवर्ड नियम; यह किसी भी तरह से स्पर्श नहीं करता है

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण एफ 12-1/2% और 5% पर, क्रमशः; और न ही यह स्पर्श करता है

अनुसूचित जनजातियों की रिक्तियों को अनुसूचित द्वारा भरना

जाति उम्मीदवार जहाँ पर्याप्त संख्या में अनुसूचित हैं

जनजातियाँ किसी विशेष वर्ष में या इसके विपरीत उपलब्ध नहीं होती हैं।

देवदासन के मामले में फैसले का प्रभाव। एयर जी

1964 एससी179, इसलिए केवल कैरी को खत्म करने के लिए है

आगे का नियम और यह साल दर साल प्रभावित नहीं करता है
 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण
 या किसी सदस्य द्वारा अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों को भरना

एच. सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.
 किसी विशेष वीर में अनुसूचित जातियों का यदि पर्याप्त हो
 अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों की संख्या उपलब्ध नहीं है
 उस वर्ष इसके विपरीत। इस समायोजन में
 अनुसूचित जाति और जनजातियों के बीच आरक्षण है
 साल दर साल कैरी फॉरवर्ड नियम से कोई लेना-देना नहीं

1952 का वर्ष जो अस्तित्व में नहीं रहा था या 1955 का वर्ष
 जिसे इस न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इस दृष्टि से

इस बात पर विचार करना अनावश्यक है कि क्या कैरी

इसके लिए 1952 का अग्र शासन असंवैधानिक होगा।

नियम अब मौजूद नहीं है। "

1952 के कैरी-फॉरवर्ड-नियम का गैर-पुनरुद्धार, जिसे 1955 में संशोधित करने की मांग की गई थी, तत्काल
 निर्धारित किया गया

निर्णय, प्रस्तुतियों के कारण नहीं था, जिनके पास है

वर्तमान विवाद में हमारे सामने पेश किया गया। लेकिन, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत
 सरकार ने स्वयं

1952 के कैरी फॉरवर्ड नियम को रद्द कर दिया गया। इसके अलावा, मुद्दा

उपरोक्त निर्णय में विचाराधीन, के समान नहीं था

हाथ में विवाद। इस प्रकार, हम संतुष्ट हैं कि निर्भरता

बी. एन. तिवारी मामले में 12 स्पष्ट रूप से गलत है। (iv) कोटेश्वर विट्टल कामत मामले पर भरोसा
 करते हुए 73, सीखा

महान्यायवादी ने निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा व्यक्त किया:

उसमें अभिलिखित है:

"8. उस सादृश्य पर, यह तर्क दिया गया था कि, यदि हम मानते हैं कि

1119 के निषेध आदेश को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। यह तर्क दोनों के बीच के अंतर को नजरअंदाज करता है।

एक नियम का अधिक्रमण, और एक नियम का प्रतिस्थापन। में

फर्म ए. टी. बी. मेहताब माजिद एंड कंपनी (ऊपर) का मामला, नया

नियम 16 को पुराने नियम 16 के स्थान पर रखा गया था। प्रक्रिया.

टी

प्रतिस्थापन में दो चरण होते हैं। सबसे पहले, पुराना नियम यह है अस्तित्व समाप्त कर दिया जाता है और इसके बाद नया नियम लाया जाता है

अपने स्थान पर। भले ही नया नियम अमान्य हो,

पुराने नियम का अस्तित्व समाप्त होने का पहला कदम आता है

प्रभाव, और यह इस कारण से था कि अदालत ने माना कि, सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं पर-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

नए नियम को अमान्य घोषित करना, पुराना नियम अमान्य नहीं हो सका

1950 के निषेध आदेश का प्रतिस्थापन, के लिए
1119 का निषेध आदेश। 1950 का निषेध आदेश,

निषेध आदेश से स्वतंत्र रूप से घोषित किया गया था

1119 का और कानून के प्रावधानों के कारण यह होगा
1119 का निषेध आदेश बनाने का प्रभाव पड़ा

निष्क्रिय यदि यह एक वैध आदेश था। अगर प्रतिबंध

1950 का आदेश शुरू से ही शून्य पाया गया है, यह कभी नहीं हो सका
1119 के निषेध आदेश को निष्क्रिय बना दें।

नतीजतन, 30 मार्च, 1950 को या तो
1119 का निषेध आदेश या 1950 का निषेध आदेश

ऐसा माना जाना चाहिए कि यह त्रावणकोर-कोचीन में लागू था।

ताकि 1950 के अधिनियम 5 की धारा 73 (2) के प्रावधान

यह उस आदेश पर लागू होगा और इसे जारी रखेगा। 1950 के अधिनियम 5 के बाद यह निरंतरता, निश्चित रूप से,

1950 के अधिनियम 5 की धारा 3 की वैधता पर निर्भर करता है, क्योंकि धारा 73 (2) आदेश को जारी रखने के लिए अभिप्रेत है

उस धारा के तहत बल, ताकि हम जांच करने के लिए आगे बढ़ें

अधिनियम 5 की धारा 3 की वैधता से संबंधित तर्क

1950. "

ऊपर दिए गए निष्कर्ष का अवलोकन,

जाहिरा तौर पर के हाथों में आगे बढ़े विवाद का समर्थन करता है

उत्तरदाताओं, कि यदि पूर्ववर्ती में संशोधन

विधायी अधिनियम, एक मौजूदा के प्रतिस्थापन की परिकल्पना करता है

प्रावधान, प्रतिस्थापन की प्रक्रिया को माना जाना चाहिए यह परिकल्पना की जाएगी कि

इसमें दो चरण शामिल हैं। पहले चरण में

पुराना नियम अस्तित्व में नहीं रहेगा और दूसरा कदम होगा पुराने नियम की जगह ले ली थी।

कल्पना कीजिए कि नए नियम ने

और इस तरह, भले ही नए नियम को अमान्य घोषित किया जाना था,

ऊपर दर्शाया गया पहला कदम, अर्थात्, कि पुराना नियम है

अस्तित्व में नहीं रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। इस प्रकार, जिससे

अनुमान, कि वर्तमान विवाद में, भले ही

विवादित संवैधानिक संशोधन को दरकिनार किया जाना था, सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

इसी से अपरिवर्तित अनुच्छेदों का पुनरुद्धार नहीं होगा

124, 127, 128, 217, 222, 224, 224 ए और 232। हमारे विचार में

देखने के लिए, निर्णय में की गई टिप्पणियों के कारण

ऊपर दर्ज प्रस्तुतियाँ और निष्कर्ष, नहीं हैं

वर्तमान मामले में लागू का प्रमुख भाग

ऊपर निकाला गया निर्णय वर्तमान में लागू होगा

चयन और नियुक्ति की एक नई योजना शुरू करना
रूप से अलग

उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीश, दिशात्मक

प्रचलित स्थिति। और इसलिए, के मूल प्रावधान

संविधान को निष्क्रिय कर दिया गया होगा, केवल अगर

संशोधित प्रावधान वैध थे। नतीजतन, यदि उपरोक्त निर्णय पर निर्भरता रखी जानी चाहिए, तो निष्कर्ष होगा

प्रस्ताव के खिलाफ प्रचार किया गया। हालांकि यह होगा

यह उल्लेख करने के लिए प्रासंगिक है कि तत्काल निर्णय, साथ ही, कुछ

के लिए विद्वान वकील द्वारा भरोसा किए गए अन्य निर्णयों में से

उत्तरदाताओं को समझाया और अलग किया गया है

महाराष्ट्र राज्य बनाम। मध्य प्रांत मैंगनीज अयस्क

कं. *Ltd.* 76, जिसे इसके बाद कालानुक्रमिक रूप से निपटाया जाएगा।

(v) विद्वान महान्यायवादी ने

तब इस पर भरोसा रखा,

मूलचंद ओधवजी मामला, और इस पर हमारा ध्यान आकर्षित किया

पैराग्राफ 8 में अभिलिखित अवलोकन। रिलायंस था

यहाँ तक कि मोहम्मद को भी रखा गया। शौकत हुसैन खान मामला 75, और
पैराग्राफ 11 में दर्ज टिप्पणियाँ।

विशेष रूप से,

हम संतुष्ट हैं कि तत्काल दिए गए दो निर्णय अप्रासंगिक हैं

नुकीले विवाद के निर्धारण के लिए, आगे बढ़ाया गया

उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील के हाथ, के रूप में

उपरोक्त मामलों में निपटाए गए विवाद की विषय वस्तु

हाथ में एक से बिल्कुल अलग था।

(vi) तब मध्य प्रांतों को संदर्भित किया गया था

मैंगनीज अयस्क कंपनी लिमिटेड मामला, और हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था

उसमें अभिलिखित निम्नलिखित टिप्पणियाँ:

सर्वोच्च अदालतें-चालू-रिकॉर्डसमाज v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

"18. हमें नहीं लगता कि प्रतिस्थापन शब्द आवश्यक है।

या हमेशा दो अलग-अलग चरणों को संदर्भित करता है, अर्थात्,

एक निरसन का और दूसरा नए अधिनियम का, भले ही वह

इसका मतलब है दो कदम। वास्तव में, "प्रतिस्थापन" शब्द का स्वाभाविक अर्थ यह इंगित करना है कि प्रक्रिया को विभाजित नहीं किया जा सकता है इस तरह दो टुकड़ों में। यदि प्रक्रिया के रूप में वर्णित है

प्रतिस्थापन विफल हो जाता है, यह पूरी तरह से अप्रभावी है ताकि अधुण्य रह सके

जिसे विस्थापित करने की कोशिश की गई थी। ऐसा लगता है कि हम "शब्दों का सामान्य और स्वाभाविक अर्थ होगा

प्रतिस्थापित "। यह भाग इसके बिना प्रभावी नहीं हो सकता था।

गवर्नर-जनरल की सहमति। राज्य के राज्यपाल

स्वीकृति अपर्याप्त थी। यह अनुमान नहीं लगाया जा सका कि, क्या

इरादा यह था कि, प्रतिस्थापन विफल होने की स्थिति में या

अप्रभावी साबित हुआ, कुछ निरसन, जिसका बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया गया था लाया गया और प्रभावी बना रहा ताकि क्या बनाया जा सके

पर वैधानिक कानून में एक शून्य के रूप में वर्णित किया जा सकता है

विषय-वस्तु। मुख्य रूप से, प्रश्न सभा का है,

अधिनियमित प्रावधान में शब्दों के उपयोग से आशय

प्रक्रिया के प्रकाश में देखा गया। यहाँ, नहीं। प्रतिस्थापन के बिना निरस्त करने का इरादा अनुमानित है। में।

ये दोनों एक अविभाज्य का अभिन्न अंग थे। प्रक्रिया और एक असंबद्ध ऑपरेशन के बिट्स नहीं।

19. वास्तविक प्रक्रिया को देखते हुए जो चली गई थी

इसके माध्यम से, हम पाते हैं कि, भले ही राज्यपाल ने सहमति दी हो

प्रतिस्थापन, फिर भी, संशोधन किया गया होगा

गवर्नर-जनरल की ओर से भी इसे प्रदान किया गया था। यह. यह नहीं कहा जा सकता था कि विधानमंडल का क्या इरादा था या क्या

राज्यपाल ने एक अलग को शामिल करने के लिए सहमति दी थी निरसन आ एकटा नव अधिनियमन। दोनों परिणाम एक ही प्रभावी विधायी प्रक्रिया से आने वाले थे।

इसलिए, इस प्रक्रिया को इस तरह से देखा जाना था और व्याख्या की।

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

20. उद्धरण द्वारा कुछ सहायता प्राप्त करने की मांग की गई थी

बी. एन. तिवारी बनाम भारत संघ [1965] 2 एस. सी. आर. 421 और मामला

फर्म ए. टी. बी. मेहताब माजिद एंड कंपनी बी. मद्रास राज्य। तिवारी का मामला जो था उसके प्रतिस्थापन से संबंधित था

विभागीय निर्देश जो अपेक्षित था द्वारा अमान्य घोषित एक संशोधित निर्देश द्वारा प्रतिस्थापित

अदालत। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब नियम में निहित

1955 के संशोधित निर्देश को रद्द कर दिया गया था

एक विस्थापित निर्देश में निहित जीवित नहीं रहा। वास्तव में,

वहाँ के तर्कों में से एक यह था कि 1952 का मूल "आगे ले जाएँ" नियम अपने आप में शून्य था। जिसे "आगे ले जाएँ" नियम, संशोधित में निहित है

1955 के निर्देशों को निरस्त कर दिया गया था। यहां तक कि

एक आदेश के दूसरे में विलय का सादृश्य जो था इसका विकल्प होने का मतलब केवल वहाँ लागू हो सकता है जहाँ एक

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निर्णय में विलय हो जाता है। अपीलीय न्यायालय या समीक्षा किए गए आदेश का उस आदेश में विलय हो जाता है जिसके द्वारा समीक्षा प्रदान की जाती है। इसका आवेदन ए

विधायी प्रक्रिया केवल वैध मामलों में ही संभव हो सकती है

प्रतिस्थापन। विधायी आशय और उसका प्रभाव एकत्र किया जाता है, अन्य बातों के साथ-साथ, प्राधिकरण की कार्यवाही की प्रकृति से जो

कार्य। किसी कार्यपालक पर किसी इरादे का आरोप लगाना आसान है।

नियम-किसी भी स्थिति में पूरी तरह से निरस्त करने का अधिकार

एक अन्य नियम द्वारा विस्थापित होने की कोशिश की जाती है। मामले उद्धृत किए गए हैं।

कार्यकारी निर्देश थे। हमें नहीं लगता कि वे

विधायी की व्याख्या करने में उपयोगी मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकता है

प्रावधान को एक नए अधिनियम द्वारा संशोधित करने की मांग की गई। द.

अधिनियमन की प्रक्रिया कहीं अधिक विस्तृत और औपचारिक है।

प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन किया गया है। किसी भी मामले में दूसरी ओर, एक कार्यकारी निर्देश में निहित नियम,

निरसन के साथ-साथ विस्थापन सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता होने में सक्षम हैं-चालू-रिकॉर्ड

समाज v. यू. ओ. आई. /जगदीश सिंह खेहर, जे. जे.

नए निर्देशों के एक नंगे मुद्दे से प्राप्त और अनुमान लगाया गया एक ही विषय पर।

21. मेहताब माजिद एंड कंपनी के मामले में एक वैधानिक भूमिका को पुनर्जीवित नहीं किया गया था क्योंकि इसे प्रतिस्थापित करने की मांग की गई थी

एक अन्य को अमान्य माना गया। यह भी एक मामला था जिसमें

के लिए कोई विस्तृत विधायी प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई थी

विधियों के वैधानिक अधिनियमन के मामले में निरसन

विधायिकाओं द्वारा। हर मामले में, यह इरादे का सवाल है

भाषा के साथ-साथ अधिनियमों से एकत्र किया जाए

ये होते हैं। 22. एक वैधानिक में अब निहित निर्माण का एक सिद्धांत

1850 से इंग्लैंड में किया गया प्रावधान है:

जहाँ 1850 के बाद पारित कोई अधिनियम पूरी तरह या आंशिक रूप से निरस्त हो जाता है।

के लिए कोई पूर्व अधिनियम और प्रतिस्थापन प्रावधान अधिनियम निरस्त किया गया, निरस्त अधिनियम में बना हुआ है

प्रतिस्थापित प्रावधानों के लागू होने तक बल।

(देखिए: हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, थर्ड एडन। खण्ड. 36, पी.

474; "कानून कानून" पर क्रेज़, 6 वीं संस्करण। p.386)। हालाँकि, हमारे सामान्य में कोई संबंधित प्रावधान नहीं है

खंड अधिनियम, फिर भी, यह दर्शाता है कि केवल शब्दों का उपयोग प्रतिस्थापन को दर्शाना वास्तव में या स्वचालित रूप से नहीं होता है।

एक प्रावधान को तब तक निरस्त करें जब तक कि प्रावधान, जो इसका लेना है

जगह कानूनी रूप से प्रभावी हो जाती है। जैसा कि हमने समझाया है
ऊपर, विचार करके एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे
"प्रतिस्थापन" शब्द का सामान्य और प्राकृतिक अर्थ
जब यह उपयोग की गई भाषा में किसी और चीज़ के बिना होता है
या इसके संदर्भ में या आसपास के तथ्यों में और
परिस्थितियाँ एक और निष्कर्ष की ओर ले जाती हैं। इसका मतलब है, सामान्यतया, कि जब तक
प्रतिस्थापित प्रावधान नहीं है
कानून में और प्रभावी रूप से, पूर्व-विद्यमान प्रावधान का स्थान लेना।
जारी है। "पुनरुत्थान" का कोई सवाल ही नहीं है।
यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि विद्वान अधिवक्ता
राल ने स्वीकार किया कि स्थिति तत्काल सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर. में समाप्त हुई।

निर्णय, उसके द्वारा अपनाए गए रुख को पराजित करेगा। हम.
उपरोक्त दृष्टिकोण का समर्थन करें। वह स्थिति जो आगे है
की ओर से दिए गए विवाद के लिए हानिकारक उत्तरदाताओं का कहना है कि उपरोक्त निष्कर्षों को
दर्ज करने में, यह
उपरोक्त उद्धृत मामले में न्यायालय ने विचार किया था,
फर्म ए. टी. बी. मेहताव माजिद मामले में निर्णय, बी. एन.
तिवारी मामला 12, कोटेश्वर विठ्ठल कामत मामला और मूलचंद ओधवजी मामला 74। पहले के निर्णयों पर
भरोसा किया गया था
इसलिए, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा, हाथ में विवाद के लिए स्पष्ट रूप से लागू नहीं होगा। इस
दृष्टि से मामले में, उत्तरदाताओं की ओर से प्रचार किए गए नुकीले मुद्दे में शायद ही कोई सार है।
(vii) विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने तब इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (बॉम्बे) प्राइवेट लिमिटेड पर निर्भरता
रखी। लिमिटेड वी. संघ का
भारत 95, और निम्नलिखित टिप्पणियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया उसमें अभिलिखित
है:

"107. हमारे सामने मामलों में हमारे द्वारा बनाए गए नियम नहीं हैं

मूलचंद मामले (1971) 3 एस. सी. सी. में दो अलग-अलग प्राधिकरण

53 और केंद्र सरकार की ओर से कोई इरादा नहीं

बाद की स्थिति में छूट को जीवित रखने के लिए

रद्द किए जाने की अधिसूचना भी स्थापित की गई है। द.

कोटेश्वर विट्टल कामत बनाम में इस न्यायालय का निर्णय। के. रंगप्पा बालिगा एंड कंपनी (1969) 3 एससीआर 40) ने भी ऐसा नहीं किया है।

याचिकाकर्ताओं का समर्थन करें। उस मामले में फिर से सवाल था

क्या एक बाद का कानून जो एक विधायिका द्वारा क्षमता के बिना पारित किया गया था, का प्रभाव होगा

एक पुराने नियम को पुनर्जीवित करना जिसे उसने प्रतिस्थापित करने का दावा किया था।

यह मामला फिर से मोहम्मद की श्रेणी में आता है। शौकत

हुसैन खान मामला, ए. आई. आर. 1974 एस. सी. 1480। यह भी हो सकता है ध्यान दिया कि कोटेश्वर विट्टल कामत मामले में, ए. आई. आर. 1969 एस. सी.

504, फर्म ए. टी. बी. मेहताब माजिद एंड कंपनी के मामले में निर्णय। ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 928 को प्रतिष्ठित किया गया है। का मामला

महाराष्ट्र राज्य बनाम। मध्य प्रांत मैंगनीज अयस्क

95 (1985) 1 एस. सी. सी. 641 - सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

कं. लिमिटेड, ए. आई. आर. 1977 एस. सी. 879 फिर से विशिष्ट है। इसमें

मामला पूरी विधायी प्रक्रिया जिसे प्रतिस्थापन कहा जाता था

निष्फल, क्योंकि, यह सहमति के अभाव में प्रभावी नहीं हुआ

गवर्नर-जनरल और न्यायालय ने अलग किया कि

तिवारी मामले से मामला, ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1430। हम भी कर सकते हैं बता दें कि पहले के कानून पर कानूनी प्रभाव जब बाद में

'सुपरसेशन'। यह समग्रता पर निर्भर करता है परिस्थितियाँ और जिस संदर्भ में उनका उपयोग किया जाता है।

ऊपर पुनरुत्पादित अर्क से क्या ध्यान देने की आवश्यकता है

यह है कि इस न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला है कि

किसी पूर्ववर्ती विधि पर कानूनी प्रभाव, जब उसके स्थान पर अधिनियमित बाद की विधि को अमान्य घोषित कर दिया गया था, केवल इस पर निर्भर नहीं था

‘प्रतिस्थापन’ या ‘प्रतिस्थापन’ जैसे शब्दों का उपयोग। और

इसके अलावा, कि यह परिस्थितियों की समग्रता पर निर्भर करेगा,

और वह संदर्भ, जिसमें प्रावधान को जोड़ा गया था। अगर

विद्वान महान्यायवादी द्वारा प्रस्तुत तर्क है

यह स्वीकार किया जाता है, यह एक संवैधानिक टूटने का कारण बनेगा। ऐसी स्थिति के झटके पहले से ही महसूस किए जा रहे हैं। सेवानिवृत्ति

उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों को प्रतिस्थापित नहीं किया जा रहा है

नई नियुक्तियाँ। उपरोक्त निर्णय, हमारे विचार में

देखें, प्रस्तुत किए जाने का समर्थन नहीं करता है,

क्योंकि परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करने पर और संदर्भ। “तत्काल विवाद स्वीकार्य नहीं है।

इसलिए हमारा मानना है कि तत्काल भी उत्तरदाताओं के लिए निर्णय का कोई लाभ नहीं हो सकता है, जहां तक

वर्तमान विवाद संबंधित है।

(viii) रिलायंस को अगले निर्णय पर रखा गया था

इस न्यायालय ने भगत राम शर्मा बनाम. भारत संघ। वह क्षण

निर्णय पर केवल यह दिखाने के लिए भरोसा किया गया था कि एक अधिनियम

एक संशोधन के रूप में कथित, समान गुणात्मक प्रभाव पड़ता है मौजूदा वैधानिक प्रावधान के निरसन के रूप में। उपरोक्त

96 1988 (सप) एस. सी. सी. 30 [2015] 13 एस. सी. आर.

दक्षिणी भूमि के सांविधिक निर्माण, तीसरे संस्करण, खंड 1 पर निर्भरता रखते हुए निष्कर्ष निकाला गया था।
चूंकि कोई नहीं है

तत्काल प्रस्ताव पर झगड़ा, रिकॉर्ड करना आवश्यक नहीं है

आगे कुछ भी। हालाँकि यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम हैं

किसी संशोधन या निरसन के प्रभाव का सामना नहीं करना पड़ा।

हम एक के हड़ताली डाउन के प्रभाव से निपट रहे हैं

न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से संवैधानिक संशोधन और एक विधायी अधिनियम।

(ix) रिलायंस को तब राजस्थान राज्य बनाम पर रखा गया था। मंगीलाल

पिंडवाल 97, और विशेष रूप से टिप्पणियों/निष्कर्षों पर

इसके पैराग्राफ 12 में दर्ज किया गया है। वह सब जो बताना आवश्यक है यह है कि उपरोक्त
निर्णय में तय किया गया मुद्दा उत्पन्न नहीं होता है

वर्तमान मामले में विचार के लिए, और तदनुसार,

उसमें निकाले गए निष्कर्षों को लागू नहीं किया जा सकता है -

वर्तमान मामला।

(x) अगले क्रम में, इंडिया टोबैको कंपनी लिमिटेड केस 77 पर निर्भरता रखी गई थी, और हमारा ध्यान
निम्नलिखित पर आमंत्रित किया गया था:

उसमें अभिलिखित टिप्पणियाँ:

"15. निर्माण का सामान्य नियम यह है कि एक का निरसन

निरस्तीकरण अधिनियम किसी भी निरस्तीकरण को पुनर्जीवित नहीं करता है।

लेकिन इस नियम का संचालन पूर्ण नहीं है। इसके अधीन है

निरसन में एक "अलग इरादे" की उपस्थिति

कानून। पुनः, इस तरह का इरादा स्पष्ट या अंतर्निहित हो सकता है।

इसलिए, निर्धारण के लिए जो प्रश्न उठते हैं, वे हैं:

चाहे सिगरेट के संबंध में, 1941 का अधिनियम निरस्त कर दिया गया था

1954 के अधिनियम द्वारा और 1958 के अधिनियम द्वारा? क्या

1954 का अधिनियम और 1958 का अधिनियम अधिनियमों को निरस्त कर रहे थे?

क्या 1954 के अधिनियम और 1958 के अधिनियम में कुछ है

सिगरेट के संबंध में 1941 के अधिनियम के पुनरुद्धार का संकेत?

16. अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि "निरसन" का अर्थ निरसन है।

या एक कानून को दूसरे द्वारा कानून से मिटा देना।

पूरी तरह से पुस्तक "जैसे कि इसे कभी पारित नहीं किया गया था"; जब

97 (1996) 5 एस. सी. सी. 60 सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

एक अधिनियम निरस्त किया जाता है, "इस पर विचार किया जाना चाहिए (सिवाय इसके कि

लेन-देन अतीत और बंद) जैसे कि यह कभी मौजूद नहीं था।

(प्रति टिंडल, के बनाम में सी. जे. गुडविन (1830) 6 बिंग 576,

750, 752 उड़ीसा राज्य बनाम में अनुमोदन के साथ उद्धृत। एम. ए. टुलोच एंड कंपनी, ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1284)।

17. निरसन केवल एक का नहीं बल्कि एक का मामला है

पदार्थ, विधानमंडल के इरादे के आधार पर।

यदि इरादा, स्पष्ट रूप से या आवश्यक रूप से इंगित किया गया है

बाद के कानून में निहितार्थ, निरस्त करना था या

पूर्ण या तत्काल निरस्तीकरण का मामला होगा। अगर इरादा केवल उत्कीर्णन द्वारा पूर्व अधिनियम को संशोधित करने के लिए था

एक अपवाद या छूट प्रदान करना, या अतिरिक्त जोड़कर शर्तों, या इसके प्रतिबंध, अवरोधन या निलंबन द्वारा

संचालन, इस तरह के संशोधन एक निरसन के बराबर नहीं होगा

-(कानून पर क्रेज़, 7 वीं संस्करण देखें। पीपी। 349, 353, 373,

374 और 375; मैक्सवेल की कानूनों की व्याख्या, 11 वीं संस्करण।

पीपी। 164, 390 माउंट वी पर आधारित। टेलर (1868) एल. आर. 3 सी. पी

645; साउदर्न लैंड्स स्टेच्युटरी कंस्ट्रक्शन थर्ड एडन। खण्ड. मैं,

पैराग्राफ 2014 और 2022, पीपी। 468 और 490)। मोटे तौर पर बोलना, एक निरसन और संशोधन का प्रमुख उद्देश्य

अधिनियम 'मृत पदार्थ को एक्साइज करना, अतिप्रवाहों को काटना और

स्पष्ट रूप से असंगत अधिनियमों को अस्वीकार करें '-मोहिंदर सिंह देखें

वी. एम.एस. ""

किन बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, जैसा कि हमने बार-बार किया है

ऊपर व्यक्त किया गया है कि निर्णयों में इस मुद्दे का प्रचार किया गया है

जिस पर भरोसा किया गया था, वह एक स्वैच्छिक निर्णय का प्रभाव था

किसी विद्यमान प्रावधान को संशोधित करने या निरस्त करने में विधायिका। कि स्थिति उत्पन्न होगी, यदि संसद ने वैध रूप से संशोधन किया था या

एक मौजूदा संवैधानिक प्रावधान को निरस्त कर दिया। इसमें,

विवादित संवैधानिक संशोधन ने निश्चित रूप से प्रभाव डाला है संविधान के कुछ मौजूदा प्रावधानों को प्रतिस्थापित करते हुए,

और इसमें कुछ नए प्रावधान भी जोड़े गए हैं।

स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

प्रतिस्थापन का तात्पर्य है कि पहले का प्रावधान अस्तित्व में नहीं है,

और संशोधित प्रावधान अपनी जगह लेता है। वर्तमान में स्थिति वह है जहाँ न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया द्वारा विवादित संवैधानिक संशोधन को दरकिनार कर दिया गया है। ऐसा होना।

स्थिति, जो भी आक्षेप का कारण और प्रभाव हो

संवैधानिक संशोधन, वही निर्धारित माना जाएगा एक तरफ, और संशोधन से पहले की स्थिति होगी

पुनर्स्थापित किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके चरण या चरण क्या हैं।

संशोधन का कारण और प्रभाव, सभी चरण और कदम

नकार दिया जाएगा, उसी तरह जैसे उन्हें पेश किया गया था संशोधन द्वारा, जब संशोधित प्रावधान निर्धारित किए जाते हैं

एक तरफ।

(xi) उपरोक्त निर्णय के अलावा, निर्भरता भी रखी गई थी

कोल्हापुर केनेसुगर वर्क्स लिमिटेड मामला, पश्चिम उत्तर प्रदेश

शुगर मिल्स एसोसिएशन बनाम। *U.P.*⁹⁸ की स्थिति, गैमन इंडिया लिमिटेड।

वी. विशेष मुख्य सचिव 99, हिरेंद्र पाल सिंह मामला 79;

एयर लाइन पायलटों के संघों की संयुक्त कार्रवाई समिति

भारत का मामला 30 और के. श्याम सुंदर का मामला 31। निष्कर्ष

उपर्युक्त उल्लिखित निर्णय या तो इन पर आधारित थे -

ऊपर या सामान्य रूप से हमारे द्वारा पहले से ही निपटाए गए निर्णय

सिद्धांत। उपरोक्त सभी निर्णयों की जांच, टिप्पणियों पर स्पष्ट रूप से ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है।

उनमें से प्रत्येक में दर्ज किया गया।

विद्वान महान्यायवादी, हमारे लिए यह दर्ज करना अनिवार्य है कि निष्कर्षों से स्पष्ट है

यह केंद्रीय में वापस किए गए

प्रांत मैंगनीज अयस्क कंपनी लिमिटेड मामला 76, कि तथ्यों में

और वर्तमान मामले की परिस्थितियों, यह होना होगा

ध्यान में रखा, कि अगर निर्माण विद्वान द्वारा सुझाया गया है

सॉलिसिटर जनरल को अपनाया जाना था, इसके परिणामस्वरूप हम ऐसा इसलिए कहते हैं, क्योंकि अगर न तो विवादित

एक रिक्त स्थान का निर्माण।

98 (2002) 2 एससीसी 645

99 (2006) 3 एस. सी. सी. 354 सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन *v.* यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

संवैधानिक प्रावधान, और न ही इसके संशोधित प्रावधान

संविधान बच जाएगा, यह टूटने की ओर ले जाएगा

संवैधानिक तंत्र, जैसे कि, एक कमी होगी

हमारे विचार में, किसी भी ठोस प्रक्रिया का परिणाम नहीं हो सकता है एक्सप्रेस समाचार पत्रों में दिए गए निर्णय से सामने आई टिप्पणियों से

व्याख्या। इसी तरह, इंडियन

(बॉम्बे) प्रा. लिमिटेड केस 95, हम संतुष्ट हैं, कि स्पष्ट इरादा संसद द्वारा, संविधान को अधिनियमित करते समय (99 वां

) अधिनियम में संशोधन करके उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति की एक नई प्रक्रिया का प्रावधान करना था।

विद्यमान प्रावधान। स्वाभाविक रूप से इसलिए, जब संशोधित

एक अलग प्रक्रिया को अभिनिर्धारित करने वाले प्रावधान को अलग रखा गया है, चयन और नियुक्ति की मूल प्रक्रिया

अपरिवर्तित प्रावधानों को पुनर्जीवित किया जाएगा। उपरोक्त स्थिति भी

कोटेश्वर विट्टल में घोषित कानूनी स्थिति से उभरता है

कामथ मामला 73.

252. हमारे लिए अनुमान को स्वीकार करना संभव नहीं है।

विद्वान सलाहकार के हाथों आगे बड़े विवाद

धारा 6,7 और 8 पर निर्भरता रखते हुए उत्तरदाता

सामान्य खंड अधिनियम। हम ऐसा इसलिए कहते हैं, क्योंकि विद्वान सॉलिसिटर जनरल का तर्क इस धारणा पर आधारित था,

कि एक न्यायिक निर्णय एक संशोधन को दरकिनार करते हुए, है

एक विधान के माध्यम से एक अधिनियम के निरसन के रूप में समान प्रभाव। यह एक अस्वीकार्य धारणा है। जब एक विधायिका

किसी मौजूदा प्रावधान को संशोधित या निरस्त करता है, इसकी कार्यवाही इसकी है

स्वयं की स्वतंत्र इच्छा, और सामान्य कारणों के प्रावधानों सहित व्याख्या के अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों पर आधारित है।

एकट करें। ऐसा नहीं है जब एक संशोधन/निरसन एक के माध्यम से अलग रखा जाता है

न्यायिक प्रक्रिया। विचार को दोहराना आवश्यक नहीं है।

ऊपर पैराग्राफ 250 (ix) में दर्ज किया गया है। जब कोई फैसला होता है

एक तरफ, विधायिका द्वारा एक संशोधन या निरसन, यह है लेकिन स्वाभाविक है कि पूर्व की यथास्थिति बहाल हो जाएगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

253. ऊपर दर्ज कारणों से, हम हैं

दृष्टिकोण, कि विवादित को अलग करने के मामले में

संविधान (99 वां संशोधन) अधिनियम,

संविधान में संशोधन करने की मांग की गई,

स्वचालित रूप से पुनर्जीवित करें। VI. निष्कर्ष -

254. अनुच्छेद 124 ए का गठन करता है

संविधान (99 वां संशोधन) अधिनियम, 2014। हड़ताली डाउन

अनुच्छेद 124 ए स्वतः ही अनुच्छेद को पूर्ववत कर देगा।

अनुच्छेद 124, 124 बी, 124 सी, 127, 128 में किए गए संशोधन,

217, 222, 224, 224 ए और 232। यह, सरल कारण के लिए,

कि बाद के अनुच्छेद केवल तभी स्थायी हैं जब अनुच्छेद 124 ए को बरकरार रखा जाए। अनुच्छेद 124 ए (1) में संविधान और

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियों की संरचना

आयोग (एनजेएसी)। इसके अवलोकन से पता चलता है कि यह रचित है निम्नलिखित में से:

(क) भारत के मुख्य न्यायाधीश, अध्यक्ष, पदेन; (ख) सर्वोच्च न्यायालय के दो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के बगल में

भारत के न्यायाधीश-सदस्य, पदेन;

(ग) केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री-सदस्य,

पदेन; (घ) नामित किए जाने वाले दो प्रतिष्ठित व्यक्ति-सदस्य।

यदि एन. जे. ए. सी. के सदस्यों में से किसी को शामिल किया जाता है

असंवैधानिक माने जाने पर अनुच्छेद 124 ए को लागू किया जाएगा

निरर्थक, पूरी तरह से। विद्वान वकील के हाथों प्रस्तुत प्रस्तुतियों के गुण-दोष पर निर्णय लेते समय प्रतिद्वंद्वी दलों के लिए, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खंड

(अनुच्छेद 124 ए (1) के ए) और (बी) में पर्याप्त प्रावधान नहीं है।

एन. जे. ए. सी. में न्यायिक घटक के लिए प्रतिनिधित्व, अनुच्छेद 124 ए (1) के खंड (ए) और (बी) को संरक्षित करने के लिए अपर्याप्त हैं चयन और सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं के मामले में न्यायपालिका की प्रधानता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [जगदीश सिंह खेहर, जे।]

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति (साथ ही स्थानांतरण भी)

वही तदनुसार, के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं "न्यायपालिका की स्वतंत्रता"। मैं स्वतंत्र रूप से आया हूँ

निष्कर्ष पर, अनुच्छेद 124 ए (1) का वह खंड (सी) अधिकार से बाहर है।

संविधान के प्रावधान, के समावेश के कारण

एन. जे. ए. सी. के पदेन सदस्य के रूप में कानून और न्याय के प्रभारी केंद्रीय मंत्री। अनुच्छेद 124 ए (1) का खंड (सी), मेरे विचार में,

"न्यायपालिका की स्वतंत्रता" के सिद्धांतों पर प्रभाव डालता है,

साथ ही, "शक्तियों का पृथक्करण"। यह भी निष्कर्ष निकाला गया है

मेरे द्वारा, अनुच्छेद 124 ए (1) का वह खंड (डी) जो

एन. जे. ए. सी. के सदस्यों के रूप में दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शामिल करना

संविधान के प्रावधानों के अधिकार से बाहर है, विभिन्न प्रकार के लिए

कारणों से। इसे "मूल" का उल्लंघन करने वाला भी माना गया है।

संविधान की संरचना। मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में, 1 सभी खंडों (ए) से (डी) का विचार है कि

अनुच्छेद 124 ए (1) को निरस्त किया जा सकता है। वही हैं,

तदनुसार मारा गया। अनुच्छेद के निरस्त होने को देखते हुए

124 ए (1), संपूर्ण संविधान (99 वां संशोधन) अधिनियम, 2014 को रद्द किया जा सकता है। तदनुसार इसी पर प्रहार किया जाता है।

अपनी संपूर्णता में नीचे, के प्रावधानों के अल्ट्रा वायर्स होने के रूप में

संविधान।

255. के हाथों में विवाद आगे बढ़ा

उत्तरदाताओं, प्रभाव के लिए, कि के प्रावधान

संविधान जिसे संशोधित करने की मांग की गई थी

विवादित संवैधानिक संशोधन, पुनर्जीवित नहीं होगा, भले ही

याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई चुनौती को स्वीकार कर लिया गया (और संविधान (99 वां संशोधन) अधिनियम, 2014 को दरकिनार कर दिया गया था) एक अलग शीर्ष के तहत विचार किया गया, सबसे सूक्ष्म विवरण के लिए, अग्रिम प्रस्तुतियों के संदर्भ में। मैंने निष्कर्ष निकाला है कि विवादित संविधान को अलग करने के साथ (99 वां संशोधन) अधिनियम, 2014, संविधान के प्रावधान इसके द्वारा संशोधित किए जाने की मांग की गई, स्वचालित रूप से पुनर्जीवित हो जाएगा, और पूर्व की स्थिति बहाल हो जाएगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

256. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग

अधिनियम, 2014 अन्य बातों के साथ-साथ अनुच्छेद 124 सी से निकलता है। इसमें कुछ नहीं है।

एन. जे. ए. सी. की अनुपस्थिति में स्वतंत्र अस्तित्व,

अनुच्छेद 124 ए (1) के तहत। चूंकि अनुच्छेद 124 ए और 124 सी में

एक स्वाभाविक परिणाम के रूप में, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014 भी निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है

एक तरफ, उसी के अनुसार इसे निरस्त कर दिया जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए

उपरोक्त, हमारे लिए यह आवश्यक नहीं था कि हमने जांच की हो

एन. जे. ए. सी. अधिनियम के व्यक्तिगत प्रावधानों के संवैधानिक अधिकार। आई. सभी समान हैं, अनुभागों को दी गई चुनौती की जांच की है

5, 6, 7 और उसके 8। मैंने निष्कर्ष निकाला है कि धारा 5, 6 और 8

एन. जे. ए. सी. अधिनियम के प्रावधान संविधान के प्रावधानों से परे हैं।

VII. उपलब्धि:

257.

ऑर्डर देने से पहले, मैं रिकॉर्ड करना चाहूंगा

हमारे द्वारा प्रदान की गई सबसे अच्छी सहायता के लिए मेरी सराहना

विद्वान सलाहकार जिन्होंने हमें दोनों पक्षों से संबोधित किया। मैं अपनी प्रशंसा की गहरी भावना भी व्यक्त करना चाहूंगा

सभी सहायक वकील, जो स्पष्ट रूप से पूरे दिल से थे

अपना समय और शक्ति मामले की तैयारी में लगा दी, और बहस करने वाले वकील को निर्देश देने में।
मैं अपने में विफल हो जाऊंगा

कर्तव्य, अगर मैं बेंच पर अपने सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त नहीं करता हूं,

साथ ही, न्यायपीठ की सहायता करने के लिए सहमत होने वाले वकील,

गर्मियों की छुट्टी। इसलिए मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं और

उनके प्रति मेरे हृदय की गहराइयों से ऋणी हूं।

ध्यान दें: मैं सभी उद्धरणों में दिए गए जोर

तत्काल निर्णय, मेरे हैं।

आदेश

चेलामेश्वर, जे. 1. बहुत महत्वपूर्ण और दूरगामी

के इस समूह में इस न्यायालय के विचार के लिए प्रश्न आते हैं

विषय हैं। संविधान की संवैधानिक वैधता (नब्बे)

नौवां संशोधन) अधिनियम, 2014 और राष्ट्रीय न्यायिक

*एड। ध्यान दें: माननीय न्यायमूर्ति जे. चेलामेश्वर ने अपने और माननीय न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल के लिए कहा।

1

सर्वोच्च न्यायालय

अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [चेलामेश्वर, जे।]

नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014 चुनौती के दायरे में है।

2. जब इन मामलों को प्रारंभिक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था

21.04.2015 पर श्री फली एस. ने आपत्ति जताई थी।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि यह न्यायमूर्ति जगदीश सिंह के लिए अनुचित है
में कार्यवाही में भाग लेंगे

खेहर अध्यक्षता के रूप

इस पीठ के न्यायाधीश। आपत्ति तथ्यों पर आधारित है।

: इस न्यायालय के तीसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होने के नाते,

न्यायमूर्ति खेहर प्रस्तावित कॉलेजियम के सदस्य हैं।

दूसरे न्यायाधीशों के मामले के तहत 'प्रयोग' महत्वपूर्ण है

न्यायाधीशों के चयन के मामले में संवैधानिक शक्ति

इस न्यायालय के साथ-साथ इस देश के उच्च न्यायालय;

विवादित कानून, जब तक वह होने की स्थिति प्राप्त नहीं करता है
न्यायाधीश न्यायमूर्ति खेहर होंगे।

इस न्यायालय के तीसरे सबसे वरिष्ठ

ऐसी शक्ति का आनंद लेना बंद कर दें; और इसलिए, एक संभावना है

उसका निष्पक्ष न होना।

3. जब आपत्ति उठाई गई, तो विभिन्न वकीलों ने

दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित होकर अलग-अलग व्यक्त किया गया

भागीदारी की उपयुक्तता के बारे में दृष्टिकोण

इन कार्यवाही में न्यायमूर्ति खेहर। इसलिए हम बुलाते हैं
को सटीक रूप से बताने के लिए

इस मामले में उपस्थित विद्वान वकील

प्रश्न पर उनके संबंधित दृष्टिकोण और सहायता

श्री फली एस. द्वारा उठाई गई आपत्ति के सही उत्तर पर।

नरीमन।

4. मामला फिर से 22.04.2015 पर सूचीबद्ध किया गया था जिस पर

तारीख श्री नरीमन ने एक संक्षिप्त लिखित बयान 2 दाखिल किया

1 उच्चतम न्यायालय के

अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ, (1993) 4 एस. सी. सी. 441

2 संवैधानिक चुनौती के इन मामलों की सुनवाई करने वाली इस पीठ में पीठासीन न्यायाधीश की स्थिति
इसके अनुरूप नहीं है (और स्पष्ट रूप से इसके साथ विरोधाभास है)। कॉलेजियम के सदस्य के रूप
में उनकी स्थिति; और इस तरह से देखे जाने की संभावना है; हमेशा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यदि
संविधान संशोधन और उससे संबंधित कानून को संवैधानिक रूप से वैध माना जाता है और बरकरार रखा
जाता है, तो वर्तमान पीठासीन न्यायाधीश अब कॉलेजियम का हिस्सा नहीं होंगे-कॉलेजियम, यह स्वीकार किया
जाना चाहिए कि यह महत्वपूर्ण संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करता है।

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उन कारणों के लिए जो उनके अनुसार इसे अनुचित बनाते हैं

न्यायमूर्ति खेहर वर्तमान पीठ की अध्यक्षता करेंगे।

5. दूसरी ओर, श्री अरविंद पी. दातार, विद्वान वरिष्ठ

याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वकील ने विस्तार से बताया

न्यायाधीश को किसी विशेष मामले की सुनवाई से खुद को अलग करना और
में कानून के स्थापित सिद्धांतों के प्रकाश में

प्रस्तुत किया कि इस

यह मानते हुए कि न्यायमूर्ति खेहर की सुनवाई में कोई अनियमितता नहीं है
ये मामले हैं और न ही उसे ऐसा करने की कोई आवश्यकता है।

6. श्री मुकुल रोहतगी, विद्वान महान्यायवादी

श्री नरीमन के सुझाव का जोरदार विरोध किया और

प्रस्तुत किया कि कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मांग करता है

न्यायमूर्ति खेहर का अलग होना और न ही भारत संघ का कोई

इन मामलों की सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति खेहर पर आपत्ति।

7. श्री हरीश एन. साल्वे और श्री के. के. वेणुगोपाल, विद्वान

वरिष्ठ वकील जिन्होंने विभिन्न की ओर से उपस्थित होने का प्रस्ताव रखा

राज्यों ने भी विद्वान महान्यायवादी के रुख का समर्थन किया

और के समर्थन में स्वतंत्र प्रस्तुतियाँ कीं

निष्कर्ष।

8. मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद, हम आए

सर्वसम्मत निष्कर्ष कि कानून का कोई सिद्धांत नहीं है जो

न्यायमूर्ति खेहर को कार्यवाही से अलग करने का आदेश देता है। हमने दिनांकित कार्यवाही में पीठ के निष्कर्ष
को दर्ज किया 22.04.2015 और संकेत दिया कि समय की कमी के कारण,

निष्कर्ष के कारण बाद में सामने आएंगे 3

3 जहां तक प्रासंगिक है, दिनांकित 22.04.2015 आदेश इस प्रकार है:

"प्रारंभिक आपत्ति, क्या न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर को ऐसा करना चाहिए

इस पीठ की अध्यक्षता करने वाले, इस न्यायालय के चौथे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होने के कारण, जो
कॉलेजियम के सदस्य भी हैं, याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए थे। याचिकाकर्ताओं और उत्तरदाताओं के लिए
विद्वान वकील द्वारा विस्तृत प्रस्तुतियाँ की गईं। सभी विद्वान वकीलों को सुनने के बाद, हमारी सर्वसम्मत राय
है कि हम कानून में ऐसा कोई कारण नहीं देखते हैं जिसके लिए न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर को मामले की
सुनवाई से खुद को अलग करने की आवश्यकता हो। कारणों का पालन किया जाएगा।

नियम जारी करें "। सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. /चेलामेश्वर, जे।/

9. शुरुआत में, हमें यह दर्ज करना चाहिए कि प्रत्येक विद्वान वकील जिन्होंने न्यायमूर्ति खेहर की भागीदारी पर आपत्ति जताई इन कार्यवाहियों ने इस आपत्ति को विशिष्टता पर आधारित किया कानून के प्रस्ताव। जबकि श्री नरीमन ने इसे जमीन पर रख दिया।

अनुचितता के बारे में श्री संतोष पॉल ने इस सिद्धांत का आह्वान किया पक्षपात का, उसके परस्पर विरोधी हितों के आधार पर-एक

कॉलेजियम के सदस्य के रूप में उनकी क्षमता में और दूसरे में संवैधानिक वैधता की जांच करने के लिए एक न्यायाधीश के रूप में उनकी क्षमता ऐसे प्रावधान जो कॉलेजियम प्रणाली को विस्थापित करना चाहते हैं। वास्तव में, कुछ याचिकाकर्ताओं की राय है कि न्यायमूर्ति खेहर को अलग होना चाहिए।

10. यह एक सभ्य कानूनी व्यवस्था के स्थापित सिद्धांतों में से एक है। प्रणाली कि एक न्यायाधीश को निष्पक्ष होना आवश्यक है। कहा जाता है कि लोकतंत्र की पहचान निष्पक्ष लोकतंत्र का अस्तित्व है। न्यायाधीश।

11. यह सब री में एक लैटिन उक्ति निमो जूडेक्स के साथ शुरू हुआ। सुआ जिसका शाब्दिक अर्थ है-कि कोई भी व्यक्ति अपने कार्यकाल में न्यायाधीश नहीं होगा। अपना ही कारण। एक अन्य नियम है जिसके लिए एक न्यायाधीश की आवश्यकता होती है - निष्पक्ष रहें। सैद्धांतिक आधार थॉमस द्वारा समझाया गया है। हॉब्स ने प्रकृति के अपने ग्यारहवें नियम में लिखा है। उन्होंने कहा, "अगर कोई आदमी मनुष्य और मनुष्य के बीच न्याय करने के लिए विश्वास किया जाता है, यह एक नियम है प्रकृति का नियम कि वह उनके बीच समान व्यवहार करता है। बिना इसके

कि, पुरुषों के विवादों को निर्धारित नहीं किया जा सकता है लेकिन यह निर्णय में आंशिक है।

युद्ध। इसलिए उन्होंने कहा कि

वह झूठ बोलता है, पुरुषों को न्यायाधीशों और मध्यस्थों के उपयोग से रोकने के लिए; परिणामस्वरूप, प्रकृति के मौलिक नियम के विरुद्ध, है

और

युद्ध का कारण "।

12. ग्रांट हैमंड, न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश

न्यूजीलैंड की अपील और एक शिक्षाविद, अपनी पुस्तक शीर्षक में

"न्यायिक अस्वीकृति" 5 ने अस्वीकृति के कानून पर सिद्धांतों का पता लगाया 4 न्यू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इंग्लिश (एक न्यायाधीश का कार्य) के अनुसार अभिव्यक्ति 'अलग' एक मामले से खुद को माफ करने के लिए क्योंकि

मतलब

-

निष्पक्षता की कमी के कारण हितों का संभावित टकराव।

5 आर. ग्रांट हैमंड, न्यायिक बहिष्कार: सिद्धांत, प्रक्रिया और समस्याएं, (हार्ट प्रकाशन, 2009)।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

जैसा कि इंग्लैंड में निम्नलिखित शब्दों में विकसित किया गया है:

"प्रारंभिक अंग्रेजी आम की केंद्रीय विशेषता

अलग होने पर कानून सरल और अत्यधिक दोनों था

बाधित: एक न्यायाधीश को केवल प्रत्यक्ष आर्थिक ब्याज के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है। आज क्या होगा?

जिसे 'पूर्वाग्रह' कहा जाता है, जो आसानी से सबसे विवादास्पद है

अयोग्यता के लिए आधार, पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था न्यायाधीशों को अलग करने का आधार, हालांकि यह नहीं था

जुरी सदस्यों के संबंध में पूरी तरह से खारिज कर दिया गया।

यह अपेक्षाकृत स्पष्ट रूप से विपरीत था

परिष्कृत कैनेन कानून, जो अलग करने के लिए प्रदान करता है

यदि किसी न्यायाधीश पर पक्षपात का संदेह था क्योंकि

किसी व्यक्ति के साथ संबंध, आत्मीयता, मित्रता या शत्रुता पार्टी, या उसकी अधीनस्थ स्थिति के कारण

एक पार्टी या क्योंकि वह एक पार्टी का था या रहा था अधिवक्ता "।

उन्होंने यह भी बताया कि इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिका में, यह विषय कानून द्वारा कवर किया गया है।

13. डाइम्स वी। ग्रैंड जंक्शन कैनाल के मालिक,

(1852) 10 ई. आर. 301, सबसे शुरुआती मामलों में से एक है जहाँ

न्यायाधीश की अयोग्यता के प्रश्न पर विचार किया गया। द. इसका आधार यह था कि इस मामले में उनकी कुछ आर्थिक रुचि थी।

हम दोनों के बीच विवाद के विवरण से चिंतित नहीं हैं

मामले के पक्षकार। लॉर्ड चांसलर कोटनहैम ने सुना कुलपति के आदेश के खिलाफ अपील की और आदेश की पुष्टि की। आदेश प्रतिवादी कंपनी के पक्ष में गया।

एक साल बाद, डाइम्स को पता चला कि लॉर्ड चांसलर कोटनहैम के प्रतिवादी कंपनी में शेयर थे। वह.

रानी के हस्तक्षेप के लिए याचिका दायर की। मुकदमे में एक था

लंबा और उतार-चढ़ाव वाला इतिहास, जिसका विवरण भौतिक नहीं है

हमारे लिए। आखिरकार मामला हाउस ऑफ लॉर्ड्स तक पहुंच गया। द.

सदन ने डाइम्स की अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया कि

लॉर्ड चांसलर के आदेश को दरकिनार करने से अभी भी सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड होंगे

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [चेलामेश्वर, जे।]

कुलपतियों के आदेश को लॉर्ड चांसलर के रूप में अक्षुण्ण रखें

उन्होंने केवल कुलपति के आदेश की पुष्टि की थी। हालांकि,

हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने माना कि लॉर्ड कोटनहैम की भागीदारी

न्यायनिर्णायक प्रक्रियामें उचित नहीं छल। हालांकि लॉर्ड कैम्पबेल ने कहा:

"कोई भी यह नहीं सोच सकता कि लॉर्ड कोटनहैम ऐसा कर सकते थे।

सुदूरतम स्तर पर ब्याज से प्रभावित होना

उन्हें इस बात की चिंता थी: लेकिन, मेरे स्वामी, यह है

अंतिम महत्व यह है कि यह उक्ति कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के कारण में न्यायाधीश नहीं होना चाहिए, पवित्र माना जाए। और यह कि

किसी ऐसे कारण तक सीमित नहीं रहना चाहिए जिसमें वह एक पार्टी, लेकिन एक कारण के लिए लागू होता है जिसमें वह एक है

ब्याज। यह सभी घटिया लोगों के लिए एक सबक होगा।

न्यायाधिकरण न केवल अपने आदेशों में इसका ध्यान रखेंगे वे अपने व्यक्तिगत हित से प्रभावित नहीं होते हैं,

लेकिन इस तरह के तहत श्रम की उपस्थिति से बचने के लिए

एक प्रभाव "।

14. द्वारा निर्धारित सिद्धांत का सारांश

उपर्युक्त मामले में, हैमंड ने निम्नानुसार देखा:

" 'ना-आर्थिक ब्याज' सिद्धांत जैसा कि व्यक्त किया गया है

डाइम्स में एक न्यायाधीश को स्वतः होने की आवश्यकता होती है

अयोग्य घोषित किया जाता है जब न तो वास्तविक पूर्वाग्रह होता है और न ही

यहाँ तक कि उस तरफ से पूर्वाग्रह की आशंका भी

न्यायाधीश। मौलिक दार्शनिक आधार

इसलिए डाइम्स को हितों के टकराव के दृष्टिकोण पर आधारित किया गया है।

लूट की साजिश रचने का अपराध और उसे सजा सुनाई गई थी
वर्ष का कारावास। यह एक मुकदमा था

विचारण न्यायालय द्वारा पंद्रह

जूरी द्वारा। दोषसिद्धि की घोषणा के बाद, ट्रायल कोर्ट के संज्ञान में लाया गया कि जूरी सदस्यों में से एक पड़ोसी था

दोषी का। दोषी ने अपील न्यायालय की सर्वोच्च अदालत की रिपोर्ट में अपील की

[2015] 13 एस सी आर।

उन आधारों में से एक जिसके आधार पर दोषसिद्धि
असफल। चुनौती दी गई थी कि, इस तथ्य को देखते हुए कि एक
जूरर्स ने दोषी का पड़ोसी होने के नाते एक संभावना प्रस्तुत की
अयोग्यता निर्धारित करने के लिए दो अलग-अलग परीक्षणों का प्रस्ताव पक्षपात के आधार पर एक
न्यायाधीश का:

(1) " वास्तविक खतरे का परीक्षण; और

(2) " उचित संदेह परीक्षण।
अपील न्यायालय ने आवेदन करके दोषसिद्धि की पुष्टि की
"वास्तविक खतरा" परीक्षण।

16. इस मामले को आगे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ले जाया गया।

17. लॉर्ड गोफ ने देखा कि अधिकारियों की एक शृंखला है
जो न केवल बड़ी संख्या में हैं, बल्कि उनमें विस्मयकारी भी हैं।
प्रभाव "। डाइम्स (ऊपर) में निर्णय का विश्लेषण करने के बाद, लॉर्ड गोफ आयोजित:

" ऐसे मामले में, इसलिए, यह न केवल अप्रासंगिक है

न्यायाधिकरण, लेकिन जाँच का कोई सवाल ही नहीं है,
वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से, क्या वहाँ था

पक्षपात की कोई वास्तविक संभावना, या कोई उचित

विशेष मामले के तथ्यों पर पक्षपात का संदेह।

रुचि की प्रकृति ऐसी है कि जनता
न्याय के प्रशासन में विश्वास की आवश्यकता है

कि निर्णय नहीं टिकना चाहिए। "

दूसरे शब्दों में, जहाँ एक न्यायाधीश का आर्थिक हित होता है,
आगे कोई जाँच नहीं की गई कि क्या कोई "वास्तविक खतरा" था या
"पक्षपात का "उचित संदेह" किया जाना आवश्यक है।
लेकिन अन्य मामलों में, इस तरह की जाँच की आवश्यकता है और प्रासंगिक
परीक्षण "वास्तविक खतरा" परीक्षण है।

"लेकिन अन्य मामलों में, जांच को निर्देशित किया जाता है
सवाल यह है कि क्या उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं की इतनी डिग्री थी-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [चेलामेश्वर, जे।]

न्यायाधिकरण की ओर से पक्षपात की संभावना है कि
प्रश्न विभिन्न प्रकार से उत्पन्न हो सकता है परिस्थितियाँ। इनमें ऐसे मामले शामिल हैं जिनमें
न्यायाधिकरण के सदस्य की रुचि है
कार्यवाही का परिणाम, जो एक से कम है
प्रत्यक्ष आर्थिक ब्याज। ऐसी रुचियाँ भिन्न हो सकती हैं। व्यापक रूप से उनकी प्रकृति में, उनके प्रभाव
में, और कार्यवाही की विषय वस्तु के लिए उनकी प्रासंगिकता में;
और ऐसा कोई नियम नहीं है कि इस तरह का अधिकार ब्याज स्वतः सदस्य को अयोग्य घोषित
कर देता है।

न्यायाधिकरण की बैठक से। हर मामला ऐसा होता है
अपने तथ्यों पर विचार करें।

18. विद्वान न्यायाधीश ने विभिन्न महत्वपूर्ण सीए की जांच की

उन्होंने विषय लिया और अंत में निष्कर्ष निकाला:

वास्तविक संभावना के बजाय वास्तविक खतरे के संदर्भ में परीक्षण, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अदालत
सोच रही है पूर्वाग्रह की संभावना के बजाय संभावना की शर्तें।

तदनुसार, प्रासंगिक का पता लगाने के बाद

परिस्थितियों में, अदालत को खुद से पूछना चाहिए कि क्या, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए,
एक था

संबंधित पक्ष की ओर से पूर्वाग्रह का वास्तविक खतरा विचाराधीन न्यायाधिकरण के सदस्य, इस
अर्थ में कि

वह अनुचित रूप से सम्मान कर सकता है (या अनुचित रूप से माना गया है)

पक्ष या नापसंद के साथ, किसी पक्ष का मामला

उनके द्वारा विचाराधीन मुद्दा "।

19. लॉर्ड वूल्फ अपने सेपा में लॉर्ड गॉफ से सहमत थे।

मन में। उन्होंने कहा:

"केवल एक स्थापित विशेष श्रेणी है और
कि वहाँ मौजूद है जहाँ न्यायाधिकरण के पास एक आर्थिक या
विषय वस्तु में स्वामित्व हित
कार्यवाही जैसा कि डाइम्स v में है।

ग्रैंड सुपर कोर्ट रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर. के मालिक
जंक्शन कैनाल, 3 एच. एल. केस 759। अदालतें
कोई अन्य बनाने से पहले बहुत संकोच करना चाहिए
विशेष श्रेणी क्योंकि यह तुरंत बनाएगा
इस बारे में अनिश्चितता कि इसके मापदंड क्या हैं
श्रेणी और किस परीक्षा में आवेदन किया जाना है
उस श्रेणी का मामला। वास्तविक खतरे का परीक्षण काफी है।
सही उत्तर देने और सुनिश्चित करने में सक्षम
कि न्याय की शुद्धता बनाए रखी जाती है
स्थितियों की सीमा जहाँ पूर्वाग्रह मौजूद हो सकता है।

20. सारतः, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ऐसे मामलों में जहां न्यायाधीश का आर्थिक हित इसके परिणाम में है -

यह जांच करना आवश्यक है कि क्या इस तरह के ब्याज से "वास्तविक खतरा" पैदा होता है या "उचित संदेह" पैदा होता है। जिन मामलों में अन्य ब्याज, यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण कि क्या न्यायाधीश है

मामले की सुनवाई के लिए अयोग्य ठहराया जाना "वास्तविक खतरे" का परीक्षण है।

21. पिनोचेट मामले में एक और श्रेणी जोड़ी गई

एक न्यायाधीश के लिए स्वचालित अयोग्यता के मामले। पिनोशे,

अपने कार्यकाल के दौरान अपने आचरण के लिए इंग्लैंड से प्रत्यर्पित कार्यालय में। मुद्दा यह था कि क्या पिनोशे इसके हकदार थे

न्यायालय की अनुमति के साथ। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने माना कि पिनोशे को ऐसी कोई छूट नहीं है। इसके बाद यह पता चला कि पिनोशे मामले की सुनवाई करने वाले बोर्ड के सदस्यों में से एक लॉर्ड हॉफमैन एक निदेशक थे और

एक कंपनी का अध्यक्ष (जिसे A.I.C.L के रूप में जाना जाता है) जो निकटता से था
 एमनेस्टी इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ है। एक आवेदन किया गया था
 हाउस ऑफ लॉर्ड्स को पहले के फैसले को दरकिनार करने के लिए
 लॉर्ड हॉफमैन की ओर से पूर्वाग्रह का आधार।

6 रेजिना वी। बो स्ट्रीट मेट्रोपॉलिटन स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट, पूर्व पक्ष पिनोचेट उगार्टे, (1999) 1 सभी ई. आर.
 577 सर्वोच्च न्यायालय-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [चेलामेश्वर, जे।]

22. हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने निम्नलिखित की जांच की:

पत्थरों;

(i) क्या लॉर्ड हॉफमैन का एमनेस्टी के साथ संबंध है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्हें स्वचालित होने की आवश्यकता थी
 अयोग्य?

(ii) क्या इस प्रश्न की जांच की जाए कि क्या कारण है।

लॉर्ड हॉफमैन का एमनेस्टी के साथ संबंध
 अंतरराष्ट्रीय ने एक वास्तविक खतरा पैदा किया या एक
 -उचित आशंका कि उसका निर्णय पक्षपातपूर्ण है
 - क्या यह आवश्यक है?

(iii) क्या इससे कोई फर्क पड़ा कि लॉर्ड हॉफमैन थे?

केवल एमनेस्टी इंटरनेशनल से जुड़ी कंपनी का एक सदस्य जो वास्तव में सुरक्षा में रुचि रखता था
 सीनेटर पिनोचे का प्रत्यर्पण?

23. लॉर्ड विल्किंसन ने उन सिद्धांतों का सारांश दिया जिन पर

डीजे को एक मामले की सुनवाई के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। लॉर्ड विल्किंसन के अनुसार -

"मूल सिद्धांत यह है कि एक आदमी नहीं कर सकता है

अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश बनें। यह सिद्धांत, के रूप में अदालतों द्वारा विकसित, दो बहुत समान हैं लेकिन

समान प्रभाव नहीं। सबसे पहले इसे लागू किया जा सकता है

वस्तुतः:: यदि कोई न्यायाधीश वास्तव में मुकदमे का पक्षकार है या

इसके परिणाम में वित्तीय या स्वामित्व हित है

तब वह वास्तव में अपने स्वयं के मामले में एक न्यायाधीश के रूप में बैठा है।

उस मामले में, केवल तथ्य यह है कि वह एक पक्ष है

इसका परिणाम उसके स्वचालित होने का कारण बनने के लिए पर्याप्त है अयोग्यता। दूसरा आवेदन

और इसके परिणाम में कोई वित्तीय हित नहीं है, लेकिन किसी अन्य तरीके से उसका आचरण या व्यवहार हो सकता है

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर. के लिए इस संदेह को जन्म देना कि वह निष्पक्ष नहीं है।

एक पार्टी के साथ उनकी दोस्ती के कारण उदाहरण।

यह दूसरे प्रकार का मामला सख्ती से नहीं बोल रहा है
इस सिद्धांत का अनुप्रयोग कि एक आदमी को नहीं होना चाहिए

अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश, क्योंकि न्यायाधीश नहीं करेगा

आम तौर पर स्वयं लाभान्वित होते हैं, लेकिन एक प्रदान करते हैं
निष्पक्ष होने में विफल रहने से दूसरे के लिए लाभ।

मेरे निर्णय में, यह मामला पहले मामले में आता है।

मामले की श्रेणी, अर्थात्। जहाँ न्यायाधीश को अयोग्य ठहराया जाता है

क्योंकि वह अपने मामले में एक न्यायाधीश है। ऐसे में

मामला, एक बार यह दिखाया जाता है कि न्यायाधीश स्वयं एक है

कारण के लिए पक्षकार, या इसके लिए एक प्रासंगिक हित है

विषय वस्तु, वह बिना किसी के अयोग्य घोषित किया जाता है

उसे अयोग्य ठहराने के लिए पर्याप्त है जब तक कि उसने
पर्याप्त प्रकटीकरण।

आई.

और सवाल तैयार किया;

..... तब सवाल यह उठता है कि क्या

वित्तीय मुकदमेबाजी, वित्तीय मुकदमे के अलावा कुछ भी

परिणाम में स्वामित्व हित पर्याप्त है।

स्वचालित रूप से एक आदमी को बैठने से अयोग्य घोषित करने के लिए

कारण में न्यायाधीश "।

उन्होंने कहा कि हालांकि पहले के सभी मामलों को निपटा लिया गया है

आर्थिक आधार पर स्वतः अयोग्यता के साथ

ब्याज, ऐसा सीमित करने के लिए सिद्धांत रूप में कोई अच्छा कारण नहीं है

स्वतः अयोग्यता "।

24. लॉर्ड विल्किंसन ने निष्कर्ष निकाला कि एमनेस्टी इंटरनेशनल

और इसकी सहयोगी कंपनी जिसे A.I.C.L. के रूप में जाना जाता है, के पास एक गैर था

आर्थिक हित ने स्थापित किया कि सीनेटर पिनोशे नहीं थे प्रत्यर्पण की प्रक्रिया से प्रतिरक्षित।

उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि,

"..... मुद्दा धन या आर्थिक सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं से संबंधित नहीं है-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [चेलामेश्वर, जे।]

लाभ लेकिन कारण के प्रचार से संबंधित है,

एक न्यायाधीश को अयोग्य ठहराने का तर्क उतना ही लागू होता है जितना कि न्यायाधीश के निर्णय से एक कारण को बढ़ावा मिलेगा जिसमें

न्यायाधीश एक पक्ष के साथ मिलकर शामिल होता है "

25. अंत में, अंतिम प्रश्न पर चर्चा करते हुए,

क्या यह तथ्य कि लॉर्ड हॉफमैन केवल एक सदस्य थे

A.I.C.L. लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल के किसी भी सदस्य ने ऐसा नहीं किया

सिद्धांत में अंतर, लॉर्ड विल्किंसन ने राय दी कि भले ही एक न्यायाधीश का परिणाम में वित्तीय हित न हो

एक मामले का, लेकिन किसी अन्य तरीके से उसका आचरण या व्यवहार हो सकता है इस संदेह को जन्म दें कि वह निष्पक्ष नहीं है और माना कि यदि

न्यायपालिका की पूर्ण निष्पक्षता को बनाए रखना है, एक ऐसा नियम होना चाहिए जो स्वचालित रूप से एक न्यायाधीश को अयोग्य घोषित कर दे

जो व्यक्तिगत रूप से या किसी कंपनी के निदेशक के रूप में उसी उद्देश्य को बढ़ावा देने में शामिल है

संगठन के रूप में मुकदमे का एक पक्ष है। जुर्माने की कोई गुंजाइश नहीं है।

भेद-भाव। मामले के इस पहलू पर पी. डी. में विचार किया गया था। दिनाकरन मामला 7.

26. उपरोक्त निर्णयों से, हमारी राय में,

निम्नलिखित सिद्धांत उभरते हैं;

(i) यदि किसी न्यायाधीश का एक के परिणाम में वित्तीय हित है

मामला, वह स्वतः सुनवाई से अयोग्य हो जाता है
मामला।

(ii) उन मामलों में जहां मामले में न्यायाधीश का हित है।

वित्तीय के अलावा, तो अयोग्यता नहीं है

स्वचालित लेकिन एक जांच की आवश्यकता है कि क्या

इस तरह के हित का अस्तित्व न्यायाधीश को अयोग्य ठहराता है।

"वास्तविक" के सिद्धांत पर या तो प्रकाश में परीक्षण किया गया

पूर्वाग्रह का खतरा या "उचित आशंका"।

71 पी. डी. दिनाकरन (1) v. न्यायाधीश जांच समिति, (2011) 8 एस. सी. सी. 380, पैरा 49 से 53।

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(iii) पिनोचेट मामले में एक नई श्रेणी जोड़ी गई अर्थात

न्यायाधीश स्वतः सुनवाई से अयोग्य हो जाता है

मामला जहाँ न्यायाधीश किसी ऐसे कारण में रुचि रखता है जो मामले के एक पक्ष द्वारा पदोन्नत किया जा रहा है।

27. यह किसी का मामला नहीं है कि, मामले में, न्याय
खेहर का कोई आर्थिक ब्याज या कोई अन्य ब्याज गिर रहा था।
उपर्युक्त श्रेणियों में से दूसरी के तहत। के द्वारा
मामले की प्रकृति, ऐसी कोई रुचि बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं हो सकती है।

28. सवाल यह है कि क्या कानून का सिद्धांत निर्धारित किया गया है।
पिनोशे के मामले में आकर्षित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, क्या न्याय
खेहर को किसी भी हित को साझा करने वाला कहा जा सकता है जिसमें से एक
के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के कारण को बढ़ावा देने का दावा एक निष्पक्ष और स्वतंत्र
न्यायपालिका। फर्क सिर्फ इतना है कि
पक्षों के बीच राय उस प्रक्रिया के बारे में है जिसके द्वारा
ऐसा परिणाम प्राप्त करना है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि
कि न्यायमूर्ति खेहर किसी भी हित को साझा करते हैं जिसमें से कोई एक

29. श्री नरीमन के निवेदन का निहितार्थ यह है कि न्यायमूर्ति खेहर अभियुक्त को पकड़ने के लिए पूर्व-
निर्धारित होंगे। कानून अमान्य होना। हम स्थिति को समझने में विफल हैं
याचिकाकर्ता। यदि याचिकाकर्ताओं की ऐसी आशंका सच हो जाती है, तो लाभार्थी केवल याचिकाकर्ता ही
होंगे। शिकायत,
यदि कोई हो, तो इस आधार पर उत्तरदाताओं की ओर से होना चाहिए।

30. संघ की ओर से उपस्थित विद्वान महान्यायवादी
भारत सरकार ने एक जोरदार बयान दिया कि भारत संघ
पीठ के पीठासीन न्यायाधीश के रूप में मामले की सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति खेहर को कोई आपत्ति नहीं
है।

31. हमारे ध्यान में कोई मिसाल नहीं लाई गई है, जहाँ
अदालतों ने पक्षपात के लाभार्थी के उदाहरण पर फैसला सुनाया न्यायनिर्णायक का भाग, कि कोई
निर्णय या प्रशासनिक सर्वोच्च न्यायालय-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन v का समर्थन करता है।

यू. ओ. आई. /चेलामेश्वर, जे।/

निर्णय या तो अमान्य है या पूर्वाग्रह के आधार पर अमान्य है। उस पर

दूसरी ओर, यह कानून का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि

न्यायनिर्णायक के पक्षपात के आधार पर आपत्ति को माफ किया जा सकता है।

न्यायालयों ने आम तौर पर इस तरह की आपत्तियों पर विचार नहीं किया
से।

पीडित पक्ष द्वारा देर

माफ किया जा सकता है, और यह ऐसा भी हो सकता है जहाँ
अयोग्यता वैधानिक है। अदालत आम तौर पर

इस बात पर जोर देते हुए कि आपत्ति को जल्द से जल्द लिया जाएगा

पक्षपातपूर्ण पार्टी उन तथ्यों को जानती है जो अधिकार देते हैं

उसे आपत्ति करने के लिए। यदि, उसके बाद उसे या उसके सलाहकारों को पता चलता है

अयोग्यता, उन्होंने कार्यवाही की अनुमति दी

बिना विरोध के जारी रखें, उन्हें आयोजित किया जाता है

उनकी आपत्ति को माफ कर दिया और दृढ़ संकल्प नहीं कर सकता

चुनौती दी जाए "। 9.

हमारी राय में, उपरोक्त सिद्धांत का निहितार्थ है -

कि केवल एक पक्ष जिसे प्रतिकूल नुकसान हुआ है या होने की संभावना है

की ओर से पक्षपात की संभावना के कारण निर्णय

न्यायनिर्णायक आपत्ति उठा सकता है।

32. श्री नरीमन द्वारा वर्णित महत्वपूर्ण शक्ति

केवल कॉलेजियम के सदस्यों के लिए नहीं है, लेकिन

इस न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश में निहित है जिसे बुलाया जा सकता है

विभिन्न प्रस्तावों के संबंध में अपनी राय व्यक्त करने के लिए

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य न्यायाधीशों या

इस न्यायालय के न्यायाधीश, जबकि कॉलेजियम के सदस्य हैं

के संबंध में ऐसी "महत्वपूर्ण शक्ति" का प्रयोग करने की आवश्यकता है

एक वेकफील्ड स्थानीय स्वास्थ्य बोर्ड बनाम। वेस्ट राइडिंग एंड ग्रिम्सबी रेल कंपनी (1865) 1 क्यू. बी. 84।

99 आर. बी. बाइल्स एक्स पी. हॉलिज (1912) 77 जे. पी. 40; आर. बी. नेल्सवर्थ लाइसेंसिंग जस्टिस एक्स पी।
बर्ड [1953] 1 डब्ल्यू. एल. आर. 1046; आर बी। लिलीडेल मजिस्ट्रेट कोर्ट एक्स पी। सिक्कोन [1973] बी. आर.

122; और आर. वी. देखें। एंटरिम जस्टिस [1895] 2 आई. आर. 603; टोलपुट (एच.) एंड कंपनी लिमिटेड बनाम मोल [1911] 1 के. बी. 836; कोरिगन बनाम। आयरिश भूमि आयोग [1977] आई. आर. 317।

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उपर्युक्त की प्रत्येक नियुक्ति -

श्रेणियों में, इस न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से अपेक्षित है -

ऐसी "महत्वपूर्ण शक्ति" का प्रयोग, कम से कम उस उच्च न्यायालय में या उससे नियुक्तियों के संबंध में जिसके साथ वे थे।

इससे पहले वे या तो न्यायाधीशों या मुख्य न्यायाधीशों के रूप में जुड़े थे। श्री नरीमन के तर्क को अगर स्वीकार कर लिया जाता है तो यह सब बदल जाएगा।

इस न्यायालय के न्यायाधीशों ने वर्तमान सुनवाई से अयोग्य घोषित कर दिया

विवाद। परिणाम कानूनी रूप से "के सिद्धांत" द्वारा अनुमत नहीं है

आवश्यकता "।

33. उपर्युक्त कारणों से, हम अस्वीकार करते हैं

निवेदन कि न्यायमूर्ति खेहर को पद से हट जाना चाहिए

कार्यवाही।

न्याय

चेलामेश्वर, जे. 1. हम सदस्य हैं

न्यायपालिका दूसरे से हमारी मुक्ति में खुश और प्रफुल्लित है

राज्य के दो अंग। लेकिन क्या हमने एक विकल्प विकसित किया है?

संवैधानिक नैतिकता हमें सिद्धांत से मुक्त करने के लिए नियंत्रण और संतुलन, हमें नियंत्रण में रखने के लिए पर्याप्त मजबूत

ऐसी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से? क्या हमने प्राप्त किया है?

हमारी बुद्धि परिपक्वता और प्रकृति से अधिक स्वतंत्रता

पच सकता है? क्या हम वास्तव में इस बीमारी से आगे निकल गए हैं?

निर्भरता या केवल इसे राजनीतिक से न्यायिक में स्थानांतरित कर दिया गया

पदानुक्रम? क्या हम इस तरह के नैतिक और संवैधानिक स्तर के करीब हैं?

नागरिक समाज को भयभीत करने वाली अव्यवस्था प्रकृति माँ के पास वापस चली जाती है

या हमें अनुशासित करने के लिए कोई अन्य कम स्वास्थ्यवर्धक अधिकार? है।

6 तारीख से न्यायिक शाखा द्वारा अर्जित सभी स्वतंत्रताएँ

अक्टूबर, 1993 एक मिथक रहा-भाई-भतीजावाद के लिए एक सौम्योक्ति अन्य बातों के साथ-
साथ औसत दर्जे को बढ़ावा देना या उससे भी कम

कभी-कभी-इस बहस के केंद्र में सवाल होते हैं ऐसे मामलों का समूह जिनके द्वारा याचिकाकर्ता
सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन v की वैधता पर सवाल उठाते हैं।

यू. ओ. आई. [चेलामेश्वर, जे।]

संविधान (99 वां संशोधन) अधिनियम, 2014 और राष्ट्रीय

न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014 (इसके बाद) सुविधा के लिए "संशोधन" और "अधिनियम"
के रूप में संदर्भित)।

2. वर्तमान विवाद को समझने के लिए, एक नज़र

भारत के संविधान के प्रासंगिक प्रावधान, जैसा कि वे थे

आक्षेपित संशोधन से पहले और बाद में, आवश्यक है।

संशोधन से पहले

अनुच्छेद 124। की स्थापना और संविधान

सुप्रीम कोर्ट

(1) भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसका गठन किया जाएगा
भारत के मुख्य न्यायाधीश का और, कानून द्वारा संसद तक

तीस से अधिक नहीं की एक बड़ी संख्या निर्धारित करता है

न्यायाधीश।

(2) उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी।

राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों के साथ परामर्श करने के बाद अपने हाथ और
मुहर के तहत वारंट द्वारा

राज्यों में न्यायालय और उच्च न्यायालयों के रूप में
राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझ सकते हैं और पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करेंगे:

बशर्ते कि किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में
मुख्य न्यायाधीश की तुलना में, भारत के मुख्य न्यायाधीश
हमेशा सलाह लें:

XXXX

अनुच्छेद 217। नियुक्ति और शर्तें

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यालय

(1) उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति इसके द्वारा की जाएगी -

राष्ट्रपति अपने हाथ और मुहर के नीचे वारंट द्वारा

भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल [2015] 13 एस. सी. आर. के साथ परामर्श

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राज्य का, और, न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में

मुख्य न्यायाधीश के अलावा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

अदालत...

XXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

3. पूर्व संशोधन पाठ में निर्धारित किया गया था कि

भारत के राष्ट्रपति इस न्यायालय और इस देश के उच्च न्यायालयों (इसके बाद संवैधानिक) के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे।

न्यायालय) भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से

(इसके बाद सीजेआई) और अन्य संवैधानिक पदाधिकारी

अनुच्छेद 124 और 217 में दर्शाया गया है। व्यवहार में, नियुक्ति

प्रमुख द्वारा रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जा रही थी

संबंधित उच्च न्यायालय या सी. जे. आई. के न्यायाधीश, जैसा भी मामला हो हो सकता है। इस तरह की प्रक्रिया एक ज्ञापन द्वारा निर्धारित की गई थी भारत सरकार का 1.

संशोधन के बाद

4. अनुच्छेद 124 और 217 जहाँ तक वे प्रासंगिक हैं

हमारा उद्देश्य पढ़ें

"अनुच्छेद 124 XXXXX

XXXXX

XXXX

(2) उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी।

राष्ट्रपति द्वारा अपने हाथ और मुहर के नीचे वारंट द्वारा

राष्ट्रीय न्यायपालिका की सिफारिश

अनुच्छेद 124 ए में निर्दिष्ट नियुक्ति आयोग और पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करेंगे।

वर्षों से।

217। नियुक्ति और शर्तें

अनुच्छेद

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद-(1) प्रत्येक न्यायाधीश

एक उच्च न्यायालय की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी -

उसके हाथ के नीचे वारंट और सिफारिश पर मुहर

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग

11 जिनका विवरण मेरे भाई जे. खेहर के निर्णय में पहले से ही उल्लेख किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [चेलामेश्वर, जे।]

अनुच्छेद 124 क में निर्दिष्ट, और में पद धारण करेगा

किसी अतिरिक्त या कार्यवाहक न्यायाधीश का मामला, जैसा कि उपबंध किया गया है

अनुच्छेद 224, और किसी अन्य मामले में, जब तक कि वह साठ-दो साल की उम्र "।

5. संशोधन में अनुच्छेद 124 ए, 124 बी और

ग. ये प्रावधान इस प्रकार हैं:

"124 ए (1) ज्ञात करने के लिए एक आयोग होगा।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के रूप में जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

अधिकारी:

(ख)

उच्चतम न्यायालय के दो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश

अधिकारी;

(ग) कानून और न्याय के प्रभारी

केंद्रीय मंत्री

- सदस्य, पदेन

(डी)। द्वारा नामित किए जाने वाले दो प्रतिष्ठित व्यक्ति
प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता से बनी समिति

लोगों के सदन में या जहाँ कोई नहीं है
ऐसे विपक्ष के नेता, फिर, के नेता

सदन में सबसे बड़ा विपक्षी दल

लोग-सदस्य:

बशर्ते

कि प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक होगा

संबंधित व्यक्तियों में से नामित

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य

पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक या महिलाएँ;

बशर्ते कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा

तीन वर्ष की अवधि के लिए नामित किया जाएगा और नहीं।

पुनः नामांकन के लिए पात्र हों।

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(2) राष्ट्रीय न्यायिक का कोई अधिनियम या कार्यवाही नहीं
नियुक्ति आयोग पर सवाल उठाया जाएगा या किया जाएगा।

संविधान में किसी भी रिक्ति या दोष के अस्तित्व के आधार पर अमान्य कर दिया गया
आयोग।

124 बी. यह राष्ट्रीय न्यायपालिका का कर्तव्य होगा।

नियुक्ति आयोग को

(क) प्रमुख के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करना।

भारत के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश

अदालतें;

(ख) मुख्य न्यायाधीशों और अन्य लोगों के स्थानांतरण की सिफारिश करना।

एक उच्च न्यायालय से लेकर किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

अन्य उच्च न्यायालय; और

(ग) सुनिश्चित करें कि अनुशंसित व्यक्ति है। क्षमता का

और ईमानदारी।

124 सी. संसद, कानून द्वारा, प्रक्रिया को विनियमित कर सकती है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य की नियुक्ति के लिए

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश और

उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीश और उन्हें सशक्त बनाना

आयोग विनियमों द्वारा प्रक्रिया निर्धारित करेगा

अपने कार्यों के निर्वहन के लिए, चयन का तरीका

नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की और ऐसे अन्य मामले जैसे

इसे आवश्यक माना जा सकता है।

अन्य अनुच्छेदों में परिणामी संशोधन भी किए जाते हैं,

विवरण आवश्यक नहीं हैं।

6. संशोधन का सार वह संस्थागत तंत्र है जिसके द्वारा चयन और नियुक्ति प्रक्रिया

संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया था

राष्ट्रीय सर्वोच्च न्यायालय अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड नामक एक नए निकाय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [चेलामेश्वर, जे।]

न्यायिक नियुक्ति आयोग (इसके बाद के रूप में संदर्भित)

एनजेएसी)। इसमें छह सदस्य होते हैं। सीजेआई इसके पदेन हैं।

अध्यक्ष। उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठ न्यायाधीश अगले

सीजेआई और केंद्रीय कानून मंत्री भी पदेन हैं।

दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के अलावा नामित किए जाने वाले सदस्य अनुच्छेद 124 ए (1) (डी) में
अनुध्यात समिति द्वारा।

7. अनुच्छेद 124 बी के तहत एन. जे. ए. सी. को यह दायित्व सौंपा गया है।

के लिए क्षमता और सत्यनिष्ठा के व्यक्तियों की सिफारिश करना

भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति

न्यायालय, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश न्यायालयों
और मुख्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश करना और

एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय तक उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीश।

8. अनुच्छेद 124 सी संसद को कानून द्वारा विनियमित करने के लिए अधिकृत करता है।

मुख्य न्यायाधीश और अन्य की नियुक्ति की प्रक्रिया

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आदि। यह एन. जे. ए. सी. को भी सशक्त बनाता है।

अपने कार्यों के निर्वहन के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने वाले विनियम बनाना।

9. अनुच्छेद 124 सी के अधिदेश के अनुसार, संसद

अधिनियम बनाया। वर्तमान के लिए, यह ध्यान रखना पर्याप्त है कि हालांकि संविधान के संशोधित
पाठ में ऐसा प्रावधान नहीं है,

अधिनियम की धारा 6 (6) 2 में प्रावधान है कि एनजेएसी

नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की सिफारिश करें, यदि कोई दो सदस्य

आयोग ऐसी सिफारिशों के लिए सहमत नहीं है।

10. संशोधन में दूरगामी बदलाव किए गए

संविधान की योजना, जहाँ तक यह संविधान के न्यायाधीशों की चयन प्रक्रिया से संबंधित है

अदालतें। राष्ट्रपति अब करने के लिए बाध्य नहीं है

परामर्श के लिए संवैधानिक न्यायालयों में नियुक्तियाँ

2 धारा 6 (6) "। आयोग इस धारा के तहत नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की सिफारिश नहीं करेगा यदि आयोग के कोई भी दो सदस्य ऐसी सिफारिश के लिए सहमत नहीं हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सीजेआई, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के राज्यपाल

राज्य लेकिन एन. जे. ए. सी. से परामर्श करने के लिए बाध्य हैं।

11. सुधार की चुनौती मुख्य रूप से जारी है

इस आधार पर कि इस तरह का प्रतिस्थापन स्वतंत्रता को कमजोर करता है

न्यायपालिका से। यह तर्क दिया जाता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है और

संशोधन इस तरह की स्वतंत्रता का विध्वंसक है। इसलिए, कानून की दृष्टि से यह संसद की क्षमता से परे है

इस न्यायालय द्वारा परम पूज्य केशवानंद भारती में घोषित

श्रीपदगलवर बनाम। केरल राज्य और दूसरा, (1973) 4 एस. सी. सी.

225 (इसके बाद भारती मामला के रूप में संदर्भित)।

12. सौभाग्य से दोनों के बीच कोई मतभेद नहीं है।

इसके पक्षकार इस प्रस्ताव के संबंध में हैं कि अस्तित्व

एक स्वतंत्र न्यायपालिका की एक अनिवार्य आवश्यकता है

लोकतांत्रिक गणराज्य। न ही कोई मतभेद है। इस प्रस्ताव के बारे में कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका एक है

भारत के संविधान की बुनियादी विशेषताएँ।

13. एकमात्र मुद्दा यह है कि अनुमत प्रक्रिया क्या है।

या तंत्र जो एक की स्थापना सुनिश्चित करेगा स्वतंत्र न्यायपालिका। इस मुद्दे के समाधान के लिए निम्नलिखित प्रश्नों की जांच की आवश्यकता है:

(i) क्या द्वारा स्थापित तंत्र

न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए संविधान सभा

संवैधानिक न्यायालयों का एकमात्र

एक स्वतंत्र सुरक्षित करने के लिए अनुमेय मोड

न्यायपालिका या कोई विकल्प हो सकता है?

(ii) यदि विकल्प हो सकते हैं, तो क्या तंत्र

(एन. जे. ए. सी.) संशोधन द्वारा स्थापित करने की मांग की गई
घटक शक्ति की सीमाओं का उल्लंघन करता है?

14. पिछले कुछ हफ्तों में सुनवाई के समापन के बाद

मामलों के इस समूह में, मैंने कई लोगों को यह कहते हुए सुना है कि सर्वोच्च न्यायालय के वकील-ऑन-रिकॉर्ड करते हैं

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. /चेलामेश्वर, जे।/

पूरा देश फैसले का इंतजार कर रहा है। कुछ ने तो यह भी कहा कि

पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। निश्चित रूप से एक तत्व है

उन कथनों में अतिशयोक्ति। यहाँ तक कि जो वास्तव में हैं

मुझे यकीन है कि प्रतीक्षा में ऐसी चिंताएँ हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती हैं। न्यायशास्त्र के संबंध में जिज्ञासा और

राजनीतिक शुद्धता, न्यायपालिका के भविष्य पर प्रभाव,

राजनीतिक और व्यक्तिगत भाग्य आदि का मूल्यांकन किया जा सकता है

उन चिंताओं में से कुछ। मुझे सिर्फ जस्टिस फजल की याद आती है।

एस. पी. गुप्ता बनाम में अली का दृष्टिकोण। भारत संघ और *Ors.*³ *AIR 1982*

एस. सी. 149 (संक्षिप्त एस. पी. गुप्ता मामले के लिए) कि यह मुद्दा अप्रासंगिक है।

जनता और वादियों के लिए। वे केवल यह चाहते हैं कि उनके मामले

विश्वास पैदा करने वाले न्यायाधीशों द्वारा जल्दी से निर्णय लिया जाना चाहिए।

सवाल यह है कि कौन सा सूत्र है जिसके द्वारा न्यायाधीश-कौन

मामलों को जल्दी से तय कर सकते हैं और विश्वास भी पैदा कर सकते हैं

जनता और वादियों को पेश किया जाए। कौन से गुण हैं?

जो एक न्यायाधीश को मामलों का जल्दी फैसला करने के लिए प्रेरित करता है और उत्पन्न भी करता है आत्मविश्वास?

3 "पैरा 520। जीवन का एक और तथ्य है, जो कितना भी अप्रिय क्यों न हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है और यह है कि हमारी जनता या वादियों की चिंता बहुत कम है कि किस न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है या नियुक्त नहीं किया जाता है या किसे जारी रखा जाता है या जारी रखा जाता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की उच्च ध्वनि अवधारणा या एक या दूसरे संवैधानिक कार्यकर्ताओं की प्रधानता या प्रभावी परामर्श के तरीके शैक्षणिक हित के ऐसे मामले हैं जिनमें हमारी जनता की रुचि कम है। दूसरी ओर, वे मुख्य रूप से काम करने वाली खतरनाक ताकतों और आर्थिक दबावों, मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों, भीषण गरीबी, महिलाओं की मुक्ति में परिलक्षित बुराइयों से चिंतित हैं।

कानून और व्यवस्था, भोजन और कपड़े, रोटी और मक्खन का रखरखाव और सबसे बढ़कर बेरोजगारी की गंभीर समस्या,

521. यह केवल बुद्धिजीवियों का एक बड़ा वर्ग है जिसमें प्रेस और वकील शामिल हैं जिन्होंने न्यायपालिका की स्वतंत्रता का एक प्रतिष्ठित मुद्दा बनाया है। मैं पूरी तरह से समझ सकता हूँ कि वकीलों या न्याय के प्रशासन से सीधे जुड़े अन्य व्यक्तियों की एक शिकायत हो सकती है, चाहे वह कितनी भी गलत क्यों न हो कि न्यायाधीशों का उचित चयन या संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति में हस्तक्षेप न्यायपालिका की संस्था को प्रभावित कर सकता है और इसलिए वे कुछ हद तक अपने अधिकारों को सही साबित करने में उचित हो सकते हैं। लेकिन साथ ही, यह चाहे कितना भी तीखा या कड़वा, अरुचिकर और शैतानी क्यों न लगे, तथ्य यह है कि आम जनता इन कानूनी बारीकियों से बिल्कुल भी चिंतित नहीं है और जहां तक न्याय के प्रशासन का संबंध है, वे केवल यह चाहते हैं कि उनके मामलों का निर्णय न्यायाधीशों द्वारा किया जाए जो विश्वास पैदा करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

15. कानून में गहरी शिक्षा, तीक्ष्ण और सचेत मन जल्दी से

समस्या महत्वपूर्ण तत्व हैं जो एक न्यायाधीश को कुशल बनाते हैं। और उसे मामलों को जल्दी से तय करने में सक्षम बनाता है। हालांकि, हर न्यायाधीश

जिनके पास उपरोक्त सभी गुण हैं, उन्हें स्वतः एक न्यायाधीश होने की आवश्यकता नहीं है जो न्यायाधीश में विश्वास पैदा कर सके।

वादी जब तक कि वादी को विश्वास न हो कि न्यायाधीश पूरी तरह से निष्पक्ष और निष्पक्ष।

16. न्यायाधीश की निष्पक्षता के बारे में विश्वास निर्भर करता है।

इस तथ्य पर कि न्यायाधीश का मुकदमे के किसी भी पक्ष के साथ कोई संबंध नहीं है। संदर्भ में संबंध हो सकता है

वह व्यक्तिगत, वित्तीय, राजनीतिक या दार्शनिक भी हो। कब

मुकदमे के पक्षों में से एक या तो राज्य या एक है
 इसकी साधनों, अनिवार्य रूप से एक संबंध है।
 क्योंकि, यह राज्य है जो न्यायपालिका की स्थापना करता है। कोष
 वेतन सहित न्यायिक प्रणाली को चलाने के लिए आवश्यक और न्यायाधीशों के भत्ते अनिवार्य
 रूप से राज्य से आते हैं
 राजकोष।

17. लोकतांत्रिक समाजों का मानना है कि राज्य न केवल
 शासन करने का अधिकार है लेकिन कुछ कानूनी रूप से लागू करने योग्य भी है
 अपने विषयों के प्रति दायित्व। न्यायिक मंचों का अधिकार
 ऐसे प्रवर्तनीय दायित्वों के अस्तित्व से राज्य को अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आदेश देता है। उत्पन्न
 करने के लिए
 विश्वास है कि न्यायिक मंच विवादों का फैसला करते हैं
 निष्पक्ष रूप से उनके विचार के लिए, उन्हें होना आवश्यक है
 स्वतंत्र। इस तथ्य के बावजूद कि वे स्थापित हैं
 और राज्य द्वारा सरकार के प्रति अपने बड़े दायित्व के एक भाग के रूप में आयोजित किया जाता है।

18. न्यायपालिका संविधान की प्रहरी है और
 मौलिक मूल्य। इसे लोकतांत्रिक समाजों में संवैधानिकता की जीवनदायिनी भी कहा जाता है। कम से कम तब
 से
 मार्बरी वी। मैडिसन * के तहत काम करने वाले न्यायालयों का अधिकार
 4 5 यू. एस. 137 (1803)

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [चेलामेश्वर, जे।]

द्वारा बनाए गए कानूनों को भी असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति विधायिका। यह एक दुर्जेय
 प्राधिकरण है जिसका अनिवार्य रूप से अर्थ है
 शानदार जिम्मेदारी। इस तरह की शक्ति का एक बुद्धिमान अभ्यास एक कुशल और स्वतंत्र
 न्यायाधीश (न्यायिक प्रणाली) की आवश्यकता होती है।

इस संदर्भ में, विवेक का अर्थ है सटीकता के साथ समझना कि क्या विधायी कार्रवाई ने संवैधानिक रूप से मांग की समाज के व्यापक हितों और स्वतंत्रताओं के बीच संतुलन विषयों से।

19. ऐसे मंचों की स्वतंत्रता दो पूर्णांकों पर टिकी होती है - संस्था और व्यक्तियों की स्वतंत्रता जो काम करते हैं संस्था को।

"(न्यायिक स्वतंत्रता) का अर्थ केवल एक नहीं है के वास्तविक अभ्यास में मन या दृष्टिकोण की स्थिति न्यायिक कार्य, लेकिन एक स्थिति या संबंध अन्य, विशेष रूप से कार्यकारी शाखा के लिए सरकार, जो वस्तुनिष्ठ शर्तों पर आधारित है या गारंटी।

*

इसमें व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों शामिल हैं।
संबंध: एक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता

न्यायाधीश, जैसा कि सुरक्षा जैसे मामलों में परिलक्षित होता है कार्यकाल, और संस्थागत स्वतंत्रता

न्यायालय या न्यायाधिकरण जिसकी वह अध्यक्षता करता है, इसके संस्थागत या प्रशासनिक रूप में परिलक्षित होता है

कार्यपालिका और विधायिका के साथ संबंध

सरकार की शाखाएँ। 115 "

20. वास्तव में मेरे लिए यह आवश्यक नहीं है कि मैं पूरे मामले का पता लगाऊँ।

अवधारणा की स्वतंत्रता के विकास का इतिहास

5 वॉलेटे बनाम में कनाडा का सर्वोच्च न्यायालय।

क्वीन, (1985) 2 एससीआर 673 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

लोकतांत्रिक समाजों में न्यायपालिका। यह बिना किसी के कहा जा सकता है विरोधाभास का डर जो सभी आधुनिक लोकतांत्रिक समाज प्रयास करते हैं

स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सबसे आवश्यक सुरक्षा उपाय न्यायपालिका-कार्यकाल की निश्चितता, पद से हटाने से सुरक्षा

न्यायाधीशों के मामलों में कड़ी प्रक्रिया को छोड़कर कार्यालय

न्यायपालिका के सदस्यों के रूप में बने रहने के लिए अयोग्य पाया गया, संरक्षण

द्वारा हस्तक्षेप से वेतन और अन्य विशेषाधिकारों का

कार्यपालिका और विधायिका, जांच से प्रतिरक्षा या तो द्वारा

न्यायाधीशों के आचरण की कार्यपालिका या विधानमंडल

कथित दुर्यवहार के मामलों को छोड़कर न्यायिक कार्यों के निर्वहन के संबंध में, नागरिक और आपराधिक दायित्व से प्रतिरक्षा

कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कार्यों के लिए, उनके विरुद्ध संरक्षण

बहुत हद तक आलोचना। इस तरह के सुरक्षा उपाय प्रदान किए जाते हैं

एक प्यारी उम्मीद के साथ जो इतनी संरक्षित है, एक न्यायाधीश बिल्कुल होगा

अपने कर्तव्यों के निर्वहन में स्वतंत्र और निडर।

21. लोकतांत्रिक समाज बड़े पैमाने पर मान्यता देते हैं

न्यायपालिका के लिए उपर्युक्त सुरक्षा की आवश्यकता

और उसके सदस्य। इस तरह की सुरक्षा या तो निहित है

संविधान या कानून द्वारा प्रदान किया गया। एक संक्षिप्त सर्वेक्षण

प्रदर्शित करने के लिए कुछ लोकतांत्रिक गणराज्यों के संविधान बिन्दु:

22. 1701 से पहले, ब्रिटिश क्राउन के पास शक्ति थी

न्यायाधीशों को अपनी इच्छानुसार बर्खास्त करें। निपटान अधिनियम, 1701

राजा से न्यायाधीशों को बर्खास्त करने की शक्ति हटा दी गई

दिलचस्प बात यह है कि 1720 तक न्यायाधीशों ने मृत्यु पर पद धारण करना बंद कर दिया था।

सम्राट जिन्होंने आयोग जारी किए। 1720 का एक अधिनियम

बशर्ते कि न्यायाधीश छह महीने तक पद पर बने रहें

राजा के निधन के बाद। 1761 में एक

क्रान्ति ने प्रावधान किया कि

6 *. न्यायाधीशों को आयोग बनाया जाए और उनके वेतन का निर्धारण और स्थापना की जाए, लेकिन संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर उन्हें हटाना वैध हो सकता है।

इस खंड को सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं-ऑन-रिकॉर्ड द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [चेलामेश्वर, जे।]

उनके निधन के बावजूद अच्छे व्यवहार के दौरान महामहिम या उनके किसी भी उत्तराधिकारी और उत्तराधिकारी-इस प्रकार एक

जीवनकाल। ब्लैकस्टोन के अनुसार,

"(1) के इस विशिष्ट और अलग अस्तित्व में

पुरुषों के एक विशिष्ट निकाय में न्यायिक शक्ति, नामित

वास्तव में, लेकिन खुशी से हटाने योग्य नहीं
मुकुट में जनता का एक मुख्य संरक्षक होता है

स्वतंत्रता जो किसी भी राज्य में लंबे समय तक नहीं रह सकती है जब तक कि सामान्य न्याय का प्रशासन कुछ में हो

विधायी और दोनों से अलग डिग्री

कार्यकारी शक्ति से "। " 37

23. अमेरिकी संविधान का अनुच्छेद III (1.) 3 निर्धारित करता है

कि उच्चतम न्यायालय और निम्न न्यायालयों के न्यायाधीश भी

कांग्रेस द्वारा स्थापित अच्छे व्यवहार के दौरान अपना पद संभालेगा और उन्हें हटा नहीं जा सकता है सिवाय इसके कि महाभियोग की प्रक्रिया। यह भी निर्धारित करता है कि वे

उनकी सेवाओं के लिए एक मुआवजा प्राप्त करें जो नहीं होगा

कार्यालय में उनके बने रहने के दौरान कम हो गए।

24. ऑस्ट्रेलिया के संविधान की धारा 7210 निर्धारित करती है

7 सर विलियम ब्लैकस्टोन की, इंग्लैंड के कानूनों पर टिप्पणियां, (1765) खंड। आई पी। 269

3 अनुच्छेद III धारा 1. संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक शक्ति, एक सर्वोच्च न्यायालय में निहित होगी, और ऐसे निम्न न्यायालयों में निहित होगी जिन्हें कांग्रेस समय-समय पर आदेश और स्थापित कर सकती है। सर्वोच्च और निम्न दोनों न्यायालयों के न्यायाधीश अच्छे व्यवहार के दौरान अपने पदों पर रहेंगे, और निर्दिष्ट समय पर, अपनी सेवाओं के लिए एक मुआवजा प्राप्त करेंगे, जिसे उनके पद पर बने रहने के दौरान कम नहीं किया जाएगा।

• अनुच्छेद 1 धारा 4, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी नागरिक अधिकारियों को देशद्रोह, रिश्वतखोरी, या अन्य उच्च अपराधों और दुराचारों के लिए महाभियोग और दोषसिद्धि पर पद से हटा दिया जाएगा। 10 धारा 72. न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक:

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश।

((ii) एक ही सत्र में संसद के दोनों सदनों से इस तरह के निष्कासन के लिए प्रार्थना करने के अलावा नहीं हटाया जाएगा। साबित दुर्व्यवहार या असमर्थता का आधार; (iii) ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद निर्धारित करे; लेकिन उनके पद पर बने रहने के दौरान पारिश्रमिक में कमी नहीं की जाएगी।

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कि उच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा बनाया गया

संसद की नियुक्ति न्यायाधीश के सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने पर समाप्त होने वाली अवधि के लिए की जाएगी और

दोनों सदनों के पते को छोड़कर हटा दिया गया

उसी सत्र में संसद ने हटाने की प्रार्थना की

साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर न्याय करें। यह,

यह भी निर्धारित करता है कि न्यायाधीशों का पारिश्रमिक नहीं होगा

कार्यालय में उनके बने रहने के दौरान कम हो गए।

25. जब भारत एक संप्रभु गणराज्य बना, तो हमने किया

ब्रिटिश संवैधानिक प्रणाली को पूरी तरह से नहीं अपनाना-हालांकि

भारत तब से ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहा है।
करना शुरू कर दिया

ब्रिटिश क्राउन ने इस क्षेत्र पर संप्रभुता का दावा

भारत में, ब्रिटिश संसद ने ऐसे अधिनियम बनाए जो कानूनी प्रावधान करते थे

समय-समय पर ज्ञात भारत के शासन के लिए रूपरेखा

भारत सरकार अधिनियमों के रूप में। जिनमें से अंतिम 1935 का था।

कनाडा 11 और ऑस्ट्रेलिया 12 जो अंग्रेजों का भी हिस्सा थे
संविधानों द्वारा शासित होना जारी है

साम्राज्य द्वारा अधिनियमित

ब्रिटिश संसद। हमने एक नया संविधान बनाया

एक संविधान सभा।

26. सामान्य रूप से संविधान सभा के सदस्य और
मसौदा समिति विशेष रूप से पुरुषों और महिलाओं की थी
महान राजनीतिक अनुभव, मानव स्वभाव में गहरी अंतर्दृष्टि, और
भारत की जटिल समस्याओं की गहरी समझ समाज। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया।
वे.

वे इतिहास, कानून, राजनीति विज्ञान में पारंगत थे और
लोकतांत्रिक प्रथाएँ। उन्होंने विभिन्न संवैधानिक पहलुओं की जांच की अन्य बातों के साथ-साथ
विभिन्न लोकतांत्रिक समाजों में प्रचलित प्रणालियाँ
अमेरिकी, ऑस्ट्रेलियाई, ब्रिटिश और कनाडाई और अपनाया गया
विभिन्न संवैधानिक प्रणालियों से अलग-अलग विशेषताएँ
भारतीय समाज की आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें उपयुक्त रूप से संशोधित करना।

11 ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम, 1867 का नाम बदलकर 1982 में संशोधन द्वारा संविधान अधिनियम,
1867 कर दिया गया।

12 ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रमंडल संविधान अधिनियम, 1900।

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [चेलामेश्वर, जे।]

27. संविधान निर्माताओं को एक का लाभ था
संघीय न्यायालय के कामकाज का गहन ज्ञान,
इस देश के उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय
भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अधीन। हालांकि वहाँ
न्यायिक प्रणालियों की संरचना में कई अंतर
उपर्युक्त प्रत्येक व्यवस्था के तहत, एक विशेषता है उन सभी के लिए आम बात यह है कि
न्यायाधीशों की नियुक्ति
कार्यकारी। इस तरह की संवैधानिक रचना अनिवार्य रूप से एक विरासत है।
ब्रिटिश संवैधानिक प्रणाली जहाँ कार्यपालिका थी

(2006 तक) न्यायाधीशों की नियुक्ति का पूर्ण अधिकार।

28. किसी भी देश में न्यायाधीशों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अन्य सार्वजनिक कार्यालय की तुलना में ईमानदारी की उच्च डिग्री धारकों। भारतीय न्यायपालिका के संबंध में अपेक्षा अलग नहीं है। इसलिए संविधान न्यायाधीशों के लिए असाधारण सुरक्षा और विशेषाधिकार प्रदान करता है। संवैधानिक न्यायालयों को उन्हें काफी हद तक सुरक्षित रखने के लिए राजनीतिक-कार्यपालिका द्वारा हस्तक्षेप की संभावना से साथ ही जन प्रतिनिधियों के निर्वाचित बहुमत 14.

1. न्यायाधीश की नियुक्ति और पद पर बने रहना नहीं है।

किसी भी चुनाव प्रक्रिया के अधीन;

13 इस मामले में संवैधानिक न्यायालयों का मौजूदा संविधान और संगठन

न्यायमूर्ति वर्मा ने द्वितीय न्यायाधीशों में देश पर कुछ विस्तार से चर्चा की है। पैरा 444,445,446 पर मामला।

444. भारत सरकार अधिनियम, 1919 ने धारा 101 में इसके लिए प्रावधान किया है -

उच्च न्यायालयों का गठन और मुख्य न्यायाधीश और स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल पात्रता की निर्धारित शर्तों के अधीन क्राउन के पूर्ण विवेक पर थी। धारा 102 के अनुसार, उनके पद का कार्यकाल पूरी तरह से क्राउन की खुशी पर निर्भर था।

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

445. फिर, भारत सरकार अधिनियम, 1935 में,

संघीय न्यायालय की स्थापना और संविधान अनुभाग में किया गया था 200, जबकि उच्च न्यायालयों के संविधान का प्रावधान धारा 220 में किया गया था।

XXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

446. इस प्रकार, भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत भी, संघीय न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियां निरपेक्ष थीं। नियुक्ति प्रक्रिया में मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के

लिए कोई विशिष्ट प्रावधान के बिना क्राउन या, दूसरे शब्दों में, कार्यपालिका का विवेकाधिकार। 14 एल. चंद्र कुमार और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य।

, (1997) 3 एस. सी. सी. 261, पैरा 78 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

II. न्यायिक नियुक्ति की समाप्ति (के दौरान)

कार्यकाल का निर्वाह) लगभग असंभव बना दिया गया है।

संविधान निर्धारित करता है कि एक न्यायाधीश

संवैधानिक न्यायालय को पद से नहीं हटाया जाएगा।

महाभियोग की एक विस्तृत प्रक्रिया का पालन करने के अलावा

अनुच्छेद 124 (4) 15 के तहत निर्धारित जो इसके लिए भी लागू होता है

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनुच्छेद 217 (1) (बी) के आधार पर।

III. वेतन, विशेषाधिकार, भत्ते और अधिकार

न्यायाधीशों की अनुपस्थिति की छुट्टी और पेंशन का सम्मान

संवैधानिक न्यायालय निर्धारित किए जा सकते हैं

संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा या उसके तहत। लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते।

के बाद न्यायाधीश 17 के नुकसान के लिए परिवर्तित किया जाए

नियुक्ति।

IV. न्यायाधीशों को देय वेतन, भत्ते और पेंशन

संवैधानिक न्यायालयों का प्रभार लिया जाता है

भारत की समेकित निधि या समेकित निधि

संबंधित राज्य का 18. लेखों के तहत आगे

15 अनुच्छेद 124 (4) उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा समर्थित और उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा राष्ट्रपति को उसी सत्र में इस तरह के निष्कासन के लिए प्रस्तुत किए जाने के बाद राष्ट्रपति के आदेश द्वारा पारित किया गया हो। 16 अनुच्छेद 217 (1) (ख) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 124 के खंड (4) में उपबंधित तरीके से राष्ट्रपति द्वारा किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है।

17 अनुच्छेद 125 (2) के प्रावधान और अनुच्छेद 221 (2) के प्रावधान के तहत। 18 अनुच्छेद 112 (3) (घ)- (3) निम्नलिखित व्यय भारत की संचित निधि पर प्रभारित व्यय होगा।

(घ) (i) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में देय वेतन, भत्ते और पेंशन;

अनुच्छेद 202 (3) (घ)-(3) निम्नलिखित व्यय प्रत्येक राज्य की संचित निधि पर प्रभारित व्यय होगा -

(घ) किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों के संबंध में व्यय; सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [चेलामेश्वर, जे।]

113 (1) 19 और 203 (1) 20 पर प्रभारित व्यय

भारत या राज्य की संचित निधि

मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

29. बेईमान वादी लगातार खोज करते रहते हैं

न्यायाधीशों को प्रभावित करने के तरीके। राज्य या उसका दृष्टिकोण

साधन (आधुनिक लोकतंत्रों में सबसे बड़े वादी)

कि राज्य के पास कानून बनाने का कानूनी अधिकार है जिसमें शामिल हैं - न्यायाधीशों के चयन की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले कानून और

उनकी सेवा स्थितियाँ सबसे बड़ा खतरा पैदा कर सकती हैं

न्यायपालिका की स्वतंत्रता यदि ऐसा कानून बनाने का अधिकार है

बिना किसी सीमा के। इसलिए, असाधारण सुरक्षा उपाय

सदस्यों के कार्यकाल और सेवा शर्तों की रक्षा करने के लिए न्यायपालिका संविधान में एक अच्छी उम्मीद के साथ प्रदान की गई है।

कि न्यायिक पद धारण करने वाले पुरुष और महिलाएँ इतने संरक्षित हैं

पूर्ण रूप से अपने कार्यों का निर्वहन करने में सक्षम होंगे

स्वतंत्रता और दक्षता।

30. हालांकि, कानूनी और संस्थागत की कोई भी राशि

संरक्षण आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान नहीं करेगा और

व्यक्तियों के लिए दक्षता यदि स्वाभाविक रूप से उनमें कमी है।

19 113 (1) भारत की संचित निधि पर लगाए गए व्यय से संबंधित जितने भी अनुमान हैं, वे भारत की संचित निधि के मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे।

संसद, लेकिन इस खंड में कुछ भी उन अनुमानों में से किसी के बारे में संसद के किसी भी सदन में चर्चा को रोकने के रूप में नहीं समझा जाएगा।

20 203 (1) - किसी राज्य की संचित निधि पर प्रभारित व्यय से संबंधित जितने भी अनुमान हैं, उन्हें विधान सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, लेकिन इस खंड की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह उन अनुमानों में से किसी की भी विधानमंडल में चर्चा में बाधा डालती है। 21 फली एस. नरीमन, बिफोर मेमोरी फेड्स: एक आत्मकथा, [पहला संस्करण हे हाउस (2010), p.348]

"मैं एक बार रंगभेद के दिनों में दक्षिण अफ्रीका में एक अच्छे, स्वतंत्र न्यायाधीश को जानता था-न्यायाधीश-नेटाल सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति जॉन मिलने। हम पत्राचार करते थे, और मिलने ने कुछ ऐसा ही कहा। मिलने ने एक अवसर पर (निराशा में) मुझे लिखा:

ऐसा लगता है कि वे इस विचार के लिए चाहे जितना भी जुबानी सेवा दें कि न्यायपालिका कार्यपालिका, राजनेताओं से पूरी तरह से स्वतंत्र है

युगों-युगों से और दुनिया भर में वास्तव में कार्यकारी दिमाग वाले नौकरों को रखना पसंद करेंगे और स्वतंत्र तरीके से काम करने वाले स्वतंत्र न्यायाधीशों से काफी चिढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

जहाँ न्यायाधीश की सेवा का प्रत्येक पहलू न्यायाधीश द्वारा संरक्षित है।

संविधान, एकमात्र तरीका है जिससे सरकारें लाभ उठाने के बारे में सोच सकती हैं न्यायपालिका पर कुछ नियंत्रण ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करने का प्रयास करना है जो स्वाभाविक रूप से लचीले हैं। विभिन्न कारक हैं

जो एक न्यायाधीश को लचीला बनाता है। कुछ कारक हैं -

व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, निष्ठा-राजनीतिक, धार्मिक या सांप्रदायिक विचार, अक्षमता और सत्यनिष्ठा की कमी।

उपर्युक्त कारकों में से कोई भी एक बनाने के लिए पर्याप्त है

सत्ता में पुरुषों के सामने झुकना है। कहा जाता है कि पुरुषों में शक्ति सबसे कम मानव जाति को इस प्यारी आशा के साथ बढ़ावा देती है कि वे

जिनके पास कोई उपलब्धि नहीं है, वे अपने हितग्राही के प्रति आभारी होंगे। इतिहास उदाहरणों से भरा हुआ है-हालांकि इसका प्रमाण

अपेक्षित निष्ठा बहुत कम है। आम तौर पर ऐसे लोग केवल सत्ता के प्रति वफादार होते हैं लेकिन परोपकारी के प्रति नहीं।

31. यह सुनिश्चित करने के लिए कि कम से कम मामले में

दुनिया भर के लोकतंत्रों ने अलग-अलग तरीके अपनाए हैं न्यायाधीशों के रूप में सही लोगों को चुनने की रणनीतियाँ। द.

इस तरह का चुनाव करने के लिए अपनाई गई प्रक्रियाएं व्यापक रूप से हैं अलग-अलग। इसे प्रदर्शित करने के लिए, इसकी जांच करना उपयोगी है

अंग्रेजी बोलने वाले कुछ देशों की न्यायिक प्रणालियाँ।

32. संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान

राष्ट्रपति को सीनेट की सलाह और सहमति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार देता है। यहाँ तक कि

22 अनुच्छेद 1 धारा 2

राष्ट्रपति के पास "सीनेट की सलाह और सहमति से नामांकन करने और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति होगी। अन्य सांविधिक संघीय न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में, कांग्रेस कानून द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति सौंप सकती है।

स्वयं। 23 अमेरिका के संघीय विधानमंडल को संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस कहा जाता है जिसमें दो कक्ष होते हैं-सीनेट और प्रतिनिधि सभा।

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [चेलामेश्वर, जे।]

संयुक्त राज्य में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के रूप में

राज्यों की चिंता है, न तो अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश और न ही

उच्चतम न्यायालय को कोई भी भूमिका सौंपी गई है। के प्रमुख

कार्यपालिका को चुनाव करने के लिए विशेष शक्ति प्रदान की जाती है।

सीनेट की सलाह और सहमति के अधीन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की। मनमाना होने की संभावना पर एक जाँच

राष्ट्रपति द्वारा शक्ति का प्रयोग।

33. कनाडाई कानूनी प्रणाली एक और चित्रण करती है

दिलचस्प मॉडल। कनाडा का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है इसकी स्थापना 1867 के संविधान अधिनियम द्वारा की गई थी।

अधिनियम का अध्याय VII न्यायपालिका से संबंधित है। धारा 10124 केवल कनाडा की संसद को प्रदान करने के लिए अधिकृत करता है

सामान्य न्यायालय का गठन, रखरखाव और संगठन कनाडा की अपील और किसी भी अतिरिक्त की स्थापना के लिए

कनाडा के कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अदालतें। यह है।

एक कानून द्वारा (सर्वोच्च और राजकोष न्यायालय अधिनियम, 1875-25) कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। सर्वोच्च

कनाडा के अस्तित्व का न्यायालय, इसकी संरचना और अधिकार क्षेत्र

समय के साथ कई परिवर्तन होते हैं। सिद्धांत रूप में, न्यायालय हो सकता है संघीय संसद की एकतरफा कार्रवाई द्वारा समाप्त कर दिया गया।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।

परिषद में (संघीय मंत्रिमंडल) शक्ति का प्रयोग करते हुए

सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम (ऊपर) की धारा 2 के तहत प्रदान किया गया।

कनाडा में ऐसी नियुक्तियों की कोई आवश्यकता नहीं है।

सीनेट या हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा अनुमोदित किया जाए। 24 धारा 101। कनाडा की संसद, इस अधिनियम में कुछ भी होने के बावजूद, समय-समय पर कनाडा के लिए एक सामान्य अपील न्यायालय के संविधान, रखरखाव और संगठन के लिए और

कनाडा के कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए किसी भी अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना।

25 अब उच्चतम न्यायालय अधिनियम, 1985 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

34. ऑस्ट्रेलिया में, सर्वोच्च संघीय न्यायालय को कहा जाता है

ऑस्ट्रेलिया का उच्च न्यायालय धारा 7126 के तहत स्थापित

ऑस्ट्रेलियाई संविधान। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य शामिल हैं।

न्यायाधीश कम से कम दो नहीं होते हैं जैसा कि संसद निर्धारित करती है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है

परिषद में जनरल।

35. न तो कनाडा और न ही ऑस्ट्रेलिया प्रमुख प्रदान करते हैं।

संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीश। ऑस्ट्रेलिया में, इसके विपरीत अमेरिकी मॉडल, संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके लिए संघीय विधायिका की सहमति की आवश्यकता हो नियुक्तियाँ।

36. इंग्लैंड इन मामलों में अद्वितीय है। इसमें कोई लिखा नहीं है।

भारत, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में संविधान के रूप में समझा जाता है। 2006 तक, न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ विशेष रूप से

राजकोष के स्वामी कुलाधिपति जो इसके सदस्य हैं कैबिनेट।

37. एक अध्ययन के बाद भारतीय संविधान के निर्माता

दूसरों के बीच ऊपर उल्लिखित विभिन्न मॉडल, प्रदान किए गए

कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में

संवैधानिक न्यायालय, सीजेआई और मुख्य न्यायाधीश

संबंधित उच्च न्यायालय से परामर्श करने की आवश्यकता है

राष्ट्रपति जो इन न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्राधिकारी है। संविधान के पाठ में स्पष्ट रूप से किसी भी भूमिका को शामिल नहीं किया गया है

या तो संसद या राज्य विधानमंडलों के लिए।

38. डॉ. अम्बेडकर ने योजना की व्याख्या की

संविधान जहाँ तक न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है

26 धारा 71। न्यायिक शक्ति और न्यायालय

राष्ट्रमंडल की न्यायिक शक्ति एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय में निहित होगी, जिसे ऑस्ट्रेलिया का उच्च न्यायालय कहा जाएगा, और इस तरह के अन्य मामलों में

संघीय अदालतें जैसा कि संसद बनाती है, और ऐसी अन्य अदालतों में जो संघीय अधिकार क्षेत्र के साथ निवेश करती हैं। उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और कई अन्य न्यायाधीश शामिल होंगे, कम से कम दो, जैसा कि संसद निर्धारित करती है।

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [चेलामेश्वर, जे।]

संवैधानिक न्यायालय और प्रतिस्पर्धी समूह

एच ने एस को अपनाने के लिए मसौदा समिति के साथ वजन किया

एल:

"इसमें कोई मतभेद नहीं हो सकता

सदन कि हमारी न्यायपालिका दोनों होनी चाहिए

अपने आप में सक्षम बनें। सवाल यह है कि इन दोनों वस्तुओं को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है।

अन्य देशों में इस मामले को दो अलग-अलग तरीकों से नियंत्रित किया जाता है। ग्रेट ब्रिटेन में

नियुक्तियाँ क्राउन द्वारा की जाती हैं, बिना किसी भी प्रकार की सीमा, जिसका अर्थ है

दिन के कार्यकारी द्वारा। वहाँ है कि

उदाहरण के लिए, उच्चतम न्यायालय के अधिकारी साथ ही राज्य के अन्य कार्यालय बनाए जाएंगे।

केवल सीनेट की सहमति से संयुक्त राज्य अमेरिका। मुझे लगता है कि

आज हम जिन परिस्थितियों में जी रहे हैं,

जहाँ जिम्मेदारी की भावना नहीं बढ़ी है जिस हद तक हम इसे पाते हैं

संयुक्त राज्य अमेरिका, यह खतरनाक होगा

नियुक्तियों को करने के लिए छोड़ दें राष्ट्रपति, बिना किसी प्रकार के आरक्षण के

या सीमा, अर्थात्, केवल पर

दिन के कार्यपालक की सलाह। इसी तरह, ऐसा लगता है कि हर

नियुक्ति जो कार्यपालिका करना चाहती है

विधानमंडल भी बहुत उपयुक्त नहीं है। प्रावधान। इसके भारी होने के अलावा, यह भी

नियुक्ति की संभावना शामिल है [2015] 13 एस. सी.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राजनीतिक दबाव से प्रभावित होना और

राजनीतिक विचार। मसौदा लेख,

इसलिए, एक मध्य मार्ग का नेतृत्व करता है। ऐसा नहीं है।

राष्ट्रपति को सर्वोच्च बनाएँ और

विधानमंडल से। लेख में प्रावधान यह है कि व्यक्तियों का परामर्श होना चाहिए जो पूर्व परिकल्पना हैं, देने के लिए अच्छी तरह से योग्य हैं इस तरह के मामलों में उचित सलाह, और मेरे निर्णय यह है कि इस प्रकार का प्रावधान हो सकता है इस समय के लिए पर्याप्त माना जाता है।

प्रश्न के संबंध में मुख्य न्यायाधीश की सहमति, ऐसा लगता है मेरे लिए कि जो लोग उस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं ऐसा लगता है कि दोनों निहित रूप से निष्पक्षता पर निर्भर हैं मुख्य न्यायाधीश और उनकी स्वस्थता निर्णय। मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई संदेह नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। लेकिन आखिरकार मुख्य न्यायाधीश सभी के साथ एक आदमी है असफलताएँ, सभी भावनाएँ और सभी पूर्वाग्रह जो आम लोगों के रूप में हमारे पास हैं; और मुझे लगता है, मुख्य न्यायाधीश को व्यावहारिक रूप से वीटो करने की अनुमति देना। न्यायाधीशों की नियुक्ति पर वास्तव में मुख्य न्यायाधीश को अधिकार हस्तांतरित करने के लिए जिसमें हम निहित होने के लिए तैयार नहीं हैं राष्ट्रपति या तत्कालीन सरकार। इसलिए मुझे लगता है कि यह भी एक खतरनाक प्रस्ताव 7 "। (जोर दिया गया)

संस्थान सभा बहस, 24 मई 1949 (खंड। VIII)

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [चेलामेश्वर, जे।]

डॉ. अम्बेडकर की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं -

विचार:

1. कि न्यायपालिका दोनों स्वतंत्र होनी चाहिए और सक्षम।

2. एक अनियंत्रित शक्ति प्रदान करना खतरनाक है

क्योंकि यह नियुक्तियों की संभावना की ओर ले जाता है राजनीतिक विचारों से प्रभावित या राजनीतिक आधार पर दबाव बना रहे हैं।

3. (क) मुख्य न्यायाधीश की सहमति की आवश्यकता भी है एक खतरनाक प्रस्ताव।

(ख) कि, मुख्य न्यायाधीश भी एक इंसान है और सभी विफलताओं, भावनाओं के साथ एक आदमी है और पूर्वाग्रह जो आम लोगों को माना जाता है 28 हैं।

(ग) सी. जे. आई. की सहमति का प्रावधान होगा सी. जे. आई. को वीटो की शक्ति प्रदान करना जिसमें पदार्थ का अर्थ है शक्ति का स्थानांतरण बिना किसी सीमा के सी. जे. आई. की नियुक्ति, जो संविधान सभा ने सोचा कि यह अनुचित है राष्ट्रपति को प्रदान करें।

4. कि, प्रारूपण समिति ने सोचा कि

(जैसा कि वे संशोधन से पहले खड़े थे), सुनिश्चित करना

अपेक्षित स्वतंत्रता और क्षमता

न्यायपालिका और ऐसी व्यवस्थाएँ होंगी

"पल" के लिए पर्याप्त।

जैक्सन, जे. के शब्दों को सचर बनाम में कॉल करें। संयुक्त राज्य अमेरिका 343 यू. एस. 1 (1952) जो बेंच में अपना रास्ता बनाते हैं, कभी-कभी घमंड, अप्रासंगिकता, विवेक, अहंकार और अन्य कमजोरियों का प्रदर्शन करते हैं जिनके लिए मानव शरीर उत्तराधिकारी है। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

39. 1977 तक, इसका सही अर्थ और आयाम

के अनुच्छेद 124 और 217 में होने वाली अभिव्यक्ति परामर्श

भारत के संविधान ने न तो कार्यपालिका को परेशान किया और न ही न्यायपालिका को। हमेशा के बीच एक परामर्श था

संवैधानिक कार्यकर्ता। नियुक्तियाँ बिना किए की गई बहुत विवाद। उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ताओं में यह न्यायालय

ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम। भारत संघ, (1993) 4 एस. सी. सी. 441

(इसके बाद दूसरे न्यायाधीशों के मामले के रूप में संदर्भित) 29 दर्ज किया गया

40. अनुच्छेद 222 30 राष्ट्रपति को उच्च का स्थानांतरण करने के लिए अधिकृत करता है।

सी. जे. आई. के परामर्श से न्यायालय के न्यायाधीश। 1975 तक, वह शक्ति

राष्ट्रपति द्वारा बहुत कम प्रयोग किया जाता था। 1976 में 1, शक्ति

अनुच्छेद 222 के तहत 16 का सामूहिक हस्तांतरण करने के लिए आह्वान किया गया था

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 32. 16 न्यायाधीशों में से एक ने हालांकि इसका पालन किया

29 पैरा 371

14

(iii) 1950 से 1959 तक सर्वोच्च न्यायालय में सभी नियुक्तियाँ थीं -

भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से किया गया। 210 211 में से

उस अवधि के दौरान उच्च न्यायालयों में की गई नियुक्तियाँ भी

भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति।

(iv) भारत के गृह मंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत ने सदन में घोषणा की

24 नवंबर, 1959 को संसद द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति

वस्तुतः भारत के मुख्य न्यायाधीश और कार्यपालिका द्वारा बनाया जा रहा था

केवल एक आदेश जारी करने वाला प्राधिकरण था।

(v) कानून मंत्री श्री अशोक सेन ने संसद में दोहराया कि

25 नवंबर, 1959 को सुप्रीम कोर्ट में लगभग सभी नियुक्तियाँ की गईं।

मुख्य न्यायाधीश की सहमति से न्यायालय और उच्च न्यायालय बनाए गए थे।

भारत का न्याया
गई न्यायाधीशों की 547 नियुक्तियों में से

(vi) 1 जनवरी की अवधि के दौरान की

आई.

1983 10 अप्रैल, 1993 तक केवल 7 ही विचारों के अनुरूप नहीं थे।

भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा व्यक्त किया गया।

30 अनुच्छेद 222-एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण

(1) राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद, स्थानांतरण कर सकते हैं।
एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश

(2) जब किसी न्यायाधीश का इस प्रकार स्थानांतरण किया गया है या किया गया है, तो वह इस अवधि के दौरान

वह संविधान (पंद्रहवां संशोधन) के प्रारंभ के बाद सेवा करता है।

अधिनियम, 1963, अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में, अतिरिक्त प्राप्त करने का हकदार होगा।

उसके वेतन के लिए ऐसा प्रतिपूरक भत्ता जो संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किया जाए और जब तक ऐसा निर्धारित नहीं किया जाता है, तब तक ऐसा प्रतिपूरक भत्ता

जैसा कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा तय कर सकते हैं

31 की एक (आंशिक रूप से विवादास्पद) घोषणा के निर्वाह के दौरान

आपातकाल

32 भारत संघ बनाम। संकलचंद हिमतलाल सेठ और अन्न।, (1977) 4 एससीसी 193

(भगवती, जे.-पैरा 46)

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [चेलामेश्वर, जे।]

स्थानांतरण के आदेश के साथ लेकिन एक दाखिल करके स्थानांतरण को चुनौती दी

न्यायपालिका की स्वतंत्रता 33. यह उस संदर्भ में था

मामला, पहली बार, अभिव्यक्ति का सही अर्थ

अनुच्छेद 222 (1) के तहत होने वाले परामर्श के लिए गिर गया

इस न्यायालय का विचार। मामला, भारत संघ बनाम। संकलचंद हिमतलाल सेठ और अन्न। ,
(1977) 4 एससीसी 193 (के लिए)

संकलचंद का छोटा मामला) पांच न्यायाधीशों द्वारा सुना गया था। चार। चंद्रचूड़, भगवती ने
अलग-अलग निर्णय दिए।

कृष्णा लायर, और उतवालिया, जे. जे। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा

कि संदर्भ में "परामर्श" का अर्थ है एक प्रभावी परामर्श और पूर्ण डेटा का साक्षात्करण जिसके आधार पर
हस्तांतरण किया जाता है

प्रभावी होने की मांग की गई लेकिन यह निष्कर्ष निकाला कि-भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ एक प्रभावी
परामर्श के बाद, यह इसके लिए खुला है

राष्ट्रपति इस प्रश्न के उचित निर्णय पर पहुँचेंगे कि क्या

एक न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाना चाहिए क्योंकि,

संविधान में मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श की आवश्यकता है

न्याय, प्रस्तावित स्थानांतरण के साथ उनकी सहमति नहीं। इसके बाद

इस तरह के निष्कर्ष को दर्ज करते हुए, उनके प्रभुता ने इस प्रकार का अवलोकन किया:

"41.

लेकिन यह दोहराना आवश्यक है कि क्या

भगवती और कृष्ण लायर जे. जे. शमशेर में कहा

सिंह (ऊपर) कि सभी संभावित मामलों में,

भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करना चाहिए
भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया जाएगा और वह

न्यायालय के पास जाँच करने का अवसर होगा यदि कोई हो

अन्य बाहरी परिस्थितियों में प्रवेश किया है

कार्यपालिका का निर्णय यदि इससे अलग हो जाता है

भारत के मुख्य न्यायाधीश से संबंधित होना चाहिए,
उनकी सलाह की अस्वीकृति को आम तौर पर माना जाता है

33 संकलचंद मामले का पैरा 47, भगवती, संकलचंद मामले का जे. 34 पैरा 41-चंद्रचूड़, जे.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तिरछे विचारों से प्रेरित होकर

आदेश "। (पृष्ठ 873)। यह आशा की जाती है कि ये शब्द

बहरे कानों पर नहीं गिरते हैं और चूंकि अब सामान्य हो गया है

प्रत्येक पक्ष आपसी विचार-विमर्श करता है, पक्ष विचारों पर विचार करता है दूसरे का सम्मान और विचार के साथ।

41. न्यायमूर्ति भगवती, कृष्ण लायर द्वारा अपने फैसले में कही गई बातों से पूरी तरह सहमत थे। 35

42. न्यायमूर्ति कृष्णा लायर ने अपने लिए और न्याय के लिए बात की।

फजल अली। न्यायमूर्ति कृष्णा लायर ने अपने विचारों को दोहराते हुए कहा,

इस न्यायालय द्वारा पहले के दो निर्णयों में व्यक्त किया गया, अर्थात्।

चंद्रमौलेश्वर प्रसाद बनाम। पटना उच्च न्यायालय और अन्य। ,

(1969) 3 एससीसी 56 और समशेर सिंह बनाम। पंजाब राज्य, आकाशवाणी

1974 एस. सी. 2192 ने राय दी कि हालांकि प्रमुख की राय

भारत का न्याय सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं हो सकता है

बड़े वजन का हकदार है और आम तौर पर द्वारा स्वीकार किया जाना है

सरकार. 36 एक चेतावनी के साथ:

"115. यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यदि सरकार प्रमुख की राय से अलग होती है

भारत को न्याय देने के लिए उसे अपनी कार्रवाई को उचित ठहराना होगा

उसी के लिए ठोस और विश्वसनीय कारण और, यदि चुनौती दी जाती है, तो न्यायालय के संतोष के लिए साबित करने के लिए

कि 'परामर्श' शब्द का उपयोग अनुच्छेद 222 में इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक शिष्टाचार के रूप में किया गया है कि दो बहुत उच्च गणमान्य व्यक्ति हैं मामले में संबंधित, अर्थात्, राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश। बेशक, प्रमुख

35 संकलचंद मामले का पैरा 62-भगवती, जे.

36 संकलचंद मामले का पैरा 115-कृष्णा लायर, जे.

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [चेलामेश्वर, जे।]

डॉ. अम्बेडकर की तरह न्याय के पास वीटो की कोई शक्ति नहीं है।
संविधान सभा में समझाया गया "।

न्यायमूर्ति उन्तवालिया ने व्यक्त किए गए विचारों से सहमति व्यक्त की
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के साथ परामर्श के प्रश्न पर भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा:
हालाँकि, सरकार ने

" 125.

मुख्य न्यायाधीश की सलाह को स्वीकार करें और उस पर कार्य करें।
यह उससे अलग हो सकता है और ठोस कारणों से हो सकता है

एक विपरीत दृष्टिकोण लें। दूसरे शब्दों में, जैसा कि इस द्वारा आयोजित किया गया है
चंद्रमौलेश्वर प्रसाद के मामले में अदालत

वी. पटना उच्च न्यायालय और अन्य। [1970] 2 एससीआर 666,
सलाह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है।

हमेशा और कानून में मजबूरी के मामले के रूप में।

यद्यपि इस न्यायालय के निर्णय में

चंद्रमौलेश्वर प्रसाद का मामला उनके पास था।

व्याख्या का संदर्भ

संविधान के अनुच्छेद 233 और 235

सिद्धांत में शायद ही कोई अंतर है।

43. एक दिलचस्प बात जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है

उपर्युक्त मामले से यह है कि सभी 16 स्थानान्तरण थे

तत्कालीन सीजेआई के परामर्श से किया गया। इसके एक साल बाद,

मार्च 1977 में, आम चुनाव हुए और एक नया राजनीतिक पार्टी सत्ता में आई। सरकार की पुनः
जाँच

मामले की राय थी कि स्थानान्तरण का कोई औचित्य नहीं था

गुजरात के न्यायमूर्ति सेठ। यह इतिहास की बात है कि सभी 16

आपातकाल के दौरान जिन न्यायाधीशों का तबादला किया गया था, उन्हें भेजा गया था न्यायमूर्ति
सेठ 37 के साथ अपने मूल उच्च न्यायालयों में वापस जाएँ।

37 प्रति फजल अली, जे. एस. पी. गुप्ता मामले, *p.403*- "यह सच है कि आपातकाल के दौरान बहुत सारे स्थानांतरण थे जो इसके अनुरूप नहीं थे। अनुच्छेद 222 की भावना और यही कारण है कि सरकार ने इस तथ्य को स्वीकार किया था और लगभग सभी न्यायाधीशों को उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित करके स्थानांतरण को रद्द करने के लिए कदम उठाए थे, जहां से उनका स्थानांतरण किया गया था। "[2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह तथ्य इस तर्क के संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि
के मामले में कार्यपालिका को कोई भी कहने की अनुमति देना संवैधानिक न्यायालयों में
न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी -
न्यायपालिका की स्वतंत्रता का विनाशकारी।

44. इसके तीन साल बाद एक और महत्वपूर्ण घटना हुई।

इस देश के संवैधानिक इतिहास में हुआ। उस समय भारत सरकार के कानून मंत्री ने दिनांकित एक परिपत्र भेजा

18 मार्च 1981 में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को। मुखिया।

मंत्रियों से सभी अतिरिक्त अधिकारियों से प्राप्त करने का अनुरोध किया गया था।

न्यायाधीश (संबंधित उच्च न्यायालयों में कार्यरत) किसी भी अन्य उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए सहमति देते हैं।

देश को। इसने मुख्यमंत्रियों को भी इसी तरह की व्यवस्था करने की सलाह दी

उन व्यक्तियों से सहमति पत्र जो पहले से ही हो चुके हैं या हो सकते हैं

न्यायाधीशों के रूप में प्रारंभिक नियुक्ति के लिए भविष्य का प्रस्ताव किया जाए

उच्च न्यायालय। उक्त पत्र को एस. पी. गुप्ता मामले में चुनौती दी गई थी।

जमीन पर यह स्वतंत्रता पर सीधा हमला था

न्यायपालिका जो संविधान की एक बुनियादी विशेषता है 38 (पैरा

अलग-अलग निर्णय दिए गए। इस अदालत के समक्ष एक सवाल यह था कि क्या सीजेआई की राय दी जानी चाहिए। अन्य संवैधानिक अधिकारियों की राय पर प्रधानता।

काफी हद तक, इस न्यायालय ने वही दृष्टिकोण अपनाया जो इसमें लिया गया था।
मामला 39

संकलचंद

45. जनसंख्या में वृद्धि, कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाना

जनसंख्या में अधिकार, न्यायिक दायरे का विस्तार
समीक्षा

की समझ में बदलाव के परिणामस्वरूप

विभिन्न मौलिक अधिकारों का विस्तार और उनके अंतर

संबंध, प्रक्रियात्मक पर कानून में एक समुद्री परिवर्तन

अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में सीमाएँ

38 एस. पी. गुप्ता मामले का पैरा 2-भगवती, जे.

39 पैराग्राफ 30 और 31 देखें-भगवती, जे। ; पैरा 134-गुप्ता, जे., पैरा 632-तुलजापुरकर, जे. ; पैरा 726-देसाई, जे.

पारस 890 और 891-पाठक, जे। ; पारस 1031 और 1032-ई. एस. वेंकटरमैया, जे. सुप्रीम कोर्टवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [चेलामेश्वर, जे।]

और 226 के डॉकेट के विस्फोट का कारण बना

इस देश के संवैधानिक न्यायालय। लेकिन, न्यायाधीश

शक्ति अपेक्षाकृत स्थिर रही। 80 के दशक तक, समस्या
सरकार ने किया

अधिक तीव्र और जटिल हो गया। भारत

आवधिक बनाने के लिए आवश्यक व्यायाम नहीं करना

न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता का आकलन। में

कुछ उच्च न्यायालयों के मामले में, 10 की कमी भी थी।

यहां तक कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में भी कानूनी रूप से असमर्थनीय होने पर
अनुचित रूप से लंबा समय लग रहा था

आधार 41. सुभाष में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ

शर्मा बनाम। भारत संघ (1991) सप. 1 एस. सी. सी. 574 (संक्षेप में
ऐसी स्थिति पर ध्यान दिया।

सुभाष शर्मा मामला) ने

46. नियुक्ति के संबंध में उथल-पुथल थी

1970 और 1980 के दशक में संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीश।

कार्यालय में नियुक्ति के लिए वरिष्ठ न्यायाधीशों को हटा दिया गया था

सीजेआई का। शायद, इस न्यायालय के फैसलों से उत्साहित

संकल्पचंद और एस. पी. गुप्ता कार्यकारी (राष्ट्रीय परिषद में)

साथ ही राज्य स्तर पर) प्रणाली के अस्वास्थ्यकर हेरफेर का सहारा लिया। अनौपचारिक संविधान: अलिखित

उच्चतम न्यायालय के लिए न्यायाधीशों के चयन में मानदंड

इंडिया⁴² ने इस तरह के हेरफेर के कुछ उदाहरण दर्ज किए हैं।

40 सुभाष शर्मा बनाम। भारत संघ, 1991 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 574, पृष्ठ 586 पर: पैरा 18 "। हमें पता चलता है कि केरल उच्च न्यायालय में जहां स्वीकृत संख्या 2 कम कर दी गई है, वहां स्वीकृत संख्या 22 है, जबकि 1 जनवरी, 1990 को इसकी विचाराधीनता 34,330 थी, जो प्रति वर्ष प्रति न्यायाधीश 650 मामलों के माप के आधार पर लगभग 50 न्यायाधीशों की संख्या को उचित ठहराती है। हम यह संकेत देना चाहते हैं कि स्वीकृत संख्या को कम करने का कोई औचित्य नहीं था।

41 पैरा 19 "। वर्तमान में हम सरकार को सुझाव देते हैं कि इस मामले की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए और मौजूदा आवश्यकता के आधार पर व्यावहारिक तरीके से स्वीकृत संख्या निर्धारित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। यदि आवश्यकता और स्वीकृत संख्या के बीच कोई संबंध नहीं है और न्यायाधीश-श्रमशक्ति का प्रावधान पूरी तरह से अपर्याप्त है, तो आवश्यक परिणाम कानून के शासन का विलंबित और सुस्त प्रवर्तन होना चाहिए।

42 अभिनव चंद्रचूड़, अनौपचारिक संविधान: भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीशों के चयन में अलिखित मानदंड, (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, यूनाइटेड किंगडम 2014) पृष्ठ 113 से 120 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट देखें।

[2015] 13 एस सी आर।

अच्छी तरह से स्थापित साख के टिप्पणीकार
53 में से

समकालीन मुद्दे और विद्वान। ऐसा प्रतीत होता है कि

85, 32 कार्यवाहक प्रमुख की सिफारिशों पर किया गया था
कुछ सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश

न्यायाधीश। ऐसा माना जाता है कि

उच्च न्यायालय (जहाँ से उक्त 32 सिफारिशें की गई थीं)

उत्पन्न) जिन्होंने उन सिफारिशों को कार्य के रूप में शुरू किया

मुख्य न्यायाधीशों को स्थायी मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने के बाद ही

वे कार्यपालिका द्वारा सुझाए गए नामों की सिफारिश करने के लिए सहमत हुए।
 एक विशेष अतिरिक्त न्यायाधीश की पुष्टि नहीं की गई थी
 के बावजूद कई वर्षों के लिए स्थायी न्यायाधीश
 लगातार तीन बार उनकी पुष्टि के लिए सिफारिशें
 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और तीन मुख्य न्यायाधीशों ने कथित तौर पर
 इस आधार पर कि न्यायाधीश ने कोई निर्णय नहीं दिया था
 राज्य सरकार के लिए स्वादिष्ट। ऐसा प्रतीत होता है कि
 प्रधानमंत्री वी. पी. सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने मुख्यमंत्री द्वारा अनुशंसित 67 व्यक्तियों की नियुक्तियों को
 रोक दिया था।
 विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। शुल्कों का स्वतंत्र रूप से आदान-प्रदान किया जाता था
 संवैधानिक कार्यकर्ताओं द्वारा एक दूसरे के खिलाफ जो हैं संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रिया का हिस्सा
 अदालतें। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत संघ के लिए एक कानून मंत्री
 शिकायत की कि राज्य सरकारें हाई पैक करने की कोशिश कर रही हैं अपने स्वयं के पुरुषों के
 साथ अदालतें '43। बुनियादी तथ्य सत्यापन योग्य हैं, उनसे निष्कर्ष शायद विवादित हैं। दुर्भाग्य से,
 सरकार और सीजेआई के बीच पत्राचार और परामर्श प्रक्रिया का रिकॉर्ड कुछ सबसे अच्छे हैं
 इस देश के रहस्यों की रक्षा की।
 47. सवाल यह नहीं है कि क्या विभिन्न बयान
 उपर्युक्त पुस्तक में बनाई गई रचनाएँ पूरी तरह से सटीक हैं।
 सुभाष शर्मा मामले में इस अदालत द्वारा की गई टिप्पणियाँ
 43 43 1978 से, राज्य स्तर और संघ स्तर पर सरकारें अनिवार्य रूप से एक ही राजनीतिक दल की नहीं रहीं।
 देश के कुछ हिस्सों में क्षेत्रीय दलों ने दोनों स्तरों पर एक दल के शासन को समाप्त करते हुए सत्ता पर कब्जा
 कर लिया था।

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [चेलामेश्वर, जे।]
 एक सुरक्षित निष्कर्ष की ओर ले जा सकता है, कि इसमें कुछ सच्चाई होनी चाहिए
 पुस्तक में दिए गए विभिन्न कथन। उपरोक्त परिदृश्य
 चाहे सच हो या आंशिक रूप से सच, इसकी पृष्ठभूमि बनी

सुभाष शर्मा मामले (ऊपर) में की गई टिप्पणियाँ। ए के रूप में

परिणामस्वरूप, पीठ ने सोचा कि यह उचित है कि

एस. पी. गुप्ता के मामले पर एक बड़ी पीठ द्वारा विचार किया जाना चाहिए।

एस. पी. गुप्ता के मामले में बहुमत का दृष्टिकोण

“49.
विचार किया जाना चाहिए

हम निर्देश देते हैं कि एक बड़ी पीठ द्वारा

1987 के डब्ल्यू. पी. सं. 1303 के कागजात रखे जाने हैं

विद्वान मुख्य न्यायाधीश के समक्ष एक के गठन के लिए

दोनों प्रश्नों की जांच करने के लिए नौ न्यायाधीशों की पीठ

हमने ऊपर उल्लेख किया है, अर्थात्, की स्थिति
प्रधानता के संदर्भ में भारत के मुख्य न्यायाधीश

और, दूसरी बात, न्यायाधीश के निर्धारण की न्याय्यता।

ताकत ”।

48. एकर परिणामस्वरूप दोसर न्यायाधीशक मामला शुरू भेल। बात यह थी कि

नौ न्यायाधीशों द्वारा सुना गया। पाँच अलग-अलग निर्णय दिए गए।

न्यायमूर्ति वर्मा ने उनमें से पाँच की ओर से बात की। न्यायमूर्ति पांडियन और न्यायमूर्ति कुलदिप
सिंह ने अलग-अलग फैसले लिखे लेकिन सहमत हो गए।

न्यायमूर्ति वर्मा के निष्कर्षों के साथ, लेकिन न्यायमूर्ति अहमदी और

न्यायमूर्ति पुंड्री ने ऐसा नहीं किया। एक प्रस्ताव जिस पर सभी नौ

संविधान, न्यायपालिका की स्वतंत्रता अपरिहार्य है। न्यायमूर्ति वर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह
बुनियादी ढांचे का एक हिस्सा है।

संविधान की संरचना। असहमति का मुद्दा

44 पैरा 421-इन प्रश्नों पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता के संदर्भ में, संविधान की मूल संरचना के एक भाग के
रूप में, लोकतांत्रिक प्रणाली के संरक्षण के लिए आवश्यक 'कानून के शासन' को सुरक्षित करने के लिए विचार
किया जाना चाहिए। संविधान में अपनाई गई शक्तियों के पृथक्करण की व्यापक योजना, सबसे निचले स्तर पर
भी 'न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने' के निर्देशात्मक सिद्धांत के साथ, संविधान में प्रासंगिक
प्रावधानों के सही अर्थ के लिए कुछ अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।

न्यायपालिका की संरचना। इन प्रावधानों का निर्माण संवैधानिक योजना में इन मौलिक अवधारणाओं के
अनुरूप होना चाहिए ताकि जीवन शक्ति को संरक्षित किया जा सके और संविधान को एक जीवंत जीव के रूप
में बनाए रखने के लिए आवश्यक विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच केवल मोड के बारे में है

जिसके द्वारा ऐसी स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना और निरंतरता प्राप्त की जा सकती है।

49. शाब्दिक रूप से, ऐसे प्रावधान जो इंगित करते हैं कि न्यायपालिका

कार्यपालिका से स्वतंत्र होना आवश्यक है अनुच्छेद 5045

और न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ का रूप

प्रपत्र IV46 में निर्धारित संवैधानिक न्यायालय और

भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत VIII47।

50. हालांकि, संरचनात्मक रूप से इसमें कई संकेत हैं

संविधान की योजना जो निर्विवाद रूप से

यह निष्कर्ष कि संविधान के निर्माता चाहते थे

एक न्यायपालिका जो कार्यपालिका से पूरी तरह से स्वतंत्र है

और क्षणिक और स्थानांतरण की अनियमितताओं से अछूता

बहुसंख्यकवादी गतिशीलता। संविधान की योजना के तहत,

संबंधित मामलों में राज्य विधानमंडलों की कोई भूमिका नहीं है।

इसके संवैधानिक न्यायालयों की स्थापना के लिए

देश। अकेले संसद कुछ मामलों से निपटने के लिए अधिकृत है।

45 अनुच्छेद 50। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना- "राज्य उठाएगा

राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम।

45 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रपत्र: —

"मैं, ए. बी., भारत के सर्वोच्च न्यायालय (या भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक) का मुख्य न्यायाधीश (या एक न्यायाधीश) नियुक्त होने के बाद, ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ कि मैं सच्चा विश्वास रखूंगा और कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति विश्वास और निष्ठा की दृढ़ता से पुष्टि करूंगा, कि मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, कि मैं विधिवत और ईमानदारी से और अपनी क्षमता के अनुसार, ज्ञान

और निर्णय के बिना अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करूंगा।
दुर्भावना और मैं संविधान और कानूनों को बनाए रखूंगा।

डर या पक्षपात, स्नेह या

47 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा की जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का रूप:

"आई, ए. बी., को उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश (या न्यायाधीश) नियुक्त किया गया है

(.....। कि मैं भारत की संप्रभुता और
अखंडता को बनाए रखूंगा, कि मैं बिना किसी डर या पक्षपात, स्नेह या दुर्भावना के अपने पद के कर्तव्यों का
विधिवत और ईमानदारी से और अपनी पूरी क्षमता, ज्ञान और निर्णय के साथ पालन करूंगा और मैं संविधान
और कानूनों को बनाए रखूंगा। सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [चेलामेश्वर, जे।]

संविधान की स्थापना के पहलू न्यायालयों और उनके प्रशासन जैसे कि न्यायालयों की संख्या, वेतन
और अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण

न्यायाधीश आदि। एक को की गई नियुक्ति की समाप्ति

संवैधानिक न्यायालय केवल इसके माध्यम से किया जा सकता है संसद द्वारा महाभियोग की
प्रक्रिया, एकमात्र विधायी

केवल 'सिद्ध दुर्यवहार या' के आधार पर एक विशिष्ट विधायी प्रक्रिया का पालन करके महाभियोग चलाने के
लिए अधिकृत निकाय

असमर्थता '। इस तरह की प्रक्रिया को अनुच्छेद 124 (5) 48 के तहत एक संवैधानिक शर्त द्वारा और अधिक
कठोर बनाया गया है कि - जाँच और दुर्यवहार के प्रमाण के लिए प्रक्रिया या

न्यायाधीश की अक्षमता को कानून द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए। इसके बाद भी

दुर्यवहार या असमर्थता स्थापित की जाती है कि न्यायाधीश को हटाना स्वतः नहीं होता है, बल्कि मतदान
और विशेष न्यायाधीश द्वारा अनुमोदन के अधीन होता है। अनुच्छेद 124 (4) 49 के तहत निर्दिष्ट
संसद का बहुमत। संशोधन से पहले, न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति

राष्ट्रपति में निहित संवैधानिक न्यायालय विभिन्न संविधान के साथ परामर्श में प्रयोग किया गया

अनुच्छेद 124 और 217 के तहत उल्लिखित पदाधिकारी

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के साथ परामर्श किया गया उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों
की नियुक्ति के लिए अनिवार्य।

51. इस तरह की योजना की पृष्ठभूमि में एक सवाल खड़ा हुआ

क्या नियुक्ति प्रक्रिया किसी भी तरह से प्रभावित करती है

न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो निश्चित रूप से एक हिस्सा थी

48 अनुच्छेद 124 (5)। संसद कानून द्वारा खंड (4) के तहत किसी न्यायाधीश के संबोधन को प्रस्तुत करने और दुर्यवहार या अक्षमता की जांच और प्रमाण के लिए प्रक्रिया को विनियमित कर सकती है।

49 अनुच्छेद 124 (4)। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से राष्ट्रपति के एक आदेश के अलावा नहीं हटाया जाएगा जो प्रत्येक न्यायाधीश द्वारा एक संबोधन के बाद पारित किया गया हो। संसद के सदन को उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत और उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई के बहुमत से समर्थित किया गया है और साबित दुर्यवहार या अक्षमता के आधार पर इस तरह के निष्कासन के लिए उसी सत्र में राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

संविधान की मूल संरचना। न्यायाधीशों का बहुमत

राय दी कि यह 50 करता है। उनके प्रभुत्वों ने इस तरह के लिए समर्थन प्राप्त किया

50 (प्रति माननीय। पांडियन, जे.)-पैरा 49 "। समय पर स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक अन्य बुनियादी और अविभाज्य महत्वपूर्ण शर्त बिल्कुल आवश्यक है

न्यायपालिका; और यह एक उचित और उपयुक्त उम्मीदवार को प्रायोजित करने, चुनने और नियुक्त करने के मामले में अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली से संबंधित है।

(उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय) उच्च न्यायपालिका। समग्र स्थिति एक प्रमुख घटक है जो अन्य संवैधानिक रूप से गारंटीकृत के साथ जाता है।

न्यायपालिका की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने में सेवा की शर्तें। अलग तरह से कहने के लिए, एक स्वस्थ स्वतंत्र न्यायपालिका को सबसे पहले न्यायाधीशों की नियुक्ति के तरीके के संबंध में तेजी से महत्वपूर्ण शर्त को पूरा करके और दूसरा, अधिकारों, विशेषाधिकारों और अन्य सेवा शर्तों को पूरा करके संरक्षित किया जा सकता है। परिणामस्वरूप अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति की विधि और रणनीति से शुरू होने वाली सभी आवश्यक शर्तों की पूर्णता या समग्रता ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित और संरक्षित करेगी। अन्यथा, न केवल न्यायपालिका की विश्वसनीयता डगमगाएगी और गिर जाएगी, बल्कि पूरी न्यायिक प्रणाली भी फट जाएगी जो बदले में लोकतंत्र के उचित कामकाज को पंगु बना सकती है और इस पोषित अवधारणा का दर्शन वास्तविकता के बजाय केवल एक मिथक होगा। (प्रति माननीय। कुलदिप सिंह, जे.)-पैरा 335 "। फिर जो सवाल विचार के लिए आता है, वह यह है कि क्या एक स्वतंत्र न्यायपालिका हो सकती है जब न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति कार्यपालिका में निहित हो? हां कहना अतार्किक होगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अटूट रूप से जुड़ी हुई है और उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति की संवैधानिक प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। * न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमारे संविधान की मूल विशेषता है और यदि इसका अर्थ वही है जिसकी हमने ऊपर चर्चा की है, तो संविधान निर्माता कभी भी कार्यपालिका को यह शक्ति देने का इरादा नहीं रख सकते थे। अन्यथा भी सरकारें-केंद्र या राज्य-बड़ी संख्या में न्यायालयों के समक्ष पक्षकार होती हैं। संघ कार्यपालिका के विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों में महत्वपूर्ण हित होते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए आते हैं। कार्यपालिका-किसी न किसी रूप में अदालतों के समक्ष सबसे बड़ा

एकल वादी होता है। इस मामले के दृष्टिकोण में न्यायपालिका लोगों और कार्यपालिका के बीच मध्यस्थ होने के नाते-संविधान के निर्माता सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अंतिम अधिकार कार्यपालिका के हाथों में नहीं छोड़ सकते थे।

(प्रति माननीय। वर्मा, जे.)-पैरा 447 "। जब संविधान का मसौदा तैयार किया जा रहा था, तो आम सहमति थी कि न्यायाधीशों की नियुक्तियों में

उच्चतर न्यायपालिका को पूर्ण विवेक पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए

कार्यपालिका, और यह भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने की बाध्यता को लागू करने वाले संविधान में किए गए प्रावधान का कारण था। यह नियुक्ति के बाद केवल कार्यकाल की सुरक्षा और सेवा की अन्य शर्तों के प्रावधान तक सीमित रहने के बजाय, उनकी नियुक्ति के समय भी वरिष्ठ न्यायपालिका के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए किया गया था। यह महसूस किया गया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा न केवल सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन v की सुरक्षा प्रदान करके की जानी चाहिए।

यू. ओ. आई. [चेलामेश्वर, जे।]

संविधान में इतिहास और बहसों से निष्कर्ष

के मामलों में की गई टिप्पणियों के अलावा सभा

संकलचंद और एस. पी. गुप्ता। उनके प्रभुत्वों ने भी ध्यान दिया

इस तथ्य का कि संविधान सभा ने जानबूझकर बहिष्कार किया

नियुक्तियों की प्रक्रिया में संसद की कोई भूमिका, अमेरिकी संवैधानिक मॉडल से सचेत प्रस्थान

जहाँ संघीय न्यायिक नियुक्तियाँ सहमति के अधीन हैं

सीनेट से।

52. इस तरह के विश्लेषण की पृष्ठभूमि में, परामर्श

अनुच्छेद 124 और 217 में भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ सीजेआई की राय को प्रधानता प्रदान करने के रूप में व्याख्या की गई थी।

सीजेआई के साथ परामर्श संविधान की रूपरेखा का हिस्सा था

(संघ कार्यपालिका को) निरंकुश अधिकार से इनकार करने के लिए सभा संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। द.

संविधान सभा ने ऐसी नियंत्रण शक्ति संसद को सौंपने का विकल्प नहीं चुना जिसके लिए कार्यपालिका अन्यथा है।

संविधान की योजना के तहत उत्तरदायी। यह न्यायालय,

इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला कि सीजेआई की राय को प्राथमिकता दिए बिना

अनुच्छेदों के तहत विचार की गई पूरी परामर्श प्रक्रिया

124 और 217 केवल सजावटी बन जाएगा अपने पूर्ण विवेक से नियुक्तियाँ करने के लिए कार्यकारी, सबसे अधिक संभावना राजनीतिक समीचीनता के विचारों के आधार पर।

ऐसी प्रक्रिया संवैधानिक लक्ष्य के विरोधी होगी।

एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करना। हालांकि, न्याय

वर्मा ने स्पष्ट रूप से घोषणा की

"438. प्रधानता पर बहस का उद्देश्य है

निर्धारित करें कि संवैधानिक में से कौन

नियुक्ति के बाद कार्यकाल और सेवा की अन्य शर्तें, लेकिन राजनीतिक विचारों के प्रभाव को रोकने के लिए भी

प्राधिकारी की नियुक्ति। यही कारण है जिसने भारत के मुख्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के दायित्व को शामिल करने के लिए प्रेरित किया। उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 124 (2) और 217 (1) में। संविधान सभा की बहसों इस तरह के परामर्श के लिए निर्धारित करने में इस उद्देश्य का खुलासा करती हैं, यहां तक कि

यद्यपि नियुक्ति अंततः एक कार्यकारी कार्य है। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

एकीकृत प्रक्रिया में शामिल कार्यकर्ता नियुक्तियों का सबसे अच्छा निर्वहन करने के लिए सुसज्जित है

प्रधानता की भूमिका से जुड़ा अधिक बोझ,

उचित चुनाव करने का; और यह बहस है

यह निर्धारित करने के लिए नहीं कि उनके बीच कौन हकदार है

अधिक महत्वपूर्ण है या विजेता को लेना है

बहस के अंत में पुरस्कार। इससे पहले का कार्य

हमें इस धारणा के साथ प्रदर्शन करना होगा।

संकेत यह है कि

450.

नियुक्ति के लिए उपयुक्त उम्मीदवार का चयन,
 परामर्श प्रक्रिया जिसमें कार्यपालक
 केवल जाँच के रूप में कार्य करने की शक्ति होनी चाहिए
 मुख्य न्यायाधीश द्वारा शक्ति का प्रयोग
 इस प्रकार, नियुक्ति में कार्यकारी तत्व
 प्रक्रिया को न्यूनतम कर दिया जाता है और कोई भी
 राजनीतिक प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसी के लिए
 कारण यह है कि इसके बजाय 'परामर्श' शब्द
 'सहमति' का उपयोग किया गया था, लेकिन यह केवल किया गया था
 यह इंगित करने के लिए कि पूर्ण विवेकाधिकार नहीं था
 किसी को दिया गया, यहां तक कि मुख्य न्यायाधीश को भी नहीं
 व्यक्तिगत रूप से भारत का, बहुत कम
 कार्यपालक, जिसके पास पहले पूर्ण विवेकाधिकार था
 भारत सरकार अधिनियमों के तहत "।

[जोर दिया गया]

53. इस न्यायालय ने उन परिस्थितियों का भी संकेत दिया जिन पर
 भारत के राष्ट्रपति को संवैधानिक रूप से न्यायोचित ठहराया जाएगा
 सीजेआई द्वारा व्यक्त राय के अनुसार कार्य करना। इस न्यायालय ने कभी यह नहीं माना कि परामर्श का अर्थ
 सहमति है
 कुछ हलकों में व्याख्या करने की मांग की गई है और मुझे यह कहते हुए खेद है
 यहाँ तक कि बताए गए उद्देश्यों और संशोधन के कारणों में भी।

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [चेलामेश्वर, जे।]

"न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में

न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के मामलों में
 अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम। भारत संघ

और 1998 में तीसरे न्यायाधीशों में इसकी सलाहकार राय

मामले में अनुच्छेद 124 (2) और 217 (1) की व्याख्या की गई थी

अर्थ के संबंध में संविधान का
"परामर्श" को "सहमति" के रूप में। यह भी था

अभिनिर्धारित किया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श

इसका अर्थ है कॉलेजियम जिसमें मुख्य न्यायाधीश और

दो या चार न्यायाधीश, जैसा भी मामला हो। यह है

जिसके परिणामस्वरूप एक प्रक्रिया ज्ञापन रखा गया

उस प्रक्रिया को नीचे करें जिसका वर्तमान में पालन किया जा रहा है
दोनों उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु

और सर्वोच्च न्यायालय। ज्ञापन

प्रक्रिया स्वयं न्यायपालिका को प्रदान करती है -

न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए शक्ति।

[जोर दिया गया]

54. 51 के बारे में परस्पर विरोधी राय हैं

द्वितीय न्यायाधीशों के निर्णय की न्यायशास्त्रीय दृढ़ता

51 सर्वोच्च लेकिन अचूक नहीं-ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस-2000 ईस्वी नामक पुस्तक में प्रकाशित लॉर्ड टेम्पलमैन की अनुकूल राय और लॉर्ड कुक ऑफ थॉर्नटन के आलोचनात्मक दृष्टिकोण के लेख देखें। " संविधान का अनुच्छेद 124 राष्ट्रपति को (प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करते हुए) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार देता है। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श करने का विवेकाधिकार दिया गया है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में, भारत के मुख्य न्यायाधीश से हमेशा परामर्श किया जाएगा। इसी तरह, अनुच्छेद 217 में किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने की आवश्यकता है। 1993 में, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और शक्तियों के पृथक्करण को ध्यान में रखते हुए, जिसे कोर्ट ने संविधान में निहित माना था, भारत के मुख्य न्यायाधीश के विचार सर्वोच्च होने चाहिए जब उनसे परामर्श किया गया था। अदालत ने दिशानिर्देश भी निर्धारित किए

अस्थायी कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद की अवधि को नियंत्रित करना। बहुमत के निर्णय की आलोचना 'परामर्श' शब्द के अर्थ के विस्तार के रूप में की गई है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट में पहले के अनुभव को ध्यान में रखते हुए

[2015] 13 एस सी आर।

मामला। मुझे नहीं लगता कि इस पहलू की जांच करने की आवश्यकता है। वर्तमान विवाद को निर्धारित करने के उद्देश्य से मामला।

55. शासन के काम करने के लगभग 20 वर्षों के बाद

दूसरे न्यायाधीशों के मामले के तहत बनाए गए, गंभीर सवाल उत्पन्न हुआ कि क्या शासन इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न हो रहा है

इस न्यायालय द्वारा दूसरे न्यायाधीशों के मामले में दी गई व्याख्या से कोई भी संवैधानिक रूप से वांछित परिणाम प्राप्त हुआ

एक स्वतंत्र और कुशल न्यायपालिका की स्थापना - संवैधानिक न्यायालय। के बारे में जवाब दें स्वतंत्रता व्यक्तिपरक हो सकती है और दक्षता शायद हो सकती है बहुत सुखद न हो।

56. कुछ वर्षों के भीतर सच्चाई के बारे में संदेह पैदा हो गया

द्वितीय न्यायाधीशों के मामले का तात्पर्य। भारत के राष्ट्रपति

अनुच्छेद 143 का आह्वान किया और इस पर कुछ स्पष्टीकरण मांगे

राय के लिए अग्रणी दूसरे न्यायाधीशों के मामले का निर्णय

इस न्यायालय ने 1998 के विशेष संदर्भ संख्या 1 में रिपोर्ट की, (1998) 7 एस. सी. सी. 739 (इसके बाद 'तीसरे न्यायाधीशों का मामला' के रूप में संदर्भित)। दुर्भाग्य से, तथ्यात्मक मैट्रिक्स जिस पर संदेह थे

भारत सरकार द्वारा मनोरंजन में दर्ज नहीं हैं

राय दें। लेकिन तीसरे न्यायाधीशों के मामले के पैरा 41 में लिखा है:

"41. हम आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं कि क्रमिक प्रमुख

न्यायपालिका के सदस्यों के व्यक्तित्वों और दृष्टिकोण को प्रभावित करने के लिए कार्यपालिका द्वारा किए गए प्रयासों का भारत, और न्यायपालिका को नियंत्रित करने के लिए पाकिस्तान में किए गए सफल प्रयासों को ध्यान में रखते हुए और संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के दुर्भाग्यपूर्ण परिणामों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति द्वारा कांग्रेस की मंजूरी के अधीन, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का बहुमत निर्णय न्यायपालिका की स्वतंत्रता का एक स्वागत योग्य दावा करता है और अखंडता और गुणवत्ता की नियुक्तियों को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है, एक पूर्ववर्ती तरीका है जिसे अंग्रेज इस तरह के लाभ का पालन कर सकते हैं।

लॉर्ड टेम्पलमैन

"कुल मिलाकर, तीसरे न्यायाधीशों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की राय किसी सर्वोच्च राष्ट्रीय द्वारा जारी किए गए सबसे उल्लेखनीय फैसलों में से एक होनी चाहिए।

कोमोन कानून की दुनिया में अपीलीय न्यायालय। चूंकि, कुछ मामलों में, मुझे संविधान की दृढ़ता के बारे में सम्मानजनक संदेह व्यक्त करना पड़ा है।

उस राय की नींव "।

लॉर्ड कुक ऑफ थॉर्नटन सुपरम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [चेलामेश्वर, जे।]

भारत के न्यायाधीश अब से इसके अनुसार कार्य करेंगे -

द्वितीय न्यायाधीशों का मामला और यह राय।

57. कोई आश्चर्य नहीं, गपशप और अटकलें इकट्ठा होती हैं

ऐसी स्थिति में गति और मुद्रा। यदि नौ-न्यायाधीश

इस न्यायालय की पीठ एक आशावादी दृष्टिकोण रखती है कि लगातार

भारत के मुख्य न्यायाधीश अब से इसके अनुसार कार्य करेंगे।

दूसरे न्यायाधीशों के मामले में, एकमात्र तार्किक निष्कर्ष है कि

यह खींचा जा सकता है कि दूसरे न्यायाधीशों द्वारा निर्धारित कानून

उत्तराधिकारी प्रमुख द्वारा मामले का ईमानदारी से पालन नहीं किया गया था

न्यायाधीश, यदि बिल्कुल नहीं तो कम से कम कुछ मामलों में आकर्षित करते हैं
मंत्रियों के बजाय, न्यायाधीशों ने संरक्षण दिया। 52

टिप्पणियाँ करें।

58. अगले डेढ़ दशक में इस देश ने

न्यायपालिका से जुड़ी कई अप्रिय घटनाओं को देखा

नियुक्तियाँ-ऐसी घटनाएँ जो अटकलों को विश्वास दिलाती हैं

कि दूसरे और तीसरे न्यायाधीशों द्वारा स्थापित प्रणाली

इसकी परिचालन वास्तविकता में मामले शायद सबसे अच्छी प्रणाली नहीं है।

एक स्वतंत्र और कुशल न्यायपालिका को सुरक्षित करने के लिए। 53

59. दो घटनाएँ इस न्यायालय के अभिलेख का हिस्सा हैं और

होने का आरोप आकर्षित किए बिना उद्धृत किया जा सकता है

की पवित्रता के बारे में गैर-जिम्मेदार और असंबद्ध

52 लायर, वी. आर. कृष्णा, न्यायपालिका: एक सुधार एजेंडा-II, द हिंदू (ऑनलाइन संस्करण) 15.08.2002

53 "एक स्वतंत्र न्यायपालिका-10 नवंबर 2011 को 5 वें वी. एम. तारकुंडे स्मारक व्याख्यान में सुश्री न्यायमूर्ति रुमा पाल द्वारा दिया गया भाषण।

"जैसा कि मैंने कहीं और कहा है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा एक न्यायाधीश को उच्च न्यायालय में नियुक्त किया जाता है, वह इस देश में सबसे अच्छी तरह से रखी गई गोपनीयताओं में से एक है। प्रक्रिया की गोपनीयता न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए संभावित उम्मीदवार की क्षमताओं और उपयुक्तता के बारे में जानकारी के अपर्याप्त इनपुट की ओर ले जाती है। एक आकस्मिक टिप्पणी, एक अफवाह या यहाँ तक कि तीसरी जानकारी भी एक न्यायाधीश की संभावनाओं को धूमिल करने के लिए पर्याप्त हो सकती है। इसके विपरीत एक व्यक्तिगत मित्रता या अधोषित दायित्व एक सिफारिश को रंग दे सकता है। कॉलेजियम के भीतर सहमति है

कभी-कभी एक सौदे के माध्यम से हल किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप संदिग्ध नियुक्तियाँ वादियों के लिए विनाशकारी परिणामों और न्यायिक प्रणाली की विश्वसनीयता के साथ होती हैं। इसके अलावा, प्रणाली के भीतर बढ़ती चाटुकारिता और 'लॉबिंग' से संस्थागत स्वतंत्रता से भी समझौता किया गया है।

!

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संस्था। इन घटनाओं के कारण शांति में बताए गए निर्णय लिए गए भूषण एंड अदर वी. भारत संघ और एक अन्य, (2009) 1

एस. सी. सी. 657, पी. डी. दिनाकरन (1) बनाम। न्यायाधीश जांच समिति

& अन्य, (2011) 8 एस. सी. सी. 380, पी. डी. दिनाकरन (2) बनाम। न्यायाधीश जाँच समिति और एक अन्य, (2011) 8 एस. सी. सी. 474।

जबकि उक्त दो घटनाओं में से पहली घटना से संबंधित है

मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, द्वितीय

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की इस पद पर पदोन्नति के संबंध में अदालत।

60. शांति भूषण मामले (ऊपर) में विवाद था

मद्रास में एक स्थायी न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में

उच्च न्यायालय। आरोप यह प्रतीत होता है कि प्रक्रिया दूसरे और तीसरे न्यायाधीशों के मामलों में संकेत नहीं दिया गया था

पीछा किया। मैं अभिव्यक्ति का उपयोग करता हूँ क्योंकि यह प्रतीत होता है

यह पहचानना मुश्किल है कि मामले में सटीक अभिवचन क्या था। इस तरह के निष्कर्ष पर केवल अनुमान से ही पहुंचा जा सकता है। यहाँ तक कि

इस न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष वास्तव में कोई प्रकाश नहीं डालता है। इस न्यायालय के फैसले के पैरा 22 में यह दर्ज किया गया है।

इस प्रकार है:

"22. स्थिति लगभग निर्विवाद है कि

17.3.2005 भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश

9 में से 8 का कार्यकाल बढ़ाने की सिफारिश की गई

अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में नामित व्यक्ति
चार महीने की अवधि डब्ल्यू. ई. एफ. 3.4.2005 29.4.2005 पर

के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सहित कॉलेजियम

54 शांति भूषण (ऊपर)-पैरा 2। आग्रह किया गया प्राथमिक आधार यह है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय को उनके वरिष्ठ सहयोगियों के विचारों को ध्यान में रखते हुए सामूहिक रूप से गठित किया जाना चाहिए, जिनके साथ राय बनाने के लिए उनसे परामर्श करने की आवश्यकता है और कोई भी नियुक्ति तब तक नहीं की जा सकती है जब तक कि यह उपरोक्त तरीके से गठित भारत के मुख्य न्यायाधीश की अंतिम राय के अनुरूप न हो। अतः यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 2 की स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति जैसा कि अधिसूचित किया गया है

2.2.2007 कानून में कोई पवित्रता नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [चेलामेश्वर, जे।]

भारत का विचार था कि उत्तरदाता का नाम 2

किसी अन्य न्यायाधीश के साथ सिफारिश नहीं की जा सकती है

स्थायी न्यायाधीश के रूप में पुष्टि के लिए। चूंकि यह

यह स्पष्ट है कि न्यायाधीश चिंतित नहीं हैं

यदि मामले में कोई राजनीतिक कोण है

अतिरिक्त न्यायाधीश या स्थायी के रूप में नियुक्ति
न्यायाधीश; तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश को इस पर कायम रहना चाहिए था

कॉलेजियम द्वारा व्यक्त विचार और होना चाहिए

के विचारों से प्रभावित नहीं हुए हैं

उत्तरदाता 2 का एक वर्ष के लिए; जैसा कि यह राशि शब्दों की बाजीगरी से प्रधानता का समर्पण "।

[जोर दिया गया]

भले ही मैं विवादास्पद बयानों को नजरअंदाज करने का विकल्प चुनता हूँ
नियुक्ति के संबंध में (हाल के दिनों में) किया गया
मामले में उन व्यक्तियों द्वारा प्रश्न, जिनके पास उच्च संवैधानिक अधिकार थे
इस न्यायालय के पूर्व सदस्यों सहित, निर्णय छोड़ देता है यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त गुंजाइश
है कि सब कुछ ठीक नहीं हुआ
नियुक्ति। ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक संयुक्त उद्यम था
द्वितीय और तृतीय द्वारा निर्धारित कानून का विध्वंस कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों द्वारा
मामलों का न्याय करता है जो
कोई भी पक्ष स्वीकार करने को तैयार नहीं है।

61. उस मामले में याचिकाकर्ताओं की शिकायत प्रकट होती है
कि " कॉलेजियम से परामर्श नहीं किया गया था। " दुर्भाग्य से,
उक्त निर्णय में इस संबंध में कोई सटीक निष्कर्ष नहीं है।
दूसरी ओर, निर्णय के पैरा 22 की सामग्री छोड़ देती है। मुझे एक असहज भावना के साथ कि कुछ
था
शायद किसी राजनीतिक दबाव में कानून से प्रस्थान। काश मैं गलत होता।

62. दूसरी घटना द्वारा की गई एक सिफारिश है
तत्कालीन सीजेआई जाहिरा तौर पर कॉलेजियम की सहमति से

1 [2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

याचिकाकर्ता की पदोन्नति के लिए। [देखिए: पी. डी. दिनाकरन (1) (ऊपर); पी. डी. दिनाकरन (2) (ऊपर)]। यह सिफारिश सफल नहीं हुई। उम्मीदवार की अयोग्यता के गंभीर आरोप
जिनके नाम की सिफारिश की गई थी, एक महान के लिए अग्रणी

सार्वजनिक बहस। उन आरोपों को दोहराना अप्रिय है। वे उपर्युक्त दो में दर्ज हैं।
निर्णय। की ओर से किसी विफलता का कोई आरोप नहीं है
कॉलेजियम निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा
दुर्भाग्यपूर्ण बनाने में दूसरे और तीसरे न्यायाधीशों के मामले
सिफारिश करें। लेकिन, सिफारिश निश्चित रूप से बेनकाब हो गई
प्रस्तावित सिद्धांत का उथलापन (कम से कम एक बार के लिए)
एस. पी. से शुरू होने वाले मामलों की त्रयी में इस न्यायालय द्वारा
गुप्ता और तीसरे न्यायाधीशों के मामले के साथ समाप्त होता है कि सीजेआई और
कॉलेजियम सबसे उपयुक्त प्राधिकरण हैं
नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता का मूल्यांकन इस देश में संवैधानिक न्यायालयों के
न्यायाधीशों के रूप में। ए.
पाठ्यक्रम के दौरान बार में कुछ और उदाहरणों का उल्लेख किया गया था
न केवल सिद्धांत की उथल-पुथल को प्रदर्शित करने के लिए सुनवाई
लेकिन कॉलेजियम की सिफारिशों में भी ऐसा नहीं है अनिवार्य रूप से हमेशा संस्थान के
सर्वोत्तम हित में रहा है
और राष्ट्र। यह वास्तव में आवश्यक नहीं है कि सभी को रिकॉर्ड पर रखा जाए
विवरण लेकिन यह उल्लेख करने के लिए पर्याप्त है कि पहले उल्लिखित दो मामले निश्चित रूप से केवल
उदाहरण नहीं हैं
कॉलेजियम की शक्ति का अनुचित प्रयोग।

63. मुझे पता है कि अनुचित के कुछ बुरे उदाहरण

शक्ति का प्रयोग चरित्र का निर्धारण नहीं करता है शक्ति। सत्ता का इस तरह का अनुचित प्रयोग
किया गया था

कार्यपालिका द्वारा भी जो पहले ही नोटिस किया जा चुका है। दोनों शाखाएँ

सरकार एक-दूसरे पर योग्य नहीं होने का आरोप लगा रही है

भरोसा रखें। 55 कम से कम नागरिक समाज का एक वर्ग मानता है कि दोनों

55 मेहता, प्रताप भानू, 'आप किस पर भरोसा करते हैं'; द इंडियन एक्सप्रेस, 14 मई 2015- "अंतर्निहित
संवैधानिक आरोप यह है। न्यायपालिका ने सुधार के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति का एक तरीका
बनाया था जिसने प्रभावी रूप से सरकार की अन्य शाखाओं को दरकिनार कर दिया था। इस व्यवस्था को

बर्दाश्त किया गया था, इसलिए नहीं कि यह एक संवैधानिक पाठ या किसी पवित्र सिद्धांत के अनुरूप था, बल्कि इसलिए कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [चेलामेश्वर, जे।]

सही हैं। विवादित संशोधन पृष्ठभूमि में आया उपर्युक्त अनुभव।

64. न्यायपालिका की स्वतंत्रता बुनियादी में से एक है

संविधान की विशेषताएँ। सात-इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ

एल. चंद्र कुमार बनाम। भारत संघ और अन्य।, (1997) 3 एससीसी

261 पहले से ही माना गया है कि विधायी की न्यायिक समीक्षा की शक्ति

संवैधानिक न्यायालयों द्वारा कार्रवाई मूल का हिस्सा है संविधान की संरचना और इस तरह के महत्वपूर्ण का अभ्यास

कार्य एक स्वतंत्र न्यायपालिका के अस्तित्व की मांग करता है।

"78. न्यायालयों की शक्ति की वैधता
संवैधानिक लोकतंत्र विधायी समीक्षा करेंगे

जब से इसकी पहली बार कल्पना की गई थी, तब से कार्रवाई पर सवाल उठाए गए हैं। भारत का संविधान,

महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय। तरीके का विश्लेषण
जिसमें हमारे संविधान के निर्माता

न्यायपालिका से संबंधित निगमित प्रावधान

यह इंगित करेगा कि वे बहुत बड़े थे

स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए चिंतित

न्यायपालिका। इन प्रयासों को निर्देशित किया गया था

यह सुनिश्चित करना कि न्यायपालिका सक्षम होगी

न्यायिक शक्तियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करना

समीक्षा करें। जबकि संविधान शक्ति प्रदान करता है

उच्च न्यायालयों पर कानूनों को निरस्त करने के लिए और

ऐसा लगता है कि इसने न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखा है। 1970 के दशक के अनुभव ने न्यायपालिका की राजनीतिक पैकिंग की संभावना को एक जीवित भय बना दिया। इस व्यवस्था को चुनौती दी जा रही है, इसलिए नहीं कि हमने एक नए सिद्धांत की खोज की है, बल्कि इसलिए कि न्यायपालिका की विश्वसनीयता कम हो गई है। हम वास्तव में कह रहे हैं कि कोई भी व्यवस्था जो पूरी तरह से न्यायपालिका पर निर्भर करती है, वह अविश्वसनीय साबित हुई है। एनजेएसी को चुनौती देने वाले 1970 के दशक के भूत पर भरोसा कर रहे हैं: क्या आप वास्तव में चाहते हैं कि नियुक्तियों में राजनीतिक वर्ग की अधिक भूमिका हो? सरकार की दोनों शाखाएँ एक-दूसरे पर आरोप लगा रही हैं कि

विश्वास के योग्य होना। इस प्रक्रिया में, उन्होंने एक-दूसरे को नीचे खींच लिया है। समस्या यह है कि दोनों सही हैं। सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी.

उच्चतम न्यायालय, इसमें विस्तृत विवरण भी शामिल है
कार्यकाल, वेतन से संबंधित प्रावधान,
भत्ते, न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु भी
न्यायाधीशों के चयन के लिए तंत्र के रूप में
उच्च न्यायालय। इस तरह के समावेशन ऐसा प्रतीत होता है कि विस्तृत प्रावधान
बनाए रखने का कार्य सौंपा गया संविधान और इस उद्देश्य के लिए, प्रदान किया गया है
इसकी व्याख्या करने की शक्ति। यह वे हैं जिन्हें यह सुनिश्चित करना है कि द्वारा परिकल्पित शक्ति का संतुलन
संविधान को बनाए रखा जाता है और विधायिका
और कार्यपालिका उनके निर्वहन में नहीं करती है
कार्य, संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन करते हैं। यह है।
समान रूप से उनका कर्तव्य इस बात की देखरेख करना है कि न्यायिक उन लोगों द्वारा लिए गए
निर्णय जो
स्वतंत्रता। संवैधानिक सुरक्षा उपाय जो न्यायाधीशों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं
उच्चतर न्यायपालिका के लिए उपलब्ध नहीं हैं अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायाधीश या उन लोगों
के लिए जो सामान्य विधानों द्वारा बनाए गए न्यायाधिकरणों का संचालन करते हैं।
नतीजतन, बाद की श्रेणी के न्यायाधीश कर सकते हैं
कभी भी पूर्ण और प्रभावी विकल्प नहीं माना जाता है
कार्य के निर्वहन में वरिष्ठ न्यायपालिका के लिए

संवैधानिक व्याख्या। इसलिए हम मानते हैं
कि विधायी पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति
अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड के तहत उच्च न्यायालयों में निहित कार्रवाई

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [चेलामेश्वर, जे।]
226 और इस न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत
संविधान एक अभिन्न और आवश्यक है
संविधान की विशेषता, भाग का गठन
इसकी मूल संरचना। सामान्यतः, इसलिए,
उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय की शक्ति
विधानों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करना
उन्हें कभी भी निष्कासित या बहिष्कृत नहीं किया जा सकता है।
[जोर दिया गया]

इस मामले का यह पहलू मुद्दे में नहीं है। इनमें से कोई नहीं
उत्तरदाताओं ने उस प्रस्ताव का विरोध किया। का पाठ
संविधान इस प्रस्ताव के लिए पर्याप्त गवाही देता है कि संविधान एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना और
पोषण करना चाहता है।
न्यायपालिका। संविधान के निर्माता इस बारे में मुखर थे कि
यह। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों की रक्षा करना चाहते हैं
अनुचित हस्तक्षेप के खिलाफ उचित सुरक्षा प्रदान करके न्यायपालिका की स्वतंत्रता न्यायाधीशों
की शर्तों के साथ विधानमंडल या कार्यपालिका
संवैधानिक न्यायालयों की सदस्यता के लिए आनुषंगिक सेवा और विशेषाधिकार, जैसे वेतन, पेंशन,
कार्यालय आदि के कार्यकाल की सुरक्षा। की योजना
इस संबंध में संविधान पर पहले ही ध्यान दिया जा चुका है। 56 इस तरह
सुरक्षा न केवल हमारे संविधान के तहत आवश्यक महसूस की जाती है,

लेकिन कई अन्य लोकतांत्रिक संविधान (का विवरण)

उनमें से कुछ पहले से ही पैरा 25 से 27 में देखे गए हैं। इस तरह

अनुभव के आलोक में सुरक्षा को शामिल किया जाता है और

इतिहास का ज्ञान। सरकारों द्वारा किए गए विभिन्न प्रयास

न्यायपालिका की स्वतंत्रता को नष्ट करने के लिए जाना जाता था
हमारे संविधान के निर्माता भी

उन संविधानों के निर्माता और

संविधान।

65. अनुच्छेद 124 और 217 एक तत्व से संबंधित हैं।

एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना के लिए आवश्यक है।

56 पैरा 31 (ऊपर) देखें।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

नियुक्ति प्रक्रिया। संविधान सभा पूरी तरह से

स्थापना में इस तरह के तत्व के महत्व के प्रति सचेत

और एक स्वतंत्र न्यायपालिका का पोषण करना। इसने विभिन्न प्रकार की जांच की।

अन्य देशों में प्रचलित मॉडल। डॉ. अम्बेडकर का भाषण

दिनांक 24 मई 194957 (ऊपर उद्धृत) इस बात का प्रमाण है

जागरूकता। संविधान सभा का पूरी तरह से मूल्यांकन किया गया था

सदस्यों की नियुक्ति की शक्ति सौंपने के खतरे

संवैधानिक न्यायालयों का विशेष रूप से

कार्यकारी। उसी समय, संविधान सभा थी

इस तरह की शक्ति सौंपने की अवांछनीयता के प्रति भी संवेदनशील

विशेष रूप से सीजेआई को या संसद को किसी भी भूमिका की अनुमति देना

न्यायिक नियुक्तियों का मामला। संभावित

ऐसी भूमिका सौंपने के परिणामों का भी उल्लेख किया गया था।

डॉ. अम्बेडकर द्वारा। संविधान सभा को प्रचलित विभिन्न मॉडलों और संस्थागत तंत्रों के बारे में जानकारी दी गई

नियुक्ति के लिए विभिन्न लोकतांत्रिक संविधानों के तहत सभा

उच्च न्यायपालिका के सदस्य। संविधान

डॉ. अम्बेडकर द्वारा बताया गया था कि मॉडल, जैसे कि

अनुच्छेद 124 और 217 में निहित (जैसा कि वे अनुच्छेद 124 और 217 से पहले थे)

संशोधन)-के लिए पर्याप्त माना जा सकता है

एक क्षण। द्वारा सुझाए गए विभिन्न वैकल्पिक मॉडल

सदस्यों को स्वीकार नहीं किया गया। 58 विधायी इतिहास स्पष्ट रूप से

57 संविधान सभा की बहस, 24 मई 1949 (खंड। VIII)

58 24 मई 1949 को जब संविधान के मसौदे के अनुच्छेद 103 के मसौदे पर वर्तमान अनुच्छेद 124 के अनुरूप चर्चा की जा रही थी, तब चार सदस्य प्रो. शिवबन लाल सक्सेना और प्रो. बिहार के संयुक्त प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले के. टी. शाह और मद्रास प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री बी. पोकर साहिब और श्री महबूब अली बेग साहिब ने अनुच्छेद 103 में संशोधन का सुझाव दिया, जिसके प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैं:

"प्रो. शिवबन लाल सक्सेना: कि अनुच्छेद 103 के खंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएँ (2) भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे, की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में एकत्रित संसद के दो तिहाई बहुमत द्वारा पुष्टि के अधीन रहते हुए की जाएगी। सर्वोच्च अदालतें-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [चेलामेश्वर, जे।]

इंगित करता है कि संविधान सभा के सदस्य स्पष्ट रूप से

नियुक्त करने के लिए एक पूर्ण और निरंकुश शक्ति निहित करने से इनकार कर दिया

इनमें से किसी एक में संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीश

3 संविधान की शाखाएँ। संविधान सभा ने संसद को कोई भूमिका सौंपने से इनकार कर दिया। यह निहित करने से इनकार कर दिया

कार्यपालिका में बेलगाम शक्ति। साथ ही नहीं किया सहमति आवश्यक है

इस प्रस्ताव से सहमत हैं कि सीजेआई की

किसी भी नियुक्ति के लिए।

66. कॉलेजियम की प्रणाली-एक का उत्पाद

अनुच्छेद 124 और 217 के पाठ पर व्याख्यात्मक विवरण
में किया गया कार्य हो सकता है या हो सकता है

द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों के मामले

कुशल न्यायपालिका। गंभीर रूप से प्रतिस्पर्धी विचार हैं
न्यायशास्त्र पर

प्रतिष्ठित लोगों द्वारा व्यक्त 59, दोनों

पिछले दो दशकों में निर्णयों की दृढ़ता और जिस तरह से कॉलेजियम प्रणाली संचालित हुई। "प्रो.
के टी शाह: उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्य परिषद और राज्यों में
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों के साथ परामर्श करने के बाद अपने हस्ताक्षर और
मुहर के तहत वारंट द्वारा की जाएगी जो इस उद्देश्य के लिए आवश्यक हों और जब तक वह पैंसठ वर्ष की आयु
प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक पद पर रहेगा।

"श्री बी. पोकर साहिब: कि अनुच्छेद 103 के खंड (2) और खंड (2) के पहले परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित
को प्रतिस्थापित किया जाए।

(2)

मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश

भारत की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति के बाद अपने हाथ और मुहर के
तहत वारंट द्वारा की जाएगी और भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के
न्यायाधीशों और राज्यों में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश के
परामर्श के बाद अपने हाथ और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जाएगी। " "श्री महबूब अली बेग
साहिब:

कि अनुच्छेद 103 के खंड (2) के पहले परंतुक में, 'भारत के मुख्य न्यायाधीश से हमेशा परामर्श किया जाएगा'
शब्दों के स्थान पर 'यह भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से बनाया जाएगा' शब्दों को प्रतिस्थापित
किया जाए।

59 फुटनोट 50 (ऊपर) देखें।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

67. न ही अवधारणा की न्यायशास्त्रीय शुद्धता

कॉलेजियम ने न ही कॉलेजियम प्रणाली कितनी अच्छी तरह से या खराब तरीके से संचालित की

पिछले दो दशकों का सवाल हमारे सामने है। सवाल यह है
संसद है

है-क्या ऐसी प्रणाली अपरिवर्तनीय है या

संविधान में संशोधन करने और एक विकल्प बनाने के लिए सक्षम
लिए तंत्र

सदस्यों के चयन और नियुक्ति के

इस देश के संवैधानिक न्यायालय।

68. विवादित संशोधन के लिए बुनियादी आपत्ति यह है कि यह संवैधानिक उद्देश्य के लिए विनाशकारी है -

एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना, और इसके परिणामस्वरूप संविधान की मूल संरचना।
इसलिए, यह गलत है

भारती मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून।

69. प्रस्तुतिकरण की शुद्धता तय करने के लिए, यह है

आवश्यक:

(1) भारती मामले के अनुपात निर्णय की पहचान करने के लिए जहाँ

"बुनियादी संरचना" और "बुनियादी विशेषताओं" का सिद्धांत

उत्पत्ति हुई।

(2) क्या संविधान की अभिव्यक्तियाँ "बुनियादी विशेषताएं" और "बुनियादी संरचना" पर्यायवाची हैं या वे हैं?

अलग-अलग विचार या अवधारणाएँ व्यक्त करते हैं? यदि ऐसा है तो क्या है?

वे क्या विचार व्यक्त करते हैं?

(3) क्या उन्हें पहले के निर्णयों द्वारा स्पष्ट रूप से पहचाना गया है?

इस अदालत का?

(4) क्या इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के कोई सिद्धांत हैं?

संविधान की बुनियादी विशेषताओं की पहचान करना?

(5) यदि दो अभिव्यक्तियाँ "बुनियादी विशेषताएं" और "बुनियादी" हैं

संशोधन अमान्य है या ऐसा संशोधन होना चाहिए
शून्य होने के लिए उन दोनों का विनाशकारी।

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [चेलामेश्वर, जे।]

(6) संविधान संशोधन कब कहा जा सकता है

किसी "मूल विशेषता" को नष्ट या निरस्त करें।

संविधान या "मूल संरचना"

संविधान?

70. भारती के मामले में, एक सवाल था-क्या

अनुच्छेद 368 संसद को बेलगाम शक्ति प्रदान करता है -

आई. सी. गोलक नाथ और अन्य में इस न्यायालय के पहले के फैसले के बारे में वी. पंजाब राज्य और
एक अन्य, (1967) 2 एससीआर 7626 0 जिसमें यह

यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अनुच्छेद 368 संसद को एक सीमित अधिकार प्रदान करता है

संविधान में संशोधन करने की शक्ति। संविधान संशोधन

अनुच्छेद 13 (3) (ए) के अर्थ के भीतर 'कानून' है। कोई भी।

संवैधानिक संशोधन जो हटाने का प्रयास करता है या यहाँ तक कि

भाग-के तहत गारंटीकृत अधिकारों में से किसी एक को कम करें

संविधान अनुच्छेद 13 (2) 62 के तहत निहित जनादेश का उल्लंघन करेगा और इसलिए अवैध होगा।

71. आई. सी. गोलक नाथ की शुद्धता उनमें से एक थी

वे प्रश्न जो वृहत न्यायपीठ के विचार के लिए पड़े

भारती मामले में यह न्यायालय। ग्यारह राय दी गई।

इस न्यायालय ने बहुमत से कहा कि संविधान का प्रत्येक अनुच्छेद

मौलिक अधिकारों को शामिल करने वाले अनुच्छेदों सहित संसद की संशोधन शक्ति के लिए
उत्तरदायी 63 के तहत

80 11 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुना गया और 6 के बहुमत से निर्णय लिया गया: 5

61 अनुच्छेद 13 (3) (ए)। “ कानून ”में कोई भी अध्यादेश, आदेश, उप-कानून, नियम, विनियमन, अधिसूचना,
प्रथा या उपयोग शामिल है जो भारत के क्षेत्र में है

कानून की शक्ति। 62 अनुच्छेद 13 (2)। राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो इस भाग और इसके
उल्लंघन में बनाए गए किसी कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीन या कम कर दे।

खंड, उल्लंघन की सीमा तक, शून्य होगा।

63 (सी. जे. सिकरी के अनुसार)-पैरा 292 में कहा गया है, “मौलिक अधिकारों को निरस्त नहीं किया जा
सकता है, लेकिन सार्वजनिक रूप से मौलिक अधिकारों को उचित रूप से कम किया जा सकता है।

ब्याज “1 ” कि संविधान के प्रत्येक प्रावधान में संशोधन किया जा सकता है बशर्ते कि परिणामस्वरूप
संविधान की मूल नींव और संरचना समान रहे। कहा जा सकता है कि मूल संरचना में निम्नलिखित विशेषताएं
शामिल हैं:

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुच्छेद 368 जो एक घटक शक्ति है लेकिन ऐसी शक्ति करता है
संसद को मूल संरचना में परिवर्तन करने में सक्षम नहीं बनाना या
संविधान की रूपरेखा। 64

(1) संविधान की सर्वोच्चता;

(2) सरकार का रिपब्लिकन और लोकतांत्रिक रूप;

(3) संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र;

(4) विधायिका, कार्यपालिका और सरकार के बीच शक्तियों का पृथक्करण

न्यायपालिका;

(5) संविधान का संघीय चरित्र "।

(प्रति शेलट, जे. जिन्होंने अपने और ग्रोवर, जे. के लिए बात की)-पारस 582,583, "यह समझने में कोई
कठिनाई नहीं हो सकती है कि निम्नलिखित को माना जा सकता है संवैधानिक संरचना के मूल तत्व।
इन्हें सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है लेकिन केवल सचित्र किया जा सकता है:

(1) संविधान की सर्वोच्चता,
संप्रभुता का रिपब्लिकन और लोकतांत्रिक रूप

(2) सरकार और

देश से।

(3) संविधान का धर्मनिरपेक्ष और संघीय चरित्र।

(4) विधायिका, कार्यपालिका और सरकार के बीच शक्ति का सीमांकन

न्यायपालिका।

(5) भाग III में विभिन्न स्वतंत्रताओं और बुनियादी अधिकारों द्वारा सुरक्षित व्यक्ति की गरिमा और
एक कल्याणकारी राज्य के निर्माण के लिए जनादेश

भाग IV में निहित।

(6) राष्ट्र की एकता और अखंडता "।

और इसलिए, "अनुच्छेद 368 के तहत शक्ति प्रत्येक अनुच्छेद के संशोधन की अनुमति देने के लिए पर्याप्त है,
जब तक कि इसके मूल तत्वों को निरस्त या उनकी पहचान से वंचित नहीं किया जाता है"। (हेगडे,
जे., जिन्होंने मुखर्जी, जे.)-पैरा 666 के लिए भी बात की, "संसद के पास बुनियादी तत्वों या मौलिक तत्वों को
निरस्त करने या समाप्त करने की कोई शक्ति नहीं है।

संविधान की विशेषताएँ जैसे कि भारत की संप्रभुता, हमारी राजनीति का लोकतांत्रिक चरित्र, देश की एकता,
नागरिकों को प्राप्त व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की आवश्यक विशेषताएं। और "एक कल्याणकारी राज्य और

समतावादी समाज के निर्माण के लिए जनादेश"। (पी. जगमोहन रेड्डी के अनुसार, जे.) - पैरा 1159, 1162 "एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। संसदीय लोकतंत्र, राज्य के तीन अंग, मूल संरचना का गठन करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि "मौलिक अधिकारों या निर्देशक सिद्धांतों के बिना यह लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं हो सकता है। इसलिए, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की शक्ति संविधान की मूल संरचना के किसी भी मौलिक अधिकार या अन्य आवश्यक तत्वों में से किसी एक को पूरी तरह से निरस्त करने और इसकी पहचान को नष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

(प्रति खन्ना, जे.)-पैरा 1426, "अनुच्छेद 368 के तहत शक्ति पुराने संविधान को नष्ट करने की शक्ति को अपने दायरे में नहीं लेती है"। जिसका अर्थ है "पुराने संविधान की मूल संरचना या ढांचे को बनाए रखना"। "नींव को छूने या बुनियादी संस्थागत पैटर्न को बदलने की अनुमति नहीं है"। न्यायमूर्ति खन्ना के अनुसार, "ऐसी सीमाएँ" संशोधन "शब्द में अंतर्निहित और निहित हैं।"

* 49 न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित निर्णय के बहुमत का सारांश देखें, पी। 1007 (1973) 4 एस. सी. सी. 225.

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [चेलामेश्वर, जे।]

72. यही मूल संरचना के सिद्धांत की उत्पत्ति है

संविधान। न्यायमूर्ति शेलट और न्यायमूर्ति ग्रोवर ने इसका उपयोग किया

अभिव्यक्ति बुनियादी तत्वों और माना कि वे नहीं हो सकते हैं उनकी पहचान को निरस्त या अस्वीकार कर दिया गया। न्यायमूर्ति हेगड़े और

मुखर्जी, जे. ने मूल तत्वों की अभिव्यक्ति का प्रयोग किया या

मूलभूत विशेषताएँ और उनका मानना था कि उन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता है

या नपुंसक। न्यायमूर्ति जगमोहन रेड्डी ने इस्तेमाल किया मूल संरचना के आवश्यक तत्वों की अभिव्यक्ति और आयोजित

कि उन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता है जिससे पहचान नष्ट हो जाती है

संविधान से। न्यायमूर्ति सीकरी और न्यायमूर्ति खन्ना ने

अभिव्यक्तियाँ मूल संरचना या ढांचा, आधार,

बुनियादी संस्थागत स्वरूप, जो सत्ता की शक्ति से परे है

संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद। इनमें से कुछ

विद्वान न्यायाधीशों ने कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया जो

उनके लिए बुनियादी या आवश्यक विशेषताएँ आदि हैं।

संविधान। वे सभी यह स्पष्ट करने के लिए सतर्क थे कि

उनके द्वारा उल्लिखित ऐसी विशेषताएँ या तत्व केवल लिमिटेड और अन्य में। वी.

सचित्र लेकिन संपूर्ण नहीं। मिनर्वा मिल्स

भारत संघ और अन्य।, (1980) 3 एससीसी 625, जस्टिस बोलते हुए

चंद्रचूड़, संविधान के बहुमत के लिए

पीठ ने कहा कि सारांश के पैरा संख्या 2 पर

नौ न्यायाधीश बहुमत के दृष्टिकोण को सही ढंग से दर्शाते हैं।

"12. विभिन्न निर्णयों का सारांश

सारांश यह कहने के लिए पढ़ता है कि बहुमत के अनुसार, "अनुच्छेद 368 संसद को परिवर्तन करने की अनुमति नहीं देता है।

मूल संरचना या ढांचा

संविधान "। सारांश एक है या नहीं निर्णय का वैध हिस्सा, या इनक्यूरियम के अनुसार है

लेखकों द्वारा उद्धृत विद्वतापूर्ण कारणों के लिए, यह है

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह सही ढंग से बहुमत को दर्शाता है

देखें "।

[जोर दिया गया] [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

73. फिर से वामन राव और ओआरएस में। आदि। वी. संघ का

भारत और ओआरएस।, (1981) 2 एस. सी. सी. 362, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़

एक अन्य संविधान पीठ के लिए बोलते हुए कहा गया:

"बहुमत का निर्णय जिसमें से सात

तेरह न्यायाधीश पक्षकार थे, उन्होंने एक लगाम लगाई

शक्ति के प्रयोग में उसे पकड़कर रास्ता अनुच्छेद 368 द्वारा प्रदत्त, संसद नहीं कर सकती है

संविधान में संशोधन करना ताकि नुकसान हो या

संविधान की मूल संरचना को नष्ट कर दें।

(पैरा 15)

[जोर दिया गया]

तब तक न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ पहले ही अपना मत व्यक्त कर चुके थे

इंदिरा नेहरू गाँधी बनाम। राज नारायण, (1975) पूरक

एस. सी. सी. 1 निम्नलिखित है:

" 663. बार में कुछ चर्चा हुई जैसे

संविधान की कौन सी विशेषताएँ मूल हैं

संविधान की संरचना के अनुसार

मौलिक अधिकारों के मामले में बहुमत निर्णय।

यह, मेरे लिए, एक व्यर्थ और अप्रासंगिक दोनों तरह की जांच है।

बहुमत निर्णय का अनुपात ऐसा नहीं है कि

संविधान की कुछ नामित विशेषताएँ हैं -

इसकी मूल संरचना का एक हिस्सा लेकिन यह कि शक्ति

संशोधन का प्रयोग इस प्रकार नहीं किया जा सकता है कि -

आवश्यक तत्वों को नुकसान पहुँचाना या नष्ट करना या

संविधान की मूल संरचना,

जो भी ये अभिव्यक्तियाँ समझ सकती हैं। "

[जोर दिया गया]

उपरोक्त परिच्छेद इंगित करते हैं कि यह बहुत स्पष्ट नहीं है

भारती मामले से क्या अभिव्यक्ति मूल संरचना है,

बुनियादी विशेषताएँ और आवश्यक तत्व एक ही विचार व्यक्त करते हैं।

या अलग विचार। इसलिए, कुछ सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं-ऑन-रिकॉर्ड की जांच करना आवश्यक है

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [चेलामेश्वर, जे।]

निर्णय जहाँ संवैधानिक संशोधनों की वैधता

भारती मामले के बाद इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया था।

74. इनमें से सबसे पहला मामला इंदिरा नेहरू गांधी का है।

(ऊपर)। संविधान के 39 वें संशोधन के अनुसार अनुच्छेद 329 अवास डाला गया। उक्त अनुच्छेद के खंड (4) और खंड (5) ने

के प्रावधानों के उल्लंघन की शिकायतों को बाहर करें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 किसी की भी जांच से

फोरम जहाँ तक ऐसी शिकायतें संबंधित हैं

प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव।

यह सवाल उठा कि क्या इस तरह के संशोधन ने संविधान की किसी भी बुनियादी विशेषता का उल्लंघन किया है। यह तर्क दिया गया था

कि संशोधन की चार बुनियादी विशेषताओं का उल्लंघन था

संविधान। वे इस प्रकार हैं: (1) सरकार का लोकतांत्रिक रूप; (2) विधायिका, कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण

और न्यायपालिका; (3) कानून के समक्ष सभी की समानता का सिद्धांत; और (4) कानून के शासन की अवधारणा। एक संविधान पीठ

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आक्षेपित खंड से परे थे

अनुच्छेद 368.65 के तहत संसद की शक्ति की क्षमता

75. पाँच में से चार न्यायाधीश इस बात पर सहमत हुए कि

यह निष्कर्ष कि विवादित संशोधन विनाशकारी था

"15 इंदिरा गांधी बनाम। राज नारायण अनुच्छेद 329-ए (4) को न्यायालय द्वारा संसद की संशोधन क्षमता से परे माना गया था, क्योंकि प्रधानमंत्री और अध्यक्ष के संसद के चुनावों के संबंध में अलग और विशेष प्रावधान करके, इसने संसद की मूल संरचना को नष्ट कर दिया था। संविधान। रे, सी. जे. ने अपने निर्णय को इस आधार पर आधारित किया कि 39 वां

जिस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 329-ए पेश किया गया था, वह कानून के शासन का उल्लंघन करता है (पी। 418) (एससीसी पी। 44); खन्ना, जे. ने अपने निर्णय को इस आधार पर आधारित किया कि लोकतंत्र संविधान की एक बुनियादी विशेषता थी, कि लोकतंत्र

विचार करता है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए और कि खंड में

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के आधार पर सवाल उठाया गया (पीपी। 467 और 471) (एससीसी पीपी। 87 और 91); मैथ्यू जे. ने खंड को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि यह विधान एड होमिनेम (पी। 513) (एससीसी पी। 127) और यह कि इसने संविधान के लोकतांत्रिक ढांचे को नुकसान पहुंचाया (पी। 515) (एससीसी पी। 129); जबकि हममें से एक, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने माना कि खंड खराब था क्योंकि यह कानून के

शासन का उल्लंघन करता है और समानता के सिद्धांत का एक स्पष्ट निषेध था जो संविधान की एक बुनियादी विशेषता है (पीपी।

663-65) (एस. सी. सी पी. 257) "। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

संविधान की मूल संरचना। प्रत्येक न्यायाधीश

राय दी कि विवादित प्रावधान ने एक विशिष्ट मूल का उल्लंघन किया है

संविधान की विशेषता जो विनाश की ओर ले जाती है

संविधान की मूल संरचना।

76. मिनर्वा मिल्स मामले (ऊपर) में, इस न्यायालय ने एक बार फिर

"मूल संरचना" की समस्या का सामना करना पड़ा

संविधान "। 66 संविधान (42 वां संशोधन) अधिनियम द्वारा अन्य बातों के अलावा, खंड (4) और (5) को जोड़ा गया।

अनुच्छेद 368 और अनुच्छेद 31-सी में संशोधन किया गया

मूल लेख में कुछ शब्दों को प्रतिस्थापित करना। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने अदालत के बहुमत के लिए बात की और संविधान (42 वां संशोधन) अधिनियम की धारा 4 और 55 घोषित की।

संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करना। निपटान

अनुच्छेद 368 में संशोधन के साथ, इस न्यायालय ने निर्णय दिया:

संसद को करने का अधिकार दिया
संविधान में परिवर्तन जब तक वे हैं

अपने मूल ढांचे के भीतर। और वह डर क्या हो सकता है?

निर्णय में वृद्धि या संदेह उत्पन्न होता है यदि केवल

इसका मतलब यह है और अधिक नहीं। प्रस्तावना आश्वस्त करती है

भारत के लोगों के लिए एक ऐसी राजनीति जिसका आधार

संरचना को उसमें एक संप्रभु के रूप में वर्णित किया गया है

लोकतांत्रिक गणराज्य; संसद बना सकती है

संविधान में कोई संशोधन जैसा वह समझता है
जब तक वे नुकसान नहीं पहुँचाते हैं या

भारत की संप्रभुता और उसकी संप्रभुता को नष्ट करना
लोकतांत्रिक, गणतंत्रवादी चरित्र। लोकतंत्र

यह कोई खाली सपना नहीं है। यह एक सार्थक अवधारणा है।

जिनकी आवश्यक विशेषताओं का पाठ किया जाता है

66 पैरा 13. केशवानंद भारती में बहुमत के दृष्टिकोण के आधार पर हमें जो सवाल तय करना है, वह यह है कि क्या संविधान (42 वां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 4 और 55 द्वारा पेश किए गए संशोधन संविधान की किसी भी बुनियादी विशेषता को नष्ट करके संविधान की संरचना को नुकसान पहुंचाते हैं।

या आवश्यक तत्व।

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. (चेलामेश्वर, जे।)

स्वयं प्रस्तावना: न्याय सामाजिक, आर्थिक और

राजनीतिक; विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास की स्वतंत्रता

और पूजा; और स्थिति और अवसर की समानता।

इसका उद्देश्य, जैसा कि प्रस्तावना में बताया गया है,

लोगों के बीच एक स्थायी भावना को बढ़ावा देना
"व्यक्ति की गरिमा का आश्वासन देने वाली बंधुत्व और

राष्ट्र की एकता "। नया पेश किया गया खंड

(5) अनुच्छेद 368 उन स्तंभों को ध्वस्त कर देता है जिन पर

प्रस्तावना संसद को सशक्त बनाने पर आधारित है।

बिना किसी के अपनी घटक शक्ति का प्रयोग करना

"सीमा जो भी हो "। कोई भी घटक शक्ति ऐसा नहीं कर सकती

संभवतः आकाश से भी ऊँचा जाएँ-उच्च शक्ति

खंड (5) द्वारा प्रदत्त, क्योंकि यह अधिकार भी देता है

संविधान ", अर्थात्, निरस्त करने के लिए
लोकतंत्र और इसके लिए एक पूरी तरह से विरोधी विकल्प

सरकार का रूप। यह सबसे प्रभावी हो सकता है

नाम, सामाजिक, आर्थिक और कुल इनकार द्वारा
लोगों को राजनीतिक न्याय, नपुंसक बनाकर

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास की स्वतंत्रता और
पूजा और प्रतिबद्धता को त्याग कर

समान समाज का शानदार आदर्श। शक्ति।

नष्ट करना संशोधन करने की शक्ति नहीं है।

[जोर दिया गया]

अनुच्छेद 31-सी में संशोधन से उत्पन्न मुद्दा
की पहचान की गई थी कि क्या के निर्देशक सिद्धांत

भाग-IV में निहित राज्य नीति की प्रधानता हो सकती है -

संविधान के भाग III में निहित मौलिक अधिकार-क्योंकि 42 वें संशोधन ने संविधान को अधीनस्थ करने की
मांग की थी।

अनुच्छेद 14 और 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार निर्देशक सिद्धांत। इस न्यायालय ने यह प्रश्न तैयार
किया कि क्या ऐसा संशोधन शीर्ष अदालत की रिपोर्ट की संशोधन शक्ति के भीतर था।

[2015] 13 एस सी आर।

इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए संसद के भारती मामला। न्यायालय ने
प्रस्ताव दिया कि:

" 41 यह केवल तभी है जब इनके द्वारा प्रदत्त अधिकार

दो लेख मूल संरचना का हिस्सा नहीं हैं

संविधान कि उन्हें अनुमति दी जा सकती है

एक संवैधानिक संशोधन द्वारा निरस्त। अगर वे

मूल संरचना का एक हिस्सा हैं, वे नहीं हो सकते हैं

अनुच्छेद 31-ग में वर्णित विधियों का या, मामले के लिए
कि, किसी भी विवरण के कानूनों के संबंध में

जो भी हो, किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पारित किया गया

या नीति जो भी हो। यह बाहर लाने के लिए काम करेगा

इस बिंदु पर कि आवश्यक का कुल विघटन
संविधान की विशेषताएँ हैं, अनुपात से
केशवानंद भारती, अनुमति नहीं है
संसद "।

न्यायालय अंततः इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि भाग III
संविधान का चौथा और चौथा दोनों रथ के दो पहियों की तरह हैं
समान रूप से महत्वपूर्ण और आयोजित:

"56.

एक ओवर को पूर्ण प्रधानता देना
दूसरा है सद्भाव को भंग करना
संविधान। इस सामंजस्य और संतुलन के बीच
मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांत हैं -
मूल संरचना की एक आवश्यक विशेषता
संविधान। "

[जोर दिया गया]

इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अनुच्छेद 31 सी में संशोधन
मूल संरचना का विनाशकारी है क्योंकि इसने निरस्त कर दिया है
उन कानूनों के खिलाफ अनुच्छेद 14 और 19 का संरक्षण जो इसके अंतर्गत आते हैं
अनुच्छेद 31 सी में निहित विवरण की सीमा।

77. वामन राव मामले (ऊपर) में, अनुच्छेद 31-ए (1) (ए) जो
संविधान (प्रथम संशोधन) द्वारा प्रस्तुत किया गया

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [चेलामेश्वर, जे।]

अधिनियम को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह मूल को नुकसान पहुंचाता है

संविधान की संरचना। उक्त अनुच्छेद ने एक घोषणा कि राज्य द्वारा किसी 'संपदा' या 'उसमें किसी
अधिकार' आदि के अधिग्रहण के लिए उपबंध करने वाली कोई भी विधि निम्नलिखित मानी जाएगी -

इस आधार पर अमान्य होगा कि ऐसी विधि ने अनुच्छेद 14,19 का उल्लंघन किया है। और संविधान के 31. दूसरे शब्दों में, यद्यपि अनुच्छेद 14,

19 और 31 कानून की पुस्तक में रहते हैं, की वैधता

अनुच्छेद 31-ए (1) (ए) में वर्णित कानूनों की श्रेणी नहीं हो सकती है

अनुच्छेद 14,19 और 31 के आधार पर परीक्षण किया गया। इस तरह के संशोधन की अनुमति से निपटने के लिए, न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

"किसी भी मामले में, निर्णायक यह है कि क्या,

जहाँ तक विवादित कानून का संबंध है, अधिकार

भाग III के किसी भी अनुच्छेद के तहत उस कानून से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पूरी तरह से या पर्याप्त रूप से उपलब्ध हैं

वापस ले लिया और नहीं कि क्या लेख,

जिसके संबंध में आवेदन वापस ले लिया गया है

कानूनों की एक परिभाषित श्रेणी, पर जारी है
कानून की पुस्तक ताकि कानूनों के संबंध में उपलब्ध हो

अन्य श्रेणियाँ। इसलिए हमें निष्कर्ष निकालना चाहिए।

कि अनुच्छेद 14 के आवेदन को वापस लेना,

19 और 31 उन कानूनों के संबंध में जो खंड के अंतर्गत आती हैं।

(a) कुल और पूर्ण है, अर्थात्,

उन अनुच्छेदों का अनुप्रयोग निरस्त कर दिया गया है, नहीं

केवल संक्षिप्त, विवादित के संबंध में

अधिनियम जो निर्विवाद रूप से खंड (क) के दायरे में आते हैं। हम यह जोड़ना चाहेंगे कि हर मामले में

जिसमें मौलिक अधिकार का संरक्षण किया जाता है

वापस लेने से आवश्यक रूप से नुकसान नहीं होगा

या संविधान की मूल संरचना को नष्ट करना।

सवाल यह है कि क्या मूल संरचना

किसी भी मामले में क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाता है

किस भाग के विशेष अनुच्छेद पर निर्भर करता है

III मुद्दे में है और क्या जो वापस लिया गया है वह सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर. है।

मूल संरचना के लिए सर्वोत्कृष्ट
संविधान "I (पैरा 14)

[जोर दिया गया]

लेकिन यह न्यायालय अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि
संशोधन ने मूल संरचना को नुकसान या नष्ट नहीं किया।
और इसलिए, संशोधन 67 को बरकरार रखा। ऐसा निष्कर्ष
तर्क के आधार पर पहुँचा गया था -

"29. प्रथम संशोधन का उद्देश्य सामाजिक और

कृषि क्षेत्र में आर्थिक विषमताएँ। ऐसा हो सकता है।

कि जबकि मौजूदा असमानताओं को दूर किया जा रहा है, नई

असमानताएँ मामूली और संयोग से उत्पन्न हो सकती हैं। इस तरह

सीमांत और आनुषंगिक असमानताएँ नुकसान नहीं पहुँचा सकती हैं या

संविधान की मूल संरचना को नष्ट करना। यह है।

किसी भी सरकार के लिए असंभव, चाहे वह कितना भी कुशल क्यों न हो।
सलाह दी गई, सामाजिक रूप से उन्मुख और विवेकपूर्ण तरीके से प्रबंधित,

कुछ पैदा किए बिना हर आर्थिक असमानता को दूर करें

व्यक्तियों के एक वर्ग के लिए कठिनाई या अन्याय जो भी हैं
कानून के तहत समान व्यवहार का अधिकार। "

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि अनुच्छेद 14 का संरक्षण

इस तरह की सुरक्षा के परिणामस्वरूप नुकसान या नुकसान नहीं होता है। संविधान की मूल
संरचना का विनाश। दूसरे शब्दों में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि मांग करने की प्रक्रिया में
सामाजिक और सामाजिक कार्यों को हटाने के एक बड़े संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करना।

कृषि क्षेत्र में आर्थिक विषमताएँ और प्रभाव

अनुच्छेद 39 (बी) और (ए) में निहित दोहरे सिद्धांत यदि नए हैं

असमानताओं का परिणाम मामूली होता है और संयोग से वे नहीं हो सकते हैं

कहा जाता है कि यह संविधान की मूल संरचना के लिए विनाशकारी है। 07 पैरा 31. इन कारणों से, हमारा विचार है कि संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 की धारा 4 द्वारा प्रस्तुत संशोधन संविधान के मूल ढांचे को नुकसान या नष्ट नहीं करता है। इसलिए, संशोधन को उसके गुण-दोषों के आधार पर बरकरार रखा जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [चेलामेश्वर, जे।]

78. मिनर्वा मिल्स और वामन राव दोनों ने इससे निपटा।

अनुच्छेद 14 और 19 को निरस्त करना या अनुच्छेद को पूरी तरह से वापस लेना।
उन मौलिक अधिकारों का संरक्षण

कुछ के संदर्भ में

विधान के वर्ग। इस न्यायालय ने उपरोक्त में से पहले में निर्णय दिया

उल्लिखित मामले कि इस तरह की वापसी निरस्तीकरण के बराबर है

एक बुनियादी विशेषता और, इसलिए, बुनियादी के विनाशकारी

मिनर्वा मिल्स में प्रतिपादित नियम के लिए एक अपवाद बनाया गया
इस तरह का निरस्तीकरण जहां तक कानून से संबंधित है

और अभिनिर्धारित किया कि

कृषि सुधारों ने बुनियादी ढांचे को नष्ट नहीं किया। ये
अभिव्यक्तियाँ 'मूल संरचना'

मामले केवल यह इंगित करते हैं कि; (i)

और 'बुनियादी विशेषताएँ' दो अलग-अलग विचारों को व्यक्त करती हैं, (ii) बुनियादी

विशेषताएँ मूल संरचना के घटक हैं। यह भी निम्नलिखित है

इन मामलों से कि या तो एक विशेष अनुच्छेद या लेखों का समूह

यह संविधान की एक बुनियादी विशेषता हो सकती है। संशोधन
का गठन करने वाले अनुच्छेदों में से

एक या कुछ मूल विशेषताओं

या मूल संरचना के विनाश में परिणाम नहीं हो सकता है

संविधान। यह सब संदर्भ पर निर्भर करता है।

79. एस. आर. बोम्मई बनाम में यह न्यायालय। भारत संघ, (1994)

3 एस. सी. सी. 1 ने धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को संविधान की बुनियादी विशेषताओं में से एक के रूप में मान्यता दी, इसलिए नहीं कि इनमें से कोई एक

कि प्रभाव लेकिन इस तरह के एक निष्कर्ष की योजना से पालन किया
प्रावधान। 68

संविधान के विभिन्न

80. एम. नागराज और अन्य बनाम में यह न्यायालय। भारत संघ

& अन्य 69, (2006) 8 एस. सी. सी. 212, ने इस सिद्धांत का अनुमान लगाया कि
बुनियादी विशेषताओं की पहचान करने की प्रक्रिया

संविधान की

68 पैरा 25 से 29 देखें-अहमदी जे., पैरा 145-सावंत जे., पैरा 183 से 186-रामास्वामी जे., पैरा 304-जीवन
रेड्डी जे. 69 इस मामले में, इस न्यायालय को संविधान (85 वां) संशोधन अधिनियम 2001 की वैधता
पर निर्णय लेना था, जिसके द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ संविधान में अनुच्छेद 16 (4 ए) में संशोधन किया
गया था। इसने सरकारी सेवा में पदोन्नति के संदर्भ में आरक्षण का नियम प्रदान किया। इस तरह के संशोधन
को संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करने के लिए चुनौती दी गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

कुछ अवधारणाओं की पहचान में निहित है जो परे हैं

किसी विशेष प्रावधान के शब्द लेकिन संविधान की योजना में व्याप्त हैं। इनमें से कुछ अवधारणाएँ ऐसी हो
सकती हैं

आवश्यक कहे जाने की योग्यता के रूप में महत्वपूर्ण और मौलिक

संविधान की विशेषताएँ या मूल संरचना का हिस्सा

इसलिए संविधान संशोधन के लिए खुला नहीं है।

इस न्यायालय ने उस प्रक्रिया को निर्दिष्ट किया जिसके द्वारा मूल

संविधान की विशेषताओं की पहचान की जानी चाहिए। अदालत ने

आयोजित:

के संदर्भ में एक बुनियादी संरचना की मान्यता
संशोधन एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि वहाँ हैं,

विशेष प्रावधानों के शब्दों से परे,

अंतर्निहित व्यवस्थित सिद्धांत और

संविधान के प्रावधानों को जोड़ना।

ये सिद्धांत संविधान को सुसंगत बनाते हैं।

और इसे एक जैविक संपूर्ण बनाएँ। ये सिद्धांत हैं -

संवैधानिक कानून का हिस्सा भले ही वे नहीं हैं
नियमों के रूप में स्पष्ट रूप से कहा गया है। एक उदाहरण है -

तर्कसंगतता का सिद्धांत जो जोड़ता है

अनुच्छेद 14, 19 और 21। इनमें से कुछ सिद्धांत

योग्यता प्राप्त करने के लिए यह इतना महत्वपूर्ण और मौलिक हो सकता है
"आवश्यक विशेषताओं" या संविधान की "मूल संरचना" के हिस्से के रूप में, अर्थात्, वे खुले नहीं हैं।

संशोधन के लिए। हालाँकि, यह केवल लिंक करके है

ऐसे व्यापक सिद्धांतों के लिए प्रावधान कि एक

आवश्यक को कम से अलग करने में सक्षम होगा

संविधान की आवश्यक विशेषताएं।

24. ध्यान देने योग्य बात यह है कि संघवाद, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत,
तर्कसंगतता और समाजवाद आदि इससे परे हैं।

किसी विशेष प्रावधान के शब्द।

वे व्यवस्थित सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड हैं।

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [चेलामेश्वर, जे।]

और अंतर्निहित और जोड़ने वाले संरचनात्मक सिद्धांत

संविधान के विभिन्न प्रावधान। वे देते हैं।

संविधान का पालन। वे बनाते हैं

संविधान एक जैविक संपूर्ण है। वे इसका हिस्सा हैं

संवैधानिक कानून भले ही वे स्पष्ट रूप से नहीं हैं

नियमों के रूप में बताया गया।

25. एक संवैधानिक सिद्धांत के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए

आवश्यक विशेषता, यह स्थापित किया जाना चाहिए कि
हिस्सा है

उक्त सिद्धांत संवैधानिक कानून का एक

संसद की शक्ति में संशोधन करना अर्थात् एक भाग बनाना।
अवधारणा

मूल संरचना। बुनियादी संरचना

तदनुसार संशोधन करने की शक्ति को सीमित करता है

संसद। संक्षेप में: योग्यता प्राप्त करने के लिए

एक आवश्यक विशेषता, एक सिद्धांत पहले होना है
 संवैधानिक कानून के हिस्से के रूप में स्थापित और इस प्रकार विधायिका पर बाध्यकारी।
 केवल
 तब, क्या इसकी जाँच की जा सकती है कि क्या ऐसा है संशोधन शक्ति को भी बांधने के लिए
 मौलिक
 संदर्भ में संवैधानिक संशोधनों की समीक्षा मूल संरचना के सिद्धांत "।
 [जोर दें

81. आई. आर. कोएल्हो (मृत) बनाम एल. आर. एस. टी. एन. राज्य (2)
 सीसी 1, इस न्यायालय ने फैसला सुनाया;
 शक्तियों का पृथक्करण मूल के भाग हैं संविधान की संरचना। इनमें से प्रत्येक
 अवधारणाएँ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं।

वहाँ [2015] 13 एस. सी. हो सकता है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट
 कानून का शासन नहीं है, अगर कानून के सामने समानता नहीं है।
 ये अर्थहीन होंगे यदि उल्लंघन किया गया था
 न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं। यह सब होगा
 अनावश्यक यदि विधायी, कार्यपालिका और न्यायिक शक्तियाँ एक अंग में निहित हैं। इसलिए
 कर्तव्य
 यह तय करने के लिए कि क्या सीमाएँ हैं उल्लङ्घन न्यायपालिका पर डाल दिया गया है।
 130. यह समझते हुए कि इसे सुरक्षित करना आवश्यक है
 मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन, शक्ति
 इस तरह के प्रवर्तन द्वारा निहित किया गया है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में संविधान
 अदालतें। न्यायिक समीक्षा एक आवश्यक विशेषता है -
 संविधान। यह व्यावहारिक सामग्री प्रदान करता है
 भाग III में सन्निहित संविधान के उद्देश्य और संविधान के अन्य भाग। यह नोट किया जा सकता
 है

कि केवल तथ्य यह है कि समानता, जिसका एक हिस्सा है किया जा सकता है

मूल संरचना, एक सीमित के लिए बाहर

इसलिए, यह इस प्रकार है कि इस पर विचार करते हुए कि क्या कोई विशेषता इसका हिस्सा है -

संविधान की विशेष

कानून की मूल संरचना नियम, का पृथक्करण

शक्तियाँ-तथ्य यह है कि सीमित अपवाद किए जाते हैं

सीमित उद्देश्यों के लिए, कुछ प्रकार के कानूनों की रक्षा के लिए,

इसका मतलब यह नहीं है कि यह मूल का हिस्सा नहीं है

संरचना "।

[जोर दें

82. उपरोक्त निर्णयों का विश्लेषण

एस भारती मामले से शुरू होता है

ऑसिशन:

(i) अनुच्छेद 368 संसद को संशोधन करने के लिए सक्षम बनाता है।

संविधान का प्रावधान; सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. 1. [चेलामेश्वर, जे।]

हालांकि अनुच्छेद 368 के तहत शक्ति सक्षम नहीं करती है।

संसद की मूल संरचना को नष्ट करने के लिए

संविधान;

(iii) ऊपर निर्दिष्ट मामलों में से कोई भी नहीं या

घोषित किया कि संविधान की मूल संरचना क्या है;

(iv) अभिव्यक्तियाँ "मूल संरचना" और "मूल विशेषताएँ"

अलग-अलग विचार व्यक्त करते हैं, हालांकि कुछ विद्वान न्यायाधीशों ने उन अभिव्यक्तियों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया।

(v) संविधान की मूल संरचना कुल राशि है।

संविधान की बुनियादी विशेषताएँ;

(vi) इसके द्वारा अब तक पहचानी गई कुछ बुनियादी विशेषताएँ

अदालतें लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, दर्जे की समानता हैं।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा और कुछ मौलिक अधिकार;

(vii) किसी भी मूल विशेषता को निरस्त करना।

आम तौर पर मूल संरचना के विनाश में परिणाम के कुछ अपवादों के अधीन;

संविधान

(viii) जब किसी विशेष बुनियादी को निरस्त किया जाता है

विशेषता को मूल संरचना को नष्ट करने के लिए कहा जा सकता है

संविधान मूल की प्रकृति पर निर्भर करता है

विशेषता को संशोधित करने की मांग की गई और इसका संदर्भ

संशोधन। कोई सार्वभौमिक रूप से लागू परीक्षण नहीं है ए-सभी बुनियादी विशेषताओं के लिए।

83. अब तक पहचानी गई अधिकांश बुनियादी विशेषताएँ

पहले उल्लिखित मामले संविधान के किसी भी अनुच्छेद से उत्पन्न नहीं होते हैं। वे अवधारणाएँ हैं जो उभर रही हैं।

उनमें से प्रत्येक में कई लेखों का संयोजन

कुछ अधिकार या दायित्व या दोनों (के लिए)

संदर्भ में मैं उन्हें "एलिमेंट्स" कहता हूँ। उदाहरण के लिए,

(क) जब यह कहा जाता है कि लोकतंत्र एक बुनियादी विशेषता है विशेषता, मेरी राय में, [2015] 13 एस. सी. आर.

हमारे संविधान की ऐसी

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों से निकलता है

जो विधान की स्थापना के लिए प्रावधान करता है

निकाय 0 (संसद और राज्य विधानमंडल) और

वयस्क मताधिकार के आधार पर इन निकायों के लिए आवधिक चुनाव निर्धारित करने वाले अनुच्छेद 71; सौंपी गई भूमिका

इन निकायों को, अर्थात् शासन के लिए कानून बनाना।

इस देश के अपने-अपने क्षेत्रों में 73; और
एक स्वतंत्र तंत्र की स्थापना के लिए

आवधिक चुनाव आदि आयोजित करना। ;

(ख) धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा विभिन्न क्षेत्रों से उत्पन्न होती है।

मौलिक अधिकार अध्याय में निहित लेख जैसे

अनुच्छेद 15 और 16 जो राज्य को प्रतिबंधित करता है

आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का अभ्यास करना
धर्म और अनुच्छेद 25 से 30 जो कुछ निश्चितता की गारंटी देते हैं

धर्म की स्वतंत्रता के संबंध में मौलिक अधिकार

प्रत्येक व्यक्ति और ऐसे अधिकारों का विशिष्ट उल्लेख
अल्पसंख्यकों का संदर्भ।

84. एक बुनियादी विशेषता का निरसन एक के रूप में हो सकता है

समूह में एकल अनुच्छेद के संशोधन का परिणाम

मूल विशेषता का गठन करने वाले अनुच्छेदों के रूप में यह हुआ मिनर्वा मिल्स मामला और इंदिरा
नेहरू गांधी मामला।

85. दूसरी ओर, इस तरह का परिणाम नहीं हो सकता है

कुछ बुनियादी विशेषताओं का संदर्भ। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 326

यह निर्धारित करता है कि लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा।
वयस्क।

उक्त अनुच्छेद में मताधिकार की व्याख्या इस प्रकार की गई है:

“..... अर्थात्, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जिसकी आयु अठारह वर्ष से कम नहीं है।

73 अनुच्छेद 245 और 246 आदि।

74 अनुच्छेद 324 शीर्ष अदालतें-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [चेलामेश्वर, जे।]

आयु ऐसी तिथि पर जो उस निमित्त निर्धारित की जाए -

या उपयुक्त द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत

विधायिका और अन्यथा के तहत अयोग्य नहीं है

इस संविधान या उपयुक्त द्वारा बनाई गई कोई कानून

गैर-निवास के आधार पर विधानमंडल,

मानसिक अस्वस्थता, अपराध या भ्रष्ट या अवैध
अभ्यास, एक मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा

ऐसे किसी भी चुनाव में।

घटकों में से एक यह है कि

न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष। निस्संदेह, अधिकार बनाया गया है
नागरिकों के पक्ष में भाग लेने के लिए

अनुच्छेद 326 के तहत भारत के

लोकसभा और विधानमंडल की चुनाव प्रक्रिया

सभा एक अभिन्न अंग है (सुविधा के लिए, मैं

इसे बुनियादी विशेषता यानी लोकतंत्र का एक तत्व) कहें।

हालाँकि, कुछ वैध कारणों से, यदि संसद को

अनुच्छेद 326 में संशोधन करके उच्च न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है।
तरह का संशोधन निरस्त होगा

संदेह है कि क्या इस

लोकतंत्र की मूल विशेषता जिसके परिणामस्वरूप

संविधान की मूल संरचना का विनाश। यह है।
वर्ष है।

यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि न्यूनतम आयु 18

आज तक अनुच्छेद 326 के तहत होने वाले

संविधान (61 वां संशोधन) अधिनियम, 1988। इससे पहले

संशोधन, न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष थी।

86. जैसा कि इस अदालत ने मिनर्वा मिल्स मामले में कहा था,

एकल अनुच्छेद के संशोधन के परिणामस्वरूप संविधान की मूल संरचना का विनाश हो सकता है जो इस पर
निर्भर करता है -

मूल विशेषता की प्रकृति और निरसन का संदर्भ

वह अनुच्छेद यदि अनुच्छेद द्वारा उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है
मूल संरचना के लिए सर्वोत्कृष्ट का गठन करता है
संविधान।

87. मेरी राय में, ये मामले वास्तव में मामले को निर्धारित करने में कोई मदद नहीं करते हैं क्योंकि वे कोई
[2015] 13 एस. सी. आर. निर्धारित नहीं करते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान की संरचना। हाथ पर मामले में, पहचान मूल विशेषता विवाद में नहीं है। सवाल यह है
कि क्या

संशोधन की स्वतंत्रता को निरस्त करना है

न्यायपालिका-(एक बुनियादी विशेषता) जिसके परिणामस्वरूप न्यायपालिका का विनाश होता है।

संविधान की मूल संरचना।

88. मूल विशेषता की प्रकृति से जिसके साथ हम

सौदा कर रहे हैं, यह किसी भी मौलिक या संवैधानिक प्रदान नहीं करता है

व्यक्तियों के पक्ष में अधिकार। यह केवल भारत के लोगों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित
करने का एक साधन है। यह एक बनाता है

न्यायपालिका के लिए राजनीति के पक्ष में सामूहिक अधिकार जो

कार्यपालिका या विधानमंडल के नियंत्रण से मुक्त है

निर्णय लेने का आवश्यक कार्य।

89. संशोधन के लिए चुनौती की आवश्यकता है

पूर्ववर्ती चर्चा के आलोक में जांच की गई। द.

संवैधानिक न्यायालय एक आवश्यक घटक (ELEMENT) है
निर्धारित प्रक्रिया

ऐसी राशि; (iii) इसके तहत

इस न्यायालय द्वारा व्याख्या किए गए अनुच्छेद 124 और 217 में संशोधन नहीं किया गया है।

द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों के मामलों में, एक बुनियादी विशेषता है और

यह सुनिश्चित करने के लिए संविधान के निर्माताओं द्वारा डिज़ाइन किया गया था

न्यायपालिका की स्वतंत्रता, की प्रधानता प्रदान करके

सीजेआई (कॉलेजियम) की राय; और सीजेआई की राय की नहीं

अध्यक्ष (कार्यपालिका); (iv) संशोधन इस प्रकार को कमजोर करता है।

प्रधानता और संतुलन को कार्यपालिका के पक्ष में झुकाता है, जिससे एक बुनियादी विशेषता को निरस्त कर दिया जाता है, जिससे बुनियादी ढांचे का विनाश होता है। संरचना।

90. याचिकाकर्ताओं द्वारा हमले का मुख्य लक्ष्य अनुभाग है

2 (क) उस संशोधन का जिसके द्वारा संस्थागत तंत्र

संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रतिस्थापित किया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [चेलामेश्वर, जे।]

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, संशोधन एक बेशर्मी है

कार्यकारी शाखा द्वारा संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति को हड़पने का प्रयास। इस तरह कार्यपालिका के हाथों में सत्ता का हस्तांतरण उन व्यक्तियों के साथ संवैधानिक न्यायालयों की पैकिंग को सक्षम करेगा जो संभावित हैं

कम स्वतंत्र होना।

91. यह आगे तर्क दिया जाता है कि में निर्धारित सिद्धांत

द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों के मामले विशुद्ध रूप से इन पर आधारित नहीं हैं -

संविधान के पाठ की व्याख्या जैसा कि यह पहले था

आक्षेपित संशोधन लेकिन एक के आधार पर भी मौलिक संवैधानिक सिद्धांत कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान की बुनियादी विशेषताओं में से एक है। द.

के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया

संवैधानिक न्यायालय एक महत्वपूर्ण तत्व है

एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना और पोषण। इस तरह

निष्कर्ष न केवल अनुच्छेद 124 के पाठ से आता है और

217 जैसा कि वे विवादित संशोधन से पहले खड़े थे लेकिन

योजना से उत्पन्न होने वाले आवश्यक निहितार्थ से प्रवाह (डी) द्वारा प्रमाणित,

संविधान के अनुच्छेद 32, 50, 112 (3)

113 (1), 203 (1), 125 (2), 221 (2) आदि।

92. श्री नरीमन, विद्वान वरिष्ठ वकील

अनुच्छेद 124 के तहत प्रदान किए गए तंत्र के परिवर्तन के खिलाफ किया कि मामले का यह पहलू

और 217। उन्होंने प्रस्तुत

न्यायमूर्ति एम. एन. वेंकटचलैया आयोग का विचार 75,

जिसने एक राष्ट्रीय न्यायपालिका के निर्माण की भी सिफारिश की

नियुक्ति आयोग लेकिन थोड़ा अलग

रचना 76. अगर वास्तव में संसद बदलना चाहती थी

75 न्यायमूर्ति एम. एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में संविधान के कामकाज की समीक्षा करने वाला राष्ट्रीय आयोग (एन. सी. आर. डब्ल्यू. सी.), 2002 76 7.3. 7 "न्यायाधीशों की नियुक्ति के तरीके से संबंधित मामले पर एक दशक से अधिक समय से बहस चल रही थी। संविधान (67 वां संशोधन) विधेयक, 1990 को 18 मई, 1990 (9 वीं लोकसभा) को पेश किया गया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों (2015) में न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के संस्थागत ढांचे का प्रावधान किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्च न्यायपालिका के सदस्यों के चयन के लिए तंत्र, न्यायमूर्ति एम. एन. द्वारा अनुशंसित मॉडल।

वेंकटचलैया आयोग को अपनाया जा सकता था। श्री नरीमन के अनुसार मॉडल की पहचान की गई वेंकटचलैया आयोग संरक्षण के लिए अधिक उपयुक्त है।

में अपनाए गए मॉडल की तुलना में न्यायपालिका की स्वतंत्रता

संशोधन। श्री नरीमन ने आगे तर्क दिया कि कोई कारण नहीं है

न्यायमूर्ति एम. एन. वेंकटचलैया की सिफारिशें

आयोग को स्वीकार नहीं किया गया।

93. दूसरी ओर, यह विद्वान द्वारा प्रस्तुत किया जाता है

विभिन्न उत्तरदाताओं की ओर से पेश होने वाले महान्यायवादी और अन्य वरिष्ठ वकील; अदालतें। इसके अलावा, ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में इस कार्य को कार्यपालिका के अनन्य आदेश से दूर करने और कुछ संस्थागत ढांचे को शामिल करने के लिए दुनिया भर में एक आंदोलन चल रहा है, जिसमें ऐसी नियुक्तियां करने से पहले कुछ स्तर पर न्यायपालिका के साथ परामर्श किया जाता है। जापान, इजराइल और ब्रिटेन में किसी न

किसी रूप में परामर्श की प्रणाली पहले से ही उपलब्ध है। संविधान (साठवां संशोधन) विधेयक, 1990 ने सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के दो अन्य न्यायाधीशों के एक कॉलेजियम का प्रावधान किया। हालाँकि, ऐसी सिफारिशें करने में कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों की भागीदारी के साथ एक सहभागी मोड होना सार्थक होगा। आयोग कॉलेजियम की संरचना का प्रस्ताव करता है जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए तंत्र के लिए एक एकीकृत योजना के रूप में राज्य की कार्यपालिका और न्यायिक शाखाओं दोनों को उचित महत्व देता है और प्रभावी भागीदारी प्रदान करता है। यह आयोग, तदनुसार, संविधान के तहत एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना की सिफारिश करता है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग

उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित शामिल होंगे:

1. भारत के मुख्य न्यायाधीश

सभापति

2. उच्चतम न्यायालय के दो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश: सदस्य

3 केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री:

सदस्य

4 द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित व्यक्ति

सदस्य

सीजेआई से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति

राष्ट्रीय न्यायपालिका की स्थापना के लिए सिफारिश

न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संरक्षित करने की आवश्यकता को देखते हुए आयोग और इसकी संरचना को अभिन्न माना जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. /चेलामेश्वर, जे।/

(i) संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति है -

पूर्ण रूप से केवल इस सीमा के अधीन कि यह निरस्त नहीं कर सकता है

द.

संविधान की मूल संरचना।

संशोधन किसी भी तरह से मूल संरचना को निरस्त नहीं करता है

संविधान से।

संविधान द्वारा परिकल्पित, यह भी परिकल्पना करता है कि कुशल न्यायपालिका। ऐसी जुड़वां वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए,

सामान्य विधान के संदर्भ में भी इस न्यायालय की जांच के लिए उत्तरदायी। तार्किक रूप से, एक संवैधानिक इसलिए संशोधन का लाभ अधिक होना चाहिए

प्रतिरक्षा।

दूसरे शब्दों में, जहां संसद द्वारा प्राप्त किया जाने वाला लक्ष्य संवैधानिक रूप से वैध है, वहां विधान

जिसके द्वारा ऐसा लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश की जा सकती है केवल सीमित आधार पर पूछताछ की गई। वे हैं (i) की कमी

विधायी क्षमता, (ii) विधान किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है। के भाग III में उल्लिखित मौलिक अधिकारों में से एक

संविधान, या संविधान के किसी अन्य स्पष्ट निषेध का उल्लंघन है। इस तरह की अनुपस्थिति

आपत्तिजनक विशेषताएँ, संभावना है कि लक्ष्य की मांग की गई थी

कानून द्वारा प्राप्त किया जाना कानून द्वारा चुने गए तरीकों के अलावा अन्य तरीकों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है

कभी भी एक साधारण को भी अमान्य करने का आधार न बनें

जैसा कि इस न्यायालय द्वारा लगातार अभिनिर्धारित किया गया है।

उपर्युक्त अर्थ में विधायी क्षमता और संविधान के अन्य प्रावधानों के साथ टकराव

अप्रासंगिक हैं और उत्पन्न नहीं होते हैं।

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

((iii) शासन की तीन महान शाखाओं को संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों की जांच और संतुलन।

- विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सबसे बुनियादी हैं।

सभी लोकतांत्रिक संविधानों की विशेषता। तीनों शाखाओं में से किसी एक की पूर्ण स्वतंत्रता है

मूल लोकतांत्रिक मूल्यों और योजना के साथ असंगत

हमारा संविधान। यह न्यायालय एक व्याख्यात्मक द्वारा संविधान की प्रक्रिया जो इससे पहले थी

सुधार ने इस तरह के संतुलन को बाधित किया। द.

संशोधन केवल इस तरह के संतुलन को बहाल करना चाहता है और

इसलिए इसे बुनियादी विनाशकारी नहीं कहा जा सकता है।

संविधान की संरचना। (iv) कि इस न्यायालय द्वारा द्वितीय में निर्धारित विधि और

इस तथ्य को देखते हुए तीसरे न्यायाधीश का मामला अब प्रासंगिक नहीं है।

उन दोनों में निर्धारित कानूनों की व्याख्या मामले अब एक अच्छा कानून नहीं है। यह आगे तर्क दिया जाता है कि

घटना यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर आता है कि कानून

संवैधानिक वैधता निर्धारित करने के लिए कुछ प्रासंगिकता संशोधन की और इसकी शुद्धता भी

उन निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों की आवश्यकता है

उचित शक्ति की पीठ द्वारा पुनर्विचार।

महान्यायवादी और अन्य विद्वानों के अनुसार

उत्तरदाताओं के लिए वकील, उपर्युक्त दो

निर्णय संविधान के पाठ के विपरीत हैं क्योंकि

यह तब खड़ा था और पूरी तरह से उपेक्षा में

संवैधानिक इतिहास और प्रासंगिक पृष्ठभूमि

प्रावधान। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि योजना के तहत

संविधान के अनुसार, न तो इस न्यायालय और न ही उच्च न्यायालयों को अयोग्य स्वायत्तता प्रदान की गई है, हालांकि एक बड़े पैमाने पर सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [चेलामेश्वर, जे।]

उदाहरण के लिए वेतन, विशेषाधिकार और भत्ते, पेंशन कानून द्वारा विनियमित किया जा सकता है

आदि को अभी भी संसद द्वारा बनाए गए

अनुच्छेद 125 और 221, 137, 140, 145 आदि के तहत।

(v) यह प्रस्तुत किया जाता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता है

निर्विवाद रूप से संविधान की एक बुनियादी विशेषता। अ.

इस मूल विशेषता का अनिवार्य तत्व यह है कि

अध्यक्ष (कार्यकारी) के पास निरंकुश नहीं होना चाहिए।

ऐसी नियुक्ति प्रक्रिया में विवेकाधिकार लेकिन यह नहीं कि

सी. जे. आई. (कॉलेजियम) की राय को प्रधानता दी जानी चाहिए या
न्यायालय के निर्णय

प्रभुत्व। द्वितीय में इस

और तीसरे न्यायाधीशों के मामले न केवल पाठ के विपरीत हैं बल्कि
रूप से विपरीत भी

संविधान के इरादे के स्पष्ट

सभा और स्पष्ट रूप से न्यायिक शक्ति की सीमाओं से परे, यह छद्म रूप में घटक प्राधिकरण का एक अभ्यास है

व्याख्या। संशोधन के तहत, राष्ट्रपति
नहीं है

न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में कोई विवेकाधिकार

संवैधानिक न्यायालयों का। वह बंधा हुआ है

एन. जे. ए. सी. की सिफारिश जिसमें सदस्य

न्यायपालिका एकल सबसे बड़ा समूह है। संसद

यह उचित माना कि सिविल के प्रतिनिधि

समाज को एक सहभागी भूमिका दी जानी चाहिए

संवैधानिक नियुक्तियों की प्रक्रिया

अदालतें और उनकी उपस्थिति एक जाँच होगी

संभावित और परिणामस्वरूप विनाशकारी 'व्यापार बंद'; (i)

तीन सदस्यों के बीच और उनके बीच
के बीच

न्यायपालिका और (ii) न्यायपालिका और न्यायपालिका

कार्यकारी; और किस चीज के लिए पारदर्शिता को बढ़ावा देगा
प्रक्रिया थी। इस तरह की बुद्धिमत्ता

यह अब तक एक अपारदर्शी

संसद सवाल करने के लिए तैयार नहीं है। यह एक

स्थापित और सम्मानित सिद्धांत कि न्यायालय

संसद के विवेक पर भी निर्णय में नहीं बैठते हैं

↓ सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

एक साधारण विधान के संबंध में; एक संवैधानिक

संशोधन अधिक सम्मान को आमंत्रित करता है।

(vi) संशोधन की योजना के तहत भी,
न्यायपालिका की एक प्रमुख भूमिका है। आशंका है कि,
नई व्यवस्था के तहत, कार्यपालिका के पास होगा
संवैधानिक न्यायालयों को पैक करने का अवसर

मित्रों के साथ इस देश का होना अतार्किक और निराधार है। द.
इस न्यायालय के तीन सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों की उपस्थिति

एन. जे. ए. सी. ऐसे लोगों के खिलाफ एक पूर्ण सुरक्षा है।

(vii) यह तथ्य कि न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आयोग
M.N.Venkatachaliah ने कुछ सिफारिशें कीं

आवश्यक रूप से इसका मतलब यह नहीं है कि द्वारा सुझाए गए मॉडल

आयोग सुरक्षा के लिए एकमात्र मॉडल है

न्यायपालिका की स्वतंत्रता या सबसे अच्छा मॉडल। किसी भी सूरत में

संसद अपनी घटक शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती है
केवल इस आधार पर असंवैधानिक माना जाए कि

कुछ लोगों की राय है कि बेहतर मॉडल हैं या

विकल्प। इस तरह का मूल्य निर्णय विशेष रूप से है

संसद की घटक शक्तियों का क्षेत्र। यह भी है

तर्क दिया कि सदस्यों के चयन के लिए तंत्र
संवैधानिक न्यायालयों की, जैसा कि द्वितीय में व्याख्या की गई है।

और तीसरे न्यायाधीशों के मामले, यहां तक कि श्री के अनुसार।

नरीमन की राय अच्छी नहीं है। श्री नरीमन चल रहे हैं

उनके द्वारा लिखित पुस्तकों में से एक में ऐसा उल्लेख किया गया है

"स्मृति लुप्त होने से पहले: एक आत्मकथा" 77।

77 फली एस. नरीमन, बिफोर मेमोरी फेड्स-एन ऑटोबायोग्राफी,

पी। 389 - "यदि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किया गया कोई एक महत्वपूर्ण मामला है जिसमें मैं
पेश हुआ और जीता, और जिस पर मुझे खेद है, तो वह निर्णय है जो शीर्षक द्वारा जाता है-सुप्रीम कोर्ट
एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ। यह वर्ष 1993 का निर्णय है और इसे द्वितीय
न्यायाधीश मामले के रूप में जाना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [चेलामेश्वर, जे।]

94. के तहत स्थापित कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया

संविधान अनिवार्य रूप से स्थापना के लिए अनुकूल होना चाहिए।

न केवल एक स्वतंत्र न्यायपालिका बल्कि यह भी सुनिश्चित करना कि दक्षता। स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए दो गुण आवश्यक हैं।

"विभिन्न शक्तियों के उस अलग और विशिष्ट प्रयोग के लिए एक उचित नींव रखने के लिए

इस तरह से गठित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक के सदस्यों के पास यथासंभव कम एजेंसी हो सदस्यों की नियुक्ति में

अन्या। क्या इस सिद्धांत का सख्ती से पालन किया गया था, इसके लिए सभी नियुक्तियों की आवश्यकता होगी

सर्वोच्च कार्यपालिका, विधायी और न्यायपालिका

जादूगरों को सत्ता के एक ही स्रोत, लोगों के माध्यम से खींचा जाना चाहिए।

चैनल जिनका एक दूसरे के साथ कोई संचार नहीं है। कुछ कठिनाइयाँ और कुछ अतिरिक्त खर्च इसके निष्पादन में शामिल होंगे। कुछ

इसलिए, सिद्धांत से विचलन को स्वीकार किया जाना चाहिए। न्यायपालिका के संविधान में

विशेष रूप से विभाग, यह हो सकता है

सिद्धांत: सबसे पहले, क्योंकि विशिष्ट योग्यताएँ सदस्यों में आवश्यक होने के कारण, प्राथमिक

पी। 400 - "मुझे नहीं लगता कि उच्चतम न्यायालय के पहले पांच न्यायाधीशों में इतना खास क्या है। वे नियुक्ति की वरिष्ठता में केवल पहले पांच हैं-जरूरी नहीं कि वे ज्ञान या क्षमता की श्रेष्ठता में हों। जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (या एक प्रख्यात अधिवक्ता) को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रस्ताव किया जाता है तो मुझे कोई कारण नजर नहीं आता कि उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों से परामर्श क्यों नहीं किया जाना चाहिए। मेरा सुझाव है कि पांच न्यायाधीशों के बंद सर्किट नेटवर्क को भंग कर दिया जाना चाहिए। वे हमेशा अपने 'कार्ड' को अपनी छाती के पास रखते हैं। वे किसी से नहीं पूछते।

वे खुद के अलावा किसी से सलाह नहीं लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

उस मोड को चुनने पर विचार किया जाना चाहिए।

कौन सा विकल्प इन्हें सबसे अच्छा सुरक्षित करता है
योग्यताएँ "। 78

[जोर दिया गया]

न्यायाधीश जो उनके सामने लाए गए कारणों का फैसला कर सकते थे
लागू होने वाले सिद्धांतों के साथ तेजी से और सुसंगत
न्यायशास्त्र, वादियों और राजनीति में विश्वास पैदा करता है
कि वे वास्तव में न्याय देते हैं। क्या नियुक्ति
संशोधन से पहले की प्रक्रिया से ऐसी नियुक्तियां प्राप्त हुईं
गहरा विवाद हुआ है। जैसा कि विद्वान द्वारा प्रस्तुत किया गया है
महान्यायवादी, नियुक्तियों का इतिहास
हमारे गणराज्य में संवैधानिक न्यायालयों को विभाजित किया जा सकता है
दो चरणों में-द्वितीय न्यायाधीशों के मामले से पहले और बाद में। नहीं। दोनों चरणों के दौरान
संदेह, नियुक्ति प्रक्रिया का परिणाम निकला
स्वतंत्रता और दोनों के सूचकांक पर मिश्रित परिणाम
दक्षता। कुछ उत्कृष्ट और कुछ उतने उत्कृष्ट नहीं हैं।
व्यक्ति को दोनों चरणों में नियुक्त किया गया। के आरोप
गंभीर रूप से अयोग्य नियुक्तियां बहुत हैं लेकिन हमारी प्रणाली लेखा परीक्षा या गुणात्मक
विक्षेपण के लिए कोई तंत्र प्रदान नहीं करता है।
इस तरह की प्रणालीगत कमी के रोगजनक परिणाम होते हैं।

95. बहुसंख्यक इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाली संसद थी

संतुष्ट हैं कि मौजूदा प्रक्रिया में बदलाव और कार्रवाई की आवश्यकता है अपनी घटक शक्ति और
सहवर्ती विवेक का प्रयोग करते हुए।

आवश्यकता का ऐसा घटक मूल्यांकन स्पष्ट रूप से सीमा से बाहर है
न्यायिक समीक्षा। क्या उपचार की शुरुआत की गई
भारती मामले में घोषित और पालन किए गए कानून के कारण उसके बाद लगातार।

96. संशोधन के पाठ और योजना में शामिल नहीं है

नियुक्तियाँ करने में राष्ट्रपति का विवेकाधिकार

78 फेडरेस्ट No.51 (हैमिल्टन या मैडिसन) (1788) देखें।

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [चेलामेश्वर, जे।]

संवैधानिक न्यायालयों और राष्ट्रपति को एन. जे. ए. सी. की सिफारिशों को स्वीकार करना आवश्यक है। संशोधित

अनुच्छेदों में कहा गया है कि संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीश

राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

एनजेएसी की सिफारिश।

97. संशोधन से पहले, केवल दो थे

नियुक्ति प्रक्रिया के पक्षकार, कार्यपालिका और

न्यायपालिका। उनकी भूमिकाओं का सापेक्ष महत्व अलग-अलग था

समय-समय पर। संशोधन तीन महत्वपूर्ण परिवर्तन करता है—(i) न्यायपालिका की प्रधानता को कम किया जाता है; (ii) न्यायपालिका की भूमिका कार्यपालिका में भी कटौती की जाती है और (iii) नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को तंत्र का हिस्सा बनाया जाता है।

98. के मामले में न्यायपालिका की राय की प्रधानता

न्यायिक नियुक्तियाँ ही एकमात्र साधन नहीं हैं

एक स्वतंत्र और कुशल न्यायपालिका की स्थापना। वहाँ

राय की प्रचुरता है (विवेकपूर्ण और जिम्मेदार में) नागरिक समाज के क्वार्टर

कानूनी बिरादरी, न्यायविदों, राजनीतिक में

सिद्धांतकार और विद्वान) कि न्यायपालिका की राय के लिए प्रधानता

के लिए एक मानक या संवैधानिक मौलिक नहीं है

एक स्वतंत्र और कुशल न्यायपालिका की स्थापना। इस तरह साबित हुई है। यह.

एक धारणा संदिग्ध सटीकता की

संसद की दृढ़ धारणा है कि नागरिक को शामिल करना वांछनीय होगा

समाज का प्रतिनिधित्व गंभीर रूप से

पारदर्शिता, प्रतिबद्धता और अंतिम की भागीदारी

हितधारक-लोग। सभी संवैधानिक का फव्वारा

प्राधिकरण, सबसे उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए

कई लोगों की वैध आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए

प्रतिस्पर्धी रुचियाँ। विभिन्न लोकतांत्रिक समाजों ने और
 ऐसी चयन प्रक्रिया में समाज का प्रतिनिधित्व। मूल्यांकन
 परिणाम अनिर्णायक हैं।
 हालाँकि इस तरह के प्रयोगों के
 सवाल यह नहीं है कि क्या मॉडल की कल्पना की गई है
 संशोधन से एक अधिक स्वतंत्र और कुशल सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर. प्राप्त होगी।

न्यायपालिका। सवाल यह है कि क्या संसद का विवेक और
 सहारा लेकर ऐसा प्रयोग करने का अधिकार
 घटक शक्ति आकस्मिक लेखापरीक्षा के अधीन है।

99. जैसा कि महान्यायवादी ने ठीक ही कहा है,
 संविधान की मूल विशेषता राय की प्रधानता नहीं है
 सीजेआई (कॉलेजियम) का लेकिन निरपेक्ष के गैर-निवेश में निहित है
 राष्ट्रपति (कार्यकारी) को चुनने और नियुक्त करने की शक्ति
 संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीश। यह विशेषता नहीं है
 संशोधन द्वारा निरस्त किया गया। कार्यकारी सबसे अच्छा हो सकता है
 केवल एन. जे. ए. सी. में अपने प्रतिनिधि के माध्यम से एक प्रस्ताव बनाएं,
 अर्थात् विधि मंत्री। ऐसा प्रस्ताव, यदि अयोग्य माना जाता है,
 एन. जे. ए. सी. के अन्य सदस्यों द्वारा अभी भी अस्वीकार किया जा सकता है। उम्मीदवार का मूल्य इस बात
 पर निर्भर नहीं करता है कि कौन प्रस्ताव देता है।
 नाम और न ही उम्मीदवार का राजनीतिक संघ, यदि कोई हो,
 अयोग्यता हो।

....., यहाँ तक कि पार्टी के लोग भी उग्र हो सकते हैं

राजनीति। न्यायमूर्ति के. एस. हेगड़े ने सदस्य के रूप में कार्य किया।
 1952 से 1957 तक राज्य सभा के सदस्य रहे और

सीधे राज्य से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत
 सभा। भले ही वे कांग्रेस के सांसद थे, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया

इतना स्वतंत्र होने के लिए कि उसे हटा दिया गया था
 1973 स्वयं सी. जे. आई. की नियुक्ति में
 पार्टी की सरकार। न्यायमूर्ति टेकचंद न्यायाधीश बनने से पहले राज्यसभा के सदस्य भी थे।
 उन्हें तब नियुक्त किया गया था जब वे एक मौजूदा सांसद थे, लेकिन
 वह एक अच्छा न्यायाधीश साबित हुआ जिसकी रिपोर्ट
 निषेध एक मील का पत्थर है। एक और प्रमुख
 उदाहरण न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा लायर हैं जिन्हें बनाया गया था।
 1968 में केरल उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश, हालांकि

वे न केवल एक विधायक रहे थे, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन में
 मंत्री भी रहे थे। यू. ओ. आई. [चेलामेश्वर, जे।]

नम्बूदिरीपद सरकार (1957-59)

केरल। 1973 में, न्यायमूर्ति एस. एम. सीकरी, सीजेआई थे।
 न्यायमूर्ति लायर की पदोन्नति का पूरी तरह से विरोध किया
 सर्वोच्च न्यायालय ने इस आधार पर कि वह एक था
 राजनेता जो एक कैबिनेट मंत्री का पद संभालते थे
 केरल में। ए. एन. रे ने ही उनकी पदोन्नति को मंजूरी दी थी।
 और जस्टिस लायर एक चमकदार उदाहरण साबित हुए।

एक न्यायाधीश को क्या होना चाहिए। वह उनमें से एक थे

सबसे अच्छे न्यायाधीश जो कभी बेंच पर बैठे थे

सर्वोच्च न्यायालय जिसने अंतर को पाटने की कोशिश की

सर्वोच्च न्यायालय और आम लोग। वहाँ

न्यायमूर्ति बहरुल इस्लाम का भी उदाहरण है जो

10 साल तक राज्य सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया
 उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने से पहले। वह.

बाद में उन्हें उच्चतम न्यायालय में पदोन्नत किया गया।

उन्होंने मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को दोषमुक्त कर दिया।

बारपेटा से-उन्होंने कभी भी एक स्वच्छ प्रतिष्ठा का आनंद नहीं लिया।
इसलिए, कोई सामान्यीकरण करना उचित नहीं है।

त्रुटिहीन ईमानदारी वाले लोगों को होना चाहिए

हाथ से चुना गया "। 79

100. अनुच्छेद 124, 217 और 124-ए का आलोचनात्मक विश्लेषण और

124 - बी इस स्थिति की ओर ले जाता है कि कार्यकारी शाखा सरकार एक 'अयोग्य उम्मीदवार' को
आगे नहीं बढ़ा सकती

जब तक कम से कम दो सदस्य न्यायिक का प्रतिनिधित्व करते हैं शाखा उस उम्मीदवार की
अनुपयुक्तता के बारे में अपने विचार में एकजुट है। यहां तक कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति और एक एकल न्यायिक

एन. जे. ए. सी. का सदस्य किसी अयोग्य व्यक्ति के प्रवेश को प्रभावी ढंग से रोक सकता है।

79 सुधांशु रंजन, 'भारत में न्याय, न्यायपालिका और लोकतंत्र: सीमाएँ और उल्लंघन' ;

p.185-186 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

नियुक्ति। इसी तरह न्यायिक सदस्य भी दबाव नहीं डाल सकते।

अपनी पसंद के व्यक्तियों के माध्यम से जब तक कि कम से कम एक अन्य

गैर-न्यायिक खंड से संबंधित सदस्य का समर्थन करता है

उनके द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवार।

101. सरकार का एक लोकतांत्रिक रूप शायद है

स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए आविष्कार की गई सबसे अच्छी संस्था। कम से कम

यह उन समाजों का विश्वास है जो इस मॉडल को अपनाते हैं

शासन। यह सच है कि लोकतंत्र के कई रूप हैं।

रूपों का विश्लेषण इस निर्णय के दायरे से बाहर है।

किसी भी संवैधानिक मॉडल के तहत, प्राथमिक जिम्मेदारी

लोगों की स्वतंत्रता को संरक्षित करना विधायिका को सौंपा गया है और कार्यकारी शाखाएँ। इस
तरह के प्रत्यर्पण पर आधारित है

संरचनात्मक और अनुभवजन्य धारणा जिसे विधायक चुनते हैं

समय-समय पर केवल उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करने का प्रयास करेंगे।

टेंडम। वे दिए गए विश्वास का निर्वहन करने के लिए बाध्य हैं और चुने जाने की महिमा खोने का डर

प्रतिनिधि। आवधिक प्रणाली में एक अंतर्निहित संभावना

चुनाव।

2. यह मान लेना या दावा करना कि केवल न्यायपालिका ही

स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है और वह काम करता है

खैर, एक धारणा है जो हठधर्मी है, साक्ष्य से रहित है आधार और ऐतिहासिक रूप से अस्वीकृत। प्रख्यात संविधान न्यायविद और

इस संदर्भ में शिक्षक लॉरेंस एच. ट्राइब का कहना है:

अमेरिकी अनुभव।

"किसी को भी यह नहीं मानना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय को हमेशा कानूनों और कार्यकारी कार्यों को रद्द करने की आवश्यकता है

हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए। इसके विपरीत,

कभी-कभी न्यायालय हमारे अधिकारों की सबसे अच्छी गारंटी देता है राजनीतिक निर्णय को टालने के बजाय

शाखाएँ। जब सर्वोच्च न्यायालय, 1900 से

1937 तक, दर्जनों बाल श्रम कानूनों को निरस्त कर दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [चेलामेश्वर, जे।]

न्यूनतम मजदूरी कानून, काम करने की स्थिति के नियम,

और श्रमिकों की रक्षा करने वाले कानून; संगठित करने के अधिकार

संपत्ति के अधिकार और "अनुबंध की स्वतंत्रता" का उल्लंघन, केवल वे अधिकार जिन्हें न्यायालय ने वास्तव में सही ठहराया था, वे अधिकार थे

अधिक काम करने वाला, कम वेतन वाला या बेरोजगार होना। द.

अदालत ने अंततः इन मुद्दों पर खुद को उलट दिया।

जब यह माना गया कि बीसवीं शताब्दी में
 अमेरिका, ऐसे कानून मानव पर घुसपैठ नहीं हैं
 किसी भी सार्थक अर्थ में स्वतंत्रता, लेकिन इसके बजाय हैं
 पूरी तरह से उचित और मुकाबला करने के उचित तरीके
 आर्थिक अधीनता। न्यूनतम बनाए रखने में
 पश्चिमी तट के जलविभाजक मामले में मजदूरी कानून
 होटल बी. पैरिश, सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि
 1937 कि, "हाल के आर्थिक" के आलोक में
 अनुभव ", इस तरह के कानूनों को उचित ठहराया गया क्योंकि
 वे श्रमिकों के एक वर्ग के शोषण को रोकते हैं।
 उनके स्वास्थ्य और कल्याण के लिए हानिकारक तरीके से "।
 स्वाभाविक रूप से, इस अपूर्ण दुनिया में, सर्वोच्च न्यायालय ने
 और जैसा हम मानते हैं वैसा ही बोलें। और उसके बाद युद्ध उन्माद में पल हार्बर पर बमबारी,
 कोरेमात्सु बनाम में सर्वोच्च न्यायालय।
 संयुक्त राज्य अमेरिका ने हजारों की कैद को बरकरार रखा
 जापानी वंश के अमेरिकी जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया था।
 इस तरह की खामियों के आलोक में, कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि यह कब आता है
 मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, सर्वोच्च न्यायालय है
 अनिवार्य रूप से अनावश्यक: अधिकांश अवसरों पर कांग्रेस और राष्ट्रपति हमारे अधिकारों की पर्याप्त रूप से
 रक्षा करेंगे।
 कठिन समय जब राजनीतिक शाखाओं को गिना नहीं जा सकता है
 न ही न्यायालय ऐसा कर सकता है। 80
 80 लॉरेंस एच. ट्राइब, गॉड सेव दिस ऑनरेबल कोर्ट, फर्स्ट एडिशन,

p.10-11 [2015] 13 एससीआर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

103. हमारा अनुभव अलग नहीं है। ए. के. में निर्णय

गोपालन 31, संकलचंद 82 और ए. डी. एम. जबलपुर (उल्लेख करने के लिए)
 कुछ) एक समान निष्कर्ष की ओर ले जाना चाहिए कि कठिन समय में
 जब राजनीतिक शाखाओं पर भरोसा नहीं किया जा सकता, न ही किया जा सकता है
 न्यायपालिका। जिस बात पर प्रकाश डाला जाना चाहिए वह यह है कि न्यायपालिका
 एकमात्र संवैधानिक अंग नहीं है जो स्वतंत्रता की रक्षा करता है
 लोगों को। तदनुसार, न्यायपालिका की राय को प्राथमिकता
 न्यायिक नियुक्तियों के मामले में यह एकमात्र तरीका नहीं है
 स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।
 नतीजतन, यह धारणा कि न्यायिक की प्रधानता
 नियुक्ति प्रक्रिया में शाखा एक आवश्यक तत्व है।
 और इस प्रकार एक बुनियादी विशेषता बिना किसी आधार के अनुभवजन्य रूप से त्रुटिपूर्ण है।
 या तो राष्ट्र के संवैधानिक इतिहास में या किसी अन्य में और राजनीतिक के विपरीत होने के
 अलावा मानक रूप से गलत है
 सिद्धांत।

104. अब मैं इस प्रस्तुति से निपटता हूँ कि

एन. जे. ए. सी. में कानून मंत्री ने स्वतंत्रता को कमजोर किया
 न्यायपालिका। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, की उपस्थिति
 कार्यपालिका के सदस्य के पास हमेशा शक्ति की गतिशीलता को बदलने का प्रभाव होता है। मैं कानून मंत्री
 की उपस्थिति
 एन. जे. ए. सी. जो प्रति मतदान शक्ति का एक तिहाई प्रदान करता है, उसे कमजोर करता है।
 न्यायपालिका की स्वतंत्रता। प्रस्तुतिकरण असमर्थनीय है।
 इसके अधीन एक विशाल प्रशासनिक तंत्र के साथ कार्यपालिका
 नियंत्रण चयन प्रक्रिया में भारी और मूल्यवान योगदान करने में सक्षम है। आपत्ति उचित है।
 कार्यकारी शाखा में विश्वास की कमी पर कुछ हद तक
 संवैधानिक अर्थ में, एन. जे. ए. सी. का एक घटक होना।

81 ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य ए. आई. आर 1950 एस. सी. 27

82 भारत संघ बनाम। संकलचंद हिमतलाल सेठ और अन्न।, (1977) 4 एससीसी 193

83 ए. डी. एम. जबलपुर बनाम एस. एस. शुक्ला आदि। आदि। आकाशवाणी 1976 एससी 1207

84 लॉरेंस एच. ट्राइब (अमेरिकी संवैधानिक कानून) दूसरा संस्करण, अध्याय 1 का पृष्ठ 2 "संवैधानिक विश्लेषण के लिए दृष्टिकोण"-"कि सभी वैध शक्तियाँ लोगों से प्राप्त होती हैं और उनके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए उन्हें नियंत्रण में रखा जाना चाहिए। स्वतंत्रता अमेरिकी संविधानवाद का सबसे पुराना और सबसे केंद्रीय सिद्धांत है। शुरुआत में, सरकारी प्राधिकरण के प्रयोग पर केवल कुछ ही स्पष्ट ठोस सीमाओं को आवश्यक माना जाता था; मुख्य रूप से, यह सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड थे।

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [चेलामेश्वर, जे।]

यही तर्क न्यायिक शाखा पर भी लागू होता है,

इस विश्वास के बावजूद कि यह सबसे कम खतरनाक शाखा है।

संविधान सभा ने आराम करने से इनकार कर दिया सीजेआई में भी विशेष विश्वास। कार्यपालिका को पूरी तरह समाप्त करने के लिए

चयन की प्रक्रिया से असंगत होगा

मूलभूत आधार है कि लोकतंत्र में सरकार द्वारा

हमारा संविधान, कार्यपालिका को स्पष्ट अधिकार दिया गया है क्षेत्र की रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का प्रशासन करना, आंतरिक

सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव, कराधान, प्रबंधन

राजकोषीय नीतियों और अन्य पहलुओं की एक श्रृंखला, जो राष्ट्र के प्रशासन और उसके जीवन के हर पहलू को छूती है लोग। इस संदर्भ में, यह अभिनिर्धारित करना कि इसे पूरी तरह से बहिष्कृत किया जाना चाहिए

न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी तरह से अतार्किक होगी।

और के सिद्धांत की नींव के साथ असंगत लोकतंत्र और एक सैद्धांतिक पाखंड। इस तरह के बहिष्कार का कोई मतलब नहीं है

किसी भी अन्य लोकतंत्र में समानांतर जिनके मॉडल की जांच की गई थी

संविधान सभा द्वारा और किसी अन्य को नहीं लाया गया था

हमारा नोटिस भी। संविधान के स्थापित सिद्धांत

सरकार, अन्य लोकतांत्रिक संवैधानिक प्रथाओं में

उनका मानना था कि व्यक्त आदेश की तुलना में विकेंद्रीकरण द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अधिक प्रभावी ढंग से सुरक्षित किया जा सकता है। सत्रहवीं शताब्दी के अंग्रेजी उदारपंथियों के विचार से, विशेष रूप से, जैसा कि मोंटेस्क्यू द्वारा अठारहवीं शताब्दी के फ्रांस में विस्तार से बताया गया था, संविधान के निर्माताओं ने यह विश्वास प्राप्त किया था कि मानवाधिकारों को निष्क्रियता और अप्रत्यक्षता द्वारा संरक्षित किया जा सकता है- जानबूझकर विरोधी शक्ति के खंडित केंद्रों के पीछे, एक दृष्टि में जो इसकी प्रेरणा में लगभग न्यूटनियन है। इस पहले मॉडल में, किसी भी व्यक्ति या पुरुषों के एकल समूह में शक्ति के केंद्रीकृत संचय का अर्थ था अत्याचार; शक्तियों का विभाजन और पृथक्करण, दोनों ऊर्ध्वाधर (संघीय, राज्य और स्थानीय प्राधिकरण के अक्ष के साथ) और क्षैतिज (विधायी, कार्यकारी और न्यायिक प्राधिकरण के अक्ष के साथ) का अर्थ था स्वतंत्रता। इस प्रकार यह आवश्यक था कि किसी भी विभाग, शाखा या सरकार के स्तर को अपने दम पर प्रभुत्व हासिल करने का अधिकार न दिया जाए। अगर विधायिका दंड देगी, उसे अन्य शाखाओं का सहयोग लेना चाहिए- कार्यपालिका को मुकदमा चलाने के लिए, न्यायिक को मुकदमा चलाने और दोषी ठहराने के लिए। सरकारी शक्ति के एक दूसरे केंद्र के साथ भी ऐसा ही है: संविधान नामक सामाजिक समझौते में लोगों द्वारा उसे सौंपे गए कार्यों के मिश्रण का प्रयोग करते हुए, प्रत्येक शक्ति केंद्र सामाजिक डिजाइनों की अंतिम प्रभावकारिता के लिए दूसरों पर निर्भर रहेगा। "[2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

व्यवस्थाएँ और यह तथ्य कि संविधान सभा कार्यपालिका के लिए एक भूमिका स्पष्ट रूप से अनुमान को प्रतिबंधित करती है

कि चयन प्रक्रिया में कार्यकारी भागीदारी निरस्त हो जाती है

एक बुनियादी विशेषता। महान्यायवादी अपनी प्रस्तुति में सही हैं।

कि कार्यकारी शाखा का बहिष्कार मूल के लिए विनाशकारी है

नियंत्रण और संतुलन की विशेषता-एक मौलिक सिद्धांत

संवैधानिक सिद्धांत।

105. यह मुझे दूसरे प्रावधान पर ले जाता है जो है

चुनौती के तहत। अनुच्छेद 124 ए। (1) (घ) जिसमें कहा गया है कि प्रतिष्ठित व्यक्ति होने चाहिए। काबिले गौर

एन. जे. ए. सी. में दो

सुनवाई के दौरान हुई थी बहस

इस प्रावधान की वैधता, जिसका सार इसमें लिया गया है

खेहर, जे. का निर्णय हमला फिर से इस आधार पर है कि

प्रावधान पूरी तरह से चयन के संबंध में मार्गदर्शन के बिना है

प्रतिष्ठित व्यक्तियों से। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि (i) हो सकता है

सत्ता में पार्टी और के बीच द्विदलीय समझौता विरोध, जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित दो स्थानों को साझा किया गया

प्रतिष्ठित व्यक्ति। इस तरह की संभावना अंततः सक्षम होगी

विचार, जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है; (ii) यह मानते हुए भी कि दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने नामांकित किया है।

पूर्ण राजनीतिक तटस्थ हैं, लेकिन न्यायपालिका के लिए अजनबी हैं

85 अनुच्छेद 124 ए। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। - (1) राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के रूप में जाना जाने वाला एक आयोग होगा जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे -

XXXX

(घ) प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोक सभा में विपक्ष के नेता वाली समिति द्वारा नामित किए जाने वाले दो प्रतिष्ठित व्यक्ति या जहां विपक्ष का ऐसा कोई नेता नहीं है, तो लोक सभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता।

बशर्ते कि प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक को अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों में से नामित किया जाएगा,

जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक या महिलाएँ।

बशर्ते कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को तीन साल की अवधि के लिए नामित किया जाएगा और वह पुनः नामांकन के लिए पात्र नहीं होगा।

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [चेलामेश्वर, जे।]

प्रणाली, वे किसी भी सार्थक बनाने में सक्षम नहीं होंगे

चयन प्रक्रिया में योगदान, क्योंकि उनके पास निर्णय के लिए उपयुक्त डेटा एकत्र करने के लिए कोई संसाधन नहीं होगा प्रक्रिया बनाना; (iii) दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों की संभावना

सर्वसम्मति से अनुमोदित व्यक्ति की उम्मीदवारी पर वीटो करना

एन. जे. ए. सी. के तीन न्यायिक सदस्य स्वयं विनाशकारी हैं

मूल संरचना।

106. संविधान में पारदर्शिता एक महत्वपूर्ण कारक है

शासन। इस न्यायालय ने असंख्य मामलों में उल्लेख किया कि तर्कसंगतता की मांग करता है

संविधानवाद राज्य के हर क्षेत्र में

कार्रवाई। न्यायिक कार्यवाही के संदर्भ में, इस न्यायालय ने कहा कि

नरेश श्रीधर मिराजकर और अन्य। वी. महाराष्ट्र राज्य और

एन. आर. 86.

खुली अदालत में सार्वजनिक मुकदमा है

" 20.

निस्संदेह स्वस्थ, उद्देश्य और उद्देश्य के लिए आवश्यक है।

न्याय का निष्पक्ष प्रशासन। मुकदमा इसके अधीन आयोजित किया गया

सार्वजनिक जांच और टकटकी स्वाभाविक रूप से एक जाँच के रूप में कार्य करती है

न्यायिक सनक या अनियमितताओं के खिलाफ, और के रूप में कार्य करता है आत्मविश्वास पैदा करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण

निष्पक्षता, निष्पक्षता और निष्पक्षता में जनता

न्याय का प्रशासन। जनता में विश्वास

न्याय का प्रशासन इतना महान है

इसका महत्व है कि कोई दो राय नहीं हो सकती हैं

व्यापक प्रस्ताव है कि उनके निर्वहन में न्यायिक न्यायाधिकरणों के रूप में कार्य करता है, न्यायालयों को आम तौर पर

कारणों को खुले में सुनें और जनता को अनुमति देनी चाहिए

अदालत में प्रवेश-कमरा। जैसे बेंथम ने किया है

"गोपनीयता के अंधेरे में भयावह हित, और हर रूप में बुराई, पूर्ण स्विंग है। केवल में

86 ए. आई. आर 1967 एस. सी. 1, पैरा 20।

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रचार के रूप में अनुपात में से कोई भी स्थान हो सकता है
न्यायिक अन्याय पर लागू चेक संचालित होते हैं।

जहाँ प्रचार नहीं है वहाँ न्याय नहीं है।

प्रचार न्याय की आत्मा है। यह सबसे उत्सुक है

परिश्रम करने के लिए प्रेरित करें, और सभी रक्षकों के खिलाफ निश्चित रूप से

असंभवता। यह कोशिश करते समय न्यायाधीश को खुद रखता है।
परीक्षण के तहत (इस अर्थ में कि) की सुरक्षा

प्रतिभूतियाँ प्रचार है "।
पारदर्शिता तर्कसंगतता का एक पहलू है। इसकी आवश्यकता

नियुक्ति प्रक्रिया के मामले में पारदर्शिता अधिक होती है।

कॉलेजियम की कार्यवाही पूरी तरह से अपारदर्शी थी और

कभी-कभी को छोड़कर, सार्वजनिक और इतिहास दोनों के लिए दुर्गम रिसावा रुमा पाल, जे.
रिकॉर्ड में है -

"कॉलेजियम के भीतर कभी-कभी सहमति होती है

एक व्यापार-बंद के माध्यम से हल किया गया जिसके परिणामस्वरूप संदिग्ध

'लॉबिंग सिस्टम के भीतर'। 87
लाभकारी उद्देश्य प्रतिनिधियों को शामिल करना है।

एक

नागरिक समाज की उम्मीद है कि यह एक चेक के रूप में कार्य करता है

कॉलेजियम के भीतर अस्वास्थ्यकर व्यापार और अनाचार पर न्यायिक और कार्यकारी शाखाओं के
बीच आवास। यह विश्वास करना कि केवल न्यायपालिका के सदस्य ही ला सकते हैं

नियुक्ति प्रक्रिया के लिए मूल्यवान निवेश की बहुत आवश्यकता होती है। नागरिक समाज के लिए
घमंड और अनादर। अय्यर, जे. ने आगाह किया -

" 74. और जब हस्तांतरण के लिए मानदंड

न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो

लोकतंत्रवादियों के रूप में हमें पिछली प्रथाओं को परेशान करना चाहिए,

87 "एक स्वतंत्र न्यायपालिका "-सुश्री न्यायमूर्ति रुमा पाल द्वारा 5 वें वी. एम. तारकुंडे स्मारक व्याख्यान में
दिया गया भाषण 10.11.2011 सर्वोच्च न्यायालय-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन v.

यू. ओ. आई. [चेलामेश्वर, जे।]

याद रखें लर्नड हैंड जिन्होंने एक बार कहा था कि स्वतंत्रता की भावना वह आत्मा है जो बहुत निश्चित नहीं है।

कि यह सही है "। उस महान न्यायाधीश को पसंद था

क्रॉमवेल के बयान को याद करते हुए: "मैं आपसे विनती करता हूँ

मसीह की आंतों, सोचें कि आप गलत हो सकते हैं।

उन्होंने सीनेट समिति को बताया। मैं चाहूँगा कि

कि हर पोर्टल पर लिखा है

चर्च, हर स्कूल और हर कोर्ट-हाउस,
हूँ, मैं प्रत्येक विधायी निकाय के

किसी भी मई 1 मैं कहता

संयुक्त राज्य अमेरिका। मैं चाहता हूँ कि हर अदालत हो
शुरू करें "मैं आपको मसीह की आंतों में विनती करता हूँ,

सोचिए कि हम गलत हो सकते हैं। " (येल कानून

पत्रिका: Vol.71: 1961, नवंबर भाग)। " 88

[जोर दिया गया]

"स्थानान्तरण" और "राष्ट्रपति" को "नियुक्तियों" से बदलें

और "संसद" और लायर, जे की चेतावनी प्रथा है। याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों (ii) और (iii) का उत्तर दें।

107. ऐसी संभावना है कि आशंका

याचिकाकर्ताओं द्वारा व्यक्त किया गया कथन सच हो सकता है। इसकी संभावना

संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का दुरुपयोग कोई आधार नहीं है। ऐसी शक्ति प्रदान करने के अधिकार से इनकार करने के लिए। बचावत, जे.

एन. आई. सी. गोलक नाथ (ऊपर) ने इस प्रकार राय दी:

"235. कहा जाता है कि संसद इसका दुरुपयोग कर रही है।

बहुत अधिक बार करके संशोधन की शक्ति

परिवर्तन होता है। यदि संसद के पास करने की शक्ति है

संशोधन, कोई भी करने का विकल्प

विशेष संशोधन उस पर छोड़ दिया जाना चाहिए। सवाल-जवाब

इस न्यायालय में नीति पर बहस नहीं की जा सकती है। द.
किसी शक्ति के दुरुपयोग की संभावना इसकी कसौटी नहीं है।

अस्तित्व! वेब वी में। आउट्रिम [1907] ए. सी. 81, लॉर्ड
88 संकलचंद मामला (ऊपर) पैरा 78।

[2015] 13 एस. सी

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हॉबहाउस ने कहा, "अगर वे इसे देय पर पाते हैं।

धारा 92, उनके लिए इसके अस्तित्व से इनकार करना काफी गलत होगा क्योंकि कुछ संभावना से यह हो सकता है दुरुपयोग किया जाता है, या सीमा को सीमित किया जाता है जो अन्यथा होगा

डोमिनियन संसद के लिए खुला रहें "। के साथ

निहित निषेध के सिद्धांत का संदर्भ में निर्धारित शक्ति के प्रयोग के विरुद्ध

निर्माण के सामान्य नियमों के अनुसार,

नॉक्स सी. जे., अमालगामेटेड सोसाइटी ऑफ इंजीनियर्स बनाम। एडिलेड स्टीमशिप कंपनी लिमिटेड 129 सी. एल. आर. 151 ने कहा, "इसका मतलब है

कुछ बाहरी और संभवतः शत्रुतापूर्ण शरीर। यह अविश्वास पर आधारित है, ऐसा न हो कि शक्तियां, अगर एक बार स्वीकार कर ली जाए कम से कम, विनाश के बिंदु तक दुरुपयोग किया जा सकता है। लेकिन सत्ता का संभावित दुरुपयोग नहीं है।

प्राकृतिक बल को सीमित करने के लिए ब्रिटिश कानून में कारण

भाषा उन्हें बनाती है "।

हालाँकि, यह एक असहमत राय थी। लेकिन यह कंपनी

कोएल्हो (सुप्रा), सभरवाल, जे. एक यूनानी के लिए बोल रहे हैं नौ न्यायाधीशों का च, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया:

" 76. यह भी तर्क दिया जाता है कि पैक करने की शक्ति

किसी भी संकेत के अभाव में नौवीं अनुसूची में कानून

अनुच्छेद 31 बी में दुरुपयोग किया गया है और यह दुरुपयोग है

जारी रहने की संभावना है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि नौवां

अनुसूची जो केवल 13 से शुरू हुई

अधिनियमों में अब 284 अधिनियमों की सूची है। द.

अनुच्छेद 31 बी की वैधता पर हमारे सामने कोई सवाल नहीं है।

इसके अलावा, केवल दुरुपयोग की संभावना नहीं है

एक की वैधता निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक परीक्षण प्रावधान।

जनता, संविधान के माध्यम से, सर्वोच्च न्यायालय अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड संगठन v. यू. ओ. आई.
[चेलामेश्वर, जे।]

उनके पास कानून बनाने की शक्ति निहित है
उसी में संसद के माध्यम से प्रतिनिधि

कानून के निर्णय, व्याख्या और निर्माण की जिम्मेदारी
और संविधान में इसकी सीमा सहित

न्यायपालिका। इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते।

शक्ति के कथित दुरुपयोग के बारे में धारणा "।

[जोर दिया गया]

अंतिम विश्लेषण में, सभी शक्तियों का दुरुपयोग किया जा सकता है।

न्यायिक शक्ति। इसका उपाय शक्ति प्रदान करने से इनकार करना नहीं है, बल्कि

इसकी संरचना करें ताकि दुरुपयोग की संभावना को समाप्त किया जा सके। द.

दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों को नामित करने की शक्ति प्रदान की गई है

तीन उच्च संवैधानिक पदाधिकारी-प्रधानमंत्री,

विपक्ष के नेता और सीजेआई। यह प्राथमिक राजनीतिक ज्ञान है कि प्रधानमंत्री और नेता

विपक्ष के हमेशा परस्पर विरोधी राजनीतिक हित होते हैं और

शायद ही कभी किसी मुद्दे पर सहमत होते। फिर भी, संभावना

द्विदलीय समझौते से इंकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि,

समिति में सीजेआई की उपस्थिति आम तौर पर मजबूत होनी चाहिए।

निवारक, सी. जे. आई. के राजनीतिक दृष्टिकोण को समझने में विफल रहने की संभावना

इस तरह के समझौते की स्थिति में समझौता या असहायता, इससे इंकार नहीं किया जा सकता है।

108. यह निर्विवाद है कि प्रतिष्ठित का नामांकन

व्यक्ति न्यायिक समीक्षा से अछूते नहीं हैं। इस प्रकार है

एन. जे. ए. सी. के कार्यकरण में देरी की संभावना और अनिवार्य रूप से
 संवैधानिक न्यायालयों में नियुक्तियों की प्रक्रिया। यह, इसलिए, यह आवश्यक है कि एक घेराबंदी होनी
 चाहिए
 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नामांकन की प्रक्रिया जो समाप्त हो जाती है
 संभावित द्विदलीय समझौतों का जोखिम। एकमात्र कल्पना योग्य
 उपचारात्मक प्रक्रिया में जांच के एक अन्य स्तर को शामिल करना है। नामांकन। मेरे
 सुविचारित विचार में, निम्नलिखित सुरक्षा
 इस प्रक्रिया को सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट की अनुमेय रूपरेखा के भीतर लाएगा।

[2015] 13 एस सी आर।

मूल विशेषता एक साथ 'विलंब कारक' को समाप्त करती है। द. अनुच्छेद 124-ए (1) (ए) के तहत
 विचार की गई समिति को दोनों में से प्रत्येक के लिए तीन सदस्यों का एक पैनल तैयार करना चाहिए।

नामांकित व्यक्तियों की श्रेणियाँ (प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिए)-सभी छह व्यक्तियों के पैनल में। इस तरह के
 पैनल को सामने रखा जाना चाहिए

मतदान के लिए उच्चतम न्यायालय का पूर्ण सदन। नामांकित व्यक्ति सुरक्षित दोनों श्रेणियों में से
 प्रत्येक में सबसे अधिक वोट अंततः होना चाहिए

एन. जे. ए. सी. के प्रतिष्ठित सदस्यों के रूप में नामित किया जाए। इस तरह
 प्रक्रिया अभी भी प्रतिष्ठित व्यक्तियों की पसंद को संरक्षित करेगी।
 मुख्य रूप से अनुच्छेद 124 के तहत विचार की गई समिति के साथ
 ए, संभावित सुरक्षा के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा को शामिल करते हुए
 समिति द्वारा शक्ति का दुरुपयोग।

109. तीसरा प्रावधान जिसकी वैधता पर हमला किया जा रहा है

अनुच्छेद 124 बी (सी), जो एनजेएसी को यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है कि

इस आधार पर है कि संशोधन किसी भी निर्धारित नहीं करता है क्षमता के आकलन के लिए एन.
 जे. ए. सी. द्वारा पालन किए जाने वाले दिशा-निर्देश

और ईमानदारी। किसी स्पष्ट घोषणा के अभाव में भी,

एन. जे. ए. सी. को सौंपी गई कार्यात्मक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा दायित्व अंतर्निहित और निहित है। द.

परिशुद्धता केवल एक प्रचुर मात्रा है। शायद प्रेरित किया गया

अतीत के कुछ बुरे अनुभवों से, पहले और बाद दोनों में

दूसरे न्यायाधीशों का मामला।

110. द्वारा दस्तावेज़ की प्रकृति (i) को ध्यान में रखते हुए

जिसे ऐसा दायित्व बनाया गया है; (ii) की संरचना

शरीर। (एन. जे. ए. सी.) जिस पर दायित्व डाला जाता है; और (iii) असाइनमेंट की प्रकृति, तर्क की आवश्यकता है

अस्वीकार कर दिया। एन. जे. ए. सी. एक संवैधानिक प्राधिकरण है जिसे कार्य करने के लिए बनाया गया है।

एक महत्वपूर्ण संवैधानिक कार्य। इसका चार्टर है स्वयं संविधान। इसके बावजूद, हमारी प्रोलिक्सिटी

संविधान, एक संविधान की वर्तनी की अपेक्षा या आवश्यकता नहीं है

राज्य के प्रशासन के बारे में हर मिनट विवरण दें।

अमेरिकी संविधान के संदर्भ में, यह कहा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड करता है

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [चेलामेश्वर, जे।]

संविधान जानबूझकर अधूरा है, अक्सर जानबूझकर

राजनीतिक भागीदारी विकास के लिए अनिश्चित संरचना आदर्श और सरकारी प्रथाएँ। संविधानों की गणना की गई है

सरकार की संरचनात्मक व्यवस्थाएँ और बाहरी व्यवस्थाएँ निर्दिष्ट करें

राज्य के विभिन्न अंगों को अपने आवंटित कार्यों का निर्वहन कैसे करना चाहिए, यह विस्तार से बताया जाना चाहिए। कानून या सम्मेलन द्वारा। सभी लिखित लोकतांत्रिक संविधान हैं -

अमूर्त नैतिक आदेशों से भरा!

111. इसके सर्वोच्च न्यायिक निकाय के तीन सदस्य

तीन वरिष्ठ सदस्यों वाली समिति द्वारा चुने गए व्यक्ति संविधान के तहत पदधारी एन. जे. ए. सी. का गठन करते हैं। को।

सुझाव है कि एन. जे. ए. सी. को स्पष्ट रूप से विस्तृत दिशानिर्देशों की आवश्यकता है
 संविधान के पाठ में वर्णित न्यायिक रूप से
 संवैधानिक प्रारूपण के लिए लचीले मानकों को अनिवार्य करना। द.
 संविधान की व्याख्या करने का कार्य उससे काफी अलग है।
 एक कानून बनाने का।

112. संविधान के प्रावधान नहीं होने चाहिए

कानून या, उस मामले के लिए, यहां तक कि एक कानून की आवश्यकता है व्याख्या की। एस. आर.
 बोम्मई के मामले में इस अदालत को एक अवसर मिला था

इस प्रश्न पर विचार करें। के अधिकार से निपटना भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत
 राष्ट्रपति और

क्या राष्ट्रपति द्वारा ऐसे अधिकार का प्रयोग किया जाता है बेरियम केमिकल्स लिमिटेड बनाम में
 इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित मापदंडों पर न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी। कंपनी विधि बोर्ड,

ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 295 ने प्रस्तुतिकरण को खारिज कर दिया।

इस न्यायालय द्वारा निर्धारित परीक्षण

"35. बेरियम केमिकल्स लिमिटेड बनाम।
 कंपनी विधि बोर्ड

और वैधता का निर्णय लेने के लिए बाद के निर्णय [2015] 13 एस. सी.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रशासनिक कार्रवाई के लिए कोई आवेदन नहीं हो सकता है

राष्ट्रपति की संतुष्टि का परीक्षण करना

अनुच्छेद 356। यह याद रखना चाहिए कि शक्ति

अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त एक असाधारण है गंभीर आपात स्थितियों में प्रयोग की जाने वाली
 प्रकृति और,

इसलिए, ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है

प्रशासनिक में प्रयोग की जाने वाली शक्ति के बराबर

कानून क्षेत्र और इसलिए, द्वारा परीक्षण नहीं किया जा सकता है
एक ही पैमाना।

के तहत शक्ति का प्रयोग

255.

अनुच्छेद 356 शक्ति का एक संवैधानिक प्रयोग है।

सामान्य व्यक्तिपरक संतुष्टि

वस्तुनिष्ठ आधार पर प्रशासनिक निर्णय लागू किया गया
लिए

न्यायालयों द्वारा प्रशासनिक निर्णयों के

अधीनस्थ अधिकारी या अर्ध-न्यायिक या अधीनस्थ

के निर्णय पर कानून लागू नहीं होता है

अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति।

जहाँ तक अपनाया गया दृष्टिकोण

373.

बेरियम केमिकल्स में इस न्यायालय का संबंध है, यह

एक कानून द्वारा बनाया गया प्राधिकरण। ये सिद्धांत
विस्तार नहीं किया जा सकता है

तब विकसित होने पर इप्सो फैक्टो का

अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक शक्ति का प्रयोग।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह एक उच्च है

वैधानिक या प्रशासनिक द्वारा की गई कार्रवाई का मामला
तरह से, पूरी तरह से।

अधिकारी-और न ही किसी भी

113. इस तरह का परीक्षण केवल बनाए गए निकायों के लिए प्रासंगिक है।

यू. टी. और अधीनस्थ विधान। अनुशासनात्मक निकाय के कामकाज को केवल अनुमोदित सर्वोच्च न्यायालय के
अधिवक्ताओं द्वारा अनुशासित किया जाता है-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [चेलामेश्वर, जे।]

कानून। संविधान में कोई दिशा-निर्देश नहीं दिए गए हैं -

राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का कार्यकरण और न ही

राष्ट्रपति और सीजेआई को पालन करने के लिए दिशानिर्देश व्यक्त करें। यह है।
मामला नहीं है कि पूर्व-संशोधन चयन

हालाँकि किसी का

परिदृश्य ने किसी भी असंबद्ध विवेकाधिकार को प्रदान किया और इसलिए

इसके परिणामस्वरूप कुछ अवांछनीय न्यायिक नियुक्तियाँ हुईं। अगर इसमें
व्यक्तिगत प्राथमिकताएँ अधिक होती हैं

अभ्यास, कभी-कभी

अवांछनीय के परिणामस्वरूप सार्वजनिक हित की चिंताएँ
कारण नहीं है

नियुक्तियाँ, यह संवैधानिक मौन के

इस क्षेत्र में लेकिन नैतिक मानकों में कमियों के कारण

चयन प्रक्रिया में प्रतिभागियों का। इसके बाद

सुधार, दायित्व अपरिवर्तित है। एकमात्र परिवर्तन यह है कि

खिलाड़ियों की संरचना में जिन्हें कार्य सौंपा गया है

और कार्य करने के तरीके को एक दृष्टिकोण के साथ बदल दिया जाता है
पारदर्शिता प्राप्त करना

चयन में अधिक

प्रक्रिया। यह तर्क देना कि संशोधन विनाशकारी है

बुनियादी संरचना क्योंकि यह कोई दिशानिर्देश निर्धारित नहीं करती है

यह मानने के समान है कि संविधान की रचना के रूप में

मूल रूप से अधिनियमित दोषपूर्ण है! 114. अगली प्रस्तुति जिस पर विचार किया जाना आवश्यक है
वह अधिनियम की धारा 6 (6) है जो यह निर्धारित करती है कि यदि कोई दो

एन. जे. ए. सी. के सदस्य सिफारिश से सहमत नहीं हैं
सिफारिश नहीं करेगा

एनजेएसी द्वारा प्रस्तावित, एनजेएसी ऐसी

उम्मीदवार। याचिकाकर्ताओं की राय में, यह एक प्रावधान है

जो एन. जे. ए. सी. के दो सदस्यों को वीटो शक्ति प्रदान करता है

प्रस्तावों को रद्द करें। यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालाँकि प्रावधान है

व्यावहारिक रूप से हानिरहित, इसके परिणामस्वरूप कार्यपालिका को [2015] 13 एस. सी. आर. द्वारा किए
गए प्रस्तावों को अस्वीकार करने के लिए वीटो की शक्ति मिलेगी।

एनजेएसी के तीन न्यायिक सदस्य। ऐसा प्रावधान है -
 संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन। यह आगे है
 तर्क दिया कि हालांकि प्रावधान का हिस्सा नहीं है
 संशोधन, चूंकि संशोधन और अधिनियम हैं
 एक साथ बनाया गया और अधिनियम का पूरक होना
 संशोधन, अधिनियम को एक भाग के रूप में समझा जाना चाहिए
 संशोधन की रूपरेखा और इसलिए, धारा 6 (6)
 जमीन पर गिराया जाना आवश्यक है यह का उल्लंघन है
 संविधान की मूल संरचना।

115. प्रत्यर्थियों ने प्रस्तुत किया कि धारा 6 (6)

अधिनियम केवल पवित्र करने के लिए एक विशेष बहुमत निर्धारित करता है
 एनजेएसी की सिफारिशें। विशेष बहुमत का निर्धारण
 कानून में एक ज्ञात घटना है। स्वयं संविधान
 कुछ मामलों में विशेष बहुमत निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए,
 अनुच्छेद 368 (2) में संशोधन के लिए विशेष बहुमत निर्धारित किया गया है।

संविधान। इसी तरह, अनुच्छेद 124 (4) एक विशेष प्रावधान करता है।
 महाभियोग के लिए बहुमत

न्यायाधीशों के

संवैधानिक न्यायालय। यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ताओं

यह धारणा कि केवल सरकार ही लाभ उठा सकती है

धारा 6 (6) के तहत निर्देश पूरी तरह से आधारहीन है। किसी मामले में ऐसा हो सकता है कि दो न्यायिक
 सदस्य

एन. जे. ए. सी. एन. जे. ए. सी. के प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता है। सीखा है।

महान्यायवादी ने यह भी प्रस्तुत किया कि एक का ऐसा प्रिस्क्रिप्शन

विशेष बहुमत भी द्वितीय न्यायाधीश मामले के तहत बनाए गए शासन का एक हिस्सा है और इसलिए, कुछ
 भी नहीं है

केवल शब्दार्थिक प्रासंगिकता। हम इसे जो भी नाम दें, परिणाम एक ही है। एनजेएसी के दो सदस्य
 ओवरराइड कर सकते हैं।

अन्य चार की राय और सिफारिश को रोकें। आई.

इस तरह के पर्चे के बारे में कुछ भी स्वाभाविक रूप से अवैध न पाएँ।

वर्तमान मामले के उद्देश्य के लिए, मैं अदालत के अधिवक्ताओं-ऑन-रिकॉर्ड का समर्थन भी नहीं करना चाहता।

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [चेलामेश्वर, जे।]

जाँच शुरू करें कि क्या संवैधानिक आकर्षण है

मूल संरचना सिद्धांत के लिए एक ट्रोजन घोड़ा बनाया जाना चाहिए

पूरे विधायी शिविर में प्रवेश करें। अपने हिस्से के लिए, मैं चाहूंगा

उत्तर देने से पहले प्रश्न की अधिक विस्तार से जांच करना।

सवाल है। इस पर इस न्यायालय के परस्पर विरोधी विचार हैं।

प्रस्ताव। 99 मेरी राय में इस तरह की जांच की आवश्यकता नहीं है।

इस मामले में बहुमत के फैसले को देखते हुए कि

सुधार अस्थिर है। कुछ विद्वान सलाहकार

याचिकाकर्ताओं के लिए एस. आर. बोम्मई मामले पर निर्भरता रखी गई
आह्वान के लिए औचित्य।

मूल संरचना के सिद्धांत के

117. केवल प्रस्तुत करने के उत्तर के लिए जांच के दायरे को इंगित करने के लिए लेकिन निर्णायक रूप से
निर्धारित करने के लिए नहीं

याचिकाकर्ताओं, मैं एस. आर. बोम्मई मामले की जांच करता हूँ। सवाल यह है

इस न्यायालय के समक्ष यह था कि क्या राष्ट्रपति की कार्रवाई

अनुच्छेद 356 के तहत शक्तियों का उपयोग करना संवैधानिक था

टिकने योग्य? दूसरे शब्दों में, क्या वह सामग्री जिस पर

राष्ट्रपति ने आह्वान के लिए संवैधानिक रूप से प्रासंगिक कार्य किया

अनुच्छेद 356 के तहत शक्तियाँ। याचिकाकर्ताओं का निवेदन
अनुच्छेद के तहत शक्तियों का प्रयोग

इस न्यायालय के समक्ष यह था कि

356 संविधान की दो विशेषताओं के साथ असंगत था, अर्थात्।

लोकतंत्र और संघवाद, इसलिए, विनाशकारी

अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की कार्यवाही के रूप में बुनियादी संरचना लोकतांत्रिक रूप से चुने गए लोगों का सुपर सत्र हुआ

इसके परिणामस्वरूप

केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारें।

118. इस तर्क को पलटते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि

धर्मनिरपेक्षता भी संविधान की बुनियादी विशेषताओं में से एक है।

विभिन्न राज्य सरकारों की सचेत निष्क्रियता और विफलता जो

कुछ गतिविधियों को रोकने में परिणामी

याचिकाकर्ताओं की राय (इस न्यायालय द्वारा समर्थित)

89 महाराव साहिब श्री भीम सिंहजी बनाम। भारत संघ और अन्य।, (1981) 1 एस. सी. सी. 166, कृष्णा लायर, जे. -

"20. बुनियादी संरचना के उल्लंघन का सवाल तब नहीं उठ सकता जब हम एक सामान्य कानून के अधिकारों की जांच करते हैं जो एक से अलग है

संवैधानिक संशोधन "। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

निर्णय) अंततः के विनाश में परिणाम होगा

संविधान के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने में निश्चित रूप से एक प्रासंगिकता है प्रयोग के लिए विचार

असाधारण शक्तियों के

अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति में। क्योंकि अनुच्छेद 356

राष्ट्रपति को विचारित कार्यवाही का सहारा लेने के लिए बाध्य करता है

इसके तहत केवल तभी जब राष्ट्रपति संतुष्ट हो कि एक स्थिति है

उत्पन्न हुआ जिसमें राज्य सरकार को नहीं चलाया जा सकता है विफलता

संविधान के प्रावधानों के अनुसार।

राज्य सरकार की उन गतिविधियों को रोकने के लिए जो बाध्य हैं

लोगों के बीच सांप्रदायिक सद्भाव को नष्ट करने के लिए

विभिन्न धर्म निश्चित रूप से संविधान के साथ असंगत हैं।

संविधान को बनाए रखने के लिए राज्य का दायित्व जिसकी धर्मनिरपेक्षता एक मूल विशेषता है। एस. आर. बोम्मई मामला कोई प्राधिकरण नहीं है

इस प्रस्ताव के लिए कि किसी विधान की वैधता स्वीकार्य है

मूल संरचना सिद्धांत के आधार पर न्यायिक समीक्षा के लिए।

119. दिनाकरन मामले (ऊपर) में पैदा हुई विफलता और

शांति भूषण मामला (ऊपर) की भागीदारी को उचित ठहराएगा

उन्मूलन की प्रक्रिया में नागरिक समाज के सदस्य

चयन प्रक्रिया से प्रक्रिया में शामिल रोग

रुमा पाल, जे. द्वारा इंगित उपरोक्त दो नहीं हैं

केवल ऐसे मामले जहां प्रणाली विफल रही। यह सार्वजनिक रिकॉर्ड की बात है कि पिछले 20 वर्षों में कॉलेजियम के आगमन के बाद

प्रणाली, कॉलेजिया द्वारा की गई सिफारिशों की संख्या
खारिज कर दिया गया

उच्च न्यायालयों को कॉलेजियम द्वारा

सुप्रीम कोर्ट। ऐसे मामले भी हैं जहाँ कॉलेजियम

इस न्यायालय ने तुरंत अपने कदमों को खारिज कर दिया

उच्च न्यायालय द्वारा की गई किसी विशेष नाम की सिफारिशें

कॉलेजियम उन कारकों के बारे में बहुत सारी अटकलों के लिए गुंजाइश दे रहा है जो कॉलेजियम के साथ वजन रखते होंगे

इतनी जल्दी वोल्टेफेस बनाएँ। ऐसे निर्णय उचित हो सकते हैं।

कुछ मामलों में और अन्य मामलों में नहीं भी हो सकता है। वहाँ कोई नहीं है

इस संबंध में उत्तरदायित्व। रिकॉर्ड बिल्कुल हैं

इस सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं के न्यायाधीशों सहित किसी भी व्यक्ति की पहुंच से परे-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई.

न्यायालय जो मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए भाग्यशाली नहीं हैं

भारत से। इस तरह की स्थिति या तो वृद्धि नहीं करती है

संस्था की विश्वसनीयता या इस देश के लोगों के लिए अच्छा।

120. उपर्युक्त सभी कारणों से, मैं इसे बरकरार रखूंगा।

संशोधन। हालांकि, बहुमत के फैसले को देखते हुए,

मैं संवैधानिकता की जांच करने में कोई उपयोगी उद्देश्य नहीं देखता।

अधिनियम से।

121. केवल एक स्वतंत्र और कुशल न्यायिक प्रणाली

समाज में विश्वास पैदा कर सकते हैं जिसकी वह सेवा करता है। विभिन्न मामलों के समक्ष मामलों की लगातार बढ़ती लंबितता

इस देश के संवैधानिक न्यायालय स्पष्ट रूप से एक नहीं है

दक्षता का प्रमाण पत्र। वह आवृत्ति जिसके साथ अवशिष्ट

अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय की अधिकारिता का अनुरोध किया जाता है

उच्च न्यायालयों द्वारा की गई त्रुटियों में सुधार,

जो तुच्छ हैं और कुछ गहरे और विस्मयकारी हैं।

इस न्यायालय की पीठें केवल यह इंगित करती हैं कि एक व्यापक प्रणाली में सुधार अतिदेय है।
चयन प्रक्रिया

संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीश केवल एक हैं - इस तरह के सुधारों का पहला। उस दिशा में एक प्रयास,

दुर्भाग्य से, इस अदालत की मंजूरी हासिल करने में विफल रहा

एकमात्र जिम्मेदारी और अनन्यता के साथ यह न्यायालय

कानूनी प्रणाली की दक्षता की जवाबदेही। मैं केवल भाग लेता हूँ।

इस मामले में मैकाले के शब्दों को याद करते हुए-“सुधार जिसे आप संरक्षित कर सकते हैं”। केवल भविष्य ही बता सकता है कि मैं

सही ढंग से उन शब्दों को याद दिलाया या नहीं।

आदेश

मदन बी. लोकुर, जे. 1. मुझे जाने का लाभ मिला है

मेरे सम्मानित भाइयों न्यायमूर्ति खेहर, न्यायमूर्ति चेलमेश्वर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ द्वारा तैयार किए गए मसौदा आदेश के माध्यम से।

90 संसदीय सुधारों पर हाउस ऑफ कॉमन्स में 2 मार्च 1831 को थॉमस बैबिंगटन मैकाले का संबोधन [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मेरे विद्वान भाइयों द्वारा व्यक्त किए गए विचार का समर्थन करते हुए न्यायमूर्ति खेहर और न्यायमूर्ति चेलमेश्वर, मैं जोड़ना चाहूंगा।

अलग करने के लिए एक आवेदन से निपटने के प्रक्रियात्मक पहलू पर कुछ शब्द।

2. न्यायमूर्ति खेहर ने अनुच्छेद 17 में उल्लेख किया है -

आदेश का मसौदा इस प्रकार है:

"पुनर्गठित के सदस्य के रूप में बने रहने का निर्णय

बेंच मेरा था, और केवल मेरा।

3. मेरी सम्मानजनक राय में, जब कोई आवेदन किया जाता है

किसी न्यायाधीश को किसी मामले की सुनवाई से अलग करने के लिए, आवेदन

संबंधित न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है न कि पीठ के समक्ष

पूरा। इसलिए, मेरे विद्वान भाई न्यायमूर्ति खेहर हैं।

यह कहना बिल्कुल सही है कि निर्णय पूरी तरह से उसका है, और मैं उनके फैसले का सम्मान करता हूँ।

4. अदालत में अपने दम पर सुनाए गए एक विस्तृत आदेश में

गति वी। राज्य और अन्य 1 का संदर्भ ज्वेल रिज में संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के लिए किया गया था।

कोयला निगम बनाम। स्थानीय संख्या 6167, संयुक्त खदान कर्मचारी

अमेरिका 2 का, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि

भाग लेने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता किसी कारण के निर्णय को समग्र रूप से न्यायालय को ठीक से संबोधित नहीं किया जा सकता है और यह प्रत्येक न्यायाधीश की जिम्मेदारी है कि वह अपने लिए किसी मामले से पीछे हटने का औचित्य निर्धारित करे।

5. इस दृष्टिकोण को न्यायमूर्ति रेहंक्रिस्ट ने स्वीकार किया था

हनराहन बनाम। हैम्पटन 3 निम्नलिखित शब्दों में:

"वादी-इन मामलों में उत्तरदाताओं और उनके वकील ने प्रस्ताव दिया है कि मुझे कार्यवाही से अलग कर दिया जाए।

यह मामला उनके 14-पृष्ठ प्रस्ताव में बताए गए कारणों और इस न्यायालय के क्लर्क के साथ दायर उनके पांच परिशिष्टों के लिए है।

3 अप्रैल, 1980 को। प्रस्ताव का राज्य द्वारा विरोध किया जाता है

1 MANU/DE/9073/2007

2 325 यूएस 897 (1945)

3 3 446 यूएस 1301 (1980)

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

कार्रवाई में प्रतिवादी याचिकाकर्ता। चूंकि आम तौर पर एक संस्था के रूप में न्यायालय इस तरह के प्रस्ताव छोड़ देता है, भले ही

उन्हें व्यक्ति के निर्णय के लिए संबोधित किया जाना चाहिए

न्यायाधीश जिनका वे उल्लेख करते हैं, देखें ज्वेल रिज कोल निगम। वी. खदान कर्मचारी, 325 यू. एस. 897 (1945)

पुनः सुनवाई के लिए याचिका) (जैक्सन, जे., सहमत), मैं करूंगा

प्रस्ताव को व्यक्तिगत रूप से मुझे संबोधित मानते हैं। मैंने प्रस्ताव, परिशिष्ट, प्रतिक्रिया पर विचार किया है।

राज्य प्रतिवादियों में से, 28 यू. एस. सी. 455 (1976 संस्करण। और सप. II), और वर्तमान अमेरिकन बार एसोसिएशन कोड ऑफ ज्यूडिशियल कंडक्ट, और प्रस्ताव तदनुसार है मना कर दिया "।

6. अलग होने के मुद्दे पर थोड़ा ध्यान दिया जा सकता है।

कानूनी बारीकियों से अलग। क्या होगा अगर, पाँच न्यायाधीशों की पीठ में, अलग होने के लिए एक आवेदन दायर किया जाता है

न्यायाधीश ए और आवेदन को सुनने के बाद न्यायाधीश ए ने मामले से अलग होने का फैसला किया लेकिन अन्य चार न्यायाधीश असहमत थे

और यह राय व्यक्त करें कि न्यायाधीश ए के सुनवाई से अलग होने का कोई उचित कारण नहीं है? क्या ए को जज किया जा सकता है

भले ही वह सुनवाई से अलग होने का इच्छुक हो, लेकिन मामले की सुनवाई करने के लिए मजबूर? यह ऐसी कठिन स्थिति से उबरने के लिए है कि अलग होने का आवेदन वास्तव में एक

व्यक्तिगत न्यायाधीश और समग्र रूप से पीठ नहीं।

7. जहाँ तक न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ का विचार है कि आवेदन पर निर्णय लेते समय कारण दिए जाने चाहिए।

अस्वीकार करते हुए, मैं उस निर्णय में शामिल नहीं होना पसंद करूंगा। सबसे पहले, कारण देना या न देना हमारे सामने कोई मुद्दा नहीं था। कि वर्तमान में कारण दिए जा रहे हैं, यह एक अलग मामला है। कुल मिलाकर। दूसरा, कारण बताना कुछ कठिनाइयों से भरा होता है। उदाहरण के लिए, यह संभव है कि किसी दिए गए मामले में, उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश एक मामले से अपने अलग होने के लिए एक आवेदन स्वीकार करते हैं और एक पक्ष इस बात को चुनौती देता है कि इस न्यायालय में आदेश। पक्षकारों को सुनने पर, यह न्यायालय यह निष्कर्ष निकालता है कि विद्वान न्यायाधीश द्वारा दिए गए कारण

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

तुच्छ थे और इसलिए आदेश गलत है और तब है

एक तरफ रख दें। ऐसी स्थिति में, क्या यह न्यायालय परिणामी निर्णय पारित कर सकता है? आदेश जिसमें विद्वान न्यायाधीश को मामले की सुनवाई करने की आवश्यकता होती है, भले ही वह वास्तव में मानता हो कि उसे मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए?

8. किसी मामले की सुनवाई से अलग होने का मुद्दा ऐसा नहीं है

सरल जैसा दिखता है। सामने रखे गए प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हैं और क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे अनुप्रयोग हैं

आवृत्ति प्राप्त करना, यह समय है कि कुछ प्रक्रियात्मक और इस संबंध में ठोस नियम बनाए गए हैं। यदि उचित नियम बनाए जाते हैं, तो, किसी दिए गए मामले में, इससे बचा जा सकता है

न्यायपीठ के अन्य न्यायाधीशों को शर्मिदा करना।

न्याय

मदन बी. लोकुर, जे. 1. इन पर उठे सवाल

विचारणीय हैं: सबसे पहले, क्या संविधान (नब्बे-नौवां)

संशोधन) अधिनियम, 2014 जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मौजूदा प्रक्रिया को प्रतिस्थापित और प्रतिस्थापित करता है।

न्यायालय और उच्च न्यायालय एक मौलिक रूप से अलग प्रक्रिया के साथ स्वतंत्रता में बाधा डालता है और इसका उल्लंघन करता है

न्यायपालिका की

संविधान की मूल संरचना; दूसरा, क्या

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014

संवैधानिक रूप से वैध विधान।

2. मेरी राय में, संविधान (नब्बे-नौवां)

संशोधन) अधिनियम, 2014 (संक्षेप में 99 वां संविधान)

संशोधन अधिनियम) संविधान की मूल संरचना को बदल देता है।

नियुक्ति में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को लागू करके

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और पुनर्लेखन

संविधान का अनुच्छेद 124 (2) और अनुच्छेद 217 (1), इस प्रकार

न्यायपालिका की स्वतंत्रता से गंभीर रूप से समझौता करना।
संशोधन अधिनियम है -

नतीजतन, 99 वां संविधान

असंवैधानिक है। 99 वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद से

असंवैधानिक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियाँ
अधिनियम) जो कि सर्वोच्च न्यायालय-चालू-अभिलेख है।

आयोग अधिनियम, 2014 (संक्षेप में एन. जे. ए. सी.

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

99 वें संविधान संशोधन अधिनियम के बच्चे नहीं कर सकते

स्वतंत्र रूप से कानून की पुस्तकों पर जीवित रहते हैं। अन्यथा, यह

मौलिक को सक्षम करके संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है

सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति में मनमानी

न्यायालय और उच्च न्यायालय।

3. मसौदा निर्णय को पढ़ने का लाभ मिला

न्यायमूर्ति खेहर, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति आदर्श

कुमार गोयल, मैं इन निष्कर्षों से सम्मानपूर्वक सहमत हूँ।

99 वीं की संवैधानिक वैधता के संबंध में आया
 संविधान संशोधन अधिनियम लेकिन उन्हें पूरक बनाना पसंद करते हैं
 अतिरिक्त कारणों से। मैं सम्मानपूर्वक असहमत हूँ
 न्यायमूर्ति चेलमेश्वर का दृष्टिकोण। मेरा मानना है कि सभी प्रस्तुतियाँ
 श्री फली एस. नरीमन के नेतृत्व में विभिन्न विद्वान वकीलों द्वारा बनाया गया
 याचिकाकर्ताओं की ओर से और श्री मुकुल रोहतगी द्वारा
 विद्वान महान्यायवादी ने उत्तरदाताओं की ओर से
 न्यायमूर्ति खेहर द्वारा अपने मसौदे में नोट किया गया और उस पर विचार किया गया
 निर्णय और उनमें से कुछ के संबंध में, मेरे पास कुछ भी नहीं है
 जो पहले ही कहा जा चुका है उसे जोड़ें।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

4. जॉर्ज संतायना, दार्शनिक, निबंधकार, कवि और

ऐसा माना जाता है कि उपन्यासकार ने इस प्रभाव के लिए कुछ कहा है:
 'जो लोग अपने अतीत को याद नहीं रखते हैं, उनकी निंदा की जाती है
 अपनी गलतियों को दोहराएँ। इसे ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक है कि
 नियुक्ति के लिए प्रक्रिया के विकास की सराहना करें
 भारतीय न्यायपालिका में न्यायाधीशों, विभिन्न विकल्पों पर चर्चा की गई
 संविधान (नब्बे-नौवां संशोधन) अधिनियम, 2014 और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014
 द्वारा दिया गया। यह एक अन्य कारण से महत्वपूर्ण है-कुछ गलतियाँ।

संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकार करने से पहले किया गया

भारत के, पुनर्जीवित और अधिनियमित किए गए हैं, भले ही संविधान सभा ने उन पर बहस की
 और उन्हें खारिज कर दिया।

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5. भारत सरकार अधिनियम, 1919 की धारा 101

मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रावधान
 उच्च न्यायालय और धारा 102 ने उनके कार्यकाल के लिए प्रावधान किया। यह
 यह प्रावधान किया गया था कि नियुक्ति उसके द्वारा की जाएगी
 महामहिम और न्यायाधीश महामहिम के कार्यकाल के दौरान पद धारण करेंगे।
 आनंद '। नियुक्ति प्रक्रिया और कार्यकाल के बाद से
 न्यायाधीश क्राउन की खुशी पर निर्भर था, शायद मुद्दा
 न्यायपालिका की स्वतंत्रता का विषय नहीं था भारत में चर्चा। किसी भी मामले में, कुछ भी इंगित
 नहीं किया गया था
 इस संबंध में प्रस्तुतियों के दौरान एक या दूसरे तरीके से
 विद्वान सलाहकार द्वारा।

6. भारत सरकार अधिनियम, 1935 में आंशिक रूप से परिवर्तन किया गया

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया और न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक प्रक्रिया
 शुरू की

उक्त अधिनियम द्वारा गठित संघीय न्यायालय। धारा 200

और 201 संघीय न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित था

अदालत और जबकि क्राउन ने नियुक्तियाँ करना जारी रखा

(जाहिरा तौर पर बिना किसी औपचारिक परामर्श प्रक्रिया के), उनके

कार्यकाल 65 वर्ष की आयु में तय किया गया था। न्यायाधीश को हटाना

केवल दुर्व्यवहार या मन या शरीर की दुर्बलता के आधार पर ही संभव था। वेतन के लिए धारा 201 का
 प्रावधान,

220 और 221 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित न्यायालय और उसके प्रावधान
 कमोबेश समान थे -

संघीय न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति।

7. भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने एक झलक दी।

एक स्वतंत्र न्यायपालिका में यह कुछ बुनियादी प्रदान करता है

वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का आश्वासन। एक बार फिर, हमें कुछ भी विशिष्ट नहीं दिखाया गया था,
 एक या दूसरे तरीके से, जो सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन v के संबंध में
 समकालीन अभ्यास पर प्रकाश डाल सकता है।

यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

नियुक्ति प्रक्रिया या न्यायपालिका की स्वतंत्रता।

तथापि, न्यायाधीशों की नियुक्ति पर सामान्य प्रथा थी,

अस्तित्व में है और यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विज्ञापित किया गया है अल-जेहाद ट्रस्ट बनाम में
पाकिस्तान का। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। 1 यह

अधिनियम लागू किया गया था और निश्चित रूप से 1915/1919 के बाद से जब भारत सरकार
अधिनियम अधिनियमित किया गया था, एक न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश
थी

स्वीकार किया गया, भले ही न्यायाधीश की नियुक्ति एक मामला था

मुकुट की खुशी से। कहा गया था:

"मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिनियम

उच्च न्यायालय में एक कार्यकारी अधिनियम है। कोई शक नहीं।

यह शक्ति कार्यपालिका में निहित है

संविधान के प्रासंगिक अनुच्छेद, लेकिन प्रश्न
यह है कि इस शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाए।

संविधान के प्रावधान का अर्थ लगाते हुए सम्मेलनों को सेवा में लगाया जा सकता है और

शक्ति के प्रयोग को व्यवस्थित और विनियमित करना

संविधान के अनुसार: जबकि इस्लामी न्यायशास्त्र के तहत, एक सम्मेलन जिसे उर्फ कहा जाता है

विभिन्न इस्लामी के आधार पर एक बाध्यकारी बल है

स्रोतों, यह एक सुसंगत अभ्यास रहा है जो

पूर्व के दौरान सम्मेलन का दर्जा प्राप्त कर लिया है

भारत के विभाजन के साथ-साथ विभाजन के बाद के दिन
अवधि कि प्रमुख की सिफारिशें

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

भारत के साथ-साथ पाकिस्तान में भी सर्वोच्च न्यायालय ने

बहुत दुर्लभ मामलों को छोड़कर लगातार स्वीकार किया गया और उन पर कार्रवाई की गई। परामर्श
का अभ्यास

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और भारतीय
संघीय न्यायालय भारतीय के अधीन भी प्राप्त कर रहा था
उच्च न्यायालय अधिनियम [1911] के साथ-साथ
11 पी. एल. डी. 1996 एस. सी. 324 (पाँच न्यायाधीशों की पीठ)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.
भारत सरकार अधिनियम 1915, हालांकि
भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति
क्राउन में निहित खुशी की बात थी। द.
मुख्य न्यायाधीशों की सिफारिशें भी
उन दिनों को निश्चित रूप से स्वीकार किया गया था।

सप्रू समिति
न्यायाधीशों की नियुक्ति का मुद्दा (

8.

स्वतंत्र भारत) सबसे पहले चर्चा के लिए आया (जैसा कि प्रतीत होता है) सप्रू समिति के समक्ष। इसके
द्वारा तैयार एक रिपोर्ट

और उसके अध्याय 5 में न्यायपालिका। प्रासंगिक अनुच्छेद न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित
अनुच्छेद 259 हैं,

261 और 268। 2 समिति की राय थी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सर्वोच्च महत्व है
संविधान का संतोषजनक कार्यकरण और कुछ भी नहीं कर सकता

शक्ति और स्वतंत्रता में कार्यकारी हस्तक्षेप की संभावना की तुलना में किसी प्रांत की भलाई के लिए अधिक
हानिकारक होना या जनता के विश्वास को कम करने के लिए सोचा जाना

प्रांत के सर्वोच्च न्यायाधिकरण का। 'यह स्पष्ट था कि वह चाहता था

उच्च न्यायालय की 'पूर्ण स्वतंत्रता' को सुरक्षित करना और

न्यायाधीशों को दलगत राजनीति या प्रभाव से ऊपर रखना। द.

समिति ने एक सीमित परामर्श प्रणाली का प्रस्ताव रखा

विधायिका को पूरी तरह से छोड़कर न्यायाधीशों की नियुक्ति

और कार्यकारी। समिति ने केवल परामर्श का प्रस्ताव दिया

राज्य के प्रमुख और भारत के मुख्य न्यायाधीश के बीच
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के लिए,
इसके अलावा, इकाई (प्रांत) के प्रमुख और मुख्य न्यायाधीश
उच्च न्यायालय से। रिपोर्ट के प्रासंगिक पैराग्राफ पढ़े गए
इस प्रकार है:

" 259. हमारी अनुशंसा No.13 में हम पहले

सिफारिश करें कि एक सर्वोच्च न्यायालय होगा

2HTTPS://अभिलेख। ओ. आर. जी./स्ट्रीम/सेप्रुकमिटी035520 एम. बी. पी./सेप्रुकमिटी 035520 एम. बी. पी.
डिब्लू। tx.

सर्वोच्च अदालतें-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

प्रत्येक इकाई में संघ और एक उच्च न्यायालय के लिए।

फिर दूसरे खंड में हम अनुशंसा करते हैं कि

इनमें से प्रत्येक न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या

संघ की स्थापना के साथ-साथ वेतन भी उन्हें भुगतान संविधान अधिनियम में तय किया जाएगा।

और दोनों में से कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा सिवाय इसके कि उच्च न्यायालय की
सिफारिश पर,

संबंधित सरकार और उच्चतम न्यायालय और राज्य के प्रमुख की मंजूरी के साथ,

तथापि, बशर्ते कि किसी भी न्यायाधीश का वेतन नहीं होगा

अपने कार्यकाल के दौरान अपने नुकसान के लिए भिन्न होना कार्यालय। उपखंड (3) में हम
अनुशंसा करते हैं:

" (क) भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे -

भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श "।

" (ख) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य के प्रमुख द्वारा की जाएगी।

राज्य के प्रमुख द्वारा नियुक्त
इकाई के प्रमुख के साथ परामर्श,

संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और

भारत के मुख्य न्यायाधीश "।

261. इन्हें बनाने में हमारा मुख्य उद्देश्य

सिफारिशें निरपेक्ष को सुरक्षित करने के लिए हैं

उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता और उन्हें रखने के लिए

दलगत राजनीति या प्रभाव से ऊपर। कुछ के बिना

इस तरह के सुरक्षा उपायों के लिए, यह असंभव नहीं है कि एक प्रांतीय सरकार राजनीतिक दबाव में हो सकती है उच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015] 13 एस. सी

उच्च न्यायालय की शक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है

इसकी अधिकारिता या इसके न्यायाधीशों के वेतन के भीतर। अगर ऐसा है।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप और राज्य के प्रमुख सभी को खारिज कर देंगे

राजनीतिक या पार्टी के अभ्यास की संभावना

प्रभाव पड़ता है। इन शर्तों को लागू करना,

एक सतही दृष्टिकोण पर, के साथ असंगत प्रतीत होता है

प्रांतों की सैद्धांतिक स्वायत्तता, लेकिन, में

हमारी राय, उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता और न्यायपालिका आम तौर पर सर्वोच्च होती है।

के संतोषजनक कार्य के लिए महत्व

संविधान और इससे अधिक हानिकारक कुछ नहीं हो सकता है।

किसी प्रांत की भलाई के लिए या जनता के विश्वास को कम करने के लिए गणना की गई

शक्ति के साथ कार्यकारी हस्तक्षेप और सर्वोच्च न्यायाधिकरण की स्वतंत्रता

प्रांत।

268. अब हम नियुक्ति के तरीके पर आते हैं।

न्यायाधीशों का। मौजूदा कानून के तहत उच्च न्यायालयों और संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति

मुकुट। हमने सिफारिश की है कि प्रमुख
 भारत के न्यायाधीश की नियुक्ति प्रमुख द्वारा की जानी चाहिए।
 राज्य से। इस संबंध में हम उल्लेख करेंगे
 अध्याय VI में 'राज्य के प्रमुख' वाक्यांश की हमारी चर्चा। इसी तरह हमने सिफारिश की है कि
 उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश होंगे -
 परामर्श पर राज्य के प्रमुख द्वारा नियुक्त
 भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ। के मुख्य न्यायाधीश
 एक उच्च न्यायालय की नियुक्ति प्रमुख द्वारा की जाएगी इकाई के प्रमुख के परामर्श से राज्य और
 भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं के अन्य न्यायाधीश-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

उच्च न्यायालय की नियुक्ति प्रमुख द्वारा की जाएगी

आई.

इकाई के प्रमुख के परामर्श से राज्य,

संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और
 भारत के मुख्य न्यायाधीश। हमने जानबूझकर रखा है

न्यायाधीशों सहित इन न्यायाधीशों की नियुक्ति

प्रांतीय उच्च न्यायालय दलगत राजनीति के दायरे से बाहर हैं और हम भी ऐसा ही करते हैं

इसके औचित्य में उपरोक्त टिप्पणियाँ

इसके प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के बावजूद प्रावधान

प्रांतों की सैद्धांतिक स्वायत्तता के साथ "।

9. जैसा कि उल्लेख किया गया है, 'राज्य के प्रमुख' पर चर्चा की गई थी

रिपोर्ट का अध्याय VI और जहाँ तक न्यायपालिका है

संबंधित, राज्य के प्रमुख से अपने दम पर कार्य करने की अपेक्षा की जाती थी ' राज्य प्रमुख के कार्यालय
 के अधिभोग के रूप में और उस पर नहीं

संघीय मंत्रालय की सलाह। विशेष रूप से, के प्रमुख
नियुक्ति के मामले में राज्य को अपने दम पर कार्य करना था।
और न्यायाधीशों को हटाना। रिपोर्ट में यही कहा गया था:

"संघ एक लोकतांत्रिक संघीय राज्य होगा और
राज्य का प्रमुख जो दोनों की जगह लेगा

और एक उपयुक्त स्वदेशी दिया जा सकता है
पदनाम, यदि आवश्यक हो तो इस तरह का प्रयोग करना चाहिए

कुछ बहुत ही असाधारण कार्यों को छोड़कर, जो उन्हें केवल उनके संघीय मंत्रालय की सलाह पर दिए
जाते हैं

विशेष रूप से उल्लिखित मामले

संविधान अधिनियम, जहाँ उसे विवेकाधिकार दिया जाता है

स्वयं या उसकी सलाह के अलावा अन्य सलाह पर कार्य करना।

संघीय मंत्रालय (1) राजनीतिक या राजनीति से बचने के लिए

सांप्रदायिक भ्रष्टाचार, या (2) में पहल करने के लिए

अपवाद के तहत (1) हमारे पास जो सुझाव हैं, वे गिर जाएंगे।
हमारी सिफारिशों के पैराग्राफ 13 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

न्यायालयों और न्यायाधीशों की नियुक्ति और निष्कासन
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय "। 3

उच्चतम न्यायालय की तदर्थ समिति

10. संविधान सभा के गठन के बाद, एक विज्ञापन

उच्चतम न्यायालय में अस्थायी समिति का गठन किया गया था जिसने संविधान को 21 मई, 1947 की अपनी
रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

सभा। रिपोर्ट का अनुच्छेद 14 प्रासंगिक है -

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का मुद्दा। यह.

सैद्धांतिक रूप से, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए योग्यता को स्वीकार किया गया, जैसा
कि सरकार में उल्लेख किया गया है।

भारत अधिनियम, 1935 का लेकिन इसे 'शक्ति छोड़ना' अनुचित पाया
 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को निरंकुश नियुक्त करने का
 संघ के अध्यक्ष का विवेकाधिकार। 'इसने दो बनाए
 नियुक्ति प्रक्रिया में सुझाव, जिनमें से दोनों
 राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश के बीच आवश्यक परामर्श और 11 (ग्यारह) के पैनल की राय
 अन्य बातों के साथ-साथ कुछ मुख्य न्यायाधीशों वाले व्यक्ति
 उच्च न्यायालय, केंद्रीय के दोनों सदनों के कुछ सदस्य
 विधानमंडल और संघ के कुछ विधि अधिकारी। यह प्रस्ताव दिया गया था कि कार्यपालिका को नियुक्ति
 प्रक्रिया से बाहर रखा जाए। द.

उक्त अनुच्छेद इस प्रकार है:

"14. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएँ
 न्यायालय को 1935 के अधिनियम के समान शर्तों पर निर्धारित किया जा सकता है।
 संघीय न्यायालय, में पैदा होने की संभावना
 ध्यान दें (जैसा कि 1935 के अधिनियम में) कि न्यायाधीश
 उन राज्यों से भी उच्च न्यायालय जो इसमें शामिल हो सकते हैं
 संघ को एक सीट पर कब्जा करने के लिए उपयुक्त पाया जा सकता है
 सुप्रीम कोर्ट। हमें नहीं लगता कि यह होगा
 न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति छोड़ने के लिए समीचीन
 सुप्रीम कोर्ट के निरंकुश विवेक के लिए

3 पैराग्राफ 288 शीर्ष अदालत के वकील-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. /मदन बी. लोकर, जे./

निम्नलिखित में से कोई भी विधि अपनाई जा सकती है।
 एक तरीका यह है कि राष्ट्रपति को

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श

न्यायालय (अब तक, कनिष्ठ न्यायाधीशों की नियुक्ति के रूप में)

संबंधित है) एक व्यक्ति को नामित करें जिसे वह

सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने के लिए उपयुक्त मानता है

और नामांकन की पुष्टि एक द्वारा की जानी चाहिए

11 के पैनल में से कम से कम 7 का बहुमत

उच्च न्यायालयों के कुछ मुख्य न्यायाधीशों में से

घटक इकाइयाँ, दोनों के कुछ सदस्य

केंद्रीय विधानमंडल के सदन और कुछ

संघ के विधि अधिकारी। दूसरी विधि यह है कि

11 सदस्यीय पैनल को तीन नामों की सिफारिश करनी चाहिए।

जिसमें से राष्ट्रपति, के परामर्श से

मुख्य न्यायाधीश, के लिए एक न्यायाधीश का चयन कर सकते हैं

नियुक्ति। एक ही प्रक्रिया होनी चाहिए

मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए

बेशक इसके अलावा कि इस मामले में मुख्य न्यायाधीश के साथ कोई परामर्श नहीं होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि

पैनल स्वतंत्र [और] कमांड दोनों होगा और पैनल को एक तदर्थ निकाय नहीं होना चाहिए

लेकिन उन्हें वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। 4

11. स्पष्ट रूप से दोनों के बीच मतभेद था।

समूह समिति और तदर्थ समिति

न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए परामर्श प्रक्रिया। द समूह समिति ने महसूस किया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए

राज्य का प्रमुख अपने दम पर कार्य कर रहा है जबकि तदर्थ समिति ने नियुक्ति प्रक्रिया को मंजूरी नहीं दी है

'राष्ट्रपति के निरंकुश विवेक' पर छोड़ दिया लेकिन सुझाव दिया

यह एक पैनल को शामिल करते हुए व्यापक-आधारित होना चाहिए।

12. हालाँकि, दोनों की रिपोर्ट से क्या स्पष्ट है

4 एचटीटीपी: // 164.100.47.132/एल. एस. एस. न्यू/घटक/वॉल्यूम 4 पी6।

एचटीएमएल [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समूह समिति और तदर्थ समिति की रिपोर्ट

यह है कि कार्यपालिका को इस प्रक्रिया में बिल्कुल भी शामिल नहीं होना था न्यायाधीशों की नियुक्ति। इसका काफी महत्व है। 5

संघ के संविधान और मसौदे पर ज्ञापन

खंड

13. 30 मई, 1947 को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बी. एन. राउ ने एक ज्ञापन सौंपा। संघ के संविधान और मसौदा खंडों पर। द.

अध्याय VI (संघ न्यायपालिका) में प्रदत्त ज्ञापन

कि तदर्थ समिति द्वारा अनुशंसित शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के साथ एक सर्वोच्च न्यायालय होगा

संघ न्यायपालिका। 16 संघ संविधान के मसौदा खंडों में

ज्ञापन में जोड़ा गया, यह प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक न्यायाधीश

उच्चतम न्यायालय के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा परिषद के कम से कम दो तिहाई सदस्यों के अनुमोदन से की जाएगी।

राज्य का। 'इस संबंध में, भारत के विधि आयोग ने नोट किया है

इसकी 80 वीं रिपोर्ट इस प्रकार है:

"संवैधानिक सलाहकार ने अपने ज्ञापन में

दिनांक 30 मई, 1947 ने सुझाव दिया कि

न्यायाधीशों की नियुक्ति द्वारा की जानी चाहिए

कम से कम दो-तिहाई की मंजूरी के साथ राष्ट्रपति

राज्य परिषद। राज्य परिषद,

उनके अनुसार, प्रकृति में एक शरीर होना था

राष्ट्रपति को कुछ मामलों पर सलाह देने के लिए एक प्रिवी काउंसिल जिस पर निर्णय लेने की आवश्यकता थी

स्वतंत्र गैर-पार्टी लाइनें। राज्य परिषद

भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल करना था

सदस्य और इसकी संरचना इस तरह से होनी थी -

पार्टी के पूर्वाग्रह से स्वतंत्रता प्राप्त करना। ऐसी परिषद

5 सामान्य व्यक्तियों को भी परामर्श प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया था। 6 बी. शिव राव: 'द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन 'सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स, वॉल्यूम II पेज 486 7 बी. शिव राव: 'द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन 'सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स, वॉल्यूम II पेज 519 सुप्रीम कोर्टवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन v.

यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

राज्य का, यह संविधान द्वारा सुझाया गया था

सलाहकार, के लिए एक संतोषजनक विकल्प होगा

विशेष समिति द्वारा अनुशंसित पैनल।

संघ संविधान समिति ने स्वीकार नहीं किया

स्थापना के लिए संवैधानिक सलाहकार का प्रस्ताव

राज्य परिषद का गठन, और सुझाव दिया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया होनी चाहिए

कि राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना चाहिए

और उच्चतम न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीश जैसे

आवश्यकता हो सकती है। " 8

14. ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय तक, की स्वतंत्रता

न्यायपालिका को हल्के में लिया गया था, एकमात्र सवाल यह था कि

यह राष्ट्रपति की अनन्य जिम्मेदारी होनी चाहिए या यह एक पैनल या राज्य परिषद को शामिल करते हुए व्यापक आधार पर होनी चाहिए। किसी भी मामले में घटना, नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यपालक का बहिष्कार

ऐसा प्रतीत होता है कि इसे स्वीकार कर लिया गया है।

संघ संविधान समिति

15. संघ संविधान समिति जिसने प्रस्तुत किया

4 जुलाई, 1947 को संविधान सभा को एक रिपोर्ट

परिषद की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया लिए राज्य। नतीजतन, एक वैकल्पिक प्रक्रिया के लिए

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का सुझाव दिया गया था,

अर्थात्, के बीच परामर्श द्वारा नियुक्ति के लिए

राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और

उच्चतम न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो आवश्यक हों। दूसरे शब्दों में, सीमित

भारत) को हालांकि संशोधनों के साथ स्वीकार किया गया था। चैप्टर IV रिपोर्ट का अनुच्छेद 18 स्वयं से संबंधित है -

8 पैराग्राफ 4.4 और 4.5 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015] 13 एस. सी

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और यह इस प्रकार है:

" 18. सुप्रीम कोर्ट। - वहाँ एक सर्वोच्च होगा

संविधान, शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के साथ न्यायालय

तदर्थ समिति द्वारा अनुशंसित

संघ न्यायपालिका, सिवाय इसके कि सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश

न्यायालय की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।

अदालतें जो इस उद्देश्य के लिए आवश्यक हों।

[नोट-सुप्रीम पर तदर्थ समिति

न्यायालय ने कहा है कि यह समीचीन नहीं होगा कि

न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति छोड़ दें

संघ के अध्यक्ष के निरंकुश विवेक के लिए सर्वोच्च न्यायालय। उन्होंने सुझाव दिया है

दो विकल्प, जिनमें से दोनों में सेटिंग शामिल है

एक विकल्प के अनुसार, राष्ट्रपति, परामर्श, नामित करना है

मुख्य न्यायाधीश के साथ

कनिष्ठ न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए एक व्यक्ति और नामांकन की पुष्टि कम से कम सात लोगों द्वारा की जानी चाहिए।

समिति के सदस्य। दूसरे के अनुसार

वैकल्पिक रूप से, पैनल को तीन की सिफारिश करनी चाहिए

नाम, जिनमें से राष्ट्रपति, परामर्श से

मुख्य न्यायाधीश के साथ, के लिए एक का चयन करना है

नियुक्ति। उपरोक्त में सुझाए गए प्रावधान

खंड संघ संविधान के निर्णय का अनुसरण करता है

समिति।/ " 9 9

एक बार फिर, कार्यपालिका की इसमें कोई भूमिका नहीं थी

न्यायाधीशों की नियुक्ति, विशेष रूप से उच्चतम न्यायालय की

बी. शिव राव: 'भारत के संविधान का निर्माण 'दस्तावेज़ का चयन करें'

खण्ड II पृष्ठ 583 सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

प्रांतीय संविधान समिति

16. उच्च न्यायालयों के संबंध में, 27 जून की एक रिपोर्ट,

1947 द्वारा संविधान सभा को प्रस्तुत किया गया था

प्रांतीय संविधान समिति। उससे संबंधित भाग-II

प्रांतीय न्यायपालिका और इसके लिए की गई सिफारिशें

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति को शामिल किया गया

भारत सरकार अधिनियम, 1935 के प्रावधान और

संघ संविधान समिति द्वारा की गई सिफारिशें।

इन्हें इस प्रकार पढ़ा जाता है:

"प्रांतीय न्यायपालिका

1. भारत सरकार अधिनियम, 1935 के प्रावधान,

उच्च न्यायालय से संबंधित उत्परिवर्तन को अपनाया जाना चाहिए
 उत्परिवर्तन; लेकिन न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाना चाहिए
 संघ के अध्यक्ष ने प्रमुख के परामर्श से
 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, के राज्यपाल
 प्रांत और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
 प्रांत (उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर)
 स्वयं को नियुक्त किया जाना है)।

2. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसा प्राप्त होगा
 द्वारा निर्धारित किए जाने वाले परिलब्धि और भत्ते
 प्रांतीय विधानमंडल का अधिनियम और तब तक जैसे कि
 अनुसूची में निर्धारित हैं।
 3. न्यायाधीशों के परिलब्धि और भत्ते

उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जाएगा। 10
 उपरोक्त चर्चा इंगित करती है कि कार्यपालिका थी
 न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया से बाहर रखा जाए
 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। यह इस बात से स्पष्ट है कि
 के विचार: (1) संप्र समिति; (2) तदर्थ समिति
 उच्चतम न्यायालय पर; (3) संघ संविधान समिति,

10 बी. शिव राव: 'द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन'-सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स, वॉल्यूम II पेज 662 सुप्रीम
 कोर्ट रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

और (4) प्रांतीय संविधान समिति। यह होगा
 कुछ असर तब पड़ता है जब राष्ट्रीय न्यायपालिका की संरचना
 नियुक्ति आयोग की जांच की जाती है।

17. न्यायपालिका से संबंधित इस पृष्ठभूमि में, पहला
 संविधान का मसौदा प्रारूपण के समक्ष रखा गया था

अक्टूबर, 1947 में समिति। इसके बाद एक और
(संशोधित) संविधान के अध्यक्ष को प्रस्तुत मसौदा
21 फरवरी, 1948 को विधानसभा। कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी
नियुक्ति के लिए इन दोनों मसौदों के बीच परिवर्तन संघीय न्यायपालिका (या उच्च न्यायालयों) के
लिए प्रक्रिया
प्रांतों/राज्यों) का संबंध है। लेकिन, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मसौदा समिति ने इस विचार को
दरकिनार नहीं किया

ऊपर वर्णित समितियों में से कोई भी, यानी, रखने के लिए
न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया से बाहर कार्यपालक।

मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन

18. संविधान के मसौदे को व्यापक प्रचार दिया गया

इच्छुक व्यक्तियों को इसके माध्यम से अपने विचार व्यक्त करने में सक्षम बनाना टिप्पणियाँ और
सुझाव। द्वारा व्यक्त किए गए विचार

मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन (संघीय के मुख्य न्यायाधीश)

न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश), अल्पसंख्यक उप-समिति और मौलिक
मामलों की सलाहकार समिति

अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं।

क्योंकि वे कार्यपालक और कार्यपालक के बीच परस्पर क्रिया की व्याख्या करते हैं।

न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में न्यायपालिका।

19. ये विचार यह भी स्पष्ट करते हैं कि लगभग

दिन की भाषा, राजनीतिक कार्यकारी) की उत्पत्ति है जिस समस्या से हम आज भी जूझ रहे हैं।

20. मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन 26 तारीख को हुआ था

और 27 मार्च, 1948 को सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

न्यायपालिका से संबंधित संविधान का मसौदा। संघीय न्यायालय और प्रमुख के विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक जापन

संघ के सभी प्रांतीय उच्च न्यायालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले न्यायाधीश भारत का प्रस्ताव सम्मेलन द्वारा तैयार और प्रस्तुत किया गया था। यह

इसे समझने के लिए जापन का बहुत महत्व है

प्रचलित नियुक्ति प्रक्रिया।

21. बहुत संक्षेप में, जिसे वर्णित किया जा सकता है

‘जापन की प्रस्तावना में कुछ मुख्य बिंदु थे -

मान लिया और देखा। यह माना जाता था कि स्वतंत्रता

और न्यायपालिका की अखंडता का ‘सर्वोच्च महत्व’ नहीं है केवल न्यायाधीशों के लिए, लेकिन अदालत से आश्रय चाहने वाले नागरिकों के लिए

उच्चाधिकारियों और सत्ता के अवैध प्रयोग के खिलाफ कानून

कार्यपालक द्वारा। यह देखा गया कि एक प्रवृत्ति है

न्यायपालिका की शक्तियों, अधिकारों और अधिकार को कम करना। अगर इसे जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो यह ‘सबसे दुर्भाग्यपूर्ण’ होगा।

इसलिए, इस प्रवृत्ति का मुकाबला करने की आवश्यकता थी जो

हाथों में अधिक शक्ति रखे जाने के साथ बढ़ने की संभावना थी

राजनीतिक दलों से। कहा गया था:

“हम मान चुके हैं कि यह सभी हाथों से माना जाता है कि सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अखंडता सबसे अधिक है।

न केवल न्यायाधीशों के लिए बल्कि न्यायाधीशों के लिए भी महत्व और हित बड़े पैमाने पर नागरिक जिन्हें निवारण की मांग करनी पड़ सकती है

किसी भी अवैध कार्य के खिलाफ कानूनी अदालतों में अंतिम उपाय या

कार्यपालिका द्वारा शक्ति का उच्च प्रयोग। आभार।

द्वारा स्थापित न्याय प्रशासन की प्रणाली के लिए

इस देश में अंग्रेज, अब तक न्यायपालिका,

की रक्षा में मुख्य, निभाई गई और स्वतंत्र भूमिका

अतिक्रमण के खिलाफ व्यक्तिगत नागरिक के अधिकार और कार्यकारी शक्ति द्वारा आक्रमण। दुर्भाग्य से,

एक प्रवृत्ति, हाल ही में, विचलित करने के लिए ध्यान देने योग्य रही है

11 ज्ञापन का पाठ बी. शिव राव में उपलब्ध है: द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन 'सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स, वॉल्यूम IV पेज 193 [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायपालिका की स्थिति और गरिमा और उनकी शक्तियों को कम करने के लिए, अधिकार एक ऐसा प्राधिकरण है जिसे यदि अनियंत्रित किया जाता है तो

सबसे दुर्भाग्यपूर्ण। जबकि हम मानते हैं कि मसौदा

संविधान ने कुछ मामलों में कार्यकारी हस्तक्षेप के खिलाफ मौजूदा सुरक्षा उपायों को उदार बनाने का प्रस्ताव किया है और

अपनी वर्तमान शक्तियों को बढ़ाने के लिए, यह महसूस किया जाता है कि आगे

उसी दिशा में प्रावधान किया जाना चाहिए
प्रभावी रूप से उपरोक्त प्रवृत्ति का मुकाबला करने के लिए जो अधिक शक्ति के रूप में अधिक स्पष्ट होने के लिए बाध्य है

राजनीतिक दलों के हाथों में जाता है जो वर्षों में सरकारी तंत्र को नियंत्रित और हावी करेंगे

आने के लिए। निम्नलिखित प्रस्तावों को बनाने में और

सुझाव, एक स्वतंत्र, अविनाशी के निडर कामकाज को सुरक्षित करने का सर्वोपरि महत्व और

कुशल न्यायपालिका को लगातार ध्यान में रखा गया है।

ज्ञापन में विशेष रूप से (दुख की बात) बताया गया कि

15 अगस्त, 1947 के बाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति

अदालतों को, योग्यता के आधार पर, अभ्यास को देखते हुए हमेशा आश्वस्त नहीं किया जाता था।

इसके बाद (कुछ राज्यों द्वारा)। इसके अलावा, द्वारा की गई सिफारिशें

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हमेशा नहीं भेजा जाता था

केंद्र सरकार, जिसका अर्थ है कि कुछ अन्य

सिफारिशें भेजी गईं। इस संबंध में कहा गया था:

"सम्मेलन में हुई चर्चाओं से पता चला कि
15 अगस्त 1947 के बाद अपनाई गई प्रक्रिया में

अभ्यास हमेशा यह सुनिश्चित करता है कि नियुक्ति विशुद्ध रूप से की जा रही है

यह सिद्धांत रूप में आसानी से स्वीकार किया जाता है कि इस तरह के विचारों को नियुक्ति को प्रभावित नहीं करना चाहिए, प्रक्रिया को काम करने में हमेशा ध्यान में नहीं रखा जाता है

अभ्यास करें। मुख्य न्यायाधीश अपनी सिफारिश प्रधानमंत्री को भेजते हैं जो अपने गृह मंत्री से परामर्श करते हैं। द.

इसके बाद प्रधानमंत्री की सिफारिश को सर्वोच्च न्यायालयों-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन v. को भेजा जाता है।

यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

केंद्र में गृह मंत्रालय बिना भेजे भी

इसके साथ मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश,

निर्धारित प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से समझा जा रहा है

ऐसा करना प्रधानमंत्री के लिए अनिवार्य नहीं है "।

22. नतीजतन, बनाने के लिए एक संशोधित प्रक्रिया

सिफारिशें सर्वसम्मति से की गईं

सम्मेलन जो यह सुनिश्चित करेगा कि

मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पास पहुँचता है और यह कि

मुख्य न्यायाधीश की सहमति से नियुक्ति की जाए किसी भी राजनीतिक दबाव से बचने के लिए। कहा गया था:

"मुख्य न्यायाधीश को अपनी सिफारिश भेजनी चाहिए।

उस ओर से सीधे राष्ट्रपति को। सलाह मशविरा करने के बाद

राज्यपाल राष्ट्रपति को नियुक्ति करनी चाहिए

भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से। यह

प्रक्रिया मुख्य न्यायाधीश की आवश्यकता को समाप्त कर देगी

उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री और उनके गृह मंत्री के साथ इस मामले पर चर्चा की और उन्हें "उचित" ठहराया

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश हमेशा नियुक्ति प्राधिकारी के सामने रखा जाता है,

अर्थात् राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश की "सहमति" प्राप्त करने की आवश्यकता प्रदान करेगी

राजनीतिक और पार्टी के दबाव के खिलाफ एक सुरक्षा

इस मामले में उच्चतम स्तर को उठाया जा रहा है "।

23. महत्वपूर्ण रूप से, ज्ञापन मौन और निहित रूप से

स्वीकार किया कि के लिए एक सिफारिश के अलावा से उत्पन्न उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सिफारिशों की जा रही थीं राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा या उसके कहने पर किया गया। क्या

ऐसी प्रक्रिया सही या गलत थी, इस पर विचार नहीं किया गया था लेकिन यह

यह सुझाव दिया गया था कि ऐसी सिफारिश की स्थिति में

किया जा रहा है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति नियुक्ति से पहले प्राप्त किया जाना चाहिए।

[2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित संविधान न्यायालय को निम्नानुसार पढ़ना चाहिए:

"उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति

राष्ट्रपति के हाथ के नीचे एक वारंट और उस पर मुहर

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश

राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद और

भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति "।

ज्ञापन में स्वीकार किया गया कि ए

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए सिफारिश

न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा भी बनाया जा सकता है (एक व्यक्ति में)। क्षमता)। (राष्ट्रपति द्वारा) इस तरह के प्रस्ताव की स्थिति में,

भारत के मुख्य न्यायाधीश के नहीं होने की कोई संभावना नहीं थी
इसे स्वीकार करना और इसलिए, प्रमुख की सहमति
भारत के न्याय को इसमें शामिल करने की आवश्यकता नहीं थी
संविधान। इसलिए, यह नोट किया गया था:

"हम इसमें कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

मुख्य न्यायाधीश की संभावना के लिए संविधान

भारत द्वारा प्रस्तावित नियुक्ति में सहमति देने से इनकार

राष्ट्रपति। दोनों सर्वोच्च स्तर के अधिकारी हैं।

जिम्मेदारी और अब तक इस तरह के इनकार का कोई मामला सामने नहीं आया है

हालाँकि अब एक परंपरा मौजूद है कि ऐसी नियुक्तियाँ

मामला प्रमुख को भेजने के बाद किया जाना चाहिए
भारत का न्याय और उनकी सहमति प्राप्त करना। यदि प्रति

शायद ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न हो सकती थी

राष्ट्रपति द्वारा एक अलग बनाते हुए पाठ्यक्रम से मुलाकात की जाए

प्रस्ताव, और कोई स्पष्ट प्रावधान की आवश्यकता नहीं है, ऐसा लगता है

हमें, उस ओर से बनाया जाए।

\$

पूर्वगामी में उत्परिवर्तन उत्परिवर्तन लागू होता है

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, और

अनुच्छेद 103 (2) को भी उपयुक्त रूप से संशोधित किया जा सकता है।

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकर, जे.]

24. इस ज्ञापन का महत्व इस प्रकार नहीं हो सकता -

इस पर अधिक जोर दिया जाता है और इसे संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है: (1) द.

न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अखंडता का सर्वोच्च महत्व था। (2) कार्यपालिका में एक प्रवृत्ति विकसित हुई थी कि

न्यायपालिका की शक्ति और अधिकार को कम करें। (3) यह था।

उल्लेख किया कि एक न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए सिफारिशें न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से उत्पन्न होता है।

एक उच्च न्यायालय उच्च

कभी-कभी, ऐसी सिफारिशों को दबा दिया जाता है

प्रांतीय स्तर पर कार्यपालिका। यह प्रस्तावित किया गया था कि सिफारिशें होनी चाहिए

मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई

प्रक्रिया के लिए सीधे राष्ट्रपति को भेजा जाता है

कि प्रांतीय स्तर पर राजनीतिक कार्यपालिका इसे दबा नहीं सकती। (4) यह माना गया कि राजनीतिक कार्यपालिका

प्रांतीय स्तर पर भी सिफारिशें की जाती हैं (हालांकि को, बिना

हमेशा योग्यता पर नहीं) सीधे केंद्र सरकार

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का ज्ञान। इस तरह

सिफारिशों को केवल स्वीकार किया जाना चाहिए होना चाहिए

भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति, और यह

संविधान के प्रारूप में ध्यान रखा गया। (5) यह माना गया

कि एक न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए एक सिफारिश

उच्च न्यायालय (या सर्वोच्च न्यायालय) द्वारा बनाया जा सकता है

राष्ट्रपति (व्यक्तिगत रूप से-दोनों सर्वोच्च अधिकारी हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति की आवश्यकता थी किया गया है। हालांकि, यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया

इस संबंध में संविधान के मसौदे में

सिफारिश, राष्ट्रपति द्वारा स्थिति को पूरा किया जा सकता है

एक अलग प्रस्ताव बनाना। ऐसा इसलिए है क्योंकि, यह नोट किया गया था,

कि 'अब एक परंपरा मौजूद है कि ऐसी नियुक्तियाँ होनी चाहिए

मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश को भेजने के बाद किया जाए

और उसकी सहमति प्राप्त करना। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

प्रारूप के अनुच्छेद 61 और अनुच्छेद 62 में संशोधन

संविधान

25. अल्पसंख्यक उप-समिति और सलाहकार

मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय समिति

संविधान के मसौदे के अनुच्छेद 61 और अनुच्छेद 62 (अन्य क्षेत्रों के साथ) को अपवर्जित किया गया और उन पर विचार किया गया। लेख

61 और संविधान के प्रारूप का अनुच्छेद 62 परिषद से संबंधित है। राष्ट्रपति और अन्य लोगों की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रियों का गठन

मंत्रियों के बारे में प्रावधान। इस संबंध में शिव राव ने उल्लेख किया है

उनके उत्कृष्ट प्रयास 'द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन-ए स्टडी' में इस प्रकार है:

"अल्पसंख्यकों में काफी चर्चा हुई
उप-समिति और सलाहकार समिति में

मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय और बहिष्कृत

अल्पसंख्यकों को शामिल करने की आवश्यकता वाले क्षेत्र

संघ और राज्य मंत्रिमंडल में प्रतिनिधि। वे.

माना जाता है कि यह पर्याप्त होगा यदि, भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रस्तुत उदाहरण का पालन करते हुए

1935, निर्देश का एक उपकरण तैयार किया गया था,

संविधान की अनुसूची के रूप में शामिल, आदेश देते हुए

राज्यपालों और राष्ट्रपति को जहां तक संभव हो
इनमें अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्य शामिल हैं।

मंत्रालय। हालांकि, फरवरी 1948 के संविधान के मसौदे में,

इस उद्देश्य के लिए निर्देश का एक उपकरण तैयार किया गया था
केवल राज्यपालों के लिए, लेकिन राष्ट्रपति के लिए नहीं। मुमकिन है।

इस चूक को सुधारने के लिए, मसौदा समिति
संबंधित लेखों पर आगे विचार करने का निर्णय लिया गया

मंत्रिपरिषद के लिए, कि एक उपकरण

राष्ट्रपति के लिए भी निर्देश आवश्यक होंगे "

26. जाहिरा तौर पर, इसके अनुसार, मसौदा समिति

अक्टूबर 1948 में अनुच्छेद 62 में संशोधन का नोटिस दिया।

निम्नलिखित खंड जोड़ने का प्रस्ताव:

12 पृष्ठ 373-374 शीर्ष अदालतें-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

"अपने मंत्रियों के चयन और उनके अभ्यास में

आम तौर पर निर्धारित निर्देशों द्वारा निर्देशित किया जाए
किसी भी चीज़ की वैधता

अनुसूची III-ए, लेकिन द्वारा की गई

राष्ट्रपति को जमीन पर प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा।

कि यह इस तरह के अनुसार के अलावा अन्यथा किया गया था

निर्देश "।

27. अनुसूची III-ए के साधन को शामिल किया गया

राष्ट्रपति के लिए कार्रवाई और यह महत्वपूर्ण है और यह पढ़ता है
अनुमति देता है:

नई अनुसूची III-ए

[अनुच्छेद 62 (5 ए)]

राष्ट्रपति को निर्देश

1. इन निर्देशों में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो

आवश्यक है, "राष्ट्रपति" शब्द में प्रत्येक व्यक्ति शामिल होगा

उस समय के लिए जो कार्यों, के, या अभिनय का निर्वहन कर रहा है

राष्ट्रपति के रूप में, इसके प्रावधानों के अनुसार

संविधान।

2.

XXX

3.

XXX

(1) राष्ट्रपति इसके लिए नियम बनाएगा -

4. एक सलाहकार बोर्ड का गठन जिसमें कम नहीं
संसद के सदनों के पंद्रह से अधिक सदस्य होंगे
प्रणाली के अनुसार दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित
एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सलाह देने के उद्देश्य से
कुछ नियुक्तियाँ करने के मामले में राष्ट्रपति
इस संविधान के तहत और सभी आवश्यक कदम उठाएंगे।
जितनी जल्दी हो सके ऐसे बोर्ड के उचित गठन के लिए
इस संविधान के प्रारंभ के बाद हो।

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(2) ऐसे नियमों में यह प्रावधान होगा कि नेता संसद के किसी भी सदन में विपक्ष, यदि कोई हो,
यदि -

वह सलाहकार मंडल के लिए नहीं चुना जाता है, इसके लिए नामित किया जाता है
अध्यक्ष द्वारा बोर्ड।

(3) इस तरह के नियम पद की शर्तों को भी परिभाषित करेंगे

((घ) भारत का महालेखा परीक्षक; (ई) संघ के अध्यक्ष या संघ के किसी अन्य सदस्य
सेवा आयोग;

(च) आयोग का कोई भी सदस्य अधीक्षण करने के लिए,

और संसद के सभी चुनावों और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनावों को नियंत्रित करता है,

राष्ट्रपति सलाहकार मंडल से परामर्श करेंगे। पैराग्राफ 4 के तहत गठित।

(2) राष्ट्रपति सलाहकार मंडल से भी परामर्श करेंगे।

इस प्रकार के आधार पर नियुक्ति करने में गठित

इस संविधान द्वारा उसे किसी अन्य को प्रदत्त शक्तियाँ

भारत सरकार या सरकार के अधीन कार्यालय
किसी अन्य राज्य का, यदि

किसी राज्य के राज्यपाल के कार्यालय के अलावा

संसद दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्तावों द्वारा

राष्ट्रपति को सिफारिश करें कि सलाहकार मंडल

ऐसे कार्यालय में नियुक्ति करते समय परामर्श लिया जाए।

6. (1) सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं के न्यायाधीशों की नियुक्ति में-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

न्यायालय और उच्च न्यायालयों के राष्ट्रपति इससे पहले

सलाहकार मंडल की सलाह लेने के बाद

निम्नलिखित प्रक्रिया:

(क) भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में,

वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करेगा और

के क्षेत्र के भीतर उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश कुछ समय के लिए निर्दिष्ट राज्यों को छोड़कर
भारत

(ख) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश के
अलावा अन्य न्यायालय, वह परामर्श करेगा

भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी

के लिए राज्यों को छोड़कर भारत के क्षेत्र के भीतर न्यायालय

पहली अनुसूची के भाग III में निर्दिष्ट किया जा रहा समय।

(ग) मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में

उच्च न्यायालय, वह राज्य के राज्यपाल से परामर्श करेगा

जिसे उच्च न्यायालय का प्रमुख स्थान है, और मुख्य न्यायाधीश

भारत का न्याया।

(घ) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में

मुख्य न्यायाधीश के अलावा, वह राज्यपाल से परामर्श करेगा।
प्रमुख स्थान है,

जिस राज्य में उच्च न्यायालय का

भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश
उच्च न्यायालय।

(2) राष्ट्रपति निम्नलिखित सिफारिशें करेगा -

उप-अनुच्छेद (1) के तहत उनके द्वारा परामर्श किए गए अधिकारी

प्राप्त करने के समय सलाहकार मंडल के समक्ष

किसी भी नियुक्ति के संबंध में उस बोर्ड की सलाह

उस उप-अनुच्छेद में संदर्भित।

7.XXX

8.XXX "13

ई. भारत के संविधान की रचना-दस्तावेजों का चयन करें, खंड-IV, पृष्ठ [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

28. यह महत्वपूर्ण है कि निर्देश का साधन भी

जहाँ तक न्यायाधीशों की नियुक्ति का संबंध है, कार्यपालिका को पूरी तरह से स्थिति से बाहर रखा।
कार्यपालिका से कोई नहीं नियुक्ति प्रक्रिया में परामर्श या शामिल किया जाना था।

29. प्रारूप समिति ने भी प्रस्ताव दिया, जाहिरा तौर पर

अनुसूची III-ए के समावेशन को ध्यान में रखते हुए कि प्रारूप संविधान का अनुच्छेद 103 (2) (के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित)

उच्चतम न्यायालय और संविधान के अनुच्छेद 124 (2) के अनुरूप

भारत का संविधान) 14 को निम्नानुसार संशोधित किया जाए:

" (i) ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद "शब्द"

राज्यों में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के
जिस उद्देश्य के लिए आवश्यक हो उसे हटा दिया जाए।

खंड (2); और

(ii) खंड (2) के पहले परंतुक को हटा दिया जाए। 15

30. दूसरे शब्दों में, राष्ट्रपति से यह उम्मीद नहीं थी कि

मंत्रिपरिषद से परामर्श करें या उसकी सलाह पर कार्य करें लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करना था और फिर सलाहकार मंडल की सलाह लें। यह एक मिश्रण था राज्य प्रमुख की संपूर्ण समिति की सिफारिश (राष्ट्रपति के रूप में उच्च पद नामित किया गया) अपने दम पर और फिर भी राष्ट्रपति के पास न्यायाधीशों की नियुक्ति में 'निरंकुश विवेकाधिकार' नहीं है।

31. द्वारा दिए गए प्रस्तावों सहित सभी प्रस्ताव

और मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति पर प्रारूपण द्वारा विचार किया गया था 14 संविधान के प्रारूप के अनुच्छेद 103 (2) में कहा गया है: उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उनके अधीन वारंट द्वारा की जाएगी और

मोहर उच्चतम न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों के साथ परामर्श करने के बाद, जो इस उद्देश्य के लिए आवश्यक हों, और जब तक वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक पद धारण करेगा:

बशर्ते कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में, भारत के मुख्य न्यायाधीश से हमेशा परामर्श किया जाएगा। 15 द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स, खंड-IV, पृष्ठ 147।

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

समिति और 4 नवंबर, 1948 को इसका दूसरा मसौदा संविधान सभा में संविधान पेश किया गया था

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष।

हालांकि, मसौदा समिति का निर्णय लिया गया

अक्टूबर, 1948 को संविधान के प्रारूप में शामिल नहीं किया गया था।

इसलिए, डॉ. अम्बेडकर ने एक संशोधन पेश किया

31 दिसंबर, 1948 को संविधान सभा ने खंड जोड़ा

(5) प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 62 में ए। संशोधन

डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित पाठ इस प्रकार है:

"कि अनुच्छेद 62 के खंड 5 के बाद निम्नलिखित नया खंड

सम्मिलित किया जाए:

(5) a अपने मंत्रियों के चयन और उनके अभ्यास में

आम तौर पर निर्धारित निर्देशों द्वारा निर्देशित किया जाए
अनुसूची III-ए, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा की गई किसी भी चीज़ की वैधता पर आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।

कि यह इस तरह के अनुसार के अलावा अन्यथा किया गया था

निर्देश दिए। ”

32. संशोधन पर संक्षिप्त चर्चा की गई और इसे स्वीकार कर लिया गया।

उसी दिन संविधान सभा द्वारा। हालांकि प्रारूपण समिति का निर्णय खंड (5) ए को सम्मिलित करना था।

प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 62 में और साथ ही साथ हटा दें।

संविधान के प्रारूप के अनुच्छेद 103 के खंड (2) का एक भाग,

अनुच्छेद 103 के खंड (2) को हटाने से संबंधित संशोधन

संविधान के मसौदे को स्पष्ट रूप से डॉ.

अम्बेडकर। इसका कारण स्पष्ट नहीं है। जहाँ तक उपकरण की बात है निर्देश संबंधित है, यह
ग्रैनविल ऑस्टिन द्वारा इंगित किया गया है

कि यह वास्तव में नहीं, बल्कि निहित रूप से संविधान द्वारा अपनाया गया था

सभा। 16

33. प्रारूपण के विचारों का एक संयुक्त अध्ययन

निर्देश के साधन के साथ पढ़ी गई समिति और

16 भारतीय संविधान-पृष्ठ 126 पर ग्रैनविल ऑस्टिन द्वारा एक राष्ट्र की आधारशिला, फुटनोट 39 सर्वोच्च
न्यायालय की रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 62 में खंड (5) ए का सम्मिलन यह इंगित करता है कि उस समय की
सोच यह थी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को अपना काम करना था

व्यक्तिगत क्षमता। यह बहुत महत्वपूर्ण है अन्यथा वहाँ था

निर्देश के साधन या एक उपकरण की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है

सलाहकार बोर्ड का गठन या पूरी तरह से बहिष्कार के लिए

की नियुक्ति में मंत्री परिषद या कार्यपालिका

न्यायाधीशों। लेकिन बाद में इस सोच को छोड़ दिया गया।

संविधान सभा की बहसों

34. इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का प्रभाव पड़ता है -

संविधान में बाद की बहस को समझना

23 और 24 मई, 1949 को हुई सभा जब
गया और

संविधान के प्रारूप के अनुच्छेद 103 पर विचार किया

इस स्तर पर जोर दिया कि जब बहस हुई
था कि

23 और 24 मई, 1949 यह इस तथ्य की पृष्ठभूमि में

मसौदे के अनुच्छेद 62 में खंड (5) ए पहले ही डाला जा चुका था।

न्यायाधीशों की नियुक्ति सहित राष्ट्रपति कार्य करेंगे।
में था

उनकी व्यक्तिगत क्षमता और मंत्रिपरिषद

तस्वीर में भी नहीं। बहस को थोड़ा संदर्भित किया जाएगा

बाद में।

35. कुछ महीनों के बाद, 11 अक्टूबर, 1949 को

संविधान सभा के अध्यक्ष को श्री.

टी. टी. कृष्णामाचारी ने कहा कि अनुसूची III-ए को स्थानांतरित नहीं किया जा रहा है और

ताकि इसे सूची से बाहर निकाला जा सके। वह भी चला गया

संविधान के प्रारूप से अनुसूची IV को हटाना। समझाते हैं।

संविधान के मसौदे से अनुसूची IV को हटाने का कदम

कहा गया था कि मामला पूरी तरह से सम्मेलन पर छोड़ दिया जाना चाहिए

संविधान के मुख्य भाग में अनुसूची के रूप में रखे जाने के बजाय

निर्देश के एक साधन के रूप में और यह कि काफी बड़ी मात्रा में राय है जो उस विचार का समर्थन करती है।

36. डॉ. अम्बेडकर ने आगे कहा:

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

"महोदय, निर्देश के साधन के संबंध में, वहाँ

दो बिंदु हैं जिन्हें ध्यान में रखना होगा। द.

निर्देश के साधन का उद्देश्य जैसा कि मूल रूप से था

सरकार के लिए ब्रिटिश संविधान में तैयार किया गया

उपनिवेशों को प्रमुख को कुछ निर्देश देने थे

राज्य इस बारे में कि उन्हें अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कैसे करना चाहिए जो उनमें निहित थीं। अब यह

निर्देश का साधन जहाँ तक प्रभावी था विशेष राज्यपाल या वायसराय जिन्हें ये निर्देश दिए गए हैं

सचिव के अधिकार के अधीन थे

राज्य का। यदि किसी विशेष मामले में जो गंभीर था

उदाहरण के लिए, राज्यपाल ने लगातार इनकार कर दिया

उसे जारी किए गए निर्देश पत्र को पूरा करने के लिए, यह

उसे हटाने के लिए राज्य सचिव के लिए खुला था, और

एक और नियुक्त करें और इस तरह प्रभावी ले जाने को सुरक्षित करें

निर्देश के साधन से बाहर। जहाँ तक हमारे

संविधान का संबंध है, कोई पदाधिकारी नहीं बनाया गया है इसके द्वारा कौन देख सकता है कि निर्देश के ये साधन हैं

राज्यपाल द्वारा ईमानदारी से किया गया।

दूसरा, इस संविधान के तहत हम राज्यपाल के पास जो विवेकाधिकार छोड़ने जा रहे हैं, वह बहुत कम है।

उसके पास शायद ही कोई विवेक है। उसे उस पर कार्रवाई करनी होगी

चयन के मामले में प्रधानमंत्री की सलाह

मंत्रिमंडल के सदस्य। उसे भी कार्रवाई करनी है

प्रधानमंत्री और उनके राज्य मंत्रियों की सलाह

किसी विशेष कार्यपालिका या विधायी के संबंध में

खंड (5) क) का यह कहना संवैधानिक पर जोर देते हुए था।

दायित्व और संवैधानिक सम्मेलन:

"प्रत्येक संविधान, जहाँ तक इसका संबंध है जिसे हम कहते हैं

संसदीय लोकतंत्र के लिए तीन अलग-अलग अंगों की आवश्यकता है राज्य, कार्यपालिका, न्यायपालिका और

विधायिका। मुझे किसी भी संविधान में कहीं नहीं मिला है।

एक प्रावधान जिसमें कहा गया है कि कार्यपालिका इसका पालन करेगी

विधायिका, और न ही मुझे किसी भी संविधान में कहीं मिला है

एक प्रावधान कि कार्यपालिका न्यायपालिका का पालन करेगी।
ऐसा प्रावधान कहीं नहीं मिलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि

आमतौर पर यह समझा जाता है कि संविधान के प्रावधान संविधान के विभिन्न अंगों पर बाध्यकारी हैं।

राज्य। नतीजतन, यह माना जाना चाहिए कि जो

संविधान का काम करते हैं, जो रचना करते हैं

17 एचटीटीपी: //भारत की संसद। ठीक है। /ls/डिबेट/वॉल्यूम 10p4 में।

एच. टी. एम. सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

विधायिका और वे जो कार्यपालिका का गठन करते हैं और

न्यायपालिका अपने कार्यों, अपनी सीमाओं और अपने कार्यों को जानती है।

कर्तव्य। अतः यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि यदि कार्यपालिका

संविधान के काम करने में ईमानदार है, फिर कार्यपालिका संविधान में निर्धारित किसी भी प्रकार के अनिवार्य दायित्व के बिना विधानमंडल का पालन करने के लिए बाध्य है।

इसी तरह, यदि कार्यपालिका काम करने में ईमानदार है

संविधान, इसे न्यायिक के अनुसार कार्य करना चाहिए

उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय। इसलिए मेरा

निवेदन यह है कि यह एक अंग का मामला है

राज्य अपनी सीमाओं के भीतर कार्य कर रहा है और इसका पालन कर रहा है

राज्य के अन्य अंगों की सर्वोच्चता। जहाँ तक

संविधान इसे सर्वोच्चता देता है

संवैधानिक दायित्व जो निहित है

स्वयं संविधान।

श्रीमान, मुझे याद है कि आपने यह सवाल उठाया था और मैंने देखा था।

और मेरे पास राजा की पीठ के दो निर्णय थे

विभाजन जिसे मैं एक दिन यहाँ लाना चाहता था और संदर्भ देना चाहता था

सदन में ताकि बात पूरी तरह से स्पष्ट हो सके। लेकिन मुझे खेद है कि मुझे आज इस मुद्दे के उठाए जाने की कोई सूचना नहीं थी। लेकिन

यह उस सवाल का जवाब है जो उठाया गया है।

किसी भी देश में कोई भी संवैधानिक सरकार काम नहीं कर सकती है।

जब तक कि कोई विशेष संवैधानिक प्राधिकरण याद न रखे

तथ्य यह है कि इसका अधिकार संविधान द्वारा सीमित है और

कि यदि संविधान द्वारा बनाया गया कोई प्राधिकरण है जिसे उस विशेष प्राधिकरण के बीच निर्णय लेना है और

तब उस प्राधिकारी का निर्णय किसी अन्य निकाय पर बाध्यकारी होगा। यही सजा है।

जिसे यह संविधान यह देखने के लिए देता है कि

राष्ट्रपति अपने मंत्रियों की इस सलाह का पालन करेंगे कि कार्यपालिका अपने कार्यकारी अधिकार से अधिक नहीं होगी - संसद द्वारा बनाई गई विधि और यह कि कार्यपालिका नहीं करेगी

उस कानून की अपनी व्याख्या दें जो विवादित है [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

द्वारा बनाए गए न्यायिक अंग की व्याख्या के साथ

संविधान।

श्री एच. बी. कामथ: यदि किसी विशेष मामले में राष्ट्रपति

अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य नहीं करता है, क्या यह संविधान के उल्लंघन के समान होगा?

और क्या वह महाभियोग के लिए उत्तरदायी होगा?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर: इसमें जरा भी संदेह नहीं है "। 18

इस अत्यंत महत्वपूर्ण प्रदर्शनी का उल्लेख करते हुए, ग्रैनविल

ऑस्टिन ने निष्कर्ष निकाला:

"इससे यह अनुमान लगाने के लिए मजबूर किया जाता है कि अम्बेडकर और

प्रारूपण समिति के सदस्य, शायद इसके तहत

नेहरू या पटेल का दबाव इस नतीजे पर पहुंचा था

कि गैर-न्यायोचित लिखत के लिखित प्रावधान

मंत्रिमंडल के निर्देश और मौन सम्मेलन

सरकार का समान मूल्य था: दोनों कानूनी थे

अप्रवर्तनीय, लेकिन दोनों ने एक तंत्र प्रदान किया जिसके द्वारा

विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित कर सकती थी; और दोनों में से, सम्मेलन सबसे सरल और सरल तरीका था

कार्यकारी प्राधिकरण को सीमित करना "। " 19

इसे न्यायपालिका के बीच संबंधों में बदलना

और कार्यपालिका, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि डॉ. अम्बेडकर और वास्तव में

संविधान सभा का विचार था कि संवैधानिक

दायित्वों और संवैधानिक परंपराओं का सम्मान किया जाना चाहिए,

अलिखित हालांकि वे हो सकते हैं। और, इनमें से एक संवैधानिक सम्मेलनों का दृष्टिकोण यह है कि

दायित्वों और संवैधानिक

न्यायपालिका का कार्यपालिका द्वारा न केवल न्यायिक निर्णयों के संबंध में बल्कि अन्य मामलों में भी सम्मान किया जाना चाहिए जो

न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा प्रभाव।

18 एचटीटीपी: //भारत की संसद। ठीक है। इन/एलएस/डिबेट/वॉल्यूम 10 पी7 सी। एच. टी. एम. 19 भारतीय संविधान-एक राष्ट्र की आधारशिला, पृष्ठ 138-139 सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

23 और 24 मई, 1949 को बहस

39. यह सराहना करना महत्वपूर्ण है कि संविधान

विधानसभा की बहसों (संक्षेप में सीएडी) जिन पर हमारा ध्यान जाता है

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में तैयार किया गया था

न्यायालय और विशेष रूप से एक न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए नहीं

उच्च न्यायालय। लेकिन बहस का योग और सार समान रूप से है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति पर लागू होता है।

40. 23 और 24 मई, 1949 को तीन महत्वपूर्ण

संविधान के प्रारूप के अनुच्छेद 103 (2) में संशोधन

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए थे

संविधान सभा में विचार किया गया। पहला स्थानांतरित किया गया था प्रो. के. टी. शाह (बिहार: जनरल) जिन्होंने सुझाव दिया कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति उसके बाद की जानी चाहिए

राज्य परिषद के साथ परामर्श। यह सुझाव था

राजनीतिक प्रभाव, पार्टी के पैतरेबाज़ी से बचने का इरादा और

- नियुक्ति प्रक्रिया में दबाव। दूसरा चला गया था

सुझाव दिया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कुल के दो-तिहाई बहुमत से पुष्टि की जा सकती है

संयुक्त रूप से एकत्रित संसद सदस्यों की संख्या

संसद के दोनों सदनों का सत्र। तीसरा चला गया। श्री बी. पोकर साहिब (मद्रास: मुस्लिम) ने सुझाव दिया कि

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होनी चाहिए

भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति। उनके समर्थन में

श्री बी. पोकर साहिब संशोधन का व्यापक रूप से उल्लेख किया गया है और

के सम्मेलन द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन पर भरोसा किया

मुख्य न्यायाधीश। जैसा कि उन्होंने कहा:

"महोदय, मैं संघीय न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को प्रस्तुत करता हूँ। और विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश

सम्मेलन में एकत्रित होने वाले उच्चतम के हकदार हैं

इस विधानसभा के समक्ष भार, इस प्रावधान से पहले है

पास हो गया। यह सर्वोच्च महत्व का है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को यह महसूस नहीं कराया जाना चाहिए कि उनकी सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

अस्तित्व या उनकी नियुक्ति राजनीतिक पर निर्भर है। विचार या राजनीतिक दल की इच्छा पर।

इसलिए, यह आवश्यक है कि पर्याप्त होना चाहिए

राजनीतिक प्रभाव के खिलाफ सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं

ऐसी नियुक्तियों पर ध्यान दें। बेशक, अगर कोई न्यायाधीश बकाया है एक राजनीतिक दल में उनकी नियुक्ति, निश्चित रूप से पाठ्यक्रम में

एक न्यायाधीश के रूप में अपने करियर के बारे में, एक साधारण इंसान के रूप में भी, वह निश्चित रूप से कुछ करने के लिए बाध्य होगा

उसे नियुक्त करने वाले प्राधिकारी के राजनीतिक विचारों पर विचार करना। कि न्यायाधीशों को सबसे ऊपर होना चाहिए

इन राजनीतिक विचारों से इनकार नहीं किया जा सकता है।

इसलिए, मैं प्रस्तुत करता हूं कि मुख्य शर्तों में से एक निर्धारित प्रक्रिया में उल्लिखित, जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति है

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनिवार्य पूरा किया जाए। इस ज्ञापन में इस पर जोर दिया गया है।

इस सदन द्वारा स्वीकार किया गया। महोदय, मेरा निवेदन है कि यह सर्वोच्च महत्व यह है कि राष्ट्रपति को न केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना चाहिए, बल्कि उनकी सहमति भी लेनी चाहिए

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। यह हो चुका है इस ज्ञापन में बहुत जोर देकर कहा गया है। कि यह बिल्कुल है

उन्हें राजनीतिक प्रभावों से ऊपर रखना आवश्यक है। नहीं।

संदेह है, इस प्रक्रिया में कहा गया है कि राज्यपाल

राज्य से भी सलाह ली जा सकती है, लेकिन यह मामूली बात है।

महत्व। यह संभावना है कि राज्यपाल ने भी

कुछ राजनीतिक झुकाव। इसलिए, मेरे संशोधन में राज्यपाल का नाम हटा दिया गया है। कि न्यायपालिका

सभी राजनीतिक दलों और सभी राजनीतिक दलों से ऊपर होना चाहिए।

विचार को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। मैं प्रवेश नहीं करना चाहता
में, जिस पर चर्चा की गई थी

वर्तमान में विवाद

कल, स्वतंत्रता की आवश्यकता के बारे में

न्यायपालिका जहाँ तक कार्यपालिका का संबंध है।

यह एक सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड है

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

ऐसा मामला जिस पर बहुत गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए

इस सदन के हाथों और मैं आशा करता हूँ कि माननीय

कानून मंत्री इस प्रश्न के इस पहलू पर भी गंभीरता से ध्यान देंगे, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि

संघीय न्यायालय द्वारा सिफारिश की गई है
और दूसरे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एकत्र हुए

सम्मेलन में। महोदय, मुझे नहीं लगता कि इस विषय पर इस सम्मेलन से बड़ा कोई अधिकार हो सकता है।

संघीय न्यायालय और विभिन्न राज्यों के मुख्य न्यायाधीश

भारत में उच्च न्यायालय "। 20
बेग साहिब (मद्रास: मुस्लिम) ने

श्री महबूब अली

कुछ इसी तरह का संशोधन। श्री द्वारा दिया गया कारण।

महबूब अली बेग साहिब थे:

"हमारे प्रस्तावित संविधान के तहत राष्ट्रपति

कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख बनें। और यह

लोकतंत्र। अतः राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किया जाएगा
प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद जो हैं

अनिवार्य रूप से एक राजनीतिक दल से लिया गया। इसलिए यह

राष्ट्रपति का निर्णय अनिवार्य रूप से प्रभावित होगा।

पार्टी के विचारों से। इसलिए यह आवश्यक है कि

मुख्य न्यायाधीश की सहमति को पूर्व-आवश्यक बनाया गया है।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए
पार्टी के प्रभावों से खुद को बचाने के लिए जो हो सकता है
न्यायाधीशों की नियुक्ति पर भार वहन किया जाए। 21

41. यह स्पष्ट है कि इन दोनों माननीय सदस्यों ने
'सहमति' का सुझाव क्योंकि वे चाहते थे
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति से मुक्त होना
किसी भी प्रकार का राजनीतिक या कार्यकारी हस्तक्षेप। ऐसा प्रतीत होता है कि
इन संशोधनों को शामिल करने की परवाह किए बिना पेश किया गया था
प्रारूप संविधान और अनुसूची के अनुच्छेद 62 में खंड (5) ए
III-ए वहाँ। 20 एचटीटीपी: //भारत की संसद। ठीक है। इन/एलएस/डिबेट/वॉल्यूम 8 पी7 ए। एचटीएम
21 एचटीटीपी: //भारत की संसद। ठीक है। इन/एलएस/डिबेट/वॉल्यूम 8 पी7 ए।

एचटीएम _ [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

42. जो भी हो, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ
नियुक्ति की प्रक्रिया में राष्ट्रपति की सटीक भूमिका पर न्यायाधीशों से। क्या राष्ट्रपति से उनकी सलाह
पर कार्य करने की अपेक्षा की जाती है?
मंत्रिपरिषद या उनकी व्यक्तिगत क्षमता में?

43. डॉ. अम्बेडकर द्वारा व्यक्त एक दृष्टिकोण यह था कि
राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा निर्देशित किया जाएगा।
दूसरा दृष्टिकोण या धारणा यह थी कि के सम्मिलन के साथ
प्रारूप संविधान और अनुसूची के अनुच्छेद 62 में खंड (5) ए III-राष्ट्रपति को अपनी व्यक्तिगत
क्षमता में कार्य करना था और
कार्यपालिका के बाद से मंत्रिपरिषद द्वारा निर्देशित नहीं किया जाता है
नियुक्ति प्रक्रिया से पूरी तरह से बाहर रखा जाना था। यह.
यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों में से किस विचार को श्री बी.

पोकर साहिब और श्री महबूब अली बेग साहिब-लेकिन दोनों स्पष्ट थे कि राष्ट्रपति को राजनीतिक या पार्टी के तहत रखा जा सकता है।

नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की सिफारिश में दबाव और इससे बचा जाना चाहिए और दबाव हो सकता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, एक निष्पक्ष व्यक्ति की सहमति की आवश्यकता द्वारा अस्वीकार किया गया।

44. लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री बी. पोकर साहिब और श्री महबूब अली बेग साहिब ने केवल एक न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए सिफारिश राष्ट्रपति-इसलिए प्रमुख द्वारा सहमति की आवश्यकता भारत का न्याय। उन्होंने, स्पष्ट रूप से, विज्ञापन नहीं किया मुख्य न्यायाधीश द्वारा न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए सिफारिश भारत का न्याय।

45. यह धारणाओं के विचलन की इस पृष्ठभूमि में है। कि 24 मई, 1949 को डॉ. अम्बेडकर का भाषण होना चाहिए सराहना की। बहस का जवाब देते हुए डॉ. अम्बेडकर ने कहा:

"अब, महोदय, कई संशोधनों के संबंध में कि इस लेख में स्थानांतरित कर दिया गया है, वास्तव में तीन हैं जिन मुद्दों को उठाया गया है। पहला है, कैसे हैं? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी?"

अब सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.] विभिन्न संशोधनों को समूहीकृत करना जो संबंधित हैं - इस विशेष मामले में, मुझे तीन अलग-अलग प्रस्ताव मिलते हैं। द. पहला प्रस्ताव यह है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश प्रमुख की सहमति से नियुक्त किया जाना चाहिए न्याय। यह एक दृष्टिकोण है। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि विषयगत होनी चाहिए। संसद द्वारा दो-तिहाई मतों की पुष्टि के लिए; और

राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियाँ

तीसरा सुझाव यह है कि उन्हें नियुक्त किया जाना चाहिए।

राज्य परिषद के साथ परामर्श।

इस मामले के संबंध में, 1 इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि

उठाया जाना सबसे महत्वपूर्ण है। नहीं हो सकता है।

सदन में मतभेद है कि हमारी न्यायपालिका को

दोनों कार्यपालिका से स्वतंत्र होने चाहिए और

अपने आप में सक्षम। और सवाल यह है कि ये दोनों कैसे?

वस्तुओं को सुरक्षित किया जा सकता है। वहाँ दो अन्य हैं देशों। ग्रेट ब्रिटेन में नियुक्तियाँ की जाती हैं।

क्राउन द्वारा, किसी भी प्रकार की सीमा के बिना,

जिसका अर्थ है दिन का कार्यपालक। वहाँ है कि

संयुक्त राज्य अमेरिका में विपरीत प्रणाली जहां, उदाहरण के लिए,

उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों के साथ-साथ अन्य अधिकारी

राज्य केवल के साथ बनाया जाएगा [नियुक्त]

संयुक्त राज्य अमेरिका में सीनेट की सहमति। ऐसा लगता है।

आज हम जिन परिस्थितियों में जी रहे हैं, उनमें मेरे लिए जिम्मेदारी की भावना उतनी नहीं बढ़ी है

नियुक्तियों को छोड़ने के लिए खतरनाक राष्ट्रपति, बिना किसी प्रकार के आरक्षण या सीमा के,

अर्थात् केवल कार्यपालिका की सलाह पर

एक दिन। इसी तरह, मुझे ऐसा लगता है कि हर नियुक्ति जिसे कार्यपालक विषय बनाना चाहता है

विधानमंडल की सहमति के लिए भी एक बहुत नहीं है

उपयुक्त प्रावधान। इसके कठोर होने के अलावा, इसमें नियुक्ति की संभावना भी शामिल है राजनीतिक दबाव और राजनीतिक [2015] 13 एस. सी. आर. से प्रभावित

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विचार करें। मसौदा लेख, इसलिए, एक मार्गदर्शन करता है

मध्य पाठ्यक्रम। यह राष्ट्रपति को सर्वोच्च और पूर्ण प्राधिकारी नहीं बनाता है।

नियुक्तियाँ करना। यह आयात भी नहीं करता है

विधानमंडल का प्रभाव। लेख में प्रावधान

यह है कि ऐसे व्यक्तियों का परामर्श होना चाहिए जो हैं

पूर्व परिकल्पना, में उचित सलाह देने के लिए अच्छी तरह से योग्य

इस तरह के मामले, और मेरा निर्णय है कि इस तरह के

प्रावधान को इस समय के लिए पर्याप्त माना जा सकता है।

प्रमुख की सहमति के प्रश्न के संबंध में

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्ताव निहित रूप से निष्पक्षता दोनों पर निर्भर करता है।
मुख्य न्यायाधीश और उनके निर्णय की दृढ़ता।

सभी विफलताओं, सभी भावनाओं और सभी के साथ
पूर्वाग्रह जो आम लोगों के रूप में हमारे पास हैं; और मुझे लगता है, मुख्य न्यायाधीश को व्यावहारिक रूप से
वीटो की अनुमति देने के लिए

न्यायाधीशों की नियुक्ति वास्तव में अधिकार को स्थानांतरित करने के लिए है

मुख्य न्यायाधीश जिसमें हम निहित होने के लिए तैयार नहीं हैं
राष्ट्रपति या उस समय की सरकार। इसलिए मैं,

सोचिए कि यह भी एक खतरनाक प्रस्ताव है। 22

46. डॉ. अम्बेडकर बिल्कुल स्पष्ट थे कि ऐसा नहीं हो सकता था

इस बात पर मतभेद कि न्यायपालिका को स्वतंत्र होना चाहिए

कार्यपालक, फिर भी सक्षम। उनका विचार था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति को उनके ऊपर छोड़ना 'खतरनाक'
होगा।

राष्ट्रपति बिना किसी आरक्षण या सीमा के, अर्थात्

मान लीजिए, केवल उस दिन की कार्यपालिका की सलाह पर। डॉ.

ऐसा लगता है कि अम्बेडकर ने निर्देश के साधन (या इसे उनके द्वारा 'छोड़ दिया गया') के अस्तित्व के बारे में
दृष्टि खो दी है।

उस दस्तावेज़ में सलाहकार मंडल की सलाह का उल्लेख किया गया था

और कार्यकारी नहीं और यह भी कि उस दस्तावेज़ ने सक्षम किया

22 एचटीटीपी: //भारत की संसद। ठीक है। इन/एलएस/डिबेट/वॉल्यूम 8 पी7 बी।

एच. टी. एम. सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

राष्ट्रपति का अपने दम पर कार्य करना, न कि राष्ट्रपति की सलाह पर कार्यकारी।

47. यदि राष्ट्रपति की भूमिका के बीच यह द्वंद्व है

और राष्ट्रपति पर कार्यपालिका की सलाह के कार्यपालिका और बाध्यकारी या गैर-बाध्यकारी प्रभाव की सराहना की जाती है, डॉ. अम्बेडकर के विचार बहुत स्पष्ट हो जाते हैं। वह बहुत स्पष्ट था।

कि नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यपालिका की प्रधानता नहीं होनी चाहिए थी और न ही वह चाहते थे कि राष्ट्रपति निरंकुश रहे

कार्यपालक या कार्य की सलाह को स्वीकार या अस्वीकार करने का विवेकाधिकार

अपने दम पर। जहाँ तक विधानमंडल की सहमति की बात है चिंतित, डॉ. अम्बेडकर ने महसूस किया कि प्रक्रिया होगी

राजनीतिक दबाव की संभावना के साथ कठोर और विचार करें। इस संदर्भ में डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि

वह एक मध्य मार्ग का संचालन कर रहा था और तैयार नहीं था

राष्ट्रपति को वीटो देना (राष्ट्रपति की सलाह को अस्वीकार करना) की नियुक्ति में कार्यपालक या अपने दम पर कार्य करना)

न्यायाधीशों, कार्यकारी प्रधानता को पहले ही खारिज कर दिया गया है

उसे। इन परिस्थितियों में, उन्होंने महसूस किया कि इस तरह का प्रावधान

[भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श पर विचार किया जा सकता है]

इस समय के लिए पर्याप्त है।

48. मुख्य न्यायाधीश की 'सहमति' के संबंध में

भारत का (भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के विरुद्ध) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में डॉ.

अम्बेडकर की राय थी कि मुख्य न्यायाधीश, इसके बावजूद

उनकी श्रेष्ठता में सभी विफलताएं, भावनाएं और पूर्वाग्रह थे

आम लोगों का अधिकार और उन्हें वीटो की शक्ति प्रदान करना, जो

राष्ट्रपति या तत्कालीन सरकार में निहित नहीं है
(वह कार्यकारी है), एक 'खतरनाक प्रस्ताव' होगा।

49. डॉ. अम्बेडकर का विचार था कि न तो
राष्ट्रपति और न ही उस समय की सरकार (कार्यपालिका) और न ही
भारत के मुख्य न्यायाधीश को इस मामले में अंतिम निर्णय लेना चाहिए।
न्यायाधीशों की नियुक्ति। फिर कौन फाइनल खेलेगा
राष्ट्रपति [2015] 13 एस. सी. आर. के बीच मतभेद की स्थिति में कहें।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट
या उस समय की सरकार या भारत के मुख्य न्यायाधीश
न्यायाधीश के रूप में किसी विशेष व्यक्ति की नियुक्ति? डॉ.
अम्बेडकर ने इस प्रश्न को सीधे संबोधित नहीं किया क्योंकि उन्होंने किया था।
इस संबंध में उत्पन्न होने वाले गतिरोध की कल्पना न करें।

50. एक छोटा सा मोड़-पहले से ही कारणों के अलावा
कार्यपालिका को निर्णय लेने से बाहर रखने के लिए उल्लेख किया गया है
न्यायाधीशों की नियुक्ति में प्रक्रिया, यह दिलचस्प होगा कि जानते हैं कि, पूरी तरह से एक अलग
विषय पर, जवाब देते हुए
न्यायपालिका के सदस्यों द्वारा पद की स्वीकृति पर बहस
सेवानिवृत्ति के बाद डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि न्यायपालिका
बहुत कम ही नागरिकों के बीच मुद्दों को तय करने में लगे हुए हैं और

4

सरकार ने। उन्होंने कहा:

"न्यायपालिका उन मामलों का फैसला करती है जिनमें सरकार
यदि है, तो सबसे दूरस्थ व्याज, वास्तव में कोई व्याज नहीं है

सभी। न्यायपालिका इस मुद्दे को तय करने में लगी हुई है
नागरिकों के बीच और बहुत कम नागरिकों के बीच और

सरकार ने। फलस्वरूप प्रभावित होने की संभावनाएँ
 न्यायपालिका के एक सदस्य का आचरण
 सरकार बहुत दूर है, और मेरा व्यक्तिगत विचार है,
 इसलिए, यह है कि जिन प्रावधानों को लागू किया जाता है
 संघीय लोक सेवा आयोग के पास ऐसा कोई स्थान नहीं है
 जहाँ तक न्यायपालिका का संबंध है "। 23

51. तब से लेकर अब तक समय नाटकीय रूप से बदल गया है।

नागरिकों और नागरिकों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों से 'बहुत कम'

सरकार, आज सरकार निर्लज्ज है

देश का सबसे बड़ा वादी। यह सुप्रीम में देखा गया है

कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन v. संघ का

इंडिया 24 कि:

"इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वर्तमान में राज्य ने

प्रमुख वादी और उच्च न्यायालय बनें

विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय, केंद्र बन गए हैं।

23 एचटीटीपी: //भारत की संसद। ठीक है। इन/एलएस/डिबेट/वॉल्यूम 8 पी7 बी। एच. टी. एम.

24 (1993) 4 एससीसी 441 (नौ न्यायाधीशों की पीठ)

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

अशांत विवादों के लिए, जिनमें से कुछ एक स्वाद के साथ

राजनीतिक नतीजों और अदालतों को सामना करना पड़ता है
 तूफान और तूफान क्योंकि उनकी जीवन शक्ति एक राष्ट्रीय है

अनिवार्य है। इन परिस्थितियों में, कर सकते हैं

सरकार, अर्थात्, प्रमुख वादी को न्यायसंगत ठहराया जाए

अपने मध्यस्थों को नामित करने और नियुक्त करने में पूर्ण अधिकार प्राप्त करना। इसका जवाब
 नकारात्मक होगा। अगर

ऐसी प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दी जाती है, लंबे समय में न्यायपालिका की स्वतंत्रता बिना किसी निशान के डूब जाएगी। 25

कार्यकारी और राजनीतिक के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव से या पार्टी का दबाव, अगर न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखना है तो आज ऐसा करने का और भी अधिक कारण है।

53. इंग्लैंड में भी कार्यकारी सबसे अधिक बार होता है।

वादी 'और स्थिति हमारी तुलना में बेहतर नहीं लगती है

देश। न्यायिक स्वतंत्रता पर एक व्याख्यान में, लॉर्ड फिलिप्स 26

यह कहना था:

"आधुनिक समाज में व्यक्तिगत नागरिक के अधीन है लगभग के संबंध में कार्यपालिका द्वारा लगाए गए नियंत्रण

जीवन का हर पहलू। उनमें से अधिकांश को लागू करने का अधिकार नियंत्रण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विधायिका से आता है।

नागरिक को वैधता को चुनौती देने में सक्षम होना चाहिए

एक स्वतंत्र न्यायपालिका के समक्ष कार्यकारी कार्यवाई। क्योंकि यह कार्यकारी है जो शक्ति का प्रयोग करता है

राज्य और क्योंकि यह कार्यपालिका है, एक रूप में या

कार्यकारी दबाव या प्रभाव से है जो न्याय करता है विशेष रूप से संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है। 27

25 पैराग्राफ 207 (जस्टिस पांडियन)। इसी तरह का विचार न्यायमूर्ति कुलदिप सिंह ने पैराग्राफ 327 में व्यक्त किया था। 26 यूनाइटेड किंगडम के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व राष्ट्रपति और इंग्लैंड और वेल्स के लॉर्ड मुख्य न्यायाधीश

27 [HTTPS://डब्ल्यू. डब्ल्यू. यूसीएल। एसी। यू. के./संविधान-इकाई/घटनाएँ/न्यायिक-स्वतंत्रता घटनाएँ/स्वामी-फिलिप्स-प्रतिलेख।](https://dbyl.dbyl.yesil.com)

पी. डी. एफ. सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

सारांश

54. संविधान तक ले जाने वाली चर्चा

विधानसभा की बहस और न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित बहस से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि;

(1) न्यायपालिका की स्वतंत्रता अडिग थी

सभी नीति और निर्णय निर्माताओं द्वारा स्वीकार किया गया;

(2) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च न्यायालयों को एक परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से होना था राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश के बीच, न तो जिनके पास मामले में निरंकुश विवेक था;

(3) किसी भी मामले में, राजनीतिक कार्यपालिका की कोई भूमिका नहीं थी या निर्णय लेने की प्रक्रिया में बहुत कम भूमिका निभानी होती है।

इसके बावजूद, राजनीतिक कार्यपालिका ने हस्तक्षेप किया

नियुक्ति प्रक्रिया जैसा कि ज्ञापन द्वारा प्रमाणित है

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करना अदालत। परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति

हमेशा योग्यता पर नहीं होता था और कभी-कभी इसके बिना भी

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश;

(4) एक संवैधानिक परिपाटी मौजूद थी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति इसके अनुरूप की जानी चाहिए - भारत के मुख्य न्यायाधीश के विचार;

(5) न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रस्ताव

राष्ट्रपति (हालांकि उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया) या भारत के मुख्य न्यायाधीश और उत्पत्ति की परवाह किए बिना, इसे आम तौर पर स्वीकार किया जाएगा।

हालांकि, राष्ट्रपति के राजनीति के आगे झुकने की संभावना

या पार्टी का दबाव कल्पना के दायरे से बाहर नहीं था। (6) ऐतिहासिक रूप से, न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश से हमेशा परामर्श किया जाता था, और

परंपरागत रूप से उनकी सहमति हमेशा इस बात की परवाह किए बिना ली जाती थी

क्या नियुक्ति के लिए कोई सिफारिश सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड से उत्पन्न हुई है

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या राजनीतिक कार्यपालिका। यह.

इस आलोक में है कि संविधान सभा में चर्चा

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मुद्दे पर सराहना की जानी चाहिए।

(7) यह एक धूसर क्षेत्र बना रहा चाहे नियुक्ति में हो।

न्यायाधीशों से अपेक्षा की जाती थी कि राष्ट्रपति स्वयं कार्य करेगा या

राजनीतिक कार्यपालिका की सलाह पर।

भारत के विधि आयोग के विचार

55. न्यायाधीशों की नियुक्ति का मुद्दा

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को सबसे पहले संबोधित किया गया था।

स्वतंत्रता, विधि आयोग की 14 वीं रिपोर्ट में भारत (संक्षेप में एल. सी. आई.), फिर 80 वीं रिपोर्ट में और अंत में

121 सेंट रिपोर्ट। (214 वीं रिपोर्ट में एक संदर्भ दिया गया था और

230 वीं रिपोर्ट लेकिन उनका कोई तत्काल परिणाम नहीं है)।

इस मुद्दे को एस. पी. गुप्ता बनाम में भी संबोधित किया गया था। संघ भारत 28 और सुभाष शर्मा बनाम। भारत संघ, 29 यह

तीन संविधान संशोधन का विषय भी था

द्वारा प्रस्तुत इस न्यायालय के विधेयक और दो अन्य घोषणाएँ

बड़ी-बड़ी बेंच। यह केवल उजागर करने के लिए उल्लेख किया गया है इस मुद्दे की जटिलता और कुछ के लिए निरंतर खोज

नियुक्ति प्रक्रिया में स्थिरता और निश्चितता

न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इस संबंध में कहा गया है

संयुक्त राज्य में न्यायाधीशों के चयन के लिए, और यह होगा

समान रूप से हमारे देश पर लागू होता है:

"यह काफी हद तक निश्चित है कि किसी एक विषय ने इसका सेवन नहीं किया है। कानून की समीक्षाओं और कानून से संबंधित पृष्ठों की संख्या

विषय के रूप में पिछले 50 वर्षों में प्रकाशन

न्यायिक चयन ", 30

(क) 14 वीं रिपोर्ट-26.9.1958

28 1981 (एस. सी. सी. 87 (सात न्यायाधीशों की पीठ) 29 1991 एस. सी. सी. 574

30 ली एपस्टीन, जैक नाइट और ओल्गा श्वेतसोवा, न्यायिक चयन प्रणालियों की तुलना, 10 डब्ल्यू. एम. और मैरी बिल आर. टी. एस. जे. 7, एन. 9 (2001) (फिलिप डुबोइस के हवाले से)।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति

56. की घोषणा के एक दशक से भी कम समय के भीतर

संविधान, न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की तीखी
आलोचना हुई

एल. सी. आई. से। 14 वीं रिपोर्ट का अध्याय 5 और अध्याय 6

एल. सी. आई., अन्य बातों के साथ-साथ, न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित

उच्चतम न्यायालय और क्रमशः उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश कुछ दुखद पढ़ने के लिए बनाता है,
विशेष रूप से क्योंकि

भारत के लिए अटॉर्नी-जनरल LCI.31 के अध्यक्ष थे

लगभग एक वर्ष के लिए देश की चौड़ाई और के रूप में जांच की गई इससे पहले समाज के विभिन्न
वर्गों के 473 गवाह

अपनी रिपोर्ट दें। इसने सह-चयन की एक नई प्रक्रिया भी अपनाई।

उन राज्यों के दो सदस्य जिनका दौरा किया गया था ताकि

स्थानीय समस्याओं को समझें। स्मारक और

आधिकारिक कार्य की केवल प्रशंसा की जा सकती है।

57. एल. सी. आई. ने पाया कि संविधान ने प्रयास किया

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को 'कार्यकारी नियंत्रण से ऊपर' रखना।

इसने विशेष रूप से महत्व को स्वीकार किया

न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करना और कहा कि 'यह स्पष्ट है कि न्यायाधीशों का चयन

राष्ट्र की प्रगति के लिए इस तरह के महत्वपूर्ण न्यायालय

यह एक जिम्मेदारी होनी चाहिए जिसे बहुत सावधानी के साथ निभाया जाना चाहिए। '32

58. इसके बाद तीन केंद्रीय मुद्दों को संबोधित किया गया -

(1) में सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विचार प्रबल थे

न्यायाधीशों का चयन करना। (2) आम धारणा कि कार्यकारी प्रभाव बार-बार से लगाया गया था कुछ नियुक्तियों के संबंध में उच्चतम तिमाही बेंच। (3) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिला।

31 रिपोर्ट का शीर्षक है 'न्यायिक प्रशासन में सुधार' 32 अध्याय 5 अनुच्छेद 51

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड
एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

59. रिपोर्ट में कहा गया है:

"यह व्यापक रूप से महसूस किया जाता है कि सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विचार न्यायाधीशों का चयन करने में प्रबल रहे हैं।

ऐसा लगता है कि इस विचार को आधार मिल गया है कि न्यायालय में प्रतिनिधित्व। हालांकि हम खुद को एक कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के विचार, जो अंग्रेजों द्वारा हमारे राजनीतिक शरीर में बुरी तरह से बोए गए थे, उन्होंने अपना प्रभाव पूरी तरह से नहीं खोया है। शायद क्या है? खेद करने के लिए और भी अधिक सामान्य धारणा है, कि उच्चतम क्वार्टर कुछ के लिए जिम्मेदार रहे हैं न्यायपीठ में नियुक्तियाँ। यह निस्संदेह सत्य है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों में सबसे अच्छी प्रतिभा है हमेशा सर्वोच्च न्यायालय तक अपना रास्ता नहीं पाया। यह है हकदार "। 33

एल. सी. आई. ने सिफारिश की, 60. अपने निष्कर्षों के आधार पर, अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कि सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विचारों को ध्यान में रखा जाना चाहिए सर्वोच्च पद पर नियुक्तियाँ करने में कोई भूमिका न निभाएँ अदालत '। हालांकि, एल. सी. आई. ने इसका कोई समाधान नहीं बताया।

उच्चतम न्यायालय में अधिक संतोषजनक नियुक्तियां करने का मुद्दा।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति।

61. इसी प्रकार, रिपोर्ट का अध्याय 6

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति समान रूप से होती है

पढ़कर दुख हुआ। नियुक्तियों में अपर्याप्तताएँ

इनका उल्लेख इस प्रकार किया गया है: (1) चयन किया गया है

असंतोषजनक और कार्यकारी प्रभाव से प्रेरित। (2) वहाँ

33 अध्याय 5 अनुच्छेद 6 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

राजनीतिक औचित्य या क्षेत्रीय या सांप्रदायिकता पर विचार भावनाओं ने एक भूमिका निभाई है।
(3) योग्यता को नजरअंदाज किया गया है

नियुक्तियाँ करना।

62. यह कहा जाता था कि ये अपर्याप्तताएँ अच्छी तरह से स्थापित थीं।

और वहाँ के साथ तीव्र सार्वजनिक असंतोष था नियुक्तियाँ की गईं:

"हमने उच्च न्यायालय के सभी केंद्रों का दौरा किया है।

हाथों के बारे में हमने कड़वी और अपमानजनक आलोचना सुनी है

उच्च न्यायालय की न्यायपालिका में की गई नियुक्तियाँ

हाल के वर्षों में। यह आलोचना सुप्रीम द्वारा की गई है।

न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सार्वजनिक

अभियोजकों के कई प्रतिनिधि, संघ

विधि महाविद्यालयों के बार, प्राचार्य और प्रोफेसर और

कानूनी पेशे के बहुत जिम्मेदार सदस्य

देश को। राज्य सरकारों में से एक को स्वीकार करना पड़ा
कि कुछ चयन अच्छे नहीं लगे और

कि सावधानीपूर्वक जाँच आवश्यक थी। लगभग सार्वभौमिक
 टिप्पणी का कोरस यह है कि चयन हैं
 असंतोषजनक और वे द्वारा प्रेरित किया गया है
 कार्यकारी प्रभाव। यह कहा गया है कि ये चयन
 ऐसा प्रतीत होता है कि वे किसी मान्यता प्राप्त सिद्धांत पर आगे नहीं बढ़े हैं
 राजनीतिक लाभ या क्षेत्रीय या सांप्रदायिक भावनाएँ।
 पीठ में नियुक्त बार के कुछ सदस्य
 पेशे में भी अग्रिम रैंक पर नहीं था
 कानूनी उपकरण या उनकी मात्रा का मामला
 बार में अभ्यास करें। कुछ अधिक सक्षम और
 ऐसा प्रतीत होता है कि योग्य व्यक्तियों की उपेक्षा की गई है
 कारण जो केवल राजनीतिक या सांप्रदायिक से उत्पन्न हो सकते हैं या
 समान आधार। समान रूप से शक्तिशाली या उससे भी अधिक
 के संबंध में प्रतिकूल टिप्पणियाँ की गई हैं
 चयनित व्यक्ति सेवाओं से होते हैं।

हम सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं को आश्वस्त करते हैं-रिकॉर्ड पर
 एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]
 कि हमें व्यक्त किए गए विचार एक अच्छी तरह से स्थापित और
 इन नियुक्तियों पर तीव्र सार्वजनिक असंतोष। 34
 63. ए की नियुक्ति के लिए अपनाई गई प्रक्रिया पर
 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अनुच्छेद का प्रशासनिक कार्य
 217 संविधान के बारे में एल. सी. आई. का यह कहना था:

"मुख्य न्यायाधीश ने अपनी सिफारिश को आगे बढ़ाया
 मुख्यमंत्री जो बदले में इस सिफारिश को आगे बढ़ाते हैं
 राज्यपाल के परामर्श से गृह मंत्री को
 केंद्र सरकार में कार्य। लेकिन अगर मुखिया

मंत्री की सिफारिश से सहमत नहीं हैं

इस पर अपनी टिप्पणी करने का अवसर
मुख्यमंत्री द्वारा की गई सिफारिश। यह

हालाँकि, अभ्यास का हमेशा पालन नहीं किया जाता है ताकि,
कुछ मामलों में ऐसा होता है कि सिफारिश की गई हो

मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी नहीं है

मुख्य न्यायाधीश। प्रतिद्वंद्वी सिफारिशें तब हैं

गृह मंत्री को भेजा गया, जिन्होंने

भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श, राष्ट्रपति को चयन के बारे में सलाह देता है। व्यक्ति।

मुख्यमंत्री द्वारा अनुशंसित हो सकता है, और

कभी-कभी व्यक्ति की वरीयता में चुना जाता है

मुख्य न्यायाधीश द्वारा सिफारिश की गई। 35

64. एल. सी. आई. ने दर्ज किया कि किसी व्यक्ति से कम नहीं

भारत के मुख्य न्यायाधीश को कार्यपालिका के बारे में यह कहना था

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में हस्तक्षेप

(योग्यता के अलावा अन्य कारणों से):

"मुख्यमंत्री का अब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हाथ है।

उच्च न्यायालय की पीठ में नियुक्ति का मामला।

अपरिहार्य परिणाम यह रहा है कि उच्च न्यायालय ने

34 अध्याय 6 पैरा 8

35 अध्याय 6 पैरा 11 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

कहो, दिन का क्रम बन गया है। मुख्यमंत्री ने
सद्भावना पर निर्भर एक राजनीतिक पद धारण करना

उनकी पार्टी के अनुयायियों को सुनने और प्रचार करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। दूसरी ओर
मुख्य न्यायाधीश

किसी भी पक्ष की पीड़ा पर अपना पद नहीं रखता है और

वह अधिवक्ताओं और उनके गुण-दोषों को जानता है।
और इसलिए मुख्य न्यायाधीश द्वारा एक सिफारिश है

केवल योग्यता पर होने की अधिक संभावना है कि मुख्यमंत्री द्वारा बनाया गया जो इसके बारे में कुछ नहीं जानता है

अधिवक्ताओं का तुलनात्मक कानूनी कौशल "। 36

65. इस पहलू को समाप्त करने के लिए, रिपोर्ट में कहा गया है कि बाहरी कारकों ने नियुक्तियों को प्रभावित किया है और ऐसा लगता है कि न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए प्रचार किया जा रहा है उच्च न्यायालय:

"यह वास्तव में एक निराशाजनक तस्वीर है और ऐसा प्रतीत होता है।

कि सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद का वातावरण और

राजनीतिक संरक्षण, काफी हद तक है

उच्च न्यायालय की न्यायपालिका में नियुक्तियों को प्रभावित किया।

इस बहुत ही परेशान करने वाली विशेषता के अलावा, व्यापकता

न्यायाधीशों के लिए प्रचार करना भी एक दुखद बात है

विकास। पूर्व में, बार के एक सदस्य को आमंत्रित किया गया था

एक न्यायाधीश को स्वीकार करने के लिए और उन्होंने इसे एक महान माना

विशेषाधिकार और सम्मान। आजादी के कुछ वर्षों के भीतर,

हालांकि, ऐसा लगता है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है यह काम करने और प्रचार करने के लिए एक पद बन जाता है। 37

66. अपने निष्कर्षों के आधार पर एल. सी. आई. ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले:

निष्कर्ष, दूसरों के बीच:

36 अध्याय 6 पैरा 14

37 अध्याय 6 पैराग्राफ 14 और 15 सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

"(8) कई असंतोषजनक नियुक्तियों की गई हैं।
राजनीतिक क्षेत्रीय और सांप्रदायिक पर उच्च न्यायालयों को या

परिणाम के साथ अन्य आधार जो सबसे योग्य पुरुषों के पास नहीं है
नियुक्त किया गया। इसके परिणामस्वरूप इसमें कमी आई है
न्यायाधीशों के काम की बारी।

(9) ये असंतोषजनक नियुक्तियाँ की गई हैं।

इस तथ्य के बावजूद कि अधिकांश मामलों में, नियुक्तियों में प्रमुख द्वारा सहमति दी गई है

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश।

(10) राज्य कार्यपालिका के साथ परामर्श आवश्यक है।

उच्च न्यायालय में नियुक्तियाँ किए जाने से पहले।

(11) जबकि यह राज्य कार्यपालिका के लिए खुला होना चाहिए कि वह प्रमुख द्वारा प्रस्तावित नाम
पर अपनी राय व्यक्त करे। न्याय,
यह एक नामांकित व्यक्ति का प्रस्ताव करने के लिए खुला नहीं होना चाहिए

अपने दम पर और इसे केंद्र को भेजें।

(12) राज्य कार्यपालिका की भूमिका सीमित होनी चाहिए।

द्वारा प्रस्तावित मनोनीत व्यक्ति के बारे में अपनी टिप्पणी करना
मुख्य न्यायाधीश और यदि आवश्यक हो तो मुख्य न्यायाधीश से पूछें

(14) संविधान का अनुच्छेद 217 होना चाहिए
यह प्रावधान करने के लिए संशोधन किया गया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति केवल प्रमुख की
सिफारिश पर की जानी चाहिए।

उस राज्य का न्याय और प्रमुख की सहमति से
जस्टिस ऑफ इंडिया "। 38

67. उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के विपरीत

एल. सी. आई. ने उच्च न्यायालयों के लिए सुझाव दिया कि अनुच्छेद 217

संविधान को शामिल करने के लिए संशोधन किया जाना चाहिए

नियुक्ति बिना सहमति के की जा सकती है भारत के मुख्य न्यायाधीश।

. 38 अध्याय 6 अनुच्छेद 82 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

68. इस रिपोर्ट पर 23 तारीख को संसद में विचार किया गया था।

2425 नवंबर, 1959 और उस समय की सरकार ने अपना दृष्टिकोण दिया, जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने किया था। लेकिन

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 24 नवंबर को होने वाली बहस में,

1959 यह बात श्री गोविंद बल्लभ पंत, माननीय ने कही थी।

गृह मंत्री ने कहा कि 1950 से उच्च न्यायालयों में 211 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई और इनमें से

एक को छोड़कर सलाह पर, सहमति के साथ किया गया था और भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति। और सरकार द्वारा स्वीकार किए गए 211 में से 196 प्रस्तावों में

इससे जुड़े सभी व्यक्तियों का समर्थन

बात है। '39

प्रमुख की सर्वसम्मत सलाह के अनुसार
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य के मुख्यमंत्री,

भारत के राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश। वहाँ थे।
पंद्रह मामले जिनमें मतभेद था

मुख्य न्यायाधीश और मुख्यमंत्री के बीच या
राज्यपाल। इसलिए, इन मामलों को भी प्रमुख को भेजा गया था

से प्राप्त सलाह या सुझाव को स्वीकार कर लिया
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। लेकिन हम अपनी तरफ से

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह के साथ उनकी सलाह

संबंधित न्यायालय और संबंधित मुख्यमंत्री का।

इसलिए, ये मामले पाँच प्रतिशत तक भी नहीं आते हैं। लेकिन

मामले, जैसा कि मैंने कहा, एक मामले को छोड़कर जहाँ एक था
मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच मतभेद

मुख्य न्यायाधीश, हमने 210 मामलों में सलाह स्वीकार की थी

भारत के मुख्य न्यायाधीश "। 40

40 पृष्ठ 288-289 सर्वोच्च न्यायालय विज्ञापन-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

70. अगले दिन, अर्थात् 25 नवंबर, 1959 को श्री

कानून मंत्री ए. के. सेन ने दिए गए बयान को दोहराया

गृह मंत्री। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक मामले में जहां मतभेद था, सरकार ने स्वीकार किया

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह (मुख्य न्यायाधीश की नहीं)

मंत्री) भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह के बजाय। 71. चर्चा का समापन एक माननीय सदस्य के इस सुझाव के साथ हुआ कि एल. सी. आई. की सिफारिशों पर ध्यान दिया जाए

और जितनी जल्दी हो सके लागू करें।

72. इस रिपोर्ट में क्या महत्व है (इसके अलावा)

कई अन्य निष्कर्ष) यह है कि ऐसे उदाहरण थे

जहाँ न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए एक सिफारिश

उच्च न्यायालय बिना मुख्यमंत्री के बनाया गया था

मुख्य न्यायाधीश के बारे में जानकारी और प्रचार शुरू हो गया था

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए होना।

लेकिन सभी मामलों में, एक को छोड़कर, प्रमुख की सहमति

जस्टिस ऑफ इंडिया लिया गया।

(ख) 80 वीं रिपोर्ट-10.8.1979

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति

73. एल. सी. आई. की 80 वीं रिपोर्ट 10 तारीख को प्रस्तुत की गई थी।

अगस्त, 1979 और यह मुख्य रूप से न्यायमूर्ति एच. आर.

खन्ना जब इसके अध्यक्ष थे। 41

74. यह देखा गया कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका है

कानून का शासन सुनिश्चित करने के लिए बिल्कुल अपरिहार्य है। आम तौर पर

न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में, यह देखा गया कि गलत

नियुक्तियों ने न्यायालयों की छवि को प्रभावित किया है और उनमें लोगों के विश्वास को कम किया है। इसके अलावा यह

यह देखा गया कि नियुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं की गई लेकिन

पक्षपात या अन्य बाहरी विचारों के कारण हो सकता है

शायद ही बार का वास्तविक और सहज सम्मान प्राप्त हो और

41 हालांकि न्यायमूर्ति एच. आर. खन्ना ने रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए, लेकिन इसमें उनकी पूर्ण सहमति (2015) थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कि अनुचित नियुक्ति का प्रभाव न केवल इसके लिए महसूस किया जाता है इस समय लेकिन इसके प्रभाव लंबे समय बाद महसूस किए जाते हैं। 42

75. इस पृष्ठभूमि में, और नियुक्ति के संबंध में

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में से, यह निष्कर्ष निकाला गया कि (1) केवल

स्वतंत्रता, निष्पक्ष दृष्टिकोण और अलगाव के लिए सर्वोच्च प्रतिष्ठा का आनंद लेने वाले व्यक्तियों को उन्नत किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट तक। (2) किसी को भी न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय का जब तक कि उसने संबद्धता को समाप्त नहीं किया है कम से कम 7 (सात) वर्षों के लिए राजनीतिक दल। (3) एक व्यक्ति को करना चाहिए

न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए यदि उसने अपने लिए खुद को प्रतिष्ठित किया है

स्वतंत्रता, निष्पक्ष दृष्टिकोण और स्वतंत्रता

राजनीतिक पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह या झुकाव। 43

76. महत्वपूर्ण रूप से, एल. सी. आई. ने एक को अपनाने की सिफारिश की

परामर्शी प्रक्रिया जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपने तीन वरिष्ठ-अधिकांश सहयोगियों से परामर्श करना चाहिए

नियुक्ति के लिए सिफारिश। उसे प्रजनन करना चाहिए।

सिफारिश करते समय उनके विचार। यह होगा

किसी भी संभावित मनमानेपन की संभावना को कम करें या

पक्षपात। 44

77. इन सिफारिशों को शामिल किया गया था

एल. सी. आई. अपनी सिफारिशों के सारांश में। मैं चिंतित हूँ

निम्नलिखित अनुशंसा:

"(32) भारत के मुख्य न्यायाधीश, की सिफारिश करते हुए

न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति का नाम

उनके सहयोगियों ने उनके बारे में परामर्श किया
सिफारिश करें। इन सहयोगियों की भूमिका होगी

42 पैराग्राफ 2.2 से 2.5 इस संदर्भ में प्रासंगिक हैं।

43 अध्याय 7

44 यह बाद में वह बन गया जिसे आमतौर पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की 'कॉलेजियम प्रणाली' कहा जाता है-सर्वोच्च न्यायालय अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन v।

यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

की सिफारिश पर टिप्पणी करने तक सीमित रहें

मुख्य न्यायाधीश। इस तरह के परामर्श कम से कम होंगे।

संभावित मनमानेपन या पक्षपात "45

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति

78. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में

न्यायालय, यह आम तौर पर एल. सी. आई. द्वारा अध्याय 6 में देखा गया था
धारणा यह थी कि उनके

रिपोर्ट करें कि प्रचलित

नियुक्ति हमेशा योग्यता के आधार पर नहीं की गई है और यह

उच्च न्यायालयों की छवि को प्रभावित किया है। '46

79. एल. सी. आई. ने इसके लिए एक परामर्श प्रक्रिया का सुझाव दिया

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति। यह सुझाव दिया गया था

कि मुख्य न्यायाधीश को, सिफारिश करते समय,

अपने दो वरिष्ठ-अधिकांश सहयोगियों से परामर्श करें और उनके विचार व्यक्त करें।

लिखित रूप में। इसका एक 'स्वस्थ प्रभाव' होगा और काफी

संभावित पक्षपात की संभावनाओं को कम करें। यह राय दी गई थी कि मुख्य न्यायाधीश की कोई भी सिफारिश जो सहमत हो

दो वरिष्ठ-अधिकांश न्यायाधीशों को आम तौर पर स्वीकार किया जाना चाहिए। एल. सी. आई., सिद्धांत रूप में, चयन के खिलाफ था

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में व्यक्ति या

धर्म, जाति या क्षेत्र पर विचार।

80. से उत्पन्न होने वाली सिफारिशों के संबंध में

राजनीतिक कार्यपालिका ने कहा:

"एक अन्य प्रश्न जिसने ध्यान आकर्षित किया है वह है -

क्या मुख्यमंत्री की भूमिका ऐसी होनी चाहिए कि

प्रमुख द्वारा अनुशंसित नाम पर टिप्पणी करना न्याय, या क्या, यदि वह असहमत है

मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश, वह (मुख्य न्यायाधीश)

मंत्री) दूसरा नाम भी सुझा सकते हैं। यह सवाल

अतीत में उत्तेजित था, और उचित विचार के बाद

यह निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री इसके हकदार होंगे

मामला वह प्रमुख की सिफारिश से असहमत है

45 अध्याय 9

40 पैराग्राफ 5.9 [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्याय एक और नाम का सुझाव देता है। मुख्यमंत्री ने

इस तरह के आयोजन में प्रमुख की टिप्पणियों को आमंत्रित करना पड़ता है।

न्याय करें और इसके बाद मामले को साथ भेजें

केंद्रीय मंत्री को मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियां

कानून और न्याय। इस तथ्य को देखते हुए कि एक निर्णय

ऊपर उल्लिखित पहले से ही देय के बाद लिया जा चुका है
कहने की आवश्यकता नहीं है

विचार करते हुए, हमें आगे कुछ भी

बात है "। 47

81. इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, कुछ

एल. सी. आई. द्वारा किए गए संशोधन इस प्रकार थे:

"(3) नियुक्ति के लिए सिफारिश करते समय
न्यायाधीश को

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में, मुख्य

अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों से परामर्श करें। मुख्य न्यायाधीश,
अपने पत्र में, बताना चाहिए

नियुक्ति की सिफारिश करने वाले

इस तरह के परामर्श का तथ्य और उसके विचारों को इंगित करता है
परामर्श किया।

दो सहयोगियों ने इस तरह से

(4) मुख्य न्यायाधीश की कोई सिफारिश जो

अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों की सहमति रखता है

सामान्य रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए।

(7) आयोग, सिद्धांत रूप में, चयन के खिलाफ है -

धर्म, जाति या जाति के आधार पर उच्च न्यायालय की पीठ क्षेत्र। योग्यता ही एकमात्र विचार होना
चाहिए। यहां तक कि जब राज्य की नीति के मामले देने के लिए आवश्यक बनाते हैं

किसी धर्म से संबंधित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व,
जाना चाहिए।

जाति या क्षेत्र, चुनने के लिए हर संभव प्रयास किया

सबसे अच्छा व्यक्ति। ऐसी नियुक्तियों की संख्या

जितना संभव हो उतना कम होना चाहिए।

(12) इस सवाल पर कि क्या मुख्यमंत्री की भूमिका

केवल नाम पर टिप्पणी करने का होना चाहिए

मुख्य न्यायाधीश द्वारा अनुशंसित, या क्या मुख्य न्यायाधीश

मंत्री एक और नाम भी सुझा सकते हैं, एक निर्णय है

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

पहले से ही लिया गया है और आगे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है

2748

मामला "।

82. आम तौर पर, एल. सी. आई. का विचार था कि

परिवर्तन, हालांकि कुछ पहलुओं में सुधार की आवश्यकता थी। द. ऊपर वर्णित सिफारिशें उसी संदर्भ में की गई थीं।

(ग) 121 वीं रिपोर्ट-31.7.1987
नियुक्तियों के लिए एक नया मंच

न्यायिक

83. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह रिपोर्ट तैयार की गई थी

एस. पी. गुप्ता में इस न्यायालय के निर्णय के बाद। अपनी 121 वीं रिपोर्ट में,

एल. सी. आई. ने नोट किया कि पिछले चार दशकों में, बढ़ते हुए

विधि और रणनीति पर असंतोष व्यक्त किया गया है। उच्चतर न्यायपालिका के लिए चयन और चयनकर्ता। 49

इसके अलावा, अपनी रिपोर्ट के अनुच्छेद 7.1 में, एल. सी. आई. ने उल्लेख किया कि

उच्च न्यायपालिका में भर्ती के लिए तंत्र विफल रहा है सामान पहुँचाएँ। 'यह कार्यपालिका के संदर्भ में था

न्यायाधीशों की नियुक्ति में प्रधानता सिद्धांत

एसपी गुप्ता। इसे ध्यान में रखते हुए एल. सी. आई. ने राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग नामक एक नए व्यापक मॉडल की सिफारिश की। 50

84. एल. सी. आई. ने पाया कि दो मॉडल उपलब्ध थे

न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। पहला मौजूदा मॉडल था

जिसने कार्यपालिका को चयन में प्रमुख शक्तियाँ प्रदान कीं

और न्यायाधीशों की नियुक्ति। लेकिन, संविधान का अनुच्छेद 50

कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच अलगाव को अनिवार्य करता है। दूसरे मॉडल में डाइलूटिंग शामिल था (अलग नहीं)।

अधिक लोगों को जोड़कर कार्यपालिका का अधिकार निर्णय लेने की प्रक्रिया और एक निकाय की स्थापना जिसमें

न्यायपालिका का एक पूर्व-प्रतिष्ठित स्थान होता है। यह प्रतिभागी

48 अध्याय 9 49 अध्याय 1 अनुच्छेद 1.4।

50 पैराग्राफ 7.8 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

मॉडल को एल. सी. आई. द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक सेवा कहा गया था। आयोग।

85. आयोग की परिकल्पना एक बहु-सदस्य के रूप में की गई थी।

भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में निकाय जिसका 'पूर्व-प्रतिष्ठित' पद में उनके पूर्ववर्ती को बिल्कुल भी कमजोर नहीं किया जाना चाहिए,

तीन वरिष्ठ-उच्चतम न्यायालय के अधिकांश न्यायाधीश, तीन मुख्य न्यायाधीश

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश अपनी वरिष्ठता के क्रम में, कानून

सिफारिश, यह उपयुक्त रूप से संशोधन करने के लिए प्रस्तावित किया गया था संविधान। 51

86. एल. सी. आई. की सिफारिश आंशिक रूप से थी

तत्कालीन सरकार और संविधान द्वारा स्वीकार किया गया (67 वां संशोधन) विधेयक, 1990 में पेश किया गया था।

संसद। इसे थोड़ी देर बाद बताया जाएगा।

बकाया समिति-1989-90
दिसंबर, 1987 के बीच एक सम्मेलन

87. 11 और 13

मुख्य न्यायाधीशों को भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ आयोजित किया गया था कुर्सी।
सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई

उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में मामलों के बकाया के लिए

बकाया राशि और यह अधिकांश मुख्य न्यायाधीशों द्वारा इंगित किया गया था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी इसके लिए जिम्मेदार है

बकाया राशि। सिफारिशें भेजे जाने के बाद भी, प्रमुख न्याय के लिए सरकार को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है

नियुक्ति के परिणामस्वरूप कई वर्षों से न्यायालय अपनी क्षमता के लगभग 50 प्रतिशत के साथ काम कर रहे हैं।

88. मामले की विस्तृत चर्चा के बाद, यह था

पूरी तरह से मुख्य न्यायाधीशों की एक समिति नियुक्त करने का निर्णय लिया

51 पैराग्राफ 7.10 और 7.15 शीर्ष अदालतें-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

उठाए गए मुद्दों की जांच करें और एक प्रस्ताव पारित किया गया
रचना

ऐसी समिति की नियुक्ति की

बकाया समिति नामक समिति को बदल दिया गया

समय की अवधि लेकिन अंत में इसमें मुख्य न्यायाधीश बी. एस.

मलिमथ (केरल उच्च न्यायालय), मुख्य न्यायाधीश पी. डी. देसाई
मुख्य न्यायाधीश डॉ. A.S.Anand (मद्रास

(कलकत्ता उच्च न्यायालय) और

उच्च न्यायालय)। बकाया समिति ने अपनी रिपोर्ट दो भागों में दी।

31 तारीख के बीच आयोजित मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन के खंड

अगस्त और 2 सितंबर, 1990 ने रिपोर्टों को स्वीकार किया, कुछ संशोधनों के अधीन।

89. रिपोर्ट के खंड 2 का अध्याय 5 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की असंतोषजनक नियुक्ति से संबंधित है।
यह.

बकाया समिति द्वारा देखा गया कि असंतोषजनक

नियुक्तियों ने बड़े पैमाने पर योगदान दिया है
देखा गया

उच्च न्यायालयों में बकाया राशि का संचय। यह

ईमानदारी, उपयुक्तता और क्षमता के लिए प्रतिष्ठा के साथ-साथ केवल योग्यता और योग्यता ही मानदंड होना
चाहिए

न्यायाधीशों और न्यायाधीशों का चयन जो उस आधार पर नहीं चुने गए हैं या

जिन्हें योग्यता के अलावा अन्य विचारों पर नियुक्त किया जाता है,

निष्पक्ष और निष्पक्ष रूप से कार्य करने में सक्षम नहीं होना। यह उल्लेख किया गया है कि

यही कारण है कि न्यायाधीशों का चयन पूरी क्षमता के साथ किया जाना चाहिए।

देखभाल और चिंता। 52

90. बकाया समिति ने भी रिपोर्ट पर विचार किया

सतीश चंद्र समिति द्वारा हाल ही में दिया गया

जो इस बात की पुष्टि करता था कि कुछ न्यायाधीशों ने नहीं किया है

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सीधे सिफारिश की गई थी न्यायालय लेकिन उच्च न्यायालय पर थोपा गया है और यदि यह यह प्रवृत्ति जारी रही, मुख्य न्यायाधीश के लिए यह बहुत मुश्किल होगा न्यायालय के न्यायिक कार्य को प्रभावी ढंग से संचालित करना। 53

91. इसके बाद, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का चयन योग्यता के अलावा अन्य कारणों पर चर्चा की गई और यह था निम्नलिखित रूप में देखा गया:

52 अनुच्छेद 5.1

53 पैराग्राफ 5.4 [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

"एक व्यक्ति का चयन, इसके अलावा अन्य विचारों पर

जो स्पष्ट रूप से आंख से मिलता है उससे अधिक नुकसान। इस तरह की प्राप्त नहीं करता है

नियुक्त व्यक्ति सदस्यों से भी

बार सम्मान और सहयोग का माप है जो

न्याय के उचित प्रशासन के लिए अनिवार्य है। वह हो सकता है

खुद पर भी विश्वास न रखें और खुद पर नियंत्रण रखें

न्यायालय की कार्यवाही। यह सब होगा

न्याय के उचित प्रशासन की लागत। इसका असर होगा

न केवल गुणवत्ता पर बल्कि मात्रा पर भी महसूस किया जाए

काम निकल गया।

सतीश चंद्र समिति के अनुसार, समुद्र

प्रक्रिया गंभीर गिरावट के लिए सीधे जिम्मेदार है

और नियुक्तियों के उच्च मानकों में गिरावट

उच्च न्यायालय की पीठ ने पहले बनाए रखा। छोड़ दें।

अपवाद के तौर पर, आज के मुख्यमंत्री सोचने लगे हैं

कि उच्च न्यायालय की पीठ में रिक्तियों को भी भरना है
 संरक्षण का मामला, चाहे वह राजनीतिक हो या अन्यथा। यह देखा गया।
 कि बार के पूर्व सदस्यों को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया गया था
 न्यायाधीश-जहाज। अब ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
 प्रचार के लिए एक पद बन गया है। यह पाया गया
 कि जब तक राज्य कार्यपालिका का प्रभावी हाथ है
 इस तरह की नियुक्तियों में, यह परेशान करने वाली विशेषता होगी जारी रखें और इसे केवल
 प्रदान करके ठीक किया जा सकता है
 कार्यपालिका की सुरक्षा में कोई अंतिम कहना नहीं है
 नियुक्ति का मामला और मामले में अंतिम शब्द
 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का होना चाहिए
 संबंधित और भारत के मुख्य न्यायाधीश। द. अतः समिति ने संशोधन का सुझाव दिया
 संविधान, गुणवत्ता सुनिश्चित करने की गारंटी के रूप में, कि उच्च न्यायालय में नियुक्ति होनी
 चाहिए
 भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति और नहीं होनी चाहिए केवल उसके साथ परामर्श करके
 किया जाए।

एक संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

संविधान के अनुच्छेद 217 (1) का सुझाव दिया गया था

उन पंक्तियों "। 54

92. यह निष्कर्ष निकाला गया कि न्यायिक प्रणाली के प्रभावी ढंग से काम करने और लोगों को इसमें विश्वास रखने के लिए,

न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल इस पर की जानी चाहिए

योग्यता, उपयुक्तता, सत्यनिष्ठा और क्षमता पर विचार और

राजनीतिक लाभ या क्षेत्रीय या सांप्रदायिकता पर नहीं

भावनाएँ। इस संबंध में यह निम्नलिखित रूप में देखा गया:

"इस समिति का दृढ़ मत है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि

न्यायिक प्रणाली प्रभावी ढंग से कार्य करती है और बनाए रखने के लिए
 न्यायिक कार्य की गुणवत्ता और मात्रा दोनों के साथ-साथ जनता का विश्वास और विश्वास, नियुक्तियाँ
 केवल योग्यता, उपयुक्तता के विचार पर किया जाए,
 सत्यनिष्ठा और क्षमता और राजनीतिक औचित्य की नहीं या
 क्षेत्रीय या सांप्रदायिक भावनाएँ। आशंका यह है कि
 उसके द्वारा की गई सिफारिश पूरी नहीं हो सकती है
 कार्यपालिका की मंजूरी, कभी-कभी एक प्रेरित कर सकती है
 मुख्य न्यायाधीश एक ऐसे व्यक्ति का नाम प्रस्तावित करेंगे जो ऐसा करता है
 अपेक्षित मानक तक नहीं मापा जाता है, जो बल्कि है
 दुर्भाग्यपूर्ण है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए यह मौलिक है कि वह खतरों से मुक्त हो
 और किसी भी हिस्से से दबाव। यह राज्य का कर्तव्य है
 यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायपालिका का अधिकार है, और यह देखा जाता है कि
 कब्जा, राजनीति में ऐसी स्थिति है कि यह प्रभावी रूप से कर सकते हैं
 संविधान द्वारा उसे सौंपे गए कार्यों का पालन करना और यह केवल तभी किया जा सकता है जब नियुक्ति की
 प्रक्रिया

अप्रदूषित छोड़ दिया गया है "। 55

93. नियुक्ति की मौजूदा प्रणाली पर टिप्पणी करना

न्यायाधीशों की बकाया समिति ने प्रणाली की समीक्षा की
 रिपोर्ट का अध्याय 6। अन्य बातों के अलावा यह देखा गया था
 कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली आपके दशकों से प्रचलित थी और यह इतने लंबे समय से संतोषजनक
 रूप से काम कर रही थी

54 पैराग्राफ 5.5 और 5.6

55 पैराग्राफ 5.8 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

स्थापित सम्मेलनों का भी सम्मान किया गया और उनका पालन किया गया
 प्रणाली नहीं है जो विफल हो गई है, बल्कि वे हैं जो काम कर रहे हैं

और यह कि यह

इसे विकृत करने की अनुमति देकर इसे विफल कर दिया था। यह देखा गया

इस प्रकार है:

"न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान प्रणाली

उच्च न्यायालय लगभग चार दशकों से प्रचलन में हैं। यह

संतोषजनक रूप से कार्य किया जब तक कि अच्छी तरह से स्थापित

लेकिन व्यवस्थित उल्लंघन और आभासी विनाश
पिछले दो दशकों या उससे अधिक समय के सम्मेलनों

वर्तमान दुर्भाग्य के लिए अनिवार्य रूप से जिम्मेदार

स्थिति। क्या सिस्टम विफल हो गया है या है

संबंधित विफल प्रणाली एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।
यह स्पष्ट है कि प्रणाली विफल नहीं हुई है, लेकिन वे सभी

प्रणाली के संचालन से संबंधित इसे विफल कर दिया है

इसे विकृत होने दें "। 56

94. प्रक्रिया ज्ञापन से निपटते समय

न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उस समय मौजूद,

बकाया समिति अपनी टिप्पणियों में बल्कि कठोर थी

प्रभाव कि ऐसे मामले थे जहाँ वहाँ था

भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के बीच समझौता
राज्य के राज्यपाल का लेकिन

संबंधित उच्च न्यायालय और

केंद्रीय कानून मंत्री या तो ऐसा नहीं करने का विकल्प चुनते हैं

नियुक्ति या नियुक्ति में अत्यधिक देरी। यह था।

यह देखा गया कि कभी-कभी केंद्रीय कानून मंत्री ने एक

इस संबंध में राजनीतिक हस्तक्षेप और अवांछनीय प्रभाव
संवैधानिक प्राधिकरणों की।

न्यायाधीशों की नियुक्ति में अतिरिक्त-

इसलिए नियुक्ति प्रक्रिया को कमजोर कर दिया गया और कार्यपालिका को न्यायाधीशों की नियुक्ति उत्कृष्टता
के आधार पर नहीं बल्कि उनके आधार पर करनी पड़ी।

प्रभाव पड़ता है। इसे इस प्रकार देखा गया:

56 पैराग्राफ 6.11 सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

"ऐसे मामले हैं जहाँ मुख्य न्यायाधीश परामर्श किए जाने पर भारत सहमत है
मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई सिफारिश संबंधित उच्च न्यायालय जो द्वारा भी सहमत है
राज्य के राज्यपाल और अपनी सिफारिश को आगे बढ़ाते हैं
केंद्रीय कानून मंत्री के लिए, नियुक्तियाँ या तो नहीं हैं

अत्यधिक देरी के बाद किया गया या बनाया गया। कभी-कभी,

चयनकर्ताओं की सूची से न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की नीति उच्च न्यायालय के मुख्य
न्यायाधीश द्वारा विधिवत सिफारिश की गई

भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सहमति या बनाता है

नियुक्तियाँ उस क्रम को बाधित करके की जाती हैं जिसमें

सिफारिशों की गई हैं। बीमारी है

राजनीतिक हस्तक्षेप को देखते हुए अधिक तीव्र हो जाता है

और "अतिरिक्त संवैधानिक" का अवांछनीय प्रभाव न्यायाधीशों की नियुक्ति में अधिकारी। इस प्रकार,

भारत के मुख्य न्यायाधीश का अधिकार और उनकी भूमिका के मामले में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश

न्याय "उत्कृष्टता" पर नहीं बल्कि "प्रभाव" पर होता है। इस प्रकार, योग्यता, क्षमता और उपयुक्तता जो निस्संदेह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्याय करने के लिए सबसे उचित व्यक्ति हैं,

राजनीतिक या अन्य औचित्य की वेदी पर बलिदान दिया जाता है। यह मनोवृत्ति अनिवार्य रूप से गिरावट के लिए जिम्मेदार है

और नियुक्तियों के उच्च मानकों में गिरावट

उच्च न्यायालय की पीठें। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन बिल्कुल सच है,

कि मुख्यमंत्री सोचने लगे हैं और केंद्रीय कानून मंत्री को विश्वास हो गया है कि रिक्तियों में

उच्च न्यायालय की पीठ राजनीतिक संरक्षण का मामला है जो

वे अपने पसंदीदा को वितरित या वितरित करने के हकदार हैं।

कार्यपालिका के साथ इस बीटो शक्ति ने तबाही मचाई है

न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला। 57

ग्राफ 6.9 [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

95. अपनी सिफारिशों में, बकाया समिति

कार्यपालिका की भूमिका को कमजोर करने की सिफारिश की गई और

नियुक्ति की मौजूदा प्रणाली से बचने के उपाय

विकृत किया जा रहा है। निम्नलिखित रूप में इसकी सिफारिश की गई थी:

"नियुक्ति के मामले में कार्यपालिका की भूमिका

न्यायाधीशों को कमजोर किया जाना चाहिए और अधिकांश के लिए कारण

वर्तमान प्रणाली के कामकाज में खामियां हो सकती हैं

कार्यपालिका की वीटो शक्ति का पता लगाया। यह,

वास्तव में, यह सुनिश्चित करके ठीक किया जा सकता है
सहमति प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 217 में संशोधन

भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करने के बजाय

उसे, उच्च के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में

अदालतें "। 58

" समिति का विचार है कि

वर्तमान

संवैधानिक योजना जो संस्थापक द्वारा तैयार की गई थी

पिता बहुत विचार-विमर्श और बहुत चिंतन के बाद आंतरिक रूप से सही हैं और यह कि यह सच्ची
भावना में काम करता है

इसमें किसी आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। रक्षा करने के लिए

में प्रकट विकृति के खिलाफ और दूर करें

योजना का संचालन, समिति ने किया है

उपयुक्त सिफारिशें। समिति का मानना है कि

यदि इन सिफारिशों को लागू किया जाता है, तो

इसे किसी अन्य द्वारा प्रतिस्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है

तंत्र। 159

96. प्रणाली के तीखे अभियोग को देखते हुए

न्यायाधीशों की नियुक्ति जहां कार्यपालिका का अंतिम अधिकार था

शक्ति '60 जिसका दुरुपयोग किया जा रहा था और ले जाने के लिए विकृत किया जा रहा था

न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इरादे के विपरीत संविधान सभा, न्यायाधीशों की नियुक्ति के पूरे मुद्दे पर नए सिरे से विचार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और

58 अनुच्छेद 124

59 अनुच्छेद 130

60 इस अभिव्यक्ति का उपयोग न्यायमूर्ति भगवती और न्यायमूर्ति डी. ए. देसाई ने एस. पी. गुप्ता बनाम के अनुच्छेद 719 में किया था। भारत संघ।

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

जिसके कारण अंततः इस मुद्दे को 1990 के दशक की शुरुआत में संदर्भित किया गया इस न्यायालय के 9 (नौ) न्यायाधीशों की पीठ को। साफ तौर पर,

कार्यपालिका ने न्यायाधीशों की नियुक्ति में गड़बड़ी की थी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को नष्ट करने के लिए कदम उठाए, चले गए

संविधान सभा के विचारों के खिलाफ और इस तरह से कार्य किया कि एक जिम्मेदार कार्यपालक को नहीं करना चाहिए।

97. स्वतंत्रता के बाद 1990 के दशक की शुरुआत तक न्यायपालिका

न्यायाधीशों की नियुक्ति। यह कार्यपालिका के रूप में था उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को व्यक्तियों की सिफारिश करना

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए। वहाँ थे।

ऐसे अवसर जब कार्यपालिका पूरी तरह से प्रमुख को पारित कर देती है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और सीधे अनुशंसित व्यक्ति

न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को। कार्यपालिका द्वारा अपनाया गया तीसरा कदम रोक देना था।

मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई सिफारिशें और इसके बजाय

केंद्र सरकार को अपनी सिफारिश भेजें।

चौथा तरीका था स्वीकृत सिफारिशों को फिर से खोलना। किसी न किसी बहाने से। पाँचवाँ तरीका मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई सिफारिश पर कार्रवाई में देरी करना था।

98. दुखद रूप से, इस दौरान की गई लगभग सभी नियुक्तियाँ

इस अवधि में सहमति थी (एक संवैधानिक सम्मेलन के रूप में)

भारत के मुख्य न्यायाधीश की और फिर भी, आलोचना की गई थी कुछ नियुक्तियाँ की गईं।
जबकि स्वतंत्रता

न्यायपालिका को कानून में बनाए रखा गया था, धीरे-धीरे इसका क्षरण हो रहा था

नियुक्ति के माध्यम से भीतर से और बाहर से दोनों

एल. सी. आई. की 14 वीं रिपोर्ट आम तौर पर आलोचनात्मक थी उच्च न्यायालयों में की गई
नियुक्तियाँ और इस संबंध में

एल. सी. आई. द्वारा एकत्र की गई जानकारी पर निर्भरता रखी गई थी

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों सहित विभिन्न स्रोत। यह सच है कि एल. सी. आई. की 80 वीं रिपोर्ट में कुछ भी गंभीर रूप से गलत नहीं पाया गया न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली के साथ, लेकिन फिर भी इसके लिए [2015] 13 एस. सी. आर. की आवश्यकता थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

परिवर्तन करें। हालाँकि, बकाया समिति का उपहास किया गया था

न्यायाधीशों की नियुक्ति की मौजूदा प्रणाली और कुछ मौजूदा प्रणाली के भीतर सकारात्मक
सिफारिशें, जबकि

एल. सी. आई. की 121 वीं रिपोर्ट ने थोक परिवर्तनों का सुझाव दिया।

99. ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में यह चर्चा इंगित करती है

कि न्यायाधीशों की नियुक्ति एक महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है

न्यायपालिका की स्वतंत्रता में वास्तविक अर्थों में

अवधि। अगर न्यायाधीश राजनीतिक विचारों से प्रभावित हो सकते हैं

केवल वेतन, भत्ते, शर्तें सुरक्षित करके स्वतंत्र ऐसे न्यायाधीशों की सेवा और पेंशन। मांस में है

न्यायाधीशों की क्षमता और उनके भत्ते नहीं।

100. संविधान के समक्ष अपने समापन भाषण में

26 नवंबर, 1949 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद की सभा

न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लेख किया और यह था कही:

"हमने संविधान में एक ऐसी न्यायपालिका का प्रावधान किया है जो स्वतंत्र होगी। कुछ भी सुझाव देना मुश्किल है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय बनाने के लिए अधिक

कार्यपालिका के प्रभाव से स्वतंत्र। वहाँ है।

किसी भी बाहरी या बाहरी से स्वतंत्र निचली न्यायपालिका प्रभाव पड़ता है। हमारा एक लेख राज्य के लिए इसे आसान बनाता है।

सरकारें कार्यपालिका को अलग करने की शुरुआत करेंगी

न्यायिक कार्य और मजिस्ट्रेट की नियुक्ति जो कार्य करती है

दीवानी अदालतों के समान आपराधिक मामलों के साथ। आई.

केवल यह आशा व्यक्त कर सकते हैं कि यह लंबे समय से लंबित सुधार

इसे जल्द ही राज्यों में पेश किया जाएगा। " 61

101. एक स्वतंत्र न्यायपालिका प्रदान करना पर्याप्त नहीं है।

- नियुक्ति के माध्यम से प्राप्त गुणवत्तापूर्ण न्याय तक पहुंच

स्वतंत्र न्यायाधीशों का होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कहा गया है कि

61 एचटीटीपी: //भारत की संसद। ठीक है। /ls/डिबेट/वॉल्यूम 11p12 में।

एच. टी. एम. सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के दौरान न्यायाधीश:

"अब रंगभेद के दौरान न्यायाधीशों के पास औपचारिक गारंटी थी

स्वतंत्रता जीवन कार्यकाल, वेतन, प्रशासनिक

स्वायत्तता-जो संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायाधीश हैं,

कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया था। यह देखने में है कि ऐसा क्यों था कि रंगभेद-युग

न्यायाधीशों के पास अधिकांश भाग के लिए स्वतंत्रता का भी अभाव था

हालाँकि उनके पास अपने औपचारिक जाल थे जो हम देखते हैं कि न्यायिक स्वतंत्रता भी एक प्रकार की निर्भरता है। कुछ सकारात्मक पर निर्भर करता है-न्यायिक खोज कानून का न्याय। किसी को सिर्फ यह नहीं पूछना है कि कौन से न्यायाधीश स्वतंत्र होने के लिए इससे बचना होगा, लेकिन जिसके लिए हम चाहते हैं कि वे स्वतंत्र रहें। 62

102. यह समीक्षा इंगित करती है कि एक महत्वपूर्ण कानून के शासन और स्वतंत्रता की विशेषताएँ न्यायपालिका नियुक्ति प्रक्रिया है। इसलिए यह आवश्यक है। स्वतंत्रता के बाद नियुक्ति प्रक्रिया के विकास और न्यायपालिका के समझने के तरीके की निष्पक्ष रूप से सराहना करना।

यह।

न्यायिक घोषणाएँ

103. न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रश्न (मुख्य रूप से उच्च न्यायालयों के) इस न्यायालय में विचार के लिए आए गया निर्णय तीन बार। इनमें से प्रत्येक मामले में दिया

न केवल काफी महत्व का है, बल्कि यह भी इंगित करता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में जटिलता और संघर्ष न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए बार कार्यकारी हस्तक्षेप और अतिक्रमण। ये हैं तीन मामले

न्यायाधीशों का मामला 64 और तीसरे न्यायाधीशों का मामला। 65 वहाँ है। 62 न्यायिक स्वतंत्रता, संक्रमणकालीन न्याय और डेविड डाइजेनहॉस द्वारा कानून का शासन, (2001-2004) 10 ओटागो एल रेव 345 345-346 पर

63 एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ, 1981 पूरक एस. सी. सी. 87 (सात न्यायाधीशों की पीठ) 64 उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम। भारत संघ, (1993) 4 एस. सी. सी. 441 (नौ न्यायाधीशों की पीठ)

65 1998 का विशेष संदर्भ सं. 1 (1998) 7 एस. सी. सी. 739 (नौ न्यायाधीशों की पीठ)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

इस विषय पर अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं और वे उचित स्तर पर विचार किया जाएगा।

प्रथम न्यायाधीश का मामला-30.12.1981।

104. प्रथम न्यायाधीशों का मामला कई लोगों के लिए महत्वपूर्ण है।

कारण हैं, लेकिन मैं उनमें से कुछ के बारे में चिंतित हूँ। ये हैं: (1)

न्यायपालिका की स्वतंत्रता को इसका एक हिस्सा माना गया था संविधान की मूल विशेषता। 66
यह पहला फैसला था
रखने के लिए।

(2) न्यायाधीश की नियुक्ति गंभीर व्यवसाय है और स्वतंत्रता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक के रूप में मान्यता प्राप्त है न्यायपालिका से। आवश्यक है कि ऐसे न्यायाधीश हों जो नए उपकरण बनाने, नए तरीके बनाने, नवाचार करने के लिए तैयार नई रणनीतियाँ और एक नया न्यायशास्त्र विकसित करना, जो न्यायिक हैं एक सामाजिक दृष्टि और एक रचनात्मक संकाय वाले राजनेता और जो सबसे बढ़कर, संविधान के प्रति प्रतिबद्धता की गहरी भावना है

सत्ता में किसी भी दल के लिए, न विपक्ष के लिए और न ही वर्गों के लिए जो मुखर हैं लेकिन
आधे-भूखे भारत के लाखों लोगों के लिए जो

उन्हें लगातार अपने बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित किया जाता है। हमें जरूरत है।

ऐसे न्यायाधीश जो भारतीय जीवन की सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं के प्रति जीवित हैं, जो हर आंख से हर आँसू पोंछने के लिए उत्सुक हैं, जो

संवैधानिक मूल्यों में विश्वास रखें और जो इसके लिए तैयार हैं

संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साधन के रूप में कानून का उपयोग करें

उद्देश्य। यह नियुक्ति का व्यापक खाका होना चाहिए।

न्यायिक सेवा के उच्च स्तरों के लिए परियोजना। यह केवल तभी है जब

न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ इन बातों को ध्यान में रखते हुए की जाती हैं।

मुख्य रूप से नियुक्ति प्राधिकरण के साथ वजन करना कि हम

वास्तव में एक स्वतंत्र न्यायपालिका हो सकती है जो केवल लिए। '67 न्याय

संविधान और भारत के लोगों के

न्यायपालिका की स्वतंत्रता केवल पद से संबंधित है कई फैसलों में इस विचार को बरकरार रखा गया है।

66 पैराग्राफ 27, 320 और 634। इसके बाद

67 पैराग्राफ 27 सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

नियुक्ति और यह कि 'यह मानना मुश्किल है कि केवल इसलिए कि नियुक्ति की शक्ति कार्यपालिका के पास है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी। द.

सही सिद्धांत यह है कि इस तरह की नियुक्ति के बाद कार्यपालिका

न्यायाधीश के कार्य में हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। '68

(3) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में

या उच्च न्यायालय, अनुच्छेद में आने वाला 'परामर्श' शब्द

124 (2) और संविधान के अनुच्छेद 217 (1) का मतलब यह नहीं है

'सहमति'। 69 तथापि, परामर्श के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक और समान तथ्य होने चाहिए।

संवैधानिक पदाधिकारी के पास पूर्ण

न्यायाधीश की नियुक्ति और परामर्श से संबंधित

इस समान सामग्री पर आधारित होना चाहिए। 70

(4) के बीच असहमति की स्थिति में

संवैधानिक अधिकारियों से परामर्श करने की आवश्यकता है सरकार तय करेगी

एक न्यायाधीश की नियुक्ति, केंद्र

किसकी राय स्वीकार की जानी चाहिए और क्या

भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय को कोई प्राथमिकता नहीं है। 71 द. 'उच्चतर न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की अंतिम शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है। 72 (यह पूरी तरह से विपरीत है।

संविधान सभा और डॉ. अम्बेडकर के दृष्टिकोण से)।

(5) न्यायाधीशों की नियुक्ति की मौजूदा प्रणाली एक नहीं है

नियुक्ति की आदर्श प्रणाली। एक सलाहकार पैनल का विचार (एक कॉलेजियम या न्यायिक आयोग कहा जाता है) के रूप में शुरू किया गया था

प्रतिस्थापन। इस निकाय में अपेक्षित व्यक्ति शामिल होने थे।

उन व्यक्तियों का ज्ञान होना जो नियुक्ति के लिए उपयुक्त हो सकते हैं

पीठ पर और ऐसी नियुक्ति के लिए आवश्यक गुणों के अधिकारी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने इस विचार पर केंद्रित कि एक न्यायिक व्यवस्था होनी चाहिए

68 पैराग्राफ 1033

69 अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 890

71 अनुच्छेद 30

72 पैराग्राफ 30 [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्च न्यायपालिका की नियुक्ति के लिए आयोग। '73

संयोग से, हमें सुनवाई के दौरान सूचित किया गया था

कि प्रथम न्यायाधीशों में निर्णय के लगभग 35 साल बाद भी

न तो ऑस्ट्रेलिया और न ही न्यूजीलैंड ने एक मामला स्थापित किया है

न्यायिक आयोग अभी तक।

105. प्रयोजनों के लिए 'परामर्श' के अर्थ पर

संविधान के अनुच्छेद 124 (2) और अनुच्छेद 217 (1) के अनुसार,

भगवती, जिन्होंने बहुमत के लिए बात की, ने भारत संघ बनाम पर भरोसा किया। संकलचंद हिम्मतलाल सेठ 74 और आर. पुष्पम

वी. मद्रास 75 राज्य का मानना है कि:

"प्रत्येक संवैधानिक पदाधिकारी को होना आवश्यक है

इन दो अनुच्छेदों के तहत परामर्श उसके लिए होना चाहिए

पूर्ण और समान तथ्यों पर विचार करना
व्यक्ति की नियुक्ति या गैर-नियुक्ति

एक न्यायाधीश के रूप में संबंधित और उनमें से प्रत्येक की राय

समान सामग्री पर लिए जाने पर विचार किया जाना चाहिए

केंद्र सरकार निर्णय लेने से पहले कि क्या
या संबंधित व्यक्ति को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त नहीं करना। 76

106. प्रथम न्यायाधीशों के मामले में बहुमत का विचार था

द्वितीय न्यायाधीशों के मामले में खारिज कर दिया गया और यह अभिनिर्धारित किया गया कि

'संविधान के अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 124 में 'परामर्श'

इसका मतलब था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में 'प्रधानता' होनी चाहिए

भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ। कॉलेजियम का विकास

प्रणाली और एक न्यायिक आयोग पर थोड़ी चर्चा की जाएगी।
जाना चाहिए कि इसके बीज थे

बाद में, हालांकि यह ध्यान दिया

प्रथम न्यायाधीशों में बोया गया (एल. सी. आई. की रिपोर्टों के अलावा)

मामला।

107. मुझे नहीं लगता कि पहले पर आगे चर्चा करने की आवश्यकता है।

73 पैराग्राफ 30 और 31 74 (1977) 4 एस. सी. सी. 1993 (पांच न्यायाधीशों की पीठ) 75 ए. आई. आर.
1953 मद 392

76 अनुच्छेद 30

"मैं न्यायमूर्ति चेलमेश्वर के इस कथन से पूरी तरह सहमत हूं कि दूसरे न्यायाधीश के मामले में यह नहीं माना
गया था कि परामर्श का अर्थ सहमति है।

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

न्यायाधीशों का मामला क्योंकि इस पर विस्तृत रूप से विचार किया गया है

न्यायमूर्ति खेहर।

सुभाष शर्मा का मामला

108. इस न्यायालय में दायर एक रिट याचिका में भरने का अनुरोध किया गया है

उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की रिक्तियों को बढ़ाना और कई

देश के उच्च न्यायालयों की तीन न्यायाधीशों की पीठ थी -

विचार है कि प्रथम न्यायाधीशों के मामले में पुनर्विचार की आवश्यकता है। 78 यह.

यह देखा गया कि बहुमत का निर्णय न केवल अस्वीकार करता है

भारत के मुख्य न्यायाधीश की प्रधानता लेकिन यह भी कम हो जाती है

'परामर्श' का महत्व।

109. यह उल्लेख किया गया कि संविधान (साठवां संशोधन) विधेयक, 1990 विचाराधीन था।

संसद और उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य

संशोधन अधिनियम ने स्वीकार किया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की मौजूदा प्रणाली की आलोचना की गई थी (जहां

कार्यपालिका की प्रधानता थी) और इसके लिए परिवर्तन की आवश्यकता थी, इसलिए

एक संशोधन Act.79 की आवश्यकता

110. न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यकारी हस्तक्षेप के मुद्दे पर पीठ ने पाया कि हस्तक्षेप चला गया

नियुक्ति को अनिवार्य रूप से फिर से खोलने की सीमा तक

प्रक्रिया भले ही नियुक्ति के लिए एक सिफारिश हो

एक न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा स्वीकार किया गया था। यह.

यह देखा गया:

"भारत संघ द्वारा दायर हलफनामों से और

विद्वान महान्यायवादी द्वारा दिए गए बयान

अलग-अलग मौकों पर जब मामले की सुनवाई हुई तो हमने पाया कि केंद्र सरकार ने ऐसा किया था। की नीति को अपनाया

फिर से खोलने की सिफारिशें भले ही वही थीं

आधार पर भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा मंजूरी दी गई

कि इस बीच में एक बदलाव आया था

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्मचारी या

78 सुभाष शर्मा बनाम। भारत संघ, 1991 का उपबंध (1) एस. सी. सी. 574 79 अनुच्छेद 27 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

राज्य के मुख्यमंत्री। व्यक्ति का चयन

न्यायाधीश के पास मुख्य न्यायाधीश के लिए कुछ भी व्यक्तिगत नहीं होता है।

उच्च न्यायालय या राज्य के मुख्यमंत्री। द.

उच्च न्यायालय राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान है जिसमें

न्यायाधीश के रूप में नियुक्त व्यक्ति में कार्य करता है

अवैयक्तिक ढंग से। चयन प्रक्रिया का उद्देश्य है

पता लगाने की दृष्टि से पूरी तरह से ईमानदार और ईमानदार होना
रिक्ति के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति। अगर एक दिए गए में

मामला उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास है

अनुशंसित और नाम पर विचार किया गया है

मुख्यमंत्री और इसके माध्यम से विधिवत संसाधित

राज्यपाल ताकि मुख्य न्यायाधीश के हाथों तक पहुँच सकें
न्याय मंत्रालय और भारत के मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से भारत के सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण के रूप में

देश ने अपने दिमाग के उचित उपयोग पर, अंतिमता दी है

उसके स्तर पर प्रक्रिया के लिए, आम तौर पर कोई नहीं हो सकता है

केवल इसलिए मामले को फिर से खोलने का औचित्य

प्रमुख के कर्मियों में बदलाव किया गया है

न्याय या संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री "। 80

111. उपरोक्त के अलावा, पीठ का विचार था

कि प्रथम न्यायाधीशों में बहुमत द्वारा दी गई व्याख्या

'परामर्श' के मामले में सही ढंग से सराहना नहीं की गई थी
किया गया कि भूमिका

संवैधानिक योजना। यह भी महसूस

प्रथम न्यायाधीशों के मामले में संवैधानिक योजना में भारत के मुख्य न्यायाधीश की संस्था को अस्वीकार कर
दिया गया था। रखते रहें।

इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से

नियुक्ति प्रक्रिया और संघ की स्वीकृति

सरकार को एक बदलाव की आवश्यकता थी, यह देखा गया:

" भगवती, जे., फजल अली, जे., देसाई, जे., द्वारा लिया गया दृष्टिकोण।

और जे. वेंकटरमैया, जिनका हम वर्तमान में विज्ञापन करेंगे,

हमारी राय में, न केवल गंभीर रूप से विचलित करता है और स्थिति की प्रधानता को नकारता है, जिसमें निहित है

80 पैराग्राफ 28 सुप्रीम कोर्ट के वकील-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

भारत के मुख्य न्यायाधीश की संवैधानिक योजना परामर्श प्रक्रिया लेकिन यह भी बहुत कम कर देता है

आवश्यकतानुसार "परामर्श" का महत्व संवैधानिक योजना और संदर्भ में समझा गया। यह

पदार्थ और प्रक्रिया दोनों पर असर पड़ता है

संवैधानिक योजना के अनुरूप

संवैधानिक उद्देश्य और प्रक्रिया यह बन जाता है

अनिवार्य है कि प्रमुख की संस्था की भूमिका

भारत के न्याय को महत्वपूर्ण महत्व के रूप में माना जाए

उच्चतम न्यायालय में नियुक्तियों के मामले में और

राज्यों के उच्च न्यायालय। हमारा मानना है कि

गुप्ता मामले में निपटाए गए इस पहलू की आवश्यकता है

एक बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार "। 81

112. एक बड़ी पीठ के विचार के लिए मुद्दे थे

फिर निम्नलिखित शब्दों में तैयार किया गया:

"जिन बिंदुओं पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, वे बहुमत के विचारों से संबंधित हैं और उनसे उत्पन्न होते हैं।

आम तौर पर और विशेष रूप से "परामर्श" की स्थिति

भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ "परामर्श" के संदर्भ में

और, दूसरी बात, प्रमुख की भूमिका की प्रधानता के बारे में

भारत का न्याय। बातचीत में विभिन्न स्थितियों में परामर्श की सामग्री और गुणवत्ता शायद भिन्न हो सकती है।

राज्य के कार्यपालिका और न्यायिक अंगों के बीच

और कुछ पहलुओं को स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो सकती है। 82

113. यह भी देखा गया कि एक विचार व्यक्त किया गया था

प्रथम न्यायाधीशों का मामला कि राज्य सरकार कर सकती है

एक न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए एक प्रस्ताव शुरू करें लेकिन कि प्रस्ताव सीधे केंद्र सरकार को नहीं भेजा जा सका,

लेकिन पहले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा जाना चाहिए। 83

इस स्पष्ट व्याख्या के बावजूद, प्रक्रिया की जा रही थी

कार्यपालिका द्वारा विकृत और नियुक्ति के लिए एक प्रस्ताव

81 अनुच्छेद 31

82 प्रथम न्यायाधीशों के मामले के पैराग्राफ 32 83 पैराग्राफ 728 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सीधे संघ को भेजा जा रहा था

सरकार। इस संबंध में कहा गया था:

"लेकिन यह उल्लेख किया गया है कि एक अभ्यास की मांग की जाती है

संवैधानिक योजना को विकृत करना और पूरी तरह से अस्वीकार्य। जहाँ तक कार्यपालिका का संबंध है,

'नियुक्ति शुरू करने का अधिकार मुख्य न्यायाधीश को उपयुक्त नाम सुझाने तक सीमित होना चाहिए।

उच्च न्यायालय या भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगर

सिफारिश एक स्रोत से सीधे निकलने के लिए है उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के अलावा

उच्च न्यायालयों और भारत के मुख्य न्यायाधीश का मामला

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय दोनों के मामले में एक उचित चयन के लिए यह मुश्किल होगा

बनाया जाए। यह दशकों से तेजी से महसूस किया जा रहा है।

कि उस समय की सरकार की ओर से अंतिम रूप से अपनी पसंद का दावा करने की चिंता रही है

न्यायाधीशों का चयन। यदि सिफारिश करने की शक्ति होगी

राज्य सरकार या यहाँ तक कि केंद्र सरकार में निहित

सरकार, तस्वीर धुंधली होने की संभावना है और

चयन की प्रक्रिया अंततः हो सकती है

मुश्किल "। 84

114. किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पारित करके

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एक अस्वास्थ्यकर प्रथा थी कि

राज्य की राजनीतिक कार्यपालिका स्वतंत्रता के समय से ही इसे स्थापित करने का प्रयास कर रही थी। यह 'छल' था

एक से अधिक अवसरों पर बहिष्कृत, जैसा कि ऊपर देखा गया है।

115. एक और प्रथा जो राजनीतिक कार्यपालिका थी

स्थापित करने का प्रयास नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करना था

84 पैराग्राफ 34 सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से लेकर उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अदालत।
इस संदर्भ में सुभाष शर्मा में भी कहा गया था।

दशकों से उस समय की सरकार की ओर से अंतिम रूप से अपनी पसंद का दावा करने की चिंता रही है
न्यायाधीशों का चयन। '85 यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि

उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यकारी हस्तक्षेप की अस्वस्थता, जिसे सबसे पहले
जापन में उजागर किया गया था

मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन से निकल कर और फिर

एल. सी. आई. ने अपनी 14 वीं रिपोर्ट में किसी न किसी रूप में जारी रखा।

आजादी से लेकर 1990 के दशक की शुरुआत तक की पूरी अवधि में।

इसके अलावा, 14 वीं रिपोर्ट में दी गई सिफारिश

एल. सी. आई. ने अध्याय 6 में कार्यपालिका के बारे में कहा है कि वह 'अपने स्वयं के नामित व्यक्ति को प्रस्तावित करने और उसे केंद्र को भेजने' का हकदार नहीं है।

उचित वजन और विचार नहीं दिया गया था कि यह इसके योग्य था कार्यपालिका से।

116. काफी स्पष्ट रूप से, कुछ जटिल मुद्दे सामने आए

एक बड़ी पीठ द्वारा विचार। अच्छी तरह से स्थापित और स्वीकृत संवैधानिक सम्मेलनों की मांग की गई थी

राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा उपेक्षित। अगर स्वतंत्रता न्यायपालिका को बनाए रखा जाना था और संसदीय लोकतंत्र को बनाए रखा जाना था, प्रथम न्यायाधीशों का मामला और नियुक्ति प्रक्रिया को नए सिरे से देखने की आवश्यकता थी।

दूसरा न्यायाधीश मामला-6.10.1993

117. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, द्वितीय न्यायाधीशों का मामला

यह एक स्वीकृति का परिणाम था कि: (1) मौजूदा न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली जिसमें कार्यपालिका ने 'परम शक्ति' पर पुनर्विचार की आवश्यकता थी क्योंकि वह 'परम शक्ति' थी। 'शक्ति' का दुरुपयोग किया जा रहा था; (2) की मौजूदा प्रणाली न्यायाधीशों की नियुक्ति के परिणामस्वरूप कुछ नियुक्तियाँ हुईं जिनमें

85 पैराग्राफ 34 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

कार्यकारी हस्तक्षेप के कारण योग्यता की अनदेखी की गई थी या

बाहरी विचार। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कभी-कभी राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा पारित किया जाता था और

न्यायाधीश के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए सिफारिश केंद्र सरकार को दिया गया था।

उच्च न्यायालय का आदेश सीधे

यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति 40 साल से अधिक समय तक बनी रही।

और बदलाव लाने का प्रयास किया गया और इसलिए एक

संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया था, लेकिन

यह खत्म हो गया।

118. दूसरे न्यायाधीशों के मामले में यह न्यायाधीश द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था

पांडियन: (1) एक उचित का चयन और नियुक्ति और

उच्च न्यायपालिका के लिए उपयुक्त उम्मीदवार अविभाज्य में से एक है

और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण शर्तें

न्यायपालिका। 86 'एक अनुपयुक्त व्यक्ति की गलत नियुक्ति

आस्था को अपूरणीय क्षति पहुँचाने के लिए बाध्य है

न्याय के प्रशासन में समुदाय और गंभीर प्रभाव डालने के लिए

लोक हित को नुकसान। '87 (2) लोकहित का एक और पहलू

संविधान के अनुच्छेद 50 द्वारा अभिनिर्धारित। 89 (3) द. चयन और नियुक्ति के लिए प्रक्रिया ज्ञापन

लिखित के साथ भारत संघ द्वारा दायर न्यायाधीशों की

प्रथम न्यायाधीशों के पूर्व मामले की अवधि से संबंधित प्रस्तुतियाँ और

की 121 वीं रिपोर्ट में उल्लिखित मौजूदा प्रक्रिया

प्रथम न्यायाधीश पद से संबंधित एल. सी. आई. मामले की अवधि अधिक या

कम समान। वे संकेत देते हैं कि भरने के लिए सिफारिश

उच्चतम न्यायालय में एक रिक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शुरू की जाती है और एक रिक्ति को भरने की सिफारिश की जाती है। उच्च न्यायालय की शुरुआत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसी व्यक्ति की सिफारिश कर सकता है।

86 अनुच्छेद 49

87 अनुच्छेद 63

88 अनुच्छेद 81

89 50. न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना-राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

उच्च न्यायालय में एक रिक्ति को भरने के लिए, लेकिन उसे रूट किया जाना है

केवल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से। 900 (4)

संकल्पचंद सेठ में व्यक्त विचार को दोहराते हुए और

प्रथम न्यायाधीशों के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि के प्रयोजनों के लिए

राष्ट्रपति और प्रमुख के समक्ष परामर्श, सामग्री

भारत का न्याय समान होना चाहिए। 91 (5) की नियुक्ति के लिए

उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश (संविधान के अनुच्छेद 124 (2) के तहत)

संविधान) या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश (अनुच्छेद 217 (1) के तहत)

संविधान का) भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श अनिवार्य है। 92 (6) संवैधानिक परामर्श की प्रक्रिया में

उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के चयन में

और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण, की राय

भारत के मुख्य न्यायाधीश को प्रधानता का अधिकार है। 93 (7) से सहमत हैं।

कि यदि स्वीकार न करने के लिए भारी और ठोस कारण हैं के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश

न्यायाधीश की नियुक्ति, तब नियुक्ति नहीं की जा सकती है।

हालांकि, अगर 'भारी और ठोस' कारण स्वीकार्य नहीं हैं

भारत के मुख्य न्यायाधीश को, और सिफारिश है

दोहराया, फिर नियुक्ति की जाएगी। 94 (8) द

प्रथम न्यायाधीशों के मामले में बहुमत की राय

न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में कार्यपालिका की प्रधानता को खारिज कर दिया गया था। 95

119. न्यायमूर्ति अहमदी ने राय से असहमति जताई

हमारी संवैधानिक योजना और संविधान के अनुच्छेद 50 में 'इसे रोशन करता है'। 96 (2) प्रथम न्यायाधीशों के मामले की आवश्यकता नहीं थी

90 पैराग्राफ 95 से 99 तक। हालाँकि ऐसी प्रथा मौजूद है और स्वीकार की जाती है, लेकिन इस संबंध में कुछ विचलन हुए हैं जैसा कि एल. सी. आई. की 14 वीं रिपोर्ट और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में उल्लेख किया गया है।

92 अनुच्छेद 172

93 अनुच्छेद 197 और 209।

94 अनुच्छेद 212

95 अनुच्छेद 254

95 पैराग्राफ 313 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

खारिज किया जाना लेकिन न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में प्रधानता के सवाल पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय

'श्रेणीबद्ध वजन' का हकदार है। 97

120. न्यायमूर्ति कुलदिप सिंह ने बहुमत से सहमति व्यक्त की और

उन संवैधानिक सम्मेलनों पर बहुत जोर दिया जो विकसित हुए थे कई दशकों से। विद्वान न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि: (1) की सुरक्षा

कार्यकाल न्यायपालिका की स्वतंत्रता का एकमात्र स्रोत नहीं है

लेकिन एक संस्थान के रूप में एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। 198 (2) न्यायपालिका की स्वतंत्रता अटूट रूप से जुड़ी हुई है और

नियुक्ति की संवैधानिक प्रक्रिया से संबंधित

उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीश। स्वतंत्र नहीं हो सकता है

न्यायपालिका जब न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति निहित होती है

कार्यकारी। 99 (3) राष्ट्रपति द्वारा दी गई सलाह से बाध्य है -

मंत्रिपरिषद्। 100 (4) एक संवैधानिक सम्मेलन है

भारत सरकार अधिनियम, 1935 के बाद से स्थापित (I

'कम से कम' शब्द जोड़ें) कि न्यायाधीशों की नियुक्ति थी

हमेशा मुख्य न्यायाधीश की सहमति से किया गया

भारत। मुख्य न्यायाधीश की राय और सिफारिशें

न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में भारत का

कार्यकारी। 101 (5) न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में,

भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श अनिवार्य है। 102 (6) अनुच्छेद 124 (2) और 217 (1)
के तहत परामर्श प्रक्रिया में

संविधान, प्रमुख की सलाह और सिफारिश

भारत का न्याय कार्यपालिका के लिए बाध्यकारी है और यह होना चाहिए अंतिम शब्द। प्रथम
न्यायाधीशों के मामले में बहुमत का विचार है

97 अनुच्छेद 303 और 313। यह अनुच्छेद 303 में देखा गया था: यदि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना है तो यह मानना मुश्किल है कि वह भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय से बंधे हैं जब तक कि हम यह नहीं मानते कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय से बंधी होगी, एक ऐसा निर्माण जो हमारे दिमाग में बहुत कृत्रिम है और स्वीकृति की सराहना करने के लिए तनावपूर्ण है।

99 अनुच्छेद 335 100 पैराग्राफ 277,356,383 और 411

101 पैराग्राफ 359,371,373 और 376। न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित आंकड़ों का उल्लेख पैराग्राफ 367 और 369 में किया गया है।

102 पैराग्राफ 377 और 411 सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

सही कानून न बनाएँ। 103

(7) अनुच्छेद 124 (2) और 217 (1) के प्रयोजनों के लिए

संविधान, भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश

उच्च न्यायालय का अर्थ है अपने-अपने न्यायालय का प्रतिनिधित्व करने वाले पदाधिकारी। 104

121. द्वारा बताए गए अधिक दिलचस्प तथ्यों में से एक

न्यायमूर्ति कुलदिप सिंह ने कहा कि 1 जनवरी, 1983 से प्रथम न्यायाधीशों के मामले में निर्णय) 10
अप्रैल, 1993 तक (यानी दस साल की अवधि के दौरान)

भारत को राष्ट्रपति ने सात में स्वीकार नहीं किया था।

मामले। यह पहले की अवधि के एक हिस्से के विपरीत है।

'परम शक्ति' सिद्धांत का प्रतिपादन तब किया गया जब राय

भारत के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था

केवल एक मामले में और उस मामले में, मुख्य न्यायाधीश की राय उच्च न्यायालय (राजनीतिक कार्यपालिका नहीं) को स्वीकार कर लिया गया।

विद्वान न्यायाधीश को यही कहना था:

"श्री एस. के. बोस, संयुक्त सचिव, न्याय विभाग,

विधि और न्याय मंत्रालय ने दिनांकित एक हलफनामा दायर किया है

22 अप्रैल, 1993 हमारे सामने। उक्त शपथपत्र के पैरा 6 में यह कहा गया है कि

इसे निम्नानुसार वर्णित किया गया है:

"जहाँ तक न्यायाधीशों की नियुक्तियों का संबंध है, न कि

प्रमुख द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के अनुरूप भारत के न्यायाधीश, यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि

1 जनवरी, 1983 से 10 अप्रैल, 1993 तक, वहाँ हैं

ऐसे केवल सात मामले हैं, जिनमें से पाँच 1983 में थे (2)। जनवरी 1983 में, जुलाई 1983 में 2, अगस्त 1983 में 1);

एक सितंबर 1985 में और एक मार्च 1991 में।

इस दौरान कुल 547 नियुक्तियां की गईं।

अवधि "।

इस प्रकार यह द्वारा दिए गए तथ्यों और आंकड़ों से स्पष्ट है

स्वयं कार्यकारी कि वास्तविक व्यवहार में

103 पैराग्राफ 385, 387 और 411

104 पैराग्राफ 392 और 411 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशें

हमेशा स्वीकार किया गया। " 105

122. बहुमत की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा: (1)

कार्यकाल की सुरक्षा और सेवा की अन्य शर्तें प्रदान करके, रोककर भी

लेकिन बनाने में राजनीतिक विचारों को

उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति। 106

(2) न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में, प्रधानता थी

भारत सरकार अधिनियम, 1919 में कार्यपालिका को दिया गया और भारत सरकार अधिनियम, 1935 लेकिन संवैधानिक योजना में, कार्यपालिका की प्रधानता को बाहर रखा गया है। 107

(3) भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश

उच्च न्यायालय मूल्य जानने और मूल्यांकन करने के लिए सबसे अच्छी तरह से सुसज्जित हैं।

एक उम्मीदवार की, और एक वरिष्ठ के रूप में नियुक्ति के लिए उसकी उपयुक्तता

न्यायाधीश '1 के बीच मतभेद की स्थिति में

कार्यपालिका और न्यायपालिका, के मुख्य न्यायाधीश की राय भारत का वजन सबसे अधिक होना चाहिए। [इसने डॉ. अम्बेडकर के इस विचार को प्रतिध्वनित किया कि परामर्श व्यक्तियों के बीच होगा।

जो इस तरह के मामलों में सलाह देने के लिए अच्छी तरह से योग्य हैं।]

इसलिए, चूंकि प्रधानता कार्यपालिका के पास नहीं है, तो ऐसे में

एक स्थिति में, यह भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास होना चाहिए। 108 यह निश्चित रूप से कार्यपालक को नियुक्ति से बाहर नहीं करता है।

एक वकील या न्यायाधीश का व्यक्तिगत चरित्र या विशेषता जो हो सकता है एक व्यक्ति के अच्छे बनने की क्षमता पर असर डालना

न्यायाधीश। 109 यह किसी व्यक्ति की न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की सिफारिश को अस्वीकार करने का आधार बन सकता है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। 110

105 पैराग्राफ 369 और 370

106 अनुच्छेद 447

107 पैरा 444, 446, 448 और 450 108 पैरा 450, 451, 455, 478 और 486

109 अनुच्छेद 462

110 पैराग्राफ 478 (7)

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

(4) भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय की प्रधानता है

उसकी व्यक्तिगत राय के लिए नहीं बल्कि सामूहिक राय के लिए
 भारत के मुख्य न्यायाधीश और उनके वरिष्ठ सहयोगी या वे
 जो नियुक्ति के कार्य से जुड़े हैं
 न्यायाधीशों। 111 इसलिए, राष्ट्रपति स्वीकार नहीं कर सकता है
 न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की सिफारिश, यदि
 भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों की सर्वसम्मति राय द्वारा समर्थित नहीं है।
 न्यायाधीशों। 112 राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौट सकता है a
 अच्छे कारणों के लिए सर्वसम्मति सिफारिश। हालांकि, इसमें
 बाद की घटना, यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश
 उनके द्वारा परामर्श किया गया, सर्वसम्मति से दोहराया गया
 वापस न लेने के कारणों के साथ 'सिफारिश' सिफारिश, फिर उस नियुक्ति को स्वस्थ के रूप में
 सम्मेलन होना चाहिए। " 113 (यहाँ मुख्य शब्द है
 सर्वसम्मति-प्रारंभिक सिफारिश के चरण में और पुनरावृत्ति के चरण में)।

(5) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए या
 उच्च न्यायालय, भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श या
 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनिवार्य हैं, 114

(6) संविधान के अनुच्छेद 124 (2) और 217 (1) में राष्ट्रपति
 संविधान का अर्थ है राष्ट्रपति के अनुसार कार्य करना प्रधान मंत्री के साथ मंत्रिपरिषद की सलाह।
 115

(7) मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह
 राष्ट्रपति को संविधान के अनुसार होना चाहिए। इस तरह की सलाह राष्ट्रपति के लिए
 बाध्यकारी है। चूंकि भारत के मुख्य न्यायाधीश (न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करने वाले) की राय अंतिम है,
 राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह होनी चाहिए

पैराग्राफ 456 और 466

112 पैराग्राफ 478 (8)

113 पैराग्राफ 478 (7)

114 अनुच्छेद 448

115 पैरा 457 [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय के अनुसार। 116

(8) परंपरा यह है कि नियुक्ति प्रक्रिया है

उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शुरू किया गया

उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय।

इस अधिवेशन से अलग होने का कोई कारण नहीं है। 117

(9) प्रथम न्यायाधीशों के मामले में निर्धारित कानून नहीं है

सही दृश्य, 1 18

123. अन्यथा अपनी असहमत राय में, न्यायमूर्ति

पुंछी ने न्यायमूर्ति वर्मा द्वारा लिए गए दृष्टिकोण का समर्थन किया

इस हद तक कि कार्यपालिका के विचारों को अस्वीकार नहीं कर सका

उच्च न्यायालय (जैसा भी मामला हो) जब कोई सिफारिश की जाती है न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए किया गया।

उच्च न्यायालय में

124. द्वितीय न्यायाधीशों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता

मामला यह है कि यह पेश किया गया है जिसे ए कहा जाता है

'न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए परामर्श की कॉलेजियम प्रणाली न्यायालय। जहाँ तक मुखिया का

उच्चतम न्यायालय और उच्च

भारत के न्याय का संबंध है, कॉलेजियम प्रणाली व्यापक है

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में उनकी भूमिका ने और (एक अर्थ में) उसे कमजोर कर दिया।

न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय

नियुक्ति प्रक्रिया में उसकी भूमिका इसे बाहर निकालकर

भारत के मुख्य न्यायाधीश की व्यक्तिगत या व्यक्तिगत भूमिका

जैसा कि डॉ. अम्बेडकर ने सोचा था। संविधान के अनुच्छेद 124 में भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाहकार भूमिका थी

इसकी एक व्यावहारिक व्याख्या के माध्यम से मौलिक रूप से परिवर्तित
प्रावधान। यह कैसे हुआ?

125. द्वितीय न्यायाधीशों के मामले में कुछ मानदंड थे -

नियुक्ति के मामले में न्यायमूर्ति वर्मा द्वारा निर्धारित

न्यायाधीशों। ये मानदंड थे: न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए

117 पैराग्राफ 478 (10) और 486 (2)

118 पैराग्राफ 486

119 पैराग्राफ 500 शीर्ष अदालत के वकील-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

सर्वोच्च न्यायालय, भारत के मुख्य न्यायाधीश को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय के
दो वरिष्ठ-अधिकांश न्यायाधीशों के विचार

और वरिष्ठ-उच्चतम न्यायालय में सबसे अधिक न्यायाधीश संबंधित उम्मीदवार का उच्च न्यायालय।
इस प्रक्रिया के माध्यम से

भारत के मुख्य न्यायाधीश की व्यक्तिगत राय थी

कई न्यायाधीशों की सामूहिक राय द्वारा प्रतिस्थापित। इस अर्थ में परामर्श प्रक्रिया में भारत के मुख्य
न्यायाधीश की राय को व्यापक बनाया गया था और उनका होना बंद कर दिया गया था।

व्यक्तिगत। इस स्तर पर यह शब्दों को याद करने लायक है

डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि 'मुख्य न्यायाधीश, अपनी श्रेष्ठता के बावजूद,

सभी विफलताओं, भावनाओं और पूर्वाग्रहों को साझा किया लोग '। डॉ. अम्बेडकर की आशंका या
भय

इस संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक मामले में कार्य करना था

नियुक्ति के लिए परामर्श के लिए इसी तरह का मानदंड निर्धारित किया गया था उच्च न्यायालय
के एक न्यायाधीश का। ऐसा कहा गया था:

"इस राय को व्यावहारिक तरीके से तैयार करना होगा।

और परंपरा पर आधारित पिछला अभ्यास एक सुरक्षित मार्गदर्शक है।
उच्चतम न्यायालय में नियुक्तियों से संबंधित मामलों में,

भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी गई राय

परामर्श प्रक्रिया का गठन करना होगा

के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के विचारों को ध्यान में रखें
सुप्रीम कोर्ट। भारत के मुख्य न्यायाधीश भी हैं

वरिष्ठतम न्यायाधीश के विचारों का पता लगाने की अपेक्षा

उच्चतम न्यायालय की राय जिसके होने की संभावना है

उम्मीदवार की उपयुक्तता का निर्णय लेने में महत्वपूर्ण,
इस तथ्य के कारण कि वह उसी से आया है

उच्च न्यायालय, या अन्यथा। अनुच्छेद 124 (2) एक संकेत है।

कि उच्चतम न्यायालय के कुछ अन्य न्यायाधीशों के विचारों का निर्धारण आवश्यक है। अंतर्निहित वस्तु

अनुच्छेद 124 (2) को प्रमुख के रूप में इस तरह से प्राप्त किया जाता है।
भारत के न्यायाधीश उनके गठन के लिए उनसे परामर्श करते हैं

120 विद्वान महान्यायवादी के अनुसार, इससे डॉ. अम्बेडकर अपनी कब्र में गिर गए होंगे। ऐसा नहीं है और
बिल्कुल विपरीत है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

राय दें। अनुच्छेद 124 (2) में यह प्रावधान आधार है -

मौजूदा परिपाटी जिसके लिए मुख्य न्यायाधीश की आवश्यकता होती है

सर्वोच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों से परामर्श करने के लिए भारत सरकार

उसकी सिफारिश करने से पहले। यह सुनिश्चित करता है कि

भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय केवल उनकी नहीं है।

न्यायपालिका में शीर्ष स्तर पर पुरुषों का एक निकाय।
उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों से संबंधित मामलों में,

भारत के मुख्य न्यायाधीश के ध्यान में रखने की उम्मीद है
उच्चतम न्यायालय में उनके सहयोगियों के विचार जो

के मामलों से परिचित होने की संभावना है

संबंधित उच्च न्यायालय। भारत के मुख्य न्यायाधीश शायद

एक या अधिक वरिष्ठ न्यायाधीशों के विचारों का भी पता लगाएं।

उस उच्च न्यायालय की राय, मुख्य न्यायाधीश के अनुसार
भारत का न्याय, गठन में महत्वपूर्ण होने की संभावना है

उसकी राय से। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की राय सबसे अधिक महत्व की होगी, और

इसमें शामिल अन्य अधिकारियों की राय होनी चाहिए

उचित वजन दिए जाने पर, राय के गठन में

भारत के मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश की राय

यह सुनिश्चित करने के बाद उच्च न्यायालय का गठन किया जाना चाहिए

कम से कम उच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के विचार

अदालत "। 121

126. मुख्य न्यायाधीश की भूमिका का महत्व

भारत को यह स्वीकार किया गया कि यह देखा गया कि

संवैधानिक परंपरा यह थी कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 124 (2) और अनुच्छेद 217 (1) के तहत कोई नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए।

संविधान का जब तक कि यह अंतिम के अनुरूप न हो

भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय। कहा गया था:

"इस प्रकार दिए गए अनुच्छेद 124 (2) और 217 (1) के प्रयोजन के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय में

सभी नियुक्तियों का मामला; और कोई नियुक्ति नहीं हो सकती है

121 पैराग्राफ 478 (1)

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

इन प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति द्वारा

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, जब तक कि वे

मुख्य न्यायाधीश की अंतिम राय के अनुरूपता

भारत का गठन संकेतित तरीके से हुआ था। 122

127. 'इंगित तरीका' यह था कि यदि ए

कारण) भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश को भारत पहले परामर्श किए गए न्यायाधीशों के सर्वसम्मत समझौते के साथ सिफारिश को दोहराता है, फिर

नियुक्ति स्वस्थ के रूप में की जानी चाहिए

सम्मेलन '। इस संदर्भ में यही कहा गया था:

"अनुशंसित किसी भी व्यक्ति की गैर-नियुक्ति, पर

अनुपयुक्तता का आधार, अच्छे कारणों से होना चाहिए,

भारत के मुख्य न्यायाधीश को प्रकट किया गया ताकि उन्हें सक्षम किया जा सके

उन पर पुनर्विचार करें और अपनी सिफारिश वापस लें

विचार करें। यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश को नहीं मिलता है

उसकी सिफारिश को वापस लेना भी आवश्यक है

इसके बाद, लेकिन उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश जिनका इस मामले में परामर्श लिया गया है, उनका विचार है

कि इसे वापस लिया जाना चाहिए, उसकी गैर-नियुक्ति

व्यक्ति, दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, जनहित में अनुमेय हो सकता है। यदि गैर-नियुक्ति एक दुर्लभ में

मामला, इस आधार पर, एक गलती साबित होती है, कि

अंतिम लोक हित में गलती गलत नियुक्ति की तुलना में कम हानिकारक है। हालाँकि, यदि उचित विचार के बाद

भारत के मुख्य न्यायाधीश को बताए गए कारणों में से,

उस सिफारिश को मुख्य न्यायाधीश द्वारा दोहराया जाता है

भारत के न्यायाधीशों के सर्वसम्मत समझौते के साथ

उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में कारणों के साथ परामर्श किया

सिफारिश को वापस नहीं लेने के लिए, फिर कि

स्वस्थ अधिवेशन के रूप में नियुक्ति होनी चाहिए

बनाया जाए "। 123

122 पैराग्राफ 478 (5)

123 पैराग्राफ 478 (7)

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

128. मानदंडों ने निष्कर्षों का रूप ले लिया जो बन गए

न्यायपालिका और कार्यपालिका पर बाध्यकारी। जिन निष्कर्षों पर पहुंचे हैं, उन्हें पुनः प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।

129. नियुक्ति प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू,

जिसे न्यायमूर्ति वर्मा ने स्वीकार किया था, वह संवैधानिक है

कन्वेंशन कि सिफारिश द्वारा शुरू की जानी चाहिए और

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (उच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिए) और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से उत्पन्न होना चाहिए भारत (उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति के लिए)। इस घटना में

एक राज्य के मुख्यमंत्री एक व्यक्ति की सिफारिश करते हैं

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति, इसे रूट किया जाना चाहिए

केवल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से। इसके बाद उक्त मुख्य न्यायाधीश को अपने सहयोगियों (और अन्य, यदि

आवश्यक) और तय करें कि व्यक्ति को होना चाहिए या नहीं

औपचारिक रूप से अनुशंसित। यदि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

उस व्यक्ति की सिफारिश है कि उसके बाद दूसरे न्यायाधीश के मामले में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। अगर मुखिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने यह सिफारिश नहीं करने का फैसला किया है कि

नियुक्ति के लिए व्यक्ति, मामला बंद है और,

इसलिए, बिना मुलाकात के मिलने का सवाल

भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति बस उत्पन्न नहीं होती है और न ही हो सकती है। यह संवैधानिक और पारंपरिक रूप से स्वीकार किया गया है। प्रक्रिया, जो स्पष्ट रूप से राजनीतिक के लिए स्वीकार्य नहीं है

कार्यपालिका, जिसने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पारित करके और सीधे सिफारिश करके राजनीतिक कार्यपालिका को प्रेरित किया है

केंद्र सरकार को न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए एक व्यक्ति

उच्च न्यायालय से। चाहे जो भी हो, बहुमत का विचार व्यक्त किया गया

दूसरे न्यायाधीशों के मामले में संवैधानिक व्यवस्था को बहाल किया गया
 डॉ. अम्बेडकर द्वारा व्यक्ति को कमजोर करके परिकल्पित स्थिति
 भारत के मुख्य न्यायाधीश का अधिकार और इसे एक
 न्यायाधीशों का कॉलेजियम, जो शायद इसके अनुरूप है
 डॉ. अम्बेडकर के विचार।

130. विद्वान महान्यायवादी के अनुसार, ये सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड हैं

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकर, जे.]

निष्कर्ष ने अनुच्छेद 124 (2) और अनुच्छेद 217 (1) को बदल दिया संविधान 'उनके सिर पर' और
 यहां तक कि न्यायमूर्ति वर्मा, लेखक

निर्णय ने महसूस किया कि निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। द.

संदर्भ न्यायमूर्ति वर्मा द्वारा उनके कार्यकाल के बाद दिए गए एक साक्षात्कार का था

सेवानिवृत्ति। इसमें न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा था:

"मेरा 1993 का फैसला, जो इस क्षेत्र को धारण करता है, बहुत अधिक था

गलत समझा और दुरुपयोग किया। यह उस संदर्भ में था!
 उन्होंने कहा कि अब कुछ समय के लिए फैसले का काम चल रहा है

गंभीर सवाल उठाते हैं, जिन्हें नहीं कहा जा सकता है

अनुचित है। इसलिए किसी प्रकार का पुनर्विचार है

आवश्यकता है "। 124

131. ऐसा प्रतीत होता है कि निर्णय की गलतफहमी

विशेष रूप से दूसरे न्यायाधीशों का मामला आज भी जारी है। राजनीतिक कार्यकारी द्वारा।
 गलतफहमी के कारण नहीं है

इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में स्पष्टता की कमी लेकिन 'निर्णय के काम करने' में असुविधा के कारण।
 मैं कहता हूँ।

ऐसा इसलिए क्योंकि यह विद्वान महान्यायवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया था

और कुछ राज्यों के लिए विद्वान वकील कि दूसरे न्यायाधीश

मामले ने कार्यपालिका को कोई भूमिका (या कोई प्रभावी भूमिका नहीं) निभाने के लिए छोड़ दिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में या उच्च न्यायालय विशेष रूप से क्योंकि कार्यपालिका की राय है अब अर्थहीन हो गया। इससे आगे कुछ नहीं हो सकता सच। कार्यपालिका को अभी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और कुछ मामलों में, एक न्यायाधीश की नियुक्ति में अंतिम कहना है - निर्णय की गलतफहमी पूरी तरह से और के कारण है खेदजनक रूप से भारत संघ और राज्यों का पराजयवादी रवैया या उनका विचार है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में, यह है उनका रास्ता या राजमार्ग। भारत का संविधान एक पवित्र दस्तावेज है न कि एक रूबिक क्यूब जिसे हेरफेर किया जा सकता है। और राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा किसी भी तरह से केवल पैंतरेबाज़ी की गई अपनी तत्काल आवश्यकताओं के अनुरूप।

132. तमिलनाडु की वेबसाइट पर पाए गए एक लेख में

124 अग्रिम पंक्ति, खंड 25 अंक 20 सितंबर 27, 2008 से 10 अक्टूबर 2008 शीर्ष अदालत रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

राज्य न्यायिक अकादमी, न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा

द्वितीय न्यायाधीशों के मामले में नियुक्ति प्रक्रिया और कार्यपालिका की भूमिका और कहा:

"निर्णय की स्पष्ट भाषा के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती है

इस बात में कोई संदेह है कि कार्यपालिका की एक सहभागी भूमिका है

ये नियुक्तियाँ; कार्यपालिका की राय है

पूर्वजों आरो गावारि बिथिडाव गिलिरसिन।

उम्मीदवार का चरित्र और आचरण; इस आधार पर गैर-नियुक्ति की शक्ति स्पष्ट रूप से कार्यपालक, की सिफारिश के बावजूद

सीजेआई; और केवल संदिग्ध पूर्ववृत्त आदि ही पर्याप्त हैं।

कार्यपालक द्वारा गैर-नियुक्ति के लिए। यह भी लिया फैसला

न्यायिक कॉलेजियम की राय, यदि नहीं

नियुक्ति।

हाल के दिनों में

कुछ रिपोर्ट किए गए मामले

इसके प्रयोग से कार्यपालक अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल रहता है।

न्यायिक की सिफारिश होने पर भी शक्ति

कॉलेजियम सर्वसम्मत नहीं था और इसके तत्कालीन अध्यक्ष

भारत ने इसे पुनर्विचार के लिए वापस कर दिया था, न केवल

अस्पष्ट लेकिन निर्णय का गलत उपयोग भी, जिसे सीजेआई, बालकृष्णन सही कहते हैं कि इस दौरान बाध्यकारी है।

इसकी वैधता। इस तरह के उदाहरण केवल भविष्यवाणी को साबित करते हैं

डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि संविधान उतना ही अच्छा होगा
उन लोगों के रूप में जो इसे करते हैं। आपको जो भी सिस्टम पसंद हो, वह है

मूल्य और प्रभावकारिता लोगों के मूल्य पर निर्भर करेगी।

कौन काम करता है! इसलिए, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली के कामकाज की निगरानी
की जानी चाहिए और

उत्तरदायित्व "। 125

कुछ समय बाद लेख में न्यायमूर्ति वर्मा कहते हैं (और यह है

विद्वान द्वारा संदर्भित साक्षात्कार में भी विज्ञापित किया गया

महान्यायवादी):

125 एचटीटीपी: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. इंजा। टीएन। ठीक है। में/लेख/न्यायिक% 20 स्वतंत्रता% 20JSVJ.pdf
सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

"हाल के विचलन के अनुप्रयोग में हैं

नियुक्तियाँ करने में द्वितीय न्यायाधीश का मामला, न कि इसके कारण। यह वही है जो मैंने अपने में
इंगित किया था

दो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों को प्रतिलिपि, जिनमें शामिल थे वर्तमान सीजेआई, के. जी. बालकृष्णन "।

133. इसलिए गलतफहमी राजनीतिक है।

कार्यकारी और कोई और नहीं। हालांकि, जैसा कि बताया गया है

99 वें संविधान के बाद न्यायाधीशों का मामला मुद्दा नहीं है संशोधन अधिनियम और इसलिए आगे कोई टिप्पणी नहीं की जाती है,

कार्यपालिका ने दायरे और प्रभाव को पूरी तरह से गलत समझा है। द्वितीय न्यायाधीशों के मामले और कॉलेजियम का कार्यकरण

प्रणाली।

तीसरा न्यायाधीश मामला-28.10.1998

134. 1998 का विशेष संदर्भ संख्या 1 आम तौर पर है

जिसे तीसरे न्यायाधीशों का मामला कहा जाता है। राष्ट्रपति ने मांग की

अन्य प्रश्नों के अलावा निम्नलिखित पर संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत इस न्यायालय की सलाहकार राय:

"(1) क्या अनुच्छेद 217 (1) और 222 (1) में 'भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श' अभिव्यक्ति की आवश्यकता है के गठन में न्यायाधीशों की बहुलता के साथ परामर्श

भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय या एकमात्र

उक्त लेखों के अर्थ के भीतर परामर्श।

(3) क्या अनुच्छेद 124 (2) जैसा कि उक्त में व्याख्या की गई है

निर्णय [दूसरे न्यायाधीशों के मामले] के लिए मुख्य न्यायाधीश की आवश्यकता होती है

भारत के न्यायाधीश केवल दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करेंगे या क्या इसके अनुसार व्यापक परामर्श होना चाहिए

पिछले अभ्यास के लिए।

(4) क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश अधिनियम [2015] 13 एस. सी. आर. के हकदार हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

केवल अपनी व्यक्तिगत क्षमता में, बिना किसी परामर्श के

सभी के संबंध में उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश
सरकार द्वारा प्रेषित सामग्री और जानकारी
न्यायाधीश की नियुक्ति न करने के लिए भारत सरकार ने की सिफारिश
नियुक्ति के लिए; "

135. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विद्वान अटॉर्नी-जनरल ने राष्ट्रपति की सुनवाई में कहा था
संदर्भ कि केंद्र सरकार न तो एक की मांग कर रही थी

द्वितीय न्यायाधीशों के मामले की समीक्षा और न ही पुनर्विचार। इसलिए, राष्ट्रपति के संदर्भ के जवाब नहीं हैं।
इस न्यायालय द्वारा लिए गए निष्कर्षों से अलग

दूसरे न्यायाधीशों का मामला। इस मायने में, यह राय नहीं ली गई
सारगर्भित चर्चा बहुत आगे है, हालांकि यह सारगर्भित है
कुछ प्रक्रियात्मक मुद्दों को हल किया और संबंधित अंतरालों को भरा।

वरिष्ठ न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए

न्यायपालिका। जो भी हो, इन तीन प्रश्नों के उत्तर

ऊपर उल्लिखित हैं:

"1. अभिव्यक्ति "मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श"

संविधान के अनुच्छेद 217 (1) और 222 (1) में
भारत में न्यायाधीशों की बहुलता के साथ परामर्श की आवश्यकता है

भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय का गठन।

भारत के मुख्य न्यायाधीश की एकमात्र व्यक्तिगत राय

अर्थ के भीतर "परामर्श" का गठन नहीं करता है

उक्त लेख।

3. भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की सिफारिश

न्यायालय और किसी मुख्य न्यायाधीश या कनिष्ठ न्यायाधीश का स्थानांतरण करना

उच्चतम न्यायालय के कनिष्ठ न्यायाधीश। जहाँ तक एक
उच्च न्यायालय में नियुक्ति का संबंध है,

के साथ परामर्श करके सिफारिश की जानी चाहिए

उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश।
4. भारत के मुख्य न्यायाधीश केवल सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं-ऑन-रिकॉर्ड में कार्य करने के हकदार नहीं हैं

समाजीकरण। वी. यू. ओ. आई. /मदन बी. लोकर, जे./
उसकी व्यक्तिगत क्षमता, दूसरों के साथ परामर्श के बिना
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, सामग्री के संबंध में
और भारत सरकार द्वारा दी गई जानकारी
के लिए अनुशंसित न्यायाधीश की गैर-नियुक्ति के लिए
नियुक्ति "। 126

136. दूसरे न्यायाधीशों के मामले में निर्णय के साथ पढ़ा गया
इस न्यायालय द्वारा उठाए गए विभिन्न प्रश्नों पर दी गई राय
राष्ट्रपति के संदर्भ में या तीसरे न्यायाधीशों के मामले में पूरी तरह से प्रक्रिया के आसपास के विवादों
को सुलझाएँ
उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में अपनाया गया। विचारों की प्रधानता और प्रमुख के साथ
परामर्श के मुद्दे
भारत के न्याय ने सभी को निर्णय द्वारा जवाब दिया और राय दें।

137. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि तीसरे न्यायाधीशों का मामला
एक महत्वपूर्ण मानक या दूसरे के निष्कर्ष को संशोधित किया
न्यायाधीशों का मामला। संशोधन यह था कि 'कॉलेजियम' के लिए
उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति का विस्तार किया गया
भारत के मुख्य न्यायाधीश और चार वरिष्ठ-सबसे
जैसा कि निष्कर्ष निकाला गया है, दो वरिष्ठ-अधिकांश न्यायाधीशों के बजाय न्यायाधीश द्वितीय
न्यायाधीशों का मामला। इस तरह से, परामर्श
भारत के मुख्य न्यायाधीश और भी व्यापक थे। यह था।
निष्कर्ष 9 में निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है:

"9. भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई सिफारिशें

मानदंडों और आवश्यकताओं का पालन किए बिना
वनों के रूप में परामर्श प्रक्रिया बाध्यकारी नहीं है

भारत सरकार पर। "

यह निष्कर्ष महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ने इसे नजरअंदाज या नजरअंदाज कर दिया है।

समशेर सिंह का मामला

138. न्यायपालिका की पूरी तस्वीर के लिए

विषय पर घोषणाएँ, यह भी उल्लेख करना आवश्यक है

126 पैराग्राफ 44 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

समशेर सिंह बनाम में इस न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय। राज्य

पंजाब से। 1 27

139. यह मामला सेवाओं की समाप्ति से संबंधित है।

अधीनस्थ न्यायिक सेवा के दो अधिकारियों द्वारा

राज्य के राज्यपाल। मुद्दा यह था कि क्या राज्यपाल

अधिकारियों ने तर्क दिया कि राज्यपाल प्रयोग करने के लिए बाध्य था उनका व्यक्तिगत विवेक और
निर्भरता सरदार लाल बनाम पर रखी गई थी। भारत संघ 128 जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि
आह्वान करने के लिए

संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के तहत 'आनंद सिद्धांत',

राष्ट्रपति की व्यक्तिगत संतुष्टि आवश्यक है क्योंकि

परंतु के खंड (ग) के तहत जांच करने के लिए संविधान का अनुच्छेद 311 (2)। दूसरी ओर, राज्य

तर्क दिया कि राज्यपाल केवल इस पर कार्य करने के लिए बाध्य था

मंत्रिपरिषद की सलाह।

140. यह न्यायालय मुख्य न्यायाधीश ए. एन. रे के माध्यम से बोल रहा है

(अपने और चार अन्य विद्वान न्यायाधीशों के लिए) ने सरदार लाल को खारिज कर दिया और कहा कि
निर्णय में कानून को सही ढंग से नहीं कहा गया है। यह. यह अभिनिर्धारित किया गया था कि व्यवसाय
के नियमों के तहत,

संबंधित मंत्री या अधिकारी राष्ट्रपति का निर्णय होता है।

या राज्यपाल, जैसा भी मामला हो। इसके बाद यह निष्कर्ष निकाला गया:

"पूर्वगामी कारणों से हम मानते हैं कि राष्ट्रपति या

राज्यपाल परिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है।

प्रधान मंत्री के साथ मंत्रियों का
केंद्र का मामला और मुख्यमंत्री शीर्ष पर

राज्य का मामला उन सभी मामलों में जो निहित हैं

कार्यकारी चाहे वे कार्य कार्यकारी हों या

राज्यपाल को कार्यकारी कार्यों का निर्वहन करना है।
व्यक्तिगत रूप से। वर्तमान अपीलें नियुक्ति से संबंधित हैं

न्यायिक के लिए जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों का

127 (1974) 2 एस. सी. सी. 831 (सात न्यायाधीशों की पीठ)

126 (1971) 1 एस. सी. सी. 411 (पाँच न्यायाधीशों की पीठ)

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

राज्य लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श और उच्च न्यायालय। राज्य की न्यायिक
सेवा से संबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति या बर्खास्तगी या निष्कासन

एक व्यक्तिगत कार्य नहीं है बल्कि एक कार्यकारी कार्य है

राज्यपाल ने नियमों के अनुसार प्रयोग किया

संविधान के तहत उस ओर से "। 129

141. द्वारा लिखित एक अलग लेकिन सहमत निर्णय में

कृष्ण लायर (अपने और न्यायमूर्ति भगवती के लिए) के विचार का उल्लेख करें।

मुख्य न्यायाधीश रे द्वारा दी गई आपत्ति को निम्नलिखित में स्वीकार किया गया था:

आरडीएस:

"हम अपने संविधान की इस शाखा के कानून की घोषणा करते हैं

राष्ट्रपति और राज्यपाल, सभी के संरक्षक हों

विभिन्न अनुच्छेदों के तहत कार्यकारी और अन्य शक्तियां,
 इन प्रावधानों के आधार पर, उनका औपचारिक प्रयोग करें
 केवल और उसके अनुसार संवैधानिक शक्तियाँ
 उनके मंत्रियों की सलाह कुछ प्रसिद्ध लोगों को बचाती है
 असाधारण परिस्थितियाँ। हठधर्मिता के बिना या
 सम्पूर्ण, ये स्थितियाँ (ए) के चयन से संबंधित हैं

प्रधानमंत्री (मुख्यमंत्री) ने हालांकि इस पर प्रतिबंध लगा दिया
 विचार से है कि उसे करना चाहिए

चयन सर्वोपरि

सदन में बहुमत का आदेश दें; (बी) एक की बर्खास्तगी
 सरकार जिसने सदन में अपना बहुमत खो दिया है, लेकिन
 करना; (ग) सदन का विघटन

पद छोड़ने से इनकार

जहाँ देश के लिए एक अपील आवश्यक है, हालांकि
 इस क्षेत्र में राज्य के प्रमुख को मिलने से बचना चाहिए
 राजनीति में शामिल हैं और उन्हें उनके प्रधान मंत्री द्वारा सलाह दी जानी चाहिए
 मंत्री (मुख्यमंत्री) जो अंततः लेंगे

कदम के लिए जिम्मेदारी "। " 130

142. दोनों विद्वानों द्वारा एक अतिरिक्त कारण दिया गया था
 इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए और यह भी महत्वपूर्ण है
 पैराग्राफ 88

पैरा 154 [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हमारे वर्तमान उद्देश्यों के लिए। अतिरिक्त कारण संबंधित है
 न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इसके लिए संदर्भ दिया गया था।
 ज्योति प्रकाश मित्र बनाम। मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता। 131 द.

उस मामले में आयु के निर्धारण से संबंधित पत्र
 एक कार्यरत न्यायाधीश

के अनुच्छेद 217 (3) के तहत उच्च न्यायालय का

संविधान। 132 इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आयु निर्धारण

राष्ट्रपति के विचारों से अप्रभावित होना चाहिए

पहले से ही। यह इस आधार पर था कि कार्यकारी थे

एक बैठे न्यायाधीश की उम्र का निर्धारण करें, यह होगा

'न्यायपालिका की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। यह दृश्य

बाद में भारत संघ बनाम में दोहराया गया। ज्योति

प्रोकाश मित्तर। 133 143. विद्वान न्यायाधीशों ने तब संविधान की उस योजना के आधार पर निर्णय दिया जिसे पहले ही स्वीकार कर लिया गया था,

कि राष्ट्रपति का अर्थ है मंत्रिपरिषद और

न्यायपालिका की स्वतंत्रता को अनुच्छेद द्वारा संरक्षित किया गया है।

217 (3) परामर्श को अनिवार्य बनाकर संविधान का आयु निर्धारण के संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ।

यह बाहरी विचारों की संभावना को रोक देगा। मंत्री के निर्णय में प्रवेश करना यदि वह छोड़ देता है

भारत के मुख्य न्यायाधीश के विचार। यह माना गया था कि कुल मिलाकर

संभावित मामले, भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श कार्यपालिका द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए और यदि कोई प्रस्थान है

भारत के मुख्य न्यायाधीश के विचारों से, न्यायालय कर सकता है

उपलब्ध तथ्यों के आलोक में मुद्दे की जांच करें। ऐसे में 'संवेदनशील विषय' अंतिम शब्द मुख्य न्यायाधीश के साथ होना चाहिए

भारत से। इस व्याख्या पर, यह अप्रासंगिक हो जाता है कि कौन

औपचारिक रूप से इस मुद्दे का फैसला करता है। यह क्या आयोजित किया गया था:

131 [1965] 2 एस. सी. आर. 53 (पाँच न्यायाधीशों की पीठ)

132 217. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की नियुक्ति और शर्तें। -

(3) यदि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो इस प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद किया जाएगा और राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा।

(1971) 1 एस. सी. 396 (पाँच न्यायाधीशों की पीठ)

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

"संविधान की योजना के आलोक में हमारे पास है पहले से ही संदर्भित, यह संदिग्ध है कि क्या व्यक्तिगत संतुष्टि के रूप में ऐसी व्याख्या

राष्ट्रपति सही हैं। हमारा विचार है कि राष्ट्रपति का अर्थ है, सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, मंत्री या

संतुष्टि या निर्णय संवैधानिक रूप से तब सुरक्षित होता है जब उनके मंत्री इस तरह की राय संतुष्टि पर पहुँचते हैं या

निर्णय लें। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो एक

संविधान का मूल सिद्धांत और उस पर भरोसा किया गया है

विचलन को उचित ठहराने के लिए, संबंधित लेख द्वारा संरक्षित है

भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करना

अनिवार्य। सभी संभावित मामलों में इसके साथ परामर्श करें।

भारतीय न्याय की सर्वोच्च गरिमा होगी और होनी चाहिए

जाँचने का अवसर है कि क्या कोई अन्य बाहरी है परिस्थितियों ने निर्णय में प्रवेश किया है

मंत्री, यदि वह प्रमुख द्वारा दी गई सलाह से अलग हो जाता है

भारत का न्याय। व्यवहार में ऐसे संवेदनशील विषय में अंतिम शब्द भारत के मुख्य न्यायाधीश का होना चाहिए,

उनकी सलाह की अस्वीकृति को आम तौर पर माना जाता है

आदेश को दूषित करने वाले तिरछे विचारों से प्रेरित।

इस दृष्टिकोण से यह मायने नहीं रखता कि राष्ट्रपति या

प्रधानमंत्री या न्याय मंत्री औपचारिक रूप से निर्णय लेते हैं

मुद्दा "। 134

144. यह निर्णय तीन प्रमुख कारणों से महत्वपूर्ण है:

(1) इसने न्यायिक रूप से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को मान्यता दी।

(यह प्रथम न्यायाधीशों के मामले से पहले था जिसने इसे मान्यता दी थी

कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता एक बुनियादी विशेषता थी
 संविधान)। (2) इसने यह निष्कर्ष निकालकर हवा को साफ कर दिया कि
 राष्ट्रपति परिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य था
 मंत्री, यहां तक कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मुद्दे पर भी। इसे संविधान (बयालीसवां संशोधन) द्वारा
 'औपचारिक' बनाया गया था।

134 पैराग्राफ 149 [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिनियम, 1976। (3) एक मायने में, यह निर्णय एक अग्रदूत था
 दूसरे न्यायाधीशों के मामले में अंतिम के साथ प्राथमिक निष्कर्ष
 इस विषय पर बात भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास है।

145. दो अवलोकन हैं जिन्हें करने की आवश्यकता है

इस स्तर पर। सबसे पहले, न्यायमूर्ति कृष्णा लायर ने निर्णय लिखा।
 न्यायमूर्ति भगवती की ओर से भी समशेर सिंह।
 आश्चर्य की बात यह है कि न्यायमूर्ति भगवती ने इस निर्णय का उल्लेख नहीं किया
 प्रथम न्यायाधीशों का मामला। इस विफलता का महत्व यह है कि
 जबकि समशेर सिंह में न्यायमूर्ति भगवती ने यह अभिनिर्धारित किया था कि
 'अंतिम शब्द' भारत के मुख्य न्यायाधीश का होना चाहिए,
 प्रथम न्यायाधीशों के मामले में यह निर्णय न्यायमूर्ति भगवती ने दिया था कि
 'अंतिम शक्ति' कार्यपालिका के पास है। यह पूरी तरह से अलग है
 दृष्टिकोण, हालांकि अलग-अलग परिस्थितियों में, समझ से परे है क्योंकि
 अंतर्निहित सिद्धांत एक ही है, अर्थात्, की स्थिति
 संबंधित मामलों के संदर्भ में भारत के मुख्य न्यायाधीश
 न्यायपालिका। दूसरा अवलोकन यह है कि अंतिम शब्द '
 कार्यपालिका द्वारा सिद्धांत पर सवाल नहीं उठाया गया था और न ही किया गया है

किसी भी मामले में, दूसरे न्यायाधीशों के मामले में भी। इसलिए,

'अंतिम शब्द' सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया है, अब कोई नहीं है इसे अस्वीकार करने का कारण। इसका उल्लेख किया जा सकता है

इस पर वापस जाने या

'अंतिम शब्द' के संदर्भ में कि जब से संविधान आया है

ग्रेनविल ऑस्टिन चीफ के हवाले से लिखते हैं कि इसे लागू किया जाना है

न्यायमूर्ति मेहर चंद महाजन की 'न्याय का एक स्तंभ':

"नेहरू ने हमेशा सलाह के अनुसार काम किया है।
सीजेआई के बारे में, उन्होंने याद किया, दुर्लभ परिस्थितियों को छोड़कर,

राज्य के राजनेताओं द्वारा 'काफी खिंचाव' के प्रयासों के बावजूद
उसे प्रभावित करने के लिए। 135

संकलचंद सेठ का मामला

146. एक और महत्वपूर्ण निर्णय है -

भारत संघ बनाम। संकलचंद हिमतलाल सेठ। 136 वह मामला
न्यायाधीशों के स्थानांतरण से संबंधित

एक उच्च न्यायालय से

135 ग्रेनविल ऑस्टिन: लोकतांत्रिक संविधान पृष्ठ 131 136 (1977) 4 एस. सी. सी. 193 (पाँच न्यायाधीशों की पीठ)

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन v. यू. ओ. जे. [मदन बी. लोकुर, जे.]

एक अन्य और अनुच्छेद 222 (1) की व्याख्या

संविधान। 137 न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लेख
भी न्यायमूर्ति वाई. बी.

साथ ही संविधान के अनुच्छेद 50 के बारे में

चंद्रचूड़:

"यह परिकल्पना करते हुए कि न्यायपालिका, जिसे कार्य करना चाहिए

लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता के गढ़ के रूप में,
के प्रभाव और हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए

कार्यपालिका, संविधान सभा ने उसे दिया

विभिन्न प्रावधानों को बनाकर एक ठोस रूप की अवधारणा
की स्वतंत्रता को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए

न्यायपालिका। संविधान का अनुच्छेद 50, जिसमें एक

न्यायपालिका को इससे अलग करने के लिए कदम उठाएगा राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालक "।

147. राष्ट्रपति द्वारा परामर्श के अर्थ पर

के अनुच्छेद 222 के संदर्भ में भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ संविधान, यह माना गया था कि इसे पूर्ण और प्रभावी होना चाहिए परामर्श और औपचारिक या अनुत्पादक नहीं। कहा गया था:

" अनुच्छेद 222 (1) राष्ट्रपति से परामर्श करने की अपेक्षा करता है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश इस सिद्धांत पर स्थापित हैं कि

ऐसे मामले में जो न्यायपालिका से संबंधित है, नहीं

कार्यपालिका को बिना निर्णय लिए निर्णय लेना चाहिए।

भारत के मुख्य न्यायाधीश के विचार प्राप्त करना, जिनके द्वारा -

प्रशिक्षण और अनुभव, विचार करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है

स्थिति निष्पक्ष, सक्षम और वस्तुनिष्ठ रूप से। लेकिन वहाँ

किसी मामले पर कोई उद्देश्यपूर्ण विचार नहीं किया जा सकता है, जिसमें

137 222. न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण। — (1) राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद, एक न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। (2) जब कोई न्यायाधीश इस प्रकार स्थानांतरित किया गया है या

किया गया है, तो वह संविधान (पंद्रहवां संशोधन) अधिनियम, 1963 के प्रारंभ के बाद अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा करने की अवधि के दौरान अपने वेतन के अतिरिक्त ऐसा प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा जो निम्नलिखित द्वारा निर्धारित किया जाए:

संसद विधि द्वारा और, इस प्रकार निर्धारित होने तक, ऐसा प्रतिपूरक भत्ता जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करे।

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तथ्यों और परिस्थितियों का अभाव

केवल इस समस्या की प्रकृति क्या हो सकती है

सराहना की और सही निर्णय लिया गया। यह होना ही चाहिए,

इसलिए, मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते समय इसका पालन करें,
 राष्ट्रपति को प्रासंगिक डेटा उपलब्ध कराना चाहिए
 जिसके आधार पर वह राष्ट्रपति को पेशकश कर सकता है
 उसकी सुविचारित राय का लाभ। अगर तथ्य
 उचित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आवश्यक नहीं हैं
 क्योंकि, राष्ट्रपति को बाध्य करने में
 मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करें, उसी समय संविधान
 मुखिया पर कर्तव्य थोपने के लिए समय निकालना चाहिए।
 पूर्ण से कम कुछ नहीं पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए न्याय
 उस मामले पर विचार करना जिस पर वह होने का हकदार है
 सलाह ली। राष्ट्रपति द्वारा उनकी पूर्ति
 प्रमुख के समक्ष पूर्ण तथ्य रखने का संवैधानिक दायित्व
 न्याय और उत्तराद्ध द्वारा निष्पादन, तथ्यों को उजागर करने का कर्तव्य जो एक उचित निष्कर्ष पर
 पहुंचने के लिए आवश्यक हैं, एक ही प्रक्रिया के हिस्से हैं और हैं
 एक-दूसरे के पूरक। वफादार पालन
 ये अच्छी तरह से एक अच्छा लाभान्श के लिए उपयोगी अर्जित कर सकते हैं
 न्याय का प्रशासन। अर्थ के भीतर परामर्श
 इसलिए अनुच्छेद 222 (1) का अर्थ है पूर्ण और प्रभावी, नहीं
 औपचारिक या अनुत्पादक, परामर्श "। 138
 148. यह देखा गया कि हालांकि 'परामर्श' नहीं हुआ
 भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श स्वीकार किया जाना चाहिए। और ऐसे संवेदनशील
 विषय में अंतिम शब्द का होना आवश्यक है
 भारत के मुख्य न्यायाधीश। यह नोट किया गया था कि यदि कोई प्रस्थान है
 भारत के मुख्य न्यायाधीश के वकील से, न्यायालय
 जाँचने का अवसर है कि क्या कोई बाहरी है निर्णय में शामिल किए गए विचार। 139
 138 अनुच्छेद 37

139 पैराग्राफ 41 शीर्ष अदालतें-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

149. इस विचार को न्यायमूर्ति कृष्ण लायर ने दोहराया था (क्योंकि स्वयं और न्यायमूर्ति फजल अली)। 140 उल्लेखनीय रूप से, यह जोड़ा गया था कि: 'हमें ऐसा लगता है कि 'परामर्श' शब्द का उपयोग किया गया है।

अनुच्छेद 222 को संवैधानिक शिष्टाचार के मामले के रूप में तथ्य यह है कि इस मामले में दो बहुत उच्च गणमान्य व्यक्ति, अर्थात् राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश, चिंतित हैं। 1 141

150. संकल्पचंद्र सेठ का अधिक महत्व

आर. पुष्पम पर भरोसा करते हुए, निष्कर्ष में निहित है कि एक सार्थक परामर्श के लिए, दोनों पक्षों के पास होना चाहिए

पूर्ण और समान तथ्यों पर विचार करें। कहा गया था:

" 'परामर्श' शब्द का अर्थ है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का सम्मेलन या दो या दो से अधिक मस्तिष्कों का प्रभाव।

एक विषय ताकि उन्हें एक सही विकसित करने में सक्षम बनाया जा सके, या

कम से कम, एक संतोषजनक समाधान "। ताकि दोनों मन

एक पारस्परिक प्रभाव प्रदान करने और उत्पन्न करने में सक्षम हो सकता है, यह है

यह आवश्यक है कि प्रत्येक को अपने विचार के लिए पूर्ण होना चाहिए और समान तथ्य, जो एक साथ अंतिम निर्णय के स्रोत और आधार दोनों का गठन कर सकते हैं। 142

151. इस दृष्टिकोण को प्रथम न्यायाधीशों के मामले में स्वीकार किया गया था।

न्यायमूर्ति भगवती, 143 न्यायमूर्ति फजल अली, 144 न्यायमूर्ति वी. डी.

तुलजापुरकर 1 45 और न्यायमूर्ति डी. ए. देसाई। 146 यह भी स्वीकार किया गया था न्यायमूर्ति पांडियन द्वारा द्वितीय न्यायाधीशों के मामले में। 147

प्रक्रिया ज्ञापन-30.6.1999

152. दिए गए निर्णय और राय का पालन करना

भारत सरकार में कानून मंत्री का गठन और नियुक्ति के लिए एक प्रक्रिया ज्ञापन तैयार किया गया

140 अनुच्छेद 115

141 अनुच्छेद 115

142 अनुच्छेद 39

143 अनुच्छेद 30

144 पैराग्राफ 563, 564 और 569

145 पैराग्राफ 632 और 663

146 पैराग्राफ 848 और 849

147 पैराग्राफ 129 से 133 और 164 [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश का और दूसरे के लिए

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति। इन्हें साझा किया गया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ। प्रत्येक क्रमिक में से कोई नहीं

भारत के मुख्य न्यायाधीशों ने किसी की भी शिकायत या आलोचना की है

जापन या उन पर प्रतिकूल टिप्पणी, या कम से कम

हमें ऐसी किसी शिकायत या आपत्ति के बारे में नहीं बताया गया है। सरकार के किसी भी क्रमिक कानून मंत्री सहित कोई नहीं

भारत सरकार ने शिकायत की कि जापन काम नहीं कर रहे थे या

या दोनों में इस न्यायालय के विचारों को सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं किया
या कि वे इसके अनुरूप नहीं थे

ऊपर वर्णित निर्णय

संविधान का कोई प्रावधान, या तो अक्षर में या भावना में या

अन्यथा भी, या कम से कम हमें ऐसी किसी बात के बारे में नहीं बताया गया है

बाधा। ये जापन चालू रहे और

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई

प्रभावी ढंग से काम करने में असमर्थता के बारे में शिकायत

प्रक्रिया जापन।

153. हमें श्री फली एस. नरीमन ने उल्लेख करने के लिए आमंत्रित किया था

दोनों सार्वजनिक रूप से न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया

ब्याज और पारदर्शिता के कारणों के लिए। जापन

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया

और उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं

भारत सरकार का न्याय विभाग 1 48 और

इसलिए इसका विस्तृत उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रक्रिया। इसी तरह के ज्ञापनों का उल्लेख किया गया है

न्यायमूर्ति पांडियन द्वारा द्वितीय न्यायाधीश का मामला। 149

154. ज्ञापन के पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि

एक न्यायाधीश की नियुक्ति की सिफारिश करने वाला एक प्रस्ताव
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाएगी

उच्च न्यायालय की शुरुआत

अदालत। हालांकि, अगर मुख्यमंत्री सिफारिश करना चाहते हैं

148 एचटीटीपी: //अभी करें। गव. /साइटों/डिफ़ॉल्ट/फाइलों/ज्ञापन में। पी. डी. एफ. (उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए): //अभी करें। गव. इन/साइट/डिफ़ॉल्ट/फाइल/मेमोस्का पी. डी. एफ. (उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए) 149 अनुच्छेद 96 और 97 सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

जिस किसी भी व्यक्ति का नाम उसे अग्रेषित करना चाहिए

मुख्य न्यायाधीश को उनके विचार के लिए। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है

स्पष्ट रूप से, यह निहित है कि मुख्य न्यायाधीश बाध्य नहीं है

मुख्यमंत्री के सुझाव को स्वीकार करें।

155. यह भी महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण है कि

'उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति करने के लिए गैर-न्यायाधीश
करने के लिए निषिद्ध नहीं है

अभिनिर्धारित है और यह नियुक्ति

उच्च न्यायालय तक। कहने का मतलब है, एक 'कॉलेजियम न्यायाधीश' नहीं है

उपयुक्तता या अन्यथा के बारे में सूचित निर्णय
लिए व्यक्ति या

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के

सुप्रीम कोर्ट। कि यह अज्ञात नहीं है ए से स्पष्ट है

एक साक्षात्कार में न्यायमूर्ति वर्मा का स्पष्ट बयान कि:

"सुप्रीम कोर्ट में हर नियुक्ति के लिए मैंने परामर्श लिया

फली एस. नरीमन और शांति भूषण जैसे वरिष्ठ वकील।

मैं पाँच या छह शीर्ष वकीलों से परामर्श करता था। मैं मध्यम स्तर के वकीलों से भी सलाह लेता था। इसी तरह

उच्च न्यायालयों के मामले में परामर्श किया गया। मैंने हर परामर्श का विवरण दर्ज किया। मैं अपने सभी की कामना करता हूँ

पत्राचार को सार्वजनिक किया जाता है।

156. इसलिए, प्रणाली के विकास के दौरान

न्यायाधीशों की नियुक्ति में चार खामियों को मंजूरी दी गई। वे थे:

(1) राष्ट्रपति की भूमिका-उनसे इस पर कार्य करने की अपेक्षा की जाती थी

नियुक्ति में भी मंत्रिपरिषद की सलाह

न्यायाधीशों की; (2) नियुक्ति के लिए प्रारंभिक सिफारिश

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जन्म मुख्य न्यायाधीश से होना था

उच्च न्यायालय का और न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए

भारत के मुख्य न्यायाधीश से उच्चतम न्यायालय; (3) परामर्श

राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश के बीच एक

एकीकृत सहभागी प्रक्रिया जिसके परिणामस्वरूप

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के तहत न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति का अंतिम निर्णय होता है।

[2015] 13 एस सी आर।

अन्य न्यायाधीशों के साथ और उनके सर्वसम्मत दृष्टिकोण पर परामर्श करना। उसके द्वारा परामर्श किया गया) निश्चित रूप से अंतिम कहना है

परिस्थितियाँ; और (4) भारत संघ ने इन्हें स्वीकार किया। तीसरे न्यायाधीशों के मामले में बिना किसी हिचकिचाहट के प्रस्ताव।

संविधान में संशोधन

157. न्यायाधीशों की नियुक्ति पर न्यायिक प्रवचनों के अलावा, संसद में भी चर्चा का अपना हिस्सा रहा है। उस पर

चार बार, संशोधन का प्रस्ताव किया गया था

नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में संविधान

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। ये

प्रस्तावित संशोधनों पर नीचे विचार किया गया है।

(क) संविधान (साठ-सातवाँ संशोधन)

बिल, 1990

158. संविधान (साठ-सातवाँ संशोधन) विधेयक,

1990 18 मई, 1990 को लोकसभा में पेश किया गया था और

इसने एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (संक्षेप में) स्थापित करने का प्रस्ताव रखा।

एन. जे. सी.), हालांकि की सिफारिशों के अनुरूप नहीं

एल. सी. आई. एन. जे. सी. की संरचना विषय के अनुसार अलग-अलग होनी थी। चिन्ता का विषय,
अर्थात्, एक न्यायाधीश की नियुक्ति

उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति।

159. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए

न्यायालय, संविधान के प्रस्तावित अनुच्छेद 307 ए के संदर्भ में,

एन. जे. सी. में भारत के मुख्य न्यायाधीश और दो न्यायाधीश शामिल होने थे।

भारत का न्याया। उच्च न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए न्यायालय, एन. जे. सी. में भारत के मुख्य
न्यायाधीश, मुख्यमंत्री या राज्यपाल (जैसा भी मामला हो) शामिल होना था।

संबंधित राज्य, उच्चतम न्यायालय का एक अन्य न्यायाधीश अगला भारत के मुख्य न्यायाधीश से
वरिष्ठता में,

वरिष्ठता में उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अगले हैं

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को।

शीर्ष अदालतों का कोई प्रावधान नहीं था-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकर, जे.]

भारत के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश।

160. व्यवसाय के लेन-देन की प्रक्रिया

एन. जे. सी. का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा परामर्श से किया जाना था

भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ और बनाए गए किसी भी कानून के अधीन था

संसद द्वारा।

161. संशोधन अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि एन. जे. सी. की सिफारिश स्वीकार नहीं होने की स्थिति में, कारण इसलिए इसे लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।

162. बिल की (आंशिक रूप से) बकायेदारों द्वारा आलोचना की गई थी।

समिति ने कहा कि:

"समिति कोई तर्क या औचित्य खोजने में असमर्थ है।

विभिन्न आयोगों के लिए। उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए

और आयोग के गठन के कारण,

अर्थात्, कार्यकारी मनमानेपन की आलोचना को दूर करने के लिए

उच्च न्यायालय की नियुक्ति और स्थानांतरण के मामले में

न्यायाधीशों और नियुक्तियों में देरी को रोकने के लिए,

प्रमुख के माध्यम से कार्यपालिका के लिए कोई औचित्य नहीं है

मंत्री आयोग में होंगे। हटाने के बजाय

कार्यकारी हस्तक्षेप का दोष जिसने दूषित कर दिया है

वर्तमान प्रणाली का संचालन-प्रमुख की उपस्थिति

सिफारिश करने वाले निकाय के मंत्री वास्तव में राहत देते हैं

उसे एक मात्र प्रतिनिधि की स्थिति से लेकर पद तक

चयन प्रक्रिया में एक समान प्रतिभागी

अनुशंसित निकाय। मुख्यमंत्री बनाकर

नियुक्तियों के लिए उम्मीदवारों की योग्यता, क्षमता, योग्यता, सत्यनिष्ठा और उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए, कार्यकारी हस्तक्षेप को बढ़ाया जाता है।

150

163. विधेयक पर विचार नहीं किया गया क्योंकि

मई, 1991 में लोकसभा का विघटन।

(ख) संविधान (नब्बे-आठवाँ संशोधन)

बिल, 2003

164. 22 फरवरी, 2000 को-मुश्किल से 8 महीने बाद

(संशोधित) प्रक्रिया ज्ञापन जारी करना ऊपर उल्लिखित भारत सरकार ने एक

समीक्षा के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की अधिसूचना

संविधान का कार्यकरण (संक्षेप में एन. सी. आर. डब्ल्यू. सी.),

न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया सहित उच्चतर न्यायपालिका। एन. सी. आर. डब्ल्यू. सी. के संदर्भ की शर्तें थीं

इस प्रकार है:

"आयोग इस बात की जांच करेगा कि

पिछले 50 वर्षों का अनुभव, कि कितना अच्छा है संविधान की बदलती जरूरतों का जवाब दे सकता है

कुशल, सुचारू और प्रभावी शासन प्रणाली और आधुनिक भारत का सामाजिक-आर्थिक विकास

संसदीय लोकतंत्र की रूपरेखा और

परिवर्तनों की सिफारिश करें, यदि कोई हो, जो आवश्यक हैं

संविधान के प्रावधानों में हस्तक्षेप किए बिना बुनियादी संरचना या विशेषताएँ। "

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की आयु न्यायाधीशों का स्थानांतरण

न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, उच्च न्यायालयों के

और एक न्यायाधीश के 'विचलित' व्यवहार से निपटने की प्रक्रिया

और उसे हटाने के लिए।

166. न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में

उच्चतर न्यायपालिका, पत्र का अनुच्छेद 8.20 महत्वपूर्ण है। करता है कि प्रक्रिया विकसित हुई है

क्योंकि यह मौन रूप से स्वीकार

विशेष रूप से दूसरे न्यायाधीशों के मामले के परिणामस्वरूप वर्ष

151 परामर्श पत्र विधि मंत्रालय की वेबसाइट पर पाया जा सकता है। यह 2 मई, 2015 को प्राप्त किया गया था: एचटीटीपी: //लॉमिन। ठीक है। इन/एन. सी. आर. डब्ल्यू. सी./फाइनलरिपोर्ट/वी2 बी 1-14।

एच. टी. एम. सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

तीसरे न्यायाधीश का मामला काफी संतोषजनक था। अनुच्छेद

इस प्रकार पढ़ता है:

" 8.20 67 वें संशोधन विधेयक का उद्देश्य

एस. सी. ए. ओ. आर. ए में निर्णय: हमने (उच्चतम न्यायालय में) नियुक्ति के कई तरीके निर्धारित किए हैं।

और उच्च न्यायालय) विभिन्न निकायों द्वारा सुझाए गए,

समितियाँ और संगठन। हमने यह भी तय किया है कि

द्वारा बनाई गई नियुक्ति की विधि और प्रक्रिया
न्यायालय का निर्णय और

1993 एस. सी. ए. ओ. आर. ए. 1 52 में उच्चतम

1998 में अनुच्छेद 143 के तहत दी गई राय में। यह होगा।
प्रभावी होता है

इससे यह स्पष्ट हो कि 1993 का निर्णय

संविधान के सार के लिए (साठ-सातवाँ

संशोधन) विधेयक, निश्चित रूप से इसे 'राष्ट्रीय' बताए बिना

न्यायिक आयोग', और आवश्यकता के बिना

उक्त द्वारा सुझाए गए संविधान में संशोधन करना

संशोधन विधेयक। वास्तव में, यह वस्तु को आगे ले जाता है

संशोधन विधेयक को अंतर्निहित करते हुए

भारत के मुख्य न्यायाधीश और उनकी सिफारिशें

राष्ट्रपति को बाध्य करने वाले सहयोगी। 1998 की राय

वास्तव में 'कॉलेजियम' का विस्तार करता है। इस अर्थ में, उक्त संशोधन विधेयक का उद्देश्य

अनुच्छेद 124 (2) के प्रावधान और इसके साथ जोड़ा गया स्पष्टीकरण

व्यापक रूप से बोलते हुए, वहाँ परोसा जाता है। की विधि

इन निर्णयों द्वारा विकसित नियुक्ति ने वास्तव में

कई न्यायविदों द्वारा सराहा गया और एक के रूप में माना जाता है
अनुकरण के योग्य उदाहरण। (देखें।

यू. के. और अन्य लोगों द्वारा

सदन के एक सदस्य, लॉर्ड टेम्पलमैन की राय

इस प्रस्ताव को कम करें कि "परामर्श" पर विचार किया गया था वास्तविक और प्रभावी होना चाहिए।

अनुच्छेद 124 और 217 को

परामर्श और अवधारणा को ध्यान में रखते हुए
न्यायिक स्वतंत्रता, जो एक बुनियादी विशेषता है
संविधान, मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी गई राय

न्यायाधीशों का मामला [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत सरकार (अपने सहयोगियों से परामर्श करने के बाद) कार्यपालिका के लिए बाध्यकारी होगी।
इस मामले के दृष्टिकोण से, अधिकांश

राष्ट्रीय न्यायिक आयोग से अपेक्षाएँ

(एन. जे. सी.) से मुलाकात हुई है। उक्त संविधान

ऐसा प्रतीत होता है कि संशोधन विधेयक इसके बाद तैयार किया गया था
सभी राजनीतिक दलों के साथ व्यापक और विस्तृत परामर्श

पार्टियाँ और अन्य हितधारक। हालांकि, अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र का पहलू अभी भी अनुत्तरित है।
हम कर सकते हैं

हालाँकि एक एन. जे. सी. की अवधारणा पर चर्चा करें जो हो सकता है

नियुक्तियाँ और अनुशासन के मामले दोनों शामिल हैं।

167. पत्र ने स्वीकार किया कि द्वितीय न्यायाधीश

मामला और तीसरे न्यायाधीशों के मामले ने 'व्यापक रूप से बोलते हुए' कार्य किया

संविधान (साठ-सातवाँ संशोधन) विधेयक का उद्देश्य

और राष्ट्रीय न्यायपालिका से बहुत अधिक अपेक्षाएँ

आयोग (एन. जे. सी.) की बैठक हो चुकी है। में कमियां

अपेक्षाओं को पेपर में निर्दिष्ट नहीं किया गया था सिवाय इसके कि

अनुशासनात्मक अधिकारिता जो उत्पन्न नहीं हुई थी और नहीं थी

दूसरे न्यायाधीशों के मामले या तीसरे न्यायाधीशों के मामले में निपटा गया

मामला। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक उदासीन न्यायविद लॉर्ड टेम्पलमैन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के एक सदस्य यह विचार कि भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली होनी चाहिए इंग्लैंड में भी इसका पालन किया जाना है। उसके अलावा, सिस्टम इन निर्णयों द्वारा निर्धारित न्यायाधीशों की नियुक्ति का कई न्यायविदों द्वारा सराहा गया और इसे एक मिसाल के रूप में माना जाता है अनुकरण के योग्य '।

168. जो भी हो, एन. सी. आर. डब्ल्यू. सी. ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 31 मार्च, 2002 को प्रधानमंत्री को। अध्याय 7 में न्यायपालिका से संबंधित रिपोर्ट, एन. सी. आर. डब्ल्यू. सी. ने सिफारिश की अनुच्छेद 7.3। 7 राष्ट्रीय न्यायपालिका की स्थापना आयोग (संक्षेप में एन. जे. सी.)। यह देखा गया कि ए आयोग राज्य की कार्यपालिका और न्यायिक दोनों शाखाओं की प्रभावी भागीदारी के लिए आवश्यक था। न्यायाधीशों के सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं की नियुक्ति के लिए तंत्र के लिए एकीकृत योजना-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.] ई एकीकृत सहभागी परामर्श प्रक्रिया के साथ इस न्यायालय द्वारा द्वितीय न्यायाधीशों के मामले में औरडी न्यायाधीशों का मामला। एन. सी. आर. डब्ल्यू. सी. का कहना था:

"न्यायाधीशों की नियुक्ति के तरीके से संबंधित मामला एक दशक से अधिक समय से बहस चल रही थी। संविधान 18 मई, 1990 (9 वीं लोकसभा) राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का संस्थागत ढांचा कार्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने के लिए उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालय। इसके अलावा, ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में पूरे क्षेत्र में एक आंदोलन है

दुनिया इस कार्य को अनन्य फिएट से दूर ले जाने के लिए
कार्यपालिका का और कुछ संस्थागत ढांचे को शामिल करना
कुछ स्थानों पर न्यायपालिका के साथ परामर्श के तहत काम करें
ऐसा करने से पहले स्तर प्रदान किया जाता है
नियुक्तियाँ। किसी रूप में परामर्श की प्रणाली यह पहले से ही जापान, इज़राइल और यूके में
उपलब्ध है। द.

संविधान (साठवां संशोधन) विधेयक, 1990
भारत के मुख्य न्यायाधीश के कॉलेजियम के लिए प्रावधान और
बनाने के लिए उच्चतम न्यायालय के दो अन्य न्यायाधीश
के साथ एक सहभागी मोड रखने के लिए सार्थक हो कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों की
भागीदारी
कॉलेजियम की संरचना का प्रस्ताव करता है जो देता है उचित महत्व और प्रभावी के लिए
प्रदान करता है
कार्यपालिका और न्यायिक दोनों शाखाओं की भागीदारी
मशीनरी के लिए एक एकीकृत योजना के रूप में राज्य का
न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। इस आयोग ने तदनुसार,
एक राष्ट्रीय न्यायपालिका की स्थापना की सिफारिश करता है
संविधान के तहत आयोग।
की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(1) भारत के मुख्य न्यायाधीश:

सभापति

सदस्य

(2) दो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश

सुप्रीम कोर्ट:

सदस्य

(3) केंद्रीय कानून मंत्री

और न्याय:

(4) एक प्रतिष्ठित व्यक्ति नामित

सदस्य

राष्ट्रपति द्वारा परामर्श के बाद
भारत के मुख्य न्यायाधीश:

राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना और इसकी संरचना के लिए निम्नलिखित सिफारिशों की जानी हैं

-

संरक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अभिन्न माना जाता है

न्यायपालिका की स्वतंत्रता "। 15

169. एन. सी. आर. डब्ल्यू. सी. की सिफारिशों के अनुसार,

संविधान (अठानवेवां संशोधन) विधेयक, 2003

8 मई, 2003 को या उसके आसपास संसद में पेश किया गया था। द.

विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है,

कि भारत सरकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक एन. जे. सी. की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है,

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों के साथ-साथ उनके

हस्तांतरण ताकि दोनों की प्रभावी भागीदारी हो सके

सरकार की कार्यपालिका और न्यायिक शाखाएँ। यह है।

उल्लेख किया कि एन. सी. आर. डब्ल्यू. सी. ने भी इस मामले पर विचार किया और

एन. जे. सी. की स्थापना की सिफारिश की।

170. उद्देश्यों और कारणों का कथन संदर्भित करता है -

एन. जे. सी. की संरचना और जबकि एन. सी. आर. डब्ल्यू. सी.

भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित प्रतिष्ठित नागरिक
साथ परामर्श

एक अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री के

153 अनुच्छेद 7.3।

7 सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

तीन साल।

171. संविधान (नब्बे-आठवाँ संशोधन) विधेयक

संविधान में अध्याय IVA को शामिल करने का प्रस्ताव
अनुच्छेद शामिल है। यह लेख

जिसमें अनुच्छेद 147 ए नामक एक

एन. जे. सी. की स्थापना से संबंधित

उद्देश्यों और कारणों का विवरण।

172. यह विधेयक संसद के किसी भी सदन में पारित नहीं हुआ था

मार्च 2004 में लोकसभा के विघटन के कारण और

आम चुनाव बुलाए जा रहे हैं।

(ग) संविधान (एक सौ बीसवाँ)

संशोधन) विधेयक, 2013

173. वरिष्ठ न्यायाधीशों की नियुक्ति के उद्देश्यों के लिए संविधान में संशोधन करने का एक और प्रयास किया गया

न्यायपालिका। यह संविधान की शुरुआत से था (एक

एक सौ बीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2013 में पेश किया गया

24 अगस्त 2013 को राज्यसभा।

174. विधेयक के उद्देश्यों और कारणों का विवरण

उल्लेख किया कि ज्ञापन न्यायपालिका को प्रदान करता है
नियुक्ति की शक्ति

स्वयं वरिष्ठ के न्यायाधीशों की

न्यायपालिका, 154 यह आगे कहा गया कि की समीक्षा के बाद

इस न्यायालय की घोषणाएँ और प्रासंगिक संवैधानिक
आयोग

प्रावधान, एक व्यापक न्यायिक नियुक्ति

सिफारिशें करने के लिए स्थापित किया जा सकता है

न्यायाधीशों का चयन। यह आयोग एक
लिए सार्थक भूमिका

कार्यपालिका और न्यायपालिका को प्रस्तुत करने के

उनका दृष्टिकोण और प्रतिभागियों को जवाबदेह बनाते हुए

चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना। द.

उद्देश्यों और कारणों के विवरण में यह भी उल्लेख किया गया है कि

प्रस्तावित विधेयक न्यायपालिका की समान भागीदारी को सक्षम बनाएगा।

154 यह तथ्यात्मक रूप से गलत है। ज्ञापन कानून मंत्री द्वारा तैयार किया गया था और न्यायपालिका को कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई थी।

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका और प्रणाली को अधिक जवाबदेह भी बनाना और जिससे न्यायपालिका में जनता का विश्वास बढ़ता है।

175. संविधान (एक सौ बीसवाँ)

संशोधन) विधेयक में अनुच्छेद 124 ए को शामिल करने का प्रस्ताव है।

एन. जे. ए. सी. की संरचना, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति और सदस्य, उनकी योग्यताएँ, सेवाओं की शर्तें,

कार्यकाल, कार्य और प्रक्रिया के साथ-साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों का चयन,

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश

द्वारा बनाए गए कानून द्वारा उच्च न्यायालयों का प्रावधान किया जाना था

संसद।

176. संविधान (एक सौ बीसवाँ)

संशोधन) विधेयक राज्य सभा द्वारा 5 तारीख को पारित किया गया था

सितंबर 2013 में लोकसभा भंग कर दी गई थी।

2014 इससे पहले कि विधेयक को भेजा जा सके और आम चुनाव फोन किया।

177. आश्चर्यजनक रूप से, उद्देश्यों और कारणों का कथन

इस तथ्य की पूरी तरह से अनदेखी की गई कि पहले से ही न्यायपालिका और कार्यपालिका की समान भागीदारी थी

उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति। दूसरे में

न्यायाधीशों का मामला यह स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से कहा गया था

वह:

"उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया एक एकीकृत सहभागी प्रक्रिया है।

सामूहिक रूप से एक दृष्टिकोण के साथ मुख्य रूप से एक सहमत तक पहुंचने के लिए निर्णय, संवैधानिक उद्देश्य को पूरा करते हुए, ताकि सर्वोच्च न्यायालय अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन v.

यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

प्रधानता का अवसर उत्पन्न नहीं होता है "। 155

हालांकि, मतभेद की स्थिति में, एक

संवैधानिक अधिकारियों को अंतिम निर्णय लेना चाहिए और देना चाहिए

दशकों से संवैधानिक सम्मेलन अंतिम कहता है

भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ होना चाहिए,

भारत में कुछ परिस्थितियों में न्यायपालिका और

कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति। अन्यथा, एक गतिरोध

या गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसकी संविधान सभा को स्पष्ट रूप से दो संवैधानिक संस्थाओं से उम्मीद नहीं थी कार्यकर्ता। द्वितीय न्यायाधीश का मामला और तृतीय न्यायाधीश

इस मामले ने राष्ट्रपति को यह साझा जिम्मेदारी दी और

भारत के मुख्य न्यायाधीश। 156 न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए

उच्चतम न्यायालय, 5 (पाँच) न्यायाधीशों के कॉलेजियम को एक

सर्वसम्मत सिफारिश। राष्ट्रपति को पलटने का अधिकार है 4-1 या 3-2 की सिफारिश करें। यदि सर्वसम्मत

राष्ट्रपति के पक्ष में सिफारिश नहीं मिलती है

मजबूत और ठोस कारण और कॉलेजियम को वापस कर दिया जाता है

पुनर्विचार, और इसे सर्वसम्मति से दोहराया जाता है, फिर राष्ट्रपति सिफारिश को स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं। हालांकि,

यदि दोहराव सर्वसम्मत नहीं है, तो राष्ट्रपति का अधिकार है

सिफारिश को अस्वीकार करना। वह सिद्धांत जो संविधान (एक सौ बीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2013 [और बाद में संविधान (एक सौ और 21 वां संशोधन) विधेयक, 2014] ने इसे ध्वस्त करने का प्रयास किया 'न्यायाधीशों की नियुक्ति 'अस्तित्व में नहीं है।

(घ) संविधान (एक सौ इकतीस) संशोधन) विधेयक, 2014

178. चौथा और अंतिम प्रयास (वर्तमान में सफल) और इन याचिकाओं में चुनौती के तहत) संशोधन करने के लिए संविधान 11 अगस्त, 2014 को प्रस्तुत किया गया था।

155 पैराग्राफ 486 (1)

156 राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ व्यवहार करते समय 'प्रधानता' शब्द से कुछ असहज हूं। न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में, एल. सी. आई. द्वारा अपनी 14 वीं रिपोर्ट में इस्तेमाल किया गया 'उत्तरदायित्व' शब्द अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है।

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) बिल, 2014। यह विधेयक 13 तारीख को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। अगस्त, 2014 और 14 अगस्त, 2014 को राज्यसभा द्वारा। यह.

संविधान के अनुच्छेद 368 (2) द्वारा आवश्यक और प्राप्त किया 31 दिसंबर, 2014 को राष्ट्रपति की मंजूरी जब यह

संविधान (नब्बे-नौवां संशोधन) अधिनियम 2014 बन गया।

179. यह उल्लेख किया जा सकता है कि विद्वान

सॉलिसिटर जनरल से रिकॉर्ड में रखने का अनुरोध किया गया था अनुसमर्थन के लिए राज्य विधानमंडलों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया

संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन)

विधेयक, 2014 लेकिन वह जानकारी आने वाली नहीं थी, कारणों से जो ज्ञात नहीं हैं। इरादा तथ्य पर सवाल उठाने का नहीं था। अनुसमर्थन का लेकिन केवल प्रक्रिया को समझने और जोड़ने के लिए प्रक्रिया में पारदर्शिता, क्योंकि ऐसे उदाहरण हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में जहां अदालतों ने इस मुद्दे की जांच की है अनुसमर्थन। 157

संविधान में संशोधन का

पारदर्शिता एक तरफा रास्ता नहीं है।

180. संविधान की धारा 1 (2) (नब्बे-नौवीं)

संशोधन) अधिनियम 2014 में प्रावधान है कि यह लागू होगा।

ऐसी तारीख को केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा

आधिकारिक राजपत्र, नियुक्त करें। नियत तिथि 13 अप्रैल है।

2015.

181. संविधान पारित होने के साथ-साथ

(एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, संसद

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति पर भी विचार किया गया

आयोग विधेयक, 2014। यह विधेयक संसद में पेश किया गया था 13 तारीख को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।

11 अगस्त, 2014 को। यह

अगस्त, 2014 और 14 अगस्त, 2014 को राज्यसभा द्वारा।

157 उदाहरण के लिए देखें - हैमंड बी। क्लार्क, 136 जीए। 313 (1911), फाहे बी। हैकमैन, 291 मो। 351 (1922), एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज ऑफ ओक्लाहोमा बनाम। ओक्लाहोमा कर आयोग, 176 ओक्ला। 120 (1936), विस्कॉन्सिन राज्य बनाम। एडम एस. गोंजालेस, 253 Wis.2d 134 (2002), द स्टेट बनाम। स्विफ्ट, 69 भारतीया। 505 (1880) आदि।

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम भी

और इसे जारी राजपत्र अधिसूचना द्वारा लागू किया गया था

13 अप्रैल, 2015 को।

182. दोनों संविधान (नब्बे-नौवां संशोधन) अधिनियम,

2014 और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम,
रिट का एक समूह

2014 इसमें चुनौती दी जाती है और संबंधित

याचिकाएँ।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर निष्कर्ष

183. जिन निष्कर्षों से निकाला जा सकता है

पृष्ठभूमि ऐतिहासिक तथ्य इस प्रकार हैं:

(1) न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमेशा से रही है

(2) स्वतंत्रता से पहले, किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति पूरी तरह से क्राउन के विवेक पर निर्भर थी। द. संविधान सभा ने महसूस किया कि ऐसा 'सर्वोच्च और निरपेक्ष'

शक्ति राष्ट्रपति या सरकार में निहित नहीं होनी चाहिए

उस दिन या भारत के मुख्य न्यायाधीश (एक व्यक्ति के रूप में) और इसलिए उस शक्ति पर एक बंधन लगाया गया था

राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेंगे (के साथ)

अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करने का विवेकाधिकार)

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए

उच्च न्यायालय ने भी, भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श किया

अनिवार्य था। इसके अलावा, मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श

उच्च न्यायालय और राज्य के राज्यपाल का होना अनिवार्य था।

महत्वपूर्ण बात यह है कि नागरिक समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ परामर्श का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) राष्ट्रपति की व्यक्तिगत भूमिका के बारे में कोई संदेह

न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया रुक गई और यह था

स्पष्ट करें कि राष्ट्रपति से केवल सलाह पर कार्य करने की अपेक्षा की जाती थी

मंत्रिपरिषद से।

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(4) इसी तरह, भारत के मुख्य न्यायाधीश से यह उम्मीद नहीं की जाती है कि

व्यक्तिगत या व्यक्तिगत क्षमता में कार्य करें लेकिन उनसे परामर्श करना चाहिए।

उसके वरिष्ठ न्यायाधीशों के लिए एक सिफारिश करने से पहले

न्यायाधीश की नियुक्ति।

(5) डॉ. अम्बेडकर और संविधान सभा ने सीएडी में 'निरंकुश विवेकाधिकार' सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया, लेकिन यह

बाद में प्रथम न्यायाधीशों के मामले में विचार को खारिज कर दिया गया था

जिसके द्वारा प्रस्तावित 'अंतिम शक्ति' सिद्धांत लाया गया

न्यायमूर्ति भगवती और न्यायमूर्ति देसाई।

(6) नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यकारी हस्तक्षेप

(शायद 'अधिग्रहण' के एक अनौपचारिक तरीके के साथ) शुरू हो गया था

स्वतंत्रता के समय के आसपास और स्वतंत्रता के बाद उग्र हो गया, जो 1980 के दशक के अंत में चरम पर था।

(7) हमें एक भी उदाहरण नहीं दिया गया था जहाँ

राष्ट्रपति ने न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए एक व्यक्ति की सिफारिश की

उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय। मुख्यमंत्री ने

हो सकता है कि किसी राज्य ने एक सिफारिश की हो (हालाँकि नहीं)

उदाहरण हमें दिया गया था) लेकिन इसे रूट करने की आवश्यकता थी

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से, के अनुसार

प्रक्रिया ज्ञापन।

(8) केवल एक उदाहरण हमें दिया गया था, पहले से पहले

न्यायाधीशों का मामला जहाँ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति

भारत से। प्रथम न्यायाधीशों के मामले को इस तरह के सात मामलों में दर्ज करें
गई। यह एक स्पष्ट संकेत है कि

नियुक्तियाँ की

'प्रथम न्यायाधीशों के मामले में प्रस्तावित अंतिम शक्ति सिद्धांत

'पूर्ण कार्यकारी प्रधानता' में अनुवादित। डॉ. का सपना

अम्बेडकर एक दुःस्वप्न बन गए, राजनीतिक कारणों से

(9) 'परम शक्ति' सिद्धांत या 'पूर्ण कार्यकारी प्रधानता' सिद्धांत अब कमजोर हो गया है और अंतिम शब्द है
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति साझा सर्वोच्च न्यायालय-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन v है।

यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश के बीच द्वितीय न्यायाधीशों के मामले और तृतीय न्यायाधीशों के मामले में। ऐतिहासिक रूप से, कार्यपालिका को अंतिम शब्द दिया गया है

कम से कम महान्यायवादी श्री एम. सी.

सीतलवाड़ जिन्होंने भारत के विधि आयोग की अध्यक्षता की जब

14 रिपोर्ट दी गई थी। उस प्रणाली ने ठीक से काम नहीं किया है।

जैसा कि समय-समय पर उल्लेख किया गया है।

(10) कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग

संविधान के साथ-साथ एक जिम्मेदार न्यायाधीश

हाउस ऑफ लॉर्ड्स की राय थी कि प्रक्रिया के लिए

द्वितीय न्यायाधीशों के मामले और तृतीय न्यायाधीशों के मामले में निर्धारित न्यायाधीशों की नियुक्ति व्यापक रूप से उद्देश्य को पूरा करती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखना और

वरिष्ठ न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक उपयुक्त विधि

अदालतें।

184. इसका मतलब यह नहीं है कि 'कॉलेजियम प्रणाली' है

एकदम सही। शायद ही ऐसा हो। सुनवाई के दौरान, कुछ आलोचनात्मक संबंध में टिप्पणियां की गईं

कुछ की नियुक्ति के

इस न्यायालय के न्यायाधीश जो, यह विद्वान द्वारा प्रस्तुत किया गया था

महान्यायवादी संभव नहीं होता अगर ऐसा न होता

कॉलेजियम प्रणाली की विफलता। यहाँ तक कि याचिकाकर्ता भी थे

कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना। लेकिन मुझे व्यक्त करना होगा कि 'हमला' शुरू किया गया था, उस पर पीड़ा

जिस तरह से एक

उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित कुछ विद्वान वकील। यह कभी-कभी विवेकहीन और पूरी तरह से अनावश्यक था।

न्यायाधीशों को बदनाम करना सबसे आसान काम है जो वे नहीं कर सकते।

वापस लड़ें और यह सुनिश्चित करने का सबसे निश्चित तरीका है कि न्यायपालिका स्वतंत्रता खो देता है और लोगों में विश्वास खो देता है

अपनी

न्यायपालिका, जो शायद ही उचित हो। बार का एक बराबर है (यदि
 न्यायपालिका की स्वतंत्रता में अधिक नहीं) हिस्सेदारी और प्रासंगिक क्षणों में बार का मौन
 अकथनीय है। द.
 समाधान, बड़े कैनवास में, एक लोकतांत्रिक लेखा परीक्षा है, एक लेखा परीक्षा है न्यायपालिका
 और कानून के शासन तक सीमित।

यदि कुछ सकारात्मक [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्याय वितरण में विकास को शामिल किया जा सकता है प्रणाली (व्यापक संदर्भ में) उन्हें इस तरह
 से शामिल किया जाना चाहिए।

इस संदर्भ में इन शब्दों को याद करना दिलचस्प है।

185.

संविधान के कार्यकरण पर डॉ. अम्बेडकर:

संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यह निश्चित रूप से बदल जाएगा।

बुरा क्योंकि जिन्हें काम करने के लिए बुलाया जाता है, वे होते हैं

बहुत बुरा होना। संविधान कितना भी खराब क्यों न हो,

अच्छा साबित हो सकता है अगर जिन्हें काम करने के लिए बुलाया जाता है,

पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर नहीं है

संविधान "। 158

186. दोनों 'पूर्ण कार्यकारी प्रधानता' प्रणाली या

'परम शक्ति सिद्धांत और कॉलेजियम प्रणाली उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों
 की नियुक्ति

अदालतें अपने समय में स्वीकार्य प्रणालियाँ थीं। 'कार्यकारी प्रधानता' प्रणाली का, दुर्भाग्य से, कार्यपालिका
 द्वारा दुरुपयोग किया गया था

और न्यायपालिका इसके बारे में बहुत कम कर सकती है, क्योंकि न्यायाधीश कानून के शासन से बंधे होते हैं।
 इस बदसलूकी के कारण

इस न्यायालय के वकील के कहने पर संवैधानिक प्रावधानों पर पुनर्विचार किया गया और पुनरीक्षण ने सही
 दिया

हमारे संवैधानिक इतिहास में व्याख्यात्मक अंतर्दृष्टि और

संवैधानिक प्रावधान। यह वह अंतर्दृष्टि है जिसके परिणामस्वरूप
द्वितीय न्यायाधीश का मामला और एक सार्थक और व्यावहारिक
संविधान की व्याख्या।

187. कि दूसरे न्यायाधीशों का मामला सही था
बहुमत द्वारा निर्णय तीसरे न्यायाधीशों में स्वीकार किया गया था
महान्यायवादी द्वारा मामला और अधिक महत्वपूर्ण क्या है
राष्ट्रपति (मंत्री परिषद द्वारा सहायता प्राप्त और सलाह प्राप्त)
जिन्होंने दूसरे में निर्धारित डिक्टा को उलटने की मांग नहीं की
न्यायाधीशों का मामला।

188. कहने के लिए, जैसा कि सुनवाई के दौरान हमें बताया गया था

158 एचटीटीपी: //भारत की संसद। ठीक है। इन/एलएस/डिबेट/वॉल्यूम 11 पी11।

एच. टी. एम. सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकर, जे.]

मामला, कि कॉलेजियम प्रणाली विफल हो गई है और इसकी आवश्यकता है

प्रतिस्थापन सही या उचित पोस्टमॉर्टम नहीं होगा। यह है।

यह सच है कि इसकी आलोचना (कभी-कभी तीखी) हुई है

न्यायाधीशों की नियुक्ति की एकीकृत प्रक्रिया में कार्यपालिका की समान रूप से महत्वपूर्ण सहभागी भूमिका
थी। कि कार्यकारी ने एक पराजयवादी को अपनाया या एक आई-डॉट-केयर रवैया सबसे अधिक है।

दुर्भाग्यपूर्ण है। कॉलेजियम को सभी बुराइयों के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति-राजनीतिक कार्यपालिका को साझा करना पड़ता है

समान रूप से दोष यदि अधिक नहीं है, क्योंकि इसने इसे गिरवी रखा है

क्या हो सकता है, इस पर नियंत्रण बनाए रखने की संवैधानिक जिम्मेदारी
निर्णयों के रूप में वर्णित किया जाए।

कॉलेजियम के गलत

189. यह कहना कि कार्यपालिका की कोई भूमिका नहीं थी (जैसे

हमें सुझाव दिया गया था) कम से कम कहना गलत है, जैसा कि स्पष्ट है

द्वितीय न्यायाधीशों के मामले को बारीकी से पढ़ने से और तीसरे न्यायाधीशों का मामला। राष्ट्रपति ने भी ऐसा नहीं सोचा था। मैं वास्तव में, राष्ट्रपति की स्पष्ट राय थी कि नियुक्ति में कार्यपालिका या कम से कम राज्य के प्रमुख की भूमिका थी न्यायाधीशों से। यह "मेरिट" शीर्षक वाले एक लेख से स्पष्ट होता है न्यायाधीशों की नियुक्ति '159 जो भारत के एक मुद्दे से उद्धृत है 25 जनवरी, 1999 की आज की पत्रिका निम्नलिखित टिप्पणी करती है: न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा किया गया उच्चतम न्यायालय का:

"मैं अपने विचारों को दर्ज करना चाहूंगा कि सिफारिश करते समय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, यह होगी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे समाज में 25 प्रतिशत जनसंख्या, और महिलाओं को देय दिया जाता है विचार करें। इन श्रेणियों के पात्र व्यक्ति उपलब्ध हैं और उनका कम प्रतिनिधित्व या गैर प्रतिनिधित्व उचित नहीं होगा। रखते रहें।

159 प्रोफेसर एम. पी. सिंह द्वारा, (1999) 8 एस. सी. सी. (जर्नल) 1 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

आवश्यकता को देखते हुए खाली पद भी वांछनीय नहीं हैं। समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व और उच्चतम न्यायालय को संभालने के लिए काम की मात्रा की आवश्यकता होती है। बताया जाता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने जवाब दिया है इस प्रकार है:

अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों सहित जातियों और जनजातियों पर हम विचार करते हैं जबकि

सर्वोच्च पद पर नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करना

न्यायालय के न्यायाधीश। हमारा संविधान इस योग्यता की परिकल्पना करता है केवल सर्वोच्च पद पर सभी नियुक्तियों के लिए मानदंड है

न्यायालय और उच्च न्यायालय। और हम ईमानदारी से पालन कर रहे हैं

इन प्रावधानों के लिए। एक अधूरी रिक्ति का कारण नहीं हो सकता है

उतना ही नुकसान जितना कि गलत तरीके से भरी गई रिक्ति "।

190. कॉलेजियम प्रणाली को बनाए रखने के लिए वह सब आवश्यक था

एक प्रभावी कार्यान्वयन रणनीति, गंभीर और सार्थक आत्मनिरीक्षण और शायद कुछ बढ़िया ट्यूनिंग और

इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ट्विकिंग। दुर्भाग्य से, कार्यकारी

शायद अपनी गलतफहमी के कारण सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी इस न्यायालय के निर्णय।

191. दूसरी ओर, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष

न्यायविद, लॉर्ड टेम्पलमैन ने एकीकृत परामर्श की प्रशंसा की

कॉलेजियम प्रणाली और इसे एक विधि के रूप में अनुशंसित किया कि

अंग्रेज फायदा उठा सकते थे। विद्वान न्यायाधीश ने लिखा:

"हालाँकि, भारत में पहले के अनुभव को ध्यान में रखते हुए

कार्यपालिका द्वारा न्यायपालिका के सदस्यों के व्यक्तित्व और दृष्टिकोण को प्रभावित करने के प्रयासों का, और

पाकिस्तान में किए गए सफल प्रयासों के संबंध में

न्यायपालिका को नियंत्रित करना, और दुर्भाग्यपूर्ण सर्वोच्च न्यायालयों को ध्यान में रखते हुए-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. /मदन बी. लोकुर, जे./

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के परिणाम

राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका अनुमोदन के अधीन

कांग्रेस द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय का बहुमत निर्णय
एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड मामले में भारत ने एक

न्यायपालिका की स्वतंत्रता का स्वागत

और नियुक्तियाँ प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है

अखंडता और गुणवत्ता, एक पूर्ववर्ती विधि जो अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई थी
लाभ के साथ पालन कर सकते हैं। " 160

जबकि अन्य लोग हमारी नियुक्ति प्रणाली की प्रशंसा करते हैं

न्यायाधीशों के लिए, हम केवल तिरस्कार कर सकते हैं!

प्रारंभिक मुद्दा-दूसरे पर पुनर्विचार

न्यायाधीशों का मामला और तीसरे न्यायाधीशों का मामला

192. इस बल्कि विस्तृत इतिहास के साथ, प्रारंभिक

99 वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद से रखरखाव योग्य नहीं है और एन. जे. ए. सी.
अधिनियम लागू नहीं हुआ है; (2) रिट याचिकाएं समय से पहले हैं और राष्ट्रीय स्तर से विचारणीय नहीं हैं।

न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन नहीं किया गया है।

और इसलिए 99 वें संविधान का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है

संशोधन अधिनियम और एन. जे. ए. सी. और कोई तथ्य नहीं बताए गए हैं।

इस संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा; (3) मामलों के इस समूह को

9 (नौ) या अधिक न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनवाई के लिए द्वितीय न्यायाधीशों के मामले 61 में
इस न्यायालय का निर्णय और

तीसरे न्यायाधीशों का मामला 62 सही कानून निर्धारित नहीं करता है लेकिन

पुनर्विचार की आवश्यकता है। यह प्रस्तुत किया गया था कि निर्णय राष्ट्रपति की शक्तियों को हड़पने
का प्रभाव है

संविधान के अनुच्छेद 124 (2) और अनुच्छेद 217 (1) और

न्यायपालिका ने न्यायाधीशों की नियुक्ति को प्रभावी ढंग से परिवर्तित कर दिया है

160 सर्वोच्च लेकिन अचूक नहीं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सम्मान में निबंध पृष्ठ 48,53 161 सुप्रीम
कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन v. भारत संघ, (1993) 4 एस. सी. सी. 441 (नौ न्यायाधीशों की
पीठ)

152 1998 का विशेष संदर्भ सं. 1 (1998) 7 एस. सी. सी. 739 (नौ न्यायाधीशों की पीठ)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

‘परामर्श’ से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को

राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश के बीच (जैसे -

संविधान के अनुच्छेद 124 (2) में ‘सहमति’ में घटित होना भारत के मुख्य न्यायाधीश की और
मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश को स्वीकार करने पर जोर देने के अधिकार को जन्म देना।

भारत से। इसके अलावा, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत

विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच है

जहाज के ऊपर फेंक दिया गया था और जाँच की प्रणाली भी

संविधान में निहित संतुलन। यह विशेष निर्णय लेने के लिए प्रारंभिक मुद्दा, विद्वान अटॉर्नी-जनरल
ने संदर्भित किया

हमारे संविधान में शक्तियों का पृथक्करण, कानून और जिन सिद्धांतों पर इस न्यायालय को निर्णय
लेने के लिए आगे बढ़ना चाहिए

क्या किसी पूर्व या पूर्व निर्णय की आवश्यकता है

पुनर्विचार किया गया।

193. जहाँ तक पहली प्रारंभिक आपत्ति का संबंध है,

इसे 99 वें संविधान संशोधन अधिनियम से पहले उठाया गया था और

एन. जे. ए. सी. अधिनियम लागू हुआ। अब प्रारंभिक आपत्ति

99 वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद से अस्तित्व में नहीं है

और वास्तव में एन. जे. ए. सी. अधिनियम लागू किया गया है। दूसरी प्रारंभिक आपत्ति में कोई सार नहीं है
क्योंकि

इन याचिकाओं में प्रश्न मूल संरचना से संबंधित है

संविधान और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। यह होगा

यह कहना फूहड़ है कि रिट याचिकाएं दायर की जानी चाहिए थीं

एक प्रतिकूल प्रभाव के बाद बुनियादी के परिवर्तन से महसूस किया जाता है संविधान की
संरचना और स्वतंत्रता के बाद

न्यायपालिका को अलग कर दिया जाता है। यदि याचिकाकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि

इतने लंबे समय तक प्रतीक्षा करें कि शायद बहुत देर हो जाएगी। इसके अलावा, जब से हमने इन याचिकाओं को विस्तार से सुना है, यह सलाह दी जाती है कि

उठाए गए मूल मुद्दों पर चर्चा करें। सच कहें तो, यह केवल तीसरी प्रारंभिक आपत्ति है जिसकी आवश्यकता है विचार करें।

तीसरी प्रारंभिक आपत्ति और अलगाव

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं की शक्तियाँ-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

194. शक्तियों के पृथक्करण का मुद्दा रहा है

कई मामलों में चर्चा का विषय। मोटे तौर पर,

शक्तियों के अलगाव को पहचानता है, यह एक कठोर अलगाव नहीं है और कुछ ओवरलैप है।

195. राम जवाया कपूर बनाम। पंजाब राज्य 1 63 यह

इस न्यायालय की ओर से बोलते हुए मुख्य न्यायाधीश मुखर्जी ने कहा:

"एक विस्तृत परिभाषा तैयार करना संभव नहीं हो सकता है।

कार्यकारी कार्य का क्या अर्थ और तात्पर्य है। आम तौर पर

कार्यकारी शक्ति के अवशेष को संदर्भित करता है सरकारी कार्य जो विधायी के बाद बने रहते हैं और

न्यायिक कार्य छीन लिए जाते हैं। भारतीय संविधान

वास्तव में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को इसकी पूर्ण कठोरता में नहीं बल्कि इसके कार्यों को मान्यता दी है

सरकार के विभिन्न भागों या शाखाओं को

पर्याप्त रूप से विभेदित और इसके परिणामस्वरूप यह बहुत अच्छी तरह से हो सकता है

कहा जा सकता है कि हमारा संविधान विचार नहीं करता है एक अंग या राज्य के हिस्से द्वारा कार्यों की धारणा

जो अनिवार्य रूप से दूसरे से संबंधित है। वास्तव में कार्यपालक

विभागीय या अधीनस्थ शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।
 विधान जब ऐसी शक्तियाँ उसे प्रत्यायोजित की जाती हैं
 विधायिका। यह भी, जब इतना सशक्त अभ्यास हो सकता है
 एक सीमित तरीके से न्यायिक कार्य। कार्यपालक

हालाँकि, सरकार कभी भी इसके खिलाफ नहीं जा सकती है
 संविधान या किसी भी कानून के प्रावधान। 164

196. हमारे संविधान में शक्तियों का पृथक्करण नहीं है
 संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह कठोर। तत्वों में से एक
 शक्तियों का पृथक्करण नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली है।
 यह भी हमारे संविधान और अनुच्छेद 226 द्वारा मान्यता प्राप्त है और
 अनुच्छेद 32 (न्यायिक समीक्षा) जाँच की विशेषताओं में से एक है और
 संतुलन। यह केशवानंद भारती बनाम में आयोजित किया गया था। की स्थिति
 163 [1955] 2 एस. सी. आर. 225 (पाँच न्यायाधीशों की पीठ)

184 पैराग्राफ 12 [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट
 केरल 1 65 जहाँ यह न्यायमूर्ति शेलत और न्यायमूर्ति द्वारा कहा गया था
 ग्रोवर इस प्रकार है:

"संविधान में ही इसके लिए पर्याप्त प्रमाण हैं -

इंगित करें कि यह नियंत्रण और संतुलन की एक प्रणाली बनाता है
 जिसके कारण शक्तियाँ इतनी वितरित की जाती हैं कि कोई भी नहीं
 यह जिन तीन अंगों को स्थापित करता है, वे इतने पूर्व हो सकते हैं

दूसरों को व्यायाम करने से अक्षम करने के लिए प्रमुख और
 उन्हें सौंपी गई शक्तियों और कार्यों का निर्वहन करना।

हालाँकि संविधान इस सिद्धांत को निर्धारित नहीं करता है
 अपनी सभी कठोरता में शक्तियों के पृथक्करण का जैसा कि मामला है

संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान ने अभी तक इस तरह की परिकल्पना की है

एक हद तक अलगाव जैसा कि रणसिंघे में पाया गया था
मामला। 166 न्यायिक समीक्षा में स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है

अनुच्छेद 226 और 32 के माध्यम से संविधान एक है -

वे विशेषताएँ जिन पर जाँच की प्रणाली निर्भर करती है और

संतुलन "। 167

197. इंदिरा नेहरू गाँधी बनाम। राज नारायण 1 68 द

संविधान की संवैधानिक वैधता (उनतीस-नौवीं)

संशोधन) अधिनियम, 1975 को चुनौती दी गई थी। इस संशोधन द्वारा अधिनियम, अनुच्छेद 39-ए
को संविधान में जोड़ा गया था और

चुनौती, अन्य बातों के साथ, उसके खंड (4) के लिए थी। 169 हड़ताली होते हुए

165 (1973) 4 एस. सी. सी. 225 (तेरह न्यायाधीशों की पीठ) 166 1965 अधिनियम 172 167
अनुच्छेद 577

168 1975 मान लीजिए कि एस. सी. सी. 1 (पांच न्यायाधीशों की पीठ) 169 (4) संविधान (उनतीसवां
संशोधन) अधिनियम, 1975 के प्रारंभ से पहले संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून, जहां तक वह चुनाव
याचिकाओं से संबंधित है और उससे जुड़े मामले लागू नहीं होंगे या माना जाएगा।

(1) खंड (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के चुनाव के संबंध में या उसके संबंध में संसद के किसी भी सदन में
आवेदन किया है और ऐसा चुनाव किसी भी आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा या कभी शून्य नहीं हुआ है,
जिसके आधार पर ऐसा चुनाव शून्य घोषित किया जा सकता है, या, ऐसे प्रारंभ से पहले, किसी ऐसी कानून के
तहत शून्य घोषित किया गया है और किसी भी अदालत द्वारा ऐसे चुनाव को शून्य घोषित करने के आदेश के
बावजूद, ऐसा चुनाव हर तरह से वैध बना रहेगा और कोई भी ऐसा आदेश और कोई भी निष्कर्ष जिस पर
ऐसा आदेश आधारित है, हमेशा शून्य और अप्रभावी माना जाएगा।

सर्वोच्च अदालतें-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

न्यायमूर्ति एच. आर. खन्ना ने उल्लंघनकारी खंड के तहत यह निर्णय दिया था:

"एक घोषणा कि कानून की अदालत द्वारा दिया गया आदेश है

शून्य आम तौर पर न्यायिक कार्य का हिस्सा है और एक नहीं है

भारत की शक्तियों का कोई कठोर पृथक्करण नहीं, मोटे तौर पर
न्यायिक कार्य और विधायी कार्य के क्षेत्रों में

न्यायिक क्षेत्र का अतिक्रमण करने के लिए विधायिका। इसमें है।
तदनुसार अभिनिर्धारित किया गया कि एक विधायिका जबकि वह हकदार है
जिस कानून का गठन किया गया था, उसे पूर्वव्यापी प्रभाव से बदलना।
न्यायिक निर्णय के आधार पर, इसकी अनुमति नहीं है
न्यायालय के निर्णय को घोषित करने के लिए विधायिका
शून्य या बाध्यकारी नहीं (देखें श्री पृथ्वी कॉटन मिल्स लिमिटेड v.
ब्रोच बरो नगरपालिका, जनपद सभा,
छिंदवाड़ा बी. सेंट्रल प्रोविंस सिंडिकेट लिमिटेड,
अहमदाबाद शहर का नगर निगम बनाम। नया।
शोराँक एसपीजी। & डब्ल्यूवीजी। कं. लिमिटेड और तमिलनाडु राज्य
बी. एम. रायप्पा गौंडर) "। 170 (आंतरिक उद्धरणों को हटा दिया गया)।

198. न्यायमूर्ति मैथ्यू ने कहा कि हमारा एक सहकारी है
संघवाद जिसमें शक्तियों का कोई कठोर पृथक्करण नहीं है
और नियंत्रण और संतुलन की एक प्रणाली मौजूद है। हेरोल्ड लास्की
यह कहते हुए उद्धृत किया गया था कि 'शक्तियों का पृथक्करण नहीं होता है
इसका अर्थ है शक्तियों का समान संतुलन। 171 इस संदर्भ में यह
अभिनिर्धारित किया कि विधानमंडल द्वारा न्यायिक शक्ति का प्रयोग है अस्वीकार्य। विद्वान
न्यायाधीश ने यह विचार व्यक्त किया कि:

"मोंटेस्क्यू तीन अंगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सरकार के तीन कार्यों की कल्पना करने वाले पहले
व्यक्ति थे।

अतिव्यापीता की डिग्री और जाँच का सिद्धांत और
संतुलन के लिए प्रत्येक अंग को बहुत अधिक बाधा डालने की आवश्यकता होती है

अन्य दो शक्तियों द्वारा अधिकार का संवर्धन। 170 अनुच्छेद 190 के अनुसार

171 ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स (वर्क्स ऑफ हैरोल्ड जे. लास्की), 297 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13
एस. सी. आर.

होल्ड्सवर्थ कहते हैं, मोंटेस्क्यू ने दुनिया को आश्चर्य किया कि उन्होंने एक नए संवैधानिक सिद्धांत की खोज की थी जो सार्वभौमिक रूप से मान्य था। पृथक्करण का सिद्धांत

दार्शनिक अवधारणा। यह एक व्यावहारिक, एक दिन का काम है। सिद्धांत। सरकार का तीन शाखाओं में विभाजन

इसका मतलब यह नहीं है, जैसा कि इसके आलोचक हमें सोचने के लिए कहेंगे, तीन जलरोधक डिब्बे। इस प्रकार, विधायी महाभियोग

कार्यपालक अधिकारी या न्यायाधीश, कार्यपालक वीटो विधान, प्रशासनिक या विधायी की न्यायिक समीक्षा

क्रियाओं को आंशिक अपवाद के रूप में माना जाता है जिनकी आवश्यकता होती है व्याख्या "। 172

199. न्यायमूर्ति वाई. वी. चंद्रचूड ने एक विशिष्टता व्यक्त की

संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में समझी गई शक्तियों के पृथक्करण के बीच और जैसा कि भारत में समझा गया और व्यक्त किया गया

इस संबंध में निम्नलिखित दृष्टिकोण:

"अमेरिकी संविधान एक कठोर प्रावधान करता है

सरकारी शक्तियों को तीन बुनियादी भागों में विभाजित करना

प्रभाग, कार्यपालिका, विधायी और न्यायिक। यह एक

उस संविधान का अनिवार्य सिद्धांत जो शक्ति प्रदान करता है

किसी एक विभाग को सौंपे जाने का उपयोग इसके द्वारा नहीं किया जाना चाहिए

कोई अन्य विभाग। ऑस्ट्रेलियाई संविधान इस प्रकार है:

शक्तियों के वितरण का एक ही पैटर्न। इन संविधानों के विपरीत, भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं करता है राज्य के तीन अलग-अलग अंगों में तीन प्रकार की शक्तियाँ निहित करें। लेकिन शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है

द्वारा देखा गया। कार्डोजो, जे. में अपनी असहमत राय में पनामा रिफाइनिंग कंपनी बनाम। रयान 173 का सिद्धांत

शक्तियों का पृथक्करण "एक सैद्धांतिक अवधारणा नहीं है

पांडित्यपूर्ण कठोरता के साथ उपयोग किया जाता है। समझदारी होनी चाहिए।

173 293 अमेरिका 388 (1935)

सर्वोच्च अदालतें-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. 1. [मदन बी. लोकुर, जे.]

अनुमान के अनुसार, सरकार की व्यावहारिक आवश्यकताओं के जवाब में समायोजन की लोच होनी चाहिए

जो आज के विकास की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कल उनकी लगभग अनंत विविधता में "।
अतः यहाँ तक कि

अमेरिका, इस सिद्धांत के बावजूद कि विधायिका अपनी शक्ति कार्यपालिका को सौंप नहीं सकती है, कई नियम और

न्यायिक रूप से वैध के रूप में मान्यता दी गई है। 174 200. मिनर्वा मिल्ल्स लिमिटेड बनाम। भारत
संघ 1 75 न्याय

स्वाति ने कहा कि संविधान ने एक ऐसी संरचना तैयार की है जिसमें शक्तियों और नियंत्रण और संतुलन का पृथक्करण किया गया है और

"केशवानंद में बहुमत के फैसले से यह स्पष्ट है।

भारती का मामला है कि हमारा संविधान नियंत्रित है संविधान जो विभिन्न को शक्तियाँ प्रदान करता है

इसके द्वारा बनाए गए और मान्यता प्राप्त अधिकारी और उन शक्तियों की सीमाओं को परिभाषित करते हैं। संविधान सर्वोपरि है,

देश का सर्वोच्च कानून और कोई अधिकार नहीं है,

राज्य का कोई विभाग या शाखा जो ऊपर या ऊपर हो।

संविधान से परे या निरंकुश शक्तियाँ हैं और

नियंत्रण और संतुलन और सीमाओं के साथ शक्ति संबंध की एक संरचना तैयार की गई है जो प्रत्येक की शक्तियों पर रखी गई है संविधान के तहत प्राधिकरण या साधन। प्रत्येक

राज्य का अंग, चाहे वह कार्यपालिका हो या विधायिका

या न्यायपालिका, अपना अधिकार संविधान से प्राप्त करती है

और उसे ऐसे प्राधिकरण की सीमाओं के भीतर कार्य करना होगा। " 176

201. थोड़ी देर बाद, विद्वान न्यायाधीश ने यह टिप्पणी की:

"यह हमारी संवैधानिक योजना का एक मौलिक सिद्धांत है,

और मैंने इसे पिछले पैराग्राफ में इंगित किया है,

रैग्राफ 87

980) 3 एस. सी. सी. 625 (पाँच न्यायाधीशों की पीठ) ग्राफ 86 [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कि राज्य का प्रत्येक अंग, इसके अधीन प्रत्येक प्राधिकारी

संविधान, संविधान से अपनी शक्ति प्राप्त करता है और
ऐसी शक्ति की सीमाओं के भीतर कार्य करना होगा। लेकिन फिर

सवाल यह उठता है कि किस प्राधिकरण को क्या तय करना चाहिए

उनका उल्लंघन किया जाता है या उन्हें पार किया जाता है। अब तीन मुख्य हैं
राज्य के ऐसे विभाग जिनकी शक्तियाँ

सरकार विभाजित है; कार्यपालिका, विधायिका और

न्यायपालिका। हमारे संविधान के तहत हमारे पास कोई कठोरता नहीं है

संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह शक्तियों का पृथक्करण, लेकिन एक व्यापक सीमांकन है, हालांकि, ध्यान में
रखते हुए

सरकारी कार्यों की जटिल प्रकृति के लिए, कुछ

शक्तियों का व्यापक पृथक्करण यह है कि "किसी एक अंग में शक्तियों की एकाग्रता" के शब्दों को उद्धृत
करने के लिए चंद्रचूड़, जे., (जैसा कि वे उस समय थे) इंदिरा
गांधी के मामले में

एक लोकतांत्रिक के मौलिक परिसर को नष्ट करना
जिसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं "। 177

सरकार

202. आई. आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य 178 यह था

मुख्य न्यायाधीश सभरवाल ने न्यायालय की ओर से कहा कि

ई शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत मूल का एक हिस्सा है

संविधान का उल्लंघन। यह आयोजित किया गया था:

"विधानमंडल के बीच शक्तियों का पृथक्करण,

कार्यपालिका और न्यायपालिका बुनियादी संरचना का गठन करते हैं,

केशवानंद भारती मामले में पाया गया है
इंदिरा गांधी के मामले में इसे दोहराया गया। बड़ी संख्या में निर्णयों ने दोहराया है कि

बहुमत। बाद में

शक्तियों का पृथक्करण इसकी मूल विशेषताओं में से एक है

संविधान ", 17

अनुच्छेद 87

3 (2007) 2 एस. सी. सी. 1 (नौ न्यायाधीशों की पीठ)

अनुच्छेद 63. इसे पैराग्राफ 67, 125 और 129 में दोहराया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

203. भीम सिंह बनाम। भारत संघ ने यह अभिनिर्धारित किया कि

शक्तियों का पृथक्करण संविधान की एक अनिवार्य विशेषता है

और आधुनिक शासन में सख्त अलगाव न तो संभव है

शासन दूसरे के साथ, लेकिन अगर एक शाखा एक एक अन्य शाखा का आवश्यक कार्य, फिर सिद्धांत का उल्लंघन होता है। न्यायमूर्ति सतशिवम ने यह टिप्पणी की

न्यायालय की ओर से बोलते हुए, संवैधानिक पर विचार करते हुए

संसद के स्थानीय क्षेत्र विकास सदस्यों की वैधता

योजना:

"शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा, भले ही किसी विशेष संवैधानिक प्रावधान में नहीं पाई जाती है, अंतर्निहित है।

राजनीति में संविधान को अपनाया गया है। शक्तियों के पृथक्करण का उद्देश्य अधिकतम सीमा तक पहुंचना है।

सरकार की प्रत्येक शाखा की जवाबदेही।

इस अवधारणा को समझते हुए [के अलगाव का]

शक्तियाँ], दो पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। एक, वह

शक्तियों का पृथक्करण एक आवश्यक विशेषता है

संविधान। दो, कि आधुनिक शासन में, एक सख्त

अलगाव न तो संभव है और न ही वांछनीय है।

फिर भी, जब तक जवाबदेही का यह सिद्धांत है
संरक्षित, शक्तियों के पृथक्करण का कोई उल्लंघन नहीं है।

हम उसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं जब हम मूल्यांकन करते हैं

संवैधानिक पाठ के भीतर स्थिति। संविधान
कार्यों के ओवरलैप को प्रतिबंधित नहीं करता है, लेकिन वास्तव में प्रदान करता है

एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में कुछ ओवरलैप के लिए। लेकिन यह दूसरी शाखा के कार्य के इस तरह
के अभ्यास को प्रतिबंधित करता है।

जिसके परिणामस्वरूप शासन से कुश्ती होती है

संवैधानिक उत्तरदायित्व।

इस प्रकार, शक्तियों के पृथक्करण के उल्लंघन के लिए परीक्षण

ठीक यही होना चाहिए। एक कानून का उल्लंघन होगा

180 (2010) 5 एस. सी. सी. 538 (पाँच न्यायाधीशों की पीठ)

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शक्तियों का पृथक्करण नहीं अगर इसके परिणामस्वरूप कुछ ओवरलैप होता है

राज्य की विभिन्न शाखाओं के कार्य, लेकिन यदि यह लेता है

की ओर ले जाने वाली दूसरी शाखा के एक आवश्यक कार्य पर
संवैधानिक जवाबदेही में चूक "। 181

204. अंत में, तमिलनाडु राज्य बनाम। केरल राज्य में शक्तियों के पृथक्करण पर विस्तृत चर्चा हुई है।
इस न्यायालय द्वारा निर्णय लिए गए कई मामलों के संदर्भ में। 183 यह था।

उसमें यह अभिनिर्धारित किया गया कि पृथक्करण के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए

केरल सिंचाई और जल संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा पारित शक्तियाँ (और अन्य कारणों से भी)

केरल विधानमंडल असंवैधानिक है क्योंकि यह इसे रद्द करना चाहता है मुल्लापेरियार पर्यावरण में
इस न्यायालय का निर्णय

संरक्षण मंच v. भारत संघ। 184

205. विद्वान महान्यायवादी की प्रस्तुति थी

कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति या उच्च न्यायालय एक कार्यकारी कार्य है और यह इस प्रकार आयोजित किया गया है यहां तक कि दूसरे न्यायाधीशों के मामले में भी। न्यायमूर्ति अहमदी ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति एक कार्यकारी कार्य है जैसा कि किया गया था न्यायमूर्ति वर्मा। 186 की एक अस्थिर व्याख्या द्वारा संविधान (एक व्याख्या जो विद्वानों के अनुसार महान्यायवादी ने डॉ. अम्बेडकर को अपने कार्यकाल में मोड़ दिया होगा। कब्र), इस कार्यकारी कार्य को ले लिया गया है या हड़प लिया गया है न्यायपालिका द्वारा और यही कारण है कि दूसरे न्यायाधीश मामले पर पुनर्विचार करने और सही संवैधानिक व्यवस्था की आवश्यकता है इस पद को बहाल किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, एक प्रक्रिया द्वारा न्यायिक अतिक्रमण का, शक्ति सिद्धांत का पृथक्करण है इस न्यायालय द्वारा मूल का उल्लंघन करते हुए तोड़ दिया गया संविधान की संरचना। 81 अनुच्छेद 77 और 78 182 (2014) 12 एस. सी. सी. 696 (पाँच न्यायाधीशों की पीठ) 183 पैराग्राफ 98 से 126.7 तक। निष्कर्ष पैराग्राफ 126.1 से 126.7 में बताए गए हैं। 184 (2006) 3 एस. सी. सी. 643 (पाँच न्यायाधीशों की पीठ) 185 पैरा 298 और 304

186 पैराग्राफ 443 सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

संविधान सभा की बहस और तीसरी बैठक

प्रारंभिक मुद्दा

206. उनके इस तर्क के समर्थन में कि दूसरा

न्यायाधीशों का मामला और तीसरे न्यायाधीशों का मामला निर्धारित नहीं करता है

कानून को सही करें और पुनर्विचार की आवश्यकता है, विद्वान वकील जनरल ने सीएडी पर बहुत अधिक निर्भरता रखी। यह आवश्यक है,

इसलिए, इस विषय पर कानून पर विचार करना और फिर
बहसों।

207. बंगाल के प्रशासक-जनरल बनाम। प्रेम लाल

एक वैध सहायता के रूप में विधानमंडल में बहस एक कानून का निर्माण। यह आयोजित किया गया
था:

"उनके प्रभुत्वों का मानना है कि दोनों विद्वान न्यायाधीश

जिसने अपीलीय न्यायालय में बहुमत का गठन किया,
हालाँकि वे अपने निर्णय को उन पर आधारित नहीं करते हैं, संदर्भ लें

विधान-मंडल की कार्यवाहियों के लिए जिसके परिणामस्वरूप

धारा 31 के निर्माण के लिए वैध सहायता के रूप में 1874 के अधिनियम [प्रशासक-सामान्य
अधिनियम] का पारित होना।

उनके अधिपति अपनी असहमति व्यक्त करना सही समझते हैं।

वह प्रस्ताव। वही कारण जो इन्हें बाहर करते हैं

विचार जब अंग्रेजों के किसी अधिनियम के खंड

विधानमंडल निर्माणाधीन हैं जिनमें समान रूप से ठोस हैं।

भारतीय कानून का मामला "।

208. इस दृष्टिकोण को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया था, जिसके संदर्भ में

ए. के. गोपालन बनाम में सीएडी। मद्रास राज्य 88 प्रमुख द्वारा न्यायमूर्ति हरिलाल कनिया, जिन्होंने
यह अभिनिर्धारित किया था कि सीएडी को बहुत सावधानी के साथ और केवल तभी संदर्भित किया जा सकता
है जब 'अव्यक्त अस्पष्टताएँ' हों।

हल किया जाना है। " 189 विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की:

"बहस और रिपोर्ट की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था

संविधान सभा की मसौदा समिति में

187 (1894-95) 22 आई. ए. 107,118

188 1950 एस. सी. आर. 88 (6 न्यायाधीशों की पीठ)

189 संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान पर विलोबी से उद्धृत, पृष्ठ 64 [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस खंड के शब्दों का सम्मान। रिपोर्ट हो सकती है
लेख के अर्थ को नियंत्रित करने के लिए नहीं पढ़ें, लेकिन अस्पष्टता के मामले में देखा जा सकता है।
नगरपालिका परिषद में

सिडनी बनाम. राष्ट्रमंडल 190 में यह सोचा गया था कि

अधिवेशन के सदस्यों की व्यक्तिगत राय

बहस में व्यक्त को संदर्भित नहीं किया जा सकता है
संविधान के निर्माण का उद्देश्य। एक ही राय

संयुक्त राज्य अमेरिका वी में व्यक्त किया गया था। वोंग किम आर्क। 191 द.

परिणाम यह प्रतीत होता है कि जबकि इसे लेना उचित नहीं है

सदस्यों की व्यक्तिगत राय पर विचार करें

संसद या सम्मेलन का अर्थ समझने के लिए

कुछ वाक्यांश या अभिव्यक्ति विचार के लिए थी
बिल्कुल भी हो या न हो, बहस के संदर्भ की अनुमति दी जा सकती है।

वर्तमान मामले में बहसों को दिखाने के लिए संदर्भित किया गया था

कि "कानून की उचित प्रक्रिया" अभिव्यक्ति को जाना जाता था

अमेरिकी संविधान में मौजूद है और एक चर्चा के बाद

हमारे संविधान में संविधान सभा द्वारा अपनाया नहीं गया था। बंगाल के प्रशासक जनरल बनाम।

प्रेमलाल मलिक की कार्यवाही का एक संदर्भ

निर्माण में वैध सहायता नहीं मानी जाती है
विशेष खंड। एक ही कारण को ठोस माना गया था

अर्थ में ऐसी बहसों के संदर्भ को हटाने के लिए

एक भारतीय कानून। इन स्रोतों को बड़ी सावधानी के साथ और केवल तभी रिसॉर्ट करना पड़ सकता
है जब अव्यक्त अस्पष्टताएँ हों।

हल करने के लिए "। 192

209. इस दृष्टिकोण का समर्थन फ्राज़ ने किया था! अली, जे जिन्होंने उल्लेख किया

अभिव्यक्ति 'कानून की उचित प्रक्रिया' जो मूल रूप से थी

संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित के रूप में व्याख्या की गई

प्रक्रिया के मामलों के लिए लेकिन बाद में कवर करने के लिए बढ़ाया गया था

मूल कानून भी। विद्वान न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि:

190 (1904) 1 कॉम एलआर 208

191 169 यूएस 649,699

192 पृष्ठ 110 और 111 सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

"तर्कों के दौरान, विद्वान वकील

जनरल ने हमें संविधान की कार्यवाही के लिए संदर्भित किया

विधानसभा यह दिखाने के उद्देश्य से कि अनुच्छेद के रूप में

मूल रूप से तैयार किए गए मसौदे में "बिना देय" शब्द शामिल थे।

कानून की प्रक्रिया "लेकिन ये शब्द बाद में थे

"प्रक्रिया के अनुसार को छोड़कर" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया कानून द्वारा स्थापित "। मेरी राय में, हालांकि

विधानसभा में कार्यवाही या चर्चा नहीं होती है

अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त अभिव्यक्तियाँ, विशेष रूप से जब वे हैं स्पष्ट और असंदिग्ध, वे यह दिखाने के लिए प्रासंगिक हैं कि

सभा का उद्देश्य अभिव्यक्ति के उपयोग से बचना था

"कानून की उचित प्रक्रिया के बिना "। शुरुआती दौर में,

अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने "उचित प्रक्रिया" का अर्थ लगाया

केवल प्रक्रिया के मामलों को शामिल करने के लिए, लेकिन धीरे-धीरे

अभिव्यक्ति का अर्थ इतना चौड़ा किया गया था कि

मूल कानून को भी शामिल करता है, इस पर जोर देकर

शब्द "देय"। 193 210. न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री की भी यही राय थी।

अतः विद्वान न्यायाधीश ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

"विद्वान परामर्श ने दिए गए भाषणों की ओर ध्यान आकर्षित किया

सदन के पटल पर कई सदस्यों द्वारा
 जैसा कि उन्होंने कहा, "ऐतिहासिक" को समझाने के लिए सदन
 पृष्ठभूमि "। बहस के दौरान दिया गया भाषण
 एक बिल पर व्यक्तिपरक इरादे का संकेत हो सकता है
 वक्ता का, लेकिन यह निष्क्रिय को प्रतिबिंबित नहीं कर सका
 बहुमत के पीछे पड़ी मानसिक प्रक्रियाएँ जो वोट देती हैं बिल ले गए। न ही यह मान लेना
 उचित है कि
 केवल विधायिका के वस्तुनिष्ठ इरादे की खोज कर सकते थे मुख्य रूप से अधिनियम में उपयोग
 किए गए शब्दों में,
 वैधानिक प्रतिवेदनों के रूप में ऐसी ऐतिहासिक सामग्री

आयु 158 और 159 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.
 समितियाँ, प्रस्ताव आदि। मैं कोई महत्व नहीं देता,
 इसलिए, कुछ लोगों द्वारा दिए गए भाषणों के लिए
 के दौरान संविधान सभा के सदस्य
 अनुच्छेद 15 (अब अनुच्छेद 21) पर बहस। 194
 211. न्यायमूर्ति मुखर्जी ने रियायत का उल्लेख किया
 उपयोग किए गए शब्दों के अर्थ की व्याख्या करें-एक स्थिति काफी हद तक विद्वान वकील द्वारा अब
 जो लिया गया है, उसके विपरीत
 जनरल। विद्वान न्यायाधीश ने तब कहा कि इस तरह के बाह्य
 साक्ष्य को सबसे अच्छा खाते से बाहर छोड़ दिया जाता है और निम्नानुसार रखा जाता है:
 "विद्वान महान्यायवादी ने हमारे सामने रखा है
 संविधान सभा में चारों ओर केंद्रित बहस
 प्रारूपण की इस सिफारिश को अपनाना
 समिति और उन्होंने हमें उनके भाषणों के लिए संदर्भित किया है

विधानसभा के कई सदस्य जिन्होंने एक खेला
संविधान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका। एक के रूप में

संविधान में शब्दों के अर्थ की खोज करने में सहायता,

ये बहसें संदिग्ध मूल्य की हैं। रिसॉर्ट हो सकता है।

उन्हें "विलोवी कहता है", बहुत सावधानी के साथ और केवल

जब अव्यक्त अस्पष्टताओं को हल किया जाना है। द.

कार्यवाहियों का कुछ महत्व हो सकता है जब वे स्पष्ट रूप से
प्रावधान के उद्देश्य को इंगित करें। लेकिन जब

प्रश्न अमूर्त अर्थ का है, इसे प्राप्त करना मुश्किल होगा

इस स्रोत से बहुत अधिक भौतिक सहायता

व्याख्या "।

विद्वान

महान्यायवादी स्वीकार करते हैं कि इन बहसों का अर्थ समझाने के लिए स्वीकार्य नहीं हैं

उपयोग किए गए शब्द और वह उनका उपयोग केवल इसके लिए करना चाहते थे

यह दिखाने का उद्देश्य कि संविधान सभा कब

अंततः उन्होंने मसौदे की सिफारिश को स्वीकार कर लिया

समिति, अभिव्यक्ति के पुराने रूप और के बीच के अंतर के निहितार्थ से पूरी तरह से अवगत थी

194 पृष्ठ 201 और 202 शीर्ष अदालत के वकील-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. /मदन बी. लोकर, जे./

नया। मेरी राय में, संविधान की व्याख्या करते हुए, यह होगा

बेहतर होगा यदि इस तरह के बाहरी साक्ष्य को खाते से बाहर छोड़ दिया जाए। इस तरह के मामलों में
अलग-अलग सदस्य अलग-अलग तरीके से काम करते हैं।

आवेग और विभिन्न उद्देश्यों से और यह काफी है
संभव है कि कुछ सदस्यों ने कुछ शब्दों को एक विशेष अर्थ में स्वीकार किया हो, जबकि अन्य ने उन्हें एक अलग
अर्थ में लिया हो

प्रकाश "। 195

212. न्यायमूर्ति एस. आर. दास ने विशेष रूप से कहा कि उन्होंने

संविधान की व्याख्या करने के लिए सी. ए. डी. की स्वीकार्यता या अन्यथा के सवाल पर कोई राय व्यक्त नहीं करता है।

213. त्रावणकोर राज्य में-कोचीन बनाम। द बॉम्बे

कं. लिमिटेड 196 यह सर्वसम्मति से माना गया कि सीएडी के संदर्भ में अनुचित है और व्याख्या के लिए ऐसी बाहरी सहायता है

कानून स्वीकार्य नहीं हैं। अदालत की ओर से बोलते हुए, प्रमुख

न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री ने कहा:

"यह केवल यह इंगित करना बाकी है कि द्वारा किया गया उपयोग

विद्वान न्यायाधीशों द्वारा दिए गए भाषणों के नीचे

के दौरान संविधान सभा के सदस्य

संविधान के मसौदे पर बहस अनुचित है। कि कानूनों की व्याख्या के लिए बाहरी सहायता का यह रूप

आम तौर पर स्वीकार नहीं किया गया है

इंग्लैंड, और वही नियम में देखा गया है

गोपालन में हम में से एक ने नियम के पीछे की व्याख्या की थी मामला इस प्रकार है:

"एक विधेयक पर बहस के दौरान दिया गया भाषण

सबसे अच्छा व्यक्तिपरक इरादे का संकेत हो सकता है

वक्ता, लेकिन यह निष्क्रिय को प्रतिबिंबित नहीं कर सका

बहुमत के वोट के पीछे पड़ी मानसिक प्रक्रिया जो

बिल ले गए। न ही यह मान लेना उचित है कि

195 पृष्ठ 273 और 274 196 1952 एस. सी. आर. 1112 (5 न्यायाधीशों की पीठ)

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उन सभी विधायकों के मन सहमत थे।

या, जैसा कि इसे एक अमेरिकी मामले में अधिक संक्षिप्त रूप से रखा गया है

"जिन लोगों ने बात नहीं की वे शायद सहमत नहीं थे
जिन्होंने किया; और जो बोले वे अलग हो सकते हैं
एक-दूसरे-संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम। ट्रांस-मिसौरी माल ढुलाई
एसोसिएशन। 197 " 198

214. गोलक नाथ बनाम। पंजाब राज्य 1 99 मुख्य न्यायाधीश
सुब्बा राव ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों को नोट किया, जिनमें से एक
जो था:

"विशेष रूप से संविधान सभा में बहस।
प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू का भाषण
भारत के मंत्री, और डॉ. अम्बेडकर का जवाब, जो
अनुच्छेद 368 संसद को निरस्त करने में सक्षम बनाता है
मौलिक अधिकार; वे परिस्थितियाँ जिनके तहत
श्री एच. वी. कामथ द्वारा प्रस्तुत संशोधन, जिनमें से एक
संविधान सभा के सदस्यों को वापस ले लिया गया और
अनुच्छेद 368 को अंततः अपनाया गया, इस तर्क का समर्थन करते हुए कि भाग III का संशोधन
अनुच्छेद के दायरे से बाहर है।
368, " 200

215. विद्वान महान्यायवादी की प्रस्तुतियाँ -
इन्हें भी नोट किया गया था और जिनमें से एक, फिर से, पूर्ण रूप से था
विद्वानों द्वारा हमारे सामने किए गए समर्पण का विरोध
महान्यायवादी:

संविधान के अनुच्छेद 368 का अर्थ लगाने के लिए और
भले ही वे हो सकते हैं, बहस में कुछ भी नहीं है
सकारात्मक रूप से साबित करें कि मौलिक अधिकारों को बाहर रखा गया था
197 169 यूएस 290,318 198 पृष्ठ 1121
199 (1967) 2 एस. सी. आर. 762 (11 न्यायाधीशों की पीठ) 200 पृष्ठ 782

1 सर्वोच्च अदालतें-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

संशोधन से "। 201

216. विद्वान मुख्य न्यायाधीश (बहुमत के लिए बोलते हुए)

सी. ए. डी. को संदर्भित किया और देखा:

" हमने पंडित जवाहरलाल के भाषणों का उल्लेख किया है।

नेहरू और डॉ. अम्बेडकर की व्याख्या करने की दृष्टि से नहीं कला के प्रावधान। 368, जिसे हम अपनी शर्तों पर करने का प्रस्ताव करते हैं, लेकिन केवल दिव्य चरित्र को नोटिस करने के लिए

दो महत्वपूर्ण अधिकारों द्वारा मौलिक अधिकारों को दिया गया

संविधान के वास्तुकार "। 202

217. न्यायमूर्ति वांचू ने इस मुद्दे को थोड़ा और उठाया।

विस्तृत रूप से और कानून पर विचार करने पर (समर्थन प्राप्त करना)

प्रेम लाल मलिक और ए. के. गोपालन) ने माना कि सीएडी

अनुच्छेद 368 की व्याख्या के लिए नहीं देखा जा सका

संविधान और उक्त अनुच्छेद की व्याख्या इस पर की जानी चाहिए

उनके शब्दों को अंततः संविधान में जगह मिली।

कहा गया था:

" संसद में बहस के दौरान बहुत सारे संदर्भ दिए गए थे और यह आग्रह किया जाता है कि

यह इस न्यायालय के लिए बहसों को देखने के लिए खुला है ताकि

के इरादे का पता लगाने के लिए अनुच्छेद 368 की व्याख्या करें संविधान निर्माता। हमारा मानना है कि हम ऐसा नहीं कर सकते

और उन बहसों को नहीं देखना चाहिए जो हुई थीं

व्याख्या निर्धारित करने के लिए संविधान सभा

अनुच्छेद 368 और प्रावधान का दायरा और विस्तार

उसमें निहित है। यह माना जा सकता है कि ऐतिहासिक

पृष्ठभूमि और शायद क्या स्वीकार किया गया था या क्या
 संविधान सभा द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था जबकि
 संविधान बनाया जा रहा था, इसमें लिया जा सकता है
 अनुच्छेद 368 के दायरे और विस्तार का पता लगाने के लिए।
 लेकिन हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें क्या कहा गया था
 संविधान सभा में बहस नहीं हो सकती और होनी भी चाहिए

201 पृष्ठ 783

202 पृष्ठ 792 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

अनुच्छेद 368 की व्याख्या करने के लिए इस पर विचार नहीं किया जाएगा।
 इसलिए हमारी राय है कि पढ़ना संभव नहीं है।
 संविधान सभा में दिए गए भाषण क्रम में
 अनुच्छेद 368 की व्याख्या करना या इसके विस्तार और दायरे को परिभाषित करना।
 और यह निर्धारित करने के लिए कि यह क्या लेता है और क्या नहीं। ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में,
 अर्थात्, क्या स्वीकार किया गया था या
 संविधान सभा में क्या टाल दिया गया था
 इस संबंध में। इसे सीमित करने के प्रस्ताव थे
 अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की शक्ति और
 मौलिक अधिकार उनसे मुक्त थे और वहाँ थे
 संविधान सभा के समक्ष प्रति-प्रस्ताव
 संशोधन की शक्ति को सर्वसमावेशक बनाना। वे.
 सभी को या तो छोड़ दिया गया या नकारात्मक कर दिया गया और
 अनुच्छेद 368 की व्याख्या जिसकी व्याख्या की जानी चाहिए
 उनके शब्दों पर जैसा कि उन्हें अंत में जगह मिली
 संविधान, और उन शब्दों पर हमें कोई संदेह नहीं है कि

सत्ता पर किसी भी प्रकार की कोई निहित सीमाएँ नहीं हैं।
उसमें संशोधन करने के लिए दिया गया। 203

218. न्यायमूर्ति बचावत ने अपना फैसला इस प्रकार सुनाया -

सी. ए. डी. के मुद्दे को व्याख्या करने में सहायता के रूप में संदर्भित करना
संविधान। बल्कि संक्षिप्त शब्दों में, विद्वान न्यायाधीश

इस संबंध में की गई प्रस्तुति को अस्वीकार कर दिया और उस पर भरोसा किया
कोच्चि। ऐसा कहा गया था:

त्रावणकोर राज्य-

"इस निर्णय को समाप्त करने से पहले मुझे कुछ का उल्लेख करना चाहिए

संविधान के सदस्यों द्वारा दिए गए भाषण

मसौदे पर बहस के दौरान सभा

संविधान। इन भाषणों का उपयोग सहायक के रूप में नहीं किया जा सकता है।

संविधान की व्याख्या के लिए। त्रावणकोर कोचीन राज्य और अन्य बनाम देखें। बॉम्बे कं. लिमिटेड
तदनुसार, मैं

203 पृष्ठ 836,837 और 838 शीर्ष अदालतें-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

निर्माण के लिए सहायता के रूप में उन पर भरोसा न करें। 204

219. न्यायमूर्ति बच्चन ने भी एक दिलचस्प बात कही है।

सर बी. एन. राउ द्वारा लिखे गए एक विशेष लेख का संदर्भ

(संवैधानिक सलाहकार) 15 अगस्त, 1948 को। सर बेनेगल टिप्पणी की:

"यह काफी अतार्किक लगता है कि एक संविधान होना चाहिए

निर्वाचित विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से तय किया गया

अप्रत्यक्ष रूप से एक बहुत ही सीमित मताधिकार पर और यह कि
एक द्वारा उसी तरह से संशोधित होने में सक्षम नहीं होना

संसद निर्वाचित हुई और शायद अधिकांश भाग के लिए

सीधे वयस्क मताधिकार द्वारा चुना गया। 205

बिना किसी टिप्पणी के इसका उल्लेख केवल फेंकने के लिए किया गया है।
 इस विचार को खोलें कि क्या संविधान की व्याख्या
 कुछ लोगों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से हमेशा के लिए बंधा जा सकता है
 संविधान सभा के माननीय सदस्य, जो थे
 निस्संदेह अत्यंत विद्वान और दूरदर्शी लेकिन जिन्होंने फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से एक सभा का गठन किया
 बहुत सीमित मताधिकार '।

220. केशवानंद भारती में यह प्रमुख द्वारा आयोजित किया गया था।

न्यायमूर्ति सीकरी ने कहा कि सदस्यों द्वारा दिए गए भाषण
 किसी कानून के अधिनियमन से संबंधित बहस के दौरान विधायिका का उपयोग किसी भी कानून की व्याख्या
 करने के लिए सहायक के रूप में नहीं किया जा सकता है।

कानून के प्रावधान '। विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि
 यही नियम संविधान के प्रावधानों पर लागू होता है।

और इसके लिए अन्य बातों के साथ-साथ प्रेम पर भी निर्भरता रखी गई थी। लाल मलिक, ए. के.
 गोपालन, त्रावणकोर राज्य-कोच्चि और

गोलक नाथ। भारत संघ की व्याख्या करते हुए *v. एच. एस. ढिल्लों 206 द*

विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने कहा:

"भारत संघ में *v. एच. एस. ढिल्लन* प्रथम, बहुमत की ओर से,
 पी में देखे गए भाषणों का उल्लेख करने से पहले। 58 कि

204 पृष्ठ 922

205 पृष्ठ 917

208 (1972) 2 एस. सी. आर. 331 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

"लेकिन हमें निम्नलिखित उद्धरणों से यह जानकर खुशी हो रही है
 बहसों से जो हमारी व्याख्या किसके साथ मेल खाती है
 इरादा था "। पुष्टि पाने में कोई नुकसान नहीं है।

बहसों में किसी की व्याख्या की लेकिन संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करना काफी अलग बात है

बहसों का प्रकाश "। 207
प्रमुख

221. केस लॉ पर निर्भर रहने के अलावा, विद्वान

स्टाईस ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए एक अतिरिक्त कारण दिया कि निर्भरता

प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए सीएडी की सलाह नहीं दी गई थी

संविधान। यह सबसे अच्छी तरह से शब्दों में समझा जाता है

सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश:

"बहसों का उल्लेख नहीं करने का एक अतिरिक्त कारण है

व्याख्या के उद्देश्य से। संविधान, जहाँ तक

जैसा कि अधिकांश भारतीय राज्यों का संबंध था, आया

केवल शासक द्वारा स्वीकृति के कारण संचालन
यह निम्नलिखित उद्धरण से पता चलता है

या राजप्रमुख।

में सरदार वल्लभभाई पटेल के बयान से

12 अक्टूबर, 1949 को संविधान सभा, (सी. ए. डी., खंड।

एक्स, पीपी। 161-63):

"दुर्भाग्य से हमारा ठीक से गठन नहीं हुआ है।

शेष राज्यों में विधानसभाएँ (मैसूर के अलावा,

सौराष्ट्र और त्रावणकोर और कोचीन संघ) और न ही

भारत के संविधान के अंतिम रूप में उभरने से पहले उनमें विधानसभाओं का गठन करना संभव है।

रूप में। इसलिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं है कि हम

के आधार पर इन राज्यों में संविधान संचालित
शासकों या राजप्रमुख द्वारा इसकी स्वीकृति,

मामला हो सकता है, जो निस्संदेह अपनी परिषद से परामर्श करेगा

मंत्रियों का "।

इस कथन के अनुसार, घोषणाएं थीं

शासकों या राजप्रमुखों द्वारा जारी किया गया

पैराग्राफ 183 सुप्रीम कोर्ट के वकील-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

संविधान।

मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई शासक या राजप्रमुख या राज्य के लोगों ने भारत के संविधान को स्वीकार किया

इसका अंतिम रूप, उन्होंने इसे भाषणों के अधीन स्वीकार नहीं किया

संविधान सभा की बहसों के दौरान किया गया। द.

देखें कि क्या किसी विशेष प्रावधान की प्रगति का क्रम या प्रावधान ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर कोई प्रकाश डालते हैं।

या यह दर्शाता है कि एक आम समझ या समझौता

यह लोगों के कुछ वर्गों के बीच आया था। 208

222. न्यायमूर्ति हेगड़े और न्यायमूर्ति ए. के. मुखर्जी ने भी फैसला सुनाया।

किसी भी व्याख्या के लिए सीएडी पर निर्भरता नहीं रखी जा सकी

संविधान का सिद्धांत। राज्य को संदर्भ दिया गया था

रावनकोर-कोचीन और यह आयोजित किया गया था:

"अनुच्छेद 31 (2) के वास्तविक दायरे का पता लगाने के लिए

अब, महाराष्ट्र के विद्वान महाधिवक्ता के रूप में

साथ ही सॉलिसिटर-जनरल ने हमें इसके माध्यम से ले लिया है

इस लेख का इतिहास। उनके अनुसार लेख के रूप में

अब खड़ा है वास्तव में के इरादे का प्रतिनिधित्व करता है

संविधान निर्माता। उस तर्क के समर्थन में, हम

संविधान सभा से गुजरने के लिए कहा गया था

उस लेख से संबंधित बहस। विशेष रूप से हम थे

पंडित द्वारा दिए गए भाषणों को पढ़ने के लिए आमंत्रित किया गया

नेहरू, सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉ. मुंशी और डॉ.

अम्बेडकर। हमारी राय में, हमारे लिए ऐसा करना अस्वीकार्य है
तो। यह निर्माण का एक सुव्यवस्थित नियम है जो बोलता है
विधानमंडल के सदस्यों द्वारा किए गए
किसी कानून के अधिनियमन से संबंधित बहस नहीं हो सकती है
के किसी भी प्रावधान की व्याख्या के लिए सहायक के रूप में उपयोग किया जाता है कानून।
यही नियम तब लागू होता है जब हमें संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए कहा जाता है। 209
आरेग्राफ 184 से 186

ए. आर. ग्राफ 683 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

विद्वान न्यायाधीशों ने कहा कि उल्लिखित दृष्टिकोण से असहमति जताते हुए उनके संज्ञान में कोई निर्णय नहीं लाया गया था

ऊपर। 223. न्यायमूर्ति एच. आर. खन्ना की यह भी राय थी कि सीएडी को केवल सीमित उद्देश्य के लिए भेजा जा सकता है -

संवैधानिक प्रावधान के इतिहास का निर्धारण करना। सीएडी
के प्रावधानों को समझने के लिए आधार नहीं बना सकता है

संविधान '। विद्वान न्यायाधीश ने आगे कहा कि इरादा किसी कानून के मसौदा तैयार करने वाले से
एकत्र करना होगा

उपयोग किए गए शब्द। विद्वान न्यायाधीश ने कहा:

"संविधान सभा में दिए गए भाषण, मेरे

राय, संवैधानिक प्रावधान के इतिहास और इसके खिलाफ पृष्ठभूमि का पता लगाने के लिए संदर्भित
किया जा सकता है

जिसे उक्त प्रावधान का मसौदा तैयार किया गया था। भाषण कर सकते हैं

यह दिखाने के लिए भी प्रकाश डाला कि क्या शरारत थी जो

इसे ठीक करने की मांग की गई थी और इसका उद्देश्य क्या था
प्रावधान का मसौदा तैयार करने में इसे प्राप्त करने की कोशिश की गई थी। द.

भाषण, हालांकि, अर्थ के लिए आधार नहीं बना सकते हैं

संविधान के प्रावधान। व्याख्या करने का कार्य
संविधान का प्रावधान किया जाना चाहिए

स्वतंत्र रूप से और दिए गए भाषणों का संदर्भ
 संविधान सभा में न्यायालय दोषमुक्त नहीं होता है
 द्वारा उपयोग किए गए शब्दों में अपने इरादे व्यक्त करने के लिए
 प्रावधानों में। वे शब्द अंतिम भंडार हैं।

इरादे का और यह अंततः शब्दों से होगा
 इस प्रावधान का कि मसौदा तैयार करने वालों का इरादा

इकट्ठा होना पड़ता है। 210

224. न्यायमूर्ति वाई. बी. चंद्रचूड ने राज्य पर भरोसा किया
 त्रावणकोर-कोचीन, ए. के. गोपालन और गोलक नाथ से
 निष्कर्ष निकालें:

"संविधान सभा और प्रथम की बहसें

210 पैराग्राफ 1368 सुप्रीम कोर्ट के वकील-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

अस्थायी संसद को हमारे सामने विस्तार से पढ़ा गया।
 के दौरान। मैं भाषणों को पढ़ता हूँ

बहस

रुचि है, लेकिन मेरी राय में, बहस स्वीकार्य नहीं हैं
 संवैधानिक प्रावधानों के निर्माण में सहायता के रूप में "। 211

थोड़ी देर बाद कहा गया:

"संसदीय बहसों पर निर्भर रहना खतरनाक है क्योंकि

वैधानिक निर्माण में सहायता। अलग-अलग वक्ता हैं

अलग-अलग उद्देश्य और "पार्टी व्हिप" की प्रणाली छोड़ देती है
 यह मानने के लिए कोई वारंट नहीं है कि जिन्होंने मतदान किया लेकिन नहीं किया

बोलने वालों के बारे में भी बताना मुश्किल है।
 सुरक्षित तरीका इरादे को इकट्ठा करना है

सबसे

विधायिका जिस भाषा का उपयोग करती है। इसलिए,

संसदीय कार्यवाहियों का उपयोग केवल सीमित अवधि के लिए किया जा सकता है।

उद्देश्य जैसा कि गोपालन मामले में समझाया गया है।

225. एक विपरीत दृष्टिकोण आलंकारिक रूप से व्यक्त किया गया था

उस्टिस जगनमोहन रेड्डी लेकिन अंततः यह माना गया कि ए. डी. व्याख्या में सहायता कर सकता है, 'मूल्यवान सामग्री' होने के विपरीत

पक्षपातपूर्ण बहसों जो पक्षपातपूर्ण विचारों से प्रेरित हो सकती हैं

और पार्टी की राजनीति। संविधान सभा में बहस नहीं हुई

इस तरह के पक्षपातपूर्ण विचारों से प्रेरित। कहा गया था:

"अपने लिए बोलते हुए, हमें उन पर गौर क्यों नहीं करना चाहिए?

[सी. ए. डी.] साहसपूर्वक यह पता लगाने के लिए कि इरादा क्या था

क्या उन्हें वर्जित मानने का तर्क है या
न्यायालय एक संवैधानिक मामले में,

निषिद्ध सामग्री।

जहां लिखित दस्तावेज़ में सन्निहित संविधान निर्माताओं के इरादे का पता लगाया जाना है,

कार्यवाही, प्रासंगिक आंकड़ों को देखना चाहिए

कोई भी भाषण शामिल है जो प्रकाश डाल सकता है
पता लगाना। अगर वे फेंकते हैं तो यह उन्हें असहयोगी के रूप में अस्वीकार कर सकता है।

इसका

अनुच्छेद 2137

पैरा 2140 [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पहचाना गया। एक पर एक विधानमंडल की कार्यवाही में
सामान्य मसौदा विधेयक, जैसा कि मैंने पहले कहा था, एक पक्षपातपूर्ण हो सकता है

और गरमागरम बहस, जो अक्सर उन मुद्दों पर कोई प्रकाश नहीं डालती है जो न्यायालय के समक्ष
आते हैं लेकिन

पक्षपातपूर्ण बारीकियाँ और उनकी एकमात्र चिंता देना है
राष्ट्रीय अपनी मूल संरचना के साथ एक कार्यशील उपकरण और

मानव मूल्य पर्याप्त रूप से संतुलित और स्थिर हैं जो बलों की परस्पर क्रिया की अनुमति देते हैं जो

आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताएँ। सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया

इसके तहत और समझ के कर्तव्य के साथ आरोपित और
फ्रेमर्स के, खुद को मार्गदर्शन के लाभ से इनकार करते हैं
कार्यवाही के अभिलेखों से व्युत्पन्न और

सभा के विचार-विमर्श "। " 213

226. न्यायमूर्ति के. के. मैथ्यू ने न्याय के दृष्टिकोण का समर्थन किया।

जगनमोहन रेड्डी और उन्होंने कहा कि: 'तार्किक रूप से, कोई नहीं है जिस कारण से हमें दिए गए
भाषणों को पूरी तरह से बाहर कर देना चाहिए

अलग-अलग सदस्यों द्वारा संविधान सभा में यदि वे फेंक देते हैं

संविधान। विद्वान न्यायाधीश ने बाद में फैसला सुनाया निर्णय का अनुच्छेद:

"अगर संविधान सभा में बहसों को देखा जा सकता है

के प्रावधान के विधायी इतिहास को समझने के लिए

संविधान जिसमें इसकी व्युत्पत्ति भी शामिल है, अर्थात् विभिन्न

इसके अधिनियमन तक पहुँचने और उसमें भाग लेने के लिए उठाए गए कदम,

संविधान निर्माताओं के इरादे का पता लगाना,
यह समझना मुश्किल है कि बहस क्यों अस्वीकार्य है

के उद्देश्य और सामान्य इरादे पर प्रकाश डालें

प्रावधान। आखिरकार, विधायी इतिहास केवल खुलासा करता है

प्रावधान को लागू करने में विधायी उद्देश्य और

213 पैराग्राफ 1088 शीर्ष अदालतें-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

इस प्रकार विधायी इरादे पर प्रकाश डालता है। यह होगा

यदि बहस का सहारा लिया जाए तो एक अदृश्य अंतर आकर्षित करना है

केवल विधायी इतिहास को दिखाने की अनुमति दी गई और

उसी मामले में विधायी इरादे को दिखाने की अनुमति नहीं है

प्रावधान में अव्यक्त अस्पष्टता "। 214

227. समशेर सिंह ने अपनी सहमति में कहा,
 न्यायमूर्ति कृष्ण लायर (अपने और न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती के लिए)
 उनके निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए व्यापक रूप से सीएडी को संदर्भित किया गया,
 जबकि मुख्य न्यायाधीश रे (अपने और चार अन्य विद्वानों के लिए)
 न्यायाधीश) ने सीएडी का कोई संदर्भ नहीं दिया।

228. जो भी हो, सीएडी का संदर्भ फिर से आया
 विद्वान मुख्य न्यायाधीश के लिए बोलते हुए, न्यायमूर्ति एम. एन. वेंकटचलैया, न्यायमूर्ति अहमदी और
 स्वयं, न्यायमूर्ति बी. पी.
 जीवन रेड्डी ने स्पष्ट किया कि हालांकि सीएडी या भाषण
 डॉ. अम्बेडकर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, वे निर्णायक या निर्णायक नहीं हैं।
 न्यायालय पर बाध्यकारी लेकिन एक सहायता के रूप में भरोसा किया जा सकता है
 एक संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या करना। सीएडी को संदर्भित किया गया था
 'संदर्भ और उद्देश्य को प्रस्तुत करने' को प्राप्त करने के लिए
 संविधान के अनुच्छेद 16 के खंड (4) द्वारा। संदर्भ था
 अन्य बातों के साथ-साथ, गोलकनाथ, दिल्ली और केशवानंद को बनाया गया भारती और यह
 आयोजित किया गया था:

"हम जानते हैं कि इन बहसों के दौरान क्या कहा जाता है
 न्यायालय पर निर्णायक या बाध्यकारी नहीं है क्योंकि कई

सदस्यों ने कई विचार व्यक्त किए होंगे, जिनमें से सभी
 अंततः अधिनियमित प्रावधान में परिलक्षित नहीं हो सकता है। द.

हालाँकि, इस पहलू पर डॉ. अम्बेडकर का भाषण कायम है।

एक अलग पायदान पर। वे केवल अध्यक्ष ही नहीं थे

प्रारूपण समिति जिसने अभिव्यक्ति को सम्मिलित किया

"अनुच्छेद 10 (3) के मसौदे में पीछे की ओर [यह संविधान में नहीं था]

मूल मसौदा अनुच्छेद 10 (3)], वह वस्तुतः पायलट कर रहा था

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लेख का मसौदा। अपने भाषण में वह इसके पीछे का कारण बताते हैं
प्रारूप खंड (3) के साथ-साथ वह कारण भी जिसके लिए प्रारूपण

समिति ने "पिछड़े" शब्द को जोड़ा

खंड। इस स्थिति में, हम यह समझने में विफल रहते हैं कि कैसे कोई यह पता लगाने की कोशिश करते
हुए उनके भाषण को नजरअंदाज कर सकता है कि
उक्त अभिव्यक्ति का अर्थ। कि बहसों में

सहायता के रूप में संविधान सभा पर भरोसा किया जा सकता है

एक संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या की जाती है

इस न्यायालय के निर्णयों की एक श्रृंखला द्वारा। चूंकि अभिव्यक्ति "पिछड़े" या "नागरिकों का पिछड़ा
वर्ग"

संविधान में परिभाषित नहीं है, इस तरह की बहसों का संदर्भ किसी भी दर पर यह पता लगाने के
लिए अनुमत है कि उनके पीछे
का संदर्भ, पृष्ठभूमि और उद्देश्य।

विशेष रूप से, जहां न्यायालय यह सुनिश्चित करना चाहता है कि

'मूल आशय 'ऐसा संदर्भ अपरिहार्य हो सकता है'। 216

229. एस. आर. चौधरी बनाम पंजाब राज्य 217 यह था

अभिनिर्धारित किया कि यह तय किया गया है कि सीएडी पर 'एक के रूप में' भरोसा किया जा सकता है
एक संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या करने में सहायता क्योंकि यह है

संविधान निर्माताओं के इरादे का पता लगाने के लिए न्यायालय का कार्य। इस दृष्टिकोण का अनुसरण मैंने
मनोज में किया था।

नरूला बनाम। भारत संघ। 218

230. टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य 219

न्यायमूर्ति खरे ने केशवानंद भारती का उल्लेख किया और इसमें कहा गया है कि हालांकि सीएडी
निर्णायक नहीं है, फिर भी

वे लागू करने में निर्माताओं के इरादे पर प्रकाश डाल सकते हैं

संविधान के प्रावधान। इस आधार पर विद्वान न्यायाधीश आयोजित:

"इस प्रकार, स्वीकृत दृष्टिकोण यह प्रतीत होता है कि संविधान सभा की बहसों की रिपोर्ट वैध रूप से
हो सकती है

प्रावधानों के निर्माण के लिए विचार किया गया

218 अनुच्छेद 772

218 (2014) 9 एस. सी. सी. 1 (5 न्यायाधीशों की पीठ)
न्यायाधीशों की पीठ)

219 (2002) 8 एस. सी. सी. 481 (11

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

अधिनियम या संविधान "। 220

231. न्यायमूर्ति वरियावा (अपने और न्यायमूर्ति भान के लिए) भी

केशवानंद भारती का उल्लेख किया और कहा कि हालांकि
संवैधानिक मामले में जहां

सी. ए. डी. निर्णायक नहीं है, लेकिन 'एक

संविधान निर्माताओं के इरादे का पता लगाया जाना है,

न्यायालय को कार्यवाही और संबंधित मामलों को देखना चाहिए।

भाषणों सहित आंकड़े, जो पता लगाने पर प्रकाश डालते हैं

इरादे '।

232. न्यायमूर्ति सैयद शाह कादरी ने एक दिलचस्प बात कही।

निम्नलिखित शब्दों में सिद्धांतः

"किसी लेख की व्याख्या करने का सही तरीका है उसके सरल तरीके से जाना।

भाषा और जो अर्थ यह बताता है उसे उजागर करें। यह होगा।

इसमें कोई शक नहीं कि यह ऐतिहासिक और राजनीतिक संदर्भ के लिए उपयोगी होगा।
द्वारा दी गई व्याख्या का समर्थन करने वाली पृष्ठभूमि

सभा सब कुछ समझने का सबसे अच्छा रिकॉर्ड होगा।
उन पहलुओं। कई तरह के विचार हो सकते हैं

सदस्यों के माध्यम से भारत के लोगों को प्रेरित किया

संविधान सभा को संविधान को अपनाना, अधिनियमित करना और खुद को सौंपना। हम वास्तव में
चिंतित हैं।

जिसे उन्होंने अपनाया, अधिनियमित किया और दिया है
स्वयं इन दस्तावेजों में। हम नहीं कर सकते और हम

उस पर निशान नहीं होना चाहिए जो आने वाली पीढ़ियों को उसके चेहरे से हटाने में वर्षों लगेंगे।
221

233. विद्वान न्यायाधीश ने तब इस पर भरोसा करते हुए रोक लगा दी
प्रेम लाल मलिक, ए. के. गोपालन, त्रावणकोर राज्य
कोचीन, केशवानंद भारती और इंद्र साहनी
'संविधान सभा में दिए गए भाषणों की स्वीकार्यता
संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने की अनुमति नहीं है '
और यह कि 'राय की प्रधानता मुझे नहीं लगती है संविधान सभा में या बहस पर भरोसा करें
220 यह निष्कर्ष संदिग्ध प्रतीत होता है।

221 पैराग्राफ 286 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.
संसद एक संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या करने के लिए हालांकि वे
अन्य उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक हो सकता है। 'विद्वान न्यायाधीश ने उद्धृत किया ब्लैक क्लॉसन
इंटरनेशनल लिमिटेड का एक वाक्य v.

अस्काफेनबर्ग

वाल्डोफ़

निम्नलिखित प्रभाव के लिए पेपियरवेर्क एक्टिंगसेलशाफ 222:

"हम यह नहीं खोज रहे हैं कि संसद का क्या मतलब है, बल्कि सच क्या है।

संसद ने जो कहा उसका अर्थ। 223 234. पुनः
में - 2002 का विशेष संदर्भ संख्या 1 (गुजरात)

विधानसभा चुनाव मामला) 224 सीएडी पर निर्भर रहने का मुद्दा
फिर से विचार के लिए आया। न्यायमूर्ति खरे (मुख्य न्यायाधीश के लिए)
न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति भान और स्वयं) ने केशवानंद का उल्लेख किया
भारती और आयोजित:

"संविधान सभा की बहसें हालांकि निर्णायक नहीं हैं,
फिर भी संविधान निर्माताओं का इरादा दिखाएँ

संविधान सभा की बहसें प्रकाश डाल सकती हैं
ऐसे प्रावधानों के पीछे के इरादे का पता लगाना। 225

235. संवैधानिक न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में

द स्टेट वी में दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का। टी. मकवान्याने 226 संयुक्त राज्य अमेरिका में कानून का
एक संक्षिप्त सर्वेक्षण

सर्वोच्च न्यायालय, जर्मन संवैधानिक न्यायालय, कनाडाई सर्वोच्च न्यायालय, यह न्यायालय,
यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय और मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति का संचालन किया गया और यह
अभिनिर्धारित किया गया (न्यायमूर्ति चास्कल्सन के अनुसार):

जिन देशों में संविधान समान है

सर्वोच्च कानून, अदालतों का सम्मान करना असामान्य नहीं है

संविधान के समय मौजूद परिस्थितियों के लिए

बहस और लेखन सहित अपनाया गया था जो

यह प्रक्रिया का हिस्सा था। संयुक्त राज्य अमेरिका सर्वोच्च

223 अनुच्छेद 297 224 (2002) 8 एस. सी. सी. 237

225 अनुच्छेद 16

226 1995 (3) एस. ए. 391 (सी. सी.) (ग्यारह न्यायाधीशों की पीठ) पैराग्राफ 16 सर्वोच्च न्यायालय के
अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. /मदन बी. लोकुर, जे. जे.

न्यायालय ऐसे मामलों और उसके निर्णयों पर ध्यान देता है।

अक्सर विधायी इतिहास की समीक्षाएँ होती हैं

बहसों के संदर्भों सहित विचाराधीन प्रावधान,

इस तरह के सबूतों पर विचार करें। कनाडा का सर्वोच्च न्यायालय
माना है, और है

पूर्व सहित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को संदर्भित किया गया

ऐसी जानकारी को संयुक्त राज्य की तुलना में कम महत्व देता है
करता है। यह भी माना जाता है कि

इस तरह के साक्ष्य को स्वीकार्य

राज्यों का सर्वोच्च न्यायालय

संसद में मंत्रिस्तरीय वक्तव्य विशेष विधान का उद्देश्य। भारत में, जबकि भाषण
 संसद या कन्वेंशन के व्यक्तिगत सदस्यों का
 जाहिरा तौर पर आम तौर पर स्वीकार्य नहीं हैं, की रिपोर्ट सीरवर्ड के अनुसार, मसौदा समितियाँ
 "एक हो सकती हैं
 निर्माण के लिए सहायक बाहरी सहायता "। सीरवर्ड ने कनिया का हवाला दिया
 ए. के. गोपालन बनाम राज्य में मुख्य न्यायाधीश इस प्रस्ताव के लिए कि
 जबकि व्यक्ति को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है।
 किसी विशेष खंड के अर्थ की व्याख्या करें, जब सवाल उठाया जाता है कि क्या कोई निश्चित
 वाक्यांश या अभिव्यक्ति है
 बिल्कुल भी विचार के लिए था या नहीं, एक संदर्भ
 बहस की अनुमति दी जा सकती है। "यूरोपीय न्यायालय
 मानवाधिकार और संयुक्त राष्ट्र समिति मानवाधिकार सभी अपने विचार-विमर्श को सूचित करने
 की अनुमति देते हैं।
 ट्रेवॉक्स तैयारी द्वारा "। 227 (आंतरिक उद्धरण हटा दिए गए हैं)
 236. इससे पहले, इंग्लैंड में कानून पर विचार करने पर यह
 अभिनिर्धारित (न्यायमूर्ति चास्कलोन के अनुसार):
 "द्वारा दिए गए बयानों सहित संसद में बहस
 कानून के लिए जिम्मेदार मंत्री, और व्याख्यात्मक

ग्राफ 16 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

नए बिलों के लिए कारण प्रदान करने वाले ज्ञापन नहीं हैं
 पृष्ठभूमि सामग्री के रूप में स्वीकार किया गया। लेकिन यह है,

न्यायिक रिपोर्ट पर ध्यान देने की अनुमति

के सीमित उद्देश्य के लिए जांच आयोग
 वैधानिक उद्देश्य की शरारत का पता लगाना

विचाराधीन अधिनियम "। ये सिद्धांत बनाए गए थे
 आंशिक रूप से अंग्रेजी कानून से। इंग्लैंड में, अदालतों ने

हाल ही में इस बहिष्करण नियम में ढील दी गई है और माना है कि काली मिर्च (कर निरीक्षक) बनाम हार्ट कि, के अधीन हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकार:

..... संसदीय सामग्री का संदर्भ होना चाहिए

कानून के निर्माण में सहायता के रूप में अनुमति

जो अस्पष्ट या अस्पष्ट या शाब्दिक अर्थ है

जो एक बेतुकेपन की ओर ले जाता है। ऐसे मामलों में भी

अदालत में संसदीय सामग्री के संदर्भ होने चाहिए

केवल तभी अनुमति दी जाएगी जब ऐसी सामग्री स्पष्ट रूप से हो। विधायी को लक्षित शरारत का खुलासा करता है

अस्पष्ट या अस्पष्ट के पीछे झूठ बोलने का इरादा

शब्द "। 228 (आंतरिक उद्धरण हटा दिए गए हैं)

237. यह बिल्कुल स्पष्ट है कि का भारी दृश्य

इसके द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों में विभिन्न विद्वान न्यायाधीश

न्यायालय और अन्य क्षेत्राधिकारों में भी यह है कि: (1) एक संदर्भ

जिसमें संवैधानिक या वैधानिक प्रावधान बनाए गए थे और कानून निर्माताओं के इरादे को इकट्ठा करने के लिए लेकिन केवल अगर वहाँ है

प्रावधान की भाषा में कुछ अस्पष्टता या अनिश्चितता या विसंगति या अस्पष्टता। सी. ए. डी. या का संदर्भ

संसदीय बहस केवल इसलिए नहीं की जानी चाहिए क्योंकि

वे वहाँ हैं; 229 (2) सी. ए. डी. या संसदीय बहस होनी चाहिए

के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए निर्भर नहीं किया जाना चाहिए

228 अनुच्छेद 14

229 जॉर्ज मैलोरी से माफी मांगते हुए, जिन्हें प्रसिद्ध रूप से इस सवाल का जवाब देने के रूप में उद्धृत किया गया है, "आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना क्यों चाहते हैं?"

"जवाब के साथ "क्योंकि यह वहाँ है"। सर्वोच्च न्यायालय-चालू-रिकॉर्ड संगठन v. यू. ओ. आई. /मदन बी. लोकर, जे./

संविधान या कानून यदि इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है प्रयोग की गई भाषा। इन प्रावधानों की स्वतंत्र रूप से व्याख्या की जानी चाहिए-या कम से कम, यदि संदर्भ सीएडी को दिया गया है या

संसद में बहस, अदालत को अनावश्यक नहीं होना चाहिए

दिए गए भाषणों से प्रभावित। व्याख्या की पुष्टि सी. ए. डी. या संसद से मांगी जा सकती है। बहसों लेकिन इसके विपरीत नहीं।

238. यह चर्चा आवश्यक हो गई है

विद्वान महान्यायवादी का निवेदन कि संविधान विधानसभा का इरादा यह नहीं था कि न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए

उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की सहमति

भारत के मुख्य न्यायाधीश की आवश्यकता है। 'परामर्श' शब्द में

संविधान के अनुच्छेद 124 और संविधान के अनुच्छेद 217 में

संविधान का अर्थ 'सहमति' नहीं था और न ही हो सकता था। यह,

विद्वान अटॉर्नी के अनुसार-जनरल विशेष रूप से और

सी. ए. डी. से स्पष्ट रूप से उत्पन्न हुआ। वास्तव में, विद्वान वकील

जनरल ने हमारा ध्यान उस चर्चा की ओर खींचा जो हुई थी

संविधान सभा 23 और 24 मई, 1949 को।

239. यह प्रस्तुत किया गया था कि वहाँ की परिस्थितियों में

'परामर्श' शब्द के अर्थ में कोई अस्पष्टता नहीं थी

और उक्ति को लागू करते हुए, सीएडी का एक संदर्भ आवश्यक था केवल व्याख्या की पुष्टि करने के लिए

मुख्य न्यायाधीश सीकरी की,

'परामर्श' का अर्थ 'सहमति' नहीं है। यही कारण है कि, अलावा

दूसरे न्यायाधीशों के मामले और तीसरे के

न्यायाधीशों के मामले में पुनर्विचार की आवश्यकता थी।

240. विद्वान महान्यायवादी ने भी हमारा ध्यान आकर्षित किया

श्री टी. टी. द्वारा राय की निम्नलिखित अभिव्यक्ति के लिए।

27 मई, 1949 को संविधान सभा में कृष्णमाचारी

प्रारूप अनुच्छेद 122 के खंड (3) के संबंध में

उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी और व्यय। 230

230 (3) उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक व्यय, जिसमें न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या उनके संबंध में देय सभी वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं, भारत के राजस्व पर प्रभारित होंगे और न्यायालय द्वारा लिया गया कोई भी शुल्क या अन्य धन उन राजस्वों का हिस्सा होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

तर्क यह था कि यह संविधान का इरादा नहीं था भारत का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायाधीश बनाने के लिए विधानसभा कार्यपालिका या विधानमंडल के ऊपर का न्यायालय इस प्रकार खारिज करता है शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, और यदि 'परामर्श' की व्याख्या 'सहमति' के रूप में की जाती है, तो वह होगा अपरिहार्य परिणाम। रिलायंस को निम्नलिखित भाषण पर रखा गया था:

"जबकि मैं निस्संदेह द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूँ

डॉ. अम्बेडकर, मुझे लगता है कि इसे समझना चाहिए

इस सदन के सदस्य, और मैं उन लोगों से आशा करता हूँ

जो न्याय का प्रशासन करेगा और प्रशासन भी करेगा भविष्य में देश कि यह एक सुरक्षा है

एक परिचालन प्रावधान की तुलना में। इसके बारे में केवल एक ही बात है कि

न्यायाधीशों द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति जैसा मामला होना चाहिए

सामान्यतः कार्यपालिका के दायरे से बाहर रखा जाए

जिसे अन्यथा शामिल करने के लिए पहल करनी होगी बजट में ये आइटम इस कारण से हैं कि

न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखा जाना चाहिए और

अनुग्रह जो कार्यपालिका समय-समय पर उन्हें दे सकती है समय के साथ और जो स्वाभाविक रूप से उनके निर्णय को प्रभावित करेगा

किसी भी मामले में उन्हें वहाँ ले जाना होगा जहाँ उनके हित हों।

कुछ समय का कार्यपालक चिंतित होता है।

साथ ही, महोदय, मुझे लगता है कि यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि यह इस सदन या इसके निर्माताओं का इरादा नहीं है।

यह संविधान जिसे वे विशेष रूप से बनाना चाहते हैं

पसंदीदा निकाय जो अपने आप में एक बन जाते हैं

साम्राज्य में साम्राज्य, पूरी तरह से स्वतंत्र

कार्यपालिका और विधानमंडल और एक प्रकार के रूप में कार्य करना

राजनीतिक सामान्य निकाय से श्रेष्ठ निकाय। यदि ऐसा था, तो मुझे लगता है कि हमें एक प्रावधान लागू करने में सावधानी बरतनी चाहिए।

लेकिन महालेखा परीक्षक के संबंध में भी, संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में, अध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के दो सदनों के अध्यक्ष-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

संसद और इसी तरह, जैसा कि हम इस प्रकार एक ऐसी स्थिति में रखे गए निकायों की संख्या कि वे संघर्ष में आने के लिए बाध्य हैं

उनके प्रदर्शन के लिए किए गए हर प्रयास में कार्यकारी

श्रेष्ठता। वास्तविक व्यवहार में, यह इन सभी के लिए बेहतर है।

निकाय कमोबेश नियमों के अनुरूप होते हैं जो लोक सेवाओं में भर्ती के मामलों में प्राप्त करना,

पदोन्नति की शर्तें और उनके कर्मचारियों को भुगतान किया जाने वाला वेतन। 231 इस बहस का जवाब देते हुए डॉ. अम्बेडकर ने स्पष्ट किया कि

यह कि साम्राज्य बनाने का कोई सवाल ही नहीं था

पेरियो। डॉ. अम्बेडकर ने कहा:

"अध्यक्ष महोदय, मैं बस कुछ करना चाहूंगा।

स्थिति को साफ करने के लिए अवलोकन। श्रीमान, वहाँ है इसमें कोई संदेह नहीं है कि आम तौर पर सदन ने सहमति व्यक्त की है कि

कार्यपालिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी चाहिए

जितना हम इसे बना सकते हैं उतना स्पष्ट और निश्चित किया जाए

कानून। साथ ही इस बात का भी डर है कि नाम में

जो मेरे दोस्त श्री टी. टी. कृष्णमाचारी ने बनाया है जाता है। हम नहीं चाहते कि

उचित रूप से "साम्राज्य में साम्राज्य" कहा

साम्राज्य में एक साम्राज्य बनाएँ, और उसी समय

हम न्यायपालिका को पर्याप्त स्वतंत्रता देना चाहते हैं ताकि वह कार्यपालिका के भय या पक्ष के बिना कार्य कर सके। मेरा।

मित्र, यदि वे ध्यान से प्रावधानों की जांच करेंगे

नया संशोधन जो मैंने इसके स्थान पर प्रस्तावित किया है लेख प्रस्तावित करता है

मूल अनुच्छेद 122, पाएगा कि नया

एक मध्य मार्ग को चलाने के लिए। यह एक साम्राज्य बनाने से इनकार करता है

साम्राज्य में, और मुझे लगता है कि यह न्यायपालिका को उतना ही देता है जितना

स्वतंत्रता जो इस उद्देश्य के लिए आवश्यक है

बिना किसी भय या पक्षपात के न्याय का प्रशासन करना। मुझे इसकी जरूरत नहीं है।

अतः इसमें निहित सभी प्रावधानों का विस्तार करें।

नया अनुच्छेद 122. "232

टीपी: //भारत की संसद। ठीक है। इन/एलएस/डिबेट/वॉल्यूम 8 पी10 बी। एचटीएम टीपी: //भारत की संसद। ठीक है। इन/एलएस/डिबेट/वॉल्यूम 8 पी10 बी।

एचटीएम [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

241. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि प्रयास

डॉ. अम्बेडकर की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना था

कार्यपालिका से न्यायपालिका बिना कोई शक्ति बनाए

इसलिए, असंतुलन और इसके लिए एक मध्य मार्ग का संचालन करने की आवश्यकता थी

चाहे वह न्यायाधीशों की नियुक्ति में हो या उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों की। इस बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता। लेकिन

न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है और यह कैसे हो सकती है?

99 वें संविधान संशोधन अधिनियम को बनाए रखा और करता है परेशान करने वाले हैं

उस स्वतंत्रता पर प्रभाव? ये कुछ

जिन प्रश्नों के प्रश्न के संदर्भ में उत्तर की आवश्यकता है
हमारे सामने, अर्थात्, 99 वीं की संवैधानिक वैधता
संविधान संशोधन अधिनियम।

न्यायिक घोषणाएँ और तीसरा प्रारंभिक निर्णय

मुद्दा

242. विद्वान महान्यायवादी ने प्रस्तुत किया कि किसी भी मामले में
दूसरे न्यायाधीश के मामले में पुनर्विचार की आवश्यकता होती है।
केस लॉ की बड़ी मात्रा है जो इस पर मार्गदर्शन देती है
ऐसी परिस्थितियाँ जब इस न्यायालय का पूर्व निर्णय होना चाहिए
पुनर्विचार किया जाए। इन मामलों पर विचार करना आवश्यक है। यह तय करने से पहले कि क्या
पुनर्विचार के लिए एक मंच है
द्वितीय न्यायाधीशों का मामला बनाया गया है।

243. बंगाल इम्युनिटी कं. लिमिटेड बनाम बिहार राज्य और

Ors. 233 अनुच्छेद 286 की व्याख्या से संबंधित है

यह तर्क दिया गया था कि संविधान गलत था

Ltd. 234 इस न्यायालय ने एक के पुनर्विचार के मुद्दे को संबोधित किया इसके द्वारा दिया गया
पिछला निर्णय। मुख्य न्यायाधीश दास (बोलते हुए)

अपने लिए, न्यायमूर्ति विवियन बोस और न्यायमूर्ति सैयद जाफर इमाम)

इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में दिए गए निर्णयों पर चर्चा की, संयुक्त राज्य अमेरिका और प्रिवी काउंसिल
द्वारा और विचार था

(कई कारणों से) कि इसके द्वारा दिया गया एक पिछला निर्णय

न्यायालय से अलग किया जा सकता है। यह देखा गया कि यह नहीं था

233 ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 661 (7 न्यायाधीशों की पीठ) 234 (1953) 4 एससीआर 1069
(5 न्यायाधीशों की पीठ)

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

संविधान में संशोधन करना आसान है और यदि इसके किसी प्रावधान पर गलत व्याख्या की गई है तो यह हो सकता है 'संभावित रूप से स्थायी किया जा सकता है या किसी भी दर पर रह सकता है

बड़े नुकसान के लिए काफी समय के लिए ठीक नहीं किया गया सार्वजनिक कल्याण '। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि यह न्यायालय था

इसकी त्रुटि और सामान्य पर 'हानिकारक प्रभाव' के बारे में आश्चर्य

एक की गलत व्याख्या के जनता के हित

संविधान का प्रावधान, तो इसमें कुछ भी नहीं है

संविधान जो इस न्यायालय को अपने पहले वाले संविधान से अलग होने से रोकता है निर्णय लें। यह पिछले निर्णय से भी अलग हो सकता है यदि यह था

अस्पष्ट या असंगत या स्पष्ट रूप से गलत। यह माना गया कि

टकटकी निर्णय का सिद्धांत कानून का एक अनम्य नियम नहीं है और

हमारी गलतियों को नुकसान पहुँचाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है

जनता या एक बड़े वर्ग के सामान्य कल्याण के लिए

बिनि। '

244. एक महत्वपूर्ण मार्ग में (एक जिसका असर होगा)

इस विषय पर), यह देखा गया:

"बहुमत का निर्णय केवल यह निर्धारित नहीं करता कि

बॉम्बे अपील के लिए दो विरोधी पक्षों के अधिकार।

इसका प्रभाव दूरगामी है क्योंकि यह सभी के अधिकारों को प्रभावित करता है।

जनता का उपभोग करना। यह अधिरोपण और शुल्क लगाने को अधिकृत करता है।

एक संवैधानिक की व्याख्या पर राज्य द्वारा कर का प्रावधान जो हमें असमर्थनीय प्रतीत होता है। को।

उस व्याख्या का पालन करने से क्या कायम रहेगा,

राय मानी जाती है, स्पष्ट रूप से और पूरी तरह से अनाधिकृत।

यह अधिकारों की घोषणा करने वाली कोई साधारण घोषणा नहीं है।

दो निजी व्यक्तियों के बीच। इसमें शामिल है

इसके विरुद्ध राज्यों की कर लगाने की शक्ति पर निर्णय

आम तौर पर उपभोक्ता जनता। यदि निर्णय लिया जाए तो

गलत, जैसा कि हम वास्तव में इसे मानते हैं, हम इसे सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के लिए देते हैं

[2015] 13 एस सी आर।

कि जनता उन्हें अवैध कर बोझ से बचाने के लिए जो राज्य ताकत पर थोपना चाहते हैं

उस गलत हाल के फैसले के बारे में "। 235

245. न्यायमूर्ति एन. एच. भगवती ने भी विभिन्न क्षेत्राधिकारों के कई फैसलों की समीक्षा की और मुख्य न्यायाधीश से सहमति व्यक्त की।

न्यायमूर्ति दास ने लेकिन पुनर्विचार के बीच अंतर बताया

एक की व्याख्या से संबंधित पिछले निर्णय का एक विधायी अधिनियम का प्रावधान और एक की व्याख्या

संविधान का प्रावधान। जबकि एक गलत व्याख्या

न्यायालय द्वारा पूर्व में से विधानमंडल द्वारा ठीक किया जा सकता है,

संविधान में संशोधन करना आसान नहीं था।

न्यायालय द्वारा गलत व्याख्या। यही कारण है कि

न्यायमूर्ति एन. एच. भगवती ने अभिनिर्धारित किया कि यदि पिछला निर्णय संविधान के प्रावधानों की व्याख्या 'स्पष्ट रूप से' की गई थी

गलत या गलत 'और यह कि' जनहित 'इसकी मांग करता है

पुनर्विचार के बाद न्यायालय को इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए ऐसा करना।

246. न्यायमूर्ति जगन्नाथदास ने यह भी कहा कि यह न्यायालय है

अपने पहले के निर्णयों पर पुनर्विचार करने के लिए सक्षम। यह जोड़ा गया था

वह: 'लेकिन, ऐसा नहीं है कि इस तरह की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है प्रतिबंध या सीमा के बिना या कि एक पूर्व निर्णय हो सकता है

इस आधार पर उलट दिया कि, बाद में विचार करने पर, न्यायालय ने पूर्व निर्णय से असहमत है और इसे गलत समझता है। यह.

यह अभिनिर्धारित किया गया था कि हालांकि पूर्व निर्णय पर पुनर्विचार करने की शक्ति

मौजूद है, उस शक्ति का वास्तविक प्रयोग सीमित होना चाहिए

'बहुत संकीर्ण सीमाओं के भीतर। 'विद्वान न्यायाधीश ने गोद लेना पसंद किया

एन. एस. डब्ल्यू. बनाम के लिए अटॉर्नी जनरल में ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति डिक्सन द्वारा व्यक्त किया गया विचार। चिरस्थायी

न्यासी कं. *Ltd.* 236 इस प्रभाव के लिए कि एक पूर्व निर्णय होना चाहिए

केवल इसलिए पुनर्विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि एक विपरीत निष्कर्ष को प्राथमिकता दी जानी है।

247. न्यायमूर्ति वेंकटरामा अय्यर ने भी यह मत व्यक्त किया कि

235 अनुच्छेद 17

235 85 सी. एल. आर. 237 सर्वोच्च न्यायालय के वकील-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

यह न्यायालय अपने द्वारा दिए गए पहले के निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है।

हालाँकि, विद्वान न्यायाधीश की राय थी कि शक्ति

पुनर्विचार का प्रयोग बहुत संयम से और केवल

असाधारण परिस्थितियाँ, जैसे कि जब कोई भौतिक प्रावधान हो

कानून की अनदेखी की गई थी, या जहाँ एक मौलिक

ऐसी धारणा जिसके आधार पर निर्णय लिया गया है

गलती हो गई '। न्याय द्वारा प्रचार किए गए दृष्टिकोण से सहमत होना

जगन्नाथदास (और न्यायमूर्ति डिक्सन) विद्वान न्यायाधीश ने प्रस्तुत किया

निम्नलिखित प्रश्न और इसका उत्तर भी दिया: 'क्या हम अलग हो सकते हैं?

इस न्यायालय के पिछले निर्णय से, क्योंकि एक विपरीत दृष्टिकोण

उसमें ली गई चीज़ बेहतर प्रतीत होती है? मैं बिना किसी हिचकिचाहट के इसका जवाब नकारात्मक रूप से दूंगा, इसलिए नहीं कि यह दृष्टिकोण है।

पहले लिया गया अनिवार्य रूप से अचूक होना चाहिए लेकिन क्योंकि यह महत्वपूर्ण है कि घोषित कानून होना चाहिए

सार्वजनिक हित में

निश्चित और अंतिम होने के बजाय इसे एक में घोषित किया जाना चाहिए।

भावना या दूसरा। '

248. न्यायमूर्ति बी. पी. सिन्हा ने न्यायमूर्ति से सहमति व्यक्त की

जगन्नाथदास और न्यायमूर्ति वेंकटरामा अय्यर ने कहा कि इस न्यायालय के पिछले फैसले की समीक्षा नहीं की जानी चाहिए केवल इसलिए कि बिंदुओं के बारे में एक और दृष्टिकोण लिया जा सकता है

विवाद। इस न्यायालय को अपने पिछले फैसलों की समीक्षा करनी चाहिए

केवल असाधारण परिस्थितियों में। यह देखा गया कि

'कानूनी स्थिति की निश्चितता और निश्चितता आवश्यक है।

कानून के शासन के विकास के लिए शर्तें "।

249. लेफ्टिनेंट कर्नल खजुर सिंह बनाम भारत संघ 237

संविधान के अनुच्छेद 226 की व्याख्या से संबंधित और संविधान का अनुच्छेद 32 (2-ए) (जैसा कि जम्मू पर लागू होता है)

& कश्मीर)। यद्यपि न्यायमूर्ति सुब्बा राव (असहमत) और

न्यायमूर्ति दास गुप्ता (सहमत) ने अलग-अलग निर्णय दिए।

उन्होंने एक के पुनर्विचार के प्रश्न का विज्ञापन नहीं किया

इस न्यायालय का निर्णय। मुख्य न्यायाधीश बी. पी. सिन्हा बोल रहे हैं

शेष विद्वान न्यायाधीशों ने यह विचार रखा कि एक पूर्व

इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार किया जा सकता है यदि

237 ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 532 (7 न्यायाधीशों की पीठ)

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ऐसा करने के लिए 'स्पष्ट और सम्मोहक कारण' हैं या यदि कोई उचित कारण है

सर्वसम्मति की मात्रा कि पिछला निर्णय 'स्पष्ट रूप से' है

गलत 'या यदि यह प्रदर्शित किया जाता है कि पहले का निर्णय था

त्रुटिपूर्ण 'सभी उचित संदेह से परे' विशेष रूप से एक पर

संवैधानिक मुद्दा। यदि कोई असुविधा महसूस की जाती है

संविधान के प्रावधानों की व्याख्या

विचार करें, तो उपाय 'एक संवैधानिक प्रतीत होता है

संशोधन '।

250. केशव मिल्स बनाम। सी. आई. टी. 238 का प्रश्न

विचार के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियों का दायरा था आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 66
(4)। इसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था

विद्वान अटॉर्नी-जनरल कि पर पहले के दो निर्णय

विषय, अर्थात् न्यू जहांगीर वकील मिल्स लिमिटेड बनाम। सी. आई. टी. 239 और

पेटलैड तुर्की रेड डाई वर्क्स कंपनी लिमिटेड, पेटलैड बनाम। सीआईटी 240

पुनर्विचार की आवश्यकता है। इस निवेदन पर विचार करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि जब यह न्यायालय किसी वैधानिक प्रावधान की व्याख्या करता है, तो केवल क्योंकि एक वैकल्पिक दृष्टिकोण पहले की राय से अलग है।

इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया अधिक तर्कसंगत होना आवश्यक नहीं है

पहले की राय पर पुनर्विचार करने के लिए एक पर्याप्त कारण। यह

न्यायालय को स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या इसके हित में

लोक कल्याण या किसी अन्य वैध और बाध्यकारी कारणों से, यह आवश्यक है कि पहले के निर्णय को संशोधित किया जाए। यह

अदालत ने कहा:

"जब यह न्यायालय कानून के प्रश्नों का निर्णय करता है, तो उसके निर्णय

अनुच्छेद 141 के तहत सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी हैं

भारत का क्षेत्र और इसलिए यह निरंतर प्रयास होना चाहिए

और इस न्यायालय की चिंता की व्याख्या में निश्चितता और निरंतरता के एक तत्व को पेश करने और बनाए रखने के लिए

देश में कानून। इसका मतलब यह नहीं है कि यदि बाद के अवसर पर, न्यायालय संतुष्ट है कि यह पहले था।

निर्णय स्पष्ट रूप से गलत था, इसे संकोच करना चाहिए

238 ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1636 (7 न्यायाधीशों की पीठ)

239 (1960) 1 एससीआर 249

240 (1963) पूरक 1 एस. सी. आर. 871 सर्वोच्च अदालतें-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

त्रुटि को ठीक करें; लेकिन पिछले निर्णय से पहले स्पष्ट रूप से गलत होने के लिए घोषित, न्यायालय को होना चाहिए इसके बीच उचित मात्रा में सर्वसम्मति से संतुष्ट सदस्यों का कहना है कि उक्त दृष्टिकोण का एक संशोधन पूरी तरह से है न्यायसंगत "। 241

251. मगनलाल छगनलाल बनाम। नगर निगम

ग्रेटर बॉम्बे 242 की कार्यवाही की वैधता से संबंधित

बॉम्बे नगर निगम अधिनियम के अध्याय V-A के तहत,

1888 और बंबई सरकार परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1955 उत्तर में इस न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में

इंडिया कैटरर्स बनाम. पंजाब राज्य। 243 न्यायमूर्ति एच. आर. खन्ना

अकेले पहले के निर्णय को रद्द करने के सवाल पर विचार किया गया इस न्यायालय का, अर्थात्, उत्तर भारत कैटरर्स में। यह था।

यह देखा गया कि यदि कोई निर्णय लिया जाता है तो कानून में निश्चितता समाप्त हो जाएगी

कई वर्षों तक 'मैदान में रहने' को आसानी से खारिज कर दिया जाता है

—

'निश्चितता और निरंतरता कानून के शासन के आवश्यक तत्व हैं।

यह माना गया था कि यदि दो विचार संभव हैं, तो केवल इसलिए कि

पहले का निर्णय एक दृष्टिकोण नहीं लेता है जो अधिक है

निर्णय लें। पहले के निर्णय को केवल इसके लिए रद्द किया जाना चाहिए बाध्यकारी कारण अन्यथा यह 'अनिश्चितता' पैदा करेगा,

अस्थिरता और भ्रम यदि इस न्यायालय द्वारा प्रस्तावित कानून जिनके आधार पर कई मामलों का फैसला किया गया है।

और कई लेन-देन हुए हैं जिन्हें नहीं माना जाता है

सही कानून '। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि नए विचार और

कानून के क्षेत्र में विकास और इसकी पूर्णता

अनुभव और वास्तव में बाद का अनुभव नहीं हो सकता है

दूर जाना चाहते हैं। विद्वान न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि:

प्रभाव के परिणामस्वरूप क्षितिज खुद को प्रकट कर सकते हैं
जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नए विचारों और विकास।

241 अनुच्छेद 23

242 (1974) 2 एससीसी 402 (7 न्यायाधीशों की पीठ)

243 एयर 1967 एससी 1581 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

कानून, यदि इसे मानव आवश्यकताओं को पूरा करना है और इसे पूरा करना है
जीवन की समस्याओं, नए से निपटने के लिए खुद को अनुकूलित करना चाहिए
परिस्थितियाँ। दूरदर्शिता के साथ कोई भी इतना प्रतिभाशाली नहीं है कि वह कर सके
सभी संभावित मानव घटनाओं को पहले से दैवीय और

उनमें से प्रत्येक के लिए उचित नियम निर्धारित करें। वहाँ हैं,
हालांकि, कुछ तथ्य जो इसके सार हैं

कानून का शासन और कोई भी कानून उन्हें समाप्त करने का जोखिम नहीं उठा सकता है। में।

उसी समय यह स्वीकार करना होगा कि एक है

कानून के विकास की निरंतर प्रक्रिया और कोई भी कर सकता है
इसे केवल जीवन से ही कानून को अलग करने के जोखिम पर रोकें।

इसे छोड़ने में ज्यादा संकोच नहीं होना चाहिए।

असमर्थनीय स्थिति जब रद्द किया जाने वाला नियम था

इसकी उत्पत्ति संस्थानों या स्थितियों का उत्पाद है जो

वर्षों की प्रगति के साथ एक नया महत्व या विकास प्राप्त किया है। कभी-कभी ऐसा होता है कि

कानून जो दूरदराज की पीढ़ियों में पला-बढ़ा हो सकता है

अनुभव की पूर्णता को दूसरे की सेवा करने के लिए पाया जाता है

पीढ़ी बुरी तरह से। न्यायालय खुद को बांधने की अनुमति नहीं दे सकता है।

नीचे से और एक दृश्य के बंदी बन जाते हैं जो प्रकाश में है
बाद के अनुभव से पता चला है कि

स्पष्ट रूप से गलत, स्पष्ट रूप से अनुचित या कारण बनाने के लिए
कठिनाई या सीधे अन्याय या सार्वजनिक परिणाम के लिए

असुविधा। " 244

252. गंगा चीनी निगम बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य

प्रदेश 245 के तहत एक लेवी की संवैधानिक वैधता से संबंधित है

उत्तर प्रदेश गन्ना (खरीद कर) अधिनियम, 1961। फैसला

विषय पर कोई विस्तृत चर्चा नहीं है

अंतिम के रूप में स्वीकार किया जाए जब तक कि विषय मौलिक न हो राष्ट्रीय जीवन के लिए
महत्व या पिछले के तर्क

निर्णय इतना स्पष्ट रूप से गलत है कि अंततः ऐसा करना बुद्धिमानी होगी।

244 अनुच्छेद 22 245 (1980) 1 एससीसी 223 (5 न्यायाधीशों की पीठ)

सर्वोच्च अदालतें-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

लगातार गलत होने के बजाय सही। टकटकी निर्णय नहीं है

सुविधा का एक अनुष्ठान लेकिन सीमित अपवादों के साथ एक नियम।

संविधान पीठों द्वारा की जाने वाली घोषणाएँ नहीं होनी चाहिए

इसे इतना घुड़सवार माना जाता है कि इसे बार-बार संशोधित किया जा सके।

253. मामलों का विस्तृत संदर्भ और

विभिन्न क्षेत्राधिकारों में निर्धारित कानून को संघ में परिवर्तित किया गया था भारत का वी।
रघुबीर सिंह। 246 यह निर्णय खुद से संबंधित था।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत सहायता अनुदान के साथ

भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 1984 द्वारा संशोधित। से निकाले गए 'दिशानिर्देशों' का
संदर्भ दिया गया था

हाउस ऑफ लॉर्ड्स 247 के निर्णय जो सुझाव देते हैं कि पहले के निर्णय पर पुनर्विचार करने की
स्वतंत्रता होनी चाहिए

संयम से प्रयोग किया गया; एक निर्णय को खारिज नहीं किया जाना चाहिए यदि यह उन व्यक्तियों की वैध
अपेक्षा को आहत करता है जिन्होंने किया है

पहले के निर्णय या कारणों के आधार पर व्यवस्थाएँ कानून में अनिश्चितता; की व्याख्या से जुड़े निर्णय

दुर्लभ या असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर कानूनों या दस्तावेजों को खारिज नहीं किया जाना चाहिए; यदि

पहले के किसी निर्णय से हटना पूर्वानुमेय नहीं है; केवल

क्योंकि पहले गलत तरीके से लिया गया निर्णय अच्छा नहीं है। इसे ओवररूल करने के लिए पर्याप्त औचित्य। दूसरी ओर, एक पूर्व

मुद्दा या सिद्धांत इसे उचित या उसके अनुरूप नहीं माना जाता है। समकालीन सामाजिक स्थितियाँ या आधुनिक अवधारणाएँ

सार्वजनिक नीति '।

254. कई फैसलों का भी उल्लेख किया गया

इस न्यायालय द्वारा पहले प्रदान किया गया (जिनमें उल्लिखित लोग भी शामिल हैं) ऊपर) और हालांकि कोई नया या अलग सिद्धांत या दिशानिर्देश नहीं

निर्धारित किए गए थे, इस न्यायालय द्वारा बताए गए कानून को दोहराया गया,

और यह देखा गया: 'सभी मामलों को संदर्भित करना आवश्यक नहीं है।

बिन्दु पर। व्यापक दिशा-निर्देशों का आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है

246 (1989) 2 एस. सी. सी. 754 (5 न्यायाधीशों की पीठ)

247 डॉ. एलन पैटरसन के लॉ लॉर्ड्स का संदर्भ दिया गया था। यह संदर्भ बिल्कुल स्पष्ट नहीं है और इसे केवल '1982 एट पीपी' के रूप में कहा गया है।

156-157 '[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जो पहले हो चुका है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों को और अधिक परिभाषित करने की संभावना की परिकल्पना आगे न्यायिक रूप से की जा सकती है।

अनुभव, और जब सामान्य न्यायशास्त्र मूल्य जुड़ते हैं

कानून की विभिन्न राष्ट्रीय प्रणालियाँ एक सहमति बना सकती हैं

संभव पैटर्न। लेकिन यह भविष्य में है। '

255. मगनलाल में व्यक्त किए गए विचारों को प्रतिध्वनित करते हुए

समय और आधुनिक के साथ परिवर्तनों को स्वीकार करने के संबंध में छगनलाल और रघुबीर सिंह सार्वजनिक नीति की अवधारणाओं के बारे में कहा गया था:

"कभी-कभी नहीं, चीजों की प्रकृति में एक गुरुत्वाकर्षण होता है

अग्रवर्ती द्वारा निर्धारित खांचे का अनुसरण करने के लिए भारी झुकाव

कानून। फिर भी एक संवेदनशील न्यायिक विवेक अक्सर समझाता है

अधिक मानदंडों के एक अलग समूह की खोज करने के लिए मन

परिवर्तित सामाजिक संदर्भ के प्रति उत्तरदायी। दुविधा

इससे पहले कि न्यायाधीश एक नया खोजने का कार्य प्रस्तुत करे संतुलन शायद ही कभी इच्छा से प्रेरित होता है

विरोधी गतिशीलताओं में सामंजस्य स्थापित करें। प्रतिस्पर्धी लक्ष्य,

डीन रोस्को पाउंड के अनुसार, न्यायाधीश के साथ निवेश करें

मानव जाति के सामने यह साबित करने की जिम्मेदारी कि कानून था

निरंतर पुनः समायोजन और कभी-कभी कट्टरपंथी परिवर्तन अनंत और परिवर्तनशील मानव इच्छाओं के दबाव में "।

लॉर्ड रीड द्वारा द जज एज लॉ मेकर में सुझाए गए सुलह दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रखने में निहित है,

"कि कानून निश्चित होगा, और यह न्यायपूर्ण होगा और समय के साथ आगे बढ़ेगा "। 248 (आंतरिक उद्धरण दिए गए हैं

छोड़ दिया गया)।

256. गैनन डंकरली एंड कंपनी बनाम की स्थिति

राजस्थान 24 9 पर कर लगाने से संबंधित प्रश्न

निष्पादन में शामिल वस्तुओं में संपत्ति का हस्तांतरण

कार्य अनुबंध। इस कर को लागू करने की शक्ति बन गई

248 अनुच्छेद 13

249 (1993) 1 एस. सी. सी. 364 सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

के परिणामस्वरूप राज्य विधानमंडलों के लिए उपलब्ध

संविधान में किए गए संशोधन

(46 वाँ संशोधन) अधिनियम, 1982। 'संवैधानिक वैधता

बिल्डर्स में इस संशोधन अधिनियम को बरकरार रखा गया था।

यह उठाया गया था कि क्या बिल्डर्स एसोसिएशन सही था तय किया या नहीं। इस न्यायालय ने इस पर चर्चा को नहीं जोड़ा

मिल्स और गंगा चीनी निगम कि वहाँ नहीं था बिल्डर्स एसोसिएशन में निर्णय पर पुनर्विचार करने का अवसर।

257. एक और निर्णय (जो काफी दिलचस्प है)

प्रदीप पहले के फैसले पर पुनर्विचार का विषय है। कुमार विश्वास बनाम। भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान। 251

इस न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या परिपद

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान को 'राज्य' के रूप में परिभाषित किया गया था

संविधान के अनुच्छेद 12 में। इस सवाल का जवाब

इसके पहले के सर्वसम्मत निर्णय पर विचार करने की आवश्यकता है

सभाजीत तिवारी बनाम में न्यायालय। भारत संघ 252 जो खड़ा था

लगभग 25 वर्षों तक परेशान नहीं हुए। इस सवाल का जवाब देते हुए,

इस न्यायालय ने पुनर्विचार के विषय पर कानून का विवरण नहीं दिया

इस न्यायालय के पहले के निर्णय के बारे में, लेकिन तथ्यों (और कानून) पर विचार करने पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि सभाजीत तिवारी ने

गलत निर्णय लिया गया और खारिज कर दिया गया। इस न्यायालय ने संदर्भित किया

मगनलाल छगनलाल और रघुबीर सिंह को और कहा:

"तथ्यों पर जिस भी दृष्टिकोण से विचार किया जाए,

इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि निष्कर्ष पर पहुंचा गया

सभाजीत तिवारी गलत थे।

तथ्यों के मूल्यांकन में, न्यायालय ने मान लिया था कि

कुछ सिद्धांत, और उनसे पूर्ववर्ती समर्थन की मांग की

ऐसे निर्णय जो अप्रासंगिक थे और जिनका पालन किया गया था एक ऐसे संदर्भ के बीच खांचे का पीछा किया गया जो लंबे समय से है

250 (1989) 2 एस. सी. सी. 645

251 (2002) 5 एस. सी. सी. 111 (7 न्यायाधीशों की पीठ)

252 (1975) 1 एस. सी. सी. 485 (5 न्यायाधीशों की पीठ)

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

टूट गया "। 253 यदि तथ्यों की उचित परिप्रेक्ष्य में बारीकी से जांच की जाती, तो यह नेतृत्व कर सकता था और केवल कर सकता था

यह निष्कर्ष निकालता है कि सी. एस. आई. आर. के अंतर्गत एक राज्य है

सभाजित होना चाहिए। तिवारी अभी भी एक प्राधिकरण के रूप में खड़े हैं तथ्यों पर केवल इसलिए कि यह 25 वर्षों से बना हुआ है?

हम नहीं सोचते हैं। तथ्यों पर भी समानताएं खींची जा सकती हैं।

जिससे अनुच्छेद 12 की असमर्थनीय व्याख्या की जा सके और परिणामस्वरूप मौलिक अधिकारों के लाभों से इनकार किया जा सके।

उन व्यक्तियों के लिए जो अन्यथा उनके हकदार होंगे

और

"[टी] यहाँ हमारे संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो रोकता है

हम एक पिछले निर्णय से प्रस्थान करने से अगर हम हैं इसकी त्रुटि और इसके हानिकारक प्रभाव के बारे में आश्चर्य

जनता के सामान्य हित "।

चूंकि हम प्रश्न के पुनः परीक्षण पर आए हैं

इस निष्कर्ष पर कि निर्णय स्पष्ट रूप से गलत था,

यह हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसा कहें और अपनी गलती को कायम न रखें।

254 (आंतरिक उद्धरणों को हटा दिया गया है)।

258. प्रदीप का एक और दिलचस्प पहलू

कुमार विश्वास 7 (सात) विद्वान न्यायाधीशों में से हैं।
न्यायाधीशों ने खारिज कर दिया

पीठ का गठन करते हुए, 5 विद्वान

5 विद्वान न्यायाधीशों के एक अन्य समूह का सर्वसम्मत निर्णय
विद्वान न्यायाधीश

सभाजीत तिवारी। प्रदीप में दो

तथ्य और कानून के मुद्दे पर एक विशेष दृष्टिकोण, वह दृष्टिकोण था
गलत पाया गया, जिनका निर्णय

5 विद्वान न्यायाधीशों द्वारा

वास्तव में आज मैदान पर है। क्या संख्याओं का भार अप्रासंगिक है?

क्या यह है कि केवल बाद की पीठ में संख्याएँ क्या हैं?

253 सभाजीत तिवारी इस न्यायालय के 5 विद्वान न्यायाधीशों का सर्वसम्मत निर्णय था। यह निष्कर्ष निकालना कि इसने "उन निर्णयों से पूर्ववर्ती समर्थन मांगा जो अप्रासंगिक थे", सम्मान के साथ, बल्कि अनुचित है।

254 पैराग्राफ 59 से 61 सर्वोच्च अदालतें-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

क्या यह वास्तव में महत्वपूर्ण है? क्या स्थिति होती अगर केवल 4
न्यायाधीशों ने फैसला किया था कि

प्रदीप कुमार विश्वास में विद्वान

सभाजीत तिवारी को खारिज करें जबकि शेष 3 विद्वान न्यायाधीश

उस निर्णय में कोई त्रुटि नहीं मिली? क्या कोई निर्णय दिया जाएगा?

के बाद की पीठ में 4 विद्वान न्यायाधीशों के निर्णय द्वारा
विश्वास प्रस्तुत करते हैं

7 विद्वान न्यायाधीश? प्रदीप कुमार

विसंगत स्थिति जिसे संबोधित करने की आवश्यकता है

प्रक्रिया के उचित नियम। यदि यह विसंगति बनी रहती है

फिर तीसरे में 9 विद्वान न्यायाधीशों का सर्वसम्मत निर्णय

न्यायाधीशों के मामले को खारिज किया जा सकता है (जैसा कि विद्वान द्वारा मांगा गया है)
महान्यायवादी) 11 विद्वानों की पीठ में 6 विद्वान न्यायाधीशों द्वारा

न्यायाधीश, जिनमें से 5 अलग दृष्टिकोण रखते हैं, एक दृष्टिकोण रखने वाले और दूसरे दृष्टिकोण रखने वाले
न्यायाधीशों की कुल संख्या को 14 पर लाते हैं।

6 तक, 6 विद्वान न्यायाधीशों के दृष्टिकोण के साथ

कानून!

259. चाहे जो भी हो, दो अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

इस न्यायालय के पूर्व निर्णय पर पुनर्विचार करने के विषय पर
केशवानंद भारती और द्वितीय न्यायाधीश का मामला है।

260. केशवानंद भारती में इसका उल्लेख किया गया है -

मुख्य न्यायाधीश एस. एम. सीकरी ने कहा कि न्यायालय के समक्ष प्रश्न था
क्या गोलक नाथ का निर्णय सही था। विद्वान प्रमुख
न्याय ने टिप्पणी की:

"हालाँकि, जैसा कि मैं इसे देखता हूँ, सवाल यह है कि क्या गोलक नाथ

मामला सही तरीके से तय किया गया था या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वास्तविक मुद्दा
अलग है और बहुत अधिक महत्वपूर्ण है।

मुद्दा यह है: संशोधन शक्ति की सीमा क्या है

संविधान के अनुच्छेद 368 द्वारा प्रदत्त, इसके अलावा

संसद पर अनुच्छेद 13 (2)? 255

261. इससे यह पता चलता है कि जहां कोई बात 'महान' की है।

महत्व, यह न्यायालय इस मुद्दे को एक बड़ी पीठ को भेज सकता है

इस न्यायालय के पहले के निर्णय पर पुनर्विचार करना।

पैराग्राफ 10 [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

262. द्वितीय न्यायाधीशों के मामले में यह अवलोकन किया गया था कि

असाधारण रूप से मजबूर करने वाली परिस्थितियाँ इसकी पुष्टि करती हैं। यह था। यह देखा गया
कि 'ना' निर्णय से पूर्ण प्रतिरक्षा प्राप्त होती है

न्यायिक समीक्षा या नए दृष्टिकोण पर पुनर्विचार

संवैधानिक या कानूनी व्याख्या और के प्रकाश में नवीन विचारों, सिद्धांतों और धारणाओं का
विकास

समय के साथ बढ़ता गया। '256 याद करते हुए

मगनलाल छगनलाल, रघुबीर सिंह और

प्रदीप कुमार विश्वास ने कहा था कि:

" इसलिए, असाधारण और असाधारण रूप से सम्मोहक

परिस्थितियों या शर्तों के नए सेट के तहत, अदालत

एक नए दृष्टिकोण पर और विकास के प्रकाश में है
नवीन विचारों, सिद्धांतों और धारणाओं में वृद्धि

समय के साथ, कानूनी और द्वारा बाध्य
अपने पहले के निर्णय या निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए नैतिक ताकतें

और यदि आवश्यक हो तो इसे रद्द करने या उलटने के लिए भी
के सिद्धांत' के अनुप्रयोग द्वारा गलत निर्णय

व्याख्या जो संविधान या कानून ने प्राप्त की है
दशकों से यह मैदान आने वाले युगों तक रहेगा।

उस गलती को ठीक किए बिना। वास्तव में, कोई ऐतिहासिक नहीं

पूर्ववर्ती और दीर्घकालिक अभ्यास एक नियम प्रदान कर सकता है

अपरिवर्तनीय निर्णय "। 257

263. इसमें कोई विवाद या संदेह नहीं है कि यह न्यायालय

पहले दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार कर सकते हैं (और अलग कर सकते हैं)

इसके द्वारा। लेकिन कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिनके तहत
सकती है? इस न्यायालय ने बहस की है और

क्या पुनर्विचार की मांग की जा

ऊपर बताए गए कई मौकों पर इस मुद्दे पर चर्चा की गई

और व्यापक सिद्धांत जो विभिन्न से निकाले जा सकते हैं

निर्णय सुझाव देते हैं कि:

258 अनुच्छेद 17

257 पैराग्राफ 19 शीर्ष अदालतें-चालू-रिकॉर्ड संगठन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]
(1) यदि निर्णय की व्याख्या से संबंधित है

संविधान, शायद पुनर्विचार के लिए बाधा हो सकती है

थोड़ा कम किया (जैसा केशवानंद भारती में है)। हालांकि

संविधान में संशोधन का उपाय संसद के पास उपलब्ध है।

सभी संशोधनों को लागू करना आसान नहीं है। कुछ संशोधनों के लिए राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है।

फिर भी, जहां एक संवैधानिक मुद्दा शामिल है, पुनर्विचार की आवश्यकता को सभी से परे दिखाया जाना चाहिए

उचित संदेह, संविधान में संशोधन का उपाय

संसद के लिए हमेशा उपलब्ध रहना।

(2) यदि निर्णय कर लगाने से संबंधित है, तो

बार को भी थोड़ा कम किया जा सकता है क्योंकि कर का बोझ होगा

यह जनता के एक बड़े वर्ग को प्रभावित करता है। हालांकि, जनरल

पुनर्विचार की आवश्यकता के लिए सिद्धांत आवश्यक रूप से नहीं आते हैं

रास्ते में।

(3) यदि निर्णय मौलिक अधिकारों से संबंधित है

लोग, तब भी स्पष्ट कारणों से बार को कम किया जा सकता है।

हालांकि फिर से, आवश्यकता के लिए सामान्य सिद्धांत

पुनर्विचार का पालन किया जाना चाहिए।

(4) अन्य मामलों में, न्यायालय को आश्वस्त होना चाहिए कि

पहले का निर्णय स्पष्ट रूप से गलत है और इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है।

जनता पर; कि यह अस्पष्ट या असंगत या स्पष्ट रूप से है गलत है।

(5) यदि निर्णय केवल दो प्रतिद्वंद्वी निजी से संबंधित है

पक्ष या व्यक्ति, तो शायद यह उचित नहीं होगा

इस पर पुनर्विचार करें। कानून की प्रत्येक त्रुटि स्पष्ट रूप से नहीं हो सकती है।

इस न्यायालय द्वारा ठीक किया जाए।

(6) पुनर्विचार करने की शक्ति अप्रतिबंधित नहीं है या

असीमित, लेकिन संकीर्ण सीमाओं के भीतर सीमित है और होना चाहिए

कम और असाधारण परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है स्पष्ट और सम्मोहक कारण। इसलिए, केवल इसलिए कि एक दृष्टिकोण जो व्यक्त किया गया है उससे अलग या विपरीत है सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

पहले बेहतर है पहले पर पुनर्विचार करने का कोई कारण नहीं है निर्णय लें। इस न्यायालय का प्रयास हमेशा यह सुनिश्चित करने का होना चाहिए कि

कि कानून में निश्चित और निश्चित और निरंतरता है

कानून की व्याख्या बनी रहती है।

इस संबंध में रघुवीर सिंह एक दिलचस्प बात प्रस्तुत करते हैं।

चित्र। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 23 (2) 1984 में संशोधित) की व्याख्या इस न्यायालय द्वारा 14 तारीख को की गई थी

फरवरी, 1985 में के. कमलाजम्मन्नियावारु बनाम। विशेष।

भूमि अधिग्रहण अधिकारी। 258 उस फैसले को छह बार खारिज कर दिया गया था

16 मई, 1989 को रघुवीर सिंह और कानून को रद्द कर दिया गया। कमलाजम्मन्नियावारु में रखी गई बात को दोहराया गया। यह बात है।

अनिश्चित रूप से और कानून में निरंतरता का अभाव जो आवश्यक है

बचने के लिए।

(7) पहले के निर्णय पर पुनर्विचार किया जा सकता है यदि कोई सामग्री हो।

कानून के प्रावधान की अनदेखी की जाती है 260 या एक मौलिक धारणा गलत पाया जाता है या यदि वैध और बाध्यकारी या सम्मोहक कारण हैं या यदि मुद्दा मौलिक है

राष्ट्रीय जीवन का महत्व। हालाँकि, अगर लोगों ने अपनी स्थिति बदल ली है तो किसी निर्णय को रद्द करना बुद्धिमानी नहीं होगी।

मौजूदा कानून का आधार। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह परेशान कर सकता है

उन व्यक्तियों की वैध अपेक्षा जिन्होंने की है

पहले के निर्णय के आधार पर व्यवस्थाएँ और इसलिए भी कि

इस तरह के निर्णय के परिणाम पूर्वानुमेय नहीं हो सकते हैं।

(8) क्या कोई निर्णय लंबे समय तक मैदान में रहा है

या नहीं, इसका बहुत अधिक परिणाम नहीं होता है। बंगाल इम्युनिटी ए

संविधान पीठ द्वारा हाल ही में दिया गया निर्णय था
 खारिज कर दिया गया; प्रदीप कुमार विश्वास में एक निर्णय
 एक चौथाई सदी के लिए क्षेत्र को रद्द कर दिया गया था।

(9) उल्लेखनीय है कि इस न्यायालय ने इस पर ध्यान दिया है और

258 (1985) 1 एस. सी. सी. 582

259 (1985) 3 एससीसी 737

260 इसका पता कैसे लगाया जा सकता है?

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

इस दृष्टिकोण को मंजूरी दी कि बदलते समय की आवश्यकता हो सकती है

कानून की व्याख्या को ध्यान में रखते हुए पुनः समायोजित किया जाना चाहिए 'अनंत और
 परिवर्तनशील मानव इच्छाएँ और बदली हुई परिस्थितियाँ

'वर्षों की प्रगति के साथ विकास' के कारण। द.

एक पीढ़ी के लिए वैध कानून की व्याख्या नहीं हो सकती है यह आवश्यक रूप से आने वाली
 पीढ़ियों के लिए मान्य होगा। यह एक वास्तविकता है

जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए जैसा कि इस न्यायालय द्वारा किया गया है

मगनलाल छगनलाल और मुख्य न्यायाधीश डिकसन द्वारा द क्वीन बनाम में कनाडाई सर्वोच्च
 न्यायालय। ब्यूरगार्ड। 261

इसी तरह, सामाजिक संदर्भ या 'समकालीन सामाजिक स्थितियाँ'

या सार्वजनिक नीति की आधुनिक अवधारणाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

ओलिवर वेंडेल होम्स बाद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे काफी विनम्रता से रखा जब उन्होंने कहा कि: 'लेकिन द.

वर्तमान को जहाँ तक हो सके खुद पर शासन करने का अधिकार है और उसे ऐसा करना चाहिए।

हमेशा याद रखना चाहिए कि अतीत के साथ ऐतिहासिक निरंतरता

यह कोई कर्तव्य नहीं है, यह केवल एक आवश्यकता है। '262

264. यह सामान्य बात है कि संविधान एक जीवित दस्तावेज है 263

261 [1986] 2 एस. सी. आर. 56 में कहा गया है: इन तर्कों में से पहले के संबंध में, मुझे नहीं लगता कि एस। 100 [संविधान अधिनियम, 1867] संसद पर यह कर्तव्य अधिरोपित करता है कि वह न्यायाधीशों को ठीक उसी प्रकार के न्यायाधीश प्रदान करना जारी रखे। 1867 में उन्हें पेंशन मिली। कनाडा का संविधान 119 साल पुराने ताबूत में हमेशा के लिए बंद नहीं है। यह जीवित है और सांस लेता है और देश और उसके लोगों के विकास के साथ तालमेल रखने में सक्षम है। तदनुसार, यदि संविधान 1867 के हवाई जहाजों, परमाणु ऊर्जा, पनबिजली में अज्ञात कई विषयों को समायोजित कर सकता है, तो यह निश्चित रूप से तनावपूर्ण नहीं है। 100 यह कहने के लिए बहुत अधिक है कि 'पेंशन' शब्द, जिसे 1867 में एक अर्थ में समझा गया था, आज 'पेंशन' की एक अलग समझ के आधार पर संघीय कानून का समर्थन कर सकता है। 262 "कानून, जहाँ तक यह सीखने पर निर्भर करता है, वास्तव में, जैसा कि इसे कहा गया है, मृतकों द्वारा जीवित लोगों की सरकार है। काफी हद तक नहीं

सन्देह यह अपरिहार्य है कि जीवित लोगों को इस तरह से शासित किया जाना चाहिए। अतीत हमें हमारी शब्दावली देता है और हमारी कल्पना की सीमाओं को तय करता है; हम इससे दूर नहीं हो सकते। हम जो कर रहे हैं और जो पहले किया जा चुका है, उसके बीच निरंतरता को प्रकट करने में भी एक विशिष्ट तार्किक आनंद है। लेकिन वर्तमान को जहां तक हो सके खुद पर शासन करने का अधिकार है और यह हमेशा याद रखना चाहिए कि अतीत के साथ ऐतिहासिक निरंतरता एक कर्तव्य नहीं है, यह केवल एक आवश्यकता है।

"लर्निंग एंड साइंस", प्रोफेसर सी. सी. लैंगडेल (25 जून, 1895) के सम्मान में हार्वर्ड लॉ स्कूल एसोसिएशन के रात्रिभोज में भाषण।

ओलिवर वेंडेल होम्स के भाषणों में (1896)। पी। 67-68

263 आई. आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य, (2007) 2 एस. सी. सी. 1 पैरा 42 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

और यह याद रखना भी बुद्धिमानी है कि इस संदर्भ में क्या कहा गया था

आर. सी. पौड्याल बनाम भारत संघ 264 कि -

"एक संवैधानिक दस्तावेज की व्याख्या में, 'शब्द'

लेकिन अवधारणाओं और अवधारणाओं का ढांचा हो सकता है

स्वयं शब्दों से अधिक बदलते हैं। इसका महत्व अवधारणाओं का परिवर्तन स्वयं महत्वपूर्ण है और संवैधानिक मुद्दों को केवल अपील से हल नहीं किया जाता है

की स्वीकृति के बिना शब्दों का अर्थ

उनके विकास की रेखा। यह उचित रूप से कहा जाता है कि 'संविधान का उद्देश्य उत्कीर्ण करने के बजाय सिद्धांतों की रूपरेखा बनाना है

विवरण "। 265

265. इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के आधार पर

और पिछले छह वर्षों के ऐतिहासिक घटनाक्रमों पर विचार करते हुए दशकों से, यह विद्वान
अटॉर्नी-जनरल द्वारा प्रस्तुत किया गया था

यह एक मौलिक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि

संविधान की व्याख्या उत्पन्न हुई है; कि दूसरा

न्यायाधीशों का मामला और तीसरे न्यायाधीशों का मामला सही नहीं था

न्यायपालिका पर संविधान सभा की बहस की सराहना करें और कि अब पाठ्यक्रम में सुधार
करने का समय आ गया है।

प्रारंभिक मुद्दे पर निष्कर्ष

266. यह बिल्कुल स्पष्ट है कि शक्ति का वितरण है।

एक शास्त्रीय के बजाय नियंत्रण और संतुलन की एक प्रणाली के माध्यम से

विधायिका, कार्यपालिका के बीच शक्ति का पृथक्करण और न्यायपालिका। राज्य के ये तीन अंग एक
सिलो में नहीं हैं और इसलिए कभी-कभी ओवरलैप होता है-लेकिन हर

ओवरलैप आवश्यक रूप से उल्लंघन का कारण नहीं बनता है

शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत। 266

267. इस 'ओवरलैप' के कई उदाहरण हैं और

विद्वान अटॉर्नी-जनरल ने हमें विभिन्न मुद्दों के माध्यम से ले लिया है

264 1994 सप्लीमेंट (1) एससीसी 324

265 1994 सप. (1) एस. सी. सी. 324 पैरा 124।

256 अपने समापन भाषण में, बी. राजेंद्र प्रसाद ने 'शक्तियों का विभाजन' अभिव्यक्ति का उपयोग किया, न कि
'शक्तियों का पृथक्करण'। देखिए: एचटीटीपी: // भारत की संसद। ठीक है। /ls/डिबेट/वॉल्यूम 11p12 में।
एचटीएम

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

इस संबंध में संविधान के प्रावधान: संविधान का अनुच्छेद 124 (1) संसद को निर्धारित करने वाला कानून
पारित करने में सक्षम बनाता है।

उच्चतम न्यायालय की संरचना जिसमें अधिक शामिल हैं

सात न्यायाधीशों से अधिक। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने

(न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 पारित किया गया था; अनुच्छेद 124 (4)

एक को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया का प्रावधान करता है

न्यायाधीश; अनुच्छेद 124 (5) संसद को इसके लिए कानून बनाने में सक्षम बनाता है

पते की प्रस्तुति के लिए प्रक्रिया को विनियमित करना

महाभियोग प्रक्रिया और जांच और सबूत में

न्यायाधीश के दुर्यवहार या अक्षमता; अनुच्छेद 125 (1)

संसद को कानून द्वारा न्यायाधीश का वेतन निर्धारित करने में सक्षम बनाता है जबकि अनुच्छेद 125 (2) संसद को न्यायाधीश का वेतन निर्धारित करने के लिए कानून पारित करने में सक्षम बनाता है।

न्यायाधीश के विशेषाधिकारों, भत्तों आदि के संबंध में। अनुसरण में

इसके लिए उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम,

1958 अधिनियमित किया गया है; अनुच्छेद 134 (2) संसद को कानून द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को और अधिक शक्तियां प्रदान करने में सक्षम बनाता है अपीलों और आपराधिक कार्यवाहियों पर विचार करें और सुनें। अनुसरण में

इसके लिए संसद ने उच्चतम न्यायालय को अधिनियमित किया है

(आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार) अधिनियम, 1970; अनुच्छेद 135 संसद को इस संबंध में कानून बनाने में सक्षम बनाता है -

संबंध में उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता और शक्ति

किसी भी मामले में जिसके लिए अनुच्छेद 133 और अनुच्छेद के प्रावधान

134 लागू नहीं होता; अनुच्छेद 137 में यह प्रावधान है कि यह किसी भी कानून के अधीन है

संसद द्वारा बनाई गई सर्वोच्च न्यायालय के पास शक्ति होगी

उसके द्वारा घोषित किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने के लिए; अनुच्छेद 138 संसद को कानून द्वारा इसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने में सक्षम बनाता है। उच्चतम न्यायालय किसी भी मामले के संबंध में

भारत सरकार और किसी भी राज्य की सरकार द्वारा

विशेष समझौता और अनुच्छेद 139 संसद को सक्षम बनाता है

में उल्लिखित रिटों के अलावा अन्य रिट जारी करने के लिए कानून बनाना।

संविधान का अनुच्छेद 32; अनुच्छेद 140 संसद को सक्षम बनाता है। उच्चतम न्यायालय को पूरक शक्तियां प्रदान करने वाला कानून बनाना; अनुच्छेद 142 संसद को सक्षम बनाता है -

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर. के आदेश या आदेश को लागू करने के लिए कानून बनाएँ।

सर्वोच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शक्ति का प्रयोग
भी आदेश देने के लिए न्यायालय

सुरक्षित करने के उद्देश्य से कोई

किसी व्यक्ति की उपस्थिति, किसी की खोज या उत्पादन

दस्तावेज़, या किसी भी अवमानना की जांच या सजा, अनुच्छेद 145 संसद को विनियमन के लिए कोई भी
कानून बनाने में सक्षम बनाता है।

उच्चतम न्यायालय का अभ्यास और प्रक्रिया जबकि अनुच्छेद

146 (2) संसद को शर्तें निर्धारित करने में सक्षम बनाता है -

उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की सेवा। लेख

130 संविधान सर्वोच्च न्यायालय को बैठने की अनुमति देता है
अलावा कोई भी स्थान

राष्ट्रपति के अनुमोदन से दिल्ली के

जबकि अनुच्छेद 145 उच्चतम न्यायालय को नियम बनाने में सक्षम बनाता है।

न्यायालय के व्यवहार और प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए

राष्ट्रपति की मंजूरी।

268. काफी स्पष्ट रूप से संसद की एक पूरी मेजबानी है

और न्यायपालिका पर विधायी जाँच की जाती है जिसके द्वारा

आवश्यक रूप से शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करते हैं
स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है जहाँ तक निर्णय की बात है।

या न्यायपालिका की

बनाना चिंता का विषय है। जैसा कि बार-बार माना गया है, सिद्धांत

शक्तियों के पृथक्करण को हमारे देश में सख्ती से लागू नहीं किया गया है।
एक चेक के रूप में एक ओवरलैप है

संविधान, लेकिन अगर

राज्य के एक अंग के किसी आवश्यक या मूल कार्य या तत्व के संदर्भ में, दूसरे के विपरीत, एक संवैधानिक मुद्दा
उठती है। यह इस संदर्भ में है कि 99 वां संविधान

संशोधन अधिनियम को देखा जाना चाहिए-क्या यह एक पर प्रभाव डालता है

स्वतंत्रता का मूल या एक आवश्यक तत्व

न्यायपालिका, अर्थात्, इसकी निर्णयात्मक स्वतंत्रता।

269. विद्वान महान्यायवादी अपने बारे में सही नहीं है प्रस्तुत करना कि दूसरे न्यायाधीशों के मामले ने अनदेखी की शक्तियों और सीएडी का पृथक्करण और गलत तरीके से व्याख्या संविधान के प्रावधान विशेष रूप से अनुच्छेद 124 (2) वहाँ से। यह दूसरी की एक संकीर्ण समझ है। न्यायाधीशों का मामला, जिस पर, अन्य बातों के अलावा, विचार किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

संविधान के अनुच्छेद 50 की व्याख्या, संवैधानिक इतिहास और सम्मेलन, संबंधित मुद्दों के पूरे स्पेक्ट्रम

न्यायपालिका की स्वतंत्रता, पारदर्शिता और सूचना साझा करने के संदर्भ में न्यायाधीशों की नियुक्ति करना।

संवैधानिक प्राधिकारियों के बीच, नियुक्ति प्रक्रिया में राष्ट्रपति या न्यायपालिका की प्रधानता (परिस्थितियों के आधार पर), का महत्व

से व्युत्पन्न एकीकृत परामर्श प्रक्रिया में राष्ट्रपति

संविधान सभा में बहस और कई अन्य

संबंधित पहलू। इन सब में एक व्यावहारिक और व्यवहार्य शामिल था। संविधान की व्याख्या, जो केवल का कार्य है

न्यायपालिका और इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है। यह छलावा था।

मार्बरी वी में कहा गया है। मैडिसन 2 67: 'यह दृढ़ता से है कि

न्यायिक विभाग का प्रांत और कर्तव्य है कि वह क्या कहे

कानून है '। यह स्पष्ट रूप से री में भी आयोजित किया गया था: शक्तियाँ, विशेषाधिकार

और राज्य विधानमंडलों की छूट 268 जहाँ यह कहा गया था:

"[डब्ल्यू/ हेदर हो या न हो, इसका विशिष्ट और कठोर पृथक्करण है

भारतीय संविधान के तहत शक्तियाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है

कि संविधान ने न्यायपालिका को सौंपा है
इस देश के प्रावधानों को समझने का कार्य

संविधान और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। जब किसी क़ानून को ज़मीन पर
चुनौती दी जाती है

कि यह बिना किसी अधिकार के विधायिका द्वारा पारित किया गया है,

या अन्यथा असंवैधानिक रूप से अतिक्रमण किया है

मौलिक अधिकार, यह अदालतों को निर्धारित करना है

विवाद करें और तय करें कि क्या क़ानून द्वारा पारित किया गया है
विधायिका वैध है या नहीं। जैसे विधायिकाएँ हैं

विधायी प्राधिकरण और उनके कार्य प्रदान किए गए हैं
आम तौर पर विधायी कार्यों तक सीमित, और

कार्यपालिका के कार्य और अधिकार इसके अंतर्गत आते हैं -

कार्यपालक प्राधिकारी का क्षेत्र, इसलिए अधिकारिता और

इस देश में न्यायपालिका का अधिकार इसके भीतर है -

287 5 अमेरिका (1 शाखा) 137,177 (1803)

268 [1965] 1 एससीआर 413 (सात न्यायाधीशों की पीठ)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

न्यायनिर्णयन का क्षेत्र। यदि किसी क़ानून की वैधता है
अदालतों के समक्ष चुनौती दी गई, यह कभी सुझाव नहीं दिया जाता है कि

इस बारे में भौतिक प्रश्न कि क्या विधायी प्राधिकरण

अतिक्रमण किया गया है या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, विधायिका द्वारा तय किया
जा सकता है

स्वयं "। 269

270. विद्वान महान्यायवादी भी सही नहीं है

दूसरे न्यायाधीशों के मामले को केवल एक पहलू तक कम करना -

इस न्यायालय के निर्णय की एक भाग के रूप में सराहना की जानी चाहिए
बड़ी संवैधानिक योजना

की स्वतंत्रता से संबंधित

न्यायपालिका। विद्वान महान्यायवादी हो भी सकता है और नहीं भी।

इस न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या से सहमत हैं संवैधानिक योजना लेकिन यह कोई संकेत नहीं है कि सिद्धांत

शक्तियों का पृथक्करण टूट गया है। अगर कोई व्याख्यात्मक त्रुटि, इसे केवल न्यायपालिका द्वारा ही ठीक किया जा सकता है,

या संविधान में किसी उपयुक्त संशोधन द्वारा जो नहीं करता है इसकी मूल संरचना का उल्लंघन करता है।

271. किसी ने नहीं सोचा था कि इस न्यायालय ने, दूसरे न्यायाधीशों के मामले में, गलत तरीके से व्याख्या या गलत समझा था

की नियुक्ति से संबंधित संवैधानिक योजना न्यायाधीशों और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। वहाँ कुछ थे समस्या क्षेत्रों और इन्हें इस न्यायालय में भेजा गया था

राष्ट्रपति द्वारा सलाहकार की मांग करते हुए उठाए गए प्रश्नों का रूप

तीसरे न्यायाधीशों के मामले में इस न्यायालय की राय। द.

द्वितीय न्यायाधीशों में दिए गए निर्णय की शुद्धता मामला संदेह में नहीं था और किसी भी गलतफहमी को दूर करने के लिए

इस संबंध में विद्वान महान्यायवादी ने स्पष्ट रूप से कहा

तीसरे न्यायाधीशों के मामले में कि 'भारत संघ मांग नहीं कर रहा है

दूसरे में निर्णय की समीक्षा या पुनर्विचार

न्यायाधीशों का मामला। 'इसलिए, न तो राष्ट्रपति और न ही संघ भारत से और न ही उस मामले के लिए किसी और ने एक

द्वितीय न्यायाधीशों के मामले पर पुनर्विचार। वहाँ कोई नहीं है

289 पृष्ठ 446 सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकर, जे.]

कारण (कानून में एक कारण की अनुपस्थिति के अलावा) ऐसा क्यों है

भारत संघ द्वारा कानून की काल्पनिक गलतफहमी को छोड़कर, इस स्तर पर अनुरोध पर विचार किया जाना चाहिए।

272. विद्वान महान्यायवादी का तर्क है -

कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति या

उच्च न्यायालय एक कार्यकारी कार्य है और इसे लिया गया है।

न्यायिक अतिक्रमण की प्रक्रिया द्वारा न्यायपालिका द्वारा

एक 'आग्रह करने के अधिकार' के माध्यम से जिससे अलगाव टूट जाता है

शक्ति सिद्धांत। इस विचार को स्वीकार करना संभव नहीं है।

न्यायाधीश की नियुक्ति एक कार्यकारी कार्य है राष्ट्रपति और यह ऐसा ही बना हुआ है। लेकिन संवैधानिक

स्वतंत्रता से पहले भी स्थापित किया गया है

कि एक न्यायाधीश की नियुक्ति केवल तभी की जाती है जब भारत का मुख्य न्यायाधीश या

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति के लिए अपनी मंजूरी देते हैं। इसके बाद भी यह स्थिति बनी रही।

स्वतंत्रता। न्यायमूर्ति कुलदिप सिंह ने संक्षेप में कहा कि द्वितीय न्यायाधीशों के मामले में नियुक्तियों की स्थिति

निम्नलिखित शब्द:

" (i) कार्यपालिका को नियुक्त करने की पूर्ण शक्ति थी।

भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत न्यायाधीश।

इसके बावजूद इसके तहत की गई सभी नियुक्तियां थीं भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से किया गया।

(ii) वर्ष तक एक सम्मेलन स्थापित हो गया था।

1948 कि न्यायाधीश की नियुक्ति केवल की जा सकती थी

भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से।

(iii) 1950 से सर्वोच्च न्यायालय में सभी नियुक्तियाँ।

1959 तक प्रमुख की सहमति से बनाया गया था

भारत का न्याय। 210 211 नियुक्तियों में से

उस अवधि के दौरान उच्च न्यायालय भी थे

(iv) श्री गोविंद वल्लभ पंत, भारत के गृह मंत्री, 24 नवंबर को संसद के पटल पर घोषित किया गया, • सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

1959 कि न्यायाधीशों की नियुक्ति वस्तुतः की जा रही थी

भारत के मुख्य न्यायाधीश और कार्यपालिका द्वारा बनाया गया था

केवल एक आदेश जारी करने वाला प्राधिकारी।

(v) श्री अशोक सेन, कानून मंत्री ने दोहराया

25 नवंबर, 1959 को संसद ने कहा कि लगभग सभी

मुख्य न्यायाधीश की सहमति से न्यायालय बनाए गए थे।
भारत का न्याय।

(iv) न्यायाधीशों की 547 नियुक्तियों में से

भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के अनुरूप। 270
273. ये तथ्य और आंकड़े स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि कम से कम

1935 से, यदि पहले नहीं, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी

भारत के मुख्य न्यायाधीश के दृष्टिकोण के अनुसार या

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जैसा भी मामला हो। वहाँ

विचलन थे लेकिन ये मुख्य रूप से हुए प्रतीत होते हैं

स्वतंत्रता के बाद ही, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। लेकिन इसमें भी

उन मामलों में जहां 1959 से पहले विचलन थे (उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पारित किए जाने के साथ)

भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति ली गई। द. कार्यकारी, इसलिए, के मामले में कभी भी
वास्तविक प्रधानता नहीं थी

न्यायाधीशों की नियुक्ति। लेकिन, प्रथम न्यायाधीशों के मामले के बाद

कार्यपालिका ने अपनी नई दी गई पूर्ण प्रधानता का प्रयोग किया

न्यायाधीशों की नियुक्ति और विचलन बढ़े। निश्चित रूप से,

कार्यपालिका अपने कहने पर हुए विचलन का लाभ नहीं उठा सकती है और फिर उन्हें एक तर्क के रूप में
नियोजित नहीं कर सकती है कि नहीं

सहमति के संबंध में संवैधानिक सम्मेलन मौजूद था

भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसके विपरीत, विसंगतियाँ
इंगित करें

राजनीतिक कार्यपालिका के गुप्त प्रयास को

नियुक्तियों के माध्यम से न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो आवश्यक रूप से योग्यता-आधारित नहीं थी, और
प्रस्तुतियाँ

270 अनुच्छेद 371।

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

हमारे सामने आगे बढ़ने से पता चलता है कि अब से स्वतंत्रता
न्यायपालिका आवश्यक रूप से पवित्र नहीं हो सकती है। इसके लिए
कारण यह है कि बार ने संरक्षण और सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ी है
मौजूदा सम्मेलनों और प्रथाओं और इच्छाशक्ति, उम्मीद है कि अपनी सतर्कता बनाए रखेगी।

274. पॉकेट वीटो मामले 271 में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय

एक व्याख्या के रूप में एक लंबे समय से चली आ रही प्रथा को संदर्भित किया जाता है
संवैधानिक प्रावधान, जो समान रूप से लागू होगा

भारत। कहा गया था:

"जिन विचारों को हमने व्यक्त किया है
यहाँ संवैधानिक प्रावधान का निर्माण और प्रभाव

प्रश्न में व्यावहारिक निर्माण द्वारा पुष्टि की जाती है

जो इसे राष्ट्रपतियों द्वारा लंबे समय से दिया गया है

वर्षों के दौरान, जिसमें कांग्रेस ने सहमति व्यक्त की है।
लंबे समय से स्थापित और स्थापित अभ्यास संवैधानिक की उचित व्याख्या में बहुत महत्वपूर्ण है।

इस चरित्र के प्रावधान। मिसौरी पैक की तुलना करें। राइ।

को. वी. कैनसस 272; मायर्स बनाम। संयुक्त राज्य अमेरिका 273; और राज्य बनाम।
दक्षिण नॉरवॉक 274 जिसमें अदालत ने कहा कि एक अभ्यास

की ओर से कम से कम बीस साल की अवधि
कार्यकारी विभाग, विधायिका द्वारा स्वीकृत

विभाग, जबकि न्यायिक पर पूरी तरह से बाध्यकारी नहीं है

विभाग, निर्धारित करने में बहुत सम्मान का हकदार है

एक संवैधानिक प्रावधान का वास्तविक निर्माण

जिसका वाक्यांश किसी भी मामले में संदिग्ध है।

जिसका अर्थ है "।

275. पूर्ण कार्यकारी प्रधानता का दावा करके, विद्वान

महान्यायवादी वास्तव में इस दृष्टिकोण का प्रचार कर रहा है कि

राष्ट्रपति को नियुक्त करने के प्रस्ताव पर वीटो का प्रयोग कर सकते हैं

न्यायाधीश, भले ही उस प्रस्ताव को अन्य सभी की मंजूरी हो

272 248 अमेरिका 276

273 272 अमेरिका 52

274 77 कॉन।

257 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

संवैधानिक प्राधिकारी। इस तरह का दृष्टिकोण स्वीकार्य नहीं था

डॉ. अम्बेडकर और संविधान सभा और इसे पिछले दरवाजे से पेश करने की अनुमति नहीं है। मुखिया।

भारत के न्यायाधीश को नियुक्ति पर 'जोर देने' का कोई अधिकार नहीं है और न ही

क्या राष्ट्रपति को अस्वीकार करने या वीटो करने का अधिकार है? द.

संविधान में परामर्श और भागीदारी की बात कही गई है।

नियुक्ति के लिए संवैधानिक

अधिकारियों के बीच प्रक्रिया

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 'सर्वश्रेष्ठ' संभावित व्यक्ति या

सुप्रीम कोर्ट। इस परामर्श प्रक्रिया में अंतिम शब्द है -

दिए गए, एक संवैधानिक सम्मेलन और विकसित अभ्यास द्वारा

वर्षों से, तब से भारत के मुख्य न्यायाधीश को

प्रभावी न्याय वितरण की आवश्यकताएँ,

न्यायपालिका की स्वतंत्रता, बाहरी को दूर रखने के लिए

प्रभाव, 'के स्तर पर भी राजनीतिक प्रभाव को समाप्त करें

न्यायाधीश '275 की प्रारंभिक नियुक्ति और इसके प्रमुख के रूप में

न्यायपालिका, उसके फैसले पर इस संबंध में भरोसा किया जाना चाहिए।

यह कि इसे 'आग्रह करने के अधिकार' के रूप में वर्णित किया जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं है।

न्यायसंगत, और न ही कार्यपालिका द्वारा असहमति की कोई आवाज हो सकती है

संवैधानिक योजना या जिम्मेदारियों के साथ तालमेल न रखें।

संवैधानिक कार्यकर्ताओं का।

276. दूसरे न्यायाधीशों के मामले और तीसरे ने क्या किया?

न्यायाधीशों का मामला तय करता है कि राजनीतिक कार्यपालिका का नेतृत्व किसे करना चाहिए

व्यक्त किए गए विचारों को गलत समझने और गलत समझने के लिए

कानून की व्याख्या या निर्धारित कानून पर पुनर्विचार करने का आह्वान
कुछ भी तय किया गया वह यह था कि प्रमुख

नीचे? संक्षेप में, जो

भारत के न्यायाधीश (व्यक्तिगत क्षमता में) न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की सिफारिश नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्हें ऐसा करना चाहिए

अन्य न्यायाधीशों के साथ परामर्श (और यदि आवश्यक हो तो गैर न्यायाधीशों के साथ)

न्यायाधीश)। भारत के मुख्य न्यायाधीश की ऐसी सिफारिश,

यदि सर्वसम्मति से किया जाता है, तो सामान्य रूप से द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए
राष्ट्रपति। हालांकि, राष्ट्रपति वापस कर सकते हैं

275 न्यायाधीशों का दूसरा मामला, पैराग्राफ 450 सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन
v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, एक सिफारिश
बनाया गया, जो शुरू में नहीं है

भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा

सर्वसम्मति, राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जैसा कि बताया गया है।

अज्ञात के लिए इस विशेष संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करें
गलतफहमी के कारण

कारण या निर्धारित डिक्टा की

इस न्यायालय द्वारा। इस न्यायालय द्वारा अपनाया गया मार्ग अनुरूप था।

संविधान सभा के विचारों के साथ, कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में, कोई भी संवैधानिक पदाधिकारी कार्य नहीं कर सकता था
व्यक्तिगत क्षमता में लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को सही सलाह देने के लिए अच्छी तरह से योग्य थे

राष्ट्रपति इस प्रकार के मामले में, और इसे स्वीकार किया जाना चाहिए था।

जब तक यह सर्वसम्मत

277. 24 मई, 1949 को हुई बहस से पता चलता है कि

संविधान के समक्ष विभिन्न विकल्प उपलब्ध थे

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में विधानसभा।

278. उपलब्ध तरीकों में से एक था राज्य परिषद द्वारा अनुमोदित न्यायाधीश की नियुक्ति। यह

श्री आर. के. सिधवा (सी. पी. और बेरार: जनरल) कौन यह राय थी कि यदि नियुक्ति परिषद पर छोड़ दी जाती है

न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अनुशंसित व्यक्ति की क्षमता आदि का मुद्दा प्रासंगिक नहीं रहेगा। श्री सिधवा यह राय थी कि यह विधि एक के समान होगी

चुनाव, हालांकि प्रो। के. टी. शाह ने कुछ और ही सोचा। द.

श्री विश्वनाथ दास (उड़ीसा) ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया।

जनरल) जिन्होंने नियुक्ति की इस विधि को विद्वानों के रूप में संदर्भित किया

एक बहुत ही खतरनाक सिद्धांत।

279. नियुक्ति का एक अन्य तरीका [2015] 13 एस. सी. आर. था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रक्रिया को पूरी तरह से राष्ट्रपति पर छोड़ दें। श्री रोहिणी कुमार

चौधरी (असम: जनरल) ने स्पष्ट रूप से इस दृष्टिकोण का समर्थन किया।

और सुझाव दिया कि डॉ द्वारा प्रस्तावित संशोधन।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ राष्ट्रपति द्वारा परामर्श को हटाने के लिए अम्बेडकर को

स्वीकार कर लिया। उनकी राय थी कि मामला होना चाहिए

केवल राष्ट्रपति द्वारा निपटा जाता है जो किसी से भी परामर्श कर सकता है, केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ही क्यों। अगर

राष्ट्रपति एक व्यक्ति को उत्कृष्ट क्षमता के रूप में जानते थे, यह

हो सकता है कि उसके लिए किसी से परामर्श करने की आवश्यकता न हो

नियुक्ति करना। इस दृष्टिकोण का समर्थन श्री एम.

अनंतसायनम अय्यंगार (मद्रास: जनरल) जिन्होंने भी महसूस किया

कि यह राष्ट्रपति पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि वह यह तय करे कि किससे परामर्श करना है,

यदि आवश्यक हो।

280. नियुक्ति का एक और तरीका अंग्रेजों का था।

प्रणाली जहाँ नियुक्तियाँ क्राउन द्वारा की जाती थीं

किसी भी प्रकार की सीमा, जो भी हो, यानी राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा। चर्चा की गई एक चौथी विधि यह थी कि

संयुक्त राज्य जहाँ नियुक्तियाँ की गई थीं

सीनेट की सहमति।

281. डॉ. अम्बेडकर का विचार था कि इनमें से कोई भी

प्रस्तावित विधियाँ विभिन्न कारणों से उपयुक्त थीं और

इसलिए एक बीच का रास्ता अपनाया गया जिसके लिए राष्ट्रपति की आवश्यकता थी

भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करना। डॉ.

अम्बेडकर ने महसूस किया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श

और अन्य न्यायाधीश आवश्यक थे क्योंकि वे पूर्व परिकल्पना थे

इस प्रकृति के मामले में सलाह देने के लिए अच्छी तरह से योग्य।

282. भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश हैं -

निस्संदेह किसी व्यक्ति के ज्ञान, क्षमता, क्षमता और उपयुक्तता के संबंध में उचित सलाह देने के लिए अच्छी तरह से योग्य

उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाना। इसलिए इस राय का कोई कारण नहीं है कि

भारत के मुख्य न्यायाधीश को अन्य सर्वोच्च न्यायालयों की राय के साथ लिया गया-ऑन-रिकॉर्ड

न्यायाधीशों को कार्यपालिका द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, जो है

निश्चित रूप से इसमें मूल्यांकन करने के लिए बेहतर योग्य नहीं है।

विशेष व्यक्ति जो मुख्य न्यायाधीश को ज्ञात नहीं हो सकता है
हिमतलाल सेठ में प्रतिपादित किया गया है

भारत का और जैसा कि संकल्पचंद्र

और दूसरे न्यायाधीशों के मामले में पूरी सामग्री होनी चाहिए
उपलब्ध कराया गया और उसे /

भारत के मुख्य न्यायाधीश को

उसे यह तय करने के लिए कि क्या उस व्यक्ति ने सिफारिश की है

नियुक्ति एक नियुक्त होने की आवश्यकता को पूरा करती है

न्यायाधीश या नहीं, किसी भी पूर्ववृत्त, विशिष्टताओं के बावजूद और

कोणीयताएँ। यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य जिनके साथ

उसने मामले पर चर्चा की है-सर्वसम्मति से - कि व्यक्ति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में
नियुक्त किया जाना चाहिए

पूर्ववृत्तियों के बावजूद न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, विशिष्टताएँ और कोणीयताएँ, कोई सांसारिक
कारण नहीं हो सकता है

उस सामूहिक दृष्टिकोण को क्यों स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। मुखिया।

न्यायपालिका संबंधित है और उसकी राय (प्राप्त) सामूहिक रूप से और सर्वसम्मति से) स्वीकार किया
जाना चाहिए

किसी ऐसे व्यक्ति की राय जो एक यात्री है (हालांकि एक

महत्वपूर्ण एक) जहाज में। डॉ. अम्बेडकर की पुष्टि की गई थी

विचार है कि न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए

और यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश का अंतिम कहना नहीं है

मामला तब न्यायपालिका, एक अर्थ में, किसी अन्य के अधीन है

प्राधिकरण और इसलिए उस हद तक स्वतंत्र नहीं है। यह

डॉ. अम्बेडकर के विचारों की अस्वीकृति होगी और

संविधान सभा के विचारों का खंडन।

283. संविधान सभा की बहसों से यह है

यह स्पष्ट है कि डॉ. अम्बेडकर की आपत्ति इस सुझाव पर थी

कि केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश (एक व्यक्ति के रूप में) को

इस मामले में अंतिम निर्णय लें। सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं है
कि संविधान सभा को कोई आपत्ति थी
एकीकृत परामर्शी भागीदारी प्रक्रिया जैसा कि [2015] 13 एस. सी. आर. में उल्लिखित है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

द्वितीय न्यायाधीशों का मामला और तृतीय न्यायाधीशों का मामला या

डॉ. राजीव धवन ने इसे 'संस्थागत भागीदारी' बताया।

न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में। आपत्ति केवल एक व्यक्ति (राष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश) पर थी।

इस मामले में अंतिम निर्णय लेना और यह कि एक व्यक्ति (भारत का मुख्य न्यायाधीश) संभवतः समान कमजोरियों से पीड़ित हो सकता है

हम में से किसी के रूप में और यही डॉ. अम्बेडकर चाहते थे

अपनी आपत्ति पर जोर दें। यह सराहना की जानी चाहिए कि जब

बहस हुई (24 मई, 1949 को) न्यायाधीशों की नियुक्ति, संविधान के अनुच्छेद 62 में खंड (5) ए के सम्मिलन के कारण हुई थी।

प्रारूप संविधान 276 की जिम्मेदारी मानी जाती है

राष्ट्रपति अपने दम पर कार्य करता है न कि मंत्रिपरिषद के माध्यम से। कि यह सिद्धांत दिए जाने की प्रक्रिया में था

ऊपर (और वास्तव में छोड़ दिया गया था) पूरी तरह से एक अलग मामला है।

वैकल्पिक रूप से, यदि उस समय की सोच यह थी कि राष्ट्रपति

केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना था (और नहीं

एक अनियंत्रित विवेक वाले व्यक्ति के रूप में) आज हो सकता है
न्यायाधीश के कार्य करने पर कोई आपत्ति नहीं होगी

संभवतः भारत के मुख्य

डॉ. अम्बेडकर द्वारा एक व्यक्ति के रूप में बांछित। दूसरे शब्दों में,
रहा है।

भारत में संविधानवाद सकारात्मक

परिवर्तन और डॉ. अम्बेडकर की आपत्ति

अंतिम कहने वाले व्यक्ति को गैर-अस्तित्व में प्रस्तुत किया जाता है। नज़र में

समशेर सिंह के राष्ट्रपति एक व्यक्ति में कार्य नहीं कर सकते हैं

क्षमता (सीमित सीमा को छोड़कर) और दूसरे को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीशों के मामले और तीसरे न्यायाधीशों के मामले में मुख्य न्यायाधीश

भारत का एक व्यक्तिगत क्षमता में कार्य नहीं कर सकता है (सीमित क्षमता को छोड़कर)

सीमा)। संविधान एक जैविक और जीवित दस्तावेज है

सकारात्मक और सार्थक रूप से व्याख्या की जानी चाहिए और की गई है।

278 अनुच्छेद 62 का खंड 5 (ए) कहता है:

"(5) क अपने मंत्रियों के चयन और इस संविधान के तहत अपने अन्य कार्यों के प्रयोग में, राष्ट्रपति आम तौर पर

अनुसूची III-ए में दिए गए निर्देश, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा किए गए किसी भी कार्य की वैधता पर इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा कि वह किया गया था

अन्यथा इस तरह के निर्देशों के अनुसार "।

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

284. यह दर्शन है, संविधान का एक

जैविक और जीवित दस्तावेज जो सकारात्मक होना चाहिए और सार्थक रूप से व्याख्या की गई, जो समशेर सिंह में पाई जाती है।

सी. ए. डी. के साथ पढ़ी जाने वाली यह रचनात्मक व्याख्या है जिसने

राष्ट्रपति पर बाध्यकारी मंत्रिपरिषद की सलाह

और 'इसे ले लो या छोड़ दो' की सलाह नहीं। इसी तरह, 'परामर्श'

भारत के मुख्य न्यायाधीश को इस संदर्भ में समझना होगा।

और 'परामर्श और अस्वीकृत राय' की स्थिति के रूप में नहीं।

285. यह सुझाव देना सही नहीं है, जैसा कि विद्वान ने किया था

संविधान को दी गई व्याख्या द्वारा टारपीडो किया गया है द्वितीय न्यायाधीशों में संविधान के अनुच्छेद 124 (2)

मामला। इसके विपरीत, संवैधानिक परंपरा, संवैधानिक योजना और संवैधानिक प्रथा को मान्यता दी जाती है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायपालिका की जिम्मेदारी

और इसे केवल दूसरे न्यायाधीशों के मामले में औपचारिक रूप दिया गया था।

शक्तियों के पृथक्करण या वितरण का सिद्धांत

इसके बजाय दूसरे न्यायाधीशों के मामले द्वारा शक्तियों को बनाए रखा गया था

ऊपर फेंकने की तुलना में। जस्टिस जैक्सन को फिर से लिखने के लिए

सायर 277 संविधान इसकी शाखाओं पर आदेश देता है। 'अलगाव लेकिन परस्पर निर्भरता, स्वायत्तता लेकिन पारस्परिकता '

और दूसरे न्यायाधीशों के मामले ने इसे प्रभावी ढंग से बनाए रखा है

न्यायपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका के बीच संतुलन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए, जिसमें

न्यायाधीशों की नियुक्ति।

286. इन सभी कारकों और सीएडी को ध्यान में रखते हुए,

जिन सभी पर दूसरे न्यायाधीशों के मामले में चर्चा की गई थी

विद्वान महान्यायवादी के तर्क को स्वीकार करना मुश्किल है

कि दूसरे न्यायाधीशों के मामले पर पुनर्विचार की आवश्यकता है गुण। जबकि संदर्भित विभिन्न निर्णयों से निपटा गया

इस न्यायालय के पूर्व निर्णय पर पुनर्विचार का मुद्दा, यह

277 343 अमेरिका 579,635 (1952)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल है कि 9 में से 8 द्वारा दिया गया निर्णय

दूसरे न्यायाधीशों के मामले का फैसला करने वाले न्यायाधीश (न्याय)

भारत) को केवल इसलिए अस्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि एक हो सकता है राय में परिवर्तन या परिस्थितियों में परिवर्तन। द सेकंड

न्यायाधीशों के मामले को महान्यायवादी द्वारा स्वीकार किया गया था

तीसरे न्यायाधीशों के मामले में और द्वारा भी उल्लिखित राष्ट्रपति जिन्होंने इस बारे में कोई सवाल नहीं उठाया

संविधान के अनुच्छेद 124 (2) और अनुच्छेद 217 (1) को दी गई व्याख्या। इन संवैधानिक अधिकारियों ने स्वीकार किया है

दूसरे न्यायाधीशों के मामले में निर्धारित कानून, नहीं है
मानदंडों पर उस निर्णय पर पुनर्विचार करने का कारण
न्यायालय द्वारा बार-बार निर्धारित किया गया। कोई अपवाद नहीं है
परिस्थितियाँ, स्पष्ट और सम्मोहक कारण
पुनर्विचार, और न ही यह कहा जा सकता है कि द्वितीय न्यायाधीश
मामला स्पष्ट रूप से गलत था या कि इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है
जनता को। इसके विपरीत, निर्णय ने पुनर्स्थापित किया
न्यायपालिका की वास्तविक रूप से स्वतंत्रता और समाप्त कार्यकारी नियंत्रणों का हानिकारक
प्रभाव।

287. यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि यह स्पष्ट रूप से था
समशेर सिंह में निर्धारित किया गया है कि मामलों में अंतिम शब्द न्यायपालिका से संबंधित
मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास होना चाहिए।
समशेर सिंह का फैसला सात विद्वानों की पीठ ने किया था।
न्यायाधीशों और किसी ने नहीं कहा है कि उस निर्णय की आवश्यकता है
पुनर्विचार या कि यह सही कानून निर्धारित नहीं करता है। दूसरे न्यायाधीशों का मामला केवल
'अंतिम शब्द' को दोहराता है।
सीमित अर्थों में देखें।

288. बोर्ड भर में राय की सर्वसम्मति बिल्कुल स्पष्ट है कि दूसरे न्यायाधीशों के मामले का सही निर्णय लिया
गया है और यह कि उस में निर्धारित सम्मेलन और सिद्धांत
यह हमारे संवैधानिक इतिहास से आता है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।
पुनर्विचार।

289. इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे न्यायाधीशों का मामला सर्वोच्च अदालतों में दर्ज किया जाता
है।

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. /मदन बी. लोकुर, जे./

और तीसरे न्यायाधीशों का मामला कोई अंतराल नहीं छोड़ता है। शायद इन निर्णयों में निर्धारित योजना के बेहतर संस्थागतकरण और ठीक ट्यूनिंग की आवश्यकता है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन, इसमें

विद्वान महान्यायवादी द्वारा की गई प्रस्तुति का दृष्टिकोण कि विचार के लिए एकमात्र सवाल संवैधानिक है

99 वें संविधान संशोधन अधिनियम और एन. जे. ए. सी. की वैधता अधिनियम पुनर्विचार का मुद्दा अकादमिक हो जाता है और यह है

वर्तमान में आगे कोई विचार व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है।

यह। 99 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शब्द

'परामर्श' को अनुच्छेद 124 (2) और अनुच्छेद से हटा दिया गया है

217 (1) संविधान से। इसलिए सवाल यह है कि क्या द्वितीय न्यायाधीशों में इस शब्द की सही व्याख्या की गई है।

मामला हो या न हो, यह आज पूरी तरह से अकादमिक है। नया संविधान

व्यवस्था लागू कर दी गई है और इसका परीक्षण किया जाना चाहिए।

यह तभी होता है जब 99 वें संविधान संशोधन अधिनियम को इस रूप में माना जाता है

संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है और घोषित किया जाता है

असंवैधानिक है कि ठीक ट्यूनिंग और अंतराल में भरने

द्वितीय न्यायाधीश का मामला और तृतीय न्यायाधीश का मामला उठें।

290. इसलिए अब एकमात्र सवाल यह है कि क्या 99 वां

संविधान संशोधन अधिनियम संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है और इस प्रश्न का निर्णय लेने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि

दूसरे न्यायाधीशों के मामले या तीसरे न्यायाधीशों पर पुनर्विचार करें मामला। यह इस तथ्य से अलग है कि पुनर्विचार नहीं है

कानून में वारंट किया गया, यहां तक कि गुण-दोष पर भी।

कानून का शासन

291. हमारे सामने विवाद के गुण-दोष पर, यह है

इस आधार पर आगे बढ़ना आवश्यक है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि

सीएडी, संविधान और न्यायिक घोषणाएँ

न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी। करता है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता में एक की नियुक्ति शामिल है

न्यायाधीश? विद्वान महान्यायवादी के अनुसार,

न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट की स्वतंत्रता का एक हिस्सा है

[2015] 13 एस सी आर।

न्यायपालिका, लेकिन एक प्रमुख हिस्सा नहीं।

292. इन मुद्दों पर विचार करने से पहले, यह आवश्यक है कि

हमारे संविधान में कानून के शासन की भूमिका की सराहना करें

इतिहास. कहा गया है: 'अंततः, यह कानून का शासन है, न कि

न्यायाधीश, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की नींव प्रदान करते हैं

और जिम्मेदार सरकार "। 278

293. कानून के शासन को हमारे संविधान की एक बुनियादी विशेषता के रूप में मान्यता दी गई है। यह इस संदर्भ में है कि सूत्र, 'आप बनें' जब भी कानून आपके ऊपर होता है, उसे न्यायपालिका द्वारा स्वीकार किया जाता है और लागू किया जाता है। यदि कानून का शासन एक बुनियादी है

हमारे संविधान की विशेषता, इसलिए इसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए

न्यायपालिका चूंकि 'कानून के शासन के प्रवर्तन की आवश्यकता है

एक स्वतंत्र न्यायपालिका अपने अभिन्न और महत्वपूर्ण घटक के रूप में।

294. जस्टिस मैथ्यू ने इंदिरा नेहरू गांधी में निष्कर्ष निकाला

कि कुछ न्यायाधीशों के अनुसार जो बहुमत का गठन करते हैं

केशवानंद भारती कानून का शासन एक बुनियादी संरचना है

संविधान। 279

295. समशेर सिंह में न्यायपालिका की स्वतंत्रता

न्याय द्वारा संविधान का एक प्रमुख सिद्धांत माना गया था

कृष्ण लायर अपने और न्यायमूर्ति भगवती के लिए बोल रहे हैं। 280 कि

यह संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है

प्रथम न्यायाधीशों के मामले में पहली बार स्पष्ट रूप से कहा गया
न्यायमूर्ति फजल अली द्वारा 281 और न्यायमूर्ति द्वारा 282

न्यायमूर्ति भगवती द्वारा,

बी. डी. तुलजापुरकर। 283

296. दूसरे न्यायाधीशों के मामले में न्यायमूर्ति पांडियन

इस विचार को व्यक्त किया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता है
हुआ और जुड़ा हुआ है।

'न्यायिक प्रक्रिया से अटूट रूप से जुड़ा

278 जोनाथन के. वान पैटन द्वारा न्यायिक स्वतंत्रता और कानून का शासन, खंड 2 बेंचमार्क पृष्ठ 117,129
(1986)

283 पैराग्राफ 634

284 पैराग्राफ 56 सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

न्यायमूर्ति कुलदिप सिंह ने भी यही विचार व्यक्त किया था।
की स्वतंत्रता एक बुनियादी विशेषता है

अभिनिर्धारित किया कि न्यायपालिका

संविधान से। 285 न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा का पक्ष लेते हुए

बहुमत और कुछ निर्णयों पर भरोसा करते हुए माना गया कि

कानून संविधान की एक बुनियादी विशेषता है। 286 इसी तरह, न्याय

पुंछी (असहमति) ने माना कि कानून का शासन एक बुनियादी विशेषता है

संविधान और न्यायपालिका की स्वतंत्रता इसकी है

आवश्यक विशेषताएँ:

"ऐसा कहा जाता है कि कानून का शासन एक बुनियादी विशेषता है

संविधान पूरे संवैधानिक ताने-बाने में व्याप्त है। मैं सहमत हूँ। न्यायपालिका की स्वतंत्रता आवश्यक है

कानून के शासन की विशेषता, और मूल संरचना का हिस्सा है

संविधान से। इस बात से मैं भी सहमत हूँ।

297. न्यायिक जवाबदेही पर उप-समिति v.

भारत संघ 288 यह न्यायमूर्ति बी. सी. रे द्वारा आयोजित किया गया था

बहुमत के लिए कि कानून का शासन एक बुनियादी विशेषता है

संविधान और एक स्वतंत्र न्यायपालिका आवश्यक है।

ओकर विशेषता। कहा गया था:

"इससे पहले कि हम तर्कों के गुण-दोष पर चर्चा करें, यह है
संविधान का अवलोकन करने के लिए आवश्यक
न्यायपालिका और उसकी स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान।
इस क्षेत्र में संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करने में
न्यायालय को एक ऐसा निर्माण अपनाना चाहिए जो मजबूत हो
की मूलभूत विशेषताएँ और मूल संरचना
संविधान। कानून का शासन एक बुनियादी विशेषता है
संवैधानिक संरचना और इसका एक अभिन्न अंग है
संवैधानिक संरचना। न्यायपालिका की स्वतंत्रता है

कानून के शासन की एक आवश्यक विशेषता, "289

286 अनुच्छेद 421

287 अनुच्छेद 502

288 (1991) 4 एस. सी. सी. 699 (पाँच न्यायाधीशों की पीठ)

289 पैराग्राफ 16 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

298. इसी तरह, कर्तार सिंह बनाम। पंजाब राज्य 290 यह

न्यायमूर्ति के. रामास्वामी (असहमति) ने कहा कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका नियम की सबसे आवश्यक विशेषता है

कानून के बारे में:

"स्वतंत्र न्यायपालिका सबसे आवश्यक विशेषता है

कानून का शासन और लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए अपरिहार्य है।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अखंडता

सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली सर्वोच्च है।

न केवल न्यायाधीशों के लिए बल्कि न्यायाधीशों के लिए भी महत्व और हित

बड़े पैमाने पर लोग जो न्यायिक निवारण की मांग करते हैं

" 1 291

कथित कानूनी चोट या कार्यकारी ज्यादातियाँ।

299. इस दृष्टिकोण को विद्वान न्यायाधीश ने अभी तक दोहराया था।

एक अन्य असहमति, वह है, कृष्ण स्वामी बनाम। संघ का
भारत। 292

300. भारत संघ में v. मद्रास बार एसोसिएशन 2 9 3

अदालत की ओर से बोलते हुए, न्यायमूर्ति रवींद्रन ने कहा:

"कानून के शासन के कई पहलू हैं, जिनमें से एक यह है कि
नागरिकों के विवादों का निर्णय न्यायाधीशों द्वारा किया जाएगा जो हैं
स्वतंत्र और निष्पक्ष; और वह वैधता के बारे में विवाद करता है
सरकार के कार्यों का निर्णय न्यायाधीशों द्वारा किया जाएगा जो
वे कार्यपालिका से स्वतंत्र हैं। 294

301. अंत में, तमिलनाडु राज्य में यह सर्वसम्मति से हुआ।

मुख्य न्यायाधीश लोढ़ा के माध्यम से बोलते हुए पीठ ने कहा कि
न्यायपालिका की स्वतंत्रता के शासन के लिए मौलिक है

कानून:

"कार्यपालिका से न्यायालयों की स्वतंत्रता और
विधायिका कानून के शासन के लिए मौलिक है और
भारतीय संविधान के मूल सिद्धांत। का पृथक्करण

290 (1994) 3 एस. सी. सी. 569 (पाँच न्यायाधीशों की पीठ)

292 (1992) 4 एस. सी. सी. 605 अनुच्छेद 66

293 (2010) 11 एस. सी. सी. 1 (पाँच न्यायाधीशों की पीठ)

294 अनुच्छेद 101

291 पैराग्राफ 412 सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. /मदन बी. लोकर, जे./

न्यायिक शक्ति एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सिद्धांत है।

भारत के संविधान के तहत "। 29 5

302. यह दृष्टिकोण कि कानून का शासन और स्वतंत्रता

इस संबंध में मामलों की एक श्रृंखला का हवाला देना आवश्यक नहीं है, सिवाय इसके कि निष्कर्ष निकालते हैं कि कानून का शासन और स्वतंत्रता

न्यायपालिका आपस में जुड़ी हुई और अविभाज्य है और बुनियादी ढांचे का एक हिस्सा है।

हमारे संविधान की संरचना।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता-इसकी प्रकृति और

सामग्री

303. स्वतंत्र न्यायपालिका की विशेषताएँ क्या हैं?

चित्रण के अलावा उन्हें परिभाषित करना असंभव है। इस स्तर पर,

यह पूर्व सर निनियन स्टीफन के शब्दों को याद करने लायक है।

ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जिन्होंने यादगार रूप से कहा: '[एन]

स्वतंत्र न्यायपालिका, हालांकि एक दुर्जेय रक्षक व्यक्तिगत स्वतंत्रता, एक ही समय में बहुत कमजोर है

संस्था, वास्तव में एक नाजुक गढ़। '296 यह नाजुक गढ़ है।

जिसे अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए सुरक्षा की आवश्यकता है और यदि यह

नाजुक गढ़ एक चुनौती के अधीन है, संवैधानिक

संरक्षण आवश्यक है।

304. न्यायपालिका की स्वतंत्रता इसके भीतर आती है

दो व्यापक अवधारणाओं को मोड़ें: (1) एक व्यक्ति की स्वतंत्रता

न्यायाधीश, अर्थात् निर्णयात्मक स्वतंत्रता; और (2) स्वतंत्रता

न्यायपालिका की एक संस्था या राज्य के एक अंग के रूप में, अर्थात्,

कार्यात्मक स्वतंत्रता। न्यायिक विषय पर एक व्याख्यान में

स्वतंत्रता, लॉर्ड फिलिप्स 297 ने कहा: निष्पक्ष होने के लिए ए

न्यायाधीश को स्वतंत्र होना चाहिए; व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र, अर्थात्

295 अनुच्छेद 126.2

296 साउथी स्मारक व्याख्यान, 1981

297 यूनाइटेड किंगडम के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व राष्ट्रपति और इंग्लैंड और वेल्स के लॉर्ड मुख्य न्यायाधीश [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

व्यक्तिगत दबाव से मुक्त और संस्थागत रूप से स्वतंत्र, कि

राज्य के दबाव से मुक्त है। '

305. जहाँ तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संबंध है,

संविधान आयु तक पद के कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान करता है।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए 65 वर्ष। 29 8 तथापि,

न्यायाधीश पहले इस्तीफा दे सकते हैं या एक प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं

साबित दुर्व्यवहार के आधार पर महाभियोग या असमर्थता। 299 इसे प्रभावी बनाने के लिए संसद ने अधिनियम बनाया है

न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968। के लिए प्रक्रिया

एक न्यायाधीश का महाभियोग यह है कि एक प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित एक संबोधन के बाद पारित किया जा सकता है उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से

उसी सत्र में। अखंडता बनाए रखने के लिए और

न्यायपालिका की स्वतंत्रता, महाभियोग प्रक्रिया है

केक वॉक नहीं।

306. न्यायाधीश का वेतन, विशेषाधिकार, भत्ते, छुट्टी

अनुपस्थिति और पेंशन और ऐसे अन्य विशेषाधिकार, भत्ते

और दूसरी अनुसूची में उल्लिखित अधिकार

संविधान संरक्षित है और उसके अनुसार बदला नहीं जाएगा।

नियुक्ति के बाद नुकसान। 300 इसे प्रभावी बनाने के लिए संसद ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को अधिनियमित किया है

(सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958।

307. या को देय वेतन, भत्ते और पेंशन

उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश के संबंध में प्रभारित किया जाता है

भारत की समेकित निधि। 301 इस व्यय का अनुमान चर्चा की जा सकती है लेकिन मत के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाएगा

संसद। 302

308. जहाँ तक इस विषय का संबंध है,

298 अनुच्छेद 124 (2)

299 अनुच्छेद 124 (4)

300 अनुच्छेद 125

301 अनुच्छेद 112 (2) (घ)

302 अनुच्छेद 113 सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, में एक व्यापक संदर्भ है

संकलचंद सेठ। मोटे तौर पर, संवैधानिक संरक्षण और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए प्रावधान समान हैं

उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश के लिए।

309. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यकाल की सुरक्षा तब तक है जब तक

62 वर्ष की आयु 303 और हटाने की प्रक्रिया समान है

उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश के लिए। 304 वेतन, विशेषाधिकार,

भत्ते, अनुपस्थिति अवकाश का अधिकार और पेंशन आदि

राज्य, 305 संचित को देय पेंशन ली जाती है। भारत का कोष। 306 जैसा कि उच्चतम न्यायालय के मामले में,

इस व्यय के अनुमान पर चर्चा की जा सकती है लेकिन इसे विधान सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। 307 द.

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा की शर्तें इन द्वारा शासित होती हैं -

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें)

संविधान के अनुच्छेद 221 के संदर्भ में अधिनियम, 1954।

310. अधिकारों और सुरक्षा का पूरा पैकेज सुनिश्चित करता है

कि एक न्यायाधीश स्वतंत्र रहता है और निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है

कानून के अनुसार उसके/के परिणामों की परवाह किए बिना

एक न्यायाधीश के रूप में उनकी निरंतरता। इसका मतलब यह नहीं है कि एक न्यायाधीश जो भी निर्णय लेना चाहता है वह ले सकता है। द.

निर्णय लेने और विवेक के मापदंड हैं -

संविधान, कानून और संविधान के नियम द्वारा सीमित

कानून. यही निर्णयात्मक स्वतंत्रता का सार है, न कि

न्यायाधीश जो चाहें कर सकते हैं।

311. इस संदर्भ में, न्यायमूर्ति एंथनी एम. कैनेडी

अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायपालिका (न्यायिक सुरक्षा और न्यायपालिका) पर संयुक्त राज्य सीनेट समिति के समक्ष यह कहना था।

स्वतंत्रता) 14 फरवरी, 2007 को:

303 अनुच्छेद 217

304 अनुच्छेद 218

306 अनुच्छेद 112 (3) (घ)

307 अनुच्छेद 203 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

"न्यायिक स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जाती है इसलिए न्यायाधीश कर सकते हैं जैसा वे चाहें वैसा करें। न्यायिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है

ताकि न्यायाधीश वही कर सकें जो उन्हें करना चाहिए। स्थायी न्यायपालिका

कार्यकाल, अन्य से पर्याप्त मात्रा में अलगाव के साथ

सरकार की शाखाएँ और अनुचित प्रभाव का विरोध करने के निर्विवाद दायित्व के साथ आवश्यक है कानून का शासन जैसा कि हम उस शब्द को समझने लगे हैं। 308

312. जहाँ तक निर्णयात्मक स्वतंत्रता का संबंध है, ए

संरक्षण का अच्छा उदाहरण एंडरसन बनाम में पाया जा सकता है।

गोरी 309 जहाँ यह लॉर्ड एशर एम. आर. द्वारा कहा गया था :

"सवाल यह उठता है कि क्या कोई कार्रवाई हो सकती है

अभिलेख न्यायालय के एक न्यायाधीश के खिलाफ कुछ करने के लिए

अच्छे विश्वास के लिए। इंग्लैंड के सामान्य कानून के अनुसार यह कानून है कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होगी। "

इसे समझाते हुए, हार्विच के लॉर्ड ब्रिज ने मैक (ए माइनर) में कहा, 310 रुपये।

"इस नियम में अंतर्निहित सिद्धांत स्पष्ट है। अगर एक न्यायाधीश

एक हजार अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर बेईमानी से कार्य करता है उसके सामने एक पक्ष का नुकसान, यह कम हानिकारक है

समाज का स्वास्थ्य उस पक्ष को बिना किसी उपाय के छोड़ने के लिए कि नौ सौ निन्यानवे ईमानदार न्यायाधीशों को चाहिए

में द्वेष का आरोप लगाते हुए परेशान करने वाले मुकदमे द्वारा परेशान किया जाए

उनके उचित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग "।

313. जहाँ तक संस्थागत स्वतंत्रता का संबंध है,

हमारा संविधान भी इसके लिए प्रावधान करता है। उच्चतम न्यायालय के लिए,

अनुच्छेद 129 में संस्थागत स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है जो संस्थान को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने में सक्षम बनाता है। एक समान

उच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 215 में प्रावधान किया गया है। कानून.

308 एचटीटीपी: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. न्यायपालिका। सीनेट। जीओवी/इमो/मीडिया/डॉक/केनेडी _ गवाही _ 02 _ 14_ 07। पीडीएफ।

309 [1895] 1 प्र. 8. 668, 670 310 [1985] ए. सी. 528,540 सर्वोच्च न्यायालय अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा।

भारत के क्षेत्र के भीतर। 311 सभी प्राधिकरण, नागरिक और न्यायिक

सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करने के लिए बाध्य हैं। 312 सर्वोच्च

न्यायालय को ऐसी डिक्री पारित करने या ऐसा आदेश देने का अधिकार है जो -

किसी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक

भारत के पूरे क्षेत्र में लागू करने योग्य। 313 एक कानून के अधीन संसद द्वारा बनाया गया, सर्वोच्च न्यायालय फ्रेम बनाने का हकदार है

इसके अभ्यास और प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम। 314 मुखिया।

भारत के न्यायाधीश को अधिकारियों और 'सेवकों' की नियुक्ति करने का अधिकार है।

उच्चतम न्यायालय की लेकिन उनकी सेवा की शर्तें होंगी

उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित (के अधीन राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन) या संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा, 325

सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय, जिनमें शामिल हैं

इसके अधिकारियों और 'सेवकों' से संबंधित खर्च भारत की संचित निधि पर प्रभारित किए जाएंगे। 316

314. उल्लेखनीय है कि इसमें कोई चर्चा नहीं होगी।

न्यायाधीश के आचरण के संबंध में संसद

महाभियोग की कार्यवाही को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय। 317 इसी प्रकार, किसी राज्य का विधानमंडल ऐसा नहीं करेगा कि

अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा करें। 318

315. उपरोक्त के अलावा, अन्य सामान्य हैं

312 अनुच्छेद 144। उच्च न्यायालय के लिए कोई संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। 313 अनुच्छेद 142। उच्च न्यायालय के लिए कोई संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है।

314 अनुच्छेद 145। उच्च न्यायालय के लिए कोई संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है।

315 अनुच्छेद 146। उच्च न्यायालय के लिए संबंधित संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 229 है। 316 अनुच्छेद 146। उच्च न्यायालय के लिए संबंधित संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 229 है।

317 अनुच्छेद 121

318 अनुच्छेद 211 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

व्यक्तिगत न्यायाधीश या संस्था के लिए उपलब्ध संरक्षण जैसे कि। अनुच्छेद 50319 के भाग IV में
एक प्रावधान के माध्यम से

संविधान (संविधान में ग्रैनविल ऑस्टिन:

'राष्ट्र की आधारशिला' के भाग III और भाग IV का वर्णन करता है

संविधान के रूप में 'संविधान की अंतरात्मा') 320

न्यायपालिका को कार्यपालिका के हस्तक्षेप से सुरक्षित रखा जाएगा। न्याय

कृष्णा लायर अपने लिए बोल रहे हैं और न्यायमूर्ति फजल अली ने कहा

संकलचंद सेठ में कहा गया है:

या न्यायाधीश द्वारा अपने न्यायिक कर्तव्यों के निर्वहन में लिखा गया है।
उच्च न्यायालय पूरी तरह से विशेषाधिकार प्राप्त है और कोई कार्रवाई नहीं की गई है

मानहानि के लिए ऐसे शब्दों के संबंध में झूठ बोल सकते हैं। यह

न्यायाधीशों को पूर्ण प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है

सार्वजनिक नीति का आधार, अर्थात् वे इस प्रकार कर सकते हैं

निडरता से अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। 321

316. इसी प्रकार, न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम की धारा 3,

1985 अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करता है कि कोई भी अदालत सुनवाई नहीं करेगी या जारी नहीं रखेगी।

किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई दीवानी या आपराधिक कार्यवाही जो या

किसी भी कार्य, वस्तु या वचन के लिए एक न्यायाधीश था जो किया गया था या किया गया था
उसके द्वारा तब बोला जाता है जब, या उसके दौरान, अभिनय या उद्देश्य

अपने आधिकारिक या न्यायिक कर्तव्य या कार्य के निर्वहन में कार्य करना।

यह भारतीय दंड संहिता की धारा 77 द्वारा दिए गए संरक्षण के अतिरिक्त है जो प्रदान करता है कि: कुछ भी
अपराध नहीं है।

जो एक न्यायाधीश द्वारा अभ्यास में न्यायिक रूप से कार्य करते समय किया जाता है

किसी भी शक्ति का जो है, या जिसे वह सद्भावना से मानता है,

उसे कानून द्वारा दिया गया। '

317. समग्र परिप्रेक्ष्य और संरचना में

न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यह प्रथम न्यायाधीशों में कहा गया था

न्यायमूर्ति डी. ए. देसाई का मामला कि: 'न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के तहत व्याख्या की जानी चाहिए

319 अनुच्छेद 50: राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा।

320 पृष्ठ 50

321 पैराग्राफ 77 शीर्ष अदालतें-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

संविधान की रूपरेखा और मानदंड '। 322 यह हो सकता है

यह जोड़ा जाए कि कानून की रूपरेखा और मापदंड हैं

इसे भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति भगवती ने इसे काफी संक्षिप्त रूप से रखा जब उन्होंने कहा:

"न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा नहीं है केवल कार्यकारी दबाव से स्वतंत्रता तक सीमित या

प्रभाव लेकिन यह एक बहुत व्यापक अवधारणा है जो इसके भीतर ले जाती है।

कई अन्य दबावों से इसकी व्यापक स्वतंत्रता और

पूर्वाग्रह। इसके कई आयाम हैं, जैसे निर्भीकता।

अन्य शक्ति केंद्रों, आर्थिक या राजनीतिक, और द्वारा अर्जित और पोषित पूर्वाग्रहों से मुक्ति

जिस वर्ग से न्यायाधीश संबंधित हैं। 323

318. आम तौर पर, इसलिए, स्वतंत्रता

न्यायपालिका की एक न्यायाधीश की लेने की क्षमता में प्रकट होती है

किसी भी बाहरी (या आंतरिक) दबाव से स्वतंत्र निर्णय या

किसी भी बाहरी (या आंतरिक) दबाव का डर और वह है 'निर्णयात्मक'

स्वतंत्रता '। यह क्षमता में भी प्रकट होता है

और 'न्यायपालिका की स्वतंत्रता' की समग्र परिभाषा है

मायावी लेकिन इसे समझना आसान है।

319. संविधान सभा ने पूरी तरह से सराहना की

एक स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता और शायद

किसी भी अन्य मुद्दे की तुलना में इस पर चर्चा करने के लिए अधिक समय दिया।

ग्रेनविल ऑस्टिन निम्नलिखित की ओर इशारा करते हैं:

"वे विषय जो मन में सबसे बड़े थे

न्यायिक प्रावधानों को तैयार करते समय विधानसभा के सदस्य

अदालतों की स्वतंत्रता थी और दो निकटता से

संबंधित मुद्दे, उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ और

न्यायिक समीक्षा। सभा बहुत हद तक चली गई

यह सुनिश्चित करें कि अदालतें स्वतंत्र, समर्पित हों

लगभग किसी भी विषय की तुलना में इस विषय पर बहस के अधिक घंटे

322 अनुच्छेद 709

323 पैराग्राफ 27 [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रावधानों का अन्य पहलू। अगर दीमक की

न्यायपालिका को उज्ज्वल रहना था, अदालतें ऊपर होनी चाहिए

निन्दा, जबरदस्ती और राजनीतिक से मुक्त

प्रभाव "। 324

न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच अलगाव

320. चर्चा का एक अन्य पहलू

न्यायपालिका की स्वतंत्रता का समाधान विचार करके किया जा सकता है

संविधान का अनुच्छेद 50। 325 इस लेख का उल्लेख किया गया था

द्वितीय न्यायाधीशों का मामला और, विद्वान वकील के अनुसार

याचिकाकर्ताओं के लिए, प्रथम न्यायाधीशों के मामले में अनदेखी की गई। यह था।

आग्रह किया कि वह अनुच्छेद उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि संविधान सभा काफी स्पष्ट थी कि एक होना चाहिए

कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच अलगाव। द. दूसरी ओर, विद्वान महान्यायवादी ने प्रस्तुत किया कि

संविधान के अनुच्छेद 50 द्वारा अभिनिर्धारित अलगाव था

केवल राज्य की सार्वजनिक सेवाओं तक ही सीमित है और समग्र रूप से न्यायपालिका तक नहीं।

321. अनुच्छेद 50 को संविधान में शामिल किया गया था

डॉ. अम्बेडकर के कहने पर राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों पर अध्याय जिन्होंने 24 तारीख को एक प्रस्ताव पेश किया

नवंबर, 1948 में संविधान के मसौदे में अनुच्छेद 39 ए को शामिल किया गया। 326

322. अनुच्छेद 39 ए को शामिल करने की आवश्यकता को समझाते हुए

संविधान के प्रारूप में डॉ. अम्बेडकर ने कहा था कि

लंबे समय से इच्छा है कि एक अलगाव होना चाहिए

कार्यपालिका से न्यायपालिका और इसके लिए एक मांग की गई थी

हालाँकि, ब्रिटिश सरकार ने इस पर कोई प्रभाव नहीं डाला 324 ग्रैनविल ऑस्टिन-"भारतीय संविधान: एक राष्ट्र की आधारशिला" पृष्ठ 164-164

325 50. न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। - राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। 326 39 - ए. वह राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा कि इस संविधान के प्रारंभ से तीन साल की अवधि के भीतर, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

माँगें। डॉ. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 39 ए को शामिल करने का प्रस्ताव रखा

संविधान के प्रारूप में निम्नलिखित शब्दों में कहा गया है:

"मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए बहुत कुछ करना आवश्यक है। संशोधन के समर्थन में लंबा बयान जो मैं

चले गए हैं। यह इस देश की इच्छा रही है

बहुत पहले कि न्यायपालिका को अलग किया जाना चाहिए
कार्यपालिका से और मांग जारी रखी गई है

कांग्रेस की स्थापना के समय से ही।

दुर्भाग्य से, ब्रिटिश सरकार ने प्रभाव नहीं डाला

इसकी मांग करने वाले कांग्रेस के प्रस्तावों पर

देश का प्रशासन। हम सोचते हैं कि समय आ गया है
यह सुधार कब होना चाहिए। वह यह है कि

बेशक, महसूस किया कि कुछ कठिनाइयाँ हो सकती हैं

इस सुधार को लागू करना; परिणामस्वरूप यह

संशोधन में दो विशेष बातों पर विचार किया गया है
ऐसे मामले जो कठिनाई के विषय पाए जा सकते हैं।

मौलिक सिद्धांत का, क्योंकि अगर हमने इसे एक बनाया होता
मौलिक सिद्धांत की बात यह बन गई होगी

के गुजरने पर तुरंत अनिवार्य रूप से

न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने के लिए संविधान। इसलिए हमारे पास

जानबूझकर इस मामले को संबंधित अध्याय में रखें

निर्देशक सिद्धांत और वहाँ भी हमने प्रदान किया है कि

यह सुधार तीन साल के भीतर किया जाएगा, ताकि

जिसे कहा जा सकता है उसके लिए कोई जगह नहीं बची है

इस तरह के मामले में विलंब। साहब, मैं चलता हूँ। " 327

323. श्री बी. दास (उड़ीसा-जनरल) ने इसका विरोध किया

संशोधन इस आधार पर कि जब लोगों को परेशान किया गया था

ब्रिटिश सरकार द्वारा, यह भावना थी कि कोई न्याय नहीं था

दिया और यही कारण है कि अलगाव की मांग की गई थी

27 एचटीटीपी: //भारत की संसद। ठीक है। इन/एलएस/डिबेट/वॉल्यूम 7 पी12।

एच. टी. एम. सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

कार्यपालिका से न्यायपालिका। आजादी के बाद कि

संदेह मौजूद नहीं था और इसलिए यह जांच करना आवश्यक था कि क्या अलगाव आवश्यक था।

324. अगले दिन 25 तारीख को भी बहस जारी रही।

संविधान के प्रारूप के अनुच्छेद 39 ए के कुछ शब्द। के रूप में इस प्रस्तावित संशोधन के परिणामस्वरूप, अनुच्छेद 39 ए इस प्रकार पढ़ा जाएगा:

निम्नलिखित है:

"राज्य न्यायपालिका को अलग करने के लिए कदम उठाएगा।

राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका "।

325. 25 नवंबर, 1948 को बहस के दौरान एक आत्म-स्पष्ट सत्य सामने आया। यह बताया गया था कि

पंडित जवाहरलाल नेहरू (संयुक्त प्रांत: सामान्य) ने कहा कि संविधान के लंबे समय तक चलने की उम्मीद है और यह होना चाहिए

कठोर न हों। जहाँ तक संविधान की 'मूल प्रकृति' की बात है,

राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में न कि उन विवरणों के साथ जो कानून बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसमें कहा गया है कि संदर्भ इस प्रकार है:

"इस वर्तमान संशोधन पर आते हुए, अगर मैं फिर से कर सकता हूँ

इस सदन के संबंध में कुछ सामान्य टिप्पणियां इस प्रकार हैं: कि मैंने महसूस किया है कि एक संविधान की गरिमा यदि कोई अंदर जाता है तो शायद पर्याप्त रूप से बनाए नहीं रखा जाता है

उस संविधान में बहुत बड़ा विवरण है। एक संविधान है कुछ ऐसा जो लंबे समय तक चलना चाहिए, जिसे बनाया गया है

एक मजबूत नींव पर, और जो निश्चित रूप से समय-समय पर भिन्न हो सकती है-यह कठोर नहीं होनी चाहिए -

फिर भी, किसी को इसे कुछ ऐसा सोचना चाहिए जो लंबे समय तक चलने वाला है, जो एक अस्थायी संविधान नहीं है,

दिन-ब-दिन बदलने जा रहा है, कुछ ऐसा जो अगले वर्ष या अगले वर्ष के लिए प्रावधान और इसलिए सर्वोच्च न्यायालय अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड संगठन v.

यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

इत्यादि। यह निश्चित करने के लिए आवश्यक हो सकता है

अस्थायी प्रावधान। यह आवश्यक होगा, क्योंकि वहाँ

इस तरह के कुछ प्रावधान होने के लिए एक परिवर्तन है, लेकिन जहाँ तक

संविधान की मूल प्रकृति का संबंध है, यह आवश्यक है

राजनीतिक के मूलभूत पहलुओं से निपटना,

विवरण जो विधान के लिए विषय हैं। आपको पता चल जाएगा कि यदि आप बहुत अधिक विस्तार में जाते हैं और वास्तव में बुनियादी और बुनियादी चीजों को महत्वपूर्ण लेकिन के साथ मिलाते हैं

फिर भी गौण चीजें, आप बुनियादी चीजें लाते हैं

माध्यमिक चीजों के स्तर तक भी। आप उन्हें खो देते हैं

विस्तार का जंगल। बड़े पेड़ जिन्हें आपको पसंद करना चाहिए

विस्तृत और छोटे पेड़ों के जंगल में। मैंने महसूस किया कि हम निस्संदेह बहुत समय खर्च कर रहे हैं

महत्वपूर्ण मामले, लेकिन फिर भी गौण मामले

- ऐसे मामले जो विधान के लिए हों, न कि संविधान के लिए।

हालाँकि, यह एक सामान्य अवलोकन है। 328

326. पंडित द्वारा व्यक्त विचार का महत्व

जवाहरलाल नेहरू का कहना है कि 'मूल प्रकृति' का अस्तित्व

संविधान को मान्यता दी गई थी और ऐसा प्रतीत होता है कि यह क्या है संरचना या बुनियादी विशेषताओं के रूप में कहते हैं

हम आज की बुनियादी

संविधान। निस्संदेह एक स्वीकृति थी

संविधान के कुछ मूलभूत पहलू लेकिन यह नहीं था

प्रत्येक के संबंध में विवरण में जाना संभव है

उन्हें। इसे 'चरम मामलों' के संदर्भ में समझाते हुए

पल 'पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत एक बहुत बड़ा देश है।

मिश्रित देश 'राजनीतिक, न्यायिक, आर्थिक और कई क्षेत्रों में

प्रत्येक क्षेत्र पर लागू किए जाने वाले तरीके और अंगूठे का कोई भी निश्चित नियम कुछ क्षेत्रों के संबंध में नुकसानदेह और कठिन हो सकता है।

क्षेत्रों। एक तरफ, यह नियम वास्तव में प्रगति को रोकेगा।

एक तरफ, और दूसरी तरफ, यह सेब-गाड़ी को परेशान कर सकता है

कुछ और क्षेत्र। इसलिए, एक निश्चित लचीलापन वांछनीय है। 1 329

328 एचटीटीपी: //भारत की संसद। ठीक है। /इस/डिबेट/वॉल्यूम 7पी13 में। एचटीएम।

329 एचटीटीपी: //भारत की संसद। ठीक है। /ls/डिबेट/वॉल्यूम 7p13 में।

एचटीएम [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

327. डॉ. बख्शी टेक चंद (पूर्व) द्वारा व्यक्त किए गए विचार

पंजाब: सामान्य) इस संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। द.

माननीय सदस्य ने इसके लिए विस्तृत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दी

कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने की मांग और

इस विचार को व्यक्त किया कि 1852 में जब जनता

बंगाल में राय एक संगठित तरीके से व्यक्त होने लगी

जिस तरह से अलगाव का मामला पहले उठाया गया था। अन्य में

शब्दों में, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने की मांग लगभग 100 वर्षों से की जा रही थी।

वेहद कहने वाले उदाहरण और यह उद्धृत करना सबसे अच्छा है कि क्या था उन्होंने कहा:

"इस संबंध में मुझे एक शब्द और कहना है और वह

है, कि लोकतंत्र और स्वतंत्रता के आगमन के साथ,
इस सुधार की आवश्यकता और अधिक बढ़ गई है।

नौकरशाही सरकार के सदस्य जिनसे
न्यायपालिका में हस्तक्षेप पकड़ा गया था, लेकिन अब,

मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि कुछ मंत्रियों को भी
प्रांतों और राजनीतिक दलों के सदस्यों ने शुरू कर दिया है

न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करना। जिनमें से
आप, जो समाचार पत्रों में न्यायिक रिपोर्ट पढ़ रहे होंगे

हस्तक्षेप जिसकी विभिन्न मामलों में समीक्षा की जा रही है
हाल ही में उच्च न्यायालय। एक प्रांत में हमने पाया कि एक मामले में

रिकॉर्ड करें और कोशिश करने का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित करें
मजिस्ट्रेट मामले में कार्यवाही पर रोक लगाएं।

यह सर्वोच्च अदालतें थीं-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

कुछ ऐसा जो बिल्कुल अनसुना है। अंत में मामला

उच्च न्यायालय तक गए और विद्वान मुख्य न्यायाधीश

एक अन्य प्रांत में एक के खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा था विधान सभा के सदस्य और एक
निर्देश चला गया

जिला मजिस्ट्रेट से लेकर मजिस्ट्रेट तक

इसके साथ आगे नहीं बढ़ने और आदमी को रिहा करने का मामला। मजिस्ट्रेट जो न्यायिक निकाय का सदस्य
था सेवा में थे और मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य कर रहे थे

इस मांग का विरोध करने की शक्ति। उनके पास वे सभी पत्र थे।

रिकॉर्ड में डाल दिया और अंत में मामला चला गया

उच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

अदालत ने इस मामले पर बहुत कड़ी टिप्पणी की।

पंजाब में फिर से हाल ही में एक मामला सामने आया है। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, श्री
न्यायमूर्ति आचारू राम,

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई की और 164 पृष्ठों का फैसला सुनाया, जिसके अंत में उन्होंने कहा

कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की गई कार्रवाई और

एक सदस्य के खिलाफ पुलिस अधीक्षक

कांग्रेस पार्टी दुर्भावनापूर्ण थी और इसका परिणाम था

व्यक्तिगत प्रतिशोध। ये उनकी टिप्पणियां थीं।

इन परिस्थितियों में, मैं प्रस्तुत करता हूं कि परिवर्तन के साथ

परिस्थितियों और स्वतंत्रता के आगमन के साथ और

लोकतंत्र की शुरुआत, यह और भी अधिक हो गया है

न्यायपालिका को अलग करने के लिए आवश्यक कार्यपालिका से जल्द से जल्द संभव अवसर पर
"। 330

329. यह बहस 25 नवंबर, 1948 को समाप्त हुई।
 संविधान सभा अंततः के सम्मिलन को स्वीकार करती है
 संविधान के प्रारूप में 39 ए। यह अब अनुच्छेद 50 में है
 संविधान।
 टीपी: //भारत की संसद। ठीक है। इन/एस/डिबेट/वॉल्यूम 7 पी13।

एच. टी. एम. सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

330. बहस के महत्व को न केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, बल्कि यह भी देखा जाना चाहिए कि यह क्या था। संविधान सभा द्वारा भविष्य के लिए अभिप्रेत। अतीत में

में कार्यपालिका द्वारा निर्लज्ज हस्तक्षेप किया गया था

अधीनस्थ न्यायपालिका द्वारा न्याय का प्रशासन और

निश्चित रूप से इसकी जाँच करने की आवश्यकता थी। इस मायने में, बहस

23 और 24 तारीख को आयोजित संविधान के मसौदे के अनुच्छेद 103 पर मई, 1949। उस समय तक यह स्पष्ट हो रहा था (अगर यह नहीं था)

पहले से ही स्पष्ट) संविधान सभा को कि वहाँ होना चाहिए

प्रशासन में कार्यपालिका द्वारा कोई हस्तक्षेप न किया जाए

न्याय और यह कि हर विवरण के लिए प्रदान करना आवश्यक नहीं था

संविधान के प्रारूप में। कि संवैधानिक सम्मेलन मौजूद थे

स्वतंत्रता से पहले ज्ञात थे, लेकिन वे आवश्यक थे

स्वतंत्रता के बाद इसे जारी रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण था।

331. संविधान में विवरणों से बचने की आवश्यकता के साथ,

प्रारूप संविधान में विशेष रूप से प्रावधान नहीं किया गया था

अधीनस्थ के अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता

न्यायपालिका। अगर इसे काफी स्पष्ट रूप से देखा जाए, तो ऐसा प्रतीत होगा।

यह विचार रखना कालातीत है कि मसौदे का अनुच्छेद 39 ए

संविधान में अधीनस्थ न्यायपालिका की आवश्यकता थी यह नहीं था

स्वतंत्र और कार्यपालिका से अलग लेकिन

उच्चतर न्यायपालिका के स्वतंत्र होने के लिए आवश्यक था

कि या तो उच्चतर न्यायपालिका पहले से ही स्वतंत्र थी (और आवश्यकता नहीं थी) या कि यदि यह स्वतंत्र नहीं था तो,

इसके लिए किसी पुनरावृत्ति की

अधीनस्थ न्यायपालिका की तरह, इसे स्वतंत्र बनाया जाना चाहिए,

कार्यपालिका को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जा रही है

न्याय का प्रशासन। किसी भी तरह से, के बीच अलगाव

न्यायपालिका और कार्यपालिका के इरादे से

स्वतंत्र न्यायपालिका एक बांछनीय उद्देश्य था।

332. कोई भी संदेह नहीं कर सकता है और वास्तव में, यहां तक कि विद्वान सर्वोच्च न्यायालय भी-चालू-रिकॉर्ड कर सकते हैं

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

महान्यायवादी को संदेह नहीं था कि स्वतंत्रता

न्यायपालिका नितांत आवश्यक है। लेकिन, की स्वतंत्रता न्यायपालिका अपने आप में कोई अंत नहीं है। इसके बजाय, इसका उद्देश्य एक स्वतंत्र न्यायपालिका को सुरक्षित करना है जो अपने मौलिक कार्यों का निर्वहन करेगी।

कानून का शासन। 1331 इसके अलावा, न्यायपालिका को स्पष्ट रूप से होना चाहिए से अलग।

कार्यपालिका

333. विषयांतर के माध्यम से, एक शब्द के बारे में भी कहा जा सकता है

न्यायपालिका की वित्तीय स्वतंत्रता। 15 जून, 2008 के एक पत्र में 'न्यायिक' पर कार्य बल की रिपोर्ट को अंग्रेषित करते हुए

प्रभाव आकलन 'का उल्लेख न्यायमूर्ति एम.

कानून और न्याय मंत्री को जगन्नाथ राव (सेवानिवृत्त)

कि 'योजना आयोग और वित्त आयोग को

मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से पर्याप्त प्रावधान करें

भारत का, 'पहुँच' के बुनियादी मानवाधिकारों की प्राप्ति के लिए

न्याय 'और' त्वरित न्याय 'नागरिक और आपराधिक दोनों। वर्तमान में

योजना परिव्यय का 0.071%, 0.078% और 0.07% का आवंटन

9 वीं, 10 वीं और 11 वीं योजना पूरी तरह से अपर्याप्त हैं। वित्तीय स्वतंत्रता एक ऐसा क्षेत्र है जो इसके लिए भी महत्वपूर्ण है

न्यायपालिका की स्वतंत्रता लेकिन सबसे कम है

चर्चा की।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता और नियुक्ति

प्रक्रिया

334. हमें इस आधार पर आगे बढ़ना चाहिए कि

न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है और वहाँ कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक अलगाव होना चाहिए

न्यायपालिका। न्यायपालिका की स्वतंत्रता शुरू होती है

न्यायाधीश की नियुक्ति। ग्रैनविल ऑस्टिन कहते हैं: 'एक स्वतंत्र

न्यायपालिका की शुरुआत इस बात से होती है कि कौन किस क्षमता के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।'
'332

331 जे. वान ज़ाइल स्मिट, राष्ट्रमंडल सिद्धांतों के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यकाल और निष्कासन: एक संग्रह और विश्लेषण। सर्वश्रेष्ठ अभ्यास (विंघम सेंटर फॉर द रूल ऑफ लॉ द्वारा किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट) का अनुच्छेद। 9

332 ग्रैनविल ऑस्टिन "एक लोकतांत्रिक संविधान पर काम करना: द इंडियन एक्सपीरियंस पेज 124 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

यह सराहना की जानी चाहिए और स्वीकार किया जाना चाहिए कि कार्यप्रणाली

स्वतंत्रता, अर्थात्, सिफारिश और नियुक्ति उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का होना इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है -

न्यायपालिका की स्वतंत्रता। 333 यदि किसी व्यक्ति की क्षमता संदिग्ध है

या सत्यनिष्ठा को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है, इसकी संभावना है

आंतरिक या बाहरी दबाव के आगे झुकना और दूषित निर्णय देना। यह जड़ पर प्रहार करेगा न्यायपालिका की स्वतंत्रता और लोगों के विश्वास को नष्ट करना

निष्पक्ष न्याय वितरण में आम व्यक्ति। अतएवं एक

सभी संवैधानिक संस्थाओं पर बड़ा दायित्व और जिम्मेदारी

भारत के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति सहित पदाधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कि न केवल वे योग्य व्यक्ति हैं

न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जाता है, लेकिन योग्य व्यक्तियों को नियुक्ति से वंचित नहीं किया जाता है। 3.

335. मार्बरी बनाम में मुख्य न्यायाधीश मार्शल। मैडिसन

यह पाया गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी अधिकारियों के कमीशन के संबंध में, संविधान और कानूनों के खंड

ऐसा लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के तीन अलग-अलग विचार हैं संचालन , अर्थात्:

" 1. नामांकन। यह राष्ट्रपति का एकमात्र कार्य है,

और यह पूरी तरह से स्वैच्छिक है।

2. नियुक्ति। यह भी राष्ट्रपति का कार्य है,

और यह एक स्वैच्छिक कार्य भी है, हालांकि इसे केवल किया जा सकता है।

सीनेट की सलाह और सहमति से।

3. आयोग। किसी व्यक्ति को कमीशन देना

नियुक्त, शायद संविधान द्वारा निर्धारित कर्तव्य माना जा सकता है। वह करेगा ", वह वाद्य कहता है,

" संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी अधिकारियों को नियुक्त करें। 335

336. इसे न्यायाधीशों की नियुक्ति में परिवर्तित करना

333 दूसरे न्यायाधीशों का मामला, अनुच्छेद 49, 335 और 447। 334 एल. सी. आई. की 14 वीं रिपोर्ट, अध्याय 5

335 पृष्ठ 155 और 156 सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

हमारे देश में, पहला कदम एक सिफारिश (या नामांकन) है

उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। कभी-कभी किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी एक सिफारिश, लेकिन इसके माध्यम से रूट किया जाना आवश्यक है

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति द्वारा किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने का कोई उदाहरण नहीं है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश।

337. दूसरा कदम एक न्यायाधीश की नियुक्ति है और

यह राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश के बीच एक परामर्शात्मक सहभागी प्रक्रिया के माध्यम से ही संभव है।

यह इस प्रक्रिया में है कि कुछ व्याख्यात्मक किया गया है

असहमति, लेकिन दूसरे न्यायाधीशों का मामला और तीसरा न्यायाधीशों के मामले ने राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश के बीच एक साझा प्रधानता और जिम्मेदारी के साथ आराम करने के लिए निर्धारित किया है।

भारत। इसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है।

338. तीसरा कदम वारंट जारी करना है

नियुक्ति (या कमीशन)। यह स्पष्ट है कि आदेश नियुक्ति केवल राष्ट्रपति द्वारा जारी की जा सकती है। वहाँ है।

इस बारे में कोई विवाद नहीं है और न ही हो सकता है। इसके तहत

परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि कार्यकारी कार्य

विद्वान वकील के विपरीत, राष्ट्रपति अक्षुण्ण रहते हैं

जनरल कहते हैं और पाठ की कोई गुंजाइश नहीं है 'न्यायाधीशों के मंत्र की नियुक्ति करने वाले न्यायाधीश।

339. शायद यह सरल तीन-चरणीय प्रक्रिया है कि

संविधान सभा ने इरादा किया। लेकिन यह इस पर विकृत हो गया

वर्षों में, राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा हस्तक्षेप के लिए धन्यवाद पहला और दूसरा कदम।

340. 'न्यायिक स्वतंत्रता' शीर्षक वाली एक रिपोर्ट में: कानून

और मानव सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट के यूरोपीय न्यायालय में नियुक्तियों का अभ्यास

अधिकार 1 336 कानून के शासन के बीच परस्पर क्रिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायाधीशों की नियुक्ति

न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका। यह यही कहा गया था:

"न्यायपालिका की स्वतंत्रता एक है

कानून के शासन की आधारशिलाएँ। चुने जाने के बजाय

लोगों द्वारा, न्यायाधीश अपना अधिकार और वैधता प्राप्त करते हैं

राजनीतिक या अन्य से उनकी स्वतंत्रता से

हस्तक्षेप। मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय मानकों से यह स्पष्ट है कि न्यायाधीशों का चयन और नियुक्ति

न्यायपालिका की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है

स्वतंत्रता और सबसे सक्षम सुनिश्चित करना
व्यक्तियों का चयन किया जाता है।

341. भारत राष्ट्रमंडल का हिस्सा है और

की जवाबदेही पर राष्ट्रमंडल सिद्धांत और

सरकार की तीन शाखाओं के बीच संबंध 337 न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में, अन्य बातों के साथ-साथ,

इस प्रकार है:

"एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, ईमानदार और सक्षम

न्यायपालिका कानून के शासन को बनाए रखने के लिए अभिन्न अंग है।

जनता का विश्वास बढ़ाना और न्याय प्रदान करना।

न्यायपालिका का कार्य व्याख्या करना और लागू करना है।

राष्ट्रीय संविधान और कानून, जिसके अनुरूप

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय
कानून, प्रत्येक के घरेलू कानून द्वारा अनुमत सीमा तक

राष्ट्रमंडल देश। इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए: (अ)

न्यायिक नियुक्तियाँ इन आधार पर की जानी चाहिए -

336 योगदानकर्ता: प्रोफेसर डॉ. जुट्टा लिम्बाच, प्रोफेसर डॉ. पेड्रो विलासोन, रोजर एरेरा, द राइट ऑन लॉर्ड लेस्टर ऑफ हर्न हिल क्यूसी, प्रोफेसर डॉ. तमारा मोर्सचाकोवा, द राइट ऑन लॉर्ड जस्टिस सेडले, प्रोफेसर डॉ. आंद्रेज जोला एच. टी. पी. पर उपलब्ध: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. अंतर्विरोध। ओ. आर. जी./दस्तावेज़/142/सूचकांक। एचटीएमएल

337 जैसा कि कानून मंत्रियों द्वारा सहमति व्यक्त की गई और राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक, अबुजा, नाइजीरिया, 2003 द्वारा समर्थित सर्वोच्च न्यायालय अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

स्पष्ट रूप से परिभाषित मानदंड और सार्वजनिक रूप से घोषित मानदंड

प्रक्रिया। प्रक्रिया को सुनिश्चित करना चाहिए: समानता

उन सभी के लिए अवसर जो न्यायिक पद के लिए पात्र हैं;

भेदभाव; "338
लॉर्ड चांसलर थे।

342. जैक स्ट्रॉ संयुक्त राज्य में

2007 से 2010 तक राज्य। उन्होंने 64 वीं शृंखला दी।

2012 में हैमलिन ने 'कानून सुधार के पहलू' शीर्षक से व्याख्यान दिया।

अंदरूनी दृष्टिकोण '। उस शृंखला का तीसरा व्याख्यान था

उनके द्वारा 4 दिसंबर, 2012 को 'न्यायिक' विषय पर दिया गया

नियुक्तियाँ '। उस व्याख्यान में वे कहते हैं:

मानक और प्रक्रिया, और किस परिणाम के साथ -
महत्वपूर्ण महत्व। न्यायपालिका को बनाए रखने के लिए जो है

स्वतंत्र, जो अच्छे निर्णय लेता है, और किसमें

जनता में विश्वास बना रह सकता है, हमें इसकी आवश्यकता है

सबसे मेधावी उम्मीदवारों की नियुक्ति करें और एक

न्यायपालिका जो समाज को यथासंभव प्रतिबिंबित करती है

सेवा कर रहा है।

और हमें इसे पहली बार, हर बार प्राप्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि,

एक बार पूर्णकालिक वेतनभोगी पद पर नियुक्त होने के बाद, न्यायाधीश

सबसे अधिक के अलावा कार्यालय से हटाया नहीं जा सकता है

चरम परिस्थितियाँ "। 339

343. इसलिए, एक न्यायाधीश की नियुक्ति में, यह नहीं है

केवल (नकारात्मक रूप से व्यक्त) कि एक 'गलत व्यक्ति' को नहीं करना चाहिए

नियुक्त किया जाए लेकिन (सकारात्मक रूप से व्यक्त) सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा,

वकीलों और न्यायिक अधिकारियों के बीच नियुक्त किया जाना चाहिए

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश

338 एचटीटीपी: //राष्ट्रमंडल।org/साइटें/डिफॉल्ट/फाइलें/इतिहास-आइटम/दस्तावेज़/लैटिमरहाउस प्रिंसिपल्स। पीडीएफ

339 पृष्ठ 52 [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्च न्यायालय या अधिवक्ताओं या प्रतिष्ठित न्यायविदों के बीच

सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया जाना चाहिए। यह कहा गया है एल. सी. आई. की 14 वीं रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यायाधीशों का चयन

राष्ट्र की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण महत्व और वह जिम्मेदारी का निर्वहन बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए।

344. न्यायिक स्वतंत्रता पर रिपोर्ट में: कानून और

यूरोपीय मानव न्यायालय में नियुक्तियों का अभ्यास

अधिकार, प्रक्रिया पर बहुत जोर दिया गया था

न्यायाधीशों की नियुक्ति और नियुक्ति के लिए मानदंड। यह था। उन्होंने कहा:

"न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है, यह मुद्दा महत्वपूर्ण है।

दो सम्मान। सबसे पहले, नियुक्ति प्रक्रियाएँ प्रभावित करती हैं।

प्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर

न्यायपालिका। चूंकि किसी की वैधता और विश्वसनीयता न्यायिक संस्थान जनता के विश्वास पर निर्भर करता है कि

स्वतंत्रता, यह अनिवार्य है कि नियुक्ति

न्यायिक कार्यालय के लिए प्रक्रियाएं न्यायिक मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं और उनके अनुरूप देखी जाती हैं।

स्वतंत्रता। यह विसंगत और अस्वीकार्य होगा।
 यदि न्यायालय [मानवाधिकार का यूरोपीय न्यायालय] विफल रहा
 अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों को पूरा करें कि यह है
 आवश्यकता सहित कार्यान्वयन के लिए प्रभारित
 कि मामलों की सुनवाई एक स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा की जाती है
 कानून की अदालत।
 दूसरा, प्रभावी कार्यान्वयन के बिना
 'उचित आधार पर वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी मानदंड
 पेशेवर योग्यता, 'बहुत वास्तविक संभावना है
 कि चयनित न्यायाधीशों के पास अपने जनादेश का निर्वहन करने के लिए आवश्यक कौशल और
 क्षमताएं नहीं होंगी। गिरावट आ रही है।
 मानकों का अंततः स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
 न्यायालय [यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय], साथ ही
 मानवाधिकारों के अनुप्रयोग और विकास पर
 अंतर्राष्ट्रीय और (अंततः) राष्ट्रीय स्तर पर कानून। सर्वोच्च अदालतें-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

345. प्रथम न्यायाधीशों के मामले में,

न्यायपालिका की स्वतंत्रता के अभिन्न अंग के रूप में न्यायाधीशों की नियुक्ति कोई मुद्दा नहीं था, बल्कि
 न्यायमूर्ति वेंकटरमैया थे

इस विचार को व्यक्त किया कि यह मानना मुश्किल है कि यदि

न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका पर छोड़ दी जाती है, इससे कार्य बाधित होगा न्यायपालिका
 की स्वतंत्रता। विद्वान न्यायाधीश थे

यह विचार कि ऐसी नियुक्ति के बाद ही कार्यपालिका को ऐसा करना चाहिए

न्यायाधीश के काम में हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश नहीं है। '340 यह

सम्मान के साथ, दृष्टिकोण बहुत संकीर्ण और संकुचित है। हालाँकि, न्यायमूर्ति डी. ए. देसाई ने एक अलग
 दृष्टिकोण रखा जो व्यक्त किया गया था।

निम्नलिखित शब्दों में:

"अब न्यायपालिका की स्वतंत्रता पूरी तरह से हो सकती है
केवल सुरक्षा प्रदान करके नहीं संरक्षित किया गया
न्यायाधीश अपने कार्यकाल के दौरान लेकिन यह सुनिश्चित करके कि
इसके अलावा जो व्यक्ति स्वतंत्र, ईमानदार और
उच्चतम चरित्र के लोगों को न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जाता है।
इसके अलावा, हमेशा यह डर रहता है कि नियुक्तियाँ छोड़ दी जाएँ
कार्यपालक की नियुक्ति के पूर्ण विवेकाधिकार पर
पार्टी के विचारों से प्रभावित हो सकता है। 341

346. दूसरे न्यायाधीशों के मामले में न्यायमूर्ति पांडियन थे
काफी स्पष्ट और इस विचार को व्यक्त किया कि चयन और
वरिष्ठ के लिए एक उचित और योग्य उम्मीदवार की नियुक्ति
न्यायपालिका न्यायपालिका की स्वतंत्रता से अविभाज्य है
और इसे सुरक्षित करने में एक महत्वपूर्ण शर्त। 342 इसी तरह, न्यायमूर्ति कुलदिप सिंह ने यह भी
कहा कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं हो सकती है
जब न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति के साथ रहता है
कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्वतंत्रता है
'अटूट रूप से जुड़ा हुआ और संवैधानिक रूप से जुड़ा हुआ उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की
नियुक्ति की प्रक्रिया। '343

न्यायमूर्ति वर्मा ने बहुमत की ओर से बोलते हुए यह विचार व्यक्त किया कि सभी संवैधानिक प्राधिकरण इस
प्रक्रिया में शामिल हैं -

340 पैराग्राफ 1033

341 पैराग्राफ 886

342 अनुच्छेद 49

343 पैराग्राफ 335 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति पूरी तरह से जीवित होनी चाहिए।

उनके संवैधानिक दायित्व के गंभीर निहितार्थ और

इसके निर्वहन में उत्साही रहें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई संदिग्ध नियुक्ति नहीं की जा सकती है। '344 विद्वान न्यायाधीश ने आगे कहा

कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाने में राजनीतिक विचार के प्रभाव को रोककर संरक्षित किया जा सकता है

उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति। 345

347. इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि नियुक्ति

उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का एक अभिन्न अंग है।
स्वतंत्रता का हिस्सा। यह संभव नहीं है कि

न्यायपालिका की

विद्वान महान्यायवादी से सहमत हैं जब वे कहते हैं कि

हालांकि न्यायाधीश की नियुक्ति स्वतंत्रता का एक हिस्सा है

न्यायपालिका का, यह एक छोटा सा हिस्सा है और निश्चित रूप से एक नहीं है
कहूंगा कि यह वास्तव में आधारभूत है।

प्रमुख भाग। मैं

न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हिस्सा।

348. शिमोन शेटीट का नियुक्ति पर यह कहना है

न्यायाधीशों के बारे में:

"किसी भी प्रणाली में, नियुक्ति के तरीके सीधे होते हैं

अखंडता और स्वतंत्रता दोनों पर असर डालते हुए

न्यायाधीशों। कमजोर नियुक्तियाँ स्थिति को कम करती हैं

जनता की नजरों में न्यायपालिका और एक माहौल बनाएँ

कमजोर होने की संभावना है। इसी तरह, राजनीतिक नियुक्तियाँ
जिन्हें जनता द्वारा योग्यता के आधार पर नहीं देखा जाता है

न्यायाधीश की स्वतंत्रता के बारे में चिंता पैदा करें और

बेंच पर निष्पक्षता। न्यायपालिका की गुणवत्ता

नियुक्तियाँ नियुक्ति अधिकारियों द्वारा लागू की जाने वाली प्रक्रिया और मानकों पर निर्भर करती हैं,
फिर भी प्रत्येक
प्रणाली की अपनी सीमाएँ हैं। यह मुश्किल है

नियुक्ति

अनुमान लगाएँ कि एक पुरुष या महिला किस तरह का न्यायाधीश होगा और न्यायिक नियुक्तियों में अपरिवर्तनीय गलतियाँ बाध्य हैं

ऐसा तब भी होता है जब नियुक्ति का तरीका उचित हो 344 अनुच्छेद 431

345 पैराग्राफ 447 सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

और कुशल और मानक उच्च हैं, जैसा कि वे हैं

इंग्लैंड। चयन में ऐसी त्रुटियाँ समान रूप से लागू होती हैं -

ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करना जो एक पर कब्जा करने के लिए अयोग्य थे

न्यायिक कार्यालय के साथ-साथ किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने में विफल रहना जो

एक अच्छा न्यायाधीश हो सकता है। " 346

349. अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इस मुद्दे को कैसे देखते हैं?

स्वतंत्रता के सिद्धांतों का बीजिंग वक्तव्य

लावासिया क्षेत्र 347 में न्यायपालिका अन्य बातों के साथ-साथ,

इस प्रकार है:

"न्यायपालिका की स्वतंत्रता की आवश्यकता है कि; क)

न्यायपालिका अपने समक्ष के मामलों का निर्णय इसके अनुसार करेगी -

तथ्यों का इसका निष्पक्ष मूल्यांकन और

अनुचित प्रभावों के बिना कानून की समझ,

प्रत्यक्ष रूप से या समीक्षा के माध्यम से, सभी पर अधिकार क्षेत्र है

न्यायसंगत प्रकृति के मुद्दे। 348

न्यायपालिका को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाना और

अपने कार्यों का पालन करते हुए, यह आवश्यक है कि न्यायाधीशों का चयन किया जाए

न्यायाधीशों की नियुक्ति का तरीका वैसा होना चाहिए जैसा वे करेंगे।

उन व्यक्तियों की नियुक्ति सुनिश्चित करें जो सर्वोत्तम योग्य हैं

न्यायिक कार्यालय के लिए। इसके खिलाफ सुरक्षा उपाय प्रदान करने चाहिए

अनुचित प्रभावों को ध्यान में रखा जा रहा है ताकि केवल

योग्यता, सत्यनिष्ठा और स्वतंत्रता वाले व्यक्ति हैं -
नियुक्त "। 350

इस दस्तावेज़ पर न्यायमूर्ति एस. सी. अग्रवाल ने हस्ताक्षर किए थे।

346 मुकदमे पर न्यायाधीश: अंग्रेजों की स्वतंत्रता और जवाबदेही

न्यायपालिका, अध्याय 4

347 28 अगस्त, 1997 को मनीला में संशोधित किया गया। इसका उल्लेख विशाखा v में किया गया है।
राजस्थान राज्य, (1997) 6 एस. सी. सी. 241 के अनुच्छेद 11 में

रिपोर्ट करें।

346 खंड 3 349 खंड 11

350 खंड 12 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

यह न्यायालय मुख्य न्यायाधीश ए. एम. अहमदी का प्रतिनिधित्व कर रहा है।

350. बेंगलोर न्यायिक आचरण के सिद्धांत, 2002

जो एक न्यायाधीश के लिए छह आवश्यक मूल्य निर्धारित करते हैं (और जो हैं

सिविल कानून और सामान्य कानून दोनों में दुनिया भर में स्वीकार किया गया देश) पूरी तरह से
अव्यवहारिक होगा यदि कोई व्यक्ति नियुक्त किया जाता है

एक न्यायाधीश के रूप में, नियुक्ति के समय, बुनियादी क्षमता का अभाव होता है

और स्वतंत्रता। 351 इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक है कि

अभिनिर्धारित किया जाए और अभिनिर्धारित किया जाए कि नियुक्ति की प्रक्रिया और

उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की वास्तविक नियुक्ति

न्यायालय न्यायपालिका की स्वतंत्रता का एक प्रमुख हिस्सा है और इसलिए, मूल संरचना का एक अभिन्न अंग
है।

संविधान से।

351. अतः नियुक्ति की प्रक्रिया

उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश प्रभावित कर सकते हैं

न्यायपालिका की स्वतंत्रता और इसकी मूल संरचना पर
संविधान।

अनुशंसा प्रक्रिया

352. राष्ट्रपति यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि सबसे अधिक

योग्य व्यक्तियों को न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जाता है या वे हैं

नियुक्ति से इनकार नहीं किया गया? यह है विवाद की जड़

हमारे सामने और यही वह समस्या है जिसने कार्यपालिका को परेशान किया है,

न्यायपालिका, शिक्षाविदों, कानूनी बिरादरी और नागरिक समाज

कई दशकों से। चूंकि न्याय वितरण निस्संदेह है

न्यायपालिका की जिम्मेदारी, इसलिए, न्यायपालिका

(प्रतीक के रूप में यह भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा था) बाध्य है

यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल सबसे योग्य व्यक्तियों पर विचार किया जाए
रूप में नियुक्ति के लिए। 352

न्यायाधीश के

353. किसी व्यक्ति के लिए विचार करने की प्रक्रिया

न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति दोनों से पहले के स्तर पर महत्वपूर्ण है
हैं: स्वतंत्रता, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा, स्वामित्व, समानता, क्षमता और परिश्रम

351 छह मूल्य इस प्रकार

352 इस चर्चा के उद्देश्यों के लिए, इस विवाद में पड़ना आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के लिए विचार किए
जाने वाले व्यक्ति की सिफारिश कार्यपालिका या न्यायपालिका से उत्पन्न होनी चाहिए या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

एक 'कॉलेजियम' का गठन करते हुए अपने सहयोगियों के परामर्श से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जा
रही सिफारिश

और सिफारिश के बाद भी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा कार्यपालिका को भेजा जाता है। दोनों चरणों में,
प्रक्रिया है

अन्य न्यायाधीश और कोई अन्य, यदि आवश्यक समझा जाए। यह
भागीदारी भी शामिल है क्योंकि

इस चरण में कार्यपालिका की

यह इस स्तर पर है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यपालिका से किसी व्यक्ति की कमजोरियों, यदि कोई हो,
के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं जो

कार्यपालिका के पास कुछ होने की स्थिति में मुख्य रूप से कार्यपालिका के साथ सशक्त के लिए किसी विशेष व्यक्ति की नियुक्ति पर आपत्ति

और ठोस कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। 354 इसलिए,

जब किसी व्यक्ति पर न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाता है, तो

के भीतर व्यापक और गहन सहभागी परामर्श है

भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष न्यायपालिका वास्तव में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए एक व्यक्ति की सिफारिश करती है।

सिफारिश की जाती है, उनके बीच परामर्श होता है

एक अधिक सार्थक परामर्श क्या हो सकता है संविधान का अनुच्छेद 124 (2)?

354. यदि किसी व्यक्ति को नियुक्ति के लिए अनुशंसित नहीं किया जाता है

उसकी नियुक्ति का अध्याय उस स्तर पर समाप्त हो जाता है। और, अगर नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की उपयुक्तता के बारे में संवैधानिक अधिकारियों के बीच कोई मतभेद नहीं है

तब, निश्चित रूप से, वारंट जारी करने में कोई बाधा नहीं है

नियुक्ति की।

353 द्वितीय न्यायाधीश मामला, अनुच्छेद 293 और 428 442,450,461,486 और 509 क्यू

354 दूसरा न्यायाधीश मामला, पैराग्राफ

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015] 13.एस सी आर।

355. एक पर विचार करने और स्वीकार करने में कठिनाई

सिफारिश तभी उत्पन्न होती है जब मतभेद हो।

कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच परामर्श के दौरान। विवाद को प्रभावी ढंग से हल करता है।

द्वितीय न्यायाधीश का मामला इस

356. पूर्व-अनुशंसा स्तर पर, यह काफी है

उस व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त होने से अयोग्य ठहराएँ। तब यह सलाहकार के रूप में, यह जानकारी लाने के लिए या

कार्यपालक के लिए, एक

भारत के मुख्य न्यायाधीश के नोटिस के लिए सामग्री। 355 तब से

न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि वह एक

न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त उम्मीदवार, प्रधानता है

न्यायपालिका के दृष्टिकोण (भारत के मुख्य न्यायाधीश के दृष्टिकोण का प्रतीक) को ध्यान में रखते हुए, जो वस्तुनिष्ठ रूप से महत्वपूर्ण होगा।

भारत, अच्छे कारण से, कार्यपालिका के दृष्टिकोण को स्वीकार कर सकता है।
भी, के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर सकता है

या, अच्छे कारण से

कार्यकारी। यह इस अर्थ में है कि 'परामर्श' में हो रहा है

संविधान के अनुच्छेद 124 (2) और अनुच्छेद 217 (1) को

समझ में आया। न्यायपालिका को प्राथमिकता केवल इसी को दी जाती है।

सीमित सीमा तक, लेकिन एक परंतुक के अधीन जिस पर चर्चा की जाएगी
थोड़ी देर बाद।

357. ऐसा क्यों है कि सीमित प्रधानता दी गई है

न्यायपालिका? कि न्यायपालिका लेने के लिए सबसे उपयुक्त है

निर्णय लें कि किसी व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त किया जाना चाहिए या नहीं

यह संविधान के अनुच्छेद 124 (2) और अनुच्छेद 217 (1) में निहित है।

संविधान के अनुच्छेद 124 (2) में राष्ट्रपति को अनिवार्य किया गया है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश और ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करना

उच्चतम न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालयों के रूप में

355 दूसरे न्यायाधीशों का मामला पैराग्राफ 462 और 478 (6)

356 दूसरे न्यायाधीशों का मामला पैराग्राफ 467, 468 और 478 (6)

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

राष्ट्रपति आवश्यक समझ सकते हैं। 'कि राष्ट्रपति कर सकते हैं
व्यक्तियों से परामर्श करने का विकल्प चुनें या

कानूनी विरादरी के प्रतिष्ठित

नागरिक समाज एक और मामला है, लेकिन राष्ट्रपति की आवश्यकता नहीं है

ऐसा करने के लिए। इसका एक संभावित कारण यह हो सकता है कि

संविधान निर्माताओं की राय थी कि अंततः क्या है

न्यायाधीशों की राय महत्वपूर्ण है और जरूरी नहीं कि दूसरों की राय हो।

इसी तरह, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए

संविधान के अनुच्छेद 217 (1) के अनुसार राष्ट्रपति को

भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करें-फिर से किसी से नहीं।

अन्यथा कानूनी विरादरी या नागरिक समाज से।

358. इसी तरह राजनीतिक दलों को सीमित प्राथमिकता दी जाती है।

कार्यकारी। यदि न्यायपालिका सर्वसम्मति से निर्णय नहीं लेती है

न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए सिफारिश

उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति के लिए हकदार है

सिफारिश को ठुकरा दें। लेकिन अगर सिफारिश है

सर्वसम्मत लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौट आया

और उसके बाद न्यायपालिका द्वारा सर्वसम्मति से दोहराया गया, फिर
के निर्णय से बंधी होती है और उसे तदनुसार राष्ट्रपति को सलाह देनी चाहिए।

मंत्रिपरिषद् न्यायपालिका

359. चूंकि संविधान एक लचीला दस्तावेज है, न ही

राष्ट्रपति और न ही भारत के मुख्य न्यायाधीश को इससे बाहर रखा गया है
सामान्य या पेशेवर की सलाह लेना। वास्तव में,

किसी भी व्यक्ति,

न्यायमूर्ति वर्मा ने इस संबंध में एक साक्षात्कार में कहा:

"क्या आप इस बात पर प्रकाश डाल सकते हैं कि आपके कार्यकाल के दौरान कैसे

सीजेआई, नियुक्तियाँ हुईं?

सुप्रीम कोर्ट में हर नियुक्ति के लिए मैंने वरिष्ठ से परामर्श किया

फली एस. नरीमन और शांति भूषण जैसे वकील। मैंने इस्तेमाल किया।

पाँच या छह शीर्ष वकीलों से परामर्श करना। मैं मध्यम स्तर के वकीलों से भी सलाह लेता था। इसी तरह का परामर्श

उच्च न्यायालयों के मामले में हुआ। मैंने विवरण दर्ज किया

हर परामर्श के लिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा सारा पत्राचार

सार्वजनिक किया गया। नियुक्ति के बाद, यह सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट क्यों होनी चाहिए?

[2015] 13 एस सी आर।

सीक्रेट? यदि न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का कोई उचित कारण है,

तब कम से कम अब भी लोग उन पर संदेह करते हैं

वहाँ नहीं होगा। और अगर कोई अच्छा कारण है कि उन्हें नियुक्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए था, तो यह खुलासा करेगा
उनके लिए जिम्मेदार थे जो लोग

नियुक्ति "। 357

360. यह संविधान की व्यावहारिक व्याख्या है।

जिसे संविधान सभा द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था, जिसने
दस्तावेज़ में हर विवरण भरने की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं,
वास्तव में ऐसा करना संभव नहीं था।

361. पाठ पर चर्चा को एक तरफ छोड़ते हुए

संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या और

संविधान सभा बहस करती है, एक संवैधानिक सम्मेलन है

स्वीकार करने के पिछले सात दशकों से अधिक समय में विकसित

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश की राय। यह संवैधानिक सम्मेलन

अस्तित्व में है, यदि भारत सरकार के दिनों से नहीं

अधिनियम, 1919 तब निश्चित रूप से सरकार के दिनों से

भारत अधिनियम, 1935। यह संवैधानिक सम्मेलन किया गया है

द्वितीय न्यायाधीशों के मामले में न्यायमूर्ति कुलदिप सिंह द्वारा पूरी तरह से निपटा गया और यह निष्कर्ष निकाला गया कि एक संवैधानिक

कन्वेंशन संवैधानिक कानून की तरह ही बाध्यकारी है। 358 जो भी हो,

संवैधानिक परंपरा को त्यागने का कोई ठोस कारण नहीं है

राजस्थान राज्य बनाम में मुख्य न्यायाधीश बेग की टिप्पणी। संघ
संवैधानिक अभ्यास और परंपरा

भारत का 359 वह: '.....

संवैधानिक के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ या जुड़ा हुआ होना

प्रावधान और अक्सर समझने के लिए इतने महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण होते हैं

संवैधानिक प्रावधानों का वास्तविक उद्देश्य और कार्य जिसे दोनों को अक्सर अलग नहीं देखा जा सकता है।
ठीक यही बात है

वर्तमान मामले में हुआ है जहाँ संवैधानिक

357 अग्रिम पंक्ति, खंड 25-अंक 20: 27 सितंबर-10 अक्टूबर, 2008 358 दूसरे न्यायाधीशों का मामला पैरा
353 और 376

359 (1977) 3 एस. सी. सी. 592 पैराग्राफ 56 सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन v.
यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

सम्मेलनों और प्रथाओं इस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं

संवैधानिक प्रावधान हैं कि उन्हें अलग करना मुश्किल है।

362. यह संवैधानिक व्याख्या है और

संवैधानिक परिपाटी जिसके परिणामस्वरूप बाध्यकारी होता है

कार्यपालिका पर भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश

जिस पर विद्वान महान्यायवादी द्वारा आपत्ति की जाती है

संविधान के विपरीत जैसा कि बनाया गया है और यह वही है जिसकी मांग की जाती है 99 वें
संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 'सुधार' किया जाएगा।

363. इस मुद्दे को एक और दृष्टिकोण से देखा जा सकता है।

यह मानते हुए कि कार्यपालिका की सिफारिश को अस्वीकार कर देता है

सर्वसम्मति से दोहराने के बाद भी भारत के मुख्य न्यायाधीश ने क्या कहा

क्या पैदा हुए गतिरोध का समाधान है? इसका जवाब है -

समशेर सिंह में पाया जाता है और संकल्पचंद्र में दोहराया जाता है शेट। समशेर सिंह में यह
आयोजित किया गया था कि इस तरह की घटना में कार्यपालिका का निर्णय न्यायिक जांच के लिए खुला है।
यह था।

उन्होंने कहा:

"सभी संभावित मामलों में उस उच्चतम के साथ परामर्श करें

भारतीय न्याय के गणमान्य व्यक्ति द्वारा स्वीकार किया जाएगा और किया जाना चाहिए

भारत सरकार और न्यायालय के पास होगा

जाँचने का अवसर कि क्या कोई अन्य बाहरी है

परिस्थितियों ने निर्णय में प्रवेश किया है

मंत्री, यदि वह प्रमुख द्वारा दी गई सलाह से अलग हो जाता है

जस्टिस ऑफ इंडिया "। 360

इस विचार को संकल्पचंद सेठ में दोहराया गया था। 361 में से

बेशक, यह एक और बात है कि किसी को भी ऐसा होने का अधिकार नहीं है

मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से न्यायपालिका की सिफारिश
नहीं किया जाता है, अगर कुछ और नहीं तो कम से कम

भारत को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार

रिकॉर्ड को सीधा रखा जाएगा और संभावित नुकसान होगा

उस व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा और सम्मान जो
बहाल किया जाएगा,

भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अनुशंसित को

360 अनुच्छेद 149

361 पैराग्राफ 41 [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कम से कम कुछ हद तक।

364. लेकिन क्या न्यायिक समीक्षा अनिवार्य रूप से इसका एकमात्र जवाब है?

इस तरह की समस्या? क्या कार्यपालिका और न्यायपालिका को

न्यायाधीश की नियुक्ति में कभी टकराव के रास्ते पर रहे हैं?

डॉ. अम्बेडकर ने न केवल यह सोचा था कि ऐसी स्थिति नहीं आएगी।

ऐसा होता है, उन्होंने इसकी कल्पना कभी नहीं की। डॉ. अम्बेडकर ने गतिरोध या गतिरोध को छोड़कर
लगभग हर आकस्मिकता के लिए प्रावधान किया।

स्थिति-उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह की संभावना होगी
कभी उठती है।

365. कि कोई अंतर या थोड़ा अंतर नहीं होगा

मामले में एक अंतिम कहना ताकि परामर्श न किया जाए
तथ्य से काफी स्पष्ट है कि

प्रक्रिया एक मात्र औपचारिकता है, इस

संविधान सभा ने जानबूझकर एक अंतर निकाला

राष्ट्रपति द्वारा किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के बीच

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश (एक ओर)
के अध्यक्ष द्वारा नियुक्ति

और अन्य संवैधानिक संस्थाओं

अधिकारीगण। एक न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए, यह अनिवार्य है

संविधान कि राष्ट्रपति को प्रमुख से परामर्श करना चाहिए

भारत का न्याय। तथापि, नियंत्रक की नियुक्ति करना और

संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत महालेखा परीक्षक (के लिए

उदाहरण के लिए); राष्ट्रपति पर परामर्श करने का कोई दायित्व नहीं है।
महत्व का हो। डॉ. अम्बेडकर ने इस संबंध में कहा था:

भले ही पद महत्वपूर्ण

"मैं यह नहीं कह सकता कि मैं इस पद को लेकर बहुत खुश हूँ।

संविधान का मसौदा, जिसमें वे संशोधन भी शामिल हैं जो लेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेदों में
स्थानांतरित किए गए हैं

इस सदन में जनरल, उसे नियुक्त करता है। व्यक्तिगत रूप से

अपने लिए बोलते हुए, मेरी राय है कि यह गणमान्य या अधिकारी शायद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी
है

भारत का संविधान। वह एक आदमी है जो जा रहा है

देखें कि संसद द्वारा मतदान किए गए खर्च नहीं हैं

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं द्वारा निर्धारित से अधिक, या भिन्न-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

संसद जिसे विनियोग अधिनियम कहा जाता है। अगर यह पदाधिकारी को अपने कर्तव्यों और कर्तव्यों का पालन करना है, प्रस्तुत करें, कर्तव्यों से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं न्यायपालिका-उन्हें निश्चित रूप से होना चाहिए था न्यायपालिका के रूप में स्वतंत्र। लेकिन, लेखों की तुलना उच्चतम न्यायालय और उससे संबंधित लेखों के बारे में महालेखा परीक्षक, मैं यह कहने से बच नहीं सकता कि हमने नहीं किया है। उसे वही स्वतंत्रता दी जो हमने दी है। न्यायपालिका के लिए, हालांकि मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि उन्हें ऐसा करना चाहिए न्यायपालिका की तुलना में कहीं अधिक स्वतंत्रता होना

स्वयं "362

इसी तरह, मुख्य चुनाव की नियुक्ति अनुच्छेद के तहत आयुक्त और चुनाव आयुक्त 324 संविधान में राष्ट्रपति से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है कोई भी, भले ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव निस्संदेह हैं यह हमारे लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। चूंकि परामर्श का प्रावधान था केवल न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निगमित, निश्चित रूप से, संविधान सभा के पास ऐसा करने के अच्छे कारण थे भेद करते हैं। न्यायमूर्ति खेहर ने अन्य राष्ट्रपतियों का भी उल्लेख किया है उनके मसौदा निर्णय में नियुक्तियाँ और यह आवश्यक नहीं है कि उन्हें दोहराएँ: महत्वपूर्ण बात यह है कि 'संदेश' की तलाश की गई है संविधान सभा द्वारा प्रेषित और दी गई पवित्रता भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा एक सिफारिश के लिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति।

366. यह सामान्य बात है कि संविधान एक जीवित दस्तावेज है। 363

इसे ध्यान में रखते हुए, क्या यह कहा जा सकता है कि एक तनावग्रस्त अनुच्छेद 124 (2) और

217 (1) संविधान का विशेष रूप से जब प्रतिस्थापन

'अनुच्छेद 124 के मसौदे में 'सहमति' के साथ परामर्श किया गया था

संविधान सभा में चर्चा की गई और स्वीकार नहीं किया गया? 364

निश्चित रूप से नहीं, विशेष रूप से यदि कोई उस संदर्भ को देखता है जिसमें

362 एचटीटीपी: //भारत की संसद। ठीक है। इन/एलएस/डिबेट/वॉल्यूम 8 पी11 ए। एच. टी. एम. 353 आई. आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य, (2007) 2 एस. सी. सी. 1 अनुच्छेद 42 364 फुट नोट 16 [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

'परामर्श' का उपयोग किया जाता है और जिस उद्देश्य के लिए इसका उपयोग किया जाता है, अर्थात्, राष्ट्रपति के विवेक को किसी के द्वारा बाधित करना।

कौन जानता है कि न्यायपालिका के सर्वोत्तम हित में क्या है।

367. लेकिन, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, प्रक्रिया की शुद्धता या अन्यथा पर विस्तार से ध्यान देना आवश्यक नहीं है।

द्वितीय में निर्धारित न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए

न्यायाधीशों का मामला और तीसरे न्यायाधीशों का मामला। सच में सवाल

क्या न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है

यह संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है। क्या हो सकता है? न्यायपालिका स्वतंत्र हो यदि नियुक्ति प्रक्रिया में है

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के हाथ?

अनुच्छेद 368 के माध्यम से संविधान का संशोधन

368. इस आधार पर कार्यवाही करना, जैसा कि हमें करना चाहिए, कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता मूल संरचना का एक हिस्सा है

संविधान, और यह कि एक न्यायाधीश की नियुक्ति

यह उत्पन्न होता है कि नियुक्ति प्रक्रिया किस हद तक हो सकती है संसद द्वारा छेड़छाड़ की जाए।

369. संविधान के अनुच्छेद 368 में प्रावधान है -

'संविधान और प्रक्रिया में संशोधन करने की संसद की शक्ति

इसके लिए '। जबकि शक्ति विशाल है, संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान को जोड़ने, बदलने या निरस्त करने का अधिकार देता है,

उस शक्ति की अंतर्निहित सीमाएँ हैं जैसा कि में समझाया गया है

केशवानंद भारती जो कि मूल संरचना है

इस न्यायालय और लोकतंत्र (उदाहरण के लिए) के कई फैसलों में संविधान की संरचना पर विचार किया गया है। और निष्पक्ष चुनाव या विधायी कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा या

विधानमंडल के बीच शक्तियों का पृथक्करण (या वितरण),

कार्यपालिका और न्यायपालिका सभी को एक हिस्सा माना गया है

संविधान की मूल संरचना। इसमें कोई संदेह नहीं है,

और किसी ने भी इस बात पर विवाद नहीं किया है कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन v.

यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

न्यायपालिका भी संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है।

370. संशोधन के लिए संवैधानिक आवश्यकता

संविधान है: (क) संशोधन केवल इसके द्वारा शुरू किया जा सकता है -

इस उद्देश्य के लिए एक विधेयक पेश करना;

(ख) विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।

(ग) विधेयक को प्रत्येक सदन में बहुमत से पारित किया जाना चाहिए।

उस सदन की कुल सदस्यता और नहीं के बहुमत से

उस सदन के दो-तिहाई से कम सदस्य उपस्थित होते हैं और

मतदान; (घ) विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो

विधेयक को अपनी सहमति देगा और उसके बाद संविधान

उस विधेयक की शर्तों के अनुसार संशोधन किया जाएगा।

371. संविधान के अनुच्छेद 368 में एक प्रावधान है।

और वर्तमान प्रयोजनों के लिए, आगे की आवश्यकता यह है कि यदि ऐसा संशोधन के अध्याय IV में कोई परिवर्तन करना चाहता है। भाग 5 (संघ न्यायपालिका) और भाग 6 का अध्याय 5 (

राज्यों में उच्च न्यायालय) 'संशोधन' की भी आवश्यकता होगी

राज्यों के विधानमंडलों द्वारा संकल्प द्वारा अनुसमर्थन किया जाना विधेयक बनाने से पहले उन विधानमंडलों द्वारा पारित किया गया प्रभाव

इस तरह के संशोधन के लिए प्रावधान राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है।

सहमति के लिए। '

372. जहाँ तक संविधान की बात है (एक सौ बीस)

प्रथम संशोधन) विधेयक, 2014 का संबंध है, इसमें कोई संदेह नहीं है या

विवाद है कि ऊपर वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया था और

31 दिसंबर, 2014 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। उस हद तक संविधान (नब्बे-नौवां) संशोधन

अधिनियम, 2014 एक प्रक्रियात्मक रूप से वैध विधान है।

संविधान में संशोधन की सीमाएँ

373. निहित सीमाओं की सराहना करने के लिए

संविधान में संशोधन के संबंध में संसद, यह

में बहुमत बनाने वाले विचारों पर विचार करना आवश्यक है

केशवानंद भारती। उस मामले में, इससे पहले का सवाल सीकरी द्वारा बनाया गया था) था:

न्यायालय (जैसा कि मुख्य न्यायाधीश

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर. की सीमा क्या है?

के अनुच्छेद 368 द्वारा प्रदत्त संशोधन शक्ति का

संसद पर अनुच्छेद 13 (2) के अलावा संविधान?

374. विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने नोट किया कि शब्द

'संविधान में 'संशोधन' को परिभाषित नहीं किया गया है। कुछ में

संविधान के प्रावधानों का एक संकीर्ण अर्थ है, जबकि

अन्य प्रावधानों में इसका एक विस्तृत अर्थ है। यह दृश्य

न्यायमूर्ति शेलत और न्यायमूर्ति ग्रोवर ने भी व्यक्त किया था,

जिन्होंने देखा कि 'संशोधन' और 'संशोधन' शब्द हैं

विभिन्न प्रावधानों में अलग-अलग अर्थ व्यक्त करने के लिए उपयोग किया गया

संविधान से। कुछ लेखों में ये शब्द संकीर्ण हैं।

जबकि अन्य में अर्थ बहुत बड़ा या व्यापक है।

यह शब्द सटीक महत्व का नहीं है और इसका उपयोग नहीं किया गया है।

संविधान के विभिन्न प्रावधानों में एक ही बात व्यक्त करने के लिए अर्थ। इसका कुछ महत्व है क्योंकि यह इसी आधार पर है।

कि इस न्यायालय ने शब्दों की व्याख्या करने के लिए सीएडी को संदर्भित किया

'संशोधन 'और' संशोधन '।

375. के विभिन्न प्रावधानों को पढ़ने पर

अनुच्छेद में आने वाली अभिव्यक्ति 'इस संविधान का संशोधन' 368 बिनि ओंथिया जायखिजाया दाजाबदेरनाय एबा सोलायनाय जागोन।

संविधान के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रस्तावना और संविधान की व्यापक रूप रेखा के भीतर 'संविधान का प्रावधान

प्रस्तावना और निर्देशक सिद्धांत। इसके लिए आवेदन किया गया

मौलिक अधिकार, इसका मतलब यह होगा कि जबकि मौलिक अधिकार

निरस्त नहीं किया जा सकता है, मौलिक के उचित संक्षिप्त अधिकारों को जनहित में प्रभावित किया जा सकता है। '365 इस संदर्भ में,

विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने सार्वभौमिक घोषणा का उल्लेख किया मानवाधिकारों का यह निष्कर्ष निकालना कि व्यक्तियों के कुछ अधिकार अपरिहार्य हैं। 366

365 अनुच्छेद 287

360 यू. डी. एच. आर. का अनुच्छेद 8 और 10 इस संबंध में प्रासंगिक हैं:

अनुच्छेद 8: प्रत्येक व्यक्ति को संविधान या कानून द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कार्यों के लिए सक्षम राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों द्वारा एक प्रभावी उपचार का अधिकार है। अनुच्छेद

10: प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों और दायित्वों और अपने खिलाफ किसी भी आपराधिक आरोप के निर्धारण में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायाधिकरण द्वारा निष्पक्ष और सार्वजनिक सुनवाई का पूर्ण समानता से अधिकार है।

सर्वोच्च अदालतें-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

376. विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला,
 अन्य बातों के साथ:
 "अभिव्यक्ति "इस संविधान का संशोधन" करता है
 संसद को निरस्त करने या हटाने में सक्षम नहीं बनाना
 मौलिक अधिकार या पूरी तरह से बदलने के लिए
 संविधान की मूलभूत विशेषताएँ ताकि इसे नष्ट किया जा सके
 उसकी पहचान। इन सीमाओं के भीतर संसद संशोधन कर सकती है।

हर लेख "। 367
 न्यायमूर्ति ग्रीवर ने पाठ को देखा।

377. न्यायमूर्ति शेलट और

अनुच्छेद 368 का, जो 24 वें द्वारा इसके संशोधन से पहले था।
 संविधान संशोधन अधिनियम और यह पाया गया कि यह आंतरिक है
 यह सुझाव देने के लिए साक्ष्य कि संसद की संशोधन शक्ति
 इसका उपयोग संविधान को अपना चरित्र खोने के लिए किया जाए या प्रकृति या पहचान और
 इसका प्रयोग इसके भीतर किया जाना चाहिए
 संविधान की रूपरेखा। यह देखा गया कि संशोधन की असीमित शक्ति अस्तित्व के लिए अनुकूल नहीं हो
 सकती है।

संविधान। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि -

" "इसका संशोधन" शब्दों का अर्थ
 संविधान "जैसा कि अनुच्छेद 368 में उपयोग किया गया है ऐसा होना चाहिए जो

प्रस्तावना, संविधान की पूरी योजना, इसकी
 संरचना और ढांचा और आंतरिक साक्ष्य

अनुच्छेद 368 सहित विभिन्न अनुच्छेद। यह संभव भी नहीं है।
 इसे एक संकीर्ण अर्थ देने के लिए और न ही इतना व्यापक अर्थ हो सकता है

दिया जाए जो संशोधन निकाय को बदलने में सक्षम बना सके
 काफी हद तक या पूरी तरह से संरचना और पहचान

संविधान "। 368

378. न्यायमूर्ति हेगड़े और न्यायमूर्ति मुखर्जी ने कहा कि
 अनुच्छेद 368 की व्याख्या संकीर्ण और पांडित्यपूर्ण तरीके से नहीं की जा सकती है।

367 अनुच्छेद 475

368 पैराग्राफ 546 [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लेकिन एक व्यापक और उदार व्याख्या दी जानी चाहिए। यह.

यह देखा गया कि 'संशोधन' शब्द का कोई सटीक अर्थ नहीं है और यह एक 'रंगहीन' शब्द है। वास्तव में, शब्द

'संविधान में 'संशोधन' और 'संशोधन' का उपयोग किया गया है

अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग अर्थों के साथ। इसके बावजूद

यह, विद्वान न्यायाधीशों का विचार था कि

ये अभिव्यक्तियाँ उतनी विस्तृत नहीं हो सकतीं जितनी कि सक्षम कर सकें।

संसद तब से संविधान के 'व्यक्तित्व' को बदलेगी
बढ़ती है कि

इसकी योजना और संरचना इस आधार पर आगे

कुछ बुनियादी विशेषताएं जो स्थायी होने की उम्मीद है। इसलिए, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करने की
शक्ति

संविधान निहित सीमाओं के अधीन है।

379. इन सभी कारकों पर विचार करने के बाद, विद्वान

न्यायाधीशों ने निष्कर्ष निकाला कि:

"के विभिन्न पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर

मामले में, हम आश्वस्त हैं कि संसद के पास कोई शक्ति नहीं है

मूल तत्वों को निरस्त करना या समाप्त करना या
संविधान की मूलभूत विशेषताएं जैसे कि भारत की संप्रभुता, हमारे देश का लोकतांत्रिक चरित्र।

राजनीति, देश की एकता, इसकी आवश्यक विशेषताएँ

नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रताएँ दी गई हैं।

संसद को निर्माण के लिए जनादेश को रद्द करने की शक्ति

एक कल्याणकारी राज्य और समतावादी समाज। ये सीमाएँ

ये केवल उदाहरणात्मक हैं और संपूर्ण नहीं हैं। इसके बावजूद
सीमाएँ, हालांकि, कोई सवाल नहीं हो सकता है कि

संशोधन की शक्ति एक व्यापक शक्ति है और यह हर किसी तक पहुँचती है।
 अनुच्छेद और संविधान का हर भाग। यह शक्ति हो सकती है
 दायित्व को पूरा करने के लिए संविधान को नया रूप देने के लिए उपयोग किया जाए
 राज्य पर थोपा गया। इसका उपयोग आकार बदलने के लिए भी किया जा सकता है
 संविधान को पहले उल्लिखित सीमाओं के भीतर, बनाने के लिए
 यह सामाजिक भलाई के लिए एक प्रभावी साधन है। हम असमर्थ हैं।
 इस तर्क से सहमत होना कि कल्याण का निर्माण करने के लिए

बता दें, कुछ मानव सर्वोच्च न्यायालय अधिवक्ताओं-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन v को नष्ट करना आवश्यक है। यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

स्वतंत्रताएँ। कि, किसी भी तरह से हमारा दृष्टिकोण नहीं है

संविधान "। 369

380. न्यायमूर्ति खन्ना ने मूल संरचना पर ध्यान केंद्रित किया

संविधान और यह विचार व्यक्त किया कि 'संशोधन'

इसकी पहचान और मूल संरचना या ढांचे का प्रतिधारण 'पुराना' संविधान। यह आयोजित किया गया था:

"यद्यपि इसकी शक्ति के तहत अनुमति है

परिवर्तनों को प्रभावी बनाने के लिए संशोधन, चाहे कितना भी महत्वपूर्ण हो, और

प्रणाली को परिवर्तन की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने के लिए

"संविधान का संशोधन "अपने व्यापक विस्तार के साथ"

और आयाम का मूल संरचना या ढांचे को नष्ट करने या निरस्त करने का प्रभाव नहीं हो सकता है

संविधान। "

381. इसके बाद, न्यायमूर्ति खन्ना ने आवश्यकता से बहुत आगे की यात्रा की और कहा कि जब तक मूल संरचना है

संबंधित लेखों सहित विभिन्न अनुच्छेदों को बदलें या निरस्त करें
 तर्क कुछ समय बाद दिया गया था।

मौलिक अधिकार '। इसके लिए

निर्णय में निम्नलिखित शब्दों में:

"अनुच्छेद 368 में "संशोधन" शब्द का उल्लेख होना चाहिए -
समान अर्थ चाहे संशोधन के भाग III में मौलिक अधिकारों को छीनने या संक्षिप्त करने से संबंधित हो

संविधान या क्या यह किसी अन्य प्रावधान से संबंधित है
संविधान के भाग III के बाहर। कोई गंभीर आपत्ति नहीं

शक्ति के तहत भाग III के प्रावधानों के अलावा संविधान के प्रावधानों को निरस्त करने, जोड़ने या बदलने के लिए लिया जाता है

अनुच्छेद 368 द्वारा प्रदत्त संशोधन। यही दृष्टिकोण, मेरी राय में, अच्छा होना चाहिए जब हम सौदा करते हैं

369 अनुच्छेद 666 [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निहित मौलिक अधिकारों से संबंधित संशोधन के साथ

संविधान के भाग III में। यह अस्वीकार्य होगा कि

शक्ति के दायरे और चौड़ाई के बीच अंतर करें

संशोधन जब यह मौलिक अधिकार से संबंधित हो, और उस शक्ति का दायरा और चौड़ाई जब यह संबंधित हो

मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान नहीं। 370

382. न्यायमूर्ति खन्ना द्वारा लिए गए निष्कर्ष में कहा गया है

विद्वान न्यायाधीश द्वारा निम्नलिखित शब्दों में:

"अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की शक्ति नहीं है।

संविधान को निरस्त करने की शक्ति शामिल करें और न ही

इसमें मूल संरचना को बदलने की शक्ति शामिल है या

संविधान की रूपरेखा के प्रतिधारण के अधीन

संविधान की मूल संरचना या ढांचा,

संशोधन की शक्ति पूर्ण है और इसमें शामिल है

के विभिन्न अनुच्छेदों में संशोधन करने की शक्ति

मौलिक अधिकारों से संबंधित संविधान सहित

साथ ही जिन्हें आवश्यक से संबंधित कहा जा सकता है

विशेषताएँ। मौलिक अधिकार का कोई भी हिस्सा दावा नहीं कर सकता है

संशोधित प्रक्रिया से प्रतिरक्षा का वर्णन किया जा रहा है

उस अधिकार के सार या मूल के रूप में। संशोधन की शक्ति में अपने भीतर यह शक्ति भी शामिल होगी कि विभिन्न अनुच्छेदों को जोड़ें, बदलें या निरस्त करें। 371

383. यह उल्लेख किया जा सकता है कि उपरोक्त

न्यायमूर्ति खन्ना द्वारा व्यक्त किए गए विचार ने बहुत कुछ उत्पन्न किया

विवाद। यह इंदिरा में विद्वान न्यायाधीश द्वारा कहा गया था।

नेहरू गाँधी और इसे पैराग्राफ 251 में स्पष्ट किया गया था और

संशोधन शक्ति की सीमा के संदर्भ में न कि संविधान की मूल संरचना का संदर्भ। विद्वान।

न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि मौलिक अधिकार संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा थे लेकिन संपत्ति का अधिकार नहीं था। 372

370 पैरा 1435

371 पैराग्राफ 1537

372 पैराग्राफ 251 और 252। न्यायमूर्ति भगवती ने मिनर्वा मिल्स बनाम में भी इसका विज्ञापन किया है। भारत संघ, (1980) 3 एस. सी. सी. 625।

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

384. सरल शब्दों में कहें तो केशवानंद भारती में निर्णय का योग और सार यह है कि उसने स्वीकार किया कि

संविधान की एक बुनियादी संरचना है और यह कि

किसी भी संदेह और चूंकि पीठ का गठन करने वाले तेरह न्यायाधीशों द्वारा नौ निर्णय दिए गए थे, निष्कर्षों का सारांश तैयार किया गया था। यह सारांश था

तेरह न्यायाधीशों में से नौ ने हस्ताक्षर किए। नौ में से अल्पमत में थे।

हस्ताक्षरकर्ता दो विद्वान न्यायाधीश थे जो

नौ विद्वान न्यायाधीशों द्वारा सहमत निष्कर्षों में से एक अनुच्छेद 368 सक्षम नहीं करता है

सारांश पर हस्ताक्षर करने वाला था: '

संसद की मूल संरचना या ढांचे को बदलने के लिए

संविधान '।

संविधान में संशोधन की न्यायिक समीक्षा

385. इंदिरा नेहरू गाँधी में यह माना गया था कि संविधान में संशोधन को केवल इस पर चुनौती दी जा सकती है -

विधायिका द्वारा अपनी विधायी क्षमता से परे पारित किया गया या यदि यह संविधान के अनुच्छेद 13 का उल्लंघन करता है। 373

373 13. मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनके अपमान में कानून (1) भारत के क्षेत्र में लागू सभी कानून

इस संविधान का प्रारंभ, जहाँ तक वे इस भाग के प्रावधानों के साथ असंगत हैं, ऐसी असंगति की सीमा तक शून्य होगा। (2) राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीन ले या कम कर दे और इस खंड का उल्लंघन करते हुए बनाई गई कोई विधि, उल्लंघन की सीमा तक, शून्य होगी।

(3) इस लेख में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो,

-

(क) "कानून" में कोई भी अध्यादेश, आदेश, उप-कानून, नियम, विनियमन, अधिसूचना, प्रथा या उपयोग शामिल है जिसका भारत के क्षेत्र में कानून का बल है;

(ख) "प्रवृत्त विधियों" में इस संविधान के प्रारंभ से पहले भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित या बनाए गए कानून शामिल हैं और जो पहले निरस्त नहीं किए गए थे, इसके बावजूद कि ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग तब बिल्कुल भी या विशेष क्षेत्रों में लागू नहीं हो सकता है।

(4) इस अनुच्छेद में कुछ भी अनुच्छेद 368 के तहत किए गए इस संविधान के किसी भी संशोधन पर लागू नहीं होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

"संवैधानिक संशोधन, के अनुपात पर हो सकता है

मौलिक अधिकार मामला, 374 का परीक्षण किया जाए

बुनियादी संरचना। लेकिन इस सिद्धांत के अलावा कि एक मामला यह केवल एक प्राधिकरण है जो यह तय करता है, यह तार्किक रूप से नहीं है

मौलिक में बहुमत के फैसले का पालन करें

संवैधानिक संशोधन के रूप में एक ही परीक्षण। सामान्य। कानूनों को अपनी वैधता के लिए दो परीक्षणों का जवाब देना होता है: (1) द.

कानून की विधायी क्षमता के भीतर होना चाहिए

संविधान के अध्याय 1, भाग 11 में परिभाषित और निर्दिष्ट विधानमंडल, और (2) इसके खिलाफ अपराध नहीं करना चाहिए

संविधान के अनुच्छेद 13 (1) और (2) के प्रावधान।
"बुनियादी संरचना", बहुमत के फैसले से, एक हिस्सा नहीं है।

मौलिक अधिकारों का और न ही वास्तव में कोई प्रावधान

संविधान और संशोधन के संदर्भ में
शक्ति इसके अधीन है क्योंकि यह एक घटक शक्ति है।

इसकी आवश्यक विशेषताओं को नष्ट करने की शक्ति अपने साथ रखें।
यह, संक्षेप में, मूल संरचना के सिद्धांत का कमान है। यह.

वैधता से संबंधित मामलों में पूरी तरह से जगह से बाहर है
संविधान के तहत बनाए गए सामान्य कानून।

386. कर्नाटक राज्य बनाम में भी ऐसा ही दृष्टिकोण लिया गया था।

भारत संघ 375 जिसमें इंदिरा से उपरोक्त मार्ग है

नेहरू गाँधी को अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था। यह कहा गया था कि

जस्टिस उन्नतवालिआ अपने लिए एक सहमति वाले फैसले में, जस्टिस सिंघाल और न्यायमूर्ति जसवंत सिंह:

"श्री सिन्हा ने यह भी तर्क दिया कि एक साधारण कानून ऐसा नहीं कर सकता है
मूल योजना या मूल योजना के खिलाफ जाएं।

संविधान में निहित केंद्र-राज्य संबंधों की रीढ़। उन्होंने इस संबंध में अपना तर्क दिया
एक बहुत ही सरल तरीका क्योंकि उन्हें रखने में कठिनाई महसूस हुई

374 केशवानंद भारती 375 (1977) 4 एस. सी. सी. 608 अनुच्छेद 238 (सात न्यायाधीशों की पीठ)

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

यह सीधे तरीके से यह कहते हुए कि एक साधारण कानून नहीं कर सकता है

संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है। मामले में
श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी बनाम। श्री राज नारायण ऐसे

इस अदालत ने तर्क को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया था। हम कर सकते हैं

निर्णय के एक अंश का उल्लेख करके शेष सामग्री

हमारे विद्वान भाई चंद्रचूड, जे.

इस प्रकार।

387. कुलदिप नायर बनाम। भारत संघ 376 ए संविधान

पीठ ने उपरोक्त विचार को निम्नलिखित शब्दों में दोहराया:

अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है
मूल के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी जाए

संविधान की संरचना। एक सामान्य कानून
इतनी चुनौती नहीं दी जा सकती। बनाए गए कानून को चुनौती,

अपनी विधायी क्षमता के भीतर, संसद द्वारा

मूल संरचना के उल्लंघन का आधार
इस प्रकार संविधान याचिकाकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है।

388. अंत में, अशोक कुमार ठाकुर बनाम। संघ का

भारत 377 यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक कानून को चुनौती दी जा सकती है यदि यह एक का
उल्लंघन करता है

संविधान का प्रावधान लेकिन एक संशोधन

संविधान को तभी चुनौती दी जा सकती है जब यह किसी बुनियादी विशेषता का उल्लंघन करता हो।

संविधान जो इसकी मूल संरचना का एक हिस्सा है। यह था।

आयोजित:

"यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई विशेष विशेषता है
संविधान मूल संरचना का हिस्सा है या नहीं, इसे होना चाहिए

संविधान की योजना, उसके उद्देश्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में
जांच की जाएगी।

और एक मौलिक के रूप में संविधान की अखंडता
देश के शासन के लिए साधन। यह देखा जा सकता है

कि यह सामान्य कानूनों को चुनौती देने के लिए खुला नहीं है

376 (1996) 7 एस. सी. सी. 1 पैरा 107 (पाँच न्यायाधीशों की पीठ) 377 (2008) 6 एस. सी. सी. 1 पैरा
116 (पाँच न्यायाधीशों की पीठ)

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मूल संरचना सिद्धांत के आधार पर। राज्य

कानून को इस सवाल पर चुनौती दी जा सकती है कि क्या यह

यह संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है। लेकिन के रूप में

संवैधानिक संशोधनों के संबंध में, यदि कोई चुनौती है

बुनियादी संरचना के आधार पर बनाया गया है, यह होना चाहिए

मूल विशेषताओं के आधार पर जांच की गई

संविधान "।

389.

मद्रास बार में एक अलग राय व्यक्त की गई थी

एसोसिएशन वी। भारत संघ 378 जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि

विचार है कि संविधान में संशोधन को चुनौती दी जा सकती है

मूल संरचना के उल्लंघन के आधार पर

संविधान को विधान पर भी लागू किया गया है। यह था।

किसी सिद्धांत का तार्किक विस्तार माना

जाता है। यह आयोजित किया गया था:

"इस न्यायालय ने बार-बार यह अभिनिर्धारित किया है कि

संविधान के प्रावधान नहीं होंगे

यदि यह संविधान की "मूल संरचना" का उल्लंघन करता है, भले ही संशोधन किया गया था

विचार की गई प्रक्रिया का पालन करके किया गया

संविधान के "भाग 11" के तहत। इसकी वजह से

यह निर्धारित करना कि "मूल संरचना" अलंघनीय है। में।

हमारा विचार है कि यही बात अन्य सभी विधानों पर भी लागू होगी।

(संविधान में संशोधनों के अलावा) साथ ही, यहां तक कि

यद्यपि विधान निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अधिनियमित किया गया था, और इसके अधिकार क्षेत्र के भीतर था

विधायिका को अधिनियमित करना, "मूल" का कोई उल्लंघन

संरचना "अस्वीकार्य होगी"।

390. वर्तमान चर्चा के उद्देश्यों के लिए, मैं

सात विद्वानों की पीठ द्वारा व्यक्त किए गए विचार का पालन करना पसंद करते हैं।

कर्नाटक राज्य में न्यायाधीश बनाम। भारत संघ कि यह केवल संविधान का एक संशोधन है जिसे चुनौती दी जा सकती है

यह आधार कि यह संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है - किसी कानून को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह इसका उल्लंघन करता है।

378 (2014) 10 एस. सी. सी. 1 पैरा 109 (पाँच न्यायाधीशों की न्यायपीठ)

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ.: आई. / मदन बी. लोकुर, जे./

संविधान की मूल संरचना। [एकमात्र अपवाद

संविधान)। चुनौती देने के लिए सिद्धांत कानून की संवैधानिकता काफी अलग होती है।

99 वें संविधान संशोधन अधिनियम को चुनौती

- प्रारंभिक

(a) चुनौती की सीमाएँ

391. विद्वान वकील द्वारा की गई पहली प्रस्तुति

99 वीं की संवैधानिकता को बनाए रखने के लिए जनरल

संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर था -

केशवानंद भारती। यह प्रस्तुत किया गया कि एक संविधान

संशोधन अधिनियम को मूल प्रावधानों के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी जा सकती है।

सीमित मापदंडों के भीतर संविधान की संरचना, अर्थात्,

केवल तभी जब यह संविधान को 'समाप्त' करता है, या इसे 'निरस्त' करता है या

इसकी मूलभूत विशेषताओं को पूरी तरह से बदल देता है ताकि नष्ट किया जा सके।
या व्यक्तित्व या उन स्तंभों को हिलाता है जिन पर यह टिका हुआ है।

इसकी पहचान

यह स्वीकार करते हुए कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता एक है

इस तरह के स्तंभ, यह प्रस्तुत किया गया था कि विधि में परिवर्तन और

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में प्रक्रिया

या एक उच्च न्यायालय नपुंसक, निरस्त या हिलाता नहीं है

न्यायपालिका की स्वतंत्रता की नींव या स्तंभ।

नतीजतन 99 वां संविधान संशोधन अधिनियम नहीं है

यह संविधान की मूल संरचना के खिलाफ है।

392. यह तर्क यह समझने में विफल रहता है कि अधिकांश

केशवानंद भारती का फैसला करने वाली पीठ का गठन करने वाले विद्वान न्यायाधीशों की राय थी कि यह पर्याप्त है।

एक संवैधानिक संशोधन को मूल का उल्लंघन घोषित करना

यदि यह मूल संरचना को बदल देता है। निस्संदेह, कुछ

विद्वान न्यायाधीशों ने पाठ्यक्रम में बहुत मजबूत शब्दों का उपयोग किया है

उनके निर्णय का-नपुंसक बनाना, नष्ट करना, निरस्त करना और

पहचान आदि को काफी हद तक बदलते हैं लेकिन जब यह कहने की बात आती है

वास्तव में क्या कानून निर्धारित किया गया है, बहुमत ने फैसला किया कि

'अनुच्छेद 368 संसद को मूल [2015] 13 एस. सी. आर. को बदलने में सक्षम नहीं बनाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान की संरचना या ढांचा। '379

393. न्यायमूर्ति खन्ना ने इसे दोहराया और समझाया।

इंदिरा नेहरू गाँधी। शब्द 'नष्ट' और 'निरस्त'

आदि का उपयोग 'संशोधन' शब्दों के संदर्भ में किया गया था और

लेकिन इसका एक सीमित अर्थ है। शब्द 'नष्ट' और 'निरस्त' आदि का उपयोग नष्ट करने या निरस्त करने के संदर्भ में नहीं किया गया था

संविधान की मूल संरचना। विद्वान न्यायाधीश स्पष्ट रूप से

संविधान/ संसद को बुनियादी ढांचे में बदलाव करने की अनुमति नहीं देता है। संविधान के ढांचे की संरचना। 'वास्तव में, यह

चुनाव के लिए विद्वान वकील की सटीक प्रस्तुति थी

याचिकाकर्ता, अर्थात्, कि संवैधानिक संशोधन 'प्रभावित करता है

संविधान की मूल संरचना या ढांचा और है,
इसलिए, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करने की शक्ति से परे
संविधान/ '। 380 विद्वान न्यायाधीश ने इस महत्वपूर्ण बात को समझाया
निम्नलिखित शब्दों में अंतर:

"प्रस्ताव है कि संशोधन की शक्ति के तहत
अनुच्छेद 368 संसद को बुनियादी नियमों में बदलाव करने की अनुमति नहीं देता है।

संविधान की रूपरेखा निर्धारित की गई थी
इस न्यायालय द्वारा परम पूज्य केशवानंद भारती बनाम के मामले में 7 से 6 के बहुमत से। केरल राज्य। इसके
अलावा

अन्य कारणों से जो कुछ में दिए गए थे

विद्वान न्यायाधीशों के निर्णय जिन्होंने

बहुमत, बहुमत ने शब्द के अर्थ से निपटा
"संशोधन"। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि शब्द "का संशोधन"

अनुच्छेद 368 में संविधान का प्रभाव नहीं हो सका

संविधान की मूल संरचना को नष्ट करना या निरस्त करना। हममें से कुछ लोग जो उस मामले में
पक्षकार थे

379 न्यायमूर्ति खन्ना ने इंदिरा नेहरू गांधी में दिए गए निर्णय में पैराग्राफ 198 में इस निष्कर्ष का उल्लेख
किया है।

380 पैराग्राफ 173 सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

एक अलग दृष्टिकोण लिया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि
अनुच्छेद 368 में "संविधान का संशोधन" शब्द

किसी भी सीमा को स्वीकार नहीं करना। हम में से जो थे

केशवानंद मामले में अल्पसंख्यक अभी भी वही स्थिति बनाए रख सकते हैं

जैसा कि उस मामले में अभिव्यक्ति दी गई थी। इसके लिए

वर्तमान मामले का उद्देश्य, हमें आगे बढ़ना होगा
बहुमत द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार

उस मामले में "। 381

394. की संवैधानिक वैधता से निपटने के दौरान

इस विचार को व्यक्त किया कि यदि कोई सिद्धांत, अनिवार्य नियम या संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन किया जाता है,

तब संवैधानिक संशोधन अपनी प्रतिरक्षा खो देता है हमला करते हैं।

"तय किया जाने वाला सवाल यह है कि अगर विवादित

संविधान का संशोधन एक सिद्धांत का उल्लंघन करता है जो

संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, क्या यह

इसकी वैधता पर हमले से प्रतिरक्षा का आनंद लें क्योंकि

तथ्य यह है कि भविष्य के लिए, संविधान की मूल संरचना अप्रभावित रहती है। इसका जवाब है

उपरोक्त प्रश्न, मेरी राय में, नकारात्मक होना चाहिए।

ऐसे मामले में यह देखना होगा कि क्या

संशोधन एक अनिवार्यता का उल्लंघन करता है या उसके विपरीत है।

नियम या अभिधारणा जो मूल का एक अभिन्न अंग है

संविधान की संरचना। यदि ऐसा है तो

अस्वीकार्य संशोधन और यह नहीं करेगा

मामलों की संख्या। यदि कोई संशोधन मूल पर प्रहार करता है संविधान की संरचना अनुमत नहीं है, यह होगा

केवल एक मामले से संबंधित होने से वैधता प्राप्त न करें। को।

के समर्थन में दिए गए तर्क को स्वीकार करें

381 अनुच्छेद 175 और 176 [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संशोधन की वैधता धारण करने के समान होगी

कि भले ही मूल को बदलने की अनुमति नहीं है
 संविधान की संरचना, जब भी प्राधिकरण
 संबंधित इस तरह का संशोधन करना उचित समझता है,
 यह ऐसा कर सकता है और इस तरह के निर्माण के लिए बार को दरकिनार कर सकता है

329 - ए इस आधार पर कि यह स्वतंत्र के सिद्धांत का उल्लंघन करता है
 और निष्पक्ष चुनाव जो एक आवश्यक अभिधारणा है

लोकतंत्र और जो अपनी बारी में बुनियादी का एक हिस्सा है
 संविधान की संरचना इस प्रकार है कि (1) यह समाप्त हो जाता है।
 जाने के लिए एक और मंच प्रदान किए बिना मंच
 के चुनाव की वैधता से संबंधित विवाद में
 अपीलार्थी और आगे यह निर्धारित करता है कि उक्त विवाद
 यह किसी भी चुनाव कानून द्वारा शासित नहीं होगा और उक्त चुनाव की वैधता पूर्ण होगी और नहीं
 फलस्वरूप हमला किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा, और (2) यह
 चुनौती देने के अधिकार और उपाय दोनों को समाप्त कर देता है
 उपरोक्त चुनाव की वैधता "। 383

395. इसी तरह, न्यायमूर्ति के. के. मैथ्यू जो इस मामले में थे।

केशवानंद भारती में अल्पसंख्यकों ने विचार व्यक्त किया (में
 इंदिरा नेहरू गांधी) कि बहुमत का निर्णय था कि

एक संशोधन, संविधान की मूल संरचना नहीं कर सकता है क्षतिग्रस्त या नष्ट किया जाए, और
 विद्वान न्यायाधीश आगे बढ़े

उस आधार पर और यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 329-ए का खंड (4) 39 वें संविधान
 संशोधन द्वारा प्रस्तुत किया गया संविधान

अधिनियम ने मूल संरचना को क्षतिग्रस्त या नष्ट कर दिया

संविधान। 384

382 अनुच्छेद 210

383 पैरा 213

384 पैराग्राफ 264 और 265 सर्वोच्च न्यायालय-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. /मदन बी. लोकर, जे.] 396. न्यायमूर्ति वाई. वी. चंद्रचूड़ भी इस मामले में शामिल थे।

केशवानंद भारती में अल्पसंख्यकों ने यह विचार रखा कि उस निर्णय में बहुमत की राय के लिए सिद्धांत कि

यह सामने आया कि संविधान का अनुच्छेद 368 'नहीं है' संसद को मूल संरचना में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करना या

संविधान का ढांचा '। 385 विद्वान न्यायाधीश ने आगे कहा

केशवानंद भारती में अनुपात का निर्धारण यह था कि

'संशोधन की शक्ति [संविधान के अनुच्छेद 368 में] आवश्यक को नुकसान या नष्ट करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है

संविधान के तत्व या मूल संरचना, चाहे वे कुछ भी हों। अभिव्यक्तियाँ समझ सकती हैं। '1 386

397. यह मुद्दा फिर से विचार के लिए आया

मिनर्वा मिल्स बनाम। भारत संघ। 387 उस मामले में सवाल

क्या 42 वें संविधान की धारा 4 और धारा 55

संशोधन अधिनियम संशोधन की सीमा का उल्लंघन करता है संविधान के अनुच्छेद 368 की शक्ति। बहुमत में अपने और अन्य विद्वान न्यायाधीशों के लिए बोलते हुए (न्यायमूर्ति ए. सी. गुप्ता,

न्यायमूर्ति एन. एल. उन्तवालिया और न्यायमूर्ति पी. एस. कैलासम) ने यह निर्णय लिया।

मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा:

"केशवानंद भारती में, इस न्यायालय ने बहुमत से निर्णय दिया

कि यद्यपि अनुच्छेद 368 द्वारा संसद को शक्ति दी गई है संविधान में संशोधन करने के लिए, वह शक्ति नहीं हो सकती है

प्रयोग किया जाता है ताकि इसकी बुनियादी विशेषताओं को नुकसान पहुंचे संविधान या तो इसकी मूल संरचना को नष्ट करने के लिए। द.

याचिकाओं के इस समूह में विचार के लिए प्रश्न

अनुच्छेद 32 यह है कि क्या धारा 4 और 55

संविधान (42 वां संशोधन) अधिनियम, 1976 का उल्लंघन करता है कि

संशोधन शक्ति पर सीमा "। 388 थोड़े समय बाद निर्णय में यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया:

"केशवानंद में विभिन्न निर्णयों का सारांश

387 (1980) 3 एस. सी. सी. 625 (पाँच न्यायाधीशों की पीठ)

388 पैराग्राफ 1 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

भारती पर तेरह में से नौ न्यायाधीशों ने हस्ताक्षर किए थे।
सारांश का पैरा 2 यह कहने के लिए पढ़ा जाता है कि

बहुमत ", अनुच्छेद 368 संसद को सक्षम नहीं करता है

संविधान की मूल संरचना या ढांचे में परिवर्तन करना।

सारांश का वैध हिस्सा है या नहीं

निर्णय, या विद्वतापूर्ण कारणों से इनक्यूरियम के अनुसार है

लेखकों द्वारा उद्धृत, यह निर्विवाद है कि यह सही ढंग से प्रतिबिंबित होता है

बहुमत का दृष्टिकोण।

वह प्रश्न जिसे हमें आधार पर निर्धारित करना है

केशवानंद भारती में बहुमत का विचार है कि क्या

संविधान की धारा 4 और 55 द्वारा प्रस्तुत संशोधन

संविधान (42 वां संशोधन) अधिनियम, 1976

संविधान की किसी भी मूल संरचना को नष्ट करके

इसकी मूल विशेषताएँ या आवश्यक तत्व। 389

यह अनुपात की उपरोक्त व्याख्या से प्रकट होता है।

केशवानंद भारती में निर्णय लिया गया है कि शब्द 'बदल' जाते हैं और
दूसरे के स्थान पर किया जाता है। इसी तरह, 'नुकसान

'डैमेज' का उपयोग एक

बुनियादी विशेषताओं 'और' बुनियादी संरचना को नष्ट करने 'का उपयोग किया जाता है।
संरचना को नुकसान' और 'नष्ट' के साथ अदला-बदली

'मूल

बुनियादी विशेषताएँ '। 390 नीचे की रेखा वह है जो इसमें निहित है
अर्थात्: अनुच्छेद 368

केशवानंद भारती का 'सारांश',

संसद को मूल संरचना में परिवर्तन करने में सक्षम नहीं बनाता है या

संविधान की रूपरेखा। इसके दो कारण हैं। सबसे पहले, यह विचारों की एक समकालीन व्याख्या है केशवानंद भारती में बहुमत और कोई अन्य या नहीं है

स्वयं न्यायाधीशों का बहुमत (दो अल्पमत सहित) और किसी और से नहीं।

398. यह उल्लेख किया जा सकता है कि कुछ संदेह थे

389 पैराग्राफ 12 और 13

390 मैं न्यायमूर्ति चेलमेश्वर से सहमत नहीं हूँ जब वे कहते हैं कि 'बुनियादी संरचना' और 'बुनियादी विशेषताएं' अलग-अलग विचारों को व्यक्त करती हैं। शब्दकोषीय रूप से-हाँ, लेकिन संवैधानिक रूप से-नहीं। वे एक ही चित्र के दो आयाम हैं। किसी भी मामले में, वर्तमान चर्चा के लिए, अंतर, यदि कोई हो, प्रासंगिक नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

संजीव कोक में मिनर्वा मिल्स के बारे में व्यक्त किया गया विनिर्माण कं. वी. भारत कोकिंग कोल
Ltd. 391 द

पीठ द्वारा संदेह व्यक्त नहीं किया गया था सिवाय इसके कि यह है

कहा कि मामले ने 'हमें उलझन में डाल दिया है' प्रतीत होता है

इसका कारण यह है कि 42 वें संविधान की धारा 4 और धारा 55 की संवैधानिक वैधता के बारे में कोई सवाल नहीं उठा था संशोधन अधिनियम। 392 यह काफी अजीब है क्योंकि बहुमत

मिनर्वा मिल्स में निर्णय यह कहते हुए शुरू होता है: 'सवाल यह है कि

अनुच्छेद 32 के तहत याचिकाओं के इस समूह में विचार है

क्या संविधान की धारा 4 और 55 (42 वीं)

संशोधन) अधिनियम, 1976 उस सीमा का उल्लंघन करता है

शक्ति में संशोधन '। न्यायमूर्ति भगवती जो आंशिक रूप से असहमत थे

बहुमत के विचारों ने यह भी कहा कि संवैधानिक संविधान की धारा 4 और 55 की वैधता (42 वीं)

संशोधन) अधिनियम, 1976 चुनौती के दायरे में था। 393 तथापि, यह

इस झाड़ी में प्रवेश करना आवश्यक नहीं है, लेकिन यह ध्यान दिया जाना चाहिए

कि संजीव कोक अपने लेख में मिनर्वा मिल्स से असहमत नहीं थे

केशवानंद भारती की समझ।

399. हाल ही में, एम. नागराज बनाम. भारत संघ 3 9 4 यह

आयोजित किया गया था (इंदिरा नेहरू गांधी में न्यायमूर्ति खन्ना का पुनर्व्याख्यान) कि मूल संरचना
सिद्धांत वास्तव में संसद की संशोधन शक्ति पर एक रोक है। मूल संरचना

संविधान में ऐसे संवैधानिक सिद्धांत हैं जो इस प्रकार हैं -

यह मौलिक है कि वे संसद की संशोधन शक्ति को सीमित करते हैं।

यह निष्कर्ष निकाला गया कि मूल संरचना सिद्धांत आधारित है -

संवैधानिक पहचान की अवधारणा (न्याय का पुनर्व्याख्यान)

मिनर्वा मिल्स में भगवती)। फिर कहा गया:

"बुनियादी संरचना न्यायशास्त्र के साथ एक व्यस्तता है
संवैधानिक पहचान। केशवानंद भारती बनाम। केरल राज्य में यह देखा गया है कि "कोई भी कानूनी रूप से
ऐसा नहीं कर सकता है।

391 (1983) 1 एस. सी. सी. 147 (पाँच न्यायाधीशों की पीठ)

392 अनुच्छेद 11

393 अनुच्छेद 77-ए

(2006) 8 एस. सी. सी. 212 (पाँच न्यायाधीशों की पीठ)

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान का उपयोग खुद को नष्ट करने के लिए करें। यह आगे देखा जाता है

"संविधान का व्यक्तित्व बना रहना चाहिए

अपरिवर्तित "। इसलिए, केशवानंद में यह न्यायालय

भारती मूल संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए,
के सिद्धांत पर भरोसा किया है। द.

संवैधानिक पहचान

"संशोधन" शब्द यह मानता है कि पुराना संविधान

परिवर्तन के बावजूद अपनी पहचान खोए बिना जीवित रहता है

और यह जारी है भले ही इसके अधीन किया गया है

परिवर्तन। यह विचारों का निरंतर विषय है

केशवानंद भारती में बहुमत का निर्णय। नष्ट करने के लिए
 संवैधानिक पहचान निरंतरता है और उस निरंतरता के भीतर
 पहचान के आधार पर परिवर्तन स्वीकार्य हैं
 उस दिन की स्थिति और परिस्थितियाँ।
 400. 'विवाद' अब निर्णय के साथ शांत हो गया है।
 आई. आर. कोएल्हो में प्रस्तुत किया गया जहाँ मूल संरचना में परिवर्तन किया गया
 जैसा कि संवैधानिक निर्धारण के लिए परीक्षण के रूप में स्वीकार किया गया था
 संविधान में संशोधन। कहा गया था:
 "केशवानंद भारती मामले में निर्णय था
 तेरह-न्यायाधीश पीठ द्वारा 24-4-1973 पर प्रस्तुत किया गया और
 खारिज कर दिया। बहुमत की राय थी कि अनुच्छेद 368 ने
 संसद को मूल संरचना में परिवर्तन करने में सक्षम नहीं बनाना या

संविधान का ढांचा "। 396 और फिर से,

"केशवानंद भारती के मामले में बहुमत ने माना कि

अनुच्छेद के तहत संविधान के संशोधन की शक्ति 368 संसद
 को संविधान की मूल संरचना में बदलाव करने में सक्षम नहीं बनाया। 397
 [1967] 2 एस. सी. आर. 762 (ग्यारह न्यायाधीशों की पीठ)

अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 119

एच. सर्वोच्च न्यायालय-चालू-रिकॉर्ड संगठन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]
 इसलिए, हमला मूल संरचना पर नहीं है
 संविधान पर लेकिन संसद की संशोधन शक्ति पर।
 401. विद्वान महान्यायवादी ने न्यायमूर्ति कृष्ण के निर्णय के निम्नलिखित अंश पर भरोसा व्यक्त किया
 भीम सिंहजी बनाम में लायर भारत संघ 398 का तर्क है कि एक के लिए
 मूल संरचना का उल्लंघन करने के लिए संवैधानिक संशोधन, यह आवश्यक है
 चौंकाने वाला, असंवेदनशील या एक अनैतिक उपहास होना

समान न्याय का सारा। उस मामले से निपटा गया

शहरी भूमि की संवैधानिक वैधता (अधिकतम सीमा और
विनियमन) अधिनियम, 1976 जिसे नौवीं अनुसूची में रखा गया था

40 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान को,

1976 और इसलिए उन्हें अनुच्छेद 31-बी और अनुच्छेद का संरक्षण प्राप्त था

31 - संविधान का सी। इस संदर्भ में यह माना गया कि संविधान की मूल संरचना का सवाल तब नहीं
उठता जब कानून की संवैधानिक वैधता (जैसा कि विशिष्ट है)

एक संवैधानिक संशोधन से) चुनौती के अधीन है। यह था।

तब उन्होंने कहा:

“जब हम एक साधारण कानून के अधिकारों की जांच करते हैं तो बुनियादी ढांचे के उल्लंघन का
सवाल नहीं उठ सकता है।

जैसा कि संवैधानिक संशोधन से अलग है।

केशवानंद भारती अंतिम शरणस्थल नहीं हो सकती।
स्वामित्व तब होता है जब सौम्य कानून उन्हें छीन लेता है

संरचना। बड़ी होने पर परिधीय असमानता अपरिहार्य है।
पैमाने की बराबरी की प्रक्रियाओं को अमल में लाया जाता है। यदि सभी

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश गंभीर सत्र में बैठते हैं

और आधे साल के लिए एक कानून बनाने के लिए विचार-विमर्श किया

अगर निबंध को परिधीय से भी बचना है तो स्पष्ट आर्थिक असमानता को कम करने के लिए उनकी
प्रतिभा उन्हें निराश करेगी।

असमानताएँ। हर बड़ा कारण कुछ शहीद होने का दावा करता है, जैसे

समाजशास्त्री जानेंगे। इसलिए, विश्वासघात क्या है

399 (1981) 1 एस. सी. सी. 166 (पाँच न्यायाधीशों की पीठ)

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मूल विशेषता केवल अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है, बल्कि

एक चौंकाने वाला, अनुचित या अनैतिक उपहास

समान न्याय का सार। अगर कोई कानून

मृत्युदंड भुगतें "। 9 99
रखे गए कानून से संबंधित था।

402. यह निर्णय नौवें में

संविधान की अनुसूची और इसलिए, जहां तक वर्तमान चर्चा का संबंध है, यह एक अलग वर्ग है।

403. इस विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि यदि

संवैधानिक संशोधन मूल संरचना को बदल देता है संविधान, तब यह घोषित किया जा सकता है
और किया जाना चाहिए

असंवैधानिक है। केशवानंद भारती में श्री पालखीवाला द्वारा प्रस्तावित 'शक्ति की चौड़ाई' परीक्षण महत्वपूर्ण है।

और एम. नागराज में अपनाया गया और अब आई. आर. में पुनः नामित किया गया।

कोएल्हो 'प्रत्यक्ष प्रभाव और प्रभाव परीक्षण' के रूप में जिसका अर्थ है कि एक संशोधन का रूप प्रासंगिक नहीं है, इसका परिणाम होगा

[द] निर्धारक कारक बनें। 1, 400

404. उपरोक्त चर्चा के आलोक में प्रश्न,

इसलिए, यह है: 99 वां संविधान संशोधन कैसे होता है?

अधिनियम संविधान की मूल संरचना को बदल देता है, यदि बिल्कुल भी? वहाँ

इसमें कोई संदेह या विवाद नहीं है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता है संविधान की एक बुनियादी
संरचना। मैं पहले ही मान चुका हूँ कि

उच्चतम न्यायालय में एक न्यायाधीश की नियुक्ति और एक उच्च न्यायालय

न्यायालय न्यायपालिका की स्वतंत्रता का एक अभिन्न अंग है।

इसलिए, राष्ट्रीय न्यायिक की शुरुआत की गई है

99 वें संविधान द्वारा नियुक्ति आयोग

संशोधन अधिनियम ने नियुक्ति प्रक्रिया को इस प्रकार बदल दिया कि -

न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रभाव जिससे

99 वां संविधान संशोधन अधिनियम असंवैधानिक है? द.

विद्वान महान्यायवादी ने इसका नकारात्मक जवाब दिया।

(ख) संवैधानिकता का अनुमान

399 अनुच्छेद 20

400 पैराग्राफ 70 और 151 सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

405. विद्वान महान्यायवादी ने कहा कि वहाँ

कानून में यह धारणा है कि 99 वां संविधान संशोधन

अधिनियम संवैधानिक रूप से वैध है और याचिकाकर्ता उस धारणा का खंडन करने में सक्षम नहीं हैं।

406. चरणजीत लाल चौधरी बनाम। भारत संघ 401

न्यायमूर्ति फजल अली ने यह विचार व्यक्त किया कि 'अनुमान है

हमेशा किसी अधिनियम की संवैधानिकता के पक्ष में।

407. इसी तरह, राम कृष्ण डालमिया बनाम। न्यायमूर्ति एस. आर.

तेंदोलकर 402 यह निर्णयों पर विचार करने पर आयोजित किया गया था।

इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस. आर. दास ने कहा कि 'हमेशा एक

और बोझ उस पर है जो यह दिखाने के लिए उस पर हमला करता है कि वहाँ यह संवैधानिक सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन रहा है।

408. केशवानंद भारती में यह न्यायमूर्ति द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था

हेगडे और न्यायमूर्ति मुखर्जी ने कहा:

"लेकिन अदालतें आम तौर पर इस धारणा पर आगे बढ़ती हैं कि

सभी विधानों की संवैधानिकता का अनुमान

कानून की संवैधानिक वैधता भी लागू होगी

संवैधानिक संशोधन "। 403

409. अंत में, आर. के. गर्ग बनाम भारत संघ 404 यह था

न्यायमूर्ति भगवती द्वारा अभिनिर्धारित, न्यायालय की ओर से निम्नानुसार बोलते हुए:

"अब अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाले एक कानून की संवैधानिक वैधता पर विचार करते हुए, यह आवश्यक है
कुछ सुस्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखना जो

न्यायिक समीक्षा के अपने संवैधानिक कार्य का निर्वहन।
पहला नियम यह है कि हमेशा पक्ष में एक धारणा होती है।

किसी कानून की संवैधानिकता और बोझ
वह जो यह दिखाने के लिए हमला करता है कि एक स्पष्ट हो गया है

401 [1950] एस. सी. आर. 869 (पाँच न्यायाधीशों की पीठ)
(पाँच न्यायाधीशों की पीठ)

402 [1959] एस. सी. आर. 279

403 अनुच्छेद 661

404 (1981) 4 एस. सी. सी. 675 (पाँच न्यायाधीशों की पीठ)

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन। यह है नियम

धारणा के आधार पर, न्यायिक रूप से मान्यता प्राप्त और

स्वीकार किया, कि विधायिका समझती है और सही ढंग से

अपने ही लोगों की जरूरतों की सराहना करता है, इसके कानून हैं

अनुभव द्वारा प्रकट की गई समस्याओं के लिए निर्देशित और

इसका भेदभाव पर्याप्त आधारों पर आधारित है। द.

संवैधानिकता की धारणा वास्तव में इतनी प्रबल है कि

इसे बनाए रखने के लिए, न्यायालय इस पर विचार कर सकता है

सामान्य रिपोर्ट, समय का इतिहास और तथ्यों की हर स्थिति को ग्रहण कर सकता है जिसकी कल्पना
की जा सकती है कानून के

समय मौजूद "। 405

410. इस संबंध में विद्वान महान्यायवादी से असहमत होना संभव नहीं है। एक कानून या एक संवैधानिक

संशोधन को हमेशा संवैधानिक रूप से वैध माना जाना चाहिए।
वैधता को चुनौती देते हैं

और यह उन लोगों के लिए है जो

संविधान का उल्लंघन या मूल में परिवर्तन

संविधान की संरचना, जैसा भी मामला हो। जहाँ तक
रूप से दिखाना है

याचिकाकर्ता चिंतित हैं, यह उन्हें निर्णायक

कि 99 वां संविधान संशोधन अधिनियम मूल को बदल देता है

संविधान की संरचना में यह न्यायाधीशों की नियुक्ति के एक सुविचारित और पूरी तरह से चर्चा किए गए तरीके को प्रतिस्थापित करता है

एक अन्य जिसमें संवैधानिक भूमिका महत्वपूर्ण मूल्य देती है

भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय के अनुसार

एन. जे. ए. सी. द्वारा कम या शायद समाप्त और प्रतिस्थापित किया गया।

सवाल यह नहीं है कि वैकल्पिक मॉडल अच्छा है या नहीं।

अच्छा नहीं है लेकिन क्या यह संवैधानिक रूप से मान्य है या नहीं।

(ग) निर्णय का आधार हटा दिया जाता है।

411. तीसरी दलील यह थी कि संविधान का अनुच्छेद 124 (2)

99 वें संविधान द्वारा संविधान में संशोधन किया गया है। संशोधन अधिनियम और इसलिए, निर्णय का आधार

इस न्यायालय द्वारा दूसरे न्यायाधीशों के मामले में दिया गया है

405 पैराग्राफ 7 शीर्ष अदालतें-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

पूरी तरह से छीन लिया गया है या संविधान को हटा दिया गया है

परिणाम के साथ संशोधन किया गया कि उस निर्णय का अब उपयोग नहीं किया जा सकता है

संविधान के अनुच्छेद 124 (2) की व्याख्या करना जैसा कि आज है। में।

दूसरे शब्दों में, 99 वें संविधान संशोधन को चुनौती

अधिनियम पर स्वतंत्र रूप से और परवाह किए बिना निर्णय लेना होगा।

दूसरे न्यायाधीशों के मामले या तीसरे मामले में निर्धारित कानून का

न्यायाधीशों का मामला।

412. श्री पृथ्वी कॉटन मिल्स लिमिटेड बनाम ब्रोच

नगर पालिका 406 यह मुख्य न्यायाधीश द्वारा कहा गया था

हिदायतुल्ला जिसने विधायी क्षमता प्रदान की, वह नहीं है
केवल यह घोषित करने के लिए पर्याप्त है कि न्यायालय का निर्णय
इसके लिए बाध्य नहीं होना निर्णय को उलटने के समान है।

न्यायिक शक्ति का प्रयोग जो विधानमंडल नहीं करता है
फैसला हमेशा बाध्यकारी होना चाहिए। रखना या व्यायाम करना। अदालत का

परिवर्तित किया कि निर्णय में नहीं दिया जा सकता था बदलती परिस्थितियाँ। कहा गया था:

"विधायी क्षमता प्रदान की गई, यह पर्याप्त नहीं है
केवल यह घोषित करें कि न्यायालय का निर्णय नहीं होगा
इसके लिए बाध्य होना निर्णय को उलटने के समान है।
न्यायिक शक्ति का प्रयोग जो विधानमंडल नहीं करता है

रखना या व्यायाम करना। अदालत का फैसला हमेशा बाध्यकारी होना चाहिए।
जब तक कि जिन शर्तों पर यह आधारित है वे इस प्रकार नहीं हैं

मौलिक रूप से बदल दिया कि निर्णय नहीं हो सकता था
परिवर्तित परिस्थितियों में दिया गया। आम तौर पर, ए
अदालत ने एक कर को अमान्य रूप से लगाया है क्योंकि

कर लगाने की शक्ति की आवश्यकता है या कानून या नियम या दोनों

अमान्य हैं या पर्याप्त रूप से अधिकार क्षेत्र नहीं बनाते हैं।
इस प्रकार अवैध घोषित कर का सत्यापन केवल किया जा सकता है।

यदि अवैधता या अयोग्यता के आधार सक्षम हैं

हटा दिया जाता है और वास्तव में हटा दिया जाता है और इस प्रकार कर लगाया जाता है
कानूनी। कभी-कभी यह अधिकार क्षेत्र प्रदान करके किया जाता है।

406 (1969) 2 एस. सी. सी. 283 (पाँच न्यायाधीशों की पीठ)

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जहाँ अधिकारिता का पहले ठीक से निवेश नहीं किया गया था।

कभी-कभी यह पूर्वव्यापी रूप से पुनः अधिनियमित करके किया जाता है

वैध और कानूनी कर प्रावधान और फिर काल्पनिक निर्माण द्वारा
 पुनः अधिनियमित के अंतर्गत आने के लिए पहले से ही एकत्रित कर
 कानून। कभी-कभी विधानमंडल अपना अर्थ देता है।
 और उस कानून की व्याख्या जिसके तहत कर एकत्र किया गया था
 और विधायी आदेश द्वारा नए अर्थ को बाध्यकारी बनाता है अदालतों में। विधानमंडल किसी भी
 एक विधि का पालन कर सकता है।
 या उन सभी को और जब यह ऐसा करता है तो यह बेअसर कर सकता है
 न्यायालय के पूर्व निर्णय का प्रभाव जो बन जाता है
 कानून के परिवर्तन के बाद अप्रभावी। जो भी विधि हो।
 अपनाया जाता है यह क्षमता के भीतर होना चाहिए
 विधायिका और कानूनी और के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त
 प्रमाणन "। 407

413. इसी तरह, इंदिरा नेहरू गांधी में यह आयोजित किया गया था

न्यायमूर्ति रे इस प्रकार हैं:

" सत्यापन का प्रभाव कानून को बदलना है ताकि किसी भी निर्णय के आधार को बदलना, जो
 हो सकता है

पुराने कानून के आधार पर दिया जाता है और इस प्रकार निर्णय को अप्रभावी बनाता है। एक औपचारिक
 घोषणा कि निर्णय पुराने अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया अमान्य है, आवश्यक नहीं है।
 अगर

मामला अपील में लंबित है, अपीलीय अदालत को परिवर्तित कानून को लागू करना होगा और फैसले को
 उलटना होगा।

निर्णय का आधार प्रदान करने वाला विधानमंडल ऐसा नहीं है "।

414. के. शंकरन नायर बनाम। देवकी अम्मा मालथी

408 में इसे इस प्रकार देखा गया:

" अब यह तय हो गया है कि विधायिका इसे रद्द नहीं कर सकती।

आरेग्राफ 4

996) 11 एस. सी. सी. 428 सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

आधार को हटाए बिना कोई न्यायिक निर्णय या

एक पूर्वव्यापी द्वारा उस निर्णय की नींव

संबंधित कानूनी प्रावधान का संशोधन। 409
पृथ्वी कॉटन पर भरोसा करते हुए

यह आगे कहा गया था, श्री

इल्स लिमिटेड निम्नानुसार है:

"यह अब इसके निर्णयों के एक समूह द्वारा अच्छी तरह से तय किया गया है।
न्यायालय कि जब तक विधायिका एक सक्षम अधिनियमित करके

विधायी प्रावधान पूर्वव्यापी रूप से हटा देता है
व्यक्ति के किसी भी निर्णय का आधार या आधार

किसी सक्षम

कार्यात्मक और इस तरह के विधान के अभाव में
विधायिका द्वारा परेशान करने का प्रयास

एक सक्षम

उनके विरुद्ध दिए गए ऐसे निर्णयों का बाध्यकारी प्रभाव
एक अक्षम और वर्जित रहेंगे

पक्ष

ऐसा अभ्यास जिसे न्यायालयों के बाध्यकारी निर्णयों को विधायी रूप से निरस्त करने का एक असफल
प्रयास कहा जा सकता है। 410

415. इसी तरह, भुवनेश्वर सिंह बनाम। संघ का
श्री पृथ्वी कॉटन मिल्स लिमिटेड पर निर्भरता रखी गई थी।
और इस न्यायालय द्वारा दिए गए कई अन्य निर्णय और
मिलर निष्कर्ष निम्नलिखित शब्दों में आया:

"समय-समय पर इस बात को लेकर विवाद पैदा हुआ है कि क्या

उच्च न्यायालय की न्यायिक घोषणाओं का प्रभाव

या उच्चतम न्यायालय का संशोधन करके सफाया किया जा सकता है

पूर्वव्यापी प्रभाव वाला विधान। ऐसे कई

संशोधनकारी अधिनियमों को विधिमान्यकारी अधिनियम कहा जाता है, जो

विशेष अधिनियमों को हटाकर की गई कार्रवाई

कानून में दोष पूर्वव्यापी रूप से जिसके कारण
 कानून या उसके हिस्से को अधिकार से बाहर घोषित किया गया था।
 इस न्यायालय द्वारा इस तरह की कवायद का अभिनिर्धारण किया गया है कि
 न्यायिक शक्ति पर अतिक्रमण की राशि

अनुच्छेद 5

पी पैराग्राफ 5

(1994) 6 एससीसी 77 [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट
 अदालतें। अप्रभावी प्रस्तुत करने का अभ्यास
 परिवर्तन द्वारा सक्षम न्यायालयों के निर्णय या आदेश
 विधान द्वारा आधार एक प्रसिद्ध उपकरण है
 कानून को मान्य करना। इस न्यायालय ने बार-बार इंगित किया है
 अयोग्यता के कारण को माना नहीं जा सकता है
 शक्ति का अतिक्रमण। साथ ही किसी भी न्यायिक
 किसी भी अधिनियम के तहत शक्ति के प्रयोग में कार्रवाई
 जिसे अदालत द्वारा अमान्य घोषित किया गया है, उसे केवल ऐसा कहकर वैधीकरण अधिनियम द्वारा वैध
 नहीं बनाया जा सकता है।
 जब तक कि वह दोष जो न्यायालय द्वारा इंगित नहीं किया गया है
 कानून को अयोग्यता के कारण को हटाना चाहिए। तब तक
 न्यायालय द्वारा इंगित दोष या अधिकार की कमी
 एक कानून के तहत बाद के अधिनियम द्वारा हटा दिया जाता है
 पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ, की बाध्यकारी प्रकृति
 अदालत के फैसले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। 412
 416. री कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण 413 में यह था
 थिली ने कहा, इस न्यायालय के कई फैसलों की समीक्षा पर यहाँ:

"इन प्राधिकरणों से जो सिद्धांत उभरता है वह है -

कि विधायिका उस आधार को बदल सकती है जिसके आधार पर

निर्णय न्यायालय द्वारा दिया जाता है और इस प्रकार कानून में परिवर्तन किया जाता है।

निर्णय अंतर-पक्षीय होते हैं और उनके अधिकारों और देनदारियों को प्रभावित करते हैं अकेले। विधायिका की ओर से ऐसा अधिनियम

राज्य की न्यायिक शक्ति का प्रयोग करना और अपीलीय न्यायालय या न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करना। 414

417. हाल ही में, तमिलनाडु राज्य में यह न्यायालय

भारतीय में निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचे

2 अनुच्छेद 11

3 (1993) पूरक (1) एस. सी. सी. 96

पैराग्राफ 76 सर्वोच्च अदालतें-चालू-रिकॉर्ड एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

एल्यूमीनियम कं. बी. केरल राज्य 415:

"विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए, विधायिका मात्र

घोषणा, बिना कुछ और के, सीधे नहीं कर सकते हैं न्यायिक निर्णय को निरस्त, संशोधित या ओवरराइड करें। यह हो सकता है।

वैध कानून बनाकर न्यायिक निर्णय को अप्रभावी बनाना मौलिक रूप से अपने विधायी क्षेत्र के भीतर विषय पर

इसके चरित्र को पूर्वव्यापी रूप से बदलना या बदलना। द. परिवर्तित या परिवर्तित स्थितियाँ ऐसी हैं कि पिछली

न्यायालय द्वारा निर्णय नहीं दिया जाता, यदि

घोषणा के समय वे शर्तें मौजूद थीं

कानून अमान्य है। इसे पूर्वव्यापी कानून को प्रभावी बनाने का भी अधिकार है, जिसकी एक निश्चित तिथि या प्रभाव होता है।

किसी विशेष तिथि से। विधायिका बदल सकती है

कर या शुल्क का चरित्र अनुज्ञेय से लेकर

अमान्य को हटाने पर इस तरह के कर को मान्य करने वाला अमान्य कर विषय से पुनर्प्राप्ति के लिए आधार या पुनर्प्राप्ति प्रदान करें

अप्रभावी राज्य से। यह विधायिका के लिए सक्षम है पूर्वव्यापी प्रभाव से कानून बनाना और अधिकृत करना

उस आधार पर कर लगाने और एकत्र करने के लिए इसकी एजेंसियां

संग्रहित कर का अधिरोपण और कर की वसूली

न्यायालय द्वारा घोषणा के बावजूद वैध बना दिया गया

या उसकी वसूली के लिए दिया गया निर्देश। 41 6

418. द्वारा प्रचार किए गए दृष्टिकोण पर टिप्पणी किए बिना

विद्वान अटॉर्नी-जनरल कि 99 वां संविधान संशोधन

अधिनियम ने वास्तव में दिए गए निर्णय के आधार को हटा दिया है

इस न्यायालय द्वारा दूसरे न्यायाधीशों के मामले में संवैधानिक

फिर भी उक्त संशोधन की वैधता की आवश्यकता होगी

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए उस धारणा पर परीक्षण किया गया

निर्णय लेते हैं।

415 (1996) 7 एस. सी. सी. 637

418 पैराग्राफ 111 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

((घ) संविधान में संशोधन का विवेक

419. विद्वान महान्यायवादी का अगला निवेदन -

यह था कि 99 वें अधिनियम को लागू करने में संसद का विवेक

संविधान संशोधन अधिनियम पर विवाद नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह

न्यायालय को आवश्यकता पर अपने स्वयं के विचारों को प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए या

अन्यथा दूसरे न्यायाधीशों के मामले में निर्धारित कानून पर 99 वें संविधान संशोधन अधिनियम।

420. लोच्चर वी। न्यूयॉर्क 417 न्यायमूर्ति ओलिवर वेंडेल

होम्स ने लगभग एक सदी पहले (असहमति में) प्रसिद्ध रूप से कहा था:

"यह मामला एक आर्थिक सिद्धांत पर तय किया जाता है जो देश का बड़ा हिस्सा मनोरंजन नहीं करता है। अगर एक यह पूछने पर कि क्या मैं उस सिद्धांत से सहमत हूँ, मुझे इच्छा करनी चाहिए मेरा मन बनाने से पहले इसका और अधिक अध्ययन करने के लिए। लेकिन मैं इसे अपना कर्तव्य नहीं मानता, क्योंकि मैं दृढ़ता से मानो कि मेरी सहमति या असहमति में कुछ भी नहीं है बहुमत के अपने विचारों को मूर्त रूप देने के अधिकार के साथ करना कानून में "।

दूसरे शब्दों में, कोई सामग्री से सहमत हो भी सकता है और नहीं भी। या एक कानून का ज्ञान, लेकिन इसका इससे कोई लेना-देना नहीं है एक द्वारा लिए गए बहुमत निर्णय की शुद्धता या अन्यथा विधायिका। हमारे देश में भी इस दृष्टिकोण का पालन किया गया है।

421. हमारे देश में अदालतें विवेक पर सवाल नहीं उठाती हैं।

या किसी कानून को अधिनियमित करने वाले विधानमंडल की समीचीनता, एक बात तो छोड़िए संवैधानिक संशोधन।

422. ज्ञान से संबंधित शुरुआती मामलों में से एक में

संसद द्वारा एक कानून बनाने में, ए. के. में इसका प्रतिवाद किया गया था।

गोपालन बनाम। मद्रास राज्य 418 कि निवारक

निरोध अधिनियम, 1950 असंवैधानिक था। न्यायमूर्ति दास ने यह विचार व्यक्त किया कि:

"हालाँकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ तक वहाँ है

417 198 यूएस 45 418 [1950] 1 एससीआर 88 (पाँच न्यायाधीशों की पीठ)

सर्वोच्च अदालतें-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

विधायी शक्ति पर कोई सीमा है, न्यायालय को, उसे की जा रही शिकायत पर, जांच करनी चाहिए और पता लगाना चाहिए

क्या ऐसी सीमा का उल्लंघन किया गया है और यदि

कोई भी उल्लंघन हुआ है जो न्यायालय करेगा

साहसपूर्वक कानून को असंवैधानिक घोषित करें, क्योंकि

न्यायालय संविधान को बनाए रखने की अपनी शपथ से बाध्य है। लेकिन विधायी शक्तियों पर लगाई गई सीमाओं के बाहर

हमारी संसद और राज्य विधानमंडल सर्वोच्च हैं।

उनके संबंधित विधायी क्षेत्रों में और न्यायालय के पास नहीं है

कानून के विवेक या नीति पर विधिवत सवाल उठाने का अधिकार उपयुक्त विधायिका द्वारा बनाया गया "।

423. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 और योजना

न्यूनतम बोनस के भुगतान के लिए जालान ट्रेडिंग कंपनी (पी) लिमिटेड बनाम में चुनौती दी गई थी। मिल मजदूर सभा संघ। 419

न्यायालय की ओर से न्यायमूर्ति जे. सी. शाह ने कहा कि

विधानमंडल द्वारा चुनी गई योजना का विवेक हो सकता है

बहस के लिए खुला है लेकिन यह केवल इसलिए अमान्य नहीं होगा क्योंकि पाई जा सकती है। कहा गया था:

योजना में कुछ त्रुटि

"क्या न्यूनतम बोनस के भुगतान की योजना है

परिस्थितियों में सबसे अच्छा, या एक अधिक न्यायसंगत तरीका तैयार किया जा सकता था ताकि कुछ मामलों में इससे बचा जा सके

हाथ में ली गई जाँच के लिए अनुचित कठिनाई अप्रासंगिक है। अगर

वर्गीकरण स्पष्ट रूप से मनमाना नहीं है, न्यायालय इसे केवल इसलिए भेदभावपूर्ण नहीं ठहराएगा क्योंकि इसमें कठिनाई शामिल है।

या बोझ की असमानता। एक विशेष को सुरक्षित करने की दृष्टि से किसी योजना का चयन विधानमंडल द्वारा किया जा सकता है,

ज्ञान जिसके बारे में बहस के लिए खुला हो सकता है; यह भी हो सकता है

प्रदर्शित किया कि योजना में सबसे अच्छा नहीं है परिस्थितियाँ और विधायिका का चुनाव हो सकता है -

गलत दिखाया गया है, लेकिन जब तक कि अधिनियम विफल न हो

बोधगम्य वर्गीकरण के दोहरे परीक्षण को संतुष्ट करना और

कानून के उद्देश्य के साथ संबंध की तर्कसंगतता, यह होगा

419 [1967] 1 एस. सी. आर. 15 (पाँच न्यायाधीशों की पीठ)

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुच्छेद 14 के तहत न्यायिक हस्तक्षेप के अधीन नहीं होगा।
कानून की अवैधता केवल खोज से स्थापित नहीं होती है।

विधानमंडल द्वारा अपनाई गई योजना के साथ दोष

उसके दृष्टिगत उद्देश्य को प्राप्त करना।

424. केशवानंद भारती में यह प्रमुख द्वारा मनाया गया था।

न्यायमूर्ति सीकरी ने कहा: 'यह निश्चित रूप से संसद को तय करना है कि (संविधान में) संशोधन आवश्यक है या नहीं। द.

अदालतें विवेक से संबंधित नहीं होंगी संशोधन। 1 420 विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा:

'यदि संसद के पास विवादित संशोधन को पारित करने की शक्ति है अधिनियम, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुझे सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है

संसद की नीति का विवेक। 1 421

425. इसी तरह, न्यायमूर्ति शेलट और न्यायमूर्ति ग्रोवर ने कहा:
"यह अदालतों के लिए नहीं है कि वे विवेक या नीति में प्रवेश करें

किसी संविधान या कानून में किसी विशेष प्रावधान का।

वह संविधान निर्माताओं के लिए है या संसद के लिए।

या विधायिका "। 422

426. न्यायमूर्ति ए. एन. रे ने निम्नलिखित में अपना विचार व्यक्त किया:

शब्द: 'अदालतें विवेक या नीति से संबंधित नहीं हैं

कानून। न्यायालय समान रूप से संबंधित नहीं हैं

संविधान में संशोधन की विवेक और नीति। '423

427. न्यायमूर्ति जगनमोहन रेड्डी ने भी यही कहा।

भावनाएँ जब विद्वान न्यायाधीश ने कहा:

"जिन नागरिकों के अधिकार प्रभावित होते हैं, वे निस्संदेह आह्वान करते हैं

उन्हें सही साबित करने के लिए न्यायिक शक्ति की सहायता, लेकिन अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, न्यायालयों का इससे कोई लेना-देना नहीं है विधानमंडल की बुद्धिमत्ता या नीति "। 424

428. एक संवैधानिक ज्ञान के सवाल पर

420 अनुच्छेद 288।

421 अनुच्छेद 317

422 अनुच्छेद 532

423 पैराग्राफ 909

424 पैराग्राफ 1106 सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

न्यायमूर्ति खन्ना ने यह विचार व्यक्त किया कि यह न्यायोचित नहीं था। स्थान पर अपनी राय नहीं रख सकता है।

न्यायालय संसद की राय के

इस संबंध में। यह आयोजित किया गया था:

"चाहे संशोधन वास्तव में कोई सुधार हो या

नहीं, मेरी राय में, एक न्यायसंगत मामला नहीं है, और

एक संशोधन की वैधता का न्याय करते हुए अदालतें

इस सवाल में नहीं जाएँ कि क्या संशोधन किया गया है

इससे वास्तव में सुधार हुआ है। यह इसके लिए है

संसद के प्रत्येक सदन में निर्णय लेने के लिए विशेष बहुमत

के रूप में क्या यह एक सुधार का गठन करता है; अदालतें

के लिए अपनी राय को प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा

इस संबंध में संसद। जो भी व्यक्तिगत हो सकता है

पीछे के ज्ञान के बारे में एक न्यायाधीश का दृष्टिकोण या

संशोधन की वैधता से संबंधित और यह, बदले में, इस सवाल पर निर्भर करेगा कि क्या

इसके

अनुच्छेद 368 में निर्धारित औपचारिकताएं

मान लिया "। 425

429. लोचनर असहमति के संदर्भ में, जस्टिस

खन्ना ने कहा कि इस विचार को बाद में स्वीकार किया गया था

फर्ग्यूसन बनाम में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय। में स्कूपा 426

निम्नलिखित शब्द:

"अस्पष्ट के उपयोग के हमारे परित्याग के सामने

विधियों को निरस्त करने के लिए नियत प्रक्रिया खंड की रूपरेखा जो

न्यायालय का बहुमत आर्थिक रूप से माना जाता है

मूर्खतापूर्ण, एडम्स बनाम पर निर्भरता। टैनर 1 27 गलत है

जैसा कि एडकिन्स बनाम का पालन होगा। बच्चों का अस्पताल 4 1 28
वेस्ट कोस्ट होटल कं. वी. द्वारा अस्वीकृत। पारिश 1 29

425 पैरा 1436। इस दृष्टिकोण को पैराग्राफ 1534 में दोहराया गया था।

426 372 यूएस 726

427 244 अमेरिका 590 (1917)

428 261 अमेरिका 525 (1923) 429 300 अमेरिका 379 (1937)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

हम एक 'सुपर विधायिका' के रूप में बैठने से इनकार करते हैं

कानून का ज्ञान , और हम दृढ़ता से जाने से इनकार करते हैं

उस समय तक जब अदालतों ने नियत प्रक्रिया का उपयोग किया था

खंड 'राज्य के कानूनों को निरस्त करने के लिए, व्यवसाय के नियामक

और औद्योगिक स्थितियाँ, क्योंकि वे अविवेकी, आशाजनक, या किसी विशेष स्कूल के साथ सामंजस्य से
बाहर हो सकती हैं

सोचा "। 430

430. न्यायमूर्ति खन्ना ने इंदिरा नेहरू में अपने विचारों को दोहराया।

गांधी जिसमें विद्वान न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया:

" इस सवाल से निपटने से पहले कि क्या

आक्षेपित संशोधन मूल संरचना को प्रभावित करता है

संविधान, मैं यह स्पष्ट कर सकता हूं कि यह न्यायालय नहीं है

इसके पीछे के ज्ञान या औचित्य से संबंधित

विवादित संवैधानिक संशोधन। ये हैं।

अनिवार्य रूप से उन लोगों के लिए जो निहित हैं
संवैधानिक संशोधन करने का अधिकार। यह सब

यह न्यायालय संवैधानिक वैधता से संबंधित है।

विवादित संशोधन "। 431

चंद्रचूड़ ने भी यही कहा।

431. न्यायमूर्ति

देखें, इसका मतलब है:

" संवैधानिक संशोधनों का विषय उच्च नीति का प्रश्न है और अदालतें इससे संबंधित हैं -

कानून की व्याख्या, नीति के विवेक के साथ नहीं

उनके अंतर्गत "। 432

432. कर्नाटक बैंक लिमिटेड बनाम में भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया गया था। आंध्र प्रदेश राज्य 433
जिसमें यह विशेष रूप से था

इस न्यायालय ने कहा कि:

" किसी कानून की संवैधानिक वैधता पर घोषणा करते हुए,

अदालत ज्ञान या अज्ञानता से संबंधित नहीं है,

431 अनुच्छेद 176

432 अनुच्छेद 661

433 (2008) 2 एस. सी. सी. 254 सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

कानून का न्याय या अन्याय। अगर वह जो पारित किया जाता है

विधायिका और उस शक्ति पर कोई प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं करता है, अदालत इसके बारे में जो भी सोचे, कानून को बरकरार रखा जाना चाहिए। 434

433. न्यायिक घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए, वहाँ है

इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं है विद्वान महान्यायवादी द्वारा। की संवैधानिक वैधता

99 वें संविधान संशोधन अधिनियम का परीक्षण किया जाना है

अपनी योग्यता। अपनी राय को प्रतिस्थापित करने वाले किसी भी न्यायालय का प्रश्न

क्योंकि विधानमंडल का ऐसा नहीं हो सकता और न ही होता है। ए.

कॉलेजियम पर न्यायाधीश का एक या दूसरे तरीके से विचार हो सकता है।

कार्यान्वयन-लेकिन वह राय आवेदन को रंग नहीं दे सकती है और कानून की व्याख्या या वह तर्क जिसे एक न्यायाधीश से किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में अपनाने की अपेक्षा की जाती है कि क्या

99 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तुत विकल्प

संवैधानिक रूप से वैध है या नहीं। इसी तरह, एक न्यायाधीश के पास हो सकता है

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के बारे में राय

- लेकिन फिर से यह दृष्टिकोण न्यायिक व्याख्या की जगह नहीं ले सकता है अधिनियम या एन. जे. ए. सी. अधिनियम।

99 वां संविधान संशोधन

434. न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली

निस्संदेह आलोचना का विषय रहा है। वास्तव में, श्री फाली

उत्तरदाता अपनी आलोचना में हृद से आगे निकल गए। लेकिन व्यक्तिगत पड़ता। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लॉर्ड टेम्पलमैन

राय से कोई फर्क नहीं

यह विचार था कि नियुक्तियों की कॉलेजियम प्रणाली है

न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सबसे उपयुक्त-लेकिन

अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जो दूसरे की आलोचना करते हैं

न्यायाधीशों का मामला।

435. इसलिए, अंतिम विश्लेषण में न्यायालयों को इसे स्थगित करना चाहिए।

434 पैराग्राफ 19 [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विधानमंडल के विवेक के लिए और उनके विचारों को स्वीकार करते हुए,

जब तक वे कानून के मापदंडों के भीतर हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं।

और कुछ भी कम नहीं। 99 वीं की संवैधानिक वैधता

संविधान संशोधन अधिनियम का परीक्षण राय के आधार पर नहीं किया जा सकता है।

चाहे वे कितने भी मजबूत हों या फिर स्पष्ट रूप से व्यक्त किए गए हों।

(ई) लोगों की आवश्यकताएँ

436. यह विद्वान वकील द्वारा भी प्रस्तुत किया गया था

सामान्य तौर पर यह कि संसद लोगों की जरूरतों से अवगत है

और लोग कॉलेजियम प्रणाली से बदलाव चाहते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति। संसद ने इसका जवाब दिया है।

माँग और इस न्यायालय को केवल इस माँग को अस्वीकार नहीं करना चाहिए

क्योंकि यह मानता है कि कॉलेजियम प्रणाली अच्छी तरह से काम कर रही है और यह कि 99 वां संविधान संशोधन अधिनियम एक

विभिन्न प्रणाली जो न्यायपालिका की भूमिका को कम करती है

इस संबंध में इसकी प्रधानता को छीनकर नियुक्तियाँ करना।

437. इस धारणा के अलावा कि एक अधिनियम है

संवैधानिक रूप से वैध, यह भी एक धारणा है कि

विधायिका जरूरतों को समझती है और सही ढंग से उनकी सराहना करती है

लोगों से। यह चरणजीत लाल चौधरी में देखा गया था और निम्नलिखित मार्ग पर निर्भरता रखी गई थी मिडलटन वी। टेक्सास पावर एंड लाइट Co.435:

"यह माना जाना चाहिए कि एक विधायिका समझती है और

कानूनों को प्रकट की गई समस्याओं के लिए निर्देशित किया जाता है अनुभव और यह कि इसके भेदभाव पर्याप्त आधारों पर आधारित हैं।

438. इसी तरह, राम कृष्ण डालमिया में यह धारणा कि विधानमंडल समझता है और सही ढंग से इसकी सराहना करता है

लोगों की जरूरतों को दोहराया गया।

439. अंत में मोहम्मद। हनीफ कुरेशी बनाम। की स्थिति

बिहार 436 इस दृष्टिकोण का समर्थन मुख्य न्यायाधीश एस. आर. दास 435 249 यू. एस. 152,157 पैराग्राफ 11 ने किया था।

436 [1959] एस. सी. आर. 629 (पाँच न्यायाधीशों की पीठ)

सर्वोच्च अदालतें-चालू-रिकॉर्ड:

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

इस न्यायालय के लिए चरम पर (हालांकि यह उल्लेख किया जा सकता है कि यह इस निर्णय को बाद में एक अन्य मुद्दे पर खारिज कर दिया गया)

बोलचाल के शब्द:

"यह स्वीकार किया जाता है कि न्यायालयों को यह मानना चाहिए कि

विधायिका समझती है और सही ढंग से सराहना करती है

अपने लोगों की आवश्यकताएँ, कि इसके कानून निर्देशित किए जाते हैं

अनुभव द्वारा प्रकट की गई समस्याएं और यह कि भेदभाव पर्याप्त आधारों पर आधारित होते हैं।

440. यह देखा गया था (से संबंधित एक मुद्दे पर

मृत्युदंड की संवैधानिकता) मकवान्याने 437 में

गुलाल:

"जनमत की जांच के लिए कुछ प्रासंगिकता हो सकती है,

लेकिन अपने आप में, यह निहित कर्तव्य का कोई विकल्प नहीं है

न्यायालयों को संविधान की व्याख्या करने और इसके प्रावधानों को बनाए रखने के लिए

भय या पक्षपात के बिना प्रावधान। अगर जनमत था

निर्णायक होने के लिए संवैधानिक होने की कोई आवश्यकता नहीं होगी

न्यायनिर्णयन। तब अधिकारों की सुरक्षा को छोड़ दिया जा सकता है

संसद को, जिसे जनता से जनादेश प्राप्त है, और

जिस तरह से इसका जनादेश है, वह जनता के प्रति जवाबदेह है प्रयोग किया गया, लेकिन यह संसद में वापसी होगी

संप्रभुता, और नई कानूनी व्यवस्था से पीछे हटना

1993 के संविधान द्वारा स्थापित।

यह न्यायालय अपने कर्तव्य से भटकने की अनुमति नहीं दे सकता है।

द्वारा संविधान के एक स्वतंत्र मध्यस्थ के रूप में कार्य करना

इस आधार पर चुनाव करना कि उन्हें अनुग्रह मिलेगा

जनता को। अपनी असहमति में न्यायमूर्ति पॉवेल की टिप्पणी

फुरमैन बनाम जॉर्जिया दोहराता है:

..... साक्ष्य का भार इंगित करता है कि जनता

आम तौर पर इतने जुनून से समर्थित विचारों की नैतिकता या सामाजिक योग्यता को स्वीकार नहीं किया है।

उन्मूलन के लिए मुखर प्रवक्ताओं द्वारा। लेकिन फिर भी

17 चास्कलोन के अनुसार, जे पैराग्राफ 88 और 89 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

अनाकार गिरावट और जनता के प्रवाह का आकलन किया जा सकता है।
इस अस्थिर मुद्दे पर आम तौर पर राय, इस प्रकार की

संवैधानिक मामलों में प्रक्रिया। का मूल्यांकन
लोकप्रिय राय अनिवार्य रूप से एक विधायी है, न कि एक

न्यायिक, कार्य। 438

वेस्ट में जस्टिस जैक्सन की टिप्पणी भी ऐसी ही है।

वर्जीनिया राज्य शिक्षा बोर्ड बनाम बार्नेट:

अधिकारों के विधेयक का उद्देश्य ही वापस लेना था

राजनीतिक परिवर्तनों से कुछ विषय
विवाद, उन्हें पहुंच से बाहर रखने के लिए

बहुसंख्यक और अधिकारी और उन्हें कानूनी के रूप में स्थापित करना
न्यायालय द्वारा लागू किए जाने वाले सिद्धांत। एक का अधिकार है

जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एक स्वतंत्र प्रेस,

पूजा और सभा की स्वतंत्रता और अन्य

मौलिक अधिकारों को मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है; वे

यह चुनाव न होने के परिणाम पर निर्भर करता है। 439

इसे अलग तरीके से कहें तो: 'न्यायिक शाखा की वैधता

अंततः निष्पक्षता के लिए इसकी प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है और गैर-पक्षपात। '440 जनमत, के माध्यम से प्रकट

संसद या अन्यथा, वास्तव में महत्वहीन हो जाती है।

कानून जिसकी व्याख्या निष्पक्ष और गैर-पक्षपातपूर्ण तरीके से की जाती है तरीके से।

441. यह सराहना की जानी चाहिए कि बहस नहीं हो सकती है

एक असंवैधानिक लेकिन लोकप्रिय की स्वीकृति तक कम हो गया

निर्णय बनाम एक संवैधानिक लेकिन अलोकप्रिय निर्णय। सब कुछ

हम संविधान से बंधे हैं और न्यायाधीशों को इसका पालन करना पड़ता है

संविधान और कानूनों को बनाए रखने के लिए पद की शपथ, यहां तक कि

यदि निर्णय अलोकप्रिय या संसद के लिए अस्वीकार्य है। यह न्यायिक समीक्षा का सार है अन्यथा कोई कानून पारित नहीं किया गया है

संसद (स्पष्ट रूप से एक लोकप्रिय जनादेश के साथ) हो सकती है

438 408 अमेरिका 238,290 (1972) 439 319 अमेरिका 624,638 (1943)

440 मिस्ट्रेटा वी। संयुक्त राज्य अमेरिका, 488 यू. एस. 361,407 (1989)

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

असंवैधानिक के रूप में मारा गया।

(च) समय का गुजरना

442. अंत में, यह विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया था

इसने दिखाया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली जो मूल रूप से चालू थी (जिसमें कार्यपालिका के पास अंतिम अधिकार होता है) शक्ति) और कॉलेजियम प्रणाली (जिसमें न्यायपालिका के पास था

साझा जिम्मेदारी) दोनों ने कुछ नकारात्मक परिणाम दिए थे। यह प्रस्तुत किया गया था कि लाखों मामले लंबित हैं, व्यक्ति

जिन्हें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए था

न्यायाधीश बनने के योग्य न केवल नियुक्त किए गए थे बल्कि लाए गए थे इस अदालत में। 99 वां संविधान संशोधन अधिनियम चाहता है कि -

एक समय अवधि में पैदा हुए असंतुलन को ठीक करें और तब से

संवैधानिक प्रयोगों की अनुमति है, 99 वां

संविधान संशोधन अधिनियम को पारित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

443. इसमें कोई संदेह नहीं है कि समय बीतने के साथ

समाज में और समाज के विकास में परिवर्तन होते हैं

कानून। वास्तव में, एकमात्र स्थिरांक परिवर्तन है। पश्चिमी राज्य में

बंगाल बनाम. अनवर अली सरकार 1 41 इसे स्वीकार किया गया था

न्यायमूर्ति मेहर चंद महाजन ने कहा कि सद्भावना और ज्ञान

विधायिका की ओर से मौजूदा शर्तों का होना चाहिए

अनुमान लगाया गया। इसकी सराहना करते हुए बाद में इसे राम में देखा गया।

कृष्ण डालमिया ने कहा:

"संवैधानिकता की धारणा को बनाए रखने के लिए

न्यायालय सामान्य मामलों पर विचार कर सकता है

ज्ञान, सामान्य रिपोर्ट के मामले, इतिहास

समय और तथ्यों की हर स्थिति को मान सकते हैं जो हो सकता है

कानून के समय मौजूद कल्पना की गई।

444. केशवानंद भारती में न्यायमूर्ति हेगड़े और

न्यायमूर्ति मुखर्जी ने कहा कि: 'समाज बढ़ता है, उसका

441 [1952] एस. सी. आर. 284 (सात न्यायाधीशों की पीठ)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आवश्यकताएँ बदलती हैं। संविधान और कानून हो सकते हैं
उन जरूरतों के अनुरूप बदला जाए। कोई भी पीढ़ी ऐसा नहीं कर सकती
आने वाली पीढ़ी के पाठ्यक्रम को बांधें। 442

445. न्यायमूर्ति खन्ना ने विचार व्यक्त किया (और यह था
विद्वान महान्यायाधीश द्वारा भरोसा किया गया) कि संविधान
यह भविष्य के लिए भी है और इसमें प्रयोग और परीक्षण के लिए पर्याप्त प्रावधान होना चाहिए। न्यायमूर्ति
खन्ना ने यही कहा:

"यह भी ध्यान में रखना होगा कि संविधान नहीं है

एक द्वार लेकिन एक सड़क। संविधान के प्रारूपण के तहत
क्या यह जागरूकता है कि चीजें स्थिर नहीं रहती हैं लेकिन चलती हैं

एक प्रगतिशील राष्ट्र का जीवन, एक व्यक्ति के रूप में, है
स्थिर और स्थिर नहीं बल्कि गतिशील और तेज। इसलिए संविधान में पर्याप्त प्रावधान होना चाहिए -

प्रशासन के कार्य में प्रयोग और परीक्षण। ए.

संविधान, इस पर जोर देने की आवश्यकता है, एक नहीं है

तेज द्वंद्वत्मकता के लिए दस्तावेज़ लेकिन के साधन

लोगों के जीवन का आदेश देना। इसकी जड़ें अतीत में थीं,
इसकी निरंतरता वर्तमान में परिलक्षित होती है और इसका इरादा है

अज्ञात भविष्य के लिए। 443

446. फैसले में थोड़ी देर बाद, विद्वान न्यायाधीश

अब्राहम वी। संयुक्त राज्य अमेरिका और न्यायमूर्ति होम्स का हवाला देते हुए

उन्होंने कहा:

"राष्ट्र का संविधान बाहरी और दृश्य होता है।

लोगों के जीवन की अभिव्यक्ति और इसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए

भीतर परिवर्तन के लिए गहरी स्पंदन के लिए। एक संविधान

यह एक प्रयोग है क्योंकि सारा जीवन एक प्रयोग है। अगर

प्रयोग विफल रहता है, बनाने के लिए प्रावधान होना चाहिए

एक और "। 445

447. सौभाग्य से देश के लोगों के लिए,

442 पैराग्राफ 634

443 पैरा 1437

444 250 यू. एस. 616 (1919)

445 पैराग्राफ 1563 सुप्रीम कोर्ट के वकील-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

न्यायपालिका की स्वतंत्रता 'प्रशासन का कार्य' नहीं है न ही भारत का संविधान एक असफल प्रयोग है और न ही ऐसा है

'दूसरे के लिए प्रावधान करने' की कोई आवश्यकता। अगर बुनियादी संविधान की संरचना को इसके माध्यम से बदला जाना है

प्रयोग या अन्यथा, फिर इसे उखाड़ फेंकना आवश्यक है। यह एक साधारण दस्तावेज़ नहीं है जिसके साथ प्रयोग किया जा सकता है या

कट एंड पेस्ट विधि के माध्यम से बदला गया। भले ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता एक बुनियादी संरचना है संविधान और लोकतंत्र का एक स्तंभ होने के नाते यह हो सकता है

के साथ प्रयोग किया, लेकिन केवल अगर यह परिवर्तन किए बिना संभव है

बुनियादी संरचना। न्यायपालिका की स्वतंत्रता एक अवधारणा है मनमानी के खिलाफ लोगों को लाभान्वित करने के लिए सदियों से विकसित किया गया

शक्ति का प्रयोग। यदि प्रयोग के दौरान, स्वतंत्रता

न्यायपालिका खो गई है, यह हमेशा के लिए चली गई है और इसे फिर से हासिल नहीं किया जा सकता है केवल यह निष्कर्ष निकालकर कि स्वतंत्रता का नुकसान एक असफल है

प्रयोग करें। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भौतिक नहीं है

लेकिन आध्यात्मिक। न्यायपालिका की स्वतंत्रता नहीं है

प्लास्टिक की तरह कि इसे किसी भी तरह से ढाला जा सकता है।

448. इसका मतलब यह नहीं है कि संविधान को मान्यता देनी चाहिए।

समय के साथ केवल भौतिक परिवर्तन होते हैं-निश्चित रूप से नहीं।

मार्ग के साथ नए विचार और विचार उत्पन्न होते हैं

समय और सोच की एक रेखा जो कुछ दशकों तक स्वीकार्य थी

पहले आज स्वीकार्य नहीं हो सकता है और आज जो स्वीकार्य है

हो सकता है कि एक दशक बाद यह स्वीकार्य न हो। लेकिन बुनियादी अवधारणाएँ

जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, कानून का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सभी बुनियादी संरचना के घटक हैं।

हमारा संविधान अवधारणाओं के रूप में अपरिवर्तनीय है, हालांकि बारीकियां हैं

बदल सकता है। इन बुनियादी अवधारणाओं का असफल प्रयोग होगा

विनाशकारी परिणामों की ओर ले जाता है। यह संभव नहीं है कि

राजतंत्र या तानाशाही की कोशिश करने या धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रयोग करें भारत
लगभग दस या पंद्रह वर्षों तक एक धार्मिक राज्य में रहा और

देखें कि प्रयोग कैसे काम करता है। न ही कानून के शासन को निलंबित करना या न्यायपालिका की स्वतंत्रता को छीनना संभव है लगभग दस या पंद्रह वर्षों तक और देखें कि प्रयोग कैसे काम करता है।

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ये अवधारणाएँ प्रयोग के लिए बहुत मूल्यवान हैं।

449. हां, संविधान की व्याख्या जीविका के रूप में की जानी चाहिए

आने वाले वर्षों और वर्षों के लिए जैविक दस्तावेज़, लेकिन इसके भीतर

स्वीकृत मापदंड। यह मुख्य न्यायाधीश डिक्सन द्वारा कहा गया था

द क्वीन बनाम में कनाडा का सर्वोच्च न्यायालय। बेयुरेगार्ड 1 46:

"कनाडा का संविधान 119 में हमेशा के लिए बंद नहीं है।
एक साल पुराना ताबूत। यह जीवित है और सांस लेता है और सक्षम है

देश और उसके विकास के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए बढ़ रहा है

लोग। तदनुसार, यदि संविधान समायोजित कर सकता है,

जैसा कि है, 1867 के हवाई जहाजों में अज्ञात कई विषय, परमाणु
ऊर्जा, पनबिजली यह निश्चित रूप से तनावपूर्ण खंड नहीं है

100 यह कहने के लिए बहुत अधिक है कि 'पेंशन' शब्द, निश्चित रूप से

1867 में एक अर्थ में समझा गया, आज संघीय का समर्थन कर सकता है

एक अलग समझ पर आधारित कानून

'पेंशन' 447
खन्ना के दिमाग में थी।

450. संभवतः यही बात जस्टिस

जब विद्वान न्यायाधीश ने अज्ञात भविष्य की बात की।

एक कानून और पैकेज सौदे को चुनौती

451. विद्वान महान्यायवादी ने भी कहा

किसी कानून को चुनौती देने के लिए कानूनी आधार। यह आवश्यक था क्योंकि

वह 99 वें संविधान की चुनौती को अलग करना चाहते थे

संशोधन अधिनियम और एनजेएसी अधिनियम। सिद्धांत रूप में, अलगाव

न्यायसंगत होगा, लेकिन जहां तक इस मामले का संबंध है,

विद्वान महान्यायवादी ने तर्क दिया था कि 99 वां संविधान

संशोधन अधिनियम और एन. जे. ए. सी. अधिनियम एक 'पैकेज सौदा' थे और इसमें वह सही है। संसद के दोनों सदनों में लगभग एक ही समय में दोनों पर चर्चा और बहस हुई, दोनों को भेजा गया

राष्ट्रपति को एक ही समय में सहमति के लिए और वास्तव में थे

एक ही समय में सहमति दी गई और अंत में दोनों को अधिसूचित किया गया

उसी समय। अंतर केवल इतना था कि 99 वें

संविधान संशोधन अधिनियम का अनुसमर्थन करना पड़ा

446 [1986] 2 एस. सी. आर 56 अनुच्छेद

447 पैराग्राफ 46 सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

प्रक्रिया, एन. जे. ए. सी. अधिनियम ने नहीं किया। इसलिए यह उस देश के सामने प्रस्तुत एक 'पैकेज सौदा' था जिसमें 99 वां संविधान था।

संशोधन अधिनियम और एन. जे. ए. सी. अधिनियम इतने परस्पर जुड़े हुए थे कि एक दूसरे के संदर्भ के बिना काम नहीं कर सकता था। वास्तव में,

अनुसमर्थन प्रक्रिया से गुजरे, लेकिन वह असमर्थ थे किसी भी कानून, न्यायिक मिसाल के साथ अपने तर्क का समर्थन करें,

सम्मेलन या अभ्यास। यह सवाल अधिक के लिए खुला छोड़ दिया गया है। अवसर आने पर उचित स्तर पर चर्चा की जाए।

452. जो भी हो, एक चुनौती के संदर्भ में

कानून, यह विद्वान अटॉर्नी-जनरल द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि

इस तरह की चुनौती के सिद्धांत एक से काफी अलग हैं

संवैधानिक संशोधन को चुनौती देना। वह इस मामले में सही है।

प्रस्तुत करना। 453. स्वीकृत दृष्टिकोण यह है कि एक संसदीय कानून को केवल तभी निरस्त किया जा सकता है जब वह विधायी क्षमता से परे हो।

या *Art.13* या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। बुनियादी संरचना

किसी कानून को निरस्त करने के लिए सिद्धांत उपलब्ध नहीं है। यह आयोजित किया गया था

ए. पी. बनाम राज्य में मैकडॉवेल एंड कंपनी 448 ने कहा:

"संसद या उस मामले के लिए राज्य की शक्ति

विधायिकाएँ दो तरह से प्रतिबंधित हैं। द्वारा बनाया गया एक कानून

संसद या विधायिका को अदालतों द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

केवल दो आधारों और दो आधारों पर।, (1) की कमी

विधायी क्षमता और (2) में से किसी का उल्लंघन

भाग III में गारंटीकृत मौलिक अधिकार

संविधान या किसी अन्य संवैधानिक प्रावधान का। कोई तीसरा आधार नहीं है।

454. लोक सेवा न्यायाधिकरण में इस दृष्टिकोण का पालन किया गया था

बार एसोसिएशन वी। निम्नलिखित शब्दों में *U.P.449* की स्थिति:

"किसी अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जा सकती है।

केवल दो आधारों पर। (1) विधायी क्षमता की कमी;

448 (1996) 3 एस. सी. सी. 709 पैरा 43 449 (2003) 4 एस. सी. सी. 104 पैरा 26 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

संविधान के भाग III या किसी अन्य में गारंटीकृत
संवैधानिक प्रावधान। ए. पी. बनाम राज्य में मैकडॉवेल और

को इस न्यायालय ने राय दी है कि उपरोक्त दो को छोड़कर

ऐसा कोई तीसरा आधार नहीं है जिसके आधार पर
 सक्षम विधायिका द्वारा बनाया गया कानून हो सकता है
 अमान्य किया गया और अमान्य होने का आधार होना चाहिए
 आवश्यक रूप से चार कोनों के भीतर आता है
 उपरोक्त दो आधार "।

455. इससे पहले, इस न्यायालय ने बहुत व्यापक दृष्टिकोण अपनाया था
 छोटाभाई में एक कानून को चुनौती देने का मुद्दा
 जेठाभाई पटेल बनाम। भारत संघ। 450 इसमें यह माना गया था कि विधायी क्षमता और
 संविधान के अनुच्छेद 13 के उल्लंघन के सवाल के अलावा, एक कानून को चुनौती दी जा सकती है
 यदि इसका अधिनियमन एक प्रावधान द्वारा निषिद्ध किया गया था
 संविधान। यह इस प्रकार आयोजित किया गया था:
 "यदि अनुच्छेद 265 के कारण प्रत्येक कर लगाया जाना है
 "कानून" द्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि यह केवल हो सकता है

एक कानून द्वारा लागू किया गया जो अनुरूपता द्वारा मान्य है
 संबंधित अनुच्छेदों में निर्धारित मानदंड
 संविधान। ये हैं कि कानून (1) के भीतर होना चाहिए।
 विधायिका की विधायी क्षमता
 अनुसूची VII में विधायी प्रविष्टियों द्वारा कवर किया गया
 संविधान; (2) कानून को किसी के द्वारा निषिद्ध नहीं किया जाना चाहिए।
 उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 276 (2), 286 आदि, और (3) विधि या
 अनुच्छेद के तहत इसका प्रासंगिक हिस्सा अमान्य नहीं होना चाहिए।
 13 उन स्वतंत्रताओं के प्रति तिरस्कार के लिए जो
 संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत जो हैं -
 विषय के लिए प्रासंगिक-कानून का मामला।

456. इस दृष्टिकोण को किहोतो होलोहन में आगे बढ़ाया गया था।
 वी. Zachillhu 451 जिसमें यह माना गया था कि के लिए प्रक्रिया
 450 1962 संप. (2) एस. सी. आर. 1 = ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 104 (पाँच न्यायाधीशों की पीठ) 451।
 1992 सप्लीमेंट (2) एस. सी. सी. 651 पैरा 61 और 62 (पाँच न्यायाधीशों की पीठ)

सर्वोच्च न्यायालय-चालू-रिकॉर्ड संगठन v. यू. ओ. आई. /मदन बी. लोकर, जे. जे.

एक 'कानून' बनाने का पालन किया जाना चाहिए। हालांकि यह स्पष्ट रूप से नहीं है कहा गया है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यदि प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है तो

उस हद तक 'कानून' का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस मामले में यह

अभिनिर्धारित किया कि संविधान की दसवीं अनुसूची का अनुच्छेद 7

अनुच्छेद के परंतुक के खंड (बी) के संदर्भ में अनुसमर्थन की आवश्यकता

368 (2) संविधान से। यह आयोजित किया गया था:

"कि पृष्ठभूमि और विकास को ध्यान में रखते हुए

संविधान (बावनवा संशोधन) अधिनियम, 1985 के अंतर्निहित सिद्धांत, जहां तक यह लागू करना चाहता है।

भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची,

दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद 7 के प्रावधान

संविधान संदर्भ में और प्रभावी रूप से एक बदलाव लाता है

अनुच्छेद 136, 226 और 227 के संचालन और प्रभाव में

भारत के संविधान का और इसलिए, संशोधन परंतुक के अनुसार पुष्टि करने की आवश्यकता होगी

भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के उप-अनुच्छेद (2) के लिए।

457. कड़ाई से बोलते हुए, इसलिए, एक संशोधन

संविधान को तभी चुनौती दी जा सकती है जब यह संविधान की मूल संरचना को बदल दे और किसी कानून को चुनौती दी जा सके यदि: यह है।

विधानमंडल की क्षमता से परे; (2) यह संविधान के अनुच्छेद 13 का उल्लंघन करता है; (3) यह एक निषेध के विपरीत अधिनियमित किया गया है।

संविधान में; और (4) यह निम्नलिखित का पालन किए बिना अधिनियमित किया गया है संविधान में निर्धारित प्रक्रिया।

458. साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया है

न्यायालय ने कहा कि किसी कानून के प्रावधान के दुरुपयोग की संभावना है

इसे नीचे गिराने के लिए कोई आधार नहीं। शिकायत की गई कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा के माध्यम से हमेशा शक्ति के दुरुपयोग की जांच की जा सकती है। से। डी. के. त्रिवेदी एंड संस बनाम गुजरात राज्य 452 में कहा गया था:

"जहाँ कोई कानून विवेकाधीन शक्तियाँ प्रदान करता है
कार्यपालक या प्रशासनिक प्राधिकारी, वैधता या
ऐसी शक्ति की संवैधानिकता का आंकलन इस आधार पर नहीं किया जा सकता है कि
यह धारणा कि कार्यपालक या ऐसा प्राधिकारी कार्य करेगा

452 1986 मान लीजिए पैराग्राफ 50 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर. में एस. सी. सी.
20।

उसे प्रदान किया गया। यदि कार्यपालक या प्रशासनिक
प्राधिकरण मनमाने तरीके से कार्य करता है, इसकी कार्रवाई होगी

कानून में खराब और अदालतों द्वारा खारिज किए जाने के लिए उत्तरदायी है लेकिन शक्ति के दुरुपयोग
या मनमाने ढंग से प्रयोग की संभावना

शक्ति प्रदान करने वाले कानून को शक्ति अमान्य नहीं कर सकती है।

या वह शक्ति जो उसके द्वारा प्रदान की गई है।
459. इसी तरह, न्यायमूर्ति बी. पी. जीवन रेड्डी (न्यायमूर्ति की ओर से बोलते हुए)

न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा, न्यायमूर्ति S.C.Agrawal, न्यायमूर्ति ए. एस. आनंद,

न्यायमूर्ति बी. एन. कृपाल और स्वयं) मफतलाल इंडस्ट्रीज में आयोजित लिमिटेड वी. भारत संघ 453.

"यह समान रूप से अच्छी तरह से तय है कि केवल दुरुपयोग की संभावना है

इसे प्रशासित करने के प्रभारी लोगों द्वारा एक प्रावधान नहीं किया जा सकता है

प्रावधान को प्रक्रियात्मक रूप से रखने के लिए एक आधार हो या
काफी हद तक अनुचित। सीमा शुल्क कलेक्टर बनाम।

नथेल्ला संपथु चेट्टी, इस न्यायालय ने टिप्पणी की: "द.

किसी कानून के दुरुपयोग की संभावना अन्यथा वैध नहीं है

इसे अयोग्यता का कोई भी तत्व प्रदान करें। राज्य में कहा गया है
राजस्थान बनाम। भारत संघ ", यह याद रखना चाहिए

केवल इसलिए कि कभी-कभी सत्ता का दुरुपयोग किया जा सकता है,

यह शक्ति के अस्तित्व को नकारने का कोई आधार नहीं है। द.
मनुष्य का ज्ञान अभी तक एक की कल्पना करने में सक्षम नहीं है
इन सब का जवाब देने के लिए पर्याप्त शक्ति के साथ सरकार
वैध आवश्यकताएँ और साथ ही असमर्थ
शरारत "। (कॉमआर को भी देखें), एच. आर. ई. वी. श्री लक्ष्मींद्र
श्री शिरूर मठ के तीर्थ स्वामी। " (आंतरिक उद्धरण
हटा दिया गया)

संविधान का अनुच्छेद 122

460. मूल मुद्दे से निपटने से पहले

हमारे सामने चुनौती, यह उल्लेख किया जा सकता है कि श्री फली एस।
नरीमन ने तर्क दिया कि संसद के पास नहीं था
99 वें संविधान तक एन. जे. ए. सी. अधिनियम को पारित करने की क्षमता
453 (1997) 5 पैराग्राफ 88 में एस. सी. सी. 536 सर्वोच्च अदालतें-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

संशोधन अधिनियम लागू किया गया था या कम से कम यह था

99 वें संविधान के पारित होने के बाद से प्रस्तुत करना संशोधन अधिनियम और एनजेएसी
अधिनियम समकालीन थे, यदि

संसद में प्रक्रिया की किसी भी कथित अनियमितता के आधार पर प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा, यह पता
लगाना संभव नहीं है संसद की कार्यवाही में।

461. बाबूलाल पराटे बनाम। बॉम्बे राज्य 454 यह न्यायालय

जोड़ दिया, एक पोस्ट-स्क्रिप्ट के माध्यम से, के अनुच्छेद 122 (1) पर इसका दृष्टिकोण
संविधान। यह देखा गया कि एक दिए गए काल्पनिक में
जिस स्थिति में प्रश्न कार्यवाही की वैधता नहीं होगी
संसद लेकिन एक संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन। यह था।

उन्होंने इस प्रकार कहा:

"शायद इसके बारे में कुछ और शब्द जोड़ने की सलाह दी जाती है।

कला. 122 (1) संविधान से। के लिए सीखा परामर्श

अपीलार्थी ने हमारे सामने यह प्रश्न रखा है कि यदि किसी विधेयक में पूरी तरह से है तो उस अनुच्छेद का क्या प्रभाव होगा?

सी. एल. एस. में निर्दिष्ट किसी भी मामले से असंबंधित। (ए) से

((ड) कला। 3 एक संशोधन प्रस्तावित किया जाना था और

किसी राज्य का नाम बदलना (उदाहरण के लिए) स्वीकार किया गया।

हमें नहीं लगता कि हमें इस तरह के काल्पनिक जवाब देने की जरूरत है।

केवल यह कहने के अलावा कि यदि कोई संशोधन है
ऐसा चरित्र कि यह वास्तव में एक संशोधन नहीं है और

यह स्पष्ट रूप से कला का उल्लंघन है। 3, तब सवाल नहीं होगा

संसद में कार्यवाही की वैधता लेकिन उल्लंघन

एक संवैधानिक प्रावधान "।

462. राजा राम पाल बनाम। लोकसभा 455 का प्रश्न

संसदीय मामलों की न्यायिक समीक्षा की सीमा सामने आई

विचार के लिए। न्यायमूर्ति के. जी. बालकृष्णन की ओर से बोलते हुए,

454 [1960 (1) एस. सी. आर. 605 (पाँच न्यायाधीशों की पीठ)

455 (2007) 3 एस. सी. सी. 184 (पाँच न्यायाधीशों की पीठ)

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

डी. के. जैन और स्वयं, यह मुख्य न्यायाधीश सभरवाल द्वारा आयोजित किया गया था,

सी. ए. डी. के संदर्भ में कि प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ

संसद अपने चार हिस्सों में जो कुछ भी होता है उसे पूर्ववत या दूषित नहीं कर सकती है।

दीवारें, यानी आंतरिक संसदीय कार्यवाही। हालांकि,

ऐसी कार्यवाहियाँ जो मूल रूप से अवैध या असंवैधानिक हैं,

अनियमित के विपरीत संविधान के अनुच्छेद 122 (1) द्वारा न्यायिक जांच से संरक्षित नहीं हैं। 456

463. जहाँ तक एन. जे. ए. सी. अधिनियम का संबंध है, कुछ भी नहीं है।

या इसके पारित होने में कुछ भी असंवैधानिक इस अर्थ में कि संविधान का कोई प्रावधान या कोई मूल नियम

संसदीय गतिविधि को विनियमित करने का उल्लंघन किया गया है। सबसे अच्छा, यह

यह तर्क दिया जा सकता है कि प्रक्रियात्मक रूप से उल्लंघन हुआ था लेकिन हमारे

प्रक्रिया के नियमों और निर्णय की ओर ध्यान आकर्षित किया गया

अधिनियम और उसका पारित होना। न्यायमूर्ति खेहर ने विस्तार से बात की है इस मुद्दे को उनके मसौदा निर्णय में पर्याप्त विस्तार से बताया गया है और जो कहा गया है उसे दोहराना आवश्यक नहीं है।

जिन संशोधनों को चुनौती दी गई है-चर्चा

464. हालाँकि किसी को भी न्यायाधीश नियुक्त होने का अधिकार नहीं है

उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में से किसी में भी, इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने से इनकार कर सकते हैं

बिना किसी तुकबंदी या कारण के और न ही इसका यह अर्थ है कि राष्ट्रपति

किसी भी योग्य व्यक्ति को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। इसके तहत

भारत सरकार अधिनियम, 1919 और भारत सरकार अधिनियम, 1935 दोनों को करने का निरंकुश विवेकाधिकार क्राउन के पास था

राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश के बीच उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति। वहाँ थे।

इसके कारण जैसा कि ऊपर बताया गया है। 99 वें से पहले

456 पैराग्राफ 360 (दो), 366 सर्वोच्च न्यायालय अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड संगठन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकर, जे.]

संविधान संशोधन अधिनियम, के अनुच्छेद 124 (2) के तहत

संविधान, राष्ट्रपति को कुछ लोगों से परामर्श करने का विवेकाधिकार था उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीश, जैसे -

राष्ट्रपति ने इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझा। वैसा ही।

जहाँ तक संवैधानिक स्थिति प्रबल थी (मुतातिस उत्परिवर्तन)

अनुच्छेद 217 (1) के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति

संविधान का संबंध था। संविधान का अनुच्छेद 124 (2)

संविधान में तीन बुनियादी तत्व थे: की शक्ति

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति; मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श की एक अनिवार्य आवश्यकता

भारत के अन्य न्यायाधीशों के साथ एक विवेकाधीन परामर्श

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय।

465. 99 वां संविधान संशोधन अधिनियम

नियुक्ति प्रक्रिया में राष्ट्रपति की भूमिका को बदला गया
संशोधित किया गया

साथ ही अनिवार्य परामर्श को मूल रूप से

भारत के मुख्य न्यायाधीश और एन. जे. ए. सी. की सिफारिश द्वारा पूरी प्रक्रिया को प्रतिस्थापित या प्रतिस्थापित किया। नीचे दी गई तालिका

के अनुच्छेद 124 (2) में किए गए पाठ्य परिवर्तन देता है

संविधान।

पूर्व-संशोधन

संशोधन के बाद

प्रावधान

प्रावधान

124. स्थापना

124. स्थापना

और का संविधान

और का संविधान

सुप्रीम कोर्ट। - (1)

सुप्रीम कोर्ट। - (1)

वहाँ एक होगा

वहाँ एक होगा

सर्वोच्च न्यायालय का

सर्वोच्च न्यायालय का

भारत में एक

भारत में एक

भारत के मुख्य न्यायाधीश

भारत के मुख्य न्यायाधीश

और, संसद तक

और, संसद तक

कानून द्वारा निर्धारित किया गया है कि

कानून द्वारा निर्धारित किया गया है कि

अधिक संख्या में, नहीं

अधिक संख्या में, नहीं

सात से अधिक

सात से अधिक

न्यायाधीश।

न्यायाधीश।

[2015] 13 एस. सी. एफ.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(2) (2) उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश

सुप्रीम कोर्ट होगा

द्वारा नियुक्त

द्वारा नियुक्त

राष्ट्रपति आदेश द्वारा

राष्ट्रपति आदेश द्वारा

उसके हाथ और मुहर के नीचे

उसके हाथ और मुहर के नीचे

उनसे परामर्श करने के बाद

सिफारिश पर
 के न्यायाधीशों में से
 राष्ट्रीय न्यायिक
 नियुक्तियाँ
 सर्वोच्च न्यायालय और
 उच्च न्यायालयों में
 आयोग को संदर्भित किया गया
 राज्यों ने
 अनुच्छेद 124 क में और
 राष्ट्रपति मान सकते हैं
 जब तक वह प्राप्त नहीं कर लेता तब तक पद धारण करें
 के लिए
 साठ-पाँच वर्ष की आयु
 आवश्यक उद्देश्य और वर्षों तक रहेगा:
 कार्यालय जब तक वह प्राप्त नहीं करता है
 बशर्ते कि लोप किए गए में नियुक्ति का मामला
 इसके अलावा एक न्यायाधीश
 मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश
 भारत का न्याय करेगा हमेशा सलाह लें:
 बशर्ते कि-(ए) ए
 न्यायाधीश लिखित रूप से
 आगे कहा गया है कि
 उसके अधीन
 हाथ
 संबोधित किया गया
 (क) एक न्यायाधीश, द्वारा

द.

हाथ के नीचे लिखा

राष्ट्रपति ने दिया इस्तीफा

उसका

कार्यालय को संबोधित;

राष्ट्रपति ने दिया इस्तीफा

उसका (बी) एक न्यायाधीश हो सकता है

कार्यालय;

कार्यालय से हटा दिया गया

(ख) एक न्यायाधीश हो सकता है

जिस तरह से प्रदान किया गया है

उनके कार्यालय से हटा दिया गया

खंड (4)।

दिए गए तरीके से

खंड (4) में।

466. एन. जे. ए. सी. की संरचना सर्वोच्च न्यायालयों-चालू-रिकॉर्ड संगठन v के लिए प्रदान की गई है। यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

संविधान और अनुच्छेद 124 (2) को पढ़ा जाना आवश्यक है। एक दूसरे के साथ संयोजन। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन. जे. ए. सी. के अध्यक्ष हैं। एन. जे. ए. सी. के दो सदस्य हैं

मुख्य न्यायाधीश के बगल में सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश

भारत, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री और दो

एक समिति द्वारा नामित किए जाने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति

प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और नेता

लोकसभा में विपक्ष का, जिसमें विफल रहने पर लोकसभा के नेता

लोकसभा में सबसे बड़ा विपक्षी दल।

467. संविधान के अनुच्छेद 124 बी में दिए गए प्रावधान के अनुसार एनजेएसी का कर्तव्य नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करना है।

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीशों और अन्य लोगों के स्थानांतरण की सिफारिश करना।

एक उच्च न्यायालय से लेकर किसी अन्य उच्च न्यायालय तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। एन. जे. ए. सी. का कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि व्यक्ति

अनुशंसित क्षमता और अखंडता है।

468. संविधान के अनुच्छेद 124 सी में प्रावधान है कि

संसद विधि द्वारा प्रक्रिया को विनियमित कर सकती है -

भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति

सर्वोच्च न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश

उच्च न्यायालय। अनुच्छेद एन. जे. ए. सी. को निर्धारित करने का अधिकार देता है,

विनियम, अपने कार्यों के निर्वहन की प्रक्रिया,

नियुक्ति के लिए व्यक्तियों के चयन की रीति और ऐसे अन्य मामले जो आवश्यक माने जाएं।

469. उपरोक्त संशोधनों के साथ-साथ

संविधान, एनजेएसी अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया था। द. एन. जे. ए. सी. अधिनियम वरिष्ठतम न्यायाधीश की सिफारिश करने का प्रावधान करता है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उच्चतम न्यायालय का 'यदि उन्हें पद धारण करने के लिए उपयुक्त माना जाता है' और नामों की सिफारिश करने के लिए

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए जो व्यक्ति

इस प्रकार नियुक्त होने के पात्र हैं। दिलचस्प बात यह है कि 'एन. जे. ए. सी.' अदालत की रिपोर्टों की अध्यक्षता करेगा

[2015] 13 एस सी आर।

यदि कोई दो सदस्य हैं तो नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की सिफारिश नहीं करें।

आयोग की ऐसी सिफारिशों के लिए सहमति नहीं है ' (एन. जे. ए. सी. अधिनियम की धारा 5)। कुछ इसी तरह की प्रक्रिया

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (एन. जे. ए. सी. अधिनियम की धारा 6)।

470. राष्ट्रपति किसी विशेष व्यक्ति की न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए एन. जे. ए. सी. की सिफारिश को स्वीकार कर सकता है।

लेकिन एन. जे. ए. सी. को इस पर पुनर्विचार करने की भी आवश्यकता हो सकती है सिफारिश करें। यदि एन. जे. ए. सी. पहले इसकी पुष्टि करता है

राष्ट्रपति की सिफारिश का आदेश जारी करेगा नियुक्ति (एनजेएसी अधिनियम की धारा 7)।

471. एन. जे. ए. सी. के अधिकारी और कर्मचारी

के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एन. जे. ए. सी. और एन. जे. ए. सी. के संयोजक सचिव होंगे विधि और न्याय विभाग में भारत सरकार (एन. जे. ए. सी. अधिनियम की धारा 8)।

472. एक से न्यायाधीशों के स्थानांतरण की प्रक्रिया

उच्च न्यायालय को दूसरे के लिए निर्धारित करने के लिए छोड़ दिया गया है

एन. जे. ए. सी. (अधिनियम की धारा 9) द्वारा बनाए जाने वाले विनियम। इसी तरह, एन. जे. ए. सी. के संबंध में नियम बनाएगा -

अपने कार्यों के निर्वहन के लिए प्रक्रिया (धारा 10)

अधिनियम)।

473. केंद्र सरकार को अधिकार है कि वह

एन. जे. ए. सी. अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम (धारा 11)

) और आयोग इसका पालन करने के लिए नियम बना सकता है

एन. जे. ए. सी. अधिनियम (इसकी धारा 12) के प्रावधान। नियम हैं।

और केंद्र सरकार और एन. जे. ए. सी. द्वारा बनाए गए विनियमों को संसद के समक्ष रखा जाएगा और ये -

यदि संसद के दोनों सदन सहमत हों तो संशोधित

संशोधन और संसद यह भी प्रावधान कर सकती है कि एक नियम या

विनियमन का कोई प्रभाव नहीं होगा (इसकी धारा 13)।

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

474. विवाद का योग और सार यह है: अगर

99 वें संविधान द्वारा एनजेएसी की स्थापना

संशोधन अधिनियम संविधान की मूल संरचना को बदल देता है, 99 वें संविधान संशोधन अधिनियम
और एन. जे. ए. सी. अधिनियम को

असंवैधानिक घोषित किया जाए। स्थापना के बाद से संविधान के अनुच्छेद 124 ए द्वारा एन. जे.
ए. सी. 99 वें संविधान का अभिन्न अंग है।

संविधान संशोधन अधिनियम और एन. जे. ए. सी. अधिनियम और वे हैं
अलग नहीं किया जा सकता और अकेले खड़े नहीं हो सकते, उन्हें भी होना चाहिए
असंवैधानिक घोषित किया गया।

475. की संवैधानिक वैधता पर विचार करते हुए

99 संविधान संशोधन अधिनियम और एनजेएसी अधिनियम यह है

के संदर्भ में की गई प्रस्तुति से निपटने के लिए आवश्यक

अंग्रेजों द्वारा पारित संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 (सी. आर. ए.)

प्रस्तुतियाँ, एक से अधिक अवसरों पर। होना चाहा गया था सुझाव दिया कि यू. के. सुप्रीम कोर्ट में
न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाए

शर्तों में गठित न्यायिक नियुक्ति आयोग द्वारा

सी. आर. ए. और कुछ भी गलत नहीं है अगर कुछ समान है

प्रक्रिया हमारी संसद द्वारा अपनाई जाती है जहाँ के न्यायाधीश

उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश की जाती है -

एनजेएसी।

476. सी. आर. ए. और इसके कामकाज को जैक द्वारा प्रचारित किया गया था।

स्ट्रॉ; 2007 से 2010 तक लॉर्ड चांसलर। उस समय यह

लॉर्ड चीफ जस्टिस ब्रिटेन में न्यायपालिका के प्रमुख थे, लेकिन लॉर्ड चांसलर फिर भी न्यायपालिका को बनाए
रखने के लिए जिम्मेदार थे।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता '। 'न्यायिक' विषय पर तीसरे व्याख्यान में
गई नियुक्तियाँ

64 दिसंबर, 2012 को दी

हैमलिन व्याख्यानों की श्रृंखला जिसका शीर्षक है 'कानून सुधार के पहलू-एक' उन्होंने कहा:

अंदरूनी दृष्टिकोण

"सी. आर. ए. ने एक की स्थापना के लिए प्रदान किया

स्वतंत्र न्यायिक नियुक्ति आयोग (जेएसी)।

जे. ए. सी. को संचालन के लिए जिम्मेदार बनाया गया था

नियुक्तियों की प्रक्रिया और सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के लिए सिफारिशें करना

[2015] 13 एस सी आर।

सबसे वरिष्ठ को छोड़कर सभी के लिए प्रभु कुलाधिपति

नियुक्तियाँ। इन बहुत वरिष्ठ नियुक्तियों के लिए (से

अपील न्यायालय और प्रभाग प्रमुख के कार्यालय,

लार्ड चीफ जस्टिस, और राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति

और यू. के. सुप्रीम कोर्ट के सदस्य), अलग

सिफारिशें करने के लिए प्रावधान किया गया था

विशेष रूप से गठित चयन द्वारा लॉर्ड चांसलर को

पैनल।

प्रत्येक नियुक्ति के लिए, जे. ए. सी. या विशेष रूप से गठित चयन पैनल को एक बनाने की आवश्यकता थी

लॉर्ड चांसलर को सिफारिश "। 457

कि मुझे दर्दनाक अनुभव के माध्यम से पता चला,

" व्यवहार में, जैसा

इस व्यवस्था में कई समस्याएं थीं। 458

उच्च न्यायालय और अपील न्यायालय में नियुक्तियां सीमित होनी चाहिए। लेकिन हमारे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों के दो समूहों के लिए, और विभिन्न कारणों से, मेरे विचार में लॉर्ड चांसलर

द्वारा प्रदान की गई भूमिका से अधिक बड़ी भूमिका होनी चाहिए

संवैधानिक सुधार अधिनियम, या प्रदान किए जाने की संभावना है

वर्तमान अपराध और न्यायालय विधेयक द्वारा।

जिन दो समूहों के न्यायाधीशों की मैं बात कर रहा हूँ, वे हैं, सबसे पहले, अपील न्यायालय के सबसे वरिष्ठ सदस्य-यानी,

डिवीजन के प्रमुख और लॉर्ड मुख्य न्यायाधीश-और,

दूसरा, यू. के. सुप्रीम कोर्ट के सदस्य। द.

निष्कर्ष एक ही है, लेकिन तर्क हैं

अलग "। 459

के लिए 'विशेष रूप से गठित चयन पैनल'

ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति (उदाहरण के लिए) सी. आर. ए. की धारा 26 (5) में इसकी अनुसूची 8 के साथ पढ़ा जाता है और चयन पैनल में (ए) राष्ट्रपति होते हैं।

457 पृष्ठ 54 458 पृष्ठ 55

459 पृष्ठ 56 सर्वोच्च न्यायालय-चालू-रिकॉर्ड संगठन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

उच्चतम न्यायालय का, (बी) सर्वोच्च न्यायालय का उप-राष्ट्रपति न्यायालय, (ग) न्यायिक नियुक्तियों में से प्रत्येक में से एक सदस्य

आयोग, (ii) स्कॉटलैंड के लिए न्यायिक नियुक्ति बोर्ड,

((iii) उत्तरी आयरलैंड न्यायिक नियुक्ति आयोग। श्रेणी (सी) में कम से कम एक सदस्य गैर-कानूनी होना चाहिए।

योग्य '। इस तरह की रचना के साथ विशेष रूप से

गठित चयन पैनल 'जैक स्ट्रॉ के खिलाफ नहीं जा सका

एक नियुक्ति के संबंध में न्यायपालिका की इच्छाएँ, जैसा कि उसने नीचे अप्रत्यक्ष रूप से संदर्भित किया है:

"यह सब पहले से ही मान्यता प्राप्त है, कम से कम सिद्धांत रूप में, द्वारा

संवैधानिक सुधार अधिनियम, जो प्रदान करता है कि बहुत वरिष्ठ नियुक्तियों के इन दो समूहों को नहीं होना चाहिए

सामान्य न्यायिक नियुक्ति आयोग द्वारा की गई प्रक्रिया।

वरिष्ठ न्यायपालिका के बीच संबंध की वास्तविकता

और कार्यपालिका को भी लगभग हर दूसरे में मान्यता प्राप्त है

अधिकार क्षेत्र। कहीं और अब तक का सबसे सामान्य तरीका
 दुनिया में, जिसमें अच्छी तरह से काम करने वाला सामान्य कानून भी शामिल है
 क्षेत्राधिकार, संबंधित मंत्री के लिए है
 तीन से पाँच नामों की सिफारिश की, और उस मंत्री के लिए
 फिर इन नामांकित व्यक्तियों में से चुनने में सक्षम होने के लिए।
 यूनाइटेड किंगडम में हम जोर देने में बहुत असामान्य हैं
 कि मंत्री को केवल एक ही नाम मिलता है। यह है।
 केवल इस संदर्भ में स्पष्ट किया जा सकता है कि हम कहाँ आए हैं।

से: प्रभु कुलाधिपति का अनियंत्रित विवेक

1990 के दशक के मध्य तक, पूर्व की गैर-वैधानिक प्रकृति
 2005 व्यवस्थाएँ, अपारदर्शी निर्णय लेना

प्रक्रिया और इसकी बढ़ती आलोचना।

लेकिन इन के लिए ये शाब्दिक रूप से विशिष्ट व्यवस्थाएँ

वरिष्ठ नियुक्तियाँ, जिनका उद्देश्य न्यायपालिका और लॉर्ड चांसलर के बीच साझेदारी दृष्टिकोण बनाना
 है
 आवश्यकताओं की मान्यता में
 कार्यालयों की

सवाल, असंतोषजनक साबित हुए हैं।

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

व्यवहार में विस्तृत शब्दांकन और अपेक्षा दोनों

लॉर्ड चांसलर के लिए व्यायाम करना बहुत मुश्किल बना दें।

यहाँ तक कि अस्वीकार करने या अनुरोध करने की उसकी सीमित शक्तियाँ भी

किसी सिफारिश पर पुनर्विचार करना। जैसा कि एक बात है
 प्रेस में रिकॉर्ड, एक अवसर था जब, के रूप में

स्वामी कुलाधिपति, मैंने इन शक्तियों का उपयोग करने की कोशिश की।

चूँकि मैंने हमेशा गोपनीयता का पालन किया है

मैं यहाँ किसी भी विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह स्वीकार किया जाएगा कि मैंने व्यायाम करने की कोशिश नहीं की होगी

ये शक्तियाँ जब तक कि मुझे विश्वास न हो कि मेरे पास ऐसा करने के लिए अधिनियम के भीतर अच्छे आधार हैं, मैंने किया-अच्छे आधार, उतने ही

अब देख सकते हैं। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए काफी हद तक गया

कि मेरे कार्यों का अर्थ नहीं लगाया जा सकता था, जो वे थे

दूर से नहीं, पार्टी राजनीतिक के रूप में। मामले में,

किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सका। पक्षकारों को नियुक्ति-प्रक्रिया में सीधे शामिल कोई भी नहीं-प्रेस को व्यापक विवरण लीक किया, एक चुनाव था

जल्दबाजी में; मैंने नियुक्ति की पुष्टि की। 460

477. इस व्याख्यान और के वास्तविक काम करने के लिए विज्ञापन

सी. आर. ए., यह कहा जाता है कि वरिष्ठ स्तर के न्यायिक बनाने के लिए

न्यायपालिका की इच्छाओं के खिलाफ '। हाल ही में प्रकाशित एक लेख में सार्वजनिक कानून में कहा गया है:

"न्यायिक नियुक्तियाँ अगला सबसे बड़ा बदलाव हैं। जिसकी जिम्मेदारी लॉर्ड चांसलर के रूप में कार्यपालिका से न्यायपालिका में स्थानांतरित हो गई है। औपचारिक रूप से

प्रक्रिया का प्रबंधन स्वतंत्र न्यायिक द्वारा किया जाता है

नियुक्ति आयोग (जे. ए. सी.), लेकिन व्यवहार में

प्रक्रिया हर जगह न्यायपालिका से बहुत प्रभावित होती है।

स्टेज। शुरुआत में लॉर्ड चीफ जस्टिस से सलाह ली जाती है प्रत्येक प्रतियोगिता। न्यायाधीश केस स्टडी तैयार करते हैं और

460 पृष्ठ 57-59 सर्वोच्च न्यायालय के वकील-चालू-रिकॉर्ड संगठन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.] योग्यता परीक्षण। न्यायाधीश संदर्भ लिखते हैं। अजुडगे बैठता है

पैनल जो उम्मीदवारों का साक्षात्कार करते हैं; और न्यायाधीश हैं

वैधानिक परामर्श में परामर्श लिया गया। जेएसी पर, 7

15 आयुक्त न्यायाधीश होते हैं। एक बार जे. ए. सी.

निम्न स्तरों पर अपना चयन पूरा किया (सर्किट न्यायाधीश)
 और नीचे) सभी न्यायिक नियुक्तियाँ अब औपचारिक रूप से हैं
 लार्ड चीफ जस्टिस और ट्रिब्यूनल द्वारा बनाया गया
 नियुक्तियाँ वरिष्ठ राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं
 न्यायाधिकरण। लॉर्ड चीफ जस्टिस और एसपीटी अब हैं
 सभी न्यायिक नियुक्तियों के 97 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार।
 अधिक वरिष्ठ स्तरों पर नियुक्तियाँ अभी भी औपचारिक रूप से होती हैं।
 प्रभु कुलाधिपति द्वारा निर्णय लिया गया; लेकिन व्यवहार में यह है
 लॉर्ड चांसलर के लिए इसके खिलाफ जाना असंभव साबित हुआ
 न्यायपालिका की इच्छाएँ "। 461

ब्रिटेन में नियुक्ति प्रक्रिया और भारत में न्यायाधीशों की 'नियुक्ति' की आलोचना के लिए इतना!

478. हममें से किसी के लिए भी सी. आर. ए. पर टिप्पणी करना (किसी न किसी तरह से) संभव नहीं है सिवाय इसके कि यह कहना उचित नहीं है।

न्यायिक स्वतंत्रता के मूल्यों और अन्य देशों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की परंपराओं और प्रणालियों पर भरोसा करना

हमारे देश की स्थिति (और निर्णयों) को बेहतर ढंग से समझें इस न्यायालय द्वारा प्रस्तुत) और कैसे
 सबसे अच्छा संरक्षण और संरक्षण किया जाए

हमारे देश में मौजूद परिस्थितियों में न्यायिक स्वतंत्रता

देश और जगह में प्रणालियों के भव्य भ्रम नहीं है अन्य देश।

संविधान के अनुच्छेद 124 ए और 124 (2) की वैधता

संविधान-पैकेज सौदा

479. विद्वान महान्यायवादी की प्रस्तुति (के रूप में)

ऊपर उल्लिखित) यह है कि 99 वां संविधान संशोधन अधिनियम

401 सार्वजनिक कानून (2015): यू. के. में न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही दोनों रॉबर्ट हेज़ेल द्वारा
 संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 के परिणामस्वरूप मजबूत हुए हैं।

[2015] 13 एस सी आर।

और एन. जे. ए. सी. अधिनियम एक 'पैकेज सौदा' है और एक को दूसरे के बिना सराहा नहीं जा सकता है। इस पर होगी चर्चा इस समर्पण का प्रकाश।

480. शुरुआत में, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पैकेज

अधूरा है। 99 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम और

एन. जे. ए. सी. अधिनियम अनुत्तरित प्रश्नों की एक श्रृंखला उठाता है। के लिए

उदाहरण के लिए, एन. जे. ए. सी. से अपने कर्तव्यों का पालन करने की उम्मीद कैसे की जाती है?

क्या एन. जे. ए. सी. के कामकाज में कोई पारदर्शिता होगी और

संबोधित? विद्वान महान्यायवादी ने प्रस्तुत किया कि ए वड़ी संख्या में काल्पनिक मुद्दे और प्रश्न पूछे गए हैं।

न केवल याचिकाकर्ताओं द्वारा बल्कि पीठ द्वारा भी उठाया गया और यह

एक समग्र कानून और विनियमों के अभाव में उन सभी का जवाब देना संभव नहीं है।

99 वें संविधान संशोधन अधिनियम के अभिधारणाओं के साथ।

विद्वान महान्यायवादी की यह प्रस्तुति नहीं हो सकती है विशेष रूप से उनके विवाद को देखते हुए उनकी सराहना की गई

एक से अधिक अवसर, कि 99 वीं द्वारा क्या अधिनियमित किया गया है

संविधान संशोधन अधिनियम एक पैकेज सौदा है। जब तक सभी संभावनाओं का ध्यान नहीं रखा जाता है, पैकेज सौदा प्रस्तुत किया जाता है

देश के लिए एक खाली पैकेज है जिसमें रैपिंग पेपर है एन. जे. ए. सी. अधिनियम का रूप और 99 वें के रूप में एक रिबन

संविधान संशोधन अधिनियम। अगर सभी का जवाब देना संभव नहीं है

एक समग्र कानून, नियमों के अभाव में प्रश्न और

नियम, 99 वां संविधान लाने में क्या जल्दबाजी थी

संशोधन अधिनियम और एन. जे. ए. सी. अधिनियम आधे-अधूरे के रूप में लागू माप?

481. यह सच है कि संविधान निर्दिष्ट नहीं कर सकता है और

प्रत्येक विवरण को शामिल करें, विशेष रूप से प्रक्रियात्मक विवरण। 462 लेकिन उसी समय, की मूल आवश्यकताएँ

एन. जे. ए. सी. योजना 99 वें संविधान से स्पष्ट होनी चाहिए।

462 पंजाब राज्य बनाम देखें। सलिल सबलोक, (2013) रिपोर्ट का 5 एस. सी. सी. 1 अनुच्छेद 115।

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]
 एन. जे. ए. सी. अधिनियम के साथ पढ़ा गया संशोधन अधिनियम, विशेष रूप से जब यह
 नियुक्ति के एक मौजूदा तरीके को उखाड़ फेंकना चाहता है
 न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने वाले न्यायाधीश। महत्वपूर्ण
 कानून, अन्यथा एक अप्रिय अंतराल होगा बनाया, मामलों को बदतर बना दिया।

482. पैकेज सौदा पूरी तरह से जीवित रहना चाहिए या गिरना चाहिए
 एक संपूर्ण-टुकड़ों में अस्तित्व नहीं हो सकता है।

483. इस दृष्टि से देखने पर, की संवैधानिक वैधता
 संविधान के अनुच्छेद 124 ए के साथ पढ़ा गया अनुच्छेद 124 (2)
 99 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया जाना संदिग्ध है।
 कई कारणों से।

(क) एन. जे. ए. सी. और अध्यक्ष की भूमिका
 484. संविधान के अनुच्छेद 124 (2) में एन. जे. ए. सी. की आवश्यकता है।

इसके अनुच्छेद 124 ए के तहत गठित
 एक की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश
 उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। श्री फली एस.
 नरीमन ने बताया कि जहां तक एन. जे. ए. सी. का संबंध है, यह
 यह स्पष्ट नहीं है कि क्या राष्ट्रपति का मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति से है
 अपनी व्यक्तिगत क्षमता या मंत्रिपरिषद में। द.

राष्ट्रपति का मतलब निश्चित रूप से व्यक्ति नहीं हो सकता है अन्यथा 99 वीं द्वारा
 अभिनिर्धारित न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया

संविधान संशोधन अधिनियम और एन. जे. ए. सी. अधिनियम साम्राज्य में एक साम्राज्य का निर्माण करेंगे जो
 संविधान

सभा को जानबूझकर टाल दिया गया। दूसरी ओर, यदि

राष्ट्रपति का अर्थ है मंत्रिपरिषद, तो किस आधार पर? क्या मंत्रिपरिषद/राष्ट्रपति एन. जे. ए. सी. से पूछ सकते हैं (के तहत)

एन. जे. ए. सी. अधिनियम की धारा 7 का परंतुक) अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने के लिए? मंत्रिपरिषद/अध्यक्ष पहले से ही

के माध्यम से एनजेएसी में 'मतदान सदस्य' के रूप में प्रतिनिधित्व किया गया

कानून मंत्री। क्या राष्ट्रपति/मंत्रिपरिषद/प्रधानमंत्री कर सकते हैं?

मंत्री ने [2015] 13 एस. सी. आर. की सिफारिश पर पुनर्विचार करने के लिए कहा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एन. जे. ए. सी. द्वारा जिसके लिए कानून मंत्री (का एक सदस्य) मंत्रिमंडल) एक पार्टी है? क्या यह विशेष रूप से अनुमत होगा क्योंकि

कानून मंत्री केंद्र सरकार/राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है।

एन. जे. ए. सी. में और क्या यह अच्छी तरह से स्थापित के खिलाफ नहीं जाएगा मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी का सिद्धांत? वैकल्पिक रूप से, क्या ऐसा नहीं होगा?

यदि किसी मामले में कानून मंत्री के अधिकार को कम करना है

कानून मंत्री एक नियुक्ति के लिए सहमत होते हैं लेकिन परिषद

एन. जे. ए. सी. तक मंत्रियों/राष्ट्रपतियों का एक निरीक्षण निकाय चिंतित हैं?

485. यह मानते हुए (उपरोक्त संदेहों के बावजूद) कि

मंत्रिपरिषद/राष्ट्रपति ने एन. जे. ए. सी. से पुनर्विचार करने की मांग की एन. जे. ए. सी. की सिफारिश और पुनर्विचार पर

अपनी सिफारिश दोहराता है, राष्ट्रपति बाध्य होंगे

इस प्रकार भले ही इसका अर्थ प्रमुख की आपत्तियों को खारिज करना हो

संविधान या 99 वां संविधान संशोधन अधिनियम। दूसरा, इस तरह की पुनरावृत्ति की स्थिति में, प्रमुख की राय

भारत का न्याय अंततः शून्य के लिए मायने रखता है, इसके विपरीत

संविधान सभा के इरादे और संवैधानिक सम्मेलनों का दशकों तक पालन किया गया। ऐतिहासिक रूप से, नहीं

नियुक्ति (शायद एक को छोड़कर) के बिना की गई है भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति।
यह 99 वां संविधान है।

संशोधन अधिनियम का उद्देश्य, जानबूझकर या अनजाने में, एक संक्षिप्त विवरण देना है।

संविधान सभा और संविधान सभा के विचारों से विमुख होना

सम्मेलनों और के मुख्य न्यायाधीश के विचारों को कम करने के लिए

भारत? यह प्रक्रिया कॉलेजियम के विपरीत हो सकती है।

नियुक्ति की प्रणाली जिसमें राष्ट्रपति अस्वीकार कर सकता है

कॉलेजियम द्वारा की गई एक सिफारिश यदि यह नहीं थी सर्वसम्मति। वर्तमान व्यवस्था में, इस
अधिकार का

राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है, भले ही सिफारिश सर्वोच्च अदालतें न हों-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

सर्वसम्मति, और इस प्रकार राष्ट्रपति का महत्व है काफी कम हो गया।

486. इसके अतिरिक्त, राष्ट्रपति का निर्णय एक में होता है

दो सदस्यों की राय पर निर्भर करने के लिए बनाया गया अर्थ

एन. जे. ए. सी., जो किसी मामले में दो प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकते हैं

के अनुच्छेद 124 ए (1) (डी) के संदर्भ में एनजेएसी के लिए नामित संविधान। ये दो प्रतिष्ठित
व्यक्ति वास्तव में बाधा डाल सकते हैं।

एन. जे. ए. सी. के प्रत्येक सदस्य को वीटो का प्रयोग करके न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए एन. जे. ए. सी. की
सिफारिश धारा 5 की उप-धारा (2) के दूसरे परंतुक द्वारा

एन. जे. ए. सी. अधिनियम, और बिना कोई कारण बताए। दूसरे शब्दों में,

दो प्रतिष्ठित व्यक्ति (या एन. जे. ए. सी. के कोई दो सदस्य)

प्रासंगिक-कि ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है, परेशान करने वाली है। ए के रूप में इस प्रावधान के
परिणामस्वरूप, एक बनाने की जिम्मेदारी

न्यायाधीश की नियुक्ति प्रभावी रूप से, आंशिक रूप से, से आगे निकल जाती है

भारत के राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश ने सदस्यों को एन. जे. ए. सी., किसी भी दो अनिर्दिष्ट पर
वीटो प्रदान किए जाने के साथ

सदस्य, बिना किसी विशिष्ट औचित्य के। यह एक बहुत 99 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया महत्वपूर्ण संवैधानिक परिवर्तन जो न केवल प्रभावित करता है बल्कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए उनका स्थानांतरण किया जाता है राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश से शेष राशि एनजेएसी के लिए। मामले को बदतर बनाने के लिए, राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकते हैं यहां तक कि किसी अन्य (अन्य न्यायाधीशों या वकीलों या वकीलों) के विचार भी लें। नागरिक समाज) जो 99 वीं से पहले अनुमेय था संविधान संशोधन अधिनियम और अनुच्छेद 124 (2) का एक भाग संविधान के संशोधन से पहले। यह स्मरणीय है कि संविधान का अनुच्छेद 124 (2) राष्ट्रपति को सक्षम बनाता है - उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करें लेकिन उस अधिकार को अब 99 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा छीन लिया गया है। प्रक्रिया में राष्ट्रपति वास्तव में है एक डमी में कम हो गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

487. यह भी याद किया जा सकता है कि राष्ट्रपति (एक के रूप में

व्यक्ति) ने एक दृष्टिकोण व्यक्त किया था जैसा कि भारत में बताया गया था सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित 25 जनवरी, 1999 की आज की पत्रिका। अस्तित्व।

ऐसी संभावना अब संभव नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति (एक व्यक्ति के रूप में) नियुक्ति में वास्तव में कोई भूमिका नहीं है

पूछने पर नियुक्ति का वारंट जारी करने के अलावा प्रक्रिया

ऐसा करने के लिए।

488. इस चर्चा का योग और सार यह है कि

राष्ट्रपति की भूमिका पर कोई स्पष्टता नहीं है। जो भी हो,

न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में सर्वोच्च न्यायालय को लिया जाता है निर्णय राय के अधीन है

दूर; राष्ट्रपति का

दो प्रतिष्ठित व्यक्ति जिनमें से कोई भी संवैधानिक रूप से नहीं है

मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी; एक कानून एन. जे. ए. सी. अधिनियम, नहीं संविधान के विपरीत बाध्य करता है।

संविधान राष्ट्रपति को

ढांचा; 99 वां संविधान संशोधन अधिनियम बनाता है

संविधान के अनुच्छेद 124 (2) में गंभीर और असंवैधानिक घुसपैठ बनाया गया था।

संविधान, जैसा कि मूल रूप से

(ख) भारत के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका और

न्यायपालिका

489. भारत के मुख्य न्यायाधीश निस्संदेह हैं

एनजेएसी के अध्यक्ष। हालांकि, की भागीदारी

एक व्यक्ति के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश और उनकी भागीदारी

एन. जे. ए. सी. में एक संस्थान के रूप में न्यायपालिका को हास्यास्पद बना दिया गया है

99 वां संविधान संशोधन अधिनियम और एन. जे. ए. सी. अधिनियम। यहाँ तक कि यद्यपि उपयुक्तता के संबंध में न्यायपालिका में एक पूर्व-प्रतिष्ठित संवैधानिक प्राधिकारी, भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय

न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति को स्वीकार किया जाता है

एन. जे. ए. सी. के अधिकांश सदस्य, इसे नीचे रखा जा सकता है

एन. जे. ए. सी. की धारा 5 के संदर्भ में इसके दो अन्य सदस्य

एकट करें।

ये दोनों व्यक्ति कानून मंत्री सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन v हो सकते हैं। यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

(राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हुए) और एक या दो प्रतिष्ठित व्यक्ति

राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं, दूसरा पूर्व-प्रतिष्ठित संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रिया में प्राधिकरण

के अनुच्छेद 124 (2) के तहत

संविधान के संशोधन से पहले।

490. 99 वां संविधान संशोधन अधिनियम कम करता है

भारत के मुख्य न्यायाधीश, न्यायपालिका के प्रमुख होने के बावजूद,

एन. जे. ए. सी. में छह में से एक के लिए एक सिफारिश करना

राष्ट्रपति इस प्रकार उन्हें पारंपरिक, ऐतिहासिक रूप से बदनाम कर रहे हैं

और वैध संवैधानिक महत्व और अधिकार और द्वारा अभिनिर्धारित नियुक्ति प्रक्रिया को काफी हद तक तिरछा करना

संविधान सभा और संविधान। भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय 'ग्रेडेड वेट' या 'ग्रेटेस्ट' थी।

एन. जे. ए. सी. अधिनियम भारत के मुख्य न्यायाधीश को केवल एक मतदान के आँकड़े। भारत के मुख्य न्यायाधीश को नामित करना

एन. जे. ए. सी. के अध्यक्ष निश्चित रूप से कोई सांत्वना या समाधान नहीं हैं

न्यायपालिका के प्रमुख को छोटा करना।

491. एक संस्था के रूप में न्यायपालिका की भागीदारी

एन. जे. ए. सी. भी हास्यास्पद है। 99 वां संविधान संशोधन अधिनियम किसी भी व्यक्ति को 'वीटो' देने की बात नहीं मानता है

एनजेएसी में। लेकिन एन. जे. ए. सी. अधिनियम प्रभावी रूप से उस शक्ति को देता है

कानून मंत्री तीनों की सर्वसम्मत राय पर वीटो करेंगे भाग लेने वाले न्यायाधीश (भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित)।

इसलिए, भले ही न्यायपालिका समग्र रूप से और एक संस्था के रूप में हो (कि तीन भाग लेने वाले न्यायाधीश) एक विशेष के पक्ष में है

नियुक्ति, कि सर्वसम्मत राय दी जा सकती है

एन. जे. ए. सी. के किसी भी दो अन्य सदस्यों द्वारा मूल्यहीन, जिनमें से एक

राजनीतिक सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर. का प्रतिनिधित्व करने वाले कानून मंत्री को भी इसमें शामिल किया जा सकता है।

कार्यपालिका और एक अन्य का शायद न्याय से कोई लेना-देना नहीं है

वितरण। यह निश्चित रूप से वह नहीं है जो संविधान ने बनाया है,

अभिनिर्धारित या अभिप्रेत।

492. इस विचित्र स्थिति से उबरने के लिए यह था

श्री के. के. वेणुगोपाल द्वारा सुझाए गए (एक वैकल्पिक तर्क के रूप में) मध्य प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित होते हुए कि सर्वसम्मत

भाग लेने वाले तीन न्यायाधीशों की राय सर्वोपरि होनी चाहिए।

वज़न, वह 'एक वीटो या एक' टाई ब्रेक वोट 'पर एक वीटो है। श्री.

वेणुगोपाल ने इस न्यायालय को कैच-22 स्थिति में डाल दिया है। द.

सुझाए गए विकल्प स्पष्ट रूप से न्यायिक होंगे अतिक्रमण और न्यायपालिका ने कानून को फिर से लिखा। एकमात्र

तर्कसंगत पाठ्यक्रम कानून की व्याख्या करना है जैसा कि यह है और यदि यह है

यह संवैधानिक रूप से वैध हो और यदि यह संवैधानिक रूप से अमान्य है

ऐसा ही हो। कानून को फिर से लिखना उचित या संभव नहीं है जब

कानून की भाषा स्पष्ट है।

493. जैसा कि ऊपर विस्तार से उल्लेख किया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर चर्चा में इतना समय लगा

कई समितियों, संविधान सभा और विभिन्न

अन्य निकाय और संस्थान। कई कानूनी दिग्गजों ने

उन्होंने काफी प्रयास भी किए और एक विचारशील अध्ययन भी किया

न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए। एक उद्देश्य था कि

यह, अर्थात्, कि स्वतंत्रता को इसके माध्यम से नष्ट नहीं किया जाना चाहिए

संविधान संशोधन अधिनियम और एनजेएसी अधिनियम, यह स्वतंत्रता को सूक्ष्मता से खतरे में डाल दिया जाता है। राष्ट्रपति ने

न्यायाधीशों की नियुक्ति में वस्तुतः कोई भूमिका नहीं है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को इस प्रक्रिया और एक ऐसी प्रणाली में दरकिनार कर दिया जाता है जो

संभावित कटाव के अधीन है। न्यायमूर्ति ओ 'कॉनर

उन्होंने कहा: 'न्यायिक स्वतंत्रता अपने आप नहीं होती है।

इसे बनाना बहुत कठिन है, और अधिकांश लोगों की कल्पना से नष्ट करना आसान है। 99 वां संविधान संशोधन अधिनियम और

एन. जे. ए. सी. अधिनियम हमें इस सत्य के संबंध में आमने-सामने रखता है

नाजुक गढ़।

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

494. इस चर्चा का योग और सार यह है कि

न्यायपालिका की सर्वसम्मत राय को दो लोगों द्वारा खारिज किया जा सकता है

प्रतिष्ठित व्यक्ति या एक प्रतिष्ठित व्यक्ति और कानून मंत्री

(जिनकी राय परिषद की राय के अधीन है

मंत्री, जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है); सर्वसम्मत राय

न्यायपालिका की एक संस्था के रूप में, एक राय जिसका सम्मान किया जाता था

(और योग्य रूप से) मार्ग के साथ लगभग कुछ भी नहीं गिना जाता है 99 वें संविधान संशोधन
अधिनियम और एन. जे. ए. सी. अधिनियम;

भारत के मुख्य न्यायाधीश को 99 वें संविधान द्वारा प्रदान किया गया है।

केवल मतदान के आंकड़ों और छह में से एक के लिए संशोधन अधिनियम एन. जे. ए. सी. में वस्तुतः
उसे संवैधानिक पद से हटा दिया गया

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जिम्मेदारी और

उसे इतिहास द्वारा प्रदत्त अधिकार से वंचित करना,

भारत और न्यायपालिका की संस्था अब एक के अधीन है अपने निर्णयों में नागरिक समाज द्वारा
वीटो। पूरी योजना

संविधान सभा द्वारा अभिनिर्धारित न्यायाधीशों की नियुक्ति

99 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा टॉपसी-टर्वी बनाया गया है

और एन. जे. ए. सी. अधिनियम। यदि यह मूल संरचना को नहीं बदलता है

संविधान क्या करता है?

(ग) प्रतिष्ठित व्यक्ति और वीटो

495. में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के होने की प्रेरणा

एन. जे. ए. सी. एन. सी. आर. डब्ल्यू. सी. की रिपोर्ट से आता है जिसने

लोकतांत्रिक प्रक्रिया के एक भाग के रूप में यह सिफारिश

उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का चयन करना। संविधान के अनुच्छेद 124 ए
(1) (डी) में दो प्रतिष्ठित प्रावधान हैं।

एन. जे. ए. सी. के सदस्यों के रूप में नामित किए जाने वाले व्यक्ति। द.

नामांकन एक समिति द्वारा किया जाता है जिसमें प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता शामिल होते हैं।

लोकसभा या जहाँ ऐसा कोई नेता नहीं है, तो

लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता। पहला परंतु यह आदेश देता है कि प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर. से संबंधित व्यक्तियों में से नामित किया जाएगा।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े

वर्ग, अल्पसंख्यक या महिलाएँ।

496. कुछ विद्वानों द्वारा व्यक्त की गई आशंका

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील का कहना है कि चूंकि कोई दिशानिर्देश नहीं है दो प्रतिष्ठित लोगों के नामांकन के लिए निर्धारित किया गया है

व्यक्तियों, वहाँ एक संभावना है कि जो लोग वास्तव में नहीं हैं प्रतिष्ठित व्यक्ति को एन. जे. ए. सी. के लिए नामित किया जा सकता है या उनका

नियुक्ति राजनीति से प्रेरित होगी। तो भी,

मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित व्यक्तियों को नामित नहीं किया जा सकता है एनजेएसी। लेकिन फिर, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति कौन है?

497. ए. के. रॉय बनाम भारत संघ 463 संदर्भ था

सटीक परिभाषाओं को तैयार करने में कठिनाई हुई। हालांकि

निर्णय निवारक निरोध और आपराधिक से संबंधित था

कानून, निम्नलिखित अवलोकन के संदर्भ में प्रासंगिक है वर्तमान चर्चा:

"के साथ एक परिभाषा तैयार करने की असंभवता

गणितीय परिशुद्धता या तो अस्पष्ट अभिव्यक्तियों के उपयोग या किसी को भी तैयार करने में कुल विफलता को उचित नहीं ठहरा सकती है।

परिभाषा जो अपनी समावेशिता से प्रस्तुत कर सकती है

कम से कम, इसका अर्थ समझने के लिए एक सुरक्षित दिशानिर्देश

विधायिका द्वारा उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्तियाँ। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसी अभिव्यक्तियाँ हैं जो स्वाभाविक रूप से

ऐसी अनंत विविधता की स्थितियों को समझें कि

आयाम या इसे आगे फ्रेम करने के लिए आवश्यक बनाने में
परिभाषित शब्दों की परिभाषाएँ। 464

498. व्यक्त किए गए दृष्टिकोण पर भी ध्यान देना आवश्यक है

न्यायमूर्ति वर्मा द्वारा दूसरे न्यायाधीशों का मामला

बहुमत। विद्वान न्यायाधीश की राय थी कि मनमानेपन विवेक के अभ्यास में एक के माध्यम से
कम किया जा सकता है

463 (1982) 1 एस. सी. सी. 271 (पाँच न्यायाधीशों की पीठ)

464 पैराग्राफ 61 शीर्ष अदालतें-चालू-रिकॉर्ड एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

सी. टी. वी. निर्णय इसे इस प्रकार देखा गया:

"कानून का शासन विवेकाधिकार के क्षेत्र की परिकल्पना करता है

न्यूनतम, गैर-मनमानेपन को सुनिश्चित करने के लिए केवल ज्ञात सिद्धांतों या दिशानिर्देशों के अनुप्रयोग की
आवश्यकता होती है, लेकिन

उस सीमित सीमा तक, विवेक एक व्यावहारिक आवश्यकता है। उच्च अधिकारियों को विवेकाधिकार प्रदान
करना और, जब भी संभव हो, बहुलता के तत्व को पेश करना

एक सामूहिक निर्णय की आवश्यकता से, आगे की जाँचें हैं

मनमानी के खिलाफ। इस तरह आदर्शवाद और व्यावहारिकता का मिलान और एकीकरण किया
जाता है, ताकि

संतोषजनक तरीके से काम करने योग्य प्रणाली। सौंपना

उच्च से उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति का कार्य

संवैधानिक पदाधिकारी; सबसे बड़ा महत्व

भारत के मुख्य न्यायाधीश के दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ, जो है

उम्मीदवारों के वास्तविक मूल्य का आकलन करने के लिए सबसे अच्छी तरह से सुसज्जित

उनकी उपयुक्तता का निर्णय करने के लिए; प्रमुख की राय

भारत के न्याय के बाद गठित सामूहिक राय है

अपने कुछ सहयोगियों के विचारों को ध्यान में रखते हुए;

नियुक्ति को अनुपयुक्त माना जाता है, मजबूत के लिए
कारण, प्रदान करें

भारत के मुख्य न्यायाधीश को बताए गए

सबसे अच्छा तरीका, संवैधानिक योजना में, प्राप्त करने के लिए
संवैधानिक उद्देश्य

निरपेक्षता प्रदान किए बिना

न्यायपालिका या दोनों में से किसी एक पर विवेक या वीटो

कार्यकारी, किसी भी व्यक्ति में बहुत कम, चाहे वह प्रमुख हो

भारत का न्याय या प्रधानमंत्री "। 465

499. न्यायमूर्ति पांडियन एक अलग लेकिन सहमत राय में

एक ही दृष्टिकोण और इसे निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया:

सहभागितापूर्ण लोकतंत्र जिसमें सभी वर्ग और वर्ग
अनुसूचित जाति के

लोग, चाहे वे पिछड़े वर्ग के हों या

या अनुसूचित जनजाति या अल्पसंख्यक या महिलाएँ, होनी चाहिए

ए. आर. ग्राफ 468 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

समान अवसर प्रदान किया ताकि न्यायिक

प्रशासन भी उत्कृष्ट द्वारा भाग लिया जाता है

और सभी वर्गों से संबंधित योग्य उम्मीदवार

" 466

समाज और किसी भी चयनात्मक या द्वितीय समूह द्वारा नहीं।

500. पी. आई. एल. के लिए केंद्र में वी. भारत संघ 467 प्रश्न

केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003। प्रासंगिक
समिति

प्रावधान इस आशय का था कि एक चयन

जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री शामिल होते हैं

और लोकसभा में विपक्ष के नेता करेंगे

राष्ट्रपति के लिए एक सिफारिश जो तब नियुक्त करेगा

केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या सतर्कता

आयुक्त, जैसा भी मामला हो, अपने या उसके अधीन वारंट द्वारा
में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

उसका हाथ और मुहर। इस संदर्भ

संसद ने एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति में अपना विश्वास रखा था और

यह माना जाता है कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति को सौंपा गया है
शक्तियों का प्रयोग करेगा

व्यापक विवेक के साथ अपनी

अधिनियम के साथ निष्पक्ष और उचित तरीके से।

501. यह श्री अरविंद दातार, विद्वान वरिष्ठ द्वारा इंगित किया गया था।

एक शरीर में, जिसमें कुछ विषय विशिष्ट भी शामिल हैं। हालांकि, यह
इंगित किया गया था कि

विद्वान महान्यायवादी द्वारा

इनमें से कुछ कानूनों का यादृच्छिक नमूना, यह पाया गया है

कि उनमें से किसी के पास ऐसी उच्चाधिकार प्राप्त समिति नहीं है जिसमें

केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम या नामित करने के लिए

किसी पद पर नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की सिफारिश करना।

502. किसी भी चीज़ के अलावा, इसे प्रस्तुत किया गया था

विद्वान महान्यायवादी कि प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति

एन. जे. ए. सी. में संरचना में विविधता होगी

'चयन पैनल' और यह कि यह आवश्यक रूप से 466 पैराग्राफ 216 (3) को प्रतिबिंबित करेगा

467 (2011) 4 एस. सी. सी. 1 शीर्ष अदालतें-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

समाज के दृष्टिकोण। इस संदर्भ में मद्रास उच्च न्यायालय के महापंजीयक बनाम. आर. गांधी 468

जिसमें यह निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया था:

"नियुक्तियाँ विशेष रूप से किसी से नहीं की जा सकती हैं।

अलग-थलग समूह और न ही इसका पूर्व-प्रभुत्व होना चाहिए
एक संकीर्ण समूह का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए न्यायपालिका में विविधता

सर्वोत्तम कानूनी रूप से प्रशिक्षित दिमागों को चुनने के लिए नियुक्तियाँ
 एक गुणात्मक व्यक्तित्व के साथ, मार्गदर्शक हैं
 जिन कारकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वे देखने योग्य हैं
 व्यक्तिगत विचारों पर विचार करना। यही कारण है कि
 उस सामूहिक परामर्श प्रक्रिया को, जैसा कि में प्रतिपादित किया गया है,
 उपरोक्त निर्णयों को अंतर्निर्मित माना गया है
 किसी भी मनमानी के खिलाफ तंत्र "। 469.

503. इन परिस्थितियों में, बहुत कम हो सकता है

प्रतिष्ठित व्यक्तियों की भागीदारी पर आपत्ति

नियुक्ति प्रक्रिया में सलाहकार: वास्तव में, न्यायमूर्ति वर्मा

उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने प्रतिष्ठित वकीलों के विचार मांगे थे

नियुक्ति के लिए सिफारिशों पर विचार करते हुए न्यायाधीशों। यदि समिति को नामित करने के लिए विश्वास नहीं किया जा सकता है

'प्रतिष्ठित व्यक्ति, शायद कोई अन्य समिति ऐसा नहीं कर सकती। ट्रस्ट समिति पर रखा गया एक साधारण या वैधानिक न्यास नहीं है लेकिन

एक संवैधानिक न्यास। इस संबंध में इन शब्दों को याद रखना उचित है।

भीम सिंहजी में न्यायमूर्ति कृष्ण लायर:

"शक्ति और उसके तिरछे के बीच भ्रम

व्यायाम एक बौद्धिक भ्रांति है जिससे हमें बचना चाहिए।

काल्पनिक संभावनाएँ, विचित्र अभ्यास और अटकलें

विचलन संवैधानिक रूप से पर्याप्त यथार्थवादी नहीं हैं।

अमान्यीकरण। विधायिका को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है

संदिग्ध आशुरचना या कार्यपालिका से भी बदतर "। 470

504. इसलिए, कुछ लोगों की तरह सतर्क रहने की सलाह नहीं दी जाती है।

470 पैराग्राफ 20 [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील थे, लेकिन साथ ही साथ

सत्ता के संभावित दुरुपयोग को दूर नहीं किया जा सकता है, जैसा कि हमारे हाल ही में हुआ है

इतिहास हमें बताता है। शायद कहीं बेहतर और सटीक विधायी

समिति की निर्णय लेने की प्रक्रिया। यह इंगित किया गया था केंद्र में पी. आई. एल. के लिए कि
वर्तमान जैसी स्थिति में,

जहाँ समिति के कार्यकरण में कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की जाती है।

बाहर, प्रतिष्ठित व्यक्तियों का नामांकन बहुमत के माध्यम से होगा

समिति के सदस्यों का निर्णय। 471 इसका मतलब यह है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहायक भूमिका होगी।

नामांकन प्रक्रिया में यदि वह अल्पमत में है। यह क्या?

इसका मतलब यह भी है कि एक कार्यकारी सह विधायी प्रभाव होगा

प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नामांकन की प्रक्रिया में चुपके से। में।

नियुक्ति की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दरकिनार कर दिया गया उच्च न्यायालयों और
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का।

505. इस तर्क को स्वीकार करना भी संभव नहीं है कि

एन. जे. ए. सी. में मतदान का अधिकार रखने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति का न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन विविधता लाने के मामले में फायदेमंद होगा।

समान परिणाम बहुत अच्छी तरह से प्राप्त किया जा सकता है, जैसा कि सुझाव दिया गया है
न्यायमूर्ति वर्मा ने संविधान के मूल ढांचे में बदलाव किए बिना

संविधान, सलाहकारों को वीटो प्रदान किए बिना।

506. जो बात मामले को बदतर बनाती है वह यह है कि अनुपस्थिति में

प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नामांकन में गणपूर्ति या सर्वसम्मति से समिति बिना परामर्श के नामांकन कर सकती थी।

भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसलिए, यदि किसी वैध कारण से,

भारत के मुख्य न्यायाधीश एक बैठक में भाग लेने में असमर्थ हैं, समिति प्रतिष्ठित व्यक्तियों को नामित कर सकती है (शायद

एन. जे. ए. सी. के लिए एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका की अवधारणा में विश्वास करना और एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका को स्वीकार करने के लिए इसके निर्णयों को प्रभावित करना।

471 रिपोर्ट के पैराग्राफ 79 से 86 में चर्चा काफी उपयोगी है।

सर्वोच्च अदालतें-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

एक स्वतंत्र न्यायपालिका के बजाय। 472 यह संभावना नहीं है कि

ऐसा होगा, लेकिन अगर राजनीतिक कार्यपालिका निर्धारित है, तो

किसी समय, एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका होने के लिए,

भारत के मुख्य न्यायाधीश के दृष्टिकोण की अवहेलना एक वास्तविक बात है संभावना है।

507. 'प्रतिष्ठित व्यक्ति' के खिलाफ एक और आपत्ति उठाई गई

श्रेणी यह है कि ऐसे व्यक्ति को कोई ज्ञान नहीं हो सकता है न्यायपालिका की आवश्यकताओं की और सक्षम नहीं होगा

न्यायाधीश के चयन में कोई भी प्रभावी योगदान दें। यह.

प्रस्तुत किया गया था कि प्रतिष्ठित व्यक्ति के पास कुछ होना चाहिए

पृष्ठभूमि. कानून और न्यायपालिका। सिद्धांत रूप में यह तर्क काफी आकर्षक है, लेकिन वास्तव में इसमें बहुत कम सार है। कई

- प्रोफेसर अमर्त्य सेन-जिनका कोई प्रशिक्षण या पृष्ठभूमि नहीं रही है कानून में और फिर भी हमें न्याय का विचार एक महत्वपूर्ण विचार दिया है

न्यायशास्त्र में योगदान, न्याय का विचार संगठनात्मक भावना (नीति) और वास्तविक न्याय का विचार

(न्याय)। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि

एन. जे. ए. सी. में प्रतिष्ठित व्यक्ति (या एक बाहरी सलाहकार के रूप में) कानून या न्याय वितरण से कुछ संबंध है। अगर

प्रतिष्ठित व्यक्ति के पास वह 'योग्यता' होती है जो उपयोगी हो सकती है, लेकिन यह निश्चित रूप से बिल्कुल आवश्यक नहीं है।

508. अंत में, यह तर्क दिया गया कि आवश्यकता यह है कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति एक निर्दिष्ट श्रेणी से होना चाहिए

अनुच्छेद 124 ए (1) (डी) के पहले परंतुक में उल्लिखित

संविधान भेदभावपूर्ण है और इसका कोई उद्देश्य नहीं है। में।

472 यह ईश्वर चंद्र बनाम में आयोजित किया गया था। सत्यनारायण सिन्हा, (1972) 3 एस. सी. सी. 383 रिपोर्ट के पैराग्राफ 10 में: जहां कोरम निर्धारित करने के लिए कोई नियम या विनियम या कोई अन्य प्रावधान नहीं है, सदस्यों के बहुमत की उपस्थिति इसे एक वैध बैठक बनाएगी और उसमें माने जाने वाले मामलों को अमान्य नहीं माना जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जवाब में विद्वान महान्यायवादी ने कहा कि

कानून के क्षेत्र से बाहर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की उपस्थिति

नियुक्ति में बहुत आवश्यक विविधता लाना

न्यायाधीशों। यूनाइटेड किंगडम में अनुभव, जैसा कि समझाया गया है

जैक स्ट्रॉ द्वारा, इस धारणा को बर्दाश्त नहीं करता है। में।

अपने व्याख्यान में उन्होंने कहा: विविधता पर धारणा-नादानी के रूप में

यह निकला-कि अगर हमने प्रक्रिया को बदल दिया, तो हम करेंगे

परिणाम को बदलें। 'किसी भी स्थिति में, कौन सी श्रेणी होनी चाहिए या एन. जे. ए. सी. में किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के माध्यम से प्रतिनिधित्व नहीं किया जाना चाहिए, यह अनिवार्य रूप से नीति का विषय है और यह नीति ऐसा करती है।

किसी भी तरह से विकृत प्रतीत नहीं होता है, लेकिन इसकी आवश्यकता होती है

फिर से सोचें।

509. दुख का असली कारण दूसरा है

एन. जे. ए. सी. अधिनियम की धारा 5 (2) का प्रावधान जो प्रभावी रूप से

एन. जे. ए. सी. के प्रत्येक सदस्य को वीटो प्रदान करता है। वीटो में क्या आपत्तिजनक है (पैकेज सौदे का एक हिस्सा) विद्वान महान्यायवादी द्वारा निर्दिष्ट) यह है कि इसका प्रयोग दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा भी किया जा सकता है जिनकी भागीदारी में

नियुक्ति प्रक्रिया की कल्पना भी नहीं की गई थी

संविधान सभा: संविधान का अनुच्छेद 124 (2) (पूर्व)

इसके संशोधन के लिए) केवल दो संवैधानिक प्राधिकरण थे

नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल-राष्ट्रपति और

भारत के मुख्य न्यायाधीश। 99 वां संविधान संशोधन अधिनियम

एक तीसरा और एक गैर-संवैधानिक पेश किया है

'प्राधिकारी' अर्थात् एक प्रतिष्ठित व्यक्ति। दो प्रतिष्ठित व्यक्ति जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया में इससे पहले कोई भूमिका नहीं थी

काफ़ेस्क अनुपात और एक साथ वे नियुक्ति प्रक्रिया को पंगु बना सकते हैं, राष्ट्रपति और प्रमुख को कम कर सकते हैं। भारत का न्याय उन कारणों के लिए संकेत देता है जिनमें कुछ भी नहीं हो सकता है

न्यायिक क्षमता या योग्यता और उपयुक्तता के संबंध में

न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए माना जाने वाला व्यक्ति। ताकि वे ऐसा कर सकें ऐसा न
करना पूरी तरह से अलग मामला है लेकिन संवैधानिक रूप से

न्यायाधीशों की नियुक्ति के रूप में गंभीर मुद्दा, सभी संभावनाएं सर्वोच्च न्यायालय-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

ध्यान में रखने की आवश्यकता है क्योंकि यह प्रभावित करता है

अन्यथा, स्पष्ट रूप से प्राधिकरण पर एक असंवैधानिक जाँच है राष्ट्रपति और भारत के मुख्य
न्यायाधीश।

510. इस चर्चा का योग और सार यह है कि

सिद्धांत रूप में, प्रतिष्ठित लोगों के साथ परामर्श करने पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है नियुक्ति
के मामले में जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यक्ति

न्यायाधीश, लेकिन यह कि ये प्रतिष्ठित व्यक्ति किसी निर्णय को वीटो कर सकते हैं

जो सर्वसम्मति से या अन्यथा मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिया जाता है

भारत (अन्य न्यायाधीशों और संभवतः अन्य न्यायाधीशों के परामर्श से)

प्रतिष्ठित व्यक्ति) अकल्पनीय है-यह वस्तुतः एक

एन. जे. ए. सी. में प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर राजतंत्रीय शक्ति, ए

बिना किसी जवाबदेही के शक्ति; प्रतिष्ठित व्यक्तियों की श्रेणियां अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तक सीमित नहीं होनी चाहिए।

जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक या महिलाएँ लेकिन

यह नीति की बात है और इसके बारे में और कुछ नहीं कहा जा सकता है।

सिवाय इसके कि एक पुनर्विचार आवश्यक है; यह तय करने के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं हो सकते हैं कि उद्देश्यों के लिए कौन एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है या नहीं है।

एन. जे. ए. सी. के लिए नामांकन, लेकिन यह कि विकल्प उच्च पर छोड़ दिया गया है अधिकार प्राप्त समिति एक पर्याप्त जाँच है, बशर्ते निर्णय लिया जाए

समिति सर्वसम्मत है।

((घ) विधि मंत्री

511. एनजेएसी में कानून मंत्री की उपस्थिति थी

याचिकाकर्ताओं ने कई कारणों से इसका विरोध किया। मुख्य रूप से, यह तर्क दिया गया था कि भारत संघ सबसे बड़ा वादी है

एन. जे. ए. सी. निष्पक्ष चयन के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, अगर इसका विरोध नहीं किया गया तो उत्पादक।

512. यह सच है कि भारत संघ सबसे बड़ा वादी है

देश में और जिसे दूसरे न्यायाधीशों में मान्यता दी गई थी मामला। न्यायमूर्ति पांडियन ने इस प्रकार कहा:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

"इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वर्तमान में राज्य ने

प्रमुख वादी और उच्च न्यायालय बनें

विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय, केंद्र बन गए हैं।

अशांत विवादों के लिए, जिनमें से कुछ को राजनीतिक नतीजों और अदालतों का सामना करना पड़ता है

तूफान और तूफान क्योंकि उनकी जीवन शक्ति एक राष्ट्रीय है

अनिवार्य है। इन परिस्थितियों में, कर सकते हैं

सरकार, अर्थात्, प्रमुख वादी को न्यायसंगत ठहराया जाए

नामित करने और नियुक्त करने में पूर्ण अधिकार प्राप्त करना

उनके मध्यस्थ। इसका जवाब नकारात्मक होगा। अगर

ऐसी प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दी जाती है, लंबे समय में न्यायपालिका की स्वतंत्रता बिना किसी निशान के डूब जाएगी। 473

513. इसी तरह, न्यायमूर्ति कुलदिप सिंह ने भी उल्लेख किया कि

भारत संघ देश का सबसे बड़ा वादी है।

विद्वान न्यायाधीश ने कहा:

"एस. पी. गुप्ता मामले में इस न्यायालय ने इन शब्दों का अर्थ लगाया

संविधान के अनुच्छेद 124 (2) और 217 (1) घड़ी को चालीस साल पीछे ले जाते हैं। एपेक्स की कार्यप्रणाली

पिछले चार दशकों के दौरान न्यायपालिका का विस्तार, 'न्यायिक समीक्षा', की व्यापक अवधारणा

'न्यायपालिका की स्वतंत्रता, व्यवहार और उदाहरण

न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला जो परिपक्व हो गया

सम्मेलनों और कार्यपालिका की भूमिका

अदालतों के समक्ष सबसे बड़े एकल वादी, कुछ हैं।

महत्वपूर्ण पहलू जिनका इस न्यायालय द्वारा समर्थन नहीं किया गया था

संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करते हुए "। 474

514. विद्वान न्यायाधीश ने भी यही भावना व्यक्त की

निम्नलिखित शब्दों में अधिक जोरदार रूप से कहें:

"फिर जो सवाल विचार के लिए आता है वह है,

क्या एक स्वतंत्र न्यायपालिका हो सकती है जब शक्ति न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका में निहित है? कहने के लिए

473 अनुच्छेद 207

74 पैराग्राफ 327 सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

हां, यह अतार्किक होगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता है

उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति की संवैधानिक प्रक्रिया से अटूट रूप से जुड़ा हुआ और जुड़ा हुआ है।

कार्यपालिका को यह शक्ति देने का इरादा कभी नहीं था। यहाँ तक कि अन्यथा सरकारें-केंद्र या राज्य-हैं

न्यायालयों के समक्ष बड़ी संख्या में मामलों में पक्षकार। द.

संघ की कार्यकारिणी के विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हित हैं।

वे मामले जो शीर्ष के समक्ष निर्णय के लिए आते हैं

अदालत। कार्यपालिका-किसी न किसी रूप में अदालतों के समक्ष सबसे बड़ा एकल वादी होता है। इस दृष्टि से

इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि न्यायपालिका मध्यस्थ है -

जनता और कार्यपालिका-संविधान के निर्माता

सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के हाथों में कार्यपालक से। एस. पी. गुप्ता मामले में यह अदालत

इस धारणा पर आगे बढ़े कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान की मूल विशेषता है लेकिन विफल रही

यह समझने के लिए कि व्याख्या, इसने दी, में नहीं थी

दोनों अवधारणाओं के व्यापक पहलुओं के साथ अनुरूपता -

'न्यायपालिका की स्वतंत्रता और 'न्यायिक समीक्षा'-जो

आपस में जुड़े हुए हैं, "475

इसे देखते हुए इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि सरकार

भारत का एक प्रमुख वादी है और एक कैबिनेट मंत्री के लिए एक के वास्तविक चयन में भाग लेना (और एक वीटो होना)

उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अत्यंत

असंगत। 476

515. ऐतिहासिक रूप से, और मैंने अध्याय और पद्य उद्धृत किए हैं

इस संबंध में लगभग हर प्रासंगिक समिति से,

475 अनुच्छेद 335

476 यह स्थिति कि राज्य देश में एक प्रमुख वादी है, आज भी वही है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

कार्यपालिका का उद्देश्य हमेशा न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर रहना था। क्या है?

कानून मंत्री को शामिल करके हासिल करने की मांग की गई

एन. जे. ए. सी. कानूनी दिग्गजों के विवेक पर संदेह करना चाहता है, डॉ.

नियुक्ति में कार्यकारी निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर न्यायाधीशों से।

516. फिर भी, यह सच है कि कार्यपालिका से इनपुट निर्णय लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हैं कि क्या व्यक्ति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए या नहीं।

न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन कार्यपालिका द्वारा जानकारी प्रदान करना निर्णय लेने की प्रक्रिया से काफी अलग है। प्रक्रिया में शामिल कार्यपालक या कार्यपालक द्वारा

महत्वपूर्ण और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली व्यक्ति जिनके विचार, संभावित रूप से, उन विचारों पर एक बड़ा प्रभाव पड़ता है जो अन्य

एन. जे. ए. सी. के सदस्य आयोजित कर सकते हैं। चूंकि कानून मंत्री, धारण किए गए पद के आधार पर, संभावित रूप से प्रभावित करने में सक्षम है

एन. जे. ए. सी. के किसी सदस्य का निर्णय अनुचित होगा

विधि मंत्री के निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए।

चयन प्रक्रिया न केवल निष्पक्ष होनी चाहिए बल्कि इसके लिए उपस्थित होना भी आवश्यक है।

निष्पक्ष रहें।

517. यह महसूस किया जाना चाहिए और सराहना की जानी चाहिए कि कई देशों में न्यायिक प्रणाली के गठन की दिशा में विवर्तनिक बदलाव

नियुक्ति आयोग केवल यह सुनिश्चित करने के लिए हो रहा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की कोई भूमिका न हो।

विद्वान महान्यायवादी ने इस बदलाव का समर्थन किया लेकिन अगर इस प्रवृत्ति को गंभीरता से लेना है, तो कानून मंत्री के लिए इसमें कोई जगह नहीं हो सकती है। एन. जे. ए. सी. में कोई आयोग या, जैसा कि वर्तमान मामले में है।

इसलिए, जबकि 99 वां संविधान संशोधन अधिनियम और सर्वोच्च न्यायालय अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन v.

यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकर, जे.]

एन. जे. ए. सी. अधिनियम स्वतंत्र होने के उद्देश्य से एक निकाय स्थापित करने का प्रयास करता है।

कार्यपालिका की, एन. जे. ए. सी. की स्थापना की गई है

इसके एक भाग के रूप में राजनीतिक कार्यकारिणी के महत्वपूर्ण सदस्य शरीर, जो बल्कि कालातीत है।

518. यह भी महसूस किया जाना चाहिए कि जैसा कि उल्लेख किया गया है

प्रथम न्यायाधीशों का मामला दो देशों ऑस्ट्रेलिया (आज एक है

उच्च न्यायालय और राज्य में कुल लगभग 200 न्यायाधीश

सर्वोच्च न्यायालय) और न्यूजीलैंड (आज कुल लगभग 20 न्यायाधीश [सर्वोच्च न्यायालय में और के न्यायालय में

अपील)) न्यायिक नियुक्ति के लिए चक्र लगा रहे थे उच्च न्यायपालिका के लिए आयोग। 477 हमें इस दौरान सूचित किया गया था

इन याचिकाओं की सुनवाई जो इन देशों ने नहीं की है,

चार दशकों के बाद भी, इस तरह के आयोगों की स्थापना की, जबकि

ऐसा लगता है कि हमारा देश ऐसा करने के लिए बहुत जल्दी में है। इन देशों में मुद्दे, बहस, चर्चा और विचार

यह हमसे अलग होगा, लेकिन केवल इसलिए कि ये और

अन्य देश न्यायिक नियुक्ति की ओर देख रहे हैं।

आयोग भारत के लिए ऐसा करने का कोई कारण नहीं है। दक्षिण अफ्रीका का भी एक संदर्भ दिया गया था, लेकिन जैसा कि हर कोई जानता है, विविधता उस देश में रंगभेद के बाद के मुद्दे बहुत चिंता का विषय हैं। यह है,

इसलिए न्यायिक नियुक्ति प्रणालियों की तुलना करना घृणित है।

हमारे देश के साथ अन्य देशों में और विचारों और अवधारणाओं को ऊपर उठाने के लिए

जो उन देशों में विचार किए बिना व्यवहार्य हो सकता है चाहे उन्हें हमारे देश में अपनाया जा सके या अनुकूलित किया जा सके।

519. ऑस्ट्रेलिया में, एक लेख गोद लेने का सुझाव देता है

सी. आर. ए. द्वारा प्रस्तुत यू. के. न्यायिक नियुक्ति आयोग

477 न्यायमूर्ति भगवती: "हम यह इंगित कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने भी इस विचार को अपनाया है कि उच्च न्यायपालिका की नियुक्ति के लिए एक न्यायिक आयोग होना चाहिए। हाल ही में जुलाई 1977 में ऑस्ट्रेलिया के मुख्य न्यायाधीश ने सार्वजनिक रूप से कहा कि ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के आयोग की नियुक्ति का समय आ गया है। इसी तरह न्यूजीलैंड में भी, श्री जस्टिस बीटल, जो अब न्यूजीलैंड के गवर्नर-जनरल बन गए हैं, की अध्यक्षता में न्यायालयों पर रॉयल कमीशन ने सिफारिश की कि एक न्यायिक आयोग को सभी न्यायिक नियुक्तियों पर विचार करना चाहिए, जिनमें शामिल हैं -

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ।

[अनुच्छेद 31] [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह न्यायिक नियुक्तियों और राजनीतिक के बारे में कहने के लिए है

ओनेज (जो एन. जे. ए. सी. में संभव हो सकता है)

ब्लिड):

"जबकि ऑस्ट्रेलियाई की सामूहिक ताकत और गुणवत्ता

न्यायपालिका संदेह में नहीं है, यह मामला है कि विशेष नियुक्तियों ने या तो संबंध में आलोचना को आकर्षित किया है

चुने गए व्यक्ति के चरित्र और क्षमता के लिए या

कार्यालय में रहते हुए उनका आचरण। यह एक कुख्यात तथ्य है कि

न्यायिक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं

उच्च न्यायालय, जिसका चरित्र और बौद्धिक और कानूनी

क्षमताओं पर संदेह किया गया है और जिनकी नियुक्तियों को राजनीतिक संरक्षण के उदाहरणों के रूप में पहचाना गया है।

जो आवश्यक है वह यह है कि निर्णयात्मक स्वतंत्रता हो

न्यायिक अधिकारियों को गारंटी। न्यायिक स्वतंत्रता का मूल केंद्र में प्रभाव से स्वतंत्रता है।

कानूनी अधिकारों के बारे में विवादों पर निर्णय लेने का न्यायिक कार्य

जो निजी पक्षों के बीच, राज्य और राज्य के बीच उत्पन्न होता है

निजी दल, और (एक संघ में) के बीच

राज्य के घटक। कोर के माध्यम से संरक्षित है

पहले से ही उल्लेख किया गया है, यह अपरिहार्य है कि राजनीति में एक होगा
में भूमिका निभाना। हालांकि, अगर

नियुक्ति प्रक्रिया

राजनीतिक संरक्षण से खतरा है (कम से कम) निर्णयात्मक स्वतंत्रता की उपस्थिति। यह है।
 असंभव-और अवांछनीय-राजनीतिक को हटाने के लिए
 दृष्टिकोण, 'राजनीतिक' विचार, के अर्थ में नियुक्तियों के लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही,
 आवश्यकता
 अस्पष्ट होने के बजाय तीव्र होना। क्या बात है।
 नियुक्तियों के मॉडल को सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं को कम करने का प्रयास करना चाहिए-चालू-
 रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]
 राजनीतिक शाखा का प्रत्यक्ष प्रभाव
 अधिक पारदर्शिता के लिए नियुक्ति प्रक्रिया और जवाबदेही, सभी मौजूदा को संरक्षित करते हुए
 निर्णयात्मक सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक व्यवस्थाएँ
 स्वतंत्रता। “ 478
 520. दक्षिण अफ्रीका में, न्यायिक मामलों से निपटते हुए
 पिंटमेंट्स, न्यायमूर्ति यवोन मोकगोरो, के पूर्व न्यायाधीश
 संवैधानिक न्यायालय का यह कहना था:
 “इस प्रकार, दक्षिण अफ्रीका में न्यायिक परिवर्तन में शामिल होना चाहिए
 एक नई न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया जो खुली है
 एक ऐसी न्यायपालिका जो एक खुली और लोकतांत्रिक सेवा प्रदान करती है समाज; उस न्यायिक
 क्षमता की सराहना करना और कैसे
 न्यायाधीश अपनी न्यायिक शक्ति और स्वतंत्रता का प्रबंधन करते हैं।
 न्याय तक पहुंच बढ़ाने के प्रमुख पहलू हैं और
 न्यायिक जवाबदेही। लागू करना और गले लगाना
 मौलिक रूप से नई कानूनी व्यवस्था के सिद्धांत और मूल्य
 यह भी एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण परिवर्तन है जो होगा न्यायिक व्याख्या के लिए ठोस निहितार्थ
 कानून और एक नए संविधान का निर्माण

न्यायशास्त्र। ये सभी सुधार निस्संदेह आवश्यक हैं।
 न्यायिक परिवर्तन के लिए विचार। अदालतों को करना चाहिए
 इसलिए कुशलता से कार्य करें ताकि न्यायाधीश कार्य समाप्त कर सकें।
 सभी को न्याय, सबसे सक्षम रूप से। इसके लिए मौलिक
 सिद्धांत यह है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय विचार करें
 न्यायपालिका को प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाना चाहिए
 मोटे तौर पर दक्षिण की नस्लीय और लिंग संरचना
 अफ्रीका।

ऑस्ट्रेलियाई न्यायाधीशों की ओर इशारा करना: साइमन इवांस और जॉन एम्स द्वारा ए न्यू मॉडल, [2008]
 सिडनी लॉ रिव्यू वॉल्यूम 30 पेज 295। देखें एच. टी. पी.: // ऑन। एड्यू। एयू/लॉ/सर/एसएलआर 30 _
 2/इवांस।

पीडीएफ [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट
 हमारे जैसे समाज में, जहाँ पितृसत्ता इतनी गहरी है
 रोजमर्रा के जीवन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हुए
 कई महिलाओं, कानून में महिलाओं सहित, रणनीतिक
 न्यायपीठ में महिलाओं की भागीदारी का मूल्य और
 सत्ता और अधिकार के पद नहीं होने चाहिए
 कम आंका गया। उनकी विकास प्रबंधन शैली,
 अद्वितीय दृष्टिकोणों का प्रभाव जो वे लाते हैं
 न्यायनिर्णायक कार्य और यहाँ तक कि उनका मात्र प्रतीकवाद
 वहाँ की उपस्थिति के लिए भारी रिटर्न ला सकता है
 परिवर्तन प्रक्रिया और महिलाओं के लिए सम्मान
 व्यापक रूप से समाज। न्यायपालिका में महिलाओं दोनों की आवश्यकता
 समग्र रूप से और विशेष रूप से नेतृत्व की स्थिति में

अतिशयोक्ति नहीं की जा सकती। हालाँकि, हमने एक लंबा सफर तय किया है, हमें इस बात से सहमत होना चाहिए कि हमने अभी-अभी खरोंच की है

सतह। हमें अपने प्रयासों को आगे बढ़ाना होगा। कुछ चीजें जरूरी हैं।

परिवर्तन करें। " 479

इसे रखने के लिए, विभिन्न देशों में विचार हैं

बस, अलग। हमें अपनी खुद की स्वदेशी प्रणाली की आवश्यकता है यह हमारे पर्यावरण और हमारी अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल है।

521. 11 दिसंबर, 2011 के एक स्थिति पत्र में

न्यायाधीशों की नियुक्ति, बोत्सवाना की विधि सोसायटी

इस बात पर जोर दिया कि विभिन्न कानूनी प्रणालियों के लिए अलग-अलग आवश्यकता होती है न्यायाधीशों की नियुक्ति में प्रतिक्रियाएँ। कहा गया था:

"पूरे क्षेत्र में, न्यायपालिका की प्रासंगिकता

मानवाधिकारों का संरक्षण और संवर्धन निर्विवाद है। इस स्वीकृति के बावजूद, न्यायिक

स्वतंत्रता को लगातार उन खतरों का सामना करना पड़ रहा है जो समझौता करते हैं न केवल व्यक्तिगत न्यायाधीश बल्कि संस्थानों को भी न्याय देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। को।

कि अंत में, न्यायिक स्वतंत्रता एक बनी हुई है

लोकतंत्र और संविधानवाद की आधारशिलाएँ

479 एचटीटीपी: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. सबर। को. ज़ा/लॉ-जर्नल्स/2010/दिसंबर/2010-दिसंबर खंड 023-संख्या 3-पीपी 43-48।

पी. डी. एफ. शीर्ष अदालतें-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकर, जे.]

दुनिया भर में, अधिकांश कानूनी का केंद्रीय लक्ष्य बना हुआ है

प्रणालियाँ। यह ध्यान दिया गया है कि स्वतंत्रता

न्यायपालिका की आवश्यकता है कि इससे स्वतंत्रता होनी चाहिए

सरकार की शाखाएँ।

महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, नियुक्ति की प्रणालियाँ

इस

न्यायिक अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्राप्त की जाती है। जबकि वहाँ न्यायपालिका के महत्व पर आम सहमति है स्वतंत्रता, विभिन्न कानूनी प्रणालियों का उपयोग किया है न्यायपालिका के अधिभोगियों की नियुक्ति के विभिन्न तरीके कार्यालय। इनमें शामिल हैं; क) राजनीतिक द्वारा नियुक्ति। संस्थान; ख) स्वयं न्यायपालिका द्वारा नियुक्ति; ग)

न्यायिक परिषद द्वारा नियुक्ति (जिसमें गैर-न्यायिक परिषद शामिल हो सकती है) न्यायाधीश सदस्य) और कभी-कभी घ) एक के माध्यम से चयन चुनाव प्रणाली। यह विविधता कम से कम इंगित करती है। कि सर्वश्रेष्ठ पर कोई सामान्य सहमति नहीं है न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी के लिए दृष्टिकोण। कि इसके बावजूद, नियुक्ति के लिए तंत्र

न्यायपालिका को बनाए रखने में न्यायाधीश महत्वपूर्ण रहते हैं न्यायपालिका में स्वतंत्रता और जनता का विश्वास "। 480 522. यह विद्वान महान्यायवादी द्वारा इंगित किया गया था

कि स्वतंत्रता के बाद से हर समय कानून मंत्री रहे हैं

न्यायाधीशों की नियुक्ति में प्रक्रिया का एक हिस्सा। वास्तव में यह कानून मंत्री के माध्यम से ही महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है

विशेष रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष

जिन मामलों के बारे में भारत के मुख्य न्यायाधीश को जानकारी नहीं हो सकती है,

जैसे कि व्यक्ति के पूर्ववर्ती और व्यक्तिगत लक्षण

न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए माना जाता है। इसलिए अब कानून मंत्री को इस प्रक्रिया से बाहर रखने का कोई कारण नहीं है।

523. जैसा कि ऊपर बताया गया है, इनके बीच एक अंतर है।

480 एचटीटीपी: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. विधि समाज। org. bw/समाचार/स्थिति% 20 पेपर% 20 ऑन% 20 नियुक्ति% 20 का% 20 न्यायाधीश% 20 अंतिम% 2014% 20 जून% 202012% 20 'अंतिम' PDF [2015] 13 S. C. R.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कानून मंत्री भारत के मुख्य न्यायाधीश को जानकारी प्रदान कर रहे हैं

और अंतिम निर्णय में कानून मंत्री का कहना है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में या

सुप्रीम कोर्ट। जबकि पहले वाले पर निश्चित रूप से आपत्ति नहीं की जा सकती है

वास्तव में यह आवश्यक होगा कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी आपत्तिजनक है। दूसरे शब्दों में, कानून मंत्री निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है (क्योंकि यह पद 99 वें संविधान से पहले था)।

संशोधन अधिनियम) लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए। यह अंतर काफी महत्वपूर्ण है। मतदान

निर्णय लेने की प्रक्रिया में कानून मंत्री की भागीदारी संविधान में बहस के खिलाफ है।

असेंबली और स्पष्ट रूप से मूल के परिवर्तन के बराबर है

संविधान की संरचना।

524. श्री नरीमन ने यह तर्क दिया कि

सदस्य के रूप में केवल भारत सरकार के कानून मंत्री

एन. जे. ए. सी. और राज्य से उसका समकक्ष नहीं होना

एन. जे. ए. सी. के सदस्य के रूप में सरकार का हमारे संविधान में संघवाद पर प्रभाव पड़ सकता है। इसका उल्लेख करने के अलावा, नहीं इस संबंध में गंभीर तर्क दिया गया था, शायद

क्योंकि मुख्य आपत्ति प्रतिनिधित्व के लिए है

एनजेएसी में भारत सरकार। इस तथ्य को देखते हुए कि नहीं इस संबंध में विस्तृत प्रस्तुतियाँ की गईं, मैं इस विवाद पर कोई राय व्यक्त नहीं करना चाहूंगा।

525. इस चर्चा का योग और सार यह है कि

न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हमेशा रहा है

निर्णय में कार्यपालिका के बहिष्कार के आसपास केंद्रित किया गया था

लेना, लेकिन एन. जे. ए. सी. में कानून मंत्री को शामिल करना है

विरोधी-उत्पादक, ऐतिहासिक रूप से विरोधी-बहुसंख्यकवादी और चला जाता है विभिन्न में
व्यक्त किए गए विभिन्न विचारों के खिलाफ

समितियाँ-अधिक इसलिए कि कानून मंत्री निर्णय लेने वाले निकाय में वीटो का प्रयोग कर सकते हैं; कानून की उपस्थिति

एन. जे. ए. सी. में मंत्री को पूरी तरह से अनावश्यक और गलत सलाह दी जाती है; सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

एन. जे. ए. सी. में कानून मंत्री की उपस्थिति संदेह पैदा करती है।

मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी के सिद्धांत पर।

(ई) एन. जे. ए. सी. और अनिवार्य पर प्रभाव

परामर्श

526. मूल रूप से बनाए गए संविधान के अनुच्छेद 124 (2) ने राष्ट्रपति के लिए मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना अनिवार्य कर दिया था

न्यायाधीशों की नियुक्ति में भारत का। इसके पीछे का तर्क

पहले ही चर्चा की जा चुकी है। 99 वाँ संविधान संशोधन

अधिनियम अनिवार्य परामर्श को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। राष्ट्रपति से किसी से परामर्श करने की अपेक्षा नहीं की जाती है

नियुक्ति प्रक्रिया-उससे केवल उस पर कार्य करने की अपेक्षा की जाती है

एनजेएसी की सिफारिश। राष्ट्रपति का अधिकार

कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिश को अस्वीकार करना पड़ा, यदि यह सर्वसम्मत नहीं था, अब राष्ट्रपति से छीन लिया गया है

जो एन. जे. ए. सी. से सिफारिश स्वीकार करने के लिए बाध्य है

भले ही यह सर्वसम्मत न हो। यह एक बहुत बड़ा झटका है।

राष्ट्रपति के अधिकार का ह्रास और नियुक्ति प्रक्रिया में भारी परिवर्तन और एक अर्थ में राष्ट्रपति को कम कर देता है।

(एक व्यक्ति के रूप में) एक रबर स्टाम्प के लिए। 481 इसी तरह, जैसा कि उल्लेख किया गया है

भारत के मुख्य न्यायाधीश से ऊपर केवल एक और न्यायाधीश रह जाता है।

एनजेएसी में संख्या।

527. राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के बीच अनिवार्य परामर्श

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने मसौदा तैयार करके अच्छी तरह से सोचा था

समिति और संविधान सभा लेकिन अब किया गया है

99वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हास्यास्पद बनाया गया, के लिए

ऊपर बताए गए कारण। संविधान का अनुच्छेद 124 (2)

(इसके संशोधन से पहले) राष्ट्रपति और प्रमुख को रखा गया

समान आधार पर भारत का न्याया। यह वही है जिसने

इन दो संवैधानिक प्राधिकरणों के बीच परामर्श

सार्थक और एक संवैधानिक प्राधिकरण के रूप में कार्य किया
दृष्टिकोण' था कि

दूसरी तरफ देखें। यह 'साझेदारी

संविधान सभा के दिमाग में था और इसे मांस दिया गया था

481 यह राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश के बीच विचारों के प्रत्यक्ष आदान-प्रदान के विपरीत हो सकता है जिसका उल्लेख पहले किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

और खून के माध्यम से, जिसे डॉ. राजीव धवन ने संदर्भित किया

'द्वितीय न्यायाधीशों के मामले में संस्थागत भागीदारी। द.

द्वितीय न्यायाधीशों के मामले का महत्व इतना अधिक नहीं है

साझा जिम्मेदारी लेकिन की 'संस्थागत भागीदारी'

नियुक्ति प्रक्रिया में न्यायपालिका के साथ एकीकृत

राष्ट्रपति की भागीदारी। यह अब गायब है।

528. अनिवार्य का क्या महत्व है

परामर्श? ध्यान से देखने के लिए दो महत्वपूर्ण कारक हैं

एक व्यक्ति के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने से पहले माना जाता है

उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय। ये हैं: (1) द.

व्यावसायिक कौशल, न्यायिक क्षमता, उपयुक्तता और एक व्यक्ति का एक अच्छा न्यायाधीश होने का स्वभाव, और (2) उसकी व्यक्तिगत शक्तियाँ, कमजोरियाँ, आदतें और लक्षण -

एक अच्छे न्यायाधीश होने के नाते व्यक्ति की उपयुक्तता और स्वभाव संबंधित है, ऐसा करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति

मूल्यांकन भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे (परामर्श में)

अन्य न्यायाधीशों के साथ) और कानूनी के बाहर से कोई नहीं

बंधुत्व। दूसरी ओर, जहाँ तक व्यक्तिगत शक्तियों की बात है, किसी व्यक्ति की कमजोरियों, आदतों और लक्षणों से संबंधित हैं,

उचित निवेश केवल कार्यपालिका से ही आ सकता है, क्योंकि

भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को शायद पता न हो

(न्यायपालिका के प्रमुख के रूप में) एक व्यक्ति के एक अच्छे न्यायाधीश और राष्ट्रपति (प्रमुख के रूप में) होने की क्षमता पर महत्वपूर्ण जानकारी होना। कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद् के माध्यम से कार्य करने वाले राज्य का) सबसे अच्छा न्यायाधीश होना

न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किए जा रहे व्यक्ति के व्यक्तिगत लक्षणों का आकलन करें। दूसरे शब्दों में, के मुख्य न्यायाधीश

भारत क्षमता के संबंध में 'विशेषज्ञ' है जबकि कार्यपालिका पूर्ववृत्त और व्यक्तिगत क्षमता के संबंध में 'विशेषज्ञ' है।

विशेषताएँ। चूँकि किसी भी न्यायाधीश के व्यक्तित्व के ये दो पहलू निस्संदेह अलग-अलग हैं, इसलिए सर्वोच्च न्यायालयों-चालू-रिकॉर्ड में कोई अंतर नहीं हो सकता है।

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

इस संबंध में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच राय क्योंकि वे दोनों न्यायपालिका के विभिन्न पहलुओं पर राय व्यक्त करते हैं।

व्यक्ति का जीवन। भारत के मुख्य न्यायाधीश इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

कार्यपालिका और न ही कार्यपालिका की 'विशेषज्ञ राय'

भारत के मुख्य न्यायाधीश की 'विशेषज्ञ राय' पर टिप्पणी करें।

529. न्यायपालिका के प्रमुख के रूप में यह न्याय वितरण प्रणाली का प्रबंधन करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए है और यह इसके लिए है

न्यायाधीश या वसीयत के रूप में कार्यों का निर्वहन, किसी भी तरह से, प्रभाव एक अच्छा न्यायाधीश बनने की क्षमता पर। जैसा कि जैक ने कहा है

स्ट्रा, जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि इसे पहली बार और हर बार सही तरीके से प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसी स्थिति हो सकती है जहाँ

किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत लक्षण इस तरह के हो सकते हैं कि उन्हें अयोग्य ठहराया जाए। एक व्यक्ति को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा रहा है और वहाँ एक हो सकता है

ऐसी स्थिति जहाँ व्यक्तिगत लक्षणों का विरोध किया गया हो

उस व्यक्ति की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है

एक अच्छा न्यायाधीश बनना। उदाहरण के लिए, हाल ही में वहाँ

अभिविन्यास। यह संभव है कि कार्यपालिका के पास एक किसी व्यक्ति के यौन अभिविन्यास पर विचार करने पर आपत्ति

न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश कर सकते हैं

इस राय का होना कि उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा

न्यायिक कार्यों या क्षमता का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने की क्षमता

उस व्यक्ति का एक अच्छा न्यायाधीश होना। 482 इस तरह की स्थितियों में, यह भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय है कि इसका अधिक महत्व होना चाहिए क्योंकि जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यह मुख्य न्यायाधीश के लिए है।

न्याय का कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए भारत का न्याय

वितरण प्रणाली और इसलिए, अंतिम शब्द के साथ होना चाहिए

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सर्वसम्मति से व्यक्त किया।

482 ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की पीठ में एक समलैंगिक न्यायाधीश है। भारत में वर्तमान राजनीतिक कार्यपालिका शायद किसी समलैंगिक व्यक्ति को पीठ में नियुक्त करने की अनुमति नहीं देगी।

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

530. 99 वां संविधान संशोधन अधिनियम और एनजेएसी

अधिनियम न केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश की संख्या को कम करता है

एन. जे. ए. सी. लेकिन अनिवार्य परामर्श को भी परिवर्तित करता है

राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश एक मूक नाटक के लिए एन. जे. ए. सी. एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। पहले के मौकों पर,

संसद ने संवैधानिक माध्यम से अपनी शक्ति बढ़ाई

इंदिरा में किए गए संशोधन, जिन्हें अन्य बातों के साथ निरस्त कर दिया गया था

नेहरू गांधी और मिनर्वा मिल्स। 483 99 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम असंवैधानिक रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश और न्यायपालिका की भूमिका को कम कर देता है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति। यह भी काफी कम करता है

राष्ट्रपति की भूमिका। यह मूल संरचना को नष्ट कर देता है

पर्याप्त रूप से परिवर्तन करके न्यायपालिका की स्वतंत्रता

उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया और

उच्च न्यायालय, या कम से कम इसे असंवैधानिक रूप से बदल देता है

न्यायपालिका की स्वतंत्रता के आधार पर प्रहार करना।

531. पूरे मुद्दे को एक और नज़र से देखा जा सकता है:

संविधान सभा ने इसे अनिवार्य क्यों बनाया

राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेंगे

उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति

जब समान रूप से महत्वपूर्ण है, यदि अधिक महत्वपूर्ण संवैधानिक नहीं है

बिना राष्ट्रपति के अधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है। किसी से भी और उसके 'निरंकुश विवेक' में परामर्श करना? द.

483 1 में। आर. कोएल्हो बनाम। तमिलनाडु राज्य, (2007) 2 एस. सी. सी. 1 इस न्यायालय ने रिपोर्ट के पैराग्राफ 138 में कहा: इंदिरा गांधी मामला, मिनर्वा मिल्स मामला और वामन राव मामला ((1981) 2 एस. सी. सी. 362] की प्रासंगिकता इस तथ्य में निहित है कि संसद द्वारा अपनी शक्ति की प्रत्येक अनुचित वृद्धि, चाहे वह अनुच्छेद 329-ए का खंड (4) हो या अनुच्छेद 368 का खंड (4) और (5) या 42 वें संशोधन की धारा 4 हो, को बुनियादी सिद्धांत के साथ असंगत माना गया है। संरचना के रूप में उन्होंने नए तत्वों को पेश किया जिन्होंने संविधान की पहचान को बदल दिया या संविधान से मौजूदा तत्वों को हटा दिया जिसके द्वारा संविधान के मूल को त्याग दिया गया है। उन्होंने न्यायिक समीक्षा जैसे महत्वपूर्ण तत्वों को मिटा दिया। उन्होंने सभी मौलिक अधिकारों के उन्मूलन के लिए निर्देशात्मक सिद्धांतों को एक कसौटी बनाया और नौवीं अनुसूची में कानूनों को शामिल करने के लिए प्रावधान किया, जिसका कृषि सुधारों के साथ कोई संबंध नहीं था।

सर्वोच्च अदालतें-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

नियुक्तियों के मामले में 'विशेष' व्यवहार का कारण

न्यायपालिका के लिए है क्योंकि संविधान सभा

सराहना की और स्वीकार किया और इसलिए, स्वीकार किया

स्वतंत्रता को संरक्षित और संरक्षित करने की आवश्यकता

न्यायपालिका, संसदीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह.

यह भी स्वीकार किया कि मार्गदर्शन करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति

और न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को सलाह देंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश के अलावा और कोई नहीं। संविधान सभा को यह पता था कि लोगों के अधिकार, जिनमें शामिल हैं

उनके मौलिक अधिकारों को मनमाने तरीके से संरक्षण की आवश्यकता है कार्यकारी शक्ति और अत्यधिक विधायी कार्रवाई और जब तक कि

न्यायपालिका कदम उठाती है और उस संरक्षण को प्रदान करती है, इस तरह की मनमानी

शक्ति या अत्यधिक कार्रवाई का दुरुपयोग और दुरुपयोग किया जा सकता है। यह

पूर्व स्वतंत्र भारत में हुआ था और में हुआ है हमारा हाल का इतिहास। 99 वां संविधान संशोधन अधिनियम और

एन. जे. ए. सी. अधिनियम सकारात्मक रूप से (असंवैधानिक रूप से) इंगित करता है कि अब भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश नहीं हैं

अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति

न्यायाधीशों की नियुक्ति।

532. नियुक्ति के महत्व को रेखांकित करते हुए

स्वतंत्र न्यायाधीशों (अमेरिकियों के लिए, और यह भारतीयों पर भी समान रूप से लागू होगा) के बारे में कहा गया है कि:

"न्यायिक नियुक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं क्योंकि न्यायाधीश

व्यवसायियों, लेकिन सभी अमेरिकियों के लिए। जज खेलते हैं रोजमर्रा के जीवन के निर्णयों में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका। यह.

यह प्रक्रिया जिसके द्वारा उनका चयन किया जाता है

विषय हैं। यह इसी तरह से माना जाता है कि क्योंकि
न्यायाधीशों की नियुक्ति का महत्व, नियुक्तियाँ
प्रक्रिया विवाद को जन्म देती है। 484

533. एक स्वतंत्र न्यायपालिका के बिना, न केवल 'रोज'

181 484 कार्ली वान ऑर्मन, संगोष्ठी का परिचय: न्यायिक प्रक्रिया नियुक्ति प्रक्रिया, 10 डब्ल्यू. एम. & मैरी
बिल आर. टी. जे. 1 (2001), एचटीटीपी: // छात्रवृत्ति। कानून। डब्ल्यू. एम. ई. डी. यू./डब्ल्यू. एम. बी. आर.
जे./वॉल्यूम 10/आई. एस. 1/2 [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

'जीवन निर्णय' प्रभावित होते हैं लेकिन एक प्रमुख कार्यकारी यह सुनिश्चित कर सकता है कि वैधानिक
अधिकारों का कोई अर्थ नहीं होगा और

देश के लोगों के मौलिक अधिकारों को आसानी से कुचला जा सकता है। न्यायपालिका के प्रभाव पर प्रकाश
डालना

(आम तौर पर) कानून के शासन और विशेष रूप से अधिकारों पर

और व्यक्तियों के हित, ऑस्ट्रेलिया के मुख्य न्यायाधीश मेसन

यह कहना था:

"न्यायाधीशों के चयन के तरीके के लिए प्रासंगिक एक अन्य कारक

एक महत्वपूर्ण शाखा के रूप में न्यायपालिका की स्थिति है या

सरकारी संस्था। न्यायाधीश सार्वजनिक अभ्यास करते हैं।

इस तरह से शक्ति जिसका अधिकारों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है

और व्यक्तियों के हितों और के निर्माण पर

सरकार और सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

एजेंसियाँ और अन्य संगठन "।

534. संविधान सभा अच्छी तरह से जानती थी कि

कार्यपालिका द्वारा शक्ति का दुरुपयोग और दुरुपयोग, जिसने लड़ाई लड़ी है

हमारी स्वतंत्रता के लिए और एक स्वतंत्र न्यायपालिका के मूल्य को जानते और समझते थे। यही कारण है कि
संविधान

सभा ने स्वतंत्रता को प्रमुख महत्व दिया

न्यायपालिका और शायद किसी भी बहस की तुलना में इस पर अधिक समय बिताया
अन्य विषय।

535. इस संबंध में, यह प्रस्तुत करने के लिए याद करने योग्य है

श्री पालखीवाला केशवानंद भारती में आधार बनाते हुए

'शक्ति की चौड़ाई' परीक्षण के लिए (बाद में एम. नागराज में अपनाया गया) कि:

"..... एक शक्ति की वास्तविक चौड़ाई का परीक्षण कितना संभावित नहीं है

यह है कि इसका प्रयोग किया जा सकता है लेकिन संभवतः क्या हो सकता है
इसके तहत किया गया; कि सत्ता का दुरुपयोग या दुरुपयोग पूरी तरह से है

अप्रासंगिक; कि शक्ति की सीमा का सवाल
इसके प्रयोग के प्रश्न के साथ मिश्रित नहीं किया जा सकता है और जब वास्तविक प्रश्न शक्ति की चौड़ाई के बारे
में है,

485 'ऑस्ट्रेलिया के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सर एंथनी मेसन ए. सी. के. बी. ई. द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति
और निष्कासन //डब्ल्यू. डब्ल्यू. जुडकोम। एनएसडब्ल्यू। गव. एयू/प्रकाशन/शिक्षा-मोनोग्राफ-
1/मोनोग्राफ 1/एफबीमेसन।

एच. टी. एम. सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

तय करें कि सबसे अच्छा और सबसे बुरा क्या है। यह केवल
यह तय करता है कि किसी शक्ति के तहत संभवतः क्या किया जा सकता है यदि

इसे प्रदान करने वाले शब्दों का इतना अर्थ लगाया जाता है कि

असीमित और असीम चौड़ाई, जैसा कि की ओर से दावा किया गया है

उत्तरदाताओं "। 486

536. अब, शक्ति की चौड़ाई को देखते हुए इस पर विचार करें।

99 वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत उपलब्ध है यदि

प्रतिबद्ध न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है (जैसा कि एक बार में प्रचारित किया गया था)

समय के साथ और यह 99 वें संविधान के बाद वास्तविक हो सकता है

संशोधन अधिनियम) तब कोई भी निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता है

आमतौर पर एक 'प्रतिबद्ध' सर्वोच्च न्यायालय से समझा जाता है या सभा पूरी तरह से चाहती थी कि

एक उच्च न्यायालय। संविधान

इससे बचें और इसलिए काफी महत्व दिया गया था

न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया और उनकी स्वतंत्रता

न्यायपालिका '। न्यायिक कार्य के सभी रूपों के लिए सामान्य है

स्वतंत्र, निष्पक्ष और तटस्थ निर्णय, हालांकि वहाँ

यह पूरी तरह से तटस्थ निर्णय प्राप्त करने की संभावना के बारे में एक सवाल है। '487 99 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम और एन. जे. ए. सी. अधिनियम एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका स्थापित किए जाने की स्पष्ट संभावना को जन्म देता है। यदि यह मूल संरचना का उल्लंघन नहीं करता है

संविधान क्या करता है?

537. इस चर्चा का योग और सार यह है कि

राष्ट्रपति और प्रमुख के बीच अनिवार्य परामर्श

संविधान में अभिनिर्धारित भारत का न्याय पारित किया जाता है -

नियुक्ति की प्रक्रिया में भारी बदलाव लाना

न्यायाधीशों की संख्या; 99 वें संविधान संशोधन अधिनियम और एन. जे. ए. सी. अधिनियम ने परामर्श प्रक्रिया को एक प्रहसन में बदल दिया है -

सार्थक सहभागी परामर्श प्रक्रिया अब मौजूद नहीं है;

486 अनुच्छेद 531

487 'ऑस्ट्रेलिया के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सर एंथनी मेसन ए. सी. के. बी. ई. द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति और निष्कासन //डब्ल्यू. डब्ल्यू. जुडकॉम। एनएसडब्ल्यू। गव. एयू/प्रकाशन/शिक्षा-मोनोग्राफ-1/मोनोग्राफ 1/एफबीमेसन।

एचटीएम [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राष्ट्रपति और प्रमुख के बीच साझा जिम्मेदारी

न्यायाधीशों की नियुक्ति में भारत का न्याय एक को दिया जाता है निकाय

संविधान के चिंतन से परे

सभा; प्रतिबद्ध न्यायाधीशों और होने की संभावना

एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका होने के परिणाम, एक न्यायपालिका जो स्वतंत्र नहीं होना अकल्पनीय है।

(च) एन. जे. ए. सी. और उच्च न्यायालय की नियुक्ति न्यायाधीशों

538. जहाँ तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की बात है 99 वें संविधान संशोधन अधिनियम और एन. जे. ए. सी. अधिनियम में दो अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया। सबसे पहले, अनिवार्य आवश्यकता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के लिए है पूरी तरह से अलग कर दिया गया। संविधान का अनुच्छेद 217 (1) मूल रूप से अधिनियमित संविधान ने इसे अनिवार्य बना दिया था राष्ट्रपति के लिए राज्य के राज्यपाल से परामर्श करना और

एक उच्च न्यायालय। मुख्य न्यायाधीश को अब छोड़ दिया गया है ठंड। दूसरा, संवैधानिक दायित्व और संवैधानिक

सम्मेलन जो पिछले कई दशकों में विकसित हुआ है कि एक न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए एक सिफारिश है

उच्च न्यायालय की उत्पत्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से होती है। इसे अब 99 वें संविधान द्वारा मंजूरी दे दी गई है।

संशोधन अधिनियम और एनजेएसी अधिनियम। नियुक्ति प्रक्रिया की पूरी शुरुआत में अब बदलाव किया गया है।

539. एनजेएसी अधिनियम की धारा 6 (2) के संदर्भ में,

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए सिफारिश

यह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से उत्पन्न नहीं हो सकता है लेकिन एन. जे. ए. सी. उस उद्देश्य के लिए मुख्य न्यायाधीश से नामांकन की मांग करेगा।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। दूसरे शब्दों में, के लिए पहल

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति से छीन ली जाती है एनजेएसी द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। वहाँ एक है

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं के बीच गुणात्मक अंतर-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन v.

यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकर, जे.]

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति को नामित करना एन. जे. ए. सी. (एन. जे. ए. सी. अधिनियम की धारा 6 (2)) और किसी व्यक्ति की सिफारिश करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की पहल पर

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए (अनुच्छेद 217 (1) संविधान)। से इतने बड़े प्रस्थान के साथ

पिछले कई दशकों में स्थापित, वितरण नामांकन के लिए प्रचार समर्थन को प्रोत्साहित कर सकता है-ए कुछ इसी तरह की घटना को नीचा देखा गया था

एल. सी. आई. ने अपनी 14 वीं रिपोर्ट में कहा।

540. लेकिन इससे अधिक परेशान करने वाली और आपत्तिजनक बात क्या है?

यह है कि मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श प्रक्रिया

उसके द्वारा किसी व्यक्ति का नामांकन किए जाने के बाद उच्च न्यायालय

उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए किया गया है

के साथ दूर। परामर्श की प्रक्रिया एक एकीकृत और

भागीदारी प्रक्रिया लेकिन 99 वें संविधान के आधार पर

संशोधन अधिनियम और एन. जे. ए. सी. अधिनियम में केवल नामांकन की मांग की जाती है।

एन. जे. ए. सी. द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। इसके बाद, मुख्य न्यायाधीश की कोई भूमिका नहीं है। यह खंड से स्पष्ट है।

6 (7) एन. जे. ए. सी. अधिनियम जो एन. जे. ए. सी. को राज्यपाल और राज्य के मुख्यमंत्री के विचारों को लिखित रूप में प्राप्त करने का आदेश देता है।

नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की सिफारिश करने से पहले बताएँ

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, लेकिन मुख्य न्यायाधीश के विचार नहीं,

जो केवल एक नामित करने वाले अधिकारी तक सीमित हो जाता है, जिसे नियुक्त किया जाता है नामांकन होते ही कार्य समाप्त हो जाता है।

541. 99 वें संविधान का संयुक्त प्रभाव

संशोधन अधिनियम और एन. जे. ए. सी. अधिनियम की धारा 6 यह है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति पर पूरा नियंत्रण एन. जे. ए. सी. द्वारा लिया जाता है और प्रतिमान पूरी तरह से है।

एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परिवर्तित किया गया

एक अनिवार्य सलाहकार, और एक के प्रवर्तक
सिफारिश

अनुच्छेद द्वारा अभिनिर्धारित नियुक्ति के लिए

217(1) संविधान का, जैसा कि पारंपरिक रूप से समझा जाता है, [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कोई ऐसा व्यक्ति जो केवल नामांकन करता है और उसके बाद

नामांकन के संबंध में एक या दूसरे तरीके से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है। प्रक्रिया में यह भारी बदलाव

दीर्घकालिक प्रभाव क्योंकि यह अंततः उच्च के 'कैडर' से होता है अदालत का मानना है कि यदि मौजूदा प्रथा का पालन किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय के अधिकांश न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। यह बदले में होगा

स्पष्ट रूप से स्वतंत्रता पर एक दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है

प्रक्रिया को पूरी तरह से बदलने के अलावा न्यायपालिका

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति।

542. न्यायाधीशों की नियुक्ति बहुत गंभीर मामला है।

और इसके महत्व को कम करना मुश्किल है। एक का उल्लेख करते हुए

शिमोन शेटीट 488 द्वारा व्यक्त विचार यह सरकार द्वारा कहा गया है

राजशाही विश्वविद्यालय, बांग्लादेश के अली अक्कास ने कहा:

"न्यायाधीशों की नियुक्ति एक महत्वपूर्ण पहलू है -

न्यायिक स्वतंत्रता जिसके लिए आवश्यक है कि

न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत चाहता है कि न्याय देने के लिए न्यायाधीशों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना

निष्पक्ष रूप से, बिना किसी डर या पक्षपात के। यह स्वतंत्रता

न्यायाधीशों का न्यायिक नियुक्ति के साथ घनिष्ठ संबंध होता है।

क्योंकि नियुक्ति प्रणाली का सीधा असर होता है

निष्पक्षता, अखंडता और स्वतंत्रता पर

न्यायाधीश ", 489

543. अनिवार्य रूप से, 99 वां संविधान संशोधन अधिनियम

नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को प्रतिस्थापित या प्रतिस्थापित करता है

एन. जे. ए. सी. द्वारा न्यायाधीशों का। यह महसूस किया जाना चाहिए कि एक न्यायिक नियुक्ति
आयोग (जिसे भी नाम से जाना जाए) एक

488 शिमोन शेद्रीट, जज ऑन ट्रायल (नॉर्थ-हॉलैंड पब्लिशिंग कंपनी, एम्स्टर्डम, (1976), पृष्ठ 46।

489 अक्कास, सरकार अली (2004) "न्यायाधीशों की नियुक्ति: न्यायिक स्वतंत्रता का एक प्रमुख मुद्दा, "बॉन्ड
लॉ रिव्यू: खण्ड. 16 : इश्यू. 2, अनुच्छेद 8. यहाँ उपलब्ध है: एचटीटीपी: //प्रकाशन। बंधन। एड्यू।

ए. यू./बी. एल. आर./वॉल्यूम 16/आई. एस. एस. 2/8 सर्वोच्च न्यायालय विज्ञापन-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

कार्यपालिका के कार्यभार संभालने और नियुक्त करने पर दुनिया भर में प्रतिक्रिया

न्यायाधीशों। कानून के शासन का पालन करने वाली कोई भी प्रणाली इसे बनाए रखना नहीं चाहेगी

न्यायाधीशों की नियुक्ति की एक प्रणाली जहाँ कार्यपालिका खेलती है

एक प्रमुख भूमिका या विषय पर अंतिम शब्द है, इसलिए न्यायिक नियुक्ति आयोग के लिए कभी-
कभार कोलाहल।

जैसा कि जैक स्ट्रॉ के हैमलिन व्याख्यान से पता चलता है, कार्यकारी

न्यायाधीशों की नियुक्ति में अधिक नियंत्रण चाहता है लेकिन

न्यायपालिका के पास अंततः ऊपरी हाथ है, जैसा कि इसे होना चाहिए-लेकिन नहीं

तो एन. जे. ए. सी. के साथ।

544. कुमार पद्म प्रसाद मामले में इस अदालत का फैसला

बी. भारत संघ 490 इस बात का एक उदाहरण है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में कार्यपालिका
कितनी गलत हो सकती है। उस मामले में, ए

न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यायिक अधिकारी की सिफारिश की गई थी

भारत के न्यायाधीश और अनुशंसित व्यक्ति की नियुक्ति का वारंट राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया था लेकिन
यह था बाद में प्रभाव नहीं दिया गया क्योंकि व्यक्ति पाया गया था

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य नहीं। हाल ही में, कनाडा के सर्वोच्च
न्यायालय ने एक संदर्भ का जवाब दिया

परिषद में गवर्नर जनरल द्वारा किया गया जिसके परिणामस्वरूप

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और शपथ ग्रहण को शुरू से ही अमान्य घोषित कर दिया गया था क्योंकि उनके पास यह अधिकार नहीं था

पात्रता आवश्यकता। 491 खुशकिस्मती से इस तरह के उदाहरणों ने एक प्रणाली में जनता के विश्वास को हिलाकर रख दिया है

न्यायाधीशों की नियुक्ति जहां कार्यपालिका की प्रधानता है,
इसलिए एक प्रभावी विकल्प की ओर बढ़ने की इच्छा। जबकि
अधिक कुशल या बेहतर प्रणाली की आवश्यकता हो सकती है
न्यायाधीशों की नियुक्ति, एन. जे. ए. सी. स्वर्ग की सीढ़ी नहीं है,
विशेष रूप से इसके कामकाज में विभिन्न अंतरालों को देखते हुए,
एन. जे. ए. सी. प्रणाली राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश का दर्जा घटाती है।
भारत और कई अन्य विशेषताओं को शामिल करना जो गंभीर रूप से

490 (1992) 2 एस. सी. सी. 428 491 उच्चतम न्यायालय अधिनियम, धारा 5 और 6, [2014] 1
एस. सी. आर. 433 [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायपालिका की स्वतंत्रता और इस प्रकार मूल संरचना पर संविधान से।

545. यह विद्वान महान्यायवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली से मोहभंग है और इसलिए इसे बदलने की आवश्यकता है

या प्रतिस्थापित किया गया और ठीक यही 99 वां संविधान है संशोधन अधिनियम ने सफलता प्राप्त की है। विद्वान महान्यायवादी

एनजेएसी को नियुक्ति में तीसरे अध्याय के रूप में संदर्भित किया गया न्यायाधीशों का-पहला
अध्याय वह है जिसमें कार्यपालिका के पास नियुक्ति प्रक्रिया में 'अंतिम शक्ति' थी और

दूसरा अध्याय वह है जिसमें कार्यपालिका और

न्यायपालिका की न्यायपालिका के साथ एक साझा जिम्मेदारी है

संस्थागत भागीदारी। ऐसा हो सकता है लेकिन 99 वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से एन. जे. ए. सी.

न केवल कार्यपालिका की बल्कि साझा जिम्मेदारी भी
जिम्मेदारी, पूरी तरह से

न्यायपालिका और कार्यपालिका की

संविधान सभा द्वारा हमें दी गई नियुक्ति प्रणाली का सिर कलम करना एक ऐसी प्रणाली जो यह सुनिश्चित
करती है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता।

546. द्वारा सुझाए गए मापदंडों के भीतर काम करना

विद्वान महान्यायवादी, अर्थात्, की धारणा
कि

99 वें संविधान संशोधन अधिनियम की संवैधानिकता,

द्वितीय न्यायाधीशों के मामले में निर्णय का आधार है

हटा दिया गया, संसद का विवेक और आवश्यकताएँ

लोगों से पूछताछ नहीं की जा सकती और यह कि इस न्यायालय को

यह स्वीकार करें कि समाज और इसकी आवश्यकताएँ बदल गई हैं

समय के साथ, यह बनाए रखना संभव नहीं है

99 वें संविधान संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता। यह विधि नियुक्ति की प्रक्रिया को काफी बदल
देती है

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा

इसके आवश्यक अवयवों को हटा दें जिससे एक संवैधानिक

चुनौती जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए। 547. समग्र रूप से और

99 वें संविधान संशोधन

अधिनियम और सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं का समग्र दृष्टिकोण-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

एन. जे. ए. सी. अधिनियम, बजाय एक टुकड़ों में चर्चा या एक

प्रत्येक प्रावधान का विच्छेदन, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि अनुच्छेद

124 संविधान का ए (संशोधित) असंवैधानिक है।

संविधान का अनुच्छेद 124 ए घोषित किया गया है

असंवैधानिक, अनुच्छेद में कुछ भी सार नहीं बचा है

124 बी और संविधान का अनुच्छेद 124 सी और अन्य

99 वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधान, जो हैं -
 विच्छेद योग्य नहीं है और इसलिए ये प्रावधान होने चाहिए और हैं
 के उल्लंघन और परिवर्तन में असंवैधानिक घोषित किया गया
 संविधान की मूल संरचना।

548. इस चर्चा का योग और सार यह है कि
 नियुक्ति के लिए सिफारिश शुरू करने की प्रक्रिया
 स्वतंत्रता के बाद से आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले न्यायाधीश को अच्छी तरह से स्थापित संवैधानिक
 व्यवस्था के साथ मौलिक रूप से बदल दिया गया है
 सम्मेलनों को छोटी छूट दी जा रही है; के मुख्य न्यायाधीश
 उच्च न्यायालय को एक मनोनीत अधिकारी की भूमिका तक सीमित कर दिया गया है,
 जिनकी राय केवल नामांकन के उद्देश्यों के लिए ली जाती है, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण मामले में सलाहकार के
 रूप में नहीं ली जाती है जैसे कि
 एक न्यायाधीश; मुख्य न्यायाधीश को दिया गया संवैधानिक महत्व
 एक उच्च न्यायालय को पूरी तरह से लगभग समाप्त कर दिया गया है
 एक लुप्त बिंदु।

एनजेएसी के संयोजक

549. कुछ परिधीय मुद्दे हैं जो होने चाहिए

चर्चा की। एन. जे. ए. सी. में कार्यकारी की भागीदारी
 कानून मंत्री के इसके सदस्यों में से एक होने के साथ नहीं रुकते हैं। द. विभाग में भारत सरकार के
 सचिव
 एन. जे. ए. सी. अधिनियम की धारा 8 (3) के संदर्भ में न्यायमूर्ति एन. जे. ए. सी. के संयोजक हैं। संयोजक के
 कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ
 एन. जे. ए. सी. अधिनियम में चित्रित नहीं किया गया है और, जैसा कि उल्लेख किया गया है ऊपर,
 अधिनियम के तहत नियम और विनियम नहीं किए गए हैं
 फ्रेम किया गया। इसलिए उन कार्यों की सराहना करना मुश्किल है जो संयोजक से प्रदर्शन करने की
 अपेक्षा की जाती है।

550. इसके अलावा, सचिव [2015] 13 एस. सी. आर. के एक अधिकारी हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सरकार और एन. जे. ए. सी. के प्रति जवाबदेह नहीं है। सचिव भुगतान किया जाता है।

सरकारी खजाने से वेतन और भत्तों का

यह उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों के बिल्कुल विपरीत है।
सीधे अपने संबंधित प्रमुख के प्रति जवाबदेह हैं

न्यायालय जो

न्याय। इसके अलावा, उनका वेतन और भत्ते भी लिए जाते हैं।

भारत की संचित निधि पर। की 'स्वतंत्रता'

इन अधिकारियों को बनाए रखा जाता है जबकि सचिव का

कार्यपालिका की सनक और इच्छाओं पर बदला जाए, एन. जे. ए. सी. को निरंतरता से वंचित करना और एक अर्थ में इसे छोड़ना।

जब भी यह कार्यपालिका को प्रसन्न करता है, उच्च और शुष्क होता है। यह स्पष्ट है कि

आपत्तिजनक। हालाँकि, विद्वान वकील के प्रति निष्पक्ष होना

जनरल, यह प्रस्तुत किया गया था कि यदि आवश्यक हो तो एक पंजीयक संयोजक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन

सर्वोच्च न्यायालय को

सम्मान जो उठाए गए मुद्दे का बिल्कुल भी जवाब नहीं है।

पारदर्शिता

551. गोपनीयता आवश्यकताओं के संदर्भ में,

विद्वान महान्यायवादी का निवेदन था कि

एन. जे. ए. सी. का कामकाज पूरी तरह से पारदर्शी होगा।

पारदर्शिता की आवश्यकता को उचित ठहराते हुए यह प्रस्तुत किया गया कि

कॉलेजियम में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया

व्यवस्था इस मायने में बेहद गुप्त रही है कि कोई नहीं

कॉलेजियम के बाहर या न्याय विभाग को इसके बारे में पता है

भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई सिफारिशें

उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति। रेनू वी का संदर्भ दिया गया था। जिला न्यायाधीश 492 से तर्क दें कि सभी न्यायिक क्षेत्रों में नियुक्ति के मामले में

लाइट हाउस में संस्थानों का पूरा अंधेरा दूर करना होगा। 1493

552. पारदर्शिता के मुद्दे के अलावा एक प्रस्तुति

यह बनाया गया था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में, सिविल

492 (2014) 14 एससीसी 50

493 पैराग्राफ 4 सुप्रीम कोर्ट के वकील-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

समाज को यह जानने का अधिकार है कि किसके लिए विचार किया जा रहा है

नियुक्ति। इस संबंध में, यह इंडियन एक्सप्रेस में आयोजित किया गया था

समाचार पत्र वी। भारत संघ 494 कि लोगों को अधिकार है

जानने के लिए। रिलायंस को अटॉर्नी जनरल बनाम पर रखा गया था। समय-सीमा

समाचार पत्र Ltd.495 जहाँ जानने के अधिकार को मान्यता दी गई थी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के
मौलिक सिद्धांत के रूप में और

चर्चा की स्वतंत्रता।

553. यू. पी. राज्य बनाम राज नारायण 496 जानने का अधिकार

की अवधारणा से व्युत्पन्न होने के रूप में मान्यता प्राप्त थी

बोलने की स्वतंत्रता।

554. अंत में, रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड बनाम।

इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र बॉम्बे (पी) के मालिक

Ltd.497 यह माना गया था कि जानने का अधिकार एक बुनियादी अधिकार है जो एक स्वतंत्र
देश के नागरिक व्यापक क्षितिज में आकांक्षा रखते हैं

अनुच्छेद 21 के तहत हमारी भूमि में इस युग में रहने का अधिकार

संविधान।

555. पारदर्शिता और पारदर्शिता के बीच संतुलन

गोपनीयता बहुत नाजुक है और अगर कुछ संवेदनशील जानकारी है

एक विशेष व्यक्ति के बारे में सार्वजनिक किया जाता है, यह एक दूर हो सकता है

उसकी प्रतिष्ठा और गरिमा पर प्रभाव डालना। 99 वां

संविधान संशोधन अधिनियम और एन. जे. ए. सी. अधिनियम लागू नहीं हुए हैं। किसी व्यक्ति की गोपनीयता संबंधी चिंताओं पर ध्यान दें। यह महत्वपूर्ण है

क्योंकि यह विद्वान महान्यायवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि

और एन. जे. ए. सी. के पास उपलब्ध जानकारी तक किसी की भी पहुंच हो सकती है। यह एक व्यापक सामान्यीकरण है जो स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति की गोपनीयता को ध्यान में नहीं रखा जाता है जिसे नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया है, विशेष रूप से

उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या पहली बार में न्यायाधीश के रूप में

सर्वोच्च न्यायालय। जानने का अधिकार मौलिक नहीं है।

494 (1985) 1 एस. सी. सी. 641

498 (1975) 4 एस. सी. सी. 428

497 (1988) 4 एस. सी. सी. 592 [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सही लेकिन सबसे अच्छा यह एक अंतर्निहित मौलिक अधिकार है और यह है

निजता के अंतर्निहित मौलिक अधिकार के साथ बचाव किया गया है कि सभी

लोग आनंद लेते हैं। दोनों के बीच संतुलन निहित है

मौलिक अधिकारों को बनाए रखना मुश्किल है, लेकिन 99 वां

संविधान संशोधन अधिनियम और एन. जे. ए. सी. अधिनियम भी नहीं

विचार करने का प्रयास करें, उस संतुलन को प्राप्त करने की तो बात ही छोड़िए।

556. यह तर्क देना संभव है कि जानकारी स्वेच्छा से

नियुक्ति के लिए अनुशंसित व्यक्ति द्वारा आपूर्ति की गई

एक न्यायाधीश के रूप में गोपनीयता का अधिकार नहीं हो सकता है, लेकिन साथ ही

समय, चूंकि जानकारी विश्वास में प्रदान की जाती है, यह है

यह तर्क देना संभव है कि इसका खुलासा तीसरे पक्ष को नहीं किया जाना चाहिए बेपरवाह लोग। इसके अलावा, यदि सिफारिश नहीं है

राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार किया गया, क्या अनुशंसित व्यक्ति

प्रतिकूल जानकारी का खुलासा न करने का अधिकार है
मुश्किल सवाल

राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया? ये हैं

जिस पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया है और केवल

जानने के अधिकार के आधार पर, किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती

धोबी-घाट में सफ़ेद किया गया।

पुनरुत्थान का सिद्धांत

557. विद्वान महान्यायवादी ने प्रस्तुत किया कि जब

एक कानून में संशोधन किया जाता है और संशोधन घोषित किया जाता है

असंवैधानिक, पूर्व-संशोधन कानून पुनर्जीवित नहीं होता है।

इसलिए, भले ही 99 वां संविधान संशोधन अधिनियम है

संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन के रूप में घोषित, संविधान का अनुच्छेद 124 (2) जो 99 वीं से पहले मौजूद था।

संविधान संशोधन अधिनियम अपने आप पुनर्जीवित नहीं होगा और

कॉलेजियम प्रणाली फिर से शुरू नहीं होगी।

558. इस संबंध में एक दिलचस्प चर्चा देखी जा सकती है।

वेस्ट यू. पी. शुगर मिल्स एसोसिएशन में। बी. *U.P.498* इस न्यायालय की स्थिति

बी. एन. तिवारी बनाम। भारत संघ 499 और फर्म ए. टी. बी.

मेहताब माजिद एंड कंपनी बनाम मद्रास राज्य 500 जिसमें से दोनों में यह

498 (2002) 2 एस. सी. सी. 645

499 ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1430 (पाँच न्यायाधीशों की पीठ) 500 ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 928 (पाँच न्यायाधीशों की पीठ)

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि कोई सांविधिक नियम किसी नियम को प्रतिस्थापित करता है और नया

नियम को निरस्त या अमान्य घोषित किया जाता है, प्रतिस्थापित या पुराना नियम पुनर्जीवित नहीं होता है क्योंकि इसके प्रतिस्थापन पर इसका अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यही तर्क इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (बॉम) (पी) लिमिटेड में एक अधिसूचना पर लागू किया गया था। भारत संघ। 501

559. तथापि, यह आगे अभिनिर्धारित किया गया कि यदि बाद का कोई कानून अमान्य माना जाता है जैसे कि ऐसे मामले में जहां विधानमंडल

कानून बनाने की कोई क्षमता नहीं थी, फिर पहले या पुराने

कानून पुनर्जीवित होगा। यह आयोजित किया गया था:

"यह एक अलग मामला होता जहां बाद में

जिस कानून ने पहले के कानून को संशोधित किया था, उसे अमान्य माना गया था। ऐसे मामले में, पूर्ववर्ती कानून को ऐसा माना जाएगा -

कभी भी संशोधित या निरस्त नहीं किया गया और इसलिए, बल में बने रहे। जहाँ यह पाया जाता है कि

विधायिका में कानून बनाने की क्षमता का अभाव था, फिर भी

मौजूदा कानून में संशोधन करता है और बाद में यह पाया जाता है कि

विधायिका या प्राधिकरण को शक्ति से वंचित कर दिया गया था मौजूदा कानून में संशोधन करने के लिए, ऐसे मामले में पुरानी कानून

पुनर्जीवित करेंगे और जारी रखेंगे। " 502

560. राज्य में टी. एन. वी. के. श्याम सुंदर 503 दोनों

इस विषय पर मौजूदा विचारों को नोट किया गया है। पैराग्राफ 56 में

प्रभावी रूप से कानून की किताबों से मिटा दिया जाता है और भले ही कानून में संशोधन [निरसन] को असंवैधानिक घोषित किया जाता है

विधानमंडल में विधायी क्षमता की कमी का आधार,

निरस्त कानून पुनर्जीवित नहीं होगा। ऐसा कहा गया था:

"यू. पी. राज्य बनाम हिरेन्द्र पाल सिंह ने इस न्यायालय में कहा:

(एस. सी. सी. पी. 314, पैरा 22)

"22. यह एक तय कानूनी प्रस्ताव है कि जब भी अधिनियम निरस्त कर दिया गया है, यह माना जाना चाहिए जैसे कि यह कभी नहीं था

501 (1985) 1 एस. सी. सी. 641

502 अनुच्छेद 15

503 (2011) 8 एससीसी 737 [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अस्तित्व में था। निरस्त करने का उद्देश्य अधिनियम को समाप्त करना है।

कुछ उद्देश्यों को छोड़कर वैधानिक पुस्तकों से

जैसा कि सामान्य खंडों की धारा 6 के तहत प्रदान किया गया है

अधिनियम, 1897। निरसन केवल रूप की बात नहीं है, बल्कि यह है पदार्थ का। इसलिए, निरस्त करने पर, पूर्ववर्ती

प्रावधान मिट गए/निरस्त/मिट दिए गए हैं

पूर्णतया अर्थात् तत्काल निरस्तीकरण के पक्ष में।

इस प्रकार, निस्संदेह, विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किया गया समर्पण उत्तरदाताओं की ओर से वरिष्ठ वकील ने कहा कि एक बार

अधिनियम निरस्त हो जाता है और संशोधन अधिनियम लागू हो जाता है

बेतुका [बेतुका] है और आगे इसकी आवश्यकता नहीं है विचार करें। यू. पी. राज्य में यही पीठ बनाम हिरेन्द्र

पाल सिंह, बड़ी संख्या में भरोसा रखने के बाद विशेष रूप से अमीर-उन-निसा बेगम में पहले के निर्णय

वी. महबूब बेगम, बी. एन. तिवारी बनाम। भारत संघ, इंडिया टोबैको कंपनी लिमिटेड बनाम सीटीओ, इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र

(बॉम्बे) (पी) लिमिटेड बनाम। भारत संघ, पश्चिम यू. पी. चीनी

मिल्स एसोसिएशन। बी. उत्तर प्रदेश राज्य, जिल सिंह बनाम। हरियाणा राज्य,

केरल राज्य बनाम। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एंड

फर्म ए. टी. बी. मेहताव माजिद एंड कंपनी उसी पर पहुंची

निष्कर्ष "। (आंतरिक उद्धरण हटा दिए गए हैं)

दूसरी ओर, इसका उल्लेख अनुच्छेद 57 में किया गया है।

रिपोर्ट करें कि यदि कोई क़ानून निरस्त किया जाता है और नया क़ानून है इस आधार पर असंवैधानिक घोषित किया गया कि यह उल्लंघन करता है मौलिक अधिकार अध्याय, फिर निरस्त क़ानून पुनर्जीवित होता है।

कहा गया था:

"इस क़ानूनी प्रस्ताव का एक और अंग है, वह है, जहां अधिनियम न्यायालय द्वारा अमान्य होने के कारण निरस्त कर दिया गया है,

के प्रावधानों को देखते हुए मनमानेपन के आधार पर

संविधान का अनुच्छेद 14 या सर्वोच्च न्यायालयों का उल्लंघन करना-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

संविधान के भाग III में निहित मौलिक अधिकार,

इस तरह के अधिनियम को शून्य के रूप में वर्णित किया जा सकता है जिसका अर्थ है

जिससे असंवैधानिक, मृत जन्म या कोई अस्तित्व नहीं है

बिल्कुल भी। ऐसी स्थिति में, वह अधिनियम जो निरस्त हो गया था,

स्वचालित रूप से पुनर्जीवित हो जाता है। (बेहराम खुरशीद को देखें

पेसिकाका और महेंद्र लाल जैनी।) " (आंतरिक उद्धरण

हटा दिया गया)

एक संदेह प्रतीत होता है (यदि एक सूक्ष्म संघर्ष नहीं है)

विचारों का) जिसे इस अर्थ में हल करने की आवश्यकता है कि यदि एक क़ानून

क़ानून की पुस्तकों से निरस्त और मिटा दिया जाता है, जिसके तहत

यदि कुछ भी हो तो परिस्थितियाँ मिट जाती हैं। हालांकि,

इनमें से कोई भी निर्णय संशोधन का कोई संदर्भ नहीं देता है।

संविधान का, और वर्तमान के लिए यह आवश्यक नहीं है कि

उस विवाद में डुबकी लगाएं। इसका सीधा सा कारण यह है कि

इस मुद्दे पर काफी बहस की आवश्यकता है, जिसके बारे में हमारे पास नहीं था

लाभ होता है। न्यायमूर्ति खेहर ने इस मुद्दे पर विस्तार से विचार किया है।

उनके मसौदा निर्णय में, लेकिन मैं इस प्रश्न को उचित अवसर पर बहस के लिए खुला रखना चाहूंगा। 561.
लेकिन, काफी

स्वीकार किया जाता है, फिर इस मामले के तथ्यों पर; परिणाम होगा विनाशकारी। इसका सरल
कारण यह है कि यदि 99 वां संविधान

संशोधन अधिनियम को संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन के रूप में निरस्त कर दिया जाता है और यदि
अनुच्छेद 124 (2) अपने मूल रूप में (99 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा) हटाए गए शब्दों को
घटाकर संविधान के अनुच्छेद 124 (2) को पुनर्जीवित नहीं किया गया और

शून्य से नीचे गिराए गए शब्द (जो 99 वें द्वारा डाले गए हैं)

संविधान संशोधन अधिनियम) निम्नानुसार होगा:

लेख

अनुच्छेद 124 (2)। अनुच्छेद 124 (2) के बाद

99 वें 99 वें के बाद

124 (2)

संविधान

संविधान

जैसा कि था

संशोधन किया गया है

संशोधन

शुरू में

नीचे और मूल

अधिनियम

अनुच्छेद 124 (2) नहीं है

पुनर्जीवित [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(2) प्रत्येक न्यायाधीश

(2) प्रत्येक न्यायाधीश

(2) प्रत्येक
के न्यायाधीश

सर्वोच्च का

सर्वोच्च का

अदालत होगी

सुप्रीम कोर्ट

अदालत होगी

द्वारा नियुक्त

होगा।

द्वारा नियुक्त

राष्ट्रपति द्वारा

राष्ट्रपति द्वारा

द्वारा नियुक्त

राष्ट्रपति

आदेश के तहत

उसके अधीन आदेश

उसका हाथ और

हाथ और मुहर

आदेश द्वारा

परामर्श के बाद

हाथ के नीचे

मोहर लगाएँ और

और उस पर मुहर लगा दें

तब तक पद संभालें

इस तरह के साथ
के न्यायाधीश

/ वह प्राप्त करता है

सिफारिशें

सुप्रीम कोर्ट

साठ-पाँच वर्ष की आयु

के एन

और ऊँचे

राष्ट्रीय

वर्ष:

न्यायालयों में

न्यायिक

नियुक्तियाँ

राज्यों के रूप में

राष्ट्रपति मई

आयोग

आवश्यक समझते हैं।

में संदर्भित

इस उद्देश्य के लिए

अनुच्छेद 124 ए

और रखेंगे।

और रखेंगे।

कार्यालय जब तक वह

कार्यालय जब तक वह

की उम्र हो जाती है

उम्र बढ़ती है।

साठ-पाँच

साठ-पाँच वर्ष:

वर्ष:

562. यह राष्ट्रपति को पूर्ण शक्ति देगा -

भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किए बिना सर्वोच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश की नियुक्ति करना (और उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश की नियुक्ति करना भी)।

अदालत)। उनके निवेदन को स्वीकार करने का परिणाम होगा -

एक अत्याचारी बनाएँ, जैसा कि जेम्स मैडिसन ने इसे फेडरलिस्ट पेपर्स नंबर 47 में रखा है:

"सभी शक्तियों का संचय, विधायी, कार्यपालिका,

और न्यायपालिका, एक ही हाथों में, चाहे एक हो या कुछ, या कई, और क्या वंशानुगत, स्व-नियुक्त, या

ऐच्छिक, न्यायसंगत रूप से बहुत परिभाषा का उच्चारण किया जा सकता है

जुल्म "। सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

563. यह विद्वान महान्यायवादी के सामने रखा गया था और यह

उसे यह भी कहा गया था कि अगर उसकी प्रस्तुतियाँ सही हैं, तो यह भारत संघ के लिए 99 वां होना बेहतर होगा।

संविधान संशोधन अधिनियम निरस्त कर दिया गया ताकि पूर्ण रूप से

राष्ट्रपति में सत्ता रहती है जो उसे साम्राज्य बनाती है। जहाँ तक न्यायाधीशों की नियुक्ति का संबंध है, साम्राज्य में।

विद्वान सॉलिसिटर-जनरल मुस्कुराए लेकिन जाहिर तौर पर नहीं

देने के लिए जवाब दें। अतः यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि संवैधानिक

99 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित प्रावधान

99 वें संविधान की घोषणा पर जीवन में वापस वसंत

संशोधन अधिनियम असंवैधानिक है।

निष्कर्ष

564. बहुत संक्षेप में, डॉ. अम्बेडकर का विचार था कि

राष्ट्रपति के पास कुछ विवेक होना चाहिए लेकिन निरंकुश नहीं होना चाहिए

न्यायाधीशों की नियुक्ति में विवेकाधिकार। दूसरे न्यायाधीश मामला स्वीकार करता है कि राष्ट्रपति को विवेकाधिकार है

मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई सिफारिश को अस्वीकार कर दें

भारत, लेकिन केवल कुछ परिस्थितियों में। यह बंधन था राष्ट्रपति के विवेक पर। हालांकि, 99 वां

संविधान संशोधन अधिनियम और एन. जे. ए. सी. अधिनियम ने राष्ट्रपति के पक्ष बदलने के विवेक को पूरी तरह से छीन लिया है।

एक न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए एक सिफारिश,

राष्ट्रपति के संवैधानिक महत्व को कम करना।

565. डॉ. अम्बेडकर का विचार था कि राष्ट्रपति

भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्ति। राष्ट्रपति थे। द्वितीय न्यायाधीशों के मामले और तृतीय न्यायाधीशों द्वारा प्रस्तुत

द्वारा किए गए परामर्श अभ्यास के परिणाम के साथ मामला

भारत के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे

करने का आदेश दिया। यह इसके अलावा भी है कि राष्ट्रपति

उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करने का हकदार था या

उच्च न्यायालय। हालांकि, 99 वां संविधान संशोधन [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिनियम और एन. जे. ए. सी. अधिनियम ने इस स्वतंत्रता को छीन लिया है

राष्ट्रपति से परामर्श, जिनके पास लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है केवल एन. जे. ए. सी. की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए और नहीं

उससे आगे की यात्रा करें। एक बार फिर, संवैधानिक महत्व

और राष्ट्रपति का महत्व काफी कम हो जाता है, यदि नहीं लिया गया।

566. डॉ. अम्बेडकर प्रत्येक मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश (एक व्यक्ति के रूप में) की सहमति के खिलाफ थे।

न्यायाधीश की नियुक्ति। दूसरे न्यायाधीशों के मामले ने इसे बना दिया

भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए अन्य न्यायाधीशों की राय लेना अनिवार्य है और इसे भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए भी खुला छोड़ दिया है

इस संबंध में न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों से परामर्श करना। राय.

भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय (डॉ. अम्बेडकर की 'इच्छा' के अनुसार) एक व्यक्तिगत राय नहीं रह गई, लेकिन एक सामूहिक राय बन गई।

या संस्थागत राय, बहुत अंतर है दोनों के बीच। हालाँकि, 99 वां संविधान संशोधन

अधिनियम और एन. जे. ए. सी. अधिनियम काफी सीमित और कम किए गए हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश का अधिकार (दोनों व्यक्तिगत रूप से साथ ही संस्थागत रूप से) और भारत के मुख्य न्यायाधीश अब हैं

अन्य न्यायाधीशों या किसी की राय लेने से वर्जित एन. जे. ए. सी. के बाहर व्यक्ति। भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं

एक संस्थागत प्रमुख से एक व्यक्तिगत व्यक्ति तक घटाया गया।

567. डॉ. अम्बेडकर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे

भारत के मुख्य न्यायाधीश (एक व्यक्ति के रूप में) की राय

न्यायाधीशों की नियुक्ति में अंतिम शब्द। ऐसा इसलिए है क्योंकि

भारत के मुख्य न्यायाधीश में हम सभी की तरह कमजोरियां हैं। द.

डॉ. अम्बेडकर की आशंका को दूसरे द्वारा दूर कर दिया गया था

न्यायाधीशों का मामला और तीसरा न्यायाधीशों का मामला जिसने इसे बना दिया

भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए सामूहिक अभिव्यक्ति अनिवार्य है राय और व्यक्तिगत राय नहीं। सामूहिक और

सर्वसम्मत राय (यदि आवश्यक हो तो विधिवत दोहराई गई) बाध्यकारी होगी।

राष्ट्रपति की सामूहिक और सर्वसम्मत राय है

ऐसे व्यक्ति जो पूर्व परिकल्पना में उचित सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता देने के लिए अच्छी तरह से योग्य थे-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [मदन बी. लोकुर, जे.]

इस तरह के मामलों में सलाह। 'हालाँकि, 99 वां संविधान संशोधन अधिनियम और एन. जे. ए. सी. अधिनियम ने प्रक्रिया को अच्छी तरह से उलट दिया दूसरे न्यायाधीशों और तीसरे न्यायाधीशों के मामले में विचार किया गया मामला और के संवैधानिक अधिकार छीन लिया है भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इसे एन. जे. ए. सी. के लिए एक थाली में रखा शोषण करें।

568. हमारे संवैधानिक इतिहास को देखते हुए, स्थापित

सम्मेलनों, पिछले समय में विभिन्न समितियों के विचार सत्तर वर्ष और कई कानूनी दिग्गजों के विचार

श्री मोतीलाल सीतलवाड़ से शुरुआत करते हुए, न्यायपालिका कई दशकों से जिस दौर से गुजरी है और हमारे संविधान के प्रावधान, मेरा मानना है कि अनुच्छेद 124 ए के रूप में

संविधान द्वारा संविधान में प्रस्तुत किया गया (नब्बे-नौवां) संशोधन) अधिनियम, 2014 स्वतंत्रता को बाधित करता है

न्यायपालिका और न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में (जो है

की स्वतंत्रता का एक मूलभूत और अभिन्न अंग

न्यायपालिका) और संविधान की मूल संरचना को बदल देती है। यह है।

तदनुसार असंवैधानिक घोषित किया गया। के अन्य प्रावधान

संविधान (नब्बे-नौवां संशोधन) अधिनियम, 2014 ऐसा नहीं कर सकता है

स्वयं खड़े रहें और इसलिए भी घोषित किए जाते हैं

आयोग अधिनियम, 2014 मनमाना और अपरिवर्तित है कानून के तहत विभिन्न प्राधिकरणों पर शक्तियाँ और यह उल्लंघन करता है

संविधान का अनुच्छेद 14 असंवैधानिक घोषित किया गया है।

अन्यथा भी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियाँ

आयोग अधिनियम, 2014 इसके अभाव में अकेला नहीं रह सकता है -

संविधान (नब्बे-नौवां संशोधन) अधिनियम, 2014।

569. इस घोषणा का परिणाम यह है कि कॉलेजियम

प्रणाली 'दूसरे न्यायाधीशों के मामले और तीसरे द्वारा अभिनिर्धारित को पुनर्जीवित किया जाता है। हालांकि, प्रक्रिया के लिए

न्यायाधीशों के मामले

इन निर्णयों में निर्धारित न्यायाधीशों की नियुक्ति पढ़ें

(संशोधित) प्रक्रिया ज्ञापन के साथ निश्चित रूप से आवश्यकताएँ न्यायालय की करीबी रिपोर्टों पर विद्वान वकील से अनुरोध किया था

बढ़िया ट्यूनिंग। हमने उच्च

[2015] 13 एस सी आर।

प्रस्तुतियों का, इस आधार पर सुझाव देना कि

याचिकाएँ खारिज की जाती हैं और इस आधार पर कि याचिकाएँ हैं हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, या सबसे अच्छा ए

अनुमति दी गई। दुर्भाग्य से,

नीरस प्रतिक्रिया। इन परिस्थितियों में, मेरी राय में, सुनवाई' की आवश्यकता है

हमें इसमें सहायता करने के लिए एक 'परिणाम

इसे सुव्यवस्थित करने के लिए भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों का मामला

न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया और प्रक्रिया, इसे बनाने के लिए

लोगों की जरूरतों के प्रति अधिक उत्तरदायी, इसे और अधिक बनाने के लिए

पारदर्शी और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप, और अधिक के मामले से बचने के लिए! इसलिए मैं,

विशेष रूप से, पांचवें न्यायाधीश

याचिकाओं को अनुमति दें लेकिन उन्हें 'परिणाम सुनवाई' के लिए सूचीबद्ध करें।

एक उपयुक्त तिथि।

आदेश

कुरियन, जे. 1. मैं अपने विचार से पूरी तरह सहमत हूँ।

सम्मानित भाई जे. चेलमेश्वर ने कहा कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है।

इस मामले में न्यायमूर्ति खेहर को अलग करने का आदेश। अब, कि

हमें एक विस्तृत और तर्कपूर्ण आदेश पारित करना होगा कि क्यों

न्यायाधीश को किसी मामले से अलग होने की आवश्यकता नहीं है, मुझे लगता है कि यह उचित भी है सिद्धे के दूसरे पक्ष से निपटने के लिए, क्या किसी न्यायाधीश को ऐसा करना चाहिए किसी विशेष मामले में उनके अलग होने के कारण बताएँ।

2. न्यायाधीश के अलग होने का एक कारण यह है कि वादियों/जनता को एक उचित आशंका हो सकती है उसकी निष्पक्षता के बारे में। जैसा कि लॉर्ड चीफ जस्टिस हेवर्ट ने कहा:

"यह केवल कुछ महत्व का नहीं है, बल्कि मौलिक है।

यह महत्वपूर्ण है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि

इसे स्पष्ट रूप से और निस्संदेह किया जाता देखा जाना चाहिए।¹ और इसलिए, की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए

सत्यनिष्ठा संस्थान, न्यायाधीश मामले की सुनवाई से अलग हो जाता है।

3. उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, जबकि

पद ग्रहण करते हुए, अनुसूची के तहत निर्धारित शपथ लेते हैं भारत के संविधान के लिए बुरा, कि:

1 आर. वी. ससेक्स जस्टिस, एक्स पार्टी मैकार्थी, [1924] 1 केबी 256, [1923] ऑल ईआर रेप।

233 सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [कुरियन, जे.]

"..... मैं संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और निष्ठा रखूंगा। भारत के कानून द्वारा स्थापित, कि मैं बनाए रखूंगा

भारत की संप्रभुता और अखंडता, कि मैं विधिवत और

ईमानदारी से और मेरी क्षमता के अनुसार, ज्ञान और निर्णय बिना किसी डर या भय के मेरे कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करते हैं।

अनुग्रह, स्नेह या दुर्भावना और मैं इसे बनाए रखूंगा

संविधान और कानून "।

4. कार्यालय के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए बुलाया गया

भय या अनुग्रह, स्नेह या दुर्भावना के बिना, यह केवल वांछनीय है, यदि

उचित नहीं है, कि एक न्यायाधीश, किसी भी अपरिहार्य कारण के लिए जैसे कुछ

में पक्षों के साथ आर्थिक हित, आत्मीयता या प्रतिकूलता

मुकदमे के परिणाम में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित, परिवार सीधे तौर पर उसी मुद्दे पर मुकदमेबाजी में कहीं और शामिल है, न्यायाधीश को पता है कि वह या उसका कोई व्यक्ति

तत्काल परिवार का कोई ब्याज, वित्तीय या अन्यथा होता है जिसका इसके परिणामस्वरूप पर्याप्त प्रभाव पड़ सकता है

मुकदमेबाजी आदि में खुद को इससे अलग करने का निर्णय किसी विशेष मामले का निर्णय। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये उदाहरण

पूर्ण नहीं हैं।

5. न्यायाधीशों के नैतिक आचरण पर दिशा-निर्देश थे

1999 में आयोजित मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में तैयार किया गया

"न्यायिक जीवन के न्यायिक मूल्यों का पुनर्कथन" के रूप में जाना जाता है।

उन सिद्धांतों ने, वास्तव में, आधार बनाया " बैंगलोर न्यायिक आचरण के सिद्धांत, 2002 "तैयार किए गए

शांति में आयोजित मुख्य न्यायाधीशों की गोलमेज बैठक में

पैलेस, द हेग। प्रस्तावना से यह देखा जाता है कि प्रारूपण समिति ने बत्तीस ऐसे विषयों पर विचार किया था

भारत सहित दुनिया भर में बयान। मान 2 "निष्पक्षता" पर, इसे निम्नानुसार हल किया जाता है:

"सिद्धांतः

न्यायिक पद के उचित निर्वहन के लिए निष्पक्षता आवश्यक है। यह न केवल निर्णय पर लागू होता है बल्कि सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट पर भी लागू होता है।

[2015] 13 एस सी आर।

उस प्रक्रिया के लिए भी जिसके द्वारा निर्णय लिया जाता है।

आवेदनः

2.1 अजुदगे अपने न्यायिक कर्तव्यों का निर्वहन इसके बिना करेगा।

पक्षपात, पक्षपात या पूर्वाग्रह।

2.2 अजुदगे यह सुनिश्चित करेगा कि उसका आचरण, दोनों में

और अदालत के बाहर, जनता, कानूनी पेशे के विश्वास को बनाए रखता है और बढ़ाता है और न्यायाधीश और न्यायाधीश की निष्पक्षता में वादी

न्यायपालिका।

2.3 एक न्यायाधीश, जहाँ तक उचित है, इस प्रकार आचरण करेगा।

स्वयं अवसरों को कम करने के लिए

जो न्यायाधीश के लिए आवश्यक होगा

मामलों की सुनवाई या निर्णय लेने के लिए अयोग्य।

2.4 एक न्यायाधीश जानबूझकर नहीं करेगा, जबकि एक कार्यवाही है

न्यायाधीश के आने से पहले या आने से पहले

ऐसी टिप्पणी जो यथोचित रूप से प्रभावित होने की उम्मीद की जा सकती है

ऐसी कार्यवाही का परिणाम या प्रकटीकरण को बाधित करना

प्रक्रिया की निष्पक्षता। न ही न्यायाधीश कोई आदेश देगा।

सार्वजनिक रूप से या अन्यथा टिप्पणी करें जो प्रभावित कर सकती है

किसी भी व्यक्ति या मुद्दे का निष्पक्ष परीक्षण।

2.5 एक न्यायाधीश स्वयं को अयोग्य ठहराएगा।

एक उचित पर्यवेक्षक को यह प्रतीत हो सकता है कि न्यायाधीश मामले को निष्पक्ष रूप से तय करने में असमर्थ है। इस तरह कार्यवाहियों में उदाहरण शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

कहाँ

2.5. 1 न्यायाधीश के संबंध में वास्तविक पूर्वाग्रह या पूर्वाग्रह है

विवादित विषय का एक पक्ष या व्यक्तिगत ज्ञान

कार्यवाहियों से संबंधित साक्ष्य संबंधी तथ्य; सर्वोच्च अदालतें-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. /कुरियन, जे./

2.5. 2 न्यायाधीश ने पहले एक वकील के रूप में कार्य किया या था

विवाद में मामले में एक भौतिक गवाह; या

2.5. 3 न्यायाधीश, या न्यायाधीश के परिवार का कोई सदस्य,

के परिणाम में एक आर्थिक हित है

विवाद का विषय:

बशर्ते कि किसी न्यायाधीश की अयोग्यता नहीं होगी
यदि सौदा करने के लिए कोई अन्य न्यायाधिकरण गठित नहीं किया जा सकता है तो इसकी आवश्यकता है
मामले के साथ या, तत्काल परिस्थितियों के कारण, विफलता
कार्रवाई करने से न्याय की गंभीर विफलता हो सकती है। "

6. सरल प्रश्न यह है कि क्या निर्णय

संबंधित न्यायाधीश, में एक उचित संदेह पैदा करेगा

उसकी निष्पक्षता के बारे में एक उचित रूप से सूचित वादी और निष्पक्ष जनता का मन। एक ऐसी संस्था
होने के नाते जिसकी पहचान है

पारदर्शिता, यह केवल उचित है कि न्यायाधीश उच्च निर्वहन करे

और महान कर्तव्य, कम से कम व्यापक रूप से कारणों को इंगित करते हैं
ताकि वादी या कुआँ-अर्थ

मामले से अलग होना

जनता किसी भी गलतफहमी को स्वीकार नहीं कर सकती है कि

पूरी तरह से अप्रासंगिक कारणों से थे जैसे कि मामले बहुत अधिक थे

पुराना, जिसमें विस्तृत विचार शामिल है, कई पर निर्णय

कानून के प्रश्न, एक ऐसी स्थिति जहाँ न्यायाधीश खुश नहीं है

रोस्टर, एक न्यायाधीश जनता के बारे में अनुचित रूप से संवेदनशील हो रहा है

उसकी छवि की धारणा, न्यायाधीश कारण नहीं बनाना चाहते हैं
हमेशा निर्णय नहीं लेना चाहते

किसी से भी नाखुशी, न्यायाधीश

अलग होने का संकेत दिया गया है, इसके लिए कोई जगह नहीं होगी
कारण। इसे अलग तरह से रखने के लिए, यह उसका हिस्सा है

अलग होने का कोई भी

संविधान को बनाए रखते हुए उसके प्रति जवाबदेह होने का कर्तव्य

बिना किसी भय या अनुग्रह, स्नेह या दुर्भावना के। इसलिए मैं

यह देखते हुए कि यह संवैधानिक कर्तव्य है, जैसा कि किसी की शपथ में परिलक्षित होता है,

पारदर्शी और जवाबदेह होना, और इसलिए, एक न्यायाधीश है

किसी विशेष पद से उसके अलग होने के कारणों को इंगित करने की आवश्यकता मामला। इससे मंच पर खरीदारी करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7. जिले के सार्वजनिक उपयोगिता आयोग में

कोलंबिया एट अल। वी. पोलक एट अल। 2, संयुक्त राज्य का सर्वोच्च न्यायालय

राज्यों ने एक सवाल से निपटा कि क्या कोलंबिया जिले में,

संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान एक सड़क रेलवे को प्रतिबंधित करता है

कंपनी अपने यात्री वाहनों में लाउडस्पीकरों के माध्यम से रेडियो कार्यक्रमों को प्राप्त करने और बढ़ाने से।
न्याय

फ्रैंकफर्टर हमेशा इस अभ्यास के खिलाफ थे और वे

यह दृष्टिकोण कि यह उचित नहीं है। उनका व्यक्तिगत दर्शन और उनका

जाहिरा तौर पर रास्ते पर खड़े लोगों को पता था।

अन्यथा भी, वह अपनी मजबूत स्थिति के बारे में आश्वस्त था

यह मुद्दा। इसलिए, ऐसा कहते हुए, उन्होंने भाग लेने से इनकार कर दिया

मामले में। उनके शब्दों को उद्धृत करने के लिए,

"न्यायिक प्रक्रिया की मांग है कि एक न्यायाधीश भीतर चले

प्रासंगिक कानूनी नियमों और वाचा की रूपरेखा

निष्पक्ष रूप से और हर किसी पर निजी भावना को डुबो दें
एक मामले का पहलू। उथली बातचीत का एक अच्छा सौदा है

कि न्यायिक वस्त्र अपने भीतर के व्यक्ति को नहीं बदलता है।

प्रशिक्षण, पेशेवर आदतों, स्वयं के माध्यम से प्राप्त किया जाता है
अनुशासन और वह भाग्यशाली कीमिया जिसके द्वारा पुरुष होते हैं

जिस दायित्व के साथ उन्हें सौंपा गया है, उसके प्रति वफादार रहें। लेकिन

यह भी सच है कि कारण अवचेतन को नियंत्रित नहीं कर सकता है।

यह विश्वास करने के लिए आधार है कि ऐसी अचेतन भावनाएँ अंतिम निर्णय में काम कर सकता है, या दूसरों को यह विश्वास करने के लिए अनुचित रूप से प्रेरित नहीं कर सकता है कि वे काम कर रहे हैं, न्यायाधीश अलग हो जाते हैं

स्वयं। वे निर्णय में नहीं बैठते हैं। वे ऐसा करते हैं।

विभिन्न कारणों से। मार्गदर्शक विचार यह है कि न्याय का प्रशासन उचित रूप से होना चाहिए।

निस्वार्थ प्रतीत होता है और वास्तव में भी ऐसा ही है।

2 343 यू. एस. 451 (1952)

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [कुरियन, जे.]

यह मामला मेरे लिए ऐसी स्थिति प्रस्तुत करता है। मेरी भावनाएँ अभ्यास के शिकार के रूप में इतनी दृढ़ता से लगे हुए हैं

विवाद कि बेहतर होगा कि मैं न्यायिक कार्य में भाग न लूं

उस पर निर्णय लें। मैं अपने कारण के बारे में स्पष्ट हूँ

इस मामले में गैर-भागीदारी क्योंकि मेरे पास कुछ हैं

समय का विचार था कि यह बताना वांछनीय है कि एक क्यों खुद को एक मामले से बाहर निकाल लेता है। "

8. एस. पार्थसारथी बनाम में न्यायमूर्ति मैथ्यू के अनुसार।

ए. पी. 3 की स्थिति, यदि सही दिमाग वाले व्यक्ति एक

यह महसूस करना कि पक्ष में पूर्वाग्रह की कोई संभावना है

जज, उसे अलग होना चाहिए। इस तरह की भावना की केवल संभावना है

पर्याप्त नहीं है। ऐसी परिस्थितियाँ होनी चाहिए जहाँ

समझदार और निष्पक्ष दिमाग वाला व्यक्ति शायद ऐसा सोचेगा या वादी के खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रस्त होगा। को।

संभावना है कि न्यायाधीश एक

उद्धरण:

" "वास्तविक संभावना" और "उचित संदेह" के परीक्षण वास्तव में एक दूसरे के साथ असंगत हैं। हम सोचते हैं कि समीक्षा प्राधिकरण को इस पर निर्णय लेना चाहिए

उसके समक्ष संपूर्ण साक्ष्य का आधार, क्या

समझदार व्यक्ति परिस्थितियों में यह अनुमान लगाएगा कि पक्षपात की वास्तविक संभावना है। अदालत को देखना चाहिए प्रभाव जो अन्य लोगों के पास है। यह इस प्रकार है

इस सिद्धांत से कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि किया जाता है। यदि सही दिमाग वाले व्यक्ति सोचेंगे कि एक पक्ष की ओर से पूर्वाग्रह की वास्तविक संभावना है

जाँच अधिकारी, उसे जाँच नहीं करनी चाहिए; फिर भी, पक्षपात की वास्तविक संभावना होनी चाहिए।

अनुमान या अनुमान पर्याप्त नहीं होंगे। वहाँ होना चाहिए।

ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिनसे समझदार लोग

सोचिए कि यह संभावित या संभावित है कि जाँच अधिकारी होगा

अपराधी के खिलाफ पूर्वाग्रह। अदालत नहीं करेगी

पूछिए कि क्या वह वास्तव में पूर्वाग्रह से ग्रस्त था। यदि उचित हो।

3 (1974) 3 एस. सी. सी. 459 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

आदमी मौजूदा के आधार पर सोचेगा

ऐसी परिस्थितियाँ जिनमें उसके पूर्वाग्रही होने की संभावना है, अर्थात् निर्णय को रद्द करने के लिए पर्याप्त [लॉर्ड डेनिंग के अनुसार देखें,

एच. आर. इन (मेट्रोपॉलिटन प्रॉपर्टीज कं. (एफ. जी. सी.) लिमिटेड वी.

लैनन और अन्य, आदि [(1968) 3 डब्ल्यू. एल. आर. 694 707 पर]]।

हालाँकि, हमें इस बात से इनकार नहीं करना चाहिए कि

न्यायालय अधिक औचित्य के साथ "उचित" को लागू कर सकता है।

संदेह "आपराधिक या आपराधिक कार्यवाही के अनुरूप कार्यवाही में परीक्षण"।

9. ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ शरारती

एक न्यायाधीश से बचने की इच्छा रखने वाले वादी हो सकते हैं क्योंकि वह ज्ञात है

उन्हें बहुत मजबूत होने के लिए और इस प्रकार मंच के लिए प्रयास करना

ब्याज। दक्षिण अफ्रीका के संवैधानिक न्यायालय में दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के राष्ट्रपति आदि।
दक्षिण

अफ्रीकी रग्बी फुटबॉल संघ आदि। 4, इस संबंध में दो बहुत ही प्रासंगिक टिप्पणियां की गई हैं:

"हालाँकि यह महत्वपूर्ण है कि न्याय को देखा जाना चाहिए

किया, यह समान रूप से महत्वपूर्ण है कि न्यायिक अधिकारी बैठने के अपने कर्तव्य का निर्वहन करें और न करें, बहुत आसानी से स्वीकार करके पक्षपात की उपस्थिति के सुझाव, पक्षों को यह विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि एक न्यायाधीश की अयोग्यता की मांग करके,

वे अपने मामले की सुनवाई किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कराएंगे जिसके बारे में सोचा गया हो

उनके पक्ष में मामले का फैसला करने की अधिक संभावना है।
"यह जोर से और स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए कि

अयोग्यता एक उचित आशंका है कि

न्यायिक अधिकारी मामले का फैसला निष्पक्षता से नहीं करेगा या

पूर्वाग्रह के बिना, इसके बजाय कि वह मामले का फैसला करेगा

एक पक्ष के लिए प्रतिकूल "।

10. आखिरकार, सवाल यह है कि क्या एक निष्पक्ष दिमाग और

उचित रूप से सूचित व्यक्ति, सही तथ्यों पर,

न्यायाधीश की निष्पक्षता पर संदेह को उचित रूप से स्वीकार करें।

4 1999 (4) एसए 147।

सर्वोच्च अदालतें-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [कुरियन, जे.]

आशंका की तर्कसंगतता का आकलन किया जाना चाहिए ए

अपने प्रशिक्षण और अनुभव के कारण शपथ लेने की क्षमता जिसके कारण वह अपने दिमाग को निष्क्रिय करने की स्थिति में है किसी भी अप्रासंगिक व्यक्तिगत विश्वास या पूर्व-स्वभाव का या

सार्वजनिक रूप से उनकी छवि के बारे में अनुचित आशंका या कठिनाई

किसी विवादास्पद मुद्दे पर निर्णय लेने में, विशेष रूप से जब वह अत्यधिक संवेदनशील हो।

11. इन मुद्दों पर संक्षिप्त चर्चा की गई है

गणराज्य के राष्ट्रपति में संवैधानिक न्यायालय
दक्षिण अफ्रीका (ऊपर), के चार अलग करने के लिए एक आवेदन पर
संवैधानिक न्यायालय में न्यायाधीश। विस्तार से बताने के बाद
तथ्यात्मक मैट्रिक्स के साथ-साथ कानूनी स्थिति पर विचार करते हुए, न्यायालय ने इस प्रकार
अभिनिर्धारित किया:

"जबकि वादियों को अलग होने के लिए आवेदन करने का अधिकार है
न्यायिक अधिकारी जहाँ उचित हो।

आशंका है कि वे किसी मामले का निष्पक्षता से फैसला नहीं करेंगे,

यह उन्हें अपने मामलों पर आपत्ति करने का अधिकार नहीं देता है।

विशेष न्यायिक अधिकारियों द्वारा केवल इसलिए सुना जा रहा है क्योंकि

उनका मानना है कि ऐसे व्यक्तियों के निर्णय लेने की संभावना कम होगी

अन्य न्यायिक अधिकारियों की तुलना में उनके पक्ष में मामला

समाज के एक अलग वर्ग से लिया गया। की प्रकृति
न्यायिक कार्य में कठिन एफ का प्रदर्शन शामिल है

और कभी-कभी अप्रिय कार्य। न्यायिक अधिकारी हैं
फिर भी सभी व्यक्तियों को न्याय देने की आवश्यकता है

बिना किसी भय, पक्षपात या पक्षपात के,

संविधान और कानून "। इसके लिए उन्हें विरोध करना होगा।

हर तरह का दबाव, चाहे वह कहीं से भी आए।

यह सभी न्यायिक संस्थाओं के लिए एक समान संवैधानिक कर्तव्य है।

अधिकारी। यदि वे विचलित होते हैं, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता

इसे कमजोर किया जाएगा, और बदले में, संविधान को ही। "

(जोर दिया गया)

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12. उपरोक्त सिद्धांत अनुप्रयोग में सार्वभौमिक हैं।

एक न्यायाधीश की निष्पक्षता सत्यनिष्ठा के लिए अनिवार्य है।

संस्था। प्रक्रिया में पारदर्शिता प्रमुख बातों में से एक है

न्यायाधीश के पद की अखंडता का गठन करने वाले कारक

अपने कर्तव्यों और न्यायालय के कामकाज का संचालन करना। द.

वादी हमेशा जानना चाहेंगे हालांकि उनके पास एक नहीं हो सकता है

यह जानने का निर्धारित अधिकार कि न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई से क्यों अलग हो गया है या अनुरोध के बावजूद सुनवाई से क्यों अलग नहीं हुआ है

उसका मामला। कारणों को व्यापक रूप से इंगित करने की आवश्यकता है। में से

बेशक, यदि कारणों का खुलासा प्रभावित करने की संभावना है

प्रतिकूल रूप से किसी और का कोई मामला या कारण या हित,

न्यायाधीश यह कहने के लिए स्वतंत्र है कि व्यक्तिगत कारणों से

जिसका न्यायाधीश खुलासा नहीं करना चाहते हैं, उन्होंने फैसला किया है कि

मामले की सुनवाई से खुद को अलग करें।

न्याय

कुरियन, जे. 1. एंटिया नॉन सन्ट मल्टीप्लिकैंडा साइन

आवश्यकता (बिना चीजों के गुणा नहीं किया जाना चाहिए) मेरे दिमाग में आया

आवश्यकता)। यह पहला विचार है जो

मेरे कुलीन भाइयों द्वारा लिखे गए निर्णयों को पढ़ने के बाद

खेहर, चेलमेश्वर, लोकुर और गोयल, जेजे। , पूरी तरह से

विषय से निपटना। इस मुद्दे के पूरे सरगम को संदर्भित करने के बाद सभी संभावित कोणों से निपटा गया है।

व्यापक रूप से पूर्ववर्ती, शैक्षणिक प्रवचनों और

विभिन्न अन्य देशों के निर्णय। हालांकि मैं ऐसा नहीं कर सकता।

विनम्रता, ऐसी उत्कृष्ट कृतियों के स्तर से मेल खाने का दावा, यह एक है

तथ्य यह है कि मैंने भी अपने निर्णय का मसौदा तैयार किया था। तथापि, अनावश्यक गुणा पर ऊपर प्रतिपादित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, I

मैंने जो किया है उसके बड़े हिस्से को पूर्ववत करने का फैसला किया, इसके लिए भी है कि इस पीठ के फैसले पर आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए

कारण यह

भारती के भाग्य (परम पूज्य केशवानंद भारती) श्रीपदगलवरु बनाम। केरल राज्य और एक अन्य राज्य की हमेशा इस कारण से आलोचना की गई है।)

1 (1973) 4 एस. सी. सी. 225 सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [कुरियन, जे.]

2. सभी कानूनी शब्दावली को छोड़कर और ए की भाषा का उपयोग करना।

आम आदमी, हमारे सामने मुख्य मुद्दा इसकी वैधता है

संविधान का 99 वां संशोधन। इसका परीक्षण किया जाना है मूल संरचना के सिद्धांत की कसौटी।
संशोधन

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक नई संवैधानिक योजना शुरू की है। बी के दौरान

संविधान के कार्यकरण का पहला चरण, कार्यपालिका

नियुक्ति में ऊपरी हाथ का दावा किया और मुख्य न्यायाधीश भारत के या संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश

केवल 'परामर्श' लिया जाना था, अभिव्यक्ति को अक्सर समझा जाता था

अपने शाब्दिक अर्थ में। दूसरे शब्दों में, निर्णय द्वारा लिया गया था

मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी के साथ कार्यपालिका। यह प्रक्रिया एक प्रसिद्ध निर्णय में जांच के लिए गिर गई

समशेर सिंह बनाम में यह न्यायालय। पंजाब राज्य और

अन्य 2.

3. समशेर सिंह मामले (ऊपर) में, एक सात-न्यायाधीश

इस न्यायालय की पीठ, स्पष्ट शब्दों में, अनुच्छेद में अभिनिर्धारित की गई

149 इस प्रकार है:

" 149. न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो एक संविधान का मूल सिद्धांत और उस पर भरोसा किया गया है

विचलन को उचित ठहराने के लिए, संबंधित लेख द्वारा संरक्षित है भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करना

अनिवार्य। सभी संभावित मामलों में इसके साथ परामर्श करें।
 भारतीय न्याय की सर्वोच्च गरिमा होगी और होनी चाहिए
 भारत सरकार और न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाएगा
 जाँचने का अवसर है कि क्या कोई अन्य बाहरी है
 परिस्थितियों ने निर्णय में प्रवेश किया है
 मंत्री, यदि वह प्रमुख द्वारा दी गई सलाह से अलग हो जाता है
 भारत का न्याय। व्यवहार में इस तरह के एक संवेदनशील में अंतिम शब्द
 विषय भारत के मुख्य न्यायाधीश का होना चाहिए,
 उनकी सलाह की अस्वीकृति को आम तौर पर माना जाता है
 आदेश को दूषित करने वाले तिरछे विचारों से प्रेरित।

2 (1974) 2 एस. सी. सी. 831 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

इस दृष्टिकोण से यह मायने नहीं रखता कि राष्ट्रपति या
 प्रधानमंत्री या न्याय मंत्री औपचारिक रूप से निर्णय लेते हैं

मुद्दा "।

(जोर दिया गया)

4. यह सिद्धांत, सात न्यायाधीशों की एक पीठ द्वारा तय किया गया,
 न्यायपीठ द्वारा बाध्यकारी के रूप में लिया जाना चाहिए था
 प्रथम न्यायाधीशों का मामला जिसमें केवल सात का कोरम था।
 दुर्भाग्य से, यह अन्यथा रहा, हालांकि चार के बहुमत के साथ।
 तीन के खिलाफ। आश्चर्यजनक रूप से, प्रथम न्यायाधीशों में पीठासीन न्यायाधीश
 मामला और बहुमत के दृष्टिकोण के लेखक, एक सदस्य थे जो
 समशेर सिंह मामले में बहुमत के साथ सहमति (ऊपर)
 और फिर भी उस फैसले का कोई संदर्भ भी नहीं था

निर्णय का नेतृत्व करें! क्या कोई उचित विज्ञापन था होता

समशेर सिंह मामला (ऊपर), शायद नहीं

दूसरे न्यायाधीशों के मामले के लिए कोई आवश्यकता थी।

5. ऐसा प्रतीत होता है, गलत पर बेचैनी

संवैधानिक संरचना और स्थिति की व्याख्या

सुपर वॉइस के साथ नियुक्तियों के मामले में न्यायपालिका

कार्यपालिका, जैसा कि प्रथम न्यायाधीशों के मामले में समर्थित है, कहा जाता है
मामले की ओर ले जाने वाले गंभीर पुनरीक्षण के लिए।

दूसरे न्यायाधीशों के

निर्णय के अनुच्छेद 85 में पर्याप्त संदर्भ दिया गया है -

पृष्ठभूमि। उद्धृत करने के लिए:

"85. अफसोस की बात है कि कुछ जटिल समस्याएं हैं जिनका समाधान नहीं किया जा सकता।

उम्मीदवारों के चयन का प्रारंभिक चरण
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जो

वर्तमान अस्वस्थता। इसलिए यह अपरिहार्य हो गया है कि
सुधार या पुनर्प्राप्ति के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे।

स्थिति। इन समस्याओं पर ध्यान देने के बाद और

विनाशकारी परिणामों को महसूस करना जो प्रवाहित हो सकते हैं,

कोई मूक दर्शक या पुराना उत्साही नहीं हो सकता।

आशावादी, दूसरे संवैधानिक को देखते हुए

पदाधिकारी, विशेष रूप से कार्यपालक, उच्च न्यायालयों-चालू-रिकॉर्ड संगठन v.

यू. ओ. आई. [कुरियन, जे.]

न्याय करने के लिए प्रेरक समाधान प्राप्त करना

अनुभव शो, कभी सफल नहीं हुए हैं।
इसलिए, ऐसी तीखी स्थिति का सामना करते हुए, यह

हमारे लिए इन समस्याओं को अपने भीतर हल करना अनिवार्य हो जाता है

विभिन्न की व्याख्या करके संवैधानिक ताना-बाना

कार्यप्रणाली से संबंधित संविधान के प्रावधान
न्यायपालिका के अक्षर और भावना के प्रकाश में
संविधान "।

(जोर दिया गया)

6. दूसरे न्यायाधीशों के मामले में नौ-न्यायाधीशों की पीठ
विस्तृत विश्लेषण के बाद प्रथम न्यायाधीशों के मामले को खारिज कर दिया गया
के अक्षर और भावना के प्रकाश में प्रासंगिक प्रावधानों का
संविधान ' , न्यायाधीशों की उस नियुक्ति को अभिनिर्धारित करते हुए
उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय एक अभिन्न अंग हैं -
न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की वह स्वतंत्रता
भारत के संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, और
इसलिए, कार्यपालिका की प्रधानता में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है
नियुक्तियों के मामले में न्यायपालिका। तीसरे न्यायाधीशों का मामला,
दूसरे न्यायाधीशों के मामले में सिद्धांतों को संस्थागत बनाकर नियुक्ति की प्रक्रिया, कॉलेजियम की
शुरुआत।

7. इस प्रकार, न्यायपालिका की संरचनात्मक सर्वोच्चता
संवैधानिक रूप से आवंटित क्षेत्र को द्वितीय द्वारा बहाल किया गया था
और तीसरे न्यायाधीश के मामले।

8. जाहिरा तौर पर, कुछ कथित रूप से अयोग्य लोगों के कारण
नियुक्तियाँ, जिन्होंने वास्तव में न्यायपालिका की छवि को प्रभावित किया,
राजनीतिक कार्यपालिका ने एक नया अभियान शुरू किया
नियुक्ति की प्रक्रिया पर पुनर्विचार। यह था।
दावा किया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करने वाली न्यायाधीशों की प्रणाली है
संविधान की भावना में नहीं, और इसलिए, पूरे
प्रक्रिया के लिए संरचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता होती है, और इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

संविधान 99 वां संशोधन जिसके द्वारा चयन को एक
तीसरा निकाय, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग
(एनजेएसी)। संसद ने राष्ट्रीय न्यायिक विधेयक को भी पारित किया
नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014, जो केवल एक रचना है
संविधान का 99 वां संशोधन। अधिनियम की वैधता भी है चुनौती के तहत।

9. 'इसमें बड़ी बात क्या है?', अक्सर बनाया गया है

मेरे सम्मानित भाई जे. खेहर का अवलोकन, अध्यक्ष
गर्मियों के दौरान एक असामान्य दो सप्ताह लंबे समय तक बैठना शामिल था तीन अलग-अलग
न्यायालयों में सुनवाई के साथ अवकाश।, अदालत

नं. 3, 4 और 6. जब यह आयोजित किया जाता है, और सही है, कि कोई नहीं है
द्वितीय न्यायाधीशों के मामले पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता,
मामले के भाग्य को सील कर दिया गया है; आगे की कोई आवश्यकता नहीं है
सौदा, बड़ा या छोटा। हालांकि मैं आम तौर पर विश्लेषण से सहमत हूँ।

और चर्चा के मामले में कानून का बयान और

पुनरीक्षण पर सिद्धांतों का सारांश

लोकुर, जे. द्वारा पैराग्राफ 263 में दिए गए निर्णयों में, मैं दसवें के रूप में एक और निर्णय जोड़ना चाहूंगा। एक
बार इस न्यायालय ने संबोधित किया है

की संरचना के रूप में कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर एक मुद्दा

संविधान और कानून निर्धारित किया है, पुनर्विचार के लिए एक अनुरोध

इसका तब तक स्वागत नहीं किया जाएगा जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि संरचनात्मक व्याख्या
स्पष्ट रूप से गलत है। हमसे पहले कोई भी धुंधला नहीं कर सकता था

न्यायाधीशों की नियुक्ति की योजना और संविधान में इसके ठोस संरचनात्मक आधार पर ग्राफिक चित्र
द्वितीय न्यायाधीशों का मामला। यह बेंच अनुपात से बंधी है

कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता मूल संरचना का हिस्सा है

संविधान और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति

न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय इस अवधारणा का एक अभिन्न अंग हैं।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और उस सरल कारण के लिए,
 संविधान का 99 वां संशोधन घोषित किया जाना तय है
 असंवैधानिक है और मैं ऐसा करता हूँ। अतः मैं इस दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हूँ।
 खेहर, लोकुर और गोयल, जेजे द्वारा लिया गया। , कि संशोधन है
 असंवैधानिक और मैं सम्मानपूर्वक सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं के विचार से असहमत हूँ-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [कुरियन, जे.]

उस संबंध में जे. चेलमेश्वर द्वारा। चूंकि यह आयोजित किया जा रहा है
 बहुमत है कि संशोधन अपने आप में बुरा है, इसका कोई मतलब नहीं है
 संशोधन के अस्तित्व की वैधता से संबंधित, अर्थात् ,
 राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014। यह.
 कानून के तहत मौजूद नहीं है। फिर क्यों एक की कुंडली लिखें मृत बच्चे!

10. हालांकि, मैं एक और उत्पाद प्रदान करना चाहूंगा।

प्रोफेसर फिलिप बॉबिट ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'कॉन्स्टीट्यूशनल फेट' में
 संविधान का सिद्धांत , के एक प्रकार से निपटा है
 संवैधानिक तर्क। उनके लिए, पाँच मूलरूप हैं:
 ऐतिहासिक, पाठ्य, संरचनात्मक, विवेकपूर्ण और सैद्धांतिक। उद्धृत करने के लिए
 अध्याय 1 से:

"ऐतिहासिक तर्क यह तर्क है कि मार्शल

संविधान के मसौदा तैयार करने वालों और लोगों का इरादा

जिन्होंने संविधान को अपनाया। इस तरह के तर्क शुरू होते हैं

विवादों के बारे में अभिकथन, दृष्टिकोण, और

उस अवधि के निर्णय जिसके दौरान विशेष

संवैधानिक प्रावधान का अर्थ लगाने का प्रस्ताव किया गया था

और पुष्टि की।

दूसरा मूल रूप पाठ्य तर्क, तर्क है।

जो वर्तमान अर्थ के विचार से लिया गया है

प्रावधान के शब्दों से। कभी-कभी पाठ्य तर्क ऐतिहासिक तर्क के साथ भ्रमित है, जिसके लिए आवश्यक है

पाठ के लिए बाहरी साक्ष्य का विचार। तीसरा।

संरचनात्मक तर्क में संवैधानिक तर्क का प्रकार।

संरचनात्मक तर्क यह दावा करते हैं कि एक विशेष सिद्धांत

या व्यावहारिक परिणाम की संरचनाओं में निहित है सरकार और उनके द्वारा बनाए गए संबंध

नागरिकों और सरकारों के बीच संविधान। चौथा।

संवैधानिक तर्क का प्रकार विवेकपूर्ण तर्क है।

विवेकपूर्ण तर्क समीक्षा संस्थान के लिए आत्म-जागरूक है और विशेष के गुणों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

विवाद (जो स्वयं संवैधानिक हो भी सकता है और नहीं भी), [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसके बजाय के अनुसार विशेष सिद्धांतों को आगे बढ़ाना

एक विशेष तरीके से अदालतों का उपयोग करने का व्यावहारिक ज्ञान।

अंत में, एक सैद्धांतिक तर्क है, यह तर्क कि

पूर्ववर्ती या न्यायिक से प्राप्त सिद्धांतों का दावा करता है या पूर्ववर्ती पर अकादमिक टिप्पणी "।

11. प्रोफेसर (डॉ.) उपेंद्र बक्शी के पास एक और उपकरण है।

ओडिक', जो उनके अनुसार, अक्सर गलत तरीके से उपयोग किया जाता है

संविधान से पहले। डॉ. बक्शी के लिए, 'संरचनात्मक' सबसे अधिक है।

संविधान की व्याख्या करते समय मौखिक तर्क।

12. संरचनात्मक तर्क को आगे अध्याय में समझाया गया है।

o कुछ टिप्पणियों का उद्धरण दें:

"संरचनात्मक तर्क अस्तित्व से निष्कर्ष हैं। संवैधानिक संरचनाओं और संबंध जो

संविधान इन संरचनाओं के बीच आदेश देता है। वे।

पाठ्य और ऐतिहासिक से अलग किया जाना है

मार्ग और फिर तर्क में उस निर्माण का उपयोग करें एक राय "।

XXX

XXX

XXX

"संरचनात्मक तर्क काफी हद तक तथ्यहीन और निर्भर हैं।

पूरी तरह से भ्रामक रूप से सरल तार्किक चालों पर
पाठ। जिसमें

इसके किसी एक भाग के बजाय संवैधानिक

उसी समय, वे एक मैक्रोस्कोपिक विवेकवाद को मूर्त रूप देते हैं

शक्ति और सामाजिक के बारे में सामान्य दावों से उत्पन्न चुनें "।

XXX

XXX

XXX

सिद्धांतवाद, के वास्तविक पाठ में आधारित है

संविधान। लेकिन, पाठ्यवादी तर्कों के विपरीत,

जो परिच्छेद महत्वपूर्ण हैं वे एक्सप्रेस सुपर कोर्टवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड के नहीं हैं।

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [कुरियन, जे.]

शक्ति या विशेष प्रतिबंधों का अनुदान लेकिन इसके बजाय

जो एक निश्चित प्रकार की संरचनाओं की स्थापना करके,

हमें संबंधों की आवश्यकताओं को पूरा करने की अनुमति दें
संरचनाओं के बीच "।

13. प्रोफेसर बॉबिट ने छोटे दृष्टिकोण पर भी काम किया है।

- नैतिक, जो उनके अनुसार, शायद ही कभी उपयोग किया जाता है

संवैधानिक कानून। संविधान की व्याख्या में, सभी साधन

उचित रूप से उपयोग किया जाना चाहिए, और अक्सर, संयोजन में

भी। तीन संवैधानिक शाखाएँ, उनकी शक्तियाँ और कार्य

संविधान के तहत, और उनके अंतर संबंध हैं

वर्तमान मामले में जिन प्रमुख मुद्दों का विश्लेषण किया जाना है, मेरा विचार है कि समाधान के लिए 'संरचनात्मक उपकरण' को प्रमुखता से लागू किया जाना चाहिए

मामले में उत्पन्न होने वाले मुद्दे। समर्थन में, मैं हाल ही में एक का उल्लेख करूंगा राज्य बनाम में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। एरिजोना

29.06.2015. यह एक दिलचस्प मामला है जो हमारे लिए काफी प्रासंगिक है। चर्चा करें। अमेरिकी संविधान अनुच्छेद I, धारा 4, खंड 1

(चुनाव खंड) इस प्रकार है:

"चुनाव कराने का समय, स्थान और तरीका

सीनेटरों और प्रतिनिधियों को निर्धारित किया जाएगा प्रत्येक राज्य उसके विधानमंडल द्वारा; लेकिन कांग्रेस

कानून द्वारा किसी भी समय ऐसे विनियम बना या बदल सकते हैं,

सीनेटरों को हटाने के स्थानों को छोड़कर। "

14. एरिजोना संविधान, अनुच्छेद IV, भाग 1, इस हद तक

प्रासंगिक, निम्नानुसार पढ़ता है:

"खंड 1. (1) सीनेट; प्रतिनिधियों का सदन;

राज्य का विधानमंडल में निहित होगा, जिसमें एक सीनेट और प्रतिनिधियों का एक सदन, लेकिन

लोगों के पास कानून प्रस्तावित करने की शक्ति सुरक्षित है और

संविधान में संशोधन और चुनावों में स्वतंत्र रूप से ऐसे कानूनों और संशोधनों को अधिनियमित या अस्वीकार करना,

3 मनु/यूएसएससी/0060/2015 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

विधायिका के; और वे भी आरक्षित करते हैं, उनके उपयोग के लिए

स्वयं का विकल्प, चुनाव में किसी भी अधिनियम, या वस्तु, धारा, या किसी भी अधिनियम के हिस्से को अनुमोदित या अस्वीकार करने की शक्ति

विधायिका "।

इस प्रकार, धारा 1 के तहत, लोग प्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं।

'जनमत संग्रह'। जबकि पहल मतदाताओं को अपनाने की अनुमति देती है सकारात्मक कानून, जनमत संग्रह एक नकारात्मक जांच के रूप में होता है। लोकप्रिय रूप से, पहल की प्रक्रिया को पापों को सुधारने के लिए कहा जाता है।

विधानमंडल द्वारा 'चूक' जबकि जनमत संग्रह पापों को ठीक करता है

विधानमंडल द्वारा 'आयोग'।

15. 2000 में, एरिजोना के मतदाताओं ने प्रस्ताव 106 को अपनाया।

जेरीमेंडरिंग की समस्या के उद्देश्य से पहल। प्रस्ताव

106 एरिजोना के संविधान में संशोधन, पुनर्वितरण को हटाना

एरिजोना विधानमंडल से अधिकार और इसे एक में निहित करना स्वतंत्र

स्वतंत्र आयोग, एरिजोना

पुनर्वितरण आयोग (ए. आई. आर. सी.)। 2010 की जनगणना के बाद, ए. आई. आर. सी. ने मानचित्रों के पुनर्वितरण को अपनाया।

2000 की जनगणना के बाद,

कांग्रेस के साथ-साथ राज्य विधायी जिलों के लिए भी। द.

एरिजोना विधानमंडल ने उस नक्शे को चुनौती दी जिसे आयोग ने

2012 में कांग्रेस के जिलों के लिए यह तर्क देते हुए अपनाया गया कि

ए. आई. आर. सी. और उसके नक्शे ने यू. एस. के "चुनाव खंड" का उल्लंघन किया।

संविधान।

16. न्यायमूर्ति गिन्सबर्ग और चार अन्य न्यायाधीशों ने

बहुमत और माना कि स्वतंत्र आयोग है

पुनर्वितरण के लिए प्रावधान करने में सक्षम। मुख्य को उद्धृत करने के लिए

तर्क:

"फ्रेमर्स ने आधुनिक की कल्पना नहीं की होगी पहल प्रक्रिया जिसमें लोगों की विधायी शक्तियाँ

राज्य विधानमंडल के अधिकार के साथ सह-विस्तारित है, लेकिन
पहल का आविष्कार पूर्ण सामंजस्य में था
लोगों की संविधान की अवधारणा

सरकारी शक्ति "। सर्वोच्च अदालतें-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [कुरियन, जे.]

17. हालांकि, मुख्य न्यायाधीश रॉबर्ट्स और तीन अन्य

न्यायाधीशों ने असहमति जताई। मुख्य न्यायाधीश रॉबर्ट्स ने बताया कि
बहुमत की स्थिति का पाठ, संरचना या इतिहास में कोई आधार नहीं है।
संविधान और यह कांग्रेस और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के उदाहरणों के विपरीत है। संविधान में शामिल हैं -
किसी राज्य के 'विधानमंडल' का उल्लेख करने वाले सत्रह प्रावधान,
जिनमें से कई को संभवतः 'लोगों' के अर्थ में नहीं पढ़ा जा सकता है। आगे उद्धृत करने के लिए:

इसके बजाय प्रत्यक्ष के बारे में डिस्कनेक्ट किए गए अवलोकनों पर
लोकतंत्र, एक अप्रासंगिक की एक विकृत व्याख्या

कानून, और सार्वजनिक नीति के लिए नग्न अपील। कहीं नहीं।

क्या बहुमत यह बताता है कि कैसे एक संवैधानिक प्रावधान

जो "विधानमंडल" में पुनर्वितरण का अधिकार निहित करता है

किसी राज्य को "विधानमंडल" को पूरी तरह से बाहर करने की अनुमति देता है।

पुनर्वितरण। एरिजोना का आयोग एक "महान" हो सकता है।

प्रयास "हालांकि यह इतना" स्वतंत्र "नहीं लगता है

व्यवहार में लेकिन तथ्य यह है कि एक दिया गया कानून या प्रक्रिया है

कुशल, सुविधाजनक और उपयोगी. अगर यह है तो इसे सहेजा नहीं जाएगा
संविधान के विपरीत "आई. एन. एस. वी. चड्ढा, 462 यू. एस.

919, 944 (1983). "

XXX

XXX

XXX

"संवैधानिक पाठ, संरचना, इतिहास और पूर्ववर्ती

एक सीधा नियम बनाएँ: चुनावों के तहत

खंड, "विधानमंडल" एक प्रतिनिधि निकाय है जो,

जब यह चुनाव नियमों को निर्धारित करता है, तो इसकी आवश्यकता हो सकती है सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया के भीतर ऐसा करने के लिए, लेकिन हो सकता है

विधायिका को कांग्रेस में अनन्य होने की आवश्यकता नहीं है विचलित करने वाला, लेकिन न ही इसे बाहर रखा जा सकता है।

XXX

XXX

XXX सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

"आज बहुमत अधिक चिंता दिखाता है

अर्थ की तुलना में प्रथाओं को पुनर्वितरित करना

संविधान। मैं उन कठिनाइयों को पहचानता हूँ जो उत्पन्न होती हैं

पक्षपात के लिए न्यायिक राहत देने की कोशिश

(2004); पहले, 1 पर। लेकिन एक प्रबंधनीय खोजने में हमारी असमर्थता उस क्षेत्र में मानक किसी मानक को छोड़ने का कोई बहाना नहीं है

इस क्षेत्र में सार्थक व्याख्या। इस अदालत ने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि एक नीति के रूप में एक कानून के गुण

नवान्वेषण इसके साथ अपनी विसंगति को दूर नहीं कर सकता है

संविधान। "

(जोर दिया गया)

18. ऐतिहासिक, पाठ्य से पूरी तरह सहमत होते हुए,

खेहर द्वारा बनाए गए विवेकपूर्ण और सैद्धांतिक दृष्टिकोण और संरचनात्मक भाग पर है। द.

लोकुर, जे. जे., मेरा अतिरिक्त जोर

एरिजोना मामले में अल्पसंख्यक (ऊपर), मेरे लिए, सही दृष्टिकोण है।

इस मामले में किया जाना है।

19. शक्तियों का पृथक्करण या शक्तियों का वितरण,

जैसा कि भाई लोकुर, जे. इसे कहते हैं, की विवर्तनिक संरचना है

भारत का संविधान। विभिन्न नियंत्रण और संतुलन हैं - केवल उनके बीच उचित संतुलन बनाए रखने के लिए प्रदान किया गया

संरचनाएँ और यही हमारे संविधान की सर्वोच्च सुंदरता है।

हमारी संवैधानिक योजना के तहत, एक शाखा हस्तक्षेप नहीं करती है

असंवैधानिक रूप से सौंपी गई शक्तियों के साथ और

एक अन्य शाखा के कार्य। अनुमेय क्षेत्र

हस्तक्षेप नियंत्रण और संतुलन हैं। लेकिन कुछ निश्चित हैं।

प्रत्येक शाखा के लिए विशेष क्षेत्र जो जे. खेहर ने कहा है 'मुख्य कार्यों' के रूप में, और जिन्हें मैं केंद्रीय शक्तियों के रूप में वर्णित करूंगा। केंद्रीय शक्तियों पर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा

प्रत्येक शाखा। संविधान क्या है, केवल अदालत के लिए है परिभाषित करें; जबकि संवैधानिक आकांक्षाएँ क्या हैं

विस्तार से और प्रदर्शित करने के लिए अन्य शाखाएँ।

जैसा कि समशेर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड में आयोजित किया गया है

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [कुरियन, जे.]

सिंह मामला (ऊपर) और द्वितीय और तृतीय न्यायाधीश मामले,

सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका की केंद्रीय शक्तियों से संबंधित है। राशि अन्य लोगों को प्रदान की जाती है।

और अनुमेय नियंत्रण और शेष

शाखाएँ नियुक्ति के क्षेत्र में स्थित होती हैं। यदि संरक्षण

शक्तियों के वितरण पर विवर्तनिक प्लेटें बाधित होती हैं, यह होगा

संविधान को ध्वस्त करें। एक बार संवैधानिक संरचना है

हिल गया, लोकतंत्र ध्वस्त हो गया। यह हमारा अपना दर्दनाक इतिहास है।

आपातकाल से। यह संसद है, आपातकाल के बाद,

जिसने संवैधानिक विकृतियों को ठीक किया और कानून के शासन की सर्वोच्चता को बहाल किया जो हमारे शासन की आधारशिला है।

संविधान। संविधान के संरक्षक के रूप में, इस न्यायालय को

सावधानीपूर्वक बुनियादी की प्राचीन शुद्धता और अखंडता की रक्षा करें संविधान की संरचना।
प्रत्यक्ष भागीदारी

कार्यकारी या अन्य गैर-न्यायिक तत्व अंततः नेतृत्व करेंगे।

नियुक्तियों में संरचित सौदेबाजी, यदि नहीं, तो कुछ भी बदतर। एक प्रतिबद्ध बनाने के लिए बुनियादी संरचना को कमजोर करने का कोई भी प्रयास

न्यायपालिका की संभावना चाहे जितनी भी हो, उसे दबाया जाना चाहिए।

गुडिया। न्यायमूर्ति रॉबर्ट्स के अनुसार, अदालत के पास कोई शक्ति नहीं है

संविधान का उल्लंघन करें। प्रासंगिक रूप से, मैं कहूंगा,

संसद के पास संविधान को अस्थिर करने की कोई शक्ति नहीं है। द. संविधान का 99 वां संशोधन
संरचनात्मक वितरण को बाधित करता है।

शक्तियों का, और इसलिए, यह अस्वीकार्य है।

20. परिणाम पर एक शब्द। यद्यपि विस्तृत तर्कों को संबोधित किया गया है कि भले ही संवैधानिक

संशोधन निरस्त कर दिया जाता है, कॉलेजियम पुनर्जीवित नहीं होता है,

मेरे अनुसार, यह सामान्य ज्ञान को भी आकर्षित नहीं करता है।

99 वें संशोधन में कुछ प्रावधानों को 'प्रतिस्थापित' करने की मांग की गई थी

संविधान और कुछ नए प्रावधान 'सम्मिलित' करें। एक बार

संशोधन को ही बुरा और अस्वीकार्य माना जाता है, पूर्व-संशोधित प्रावधान स्वचालित रूप से फिर
से उभरते हैं और पुनर्जीवित होते हैं।

केवल यही उचित रूप से अनुमानित निष्कर्ष हो सकता है।

कानूनी [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बोलचाल और आम बोलचाल अलग हो सकती है लेकिन वहाँ किसी ऐसे मुद्दे का कोई कानूनी अर्थ नहीं हो सकता है जो अपील नहीं करता है सामान्य ज्ञान के लिए।

21. सब कुछ ठीक था और सब कुछ ठीक नहीं है। इस हद तक, मैं सहमत हूँ

जे. चेलमेश्वर ने कहा कि वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता का अभाव है। विश्वास की कमी

कॉलेजियम प्रणाली की विश्वसनीयता को प्रभावित किया है, जैसा कि कभी-कभी नागरिक समाज द्वारा देखा जाता है। अक्सर, बहुत

सामाजिक और अन्य राष्ट्रीय वास्तविकताओं की अनदेखी की गई, कुछ नियुक्तियों में जानबूझकर देरी की गई थी ताकि या तो

निहित विकल्पों का लाभ उठाना या ऐसे लाभों को कम लोगों को देने से इनकार करना।

संरक्षण प्राप्त, संरक्षण प्राप्त या पसंदीदा व्यक्तियों का चयन दिशानिर्देशों के घोर उल्लंघन में किया गया था जिसके परिणामस्वरूप अयोग्य, यदि नहीं, खराब नियुक्तियाँ, का तानाशाही रवैया

कॉलेजियम न्यायाधीशों, विशेष रूप से न्यायालय की स्वतंत्रता, यदि नहीं, तो आत्म-सम्मान और गरिमा को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।

सर्वोच्च न्यायालय, जिसे अक्सर न्यायालय के रूप में शैलीबद्ध किया जाता है कॉलेजियम, निष्पक्षता को प्रभावित करने वाला लुकिंग फॉरवर्ड सिंड्रोम

मूल्यांकन, आदि, में कुछ अन्य आरोप रहे हैं

कुछ समय के लिए हवा। ये आरोप निश्चित रूप से मांग करते हैं

एक गहरा आत्मनिरीक्षण कि क्या संस्थागत ट्रस्टीशिप संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं को पूरा किया है।

हालांकि कोई इसके विस्तृत विश्लेषण में नहीं जाना चाहेगा

कारणों से, मुझे लगता है कि यह ट्रस्टीशिप नहीं है जो विफल रही, लेकिन

न्यासियों और सहयोगियों की कमियाँ जो विफल रहीं

प्रणाली। मेरे लिए, यह अभी तक एक ठीक होने वाली स्थिति है।

22. व्यवहार में कोई स्वस्थ प्रणाली नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि

गलती पूरी तरह से कॉलेजियम की नहीं है। सक्रिय मौन

इस तरह की अयोग्य नियुक्तियों को रोकने में कार्यकारी था

वास्तव में प्रमुख समस्याओं में से एक।

द्वितीय और तृतीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई.

न्यायाधीशों के मामले ने प्रभावी उपकरण प्रदान किए थे

इस तरह के विचलन को रोकने के लिए कार्यकारी। चाहे 'संयुक्त उद्यम';

जैसा कि जे. चेलमेश्वर ने देखा है या नहीं, कार्यकारी ने शायद ही कभी उन उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया हो।

23. इसलिए, कॉलेजियम प्रणाली की आवश्यकता है

एक 'ग्लासनोस्ट' और एक 'पेरेस्ट्रोइका' की आवश्यकता में सुधार, और इसलिए

इस संबंध में मामले की आगे सुनवाई की आवश्यकता है।

न्याय

आदर्श कुमार गोएल, जे. परिचय 1. लेख

124, 127, 128, 217, 222, 224 और संविधान की धारा 232

भारत ('संविधान') न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है।
(संवैधानिक

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों

न्यायालय), और अन्य संबद्ध मामले। संविधान (नब्बे-नौवां)

संशोधन) अधिनियम, 2014 ('संशोधन अधिनियम') अन्य बातों के साथ-साथ
प्रावधानों में संशोधन करना। राष्ट्रीय न्यायिक

इन संवैधानिक

नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014 ('एन. जे. ए. सी. अधिनियम'), एक साथ अधिनियमित, की प्रक्रिया को
विनियमित करने का उद्देश्य है - राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी)। द.

याचिकाओं का वर्तमान समूह संवैधानिक वैधता को चुनौती देता है

संशोधन अधिनियम और एन. जे. ए. सी. अधिनियम। उच्चतम न्यायालय

एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन ने रिट याचिका (सिविल) दायर की है

2015 का सं. 13, जिसे प्रमुख याचिका माना गया है।

2. मैंने अपने सम्मानित व्यक्तियों के विद्वतापूर्ण विचारों को पढ़ा है।

भाइयों। जबकि मैं सम्मानपूर्वक आए निष्कर्षों से सहमत हूँ

खेहर जे।, . लोकर जे. और कुरियन जोसेफ जे., और सम्मानपूर्वक असहमत हूं। मैं रिकॉर्ड करना पसंद करता हूं।

जे. चेलमेश्वर के विचार से

मेरे अपने कारण।

नियुक्ति की पूर्व-संशोधन योजना और

न्यायाधीशों का स्थानांतरण

3. न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की योजना

संशोधन से पहले बल भारत सरकार द्वारा 30 जून, 1999 को जारी किए गए दो ज्ञापनों में निर्धारित किया गया है -

सबसे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) और न्यायाधीशों (2015) की नियुक्ति के लिए 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय और नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए दूसरा

मुख्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की।

3.1 मोटे तौर पर पहले में निर्धारित प्रक्रिया

ज्ञापन यह है कि सीजेआई के कार्यालय में नियुक्ति होनी चाहिए न्यायाधीशों में से एक माने जाएँ

सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ

पद धारण करने के लिए उपयुक्त। इस उद्देश्य के लिए, सिफारिश है

निवर्तमान सी. जे. आई. से माँगा गया और यदि इसके बारे में संदेह है

सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश की योग्यता, उनके साथ परामर्श किया जाता है

अनुच्छेद 124 (2) के तहत अन्य न्यायाधीश। इसके बाद, कानून मंत्री ने (पीएम) के सामने रखता है जो सलाह देते हैं

इस मामले को प्रधानमंत्री

राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद, नियुक्ति है न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए,

अधिसूचित किया। उच्चतम न्यायालय के

सीजेआई प्रस्ताव की शुरुआत करता है और उसे आगे बढ़ाता है

केंद्रीय कानून मंत्री को सिफारिश जो प्रस्तुत करता है

प्रधान मंत्री के लिए मामला, जो बदले में राष्ट्रपति को सलाह देता है। राय सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से किया जाता है।

सीजेआई का गठन चार

और यदि उत्तराधिकारी सीजेआई उक्त चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों में नहीं हैं, का हिस्सा बनाया जाता है। सीजेआई यह भी सुनिश्चित करता है कि

उसे भी कॉलेजियम

उच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के विचार

उच्च न्यायालय से जहाँ से एक व्यक्ति ने सिफारिश की थी

आता है। सिफारिश के संबंध में राय इस प्रकार है -

लिखने के लिए और भारत सरकार को प्रेषित किए जाते हैं

रिकॉर्ड करें। यदि गैर-न्यायाधीशों के विचार मांगे जाते हैं, तो एक ज्ञापन

इसका और इसका सार सरकार को सूचित किया जाता है

भारत। एक बार नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित हो जाने के बाद,

शारीरिक स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है और वारंट के बाद

नियुक्ति पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, नियुक्ति है

घोषणा की और भारत के राजपत्र में एक अधिसूचना जारी की गई।

3.2 दूसरे में निर्धारित प्रक्रिया

उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों से संबंधित ज्ञापन न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है

और स्थानांतरण। उच्च न्यायालयों के मुख्य

बाहर से। किसी विशेष उच्च न्यायालय में अंतर वरिष्ठता है

उस उच्च सर्वोच्च न्यायालय से मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया गया-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

अदालत। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव की शुरुआत

उच्च न्यायालय का सी. जे. आई. द्वारा होता है। सीजेआई उच्चतम न्यायालय के दो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श करता है और उनके विचारों का भी पता लगाता है

उच्चतम न्यायालय में उनके सबसे वरिष्ठ सहयोगी जो हैं

उच्च न्यायालय के मामलों से बात करते हुए जिसमें

सिफारिशकर्ता कार्य कर रहा है और जिसकी राय है
उपयुक्तता का निर्णय लेने में महत्वपूर्ण होने की संभावना
उम्मीदवार। न्यायाधीशों के विचार इसके साथ भेजे जाते हैं - केंद्रीय कानून मंत्री का प्रस्ताव जो
विचार प्राप्त करता है
संबंधित राज्य सरकार का और फिर प्रस्तुत करता है
प्रधानमंत्री को प्रस्ताव जो राष्ट्रपति को सलाह देता है। जैसे ही राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति को मंजूरी दी जाती है,
अधिसूचना है
भारत के राजपत्र में जारी किया गया। नियुक्ति के संबंध में
उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
उपयुक्तता के बारे में अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों से परामर्श करने के बाद मुख्यमंत्री को अपने विचारों से
अवगत कराता है।
व्यक्ति का चयन किया जाता है। सभी परामर्श लिखित में होने चाहिए और
इन विचारों को मुख्यमंत्री को भेजा जाता है, साथ ही
सिफारिश करें। यदि मुख्यमंत्री किसी नाम की सिफारिश करना चाहते हैं, तो उन्हें इसे मुख्य न्यायाधीश के
पास भेजना होगा।
उसका विचार। सिफारिश की एक प्रति भी भेजी जाती है।
सीजेआई और केंद्रीय कानून मंत्री को। मुख्यमंत्री ने
राज्यपाल को सलाह देता है जो अपनी सिफारिश को आगे बढ़ाता है
कानून मंत्री। कानून मंत्री का मानना है कि
ऐसी अन्य रिपोर्टों के आलोक में सिफारिश (जैसे आई. बी. रिपोर्ट) जो सरकार को उपलब्ध हो और
फिर
सीजेआई को सामग्री भेजें। सीजेआई ने दो वरिष्ठों से परामर्श किया
न्यायाधीश और प्रमुख के विचारों को भी ध्यान में रखते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और
न्यायाधीश (मुख्य न्यायाधीश द्वारा परामर्शित)
न्यायमूर्ति) और उच्चतम न्यायालय के वे न्यायाधीश जो हैं
उम्मीदवार के मामलों से बातचीत करना। इसके बाद
सीजेआई केंद्रीय कानून मंत्री को अपनी सिफारिश भेजते हैं
अपने सहयोगियों के साथ पत्राचार के साथ। अगर कानून मंत्री
सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर. की राय के लिए नाम वापस लेना समीचीन समझता है।

राज्य संवैधानिक प्राधिकरणों, सीजेआई की राय होनी चाहिए

प्राप्त किया। इसके बाद कानून मंत्री प्रधानमंत्री को सिफारिश प्रस्तुत करता है जो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। पत्राचार

मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच

इंटर से लिखित रूप में है। जैसे ही नियुक्ति को मंजूरी मिलती है

राष्ट्रपति द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य का पता लगाया जाता है और जल्द ही

नियुक्ति आदेश पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के कारण, अधिसूचना भारत के राजपत्र में जारी की जाती है।

3.3 स्थानांतरण का प्रस्ताव सीजेआई द्वारा शुरू किया जाता है। सहमति दें।

संबंधित न्यायाधीश की आवश्यकता नहीं है। सीजेआई सलाह लेते हैं

उच्चतम न्यायालय के चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश और

से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विचारों को ध्यान में रखें

जिनका न्यायाधीश को स्थानांतरित किया जाना है और मुख्य न्यायाधीश

उच्च न्यायालय जहाँ स्थानांतरण किया जाना है। सीजेआई ने भी

एक या अधिक उच्चतम न्यायालय के विचारों को ध्यान में रखता है

ऐसे न्यायाधीश जो अपने विचार प्रस्तुत करने की स्थिति में हों। इन दृश्यों

लिखित रूप में व्यक्त किए जाते हैं, और सीजेआई द्वारा विचार किया जाता है और

चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश। से संबंधित व्यक्तिगत तथ्य

न्यायाधीश और प्रस्ताव पर उनकी प्रतिक्रिया हमेशा ली जाती है।

हिसाब में। इसके बाद प्रस्ताव को सरकार के पास भेजा जाता है।

कानून मंत्री प्रधानमंत्री को सिफारिश प्रस्तुत करता है जो राष्ट्रपति को सलाह देता है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद

स्थानांतरण, आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना जारी की जाती है।

3.4 उपरोक्त ज्ञापन जारी किए गए थे

असंशोधित संवैधानिक व्यवस्था के आलोक में भारत सरकार

28 अक्टूबर को इस न्यायालय के प्रावधानों और निर्णय,
 एस. सी. ए. ओ. आर. ए. बनाम भारत संघ 2 (दूसरा) में न्यायपीठ का निर्णय (न्यायाधीशों का मामला)।

3.5 असंशोधित का भी उल्लेख किया जा सकता है।

11 (1998) 7 एससीसी 739

2 (1993) 4 एस. सी. सी. 441 सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 124 (2) में प्रावधान है कि एक न्यायाधीश

उच्चतम न्यायालय की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।

उच्चतम न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों के साथ परामर्श और

उच्च न्यायालय जो आवश्यक समझे जाते हैं। हालांकि, सीजेआई है

हमेशा सलाह लेनी चाहिए। अनुच्छेद 217 में यह प्रावधान है कि

उच्च न्यायालय की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।

सीजेआई, राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श और एक के मामले में
 मुख्य न्यायाधीश

मुख्य न्यायाधीश के अलावा,

उच्च न्यायालय। इस न्यायालय के समक्ष कई मुद्दों पर सवाल उठे
 मूल्य के बारे में अवसर

प्रक्रिया में सीजेआई की राय के

'परामर्श' का। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि योजना के तहत
 न्यायालय में नियुक्ति का प्रस्ताव

संविधान-उच्चतम

सी. जे. आई. से आनी चाहिए और उच्च पद पर नियुक्ति के लिए

न्यायालय में यह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से उत्पन्न होना चाहिए।

अदालत और नियुक्ति पर अंतिम शब्द सीजेआई 3 के पास होना चाहिए। इस न्यायालय ने नोट किया कि
 नियुक्तियों के लिए पारंपरिक प्रस्तावों द्वारा

हमेशा न्यायपालिका द्वारा शुरू किया गया था और नियुक्तियाँ थीं

सी. जे. आई. की सहमति से किया गया। इस विचार को दोहराया गया था

तीसरे न्यायाधीशों के मामले में जिसके आधार पर उपरोक्त

भारत सरकार द्वारा ज्ञापन जारी किए गए थे।

संशोधन के तहत योजना

4. अब आक्षेपित को संदर्भ दिया जा सकता है

संशोधन। यह अनुच्छेद 124 में संशोधन करता है और यह प्रावधान करता है कि

नियुक्तियाँ और स्थानांतरण अब सिफारिश पर होंगे।

एन. जे. ए. सी. (धारा 2)। अनिवार्यता

प्रधान न्यायाधीश के साथ परामर्श और ऐसे न्यायाधीशों के साथ परामर्श

आवश्यक समझा जा सकता है जिसे हटा दिया गया है। सम्मेलन

उच्च न्यायालयों के लिए मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रस्ताव की शुरुआत
योजनाओं के लिए सीजेआई जैसा कि परिलक्षित होता है

और सुप्रीम कोर्ट और अन्य

पहले उल्लिखित ज्ञापनों में और जैसा कि निर्धारित किया गया है

इस न्यायालय के फैसलों को बदल दिया गया है। संशोधन 3 पैरा 210, 214, पांडियान, जे., पारस
361 से 376, कुलदिप सिंह, जे., पैरा 486, वर्मा, जे., पैरा 505, पुंछी, जे. दूसरे न्यायाधीशों के मामले में [2015]
13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक नया अनुच्छेद 124 ए शामिल किया गया है, जिसके तहत एनजेएसी को बनाया जाना है।

गठित किया गया। इसमें सीजेआई, दो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होंगे।

सीजेआई के बगल में सुप्रीम कोर्ट, केंद्रीय कानून मंत्री और दो

समिति द्वारा नामित किए जाने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसमें प्रधानमंत्री, सीजेआई और विपक्ष के
नेता शामिल होते हैं

लोक सभा में/सबसे बड़े विपक्ष के नेता

जनता के सदन में पार्टी। एक का नामांकन

ये प्रतिष्ठित व्यक्ति संबंधित व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक

छह सदस्यों को सहमत होना होगा। यदि कोई दो सदस्य असहमत हैं, तो नहीं।
सकता है।

प्रस्ताव दिया जा

5. संशोधन अधिनियम में संसद के लिए भी प्रावधान है
नियुक्ति की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए कानून बनाना
उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को और आयोग को सशक्त बनाने के लिए
विनियमों द्वारा, इसके निर्वहन के लिए प्रक्रिया निर्धारित करें
कार्य, इसके सदस्यों के चयन का तरीका और ऐसे अन्य मामले, जिन्हें आवश्यक माना जाए (धारा 3)।

6. एन. जे. ए. सी. अधिनियम नियुक्ति के लिए प्रावधान करता है

सी. जे. आई. के रूप में उच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश, यदि पद धारण करने के लिए उपयुक्त
माने जाते हैं; और नियुक्ति के लिए सिफारिश के लिए

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में (धारा 5)। द सेकंड
5 (2) के प्रावधान में कहा गया है कि

एन. जे. ए. सी. अधिनियम की धारा

आयोग दो सदस्यों वाले किसी व्यक्ति की सिफारिश नहीं करेगा।

आयोग सहमत नहीं है। इसके अन्य कार्यों के अलावा,

आयोग मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियों की भी सिफारिश करेगा (धारा 6
(1), (3))।

वैकल्पिक रूप से, आयोग नियुक्ति की सिफारिश करने के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से नामांकन
ले सकता है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में (धारा 6 (2))। नियुक्ति के लिए

हालांकि, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को आयोग की मांग करनी चाहिए

संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ पूर्व परामर्श न्यायालय, जिसे बदले में सर्वोच्च
न्यायालय के दो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श करना पड़ता है-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

उच्च न्यायालय और ऐसे अन्य न्यायाधीशों और प्रख्यात अधिवक्ताओं, जिन्हें निर्दिष्ट किया जा सकता है, ने
कहा। (धारा 6 (4))। आयोग भी है

संबंधित राज्य। आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की शक्ति केंद्र सरकार के पास है।
आयोग के संयोजक सचिव, सरकार हैं।

भारत के न्याय विभाग में। केंद्र सरकार है के प्रावधानों को पूरा करने के लिए नियम बनाने के लिए अधिकृत

अधिनियम (धारा 11)। आयोग को ऐसा करने का अधिकार है

अधिनियम और नियमों के अनुरूप विनियम। नियम हैं।

और अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों की आवश्यकता है

संसद के समक्ष रखा जाता है, जो ऐसे नियमों को संशोधित कर सकती है या

विनियम (धारा 12,13)।

7. उद्देश्यों और कारणों का कथन

संशोधन में उल्लेख किया गया है कि इस न्यायालय ने इस शब्द की व्याख्या की थी

"अनुच्छेद 124 (2) और 217 (2) में "सहमति" के रूप में परामर्श संविधान (धारा 2)। इसमें आगे कहा गया है कि समीक्षा के बाद

इस न्यायालय के संवैधानिक प्रावधानों, घोषणाओं और

प्रख्यात न्यायविदों के साथ परामर्श, यह महसूस किया गया कि एक व्यापक आधार

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को करना चाहिए

नियुक्ति के लिए सिफारिश करने के लिए स्थापित

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। द.

आयोग न्यायपालिका को सार्थक भूमिका प्रदान करेगा,

और चयन प्रक्रिया (एस. 3) में पारदर्शिता लाने के साथ-साथ प्रतिभागियों को जवाबदेह बनाना।

7.1 यद्यपि 13 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना द्वारा, संशोधन और अधिनियम को लागू कर दिया गया है,

आयोग का गठन अभी तक नहीं किया गया है, क्योंकि दो प्रतिष्ठित

अभी तक व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं की गई है।

7.2 प्रमुख असंशोधित संवैधानिक प्रावधान और

संशोधन और अधिनियम के प्रावधान इस प्रकार हैं:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015] 13 एस. सी. आर

संशोधनों के प्रावधान

अपरिवर्तित प्रावधान

अनुच्छेद 124 XXXX

“124 ए. (1)

वहाँ एक होगा

आयोग के रूप में जाना जाता है

(2) सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश

न्यायिक

राष्ट्रीय

द.

न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा

नियुक्तियाँ

आयोग

राष्ट्रपति अपने अधीन आदेश द्वारा

निम्नलिखित से मिलकर,

और उसके बाद सील करें

हाथ

अर्थात्:

ऐसे लोगों के साथ परामर्श

(क) भारत के मुख्य न्यायाधीश,

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश

और उच्च न्यायालयों में

अध्यक्ष, पदेन;

राष्ट्रपति के रूप में राज्य

(ख) के दो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश

के लिए आवश्यक है

सुप्रीम कोर्ट के बगल में

उद्देश्य और पद धारण करेगा

भारत के मुख्य न्यायाधीश

जब तक वह साठ वर्ष का नहीं हो जाता

सदस्य, पदेन;

पाँच साल।

((c) केंद्रीय मंत्री

बशर्ते कि किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में

विधि और न्याय और न्याय का प्रभार -

सदस्य, पदेन;

मुख्य न्यायाधीश की तुलना में,

भारत के मुख्य न्यायाधीश

(घ) दो प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के लिए

हमेशा सलाह लें:

समिति द्वारा नामित

जिसमें प्रधान शामिल है

मंत्री, मुख्य न्यायाधीश

अनुच्छेद 217। नियुक्ति और

भारत और उसके नेता

एक के कार्यालय की शर्तें

सदन में विपक्ष

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश-प्रत्येक

लोग या जहाँ वहाँ है

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे

विपक्ष का ऐसा कोई नेता नहीं,

तब, एकल का नेता

राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त

उसके हाथ के नीचे आदेश और

सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी

परामर्श के बाद सील करें

लोगों का सदन -

भारत के मुख्य न्यायाधीश,

सदस्य:

राज्य के राज्यपाल, और,

बशर्ते कि एक

ए की नियुक्ति का मामला

प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे

मुखिया के अलावा अन्य न्यायाधीश

के बीच से नामित

न्यायमूर्ति, के मुख्य न्यायाधीश

संबंधित व्यक्ति

द.

उच्च न्यायालय, और आयोजित करेगा

अनुसूचित जातियाँ,

कार्यालय, एक मामले में

अनुसूचित जनजाति, अन्य

अतिरिक्त या कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में

पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक

अनुच्छेद 224 में उपबंधित, और

या महिलाएँ:

कोई अन्य मामला, जब तक वह प्राप्त नहीं करता है

बशर्ते कि एक

बासठ वर्ष की आयु:

प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे
 एक अवधि के लिए नामित
 तीन साल और नहीं होगा
 पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र।

अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

आई. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

(2) का कोई अधिनियम या कार्यवाही नहीं

राष्ट्रीय

न्यायिक

नियुक्ति आयोग पर केवल आयोग के गठन में किसी रिक्ति या दोष के अस्तित्व के आधार पर सवाल उठाया जाएगा या उसे अमान्य कर दिया जाएगा।

124 बी. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का यह कर्तव्य होगा कि

(क) भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करना;

(ख)

स्थानांतरण की सिफारिश करें

एक उच्च न्यायालय से लेकर किसी अन्य उच्च न्यायालय तक उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश; और

(ग)

सुनिश्चित करें कि व्यक्ति

क्षमता और ईमानदारी की सिफारिश की जाती है।

124 सी. संसद, विधि द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया को विनियमित कर सकती है और आयोग को निम्नानुसार निर्धारित करने का अधिकार दे सकती है -

अपने कार्यों के निर्वहन की प्रक्रिया, नियुक्ति के लिए व्यक्तियों के चयन का तरीका और ऐसे अन्य मामले जो उसके द्वारा आवश्यक माने जाएं। ” .

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7.3 प्रासंगिक संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान

इस राय के लिए एक परिशिष्ट में अलग से निर्धारित किया गया है।

प्रतिद्वंद्वी विवाद

8.

संशोधन अधिनियम को अति अधिकार के रूप में चुनौती दी गई है

संसद की क्षमता से परे होने के लिए क्योंकि यह संविधान की मूल संरचना को परिवर्तित और नष्ट करता है, जैसे कि

के संदर्भ में न्यायपालिका की स्वतंत्रता में सन्निहित उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति।
याचिकाकर्ताओं ने

प्रस्तुत करें कि संसद की संशोधन करने की शक्ति

अनुच्छेद 368 के तहत संविधान सीमित है और इसका विस्तार बुनियादी संरचना या बुनियादी विशेषताओं को बदलने या नष्ट करने तक नहीं है।

संविधान, और इससे न्यायपालिका को अलग करना शामिल है कार्यपालिका या विधायी नियंत्रण,
उच्च न्यायपालिका की प्रधानता

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला, सेवा की शर्तों की गैर-
संशोधनशीलता

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके

हानि। संशोधन की प्रधानता छीन लेता है

सीजेआई और सबसे वरिष्ठ सर्वोच्च की सामूहिक राय

उनके द्वारा यदि दो गैर-न्यायाधीश आयोग के सदस्यों द्वारा सहमति नहीं है [धारा 5 (2) का दूसरा परंतुक
और धारा 6 (6)]। यह गैर को अनियंत्रित वीटो शक्ति प्रदान करता है

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायाधीश, समझौता करना

न्यायपालिका की स्वतंत्रता। संशोधन भी कमजोर करता है न्यायपालिका को संवैधानिक रूप से
प्रदान करने की शक्ति

संसद को सामान्य कानून द्वारा नियंत्रित करने की बेलगाम शक्ति,

उच्च पद पर नियुक्ति के लिए व्यक्ति के चयन का तरीका

न्यायपालिका, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भी नुकसान पहुंचाती है।

कार्यपालिका के साथ प्रधानता। अगर खड़े होने की अनुमति है, तो प्रावधान को आसानी से और
संशोधित किया जा सकता है जिससे किसी भी सर्वोच्च न्यायालय-चालू-रिकॉर्ड से इनकार किया जा सके।

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

उच्च न्यायपालिका के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों के लिए प्रभावी भूमिका

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में अदालतें। इस प्रकार, संशोधन में प्रमुखता की परिकल्पना नहीं की गई है

न्यायाधीशों के लिए आवाज उठाती है और कार्यकारी तत्व बनाती है

न्यायाधीशों की नियुक्ति जो परिवर्तन और नुकसान पहुँचाती है

संविधान की मूल संरचना। यह भी दावा किया जाता है कि एन. जे. ए. सी. अधिनियम अमान्य था क्योंकि इसे संसद द्वारा पारित किया गया था

संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले।

9. इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलें इस प्रकार हैं:

(i) संविधान सर्वोच्च है और सभी अंगों की शक्तियाँ हैं -

इसके तहत परिभाषित और नियंत्रित;

(ii) संसद की संशोधन करने की शक्ति इसके द्वारा सीमित है -

न्यायिक रूप से व्याख्या की गई बुनियादी संरचना की अवधारणा;

(iii) संविधान का अंतिम दुभाषिया और इसका दायरा

इसके तहत शक्तियाँ यह न्यायालय है;

(iv) न्यायपालिका की स्वतंत्रता और शक्तियों का पृथक्करण

बुनियादी संरचना का हिस्सा हैं;

(v) न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायपालिका की प्रधानता महत्वपूर्ण है।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता और शक्तियों के पृथक्करण का हिस्सा और इस प्रकार मूल संरचना का हिस्सा;

(vi) की नियुक्ति में कार्यपालिका और विधायिका की भूमिका

न्यायाधीशों को कम से कम रखना भी बुनियादी बातों का हिस्सा था

संरचना;

(vii) विवादित मामले में आयोग की संरचना

संशोधन न्यायपालिका की प्रधानता को नष्ट करके संविधान के मूल ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाता है

न्यायाधीशों की नियुक्ति और नियंत्रण की भूमिका देने में

ऐसी नियुक्तियों में कार्यपालिका और विधायिका को;

(viii) विवादित संशोधन रोकने में सक्षम बनाता है -

न्यायपालिका द्वारा प्रस्तावित न्यायाधीशों की नियुक्ति जब तक कि कार्यपालिका द्वारा सुझाए गए उम्मीदवार सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर. न हों।

इस प्रकार स्वतंत्रता से समझौता करते हुए नियुक्त किया गया

न्यायपालिका;

(ix) आक्षेपित संशोधन की शक्ति का विस्तार करता है

महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रत्यायोजित करके संशोधन

संसद में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो इसके खिलाफ है

संविधान की मूल संरचना;

(x) आयोग की संरचना हिल जाएगी।

न्यायपालिका में लोगों का विश्वास यदि कार्यपालिका या

विधायिका की प्रमुख आवाज होती है; और

(xi) विवादित अधिनियम विधायी क्षमता से परे है।

संसद से।

10. न्याय विभाग के संयुक्त सचिव ने दायर किया है

भारत संघ (यू. ओ. आई.) की ओर से एक जवाबी हलफनामा,

न्यायपालिका की स्वतंत्रता नियुक्ति के बाद ही होती है।
न्यायपालिका का

नियुक्ति एक कार्यकारी अधिनियम है और

स्वतंत्रता की कार्यकारी अधिनियम के साथ कोई प्रासंगिकता नहीं है
करता है कि न्यायिक स्वतंत्रता होनी चाहिए

नियुक्ति। यू. ओ. आई. प्रस्तुत

नियंत्रण और संतुलन के साथ और यह कि एक प्रासंगिक
 संविधान के साथ अनुच्छेद 124 (2) और 217 (1) को पढ़ना
 विधानसभा बहस (सीएडी) यह स्पष्ट करता है कि कोई नहीं है
 न्यायाधीशों की नियुक्ति में सीजेआई की प्रधानता। के साथ परामर्श
 सीजेआई केवल कार्यकारी पर एक चेक के माध्यम से था, जो था
 मामले में अंतिम कहना। इसके अलावा, परामर्श का प्रावधान अन्य न्यायाधीशों के साथ कॉलेजियम
 के निर्माण को उचित नहीं ठहराता है। यूओआई का
 प्रस्तुतिकरण हटाने के लिए महाभियोग प्रावधानों को संदर्भित करता है
 न्यायाधीश (अनुच्छेद 124 (4); संसद को विनियमित करने की शक्ति
 पता प्रस्तुत करने और जाँच करने की प्रक्रिया
 और न्यायाधीश के दुर्व्यवहार या अक्षमता का प्रमाण (अनुच्छेद
 124 (5)) और न्यायाधीशों के वेतन और प्रावधानों का निर्धारण करना न्यायिक कार्यप्रणाली के
 अन्य पहलुओं से संबंधित
 संसद को कानून बनाने की शक्ति (अनुच्छेद 125)। यू. ओ. आई. प्रस्तुत करता है कि द्वितीय न्यायाधीशों के
 मामले में इस न्यायालय के निर्णय और सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]
 न्यायपालिका की प्रधानता निर्धारित करने वाले तीसरे न्यायाधीशों के मामले में
 अनुच्छेद 124 (1) के तहत परामर्श प्रक्रिया का संदर्भ और
 217 (1) विवादित की वैधता का परीक्षण करने के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है
 99 वां संशोधन जिसके द्वारा अनुच्छेद 124 (2) के प्रावधान
 और 217 (1) को संशोधित किया गया है। हालांकि, यह तर्क दिया जाता है कि
 उक्त निर्णयों में यह विचार लिया गया है कि न्यायपालिका की प्रधानता है
 नियुक्ति में गलती है, और इसे फिर से देखने की आवश्यकता है। किसी भी मामले में
 ओ. आई. का तर्क है कि न्यायपालिका की प्रधानता
 उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति का कोई मामला नहीं है

मामले में, यू.

न्यायपालिका की स्वतंत्रता के साथ संबंध और बुनियादी नहीं है

ऑस्ट्रेलिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की प्रधानता के बिना मौजूद है उच्च न्यायपालिका में
न्यायाधीशों की नियुक्तियों में न्यायपालिका।

यू. ओ. आई. प्रस्तुत करता है कि संसद को अधिनियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है

विनियम बनाने में संसद के प्रति उत्तरदायी। द. एन. जे. ए. सी. के सदस्य के रूप में कानून मंत्री की
उपस्थिति सुनिश्चित करती है

जनता के प्रति उत्तरदायित्व। दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति

न्यायपालिका के कामकाज में। एनजेएसी के अंतर्गत आएका सूचना का अधिकार अधिनियम,
2005 की परिधि जो यह सुनिश्चित करेगी कि

पारदर्शिता। भले ही संशोधन को निरस्त कर दिया गया हो, मूल

संवैधानिक संशोधनों पर लागू होता है। इस मुद्दे को उठाया गया संपत्ति मालिक संघ बनाम
महाराष्ट्र राज्य

संविधान के अनुच्छेद 31 सी के संबंध में जो लंबित है

नौ न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि रिट याचिका पूर्व-परिपक्व है
क्योंकि नई प्रणाली को एक नहीं दिया गया है

संचालन का अवसर और कोई अधिकार प्रभावित नहीं हुए हैं।

11. उत्तरदाताओं की ओर से तर्क हो सकते हैं -

4 (1996) 4 एस. सी. सी. 49 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

इस प्रकार ध्यान दें:

(क) न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति के साथ रहता है -

कार्यपालिका और न्यायपालिका की भूमिका इन तक सीमित है -

परामर्श जिसे स्वीकार किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है
कार्यपालक;

(ख) नियुक्तियों में न्यायपालिका की प्रधानता को मान्यता दी गई।

अपरिवर्तित प्रावधानों की गलत व्याख्या द्वारा

संविधान का और ऐसे संशोधन के माध्यम से

व्याख्या को सही किया गया है और इस प्रकार कोई नहीं है

मूल संरचना का उल्लंघन। वैकल्पिक रूप से बड़ी बेंच

पहले की व्याख्या को सही करने के लिए गठित किया जाए;

(ग) नियुक्तियों में न्यायपालिका की प्रधानता नहीं थी।

अपरिहार्य और बदली हुई स्थिति में, के प्रकाश में
अनुभव, प्रधानता को दूर किया जा सकता है

प्राप्त

के साथ या संशोधित;

(घ) चुनाव करने में घटक निकाय की बुद्धिमत्ता थी

न्यायिक समीक्षा के लिए खुला नहीं है;

(ई) संविधान को समग्र रूप से लेते हुए,

न्यायपालिका की स्वतंत्रता को अन्य के साथ संतुलित किया जा सकता है
लोकतंत्र के संवैधानिक मूल्य, जवाबदेही और

नियंत्रण और संतुलन;

(च) संशोधन की शक्ति पूर्ण थी और नहीं हो सकती थी

पूछताछ की जाती है जब तक कि इसके परिणामस्वरूप एक स्तंभ का विनाश न हो
संविधान;

(छ) भले ही शक्ति कार्यकारी या शक्ति के साथ हो

कार्यपालिका के साथ वीटो होना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता

जब तक न्यायाधीशों के कार्यकाल और सेवा शर्तों का संरक्षण था, तब तक जीवित रह सकता था।

(ज) प्रत्येक राज्य के कामकाज में जवाबदेही और पारदर्शिता।

संवैधानिक अंग लोकतंत्र का हिस्सा था जिसमें

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन के साथ न्यायाधीशों की नियुक्ति की विशेष शक्ति। यू.
ओ. आई. [आदर्श कुमार गोएल, जे. जे.

न्यायपालिका अलोकतांत्रिक थी;

(i) आक्षेपित संशोधन ने प्रधानता बरकरार रखी है

छह में से तीन सदस्य, जिनमें से दो रुक सकते थे
 एक अवांछनीय नियुक्ति। कार्यपालक ने नहीं किया
 दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई है
 प्रधानमंत्री की एक समिति द्वारा नियुक्त,
 सीजेआई और विपक्ष के नेता की भूमिका
 प्रधानमंत्री सीमित हैं। कानून मंत्री और
 सदस्यों के रूप में प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने प्रासंगिक प्रतिक्रिया देना और जवाबदेही सुनिश्चित करना
 सुनिश्चित किया और
 पारदर्शिता ;

(जे) को शक्ति प्रदान करने में विवादित संशोधन

प्रक्रियात्मक रूप में संसद और केंद्र सरकार

मामलों ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं किया; और

(के) विवादित अधिनियम विधायी क्षमता के भीतर था

संसद से।

12. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री फली एस. नरीमन ने इसका नेतृत्व किया।

मुख्य याचिका में याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलें

इसके बाद एस/श्री राम जेठमलानी, अनिल बी. दीवान, के. एन. भट्ट,

अरविंद दातार, डॉ. राजीव धवन, विद्वान वरिष्ठ वकील और व्यक्तिगत रूप से या मध्यस्थ के रूप में
 उपस्थित होने वाले अन्य वकील या

अन्यथा। विद्वान वकील ने उनका विरोध किया है।

जनरल श्री मुकुल रोहतगी, विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री

रंजीत कुमार और एस/श्री के. परासरन, सोली जे. सोराबजी, के. के. वेणुगोपाल, हरीश एन. साल्वे, टी.
 आर. अंधारुजिना, दुष्यंत दवे

विद्वान वरिष्ठ परामर्शदाता और विभिन्न क्षेत्रों के लिए अन्य विद्वान परामर्शदाता

राज्य और हस्तक्षेपकर्ता या अन्यथा। मैं अपना आभार दर्ज करता हूँ

न्यायालय को उनकी श्रमसाध्य सहायता के लिए विद्वान वकील

महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए अपनी असाधारण क्षमता और कौशल के साथ

विचार के लिए उत्पन्न होने वाले मुद्दे। उनकी दलीलें होंगी

आवश्यक सीमा तक उचित स्तर पर निर्दिष्ट किया जाता है।

13. जबकि आम तौर पर दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों के पास सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर. है।

राज्य की ओर से पेश हुए श्री वेणुगोपाल ने भी ऐसा ही रुख अपनाया

एम. पी. का, जो अन्यथा संशोधन का समर्थन कर रहा है, अपने

14 जुलाई, 2015 को अतिरिक्त प्रस्तावों के माध्यम से दायर वैकल्पिक प्रस्तुति, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार प्रस्तुत की गई:

"3 99 वें संशोधन की योजना को देखते हुए और

राष्ट्रीय न्यायिक आयोग नियुक्ति अधिनियम,

2014 (एन. जे. ए. सी. अधिनियम), विकसित योजना के लिए प्रदान करता है

6 सदस्यीय आयोग का गठन और

अनुच्छेद 124-सी, के तहत प्रदान की जाने वाली प्रक्रिया के लिए

संसद द्वारा बनाया गया कानून। एन. जे. ए. सी. अधिनियम में निश्चित है

धारा 5 (2) के अनुसार, 'वीटो' की प्रकृति का एक प्रावधान, कोई नियुक्ति नहीं की जा सकती है यदि दो सदस्य

आयोग उस नियुक्ति से सहमत नहीं है। यह

याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रावधान को 99 वें के रूप में चुनौती दी गई है

संशोधन अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और छह में से दो द्वारा 'वीटो' का प्रावधान करना, जैसा कि यह था

सदस्यों को संशोधन के अधिकार से बाहर बताया गया है

अधिनियम या, किसी भी मामले में, प्रक्रिया का विषय नहीं है।

4 यह प्रस्तुति निम्नलिखित के लिए सही प्रतीत होती है।

कारण:

ए। न्यायपालिका की 'प्रधानता' का सिद्धांत, जो एक है

न्यायिक स्वतंत्रता का हिस्सा, अनिवार्य रूप से पढ़ा जाना चाहिए

एन. जे. ए. सी. अधिनियम में भी। के लिए प्रावधान करने वाला कोई भी अधिनियम प्रक्रिया संवैधानिक अधिकार के बाहर होगी प्रावधान यदि यह आवश्यकता को पूरा नहीं करता है प्रधानता। इसलिए 'बीटो' प्रावधान स्पष्ट रूप से है 'प्रधानता' की अवधारणा के विरोधी और होना चाहिए संशोधन को अधिकार से बाहर होने के रूप में खारिज कर दिया गया।

XXXXXX

XXXXXX

XXXXX

6. नौ न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के बावजूद, सर्वोच्च न्यायालयों के मामले में कानून में कुछ अवधारणाएं मौजूद हैं-ऑन-रिकॉर्ड

एस. एस. ओ. सी. एशन वी. यू. ओ. आई. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

लोकतंत्र में न्यायपालिका का कार्यकरण। द.

एक स्वतंत्र न्यायपालिका का अस्तित्व अनिवार्य है।

लोकतंत्र के विकास के लिए। यहाँ, हम चिंतित हैं

उच्च पदों पर न्यायाधीशों की नियुक्ति का मुद्दा

न्यायपालिका। चाहे, शक्ति कार्यकारी हो या नहीं, यह

यह नहीं कहा जा सकता है कि यह प्रभावित करता है स्वतंत्रता कार्यपालिका के मामले में न्यायपालिका की

विशेष रूप से नियुक्त करने की शक्ति होनी थी

न्यायाधीशों। नियुक्ति की ऐसी प्रणाली के परिणामस्वरूप हो सकता है

उन न्यायाधीशों को अस्तित्व में लाना जो अधीन हैं

सरकार की इच्छा, जो एक प्रमुख होगी

न्यायालयों में वादी। इसलिए स्वतंत्रता होगी

प्रभावित रहें।

7. यदि 'वीटो' अमान्य है, तो सामान्य कानून सिद्धांत

बहुमत लागू होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश और

दो अन्य न्यायाधीशों के पास इस मामले में विशेषज्ञता है

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों का चयन और

क्षमता के कार्यकरण का पूर्ण ज्ञान

उम्मीदवार। हालांकि, तीनों का सर्वसम्मत दृष्टिकोण

यदि दूसरे द्वारा विरोध किया जाता तो न्यायाधीश उस दिन को नहीं ले जाते

तीन सदस्य। प्रत्येक अन्य मामले में, जहां सभी छह हैं

एक उम्मीदवार पर सहमति में, बनाने में कोई समस्या नहीं

सही निर्णय लिया जाएगा। असली सवाल, इसलिए, यह स्थिति क्या होगी यदि गतिरोध हो

यह तब उत्पन्न होता है जब तीनों न्यायाधीशों का सर्वसम्मत निर्णय अन्य तीन सदस्यों ने इसका विरोध किया। अनावश्यक है।

राज्य, कि यदि तीन न्यायाधीश एक पर विज्ञापन नहीं हैं उम्मीदवार, कोई 'प्रधानता का मुद्दा' उत्पन्न नहीं होगा और

बहुमत की जीत होगी।

8. यह सच है कि नौ न्यायाधीशों का मामला अब और नहीं चल सकता है

99 वें को रद्द करने के उद्देश्य से क्षेत्र

संशोधन, जो, जाहिर है, के साथ असंगत है

कॉलेजियम प्रणाली नौ न्यायाधीशों [2015] 13 एस. सी. आर. द्वारा विकसित की गई।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निर्णय। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सिद्धांत

उक्त निर्णय द्वारा प्रतिपादित एक न्यायिक सिद्धांत के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता है जो होगा

ऐसे मामलों में लागू होता है। दूसरे शब्दों में, ये

सिद्धांतों को आने वाले सभी समय के लिए प्रासंगिक कहा जा सकता है। निम्नलिखित कारणों से:

ए। नियुक्ति की शक्ति का उपयोग प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है

या नियुक्त व्यक्तियों की स्वतंत्रता को नष्ट कर दें।
जब वरिष्ठ के सदस्यों के रूप में कार्य करते हैं

न्यायपालिका।

बी। नियुक्ति की एक प्रणाली जहाँ कार्यपालक

आवाज प्रबलता इस तरह को प्रभावित करेगी

स्वतंत्रता।

सी। यदि तथापि, भारत के मुख्य न्यायाधीश की आवाज,

न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करना प्रबल है, यहां तक कि एक

खेलने के लिए एक छोटा सा हिस्सा, यह फिर भी नहीं होगा
स्वतंत्रता को प्रभावित करता है और दूसरी ओर

स्वतंत्रता की सेवा करेंगे। दूसरे शब्दों में,
नियुक्ति के मामले में प्रधानता होनी चाहिए

न्यायपालिका के साथ।

XXXXX

XXXXX

XXXXX

11. ये सामान्य सिद्धांत हैं जो

स्वतंत्रता की अवधारणा पर आधारित सर्वोच्च न्यायालय

न्यायपालिका से। यह अवधारणा सर्वव्यापी है और जब भी वह स्थिति उत्पन्न होती है, न्यायालय,

जिस तरह से उसने दूसरे न्यायाधीशों के मामले में किया था,

वर्तमान अनुच्छेद 124-ए की व्याख्या करें। इसका मतलब यह होगा कि

कि स्वतंत्रता का सिद्धांत अंतर्निहित है उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति

यह आवश्यक है कि तीन न्यायाधीशों के विचार

आयोग, एकल आवाज के साथ बोलने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड होंगे।

एस. एस. ओ. सी. एशन वी. यू. ओ. आई. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

प्रधानता। यह परिणाम नहीं होगा क्योंकि

द्वितीय न्यायाधीशों के मामले में निर्णय बाध्य करेगा

न्यायालय लेकिन क्योंकि न्यायिक की अवधारणा

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की संख्या लागू होगी
जहाँ नहीं

जहाँ भी और जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई

संविधान में स्पष्ट प्रावधान ने प्रधानता दी

न्यायिक शाखा। ऐसे मामलों में, की वैधता

ठीक उसी आधार पर जब अवधारणा विकसित की गई थी
नतीजतन, 99 वां

दूसरे न्यायाधीशों के मामले में।

संविधान में संशोधन, हमेशा होगा

संविधान का एक वैध अभ्यास माना जाता है

शक्ति। 'वीटो' के अस्तित्व के अभाव में, यदि

तीन न्यायाधीश एक ही आवाज़ में बोलते हैं, उनका निर्णय

प्रबल होंगे। राष्ट्रपति को तब जारी करना होगा

नियुक्ति का आदेश।

XXXXX XXXX

XXXXX

उपरोक्त के अलावा, याचिकाकर्ताओं ने भी

16.

तर्क दिया कि 'प्रतिष्ठित व्यक्ति' शब्द बहुत व्यापक है

और यह कि प्रतिष्ठित व्यक्तियों की नियुक्ति जिन्होंने

कानून से कोई लेना-देना नहीं है और जो न्यायिक प्रणाली के काम करने के बारे में नहीं जानते हैं, उनके
परिणामस्वरूप उल्लंघन होगा

न्यायिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। का नियम

इस प्रावधान पर 'उद्देश्यपूर्ण व्याख्या' लागू की जा सकती है।

इस नियम को लागू करके, न्यायालय व्याख्या कर सकता है

प्रतिष्ठित व्यक्तियों का अर्थ केवल कानून में प्रशिक्षित व्यक्ति होना है '

या 'प्रख्यात न्यायविद' (इस संबंध में देखें, पी. वैकुण्ठ शेनॉय बनाम. पी. हरि शर्मा (2007) 14 एससीसी 297 @पारस 11-13 और वीसी शुक्ला बनाम। राज्य (दिल्ली आम.) (1980 सप.

एससीसी 249 @पैरा 28) "

मुद्दा

14. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि एक संवैधानिक [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संशोधन तभी वैध हो सकता है जब यह संविधान की मूल संरचना के अनुरूप हो, जो विचार के लिए मुख्य मुद्दा है।

यह है कि क्या आक्षेपित संशोधन उक्त मूल संरचना को बदलता है या नुकसान पहुंचाता है और उस आधार पर शून्य है। के अनुसार

याचिकाकर्ता न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायपालिका की प्रधानता

और उसमें कार्यपालिका द्वारा हस्तक्षेप की अनुपस्थिति अपने आप में है।

संविधान की मूल विशेषता का एक हिस्सा जिसका अभिन्न अंग है

न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायपालिका को उससे अलग करना

कार्यकारी। उत्तरदाताओं के अनुसार न्यायपालिका की प्रधानता

न्यायाधीशों की नियुक्ति में स्वतंत्रता का हिस्सा नहीं है

न्यायपालिका। यहां तक कि जब नियुक्तियां कार्यपालिका द्वारा की जाती हैं,

न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होती है। वैकल्पिक रूप से

संशोधित योजना, न्यायपालिका की प्रधानता बरकरार रखी जाती है और

न्यायपालिका की स्वतंत्रता को मजबूत किया जाता है। संशोधन

मौलिक विशेषता की अवधारणा जो संशोधन शक्ति को नियंत्रित करती है निर्णय की ओर ले जाएगी

संसद से। यह समझ

क्या न्यायपालिका की प्रधानता और कार्यपालिका की अनुपस्थिति

न्यायाधीशों की नियुक्ति में हस्तक्षेप इस तरह के बुनियादी प्रावधानों का हिस्सा है

संरचना।

चर्चा.

ए. बुनियादी विशेषताओं की अवधारणा-सीमा के रूप में

संसद की संशोधन करने की शक्ति

संविधान

15. संविधान का अनुच्छेद 368 शक्ति प्रदान करता है -

संविधान और उसके लिए प्रक्रिया में संशोधन करना। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (केशवानंद) भारती मामले), शक्ति संशोधन के दायरे में चला गया था

13 न्यायाधीशों की पीठ। 9 द्वारा हस्ताक्षरित समापन पैरा में

न्यायाधीशों ने यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 सक्षम नहीं करता है

5 1973 (4) एस. सी. सी. 225 सर्वोच्च न्यायालय

अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

संसद द्वारा संविधान की मूल संरचना या ढांचे में परिवर्तन करना। निष्कर्ष की व्याख्या पर आधारित था

शब्द 'संशोधन'। यह देखा गया कि शब्द था

व्यापक के साथ-साथ संकीर्ण अर्थ में सक्षम और जबकि व्यापक अर्थ को प्राथमिकता दी जानी थी लेकिन इरादे के अनुरूप

संविधान निर्माताओं और संदर्भ। नहीं दिया जा सका

बहुत व्यापक अर्थ ताकि संवैधानिक क्षति की अनुमति दी जा सके

ऐसे मूल्य जो संविधान की पहचान को दर्शाते हैं। 6

15.1 बुनियादी संरचना या ढांचा नहीं था

गोवर, हेगड़े, मुखर्जी, रेड्डी और खन्ना, जेजे। दृष्टांत लोकतांत्रिक

उनके द्वारा संविधान की सर्वोच्चता शामिल है,

सरकार का रूप, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, न्यायपालिका, कार्यपालिका और सरकार के बीच शक्तियों का पृथक्करण विधानमंडल, संविधान का संघीय चरित्र, गरिमा

के अनुसार बुनियादी अधिकारों द्वारा सुरक्षित व्यक्ति का

भाग III और IV, राष्ट्र की एकता और अखंडता।

15.2 यह अभिनिर्धारित किया गया कि संसद की संशोधन करने की शक्ति संविधान इस आवश्यकता से सीमित था कि बुनियादी संविधान की नींव और संरचना समान है। की चुनौती का सामना करने के लिए संशोधन की शक्ति की परिकल्पना की गई थी सामाजिक आर्थिक विकास के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याएं देश की प्रगति पर विचार किया गया लेकिन यह कभी नहीं सोचा गया कि संशोधन की कुछ अपरिहार्य शक्तियों का प्रयोग संविधान की विशेषताओं में बदलाव किया जाएगा। न्यायालय ने विभिन्न क्षेत्राधिकारों में विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया संविधान के संशोधन का दायरा। सी. जे. सीकरी। देखा गया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व को ध्यान में रखते हुए और आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय का महत्व, * 6 (पैरा 284, सीकरी, सी. जे.); (पैरा 583, शेल्ट एंड ग्रोवर, जे. जे.); (पैरा 651 हेगड़े और मुखर्जी, जे. जे.); (पैरा 1162, रेड्डी जे.) और (पैरा 1426, खन्ना जे.) 7 पैरा 292, 582, 666, 1159, 1426 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द "संशोधन" नहीं हो सका इसे व्यापक अर्थों में पढ़ें। मौलिक अधिकार हो सकते हैं अस्तित्व से बाहर संशोधित नहीं किया जाएगा। धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और व्यक्ति की स्वतंत्रता की बुनियादी विशेषताएँ होनी चाहिए। हमेशा जीवित रहें। "संशोधन" अभिव्यक्ति की सीमा थी अर्थ। अन्यथा दो-तिहाई बहुमत वाला राजनीतिक दल संविधान में ऐसा संशोधन कर सकता है कि किसी अन्य दल पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। कार्य करने से, अधिनायकवाद स्थापित करें और गुलाम बनाएँ लोग और उसके बाद संविधान को अपरिवर्तनीय बनाते हैं। लोकतांत्रिक सिद्धांत। इस प्रकार, संशोधन का अर्थ था जोड़ या प्रस्तावना के व्यापक रूप के भीतर परिवर्तन

संविधान। संसद मौलिक को समायोजित कर सकती है
निदेशक सिद्धांतों के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के अधिकार, जबकि
न केवल प्रस्तावना से बल्कि पूरी योजना से संविधान। शेल्ट एंड ग्रोवर, जे. जे. उन्होंने कहा कि
संविधान
निर्माता नहीं चाहते थे कि नागरिक बुनियादी सुविधाओं का आनंद न लें
स्वतंत्रता, समानता, धर्म की स्वतंत्रता आदि ताकि
एक व्यक्ति को रखा जाता है। आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन
व्यक्ति की गरिमा को खोए बिना बनाया जाना था।
भाग III या भाग IV के महत्वपूर्ण प्रावधानों में कटौती नहीं की जा सकी या
उनकी पहचान का अपमान किया। हेगड़े और मुखर्जी, जेजे. देखा गया
कि संशोधन की शक्ति संसद को प्रदान की गई थी।
इस तरह के लोग संशोधन से जुड़े नहीं थे। द. संविधान लोगों द्वारा स्वयं को दिया गया था। आवाज़.
संविधान सभा के सदस्यों की आवाज थी लोगों से। दोनों सदनों के दो-तिहाई सदस्य
जरूरी नहीं कि संसद ने भी बहुमत का प्रतिनिधित्व किया हो।
लोगों को। इस प्रकार, दोनों सदनों के दो-तिहाई सदस्य
संसद सर्वोच्च न्यायालय के सभी लोगों की ओर से नहीं बोल सकी

अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

देश 3. यहां तक कि सबसे अच्छी सरकार भी इसके खिलाफ नहीं थी
अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए अधिक से अधिक शक्तियां हैं, जिन्हें वे जनहित में
मानते हैं, लेकिन एक बार खो जाने के बाद स्वतंत्रता शायद ही फिर से प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक
स्वतंत्रता का अतिक्रमण आगे के लिए एक पैटर्न निर्धारित करता है
अतिक्रमण। बिना विकास की परिकल्पना की गई थी व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का विनाश। रेड्डी, जे. ने
देखा कि यदि कोई हो
आवश्यक विशेषताओं में से बदल दिया गया था, संवैधानिक

संरचना अपनी पहचान बनाए नहीं रख सकी। नहीं हो सकता है।

लोकतंत्र के बिना न्याय, स्वतंत्रता या समानता हो सकता है कि

न्याय, समानता और स्वतंत्रता के बिना कोई लोकतंत्र नहीं है। संरचना

संविधान एक जैविक उपकरण था। मूल।

स्वतंत्रता के संघर्ष में। वे शामिल थे उम्मीद है कि एक दिन भारत में लोगों की जीत होगी। वे.

भारत के भविष्य, वर्तमान और अतीत को जोड़ें। की मांग

मौलिक अधिकारों की प्रेरणा मैग्ना कार्टा में थी, अंग्रेजी बिल ऑफ राइट्स, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी बिल

अमेरिकी संविधान में शामिल अधिकार। इसका उल्लेख करते हुए डॉ. अम्बेडकर का कथन कि अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा थी

संविधान और इसके मूल में, यह देखा गया कि इस तरह

किसी अनुच्छेद को संशोधन द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता था। खन्ना,

जे. ने कहा कि संशोधन के परिणामस्वरूप, पुराना संविधान

इसे दूर नहीं किया जा सका। ढांचे की बुनियादी संरचना

बनाए रखा जाना चाहिए। नींव को छूने की अनुमति नहीं थी।

या बुनियादी संस्थागत स्वरूप को बदलना। क्या संशोधन किया जा सकता है क्या मौजूदा संविधान है और इसके परिणामस्वरूप क्या उभरना चाहिए

संशोधन एक नया और अलग संविधान नहीं है लेकिन

मौजूदा संविधान। संशोधन द्वारा क्या विचार किया गया था

यहाँ और वहाँ संविधान में भिन्नता थी और इसकी मूल संरचना को समाप्त नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप इसकी पहचान खो गई थी।

15.3 विचार किए गए प्रश्नों में से एक की वैधता थी

* पैरा 652 और 653 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

पञ्जीसवां संशोधन अधिनियम, 1971 की धारा 3

अनुच्छेद 31-सी इस प्रकार है:

" 416. पँचिशवें संशोधन की धारा 3 इस प्रकार है:

3. संविधान के अनुच्छेद 31 बी के बाद, निम्नलिखित लेख जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

31. ग. अनुच्छेद में कुछ भी निहित होने के बावजूद

13, राज्य की नीति को प्रभावी बनाने वाला कोई कानून नहीं

खंड में निर्दिष्ट सिद्धांतों को सुरक्षित करने की दिशा में

(बी) या अनुच्छेद 39 के खंड (सी) को माना जाएगा

यह इस आधार पर शून्य है कि यह अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार के साथ असंगत है, या छीनता है या कम करता है।

14, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 31; और ऐसा कोई कानून नहीं जिसमें

घोषणा करें कि यह ऐसी नीति को प्रभावी बनाने के लिए है जमीन पर किसी भी अदालत में प्रश्न में बुलाया जाएगा

कि यह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं करता है:

" बशर्ते कि जहां ऐसा कानून विधायिका द्वारा बनाया जाता है

इस अनुच्छेद के प्रावधान किसी राज्य में लागू नहीं होंगे।

जब तक कि ऐसा कानून, के लिए आरक्षित नहीं किया गया है

राष्ट्रपति के विचार को उनकी सहमति मिल गई है।

हाइलाइट किया गया हिस्सा बहुमत द्वारा आयोजित किया गया था

असंवैधानिक, चुनौती से प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए जिससे न्यायिक समीक्षा की मूल विशेषता प्रभावित हो 9 9 पैरा 1535 ए। (खन्ना, जे.) मेरी राय में, अनुच्छेद 31-सी का दूसरा भाग निम्नलिखित आधारों पर रद्द किया जा सकता है:

(1) यह विधानमंडल को किसी भी कानून को अनुच्छेद 14, 19 और 31 का उल्लंघन करने वाला बनाने और आवश्यक घोषणा को सम्मिलित करके इसे हमले से मुक्त बनाने के लिए एक कार्टे ब्लैंच देता है। अनुच्छेद 31-सी अपने दूसरे भाग के साथ प्रभावी रूप से राज्य विधानमंडल सहित विधानमंडल को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है।

(2) विधायिका को यह तय करने का अंतिम अधिकार दिया गया है कि उसके द्वारा बनाया गया कानून अनुच्छेद 31-सी में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए है या नहीं। अनुच्छेद 31-सी के दूसरे भाग का दोष इस तथ्य में निहित है कि भले ही अधिनियमित कानून अनुच्छेद 31-सी में उल्लिखित उद्देश्य के लिए नहीं है, विधानमंडल द्वारा की गई घोषणा एक पक्ष को यह दिखाने से रोकती है कि कानून उसके लिए नहीं है।

एक अदालत को इस सवाल में जाने से रोकता है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय

अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

15.4 शक्ति में संशोधन का दायरा फिर से था

तीस को चुनौती देने के क्रम में इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया

नौवां संशोधन जिसने चुनाव के लिए किसी भी चुनौती को प्रतिबंधित कर दिया

इंदिरा नेहरू गाँधी में प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष

बनाम राज नारायण 1. चंद्रचूड़, जे. (बाद में मुख्य न्यायाधीश)

यह देखा गया कि ऐसा नहीं है कि केवल कुछ नामित विशेषताएँ हैं

संविधान इसकी मूल संरचना का हिस्सा है। नाम की विशेषताएँ

चित्रण और उनका उद्देश्य संपूर्ण होना नहीं था। होने के नाते
के संबंध में, इसका उद्देश्य

संविधान की योजना में इसके स्थान

और उद्देश्य और अखंडता पर इसके इनकार के परिणाम

संविधान की एक विशेषता को एक बुनियादी विशेषता माना जा सकता है। उन्होंने कहा कि निस्संदेह
अपरिवर्तनीय

बुनियादी विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

“(i) भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य है; (ii)

स्थिति और अवसर की समानता सुनिश्चित की जाएगी

(iii) राज्य का कोई धर्म नहीं होगा -

इसके अपने और सभी व्यक्ति समान रूप से हकदार होंगे

अनुच्छेद 31-सी के दूसरे भाग को अनुच्छेद 31-सी के शेष भाग से अलग किया जा सकता है और इसकी
अयोग्यता शेष भाग की वैधता को प्रभावित नहीं करेगी। इसलिए, मैं अनुच्छेद 31-सी में निम्नलिखित शब्दों को
हटा दूंगा: “और यह घोषणा रखने वाली कोई भी विधि जो ऐसी नीति को प्रभावी बनाने के लिए
है, किसी भी न्यायालय में इस आधार पर प्रश्न में नहीं रखी जाएगी कि वह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं करती
है।

10 (1975) सप. एससीसी 1

11 अनुच्छेद 663-यह निर्धारित करने के लिए कि क्या संविधान की कोई विशेष विशेषता इसकी मूल
संरचना का हिस्सा है, प्रत्येक व्यक्ति के मामले में हमारे संविधान की योजना में विशेष विशेषता के स्थान, इसके

उद्देश्य और उद्देश्य और देश के शासन के एक मौलिक साधन के रूप में संविधान की अखंडता पर इसके इनकार के परिणामों की जांच करने के लिए बल है। लेकिन इन अपीलों के उद्देश्य के लिए मूल संरचना की ईंटों की खोज के लिए संविधान के हर नुक्कड़ पर तोड़फोड़ करने की आवश्यकता नहीं है। जो बहुमत के निर्णयों में गिने जाते हैं, वे इतने बड़े होते हैं कि

श्री शांति भूषण की चुनौती की आवश्यकताएँ।

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विवेक की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से स्वीकार करने का अधिकार,

धर्म का पालन और प्रचार करना और यह कि (iv) राष्ट्र

कानून की सरकार द्वारा शासित किया जाएगा न कि पुरुषों की।

39 अन्य बातों के साथ-साथ चुनाव को चुनौती देने से इनकार करने वाला संशोधन

प्रधान मंत्री को संविधान की बुनियादी विशेषताओं के खिलाफ होने के कारण खारिज कर दिया गया था। 1 2 अनुच्छेद 329 क, खंड (4) (के माध्यम से जोड़ा गया)

संशोधन) बशर्ते कि चुनाव कानून लागू नहीं होगा

प्रधानमंत्री और अध्यक्ष का पद धारण करने वाला व्यक्ति और इस तरह का चुनाव

ऐसे किसी भी कानून के तहत व्यक्तियों को शून्य नहीं माना जाएगा। यह. यह माना गया था कि लोकतंत्र मूल संरचना का हिस्सा था

जिसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर विचार किया गया। इसके बिना

एक चुनाव विवाद को हल करने के लिए मशीनरी, चुनाव कर सकते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगा जो बदले में मूल विशेषता को नुकसान पहुंचाएगा

लोकतंत्र से। की वैधता से निपटने के लिए किसी भी कानून के अभाव में

प्रधानमंत्री का चुनाव, कानून के शासन की मूल विशेषता का उल्लंघन किया जाएगा।

"द फेडरलिस्ट" में मैडिसन के लेखन का उल्लेख करते हुए, यह था

यह देखा गया कि सरकार की सभी शक्तियों को निहित नहीं किया जा सकता है

एक विभाग में। कोई भी संविधान इसके बिना नहीं रह सकता था।

नियंत्रण और संतुलन का पालन "। जिस तरह अदालतों को नहीं करना चाहिए "राजनीतिक झंझट" में उलझी समस्याओं में प्रवेश करना,

संसद को न्यायालयों के संरक्षण का भी सम्मान करना चाहिए।

15.5. 42 वें संशोधन की वैधता थी

इस न्यायालय द्वारा मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम मिनर्वा मिल्स लिमिटेड मामले में विचार किया गया। संघ का

भारत 14. न्यायालय ने धारा 4 और 55 की वैधता पर विचार किया।

42 वाँ संशोधन अधिनियम। धारा 4 द्वारा, अनुच्छेद 31 सी था यह प्रावधान करने के लिए संशोधन करने की मांग की गई कि प्रभावी कानून

संविधान के भाग IV को अमान्य नहीं माना जा सकता था क्योंकि

अनुच्छेद 14, 19 और 31 के साथ असंगत होना और नहीं कर सका

इस आधार पर चुनौती दी जाए कि उक्त कानून देने के लिए नहीं था 12 खन्ना और मैथ्यू, जे. जे. ने माना कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र के लिए आवश्यक था और यह बुनियादी ढांचे का हिस्सा था। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ का मानना था कि समानता का अधिकार मूल संरचना का हिस्सा था जिसका उल्लंघन किया गया था। सीजे रे ने माना कि कानून का शासन संविधान की मूल संरचना है जिसका उल्लंघन किया गया है। 13 पैरा 688

144 (1980) 3 एस. सी. सी. 625 शीर्ष अदालतें-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

उक्त भाग IV का प्रभाव। धारा 55 द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि संविधान के किसी भी संशोधन को किसी भी मामले में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

आधार और यह कि घटक पर कोई सीमा नहीं होगी संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति। यह न्यायालय

यह देखा गया कि संविधान ने सीमित संशोधन प्रदान किया था संसद पर शक्ति जो स्वयं एक बुनियादी विशेषता थी

संविधान। संसद अपने संशोधन का विस्तार नहीं कर सकी।

शक्ति ताकि उक्त मूल विशेषता को नष्ट किया जा सके

संविधान। सीमित शक्ति को परिवर्तित नहीं किया जा सका असीमित। अनुच्छेद 368 के खंड 4 और 5 को चालीस द्वारा जोड़ा गया

दूसरा संशोधन मूल के उल्लंघन के रूप में निरस्त कर दिया गया था

संविधान की संरचना। यह देखा गया कि संतुलन

संविधान के भाग III और भाग IV के बीच संविधान की मूल विशेषता थी। की सीमित संशोधन शक्ति संसद भी मूल संरचना का हिस्सा थी। 16 यह भी आयोजित किया गया था वह न्यायिक समीक्षा यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई कानून देना था भाग IV के प्रभाव को बाहर नहीं किया जा सका क्योंकि न्यायिक समीक्षा की गई थी मूल संरचना का हिस्सा। 17 यह भी देखा गया कि हालांकि तीन विभागों में शक्तियों का कोई कठोर विभाजन नहीं है राज्य-कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका, व्यापक सीमांकन है। तीनों अंगों के बीच ठीक संतुलन बिगड़ नहीं सकता क्योंकि यह मूल अंगों को नष्ट कर देगा। एक लोकतांत्रिक सरकार का आधार। न्यायपालिका को सौंपा गया है कार्यपालिका और विधानमंडल को भीतर रखने के कर्तव्य के साथ उन्हें प्रदान की गई शक्ति की सीमाएँ जो एक बुनियादी भी है संविधान की विशेषता। 18

15.6. एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ 19, भाग अनुच्छेद 323-ए (2) (डी) और 323-बी (3) (डी) की सीमा तक निर्दिष्ट के संबंध में उच्च न्यायालयों की अधिकारिता को बाहर रखा गया वे मामले जिनके लिए न्यायाधिकरणों को अधिकारिता प्रदान की गई थी 16 पारस 17 और 88 17 पारस 12,88 18 पारस 21,86 और 87 19 (1997) 3 एस. सी. सी. 261 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

मूल संरचना के उल्लंघन के रूप में मारा गया। न्यायपालिका की शक्ति इस न्यायालय और उच्च न्यायालयों को प्रदान की गई समीक्षा आयोजित की गई थी पहले की दृष्टि से संवैधानिक योजना का अभिन्न अंग होना

निर्णय लेना और दूसरे को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करना।

न्यायिक निकाय उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के बहिष्करण को उचित नहीं ठहरा सका। 20

15.7. आई. आर. कोएल्हो बनाम। तमिलनाडु राज्य 21, पीठ

नौ न्यायाधीशों की न्यायिक समीक्षा का दायरा माना जाता है

संविधान द्वारा नौवीं अनुसूची में एक कानून का समावेश

संशोधन जिससे चुनौती से प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है

संविधान का अनुच्छेद 31 बी। यह माना गया था कि ऐसे सभी

संशोधन का टचस्टोन पर परीक्षण करना होगा

संविधान की आवश्यक विशेषताएं जिनमें वे शामिल हैं जो अनुच्छेद 14, 19 और 21 में परिलक्षित होती हैं और अंतर्निहित सिद्धांत

उन्हें। इस तरह के संशोधन इस आधार पर हमले से अछूते नहीं हैं कि वे बुनियादी संरचना को नष्ट या नुकसान पहुंचाते हैं। द.

न्यायालय 'अधिकार परीक्षण' और 'अधिकारों का सार' लागू करेगा।

संविधान के भाग III में अनुच्छेदों का संक्षिप्त दृष्टिकोण लेते हुए परीक्षण।

यह भी कहा गया कि न्यायालय का मार्गदर्शन किया जाना चाहिए

'प्रभाव परीक्षण' यह निर्धारित करने में कि क्या एक बुनियादी विशेषता थी

उल्लंघन किया गया। न्यायालय पहले यह निर्धारित करेगा कि क्या इसका उल्लंघन हुआ है

विवादित संशोधन द्वारा भाग III में अधिकार, संविधान की मूल संरचना पर इसका प्रभाव और 2. ऐसे संशोधन को अमान्य करना।

15.8 एम. नागराज बनाम भारत संघ 2 में 3,80-5

और संविधान में संबद्ध संशोधनों का आह्वान किया गया

संविधान की मूल विशेषता के रूप में समानता के अधिकार के उल्लंघन के आधार पर प्रश्न। इस पर विचार करते हुए

चुनौती, यह देखा गया कि संविधान निर्धारित करता है

20 संवैधानिक न्यायालयों द्वारा न्यायिक समीक्षा को मूल संरचना का हिस्सा माना गया था। (पारस 77,78) 21 (2007) 2 एससीसी 1

22 अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों को मूल संरचना का हिस्सा माना गया था। (पैरा 109 और 147)

23 (2006) 8 एससीसी 212।

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

भविष्य के विस्तार के लिए सिद्धांत। यह एक उद्देश्य के लिए कहा जाता है

व्याख्या के लिए दृष्टिकोण। यह देखा गया कि ए

संवैधानिक प्रावधान को संकीर्ण अर्थों में नहीं लिया जाना चाहिए।

लेकिन एक व्यापक और उदार अर्थ में ताकि ध्यान में रखा जा सके

बदलती परिस्थितियों और उभरती हुई समस्याओं और चुनौतियों।

अधिकारों की सामग्री को न्यायालयों द्वारा परिभाषित किया जाना है। कुछ संघवाद,
धर्मनिरपेक्षता, तर्कसंगतता जैसी अवधारणाओं का

और समाजवाद की तर्कसंगतता शब्दों से परे है

विशेष प्रावधान। वे संविधान को सुसंगतता प्रदान करते हैं और संविधान को एक जैविक समग्र
बनाएँ। वे इसका हिस्सा हैं

संवैधानिक कानून भले ही उन्हें नियमों के रूप में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया हो। आवश्यक विशेषता के रूप
में अर्हता प्राप्त करने के लिए, एक सिद्धांत होना चाहिए

संवैधानिक कानून के हिस्से के रूप में स्थापित किया जाए और इस तरह के बाध्यकारी

विधायिका में। इसके बाद ही इसकी जांच की जा सकती है कि क्या

यह मूल विशेषता का एक हिस्सा था। मूल विशेषता का सिद्धांत आधारित था

संवैधानिक पहचान की अवधारणा पर। व्यक्तित्व का

संविधान अपरिवर्तित रहना चाहिए। शब्द 'संशोधन'

उन्होंने कहा कि परिवर्तन के बावजूद संविधान अपनी पहचान खोए बिना बचा रहा। 24

निष्कर्ष:

15.9 यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि एक संवैधानिक संशोधन

बुनियादी संरचना की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। चाहे वह हो या नहीं

मूल संरचना का उल्लंघन किया गया था जिसे अंततः निर्धारित करना होगा

यह न्यायालय एक मामले से दूसरे मामले में।

B. क्या नियुक्ति में न्यायपालिका की प्रधानता

न्यायाधीश मूल संरचना का हिस्सा हैं

16. क्या संविधान की कोई विशेषता मूल विशेषता है

या मूल संरचना का हिस्सा निर्धारित किया जाना है

संविधान की योजना में इसका स्थान और परिणाम

संविधान के काम करने पर इसका इनकार।

16.1 न्यायपालिका को भूमिका सौंपी गई है

24 एम. नागराज मामले में चर्चा की गई पहचान परीक्षण (ऊपर) (पैरा 28)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

व्यक्तियों के अधिकार। के बीच विवाद उत्पन्न हो सकते हैं
नागरिक और

भारत सरकार और राज्यों के बीच, एक

राज्य या एक नागरिक और एक नागरिक के बीच। संबंधित विवाद

संघ विधानमंडल और राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ या
मुद्दे शामिल हो सकते हैं -

कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में निम्नलिखित

संवैधानिकता या वैधता। इसमें आरोप शामिल हो सकते हैं -
खिलाफ भी दुर्भावना। यह

सर्वोच्च संवैधानिक गणमान्य व्यक्तियों के

एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता है। न्यायपालिका

कार्यकारी नियंत्रण से अलग होना आवश्यक है। न्यायपालिका

अपनी निष्पक्षता के लिए लोगों के विश्वास को प्रेरित करना है और

योग्यता। विद्वान वकील द्वारा इस पर विवाद नहीं किया गया है।

सामान्य तौर पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता बुनियादी का हिस्सा है

संरचना। यह भी निर्विवाद है कि न्यायिक समीक्षा इसका हिस्सा है

बुनियादी संरचना। इस न्यायालय के निर्णय स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं

कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा का हिस्सा हैं

बुनियादी संरचना। तीनों के बीच शक्तियों का व्यापक विभाजन

राज्य के विभाग जाँच के सिद्धांत का एक हिस्सा हैं और
है। की स्वतंत्रता

संतुलन। यह लोकतंत्र का भी एक हिस्सा

न्यायपालिका संविधान की पूरी योजना का अभिन्न अंग है

जिनके बिना न तो संविधान की प्रधानता और न ही संघीय

चरित्र, सामाजिक लोकतंत्र और न ही समानता और स्वतंत्रता के अधिकार
है।

प्रभावी हो सकता

16.2 न्यायपालिका की अपनी अराजनैतिक प्रतिबद्धता है।

कार्य कर रहा है। एक बार न्यायपालिका की स्वतंत्रता को स्वीकार किया जाता है

संविधान की एक बुनियादी विशेषता के रूप में, सवाल यह है कि क्या न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति को
अवधारणा से अलग किया जा सकता है

न्यायपालिका की स्वतंत्रता या इसका अभिन्न अंग है। क्या हो सकता है?
को बनाए रखा जाए, भले ही

न्यायपालिका की स्वतंत्रता

न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित होती है -

कार्यपालक?

16.3 नियुक्ति में न्यायपालिका की प्रधानता किस हद तक है

न्यायाधीशों की संख्या सर्वोच्च न्यायालय की अपरिवर्तनीय बुनियादी विशेषता का हिस्सा है

अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

संविधान। चूंकि इस मुद्दे को पहले ही उठाया जा चुका है

बाध्यकारी उदाहरण, ऐसे निर्णयों का संदर्भ उपयुक्त है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, यह
निर्विवाद है कि न्यायिक शक्ति

न्यायपालिका की स्वतंत्रता, शक्तियों का व्यापक पृथक्करण

राज्य के तीन विभागों में, संघवाद और लोकतंत्र

संविधान की बुनियादी विशेषताएं हैं। का स्टैंड

उत्तरदाताओं का कहना है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति का न्यायाधीशों की स्वतंत्रता जैसी बुनियादी
विशेषताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है

नियुक्ति के बाद की परिकल्पना की गई है। एक संशोधन द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को बदला जा सकता है ताकि न्यायाधीशों की भूमिका को कम किया जा सके।

न्यायपालिका और कार्यपालिका और विधानमंडल की भूमिका को बढ़ाना।

वैकल्पिक रूप से, यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। उक्त भूमिकाओं में हुआ।

16.4 द्वितीय न्यायाधीश के मामले में, 9 की एक पीठ -

इस न्यायालय ने व्याख्या के प्रश्न की जांच की
से निपटने वाली असंशोधित संवैधानिक योजना
संविधान मामले के न्यायाधीशों की नियुक्ति। मुद्दा यह है
संदेह के कारण 9-न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया था
व्यक्त किए गए दृष्टिकोण की शुद्धता के बारे में उत्पन्न होने पर
एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ 25 (प्रथम न्यायाधीशों का मामला)
न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में यह प्रमुखता रही

केंद्र सरकार के साथ 26. उक्त निर्णय का आधार यह था कि अनुच्छेद 124, 217 आदि में 'परामर्श' शब्द का उपयोग किया गया था।

नियुक्ति की अंतिम शक्ति के रूप में बाध्यकारी केंद्र सरकार के पास थी। यह अभिनिर्धारित किया गया कि सी. जे. आई. के विचार या जिन अन्य न्यायाधीशों से परामर्श किया गया था, वे महान पुरस्कार के हकदार हो सकते हैं।

वजन लेकिन मतभेद के मामले में अंतिम दृष्टिकोण हो सकता है

केंद्र सरकार द्वारा लिया जाएगा। 'परामर्श' शब्द

25 1981 सप. एस. सी. सी. 87, पैरा 30 (न्यायाधीशों की नियुक्ति में प्रधानता केंद्र सरकार की मानी जाती है क्योंकि राष्ट्रपति (केंद्र सरकार) का दायित्व केवल न्यायपालिका से परामर्श करना था जिसे बाध्यकारी नहीं माना जा सकता था)

26 पैरा 25, जे. पांडियन। (दूसरा न्यायाधीश मामला): जिन कारणों से

प्रथम न्यायाधीशों के मामले की सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट पर पुनर्विचार

इसे 'सहमति' के रूप में नहीं पढ़ा जा सका।

16.5 सुभाष शर्मा में लिए गए दृष्टिकोण पर संदेह था

बनाम भारत संघ 27. सवाल यह है कि क्या सीजेआई की राय

न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में जो प्रधानता के हकदार थे, एक बड़ी पीठ के विचार के लिए भेजा गया था, जैसा कि पहले से ही था उल्लेख किया है। इस न्यायालय ने कहा कि संवैधानिक

वाक्यांश विज्ञान को पढ़ने और व्याख्या करने की आवश्यकता थी

शक्तियों के पृथक्करण के संवैधानिक दर्शन का संदर्भ

और न्यायिक स्वतंत्रता के पोषित मूल्यों की भूमिका

सीजेआई को महत्वपूर्ण महत्व के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता थी

जिसके लिए प्रथम न्यायाधीशों के मामले में लिया गया दृष्टिकोण आवश्यक है

एक बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार। यह उल्लेख किया गया था कि

उस समय की सरकार की ओर से चिंता व्यक्त करने के लिए

न्यायाधीशों के चयन में चयन और यदि न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने की शक्ति राज्य सरकार में निहित थी या केंद्र सरकार, तस्वीर धुंधली होने की संभावना थी

और चयन की प्रक्रिया कठिन हो सकती है। यह था।

यह भी देखा कि न्यायपालिका की अराजनैतिक प्रतिबद्धता थी और

न्यायपालिका के गैर-राजनीतिक रंग का आश्वासन दिया जाना चाहिए

नियुक्ति की प्रक्रिया से तलाक न लें। वाक्यांश

"परामर्श को सुसंगत रूप से समझना था और

एक कार्यकारी अधिनियम के रूप में। नियुक्ति बल्कि इसका परिणाम था प्रक्रिया। यह नहीं कहा जा सकता कि शक्ति

सामूहिक संवैधानिक

केवल कार्यपालिका के साथ निहित या कार्यपालिका को नियुक्त करना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र था जो वह उचित समझे

परामर्श के बाद ऐसा

न्यायपालिका के साथ। "परामर्श" शब्द का उपयोग उच्च संवैधानिक गणमान्य व्यक्ति के दर्जे की मान्यता में किया गया था और

इसकी शाब्दिक व्याख्या नहीं की जा सकती थी। इसके अलावा, नियुक्ति की सिफारिश राज्य के मुख्य न्यायाधीश और सीजेआई द्वारा नहीं की गई थी

सत्ता का अनुचित और मनमाना प्रयोग होगा। सीजेआई की प्रमुख भूमिका होनी चाहिए। सीजेआई की प्रधानता में सुधार होगा

27 1991 पूरक (1) एस. सी. सी. 574-पारस 31-34,42-46 सर्वोच्च न्यायालय विज्ञापन-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

चयन की गुणवत्ता। राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों का दृष्टिकोण

और सीजेआई को निर्णायक होना चाहिए जब तक कि कार्यपालिका के पास यह संकेत देने वाली सामग्री न हो कि नियुक्त व्यक्ति अवांछनीय होगा। का दृश्य

प्रथम न्यायाधीशों के मामले में बहुमत ने उक्त को मान्यता नहीं दी

सी. जे. आई. की संस्था की महत्वपूर्ण स्थिति और इसकी शुद्धता

उक्त राय पर पुनर्विचार की आवश्यकता थी। यह नोट किया गया था कि केंद्र सरकार ने अक्सर संसद के समक्ष कहा था और

सीजेआई द्वारा दिए गए नाम के बिना नियुक्ति और कार्यपालिका को उस मानक पर रखा जाना चाहिए जिसके द्वारा वह कार्य करती है।

प्रथम न्यायाधीशों के मामले में लिए गए दृष्टिकोण को द्वितीय में खारिज कर दिया गया था न्यायाधीशों का मामला जिसे तीसरे न्यायाधीशों के मामले में दोहराया गया था।

इसने माना कि अनुच्छेद 124 में "परामर्श" शब्द नहीं होना चाहिए

शाब्दिक रूप से समझाया गया। इसका अर्थ इसके उद्देश्य की संवैधानिक पृष्ठभूमि में लगाया जाना था और इसे बनाए रखना और बनाए रखना था

न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इसलिए व्याख्या की गई, यह माना गया कि

संविधान की परस्पर विरोधी राय की घटना पदाधिकारी, न्यायपालिका की राय के प्रतीक के रूप में

सी. जे. आई. का दृष्टिकोण और इंगित तरीके से गठित,

प्रधानता रखें।

16.6 पांडियन, जे. ने माना कि परामर्श की आवश्यकता

किसी अन्य सेवा से संबंधित नहीं था और केवल इसके लिए आवेदन किया गया था

अन्य उच्च पदस्थ कार्यालयों के विपरीत न्यायाधीशों की नियुक्ति।

सीजेआई के साथ परामर्श पूर्ववर्ती शर्त थी

प्रक्रिया में न्यायपालिका द्वारा दी गई नियुक्ति और सलाह

पवित्रता थी। नियुक्ति की कार्यकारी शक्ति आती है

अनुच्छेद 74 और 163 के आधार पर खेला जाता है, हालांकि यह नहीं था
अनुच्छेद 124 और 217 में प्रावधान किया गया है। राज्य

विशेष रूप से

प्रमुख वादी था। उच्च न्यायालयों का सामना करना पड़ा
राजनीतिक स्वाद के साथ विवाद और ऐसी स्थिति में यदि
न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका का पूर्ण अधिकार था,
न्यायपालिका की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचेगा। कानून.

आयोग की रिपोर्ट और न्यायविदों की राय ने सुझाव दिया कि कट्टरपंथी सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13
एस. सी. आर.

कार्यपालिका पर अंकुश लगाकर न्यायाधीशों की नियुक्ति में परिवर्तन
शक्ति 28.

16.7 कुलदिप सिंह, जे. ने कहा कि न्यायपालिका की अवधारणा
स्वतंत्रता का अर्थ केवल कार्यकाल की सुरक्षा नहीं था
व्यक्तिगत न्यायाधीश। न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी चाहिए
एक संस्था के रूप में ताकि यह प्रभावी रूप से एक निष्पक्ष के रूप में कार्य कर सके
सरकारों और व्यक्तियों के बीच या सरकारों के बीच अंपायर। यह कहना अतार्किक होगा
कि न्यायपालिका स्वतंत्र हो सकती है जब की शक्ति
कार्यपालिका में निहित नियुक्ति। के फ्रेमर्स
संविधान का कभी भी कार्यपालिका को यह शक्ति देने का इरादा नहीं था।
जो अदालतों के समक्ष सबसे बड़ा वादी था। प्राइमल को मान्यता देने वाला संवैधानिक सम्मेलन स्थापित
किया गया था
और नियुक्ति के मामले में सीजेआई की बाध्यकारी राय
न्यायाधीशों। शुरुआत के बाद से सभी नियुक्तियाँ
सीजेआई की सहमति से संविधान बनाया गया था। द.
14 विधि आयोग की रिपोर्ट और इसमें चर्चा
23 और 24 नवंबर, 1959 को संसद को भेजा गया था।

30 तक। 24 तारीख को डॉ. अम्बेडकर के बयान के संबंध में

मई, 1949 संविधान सभा के समक्ष कि सीजेआई कर सकता था

यह देखा गया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति पर वीटो नहीं दिया जाएगा

प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने वाले सी. जे. आई. की प्रधानता

व्यक्तिगत क्षमता के उद्देश्य के खिलाफ नहीं होगा कथन 31 ने कहा।

16.8 वर्मा, जे. ने देखा कि योजना

शक्तियों के पृथक्करण का संविधान, निर्देश के साथ

न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के सिद्धांत और भूमिका

न्यायपालिका को कानून के शासन को सुरक्षित करने के लिए उस नियुक्ति की आवश्यकता थी
उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की संख्या को कार्यपालिका के विवेक पर नहीं छोड़ा जा सकता था।
न्यायाधीशों की स्वतंत्रता की भी आवश्यकता थी

28 पारस 195 और 207

29 पारस 334, 335 30 पैरा 357

31 पैरा 392 सर्वोच्च न्यायालय

अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड संगठन v. यू. ओ. आई. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

उनकी नियुक्ति के समय इसे सीमित करने के बजाय कार्यकाल की सुरक्षा और सेवा की शर्तों के लिए प्रावधान। यह.

राजनीतिक विचार के प्रभाव को रोकने के लिए आवश्यक था

कार्यपालिका द्वारा नियुक्तियों के कारण। एक के चयन में

उम्मीदवार, सीजेआई की राय का सबसे अधिक महत्व होना चाहिए। सहभागी परामर्श प्रक्रिया में कार्यपालक की भूमिका शक्ति के प्रयोग पर एक जाँच के माध्यम से होने का इरादा था

सीजेआई द्वारा। कार्यकारी तत्व न्यूनतम होना चाहिए था

राजनीतिक प्रभाव को समाप्त करना 32,

16.9 तदनुसार, इस आशय के निष्कर्ष पैरा 486 में दर्ज किए गए थे कि नियुक्ति के लिए प्रस्ताव की शुरुआत और स्थानांतरण न्यायपालिका द्वारा शुरू किया जा सकता था और परस्पर विरोधी राय के मामले में, सीजेआई की राय को प्राथमिकता दी जाती थी। में।

असाधारण मामलों में नियुक्ति को अस्वीकार किया जा सकता है

कारणों का खुलासा करना लेकिन यदि कारणों को स्वीकार नहीं किया गया था
में कार्य करने वाले सीजेआई द्वारा, नियुक्ति

प्रतिनिधि क्षमता

एक स्वस्थ सम्मेलन के रूप में बनाए जाने की आवश्यकता थी। सीजेआई
किया जाना था। सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश,

वरिष्ठता द्वारा नियुक्त

पद धारण करने के लिए उपयुक्त माने जाने वाले, सीजेआई होने वाले थे।

16.10 पैरा 44 में तीसरे न्यायाधीशों के मामले में निष्कर्ष

इस विचार को केवल मामूली संशोधन के साथ दोहराया गया। इसी आधार पर,
उल्लिखित प्रक्रिया के ज्ञापन

इसके पूर्व भाग में

राय जारी की गई। समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग

न्यायाधीश की अध्यक्षता में संविधान का कार्यकरण (एन. सी. आर. डब्ल्यू. सी.)

एम. एन. वेंकटचलैया ने 31 मार्च, 2002 की अपनी रिपोर्ट में कहा,

यह पाया गया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति स्वतंत्रता का हिस्सा थी

न्यायपालिका से। यह देखा गया कि नियुक्ति की शक्ति संभालने और प्रमुख भूमिका निभाने वाली
कार्यपालिका होगी

संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन, स्वतंत्रता का

न्यायपालिका 33.

16.11 याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि उक्त

32 पारस 421,422,447 और 450

33 पैरा 9.6 और 9.7।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर.

निर्णय निर्णायक रूप से न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायपालिका की प्रधानता को मान्यता देते हैं

संविधान और इस तरह की प्रधानता बुनियादी संरचना का हिस्सा थी।

16.12 यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि कार्यपालिका की प्रधानता है, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति
का उपयोग प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है या

सदस्यों के रूप में नियुक्त लोगों की स्वतंत्रता को नष्ट करना

संवैधानिक न्यायालय। यह इरादे के खिलाफ होगा।

संविधान निर्माताओं से। अपरिवर्तित प्रावधान हो सकता है

नए तंत्र द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा जब तक कि नया तंत्र ने यह सुनिश्चित किया कि न्यायपालिका की भूमिका नहीं थी

कमी आई और कार्यपालिका की भूमिका नहीं बढ़ाई गई।

और किए गए परिवर्तन का कार्यप्रणाली पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा संविधान से। यदि इस विवाद को बरकरार रखा जाता है, तो विवादित

संशोधन को तब तक निरस्त करना होगा जब तक कि इसे आयोजित नहीं किया जा सके

कि संशोधित प्रावधानों ने भी उक्त प्रधानता को बनाए रखा।

यदि न्यायपालिका की प्रधानता को बुनियादी ढांचे का हिस्सा नहीं माना जाता है

संविधान का या यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि वह अभी भी बरकरार है,

संशोधन को बरकरार रखना होगा।

ग. उत्तरदाताओं की पूर्व में फिर से आने की याचिका

बाध्यकारी पूर्ववर्ती

17. उपरोक्त में लिए गए दृष्टिकोण की शुद्धता

विद्वान वकील द्वारा निर्णयों को चुनौती देने की मांग की गई थी

उत्तरदाताओं। जिस आधार पर पुनरीक्षण किया गया

पहले के दृष्टिकोण की मांग की जाती है कि द्वितीय और द्वितीय में व्याख्या

तीसरे न्यायाधीश के मामले स्पष्ट रूप से गलत हैं। के सदस्य संविधान सभा का कभी यह इरादा नहीं था कि सीजेआई के पास होना चाहिए

न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय पर अंतिम शब्द। पाठ

जिसे अंततः मंजूरी दे दी गई और जो इसका हिस्सा बन गया

संविधान में सीजेआई की सहमति का प्रावधान नहीं है जैसा कि है

इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा ली गई व्याख्या पर उचित ठहराया जा सकता है कार्यपालिका द्वारा विशेष रूप से आपातकाल के दौरान शक्तियों के दुरुपयोग का लेखा (जैसा कि भारत संघ बनाम भारत संघ में देखा गया है)।

& पीवाई सर्वोच्च न्यायालय

अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड संगठन v. यू. ओ. आई. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

संकलचंद हिमतलाल सेठ 334) और विधि आयोग में रिपोर्ट (विशेष रूप से 14 वीं और 121 वीं रिपोर्ट), एक ही स्थिति

अब जारी नहीं है। न्यायपालिका के लिए वैश्विक प्रवृत्ति अधिक है
नियुक्ति आयोग। प्रमुखता के बिना भी
न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायपालिका, न्यायपालिका काम कर सकती है
स्वतंत्र रूप से। न्यायिक नियुक्ति आयोग था

पहले भी सुझाए गए। प्रख्यात न्यायविदों ने आलोचना की थी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए
विद्यमान तंत्र और विशेष रूप से
कॉलेजियम प्रणाली का कार्यकरण।

17.1 के अध्याय IV की योजना का उल्लेख करते हुए

संविधान, विद्वान महान्यायवादी ने प्रस्तुत किया कि कार्यपालिका
न्यायाधीशों का वेतन और सेवा की शर्तें निर्धारित की जाती हैं - संसद। उच्चतम न्यायालय के
कार्यकरण के लिए नियम

राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ तैयार किए जाते हैं और विषय होते हैं
संसद द्वारा बनाए गए कानून के लिए। संसद उच्चतम न्यायालय को पूरक शक्तियाँ प्रदान कर सकती है। की
शर्तें

उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की सेवाएँ हैं
संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन। द्वारा बनाए गए नियम
सीजेआई को राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता होती है। वहाँ अंतर था
के कार्यकरण में कार्यपालिका और विधानमंडल की भूमिका
न्यायपालिका। न्यायाधीशों की स्वतंत्रता उनके संबंध में थी

कार्यकाल और सेवा शर्तों की सुरक्षा। का तरीका नियुक्ति ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को
प्रभावित नहीं किया।

भारत के महानियंत्रक की नियुक्ति या चुनाव
आयोग ने उनकी स्वतंत्रता को प्रभावित नहीं किया। की शक्ति

न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यकारी शक्ति है जिसका प्रयोग किया जाना है। राष्ट्रपति द्वारा
मंत्रिपरिषद की सलाह से

न्यायपालिका के साथ परामर्श के बाद। अलगाव का सिद्धांत

कार्यपालिका से न्यायपालिका की शक्तियों या पृथक्करण आवश्यकता है कि नियुक्ति में कार्यपालक की कोई भूमिका नहीं हो सकती है न्यायाधीशों से। न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायपालिका की प्रधानता नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांतों की उपेक्षा करती है। द.

34 1977 (4) एस. सी. सी. 193 (पैरा 125 से 130 द्वितीय न्यायाधीशों के मामले में संदर्भित)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर. पहले के निर्णयों में दी गई व्याख्या की उपेक्षा करता है पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांत। इसके बिना भी पूर्व निर्णयों में स्पष्ट त्रुटि होना, ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे की संवेदनशील प्रकृति और इस तथ्य के लिए भी कि संशोधन अब लाया गया है, पहले के निर्णय इसे फिर से देखने की जरूरत है।

17.2 विद्वान महान्यायवादी और अन्य का रुख

उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को चुनौती दी गई थी याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा। यह प्रस्तुत किया गया था कि सभी उत्तरदाताओं द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दे विधिवत थे नौ-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा विचार किया गया। द सेंट्रल

सरकार ने अनुच्छेद 143 के तहत इस न्यायालय की राय मांगी। ए. तत्कालीन विद्वान महान्यायवादी ने बयान दिया था कि द्वितीय न्यायाधीशों के मामले पर पुनर्विचार करने की मांग नहीं की गई थी। नौ न्यायाधीशों की पीठ का विचार पहले के बाध्यकारी पर आधारित था।

संकलचंद मामले (ऊपर) में कहा गया है कि अंतिम शब्द ऐसे मामले सीजेआई के थे। विशेषज्ञ अध्ययन और

संविधान सभा की बहसों ने पूर्व-प्रमुख भूमिका को खारिज कर दिया न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका या विधानमंडल। द.

संवैधानिक योजना ने हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी

न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालक। कार्यपालक दे सकता है
 वापस फ्रीड करें और कार्यकारी कार्यों को पूरा करें
 नियुक्तियाँ लेकिन प्रस्ताव को शुरू और अंतिम रूप दिया जाना था
 न्यायपालिका द्वारा। व्यापक रूप से विचारों पर बार-बार पुनर्विचार इस न्यायालय की पीठ
 किसी की अनुपस्थिति में बांछनीय नहीं थी।
 पहले के दृष्टिकोण की शुद्धता के बारे में संदेह।

17.3 यह निर्धारित करने के लिए मापदंड कि कब पहले
 बाध्यकारी निर्णयों को फिर से खोला जाना चाहिए जो बार-बार किए गए हैं।
 इस न्यायालय द्वारा निर्धारित। तय सिद्धांत यह है कि अदालत
 ऐसा नहीं होना चाहिए, सिवाय इसके कि जब यह सभी उचित संदेहों से परे प्रदर्शित किया जाता है कि
 इसका पिछला निर्णय देय होने के बाद दिया गया है। विचार-विमर्श और पूर्ण सुनवाई गलत थी,
 पहले फिर से देखें

35 1974 (2) एस. सी. सी. 831

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड
 एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]
 निर्णय ताकि कानून निश्चित रहे। 36 अपवादात्मक रूप से
 परिस्थितियों या परिस्थितियों के नए सेट के तहत नए विचार, पूर्व दृष्टिकोण, यदि गलत माना
 जाता है, तो हो सकता है
 उल्टा हुआ। जबकि कानून की प्रगति जारी है और नई प्रणालियाँ कर सकती हैं
 जब भी आवश्यकता हो विकसित किया जा सकता है, यह केवल तभी किया जा सकता है जब पहले
 प्रणालियों को अव्यवहारिक माना जाता है।

17.4 ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। स्थिर सिद्धांतों पर,
 बड़ी पीठों द्वारा पहले के फैसलों पर पुनर्विचार करने का कोई मामला नहीं है।
 बनाया गया। जहाँ तक इस तर्क का संबंध है कि पेटेंट था
 पहले के फैसलों में त्रुटि, दूसरे न्यायाधीशों के मामले से पता चलता है
 कि संविधान सभा की बहसों को पूरी तरह से उद्धृत किया गया है

और विचार किया। न तो बहस और न ही द्वारा अपनाया गया पाठ संविधान से पता चलता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति कार्यपालिका को सम्मानित करने का इरादा था या विधायिका। 'परामर्श' शब्द की व्याख्या और समझने का मतलब था कि विषय पर अंतिम शब्द न्यायाधीशों की नियुक्ति सीजेआई के पास होती थी। अभ्यास और संविधान के प्रारंभ के बाद से सम्मेलन यह दर्शाता है कि नियुक्ति का प्रस्ताव हमेशा शुरू किया गया था न्यायपालिका और इस विषय पर अंतिम शब्द का था सीजेआई। यह योजना के इरादे के अनुरूप थी संविधान निर्माता। अब सभी बिंदुओं को उठाने की मांग की गई विद्वान महान्यायवादी पर व्यापक रूप से विचार किया गया है दूसरे न्यायाधीशों के मामले में। यह तर्क कि पहले कार्यकारी हस्तक्षेप की स्थिति अब बदल गई है पहले के दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करना उचित नहीं है। यदि स्थिति बदल गया है, सिस्टम बदलने का कोई कारण नहीं हो सकता है जो संविधान के इरादे के अनुसार काम कर रहा है निर्माता जब इस तरह का परिवर्तन मूल संरचना के विपरीत होगा जो संवैधानिक रूप से अनुमत नहीं है। जिस पर आपत्ति है कॉलेजियम प्रणाली के कामकाज में कमियां होंगी इस निर्णय के बाद के भाग में चर्चा का विषय। 36 गन्नन डंकरली बनाम राजस्थान राज्य, 1993 (1) एस. सी. सी. 364, पैरा 28 से 31 37 द्वितीय न्यायाधीशों का मामला, पैरा 19 से 22 [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

किसी भी कार्य के संचालन में व्यक्तिगत विफलताओं से कभी इनकार नहीं किया जा सकता है।

प्रणाली। इससे पहले न्यायिक नियुक्ति आयोग

न्यायाधीशों का मामला, प्रधानता को समाप्त करने के उद्देश्य से
मामले में निर्धारित किया गया है। साथ में

जैसा कि प्रथम न्यायाधीशों के

सातवाँ संशोधन विधेयक, उद्देश्यों के विवरण में और

कारण, यह उल्लेख किया गया है कि स्थापना का उद्देश्य

आयोग को मनमानेपन की आलोचना को दूर करना था

कार्यपालिका '38 का भाग। नब्बे-आठवाँ संशोधन विधेयक,

2003 एक अलग रचना के साथ पेश किया गया था

समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग की सिफारिश

संविधान का कार्य। एक-बीसवाँ संशोधन विधेयक,

2013 किसी भी रचना के लिए प्रदान नहीं किया और छोड़ दिया

संसद द्वारा प्रदान की जाने वाली संरचना। की वैधता

ऐसे प्रस्तावित आयोगों का कभी परीक्षण नहीं किया गया। आयोग कभी अस्तित्व में नहीं आए।

17.5 अन्य देशों में न्यायिक आयोग और

शक्ति प्रदान करने वाले अन्य देशों के संविधान के प्रावधान
नियुक्ति के लिए भी आह्वान नहीं किया जा सकता है

कार्यपालिका पर न्यायाधीशों की

दूसरे न्यायाधीशों के मामले में ऐसे कई मामलों पर पुनर्विचार

और इसी तरह के प्रावधानों पर दूसरे में विधिवत विचार किया गया था

न्यायाधीशों का मामला जिस पर निर्देश दिया जाएगा। कोई मामला नहीं है

इस प्रकार द्वितीय में पहले के निर्णयों पर पुनर्विचार करने के लिए बनाया गया

और तीसरे न्यायाधीशों के मामले।

D. प्रधानता के मुद्दे पर परिणामी विचार

न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायपालिका के भाग के रूप में

बुनियादी संरचना।

18. द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों में पहले के निर्णय '

मामले को बाध्यकारी उदाहरण के रूप में लिया जाना चाहिए। एक बार ऐसा होने के बाद, यह माना जाना
चाहिए कि नियुक्ति में न्यायपालिका की प्रधानता

न्यायाधीश मूल संरचना का हिस्सा हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति

30 यह विधेयक विधि आयोग की 121 वीं रिपोर्ट के आलोक में पेश किया गया था।

सर्वोच्च अदालतें-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हिस्सा। इसे बनाए रखना भी आवश्यक है।

विधायिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का संतुलन

न्यायपालिका जो अपने आप में संपूर्ण कार्यप्रणाली की कुंजी है

संविधान। न्यायपालिका को नियंत्रण करने की शक्ति सौंपी गई है

कार्यपालिका और विधानमंडल की शक्ति जब भी हो

आरोप लगाया कि उक्त अंगों ने उनकी सीमा को पार कर लिया है

संवैधानिक रूप से सौंपा गया अधिकार। यही सार है कि

लोकतंत्र। याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील ने प्रकाश डाला

कि कभी-कभी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों का प्रयोग

संवैधानिक न्यायालय कार्यपालिका को पसंद नहीं कर सकते हैं।

या विधानमंडल। विशेष उदाहरण दिए गए हैं

2 जी स्पेक्ट्रम मामला 39 और कोयला घोटाले में इस न्यायालय के निर्णय
कार्यपालिका की कार्रवाई उल्लंघनकारी पाई गई थी

मामला जहाँ

जनता को भारी नुकसान पहुँचाने वाले संवैधानिक दायित्वों का

राजकोष। यह प्रस्तुत किया गया था कि राज्य का मनमाना वितरण

दुर्लभ संसाधनों या अनुबंधों या नौकरियों को देने के माध्यम से अनुदान

या 'खराब करने वाली प्रणाली' के समान महत्वपूर्ण पदों को रखा गया है

इस न्यायालय द्वारा संविधान का उल्लंघन माना गया। नीतियाँ

भूमि के मनमाने अधिग्रहण या उल्लंघन के लिए राज्य का

इस न्यायालय द्वारा पर्यावरण कानूनों को निरस्त कर दिया गया है।

इस न्यायालय 41 द्वारा सरकारों को भी निरस्त कर दिया गया है। यह
से उत्पन्न होने वाले मुद्दों से भी निपटना पड़ता था।

न्यायालय को निर्णयों

दलबदल को पहचानने या अन्यथा स्वीकार करने में वक्ताओं का

ऐसे मामले जब न्यायालयों को वैधता से निपटना होता है
कार्यकारी निर्णय। यह है।

दूरगामी प्रकृति के विधायी या

निष्पक्षता और क्षमता में लोगों का विश्वास

न्यायपालिका जो लोकतंत्र को बनाए रखती है। यदि न्यायाधीशों की नियुक्ति,

जो न्यायपालिका के कामकाज के लिए अभिन्न है, प्रभावित है या

कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित, यह निश्चित रूप से निष्पक्षता को प्रभावित करेगा

39 जनहित याचिका केंद्र बनाम यू. ओ. आई. (2012) 3 एस. सी. सी. 1

40 मनोहर लाल शर्मा बनाम यू. ओ. आई (2014) 2 एस. सी. सी. 532 41 एसआर. बोम्मई बनाम
यूओआई (1994) 3 एससीसी 1; रामेश्वर प्रसाद बनाम यूओआई (2006) 2 एससीसी 1; एमसी। मेहता बनाम
कमल नाथ (1997) 1 एस. सी. सी. 388

42 किहोतो होलोहन बनाम ज़चिल्लु (1992) सप। (2) 651

:

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

}

न्यायाधीश और उनकी कार्यप्रणाली। निष्पक्षता में लोगों का विश्वास और

अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका की प्रभावशीलता

नष्ट हो जाएगा।

18.1 विद्वान महान्यायवादी की दलीलें यह हैं कि

भले ही न्यायाधीशों की नियुक्ति का हिस्सा माना जाता है
विशेष मॉडल का चयन नहीं है

न्यायपालिका की स्वतंत्रता, किसी

न तो पूरी तरह से इनकार किया जा सकता है और न ही सदस्यों को कोई आपत्ति हो सकती है
नियुक्ति की प्रक्रिया में नागरिक समाज को शामिल किया जाना।

न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायपालिका की प्रधानता नहीं है

निरंकुश आदर्श। नियुक्ति की शक्ति में देखा जाना चाहिए

नियंत्रण और संतुलन की आवश्यकता का प्रकाश। की स्वतंत्रता
 न्यायपालिका एक आयामी परीक्षा नहीं है। अंतर हो सकता है
 न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में अन्य शाखाओं का मिश्रण।
 अनुच्छेद 124 और 217 के निरसन के बाद, द्वितीय न्यायाधीशों का आधार '
 मामला नहीं बचा। नियुक्ति में न्यायपालिका की प्रधानता
 न्यायाधीश केवल गलत नियुक्ति को रोकने के संदर्भ में हैं या
 कार्यपालिका के पूर्व-प्रभुत्व को रोकना। भले ही प्रधानता न्यायपालिका को एक निश्चित समय
 पर मान्यता दी गई थी, उसी समय
 यह केवल तब तक लागू हो सकता है जब तक कि संविधान में संशोधन नहीं हो जाता। दो प्रख्यात
 व्यक्ति सामाजिक दृष्टिकोण देने के लिए आम आदमी हो सकते हैं। कानून.
 मंत्री को आयोग का सदस्य बनाया गया था
 जवाबदेही और पारदर्शिता। जैसा कि आई. आर. कोएल्हो में बताया गया है मामलों में, शक्तियों
 के पृथक्करण के बावजूद, की विभिन्न शाखाएँ
 सरकार के अतिव्यापी कार्य हो सकते हैं। सहारा में
 इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन। लिमिटेड बनाम। SEBI44, यह देखा गया था
 कि संविधान के तहत अलग-अलग मूल्य हैं जो आवश्यक हैं
 संतुलित रहें। इस प्रकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, नियंत्रण और
 संतुलन, लोकतंत्र और शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए
 समग्र रूप से माना जाता है। उन्होंने पृष्ठभूमि का उल्लेख किया
 वर्ष 1973 और 1977 में न्यायाधीशों का अधिक्रमण और आपातकाल के दौरान न्यायाधीशों का चयनात्मक
 स्थानांतरण, जैसा कि 121 में उल्लेख किया गया है।

43 पैरा 64

44 (2012) 10 एससी 603 सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

विधि आयोग की रिपोर्ट 45. रिपोर्ट में कहा गया है कि

1976, सोलह न्यायाधीशों का संबंधित उच्च न्यायालय से स्थानांतरण किया गया
 जिन न्यायालयों में वे अन्य उच्च न्यायालयों के लिए काम कर रहे थे। इसे हस्तक्षेप का कार्य माना
 गया था
 न्यायपालिका। स्थानांतरण का प्रावधान करने वाले तत्कालीन कानून मंत्री का परिपत्र
 और प्रथम में विचार किए गए न्यायाधीशों की अल्पकालिक नियुक्ति
 न्यायाधीशों के मामले को उक्त रिपोर्ट में कार्यकारी के रूप में लिया गया था।
 हस्तक्षेप। रिपोर्ट में उत्पन्न होने वाली चिंता का भी उल्लेख किया गया है
 सी. जे. आई. की नियुक्ति में अधिस्थगन से बाहर, की पुष्टि नहीं
 अतिरिक्त न्यायाधीश, न्यायाधीशों का स्थानांतरण
 न्यायपालिका की स्वतंत्रता के क्षरण की आशंका
 सामान भेजे। इसके परिणामस्वरूप 67 वां संशोधन पेश किया गया। बिल, 1990।

18.2 विद्वान महान्यायवादी की दलीलें नहीं हो सकतीं
 स्वीकार किया जाए। इस मामले में बहुत विस्तार से चर्चा की गई है
 उपरोक्त बाध्यकारी उदाहरणों में जिनकी आवश्यकता नहीं है
 पुनर्विचार, मैं इसे दोहराना आवश्यक नहीं मानता
 चर्चा का विवरण जो उक्त में दर्ज की गई है निर्णय लेते हैं।

18.3 द्वितीय न्यायाधीशों के मामले में निम्नलिखित निष्कर्ष हैं -
 दर्ज किया गया:

(i) अनुच्छेद 124, 217 में प्रयुक्त 'परामर्श' शब्द और

222 संविधान का अर्थ था कि

आम तौर पर प्रतिनिधि को इस प्रकार स्वीकार किया जाना था
 न्यायपालिका की प्रधानता के अनुसार;

(ii) कार्यपालिका प्रमुख वादी है और इसकी भूमिका

न्यायपालिका को विवादों का निष्पक्षता से फैसला करना है

न्यायाधीशों की नियुक्ति में नागरिक और राज्य के बीच कार्यपालिका निर्णायक भूमिका नहीं निभा
 सकती थी।

45 पैरा 1.21 से 1.23, 7.1 और 7.2 [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(iii) के तहत शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत

संविधान में न्यायपालिका की प्रधानता की आवश्यकता थी
न्यायाधीशों की नियुक्ति;

(iv) चूंकि उम्मीदवारों के लक्षणों का बेहतर मूल्यांकन किया जा सकता है।

मुख्य न्यायाधीश द्वारा, मुख्य न्यायाधीश का दृष्टिकोण

उम्मीदवार की उपयुक्तता और योग्यता अधिक थी

वजन;

(v) भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक नहीं बनाना था

व्यक्तिगत रूप से लेकिन प्रतिनिधित्व के रूप में सिफारिश

न्यायपालिका निर्धारित तरीके से, अर्थात्, उसके बाद

कॉलेजियम से परामर्श करना; और

(vi) न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायपालिका की प्रधानता एक हिस्सा है।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता और इसका पृथक्करण

संविधान के तहत शक्तियाँ।

18.4 संवैधानिक योजना का उल्लेख करते हुए, इसकी

पृष्ठभूमि और व्याख्या, चाहे शाब्दिक कुछ भी हो
भाषा का अर्थ

संविधान के अनुच्छेद 214 और 217 में प्रयुक्त

संविधान, यह देखा गया था कि प्रस्ताव की शुरुआत होनी चाहिए

हमेशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश/सीजेआई से निकलता है

(प्रतिनिधि क्षमता में जैसा कि निर्धारित किया गया है) और किसी पर अंतिम शब्द

उस पर आपत्ति सामान्य रूप से CJI.46 की होनी चाहिए।

18.5 न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में 'परामर्श' शब्द की व्याख्या का संदर्भ दिया गया था

चंद्र मौलीश्वर प्रसाद बनाम पटना में पहले के निर्णय

उच्च न्यायालय ", शमशेर सिंह और संकलचंद मामले।

यह माना गया था कि "व्यवहार में, इस तरह के संवेदनशील में अंतिम शब्द

विषय सीजेआई का होना चाहिए, उनकी सलाह की अस्वीकृति

आम तौर पर आदेश को दूषित करने वाले तिरछे विचारों द्वारा प्रेरित माना जाता है।

46 न्यायपालिका के साथ न्यायाधीशों की नियुक्ति में प्रधानता रखने के कारणों का सारांश पांडियान, जे. द्वारा पैरा 195 (द्वितीय न्यायाधीशों का मामला) में दिया गया है।

47 1969 (3) एस. सी. सी. 56 सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [आदर्श कुमार गोल, जे।]

18.6 डॉ. के बयान का भी संदर्भ दिया गया।

अम्बेडकर ने कहा कि नियुक्त करने की शक्ति देना खतरनाक था

कार्यपालिका के न्यायाधीश या विधानमंडल की सहमति से। 48

आगे का बयान कि वीटो शक्ति देना खतरनाक था सीजेआई को यह समझाया गया था कि सीजेआई को व्यक्तिगत रूप से कार्य नहीं करना चाहिए

क्षमता लेकिन वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद। 49 49

18.7 कहने की जरूरत नहीं है कि भारत का संविधान है

अद्वितीय। जबकि अन्य संविधानों का संदर्भ दिया जा सकता है।

कुछ उद्देश्यों के लिए 50, भारतीय संविधान की बुनियादी विशेषताएं

(जो अन्य संविधानों से स्पष्ट रूप से अलग हो सकते हैं) बनाए रखा जाए और उसे अनुमति नहीं दी जा सकती है। उपरोक्त में

निर्णय, भारतीय संविधान के कार्यकरण के संदर्भ में, यह

यह अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका और विधानमंडल की भूमिका प्रमुख नहीं हो सकती है। यहां तक कि

संविधान सभा, अन्य देशों के मॉडल नहीं थे

भारत 51 में पालन करने के लिए उपयुक्त पाया गया। पहले की तरह

भारत सरकार द्वारा नियुक्त प्रथम कानून का उल्लेख किया गया

श्री एम. सी. स्टीलवाड की अध्यक्षता में आयोग समीक्षा करेगा उसके सभी पहलू। द.

न्यायिक प्रशासन की प्रणाली और

आयोग ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि कार्यपालिका न्यायाधीशों की नियुक्ति में हस्तक्षेप अनुकूल नहीं रहा है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए। आयोग ने कहा कि मुख्यमंत्रियों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हाथ था। न्यायाधीशों की नियुक्ति जिसके परिणामस्वरूप नियुक्तियों की जाती हैं योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि समुदाय, जाति के आधार पर, यह अपने पार्टी अनुयायियों की सद्भावना पर निर्भर है। द. सीजेआई की सिफारिश योग्यता के आधार पर होने की अधिक संभावना है। अ.

रिपोर्ट में उल्लिखित राय में उल्लेख किया गया है कि यदि कार्यपालिका 48 पैरा 25 (5), पांडियन, जे.

49 पैरा 392, वर्मा, जे. (द्वितीय न्यायाधीशों का मामला)

50 जैसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति, जीवन के अधिकार की सामग्री आदि।

51 पैरा 184 और 192, द्वितीय न्यायाधीशों का मामला (पैरा 192 में इस संबंध में यू. के. और यू. एस. मॉडल की अनुपयुक्तता के बारे में डॉ. अम्बेडकर के प्रसिद्ध कथन का संदर्भ दिया गया है)

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3

शक्तिशाली भूमिका निभाना जारी रखा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता गायब हो जाएँगे और न्यायालय उन न्यायाधीशों से भर जाएँगे जो राजनेताओं की नियुक्तियों से 52। यह सिफारिश की गई थी कि सीजेआई के हाथों को मजबूत किया जाना चाहिए और इसके बजाय परामर्श की आवश्यकता के लिए इसके द्वारा सिफारिश की आवश्यकता होनी चाहिए 53. सीजेआई 54 की सहमति की आवश्यकता होनी चाहिए।

सीजेआई

रिपोर्ट पर संसद में चर्चा की गई और तब

गृह मंत्री ने घोषणा की कि कार्यपालिका केवल एक आदेश है

प्राधिकरण जारी करना और नियुक्तियां वस्तुतः की जा रही थीं।
तत्कालीन कानून द्वारा दोहराया गया था

सीजेआई द्वारा। इस कथन को

मंत्री 55. 121 की 1 रिपोर्ट में फिर से यह देखा गया कि कार्यकारी प्रभाव वाले न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं की गई थी न्यायिक समीक्षा के स्वस्थ विकास के लिए अनुकूल। हर तरफ रुझान

दुनिया इंगित करती है कि नियुक्ति में कार्यपालिका की शक्ति

न्यायाधीशों की संख्या को 56 से कम करना आवश्यक था। दूसरे न्यायाधीश '

मामले ने संवैधानिक व्यवस्था के आलोक में जमीनी वास्तविकताओं का ध्यान रखा सम्मेलन।
इसने अभिनिर्धारित किया कि सीजेआई चयन करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित था

सबसे अच्छा और नियुक्तियों के लिए कार्यकारी से मुक्त होना

निष्पक्षता में जनता के विश्वास को प्रेरित करने के लिए प्रभुत्व और

न्यायपालिका को अलग करने के सिद्धांत के अनुरूप

कार्यपालिका और संविधान की भावना के अनुरूप भी

निर्माता। प्रधानता के सिद्धांत को मान्यता दी गई और

न्यायाधीशों की नियुक्ति को इसका अभिन्न अंग माना गया था

न्यायपालिका की स्वतंत्रता 57. मनमाना अभ्यास की जाँच करने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा
शक्ति, यह अनिवार्य कर दिया गया था कि प्रमुख

न्यायाधीश वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श करते हैं। इस प्रकार, न्यायपालिका की प्रधानता थी
प्रस्ताव शुरू करने के साथ-साथ अंतिम रूप देने में मान्यता प्राप्त

निर्णय 58. तथापि, देने में कार्यपालिका की भागीदारी प्रस्ताव शुरू होने से पहले नामों का सुझाव
देकर इनपुट

52 पैरा 14

55 पारस 362-371 (दूसरे न्यायाधीशों का मामला) 56 पैरा 7.5-7.11 (121 वीं विधि आयोग
रिपोर्ट)

57 पारस 333-335, कुलदिप सिंह, जे., पारस 47,49,63, पांडियन, जे. 58 पैरा 486 सर्वोच्च न्यायालय

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

या प्रस्ताव शुरू होने के बाद भी प्रतिक्रिया देना था

अनुमति है। यह नोट किया गया था कि शुरुआत से ही संविधान, नियुक्तियों के लिए सभी प्रस्ताव हमेशा थे

मुख्य न्यायाधीश 59 द्वारा शुरू किया गया। प्रथम न्यायाधीशों के मामले में दृश्य

कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में प्रधानता केंद्रीय की थी

वृहत पीठ ने सरकार को त्रुटिपूर्ण ठहराया

निम्नलिखित कारणों से:

(i) न्यायपालिका की अराजनैतिक प्रतिबद्धता और यदि शक्ति है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका को दी जाती है,

यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा 50;

(ii) कानून के शासन के लिए यह आवश्यक है कि न्याय निष्पक्ष हो और लोग

न्यायपालिका के अलग होने पर विश्वास रखें और

कार्यपालिका से स्वतंत्र ताकि वह निर्वहन कर सके

सुरक्षा के लिए सतर्क निगरानी रखने के इसके कार्य

कार्यपालिका के खिलाफ भी अधिकार;

(iii) लोकतंत्र के काम करने में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है।

और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए।

(iv) संवैधानिक योजना में अनिवार्य प्रावधान है -

सीजेआई के साथ परामर्श क्योंकि सीजेआई बेहतर था
उम्मीदवार की योग्यता का आकलन करने के लिए सुसज्जित जो

अन्य के संबंध में परामर्श प्रदान नहीं किया गया था
उच्च संवैधानिक नियुक्तियाँ 63.

(v) न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ था

न्यायपालिका की स्वतंत्रता और यहां तक कि मामले में भी

जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, निर्णायक कहते हैं
यह उच्च न्यायालयों का था न कि सरकार का।

59 पैरा 505, पुंछी, जे। ; 210, 214, पांडियन, जे। ; पारस 361 से 376, कुलदिप सिंह, जे। 50 पारस
84 और 197, पांडियन जे; पारस 428 और 439, वर्मा जे; पैरा 334, कुलदिप सिंह जे।

01 पारस 56,72 से 74 और 207, पांडियन, जे. 62 पारस 55 से 57, पांडियन, जे.

63 पैरा 195 पांडियन, जे और पैरा 450, वर्मा, जे। ; पारस 447 से 463, वर्मा, जे। ; पारस 195 से 197,
पांडियन, जे। ; पारस 335 और 380, कुलदिप सिंह, जे। (पैरा 215, पांडियन, जे.-नियुक्ति और नियंत्रण
जिला न्यायाधीश उच्च न्यायालयों के साथ हैं)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

(vi) उन देशों में भी जहाँ नियुक्ति की शक्ति

न्यायाधीश कार्यपालिका के साथ थे, मांग है /

कार्यपालिका 65 की भूमिका को न्यूनतम करने का प्रस्ताव।

(vii) कार्यपालिका का नियुक्ति में अपनी बात रखने का प्रयास

विशेषज्ञ अध्ययनों द्वारा न्यायाधीशों की संख्या नहीं पाई गई

न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए अनुकूल 66।

कानून की 14 वीं रिपोर्ट का संदर्भ दिया गया था

आयोग कि अगर कार्यपालिका के पास शक्तिशाली आवाज थी

न्यायाधीशों की नियुक्ति में, स्वतंत्रता

* न्यायपालिका गायब हो जाएगी और अदालतें भरी जाएंगी।

न्यायाधीश जो अपनी नियुक्तियों के लिए राजनेताओं के ऋणी होते हैं।

कानून की 121 वीं रिपोर्ट का भी संदर्भ दिया गया था

इस प्रभाव के लिए आयोग कि ब्रिटेन में भी था

कार्यपालिका की शक्ति पर एक नियंत्रण बनाने के बारे में सोचना
न्यायाधीशों का चयन और नियुक्ति करना।

(viii) सीजेआई के साथ परामर्श की परिकल्पना नहीं की गई थी

संविधान निर्माता औपचारिक प्रकृति के होंगे लेकिन निहित होंगे

उस महान वजन को दिया जाना था ताकि अंतिम शब्द

सी. जे. आई. 67 के थे।

(ix) अनुच्छेद 50 और इसके अधिनियमन की पृष्ठभूमि

न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जनादेश लिया जा रहा है
कार्यपालिका और उसके हस्तांतरण से दूर

न्यायपालिका। 68

18.8 उपरोक्त पृष्ठभूमि में, के प्रबल विवाद

महान्यायवादी ने सीखा कि संविधान की योजना न्यायपालिका की प्रधानता की परिकल्पना नहीं
की गई थी, बल्कि केवल अनिवार्य थी

सीजेआई के साथ परामर्श और इस तरह के वैकल्पिक विचार

65 पैरा 25 (6), पांडियन, जे.

86 14 विधि आयोग की रिपोर्ट का उल्लेख पैरा 64 और 65 में न्यायमूर्ति पांडियन द्वारा किया गया है। ;
121 विधि आयोग की प्रथम रिपोर्ट का उल्लेख अनुच्छेद 184 से 191 और 204, पांडियन, जे.

67 पारस 383 से 387, कुलदिप सिंह, जे। (हालाँकि, सीजेआई को व्यक्ति पदनाम नहीं होना था, बल्कि निर्णय
में निर्धारित तरीके से न्यायपालिका के प्रवक्ता के रूप में होना था।)

68 दूसरे न्यायाधीशों का मामला (पारस 74 से 81)

सर्वोच्च न्यायालय

अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

अन्य न्यायाधीश जिन्हें आवश्यक माना जा सकता है, वे नहीं हो सकते हैं -

स्वीकार किया गया, भले ही यह शाब्दिक अर्थ से सुझाया गया हो

प्रावधान के पाठ में उपयोग किए गए शब्द। इसका उल्लेख किया जा सकता है कि संविधान की
योजना के कारण 'परामर्श' शब्द को एक उद्देश्य पर विशेष अर्थ रखने के लिए माना गया था

व्याख्या। व्याख्या केवल 'परामर्श' शब्द पर आधारित नहीं थी, बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की योजना
पर आधारित थी।

यह तर्क कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित नहीं हुई थी भले ही कार्यपालिका ने नियुक्ति की
हो, इसके विपरीत है

इस न्यायालय के विशेषज्ञ अध्ययन और सुविचारित निर्णय।

संविधान की स्वीकृत योजना और इसका कार्य नियुक्ति में कार्यपालिका के वर्चस्व की अनुमति देना नहीं है न्यायाधीश। इस तरह का प्रभुत्व न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है, अपनी निष्पक्षता में जनता का विश्वास (जब सरकार बड़ी होती है) वादी), बाहरी विचार, समझौते लाता है

न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। इस प्रकार, प्रतिस्थापन द्वारा शब्दों में, संसद प्रधानता में हस्तक्षेप नहीं कर सकती

न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायपालिका का हस्तक्षेप संविधान की मूल विशेषता। उल्लेख किया जा सकता है कि

संविधान के अनुच्छेद 74 में इसी तरह की अभिव्यक्ति का उपयोग

राष्ट्रपति की सहायता पर कार्य करने की कार्यकारी शक्ति का संदर्भ-और मंत्रिपरिषद की सलाह का अर्थ यह माना गया था कि

राष्ट्रपति केवल एक औपचारिक प्रमुख थे। 69 यह सुझाव नहीं दिया जा सकता है

कि प्रयोग की गई अभिव्यक्ति के संशोधन द्वारा, संवैधानिक

राष्ट्रपति के औपचारिक प्रमुख होने की योजना को बदला जा सकता है।

क्योंकि इस प्रकार का संशोधन संविधान की मूल संरचना के प्रतिकूल होगा। इसी तरह, संशोधन की प्रधानता से भी न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायपालिका को बाहर नहीं रखा जा सकता है। इस तरह

प्रधानता केवल शब्द 'परामर्श' से नहीं बल्कि सद्गुण से मौजूद थी।

उम्मीदवार की योग्यता का आकलन करने के लिए बेहतर है और कार्यपालिका का प्रमुख वादी होना। इनमें कोई बदलाव नहीं है।

69 पारस 48 और 57, शमशेर सिंह मामला 2

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" "

संशोधन के बाद भी कारक। इस प्रकार यह प्रश्न नहीं है कि

संसद के साथ मॉडल या उपलब्ध विकल्प का परिवर्तन।

संवैधानिकता के अनुमान की याचिका का कोई फायदा नहीं हो सकता है जहां

संविधान की एक स्थापित बुनियादी विशेषता को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की जाती है। इसी तरह, यह दलील कि संसद सबसे अच्छी है

लोगों की जरूरतों का आकलन करने के लिए सुसज्जित होना पर्याप्त नहीं है

संविधान की विशेषता। समय का परिवर्तन उचित नहीं है न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की अधिक भूमिका। द.

विभिन्न विभागों की अतिव्यापी भूमिका का अनुरोध

जहां तक नियुक्ति की बात है तो सरकार बुनियादी ढांचे के खिलाफ है न्यायाधीशों की चिंता है।

18.9 जबकि यह सच है कि विधानमंडल भी कर सकता है

कानून में परिवर्तन 70, वर्तमान संदर्भ में अर्थ अपरिवर्तित प्रावधान केवल उपयोग किए गए शब्दों पर आधारित नहीं था

लेकिन संविधान की पूरी योजना विशेष रूप से न्यायपालिका की स्वतंत्रता। यह माना गया है कि इस संदर्भ में

भारतीय संविधान, सुसंगत अतीत को ध्यान में रखते हुए

अभ्यास करना और नियुक्ति में राजनीतिक हस्तक्षेप से बचना

न्यायाधीश, और सीजेआई/सीजे के बेहतर होने के कारण भी

एक उम्मीदवार की योग्यता का आकलन करने के लिए सुसज्जित, प्रस्ताव होना चाहिए हमेशा सीजेआई/सीजेआई द्वारा शुरू किया जाना चाहिए और सीजेआई के पास भी होना चाहिए

विषय पर अंतिम शब्द। इसमें संदेह नहीं किया जा सकता है कि

संविधान एक गतिशील दस्तावेज है और इसकी व्याख्या की जानी चाहिए।

समय की महसूस की गई जरूरतों को पूरा करने के लिए और सभी भविष्य को बांध नहीं सकते

पीढ़ियाँ। उसी समय, यह भी अब अच्छी तरह से स्थापित है कि

संशोधन की शक्ति गैर-आवश्यक/गैर-बुनियादी तक सीमित है। विशेषताएँ और संविधान की बुनियादी विशेषताओं और ढांचे को बदलने के लिए विस्तारित नहीं है। न्यायपालिका की प्रधानता है

निश्चित रूप से यह संविधान की मूल विशेषता का एक हिस्सा है। अगर

न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायपालिका की प्रधानता मानी जाती है -

70 श्री पृथ्वी कॉटन मिल्स लिमिटेड बनाम ब्रोच बरो नगरपालिका, 1969 (2) एस. सी. सी. 283 सर्वोच्च न्यायालय-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. /आदर्श कुमार गोएल, जे. जे.

बुनियादी विशेषता का हिस्सा नहीं, संसद प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हो सकती है

कार्यपालिका या विधानमंडल या किसी पर उक्त शक्ति

अन्य प्राधिकरण जो निश्चित रूप से न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता कर सकते हैं। यह बदले में सिद्धांत को भी बाधित करेगा।

शक्तियों के पृथक्करण और अन्य बुनियादी विशेषताओं जैसे

कानून, लोकतंत्र और संघवाद और संविधान का कार्यकरण

समग्र रूप से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता में प्रमुख तत्व है

संविधान की संपूर्ण कार्यप्रणाली और ऐसी स्वतंत्रता

स्वतंत्र न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है
वैकल्पिक प्रस्तुति

कार्यकारी हस्तक्षेप। श्री की

वेणुगोपाल, राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील

मध्य प्रदेश पैरा 4 और 8 में (पैरा 13 में पुनः प्रस्तुत)
की नियुक्ति

ऊपर) इस निष्कर्ष का भी समर्थन करता है कि

न्यायाधीश न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हिस्सा हैं और न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायपालिका की प्रधानता को बनाए रखने की आवश्यकता है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति का प्रयोग कार्यपालिका द्वारा नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा।

मूल प्रावधानों में संशोधन के बाद भी, यह सिद्धांत

अभी भी लागू है।

18.10 इस स्तर पर यह उल्लेख किया जा सकता है कि कोई भी

मौजूदा तंत्र के काम करने में कथित कमी

न्यायाधीशों की नियुक्ति अपने आप में परिवर्तन को उचित नहीं ठहरा सकती है या
का नुकसान एक बार जब इसे इसका हिस्सा माना जाता है

मौजूदा योजना

बुनियादी विशेषता। जैसा कि डॉ. अम्बेडकर ने 71 में कहा:

"संविधान केवल राज्य के अंगों को प्रदान कर सकता है

जैसे विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका।

जिन कारकों पर उन अंगों का कार्य करना
राज्य जनता और राजनीतिक दलों पर निर्भर है

वे उन्हें पूरा करने के लिए अपने उपकरणों के रूप में स्थापित करेंगे

इच्छाएँ और उनकी राजनीति "।

71 संविधान सभा की कार्यवाही के समापन पर दिनांक 25.11.1949 के भाषण में (CAD का पृष्ठ 975)।

* संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में अपने भाषण में दूसरे न्यायाधीशों के मामले के पैरा 429 में उद्धृत)

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसी आशय से डॉ. राजेंद्र प्रसाद * ने कहा:

"यदि निर्वाचित लोग सक्षम हैं और पुरुष हैं

चरित्र और अखंडता, वे बनाने में सक्षम होंगे
सबसे अच्छा एक दोषपूर्ण संविधान का भी। अगर उनकी कमी है

इनमें संविधान देश की मदद नहीं कर सकता। इसके बाद

कुल मिलाकर, एक मशीन की तरह एक संविधान एक निर्जीव चीज है। यह.
उन लोगों के कारण जीवन प्राप्त करता है जो इसे नियंत्रित करते हैं और

इसे संचालित करें, और भारत को आज एक के अलावा और कुछ नहीं चाहिए

ईमानदार पुरुषों का समूह जिनका हित होगा

उनके सामने देश "।

यहाँ तक कि एक अच्छी प्रणाली में भी कमियाँ हो सकती हैं।

व्यक्तिगत विफलताओं के कारण काम करना। इसका उल्लेख किया जा सकता है

कि कार्यपालिका सहित संविधान के प्रत्येक अंग के कार्यकरण के विरुद्ध कार्य करने की आलोचना की जा
सकती है और विधानमंडल और जबकि सभी प्रयास लगातार किए जाने चाहिए

हर क्षेत्र में सुधार लाने के लिए, मूल योजना

संविधान द्वारा स्थापित इस पर मंजूरी नहीं दी जा सकती है

जमीन। यह टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है कि कितना अच्छा या बुरा है।

किसी भी संवैधानिक प्राधिकरण ने निर्वहन में प्रदर्शन किया है

उनके कर्तव्य या न्यायपालिका ने कितना अच्छा या बुरा प्रदर्शन किया है,

न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली का विषय हो सकता है - अलग विचार जो प्रस्तावित किया जा रहा है लेकिन निश्चित रूप से

न्यायपालिका की स्वतंत्रता के संविधान की बुनियादी विशेषताओं को मंजूरी दिए बिना। मनोज नरूला बनाम यूनियन ऑफ भारत ", इस सवाल पर विचार किया गया कि अपराधी व्यक्तियों के साथ कैसे

पूर्ववर्तियों को नियुक्त होने से रोका जा सकता था

मंत्री। इस चिंता का भी संदर्भ था कि कैसे

इस तरह की पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को विधायक बनने से रोका जा सकता था। इस न्यायालय ने कहा कि इस मुद्दे से निपटा जाना चाहिए जिन्हें संविधान ने सौंपा है

72 2014 (9) एस. सी. सी. 1 सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

जिम्मेदारी और यह न्यायालय केवल संवैधानिक को लागू कर सकता है

योजना।

18.11 इस स्तर पर, यह उल्लेख किया जा सकता है कि दावा

विद्वान महान्यायवादी जिनका संसद ने प्रतिनिधित्व किया था

लोगों की इच्छा या कि संशोधन का प्रतिनिधित्व करता है

लोगों की इच्छा और उसके साथ हस्तक्षेप अवांछनीय होगा।

केशवानंद भारती मामले में निर्धारित कानून के विपरीत है (ऊपर) "। लोगों की इच्छा संविधान है जबकि

संसद एक निश्चित बिंदु पर बहुमत की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है।

समय जो संविधान के अधीन है, अर्थात् इच्छा लोगों से। संविधान सर्वोच्च था और यहाँ तक कि

संसद के पास संशोधन करने की कोई असीमित शक्ति नहीं है। सीखा है।

संवैधानिक संशोधन की वैधता इस न्यायालय की है। भले ही न्यायपालिका एक निर्वाचित निकाय नहीं है, यह निर्वहन करती है

संविधान में प्रतिबिंबित लोगों की इच्छा के अनुसार संवैधानिक कार्य और लोगों की शक्तियों को निर्धारित करने का कार्य

विभिन्न संवैधानिक अंग न्यायपालिका को सौंपे गए हैं।

निष्कर्ष:

18.12 तदनुसार, मेरा मानना है कि न्यायपालिका की प्रधानता और न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की सीमित भूमिका का हिस्सा है

संविधान की मूल संरचना। न्यायपालिका की प्रधानता

एक प्रस्ताव शुरू करने और उसे अंतिम रूप देने में है। सीजेआई ने

मामले में अंतिम शब्द। कार्यपालिका को देने की स्वतंत्रता है

प्रस्ताव की शुरुआत से पहले सुझाव देना और प्रतिक्रिया देना।
और पूर्ववृत्त पर और

प्रस्तावित उम्मीदवारों के चरित्र

घोषित कारणों के लिए नियुक्ति पर आपत्ति, जैसा कि में आयोजित किया गया है

द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों के मामले।

ई. क्या विवादित संशोधन बदल जाता है या

बुनियादी संरचना को नुकसान पहुँचाता है

19. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, एकमात्र प्रश्न जो

73 पारस 652 एएमडी 653
मामला)

14 पारस 328 और 334, कुलदिप सिंह, जे। (द्वितीय न्यायाधीशों का

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायपालिका की प्रधानता की मूल विशेषता में संशोधन
गया है या क्षतिग्रस्त कर दिया गया है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति को बदल दिया

19.1 विद्वान महान्यायवादी ने प्रस्तुत किया कि बुनियादी

संरचना में कई स्तंभों जैसी कई विशेषताएं शामिल हैं।

फाउंडेशन, जिनमें से कुछ केशवानंद भारती मामले में दी गई राय में गिने जाते हैं। वैधता का न्याय करने में

एक संवैधानिक संशोधन का परीक्षण यह है कि क्या संशोधन

यह संविधान के पतन का कारण बनेगा। केवल प्रभावित करना या

एक ऐसी विशेषता को मूर्त रूप देने वाले लेख पर प्रभाव डालना जो इसका हिस्सा है
मौलिक संरचना संशोधन घोषित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी।

असंवैधानिक है। संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन

ऐसा होना चाहिए कि संरचना ही ध्वस्त हो जाए। वह भी। भीम सिंह जी बनाम संघ में
टिप्पणियों पर भरोसा किया।

इंडिया 75 विशेष रूप से निम्नलिखित टिप्पणियाँ:

"इसलिए, मूल विशेषता के साथ विश्वासघात क्या है

यह केवल अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, लेकिन चौंकाने वाला है।

अनुचित या अनैतिक उपहास

समान न्याय का सारा। यदि कोई कानून चला जाता है

जहाँ तक यह लोकतांत्रिक नींव को हिलाता है और होना चाहिए

मृत्युदंड भुगतें। लेकिन भारती भूत को अनुमति देने के लिए

अदालत के गलियारों को घातक रिटों के साथ परेशान करने के लिए

असमानता की हर विशेषता न्यायिक पक्षाघात है

संसदीय कार्य। न ही संवैधानिक

बुनियादी संरचना सिद्धांत के प्रति आकर्षण को पूरे विधायी शिविर में प्रवेश करने के लिए एक ट्रोजन
हॉर्स बनाया जाए

एक नई सामाजिक व्यवस्था के लिए लड़ना और लड़ाई पर विजय प्राप्त करना

'बुनियादी संरचना' द्वारा बुनियादी गरीबी के उन्मूलन के लिए

मिसाइल "।

और अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ 76 में निम्नलिखित टिप्पणियाँ:

75 (1981) 1 एससीसी 166

76 (2008) 6 एस. सी. सी. 1 सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

"इसमें बड़ी संख्या में प्रावधान हैं

संघीय चरित्र से संबंधित संविधान
संविधान। यदि प्रावधानों में से किसी एक में परिवर्तन किया जाता है या

संविधान की मूल संरचना। विभिन्न मौलिक
संविधान में विभिन्न प्रकार के अधिकार दिए गए हैं।

मानव जीवन के पहलू। संविधान स्वयं निर्धारित करता है कि
एक विस्तारित भविष्य के लिए सिद्धांत और इसके लिए बाध्य है
आने वाले युगों के लिए सहन करें और इसके परिणामस्वरूप यह है
विभिन्न परिवर्तनों के अनुकूल होने के लिए जो हो सकते हैं

मानव मामलों में जगह "।

19.2. उपरोक्त परीक्षणों को लागू करते हुए यह प्रस्तुत किया गया था कि

नब्बे-नौवां संशोधन सुसंगत था और मजबूत करता है

लोकतंत्र को बनाए रखते हुए न्यायपालिका की स्वतंत्रता,

न्यायपालिका के पक्ष में कार्यपालिका की शक्ति को कम करता है। वह. प्रस्तुत किया कि पहचान
परीक्षण लागू करने की आवश्यकता थी जो

इसका मतलब है कि संशोधन के बाद संशोधित संविधान

मूल संविधान की पहचान खो देता है। कोई बार नहीं है संशोधन करना और संविधान को अपनाना

नींव को छुए बिना समय बदलने की आवश्यकताएँ या मूल संवैधानिक स्वरूप को बदलना।
उन्होंने आगे भरोसा किया

इंदिरा गांधी और मिनर्वा मिल्स लिमिटेड मामलों में टिप्पणियों पर (ऊपर)।

19.3 विद्वान महान्यायवादी ने आगे कहा कि

संशोधन का उद्देश्य महाविद्यालय के आधार को व्यापक बनाना है।

निकाय ताकि सहभागी और सामूहिक भूमिका प्रदान की जा सके

न्यायपालिका, कार्यपालिका और नागरिक समाज। कार्यपालक

इसमें केवल एक सदस्य है, कानून मंत्री। होने का उद्देश्य

कानून मंत्री को उम्मीदवारों के बारे में जानकारी प्रदान करनी है

जो जानकारी अन्य सदस्यों के पास नहीं हो सकती है।

[2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3

प्रतिष्ठित व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से नियुक्त किया जाएगा

प्रधानमंत्री, सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के नेता की समिति

विपक्ष। इस तरह से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को निरस्त नहीं किया जाता है। इसके अलावा, छह में से तीन सदस्य हैं

न्यायपालिका और इस प्रकार, अस्वीकार करने का अधिकार न्यायाधीशों को उपलब्ध था,

जबकि अकेले कार्यपालिका अस्वीकार करने के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती है।

द्वितीय न्यायाधीशों के मामले में भी यह देखा गया है कि प्रक्रिया

नियुक्ति एक सहभागी प्रक्रिया है। संबंधित क्षेत्र

उम्मीदवारों की उपयुक्तता जैसे कि उनका पूर्ववृत्त और व्यक्तिगत दूतों के लिए बेहतर जाना जा सकता है

चरित्र के अलावा अन्य वाणिज्य

चरित्र या उपलब्धियों या सफलता में विशिष्टता का अर्थ है अभिव्यक्ति 'विशिष्ट' का उपयोग किया जाता है

जीवन के किसी भी क्षेत्र में।

अनुच्छेद 124 (3) न्यायाधीशों के लिए पात्रता मानदंड प्रदान करता है

सुप्रीम कोर्ट। चूंकि उच्चाधिकार प्राप्त समिति

तीन उच्च अधिकारियों को एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की नियुक्ति करनी है।

व्यक्ति, किसी भी असंबद्ध के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा है

न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति। संरचना में विविधता अन्य निकायों में

आयोग क्लोनिंग के खतरे को कम करेगा।

गैर-न्यायाधीशों के लिए भी प्रावधान हैं। उदाहरण के लिए,

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। अल्पसंख्यकों के पक्ष में आरक्षण,

महिलाएँ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग

समस्याओं के लिए अन्य सदस्यों को संवेदनशील बनाने का प्रभाव है

इन वर्गों का सामना करना पड़ेगा। यहां तक कि राष्ट्रीय रिपोर्ट में भी

संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए आयोग

(एन. सी. आर. डब्ल्यू. सी.), जिसे वेंकटचलैया आयोग के नाम से भी जाना जाता है,

एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए प्रावधान बिना निर्धारित किए किया गया था

कोई भी मानदंड। प्रतिष्ठित व्यक्ति का मार्गदर्शन सी. जे. आई. द्वारा किया जाएगा, जो अध्यक्ष होंगे और कानून तक पहुँचने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में होंगे।

उम्मीदवारों की योग्यता। कार्यकारी सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड में एक प्रमुख हितधारक है।

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

न्याय वितरण प्रणाली जिसके लिए यह उत्तरदायी है

संसद और इसकी नियुक्ति में भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है

न्यायाधीशों। प्रावधान के दुरुपयोग की केवल संभावना नहीं हो सकती है

किसी प्रावधान को अनुचित ठहराने का आधार। रिलायंस ने

मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम. भारत संघ "

जो नीचे लिखा है:

"इसी प्रभाव के लिए खन्ना, जे।

केशवानंद भारती बनाम। केरल राज्य (एससीआर पी।

755 : एस. सी. सी पी. 669) . विद्वान न्यायाधीश ने कहा: (एस. सी. सी पी. 821 , पैरा 1535)

"न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए, न्यायालय

की व्यावहारिक आवश्यकताओं से अनजान नहीं हो सकता है

सरकार। मुकदमे के लिए दरवाज़ा खुला छोड़ना होगा और

बुटि। अन्य नश्वर षड्यंत्रों की तरह संवैधानिक कानून

कुछ मौका लेना पड़ता है। मौका मिलना चाहिए।

अनुभव द्वारा उचित विश्वास की पुष्टि करने के लिए।

इसी प्रभाव के लिए टी. एन. में अवलोकन हैं।

शिक्षा विभाग। मंत्रिस्तरीय और सामान्य अधीनस्थ सेवा संगठन वी. टी. एन. राज्य [(1980) 3 एस. सी. सी. 97] (एस. सी. आर. पी पर। 1031) (कृष्ण लायर, जे.)। यह समान रूप से अच्छी तरह से स्थापित है।

कि केवल उन लोगों द्वारा किसी प्रावधान के दुरुपयोग की संभावना इसे प्रशासित करने का प्रभार रखने का आधार नहीं हो सकता है। प्रावधान प्रक्रियात्मक या मूल रूप से अनुचित है। सीमा शुल्क कलेक्टर बनाम। नाथेला संपथु चेट्टी [1962 (3) एससीआर 786], यह न्यायालय देखा: "अन्यथा किसी कानून के दुरुपयोग की संभावना वैध इसे अयोग्यता का कोई तत्व प्रदान नहीं करता है। यह. राजस्थान राज्य बनाम में कहा गया था। भारत संघ [(1977) 3 एस. सी. सी. 592] (पी. पर एस. सी. आर. 77) ", यह याद रखना चाहिए केवल इसलिए कि कभी-कभी सत्ता का दुरुपयोग किया जा सकता है, यह शक्ति के अस्तित्व को नकारने का कोई आधार नहीं है। द. मनुष्य का ज्ञान अभी तक एक की कल्पना करने में सक्षम नहीं है " 77 7 (1997) 5 एससीसी 536 [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इन सब का जवाब देने के लिए पर्याप्त शक्ति के साथ सरकार वैध आवश्यकताएँ और साथ ही शरारत करने में असमर्थ "। (कॉमआर को भी देखें) , एच. आर. ई. बी. श्री लक्ष्मीद्र

श्री शिरूर मठ के तीर्थ स्वामी [(1954) एससीआर 1005]

(एस. सी. आर. पी. 1030) "। के मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही

न्यायपालिका में जनता के विश्वास के लिए नियुक्ति आवश्यक है। इस संबंध में इंदरप्रीत का हवाला दिया गया है।

सिंह काहलों बनाम पंजाब राज्य 'जो इस प्रकार है:

"यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाती है

सबक यह है कि संवैधानिक नियुक्ति से पहले

अधिकारियों को पूरी तरह से और सावधानी बरतनी चाहिए उनकी पूर्ववृत्तियों के बारे में पूछताछ और जांच।

ईमानदारी और योग्यता पर उचित रूप से विचार किया जाना चाहिए और

ऐसे उच्च पदों पर नियुक्तियों में मूल्यांकन किया जाता है।

यह समय की एक तत्काल आवश्यकता है कि इस तरह

नियुक्तियों में पूर्ण पारदर्शिता की आवश्यकता है

बनाए रखा और प्रदर्शित किया। कर्मों का प्रभाव

और संवैधानिक अधिकारियों के कुकर्म (जो हैं)

उच्च स्थान पर), बहुत बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करता है

बहुत लंबे समय तक, इसलिए, यह बिल्कुल अनिवार्य है।

कि केवल उच्च सत्यनिष्ठा, योग्यता, ईमानदारी वाले लोग और

इन संवैधानिक पदों पर ईमानदारी नियुक्त की जाती है।

19.4 इन प्रस्तुतियों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह है।

स्पष्ट है कि न्यायपालिका की पूर्व-प्रमुख भूमिका, जैसा कि इसमें मौजूद है

अंतिम निर्णय लेने में मूल संवैधानिक योजना का प्रकाश

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मुद्दे पर

उन्हें विदा कर दिया गया है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की अपरिवर्तित योजना के तहत, जो एक बुनियादी विशेषता है संविधान, राष्ट्रपति को नियुक्ति करनी है, उसके बाद

न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करने वाले सीजेआई के साथ परामर्श।

78 (2006) 11 एस. सी. सी. 356 शीर्ष अदालतें-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

सी. जे. आई. के विचारों को नजरअंदाज करना असाधारण रूप से स्वीकार्य है।
से चरित्र पर असर डालने वाली स्थितियाँ

अभिलिखित कारणों

और किसी उम्मीदवार का पूर्ववृत्त और यदि ऐसे कारण पाए जाते हैं

सी. जे. आई. को स्वीकार्य होना। संशोधित योजना के तहत, सीजेआई द्वारा ऐसा कोई अंतिम विचार नहीं लिया जा सकता है। बिना कुछ दिए

कारण, मंत्री या नामित सदस्य अस्वीकार कर सकते हैं

न्यायाधीशों का सर्वसम्मत दृष्टिकोण। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

आयोग का सदस्य नहीं है और कोई संवैधानिक नहीं है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति/स्थानांतरण में भूमिका।

केवल यह तथ्य कि न्यायाधीशों के बिना, मंत्री और

नामित सदस्य नियुक्ति नहीं कर सकते हैं

उस स्थिति के बराबर जहां एक निर्णय स्वयं द्वारा लिया जाता है

सीजेआई न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करते हैं। की संवैधानिक शक्ति

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने प्रस्ताव शुरू करने के लिए

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति समाप्त कर दी गई है

कम से कम जहाँ तक संवैधानिक प्रावधान हैं

चिंतित हैं।

19.5 यह तर्क कि संशोधन को मजबूत करता है

न्यायपालिका या लोकतंत्र की स्वतंत्रता या पारदर्शिता या जवाबदेही का आधार नहीं दिखाया गया है

सदस्य सीजेआई भी समिति के सदस्य हैं, तथ्य यह है कि कि प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता के पास है

ऐसे सदस्यों की नियुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका, जिनकी होगी

शक्ति न केवल सीजेआई और दो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों के बराबर है

न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में सर्वोच्च न्यायालय

सीजेआई और दो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश। इस तरह की रचना आयोग को अनुकूल नहीं माना जा सकता है

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति/स्थानांतरण न्यायालय, निश्चित रूप से कानून मंत्री और दो नामित सदस्यों द्वारा काफी हद तक प्रभावित हो सकते हैं, जिससे सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट प्रभावित होती है।

ई.

[2015] 13 एस सी आर।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता।

19.6 विद्वान महान्यायवादी की दलील कि यह धारणा है कि विधि मंत्री और नामित

सदस्य स्वतंत्र रूप से आचरण करेंगे और करेंगे

न्यायाधीशों के चयन में बेहतर तरीके से मूल्यवर्धन नहीं किया जा सकता है।

स्वीकार किया जाए। संविधान निर्माताओं के विचार और प्रख्यात विशेषज्ञ समितियाँ स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि

न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालक न्यूनतम होना चाहिए और

और चरित्र और पूर्ववृत्त की जाँच करने के लिए सीमित

उम्मीदवारों और अंत में योग्यता और उपयुक्तता का आकलन करने के लिए नहीं

ऐसे उम्मीदवारों के लिए। मामले के इस दृष्टिकोण में, भले ही

यह तर्क कि मानदंड के लिए किसी दिशानिर्देश की आवश्यकता नहीं थी

प्रतिष्ठित व्यक्तियों की नियुक्ति कब की जाएगी इस तथ्य को स्वीकार किया जाता है कि इसमें उच्च गणमान्य व्यक्ति शामिल होते हैं

कि ऐसे व्यक्ति न केवल समर्थन करेंगे बल्कि पूर्व भी खेलेंगे

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की नियुक्ति में प्रमुख भूमिका

न्यायाधीश जो स्वतंत्रता के लिए अनुकूल नहीं होंगे न्यायपालिका। इनमें से एक के लिए आरक्षण का कोई औचित्य नहीं है।

नामित सदस्य निर्दिष्ट श्रेणियों से होते हैं। इस तरह प्रावधान संविधान की योजना के खिलाफ है और इसके विपरीत है

विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर न्यायाधीशों का चयन करने का उद्देश्य। की प्रकृति

नियुक्ति किसी भी सकारात्मक कार्रवाई को उचित नहीं ठहराती है सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े किसी भी व्यक्ति की उन्नति

वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए या

महिलाएँ। न्यायाधीशों की नियुक्ति मूल्यांकन पर होनी चाहिए

उम्मीदवारों की योग्यता और उपयुक्तता। धर्म, जाति या लिंग

मूल्यांकनकर्ता की कोई प्रासंगिकता नहीं है। याचिका है कि कानून

मंत्री और नामित सदस्य फीडबैक देंगे।

उनके सदस्य होने का कोई औचित्य भी नहीं देता है।
लेना और

आयोग का और इस प्रकार मूल्यांकन में भाग

न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता
न्यायालय और जिन्हें रद्द करने की शक्ति है

उच्चतम न्यायालय या उच्च

न्यायाधीशों का सर्वसम्मत दृष्टिकोण। न्यायाधीश की नियुक्ति

उच्चतम न्यायालय आम तौर पर उच्च सर्वोच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से बना होता है-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

अदालतें या वरिष्ठ न्यायाधीश या प्रख्यात वकील या प्रख्यात न्यायविद

जिनकी योग्यता वरिष्ठ न्यायाधीशों को बेहतर पता है। उनका मूल्यांकन

और न्यायपालिका की निर्णायक भूमिका न केवल एक आवश्यकता है
और शक्तियों का पृथक्करण लेकिन

न्यायपालिका की स्वतंत्रता

बड़े पैमाने पर लोगों के विश्वास को प्रेरित करने के लिए आवश्यक है
मौलिक और कानूनी अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत रखने वाले नागरिक

लोकतंत्र की ताकत। अपने

कार्यपालिका या विधानमंडल द्वारा। अगर कोई मुलाकात है
प्रभावित होने के रूप में माना जाता है

राजनीतिक विचार या किसी से

अन्य बाहरी प्रभाव, निष्पक्षता में विश्वास, जो हॉल है

न्यायपालिका की स्वतंत्रता का निशान मिट जाएगा। यह योजना

भारतीय संविधान की मूल योजना के विपरीत।

19.7 इस संबंध में, यह याद किया जा सकता है

कि संशोधन शब्द का शाब्दिक अर्थ है बेहतरी या सुधार और

संशोधन का प्रायोजक हमेशा सुधार का दावा कर सकता है। इस तरह
परीक्षण' लागू करके किया जाना है और

दावे का परीक्षण 'पहचान

'प्रभाव परीक्षण'। उक्त परीक्षणों का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है

उनकी राय का पहला भाग। संशोधन को प्रभावित नहीं करना चाहिए
विशेषता की पहचान। द.

संविधान की एक अनिवार्य

योजना के कार्यक्रम पर संशोधन का प्रभाव
लाता है

संविधान को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह कुछ

व्यक्तिपरक तत्व का विस्तार जो किसी भी कानून का परीक्षण करते समय भी अपरिहार्य है जिसका उल्लंघन करने का आरोप है

मौलिक अधिकार और 'उचित' की अवधारणा पर न्यायोचित

प्रतिबंध '80। इस संबंध में, कार्यकारी हस्तक्षेप का प्रभाव

79 केशवानंद भारती मामला-पैरा 531; मेनका गांधी बनाम यू. ओ. आई. (1978) 1 एस. सी. सी. 248-पैरा 19; आई. आर. कोएल्हो मामला-पैरा 149

80 वी. जी. रो बनाम मद्रास राज्य (1952) एससीआर 597 [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जिसे विशेषज्ञ अध्ययनों द्वारा प्रलेखित किया गया है, आयोजित नहीं किया जा सकता है

इस आधार पर अप्रासंगिक या उपेक्षित होना कि यह एक विषय है

संसद का विवेक। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, कार्य

(चित्रण के माध्यम से) प्रिवी सहित कई अवसरों पर पर्स केस 31, बैंक राष्ट्रीयकरण केस 82, प्रेस की स्वतंत्रता केस 33, केशवानंद भारती केस (ऊपर), इंदिरा

गांधी मामला (ऊपर), मिनर्वा मिल्स मामला (ऊपर), एल।

चंद्रकुमार मामला (ऊपर), एम. नागराज मामला (ऊपर), आई. आर.

कोएल्हो मामला (ऊपर), एस. आर. बोम्मई मामला,

19.8 नई संरचना निर्णायक आवाज प्रदान करती है

आयोग जिसमें न्यायाधीशों के अलावा कानून भी शामिल है

मंत्री और दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों को एक द्वारा नामित किया जाएगा

निर्दिष्ट समिति। उक्त संरचना की जांच करने से पहले, यह केवल संशोधन का पाठ नहीं है

यह ध्यान दिया जा सकता है कि यह

लेकिन इसके प्रभाव और क्षमता को भी ध्यान में रखना होगा शक्ति की 'चौड़ाई' पर

मूल योजना की 'पहचान' और

नई योजना 35 के तहत। इसी तरह के संदर्भ में जब एक विकल्प

इससे निपटने के लिए न्यायिक मंच बनाने की मांग की गई थी

उच्च न्यायालयों के स्थान पर कंपनी मामले, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

कानून के शासन की अवधारणा के लिए आवश्यक था कि नया तंत्र

जितना संभव हो सके, उतने ही मानक होने चाहिए। वैसा ही
में विचार लिया गया था

राष्ट्रीय कर की स्थापना के संदर्भ

मामले 87। नई योजना क्रीज को इस्त्री कर सकती है लेकिन
तुलनीय होना चाहिए।

तंत्र प्रतिस्थापित योजना के साथ

19.9 जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है कि असंशोधित

इस न्यायालय द्वारा प्राधिकृत रूप से व्याख्या की गई योजना की शक्ति

81 माधव राव जीवाजी राव सिंधिया बनाम यू. ओ. आई. [1971 (1) एस. सी. सी. 85], 82 रुस्तम कावासजी
कूपर बनाम भारत संघ [1970 (1) एस. सी. सी. 248] 83 बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड बनाम। भारत
संघ [1972 (2) एस. सी. सी. 788] 84 एस. आर. बोम्मई बनाम। यूओआई [(1994) 3 एससीसी 1]

85 केशवानंद भारती मामला-पैरा 531; मेनका गांधी बनाम यू. ओ. आई. (1978) 1 एस. सी. सी. 248-पैरा
19; आई. आर. कोएल्हो मामला-पैरा 149

86 भारत संघ बनाम मद्रास बार एसन। (2010) 11 एस. सी. सी. 1-पैरा 108 87 मद्रास बार एसन। बनाम
यू. ओ. आई. (2014) 10 एस. सी. सी. 1-अनुच्छेद 136 और 137 सर्वोच्च न्यायालय

अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

प्रस्ताव की शुरुआत हमेशा न्यायपालिका के पास होती थी। उस समय

संविधान के निर्माण का, संविधान का मसौदा था

विचार प्राप्त करने के लिए संघीय न्यायालय और उच्च न्यायालयों को प्रसारित किया गया
न्यायाधीशों से। के विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाले ज्ञापन में

न्यायाधीशों, यह उल्लेख किया गया था कि मौजूदा सम्मेलन था

कि न्यायाधीशों की नियुक्ति मामले को भेजने के बाद की गई थी

मुख्य न्यायाधीश को और उनकी सहमति प्राप्त करना।

19.10 सीएडी में, विभिन्न मॉडलों पर विचार किया गया था लेकिन

अन्य देशों में लागू प्रणाली जो अंतिम कहने के लिए प्रदान करती है

अनुपयुक्त पाए गए। यह बात डॉ. अम्बेडकर ने कही थी। कि शक्ति को सलाह पर प्रयोग करने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता था

कार्यपालिका की या उसकी सहमति के अधीन किया जाए
विधायिका। यह आगे कहा गया कि मुख्य न्यायाधीश कर सकते हैं
89 न्यायाधीशों की नियुक्ति पर भी वीटो नहीं दिया जाएगा।
विधि आयोग ने अपनी 14 वीं रिपोर्ट में इसकी आलोचना की
न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका का हस्तक्षेप। द.

मामला संसद में चर्चा के लिए आया और गृह मंत्री और कानून मंत्री ने बयान दिया कि सभी नियुक्तियां सीजेआई की सिफारिश पर की गई थीं

क्योंकि सीजेआई उम्मीदवारों की योग्यता से परिचित थे। बाहर। 211 में से 210 नियुक्तियां सहमति से की गईं और

सीजे 90 की सहमति। यह नोट किया गया था कि प्रक्रिया द्वितीय न्यायाधीश से पहले लागू न्यायाधीशों की नियुक्ति

मामला यह था कि नियुक्ति के लिए एक प्रस्ताव शुरू किया गया था
सुप्रीम कोर्ट के मामले में सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में उच्च न्यायालय। यह तंत्र
सम्मेलन 92 का हिस्सा होने के लिए आयोजित किया गया था।

19.11 शमशेर सिंह मामले (ऊपर) में यह न्यायालय

88 दूसरे न्यायाधीशों का मामला-पारस 360 और 361 89 द्वितीय न्यायाधीशों के मामले में पैरा 192 में निर्दिष्ट डॉ. अम्बेडकर का वक्तव्य 90 द्वितीय न्यायाधीशों के मामले में पैरा 362 368 में पुनः प्रस्तुत की गई बहसों

91 पैरा 98 द्वितीय न्यायाधीशों का मामला

92 पैरा 370, कुलदिप सिंह, जे. और पैरा 505, पुंछी, जे. द्वितीय न्यायाधीशों के मामले में [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह देखा गया कि व्यवहार में न्यायपालिका के मामलों में अंतिम शब्द सीजेआई से संबंधित होना चाहिए। एक ही विचार व्यक्त किया गया था

न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संदर्भ में संकलचंद मामला (उपर्युक्त) 93 की अध्यक्षता में विधि आयोग की 80 वीं रिपोर्ट में

न्यायमूर्ति एच. आर. खन्ना, जे. (1979), एक आयोग प्रस्तावित किया गया था।

से निपटने के लिए न्यायपालिका की एक पूर्व-प्रमुख आवाज के साथ

न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण। रिपोर्ट महत्वपूर्ण थी।

नियुक्ति में न्यायाधीशों के अधिक्रमण की पृष्ठभूमि में सी. जे. आई. और न्यायाधीशों का चयनात्मक स्थानांतरण जो माना जाता था

न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करना। हालांकि,

उक्त सिफारिशों के विपरीत, एक परिपत्र जारी किया गया था 1981 में विधि मंत्री द्वारा न्यायाधीशों के स्थानांतरण का प्रस्ताव और

कम अवधि के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति करना जो स्वयं था

न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप माना जाता है और प्रथम न्यायाधीशों के मामले में चुनौती दी गई थी। पहले की तरह

उल्लेख किया, बहुमत का मानना था कि ऐसे मामलों में प्रधानता है

केंद्र सरकार के साथ। उक्त दृष्टिकोण विषय था

गंभीर आलोचना का विषय। प्रख्यात संवैधानिक विशेषज्ञ सीरवाई ने टिप्पणी की कि कार्यपालिका इसके लिए योग्य नहीं थी

उम्मीदवार के गुण या दोष का आकलन करें। ए की शुरुआत

कार्यपालिका द्वारा प्रस्ताव के इरादे के खिलाफ था

संविधान के निर्माता। राजनीतिक, कार्यकारी या विधायी

न्यायाधीश 95 की नियुक्ति में दबाव नहीं पड़ना चाहिए।

न्यायमूर्ति डी. ए. देसाई की अध्यक्षता में विधि आयोग ने अपने

121 सेंट रिपोर्ट ने उस प्रणाली की भी आलोचना की जहाँ कार्यपालिका न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में उनके पास प्रमुख शक्तियाँ थीं।

उन्होंने कहा कि वरिष्ठ न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की शक्ति

कार्यपालिका द्वारा न्यायालय न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं और यह इसके स्वस्थ विकास के लिए अनुकूल नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि

न्यायिक आयोग की ओर से मनमानी की जांच करने के लिए

ऐसी नियुक्तियों और स्थानान्तरणों में कार्यपालक 96

93 पारस 39,41 चंद्रचूड़, जे। ; 50-52 भगवती, जे। ; 103, 115 कृष्ण लायर, जे., 94 पैरा 30-प्रथम न्यायाधीशों का मामला

95 सीरवाई, चौथा संस्करण, भारत का संवैधानिक कानून-पारस 25.350,25.353 और 25.354

96 पैरा 7.5 और 7.8-121 1 विधि आयोग के सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. 1. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

19.12 दूसरे न्यायाधीश के मामले में व्याख्या

यह उपरोक्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में था। के संदर्भ में

भारतीय संविधान का कार्यकरण, की प्रमुख भूमिका

न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा

न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका को महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है

कानून और लोकतंत्र के शासन को बनाए रखने के लिए भूमिका। इसका

स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा की इसकी शक्ति बुनियादी का हिस्सा हैं। संरचना। न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायपालिका की प्रधानता एक हिस्सा है

मूल संरचना। इस पृष्ठभूमि में सवाल यह है कि क्या नई योजना न्यायपालिका की उक्त प्रधानता को बरकरार रखती है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति।

19.13 नई योजना के तहत कानून मंत्री ने

सीजेआई के बराबर भूमिका दी गई। शुरुआत से ही

संविधान, कानून मंत्री की यह भूमिका कभी नहीं थी

प्रक्रिया शुरू करते समय और इसे अंतिम रूप देते समय इसकी परिकल्पना की गई थी। कानून

मंत्री, सहभागी योजना में, सबसे अच्छा एक नाम सुझा सकते हैं

या प्रस्तावित नामों पर अपनी टिप्पणी दें लेकिन प्रस्ताव

सीजेआई द्वारा शुरू किया जा सकता था और हमेशा किया जाता था। दीक्षा के चरण में, यदि समान अधिकार प्रदान किया जाता है, तो यह नष्ट हो जाएगा

न्यायपालिका की प्रधानता, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अधिकृत रूप से घोषित किया गया है।

अतीत में किसी भी विचलन पर हमेशा प्रतिकूल टिप्पणी की जाती थी

हस्तक्षेप के लिए अवांछनीय माना जाता है

न्यायपालिका की स्वतंत्रता के साथ 97. दो अन्य लोग

एक समिति द्वारा नामित जो भी प्रमुख है

प्रस्ताव को शुरू करने और अंतिम रूप देने में सीजेआई के बराबर राजनीतिक आवाज को रखा जाना मूल योजना को नष्ट कर देता है।

पहचान। किसी नाम या प्रतिक्रिया की शुरुआत करने से पहले कोई भी सुझाव

दीक्षा के बाद भी उपयोगी हो सकता है और प्रभावित नहीं कर सकता है

न्यायपालिका की स्वतंत्रता लेकिन कानून द्वारा समान भागीदारी

दीक्षा या दीक्षा के लिए अंतिम निर्णय में मंत्री और दो बाहरी लोग

नियुक्ति स्वतंत्रता के लिए हानिकारक हो सकती है

न्यायपालिका। यह मानते हुए इसे दूर नहीं किया जा सकता है कि कानून मंत्री और दो वितरक किसी से प्रभावित नहीं होंगे।

97 पैरा 505, पुंछी, जे। ; पारस 210,214, पांडियन, जे। ; दूसरे न्यायाधीशों के मामले में (2015) 13 एस. सी. आर. में अनुच्छेद 361 से 376, कुलदिप सिंह, जे.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3

असाधारण विचार। ऐसी धारणा विपरीत होगी।

मान्यता प्राप्त तथ्यात्मक अनुभव के लिए। इसके खिलाफ भी होगा।
अलग करने की अवधारणा। अधिक

न्यायपालिका को कार्यपालिका से

इस पर संविधान के मूल इरादे के विपरीत होगा।

निर्माता। यह संशोधन कोई मामूली संशोधन नहीं है।

और के काम करने के बुनियादी ढांचे के भीतर नहीं है

संविधान। संशोधन का आधार और उद्देश्य

जैसा कि उद्देश्यों और कारणों के कथन में परिलक्षित होता है और

तर्कों का यह है कि न्यायपालिका की प्रधानता के द्वारा विकसित किया गया था गलत व्याख्या जिसे ठीक करने की कोशिश की जाती है। यह है।

कहा कि न्यायपालिका की प्रधानता अलोकतांत्रिक थी और

कार्यपालिका को एक सार्थक भूमिका से वंचित कर दिया। ये हैं कारण पहले से चर्चा किए गए कारणों के लिए असमर्थनीय। जहां तक पारदर्शिता और जवाबदेही के अनुरोध का संबंध है, वही होना चाहिए

पारदर्शिता और जवाबदेही के कथित अनुरोध पर, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की कोशिश की जाती है

संशोधन द्वारा, यह गंभीर क्षति का कारण बनेगा संविधान की कार्यप्रणाली। न्यायपालिका की प्रधानता, जैसे

न्यायपालिका की स्वतंत्रता को नष्ट करना, उनकी यह दलील कि सुझाव देकर स्थिति को पुनः प्राप्त किया जा सकता है व्याख्या स्वीकार नहीं की जा सकती है। ऐसी व्याख्या नहीं है

संशोधन के पाठ या के सिद्धांतों द्वारा समर्थित

व्याख्या। यह मानना मुश्किल है कि न्यायपालिका की प्रधानता है

फिर भी एक गलत प्रस्ताव के रूप में बनाए रखा जा सकता है अभी भी किसी भी शीर्ष अदालत के अधिवक्ताओं द्वारा रोका जा सकता है-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

दो न्यायाधीशों सहित दो सदस्य। न्यायपालिका की प्रधानता

जैसा कि हमेशा बाध्यकारी न्यायिक उदाहरणों में समझा जाता है

नाम की दीक्षा और अंतिम कॉल 98 लेना। ये दो मूल

विशेषताएँ न्यायपालिका की प्रधानता की पहचान का गठन करती हैं। विषय इन दो विशेषताओं के लिए कोई भी संशोधन किया जा सकता था।

और अगर इन दो विशेषताओं से समझौता किया जाता है, तो मूल पहचान यह माना जा सकता है कि संविधान में परिवर्तन किया गया है या

क्षतिग्रस्त कर दिया।

19.14 प्रस्तावों के बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता है

उत्तरदाताओं द्वारा बलपूर्वक प्रचार किया गया कि संसद की पसंद का विधायी ज्ञान इसके लिए खुला नहीं था

सवाल और सत्ता के दुरुपयोग की संभावना प्रभावित नहीं कर सकी

क्या मूल विशेषता को बदलने की मांग की गई थी, यह अलग है संसद के विवेक पर सवाल उठाने से। यह परीक्षण है

संविधान द्वारा प्रदत्त संसद की शक्ति। इसी तरह यह निर्धारित करना कि क्या नया तंत्र अनुपालन करता है संविधान का ढांचा इस मुद्दे से अलग है कि

संविधान के निर्माता। यहाँ तक कि सबसे अच्छा मानते हुए भी इरादा, संवैधानिक द्वारा न्यायिक समीक्षा की शक्ति हो सकती है

अदालतें किसी भी 'प्रतिष्ठित व्यक्ति' द्वारा जांच के अधीन हों।

इस आधार पर कि न्यायपालिका के कामकाज को असंतोषजनक माना जाता था। जाहिर है कि यह स्पष्ट हस्तक्षेप होगा

न्यायपालिका की स्वतंत्रता 99. उसी तरह, संवैधानिक रूप से न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायिक प्रधानता प्रदान नहीं की जा सकती है

नीचे गिराया गया या उन लोगों द्वारा नियंत्रित होने की मांग की गई जो नहीं हैं

दिए गए या ऐसे कार्यों को संभालने की अनुमति दी गई। यहाँ तक कि अनुदान भी

98 पारस 471,478,486 (2), 486 (3), 486 (4 और 5), वर्मा, जे. 99 चित्रण के माध्यम से: पी. संबमूर्ति बनाम ए. पी. राज्य [(1994) 3 एस. सी. सी. 1]; अमरीक सिंह लायलपुरी बनाम यू. ओ. आई. (2011) 6 एस. सी. सी. 535; भारत संघ बनाम मद्रास बार एसना (2010) 11 एस. सी. सी. 1; मद्रास बार एसना बनाम यू. ओ. आई. (2014) 10 एस. सी. सी. 1 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

[2015] 13 एस सी आर।

सबसे अच्छा इरादा, संसद से परे कार्य नहीं कर सका

संविधान द्वारा इसे प्रदत्त अधिकार। इस प्रकार, दूर ले जाना

न्यायपालिका की प्रधानता या किसी निकाय को ऐसी प्रधानता प्रदान करना जो

उक्त अवधारणा के बराबर नहीं होना निश्चित रूप से संसद के पास उपलब्ध विकल्प नहीं है। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, न्यायपालिका की प्रधानता की अवधारणा में आरंभ करना शामिल है

किसी भी प्रतिकूल फीड के मामले में प्रस्ताव और अंतिम निर्णय लेना

प्रस्ताव शुरू होने के बाद वापस प्राप्त किया जाता है। यह अवधारणा

यदि न्यायपालिका आरंभ करने में असमर्थ है तो प्रधानता से समझौता किया जाता है

पहली बार में एक प्रस्ताव या यदि ऐसा प्रस्ताव हो सकता है
 प्रभावी रूप से अस्वीकार कर दिया। इसका प्रभाव यह है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रभाव में किया जा सकता है कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व कानून मंत्री या गैर-न्यायाधीश द्वारा किया जाता है
 जिन सदस्यों की नियुक्ति में पूर्व-प्रमुख आवाज नहीं है
 न्यायपालिका से। ऐसी नियुक्तियों का प्रभाव यह होगा कि
 नियुक्त न्यायाधीश अपनी नियुक्तियों के लिए ऋणी होंगे
 कार्यपालिका जो जनता के विश्वास के लिए विनाशकारी हो सकती है
 न्यायपालिका की निष्पक्षता और न्यायपालिका की भूमिका पर प्रतिकूल प्रभाव
 न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण निष्पक्ष संवैधानिक अंग के रूप में। के रूप में
 पहले से ही उल्लेख किया गया है कि न्यायपालिका की भूमिका परिभाषित करना और विनियमित करना है
 के दायरे में अन्य संवैधानिक प्राधिकरणों का काम करना
 उन्हें सौंपी गई भूमिकाएँ।

19.15 यदि संशोधन में केवल सलाह का प्रावधान किया गया था

या कानून मंत्री या गैर-न्यायिक सदस्यों को पारदर्शिता के उद्देश्य के साथ सिफारिश करने वाली भूमिका और जवाबदेही, स्थिति अलग हो सकती है। हो सकता है कि उस मामले में इसने न्यायपालिका की प्रधानता में हस्तक्षेप नहीं किया हो।

न्यायाधीशों की नियुक्ति में जो अधिदेश है संविधान। इस तरह की शक्ति को संसद के विवेक के सिद्धांत के तहत और न ही एक बार विश्वास के सिद्धांतों के तहत उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

ऐसी शक्ति न्यायपालिका की प्रधानता के सिद्धांत का उल्लंघन है। न्यायाधीशों की नियुक्ति। कार्यपालिका या विधानमंडल या मौजूदा प्रणाली के काम करने का कोई व्यक्तिगत उदाहरण नहीं

100 446 सर्वोच्च न्यायालयों में विशेष संदर्भ संख्या 1 (1965) 1 एस. सी. सी. 413-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

न्यायाधीशों की नियुक्ति पर चर्चा की आवश्यकता है यहाँ शामिल संविधान की व्याख्या की है न कि

किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति की सफलता या विफलता। पहले की तरह

उल्लेख किया गया है, प्रत्येक संस्थान के काम करने में कमियां हो सकती हैं संवैधानिक रूप से
निरंतर प्रयासों से इसे हटाने की आवश्यकता है

अनुमेय लेकिन ढांचे के परिवर्तन को उचित नहीं ठहरा सकते
संविधान या उसी को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है।

20. अब प्रस्तुत करने के लिए संदर्भ दिया जा सकता है

उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील कि कई देशों में

न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायपालिका की प्रधानता के बिना, स्वतंत्र न्यायपालिका काम कर रही है
और इस प्रकार निरंकुश न्यायपालिका है

प्रधानता अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति के साथ असंगत थी। खास तौर पर 15 देशों, अर्थात् केन्या, का उल्लेख
किया गया है।

पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, इजराइल, फ्रांस, इटली, नाइजीरिया, श्री
श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका।

20.1 विद्वान महान्यायवादी का प्रस्तुतिकरण

उक्त 15 देशों में न्यायिक नियुक्तियों का संबंध इस प्रकार है - निम्नलिखित है:

"ए। 9 देशों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के माध्यम से

परिषद (फ्रांस, इटली, नाइजीरिया और सर लंका); 4
देश एक प्रत्यक्ष आदेश के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं

गवर्नर जनरल (ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड)

या राष्ट्रपति (बांग्लादेश), जहां लागू हो; (
जर्मनी) नामांकन की एक बहु-चरणीय प्रक्रिया का पालन करता है।

न्याय मंत्री द्वारा, द्वारा पुष्टि

संसदीय समितियाँ और राष्ट्रपति द्वारा अंतिम नियुक्ति; और 1 (संयुक्त राज्य अमेरिका) एक प्रक्रिया का
पालन करता है।

राष्ट्रपति (कार्यपालिका) द्वारा नामांकन और

सीनेट (विधायिका) द्वारा पुष्टि।

बी। सभी 15 देशों में, कार्यपालिका अंतिम या सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर. है।

निर्धारक नियुक्ति प्राधिकरण। 9 में से

आयोग वाले देश, 2 देशों में (दक्षिण अफ्रीका)

और श्रीलंका) में कार्यपालिका के पास पूर्ण बहुमत है अन्य समूहों के सदस्यों के साथ तुलना
(न्यायपालिका,

विधायिका और स्वतंत्र व्यक्ति)। 4 देशों (फ्रांस, इज़राइल, केन्या और यूके) में एक संतुलित स्थिति है।

सहित विभिन्न हितधारकों का प्रतिनिधित्व

कार्यकारी। 3 देशों में से जहाँ की संख्या

न्यायाधीशों का बहुमत (इटली, नाइजीरिया और पाकिस्तान) में है।

2 देशों (नाइजीरिया और पाकिस्तान) का निर्णय

आयोग संसद के मतदान के अधीन है।

समिति/सीनेट, जबकि 1 (इटली) में, के अध्यक्ष

गणराज्य अंतिम नियुक्ति प्राधिकरण है और

न्यायिक नियुक्ति निकाय के अध्यक्ष। 5 में से आयोग के बिना देश (कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यू यॉर्क)

कार्यपालिका द्वारा बिना किसी औपचारिक के निर्णय लिया जाता है। न्यायपालिका के साथ परामर्श
की प्रक्रिया, जबकि 1

(जर्मनी), नियुक्ति प्रक्रिया द्वारा आयोजित की जाती है

संसद, और बाद में राष्ट्रपति द्वारा पुष्टि की गई।

सी। 8 देशों में (फ्रांस, इज़राइल, इटली, केन्या, नाइजीरिया,

नियुक्तियाँ, स्वतंत्र सदस्यों के लिए अनिवार्य हैं प्रतिनिधित्व के माध्यम से चयन प्रक्रिया में
भूमिका

उक्त शरीर। 4 देशों में जहाँ स्वतंत्र हैं

सदस्य नियुक्ति प्रक्रिया (कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड) में औपचारिक भूमिका
नहीं निभाते हैं। नियुक्ति प्राधिकारी (निकाय या व्यक्ति) परामर्श करता है

विभिन्न चरणों में स्वतंत्र सदस्य चयन पर उनकी प्रतिक्रिया के लिए नियुक्ति प्रक्रिया

देश (बांग्लादेश, जर्मनी और श्रीलंका) नहीं स्वतंत्र के साथ परामर्श की प्रलेखित प्रक्रिया

सदस्यों को प्रदान किया जाता है "। सर्वोच्च अदालतें-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

20.2 उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील का भी उल्लेख किया गया है

कुछ न्यायविदों द्वारा कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना करने के लिए

वर्तमान मामले में उपस्थित प्रख्यात न्यायविद श्री नरीमन

याचिकाकर्ताओं के लिए।

गिरा दिया। उन्होंने विशेषज्ञ अध्ययनों का भी उल्लेख किया जिनमें शामिल हैं - 14 वें और 121 वें
विधि आयोगों की रिपोर्ट और

संविधान के कामकाज की समीक्षा करेगा राष्ट्रीय आयोग (एन. सी. आर. डब्ल्यू. सी.), न्यायमूर्ति एम.
एन. वेंकटचलैया (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में

सीजेआई), जिसमें यह कहा गया था कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता

संविधान की मूल विशेषता और एक की संरचना थी राष्ट्रीय आयोग के अनुरूप होने की आवश्यकता
थी

न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा। नियुक्ति का तरीका

न्यायाधीशों को इस तरह से बदला नहीं जा सकता था जिससे उन्हें नुकसान हो। न्यायपालिका की
स्वतंत्रता पर। न्यायपालिका की संरचना

आयोग को न्यायपालिका की प्रधानता को बनाए रखना होगा। 1 01

20.4 श्री नरीमन ने यह भी कहा कि विवादित

इसके निर्णयों के जवाब में संशोधन पेश किया गया था कुछ विधायकों को प्रभावित करने वाला
न्यायालय। उन्होंने कहा कि

न्यायपालिका का स्वतंत्र कामकाज अक्सर संघर्ष में आता है।

कार्यपालिका और विधानमंडल के साथ लेकिन के अधिदेश

न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने का संविधान था

कानून के शासन जैसे संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखें और लोकतंत्र, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा
को बनाए रखते हुए भी

राज्य के खिलाफ। उन्होंने विशेष रूप से 1978 के विधेयक 88 के माध्यम से प्रस्तावित पैंतालीसवें संशोधन के
इतिहास का संदर्भ दिया।

अनुच्छेद 368 में प्रावधान किया गया है कि समझौता करने वाला एक संशोधन

न्यायपालिका की स्वतंत्रता अनुमोदन द्वारा की जा सकती है

101 (रिपोर्ट दिनांक 26.9.2001 के पैरा 9.6 और 9.7 को खंड में शामिल किया गया है। एन. सी. आर. डब्ल्यू. सी., 2002 की रिपोर्ट का II)

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जनमत संग्रह में बहुमत। उसी के द्वारा लाया गया था

के दौरान गिरफ्तार किए गए नेताओं के नेतृत्व में जनता सरकार आपात स्थिति। राज्यसभा में बहुमत के अभाव में इसे मंजूरी नहीं दी गई थी।

सभा। उन्होंने इस कोर्ट लिली थॉमस के फैसलों का भी उल्लेख किया। बनाम भारत संघ 1 02 और मुख्य चुनाव आयुक्त

बनाम जन चौकिदार 103 अभिनिर्धारित करता है कि एक विधानमंडल का सदस्य

दोषी ठहराए जाने पर योग्य होगा और कि एक व्यक्ति में सीमित है

जेल चुनाव नहीं लड़ सकी और इस तरह के चुनाव को रद्द करने के प्रयास किए गए

निर्णय लेते हैं। उन्होंने संवैधानिक ग्रंथ का भी उल्लेख किया।

सीरवई द्वारा भारत का कानून, चौथा संस्करण, इस प्रभाव के लिए कि

प्रथम न्यायाधीशों के मामले के निर्णय ने न्यायिक स्वतंत्रता को कार्यपालिका 104 की दया पर डाल दिया

20.5 उन्होंने जवाब में एक व्यक्तिगत नोट भी दिया

उत्तरदाताओं की ओर से उनकी अपनी जीवनी पर निर्भरता

"स्मृति लुप्त होने से पहले "इस प्रकार है:

"मैं इसका समर्थक रहा हूं और बना रहूंगा।

"न्यायिक-नियुक्ति-आयोग-प्रणाली "और इसी तरह

क्या मेरे ग्राहक हैं जिनका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं (यह इस प्रकार कहा गया है)

पृष्ठ 26 से 31 और 44 से 45 पर याचिका लिखें)। बुटी एम

निश्चित रूप से एक न्यायिक के ढोंग के खिलाफ

नियुक्ति आयोग जो वास्तव में नहीं है

न्यायिक, केवल आंशिक या अर्ध न्यायिक। "न्यायिक

नियुक्ति आयोग प्रणाली "(तथाकथित)

बी. के. ए. यू. एस. ई. के अनुरूप नहीं है और नहीं है
की स्वतंत्रता पर बीजिंग सिद्धांतों के अनुरूप

न्यायपालिका (जिसके द्वारा हम भारत में शासित हैं)। द.

सिद्धांतों को लंबे विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया था

लावासिया क्षेत्र में न्यायपालिका के प्रमुख

(भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित)-जो सभी हस्ताक्षरकर्ता हैं

102 2013 (7) एस. सी. सी. 653

103 2013 (7) एस. सी. सी. 507

104 पारस 25.350 से 25.354 सर्वोच्च न्यायालय विज्ञापन-चालू-रिकॉर्ड

एस. एस. ओ. सी. एशन वी. यू. ओ. आई. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

बीजिंग सिद्धांत के लिए। सिद्धांत No.15 इस प्रकार है

निम्नलिखित है:

" 15. कुछ समाजों में न्यायाधीशों की नियुक्ति,

एक की सहमति से या उसके साथ परामर्श के बाद

न्यायिक सेवा आयोग के रूप में देखा गया है

यह सुनिश्चित करने का साधन कि वे चुने हुए न्यायाधीश हैं
उद्देश्य के लिए उपयुक्त। जहाँ एक न्यायिक

सेवा आयोग को अपनाया जाता है, इसमें शामिल होना चाहिए

उच्च न्यायपालिका के प्रतिनिधि और
के रूप में स्वतंत्र कानूनी पेशा

सुनिश्चित करने के साधन

कि न्यायिक क्षमता, अखंडता और स्वतंत्रता
जाता है "।

बनाए रखा

नोट-बाहरी नहीं, प्रतिनिधि नहीं

निष्पादन: क्योंकि यह हितों में सहायक नहीं है।

स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए

न्यायपालिका। बीजिंग सिद्धांतों का पाठ संलग्न किया गया है

प्रदर्शनी-// के रूप में।

तत्कालीन कानून मंत्री ने संसद में कहा था कि कब

स्वयं सहित नामित व्यक्तियों से परामर्श किया-और
किया गया है

मैंने जो कहा वह मिनटों में सटीक रूप से दर्ज

कानून मंत्री के कार्यालय द्वारा तैयार की गई बैठक। यह

मिनट्स रिकॉर्ड क्या है:

संवैधानिक विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिवक्ता,

श्री फली नरीमन ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि

न्यायपालिका की स्वतंत्रता और शक्तियों के पृथक्करण को याद रखें। बुनियादी संरचना सिद्धांत
जैसा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है

न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोई भी प्रस्ताव होना चाहिए
मूल संरचना के अनुरूप। उन्होंने महसूस किया कि

सरकार को मॉडल का पालन करने पर विचार करना चाहिए

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 13 एस. सी. आर. द्वारा सुझाए गए अनुसार नियुक्ति आयोग।

एस.

न्यायमूर्ति वेंकटचलैया आयोग जिसने दिया
नियुक्ति में न्यायपालिका का प्रभुत्व

प्रक्रिया। उन्होंने कहा कि रचना

आयोग मूल मुद्दा है, और एक आयोग

गैर-न्यायाधीश वर्चस्व के साथ व्यवहार्य नहीं होगा

भारत। .

21. जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, भारत का संविधान

इसकी अपनी पृष्ठभूमि और व्यक्तित्व 105। अन्य मॉडलों भारतीय संविधान की पहचान और
व्यक्तित्व को नुकसान पहुँचाने के लिए देशों का आंख मूंदकर पालन नहीं किया जा सकता था। न्यायिक

विद्वान महान्यायवादी द्वारा निर्दिष्ट आयोग नहीं करते हैं न्यायपालिका की पूर्व-विद्यमान भूमिका को कम करने की प्रवृत्ति दिखाएँ। में।

वास्तव में, प्रवृत्ति की पूर्व-मौजूदा भूमिका को कम करने के लिए है

कार्यकारी। विवादित संशोधन में यह उल्टा है। इस प्रकार,

अन्य संविधानों के कार्यकरण या स्थापना का विवाद

अन्य में अलग-अलग संरचनाओं के साथ न्यायिक आयोगों का देश विवादित संशोधन को उचित नहीं ठहराते हैं जो है

भारतीय संविधान की मूल संरचना के विपरीत।

22. इस तर्क में भी कोई योग्यता नहीं है कि

वर्तमान मामला केवल एक संवैधानिक प्रावधान में परिवर्तन है

किसी मूल विशेषता के नुकसान के बराबर नहीं है। यह एक मामला नहीं है क्रीज को इस्त्री करने के लिए सरल संशोधन। इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से प्रभावित करता है।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, न्यायाधीशों की नियुक्ति पर हमेशा विचार किया गया है

भारतीय संविधान के कार्यकरण की योजना अभिन्न होगी

न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए। यही कारण है कि

न्यायाधीशों की नियुक्ति में प्राथमिकता का हमेशा उद्देश्य रहा है।

न्यायपालिका का होना। कार्यपालिका की प्रमुख भूमिका नहीं है

अनुमति है। इस तरह की प्रधानता में प्रस्ताव को शुरू करना शामिल है।

न्यायपालिका द्वारा और अंतिम शब्द सामान्य रूप से सीजेआई के साथ होना (में) प्रतिनिधि क्षमता)। यह योजना शक्ति से परे है।

संसद के लिए उपलब्ध संशोधन।

105 आर. सी. पौड्याल बनाम यू. ओ. आई. (1994) सप.

1 एस. सी. सी. 324, पैरा 53 सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

22.1 नई योजना में, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

अदालतों को कोई संवैधानिक राय नहीं दी गई है। द. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शुरू में बेहतर स्थिति में हैं

न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उम्मीदवार की योग्यता का आकलन करना

राज्य के मुख्यमंत्री की किसी भी भूमिका के लिए। यह प्रभावित कर सकता है चयनित उम्मीदवार की गुणवत्ता और इस प्रकार

न्यायपालिका की स्वतंत्रता। एन. जे. ए. सी. में वैधानिक प्रावधान

अधिनियम को अलग से लिया जाएगा।

22.2 विद्वान महान्यायवादी का तर्क है कि

जाँच के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए संशोधन उचित था और संतुलन और पारदर्शिता जो समान रूप से महत्वपूर्ण संवैधानिक मूल्य थे, उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह मानते हुए भी कि

कॉलेजियम के कामकाज में सुधार की गुंजाइश है

प्रणाली, यह नहीं माना जा सकता है कि मौजूदा प्रणाली के तहत वहाँ कोई पारदर्शिता या नियंत्रण और संतुलन नहीं है। प्रक्रिया.

केंद्र सरकार द्वारा जारी ज्ञापन में रखा गया

इस राय के पूर्व भाग में उल्लेख किया गया है। सभी

प्रस्ताव शुरू करने की कार्यवाही लिखित रूप में होती है और

संवैधानिक अधिकारियों को भेजा गया। मुखिया।

मंत्री, राज्यपाल, कानून मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास इस मामले में अपने विचार रखने का अवसर है -

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों की नियुक्ति

प्रक्रिया में शामिल न्यायाधीशों और गैर-न्यायाधीशों से। कानून.

मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास भी अवसर है

सीजेआई और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर अपनी टिप्पणी दें। सुझाव देने का भी अवसर है

प्रस्ताव की शुरुआत से पहले नाम। वहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है

शामिल संवैधानिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से नागरिक समाज से विशेषज्ञ प्रतिक्रिया। इस प्रकार पारदर्शिता के साथ-साथ

न्यायपालिका द्वारा प्रस्ताव की अंतिम शुरुआत में हस्तक्षेप अंतिम दृष्टिकोण लेने में, सुसंगत

या न्यायपालिका द्वारा मामले में

संविधान के आदेश के साथ।

[2015] 13 एस सी आर।

3

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

22.3 सीखी हुई महान्यायवादी ने तुलना करने की मांग की

कॉलेजियम के दो सदस्यों द्वारा वीटो के लिए मौजूदा प्रावधान

तीसरे न्यायाधीशों के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति ' धारा 6 (6) के तहत वीटो को उचित ठहराने का मामला। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है,

कानून मंत्री और गैर-न्यायाधीश सदस्यों की भूमिका नहीं हो सकती

मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों के बराबर रखा जाए

सुप्रीम कोर्ट। स्पष्ट रूप से उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। कारणों से। कानून मंत्री के साथ या गैर के साथ वीटो शक्ति

न्यायाधीश सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध जो है

कॉलेजियम के सदस्य के साथ हस्तक्षेप शामिल हो सकता है

न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इसी तरह, विशेष की आवश्यकता

किसी भी अन्य सामान्य स्थिति में बहुमत की तुलना नहीं की जा सकती थी

न्यायाधीशों की नियुक्ति की योजना जो सुई जेनरिस है।

इसी तरह, महत्वपूर्ण जानकारी देने की दलील उचित नहीं है। मुख्य न्यायाधीश के साथ गैर-न्यायाधीश सदस्यों की भागीदारी

और न्यायाधीश एक प्रस्ताव शुरू करने या अंतिम विचार लेने के अपने कार्यों का निर्वहन करने में। हालांकि, औपचारिक कार्य

न्यायाधीशों की नियुक्ति एक कार्यकारी कार्य हो सकता है,

संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में एक अद्वितीय न्यायिक तत्व। कथित के खिलाफ आलोचना

कॉलेजियम के कामकाज में भी कमी नहीं आती है

विवादित प्रावधानों को उचित ठहराएँ। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, वहाँ

न्यायिक कार्यों के निर्वहन के खिलाफ भी आलोचना हो सकती है

पीडित पक्षों द्वारा या अन्यथा। लेकिन यह न्यायिक निर्णय 106 में हस्तक्षेप को उचित नहीं ठहराता है। कहने की जरूरत नहीं है कि आलोचना किसी भी प्रणाली के काम करने के खिलाफ हो सकती है लेकिन

व्यवस्थाओं को केवल संविधान के अनुसार ही बदला जा सकता है। प्रयास

सुधार के लिए सभी प्रणालियों को लगातार बनाना होगा।

निष्कर्ष:

22.4 मैं यह निष्कर्ष निकालूंगा कि नई योजना नुकसान पहुंचाती है।

संविधान की मूल विशेषता जिसके तहत प्रधानता

105 पी. संबमूर्ति बनाम ए. पी. राज्य (1987) 1 एस. सी. सी. 362-अनुच्छेद 3 और 4, अनुच्छेद 371 डी (5) को निरस्त करना, अमरीक सिंह लायलपुरी बनाम यू. ओ. आई. (2011) 6 एस. सी. सी. 535 पैरा 15-17, दिल्ली नगर निगम की धारा 347 डी को निरस्त करना।

निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66)

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

नई योजना को इस तरह की प्रधानता दी गई है। इस प्रकार यह विवादित संशोधन को कायम नहीं रखा जा सकता है।

च. एन. जे. ए. सी. अधिनियम की वैधता

23. संशोधन के संसद की क्षमता से परे होने के बारे में मेरे निष्कर्ष को देखते हुए, मैं इसे नहीं मानता। एन. जे. ए. सी. अधिनियम की वैधता पर विस्तार से चर्चा करना आवश्यक है

क्योंकि उक्त अधिनियम एक बार संशोधन किए जाने के बाद जीवित नहीं रह सकता है। नीचे। हालांकि, मेरे पहले के दृष्टिकोण के अनुरूप कि प्रधानता

और उस आधार पर न केवल संशोधन की धारा 2 न्यायपालिका के साथ अनिवार्य परामर्श के साथ वितरण

जैसा कि असंशोधित प्रावधानों के तहत विचार किया गया है, धारा 3

एन. जे. ए. सी. को (अनुच्छेद 124 बी के तहत) शक्ति प्रदान करना और

अनुच्छेद के तहत आयोग की संरचना के लिए प्रावधान करना

124 कानून मंत्री और दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भूमिका देना।

सीजेआई, न्यायाधीशों के रूप में नियुक्तियों की सिफारिश करने में सीजेआई के बराबर उच्चतम न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश

न्यायालयों और मुख्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश करना और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश असंवैधानिक हैं लेकिन अनुच्छेद भी हैं।

124 ग. संसद को प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति देना।

और चयन का तरीका भी निर्धारित करना था

असंवैधानिक, विवादित अधिनियम को निरस्त किया जाना चाहिए। यह.

प्रक्रियात्मक पहलुओं से बहुत आगे जाता है। धारा 5 (2) में

'उपयुक्तता मानदंड' को विनियमों द्वारा तैयार किया जाना बाकी है।

धारा 5 (2) और धारा 6 (6) का दूसरा परंतुक आयोग के दो सदस्यों को वीटो देता है जिस पर विचार नहीं किया गया है।

संशोधन द्वारा। धारा 5 (3) और धारा 6 (8) प्रदान करती है

चयन के लिए विनियमों द्वारा निर्धारित शर्तों के लिए जो

ये केवल प्रक्रियात्मक मामले नहीं हैं। धारा 6 प्राधिकृत करती है कि

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए सिफारिशें

प्रस्ताव को पहले मुख्य न्यायाधीश द्वारा शुरू किए बिना उच्च न्यायालय। धारा 6 (1) में अनुशंसा [2015] 13 एस. सी. आर. का प्रावधान है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आधार पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अंतर वरिष्ठता। यह प्रभावित कर सकता है जितने व्यवहार्य हों उतने उच्च न्यायालयों को प्रतिनिधित्व देना

वरिष्ठता के बीच, केवल एक उच्च न्यायालय के कई न्यायाधीश हो सकते हैं सबसे वरिष्ठ। धारा 6 (2) नामांकन के लिए प्रावधान करती है।

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से, लेकिन धारा 6 (3) सशक्त करती है आयोग स्वयं इसके लिए सिफारिश करेगा

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति और टिप्पणी मांगना

मुख्य न्यायाधीश से उम्मीदवारों को स्वयं सूचीबद्ध करने के बाद।

धारा 8 केंद्र सरकार को आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करने और उन्हें निर्धारित करने में सक्षम बनाती है। सेवा की शर्तें। सरकार का सचिव है

आयोग के संयोजक। धारा 13 में सभी विनियमों को संसद द्वारा अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता है। ये अधिनियम के प्रावधान स्वतंत्रता को बाधित करते हैं

न्यायपालिका। भले ही बुनियादी संरचना के सिद्धांत को लागू नहीं किया जाता है

न्यायपालिका और कानून का शासन अनुच्छेद 14, 19 और 21 के अंग हैं। संविधान और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अभाव

उक्त मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है। एनजेएसी अधिनियम इस प्रकार है गिराए जाने की संभावना।

G. संशोधन का प्रभाव निरस्त किया जा रहा है

24. यह तर्क कि भले ही संशोधन माना जाता है

शून्य, पहले से मौजूद प्रणाली को बहाल नहीं किया जा सकता है, इसका कोई तर्क नहीं है।

न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए, एक प्रावधान हो सकता है -

शून्य घोषित किया गया जिस मामले में कानूनी स्थिति जैसी है

इस तरह के शून्य प्रावधान के बिना प्रबल माना जा सकता है। यह एक नहीं है

स्थिति जब निर्णय लेते समय स्थिति स्पष्ट नहीं की गई हो एक मुद्दा। अपने आदेश के प्रभाव को घोषित करने की इस न्यायालय की शक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता है और न ही उनके द्वारा किए गए निर्णयों पर संदेह किया जा सकता है।

उत्तरदाता अन्यथा दिखाते हैं। मेरा मानना है कि संशोधन होने पर

निरस्त होने पर, पूर्व-विद्यमान प्रणाली पुनर्जीवित हो जाती है।

एच. मौजूदा प्रणाली शीर्ष अदालत के अधिवक्ताओं के काम करने की समीक्षा-चालू-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

25. चूंकि संशोधन से पहले मौजूद प्रणाली

संशोधन को निरस्त किए जाने पर पुनर्जीवित किया गया और इसके कामकाज के बारे में शिकायतें व्यक्त की गई हैं, मैं हूँ

यह विचार कि ऐसी शिकायतों पर विचार किया जाना चाहिए। यह है।

नियुक्ति लेकिन व्यवहार में इसके कामकाज के बारे में। यह हो चुका है उन्होंने तर्क दिया कि यह न्यायालय इस पहलू पर फिर से विचार किए बिना जा सकता है।

बड़ी पीठों के पहले के निर्णय। मेरा नज़रिया है कि ऐसी शिकायतों पर ध्यान दिया जाना चाहिए जिनके लिए मामला दर्ज किया जाना चाहिए

सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

26. विवादित संशोधन और अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है

असंवैधानिक के रूप में नीचे। नियुक्ति की पूर्व-विद्यमान योजना

कार्य के रूप में शिकायतों के जीवित मुद्दे पर विचार करना पूर्व-विद्यमान प्रणाली।

एपेन्डिक्स

(1) असंशोधित संविधान के प्रमुख प्रावधान

"124. सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और संविधान न्यायालय-(1) भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा।

भारत के मुख्य न्यायाधीश से मिलकर और, जब तक

संसद कानून द्वारा एक बड़ी संख्या निर्धारित करती है, नहीं

सात से अधिक अन्य न्यायाधीश।

(2) उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश होगा -

राष्ट्रपति द्वारा अपने हाथ के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया गया और ऐसे न्यायाधीशों के साथ परामर्श करने के बाद मुहर

उच्चतम न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय जो राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझें

और साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करेंगे।

पाँच साल:

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बशर्ते कि न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में
न्यायाधीश

मुख्य न्यायाधीश के अलावा, भारत के मुख्य

हमेशा सलाह ली जाएगी:

आगे कहा गया है कि

(क) न्यायाधीश अपने हाथ के नीचे लिख कर संबोधित कर सकता है।

राष्ट्रपति को, अपने पद से इस्तीफा दें;

XXXXXX 217. एक के कार्यालय की नियुक्ति और शर्तें

उच्च न्यायालय का न्यायाधीश-उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश

राष्ट्रपति द्वारा आदेश द्वारा नियुक्त किया जाएगा

भारत के न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल, और
का मामला

प्रमुख के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति

न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और

किसी अतिरिक्त या कार्यवाहक न्यायाधीश के मामले में पद धारण करना,

जैसा कि अनुच्छेद 224 में प्रावधान किया गया है, और किसी अन्य मामले में, जब तक

वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करता है:

XXXXXX

222. एक उच्च न्यायालय से एक न्यायाधीश का स्थानांतरण
बाद

दूसरा-राष्ट्रपति, के साथ परामर्श के

भारत के मुख्य न्यायाधीश, एक उच्च न्यायाधीश से एक न्यायाधीश का स्थानांतरण

किसी अन्य उच्च न्यायालय का न्यायालय।

XXXX "

((2) 99 वां संशोधन अधिनियम

वह संविधान (नौवीं-नौवीं संशोधन)

अधिनियम, 2014

[31 सेंट दिसंबर, 2014]

भारत के संविधान में संशोधन करने के लिए एक और अधिनियम।

1 सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एस. एस. ओ. सी. एशन वी. यू. ओ. आई. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

चाहे वह संसद द्वारा संसद के साठवें वर्ष में अधिनियमित किया गया हो।
निम्नानुसार है:

भारत गणराज्य

1. (1) इस अधिनियम को संविधान कहा जा सकता है (नब्बे

नौवां संशोधन) अधिनियम, 2014।

(2) यह ऐसी तारीख को लागू होगा जब केंद्रीय

सरकार, आधिकारिक में अधिसूचना द्वारा

राजपत्र, नियुक्त करें।

2. संविधान के अनुच्छेद 124 में खंड (2) में -

(a शब्दों के लिए "ऐसे लोगों के साथ परामर्श के बाद" उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के
न्यायाधीश

उन राज्यों में जिनके लिए राष्ट्रपति आवश्यक समझे

उद्देश्य ", शब्द, आंकड़े और अक्षर"

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियों की सिफारिशें

अनुच्छेद 124 ए में निर्दिष्ट आयोग होगा -

प्रतिस्थापित; (ख) पहला परंतुक हटा दिया जाएगा;

(ग) दूसरे परंतुक में, "आगे प्रदान किया गया" शब्दों के लिए

कि ", बशर्ते कि "शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. संविधान के अनुच्छेद 124 के बाद, निम्नलिखित

लेखों को जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

"124 ए. (1) ज्ञात करने के लिए एक आयोग होगा

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के रूप में

जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) भारत के मुख्य न्यायाधीश, अध्यक्ष, पदेन;

(बी) उच्चतम न्यायालय के दो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश

अधिकारी;

(ग) कानून और न्याय के प्रभारी केंद्रीय मंत्री

-सदस्य, पदेन;

(घ) [2015] 13 एस. सी. आर. द्वारा नामित किए जाने वाले दो प्रतिष्ठित व्यक्ति।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से बनी समिति

भारत के न्यायाधीश और विपक्ष के नेता

लोक सभा या जहाँ ऐसा कोई नेता नहीं है

विपक्ष का, तब, सबसे बड़ा नेता

लोक सभा में विपक्षी दल

सदस्य:

बशर्ते कि प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक होगा

संबंधित व्यक्तियों में से नामित

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य

पुनः नामांकन के लिए पात्र हों।

(2) राष्ट्रीय न्यायिक का कोई

अधिनियम या कार्यवाही नहीं

नियुक्ति आयोग पर सवाल उठाए जाएंगे या

के संविधान में किसी भी रिक्ति या दोष के अस्तित्व के आधार पर अमान्य किया जाएगा

आयोग।

124 बी. यह राष्ट्रीय न्यायपालिका का कर्तव्य होगा।

नियुक्ति आयोग को

(क) प्रमुख के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करना।

भारत के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश
उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश

अदालतें;

(ख) मुख्य न्यायाधीशों और अन्य लोगों के स्थानांतरण की सिफारिश करना।
एक उच्च न्यायालय से लेकर किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

अन्य उच्च न्यायालय; और

(ग) यह सुनिश्चित करें कि अनुशंसित व्यक्ति योग्य है।

और ईमानदारी।

124 सी. संसद, कानून द्वारा, प्रक्रिया को विनियमित कर सकती है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं की नियुक्ति के लिए-ऑन-रिकॉर्ड

एस. एस. ओ. सी. एशन वी. यू. ओ. आई. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश और

उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीश और उन्हें सशक्त बनाना

आयोग विनियमों द्वारा प्रक्रिया निर्धारित करेगा

अपने कार्यों के निर्वहन के लिए, चयन का तरीका

नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की और ऐसे अन्य मामले जैसे

4. संविधान के अनुच्छेद 127 में, खंड (1) में, शब्द "भारत के मुख्य न्यायाधीश, पिछले के साथ हो सकता है

राष्ट्रपति की सहमति ", शब्द "राष्ट्रीय

न्यायिक नियुक्ति आयोग एक संदर्भ पर

भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इसे बनाया गया, मई के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा।

राष्ट्रपति की पूर्व सहमति को

5. संविधान के अनुच्छेद 128 में इन शब्दों के लिए "

भारत के मुख्य न्यायाधीश ", शब्द "राष्ट्रीय न्यायिक

नियुक्ति आयोग "को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

6. संविधान के अनुच्छेद 217 में, खंड (1) में,

"परामर्श के बाद" शब्दों से शुरू होने वाला भाग,

और "उच्च न्यायालय" शब्दों के साथ समाप्त होता है, शब्द,

आँकड़े और पत्र "की सिफारिश पर

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को भेजा गया

अनुच्छेद 124 क के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाएगा।

7. संविधान के अनुच्छेद 222 में, खंड (1) में,

शब्द "भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद",

सिफारिश पर शब्द, आँकड़े और अक्षर

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अनुच्छेद 124 ए में निर्दिष्ट "को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

8. संविधान के अनुच्छेद 224 में,

(क) खंड में (1), इन शब्दों के लिए "राष्ट्रपति हो सकता है
"नियुक्त करें", शब्द "राष्ट्रपति कर सकता है, में

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियों के साथ परामर्श

नियुक्त आयोग को प्रतिस्थापित किया जाएगा; [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(ख) खंड (2) में, इन शब्दों के लिए "राष्ट्रपति कर सकता है

"नियुक्त करें", शब्द "राष्ट्रपति कर सकता है, में

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियों के साथ परामर्श
प्रतिस्थापित किया जाएगा।

नियुक्त आयोग को

9. संविधान के अनुच्छेद 224 ए में इन शब्दों के लिए "

किसी भी राज्य के लिए उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय
समय, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के साथ ",

शब्द "राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिए गए एक संदर्भ पर

किसी भी राज्य के लिए न्यायालय, की पूर्व सहमति से हो सकता है

राष्ट्रपति को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

10. संविधान के अनुच्छेद 239 में, खंड (2) में, उप -

खंड (क) का लोप किया जाएगा। " (II) एन. जे. ए. सी. अधिनियम

"राष्ट्रीय न्यायिक आवेदन

आयोग अधिनियम, 2014 सं। 40 2014 का

[31 सेंट दिसंबर, 2014]

द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए एक अधिनियम

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग

प्रमुख के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करना

भारत के न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश

और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश

और उनके स्थानांतरण और संबंधित मामलों के लिए

इसके साथ या उससे आनुषंगिक।

चाहे वह संसद द्वारा संसद के साठवें वर्ष में अधिनियमित किया गया हो।

भारत गणराज्य निम्नानुसार है:

1. (1) इस अधिनियम को राष्ट्रीय न्यायिक कहा जा सकता है।

नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014।

(2) यह ऐसी तारीख को लागू होगा जब केंद्रीय

सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,

नियुक्त करें।

सर्वोच्च अदालतें-चालू-रिकॉर्ड

एस. एस. ओ. सी. एशन वी. यू. ओ. आई. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो,

(क) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है -

आयोग;

((ख) "आयोग" से राष्ट्रीय न्यायिक आयोग अभिप्रेत है।

अनुच्छेद 124 ए में निर्दिष्ट नियुक्ति आयोग

((ग) "उच्च न्यायालय" से वह उच्च न्यायालय अभिप्रेत है जिसके संबंध में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए सिफारिश की जाती है - आयोग द्वारा प्रस्तावित;

((घ) "सदस्य" से आयोग का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अध्यक्ष शामिल हैं;

((ङ) "विहित" का अर्थ है बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित।

इस अधिनियम के तहत;

((च) "विनियम" से अभिप्रेत है उनके द्वारा बनाए गए विनियम

इस अधिनियम के तहत आयोग।

3. आयोग का मुख्यालय होगा दिल्ली।

4. (1) केंद्र सरकार, एक अवधि के भीतर,

इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से तीस दिन,

न्यायाधीशों के पदों में मौजूद रिक्तियों की जानकारी दें

उच्चतम न्यायालय में और उच्च न्यायालय में

अपनी सिफारिशें करने के लिए आयोग

ऐसी रिक्तियां।

(2) केंद्र सरकार छह महीने पहले

के कारण किसी भी रिक्ति की घटना की तारीख

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल पूरा करना
को निर्देश दें।

या किसी उच्च न्यायालय का, आयोग

ऐसी रिक्ति को भरने के लिए अपनी सिफारिश करने के लिए।

(3) केंद्र सरकार, एक अवधि के भीतर,

कोई भी रिक्ति होने की तारीख से तीस दिन [2015] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायाधीश की मृत्यु या इस्तीफे के कारण

उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का, एक संदर्भ दें

ऐसी रिक्ति को भरने के लिए अपनी सिफारिशें करने के लिए आयोग।

5. (1) आयोग सिफारिश करेगा कि

सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की नियुक्ति

भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायालय यदि उन्हें उपयुक्त माना जाता है

पद संभालने के लिए: बशर्ते कि एक सदस्य

और उपयुक्तता के कोई अन्य मानदंड जो निर्दिष्ट किए जाएं।
नाम की सिफारिश करें

नियमों के अनुसार, नियुक्ति के लिए

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में

ऐसे व्यक्ति जो इस प्रकार नियुक्त होने के पात्र हैं -

संविधान के अनुच्छेद 124 का खंड (3):

बशर्ते कि के लिए सिफारिश करते समय

वरिष्ठता के अलावा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति,

ऐसे न्यायाधीश की क्षमता और योग्यता पर विचार किया जाएगा:

बशर्ते कि आयोग नहीं करेगा

अगर कोई दो हैं तो नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की सिफारिश करें।

आयोग के सदस्य इसके लिए सहमत नहीं हैं।

सिफारिश करें।

(3) आयोग, विनियमों द्वारा, ऐसा निर्दिष्ट कर सकता है -

चयन के लिए अन्य प्रक्रिया और शर्तें और

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो वह आवश्यक समझे।
करेगा कि

6. (1) आयोग सिफारिश

अंतर वरिष्ठता के आधार पर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश
क्षमता, योग्यता और कोई अन्य

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की

उपयुक्तता के मानदंड जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एस. एस. ओ. सी. एशन वी. यू. ओ. आई. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

(2) आयोग से नामांकन की मांग करेगा

संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने का उद्देश्य उस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना।

(3) आयोग भी क्षमता के आधार पर, योग्यता और उपयुक्तता का कोई अन्य मानदंड जो हो सकता है विनियमों द्वारा निर्दिष्ट, नाम नामित करें

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उन व्यक्तियों में से नियुक्ति जो इस प्रकार नियुक्त होने के पात्र हैं -

संविधान के अनुच्छेद 217 का खंड (2) और आगे

संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए ऐसे नाम

अपने विचारों के लिए न्यायालय।

(2) या उप-धारा (3) के तहत अपने विचार देते हुए, प्रमुख संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दो न्यायाधीशों से परामर्श करेंगे।

वरिष्ठ-उस उच्च न्यायालय के अधिकांश न्यायाधीश और ऐसे अन्य

उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और प्रख्यात अधिवक्ता

नियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। (5) उप के तहत विचार और नामांकन प्राप्त करने के बाद

आयोग धारा (2) और (3) की सिफारिश कर सकता है।

नियुक्ति के लिए वह व्यक्ति जो उपयुक्त पाया जाता है क्षमता, योग्यता और किसी भी अन्य मानदंड का आधार

उपयुक्तता जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है।

(6) आयोग किसी व्यक्ति की सिफारिश नहीं करेगा।

इस धारा के तहत नियुक्ति के लिए यदि कोई दो सदस्य हैं

आयोग इस पर सहमत नहीं है। सिफारिश करें।

(7) आयोग लिखित रूप में इन विचारों का पता लगाएगा -

राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री

ऐसी रीति जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।
13 एस. सी. आर. निर्दिष्ट कर सकता है।

(8) आयोग विनियमों द्वारा ऐसी [2015]

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और
समझे।

उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो आवश्यक

7. राष्ट्रपति की गई सिफारिशों पर

आयोग द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश या, जैसा भी मामला हो

किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों:

बशर्ते कि राष्ट्रपति, यदि आवश्यक समझे, तो आयोग से पुनर्विचार करने की मांग कर सकता है, या तो

आम तौर पर या अन्यथा, द्वारा की गई सिफारिश

वह:

बशर्ते कि यदि आयोग एक

तदनुसार पुनर्विचार के बाद सिफारिश

धारा 5 या 6 में निहित प्रावधानों के साथ, राष्ट्रपति तदनुसार नियुक्ति करेगा।
के साथ परामर्श कर सकती है

8. (1) केंद्र सरकार,

आयोग, इतनी संख्या में अधिकारियों की नियुक्ति करता है और

के कार्यों के निर्वहन के लिए अन्य कर्मचारी

इस अधिनियम के तहत आयोग।

और आयोग के अन्य कर्मचारी नियुक्त किए गए

उप-धारा (1) के तहत ऐसा होगा जो

निर्धारित किया गया।

(3) आयोग का संयोजक होगा -

विभाग में भारत सरकार के सचिव

न्याय का।

9. आयोग स्थानांतरण के लिए सिफारिश करेगा -

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश

एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय को, और इस उद्देश्य के लिए, विनियमों द्वारा, ऐसी प्रक्रिया निर्दिष्ट करें

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन v. यू. ओ. आई. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

स्थानांतरण।

10. (1) आयोग के पास निर्दिष्ट करने की शक्ति होगी -

विनियमों द्वारा, इसके निर्वहन की प्रक्रिया

कार्य।

(2) आयोग की बैठक ऐसे समय और स्थान पर होगी जिसे अध्यक्ष निर्देशित करे और ऐसे नियमों का पालन करे।

व्यवसाय के लेन-देन के संबंध में प्रक्रिया

इसकी बैठकें (इसकी बैठक में कोरम सहित), जैसा कि

विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

11. (1) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा

आधिकारिक राजपत्र, लागू करने के लिए नियम बनाते हैं

इस अधिनियम के प्रावधान।

(2) विशेष रूप से और व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना

पूर्वगामी शक्ति में से, ऐसे नियम सभी के लिए प्रावधान कर सकते हैं
भी मामला, अर्थात्:

या निम्नलिखित में से कोई

(क) प्रतिष्ठित व्यक्ति को देय शुल्क और भत्ते

खंड (1) के उपखंड (घ) के तहत नामित व्यक्ति

संविधान के अनुच्छेद 124 ए का;

(ख) अधिकारियों की सेवा के नियम और अन्य शर्तें

और आयोग के अन्य कर्मचारी उप के तहत

धारा 8 की धारा (2);

(ग) कोई अन्य विषय जो होना है या हो सकता है -
विहित, जिसके संबंध में प्रावधान किया जाना है
नियमों के अनुसार।

12. (1) आयोग अधिसूचना द्वारा

आधिकारिक राजपत्र, इसके अनुरूप नियम बनाएँ
अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम, को लागू करने के लिए
इस अधिनियम के प्रावधान।

(2) विशेष रूप से, और व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना
पूर्वगामी शक्ति से, ऐसे विनियम प्रदान कर सकते हैं
निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए, अर्थात्:

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उप-धारा (2) के अधीन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का धारा 5 का;

(ख) चयन के लिए अन्य प्रक्रिया और शर्तें और
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति
धारा 5 की उप-धारा (3);

(ग) नियुक्ति के संबंध में उपयुक्तता के मानदंड
की उप-धारा (3) के अधीन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का
धारा 6;

(घ) अन्य न्यायाधीश और प्रख्यात अधिवक्ता जो हो सकते हैं
की उप-धारा (4) के तहत मुख्य न्यायाधीश द्वारा परामर्श
धारा 6;

(ङ) राज्यपाल के विचार प्रकट करने का तरीका और

धारा 6 की उप-धारा (7) के तहत मुख्यमंत्री;

(च) चयन के लिए अन्य प्रक्रिया और शर्तें और

उप के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति धारा 6 की धारा (8);

(छ) मुख्य न्यायाधीशों और अन्य लोगों के स्थानांतरण की प्रक्रिया

एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

धारा 9 के तहत;

(ज) आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

धारा 10 की उप-धारा (1) के तहत अपने कार्यों का निर्वहन;

(i) लेन-देन के संबंध में प्रक्रिया के नियम

आयोग की बैठकों में व्यवसाय, जिसमें शामिल हैं अपनी बैठक में कोरम, धारा की उप-धारा (2) के तहत

10;

(जे) कोई अन्य मामला जो होना आवश्यक है, या हो सकता है -

विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट या किस प्रावधान के संबंध में

नियमों द्वारा बनाया जाना है।

सर्वोच्च न्यायालय

अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

एस. एस. ओ. सी. एशन वी. यू. ओ. आई. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

13. इस अधिनियम के तहत बनाए गए प्रत्येक नियम और विनियम

जितनी जल्दी हो सके, इसे बनाने के बाद, प्रत्येक से पहले रखा जाए संसद का सदन, जब यह सत्र में है, कुल मिलाकर

तीस दिनों की अवधि, जो एक में शामिल हो सकती है

सत्र या लगातार दो या अधिक सत्रों में, और यदि,

इसके तुरंत बाद सत्र की समाप्ति से पहले

उपर्युक्त सत्र या क्रमिक सत्र, दोनों

सदन नियम में कोई भी संशोधन करने के लिए सहमत हैं।

इसके बाद केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभाव पड़ेगा। या कोई प्रभाव नहीं होगा, जैसा कि मामला हो सकता है; तो, हालांकि, कि

ऐसा कोई भी संशोधन या रद्द करना बिना किसी संशोधन के होगा।

पहले की गई किसी भी चीज़ की वैधता के प्रति पूर्वाग्रह

उस नियम या विनियम के तहत।

14. (1) यदि प्रभाव देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है

इस अधिनियम के प्रावधानों के बाद, केंद्र सरकार

एक आदेश द्वारा आयोग के साथ परामर्श

सरकारी राजपत्र में प्रकाशित, ऐसे प्रावधान करें,

इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है जैसा कि दिखाई देता है

इसे हटाने के लिए आवश्यक या समीचीन होना

कठिनाई:

बशर्ते कि ऐसा कोई आदेश इसके बाद नहीं किया जाएगा

की तारीख से पाँच साल की अवधि की समाप्ति

इस अधिनियम का प्रारंभ।

(2) इस धारा के तहत किया गया प्रत्येक आदेश जल्द से जल्द

जैसा कि इसे बनाए जाने के बाद हो सकता है, प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाए

संसद से। " (III) उद्देश्यों और कारणों का विवरण

संशोधन अधिनियम

"उद्देश्यों और कारणों का विवरण

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति [2015] 13 एस. सी. आर. के तहत की जाती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुच्छेद 124 का खंड (2) और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

न्यायालयों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के खंड (1) के तहत की जाती है।

संविधान, राष्ट्रपति द्वारा। तदर्थ न्यायाधीश

और उच्चतम न्यायालय के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 127 के खंड (1) और अनुच्छेद 128 के अधीन

क्रमशः संविधान। की नियुक्ति

उच्च न्यायालय के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश और कार्यवाहक न्यायाधीश

अनुच्छेद 224 के तहत किया जाता है और उच्च न्यायालयों की बैठकों के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्नानुसार की जाती है -

संविधान का अनुच्छेद 224 ए। न्यायाधीशों का स्थानांतरण

एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद राष्ट्रपति के अनुच्छेद 222 के खंड (1) के तहत भारत का संविधान।

2. उच्चतम न्यायालय के मामले में सर्वोच्च न्यायालय

अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ

वर्ष 1993 में, और वर्ष में अपनी सलाहकार राय में

1998 तीसरे न्यायाधीशों के मामले में, खंड की व्याख्या की गई थी

(2) अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 217 का खंड (1)

के अर्थ के संबंध में संविधान

"सहमति" के रूप में परामर्श। नतीजतन, ए

न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया ज्ञापन

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को तैयार किया गया था,

और नियुक्ति के लिए पालन किया जा रहा है।

3. प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों की समीक्षा के बाद,

उच्चतम न्यायालय की घोषणाएँ और

प्रख्यात न्यायविदों के साथ परामर्श करते हुए, यह महसूस किया जाता है कि एक व्यापक आधार वाला राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग

सिफारिशें करने के लिए स्थापित किया जाना चाहिए

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए और

उच्च न्यायालय। उक्त आयोग एक न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के लिए सार्थक भूमिका

प्रतिष्ठित व्यक्तियों को अपने विचार प्रस्तुत करने और सर्वोच्च न्यायालय बनाने के लिए-ऑन-रिकॉर्ड

एस. एस. ओ. सी. एशन वी. यू. ओ. आई. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

प्रतिभागियों को जवाबदेह, जबकि भी परिचय

चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता।

4. संविधान (एक सौ इकतीस) संशोधन) विधेयक, 2014 एक सक्षमकारी संवैधानिक विधेयक है।

संबंधित प्रावधानों में संशोधन के लिए संशोधन

संविधान और एक राष्ट्रीय न्यायपालिका की स्थापना के लिए

नियुक्ति आयोग। प्रस्तावित विधेयक की मांग

संविधान के अनुच्छेद 124 के बाद नए अनुच्छेद 124 ए, 124 बी और 124 सी को सम्मिलित करना। उक्त विधेयक में यह भी प्रावधान है कि प्रस्तावित की संरचना और कार्य

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। इसके अलावा,

इसका प्रावधान है कि संसद, कानून द्वारा, विनियमित कर सकती है

न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया और उन्हें सशक्त बनाना

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग गठित करेगा इसके निर्वहन के लिए विनियमन द्वारा डाउन प्रक्रिया

कार्य, व्यक्तियों के चयन का तरीका

नियुक्ति और ऐसे अन्य मामले जो हो सकते हैं

आवश्यक माना जाता है।

5. प्रस्तावित विधेयक विधि के आधार को व्यापक बनाना चाहता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति और

उच्चतम न्यायालय में

उच्च न्यायालय न्यायपालिका की भागीदारी को सक्षम बनाते हैं, अधिक से अधिक सुनिश्चित करते हैं

कार्यकारी और प्रतिष्ठित व्यक्ति और

पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता

उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति और

उच्च न्यायालय।

6. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है।

न्यायालय का आदेश

1. एक बड़ी पीठ के संदर्भ के लिए और दूसरे और तीसरे न्यायाधीशों के मामलों पर विचार करने के लिए प्रार्थना [(1993)

सी. सी. 441, और (1998) 7 एस. सी. सी. 739, क्रमशः], को अस्वीकार कर दिया गया है।

2. संविधान (नब्बे-नौवां संशोधन) अधिनियम, 2014

असंवैधानिक और अमान्य घोषित।

[2015] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6

3. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम,

2014, असंवैधानिक और अमान्य घोषित किया जाता है।

4. सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली

न्यायालय, और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश; और

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों का एक से स्थानांतरण

उच्च न्यायालय, दूसरे के लिए, जैसा कि संविधान से पहले मौजूद था

(99 वां संशोधन) अधिनियम, 2014 (जिसे "कॉलेजियम" कहा जाता है) सिस्टम"), को ऑपरेटिव घोषित किया गया है।

5. उचित उपायों की शुरूआत पर विचार करने के लिए, यदि

"कॉलेजियम प्रणाली" के बेहतर कामकाज के लिए, सूची में शामिल करें 3.11.2015.

योग्यता के आधार पर दिया गया निर्णय।

बिभूति भूषण बोस

